सत्यमेव जयते

आर्थिक समीक्षा
2022-23

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
आर्थिक प्रभाग
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली–110001
जनवरी, 2023

विषय सूची

	vii	*प्रस्तावना*
	xi	*आभारोक्ति*
	xiii	*संकेताक्षर*
	xxxi	*तालिकाओं की सूची*
	xxxiii	*चित्रों की सूची*
	xli	*बॉक्स की सूची*
अध्याय सं.	**पृष्ठ सं.**	**अध्याय का नाम**
1		**अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022-23 : पूर्ण सुधार**
	3	वैश्विक अर्थव्यवस्था विशिष्ट चुनौतियों का सामना कर रही है
	9	भारतीय अर्थव्यवस्था में मैक्रोइकॉनॉमिक और विकास संबंधी चुनौतियाँ
	12	भारत का आर्थिक लचीलापन और विकास संचालक
	19	भारत का समावेशी विकास
	22	आउटलुक 2023-24
2		**भारत का मध्यावधि विकास परिदृश्यः आशापूर्ण दृष्टि और उम्मीद के साथ**
	24	परिचय
	25	उत्पाद और पूंजी बाजार में सुधार
	28	नए भारत के लिए सुधार - सबका साथ सबका विकास
	36	2014 के बाद आर्थिक और संरचनात्मक सुधारों की वापसी
	39	इस दशक में ग्रोथ मैग्नेट (2023-2030)
3		**राजकोषीय विकास - राजस्व सुधार**
	42	परिचय
	42	केंद्र सरकार की आय में वृद्धि
	54	राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था का अवलोकन
	61	सरकार का ऋण प्रोफाइल
	67	निष्कर्ष
4		**मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थताः एक अच्छा वर्ष**
	79	मौद्रिक विकास
	82	नकदी की स्थिति
	83	मौद्रिक नीति संचरण
	84	जी-सेक बाजार में विकास
	85	बैंकिंग क्षेत्र
	88	सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली और ऋणमुक्त कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा सहायता प्राप्त ऋण वृद्धि
	89	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का सुधार जारी है
	91	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत की गई प्रगति
	94	पूंजी बाजार में विकास
	102	अन्य विकास
	106	आईएफएससी - जीआईएफटी सिटी

109 बीमा बाजार में विकास
113 पेंशन क्षेत्र
116 दृष्टिकोण

5 **कीमतें और मुद्रास्फीतिः नाज़ुक परिस्थितियों पर कामयाबी**
118 परिचय
120 घरेलू खुदरा मुद्रास्फीति
129 घरेलू थोक मूल्य मुद्रास्फीति
133 ईंधन मूल्य मुद्रास्फीतिः वैश्विक कच्चे तेल की घटती कीमत
134 डब्ल्यूपीआई और सीपीआई मुद्रास्फीति का अभिसरण
137 मुद्रास्फीतिक संभावनाओं में गिरावट
138 मूल्य स्थिरता के लिए मौद्रिक नीतिगत उपाय
139 आवासन मूल्यः महामारी के बाद उभरता हुआ आवासन क्षेत्र
142 भेषज मूल्य निर्धारण को नियंत्रित रखना
142 निष्कर्ष

6 **सामाजिक अवसंरचना और रोजगारः व्यापक व्यवस्था**
146 परिचय
147 क्षेत्र के बढ़ते महत्व को गति देने के लिए सामाजिक क्षेत्र व्यय
149 मानव विकास मानदंडों में सुधार करना
151 आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम का परिवर्तन
153 प्रगामी श्रम सुधार उपाय
155 आधारः विशिष्ट पहचान की कई उपलब्धियां
157 रोजगार प्रवृतियों में सुधार करना
174 सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना
182 मिशन मोड में कार्यबल को नियोजनयोग्य कौशल एवं ज्ञान से सुसज्जित करना
185 सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती स्वास्थ्य सेवा
199 आपातकाल के लिए सामाजिक संरक्षक
200 भारत की आकांक्षी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास
212 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणः गेम चेंजर
213 समावेशी विकास के लिए ग्रामीण शासन में सुधार करना
215 निष्कर्ष और वे-फॉरवार्ड

7 **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणः भविष्य का सामना करने की तैयारी**
217 परिचय
221 भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाई पर प्रगति
231 संधारणीय विकास के लिए वित्त
234 सीओपी-27 में लिए गये प्रमुख निर्णय
235 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहल
236 अन्य पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित पहल
242 निष्कर्ष

8 **कृषि और खाद्य प्रबंधन: खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक**
243 परिचय
245 खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन
246 उत्पादन की लागत पर प्रतिलाभ सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)
246 कृषि संबंधी ऋण तक पहुंच में वृद्धि
247 फार्म मशीनीकरण- उत्पादकता में सुधार की कुंजी
247 रसायन मुक्त भारत: जैविक और प्राकृतिक खेती
248 कृषि में अन्य महत्वपूर्ण पहलें
252 संबद्ध क्षेत्र - पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन हाल के वर्षों में तेजी पकड़ रहा है।
253 सहकार-से-समृद्धि: सहयोग से समृद्धि तक
255 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र-सूर्योदय क्षेत्र
258 निष्कर्ष

9 **उद्योग: स्थायी विकास**
261 परिचय
262 औद्योगिक विकास के लिए मांग प्रोत्साहन
265 उद्योग की आपूर्ति प्रतिक्रिया
269 उद्योग के लिए बैंक ऋण में मजबूत वृद्धि
270 विनिर्माण क्षेत्र में लचीला एफडीआई अंतर्वाह
272 औद्योगिक समूह एवं उनकी चुनौतियां
284 वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की संभावनाएं
291 निष्कर्ष और दृष्टिकोण

10 **सेवाएं: शक्ति का स्रोत**
293 परिचय
294 उच्च-आवृत्ति संकेतकों का रुझान
297 प्रमुख सेवाएं: उप-क्षेत्रवार प्रदर्शन
310 आउटलुक

11 **वैदेशिक क्षेत्र: सतर्क और आशावान**
312 परिचय
313 वैश्वीकृत संसार के लाभ उठाने में मददगार व्यापार
326 चुनौतीपूर्ण अवधि में भुगतान संतुलन
333 वैश्विक विकास के साथ घटती बढ़ती विनिमय दर
335 अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति: भारत की ठोस वित्तिय स्थिति का प्रतिबिम्ब
336 सुरक्षित एवमं ठोस वैदेशिक ऋण स्थिति
339 सतर्क और आशावान वैदेशिक क्षेत्र की स्थिति

12 **भौतिक और डिजिटल आधारभूत संरचना: संभावित विकास को प्रोत्साहन**
343 परिचय
345 भारत में अवसंरचना के विकास के लिए सरकार की परिकल्पना और दृष्टिकोण
352 भौतिक अवसंरचना क्षेत्रों में विकास
360 डिजिटल अवसंरचना में विकास
371 निष्कर्ष/आउटलुक

प्रस्तावना

वर्ष 2023 की आर्थिक समीक्षा अवधि वैश्विक स्तर पर अनिश्चतापूर्ण है। अभी महामारी से उबर ही रहे थे कि फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध छिड़ गया। भोजन, ईंधन और उर्वरक की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जैसे-जैसे मुद्रास्फीति की दर में तेजी आई, उन्नत देशों के केन्द्रीय बैंकों ने प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी मौद्रिक नीति को सख्त किया। कई विकासशील देशों, विशेषरूप से दक्षिण एशियाई क्षेत्रों को कमजोर मुद्रा, उच्च आयात की कीमतों, जीवन यापन की बढ़ती लागत और मजबूत डॉलर के मेल के कारण गंभीर आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, जिससे सेवा और अधिक महंगी हो गई और इससे उबरना काफी मुश्किल साबित हुआ।

वर्ष 2022 की द्वितीय छमाही में सरकारों और परिवारों को राहत मिली। वस्तुओं की कीमतें अधिक बढ़ी और फिर कम हुईं। कुछ समय बाद विकट परेशानी से राहत मिली। हालांकि, कुछ वस्तुओं (जैसे कच्चा तेल) की कीमतें अपने महामारी-पूर्व स्तर से काफी ऊपर बनी हुई हैं। डॉलर की कीमत में भुगतान करने वाले आयात पर निर्भर देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक मंदी के फलस्वरूप वैश्विक मंदी में तिहरी राहत मिली है। जब वस्तुओं की कीमतों में कमी होती हैं, अमेरिकी ब्याज दरें अधिक हो जाती हैं, जैसा कि अमेरिकी डॉलर के साथ होता है। पूंजी और चालू खाता असंतुलन कम हो जाता है।

वर्ष 2023 के शुरूआत में ही चीन ने अपनी जीरो कोविड नीति के उलट, अपने रवैया उजागर कर दिया। अप्रत्याशित हल्की सर्दी के फलस्वरूप परिवार संबंधी ईंधन की कीमतों में होने वाली वृद्धि से अप्रभावित रहे, जो उनकी विक्रय आय को अत्यधिक प्रभावित कर सकती थी, इससे यह आशा जगी है कि मंदी के दौर से यूरो जोन व्यवस्था बाल-बाल बच जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका की शीर्ष मुद्रास्फीति दर में गिरावट आने से, नीतिगत दरों का धीरे-धीरे बढ़ना निश्चित है। इसी प्रत्याशा में, बांड प्रतिफलों में कमी आई है, और अप्रत्याशित वित्तीय प्रणाली के दबाव से संयुक्त राज्य अमेरिका के अप्रभावित रहने की संभावना कम है।

निर्यात पर निर्भर, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आने की संभावना कम है और उनकी आर्थिक गतिविधियों की बहाली से उन्हें उम्मीदें बंधी हैं, परन्तु यह उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जो आवश्यक वस्तुओं के लिए आयात पर निर्भर हैं। पूर्वानुमानित मांग से पहले उच्च मांग के कारण औद्योगिक धातुओं की कीमतों की तरह ही कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होनी शुरू हो गई है। अटलांटिक के दोनों ओर श्रम मजदूरी समझौतों में आरोही संशोधन हो रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरो जोन की सार्थक ब्याज दर में कटौती शायद आशा अनुरूप त्वरित गति से नहीं हैं। इस वर्ष के पूर्वानुमान वस्तु स्थिति से बहुत दूर हैं और देशों और परिवारों के लिए यह आश्चर्य का विषय हो सकता है।

वर्ष 2022, भारत के लिए खास रहा है। यह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करता है। मौजूदा डॉलर के मापदण्ड के अनुसार भारत विश्व की पॉचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आगामी मार्च तक भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। वास्तव में, मार्च 2023 को समाप्त हो रहे वर्ष में अर्थव्यवस्था के 7.0 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह विगत वित्त वर्ष की 8.7 प्रतिशत की वृद्धि की राह पर है। उपभोक्ता वस्तुओं में धीमी गती से वृद्धि हो रही है। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 6.0 प्रतिशत से नीचे है। थोक कीमतें 5.0 प्रतिशत से कम की दर से बढ़ रही हैं। वित्त वर्ष के प्रारंभिक नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर) में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वर्ष 2021-22 की समान अवधि की तुलना में 16 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष तेल की उच्च कीमत ने भारत के आयात बिल को बढ़ा दिया है और व्यापारिक घाटे के कारण हुए चालू खाते के घाटे को लेकर चिंताएं बढ़ीं हैं और वर्ष के बीतने के साथ-साथ वित्त पोषण कम होता गया। विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर सुविधापूर्ण है और बाह्य ऋण कम हैं।

भारत में मानसून अच्छा रहा और जल संग्रह का स्तर पिछले वर्ष तथा विगत दस वर्षों के औसत से अधिक रहा है। आधुनिक, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सदी की आगामी पच्चीस वर्ष की यात्रा के अपने '*अमृत काल*' में प्रवेश करने के समय भारत की अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत स्थिति में है। सावधानीपूर्वक तथा सर्तकता से अपनाई गई नीतियों ने यह सुनिश्चित हुआ है कि रिकवरी ठोस एवं सतत् है। यही वह संदर्भ है, जिसका आर्थिक समीक्षा, हाल ही के विगतकाल के आलोक में, वर्तमान अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करता है और आगामी वर्षों में इसकी संभावनाओं का परीक्षण करता है। इससे पहले मैं आपको वर्ष 2022-23 के आर्थिक समीक्षा का भीतरी सिंहावलोकन प्रस्तुत करूं, यह उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष अभी जारी है, और समीक्षा केवल नौ महीनों या अधिकतम आठ महीनों के आंकड़ों पर आधारित है।

परिपाटी के अनुसार, प्रथम अध्याय में अर्थव्यवस्था की स्थिति के परीक्षण के बारे में बताया गया है और इसमें कहा गया है कि यह अर्थशास्त्र और राजनीति की दुनिया के उतार-चढ़ाव के एक और वर्ष के रूप में अर्थव्यवस्था कैसे उभरी। महामारी के प्रभाव के कम होने के साथ ही जापान में मौसमी फ्लू ढलान पर है, और शायद डेनमार्क में पहले ही समाप्त हो चुका है। अध्याय 2 भारत की मध्यावधि के आर्थिक दृष्टिकोण का विश्लेषण करता है और इसकी बेहतरी के आकलन के साथ समाप्त होता है। यह वित्तीय चक्रों तथा मध्यम अवधि के आर्थिक विकास को प्रभावित करने में इसकी भूमिका का विश्लेषण करता है। पिछले दशक में भारत के वित्तीय चक्र में गिरावट आई है, क्योंकि सहस्त्राब्दि के प्रथम दशक में ऋण विस्तार अंतत: अस्थिर साबित हुआ। विश्व के वित्तीय इतिहास से पता चलता है कि ये परिणाम चौंकाने वाले थे। प्रचुर मात्रा में आए पूंजी प्रवाह से प्रेरित, ऋण का तीव्र विस्तार, सदैव वित्तीय संकट की भविष्यवाणी का

संकेत देतें हैं। भारत भी कोई अपवाद नहीं रहा। इस अध्याय से पता चलता है कि वित्तीय दबाव की अवधि के दौरान सरकार ने कैसे अर्थव्यवस्था को संचालित किया, जिसमें कार्पोरेट, बैंकिंग और गैर-बैंकिंग बैलेंस-सीट को दुरूस्त किया और सुधारों की वापसी की। संकट में भी संभावना की तलाश करते हुए सरकार ने बुनियादी ढांचें में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया ताकि निजी क्षेत्र के निवेश, पारिश्रमिक और समृद्धि के लिए जमीन तैयार की जा सके। इसमें सरकार द्वारा वर्ष 2014 से शुरू किए गए शासन के प्रक्रियागत सुधारों और व्यापक संरचनात्मक सुधारों को दर्ज किया गया है।

जहां वर्ष 2014 से पहले के सुधारों ने उत्पाद तथा पूँजी बाजार को पुष्ट किया, वहीं 2014 के बाद किए गए सुधारों ने जीवन यापन को सुगम बनाने और आर्थिक दक्षता में सुधार लाने के लिए व्यवसाय पर बल दिया। ये नीतियां जिन प्रमुख सिद्धांतों पर टिकी हुई हैं, वे सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर रहे हैं, विश्वास आधारित शासन व्यवस्था को अपना रहे हैं, विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी कर रहे हैं और कृषि उत्पादकता में सुधार कर रहे हैं। साफ-सुथरी, स्पष्ट और मजबूत बैलेंस-सीट और सुधारों से होने वाले भुगतान से भारत की अर्थव्यवस्था में संभावित वृद्धि हुई है और अर्थव्यवस्था की अपनी संभावित वृद्धि की क्षमता बढ़ी है। अनावश्यक दावे किए बिना, यह अध्याय भारत की मध्यम अवधि के दृष्टिकोण संबंधी आशावादी निष्कर्ष के साथ समाप्त होता है।

अध्याय 3, भारत की राजकोषीय नीति प्रक्षेप पथ पर केन्द्रित है, और राज्यों तथा केन्द्र के लिए टिकाऊ एवं भरोसेमंद राजस्व के स्रोत के रूप में माल और सेवा कर की प्रगति का परीक्षण करता है। आगामी वर्षों में, भारत के जनसांख्यिकीय लाभ और वार्षिक नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के औसतन लगभग 10 से 12 प्रतिशत रहने की संभावना को देखते हुए राजकोषीय मापदंडों में सुधार जारी रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि वृद्धि ही भारत के राजकोषीय संतुलन को संचालित करती है और यही सच है। यह भी संभव है कि भविष्य में राजकोषीय विषय राजकोषीय प्रोत्साहन में बदल जाए, चूंकि सार्वजनिक व्यय में ब्याज के भुगतान के वर्तमान शेयर को कम करने से सरकार की उधार लागत में कमी आएगी तथा इससे आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध होगी।

अध्याय 4 मुद्रा, बैंकिंग और पूंजी बाजार से संबंधित हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाली वस्तुओं पर पड़ने वाली महंगाई की मार के द्वितीय चरण के प्रभावों से बचाने के लिए ब्याज दरों में तीव्र वृद्धि की है। इसने डॉलर की मजबूती के एक वर्ष के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की सापेक्ष स्थिरता में बड़ी भूमिका निभाई। विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता रही। भारत का आयात क्षेत्र और बाह्य ऋण अनुपात चिंता का विषय नहीं है, और काफी हद तक यह आरबीआई के कुशल प्रबंधन के कारण हुआ है। भारत का पूंजी बाजार ऐतिहासिक सफलता की कहानी कह रहा है। भारतीय शेयरों के अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क सूचकांकों ने अपने उभरते बाजार का बेहतर प्रदर्शन किया है, और अपने वैश्विक समकक्षों को पीछे छोड़ दिया है। संक्षेप में, वर्षो से भारतीय शेयरों ने निवेशकों को अच्छा प्रतिफल दिया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को इससे काफी लाभ हुआ है। पिछले दो वर्षों में भारतीय शेयरों में बड़ी संख्या में भारतीय घरेलू खुदरा निवेशकों की भागीदारी में भी वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2021 और 2022 में भारतीय शेयरों के प्रदर्शन को देखते हुए न केवल उनके निवेश ने समय-समय पर होने वाले पोर्टफोलियो के बहिर्वाह के प्रभाव को सहन ही किया है, बल्कि इन्होंने अपने धन-भंडारण में भी इजाफा किया।

अगले अध्याय में, वर्ष भर की कीमतों संबंधी भारत के थोक एवं खुदरा मूल्यों के अभिसरण का वृतांत प्रस्तुत किया गया है। मई 2022 में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति बढ़कर 16.6 प्रतिशत हो गई और थोक मूल्य मुद्रास्फीति और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के बीच का अंतर बढ़ गया। जब थोक मूल्य मुद्रास्फीति अधिक होती है, तो हमेशा एक जोखिम बना रहता है कि यह खुदरा कीमतों को प्रभावित करेगी। वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में कमी आने और सरकार द्वारा उनकी घरेलू कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए उठाए गए सक्रिय कदमों के कारण वर्ष के अंत तक दोनों के बीच की खाई या रूकावट समाप्त हो गई।

विगत से आगे बढ़ते हुए, हम भारत के सामाजिक क्षेत्र (अध्याय-6) और उसके बाद जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण को (अध्याय-7) शामिल कर रहे हैं, जिसका महत्व भी कम नहीं है। समाज कल्याण सरकार के लिए 'उपसंहार' नहीं है बल्कि उसका मूलमंत्र है। इस अध्याय में सरकार द्वारा समाज कल्याण के लिए अपनाए गए व्यापक और 'कोई भी पीछे न छूटे' दृष्टिकोण को इस अध्याय में महत्व दिया गया है। इस अध्याय में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि विशेष रूप से महामारी के दौरान लक्षित लाभार्थियों तक सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग ने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, 'आधार' के प्रयोग और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बुनियादी ढांचे की उपलब्धता की विभिन्न पहलों के माध्यम से हो रहे नागरिकों के जीवन में परिवर्तन इस अध्याय के मुख्य आकर्षण हैं। इस अध्याय के तेरह बॉक्सों, जो एक बड़ी संख्या है - में समाज कल्याण योजनाओं तथा उनके वितरण में असंख्य नवाचारों की एक अभिस्वीकृति है, जिसे सरकार ने अपनाया और कार्यान्वित किया है।

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, वैश्विक स्तर पर न केवल ज्वलंत मुद्दे हैं बल्कि भारत के लिए अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) से सर्वाधिक सशक्त जलवायु कार्रवाइयों में से एक का नेतृत्व

कर रहा है, विश्व स्वच्छ ऊर्जा के प्रसार के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम इसमें शामिल है। अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद, देश ने अपनी जलवायु महत्वाकांक्षा को कई गुना बढ़ाया है।

देश के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए कृषि क्षेत्र की स्थिती महत्वपूर्ण है। भारत ने घरेलू खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है और हाल के वर्षों में दुनिया के लिए कृषि उत्पादन का निवल निर्यातक बन गया है। कृषि क्षेत्र में क्षमता बढ़ी है। भारत में खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक के परिवर्तन काल और सरकार द्वारा कृषि उत्पादकता को दिए जाने वाले महत्व को अध्याय 8 में दर्ज किया गया है।

अध्याय 9 से 12, में आर्थिक सर्वेक्षण के जीविकोपार्जन संबंधी विशेषताओं का वर्णन किया गया हैं। उसी क्रम में उद्योग, सेवा, बाह्य क्षेत्र और बुनियादी ढांचे का वर्णन है। भारतीय उद्योग, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सार्वजनिक निवेश तथा नीतियों के बदौलत सुगम विकास पुनरुद्धार के शिखर पर है, जिसने व्यावसायिक परिस्थितियों को आसान बनाया है और व्यवहार्यता में सुधार किया है। उद्योग के लिए बैंक ऋण ने, विशेष रूप से, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए गति पकड़ी है। अन्य बातों के अतिरिक्त, महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रति दक्षता से सुरक्षा और 'समय पर' से 'जरुरत पड़ने पर' के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है। आपूर्ति श्रृंखलाओं में फिर से सुधार किया जा रहा है। सरकार को यहां बेहतर संभावना नजर आती है और उत्पादन-लिंक्ड-प्रोत्साहन योजना में इसका निवेश और प्रतिबद्धता भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में जोड़ने के अपने दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। यह वैश्विक दृष्टि वाली औद्योगिक नीति है। अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का महत्वपूर्ण अंग बनने के लिए वास्तविक बोली लगाने के लिए अब भारत के पास भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचा है। विगत आठ वर्षों में, इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सरकार ने एक मंच तैयार किया है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि यह पूर्वानुमान उज्ज्वल है।

भारत का सेवा क्षेत्र शक्ति का एक स्रोत है और अधिक लाभ प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जीवंत विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को समायोजित करने और उनका पोषण करने के लिए भारत काफी सक्रिय है। इस क्षेत्र में निर्यात क्षमता के साथ-साथ निम्न से उच्च मूल्य वर्धित गतिविधियों तक, रोजगार और विदेशी मुद्रा तैयार करने और भारत की बाह्य स्थिरता में योगदान करने की पर्याप्त गुंजाइश है।

आयातित ईंधन पर निर्भरता के कारण बड़े व्यापारिक घाटे वाले देश के रूप में, विशेषकर बढ़ती तेल की कीमतों के दौरान, बाह्य क्षेत्र को हमेशा बारीकी से देखा जाता है। यह वित्त वर्ष ऐसा ही है। सरकार के विभिन्न अंगों ने यह सुनिश्चित किया कि अत्यधिक आपूर्ति अनिश्चितता और मूल्य अस्थिरता के एक वर्ष में, भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं किया गया। वैश्विक विकास को मंदी के कारण निर्यात वृद्धि धीमी हुई है, लेकिन अप्रैल-दिसंबर 2022 में मौजूदा डॉलर में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का संयुक्त मूल्य अप्रैल-दिसंबर 2021 की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक रहा है। भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमित रहा, और उनकी आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण में भारत को शामिल करने में निवेशकों की रुचि अब भी काफी अधिक है। आने वाले वर्षों में '*गति शक्ति*' और 'राष्ट्रीय रसद नीति' से भारत की लागत और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद है।

इससे हम सर्वेक्षण के बारहवें और अंतिम अध्याय में आते हैं। यह बुनियादी ढांचे की व्याख्या करता है। 'आखिरी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है' एक पिष्टोक्ति है, लेकिन इस मामले में, यह एक सच्ची पिष्टोक्ति है। हमने हाल के वर्षो की भारत की सबसे अच्छी सफलता की कहानियों में से एक को अंतिम अध्याय के लिए रखा है। वर्ष 2019 में, भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे के प्रति एक दूरदर्शी कार्यक्रम संबंधी दृष्टिकोण अपनाया है। देश में बुनियादी ढांचे के विकास के व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए वित्त वर्ष 2020-25 के लिए लगभग 111 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उदय हुआ। जबकि, पिछले आठ वर्षों में सड़क, रेलवे और जलमार्गों में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, बंदरगाहों और हवाई अड्डों का काफी उन्नयन किया गया है। अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार कहानी का केवल एक भाग है; आधुनिकीकरण एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका दृढ़ता से प्रयास किया गया और प्रशंसनीय गति के साथ हासिल किया गया है।

अंत में, भारत के सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास न केवल संख्या और '*मील के पत्थर*' की कहानी है, बल्कि विचारशील विनियामक एवं नवोन्मेषी वास्तुकला की बानगी भी है, जिसने निजी क्षेत्र को नवाचार और निवेश करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन के साथ अपने सार्वजनिक सच्चरित्र को बनाए रखने में सक्षम बनाया है। अप्रयुक्त क्षमता अत्यधिक वृहद है, और देश को नवाचार जारी रखने की आवश्यकता है। डिजिटल तकनीक और बुनियादी ढांचे के साथ, इसे अपनी जगह बनाए रखने के लिए कार्यशील रहना होगा।

द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में विकसित हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था में हाल ही में गलतियां हुई हैं, यदि इतिहास मार्गदर्शक होता तो ऐसा होना अनिवार्य था। नतीजतन, वैश्विक सहमति के मंच के रूप में परिकल्पित, बोर्ड में बहुपक्षीय मंच अस्तित्व बचाने संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा हैं और आज उसे अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए सहायता की आवश्यकता है। भारत, अपने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक उद्भव के साथ, घटनाओं के क्रम को प्रभावित कर सकता है और इस प्रक्रिया में प्रासंगिकता की वैश्विक शक्ति बनने की अपनी आकांक्षा को पूरा कर सकता है। यह विदित है कि भारत ने अपने अमृत काल के दौरान दिसंबर 2022 में जी-20 देशों की अध्यक्षता ग्रहण की है। वैश्विक समस्याओं के लिए वैश्विक समाधान की आवश्यकता है, और वैश्विक समाधान के

लिए सहभागिता और सहयोग की आवश्यकता है। ''वसुधैव कुटुंबकम'' के प्रसंग के आधार पर: 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य', भारत की वर्ष 2023 जी-20 की अध्यक्षता का उद्देश्य वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों का समन्वित समाधान करना है, जैसे कि 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करना, समय पर पर्याप्त जलवायु वित्त जुटाना, महामारी की तैयारी के लिए वित्तपोषण बढ़ाना, वैश्विक व्यापक आर्थिक कमजोरियों जैसे ऋण, वैश्विक खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा और शहरी अवसंरचना का वित्तपोषण करना। भारत के लिए अध्यक्षता करना वैश्विक समुदाय के समक्ष भारतीय विकास की कहानी दिखाने का एक मंच है, विशेष रूप से जिस तरह से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने एक समावेशी जन-केंद्रित विकास प्रतिमान का समर्थन किया है। संक्षेप में, भारत के लिए जी-20 की अध्यक्षता करना अन्यथा रूप से खंडित वैश्विक व्यवस्था को एकजूट करने का एक अवसर है।

आर्थिक सर्वेक्षण को सार्वजनिक विचार के लिए रखना एक अधिगम जनित अनुभव है। यह निश्चयात्मक सोच, विचारों के निर्माण और उनकी प्रभावी अभिव्यक्ति का एक प्रयोग है। अर्थव्यवस्था के तर्ज पर ही, यह सदैव प्रगतिशील कार्य है। हालांकि सर्वेक्षण एक वार्षिक दस्तावेज है। इस दस्तावेज को एक साथ रखने वाले अधिकारियों का समूह कभी भी समान नहीं होता है और यह प्रत्येक वर्ष प्रकाशन को समृद्ध करता है। जबकि पुराने विचार अपने साथ अनुभव और विशेषज्ञता लाते हैं और नए प्रवेशकर्ता, जैसे कि 'आपका विश्वासी', नए दृष्टिकोण लाते हैं। मैं इस वर्ष के सर्वेक्षण में अपनी अंतर्दृष्टि, विषय विशेषज्ञता और अनुभव लाने के लिए उनमें से प्रत्येक का आभारी हूं। मैं विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, विनियामकों और विषय विशेषज्ञों के अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने समय पर सूचना सामग्री प्रदान की और इस प्रकाशन को सफल बनाया। मैं मसौदा तैयार करने में संपादकीय टीम को उनके सत्यनिष्ठ प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं।

देश की सभी आर्थिक गतिविधियों को एक छतरी के नीचे रखने और इसे अर्थशास्त्रियों की भांति संशोधित करने से लेकर सामान्य नज़रिये से परिष्कृत करने, संबंधी कार्य एक अहम प्रयास हैं। यह एक संतोषजनक और सार्थक अनुभव रहा है, क्योंकि इसने देश और इसके लोगों के प्रति मेरी आशा और विश्वास को मजबूत किया है। मुझे उम्मीद है कि सर्वेक्षण के आंकड़ों और विश्लेषण से अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और चिकित्सकों को मदद मिलेगी।

विशेष रूप से, मुझे उम्मीद है कि यह पाठकों को इस महान राष्ट्र के भविष्य निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। यह भरोसा दिलाता है, कि अगर यह बेहतर नहीं, तो कम से कम हर प्रकार से अपने अतीत की तरह गौरवशाली होगा।

(वी. अनंत नागेश्वरन)
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मत्रांलय, भारत सरकार

आभारोक्ति

आर्थिक समीक्षा 2022-23 सामूहिक कार्य और पारस्परिक सहयोग का परिणाम है। यह आर्थिक समीक्षा माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा समय-समय की गई टिप्पणियों और उनकी अंतर्दृष्टि से अत्यंत लाभान्वित हुई है। यह समीक्षा माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, डॉ. भागवत किशनराव कराड और वित्त सचिव डॉ. टी. वी. सोमनाथन, सचिव डीईए श्री अजय सेठ राजस्व सचिव श्री संजय मल्होत्रा, डीएफएस सचिव श्री विवेक जोशी और दीपम सचिव श्री तुहिन कांता पांडे द्वारा की गई टिप्पणियों और उनके सहयोग के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करती है।

इस समीक्षा में आर्थिक प्रभाग और प्रधान आर्थिक सलाहकार के कार्यालय से जिन व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया है, उनमें: राजीव मिश्रा, सैकत सरकार, चांदनी रैना, अनुराधा गुरु, साजू के. सुरेंद्रन, शशिकुमार एस., श्वेता कुमार, टी. गोपीनाथ, वसंती वी. बाबू, स्वेता सत्या, धर्मेंद्र कुमार, एम. राहुल, हरीश कुमार कल्लेगा, गुरविंदर कौर, दीपिका श्रीवास्तव, अमित श्योराण, श्रेया बजाज, मनोज कुमार मिश्रा, मेघा अरोड़ा, दीक्षा सुपयाल बिष्ट, रीतिका बंसल, मोहम्मद आफताब आलम, प्रद्युत कुमार पायने, अभिनव बांका, शिवानी मोहन, सहर, मृत्युंजय कुमार, राजेश शर्मा, अमित कुमार केसरवानी, रोहित कुमार तिवारी, दीपद्युति सरकार, हेमा राणा, जेरिन थॉमस अब्राहम, सोनाली चौधरी, सुरभि सेठ, भारद्वाज आदिराजू, उन्नी नारायणन कुरुप, मीरा उन्नीकृष्णन, आकाश फजारी, सत्येंद्र किशोर, एस. रामकृष्णन, विशाल गोरी, रितेश कुमार, मीनाक्षी, मुना साह, मोहन सुना, गुलशन और अधिकारियों के निजी कर्मचारी शामिल हैं।

इस आर्थिक समीक्षा में जिन अधिकारियों की टिप्पणियों और इनपुट से विशेष लाभ मिला है उनमें जुबैर नकवी, विनोद कोतवाल, डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, रवि दाधीच, प्रशांत कुमार राय, प्रोसेनजीत सान्याल, विशाल गोयल, अपराजिता त्रिपाठी, अपराजिता जैन, अबू हुजैफा, शिवा सिंह, पीयूष मिश्रा, अनुराग भटनागर, एस.वी. सिंह, वंदना गौतम, सिद्धार्थ शंकर, ज्योत्सना गुप्ता, विशाल, ए.आर. राव, डॉ. अंसी मैथ्यू, डॉ. दिगंबर स्वैन, डॉ. प्रतिभा ए, दिगंबर सिंह, नवीन कुमार, जतिंदर सिंह, रमेश यादव, गुलजार नटराजन, देवी प्रसाद मिश्रा, गौरव मसलदान, डॉ. सी. वनलालरामसांगा, रेणु लता, सुदीप्त भट्टाचार्य, ऋषिका चोरारिया, श्याम सुंदर पारुई, सौरभ गर्ग, आलोक शुक्ला, समीर कुमार, प्रवीण महतो, नीलांभुज शरण, अंशुमान कामिला, आर. राजेश, मनीष शर्मा, राकेश रंजन, डॉ. बिजय कुमार बेहरा, इंद्राणी कौशल, धीरेंद्र गजभिए, दीपिका रावत, अशोक कुमार, यशवंत सिंह, सुभाष चंदर, ए. श्रीजा, स्मृति शरण, वी. धन्या, इप्सिता पाधी, सत्यार्थ सिंह, रचित सोलंकी, अविलेश शर्मा, रितेश पटेल, अजय कुमार सिंह, दिव्या शर्मा, उमेश चंद्र, धर्मेंद्र, सीएम डे कर्मकार, धरम प्रकाश, सी. मोहनदास, ओ.पी. ठाकुर, दीपक मेहरा, शैलेंद्र मिश्रा, आलोक चंद्र, संतोष कुमार सिन्हा, संजीत सिंह, तनुश्री चंद्रा, सुरजीत कार्तिकेयन, दीक्षा सचदेवा, कुमार सुंदरम, डॉ. सुरेंद्र कुमार ए हिरवार, जमीरुद्दीन अंसारी, देबप्रसाद रथ, प्रभात कुमार, सुप्रियो मंडल, एलेक्स फिलिप, अक्षरा अवस्थी, प्रतिभा केडिया, जंग बहादुर सिंह, आशीष कुमार मल्लिक, वेंकटेश्वरन रामकृष्णन, प्रभात रथ, अनंत नारायण जी, सुजीत प्रसाद, राकेश गोयल, आशीष अग्रवाल, तेजस्वी गुप्ता, मेधा शेवर, सुधाकर शुक्ला, संतोष शुक्ला, सुशिर शर्मा, एडमिरल आर हरि कुमार, सौगत भट्टाचार्य, आशीष त्रिपाठी, देबाशीष पांडा शामिल हैं।

उपर्युक्त के अलावा, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों ने भी अपने क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। हमें कई उद्योग निकायों, सार्वजनिक संस्थानों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं जैसे आरबीआई, सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, एनपीपीए, आईएसए, सीईए, नैसकॉम, आईबीबीआई, नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, ओ/ओ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एक्सिस बैंक, आईआरडीएआई से भी मदद मिली।

प्रशासनिक सहयोग मनीषा सिन्हा, मनोज सहाय, एंटनी सिरिएक, अपर्णा भाटिया, जसबीर सिंह, अरूप श्याम चौधरी, सुश्रुत सामंत, दलीप कुमार, सुनील कुमार गुप्ता, एस.के. अग्रवाल, दिनेश विश्वकर्मा, अवनीश अग्रवाल और डीईए के अन्य सदस्य द्वारा प्रदान किया गया। इस आर्थिक समीक्षा का हिंदी अनुवाद कार्य आनंद कुमार, पूरन सिंह तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के डॉ. सुरेश कुमार यादव, मनीष भटनागर, ओमप्रकाश सिंह, राजीव कुमार, अश्विनी कुमार, मनोज कुमार, रवि कुमार मीणा ने किया। समीक्षा के हिंदी संस्करण का टंकण कार्य भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड़, नई दिल्ली (मुद्रण निदेशालय) के शशिपाल सिंह रावत, अरुण कुमार, यतेन्द्र कुमार, संजय प्रसाद द्वारा किया गया। सर्वे का कवर पेज इज्जुर रहमान द्वारा डिजाइन किया गया। आर्थिक समीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों की पेज सेटिंग सिग्नेचर प्रिंटरर्स के इज्जुर रहमान, दीपक अग्रवार, गौतम हलदर, जफरुद्द और जगदीश ने की।

अंत में, इस आर्थिक समीक्षा से जुड़े समस्त कार्मिकों के परिजन भी हृदय की गहराइयों से आभार के पात्र हैं जिन्होंने इस कार्य के दौरान असीम धैर्य और उदारता का परिचय दिया।

वी. अनंत नागेश्वरन
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

संकेताक्षर

एए	खाता समूहक
एएआई	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
एएवाई	अंत्योदय अन्न योजना
एबी पीएम-जेएवाई	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
एबीडीएम	आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
एबीपी	आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम
एबी-पीएमजेएवाई	आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
एबीआरवाई	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एडीजीएम	अबू धाबी वैश्विक बाजार
एडीपी	आकांक्षी जिला कार्यक्रम
एडीएस	आकांक्षी जिले
एई	अग्रिम अनुमान
एईपीएस/एईपीएस	आधार युक्त भुगतान प्रणाली
एईएस	अग्रिम अर्थव्यवस्थायें
एएफसीएफटीए	अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र
एएफएसए	अल्बानियाई वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण
एजीईवाई	आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना
एएचएफ	किफायती आवास फंड
एएचआईडीएफ	पशफपालन अवसंरचना विकास निधि
एआई	आर्टिफीशियल इंटेलिजेंश
एआईडीसी	कृषि अवसंरचना और विकास उपकर
एआईएफ	कृषि अवसंरचना कोष
एआईएम	अटल इनोवेशन मिशन
एआईएसएचई	उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण
एकेएएम	आजादी का अमृत महोत्सव
एएमएफ	फ्रांस के ऑटोराइट डेस मार्च फाइनेंसर्स
एएनबी	आत्मनिर्भर भारत
एपीबी	आधार भुगतान फल
एपीईडीए	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एपीआई	एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
एपीवाई	अटल पेंशन योजना
एक्यूआर	आस्ति गुणवत्ता समीक्षा
एआरआर	औसत राजस्व दर
एएसईएएन	दक्षिण - पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ
एएसईईएम	आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण
एएसआई	उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण
एटीएमपी	विधानसभा, परीक्षण, अंकन और पैकेजिंग
एयूएम	प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों
बीसीडी	बुनियादी सीमा शुल्क
बीई	बजट अनुमान

बीईआई	व्यापार अपेक्षा सूचकांक
बीएफटी	बेयर फुट तकनीशियन
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय फनर्निर्माण बोर्ड
बीआईएस	अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए बैंक
बीएमआई	बॉडी मास इंडेक्स
बीओई	बैंक ऑफ इंग्लैंड
बीओपी	भुगतान संतुलन
बीओटी	बिल्ड – ऑपरेट – ट्रांसफर
बीपीकेपी	भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति
बीपीओ	व्यापार प्रक्रिया बाहरी स्रोत से सेवाएँ प्राप्त करना
बीपीएस	आधार अंक
बीआरएपी	व्यापार सुधार कार्य योजना
बीआरएसआर	व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट
बीएससीसीएल	बांग्लादेश पनडुब्बी केबल कंपनी लिमिटेड
बीएसई	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
सीए	सहयोग समझौता
सीएबी	चालू खाता शेष
सीएडी	चालू खाता घाटा
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
सीएजीआर	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
सीएएमपीए	क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण
सीएएनआई	चेन्नई से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक सबमरीन ओएफसी कनेक्टिविटी
सीएपीईएक्स	पूंजीगत व्यय
सीबीएंडटी	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
सीबीडी	जैविक विविधता पर कन्वेंशन
सीबीडीसी	सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा
सीबीडीआर–आरसी	सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएं
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
सीबीएन	सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया
सीबीओई	शिकागो बोर्ड विकल्प एक्सचेंज
सीसीबी	पूंजी संरक्षण बफर
सीसीईएस	फसल काटने के प्रयोग
सीसीपी	केंद्रीय काउंटर पार्टियां
सीडी	कॉर्पोरेट कर्जदार
सीडीपी	क्लस्टर विकास कार्यक्रम
सीडीआरआई	आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन
सीईए	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीईसीए	व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते
सीईपीए	व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता
सीएफपीआई	उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक
सीजीए	लेखा महानियंत्रक
सीजीसी	क्रेडिट गारंटी निगम

सीजीएसएस	स्टार्ट-अप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
सीजीएसटी	केंद्रीय माल और सेवा कर
सीएचसी	कस्टम हायरिंग सेंटर
सीएचई	वर्तमान स्वास्थ्य व्यय
सीएचआईपीएस और साइंस एक्ट, 2022	अर्धचालक और विज्ञान अधिनियम, 2022 के उत्पादन के लिए सहायक प्रोत्साहन बनाना
सीआईबीआईएल	क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड
सीआईसी	चलन में मुद्रा
सीआईडीआर	केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी
सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड
सीआईआरपी	कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया
सीआईआरपी	कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया
सीआईटीईएस	वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन
सीएलएपी	व्यापक रसद कार्य योजना
सीएलएसएस	क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना
सीएम	महत्वपूर्ण खनिज
सीएमआईई	भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्र
सीएमएसएस	केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी
सीओडी	वाणिज्यिक संचालन तिथि
सीओपी	पार्टियों का सम्मेलन
कोविड 19	कोरोनावाइरस रोग
कोविन	कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क
सीपीसीबी	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीआई-एएल	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि मजदूर
सीपीआई-सी	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त
सीपीआई-आईडब्ल्यू	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक
सीपीआई-आरएल	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण मजदूर
सीपीएसई	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
सीआरएआर	कैपिटल-टू-रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो
सीआरएआर	सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी
सीआरपीएस	सामुदायिक संसाधन व्यक्ति
सीआरआर	नकद आरक्षित अनुपात
सीआरएस	सामुदायिक रेडियो स्टेशनों
सीआरजेड	तटीय विनियमन क्षेत्र
सीएससीएस	सार्वजनिक सेवा केंद्रों
सीएसडी	केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी
सीएसआई	वर्तमान स्थिति सूचकांक
सीएसआईएस	ब्याज सब्सिडी पर केंद्रीय योजना
सीएसआर	कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी
सीएसएस	केंद्र प्रायोजित योजना
सीटीडीपी	व्यापक दूरसंचार विकास योजना
सीटीएस	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना
सीडब्ल्यूएस	वर्तमान साप्ताहिक स्थिति

सीडब्ल्यूएसएन	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
सीवाईकेसी	सेंट्रल नो योर कस्टमर
डीएवाई-एनआरएलएम	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डीएवाई-एनयूएलएम	दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
डीबीएफओटी	डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीबीयू	डिजिटल बैंकिंग इकाइयां
डीसीआईएल	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
डीडीई	डिजिटल दस्तावेज निष्पादन
डीडीयूजीजेवाई	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
डीडीयू-जीकेवाई	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना
डीईए	आर्थिक कार्य विभाग
डीएफसी	समर्पित मालभाड़ा गलियारा
डीएफआई	समर्पित वित्तीय संस्थान
डीएफआईएस	विकास वित्तीय संस्थान
डीएफएसए	दुबई वित्तीय सेवा प्राधिकरण
डीजीसीआईएंडएस	वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीजीआरसी	जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति
डीआईआई	घरेलू संस्थागत निवेश
डीआईएसईआर	उद्योग, विज्ञान, ऊर्जा और संसाधन विभाग
डीएलसी	डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
डीएलआई	डिजाइन से जुड़ा प्रोत्साहन
डीएलटी	वितरित खाता प्रौद्योगिकी
डीएनबी	राष्ट्रीय बोर्ड के राजनयिक
डीओसीए	उपभोक्ता मामलों का विभाग
डीओपी	डाक विभाग
डीपीसीओ	औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश
डीपीआई	डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर
डीपीआईआईटी	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
डीपीआर/डीपीआरएस	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीआरएएएस	ड्रोन-एज-ए-सर्विस
डीआरडीओ	रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
डीआरटी	ऋण वसूली न्यायाधिकरण
डीएससीएस	जिला कौशल समितियां
ई पीपीओ	इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश
ई-बीजी	इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी
ई-बीएल	लदान का इलेक्ट्रॉनिक बिल
ईबीआर	अतिरिक्त-बजटीय संसाधन
ईसीबी	यूरोपीय केंद्रीय बैंक
ईसीबीएस	बाहरी वाणिज्यिक उधार
ईसीआईबी	बैंकों को निर्यात ऋण बीमा
ईसीएल	इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर
ईसीएलजीएस	आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना

ईसीआरपी	आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज
ईसीटीए	आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता
ईसीटीएस	इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज
ईडीएलआई	कर्मचारी डीपोजिट लिंक्ड बीमा
ई–डीओ	इलेक्ट्रॉनिक वितरण आदेश
ईईडी	एंड–टू–एंड डिजिटाइज्ड
ईईई	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
ई–एफएमएस	इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम
ईकेवाईसी	इलेक्ट्रॉनिक अपने ग्राहक को जानें
ईएमडीईएस	उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ईएमईएस	उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं
ई–एनएएम	राष्ट्रीय कृषि बाजार
ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य - निधि संस्था
ईपीआई	निर्यात तैयारी सूचकांक
ई–पीओएस	बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु
ईपीआर	विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी
ई–पीआरएएन	इलेक्ट्रॉनिक–पेंशन सेवानिवृत्ति खाता संख्या
ईपीटीए	प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौता
ईआरएंडडी	इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास
ईआरएस	निर्वाचित प्रतिनिधि
ईएसजी	पर्यावरण, सामाजिक और शासन
ईएसआईसी	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
ईएसओपीएस	कर्मचारी स्टॉक विकल्प
ईटीएफ	विनिमय व्यापार फंड
ईयू	यूरोपीय संघ
ईवी	बिजली के वाहन
ईवीआईएन	इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क
ईवीएस	बिजली के वाहन
ईडब्ल्यूएस	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
ईएक्सआईएम	निर्यात आयात
एफएजी	फेसलेस असेसमेंट ग्रुप
एफएओ	खाद्य और कृषि संगठन
एफबीएस	विदेशी बैंक
एफसीसीबी	विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड
एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफडीआईसी	फेडरल डिपाजिट इंश्योरेंस कारपोरेशन
एफईडीएआई	फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
एफईआई	भविष्य की उम्मीदों का सूचकांक
एफईआर	विदेशी मुद्रा भंडार
एफएफसी	पंद्रहवां वित्त आयोग
एफएफएस	स्टार्ट–अप के लिए फंडों की निधि
एफआईसी	पूर्ण टीकाकरण कवरेज
एफआईडीएफ	अवसंरचना विकास निधि

एफआईएफपी	विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल
फिन टेक	वित्तीय प्रौद्योगिकी
एफआईपीबी	विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड
एफआईपीएस	वित्तीय सूचना प्रदाता
एफआईयूएस	वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता
एफएलएफपीआर	महिला श्रम बल भागीदारी दर
एफएमआई	वित्तीय बाजार अवसंरचना
एफएमएसए	वित्तीय बाजार पर्यवेक्षी प्राधिकरण
एफओएफ	फंडों की निधि
एफपीआई	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
एफपीओ	पब्लिक ऑफर पर फॉलो करें
एफपीओ	विदेशी डाकघर
एफपीओएस	किसान उत्पादक संगठन
एफपीएस	उचित मूल्य की दुकान
एफआरबीएम	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन
एफआरएल	राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफएसआई	भारतीय वन सर्वेक्षण
एफएसआरए	वित्तीय सेवा नियामक प्राधिकरण
एफटीए	विदेशी पर्यटकों का आगमन
एफटीएएस	मुक्त व्यापार समझौतों
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
एफटीटीएच	घर के लिए तंत्रिका
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीसी	आमान परिवर्तन
जीसीसी	वैश्विक योग्यता केंद्र
जीसीसी	खाड़ी सहयोग परिषद
जीसीईएस	सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण
जीसीएफ	हरित जलवायु कोष
जीसीटी	गतिशक्ति मल्टी–मॉडल कार्गो टर्मिनल
जीडीपी	सकल घरेलु उत्पाद
जीईएम	सरकारी ई–मार्केटप्लेस
जीईआर	सकल नामांकन अनुपात
जीएफसीएफ	कुल निश्चित पूंजी निर्माण
जीएफडी	सकल राजकोषीय घाटा
जीएचई	सरकारी स्वास्थ्य व्यय
जीएचजी	ग्रीनहाउस गैस
जीआईएफटी	गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक–सिटी
जीआईआई	ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स
जीआईएम	हरित भारत मिशन
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीएमवी	सकल पण्य वस्तु मूल्य
जीएनआई	सकल राष्ट्रीय आय
जीएनपीएएस	सकल गैर–निष्पादित आस्तियां

जीओआई	भारत सरकार
जीपीएस	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जी–एसईसी	सरकारी प्रतिभूतियां
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीएसटीएन	माल और सेवा कर नेटवर्क
जीटीआर	सकल कर राजस्व
जीवीए	सकल मूल्य जोड़ा गया
जीडब्ल्यू	गीगा वाट
जीडब्ल्यूएच	गीगा वाट घंटे
एचएएम	हाइब्रिड एनुइटी मॉडल
एचडीआई	मानव विकास सूची
एचईआई	उच्च शिक्षा संस्थान
एचएफसी	आवास वित्त क्षेत्र
एचएफसी	आवास वित्त कंपनियां
एचएफआई	उच्च आवृत्ति संकेतक
एचपीसीएल	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एचपीआई	आवास मूल्य सूचकांक
एचपीओ	जलविद्युत खरीद दायित्व
एचएससीसी	अस्पताल सेवा परामर्श निगम
एचयूएफ	हिंदू अविभाजित परिवार
एचडब्ल्यूसीएस	स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र
आईएआईएस	बीमा पर्यवेक्षकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ
आईबीबीआई	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
आईबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता
आईबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता
आईबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईसीईजीएटीई	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे
आईसीएफआरई	भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद
आईसीएमए	अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईसीटी	अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल
आईडी	पहचान दस्तावेज
आईएफपीआरआई	अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान
आईएफएससी	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
आईएफएससीए	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
आईजीसीआरएस	शुल्क की रियायती दर पर या निर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात
आईजीएनडीपीएस	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
आईजीएनओएपीएस	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
आईजीएनडब्ल्यूपीएस	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
आईजीएसटी	एकीकृत माल और सेवा कर
आईआईएफटी	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

आईआईजी	इन्वेस्ट इंडिया ग्रिड
आईआईएम	भारतीय प्रबंधन संस्थान
आईआईएमए	भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद
आईआईपी	अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति
आईआईपी	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक
आईआईपीडीएफ	भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि योजना
आईआईएसईआर	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईएलएंडएफएस	इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज
आईएलडीएस	ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण
आईएलएमडीएस	नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण
आईएमबी	अंतर–मंत्रालयी बोर्ड
आईएमएफ	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएमपीएस	तत्काल भुगतान सेवा
आईएमआर	शिशु मृत्यु दर
आईएनवीआईटी	इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
आईओएससीओ	प्रतिभूति आयोगों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन
आईओटी	थींग्स की इंटरनेट
आईपी	इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी
आईपीसीसी	जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर – सरकारी पैनल
आईपीओ	प्रथम जन प्रस्ताव
आईपीआर	इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी अधिकार
आईआर	भारतीय रेल
आईआरडीएआई	भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण
आईएसए	अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
आईएसएफआर	भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट
आईएसएस	ब्याज अनुदान योजना
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटी–बीपीएम	सूचना प्रौद्योगिकी–व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन
आईटीसी	इनपुट टैक्स क्रेडिट
आईटीआईएस	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आईटीआर	आयकर रिटर्न
आईडब्ल्यूएआई	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
आईवाईएम	बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष
जेएंडके	जम्मू और कश्मीर
जेएएम	जनधन–आधार–मोबाइल
जेसी	जॉब कार्ड
जेजेएम	जल जीवन मिशन
जेपीसी	संयुक्त संयंत्र समिति
जेआरएस	नौकरी प्रतिधारण योजना
जेएसएस	जन शिक्षण संस्थान
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
केएलआई	कोच्चि से लक्षद्वीप द्वीप समूह तक सबमरीन ओएफसी कनेक्टिविटी
केएमएस	खरीफ विपणन सीजन

केपीआई	मुख्य निष्पादन संकेतक
केआरसीएल	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानो
एलएएफ	लिक्वीडीटी एडजस्टमेंट ेसिलिटी
एलसी	लेटर ऑफ क्रेडिट
एलसीओएच	हाइड्रोजन की स्तरित लागत
एलडीसीएस	कम से कम विकसित देश
एलईएडीआईटी	उद्योग संक्रमण के लिए नेतृत्व समूह
एलईएडीएस	विभिन्न राज्यों में रसद आसान
एलएफपीआर	श्रम बल भागीदारी दर
एलजीएससीएटीएसएस	कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना
एलएचएंडडीसी	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण
एलआईसी	जीवन बीमा निगम
एलएलपी	सीमित दायित्व भागीदारी
एलएमटी	लाख मीट्रिक टन
एलपीजी	तरल पेट्रोलियम गैस
एलपीआई	रसद प्रदर्शन सूचकांक
एलएसए	लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र
एलएसबीएस	लॉन्ग स्पैन ब्रिज
एलएसडीजीएस	सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण
एलटी-एलईडीएस	दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति
एलडब्ल्यूई	वामपंथी उग्रवाद
एमएंडए	विलय और अधिग्रहण
एमएएचएसआर	मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल
एमएएस	सिंगाफर का मौद्रिक प्राधिकरण
एमबीबीएस	बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी
एमसीएएस	मॉडल रियायत समझौते
एमसीएलआर	निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत
एमडीबी	बहुपक्षीय विकास बैंक
एमईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्थान
एमएफएन	मोस्ट फेवर्ड नेशन
एमजीएनआरईजीएस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमआई	मिशन इंद्रधनुष
एमआईसीए	क्रिप्टो संपत्ति में बाजार
एमआईसीई	बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनियां
एमआईडीएच	बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमआईएसएस	संशोधित ब्याज अनुदान योजना
एमएम	पैसा गुणक
एमएमएफ	मानव निर्मित फाइबर
एमएमआर	मातृ मृत्यु अनुपात
एमएमटी	लाख मीट्रिक टन

एमओएचएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
एमओएलई	श्रम और रोजगार मंत्रालय
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओवीसीडीएनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
एमपीसी	मौद्रिक नीति समिति
एमपीआई	बहुआयामी गरीबी सूचकांक
एमएसडीई	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
एमएसएफ	सीमांत स्थायी सुविधा
एमएसएच	मेटी स्टार्ट-अप हब
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमईडी एक्ट	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमटी	मीट्रिक टन
एमटीओई	तेल समतुल्य मिलियन टन में
एमटीपीए	मिलियन टन प्रति वर्ष
एमयूडीआरए	सूक्ष्म इकाइयों के उद्यमों के विकास और फनर्वित एजेंसी
एमवीटी	चिकित्सा मूल्य पर्यटन
एमडब्ल्यू	मेगा वाट
एनएबीएआरडी	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएबीएफआईडी	बुनियादी ढांचे और विकास के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक
एनएडीसीपी	राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
एनएएफसीसी	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष
एनएआईएस	सूचना सोसायटी के लिए राष्ट्रीय एजेंसी
एनएपी	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम
एनएपीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना
एनएपीएस	राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना
एनएएसडीएक्यू	नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन
एनएएसएससीओएम	सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों के राष्ट्रीय संघ
एनबीसी	शुद्ध उधारी सीमा
एनबीएफसी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एनसीएईआर	अनुप्रयुक्त और आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद
एनसीएफ	राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
एनसीजीटीसी	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी
एनसीक्यूजी	नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य
एनसीआरएफ	राष्ट्रीय ऋण ढांचा
एनसीएस	राष्ट्रीय कैरियर सेवा
एनसीएस	गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियां
एनडीसी	राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान
एनईईपीसीओ	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एनईईआर	नाममात्र प्रभावी विनिमय दर
एनई-एफएमएस	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष प्रबंधन प्रणाली
एनईएफटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर
एनईपी	राष्ट्रीय शिक्षा नीति

एनईएसएल	नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड
एनएफएपी	राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना
एनएफएचएस	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनएफएसए	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एनएफएसएम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनएचए	राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता
एनएचएआई	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एनएचईक्यूएफ	राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा
एनएचएम	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
एनएचपी	राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति
एनएचएस	राष्ट्रीय राजमार्ग
एनआईडीएचआई	आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस
एनआईडीएचआई	नवाचारों के विकास और दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल
एनआईआई	कुल ब्याज आय
एनआईएनएल	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड
एनआईपी	राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनआईटीआई	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
एनएल	नई पंक्तियाँ
एनएलईएम	आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची
एनएलएम	राष्ट्रीय पशुधन मिशन
एनएलपी	राष्ट्रीय रसद नीति
एनएलपी-मेरीन	राष्ट्रीय रसद पोर्टल-समुद्री
एनएमसी	राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
एनएमएमएस	राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर
एनएमपी	राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन
एनएमआर	नवजात मृत्यु दर
एनएनपीए	नेट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण पत्र
नॉन-एसईडी	गैर-संप्रभु बाह्य ऋण
एनपीए	गैर-निष्पादित संपत्ति
एनपीसीसी	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीसीआईएल	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इंटरनेशनल
एनपीआईएसएचएस	घरेलू और गैर-लाभकारी
एनपीपीए	राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
एनपीपीपी	राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स मूल्य निर्धारण नीति
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन योजना
एनआरसीपी	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना
एनआरआई	विदेश वाले प्रवासी भारत
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनएसएपी	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

एनएसई	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
एनएसओ	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
एनएसपी	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल
एनएसक्यूएफ	राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा
एनएसएस	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
एनएसएस-ईयूएस	एनएसएस रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण
एनएसडब्ल्यूएस	राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली
एनटीबीएस	गैर टैरिफ बाधाएं
एनटीसीए	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
एनडब्ल्यूएस	राष्ट्रीय जलमार्ग
ओसीबी	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय
ओसीसी	मुद्रा नियंत्रक का कार्यालय
ओसीईएन	क्रेडिट सक्षमता नेटवर्क खोलें
ओसी-एमआईएस	ऑक्सीकेयर प्रबंधन सूचना प्रणाली
ओडीएफ	खुले में शौच मुक्त
ओडीएल	मुक्त और दूरस्थ शिक्षा
ओडीओपी	एक जिला एक उत्पाद
ओडी-ओपी	एक जिला-एक उत्पाद
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओईएम	मूल उपकरण निर्माता
ओएनडीसी	डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क
ओएनजीसी	तेल और प्राकृतिक गैस निगम
ओएनओआरसी	वन नेशन वन राशन कार्ड
ओओपीई	आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय
ओपीईसी	पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन
ओपेएक्स	परिचालन व्यय
ओएसएटी	आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट
पीए	अनंतिम वास्तविक
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि साख समितियां
पीएटी	कर के बाद लाभ
पीएटी	प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार
पीबीई	निर्यात का डाक बिल
पीसीए	शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई
पीसीआर	प्रावधान कवरेज अनुपात
पीसीएस	पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम
पीडीसीएस	परियोजना विकास प्रकोष्ठ
पीडीएमसी	लोक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीई	निजी इक्विटी
पीई	अनंतिम अनुमान
पीएफसी	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
पीएफसीई	निजी अंतिम उपभोग व्यय
पीएफआरडीए	पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण
पीएफआरडीए	पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण

पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पीआईबी	प्रेस सूचना ब्यूरो
पीआईबीओएस	निर्माता, आयातक और ब्रांड स्वामी
पीकेवीवाई	परम्परागत कृषि विकास योजना
पीएलएफएस	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
पीएलआई	प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव
पीएलआईएसएफपीआई	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
पीएम केयर्स	प्रधान मंत्री की नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत
पीएम मित्र	प्रधान मंत्री मेगा एकीकृत कपड़ा क्षेत्र और परिधान
पीएम श्री	राइजिंग इंडिया के लिए प्रधान मंत्री स्कूल
पीएम एसवीए निधि	प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना
पीएमएवाई-जी	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
पीएमएवाई-यू	प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी
पीएमबीजेकेएस	प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र
पीएमबीजेपी	प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना
पीएमईएसी	प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद
पीएमएफबीवाई	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
पीएमएफएमई	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का प्रधान मंत्री का औपचारिककरण
पीएमजी	परियोजना निगरानी समूह
पीएमजीकेएवाई	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
पीएमजीकेवाई	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
पीएमजीएसवाई	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पीएमआई	क्रय प्रबंधकों की सूची
पीएमजेबीवाई	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पीएमजेडीवाई	प्रधानमंत्री जन धन योजना
पीएमजेजेबीवाई	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पीएम-किसान	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
पीएमकेके	प्रधानमंत्री कौशल केंद्र
पीएमकेएसवाई	प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
पीएम-कुसुम	प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान
पीएमकेवीवाई	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
पीएमएमएसवाई	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
पीएमएमवीवाई	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
पीएमपी	चरणबद्ध विनिर्माण योजना
पीएम-सौभाग्य	प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना
पीएमएसबीवाई	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पीएमएसएसवाई	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
पीएम-एसवाईएम	प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन
पीएमयूवाई	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
पीएमवीवीवाई	प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
पीओएल	पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक
पोषण	समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक योजना
पीपीएसी	पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल
पीपीपी	सरकारी निजी कंपनी भागीदारी

पीपीपी	क्रय शक्ति समता
पीपीपीएसी	सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति
प्रशस्त	प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल
पीआरआईएस	पंचायती राज संस्थाएं
पीएसए	प्रेशर स्वींग एडसोरप्सन
पीएसबीएस	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पीएसई	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
पीएसएल	प्राथमिकता क्षेत्र उधार
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पीवी	फोटोवोल्टिक
पीवीबीएस	निजी क्षेत्र के बैंक
पीडब्ल्यूपीएस	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर
क्यूई	क्वार्टर एंडिंग
क्यूईएस	त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण
क्यूएफएसए	कतर वित्तीय सेवा प्राधिकरण
क्यूआईपी	योग्य संस्थागत प्लेसमेंट
आरएंडडी	अनुसंधान और विकास
रफ्तार	कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण
आरएएमपी योजना	एमएसएमई प्रदर्शन योजना को बढ़ाना और उसमें तेजी लाना
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरसीबी	अनुपालन बोझ को कम करना
आरसीईपी	क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता
आरसीएस	क्षेत्रीय संपर्क योजना
आरडीसी	अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ
आरई	संशोधित अनुमान
आरईसी	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
आरईई	दुर्लभ पृथ्वी तत्व
आरईईआर	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर
आरईआईटी	रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट
आरईआईटीएस	रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट
आरईआरए	रियल एस्टेट विनियमन अधिनियम
आरईआरए	रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम
आरईवीपीएआर	राजस्व प्रति उपलब्ध कमरा
आरएफआईडी	रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस
आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरएफक्यू	योग्यता के लिए अनुरोध
आरजीएसए	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
आरएचएस	दाहिने हाथ की ओर
आरआईसी	सड़क और अवसंरचना उपकर
आरकेएम	रूट किलोमीटर
आरकेवीवाई	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
आरएमएनसीएएच+एन	प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य प्लस पोषण
आरएमएस	रबी विपणन मौसम
आरएनएफसी	रूट नेविगेशन सुविधा शुल्क

आरओए	संपत्ति पर वापसी
आरओडीटीईपी	निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट
आरओई	लाभांश
आरओएससीटीएल	राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों की छूट
आरओटी	फनर्वास-संचालन-स्थानांतरण
आरओडब्ल्यू	मार्ग – अधिकार
आरपीएल	पहले की सीख की मान्यता
आरपीओ	नवीकरणीय खरीद दायित्व
आरएसईटीआई	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
आरटीएएस	क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था
आरटीई	शिक्षा का अधिकार
आरटीजीएस	रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट
आरडब्ल्यूएएस	जोखिमपूर्ण संपत्ति
एसएंडपी	मानक और गरीब
साथी	आतिथ्य उद्योग के लिए मूल्यांकन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली
समर्थ	स्मार्ट एडवांस्ड मैन्यफैक्चरिंग और रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब
एसएआरएफएईएसआई	वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और फनर्निर्माण और प्रतिभूतियों के हित का प्रवर्तन
एसबीआई	भारतीय स्टेट बैंक
एसबीआई	कार्यान्वयन के लिए सहायक निकाय
एसबीएम(जी)	स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण
एसबीएसटीए	वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह के लिए सहायक निकाय
एससीबीएस	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एससीसीएल	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड
एससीएस	उप केंद्र
एसडीएफ	स्थायी जमा सुविधा
एसडीजीएस	सतत विकास लक्ष्यों
एसडीएलएस	राज्य विकास ऋण
एसडीआरएस	विशेष रेखा – चित्र अधिकार
एसईबीआई	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसईसीसी	सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना
एसईडी	संप्रभु बाहरी ऋण
एसजीआरबीएस	सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स
एसजीआरसी	राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति
एसजीएसटी	राज्य माल और सेवा कर
एसएचसीएस	उप स्वास्थ्य केंद्र
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसएचजी-बीएलपी	एसएचजी बैंक लिंकेज परियोजना
एसएचजीएस	स्वयं सहायता समूह
एसआईएएम	सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यफैक्चरर्स
एसआईडीएस	छोटे द्वीप विकासशील राज्य
एसआईपी-ईआईटी	ईएंडआईटी में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण के लिए समर्थन
एसएमएएफ	कृषि-वानिकी पर उप-मिशन
एसएमएएम	कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन
एसएमईएस	छोटे और मध्यम उद्यम

एसओपी	मानक संचालन प्रक्रियाएं
एसपीईसीएस	इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना
एसपीआई	फार्मास्युटिकल उद्योग को मजबूत बनाना
एसपीएसई	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
एसआरएफ	विशेष फनर्वित्त सुविधा
एसआरएस	नमूना पंजीकरण प्रणाली
एसएसबीएस	मानक-सेटिंग निकाय
एसएसएस	प्रतिभूति निपटान प्रणाली
एसटी	अनुसूचित जनजाति
एसटीएआरएस	राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणामों का सुदृढ़ीकरण
एसटीटी	लघु अवधि प्रशिक्षण
स्वामित्व	ग्राम क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण
एसवीईपी	स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम
एसडब्ल्यूआईएफटी	व्यापार के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस
टीएटी	बदलाव का समय
टी-बिल्स	राजकोष चालान
टीडीजीवीए	टूरिज्म डायरेक्ट ग्रॉस वैल्यू एडेड
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
टीईडीएस	तकनीकी विशेषज्ञ संवाद
टीएचडीसी	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
टीएचई	कुल स्वास्थ्य व्यय
टीआईडीई	प्रौद्योगिकी ऊष्मायन और उद्यमियों का विकास
टीकेएम	ट्रैक किलोमीटर
टीएनएलसी	टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क
टीओटी	टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर
टीआर	व्यापार भंडार
ट्राई	भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
टीआरईडीएस	ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम
टीआरआईएफईडी	ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
टीटीएस	यात्रा और पर्यटन हितधारक
यू5एमआर	पांच से कम मृत्यु दर
यूएई	संयुक्त अरब अमीरात
उडान	उड़े देश का आम नागरिक
यूडीआईएसई	शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूआईपी	सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम
यूके	यूनाइटेड किंगडम
उमंग	नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन
यूएनसीटीएडी	व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनएफसीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन
यूनिसेफ	संयुक्त राष्ट्र अंतराष्ट्रीय बाल आपातकालीन फंड
यूएनडब्ल्यूटीओ	संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन

यूपीआई	एकीकृत भुगतान इंटरफेस
यूआर	बेरोजगारी दर
यूएस एफईडी	यूएस फेडरल रिजर्व
यूएसए	संयुक्त राज्य अमेरिका
यूएसओएफ	यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड
यूटीएस	संघ राज्य क्षेत्र
वीए	वर्चुअल एसेट
वीएएसपी	वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर
वीएटी	मूल्य वर्धित कर
वीसी	उद्यम पूंजी
वीडीए	वर्चुअल डिजिटल एसेट्स
वीजीएफ	वायबिलिटी गैप फंडिंग
वीआईपी	वेंटिलेटेड इम्प्रूव्ड पिट
वीआईएक्स	अस्थिरता सूचकांक
वीओएस	ग्राम संगठन
वीआरआर	परिवर्तनीय रेपो दर
डब्ल्यूएसीआर	भारित औसत कॉल दर
डब्ल्यूएडीटीडीआर	भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर
डब्ल्यूएएलआर	भारित औसत उधार दर
डब्ल्यूईओ	विश्व आर्थिक आउटलुक
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यूपीआर	श्रमिक जनसंख्या अनुपात
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन
वाईओवाई	वर्ष दर वर्ष
जेडबीएनएफ	शून्य बजट प्राकृतिक खेती

तालिकाओं की सूची

तालिका सं.	तालिका	पृष्ठ सं.
I.1	वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के कारण सभी देशों में विकास के पूर्वानुमान में गिरावट आई है	7
I.2	भारत को छोड़कर अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का मूल ऋण 2008 की तुलना में अधिक है	8
II.1	वर्ष 2000 और 2002 के बीच भारत में सूखे की घटना, प्रभावित लोगों की संख्या और नुकसान	27
II.2	कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपराधों के डिक्रिमिनलाइजेशन (वैधीकरण) का स्नैपशॉट	32
II.3	अवधियों के बीच समानांतर 1998-2002 और 2014-2022	38
III.1	अप्रैल से नवंबर 2022 तक केंद्र सरकार के राजकोषीय संकेतकों का स्थिर प्रदर्शन	44
III.2	अप्रैल से नवंबर 2022 तक केंद्र सरकार के कर में वृद्धि	45
III.3	केन्द्र सरकार के गैर-कर राजस्व की प्रवृति	49
III.4	केंद्र का अवसंरचना से जुड़े क्षेत्रों पर आधारित पूंजीगत व्यय	51
III.5	केंद्र सरकार द्वारा किए गए राजस्व व्यय की प्रमुख मदें	52
III.6	केंद्र से राज्यों को किए गए हस्तांतरण का विवरण (राज्यों के लिए अंतरण के अलावा)	56
III.7	15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकारों को अनुदान का आवंटन	56
III.8	वित्तीय वर्ष 2023 में पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों के लिए विशेष सहायता योजना का ब्यौरा	60
III.9	केंद्र सरकार की ऋण स्थिति (लाख करोड़ रु. में)	62
IV.1	मौद्रिक योग में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)	81
IV.2	सभी बैंक समूहों में ऋण और जमा दरों में अंतरण	84
IV.3	जी-सेक में कुल एकमुश्त व्यापार गतिविधि का श्रेणी-वार हिस्सा (प्रतिशत)*	85
IV.4	30 सितंबर के अनुसार संकटग्रस्त आस्तियों का बचाव (राशि करोड़ रुपये में)	93
IV.5	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विभिन्न माध्यमों से वसूल की गई राशि (राशि करोड़ में)	94
IV.6	प्राथमिक बाजार से संसाधन जुटाना	95
IV.7	वित्त वर्ष 2023 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान भारत ने अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन किया	96
IV.8	इक्विटी कैश सेगमेंट टर्नओवर में व्यक्तिगत निवेशकों की हिस्सेदारी में गिरावट आई	99
IV.9	वित्त वर्ष 2022 में डीमैट खातों में तेज वृद्धि देखी गई	99
IV.10	इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी डेरिवेटिव्स में टर्नओवर सांख्यिकी में वृद्धि हुई	99
IV.11	म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम में वृद्धि	100
IV.12	इक्विटी-उन्मुख योजनाओं में शुद्ध प्रवाह देखा गया	100
IV.13	एफपीआई के तहत संरक्षित संपत्तियां में वद्धि	101
IV.14	एफपीआई में दर्ज बहिर्वाह के अनुसार शुद्ध निवेश	101
IV.15	चयनित बाजारों में कुल पोर्टफोलियो प्रवाह का रुझान (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	102
IV.16	सरकारी बीमा योजनाएं और प्रगति	112
IV.17	भारत के पेंशन क्षेत्र का प्रदर्शन	115
V.1	सीपीआई-सी के आधार पर औसतन वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति (प्रतिशत) (आधार 2012=100)	120
V.2	डब्ल्यूपीआई (प्रतिशत) के आधार पर औसतन वार्षिक थोक मुद्रास्फीति (आधार 2011-12=100)	130
V.3	मौद्रिक नीति संबंधी विवरण- सख्त मौद्रिक नीति	138
VI.1	सामान्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्र के व्यय में रुझान (संयुक्त केंद्र और राज्य)	148
VI.2	वैश्विक एचडीआई 2021 में भारत की स्थिति एवं रुझान	149
VI.3	चार श्रम संहिताओं के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा नियमों की स्थिति	154
VI.4	सामान्य स्थिति में रोजगार के रुझान	158

VI.5	वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में रोजगार के रुझान	159
VI.6	क्यूईएस के अनुसार क्षेत्रवार श्रमिकों की अनुमानित संख्या	166
VI.7	रोजगार की शर्तों के अनुसार श्रमिकों का क्षेत्रवार वितरण (त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार)।	167
VI.8	सभी आयु समूहों में मुख्य उद्योगों के लिए ईपीएफओ पेरोल डेटा	170
VI.9	स्कूल सकल नामांकन अनुपात	175
VI.10	स्कूल ड्रापआउट रेट	176
VI.11	मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या में रुझान	176
VI.12	स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार	177
VI.13	उच्च शिक्षा में छात्रों का नामांकन	180
VI.14	उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की संख्या	181
VI.15	औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का वितरण	182
VI.16	औपचारिक कौशल विकास प्रशिक्षण और ऑन जॉब प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अनुमानित प्रतिष्ठानों का क्षेत्रवार प्रतिशत	183
VI.17	स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों में सुधार	186
VI.18	मृत्यु दर संकेतकों में रुझान	187
VI.19	स्वास्थ्य ढांचे में प्रगति	191
VI.20	ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्ष	202
VI.21	डीएवाई-एनआरएलएम के तहत प्रगति	204
VI.22	मनरेगा के तहत प्रगति	205
IX.1	औद्योगिक घटकों का विकास एंव भागीदारी (प्रतिशत में)	261
IX.2	विनिर्माण क्षेत्रों में वृद्धि (प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)	268
IX.3	उद्योग उपखंडों में नियोजित ऋण में वृद्धि (प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)	270
XI.1	भारत के व्यापार के प्रमुख पहलू (कैलेंडर वर्षवार)	315
XI.2	सेवा व्यापार का लचीला प्रदर्शन	319
XI.3	विदेशी ऋण बकाया	337
XI.4	भारत के प्रमुख विदेशी ऋण संकेतक स्थिरता का चित्र	338
XII.1	रेलवे पर अवसंरचना पूंजीगत व्यय में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है	354
XII.3	अखिल भारतीय स्थापित क्षमता मोड-वार (जीडब्ल्यू)	359
XII.4	अखिल भारतीय सकल विद्युत उत्पादन मोड-वार	359

चित्रों की सूची

चित्रों सं.	चित्रों	पृष्ठ सं.
I.1	रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण जिंसों की कीमतों में तीव्र वृद्धि; कीमतें अभी भी संघर्ष - पूर्व स्तर तक नहीं पहुंची हैं	4
I.2क	विकसित अर्थव्यवस्थायें	4
I.2ख	उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं	4
I.3क	विकसित अर्थव्यवस्थायें	5
I.3ख	उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं	5
I.4क	एई में 10 वर्षीय बॉन्ड	6
I.4ख	ईएमई में 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड	6
I.5	फेडरल फंड्स रेट जनवरी 2022 से संचयी 425 आधार अंकों से बढ़ाया गया है, जिससे ईएमई और एई से पूंजी निकल गयी है।	6
I.6	अगस्त 2022 से वैश्विक समग्र पीएमआई संकुचन क्षेत्र में	7
I.7	खुदरा बिक्री, औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि गिर रही है	7
I.8क	चीन के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) घट रही है	8
I.8ख	चीन की खुदरा बिक्री वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) कम हो रही है	8
I.9	आर्थिक विकास लचीला बना हुआ है	9
I.10क	वास्तविक जीवीए में वर्ष दर वर्ष संवृद्धि	10
I.10ख	वास्तविक जीडीपी घटकों के हिस्से	10
I.11	सीपीआई मुद्रास्फीति आरबीआई की लक्ष्य सीमा में वापस आ गई	10
I.12	भारतीय रुपये ने अन्य ईएमई की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया	10
I.13	बढ़ा हुआ चालू लेख घाटा	11
I.14	सीएडी के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार	11
I.15	व्यापार धीमा होने के कारण शिपिंग माल ढुलाई लागत में कमी	12
I.16	वैश्विक मंदी के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात का हिस्सा बढ़ता है	12
I.17	वित्त वर्ष 23 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत के विकास अनुमान	12
I.18	बढ़ी हुई क्षमता उपयोग और व्यावसायिक भाव	13
I.19क	वित्त वर्ष 15 के बाद वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में निजी खपत सबसे अधिक पर	14
I.19ख	उपभोक्ता विश्वास में सुधार	14
I.20	आवास के लिए बैंक ऋण में वृद्धि गिरते हाउसहोल्ड को संपुरित कर रहा है	14
I.21	वित्त वर्ष 12 और वित्त वर्ष 23 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय औसतन 13 की दर से बढ़ा	15
I.22	कैपेक्स पिछले पांच वर्षों में दोगुना हो गया	16
I.23	निजी निवेश आशा के अनुरूप बना हुआ है	16
I.24	कर संग्रह में उछाल (अप्रैल-नवंबर)	16
I.25	राजस्व व्यय में सीमित वृद्धि	16
I.26	एमएसएमई के बैंक ऋण में दोहरे अंकों में वृद्धि	17
I.27	एससीबी के जीएनपीए अनुपात में गिरावट	18
I.28	प्रावधान (प्रोविजनिंग) कवरेज अनुपात	18
I.29	बढ़ता कॉरपोरेट बॉन्ड प्रतिफल	18
I.30	कॉरपोरेट बॉन्ड के निजी नियोजन में कमी	18
I.31	उच्च ब्याज/हेजिंग लागत में ईसीबी और एफसीसीबी को निधियों का कम आकर्षक स्रोत बना दिया	18
I.32	मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं की स्थिरता	19
I.33	शहरी बेरोजगारी पांच वर्षों के निम्नतम स्तर पर	20

चित्रों सं.	चित्रों	पृष्ठ सं.
I.34	वित्त वर्ष 2022 में एमएसएमपी द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी में महामारी- पूर्व के स्तर को पार किया	20
I.35	ईसीएलजीएस में एमएसएमई को अपनी सम्पत्ति की गुणवत्ता को सुधारने में सहायता की	20
I.36	ग्रामीण कल्याण सूचकांको में सुधार	21
I.37	वैश्विक आर्थिक वृद्धि और व्यापार में मंदी	22
II.1	वर्ष 2000-2003 में निवेश के उदारीकरण को बढ़ावा देने के बाद भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि	26
II.2	सकल राजकोषीय घाटा (केंद्र और राज्यों को मिलाकर) (जीडीपी का)	26
II.3	कुल संपत्ति के के रूप में एससीबी का सकल एनपीए	26
II.4	एससीबी द्वारा गैर-खाद्य ऋण में वृद्धि	27
II.5	अमेरिका द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद मासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी आई (1998)	27
II.6	डॉट-कॉम बबल संकट के कारण कई देशों में मंदी आई, जिससे वैश्विक अनिश्चितता बढ़ गई	28
II.7	केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बढ़ रहा है	29
II.8	महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षमता में विकास (पहले उपलब्ध	30
II.9	औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह में वृद्धि	33
II.10	2014-15 के दौरान सकल एफडीआई/जीडीपी में संरचनात्मक बदलाव	35
II.11	अधिकांश 2010 के लिए जीडीपी गैप के लिए त्रैमासिक क्रेडिट नकारात्मक रहा	37
III.1	पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार के घाटे की प्रवृत्ति- राजकोषीय समेकन के मार्ग पर	43
III.2	सरकार वित्तीय वर्ष 2023 में लक्षित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के ट्रैक पर	43
III.3	केंद्र सरकार के टैक्स प्रोफाइल की संरचना (वित्तीय वर्ष 2023 ब.अ.)	46
III.4	अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान केंद्र के प्रत्यक्ष करों में वृद्धि उनके दीर्घावधि औसत से अधिक है	46
III.5	अप्रैल से दिसंबर तक संचयी सकल जीएसटी संग्रह में वर्ष-दर-वर्ष उच्च वृद्धि	47
III.6	पिछले कई वर्षो से मासिक सकल जीएसटी संग्रह में निरंतर वृद्धि	47
III.7	केंद्र सरकार के कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का बढ़ता हुआ अंश	50
III.8	केंद्र सरकार का जीडीपी अनुपात में कैपेक्स पूर्व के दीर्घावधि औसत से अधिक है	50
III.9	अप्रैल-नवंबर की अवधि के दौरान केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में उच्च वृद्धि	50
III.10	संसाधन जुटाने के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उच्च-ब्याज भुगतान को कम करने	53
III.11	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों के घाटे का समेकन	55
III.12	अप्रैल-नवंबर के दौरान राज्यों का कम राजकोषीय घाटा	55
III.13	कुछ देशों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक शेष राशि में वृद्धि	61
III.14	वैश्विक महामारी के कारण आई तेजी के बाद केंद्र सरकार के ऋण-जीडीपी अनुपात में सुधार	62
III.15	सार्वजनिक ऋण में बाह्य देयता का अनुपात	63
III.16	जीडीपी के अनुपात में सामान्य सरकार की देनदारियां वित्त वर्ष 21 में प्राप्त अपने चरम बिन्दु से नीचे आ गई हैं	63
III.17	जीडीपी के अनुपात में सामान्य सरकार की देनदारियां वित्त वर्ष 21 में प्राप्त अपने चरम बिन्दु से नीचे आ गई हैं	64
III.18	भारत के लिए विकास-ब्याज दर का अंतर	65
III.19	कई देशों में वर्ष 2005 और वर्ष 2021 के जीडीपी अनुपात की सामान्य सरकारी ऋण के साथ तुलना	65
IV.1	पॉलिसी दरें	80
IV.2क	व्यापक मुद्रा की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि में गिरावट	81
IV.2ख	अभिसरण मुद्रा गुणक (एमएम) उपाय	81
IV.3क	व्यापक धन की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि में गिरावट	82
IV.3ख	ओवरनाइट कॉल मनी दरें अब एलएएफ कॉरिडोर के भीतर सुव्यवस्थित चलन में हैं	82
IV.4	घरेलू ऋण देने और जमा दरों में वृद्धि	83
IV.5	जुलाई से जी-सेक प्रतिफल में कमी आ रही है, तेल की कीमतों में गिरावट और वैधिक बांड प्रतिफल द्वारा समर्थित	84
IV.6क	एससीबी के जीएनपीए अनुपात में गिरावट	86

चित्रों सं.	चित्रों	पृष्ठ सं.
IV.6ख	प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात	86
IV.7	जीएनपीए अनुपात में व्यापक आधार पर सुधार	86
IV.8	पूंजी पर्याप्तता अनुपात आवश्यकता मानदंडों से काफी ऊपर है	87
IV.9क	आरओई- वार्षिक	87
IV.9ख	आरओए- वार्षिक	87
IV.10	अप्रैल 2022 से गैर-खाद्य बैंक ऋण उच्चतम वृद्धि	88
IV.11	क्षेत्रीय गैर-खाद्य बैंक ऋण में व्यापक आधारित वृद्धि	88
IV.12	एनबीएफसी को और उनके द्वारा संवितरित ऋण में वृद्धि	89
IV.13	जीएनपीए अनुपात में गिरावट सभी क्षेत्रों में एनबीएफसी की आस्ति की गुणवत्ता में सुधार	90
IV.14	एनबीएफसी का प्रदर्शन मजबूत पूंजी स्थिति के साथ आरओए की भरपाई करना	90
IV.15	उद्योग में मामूली सुधार के साथ सभी क्षेत्रों में एनबीएफसी द्वारा ऋण संवितरण में मजबूत वृद्धि	91
IV.16	स्थापना से सीआईआरपी की स्थिति (सितंबर 2022 तक)	91
IV.17	क्षेत्रवार सीआईआरपी की स्थिति (सितंबर 2022 तक)	92
IV.18	विनिर्माण क्षेत्र में चल रहे सीआईआरपी का क्षेत्रीय विभाजन	92
IV.19	सेवा क्षेत्र में चल रहे सीआईआरपी का क्षेत्रीय विभाजन	92
IV.20	भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों में तेजी से सुधार देखा गया	97
IV.21	इंडिया वीआईएक्स में गिरावट का रुख देखा गया	97
IV.22	वित्तीय वर्ष 23 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान भारतीय सूचकांकों में वार्षिक अस्थिरता अपेक्षाकृत कम रही	98
IV.23	निफ्टी 50 वैश्विक बाजारों की तुलना में महंगा है, हालांकि अपने 5 साल (2017-2021) के औसत की तुलना में अभी भी कम है	98
IV.24	हाल के वर्षों के दौरान एफपीआई बहिर्गमन के लिए डीआईआई निवेश ने बराबर करने वाले बल के रूप में कार्य किया	102
IV.25क	2021 में जीवन-बीमा प्रीमियम की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन	110
IV.25ख	2021 में गैर-जीवन बीमा प्रीमियम की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन	110
IV.26क	बीमा प्रवेश में लगातार वृद्धि	111
IV.26ख	बीमा घनत्व में दो अंकों की वृद्धि	111
V.1	कैलेंडर वर्ष 2022 में रिकॉर्ड उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति	119
V.2	विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उच्च उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति	119
V.3	खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट	121
V.4	'खाद्य और पेय पदार्थ' समूह द्वारा प्रेरित खुदरा मुद्रास्फीति	122
V.5	प्रमुख समूहों/उप-समूहों में खुदरा मुद्रास्फीति	123
V.6	वित्त वर्ष 23 में खाद्य मुद्रास्फीति के प्रेरक - सब्जियां, अनाज, दूध और मसालें	124
V.7	वित्त वर्ष 23 में टमाटर की कीमत और 'सब्जियों' की मुद्रास्फीति में उछाल	124
V.8	खाद्य तेलों में आयातित मुद्रास्फीति	125
V.9	खाद्य तेलों का आयात	125
V.10	खाद्य तेलों की संयत खुदरा कीमत	126
V.11	शहरी और ग्रामीण मुद्रास्फीति	128
V.12	वित्त वर्ष 23* में अधिकांश राज्यों में उच्च खुदरा मुद्रास्फीति	128
V.13	वित्त वर्ष 23* में अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उच्चतर ग्रामीण मुद्रास्फीति	129
V.14	मूल और खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट	131
V.15	वित्त वर्ष 23* में थोक मुद्रास्फीति के प्रेरक - ''प्राथमिक सामग्री'' और ''ईंधन और विद्युत''	131
V.16	वैश्विक वस्तु कीमतों में कमी	132
V.17	कच्चे तेल की कीमतों में कमी	134

चित्रों सं.	चित्रों	पृष्ठ सं.
V.18	प्रमुख डबल्यूपीआई की मुद्रास्फीति सहित मुख्य सीपीआई- मुद्रास्फीति अभिसरण	135
V.19	मूल मुद्रास्फीति में अभिसरण सीपीआई-सी बनाम डब्ल्यूपीआई	135
V.20	खाद्य मुद्रास्फीति में अभिसरण सीपीआई-सी बनाम डब्ल्यूपीआइ	136
V.21	सीपीआई (ईंधन और विद्युत) और डब्ल्यूपीआई (ईंधन और बिजली) के बीच मुद्रास्फीति दरों का अभिसरण	136
V.22	खुदरा और थोक ऊर्जा मुद्रास्फीति दरों में अभिसरण	137
V.23	व्यापार और घरेलू मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं कम हो रही हैं	137
V.24	मेट्रो शहरों के लिए एचपीआई – 'अहमदाबाद' और 'हैदराबाद' में उछाल	140
V.25	अखिल भारतीय समग्र एचपीआई – आवास बाजार में सुधार	141
VI.1	सामान्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्र के व्यय में रुझान	147
VI.2	ई-श्रम पोर्टल के तहत संचयी पंजीकरण	159
VI.4	महिला श्रम बल भागीदारी दर में बदलाव	160
VI.5	त्रैमासिक शहरी रोजगार संकेतक	165
VI.6	तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार श्रमिकों की अनुमानित संख्या	166
VI.7	तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार कुल रोजगार का क्षेत्रवार हिस्सा	166
VI.8	एएसआई के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा कारखानों में लगे कुल व्यक्ति	168
VI.9	एएसआई के अनुसार कारखानों में रोजगार के रुझान	168
VI.10	ईपीएफओ में ग्राहकों की शुद्ध वृद्धि	170
VI.11	मनरेगा के तहत काम मांगने वाले व्यक्तियों की संख्या	171
VI.12	मनरेगा के अंतर्गत परियोजनाओं की संख्या	172
VI.13	मनरेगा के तहत पूर्ण कार्यों का हिस्सा (गणना के अनुसार)	172
VI.14	ग्रामीण मजदूरी में रुझान	174
VI.15	उच्च शिक्षा में छात्रों का कुल नामांकन	180
VI.16	कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय और जेब से व्यय	188
VI.17	कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सुरक्षा व्यय और निजी स्वास्थ्य व्यय	189
VI.18	कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में जेब से व्यय - 2018-19 के लिए राज्य-वार	189
VI.19	कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय - 2018-19 के लिए राज्यवार	189
VI.20	कोविड-19 वैक्सीन के साथ वयस्क आबादी का संचयी प्रतिशत	195
VII.1	विभिन्न देशों (प्रतिज्ञा वर्ष दंडा रेख के ऊपर है) की निवल शून्य प्रतिज्ञा	217
VII.2	एनएपीसीसी के आठ राष्ट्रीय मिशनों की प्रगति	221
VII.3	आईएसएफआर 2013 से आईएसएफआर 2021 तक कार्बन स्टॉक	224
VII.4	भारत में मैंग्रोव आवरण (वर्ग किमी)	225
VII.5	दिनांक 30.11.2022 की स्थिति के अनुसार संस्थापित बिजली उत्पादन क्षमता (मीगावाट)	226
VII.6	भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	226
VII.7	वर्ष 2029-30 के लिए संस्थापित क्षमता का इष्टतम मिश्रण	227
VII.8	बिजली की प्रति किलोवाट औसत कार्बन डाइऑक्साइड (ब्व्2) उत्सर्जन का दर	227
VII.9	राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मुख्य विशेषताएं।	228
VII.10	हरे और भूरे हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन की स्तरीकृत लागत (एलसीओएच)।	229
VII.11	चयनित खनिजों के प्रमुख उत्पादक देश, वर्ष 2019 और 2025	230
VII.12	वर्ष 2021 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करना (अमेरिकी बिलियन डॉलर)	232
VII.13	बाघों की संख्या	239
VII.14	शेरों की संख्या	239
VIII.1	कोविड-19 महामारी के कारण कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने लोचदार वृद्धि	244

चित्रों सं.	चित्रों	पृष्ठ सं.
VIII.2	कृषि में निजी निवेश को बढ़ावा देना	244
VIII.3	कृषि के लिए भारत की बिजली खपत (वार्षिक)	245
VIII.4	भारत के खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि (मिलियन टन)	245
VIII.5	चयनित खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹/क्विंटल)	246
VIII.6	कृषि क्षेत्र के संस्थागत ऋण में निरंतर वृद्धि (₹ लाख करोड़)	247
VIII.7	यद्यपि कृषि सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में अभी भी फसल क्षेत्र का प्रमुख योगदान है, पशुधन क्षेत्र (प्रतिशत में) की ओर बढ़ रहा है	252
VIII.8	20 अक्टूबर 2022 तक बहु-राज्य सहकारी समितियों वाले शीर्ष दस राज्य	254
VIII.9	2022-23 और 1 जनवरी 2023 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिमियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न का आवंटन (लाख टन)	257
VIII.10	2014-15 से भारत सरकार द्वारा जारी कुल खाद्य सब्सिडी (हजार करोड़)	258
IX.1	निजी क्षेत्र में निवेश से गति प्राप्त करना	263
IX.2	पीएमआई उत्पादन विस्तारक क्षेत्र में बना हुआ है	266
IX.3	आईआईपी के उप-सूचकांक मजबूत गति से बढ़ रहे हैं (अप्रैल-अक्टूबर)	266
IX.4	प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के घटकों में स्थिर वृद्धि	266
IX.5	उच्च वर्षा द्वारा सीमित जीवीए निर्माण (विनिर्माण उत्पादन के लिए एक प्रॉक्सी)	267
IX.6	भंडार में बिल्ड-अप और बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितता के साथ जीवीए विनिर्माण धीमा है	267
IX.7	एमएसएमई द्वारा संचालित उद्योग में दो अंकों की ऋण वृद्धि	269
IX.8	अप्रैल-सितंबर 2022 के दौरान 2022-23 में क्षेत्र-वार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह	271
IX.9क	निर्यात में एमएसएमई की हिस्सेदारी	272
IX.9ख	समग्र जीवीए और निर्माणकारी जीवीए में एमएसएमई की हिस्सेदारी	272
IX.10	वित्त वर्ष 22 में एमएसएमई द्वारा जीएसटी भुगतान, महामारी-पूर्व स्तर को पार कर गया है।	274
IX.11	ईसीएलजीएस सहायता प्राप्त एमएसएमई, उनकी संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार	274
IX.12	इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में मजबूत वृद्धि (अप्रैल-अक्टूबर)	275
IX.13	पर्याप्त कोयला उत्पादन	278
IX.14	कोयला भंडार में वृद्धि	278
IX.15	रूइस्पात उत्पादन और खपत में वृद्धि	279
IX.16	वित्त वर्ष 23 के दौरान लौह और इस्पात निर्यात में मामूली सुधार	279
IX.17	कपड़ा निर्यात में कमी आई, जबकि रेडीमेड गारमेंट निर्यात में तेजी आई है।	280
IX.18	कपड़ा उद्योग में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह अभी तक बहाल नहीं हुआ है	280
IX.19	फार्मास्युटिकल निर्यात में अत्यधिक वृद्धि	281
IX.20	फार्मा क्षेत्र में एफडीआई का अधिक अंतर्वाह	281
IX.21	औषधि क्षेत्र में विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए तीन पीएलआई योजनाएं	281
IX.22	ऑटोमोबाइल की वृद्धिशील बिक्री	282
IX.23	कमजोर वैश्विक मांग के बीच ऑटोमोबाइल निर्यात में मंदी	282
IX.24	ऑटोमोबाइल की वृद्धिशील बिक्री	283
IX.25	खपत बढ़ाने वाली प्रोत्साहन योजनाएं	283
IX.26	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं	284
IX.27	मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत 24 उप-क्षेत्र	285
X.1	सेवा क्षेत्र में व्यापक आधार वाली वृद्धि	293
X.2	वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई।	294
X.3	पीएमआई सेवाएं भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद विस्तार क्षेत्र में बनी रहीं	294

चित्रों सं.	चित्रों	पृष्ठ सं.
X.4	अप्रैल 2022 से सेवा क्षेत्र द्वारा ऋण लेने में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई	295
X.5	भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच सेवा निर्यात लचीला बना रहा।	296
X.6	पूर्व-महामारी स्तर के पास होटल अधिभोग दर	299
X.7	औसत दैनिक दर (एडीआर) और राजस्व प्रति उपलब्ध कक्ष (रेवपीएआर) में सुधार	299
X.8	अभी भी भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन (एफटीए) महामारी पूर्व स्तर से नीचे है	299
X.9	हाउसिंग सेल्स और लॉन्च में निरंतर वृद्धि, पूर्व-महामारी के स्तर को पार करनाचित्र	302
X.10	इन्वेंटरी ओवरहैंग में गिरावट	302
X.11	2020 और 2022 के बीच वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में शीर्ष पारदर्शिता सुधारक	303
X.12	IT-BPM निर्यात का भौगोलिक वितरण (हार्डवेयर को छोड़कर)	304
X.13	FY22 में राजस्व का खंड-वार ब्रेक-अप	304
X.14	2027 तक भारतीय ई-कॉमर्स बाजार के लगभग दो-तिहाई हिस्से पर का करने के लिए फैशन, किराना और सामान्य व्यापार	306
XI.1	वैश्विक पण्य व्यापार में वृद्धि वास्तविक और पूर्वानुमान	314
XI.2	भारतीय व्यापार से वैश्विक व्यापार से स्तरों के साथ गति आ रही है	315
XI.3	भारत का पण्य निर्यात	316
XI.4	भारत का पण्य आयात	317
XI.5	पण्य का आयात, निर्यात और व्यापार संतुलन की प्रवृत्ति	318
XI.6	सेवा व्यापार में तेजी का रुझान	319
XI.7	चालू खाता शेष (बठ) परिमाण और संरचना	326
XI.8	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष भारत बनाम चुनिंदा देश	327
XI.9	व्यापार की निवल अदृश्य मदों की संरचना मजबूत सेवाएं और बड़ा धन-प्रेषण	327
XI.10	2022 के दौरान विश्व के शीर्ष धन-प्रेषण प्राप्तकर्ता (अनुमानित)	328
XI.11	पूंजीगत खाता शेष परिमाण और संरचना	328
XI.12	निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	329
XI.13	निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश	329
XI.14	समग्र भुगतान संतुलन शेष और विदेशी मुद्रा भंडार	330
XI.15	भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता (वार्षिक आयात के प्रतिशत के रूप में) एक क्रॉस-कंट्री परिप्रेक्ष्य	330
XI.16	प्रमुख मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये की विनिमय दर	334
XI.17	6-मुद्रा और 40-मुद्रा नोमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (एनईईआर) और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (आरईईआर) (ट्रेड -वेटेड) के सूचकांक में उतार-चढ़ाव (आधार वर्ष 2015-16 = 100)	334
XI.18	सितंबर 2022 के अंत में शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश में भारत की स्थिति	335
XI.19	ऋण अनुपात 2021 के लिए क्रॉस-कंट्री तुलना	338
XII.1	अवसंरचना की मात्रा और गुणवत्ता और देशों में आर्थिक विकास का स्तर दृढ़ता से सहसंबद्ध है	343
XII.2	केंद्र सरकार ने पिछले दो वर्षों में लगातार पूंजीगत व्यय में वृद्धि की है'	345
XII.3	एनआईपी के तहत परियोजनाओं की स्थिति	348

चित्रों सं.	चित्रों	पृष्ठ सं.
XII.4	एनआईपी में परिवहन क्षेत्र का दबदबा है	348
XII.5	2015-16 से राष्ट्रीय राजमार्ग/सड़क निर्माण में वृद्धि हुई है, जो 2020-21 में अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है	353
XII.6	सड़क क्षेत्र में निवेश के लिए कुल बजटीय सहायता में भारी वृद्धि	353
XII.7	कोविड -19 की अवधि के बाद रेलवे यात्री और माल यातायात में मजबूत वृद्धि देखी गई है	354
XII.8	भारतीय विमानन क्षेत्र का प्रदर्शन	356
XII.9	विभिन्न राज्यों में जलमार्गों की नौगम्य लंबाई	357
XII.10	लाइसेंस सेवा क्षेत्र-वार समग्र टेली घनत्व स्रोत दूरसंचार विभाग	361
XII.11	डलैबीमउम पोर्टल तीन आसान चरणों में योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है	367

बाक्स की सूची

बाक्स सं.	बाक्स	पृष्ठ सं.
III.1	अप्रत्यक्ष कर संग्रह की परिपक्व प्रणाली	47
III.2	पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय बजट में किए गए प्रमुख सुधार	53
III.3	जीएसटी और राज्यों को संसाधन प्रदान करना	56
III.4	राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों में सुधार के लिए की गई पहले।	60
III.5	राजकोषीय समेकन के मार्ग के रूप में सतत विकास का मार्ग	66
IV.1	क्रॉस कंट्री विश्लेषण क्रिप्टोकरंसी का विनियमन	103
IV.2	जीआईएफटी आईएफएससी-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए एक पसंदीदा क्षेत्राधिकार के रूप में उभर रहा है	106
V.1	आवश्यक खाद्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय	126
V.2	निविष्टि मूल्यों में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय	133
V.3	वर्तमान मुद्रास्फीति 1970 के दशक से कैसे भिन्न है?	138
V.4	आवासन वित्त क्षेत्र (एचएफसी) को एनएचबी समर्थन	141
VI.1	यूएनडीपी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022	150
VI.2	महिला श्रम बल भागीदारी दर में माप के मुद्दे	160
VI.3	महिला सशक्तिकरण में स्व-सहायता समूहों की भूमिका	162
VI.4	नेशनल कैरियर सर्विस (एनसीएस) परियोजना	173
VI.5	अखिल भारतीय शिक्षा समागम	182
VI.6	स्किल इंडिया मिशन की प्रगति	184
VI.7	आयुष्मान भारत के अधीन प्रगति	192
VI.8	राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करना	193
VI.9	स्वास्थ्य- समर्पित कोविड अवसंरचना पर एक वर्णनात्मक व्याख्या	195
VI.10	को-विन बताने के लिए टीकाकरण की एक सफल डिजिटल कहानी	198
VI.11	मनरेगा के तहत उपलब्धियां	205
VI.12	जन स्वास्थ्य के साधन के रूप में जल जीवन मिशन	208
VI.13	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना में प्रगति	213
VII.1	भारत का राष्ट्रीय स्तिर पर निर्धारित अद्यतन योगदान (एनडीसी)	222
VII.2	महत्वपूर्ण खनिज-हरित परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक	229
VII.3	प्रोजेक्ट चीता	238
VIII.1	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	249
VIII.2	मोटा अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हमारा पारंपरिक स्टेपल और एक स्वस्थ विकल्प	251
VIII.3	नई राष्ट्रीय सहयोग नीति	254
IX.1	निजी पूंजी निवेश चक्र का विकास	263
IX.2	निवेश को बढ़ावा देने के लिए एफडीआई नीति में सुधार	271
IX.3	अमेरिका और भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन	275
IX.4	‘फ्लिपिंग एंड रिवर्स फ्लिपिंग स्टार्ट-अप्स में हालिया घटनाक्रम	286
IX.5	‘फ्लिपिंग एंड रिवर्स फ्लिपिंग स्टार्ट-अप्स में हाल का घटनाक्रम’	287
X.1	वितीय वर्ष 2023 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्त्क्ण्) द्वारा बीमा क्षेत्र में पहल1	297
X.2	भारत को आकर्षक पर्यटन स्थल बनाना	300
X.3	आवासीय क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय	301
X.4	आईटी-बीपीएम उद्योग में प्रमुख विकास वाहक	304
X.5	अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क: भारत की वित्तीय सेवाओं में बदलाव	308

बाक्स सं.	बाक्स	पृष्ठ सं.
X.6	दस्तावेजों का डीमैटीरियलाइजेशन: डिजिटलीकरण की अगली लहर	309
XI.1	मुक्त व्यापार समझौते	324
XI.2	विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता	331
XII.1	विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता	350
XII.2	भारतीय रेलवे की प्रमुख पहलें	355
XII.3	अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021	358
XII.4	ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को कम करना	361
XII.5	रेडियो - जुड़ी हुई तरंगें..!!	365
XII.6	एकीकृत भुगतान इंटरफेस - रीयल-टाइम भुगतान में बड़ा परिवर्तक !	369

01

अध्याय

अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022-23 : पूर्ण सुधार

सामान्य तौर पर, पूर्व के वैश्विक आर्थिक झटके काफी गंभीर थे लेकिन समय के साथ इन पर काबु पा लिया गया। इस सहस्राब्दी के तीसरे दशक में स्थिति में परिवर्तन आया। वर्ष 2020 के बाद से कम से कम तीन झटकों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। यह सब वैश्विक उत्पादन के महामारी-कारित संकुचन से शुरू हुआ, इसके बाद रूसी-यूक्रेन सांर्ष ने पूरी दुनिया को मुद्रास्फीति में वृद्धि की ओर अग्रसर किया। फिर, फेडरल रिजर्व के पीछे-पीछे अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने हेतु समकालिक नीतिगत दरों में वृद्धि की। यूएस फेड द्वारा दरों में की गयी वृद्धि ने अमेरिकी बाजारों में पूंजी आकर्षित किया, जिससे अधिकांश मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर का मूल्य बढ़ गया। परिणामस्वरूप चालू लेखा घाटा (सीएडी) बढ़ गया और निवल आयातक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति दबाव में वृद्धि हुई। दर में वृद्धि और सतत मुद्रास्फीति ने आईएमएफ द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक के अक्टूबर 2022 के अपडेट में 2022 और 2023 के लिए वैश्विक विकास पूर्वानुमानों को कम कर दिया। चीनी अर्थव्यवस्था की क्षीणता ने आगे विकास के पूर्वानुमानों को और कमजोर किया। मौद्रिक तंगी के अलावा धीमी वैश्विक वृद्धि भी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उत्पन्न वित्तीय संक्रमण का कारण बन सकती है जहां गैर-वित्तीय क्षेत्र का ऋण वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से सबसे अधिक बढ़ गया है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के बने रहने और केंद्रीय बैंकों द्वारा और दरों में अधिक वृद्धि के संकेत से, वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम बढ़ा हुआ दिखाई देता है।

तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्था, महामारी से सामना करने के बाद आगे बढ़ी हुई प्रतीत होती है, वित्तीय वर्ष 22 में कई देशों से आगे पूर्ण पुनर्प्राप्ति कर ली है और वित्त वर्ष 23 में महामारी-पूर्व विकास पथ पर खुद को चढ़ाने की स्थिति में आ गयी है। फिर भी चालू वर्ष में, भारत को मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने की चुनौती का भी सामना करना पड़ा है जिसे यूरोपीय सांर्ष ने बढ़ा दिया है। वैश्विक जिंस कीमतों में कमी के साथ-साथ सरकार और आरबीआई द्वारा किए गए उपायों ने अंततः नवंबर 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति को आरबीआई के ऊपरी स्वीकार्य सीमा लक्ष्य से नीचे लाने में कामयाबी हासिल की है। तथापि, रुपये में मूल्यह्रास की चुनौती, हालांकि अधिकांश अन्य मुद्राओं की तुलना में हमारी मुद्रा बेहतर निष्पादन कर रही है, यूएस फेड द्वारा नीतिगत दरों में और वृद्धि किए जाने की संभावना के कारण बनी हुई है। सीएडी का बढ़ना भी जारी रह सकता है क्योंकि वैश्विक जिंस कीमतें उच्चतर बनी हुई हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास गति मजबूत बनी हुई है। निर्यात प्रोत्साहन का नुकसान आगे भी संभव है क्योंकि धीमी पड़ती वैश्विक संवृद्धि और व्यापार चालू वर्ष की दूसरी छमाही में वैश्विक बाजार के आकार को कम करती है।

इसके बावजूद, दुनिया भर की एजेंसियां वित्त वर्ष 23 में भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में 6.5-7.0 प्रतिशत की संवृद्धि का अनुमान लगाना जारी रखा हैं। ये आशावादी विकास पूर्वानुमान आंशिक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन से जनित होते हैं, जो विकास के प्रमख चालक के रूप में निर्यात प्रोत्साहनों की जगह निजी खपत की उछाल में देख जाता है। निजी खपत में वृद्धि ने भी

उत्पादन गतिविधि को बढ़ावा दिया है जिसके परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। खपत का फिर से बढ़ना, सरकार के पर्यवेक्षण में लगभग-सर्वजनीन टीकाकरण कवरेज द्वारा प्रबंधित रहा, जो लोगों को रेस्तरां, होटल, शॉपिंग मॉल और सिनेमाारों जैसी संपर्क-आधारित सेवाओं पर खर्च करने के लिए सड़कों पर वापस लाया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जिसमें 2 बिलियन से अधिक खुराक शामिल हैं, ने भी उपभोक्ता मनोभावों को ऊपर उठाया जो खपत में फिर से वृद्धि को आगे भी जारी रख सकता है। टीकाकरण से शहरों में निर्माण स्थलों पर काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों की वापसी हुई, क्योंकि खपत में फिर से वृद्धि आवासीय बाजार में भी खपत में वृद्धि की है। यह आवासीय बाजार में इन्वेंट्री ओवरहैंग में गिरावट से परिलक्षित होता है, जो पिछले वर्ष के 42 माह की तुलना में वित्तीय वर्ष 23 की तीसरी तिमाही में घटकर 33 माह रह गयी है।

केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), जो वित्त वर्ष 23 के पहले आठ महीनों में 63.4 प्रतिशत बढ़ा है, चालू वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक और विकास चालक था, जिससे वर्ष 2022 की जनवरी-मार्च तिमाही से निजी पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई। वर्तमान प्रवृति को देखते हुए, यह प्रतीत होता है कि पूरे वर्ष के पूंजीगत व्यय की पूर्ति हो जाएगी। कॉरपोरेटों के तुलन पत्रों के सुदृढीकरण से और परिणामी ऋण वित्तपोषण वृद्धि, जो यह जनित करने में सक्षम रहा है, निजी पूंजी व्यय में भी सतत वृद्धि भी अपेक्षित है। अच्छी तरह से पूंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बेहतर वित्तीय स्थिति ने उन्हें ऋण आपूर्ति बढ़ाने के लिए बेहतर स्थिति में ला खड़ा कर दिया है। परिणामस्वरूप केंद्र सरकार की विस्तारित आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) द्वारा समर्थित, जनवरी-नवंबर 2022 के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में ऋण वृद्धि औसतन 30.6 प्रतिशत से अधिक रही है। समग्र बैंक ऋण में वृद्धि उधारकर्ताओं के निधियन विकल्पों में परिवर्तन से भी प्रभावित हुई है, जिन्होंने अस्थिर बॉड बाजारों, जहॉ प्रतिल में वृद्धि हुई है, और वाह्य वाणिज्यिक उधारों, जहॉ ब्याज और प्रतिरक्षण लागत में वृद्धि हुई है, की तुलना में बैंक की ओर रुख किया है। यदि वित्त वर्ष 24 में मुद्रास्फीति कम होती है और यदि ऋण की वास्तविक लागत नहीं बढ़ती है, वित्त वर्ष 24 में ऋण संवृद्धि में तेजी आने की संभावना है।

वित्त वर्ष 23 में भारत की आर्थिक संवृद्धि मुख्यतया निजी खपत और पूंजी संरचना के कारण हुई है। इसने रोजगार के सृजन में मदद की है जो टती शहरी बेरोजगारी और कर्मचारी भविष्य निधि में पंजीकरण निवल पंजीकरण में देखी जा सकती है। फिर भी, जल्द ही निजी पूंजी व्यय को रोजगार सृजन में तेजी लाने की जिम्मेदारी निभाने की जरूरत पड़ेगी। एमएसएमई की पुनर्प्राप्ति कदम से कदम मिलाकर हो रही है, जैसा कि उनके द्वारा भुगतान किए जा रहे वसतु एवं सेवा कर (जीएसटी) में दिखायी दे रहा है, जबकि आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीजीएलएस) उनकी ऋण सेवा संबंधी समस्याओं को कम कर रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान कर रही है और अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण परिवारों के लिए उनके आय सृजन के स्रोतों में विविधता लाने के अवसर पैदा कर रही है। पीएम-किसान और पीएम गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं ने देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद की है, और उसके प्रभाव को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)[1] रिपोर्ट में भी अभिपुष्टि की गयी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के परिणाम भी वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 20 तक ग्रामीण कल्याण संकेतकों में सुधार दिखते हैं, जिसमें लिंग, प्रजनन दर, घरेलू सुविधाएं और महिला सशक्तिकरण जैसे पहलू शामिल हैं।

वर्ष 2023 में वैश्विक संवृद्धि में गिरावट का अनुमान लगाया गया है और इसके बाद के वर्षों में भी आम तौर पर कमजोर रहने की संभावना है। धीमी मांग की वजह से वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में

[1] https://www.undp.org/publications/addressing-cost-living-crisis-developing-countries-poverty-and-vulnerability-projections-and-policy-responses

कमी आएगी और वित्त वर्ष 24 में भारत के सीएडी में सुधार होगा। हालांकि, चालू खाता शेष के लिए नकारात्मक जोखिम मुख्य रूप से घरेलू मांग और कुछ हद तक निर्यात द्वारा संचालित तेज रिकवरी से उत्पन्न होता है। सीएडी पर बारीकी से नजर रखने की आवश्यकता है क्योंकि चालू वर्ष की विकास गति अगले वर्ष की विकास गति बनाए रखेगी। वित्त वर्ष 24 में एक जोरदार क्रेडिट संवितरण के रूप में विकास तेज होने की संभावना है तथा भारत में कॉर्पोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की बैलेंस शीट को मजबूत करने के साथ पूंजी निवेश चक्र शुरू होने की उम्मीद है। आर्थिक विकास को अतिरिक्त समर्थन सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार और पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय रसद नीति और विनिर्माण उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं जैसे उपायों से और मिलेगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था विशिष्ट चुनौतियों का सामना कर रही है

1.1 पिछली सदी में ऐसी कई घटनाओं को याद किया जा सकता है जिनका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। स्पैनिश फ्लू और महामंदी के साथ-साथ दो विश्व युद्ध अभी भी सार्वजनिक स्मृति में ज्वलंत हैं। कई क्षेत्रीय संघर्ष रहे हैं, साथ ही रुक-रुक कर तेल के झटके भी आए हैं। पिछली सहस्राब्दी पूर्वी एशियाई संकट के साथ समाप्त हो गई, और अपने पहले दशक में नई सहस्राब्दी प्रौद्योगिकी की हलचल के साथ खुली, जिसके कई वर्षों बाद वैश्विक वित्तीय संकट आया। दूसरे दशक में, टेपर टैंट्रम के मामूली एपिसोड और महाशक्तियों के बीच बढ़ते व्यापार तनाव के अलावा, विश्व स्तर पर अपेक्षाकृत घटना-मुक्त हो गया था, हालांकि दशक के दौरान यूरोप में तनाव के क्षण आए थे। नई सहस्राब्दी के तीसरे दशक के शुरू होने से पहले वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल की घटनाओं को आम तौर पर अलग रखा गया था, जिससे अर्थव्यवस्थाओं को अगली चुनौती के लिए तैयार होने से पहले ठीक होने का समय मिल गया।

1.2 जनवरी 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अधिसूचित कोविड-19 महामारी (इसमें इसके पश्चात् 'महामारी') तीसरे दशक की पहली चुनौती थी जिसने वैश्विक विकास को प्रभावित किया। दो साल बाद, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था महामारी-कारित उत्पादन संकुचन से उबर रही थी, फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष छिड़ गया, जिससे कमोडिटी की कीमतों में उछाल आया और इस प्रकार, मौजूदा मुद्रास्फीति के दबावों में तेजी आई। इसने दूसरी चुनौती पेश की। इसके तुरंत बाद, तीसरी चुनौती सामने आई जब राष्ट्रों ने मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए मौद्रिक सख्ती की जिससे विकास की गति धीमी पड़ी। मौद्रिक सख्ती ने अमेरिकी बाजारों में पूंजी प्रवाह को भी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया, सॉवरेन बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि और अमेरिकी डॉलर की तुलना में अधिकांश मुद्राओं के के मूल्य में मूल्यह्रास कारित किया। उधार लागत में परिणामी वृद्धि ने सार्वजनिक और निजी ऋण के उच्च स्तर पर भी दबाव डाला, जिससे वित्तीय प्रणाली को खतरा पैदा हो गया। वैश्विक गतिरोध की संभावनाओं का सामना करते हुए, राष्ट्रों ने अपने संबंधित आर्थिक स्थिति की रक्षा करने के लिए मजबूरी महसूस की, सीमा पार व्यापार धीमा कर दिया, जिसने विकास के लिए चौथी चुनौती पेश की। शुरुआत से पांचवीं चुनौती बढ़ रही थी क्योंकि चीन ने अपनी नीतियों से प्रेरित काफी मंदी का अनुभव किया। विकास के लिए छठी मध्यम अवधि की चुनौती को शिक्षा और आय-अर्जन के अवसरों के नुकसान से उत्पन्न महामारी से डरा हुआ देखा गया। विकास के लिए कई चुनौतियों का एक साथ होना शायद अभूतपूर्व है। दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह, भारत ने भी इस असाधारण चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में इसने उन्हें बेहतर तरीके से सामना किया।

1.3 फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने से पहले तक वैश्विक आर्थिक सुधार अच्छी तरह से पटरी पर आ गया था। लॉकडाउन और सीमित व्यापार सौदे से पहले बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं की बहाली को बाधित

करते हुए सांर्ष अब लगभग एक वर्ष से जारी है। पिछले ग्यारह महीनों में, विश्व अर्थव्यवस्था ने लगभग उतने ही व्यवधानों का सामना किया है जितना दो वर्षों में महामारी के कारण हुआ है। सांर्ष के कारण कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और गेहूं जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। इसने मुद्रास्फीति के दबावों को बढ़ाया, जिससे वैश्विक आर्थिक सुधार शुरू हो गया था, जो 2020 में उत्पादन संकुचन को सीमित करने के लिए बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन और अति-समायोजनकारी मौद्रिक नीतियों से समर्थित था। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में मुद्रास्फीति, जो अधिकांश वैश्विक राजकोषीय विस्तार और मौद्रिक सहजता के लिए जिम्मेदार है, ने ऐतिहासिक ऊंचाई को पार कर लिया है। बढ़ती कमोडिटी की कीमतों ने उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में भी उच्च मुद्रास्फीति को जन्म दिया, जो अन्यथा 2020 में आउटपुट संकुचन को संबोधित करने के लिए अपनी सरकारों द्वारा अंशाकित राजकोषीय प्रोत्साहन के आधार पर निम्न मुद्रास्फीति क्षेत्र में थे।

चित्र 1.1: रूस-यूक्रेन सांर्ष के कारण जिंसों की कीमतों में तीव्र वृद्धि; कीमतें अभी भी सांर्ष - पूर्व स्तर तक नहीं पहुंची हैं

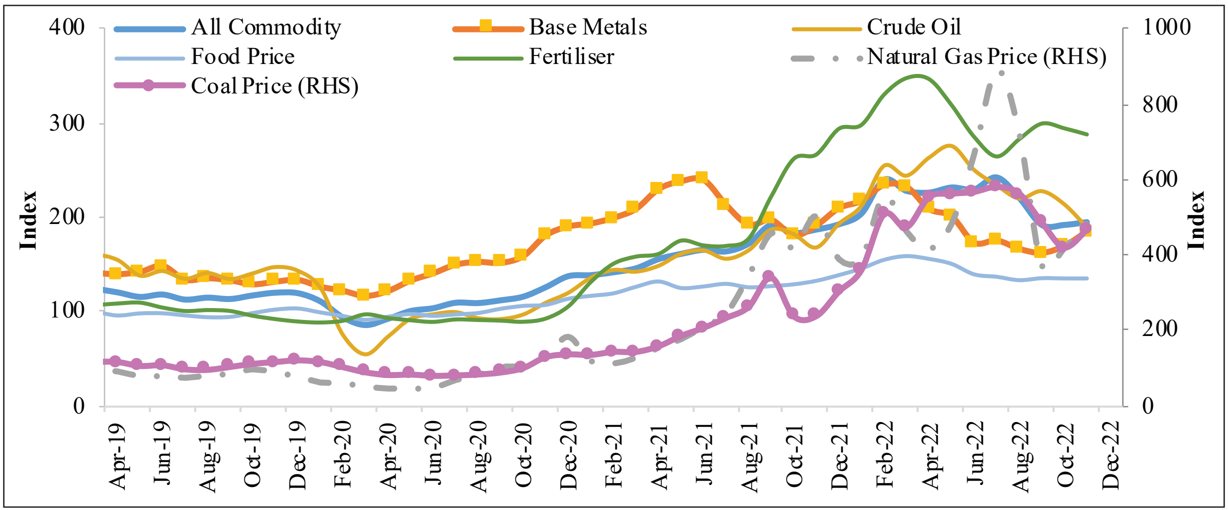

स्रोत: आईएमएफ

मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है, जो खाद्य और ऊर्जा की उच्च कीमतों से साकारित है

चित्र 1.2 क: विकसित अर्थव्यवस्थायें

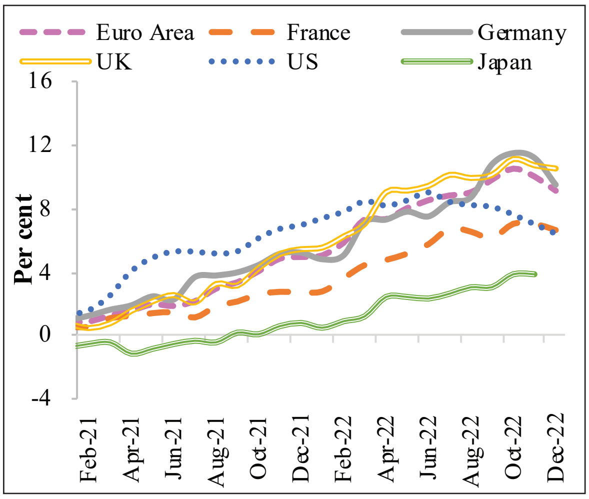

चित्र 1.2 ख: उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं

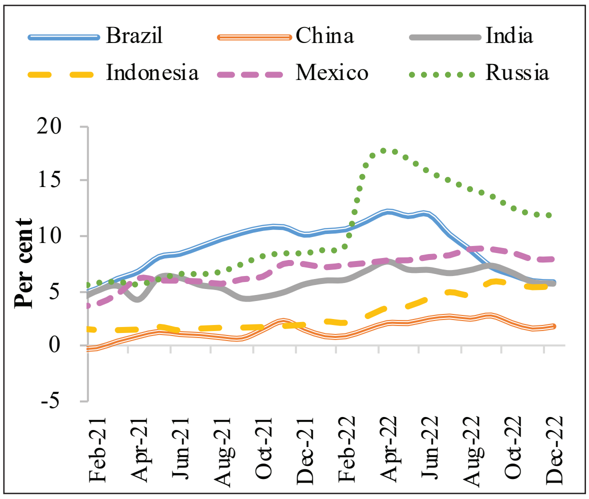

स्रोत: ब्लूमबर्ग

1.4. केंद्रीय बैंक, जो महामारी से नवोदित रिकवरी के दौरान मूल्य दबावों पर प्रतिक्रिया करने में धीमे थे, एक मजबूत मौद्रिक नीति प्रतिक्रिया की आवश्यकता और अनिवार्यता को देर से महसूस करने के लिए उन्हें क्षणिक माना। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नेतृत्व में, केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं और समकालिक रूप से मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए नकदी को कम कर रहे हैं। इस कठोरता (टाइटनिंग) चक्र की गति तेज रही है – फेडरल रिजर्व की दरों में बढ़ोतरी की गति 1970 के दशक की मुद्रास्फीति की घटना के बाद से सबसे तेज है, केंद्रीय बैंक ने मार्च 2022 से ब्याज दरों में 425 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। जैसा कि मौद्रिक नीति कार्रवाईयों का प्रभाव एक अंतराल के बाद महसूस किया जाता है, दर वृद्धि चक्र के शुरुआती चरण के दौरान मुद्रास्फीति की दरें अत्यधिक उच्च बनी रहीं, परंतु बाद में इसमें गिरावट आना शुरू हुआ। वहीं, केन्द्रीय बैंकों द्वारा समकालिक दर वृद्धियां वित्तीय स्थितियों को पर्याप्त रूप से इतना नहीं कसा कि केन्द्रीय बैंकों को अपनी सख्ती मुहिम रोकना पड़ सके।

आर्थिक स्थितियाँ सीमित

चित्र 1.3क: विकसित अर्थव्यवस्थायें **चित्र 1.3ख: उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं**

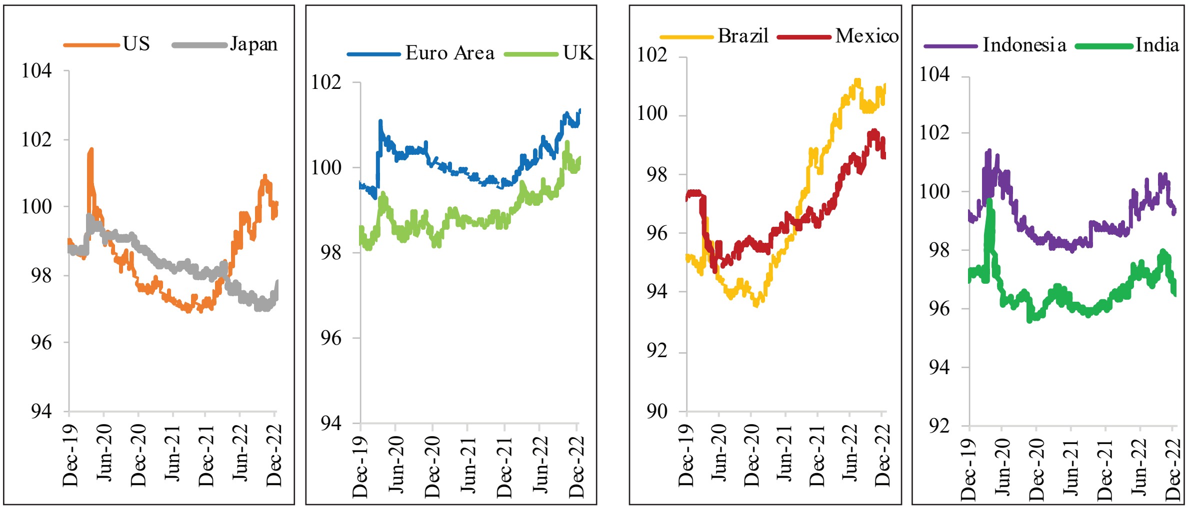

स्रोत: गोल्डमैन सैक्स, ब्लूमबर्ग

नोट: सभी वाई सूचकांक हैं; डाटा गोल्डमैन सैक्स वित्तीय स्थिति सूचकांक से प्राप्त किया गया है

1.5 मुद्रास्फीति और मौद्रिक तंगी ने सभी अर्थव्यवस्थाओं में बॉन्ड प्रतिफल को सख्त कर दिया और इसके परिणामस्वरूप दुनिया भर की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं से इक्विटी पूंजी का बहिर्वाह अमेरिका के पारंपरिक रूप से सुरक्षित आश्रय बाजार में हो गया। पूर्व के विपरीत जब ईएमई की अपेक्षाकृत अधिक कमजोरियों, या उसकी धारणा को देखते हुए पूंजी उड़ान अधिक बाहर थी, तब इस बार पूंजी भी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से बाहर निकल गई है। पूंजी उड़ान ने बाद में अन्य मुद्राओं के प्रति अमेरिकी डॉलर को मजबूत किया – जनवरी और सितंबर 2022 के बीच अमेरिकी डॉलर सूचकांक 16.1 प्रतिशत मजबूत हुआ। अन्य मुद्राओं का परिणामी मूल्यह्रास सीएडी को बढ़ा रहा है और शुद्ध आयातक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के दबावों को बढ़ा रहा है।

अर्थव्यवस्थाओं में बॉन्ड प्रतिफल का स्थिर होना

चित्र 1.4क : एई में 10 वर्षीय बॉन्ड

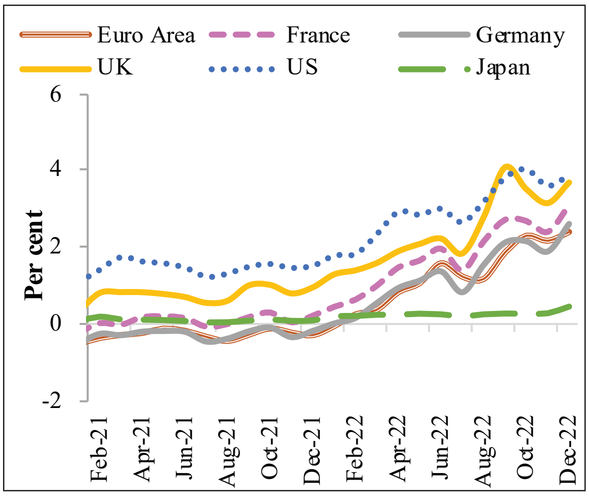

चित्र 1.4ख : ईएमई में 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड

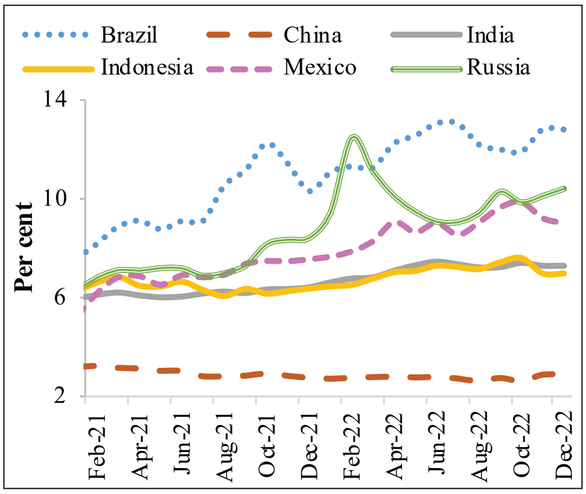

स्रोतः ब्लूमबर्ग

चित्र 1.5 फेडरल फंड्स रेट जनवरी 2022 से संचयी 425 आधार अंकों से बढ़ाया गया है, जिससे ईएमई और एई से पूंजी निकल गयी है।

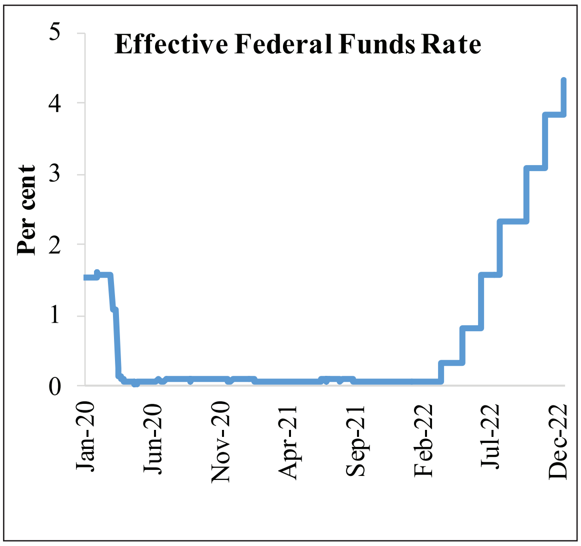

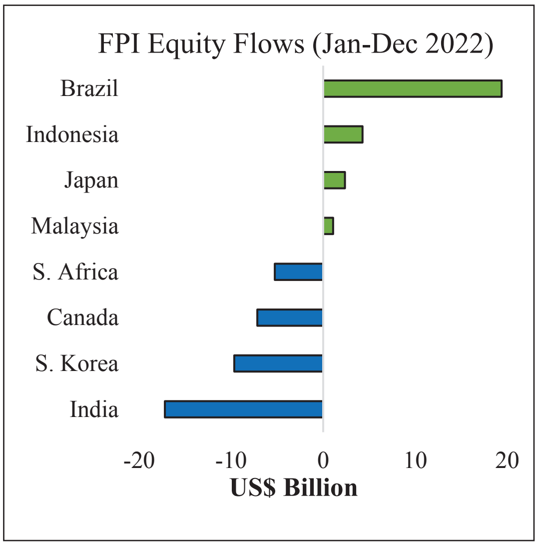

स्रोतः फेडरल रिजर्व

स्रोतः ब्लूमबर्ग

1.6 बढ़ती मुद्रास्फीति और मौद्रिक तंगी के कारण 2022 की दूसरी छमाही में वैश्विक उत्पादन में मंदी आई। वैश्विक पीएमआई समग्र सूचकांक अगस्त 2022 से संकुचन क्षेत्र में रहा है, जबकि वैश्विक व्यापार, खुदरा बिक्री और वार्षिक विकास दर में वृद्धि हुई है। 2022 की दूसरी छमाही में औद्योगिक उत्पादन में काफी गिरावट आई है। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के परिणामी ह्रास, उधार लेने की लागत में अतिरिक्त वृद्धि की संभावनाओं से भी मिश्रित, आईएमएफ द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) के अपने अक्टूबर 2022 के अपडेट में वृद्धि के पूर्वानुमानों को कम करने में परिलक्षित हुआ था।

सारणी 1.1 : वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के कारण सभी देशों में विकास के पूर्वानुमान में गिरावट आई है

	संवृद्धि अनुमान (प्रतिशत)		डब्ल्यू ई ओ अपडेट से बदलाव (जुलाई 2022) (प्रतिशत)	
	2022	2023	2022	2023
दुनिया	3.2	2.7	0	-0.2
विकसित अर्थव्यवस्थायें	2.4	1.1	-0.1	-0.3
संयुक्त राज्य अमेरिका	1.6	1	-0.7	0
यूरो क्षेत्र	3.1	0.5	0.5	-0.7
यूके	3.6	0.3	0.4	-0.2
जापान	1.7	1.6	0	-0.1
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं	3.7	3.7	0.1	-0.2
चीन	3.2	4.4	-0.1	-0.2
भारत*	**6.8**	**6.1**	**-0.6**	**0**

स्रोत: आईएमएफ
नोट: *भारत के लिए किया गया अनुमान उसके वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के लिए है जबकि अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए, यह जनवरी-दिसंबर से है।

चित्र 1.6 : अगस्त 2022 से वैश्विक समग्र पीएमआई संकुचन क्षेत्र में

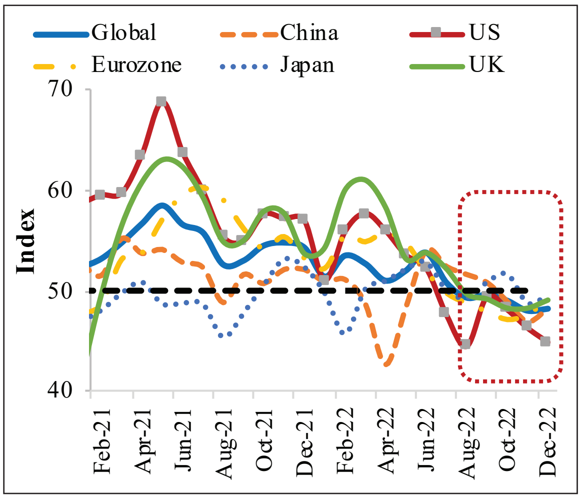

स्रोत: आईएचएस मार्किट

चित्र 1.7 : खुदरा बिक्री, औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि गिर रही है

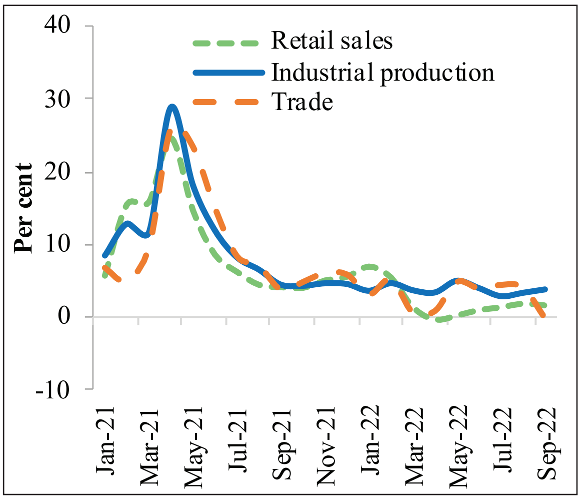

स्रोत: ओईसीडी, नवंबर 2022

1.7 सरकार की शून्य कोविड नीति, एक सिकुड़ते रियल एस्टेट क्षेत्र, और एक सुस्त राजकोषीय विस्तार से उभरती चीनी अर्थव्यवस्था में निराशाजनक विकास परिदृश्य क्षीण वैश्विक संवृद्धि को और जटिल बना रहा है। तथापि, चीन ने कोविड से संबंधित अपनी ज्यादातर प्रतिबंधित नीतियों को रोक दिया है या शिथिल कर दिया है। संभवत: चीन की आर्थिक गतिविधियां प्रत्याशा से पूर्व गति पकड़ सकती है। परंतु अभी यह कहना मुश्किल है।

चित्र 1.8क: चीन के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) घट रही है

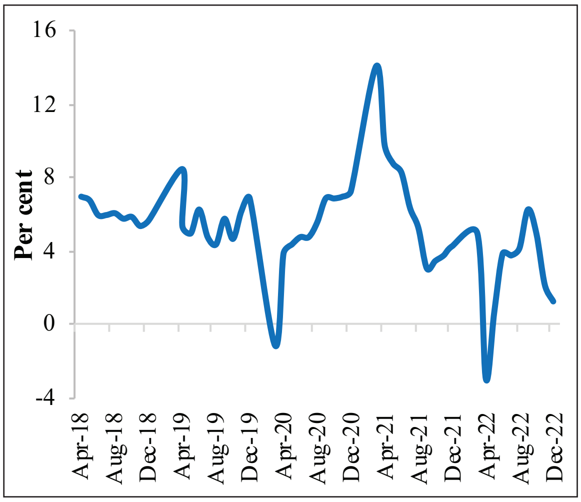

चित्र 8.8ख: चीन की खुदरा बिक्री वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) कम हो रही है

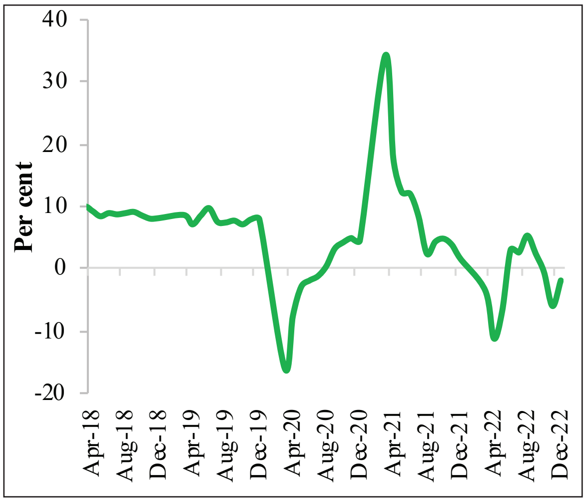

स्रोत: ब्लूमबर्ग, चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो

1.8 मौद्रिक नीति को और कड़ा करने से वर्षों से वित्तीय प्रणाली में निर्मित दोष बढ़ सकते हैं, जैसे कि निजी और सरकारी ऋण संरचनाएँ, जिसके प्रभाव के कारण वित्तीय संक्रमण शुरू हो सकता है। अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के गैर-वित्तीय क्षेत्र ऋण वर्ष 2008 के प्रथम तिमाही, जब वैश्विक वित्तीय संकट शुरू हुआ था, से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में काफी बढ़ गए हैं। हालाँकि, भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है, जिनके ऋण का बोझ इस अवधि में कम हुआ है, इसका मुख्य कारण पिछले दशक के दौरान देश के बैंकिंग क्षेत्र की बैलेंस शीट का परिशोधन और कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा ऋण कम करने की कवायद है। अभी भी, भारत में सामान्य सरकारी ऋण के बोझ में वृद्धि ने बहुत ध्यान आकर्षित किया है, भले ही वित्तीय संकट के प्रणालीगत जोखिम दुनिया के अन्य हिस्सों में केंद्रित हैं।

सारणी 1.2: भारत को छोड़कर अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का मूल ऋण 2008 की तुलना में अधिक है

	गैर-वित्तीय क्षेत्र का मूल ऋण (2022 की दूसरी तिमाही, जीडीपी का %)				2008 की दूसरी तिमाही के बाद से बदलाव			
ऋण/जीडीपी (औसत %)	हाउसहोल्ड	प्रा. नॉन फाईनेंशियल	सरकार	कुल	हाउसहोल्ड	प्रा. नॉन फाईनेंशियल	सरकार	कुल
वैश्विक औसत	62	160	88	**248**	-4	15	27	**38**
ऑस्ट्रेलिया	117	181	52	**232**	7	-9	42	**33**
ब्राजिल	35	88	91	**179**	17	-36	28	**66**
मेनलैंड चाइना	62	220	74	**295**	43	107	47	**155**
फ्रांस	67	231	114	**345**	19	71	47	**118**
जर्मनी	56	128	67	**195**	-4	0.4	2	**3**
भारत	36	88	82	**170**	-7	**-17**	16	**-7**
इटली	43	113	151	**264**	4	-4	47	**43**
जापान	69	187	238	**426**	9	29	94	**122**
दक्षिण कोरिया	106	222	45	**268**	35	61	23	**84**
मेक्सिको	16	40	41	**81**	3	12	20	**33**
दक्षिण अफ्रीका	35	67	71	**138**	-9	-13	45	**32**

स्पेन	57	155	118	**273**	-26	-56	82	**26**
यूके	84	150	107	**257**	-11	-28	62	**34**
यू.एस.	76	155	108	**264**	-22	-15	48	**33**

स्रोत: बीआईएस ('गैर-वित्तीय क्षेत्र को ऋण' के उनके 5 दिसंबर 2022 के अपडेट की जानकारी के आधार पर)

1.9 विकसित दुनिया में, मुद्रास्फितिक दबाव कम हो रहें हैं परंतु वे ऐतिहासिक रूप से और कई देशों के अंगीकृत मुद्रास्फीतिक लक्ष्यों की तुलना में उच्चतर स्तर पर हैं। अब तक के प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति समीक्षा के अपने नवीनतम दौर में ब्याज दरों में वृद्धि की गति को कम कर दिया है। फिर भी, उन्होंने दोहराया है कि टर्मिनल पॉलिसी दरें बाजार की अपेक्षाओं से काफी अधिक होंगी। सुदृढ रोजगार आंकड़े और तीव्रतर निम्न दिसंबर मुद्रास्फीतिक मुख्य समाचार ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था द्वारा कम दर पर उधार देने की आशा बढ़ायी है। इसी प्रकार, यूरोप में, अधिक गर्म शीत ऋतु ने निकट काल के ऊर्जा संकट के जोखिम को निष्क्रिय कर दिया है। गतकाल में, तथापि, बैंकों ने निम्नतर अर्जन संवृद्धि की सूचना दी है, और प्रौद्योगिकीय कंपनियों ने अमेरिका में छटनी करना शुरू कर दिया है। इसलिए, संतुलित शब्दों में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नाकारत्मक जोखिम हावी हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में मैक्रोइकॉनॉमिक और विकास संबंधी चुनौतियाँ

1.10 भारत पर महामारी के प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 21 में एक महत्वपूर्ण जीडीपी संकुचन देखा गया था। अगले वर्ष, वित्तीय वर्ष 22, में भारतीय अर्थव्यवस्था जनवरी 2022 की ओमिक्रॉन लहर के बावजूद पटरी पर आने लगी थी। इस तीसरी लहर ने भारत में आर्थिक गतिविधियों को उतना प्रभावित नहीं किया, जितना महामारी की पिछली लहरों ने जनवरी 2020 में इसका प्रकोश शुरू होने पर प्रभावित किया था। स्थानीयकृत लॉकडाउन, तेजी से टीकाकरण कवरेज, हल्के लक्षण और वायरस से जल्दी ठीक होने के कारण 2022 की जनवरी-मार्च तिमाही में आर्थिक उत्पादन के नुकसान को कम करने में मदद मिली। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2022 का आउटपुट, कई देशों से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के पूरी तरह से पटरी पर आ जाने के कारण, वित्तीय वर्ष 20 के महामारी-पूर्व स्तर पर जा पहुँचा। ओमिक्रॉन वैरिएंट के साथ अनुभव ने एक सतर्क आशावाद को जन्म दिया कि महामारी के बावजूद शारीरिक रूप से गतिशील रहना और आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहना संभव था। इस प्रकार, वित्त वर्ष 23 एक दृढ़ विश्वास के साथ शुरू हुआ कि महामारी तेजी से कम हो रही थी और भारत तेज गति से बढ़ने के लिए तैयार था और जल्दी ही महामारी पूर्व विकास पथ अग्रसर होने वाला था।

चित्र 1.9 : आर्थिक विकास लचीला बना हुआ है

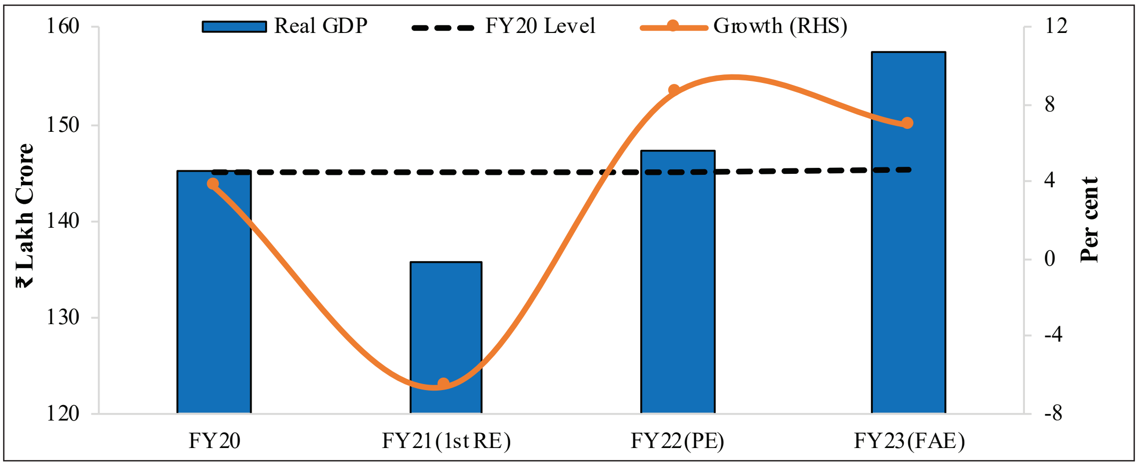

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई

मांग और निवेश द्वारा कारित व्यापक संवृद्धि

चित्र 1.10क : वास्तविक जीवीए में वर्ष दर वर्ष संवृद्धि

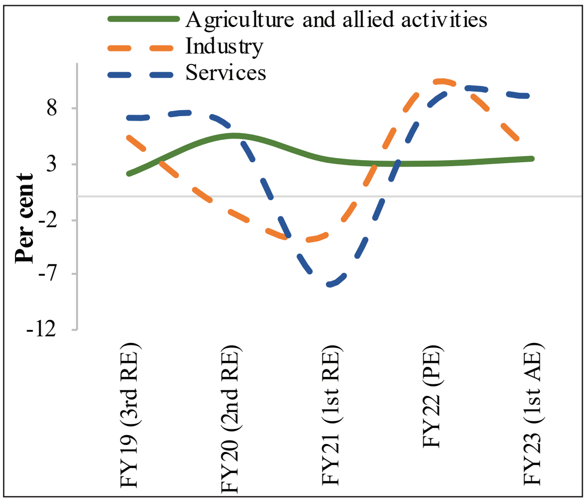

चित्र 1.10ख: वास्तविक जीडीपी घटकों के हिस्से

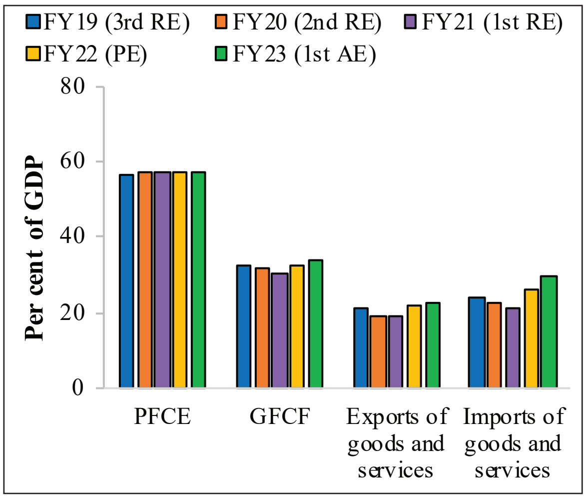

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई

नोट: एई का तात्पर्य है अग्रिम अनुमान, पीई का अर्थ है अनंतिम अनुमान, आरई का अर्थ है संशोधित अनुमान

चित्र 1.11 : सीपीआई मुद्रास्फीति आरबीआई की लक्ष्य सीमा में वापस आ गई

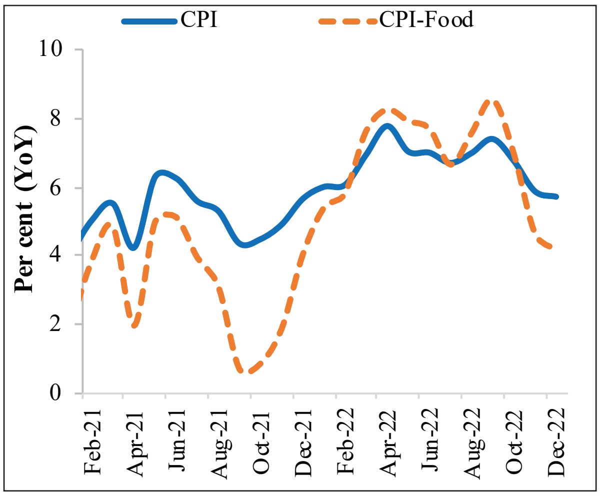

स्रोत: एमओएसपीआई

चित्र 1.12 : भारतीय रुपये ने अन्य ईएमई की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया

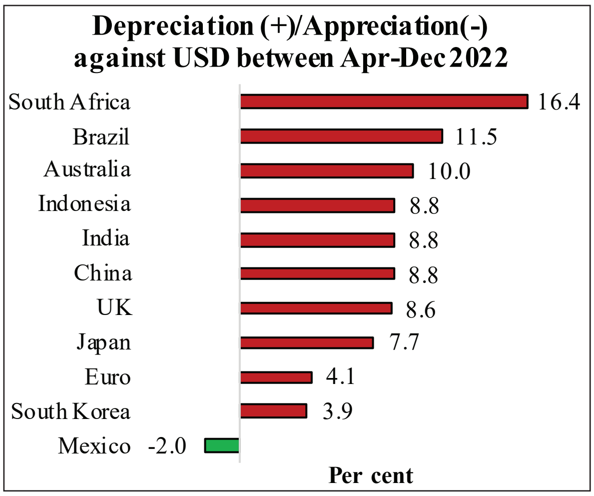

स्रोत: ब्लूमबर्ग, आरबीआई (16 दिसंबर 2022 को दिसंबर के लिए विनिमय दरें)

1.11 तथापि, यूरोपीय संघर्ष ने वित्त वर्ष 23 में आर्थिक संवृद्धि और मुद्रास्फिति की प्रत्याशा में एक संशोधन आवश्यक कर दिया। जनवरी 2022 में देश की खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई की स्वीकार्य सीमा से ऊपर चली गई थी। यह नवंबर 2022 से 6 प्रतिशत के लक्ष्य सीमा के ऊपरी छोर से नीचे लौटने से पहले दस महीनों के लिए लक्ष्य सीमा से ऊपर रही। उन दस महीनों के दौरान, अत्यधिक गर्मी और बेमौसम बारिश जैसे स्थानीय मौसम के चरम पर होने के बावजूद भी बढ़ती अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों ने भारत की खुदरा मुद्रास्फीति में योगदान

दिया, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई। सरकार ने उत्पाद और सीमा शुल्क में कटौती की और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निर्यात को प्रतिबंधित किया, जबकि अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह आरबीआई ने खेपो दरों में वृद्धि की और अतिरिक्त नकदी को वापस ले लिया।

1.12 मौद्रिक सख्ती के साथ, भारतीय रुपये सहित कई मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि हुई है। तथापि, भारतीय रुपया दुनिया भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक रहा है, लेकिन इसमें होने वाले मामूली मूल्यह्रास ने सीएडी को बढ़ाने के अलावा हो सकता है घरेलू मुद्रास्फीति के दबावों में इजाफा किया हो। वैश्विक जींस कीमतों में भले ही कमी आई हो लेकिन पूर्व के टकराव स्तरों की तुलना में यह अब भी अधिक है। उन्होंने सीएडी को और बढ़ाया है, जोकि पहले से ही भारत के विकास की गति से अधिक बढ़ा हुआ है। वित्त वर्ष 23 के लिए, भारत के पास सीएडी को वित्तपोषित करने और भारतीय रुपये में अस्थिरता का प्रबंधन करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध है।

चित्र 1.13 : बढ़ा हुआ सी.ए.ड लेख घाटा

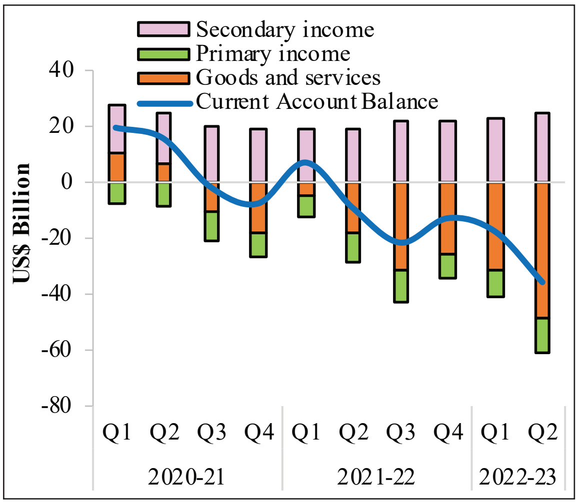

स्रोत: आरबीआई

चित्र 1.14 : सी.ए.डी के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार

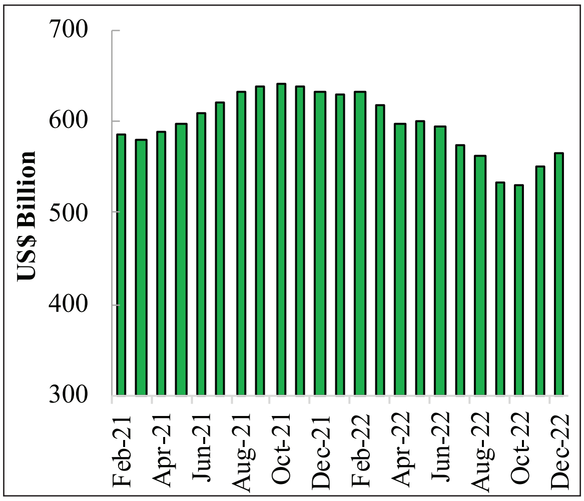

स्रोत: आरबीआई

1.13 भारत सहित पूरी दुनिया के कई देशों के लिए, वर्ष 2021 महामारी के प्रभाव से स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्थाओं के लिए रिकवर करने की अवधि था। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए, उनकी सरकारों द्वारा विशेष रूप से, पहले दिए गए भारी राजकोषीय प्रोत्साहन ने एक मजबूत मांग पुनरुद्धार का समर्थन किया। बाद में विश्व व्यापार में वृद्धि हुई, जिसका भारत को भी लाभ हुआ। वित्त वर्ष 22 में भारत के निर्यात में वृद्धि हुई, और यह गति वित्त वर्ष 23 की प्रथम छमाही तक जारी रही। व्यापारिक निर्यात संबंधी विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निर्यात वृद्धि काफी मजबूत थी। तथापि, आक्रामक और समकालिक मौद्रिक सख्ती से वैश्विक आर्थिक संवृद्धि में गिरावट आना शुरू हो गया और विश्व व्यापार भी कम हो गया। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास कॉन्फ्रेंस (यूएनसीटीएडी) के नवीनतम वैश्विक व्यापार अद्यतन के अनुसार, वैश्विक व्यापार संवृद्धि वर्ष 2022 की दूसरी छमाही के दौरान ऋणात्मक हो गयी, और भू-राजनीतिक सांर्ष, सतत मुद्रास्फीतिक दबाव और कम मांग से वैश्विक व्यापार वर्ष 2023 में और कम होने की प्रत्याशा है। इससे भारत सहित कई देशों के प्रभावित होने की संभावना है, और वित्तीय वर्ष 2024 में भी निर्यात, वर्तमान वर्ष की शुरूआत में दिख रही संभावना की तुलना में धीमा ही रह सकता है।

चित्र 1.15 : व्यापार धीमा होने के कारण शिपिंग माल ढुलाई लागत में कमी

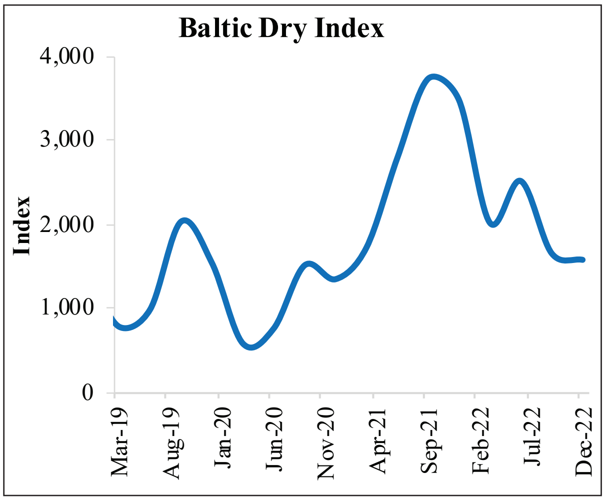

स्रोत: द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड

चित्र 1.16 : वैश्विक मंदी के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात का हिस्सा बढ़ता है

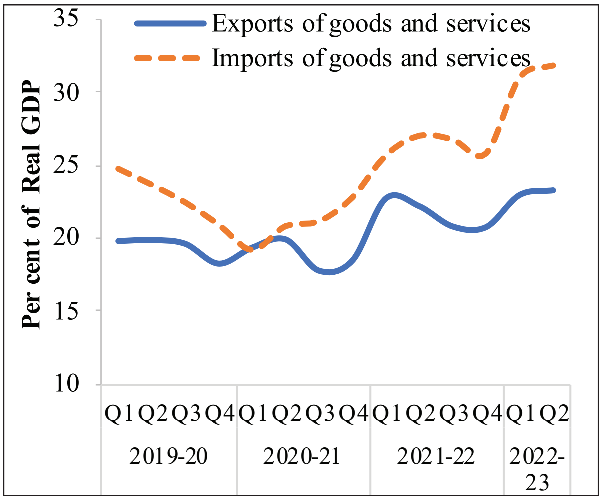

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई

भारत का आर्थिक लचीलापन और विकास संचालक

1.14 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक सख्ती, सीएडी का बढ़ना, और निर्यात की स्थिर वृद्धि अनिवार्य रूप से यूरोप में भू-राजनीतिक विवाद का परिणाम है। जैसा कि इन गतिविधियों ने वित्त वर्ष 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा किया है, दुनिया भर में कई एजेंसियां रुक-रुक कर भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने विकास पूर्वानुमान को नीचे की ओर संशोधित कर रही हैं। एनएसओ द्वारा जारी किए गए अग्रिम अनुमानों सहित ये पूर्वानुमान अब मोटे तौर पर 6.5-7.0 प्रतिशत की सीमा में हैं। नीचे की ओर संशोधन के बावजूद, वित्त वर्ष 23 के लिए विकास का अनुमान लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक बना हुआ है और यहां तक कि महामारी से पहले के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि से थोड़ा ऊपर है। आईएमएफ का अनुमान है कि भारत 2022 में तेजी से बढ़ती शीर्ष दो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। मजबूत वैश्विक विपरीत परिस्थितियों और कड़ी घरेलू मौद्रिक नीति के बावजूद, यदि भारत अभी भी 6.5 और 7.0 प्रतिशत के बीच बढ़ने की उम्मीद करता है, और वह भी आधार प्रभाव के लाभ के बिना, तो यह भारत की अंतर्निहित आर्थिक लचीलापन का प्रतिबिंब है; और अर्थव्यवस्था के विकास चालकों को पुनः प्राप्त करने, नवीनीकृत करने और फिर से सक्रिय करने की इसकी क्षमता है।

चित्र 1.17 वित्त वर्ष 23 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत के विकास अनुमान

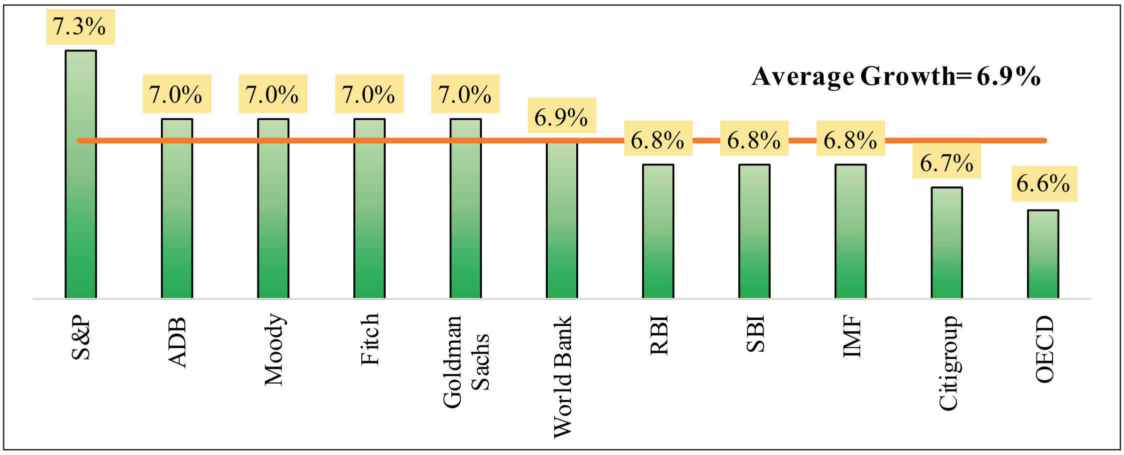

स्रोत: विभिन्न एजेंसियां,

नोट: एडीबी का अर्थ एशियाई विकास बैंक है, आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है।

1.15 भारत के आर्थिक लचीलेपन को विकास के लिए घरेलू प्रोत्साहन में देखा जा सकता है जो बाहरी प्रोत्साहनों की जगह ले सकता है। निर्यात की वृद्धि वित्त वर्ष 23 की दूसरी छमाही में कम हो सकती है। हालाँकि, वित्त वर्ष 22 में उनके उछाल और वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही ने उत्पादन प्रक्रियाओं के गियर में हल्की तेजी से क्रूज मोड में बदलाव के लिए प्रेरित किया। विनिर्माण और निवेश गतिविधियों ने इसके परिणामस्वरूप ट्रैक्शन प्राप्त किया। जब तक निर्यात की वृद्धि में कमी आई, तब तक घरेलू खपत में उछाल भारत की अर्थव्यवस्था के विकास को आगे ले जाने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व हो चुका था। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में निजी खपत 58.4 प्रतिशत रही, जो 2013-14 के बाद से सभी वर्षों की दूसरी तिमाहियों में सबसे अधिक है, व्यापार, होटल और परिवहन जैसी संपर्क-गहन सेवाएं जोकि एक प्रतिक्षेप द्वारा समर्थित है, इनमें पिछली तिमाही की तुलना में वित्त वर्ष 23 की दूसरी तिमाही में वास्तविक रूप से 16 प्रतिशत की क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई।

1.16 यद्यपि कई देशो में घरेलू खपत में फिर से वृद्धि होना शुरू हो गयी है, भारती की वृद्धि बहाली इसके पैमाने की दृष्टि से शानदार थी। इसने घरेलू क्षमता उपयोग में वृद्धि में योगदान दिया है। घरेलू निजी खपत नवंबर, 2022 में तेज बनी रही, जैसा कि मोतीलाल ओसवाल के आर्थिक गतिविधि सूचकांक में देखा जा सकता है। यह सूचकांक अनुमान कि निजी खपत वर्ष दर वर्ष आधार पर 5.6 प्रतिशत की पांच माह की उच्च गति से बढ़ा है, वह ओटो बिक्री और सेवाओं में व्यापक विस्तार के कारण हुआ है।[2]

चित्र 1.18 : बढ़ी हुई क्षमता उपयोग और व्यावसायिक भाव

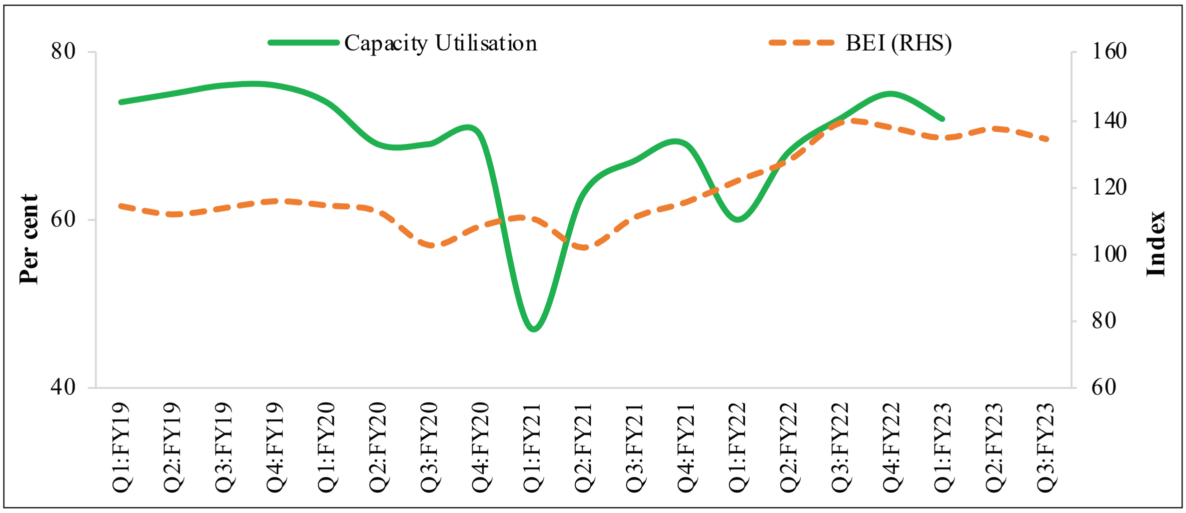

स्रोतः आरबीआई
नोटः बीईआई - व्यापार अपेक्षा सूचकांक

1.17 भारत में सरकार द्वारा कराए जाने वाले टीकाकरण का लगभग-सार्वजनीन कवरेज एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कारण था जिसने लोगों को ''बाजार'' का फिर से अनुभव कराने के लिए सड़कों पर ला दिया, क्योंकि मार्केटप्लेस तेजी से सेवा प्रदाताओं के व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए लोगों से भर गया। रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा और पर्यटन स्थलों जैसे संपर्क-आधारित सेवा प्रदाताओं ने शीघ्र ही एक संपन्न व्यवसाय शुरू कर दिया और उपभोक्ता भावनाओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसा कि बार-बार सर्वेक्षणों में दिखया गया है। एक ओर जहां, सर्वजनीन टीकाकरण कवरेज ने जीवन बचाया, वहीं दूसरी ओर, इसने उपभाक्ता भावनाओं को बढ़ाने के लिए एक स्वास्थ्य प्रेरक के रूप में कार्य किया और इस प्रकार अर्थव्यवस्था की रिकवरी और विकास हुआ।

2 https://www.motilaloswal.com/site/rreports/HTML/638084191269979180/index.htm

चित्र 1.19क: वित्त वर्ष 15 के बाद वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में निजी खपत सबसे अधिक पर

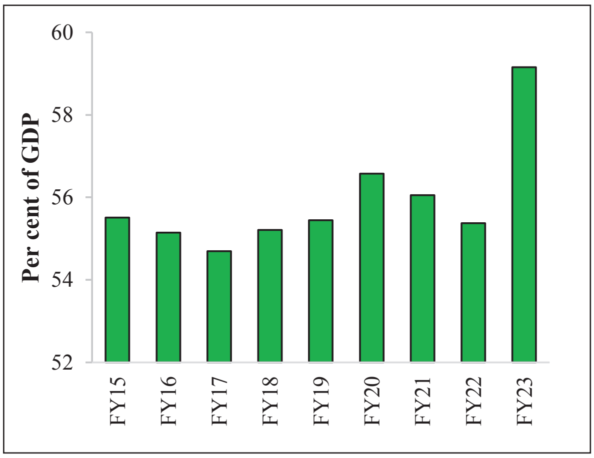

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई

चित्र 1.19ख: उपभोक्ता विश्वास में सुधार

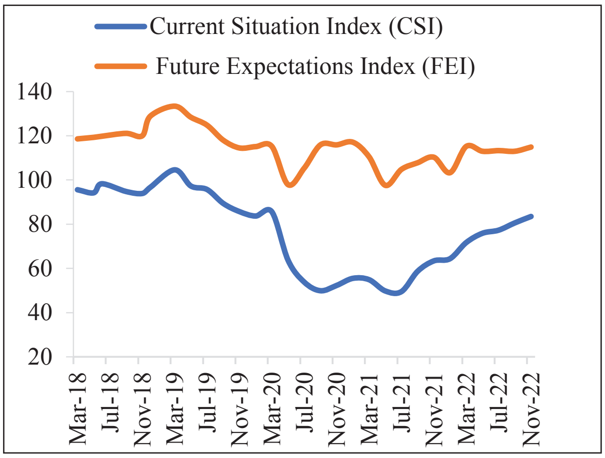

स्रोत: आरबीआई

1.18 खपत में फिर से वृद्धि को ''पेंट-अप'' मांग के बाहर निकलने से भी समर्थन मिला है, एक ऐसी घटना जो फिर से भारत के लिए अद्वितीय नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्पोजेबल आय में खपत के हिस्से में वृद्धि से प्रभावित एक स्थानीय घटना का प्रदर्शन करती है। चूंकि भारत में प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) आय में खपत का हिस्सा अधिक है, इसलिए महामारी के कारण खपत को कम करने से बहुत अधिक परावर्तन की शक्ति का निर्माण हुआ। इसलिए, खपत पुनर्वृद्धि स्थायी शक्ति हो सकती है। भारत में व्यक्तिगत ऋणों में उच्च वृद्धि खपत के लिए ''पेंट-अप'' मांग की स्थायी निर्मोचन को प्रमाणित करती है। दिसंबर, 2022 में जारी ग्राहक विश्वास के आरबीआई के हालिया सर्वेक्षण[3] ने वर्तमान और भावी नियोजन और आय स्थिति के संबंध में भावनाओं में सुधार की ओर इंगित करता है।

1.19 ''रिलीज ऑफ पेंट-अप डिमांड'' के स्पिलओवर ने हाउसिंग बाजार में भी अपना रास्ता खोज लिया, जो हाउसिंग ऋणों की उच्च वृद्धि में परिलक्षित हुआ। फलस्वरूप, हाउसिंग इन्वेंटरी कम हो गई है, कीमतें बढ़ रही हैं, और नए आवासों का निर्माण गति पकड़ रहा है। इससे अनगिनत संख्या में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को बढ़ावा मिला है, जिसके लिए निर्माण क्षेत्र जाना जाता है। आवास बाजार को उठाने में टीकाकरण कवरेज के सार्वभौमिकरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसके अभाव में, प्रवासी कार्यबल नए आवासों का निर्माण करने के लिए वापस नहीं आ सकते थे।

चित्र 1.20 : आवास के लिए बैंक ऋण में वृद्धि गिरते हाउसहोल्ड को संपुरित कर रहा है

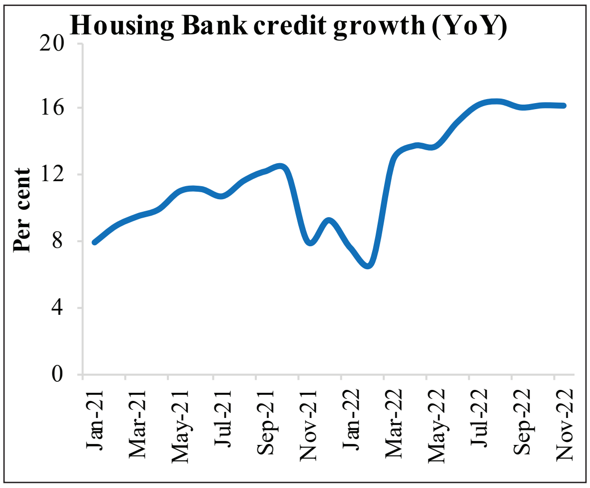

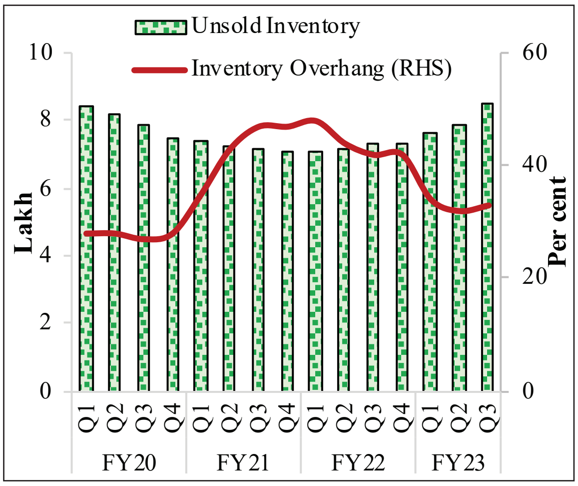

स्रोत: आरबीआई, प्रॉपटाइगर

3 See https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspxid=21569

1.20 आवासन के अलावा, निर्माण गतिविधि, वित्त वर्ष 23 में सामान्यत: उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है क्योंकि केंद्र सरकार और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का बहुत अधिक पूंजी बजट (कैपेक्स) तेजी से इसमें इस्तेमाल हो रहा है। देश के लिए अनुमानित कैपेक्स गुणक के अनुसार, देश का आर्थिक उत्पादन कैपेक्स[4,5], की मात्रा से कम से कम चार गुना बढ़ना तय है। पीएम गतिशक्ति, पूंजीगत परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक प्रमुख समन्वय/निगरानी तंत्र है, जिसने कैपेक्स का तेजी से उपयोग सुनिश्चित किया है। राज्य, कुल मिलाकर, अच्छी तरह से प्रगति कर रहे हैं, उनके कैपेक्स में वित्त वर्ष 23 में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि (बजट अनुमान के अनुसार) और वित्त वर्ष 21 की तुलना में 38.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्र सरकार की तरह, राज्यों के पास पूंजीगत कार्यों के लिए केंद्र की अनुदान सहायता और 50 वर्षों में चुकाने योग्य ब्याज मुक्त ऋण द्वारा समर्थित एक बहुत बड़ा पूंजीगत बजट है।

चित्र 1.21 : वित्त वर्ष 12 और वित्त वर्ष 23 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय औसतन 13.3 की दर से बढ़ा

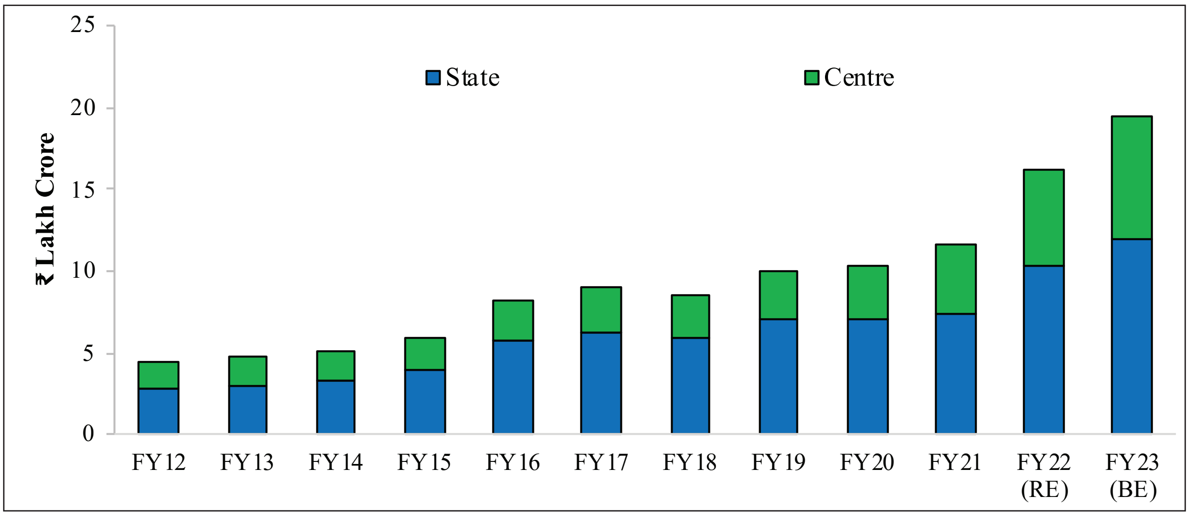

स्रोत: केंद्रीय बजट, राज्यों के बजट, आरबीआई

1.21 भारत सरकार के पिछले दो बजटों में केपेक्स पर जोर केवल देश में बुनियादी ढांचे के अंतर को दूर करने के लिए एक अलग पहल नहीं थी। यह एक रणनीतिक पैकेज का हिस्सा था जिसका उद्देश्य गैर-रणनीतिक पीएसई (विनिवेश) से छुटकारा और सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को निष्क्रिय करके एक विस्तृत आर्थिक परिदृश्य में भीड़-भाड़ करना था। तीन गतिविधियां इसका समर्थन करती हैं।[6] सबसे पहली, वित्त वर्ष 23 में कैपेक्स बजट में उल्लेखनीय वृद्धि, साथ ही इसके खर्च की उच्च दर। दूसरी, प्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रह अत्यधिक उछाल वाला रहा है, और साथ ही जीएसटी संग्रह भी है, जिसको बजटीय राजकोषीय घाटे के भीतर केपेक्स बजट के पूर्ण व्यय को सुनिश्चित करना चाहिए। कैपेक्स में उच्च वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राजस्व व्यय में वृद्धि को भी सीमित कर दिया गया है। तीसरी, 2022 की जनवरी-मार्च तिमाही से निजी क्षेत्र के निवेश में तेजी। साक्ष्य निजी प्लेयर्स द्वारा घोषित परियोजनाओं और कैपेक्स खर्च में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। प्रमुख उद्योग सीईओ के सर्वेक्षण भी कैपेक्स बढ़ाने के लिए उनकी योजनाओं और प्रतिबद्धता को प्रकट करते हैं।

4 https://rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspxId=15369
5 https://www.nipfp.org.in/media/medialibrary/2014/02/WP_2013_125.pdf
6 https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Crowding-Out-or-Crowding-In-Public-and-Private-Investment-in-India-43470

चित्र 1.22 : कैपेक्स पिछले पांच वर्षों में दोगुना हो गया

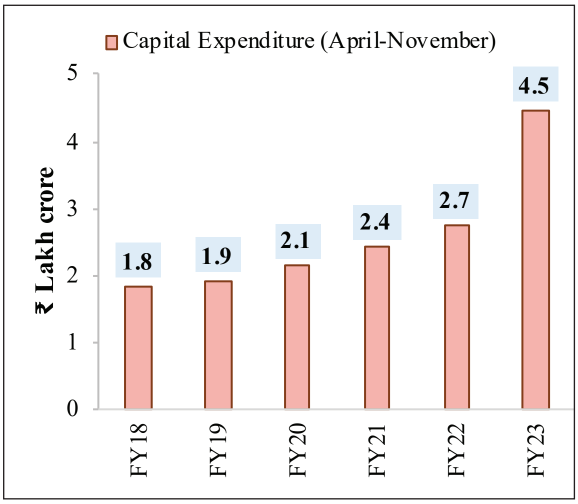

स्रोत: सीजीए

चित्र 1.23 : निजी निवेश आशा के अनुरूप बना हुआ है

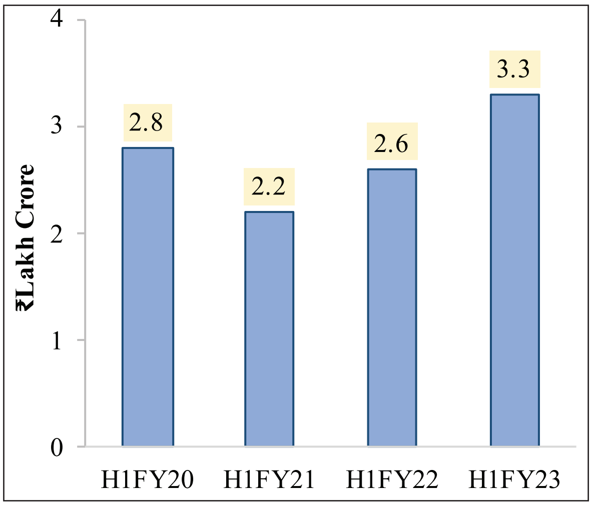

स्रोत: कैपिटल लाइन, एक्सिस बैंक रिसर्च

चित्र 1.24 : कर संग्रह में उछाल (अप्रैल-नवंबर)

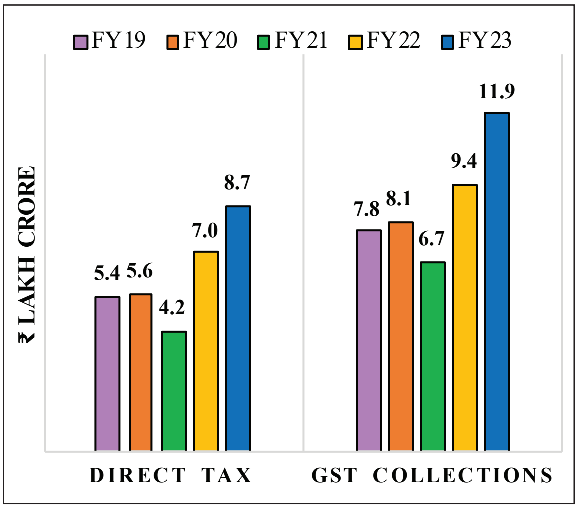

स्रोत: सीजीए

चित्र 1.25 : राजस्व व्यय में सीमित वृद्धि

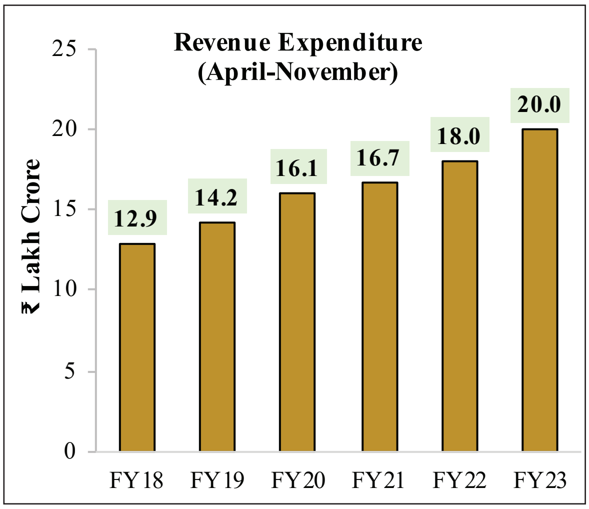

स्रोत: सीजीए

1.22 जबकि, निर्यात संबंधी मांग में वृद्धि, खपत में उछाल और सार्वजनिक कैपेक्स ने कॉरपोरेट्स की निवेश/विनिर्माण संबंधी गतिविधियों को प्रभावित किया, अत: उनकी मजबूत बैलेंस शीट ने भी उनकी व्ययगत योजनाओं को साकार करने में समान योगदान दिया है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के गैर-वित्तीय ऋण के आंकड़ों के अनुसार, पिछले दशक के दौरान, भारतीय गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र ऋण में और गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ऋण में सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में लगभग तीस प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है। इसने ब्याज लागत में वृद्धि को सीमित कर दिया, जिसने लॉकडाउन के दौरान ओवरहेड्स पर संभावित बचत के साथ, उच्च लाभ द्वारा कॉर्पोरेट बैलेंस शीट के हाल के सुदृढ़ीकरण में योगदान दिया। वित्तीय वर्ष 22 में, निर्यात में उछाल ने कॉर्पोरेट जगत में बढ़ते मुनाफे में भी योगदान दिया। वर्ष 2019 में घोषित निम्नतर करों ने करोपरांत लाभ को जबर्दस्त

बढ़त प्रदान किया है। बेहतर लाभप्रदता ने कॉरपोरेटों को कर्ज का भुगतान करने में मदद की है। परिणामस्वरूप, कॉरपोरेट्स के पास न केवल अब उधार लेने के अधिक अवसर उपलब्ध हैं, बल्कि उनके बेहतर वित्तीय स्वास्थ्य ने उनके संभावित उधारदाताओं को अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो में विस्तार करने के प्रति आश्वस्त किया है। एक्सिस बैंक बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार, बिजली, स्टील, रासायन, ओटो और फार्मास्युटिकल्स क्षेत्रों में भारी निवेश से वित्तीय वर्ष 2022 में निजी कैपेक्स बढ़कर 3.3 लाख करोड़ हो गया।

1.23 भारत के बैंकिंग क्षेत्र ने ऋण की मांग के अनुरूप कार्रवाई की है। वर्ष 2022 की जनवरी–मार्च तिमाही से वर्ष–दर–वर्ष ऋण में वृद्धि दोहरे अंकों में पहुंच गई है और यह अधिकांश क्षेत्रों में बढ़ रही है। केंद्र सरकार के विस्तृत ईसीएलजीएस की सहायता से, जनवरी–नवंबर 2022 के दौरान, एमएसएमई क्षेत्र में ऋण वृद्धि उल्लेखनीय रूप से 30.5 प्रतिशत से अधिक रही है। बैंकिंग क्षेत्र के बेहतर वित्तीय स्वास्थ्य ने उनके द्वारा की जाने वाली ऋण की शीघ्र आपूर्ति को कॉरपोरेट्स की भांति ही प्रेरित किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्तपोषण में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है, जिसमें नियमित अंतराल पर मुनाफा दर्ज किया जा रहा है और शीघ्र समाधान/परिशोधन के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा उनके गैर–निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को तेजी से ट्रैक किया जा रहा है। साथ ही, सरकार पीएसबी को भलीभांति पूंजीगत बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करते हुए पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान कर रही है, कि उनका पूंजी जोखिम–भारित समायोजित अनुपात (सीआरएआर) सुगमतापूर्वक पर्याप्तता के प्रारंभिक स्तर से ऊपर रहता है। बैंकिंग क्षेत्र पर किए गए सफल मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट भी इसकी वित्तीय क्षमता को प्रमाणित करते हैं। इससे यह मदद मिलती है कि जब मुद्रा जोखिम अधिक होता है तो बैंकिंग क्षेत्र में सीमा से अधिक दावे कम होते हैं। कदाचित, वित्तीय मजबूती ने बैंकों को वित्तीय वर्ष 2023 में अब तक कॉर्पोरेट बॉन्ड और बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के माध्यम से हुए कम ऋण का वित्तपोषण करने में मदद मिली है। कॉरपोरेट बॉन्ड पर अस्थिर आश्रय और ईसीबी पर उच्च ब्याज/हेजिंग लागत ने इन लिखतों को पिछले वर्ष की तुलना में कम आकर्षक बना दिया है।

चित्र 1.26 : एमएसएमई के बैंक ऋण में दोहरे अंकों में वृद्धि

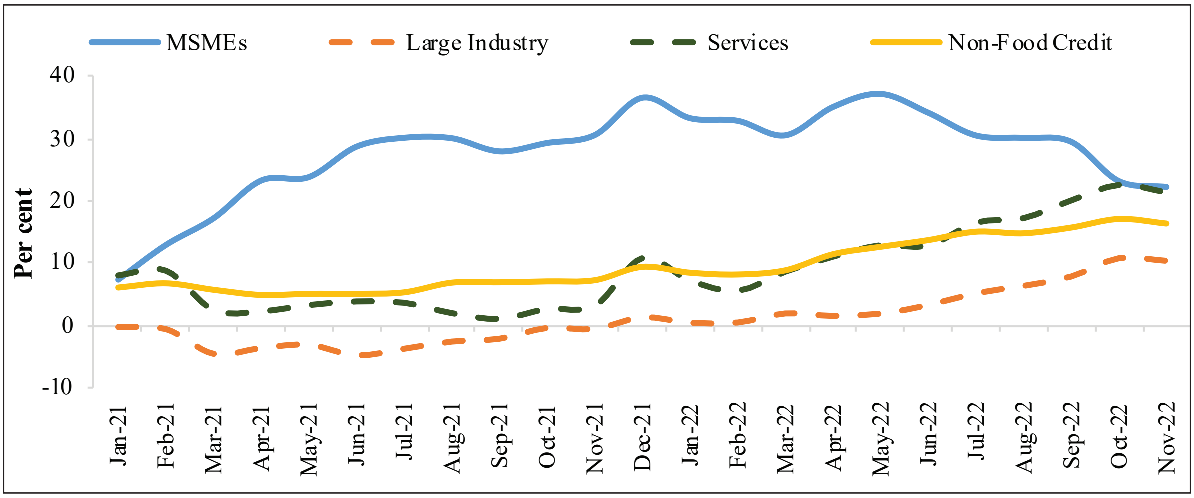

स्रोतः आरबीआई

चित्र 1.27 एससीबी के जीएनपीए अनुपात में गिरावट

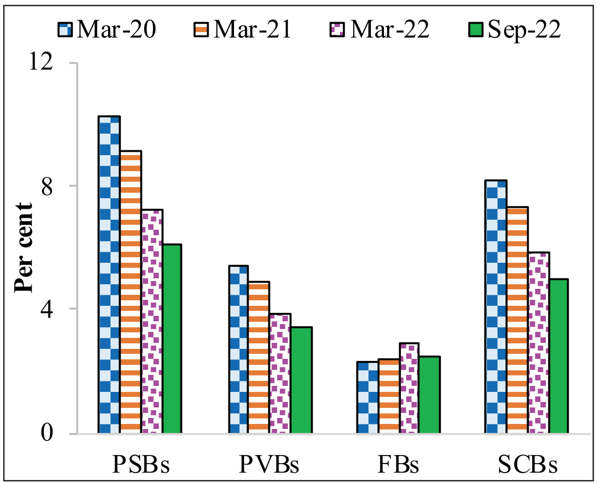

चित्र 1.28 : प्रावधान (प्रोविजनिंग) कवरेज अनुपात

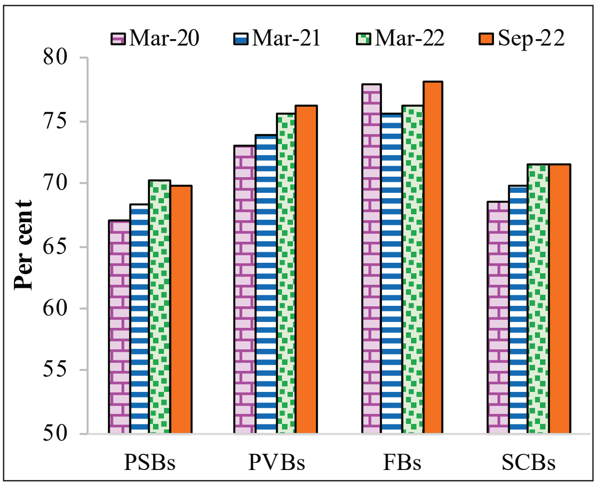

स्रोतः आरबीआई

नोटः एससीबी का अर्थ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, पीएसबी का अर्थ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पीवीबी का अर्थ निजी क्षेत्र के बैंक तथा एबी का अर्थ विदेशी बैंक है।

चित्र 1.29 : बढ़ता कॉरपोरेट बॉन्ड प्रतिफल

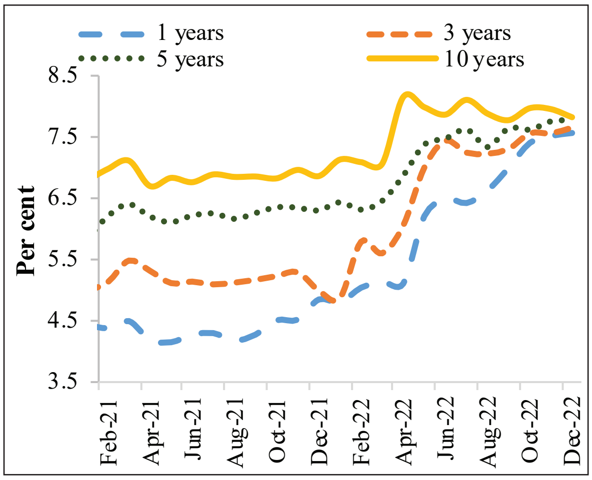

स्रोतः सीएमआईई

चित्र 1.30 : कॉरपोरेट बॉन्ड के निजी नियोजन में कमी

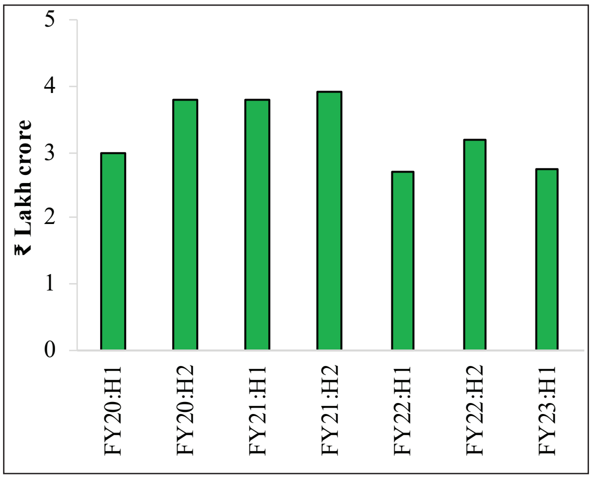

स्रोतः सेबी

चित्र 1.31 : उच्च ब्याज/हेजिंग लागत में ईसीबी और एसीसीबी को निधियों का कम आकर्षक स्रोत बना दिया

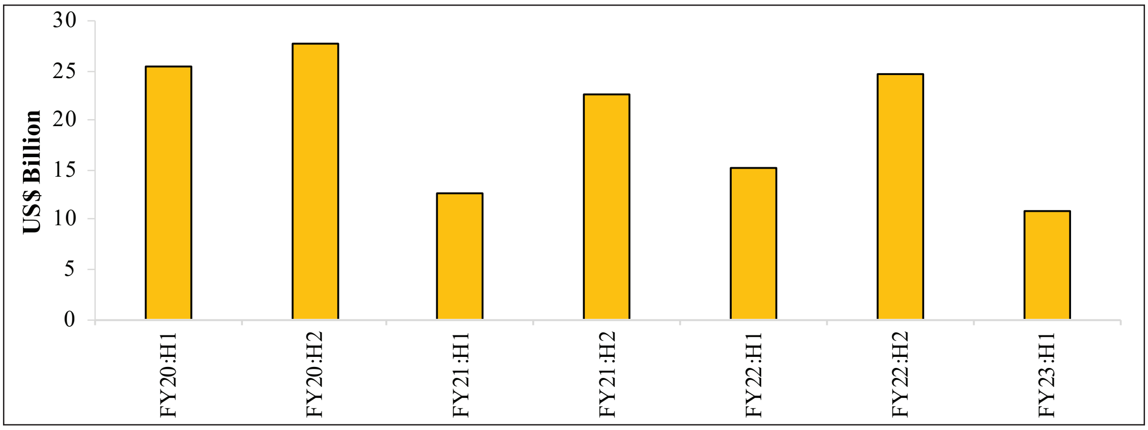

स्रोतः आरबीआई

1.24 आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2023 में हेडलाइन मुद्रास्फीति के 6.8 प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है, जो लक्षित सीमा के बाहर है। वहीं, यह इतना अधिक नहीं है जो निजी खपत को रोके और इतना कम नहीं है कि निवेश करने की प्रेरणा को कमजोर कर सके। भारत में सामान्य रूप से उच्च मुद्रास्फीति ने मांग में कमी करके और कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए विकास के माध्यम से मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं की स्थिरता सुनिश्चित की है। इसके अतिरिक्त, मुद्रास्फीति में गिरावट होने से घरेलू ऋण की ब्याज लागत में भी गिरावट होगी और कॉरपोरेट्स तथा खुदरा उधारकर्ताओं द्वारा की जाने वाली ऋण की मांग में और वृद्धि होगी।

चित्र 1.32 : मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं की स्थिरता

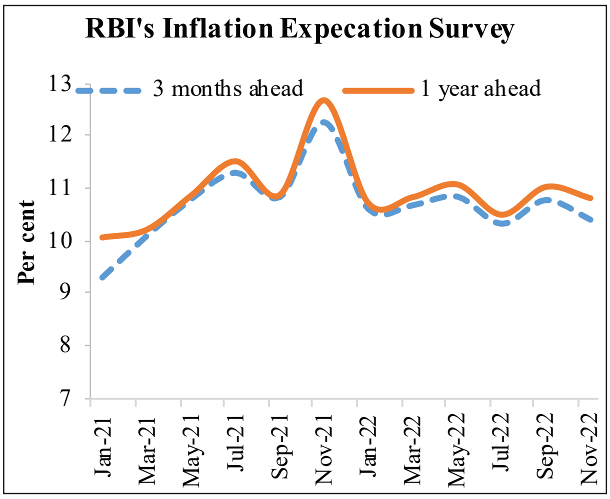

स्रोतः आरबीआई

स्रोतः आईआईएमए

भारत का समावेशी विकास

1.25 विकास तब समावेशी होता है जब यह रोजगार सृजित करता है। आधिकारिक और गैर-अधिकारिक दोनों स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि चालू वित्त वर्ष में रोजगार के स्तर में वृद्धि हुई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से पता चलता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही में 9.8 प्रतिशत से घटकर एक वर्ष बाद (सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही में) 7.2 प्रतिशत हो गई। इसके साथ-साथ श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में भी सुधार हुआ है, जो वित्त वर्ष 2023 की शुरुआत में अर्थव्यवस्था के महामारी से प्रेरित मंदी से उभरने की पुष्टि करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्यात में प्रारंभिक वृद्धि, ''पेंट-अप'' मांग की एक ठोस निर्मुक्ति और कैपेक्स के तेजी से रोलआउट के कारण नौकरी का सृजन करना कठिन हो गया है। चूंकि निर्यात वृद्धि स्थिर हो रही है और मांग की ''पेंट-अप'' निर्मुक्ति हो जाएगी, अतः यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार को सुगम बनाने के लिए कैपेक्स में कम से कम ऐसे समय तक वृद्धि होती रहे जब तक कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में वापस वृद्धि शुरू न हो जाए और निर्यात चौनल के माध्यम से, रोजगार सृजन के लिए भारत को एक अतिरिक्त अवसर प्राप्त न हो जाए। भला हो, निजी क्षेत्र ने सभी आवश्यक पूर्व शर्तें तैयार कर ली हैं ताकि रोजगार को बढ़ावा मिले और कैपेक्स में भारी वृद्धि हो। उनका आंतरिक संसाधन सृजन अच्छा है; क्षमता उपयोग उच्च है, और मांग परिदृश्य में सुधार होता रहता है। पूंजीगत बाजार वित्तीय संस्थानों की तरह नए निवेशों को वित्तपोषित करने के इच्छुक हैं।

1.26 वित्तीय वर्ष 21 में, सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की घोषणा की। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय संकट से बचाने में सफल रही है। सिबिल की एक हालिया रिपोर्ट (इसीएलजीएस अंतर्दृष्टि, अगस्त 2022) ने दिखाया कि इस योजना ने एमएसएमई को कोविड झटके का सामना करने में मदद की है, जिसमें 83 प्रतिशत उधारकर्ताओं ने ईसीएलजीएस का सूक्ष्म-उद्यमों के रूप में लाभ उठाया

है। इन सूक्ष्म इकाइयों में, आधे से अधिक का समग्र जोखिम ₹ 10 लाख से कम था। इसके अलावा, सिबिल डेटा से यह भी पता चलता है कि ईसीएलजीएस उधारकर्ताओं की अनुपयोज्य संपत्ति दरें उन उद्यमों की तुलना में कम थीं जो ईसीएलजीएस के लिए पात्र थे, लेकिन इसका लाभ नहीं उठाया। इसके अलावा, वित्त वर्ष 21 में गिरावट के बाद एमएसएमई द्वारा भुगतान किया गया जीएसटी तब से बढ़ रहा है और अब वित्तीय वर्ष 20 के पूर्व–महामारी स्तर को पार कर गया है, जो छोटे व्यवसायों की वित्तीय लचीलापन और एमएसएमई के लिए लक्षित सरकार के हस्तक्षेप की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

चित्र 1.33 : शहरी बेरोजगारी पांच वर्षों के निम्नतम स्तर पर

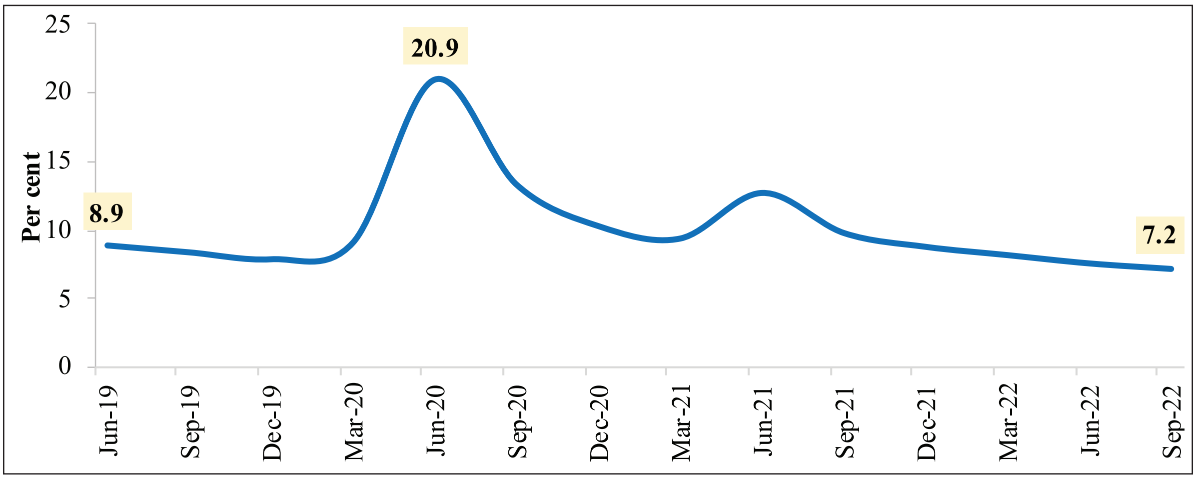

Source: NSO, MoSPI

चित्र 1.34 : वित्तीय वर्ष 2022 में एमएसएमपी द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी में महामारी- पूर्व के स्तर को पार किया

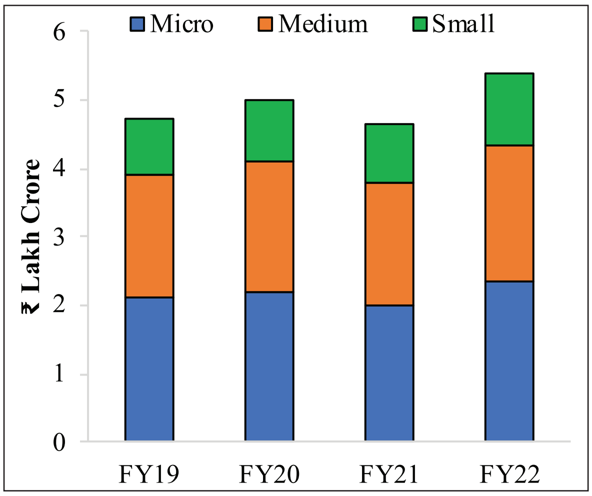

स्रोतः वित्त मंत्रालय

नोटः इसमें 1000 करोड़ रु. तक के टर्नओवर वाली फर्म शामिल है। सूक्ष्म .ढ= 25 करोड़; लु ढ= 25 से 100 करोड़; मध्यम 100 से 1000 करोड

चित्र 1.35 ईसीएलजीएस में एमएसएमई को अपनी सम्पत्ति की गुणवत्ता को सुधारने में सहायता की

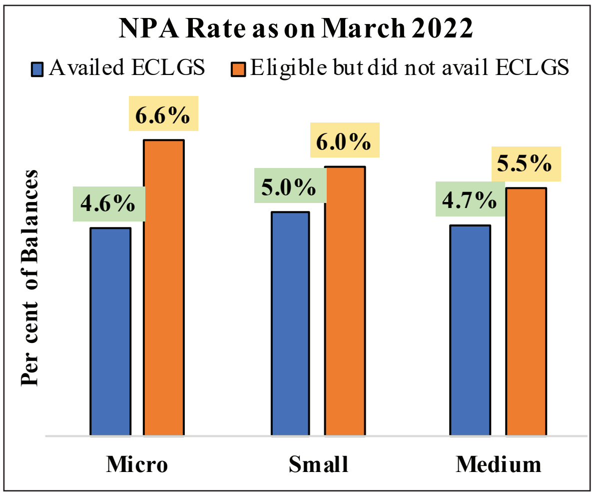

स्रोतः ईसीएलजीएस निरीक्षण रिपोर्ट, ट्रांसयूनियन सीबिल, अगस्त 2022

1.27 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत सरकार द्वारा लागू की गई योजना किसी भी अन्य श्रेणी की तुलना में ''व्यक्तिगत भूमि पर काम'' के संबंध में तेजी से अधिक संपत्ति का सृजन कर रही है। वित्तीय वर्ष 2022 में इस श्रेणी की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत हो गई, जो

यह दर्शाती है कि मनरेगा, दैनिक मजदूरी रोजगार पैदा करने के अलावा, व्यक्तिगत परिवारों के लिए भी उनकी आय के स्रोतों में विविधता लाने और उनकी पूरक आय बढ़ाने के लिए संपत्ति का सृजन कर रहा है। मनरेगा के तहत संपत्ति सृजन के विवरण पर आगे अध्याय- ''संख्या'' सामाजिक अवसंरचना और रोजगार'' बिग टेंट में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण आबादी के आधे हिस्से को कवर करने वाले परिवारों के लिए लाभकारी पीएम-किसान जैसी योजनाएं और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ने देश में गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जुलाई 2022 की यूएनडीपी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हाल ही में मुद्रास्फीति के प्रकरण में अच्छे लक्षित समर्थन के कारण गरीबी पर कम प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) वित्तीय वर्ष 2016 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 में ग्रामीण कल्याण संकेतकों में सुधार को दर्शाता है, जिसमें लिंग, प्रजनन दर, घरेलू सुविधाओं और महिला सशक्तिकरण जैसे पहलुओं को कवर किया गया है।

चित्र 1.36 : ग्रामीण कल्याण सूचकांको में सुधार

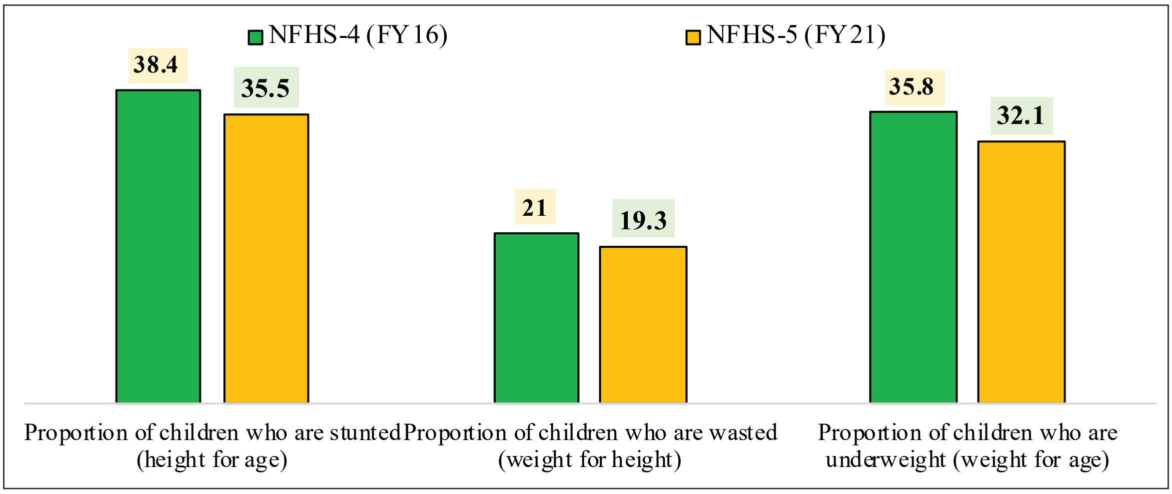

स्रोत: एनएफएचएस-4 और एनएफएचएस-5

1.28 भारत के लिए अब तक वित्तीय वर्ष 2023 ने आर्थिक लचीलापन के प्रति देश के विश्वास को मजबूत किया है। अर्थव्यवस्था ने इस प्रक्रिया में विकास की गति को खोए बिना रूसी-यूक्रेन सांर्ष के कारण हुए बाहरी असंतुलन को कम करने की चुनौती का सामना किया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा की गई निकासी से प्रभावित हुए बगैर चालू वर्ष 2022 में भारत के शेयर बाजारों में सकारात्मक वापसी हुई। कई उन्नत देशों और क्षेत्रों की तुलना में भारत की मुद्रास्फीति दर अपनी लक्षित सीमा से बहुत अधिक नहीं बढ़ी। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक अपेक्षाकृत उच्च विकास पूर्वानुमान, अनुमानित खुदरा मुद्रास्फीति केवल लक्षित सीमा से थोड़ी अधिक होना और सामान्य पूंजी प्रवाह के साथ वित्तपोषित एक अनुमानित चालू खाता घाटा तथा एक वर्ष के आयात के वित्तीय समापन के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार एक बहुसंकट वाली वैश्विक विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक लचीलापन के स्पष्ट प्रमाण हैं। एक मजबूत खपत पलटाव, ठोस राजस्व संग्रह, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में निरंतर कैपेक्स, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते रोजगार के स्तर में वृद्धि और लक्षित सामाजिक सुरक्षा उपाय आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता तथा निरंतर विकास की संभावनाओं को और अधिक मजबूत करते हैं। क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार विनिमय दरों में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इतने बड़े एक राष्ट्र की अपेक्षा के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगभग उसे 'पुन:प्राप्त' किया है जो खो गया था, उसे ''नवीनीकृत'' किया है जो रुका हुआ था, और उसे ''पुन: सक्रिय'' किया है जो वैश्विक महामारी के दौरान और यूरोप में सांर्ष के बाद से धीमा हो गया था।

आउटलुक 2023-24

1.29 वैश्विक महामारी से भारत की रिकवरी अपेक्षाकृत तेज थी और आगामी वर्ष में ठोस घरेलू मांग और पूंजी निवेश में सुधार से विकास मिलेगा। वर्तमान विकास की गति को पिछले कुछ वर्षों में लागू किए गए अनेक संरचनात्मक परिवर्तनों से बल मिलेगा। निजी क्षेत्र - वित्तीय और गैर-वित्तीय - बैलेंस शीट में सुधार कर रहा था, जिसके कारण पिछले दशक में पूंजी निर्माण में मंदी आई थी। पहले दशक में दखी गई उधारी के उछाल के कारण सहस्राब्दी के दूसरे दशक में निर्मित वित्तीय प्रणाली का तनाव अब हमारे पीछे है, जिसका साक्ष्य है अनुपयोज्य आस्तियों में वृद्धि, निम्न ऋण संवृद्धि और पूंजी संरचना की घटती संवृद्धि दरें, जो प्रथम दशक से अधिक में देखा गया था। स्वस्थ वित्तीय सहायता से, एक नए निजी क्षेत्र के पूंजी निर्माण चक्र के शुरुआती संकेत दिखाई दे रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूंजीगत व्यय में निजी क्षेत्र की चिंता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने पूंजीगत व्यय में काफी वृद्धि की। वित्तीय वर्ष 2016 से वित्तीय वर्ष 2023 तक पिछले सात वर्षों में बजटीय पूंजीगत व्यय 2.7 गुना बढ़ गया, जिससे कैपेक्स चक्र पुनः सक्रिय हो गया। वस्तु एवं सेवा कर और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता जैसे संरचनात्मक सुधारों ने अर्थव्यवस्था की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाया तथा वित्तीय अनुशासन एवं बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया।

चित्र 1.37 : वैश्विक आर्थिक वृद्ध और व्यापार में मंदी

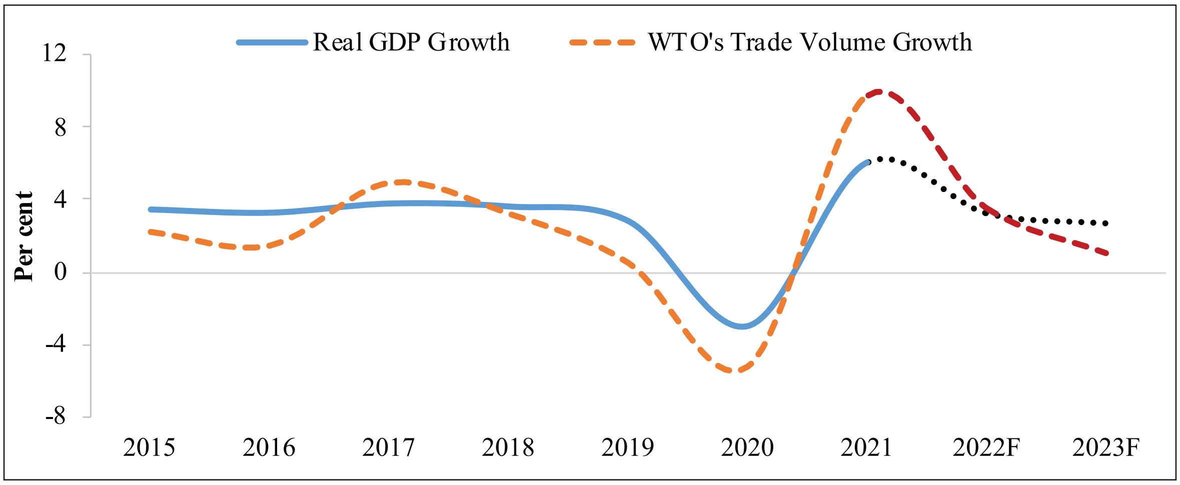

स्रोत: आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ

1.30 जबकि भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है, अगले वर्ष के लिए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर विशेष प्रकार की चुनौतियों के संयोजन का बोझ है, जिससे गिरावट होने वाले जोखिम की संभावना है। बहु-दशकीय उच्च मुद्रास्फीति के अंको ने दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को वित्तीय शर्तों को सख्त करने के लिए मजबूर किया है। आर्थिक सख्ती का असर धीमी आर्थिक गतिविधियों, विशेषकर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में दिखने लगा है। इसके अलावा, आपूर्ति श्रृंखलाओं में लंबे समय तक रहे तनाव से प्रतिकूल स्पिलओवर और भू-राजनीतिक सांर्ष के कारण बढ़ी अनिश्चितता ने वैश्विक दृष्टिकोण को और अधिक खराब कर दिया है। इसलिए, आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जनवरी 2023 के अनुसार, वैश्विक विकास का वर्ष 2022 में 3.2 प्रतिशत से धीमा होकर वर्ष 2023 में 2.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। आर्थिक उत्पादन में धीमी वृद्धि के साथ बढ़ती अनिश्चितता व्यापार वृद्धि को कम कर देगी। इसे वैश्विक व्यापार में वृद्धि के संबंध में विश्व व्यापार संगठन द्वारा किए गए कम पूर्वानुमान में देखा गया है, जिसकी आईएमएफ वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलूक, अक्तूबर, 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में 3.5 प्रतिशत से घटकर 2023 में 1.0 प्रतिशत होने की संभावना है।

1.31 बाह्य दृष्टि से, चालू लेखा शेष के जोखिम अनेक स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। जबकि वस्तुओं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से कम हो गई हैं, वे अभी भी सांर्ष-पूर्व के स्तर से ऊपर हैं। वस्तुओं की उच्च कीमतों के बीच मजबूत घरेलू मांग से भारत के कुल आयात बिल में वृद्धि होगी और चालू खाता शेष में अलाभकारी विकास को बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक मांग में कमी के कारण निर्यात वृद्धि को स्थिर करके इन्हें और बढ़ाया जा सकता है। यदि चालू लेखा घाटे में और वृद्धि होती है तो मुद्रा पर मूल्यह्रास का दबाव बढ़ेगा।

1.32 जारी आर्थिक सख्ती की प्रक्रिया से उक्त दृष्टिकोण के लिए एक और जोखिम उत्पन्न होता है। जबकि मूल्य वृद्धि की गति धीमी हो गई है, तथापि प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति पर अपने आक्रामक रुख की पुष्टि की है। बढ़ी हुई मुद्रास्फीति सख्ती की प्रक्रिया को लंबा कर सकती है, और इसलिए, उधार लेने की लागत 'लंबे समय तक अधिक' रह सकती है। ऐसे परिदृश्य में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष-2024 में कम वृद्धि हो सकती है। तथापि धीमे वैश्विक विकास के परिदृश्य से दो उम्मीदें पैदा होती हैं - तेल की कीमतें कम रहेंगी, और भारत का सीएडी वर्तमान के स्तर से बेहतर होगा। कुल मिलाकर बाहरी स्थिति नियंत्रण में रहेगी।

1.33 भारत के विकास के दृष्टिकोण का बेहतर पक्ष (i) चीन में कोविड-19 संक्रमणों में मौजूदा उछाल से शेष दुनिया के लिए सीमित स्वास्थ्य और आर्थिक समस्या और इसलिए, आपूर्ति श्रृंखलाओं का सामान्यीकरण जारी है; (ii) चीन की अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने से मुद्रास्फीति संबंधी आवेग न तो महत्वपूर्ण और न ही लगातार बने रहे; (iii) प्रमुख एई में मंदी की प्रवृत्ति ने मौद्रिक तंगी की समाप्ति और 6 प्रतिशत से नीचे स्थिर घरेलू मुद्रास्फीति दर के बीच भारत में पूंजी प्रवाह की वापसी शुरू की; और (iv) इससे उत्साह में सुधार हुआ और निजी क्षेत्र के निवेश को और प्रोत्साहन मिला, से मिलता है।

1.34 इस पृष्ठभूमि में, सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2024 में सामान्यत: बेसलाइन जीडीपी में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमान विस्तृत तौर पर विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबी जैसी बहुपक्षीय और आरबीआई जैसी घरेलू एजेंसियों द्वारा किए गए अनुमानों के बराबर है। वास्तविक जीडीपी संवृद्धि का वास्तविक परिणाम संभवत: 6.0 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के बीच रहेगा, जो वैश्विक स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक विकास की गति पर निर्भर करेगा।

******

भारत का मध्यावधि विकास परिदृश्यः आशापूर्ण दृष्टि और उम्मीद के साथ

02

अध्याय

भारत के आर्थिक इतिहास में वर्ष 2014-2022 एक महत्वपूर्ण अवधि रही है। अर्थव्यवस्था व्यापक संरचनात्मक और प्रशासनिक में सुधारों के दौर से गुजरी, जिसमें अर्थव्यवस्था की समग्र दक्षता बढ़ी और अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत सशक्त हुए। यह प्रणाली ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस के सुधारों पर बल देने सहित सार्वजनिक वस्तुओं के निर्माण, विश्वास-आधारित शासन को अपनाने, विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ सह-भागीदारी और कृषि उत्पादकता में सुधार के व्यापक सिद्धांतों पर आधारित थी। सामान्य परिस्थितियों में, इस तरह के पैमाने और प्रासंगिक सुधारों से आर्थिक विकास में तेजी आएगी। हालांकि, मोटे तौर पर पिछले वर्षों में क्रेडिट बूम के फलस्वरूप बैलेंस शीट के दबाव के कारण और दूसरी बार के वैश्विक संकटों के कारण, प्रमुख मैक्रोइकॉनॉमिक वैरिएबल, जैसे कि क्रेडिट ग्रोथ, पूंजी निर्माण का आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अलावा, कुछ सुधारों के परिणाम आने में देरी होती है चूंकि अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के सुधारों के प्रसार में समय लगता है।

यह स्थिति 1998-2002 की अवधि के अनुरूप है क्योंकि उस समय भी सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनकारी सुधारों ने अर्थव्यवस्था में अस्थायी आघातों के कारण विकास प्रतिफल को कम कर दिया था। आघातों के कम होने के बाद संरचनात्मक सुधारों ने 2003 से विकास लाभांश का प्रतिफल देना शुरू कर दिया था। इसी तरह, वर्तमान दशक में, मजबूत मध्यावधि ग्रोथ मैग्नेट्स से हमें आशावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है और उम्मीद है कि एक बार जब महामारी के वैश्विक आघातों के कारण 2022 में वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों में कमी आनी शुरू हो जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले दशक में तेजी से बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगी। बैंकिंग, गैर-बैंकिंग और कॉर्पोरेट क्षेत्रों की बेहतर और स्वस्थ बैलेंस शीट के साथ, एक नया ऋण-चक्र (क्रेडिट साईकल) पहले ही शुरू हो चुका है, जो पिछले महीनों में बैंक ऋण में दो अंकों की वृद्धि से स्पष्ट झलकता है। इसके अतिरिक्त, अधिक औपचारिकता, उच्च वित्तीय समावेशन, और डिजिटल प्रौद्योगिकी-आधारित आर्थिक सुधारों द्वारा मिले आर्थिक अवसरों के परिणामस्वरूप दक्षता लाभ से अर्थव्यवस्था को फायदा मिलना शुरू हो गया है। इस प्रकार, भारत का विकास दृष्टिकोण पूर्व-महामारी के वर्षों की तुलना में बेहतर प्रतीत होता है, और भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यावधि में अपनी क्षमता से बढ़ने के लिए तैयार है।

परिचय

2.1 भारत पिछले आठ वर्षों के दौरान नए युग के सुधारों के क्रान्तिकारी परिवर्तन से गुजरा है। इन सभी विविध सुधारों से अर्थव्यवस्था की समग्र दक्षता में सुधार होता है और इसके संभावित विकास को बढ़ावा मिलता है। अर्थव्यवस्था और उसके लोगों की उत्पादक क्षमता को उजागर करने के व्यापक नीतिगत लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन सुधारों का उद्देश्य, मौलिक स्तर के जीवनयापन और व्यापार करने में सुविधा को बढ़ाना है। विशेष रूप से डिजिटल प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी का उपयोग, सुधारों को रेखांकित करता है। सुधारों से मिली आर्थिक ऊर्जा और सकारात्मक मानसिकता के फलस्वरूप तीव्र गति से विकास हुआ, परन्तु घरेलू वित्तीय क्षेत्र (बैंकिंग

और गैर-बैंकिंग) अधिक वरीयता दी और कॉर्पोरेट क्षेत्र; वह दूसरा क्षेत्र था, जिसने एक बार के वैश्विक आघातों का सामना किया।

2.2 देश में शुरू किए गए स्थायी संरचनात्मक और शासन सुधारों की गति और मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता, भारत के मध्यम अवधि के विकास के दृष्टिकोण को नियंत्रित करना आवश्यक है। क्या एक बार के आघातों को उभरने के बाद अर्थव्यवस्था स्थिर विकास दर हासिल कर लेगी और उसे बनाए रखेगी? इस अध्याय में इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया गया है और इसका यह निष्कर्ष है कि भारत की अपनी क्षमता संबंधी संवर्धन और संभावित विकास को बढाने की संभावना पिछले दो दशकों की तुलना में अधिक है। यह अध्याय पिछले तीन दशकों में भारत के उत्पाद और पूंजी बाजार सुधारों के इतिहास की संक्षिप्त चर्चा के साथ शुरू होता है। इनमें आगे चलकर 2014 से 2022 तक किए गए ऐतिहासिक सुधारों की व्यापक को सोच दर्शाया गया है और भारतीय अर्थव्यवस्था को इस अवधि के दौरान लगे आघातों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय के अंत में भारत के मध्यावधि विकास मैग्नेट्स पर चर्चा की गई है।

उत्पाद और पूंजी बाजार में सुधार

सुधारों की शुरुआत- 1991

2.3 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक के प्रारंभ के मैक्रोइकॉनॉमिक असंतुलन को लेकर सरकार ने 1991 के संरचनात्मक सुधारों को शुरू किया। केंद्र और राज्य सरकारों के उच्च संयुक्त घाटे, बढ़े हुए मुद्रास्फीति के दबाव, और बड़े और अस्थिर चालू खाता घाटे (सीएडी) के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन का संकट[1] पैदा हुआ। इस स्थिति के जवाब में, वर्ष 1991 में व्यापार और निवेश को उदार बनाया गया। लगभग सभी मध्यवर्ती इनफट और पूंजीगत वस्तुओं के आयात लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया और फर्मों के लिए प्रवेश प्रतिबंधों को सरल बना दिया गया। नई नीति ने सार्वजनिक क्षेत्र कई क्षेत्रों में के एकाधिकार को समाप्त किया और 51 प्रतिशत तक एफडीआई के लिए स्वत: अनुमोदन नीति शुरू करके निजी क्षेत्र की फर्मों के प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया। विनिमय दर को लचीला बनाया गया और प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार मूल्यह्रास की अनुमति दी गई। रुपये को चालू खाते में पूरी तरह से परिवर्तनीय और पूंजी खाते पर आंशिक रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया। इन सुधारों से अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। वास्तविक वृद्धि 1980 के दशक के दौरान औसतन 5.5 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 93 से वित्त वर्ष 2000 तक 6.3 प्रतिशत हो गई। बाह्य व्यापार पर व्यापार उदारीकरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ा क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद के लिए कुल माल और सेवा व्यापार वर्ष 1990 के 17.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2000 में 30.6 प्रतिशत हो गया।[2]

नए उत्साह के साथ सुधारों में निरंतरता

2.4 1990 के दशक के दौरान उत्पाद और पूंजी बाजार के सुधार धीरे-धीरे जारी रहे। उन्हें सरकार से दशक के अंत में एक नवीकृत प्रोत्साहन मिला। गैर-ऋण-सृजन पूंजी प्रवाह के मुख्य स्रोत के रूप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश को और अधिक उदार बनाया गया (चित्र 1)। नई दूरसंचार नीति 1991 द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में सपूंर्ण सुधार किया गया। सशक्त विनियामक व्यवस्था (ट्राई) के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए इस क्षेत्र को खोल दिया गया था। इन सुधारों ने सरकार के लाइसेंसिंग और नीति संबंधी कार्यों को ऑपरेटर (बीएसएनएल) से अलग कर दिया। ये सुधार भारत के आईटी क्षेत्र में आने वाली तेजी की आधारशिला थी और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के लिए अधिक व्यापक लाभकारी थे। इस अवधि के दौरान विनिवेश और निजीकरण की नीति ने भी गति पकड़ी। सरकार ने इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक समर्पित मंत्रालय का गठन किया। इसने कुछ सीपीएसई और निजीकृत कंपनियों जैसे मारुति उद्योग, हिंदुस्तान जिंक, भारत एल्युमिनियम और विदेश संचार निगम लिमिटेड में इक्विटी हिस्सेदारी बेची।

[1]भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास-खंड IV (https://www.rbi.org.in/scripts/RHvol-4.aspx)

[2]श्री अरविंद पनगढ़िया, 2004। "1980 और 1990 के दशक में भारत: सुधारों की जीत," आईएमएफ वर्किंग पेपर्स 2004/043, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। (https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp0443.pdf)

चित्र II.1 वर्ष 2000-2003 में निवेश के उदारीकरण को बढ़ावा देने के बाद भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि

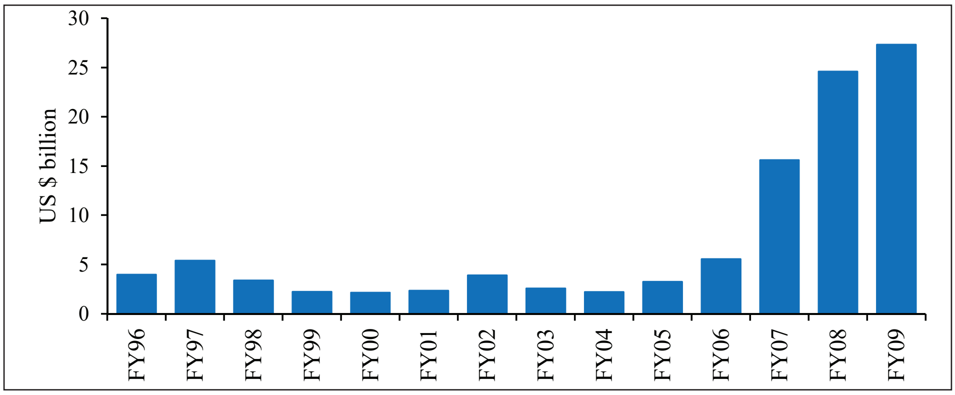

स्रोत: आरबीआई

2.5 इस अवधि में स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना, 'स्वर्णिम चतुर्भुज' की शुरुआत भी हुई। इस परियोजना से बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर औद्योगिक गतिविधि, व्यापार और आर्थिक विकास के माध्यम से देश को महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ हुआ।[3] इसके साथ ही व्यापक आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए ढांचागत नीतियां बनाई गईं। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम सरकार के संयुक्त सकल राजकोषीय घाटे के ऐतिहासिक उच्च स्तर से निपटने के लिए पारित किया गया था (चित्र II.2)। बैंकिंग प्रणाली, जिसने 1991 के सुधारों के बाद आर्थिक पुनरुत्थान की अवधि के दौरान अशोध्य ऋण जमा कर लिया था, को ब्याज दरों के अविनियमन और सरफेसी अधिनियम 2002 के अधिनियमन के माध्यम से समर्थित किया गया था। बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, जमाकर्ताओं को अधिक बैंकिंग विकल्प देने और मौद्रिक नीति संचरण को मजबूत करने के लिए ब्याज दरों को अविनियमित किया गया।[4] सरफेसी अधिनियम ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अदालतों/न्यायाधिकरणों के हस्तक्षेप के बिना उधारकर्ता/गारंटर की सुरक्षित संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई करके अपना बकाया वसूलने की अनुमति दी।[5] इन दोनों सुधारों ने अर्थव्यवस्था में ऋण की स्थिति में सुधार किया (चित्र II.3)।

चित्र II.2: सकल राजकोषीय घाटा (केंद्र और राज्यों को मिलाकर) (जीडीपी का %)

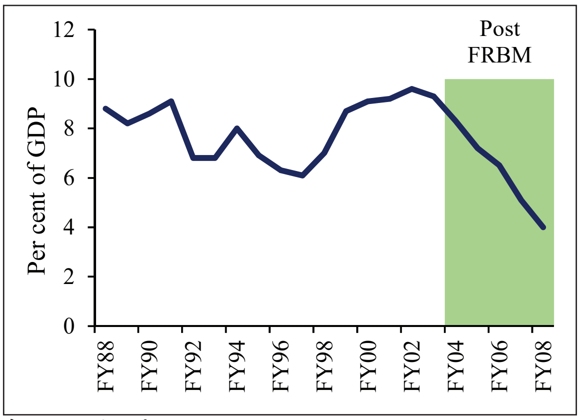

स्रोत: आरबीआई

चित्र II.3: कुल संपत्ति के : के रूप में एससीबी का सकल एनपीए

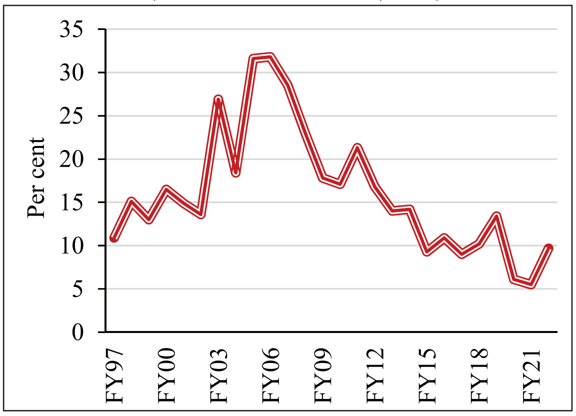

स्रोत: आरबीआई

[3]गनी, एजाज एंड ग्रोवर, आरती एंड केर, विलियम। (2012)। सफलता का मार्ग: भारतीय विनिर्माण के स्थान और प्रदर्शन के लिए स्वर्णिम चतुर्भज परियोजना का प्रभाव। द इकोनॉमिक जर्नल। (https//onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ecoj.12207)

[4]भारतीय रिज़र्व बैंक आरबीआई, 2011. "बचत बैंक जमा ब्याज दर का अविनियमन: एक चर्चा पत्र," वर्किंग पेपर्स आईडी: 3959, ईसोशलसाइंसेज। (https//rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/DPS2770411F.pdf)

[5]विनोद कुमार, और राजीव खोसला। (2017)। सरफेसी अधिनियम 2002 का कार्यान्वयन और प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और अनुसंधान जर्नल (IERJ), 3(5) । https//ierj.in/journal/index.php/ierj/article/view/863/869 https//pib.gov.in PressReleasePage.aspx?PRID=1578808

एक आघात से 1998-2002 के सुधार हो गए

2.6 इन सुधारों की अवधि में घरेलू और वैश्विक आघातों की एक श्रृंखला भी देखी गई, जिसने निवेशकों के विश्वास को कमजोर कर दिया। भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण परमाणु परीक्षणों के बाद के महीनों के दौरान भारत में पूंजी प्रवाह में तेजी से गिरावट आई (चित्र II.4)[6]। वर्ष 2000 और 2002 के बीच की अवधि में लगातार दो सूखे भी देखे गए (तालिका II.1)। इन घरेलू आघातों से तकनीकी में आए उछाल की समाप्ति और 9/11 के हमलों (चित्र II.5) के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितताएँ थीं। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान भारतीय वित्तीय प्रणाली और कॉर्पोरेट क्षेत्र के तुलन-पत्र को ठीक किया जा रहा था (चित्र II.5)। हालांकि इन सभी कारकों ने सरकार द्वारा किए गए सुधारों के तत्काल प्रभाव को कम कर दिया, लेकिन उन्होंने इसकी आधार रखा और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक उछाल में भाग लेने के लिए संरचनात्मक रूप से तैयार किया, जो इसके तुरंत बाद फलीभूत हुआ।

Figure II.4: Monthly Foreign Direct Investment came down (1998)

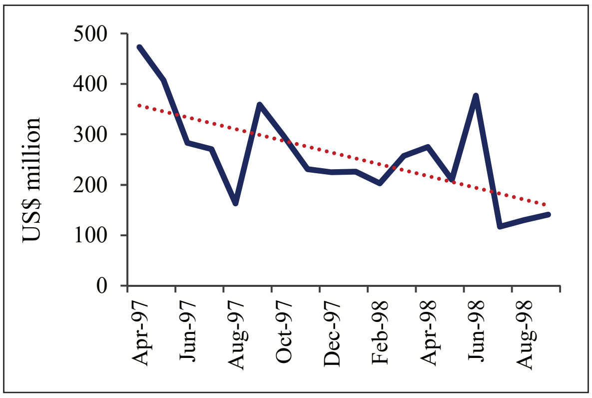

स्रोत: आरबीआई

Figure II.5: Trends in the NASDAQ Composite index (Dot-Com Bubble crisis)

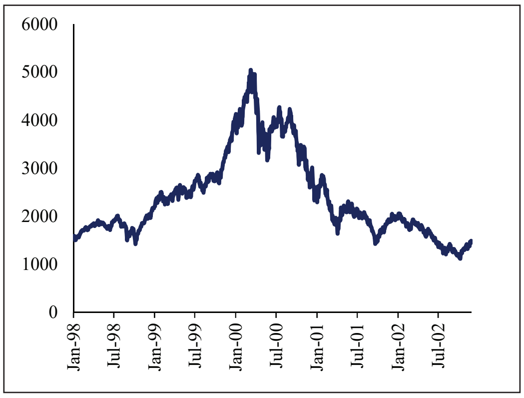

स्रोत: एफआरईडी

तालिका 1: वर्ष 2000 और 2002 के बीच भारत में सूखे की घटना, प्रभावित लोगों की संख्या और नुकसान

तारीख	स्थान	संख्या
अप्रैल 2000	गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र	प्रभावित-9 करोड़; नुकसान- 588,000,000 अमेरिकी डॉलर
नवंबर 2000	महासमुंद, रायपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग जिले (छत्तीसगढ़ क्षेत्र)	
मई 2001	नई दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा	20 मौत
जुलाई 2002	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु	प्रभावित-30 करोड़; नुकसान-910,721,000 अमेरिकी डॉलर

स्रोत: सामरा, जे.एस., 2004 ''भारत में सूखे की निगरानी, घोषणा और प्रबंधन की समीक्षा और विश्लेषण,'' आईडब्ल्यूएमआई वर्किंग पेपर्स H035617] अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान। (https://www.preventionweb.net/files/1868.VL102135.pdf)

[6]डेनियल मॉरो और माइकल कैरीयर) 1999 (भारत और पाकिस्तान पर 1998 के प्रतिबंधों के आर्थिक प्रभाव, अप्रसार समीक्षा, 6:4, 1-16)। (https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/npr/morrow64.pdf)

2003-08 के वैश्विक उछाल में भारत की भागीदारी

2.7 इन आघातों के समाप्त होने के बाद वर्ष 1998-2002 के सुधारों का विकास लाभांश देखा गया। संरचनात्मक सुधारों के वर्षों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक विकास में योगदान देने और इससे लाभान्वित होने के लिए तैयार किया था। जबकि 2003-2008 के दौरान वैश्विक विकास औसतन 4.8 प्रतिशत रहा, भारतीय अर्थव्यवस्था औसतन 8 प्रतिशत से अधिक बढ़ी। इस अवधि के दौरान आर्थिक विकास को मजबूत पूंजी प्रवाह (चित्र II.1) भी मिला गया था, जिसने अनुकूल घरेलू और बाहरी कारकों का संकेत दिया था। इनमें से कुछ में घरेलू आर्थिक गतिविधि में निरंतर गति, बेहतर कॉर्पोरेट प्रदर्शन, एक अनुकूल निवेश माहौल, पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में भारत के लिए सकारात्मक भावना और वैश्विक तरलता की स्थिति/ब्याज दरों को प्रोत्साहित करना शामिल है।[7] वर्तमान में आर्थिक विकास के अपने पिछड़े प्रभाव के साथ संरचनात्मक आर्थिक सुधारों का यह संयोजन भारतीय अर्थव्यवस्था के समानांतर है।

नए भारत के लिए सुधार - सबका साथ सबका विकास

2.8 वर्ष 2014 से पहले किए गए सुधार मुख्य रूप से उत्पाद और पूंजी बाजार क्षेत्र के लिए किए गए थे। ये आवश्यक थे और इसे 2014 के बाद भी इन्हें जारी रखा गया। सरकार ने, हालांकि, पिछले आठ वर्षों में इन सुधारों को एक नया आयाम प्रदान किया। जीवनयापन और व्यवसाय करने की सुविधा को बढ़ाने और आर्थिक दक्षता में सुधार पर अंतर्निहित बल के साथ, अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि को और बढाने के लिए सुधारों को अच्छी तरह से स्थापित किया गया है। इन सुधारों का व्यापक सिद्धांत सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण, विश्वास-आधारित शासन को अपनाना, विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ सह-साझेदारी करना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना था। यह दृष्टिकोण सरकार की वृद्धि और विकास रणनीति में आमूल-चूल बदलाव को दर्शाता है, जिसमें विकास प्रक्रिया के विभिन्न हितधारकों के बीच साझेदारी बनाने पर जोर दिया गया है, जहां प्रत्येक सुधार से विकास होता है और इसका लाभ मिलता है (सबका साथ, सबका विकास)।

चित्र II.6: डॉट-कॉम बबल संकट के कारण कई देशों में मंदी आई, जिससे वैश्विक अनिश्चितता बढ़ गई

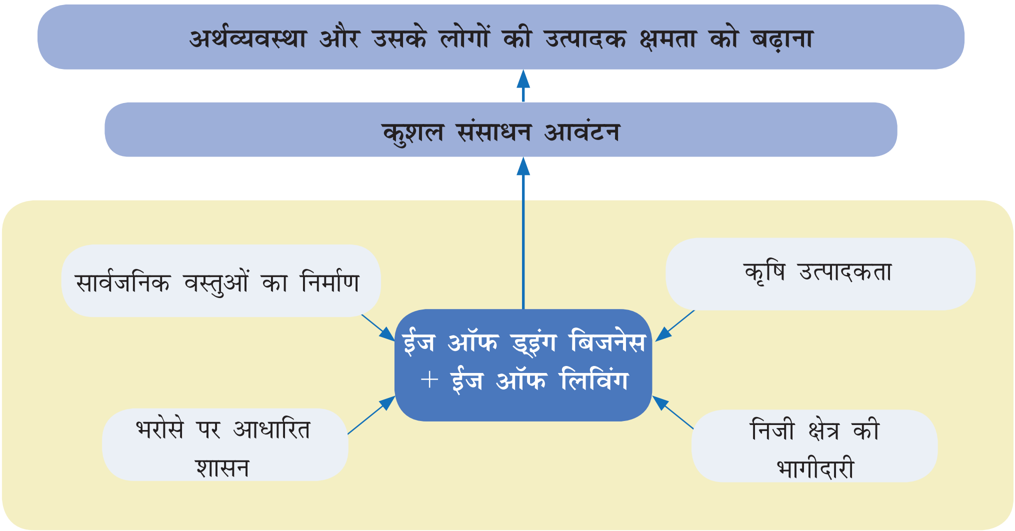

2.9 जबकि वर्ष 2014 के बाद की अवधि में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था के लिए कई सामाजिक आर्थिक लाभ हुए हैं, यह अध्याय इन सुधारों के विकास-केंद्रित पहलुओं पर केंद्रित है। आगामी भाग में इस बात पर चर्चा

[7]मोहन, राकेश, (2008, कैपिटल फ्लो टू इंडिया, पृ. 235-263 में सेटलमेंट्स, बैंक फॉर इंटरनेशनल एड।, वित्तीय वैश्वीकरण और उभरते बाजार पूंजी प्रवाह, वॉल्यूम 144, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स), (https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap44m.pdf)

की गई है कि कैसे प्रत्येक सिद्धांत जो नए सुधार ढांचे को सहारा देता है, अर्थव्यवस्था और इसके लोगों की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने में योगदान देता है। भारत के मध्यावधि विकास दृष्टिकोण में इनका गहन सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

I. जीवन को आसान बनाने के लिए अवसरों, दक्षताओं संबंधी सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन करना

2.10 2000 के दशक में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरूआत भारत में बुनियादी ढांचा-गहन नीति निर्माण का शुभारंभ हुआ, जो एक और दशक तक धीमी गति से जारी रहा। पिछले कुछ वर्षों नीतिगत प्रतिबद्धता और बुनियादी ढांचे के परिव्यय में आई बड़ी उछाल अब (चित्र II.7) दिखाई दे रही है। जब बैलेंस शीट की समस्याओं के कारण गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र निवेश करने में असमर्थ थे, तब आर्थिक विकास को इससे सहायता मिली। ऐसा करके, सरकार ने आने वाले दशक के निजी निवेश और विकास में बढ़ोतरी के लिए एक अच्छा मंच तैयार किया है।[8]

चित्र II.7: केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बढ़ रहा है

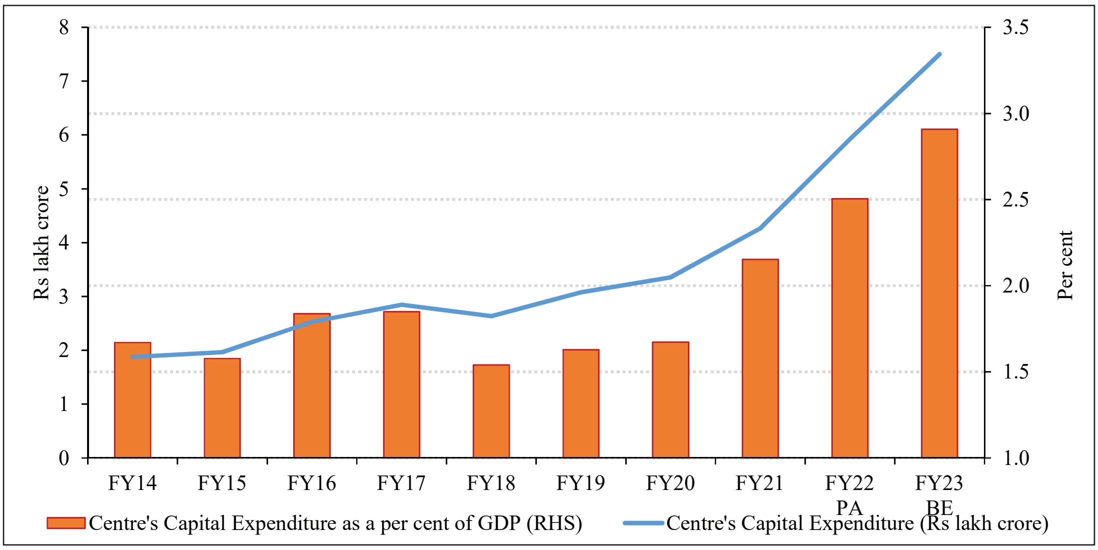

स्रोतः आरबीआई, एमओएसपीआई

2.11 सड़क संपर्क (भारतमाला), बंदरगाह अवसंरचना (सागरमाला), विद्युतीकरण, रेलवे उन्नयन, और नए हवाई अड्डों/हवाई मार्गों (उड़ान) के संचालन के लिए समर्पित कार्यक्रमों से पिछले कुछ वर्षों में भौतिक बुनियादी ढांचे में काफी सुधार किया है (चित्र II.8)। भौतिक अवसंरचना के उन्नयन के विषय में विवरण अध्याय 12 में देखा जा सकता है। 2019 की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और 2021 की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन से, बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए एक मजबूत आधार रेखा तैयार की गई, जिससे बड़ी संख्या में विदेशी निवेश एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। 111 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित बुनियादी ढांचा निवेश 6,835 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ एनआईपी को लॉन्च किया गया था। यह 35 उप-क्षेत्रों की 9,000 से अधिक परियोजनाओं तक विस्तारित हो गया है और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं। अपने अगले और पिछले सशक्त संबंधों, भौतिक अवसंरचना मध्यावधि में अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में वृद्धि होगी।

---
[8]क्राउडिंग-आउट या क्राउडिंग-इन? पब्लिक एंड प्राइवेट इनवेस्टमेंट इन इंडिया, IMF वर्किंग पेपर (WP/15/264), दिसंबर 2015 (https:/www.imf.org/en/Publication/WP/issues/2016/12/31/Crowding-Out-or-Crowding-In-Public-and-Private-Investment-in-India-43470)

चित्र II.8: महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षमता में विकास (पहले उपलब्ध मूल्य के साथ मान 100 के रूप में एक सूचकांक हैं)

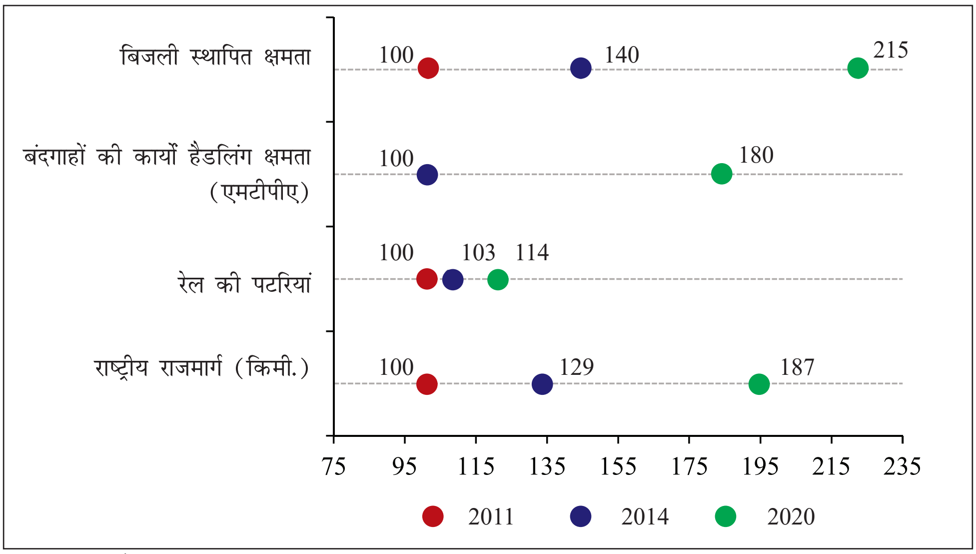

स्रोतः मुद्रा और वित्त जून 2022 संबंधी आरबीआई की रिपोर्ट
नोटः (क) रेलवे ट्रैक रनिंग-ट्रैक किलोमीटरों को दर्शाता है
(ख): 2019 राष्ट्रीय राजमार्गो का डेटा, नवीनतम है और 2020 के लिए दिखाया गया है

2.12 सरकार द्वारा भौतिक बुनियादी ढाँचे पर जोर देने के अलावा, पिछले कुछ वर्षों के दौरान सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढाँचे को तैयार करके उससे व्यक्तियों और व्यवसायों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना एक गेम चेंजर रहा है। आरबीआई के मासिक बुलेटिन में हाल ही में प्रकाशित एक लेख[9] में अनुमान लगाया गया है कि भारत की मुख्य डिजिटल अर्थव्यवस्था 2014 और 2019 के बीच समग्र आर्थिक विकास का 2.4 गुना बढ़ी है। गैर-डिजिटल क्षेत्रों से इसके मजबूत जुड़ाव, डिजिटलीकरण विभिन्न चौनलों के माध्यम से संभावित आर्थिक विकास को मजबूत करता है। इनमें से कुछ, जैसे उच्च वित्तीय समावेशन, अत्यधिक औपचारिकता, बढ़ी हुई दक्षता और उन्नत अवसरों की चर्चा नीचे की गई है।

2.13 डिजिटल पहचान आधार के स्तंभों (पिलर्स) के आधार पर, पीएम-जन धन योजना के साथ बैंक खातों को जोड़ने और मोबाइल फोन (जेएएम ट्रिनिटी) की पहुंच के आधार पर, देश ने हाल के वर्षों में वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। बैंक खाता धारकों की संख्या 2015-16 के 53 प्रतिशत से बढ़कर 2019-21 में 78 प्रतिशत हो गई (एनएफएचएस के अनुसार)। अंतर्राष्ट्रीय साक्ष्यों से यह पता चलता है कि विकास के मामले में समान स्तर वाले देशों के बैंक खातों धारकों की इतनी संख्या तक पहुँचने में लगभग आधी सदी लग गई है (डीसिल्वा और अन्य 2019)[10] डिजिटल सत्यापन (ई-केवाईसी), डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल रिपॉजिटरी (डिजीलॉकर) और डिजिटल भुगतान (यूपीआई) जैसी कई डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं ने औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके और लेनदेन लागत को कम करके वित्तीय समावेशन का प्रोत्साहित किया है[11] बड़ी संख्या में वित्तीय समावेशन और ऋण तक पहुंच, उच्च खपत और निवेश को प्रोत्साहित करती है, जिससे उच्च आर्थिक विकास होता है। हाल ही में शुरू की गई कुछ डिजिटल पहलें, जैसे कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, छोटे व्यवसायों, ई-कॉमर्स मार्केट एक्सेस और क्रेडिट उपलब्धता के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगें और मध्यावधि आर्थिक विकास को मजबूत करेंगी।

[9]धीरेंद्र गजभिए एट अल। (2022), 'भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का मापन', आरबीआई मासिक बुलेटिन दिसंबर 2022
[10]डिसिल्वा, डेरिल और फिल्कोवा, जुजाना और पैकर, फ्रैंक और तिवारी, सिद्धार्थ, द डिज़ाइन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल इन्फ्रास्ट्रक्चरः लेसन्स फ्रॉम इंडिया (15 दिसंबर, 2019) बीआईएस पेपर नंबर 106 (https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap106.pdf)

2.14 अर्थव्यवस्था का बड़े पैमाने पर औपचारिकीकरण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 'द इकोनॉमिस्ट' की एक रिपोर्ट (जनवरी 2023), भारत में कार्यबल की औपचारिकता के रुझान को दर्शाती है जो कि परिवर्तित डिजिटल वित्तीय वास्तुकला, डिजिटलीकृत जीएसटी प्रणाली और यूपीआई के उपयोग में वृद्धि के फलस्वरूप संभव हुआ है। आधार जैसी डिजिटल पहचान का निर्माण, असंगठित श्रमिकों का आश्रम पोर्टल पर पंजीकरण,[12] स्वनिधि पर रेहड़ी-पटरी वालों, जीएसटीएन पर कर भुगतान करने वाली फर्मों और उदयम पोर्टल पर एमएसएमई के पंजीकरण ने औपचारिक रूप से इन समूहों को इकनोमिक नेट में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के रूप में, अब हम देख सकते हैं कि उद्योग पोर्टल पर पंजीकृत 1.27 करोड़ उद्यमों में से, 93,000 से अधिक सूक्ष्म उद्यम अब छोटे उद्यम बन गए हैं, और 10,000 छोटे उद्यम पिछले दो वर्षों में मध्यम उद्यम बन गए हैं।[13] इनमें से कई समूहों के लिए पहचान बनाने से औपचारिक ऋण तक उनकी पहुँच आसान हुई है। 32.7 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का पहले ऋण का लाभ उठाया है, और इनमें से 6.9 लाख से अधिक ने 20,000 रुपये का दूसरा ऋण प्राप्त किया है। इसके अलावा, डिजिटल सिस्टम जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) और ई-वे बिल सिस्टम ने व्यापार लेनदेन की औपचारिकता को भी सबल किया है। जीएसटी करदाताओं[14] की बढ़ती संख्या, वर्ष 2017 में 70 लाख से 2022 में 1.4 करोड़ से अधिक हो जाना औपचारिक व्यवसायों में विस्तार का संकेत देती है। यूपीआई की डिजिटल भुगतान प्रणाली के व्यापक उपयोग से छोटी से छोटी राशि के लिए भी लेनदेन को औपचारिक बनाना संभव हो गया है। अपने प्रचालनों में क्रेडिट और दक्षता लाभ की उन्नत पंहुच द्वारा व्यापक औपचारिकता से अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायों की उत्पादकता बढ़ेगी।

2.15 शासन की बाध्यकारी अडचनों को दूर किए जाने पर आर्थिक और संरचनात्मक सुधारों से मिलने वाला लाभ अधिक महत्वपूर्ण होता है।[15] विभिन्न पहलों/पोर्टलों को जोड़ने वाली एकीकृत डिजिटल इंटरुेस ने प्रक्रियाओं को सरल बनाया है जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में अधिक कुशल (दक्ष) संसाधन का आवंटन हुआ है। व्यापार संबंधी अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, केंद्र सरकार की क्रेडिट-लिंक्ड योजना के लिए जनसमर्थ पोर्टल, और केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं तक पहुंच के लिए उमंग ऐप मौजूदा प्रणालियों के एकीकरण के माध्यम से व्यापार करने में आसानी बढ़ाने की दिशा में आवश्यक कदम हैं। 28.5 करोड़ से अधिक पंजीकृत श्रमिकों के साथ ईशराम पोर्टल का आसानी से उपयोग करने के लिए विभिन्न अन्य डिजिटल पोर्टलों के साथ एकीकृत किया गया है। पीएम गतिशक्ति, जीआईएस-आधारित एक प्लेरुॉर्म है जो मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए कई मंत्रालयों को एक साथ जोड़ता है, जिसका उद्देश्य रसद (लोजिस्टिक्स) लागत को कम करना है। इस प्रकार, डिजिटल प्रौद्योगिकियां सुधारों में सबसे आगे होने के कारण भारत के आर्थिक विकास को गति देने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती हैं। डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रगति के बारे में अधिक जानकारी अध्याय 12 में देखी जा सकती है।

II. विश्वास-आधारित शासन

2.16 सरकार और नागरिकों/व्यवसायों के बीच विश्वास बढ़ने से निवेशक भावना में वृद्धि और व्यापार करने में सुगमता और अधिक प्रभावी शासन व्यवस्था से दक्षता में भी इजफा होता है। पिछले आठ वर्षों के दौरान इस दिशा में लगातार सुधार किए गए हैं। इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) और रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (आरईआरए) जैसे सुधारों के माध्यम से नियामक ढांचे के सरलीकरण से व्यापार करने में

[12]स्वॉलो, हक्सर, और पटनाम (2021), स्टैकिंग अप फाइनेंशियल इन्क्लूजन गेन्स इन इंडिया, IMF फाइनेंस एंड डेवलपमेंट (https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2021/07/india-stack-stack-financial-igqap&vkSj&fMftVy&inclusion.htm) 'इमेजिन एन इंडिया विदाउट हॉकर्स', द इकोनॉमिस्ट जनवरी 2023

[13]https://pqars.nic.in/annex/257/AU904.pdf

[14]पीएमईएसी रिपोर्ट-'जीएसटी-बाकी बिंदुओं को जोड़ना', जून 2022

[15]आईएमएफ विश्व आर्थिक आउटलुक 2019

आसानी हुई है। आईबीसी ने परिसंपत्ति समाधान तंत्र की कुछ सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पध्दि्तयों को आत्मसात किया है। इसके ईमानदार व्यापार किलताओं के लिए सम्मानजनक निकास तंत्र की व्यवस्था होती है और बेहतर संसाधन आवंटन के लिए स्ट्रेस्ड एसेट्स में लॉक क्रेडिट को जारी (मुक्त) किया जा सकता है। यह बाजार-प्रेरित, पारदर्शी समाधान तंत्र वित्तीय प्रणाली में विश्वास पैदा करता है और कई नए निवेशकों को भारतीय व्यवसायों में निवेश करने के लिए आकर्षित करता है। आईबीसी की महत्वपूर्ण उपलब्धि डेब्टर-क्रेडिटर (देनदार-लेनदार) के संबंध ों में लाया गया परिवर्तन भी है। दिवालियापन से बचने के लिए कर्जदार व्यक्ति से मुक्ति पाने के लिए तनाव जल्दी समाधान कर रहे हैं। 30 सितंबर 2022 तक, ₹7.3 लाख करोड़ की बुनियादी चूक वाले कॉर्पोरेट कर्जदारों के लिए कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने के लिए कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) में उनके प्रवेश से पहले ही 23,417 आवेदनों का निपटान किया गया था।2

2.17 एक अन्य नियामक सुधार, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (आरईआरए), रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शी लेनदेन की संस्कृति को विकसित कर रहा है।[18] इस अधिनियम ने रियल एस्टेट ब्रोकरों और एजेंटों को नियामक के साथ पंजीकृत कर, विवादों के त्वरित निवारण के लिए तंत्र स्थापित करने और डेवलपर्स को समय पर अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस के लिए सक्षम बनाकर रियल एस्टेट क्षेत्र में बदलाव ला दिया है। देश भर में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों ने 1.06 लाख से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया है। आरईआरए (आरईआरए) के अंतर्गत 99262 परियोजनाओं और पहले से पंजीकृत 71514 एजेंटों के पंजीकृत से यह अधिनियम इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित कर रहा है।

2.18 व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार, 2013 के कंपनी अधिनियम (तालिका II.2) के अंतर्गत किया गया है और इसके तहत 'मामूली आर्थिक अपराधों' का वैधीकरण किया गया है। सामान्य डिफ़ॉल्ट से निपटने के लिए नागरिक देनदारियों (सिविल लायबिल्टीज) को शुरू करके, जिसमें धोखाधड़ी शामिल नहीं है या जहां चूक की प्रकृति विशुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक है, सरकार ने घरेलू और वैश्विक निवेशकों की व्यापार करने की आसान व्यवस्था को बढ़ावा देने संबंधी अपने इरादे का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा, अनुपालन के प्रति विश्वास-आधारित दृष्टिकोण कॉर्पोरेट संस्थानों में उद्यमियों का विश्वास पैदा करता है और उन्हें निष्पक्ष और अधिक पारदर्शी व्यवसाय परम्परा को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। सुधार के बाद, बिना कोर्ट का सहारा लिए अब तक 1400 से ज्यादा डिफॉल्ट के मामले निपटाए जा चुके हैं। साथ ही, कंपनी अधिनियम के तहत जुर्माने से बचने के लिए 4,00,000 से अधिक कंपनियों ने स्वेच्छा से पिछले चूक को ठीक किया है।[19]

तालिका 2: कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपराधों के डिक्रिमिनलाइजेशन (वैधीकरण) का स्नैपशॉट

	गैर-अपराधीकरण से पहले	गैर-अपराधीकरण के बाद [दो चरणों में]
कुल दंड प्रावधान	134	124
शमनीय (संयोजनीय) अपराध [ज्यादातर जुर्माना लगाया जाता है]	81	31
अशमनीय (असंयोजनीय) अपराध [गंभीर अपराध, जहां सजा के कारावास का आदेश दिया जाता है]	35	35
नागरिक दायित्व के अधीन चूक (आंतरिक अधिनिर्णय तंत्र के माध्यम से)	18	58

[16]साहू, एमएस, और गुरु, ए. (2020)। भारतीय दिवाला कानून। विकल्प, 45(2), 69-78 (https://www.ies.gov.in/pdfs/Indian-Insolvency-Law-Dr-MS-Sahoo-and-Dr-Anuradha-Guru.pdf)

[17]IBBI तिमाही न्यूज़लेटर (जुलाई-सितंबर 2022)

[18]निवेशक हित में सुधार-हालिया विधायी और विनियामक उपाय (2017) पर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, आर. गांधी का भाषण

[19]कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम का उपयोग करना

2.19 नीतिगत अनिश्चितताओं के समाप्त होने से सरकार और उसके नागरिकों के बीच के विश्वास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 25000 अनावश्यक अनुपालनों को समाप्त करके प्रक्रियाओं को सरल बनाना, 1400 से अधिक पुरातन कानूनों को निरस्त करना, एंजल टैक्स को समाप्त करना और भारत में स्थित संपत्तियों के अपतटीय अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर पूर्वव्यापी कराधान को हटाना, इत्यादि जैसे कदमों से सरकार की गैर-प्रतिकूल नीतिगत माहौल को सुनिश्चित करने के संकल्प दिखाई देता है। इन प्रयासों से निवेशकों की भावनाओं में सुधार हुआ है और विकास की संभावनाएं मजबूत हुई है।

2.20 विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद, देश में कराधान पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) में काफी सुधार हुए हैं। कर नीति में सुधार जैसे एकीकृत जीएसटी को अपनाना, कॉर्पोरेट टैक्स दरों को कम करना, सॉवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को करों से छूट देना और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटाना, जैसे कदमों से व्यक्तियों और व्यवसायों पर कर का बोझ कम हुआ है; और अर्थव्यवस्था से विकृत प्रोत्साहनों को हटा दिया गया है। उदाहरण के लिए, जीएसटी ने अनुपालन को कम करके व्यवसायों की मदद की है, राज्यों में माल का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित किया है, व्यवसायों के लिए प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग गोदाम रखने की आवश्यकता को समाप्त किया है और इस प्रकार व्यापार करना आसन हुआ है। पहले की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था उत्पति आधारित थी, और इसने व्यवसायों के स्थान संबंधी विकल्पों को विकृत कर दिया था।

2.21 कर व्यवस्था के सुव्यवस्थितकरण के बावजूद, अर्थव्यवस्था में उच्च कर उछाल की सकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। विख्यात अर्थशास्त्री इंदिरा राजारमन ने वर्ष 2019 में जीएसटी को 'एक राजस्व सफलता' करार दिया; इसके बाद, सकारात्मक जीएसटी राजस्व संग्रह रुझान महामारी के बावजूद और भी मजबूत हुआ है। औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह वित्त वर्ष 2018 में 0.90 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 1.49 लाख करोड़ रुपए हो गया है (चित्र II.10)। साक्ष्य बताते हैं कि जीएसटी के बाद के काल में जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की उछाल में सुधार हुआ है (बॉक्स III.1, अध्याय 3)।[20] चूंकि अन्य कर सुधार, जैसे कि महामारी के बाद की अनिश्चितता और व्यवधानों को देखते हुए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की गई जिसका प्रभाव कर संग्रहण पर धीरे-धीरे उच्च कर संग्रह के रूप में दिखाई दे रहा है। वित्त वर्ष 2013 से वित्त वर्ष 19 की इसी अवधि के दौरान 10.3 प्रतिशत की लंबी अवधि की औसत वार्षिक वृद्धि की तुलना में अप्रैल से नवंबर 2022 के लिए कॉर्पोरेट कर संग्रह में साल-दर-साल आधार पर 21.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

चित्र II.10: औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह में वृद्धि

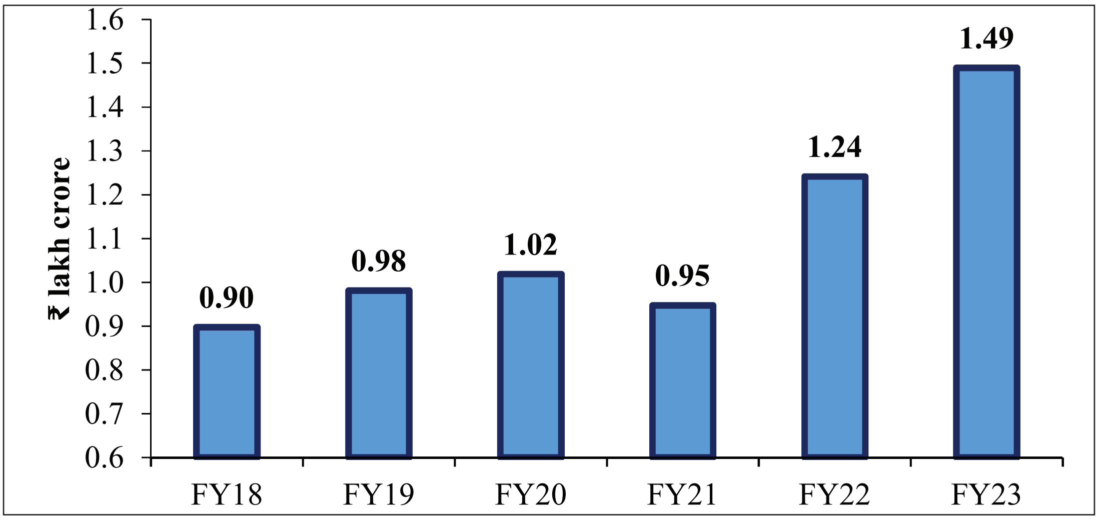

स्रोत: राजस्व विभाग

[20]2019 में मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चेलिया मेमोरियल लेक्चर के रूप में इंदिरा राजारमन द्वारा दिया गया द इवॉल्विंग जीएसटी शीर्षक वाला मोनोग्राफ। (http://www.mse.ac.in/wp-content/uploads/2021/05/Monograph-43 ihMh,iQ)

2.22 उच्च राजस्व उछाल का प्रमुख कारण कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनुपालन बढ़ाना और धोखाधड़ी का पता लगाने वाली प्रणालियों में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित कर प्रशासन सुधारों की शुरूआत करना है। फेसलेस मूल्यांकन और अपील प्रणाली को अब करदाताओं और आयकर विभाग के बीच प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, एकीकृत डिजिटल सिस्टम की बहुल संबद्धता जांच संभव से कर चोरी को कम हुआ हैं। एक उदाहरण के रूप में, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग तंत्र के परिणामस्वरूप बेहतर आय रिपोर्टिंग होती है, जिससे उच्च प्रत्यक्ष कर संग्रह होता है। इस संबंध में, सीबीडीटी और सीबीआईसी के बीच स्वचालित और नियमित आधार पर डेटा और सूचना साझा करने का निर्णय एक आशाजनक सुधार है और इसके परिणामस्वरूप कर प्रणाली में दक्षता लाभ होगा। ये सुधार भविष्य के आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था में भविष्य में संसाधन जुटाने के लिए शुभ संकेत देते हैं।

III. विकास में सह-भागीदार के रूप में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना

2.23 2014 के बाद की अवधि में सरकार की नीति का एक मूलभूत सिद्धांत विकास प्रक्रिया में को भागीदार निजी क्षेत्र को भागीदार के रूप में अपनाया है। पिछले आठ वर्षों में सरकार विनिवेश नीति को हिस्सेदारी की बिक्री और शेयर बाजार में पीएसई की स्रूल लिस्टिंग के साथ पुनर्जीवित किया गया है। वित्त वर्ष 15 से वित्त वर्ष 23 (18 जनवरी 2023 तक) के दौरान, लगभग ₹4.07 लाख करोड़ की राशि विनिवेश से आय के रूप में 154 लेनदेन के माध्यम से विभिन्न तरीकों / उपकरणों से प्रयोग से प्राप्त की गई है। निजीकरण अभियान को फिर से शुरू करने के लिए एयर इंडिया का निजीकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। साक्ष्य से पता चलता है कि निजीकरण ने श्रम उत्पादकता में सुधार किया है और रणनीतिक क्षेत्रों तक कम करके उच्च दक्षता लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

2.24 भारत की विनिर्माण क्षमताओं और उद्योगों में निर्यात को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों के तहत महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई हैं। घरेलू और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और विनिर्माण उद्योग में वैश्विक चौंपियन बनने के लिए महामारी के बाद क्षेत्र-विशिष्ट उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) शुरू किए गए हैं। पीएलआई योजना मध्यम अवधि में उत्पादन, निर्यात और रोजगार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी; हालाँकि, समय के साथ ही इसका प्रभाव दिखाई देगा। पीएलआई के प्रभाव के शुरुआती अनुमान के अनुसार कुछ क्षेत्रों में उत्साहजनक रुझान हैं। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना ने ₹4,784 करोड़ का निवेश आकर्षित किया है और कुल उत्पादन ₹80,769 करोड़ (सितंबर 2022 तक)[22] के निर्यात सहित ₹2.04 लाख करोड़ का योगदान दिया है। 1960-1990 में दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे पूर्वी एशियाई देशों के औद्योगीकरण के अनुभवों से विदेशी प्रतिस्पर्धा के बीच घरेलू औद्योगीकरण की सहायता करने के लिए समर्पित सरकारी नीति की सराहना की जा सकती है। इन देशों ने उद्योग के विकास के लिए आवश्यक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित अपने उच्च विकास चरण के दौरान अपने घरेलू उद्योगों की सहायता की।[23]

2.25 आत्मनिर्भर भारत के तहत दिए जाने वाले उत्पादन प्रोत्साहन से घरेलू उत्पादन के विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलता है। पिछले आठ वर्षों में विदेशी निवेशकों के प्रति अपनाई जाने वाली नीति में और अधिक उदारीकरण देखा गया है, अधिकांश क्षेत्र अब स्वत: मार्ग के तहत 100: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के

---

[21]छिब्बर, अजय और गुप्ता, स्वाति, 2017। ''बोल्डर विनिवेश या बेहतर प्रदर्शन अनुबंध? भारत के राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए कौन सा रास्ता, ''वर्किंग पेपर्स 17/205, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ꠰ाइनेंस एंड पॉलिसी

[22]https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1885189

[23]जोस्टीन हौज, 2020 ''वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के युग में औद्योगिक नीति: दक्षिण कोरिया और ताइवान के औद्योगीकरण के अनुभवों पर एक विकासवादी ढांचे की ओर, ''विश्व अर्थव्यवस्था, विली ब्लैकवेल, वॉल्यूम। 43(8), पृष्ठ 2070-2092, अगस्त।

लिए खुले हैं। इसके परिणामस्वरूप पिछले दशक के दौरान भारत में सकल एफडीआई प्रवाह में स्पष्ट संरचनात्मक बदलाव आया है। भारत की सकल एफडीआई वित्त वर्ष 05-22 के दौरान जीडीपी का औसत 2.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2015-वित्त वर्ष 22 (चित्र II.10) में 2.6 प्रतिशत हो गया है। वित्त वर्ष 22 में 84.8 बिलियन अमरीकी डालर का उच्चतम वार्षिक सकल एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया। इन रुझानों से वैश्विक निवेशक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में भारत को वरीयता देते हैं।

चित्र II.10: 2014-15 के दौरान सकल एफडीआई/जीडीपी में संरचनात्मक बदलाव

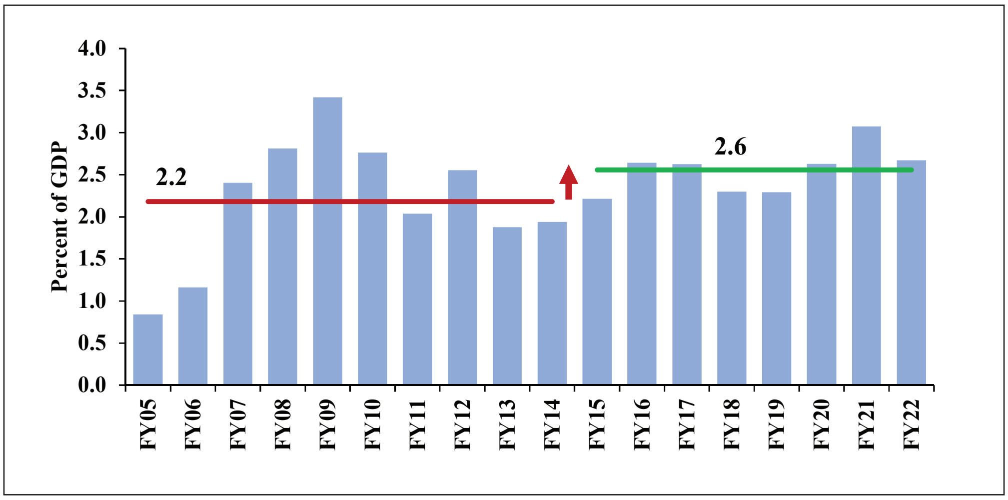

स्रोतः भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की भारतीय रिजर्व बैंक पुस्तिका (एफडीआई डेटा); मौजूदा कीमतों पर अमेरिकी डॉलर जीडीपी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व आर्थिक आउटलुक डेटाबेस (अक्टूबर 2020)।

2.26 भारत को लागत प्रभावी उत्पादन केंद्र बनाने के लिए सरकार सक्षम बुनियादी ढांचा विकसित कर रही है। रसद की लागत को कम करने और इसे अन्य विकसित देशों के बराबर खड़ा करने के लिए एक व्यापक रसद पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए राष्ट्रीय रसद नीति (2022)[24] शुरू की गई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे और भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के लिए रक्षा, खनन और अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को खोलने से अर्थव्यवस्था में व्यापार के अवसरों में वृद्धि हुई है। निवेश प्रोत्साहन और आसान व्यापार अनुपालन ने स्टार्ट-अप के पोषण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप की संख्या 2016 में 452 से बढ़कर 2022 में 84,012 हो गई है। उद्योगों के सुधारों संबंधी अधिक विवरण अध्याय 9 में देखे जा सकते हैं।

2.27 हाल के वर्षों में एमएसएमई द्वारा सामना की जाने वाली संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए किए जाने वाले सुधार औद्योगिक नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के रूप में महामारी के दौरान एमएसएमई के लिए समर्थन उपायों और आत्मनिर्भर भारत के दायरे में एमएसएमई की परिभाषा में किए गए संशोधन ने उन्हें संकट के आघात का सामना करने में मदद की। ईसीएलजीएस, विशेष रूप से, पिछले दो वर्षों में 1.14 करोड़ एमएसएमई को लाभान्वित किया है, जिन्होंने ₹2.38 लाख करोड़ के संपार्श्विक-मुक्त ऋण का लाभ उठाया है। आगामी उपाय, जैसे एमएसएमई के लिए विलंबित भुगतानों को निपटाने के लिए टीआरईडीएस की शुरुआत, एमएसएमई के रूप में खुदरा और थोक व्यापारों को शामिल करना, और स्थिति में ऊपर की ओर बदलाव के मामले में तीन साल के लिए गैर-कर लाभों का विस्तार एमएसएमई ने एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए एक लचीला समर्थन प्रणाली बनाई है। एमएसएमई को अपनी मार्केटिंग जरूरतों और आसान भुगतान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच का भी लाभ मिला है। डिजिटल

[24]अध्याय 12 में विवरण

कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के साथ एमएसएमई के लिए ई-कॉमर्स तकनीक का उपयोग करने और अपने लक्षित बाजारों में विविधता लाने के अवसर देने से, इस प्रवृत्ति के आगे और मजबूत होने की संभावना है। इसके अलावा, अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर एक वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में जी एसटीएन को ऑनबोर्ड करने से एमएसएमई के लिए क्रेडिट तक पहुंच के रास्ते खुलेंगे। एमएसएमई क्षेत्र के अवसरों और उत्पादकता में वृद्धि के लचीले उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बड़े पैमाने पर निहितार्थ हैं, इस प्रकार यह उद्योग और अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं को मजबूत करता है। इसलिए, ये सुधार जारी रहने चाहिए।

IV. कृषि में उत्पादकता बढ़ाना

2.28 पिछले छह वर्षों के दौरान भारत का कृषि क्षेत्र 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। यह वृद्धि आंशिक रूप से अच्छे मानसून के वर्षों और आंशिक रूप से कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों से हुई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सूक्ष्म सिंचाई कोष, और जैविक और प्राकृतिक खेती जैसी नीतियों ने किसानों को संसाधनों के इष्टतम उपयोग और खेती की लागत को कम करने में मदद की है। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) के विस्तार मंच के प्रचार ने किसानों को सशक्त बनाया है, उनके संसाधनों को बढ़ाया है और उन्हें अच्छा लाभ लेने में सक्षम बनाया है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) ने विभिन्न कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण मे सहायता की है। विशेष रूप से खराब होने वाली कृषि बागवानी वस्तुओं की आवाजाही को किसान रेल से पूरा किया जाता करती है। क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) ने बागवानी क्लस्टरों के लिए एकीकृत और बाजार आधारित विकास को बढ़ावा दिया है। किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए भी सहायता दी जा रही है। ये सभी उपाय कृषि उत्पादकता में वृद्धि का समर्थन करते हैं और मध्यम अवधि में समग्र आर्थिक विकास के योगदान को दर्शाते हैं।

2014 के बाद आर्थिक और संरचनात्मक सुधारों की वापसी

2014-22 के दौरान अर्थव्यवस्था को लगे आघात

2.29. सामान्य परिस्थितियों में, पिछले आठ वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था में किए गए व्यापक और विस्तृत सुधारों (जैसा कि पिछले खंड में शामिल किया गया है) ने भारत के विकास को गति दी। किन्तु ऐसा नहीं था। पिछले वर्षों में क्रेडिट बूम के कारण भारत की बैलेंस शीट का स्ट्रेस इसके लिए 'दोषी' है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के आंकड़ों के अनुसार, भारत का गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र का ऋण जीडीपी अनुपात मार्च 2004 में 72.9 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2010 तक 113.6 प्रतिशत हो गया। यह केवल छह वर्षों में 40.7 प्रतिशत अंकों की वृद्धि है। रुपये के संदर्भ में, गैर-वित्तीय क्षेत्र द्वारा संचित ऋण की राशि लगभग 44 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 133 लाख करोड़ हो गई। यह छह साल में तिगुनी हो गयी। सीमित आर्थिक सुधारों के बावजूद, वैश्विक पूंजी प्रवाह और ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के बारे में आशावादी दृष्टिकोण से घरेलू ऋण और निवेश उछाल आया जो अंततः अस्थिर साबित हुआ, जैसा कि 2013 के दोहरे घाटे - राजकोषीय और बाहरी-संकटो से पता चलता है। केवल 2015 के बाद ऋण अनुपात से सार्थक रूप कम होना शुरू हुआ, तथा दिसंबर 2018 तक 83.8 प्रतिशत के निचले स्तर पर गिर गया। आठ वर्षों में, इसने दिसंबर 2010 के 113.6 प्रतिशत से लगभग 30 प्रतिशत अंक की कमी की है।

2.30 अस्वाभाविक रूप से, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र का ऋण सहस्राब्दी के दूसरे दशक में अधिकांश समय के लिए अपने प्रवृत्ति मूल्य से लगातार कम था, जो जीडीपी अनुपात में ऋणात्मक अंतर को दर्शाता है (चित्र II.11)। 2017 में यह अंतर 25 प्रतिशत के अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया। यह सकल एनपीए और ऋण वृद्धि के बीच सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नकारात्मक सहसंबंध (-0.5) दर्शाता है। उनकी

बैलेंस शीट में स्ट्रेस के कारण बैंकों की ऋण आपूर्ति दूसरे दशक[25] में गंभीर रूप से बाधित हुई। यह प्रवृत्ति क्रेडिट-टू-जीडीपी अनुपात के बड़े नकारात्मक विचलन की व्याख्या करती है।

चित्र II.11: अधिकांश 2010 के लिए जीडीपी गैप के लिए त्रैमासिक क्रेडिट नकारात्मक रहा

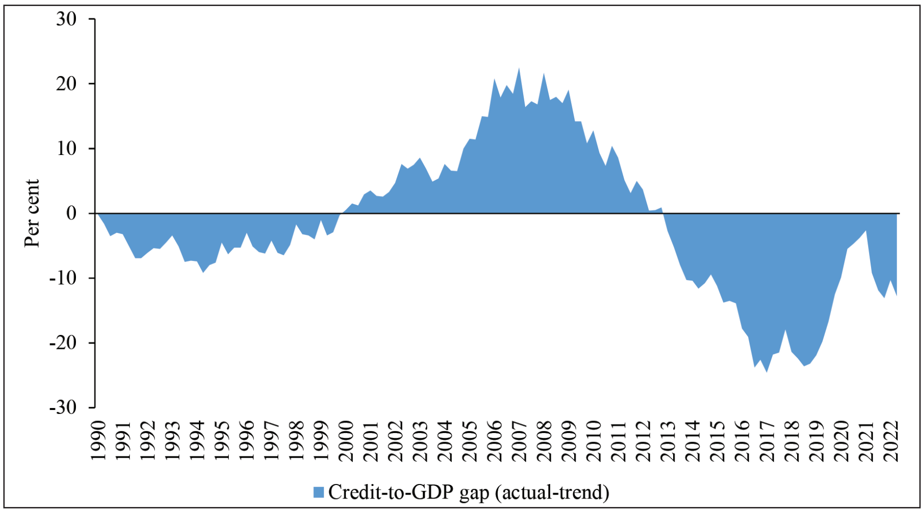

2.31 कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों के फलीभूत नहीं होने के कारण, इसने बैंक ऋण चुकाने की उनकी क्षमता को क्षीण कर दिया। इसलिए, बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां बढ़ने लगीं। इसने पिछले दशक के उत्तरार्ध में वित्तीय और गैर-वित्तीय क्षेत्र के बैलेंस शीट को ठीक करके दीर्घावधि गति दी। सरकार और आरबीआई ने 2010 के दौरान वित्तीय क्षेत्र को बैलेंस शीट के तनाव से उबरने में मदद करने के लिए कई नीतिगत पहलें कीं। इनमें से कुछ जैसे एसएआरएफएईएसआई अधिनियम 2002 में संशोधन, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का कार्यान्वयन, 'संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा' (एक्यूआर) की शुरुआत, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे की शुरुआत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण (पीएसबी), और अन्य के बीच पीएसबी के विलय से बैंकों/कॉर्पोरेटों की बैलेंस शीट के समाशोधन करने में मदद मिली।

2.32 जब बैंकों और कंपनियों की बैलेंस शीट में सुधार और सुधार होना शुरू हुआ, तो सितंबर 2018 में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड लीजिंग सर्विसेज (आईएलएण्डएफ) का पतन हो गया। यह एक बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) थी, जिसके पास एक विशाल संपत्ति का आधार था। इसके पतन का अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं पर भी भारी प्रभाव पड़ा। कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी डूब गईं। इसलिए, आवास ऋण वितरण बाधित हो गया। आमतौर पर, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां बैंकों की तुलना में अधिक उधारकर्ताओं और जोखिम वाले उधारकर्ताओं को उधार देती हैं। उन्हें बैंकों द्वारा पुनर्वित्त किया जाता है। एक बड़ी एनबीएफसी आईएल एंड एफएस के पतन के बाद कुछ आवास वित्त कंपनियों के पतन के बाद उनका पुनर्वित्त पोषण कम हो गया। इसलिए, बैंक ऋण वृद्धि 2019 के अंत तक एकल अंकों में आ गई, जो 2020 तक जारी रही। कम ऋण वृद्धि और इसलिए कमजोर पूंजी निर्माण ने आर्थिक विकास को प्रभावित किया।

2.33 सरकार ने सितंबर 2019 में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती सहित आईएल एंड एफएस और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के पतन के नतीजों को रोकने के लिए कई उपाय किए। इसके तुरंत बाद, महामारी आ गई और सरकार को स्वास्थ्य, सामाजिक और अप्रतयाशित प्रकृति की आर्थिक स्थितियों का सामना किया। 2020-21 और 2021-22 के पिछले दो आर्थिक सर्वेक्षणों में इन पर विस्तार से चर्चा की गई है।

[25] ...

2014-2022 की अवधि 1998-2002 की अवधि के अनुरूप है

2.34 भारत का हालिया आर्थिक इतिहास इस स्थिति के समान है। 1998-2002 के दौरान, परिवर्तनकारी सुधार शुरू किए गए थे लेकिन कम मात्रा में विकास लाभांश मिले (तालिका 11.3)। इस घटना को बाह्यय कारकों और घरेलू वित्तीय क्षेत्र के समाशोधन से उत्पन्न के आघातों की श्रृंखला के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसने 1998 से 2002[26] तक के विकास रिटर्न को पीछे छोड़ दिया। 2003 में आघातों की समाप्ति के बारे भारत ने वैश्विक उछाल में भाग लिया और उच्च दर से विकास किया। इसी तरह, वर्तमान संदर्भ में, महामारी के वैश्विक झटकों और 2022 में कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी के कम होने से, भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले दशक में अपनी क्षमता से बढ़ने के लिए पूर्णत: तैयार है।

तालिका II.3: अवधियों के बीच समानांतर: 1998-2002 और 2014-2022

1998-2002	2014-2022
अर्थव्यवस्था को झटका	
• परमाणु उपकरण परीक्षण 1998; प्रतिबंधों का पालन किया	• बैंकिंग, गैर-बैंकिंग और गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र की बैलेंस-शीट स्ट्रैस की अवधि
• बैंकिंग और कॉर्पोरेट क्षेत्र तुलन-पत्रों को कम तरजीह देना करना और उनको ठीक करना	• महामारी के अभूतपूर्व आधात के बाद मुद्रास्फीति वैश्विक वस्तु मूल्य आघात के बाद वित्तीय स्थिति खराब हो गई
• लगातार दो सूखे	
• प्रौद्योगिकी बस्ट; अमेरिकी मंदी और 09/11	
अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार	
ब्याज दर विनियमन	अनूठी पहचान
निजीकरण	वित्तीय समावेशन
बैंकों के लिए संपत्ति वसूली	जीएसटी औपचारिकता की ओर ले जा रहा है
इन्फ्रास्ट्रक्चर (स्वर्णिम चतुर्भुज)	दिवालियापन और दिवालियापन संहिता
एफआरबीएम अधिनियम	निजीकरण
	कर दरों का युक्तिकरण और कर प्रशासन (ईओडीबी) सुधार;
	अपराधों का विमुद्रीकरण
	टीके रोल-आउट
	व्यय प्रबंधन सुधार
	आत्मानिर्भर
	पब्लिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर
ग्रोथ रिटर्न	
• एक बार संरचनात्मक सुधारों ने आघातों की समाप्ति के बाद 2003 से विकास लाभांश का भुगतान किया	• वित्तीय क्षेत्र में बैलेंस शीट मजबूत; कॉर्पोरेट क्षेत्र में लगभग 30 प्रतिशत अंक (ऋण/जीडीपी अनुपात) की कमी
	• वैश्विक आघातों से निपटने के दौरान मैक्रो-इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर जोर

[26]विवरण के लिए इस अध्याय के अनुच्छेद 6 का संदर्भ लें

इस दशक में ग्रोथ मैग्नेट (2023-2030)

एकबारगी आघातों से उबरने के बाद भारत अपनी क्षमता से वृद्धि के लिए तैयार है।

2.35 वित्तीय और कार्पोरेट क्षेत्र में तुलन पत्र के सुधार की एक लंबी अवधि के बाद वित्तीय चक्र आगे की दिशा में बढ़ने के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त महामारी के स्वास्थ्य और आर्थिक आघातों और 2022 की समाप्ति के समय में वस्तु मूल्यों में बढ़ोत्तरी से भारतीय अर्थव्यवस्था 2003 के बाद के वृद्धि संबंधी अनुभव की तरह आने वाले दशक में अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ने को तैयार है। भारत के वृद्धि दृष्टिकोण को पूर्व महामारी वर्षों से बेहतर होने की संभावना का प्राथमिक कारण यही है। पिछले कुछ वर्षों में विकसित और स्वस्थ वित्तीय प्रणाली ने प्रभावी ऋण सुविधा, उच्चतर निवेशों और उपयोग के माध्यम से आने वाले वर्षों में उच्चतर वृद्धि में योगदान दिया है। भला हो भारत की डिजिटल क्रांति और औपचारिकरण का, जिससे बैंक पहले की अपेक्षा अपने ग्राहकों के ऋण जोखिमों की अधिक सूचना रखते है। जिससे वे ऋण देने और मूल्य निर्णयों को पहले से बेहतर बनाने में सक्षम हों। यह पहले से स्वास्थ्यकारी और लंबे ऋण चक्र बनाने को सुगम बनाएगा। बैंक क्रेडिट वृद्धि अब से कुछ समय पहले से दो अंकों में रही है। 2012 से भारत में एक हालिया आईएमएफ कार्यरत अखबार ने क्रेडिट-से-जीडीपी अनुपात अंतर, बैंक तुलन पत्रों और जीडीपी विकास में रूझानों का विश्लेषण किया है और उच्चतर क्रेडिट वृद्धि में बेहतर पूंजीकृत बैंकों के परिणाम को दर्शाता है, जो आगे चलकर उच्चतर जीडीपी वृद्धि में रूंपातरित करेगा।

2.36. उच्च वित्तीय समावेशन, और अधिक आर्थिक अवसरों के संदर्भ में डिजिटलीकरण सुधार और अधिक औपचारिकता, परिणामी दक्षता लाभ मध्यम अवधि में भारत के आर्थिक विकास का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चालक होगा। भारत के लिए अपनी हालिया अनुच्छेद IV रिपोर्ट में, आईएमएफ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत द्वारा व्यापक सुधारों के सफल कार्यान्वयन और डिजिटलीकरण से भारत की मध्यम अवधि की विकास क्षमता को अपेक्षित लाभांश से अधिक बढ़ा सकता है। कौशलात्मक पहलों सहित सरकार द्वारा की गई विविध उत्पादकता-संवर्धन सुधार आने वाले वर्षों में की गई विविध पहलों ने भारत की वृद्धि क्षमता को और दृढ़ किया है, और यह एकबारगी झटकों के प्रभावों के रूप में वास्तविक जीडीपी में दिखाई देगा।

2.37 इसके अलावा, उभरती हुई भू-राजनीतिक स्थिति भारत के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण से लाभ उठाने का अवसर प्रस्तुत करती है। पिछले कुछ वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वैश्विक व्यापार तनाव, महामारी से प्रेरित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और यूरोप में संघर्ष के कारण अभूतपूर्व जोखिम का सामना करना पड़ा है। फर्मों को अपने उत्पादन को एक ही देश में केंद्रित करने के जोखिम से अवगत कराया गया था। इसलिए, वैश्विक नीति की अनिश्चितता को देखते हुए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां धीरे-धीरे अपने उत्पादन आधारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की रणनीति तलाश रही हैं। यूएनसीटीएडी ने अपनी एक रिपोर्ट में दिखाया है कि 'पुनर्स्थापन, विविधीकरण और क्षेत्रीयकरण आने वाले वर्षों में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के पुनर्गठन को बढ़ावा देंगे'।[30] सक्षम नीतिगत ढाँचे के साथ, भारत स्वयं को अन्य देशों से पूंजी विविधीकरण के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करता है।[31] [32]

---

[27]उभरती अर्थव्यवस्थाएं लंबे समय तक उत्पादकता में मंदी का सामना कर रही हैं, 'द इकॉनॉमिस्ट' 16 जनवरी 2020 longed-productivity-slowdown, 4 फरवरी 2020 को देखा गया)

[28]फ्रेडरिक बोड्से, 'फैब्रिस कोलार्ड, और स्मेट्स, बूम और प्रणालीगत बैकिग संकट, यूरोपीय सेंट्रल, यूरोपीय सेंट्रल बैंक वर्किंग पेपर नंबर 1514 फरवरी 2013(https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1514.pdf)

[29]स्टीफन जी॰ सेचेती और मैरियन कोहलर और क्रिश्चियन अपर, 2009 ''वित्तीय संकट और आर्थिक गतिविधि,'' एनबीईआर वर्किंग पेपर्स 15379, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, इंक।

[30]मुदुली, एस और बेहरा, एच., 2021 भारत में बैंक कैपिटल एंड मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में समष्टि अर्थशास्त्र और वित्त, पीपी. 1.25। (https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/1MACROECONOMIC3C3EEF439E4C49459A3C9EB4011B3B39)

[31]मार्गाक्स मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में वित्तीय क्षेत्र और आर्थिक विकास; टेंगटेंग जू (जुलाई 2022) https://www.imf.org/en/Publications/WP/issues/2022/07/08/Financial-Sector-and-Economic-Growth-in-india-520580)

[32]वास्तविक अनुपात और उसके रूझान मूल्य के बीच अंतर

हाल ही में प्रकाशित चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक 2023 (विश्व आर्थिक मंच) ने भारत को इन वैश्विक रुझानों से लाभ उठाने के बारे में प्रकाश डाला है।[33]

2.38 पिछले आठ वर्षों में किए गए नए युग के सुधार एक लचीले, साझेदारी–आधारित शासन पारिस्थितिकी तंत्र की नींव हैं और सुदृढ़ रूप से बढ़ने के लिए अर्थव्यवस्था की क्षमता को बहाल करते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए और सुधारों की आवश्यकता है कि आर्थिक विकास में तेजी और संधारणीयता आ सके उससे एक बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन मिल सके। अनुपालनों का विनियमन और सरलीकरण लाइसेंसिंग, निरीक्षण और अनुपालन व्यवस्था को पूरी तरह से विघटित करना जारी रखेगा। राज्य सरकारों को बिजली क्षेत्र के मुद्दों का समाधान करना होगा और डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यता संबंधी चिंताओं को दूर करना होगा। आधुनिक उद्योग और प्रौद्योगिकियों की आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए शिक्षा और कौशल पर जोर दिया जाना चाहिए, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण जैसी इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों से निपटना चाहिए और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने की पहल जारी रहनी चाहिए। बढ़ते मोटापे के स्तर को रोकने और उसे कम करने की रणनीति अपनाई जानी चाहिए।[34] ऊर्जा संक्रमण और विविधीकरण के लिए आवश्यक आवश्यक धातुओं और खनिजों को सुरक्षित करने के लिए दूरगामी योजनाएँ तैयार करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम से व्यापक दक्षता लाभ लेने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति मुद्रीकरण योजना को सफल बनाने के लिए दृढ़ प्रयास किए जाने चाहिए। यदि सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण को कम करने के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण राजस्व का उपयोग किया जाता है, तो क्रेडिट रेटिंग में उत्तम सुधार होगा, जिससे पूंजी की लागत कम होगी। यह अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा राजकोषीय प्रोत्साहन होगा। एमएसएमईएस पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए सुधार, वित्त और कार्यशील पूंजी तक उनकी पहुंच बढ़ाने और उन्हें अपने व्यवसायों को जिम्मेदारी से विकसित करने के लिए कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण से लैस करने के प्रयास जारी रहने चाहिए। राज्य सरकारों को विभिन्न कारक बाजार सुधारों को पूरा करने के विभिन्न चरणों में निर्णायक प्रगति करनी चाहिए।

2.39 इस अध्याय में हमने देखा भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपना उत्साह नहीं खोया था, न ही सरकारी सुधार ने उनकी प्रभाविकता मापी थी। वित्तीय और कार्पोरेट क्षेत्र में तुलन पत्र में स्ट्रेस के न होने से भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वृद्धि कर सकती थी। नए दशक में बेहतर और स्वास्थ्यकर तुलन पत्रों का लाभ उठाने के लिए हम अर्थव्यवस्था में आगे की ओर देख रहे थे, यह वैश्विक महामारी द्वारा स्वरूचि के बाद खाद्य, ईंधन और खाद के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई थी। नकारात्मक आघात अवश्य कम हो जाएंगे जैसा कि उन्होंने नई सहस्त्राब्दी के प्रारंभिक वर्षों में किया था। उधार लेने और उधार देने की इच्छुक है। इसलिए, यह अवश्यम्भावी है कि इन सुधारों के प्रभाव अब और स्पष्ट होंगे। एक पुनर्स्थापित क्रेडिट चक्र भारतीय निजी क्षेत्र के कैपेक्स चक्र को फिर से जीवंत करेगा। यह अकेले ही भारत को वास्तविक रूप से कम से कम 6 प्रतिशत दर प्रतिवर्ष बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है। उसके शीर्ष पर, पिछले 6–7 वर्षों में बनाए गए सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे से उत्पन्न उच्च आर्थिक दक्षता भी संभावित सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 30–50 आधार अंक जोड़ देगी। भारत के सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे की परिपक्वता के विकास प्रभावों को अपर्याप्त रूप से समझा गया है। औपचारिकता और सक्षम वित्तीय समावेशन, इतने स्पष्ट हैं कि इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह समय की बात है कि इसकी वृद्धि डाटा पर पड़ने वाले प्रभावों से पहले सशक्त हो जाए। यही कारण है कि भारत की मध्यावधि में जीडीपी वास्तविक वृद्धि 6.5 प्रतिशत की औसत से प्राप्त करने की संभावना है। इसके अलावा, अगर आने वाले वर्षों में पिछले पैराग्राफ में बताए गए अन्य सुधारों को आगे बढ़ाया जाता है, तो मध्यम अवधि में भारत की संभावित जीडीपी वृद्धि 7–8 प्रतिशत प्रति वर्ष तक बढ़ सकती है।

---

[33]https://www.imf.org/en/Publications/CR/issues/2022/12/21/India-2022-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and Statement-by-the-527283

[34]विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 (https://uncatad/org/news/covid-19-will-likely-transform-global-production-says-un report; दस्तावेज/पत 2020 en.pdf)

03
अध्याय

राजकोषीय विकास - राजस्व सुधार

वित्तीय वर्ष 2023 का केंद्रीय बजट एक व्यापक आर्थिक अनिश्चित वातावरण में प्रस्तुत किया गया था। इसे प्रस्तुत किए जाने के बाद, भू-राजनीतिक संघर्ष से वैश्विक आपूर्ति अवरोध बढ़ गए और ईंधन, भोजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस संकट के प्रति भारत सरकार की राजकोषीय नीति में एक ओर बढ़ती खाद्य और उर्वरक सब्सिडी प्रदान करना तथा दूसरी ओर ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर करों में कटौती करने का विवेकपूर्ण मिश्रण शामिल था। वर्ष के दौरान इन अतिरिक्त राजकोषीय दबावों के बावजूद, केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2023 में राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए बजट अनुमान को प्राप्त करने के ट्रैक पर है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार, प्रत्यक्ष करों और जीएसटी से राजस्व में वृद्धि और बजट में यथार्थवादी संकल्पनाओं से केंद्र सरकार के प्रर्दशन में लचीलापन सुकर हुआ है। अप्रैल से नवंबर 2022 तक सकल कर राजस्व में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो प्रत्यक्ष करों और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में मजबूत वृद्धि से प्रेरित है। वर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान प्रत्यक्ष करों में वृद्धि उनके दीर्घावधि औसत की तुलना में बहुत अधिक थी। जीएसटी केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत के रूप में स्थिर हो गया है, अप्रैल से दिसंबर 2022 तक वर्ष दर वर्ष आधार पर सकल जीएसटी संग्रह में 24.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

व्यय पक्ष पर, वर्ष के दौरान केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) पर ध्यान, उच्च राजस्व व्यय आवश्यकताओं के बावजूद जारी रहा है। केंद्र सरकार का कैपेक्स जीडीपी के 1.7 प्रतिशत (वित्त वर्ष 09 से वित्त वर्ष 20) के दीर्घकालिक औसत से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 पीए में जीडीपी का 2.5 प्रतिशत हो गया है। केंद्र सरकार ने ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से राज्य सरकारों को भी प्रोत्साहित किया है और कैपेक्स पर उनके व्यय को प्राथमिकता देने के लिए उधार लेने की सीमा बढ़ा दी है। सड़कों और राजमार्गों, रेलवे, और आवास और शहरी मामलों जैसी अवसंरचना-गहन क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ, कैपेक्स में वृद्धि का मध्यम अवधि के विकास के लिए बड़े पैमाने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह कैपेक्स-आधारित विकास कार्यनीति भारत को विकास-ब्याज दर के अंतराल को सकारात्मक बनाए रखने में सक्षम बनाएगी, जिससे मध्यम अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के लिए ऋण सतत् होगा।

परिचय

3.1 निरंतर जारी वैश्विक जोखिमों और अनिश्चितताओं के कारण, सरकारों के पास राजकोषीय स्थान की उपलब्धता सर्वोपरि हो गई है। हाल में वैश्विक महामारी की घटना के बाद यह विशेष रूप से सच है जब राजकोषीय नीति विश्व स्तर पर वृहत अर्थव्यवस्था के संतुलन का एक प्रभावकारी टूल बन गई। भारत में, विशेष रूप से जब सभी आर्थिक गतिविधियों में एक ठहराव आ गया था, राजकोषीय नीति कमजोर लोगों को सुरक्षा प्रदान करने, मांग को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को फनर्जीवित करने और सार्वजनिक निवेश तथा लगातार संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से कुछ घरेलू आपूर्ति-संबंधी कतिपय को दूर करने में सहायक थी।

3.2 सभी देशों के बाहर से मिलन वाले बड़े, अधिक लाभकारी पैकेजों के कारण मांग में तेजी आई, जिससे इसमें तेजी से सुधार हुआ। अभी भी मौजूदा आपूर्ति व्यवधानों और बाधाओं में, इकॉनोमी की ओवरहीटिंग से मुद्रास्फीति के दबाव उत्पन्न हुए। यूरोप में संघर्ष और संबंधित भू-राजनीतिक विकास ने संकट को और अधिक बढ़ा दिया। धीमी वैश्विक वृद्धि, बढ़ती ब्याज दरों, सतत उच्च मुद्रास्फीति दर और अनिश्चित वैश्विक वातावरण ने इस प्रकार राजकोषीय-नीति विशेषज्ञों के समक्ष राजकोषीय नीति संबंधी महत्वपूर्ण रणनीति तैयार करने से संबंधित कुछ प्रासंगिक प्रश्न खड़े किए हैं। राजकोषीय सहायता को बनाए रखने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा खोए हुए राजकोषीय स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था से राजकोषीय प्रोत्साहन को वापस लेते हुए जारी संकट का प्रबंधन करने के बीच व्यापार सामंजस्य कैसे बनाया जाए? ऐसा कब और किस गति से करें? जहां अचानक वापसी मध्यम अवधि की विधि हेतु लागत रखती है, तथापि धीमी वापसी से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और पैदावार कम हो सकती, जिससे कर्ज महंगा हो सकता है। इसके अतिरिक्त, बढ़ती ब्याज दरों[1] के समय में वित्तीय बाजारों में राजकोषीय अपरंपरागतता के लिए कम सहिष्णुता हो सकती है।

3.3 इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध भारत सरकार ने वैश्विक महामारी के प्रति एक व्यवस्थित राजकोषीय कार्रवाई प्रतिक्रिया को अपनाया और राजकोषीय प्रोत्साहन को धीरे-धीरे वापस लेने की योजना बनाई क्योंकि यह बजट वित्तीय वर्ष 2022 में निर्धारित ग्लाइड पथ के साथ आगे बढ़ता है। यह अध्याय अनिश्चित भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच सरकार की राजकोषीय रणनीति पर चर्चा करता है। अध्याय केंद्र सरकार के वित्तीय प्रदर्शन की चर्चा के साथ शुरू होता है, इसके बाद राज्य के वित्त का अवलोकन होता है। यह भारत के ऋण प्रोफाइल पर एक टिप्पणी के साथ समाप्त होता है।

केंद्र सरकार की आय में वृद्धि

3.4 भारत ने एक विस्तारित राजकोषीय स्थिति के साथ महामारी में प्रवेश किया, सरकार द्वारा एक विवेकपूर्ण और सुधारात्मक राजकोषीय कार्रवाई ने वर्तमान अनिश्चितताओं में भी सार्वजनिक आय को स्थिर करने में सहायता की। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा, जो वैश्विक महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2021 में जीडीपी 9.2 प्रतिशत तक पहुंच गया था, वैश्विक महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2022 में घटकर जीडीपी के 6.7 प्रतिशत तक हो गया है और इसका आगे वित्तीय वर्ष 2023 में जीडीपी के 6.4 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है (चित्र 1)। सरकार द्वारा परिकल्पित राजकोषीय ग्लाइड पथ के अनुरूप जीडीपी के अनुपात में केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे में यह क्रमिक गिरावट, पिछले दो वर्षों में से राजस्व संग्रह में वृद्धि के माध्यम से किए गए सावधानीपूर्वक राजकोषीय प्रबंधन का परिणाम है।

---

[1]'रुचिर शर्मा की इन्वेस्टर्स गाइड टू 2023: फ्रॉम पीक डॉलर टू बेटर टीवी', फाइनेंशियल टाइम्स, 6 जनवरी 2023 (https://www.ft.com/content/3e040c2c-f7e4-4121-9dfe-7ba5732707f7)

आकृति III.1: पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार के घाटे की प्रवृति- राजकोषीय समेकन के मार्ग पर

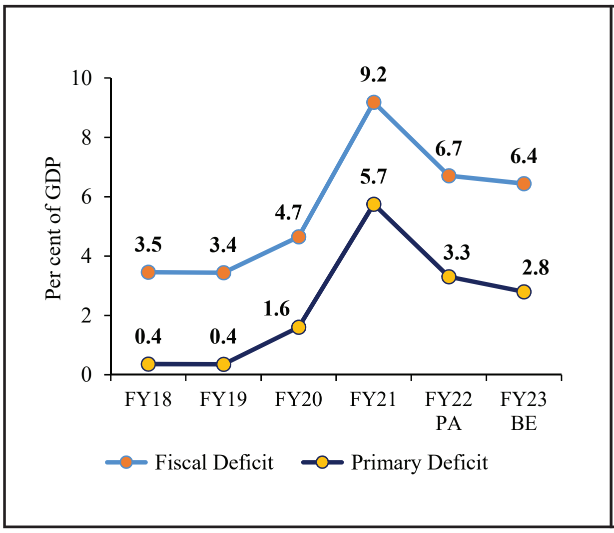

स्रोत: सीजीए कार्यालय, केंद्रीय बजट दस्तावेज

आकृति III.2 : सरकार वित्तीय वर्ष 2023 में लक्षित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के ट्रैक पर

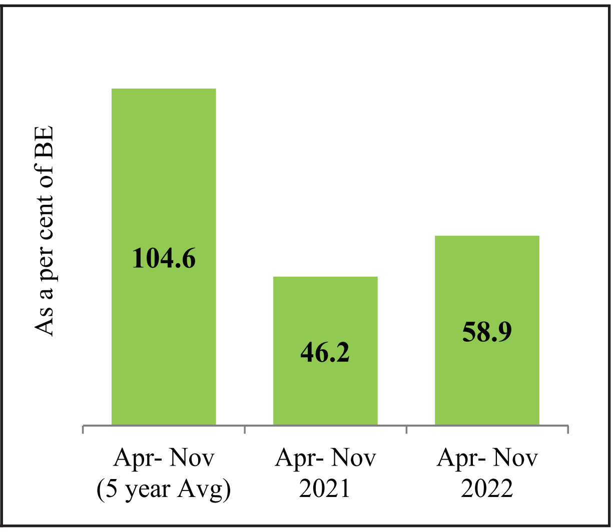

स्रोत: सीजीए कार्यालय

केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2023 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त करने के ट्रैक पर

3.5 वित्तीय वर्ष 2023 का केंद्रीय बजट रिकवरी किए अनिश्चित व्यापक आर्थिक वातावरण में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें वर्ष के दौरान सामने आने वाले भू-राजनीतिक घटनाक्रमों की आशंका नहीं की गई थी। जैसे ही वर्ष की शुरुआत में यूरोप में संघर्ष शुरू हुआ, इसने आपूर्ति के प्रतिबंधों को बढ़ा दिया और इससे ईंधन, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सरकार की राजकोषीय नीति संबंधी कार्रवाई में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी पर अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता हुई, उपभोक्ताओं/उपयोगकर्ताओं को आयात की उच्च कीमतों के जरिएं विशिष्ट शुल्क कटौती लागू की गई। वर्ष के दौरान अतिरिक्त राजकोषीय संसाधनों के दबाव के बावजूद, केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2023 में राजकोषीय घाटे की पूर्ति हेतु बजट अनुमान को प्राप्त करने के सही ट्रैक पर है। नवंबर 2022 के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 58.9 प्रतिशत था, जो इसी अवधि के दौरान बजट अनुमान के 104.6 प्रतिशत के पांच साल के चल औसत (मूविंग एवरेज) से कम है (चित्र 2)।

परंपरागत बजट अनुमान वैश्विक अनिश्चितताओं के दौरान एक बफर प्रदान करना।

3.6 आर्थिक गतिविधियों में सुधार, वर्ष के दौरान देखे गए राजस्व में उछाल और बजट में व्यापक आर्थिक परिवर्तनों की परम्परागत धारणाओं के कारण केंद्र के राजकोषीय प्रदर्शन में यह लचीलापन आया है। वित्तीय वर्ष 2023 के बजट में विवेकपूर्ण धारणाओं ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौरान सरकार को एक बफर प्रदान किया। यद्यपि एक उदाहरण के रूप में, वित्तीय वर्ष 2022 में संशोधित अनुमान से संबंधित सकल कर राजस्व (जीटीआर) के अनुमित उच्च 'अनंतिम वास्तविक' आंकड़ों की परिकल्पना की गई थी। तथापि वैश्विक महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2022 के बाद वित्तीय वर्ष 2023 के बजट अनुमान की जीडीआर में वृद्धि मात्र 1.8 प्रतिशत है। इस निहित (बजट) वृद्धि के विपरीत, वर्ष के पहले आठ महीनों के आंकड़े दर्शाते हैं कि जीटीआर में अत्यधिक उच्च दर से वृद्धि हुई है (तालिका 1)। इस प्रकार वर्ष 2023 के जीटीआर के वार्षिक अनुमान में बजट अनुमानों से अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है।

तालिका: III.1: अप्रैल से नवंबर 2022 तक केंद्र सरकार के राजकोषीय संकेतकों का स्थिर प्रदर्शन

	लाख करोड़ रु.			ब.अ. के प्रतिशत के रूप में		वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)		
	ब.अ. वित्तीय वर्ष 2023	अप्रैल-नवम्बर 2021	अप्रैल-नवम्बर 2022	अप्रैल-नवम्बर 2021	अप्रैल-नवम्बर 2022	लगभग 5 वर्ष अप्रैल-नवम्बर	अप्रैल-नवम्बर 2021	अप्रैल-नवम्बर 2022
राजस्व प्राप्तियां	22.04	13.58	14.23	75.9	64.6	12.3	67.1	4.8
कुल कर राजस्व	27.58	15.42	17.81	69.5	64.6	13.9	50.3	15.5
राज्यों को हस्तांतरित	8.17	4.03	5.51	60.5	67.5	16.6	20.4	36.8
कर राजस्व (केंद्र हेतु शुद्ध)	19.35	11.35	12.25	73.5	63.3	12.9	64.9	7.9
गैर-कर राजस्व	2.70	2.23	1.98	91.8	73.5	13.3	79.5	-11.1
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	0.79	0.21	0.41	11.0	52.3	30.6	14.1	100.4
गैर-ऋण प्राप्तियां	22.84	13.79	14.65	69.8	64.1	12.2	66.0	6.2
कुल व्यय	39.45	20.75	24.43	59.6	61.9	11.4	8.8	17.7
राजस्व व्यय	31.95	18.01	19.96	61.5	62.5	11.4	8.2	10.8
पूंजीगत व्यय	7.50	2.74	4.47	49.4	59.6	12.9	13.5	63.4
राजस्व घाटा	9.90	4.43	5.73	38.8	57.8	11.4	-48.1	29.3
राजकोषीय घाटा	16.61	6.96	9.78	46.2	58.9	11.5	-35.3	40.6
आरंभिक घाटा	7.21	2.34	4.33	33.5	60.1	13.1	-66.2	85.1

Source: O/o CGA

केंद्र सरकार की गैर-ऋण प्राप्तियों का प्रदर्शन

3.7 केंद्र सरकार की गैर-ऋण प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां (कर और गैर-कर) और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। व्यय संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए गैर-ऋण प्राप्तियों की कमी को सरकार की उधारी (राजकोषीय घाटे के रूप में ज्ञात) से पूरा किया जाता है। इस खंड में केंद्र सरकार की आय प्राप्ति के पक्ष के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

पिछले दो वर्षों के दौरान राजस्व निरंतर वृद्धि

3.8 वैश्विक महामारी से प्रभावित वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान गिरावट के बाद, वित्तीय वर्ष 2022 के वैश्विक महामारी के समय में राजस्व प्राप्तियों दोनों वर्ष-दर-वर्ष आधार पर और महामारी-पूर्व वित्तीय वर्ष 2020 (अनुलग्नक 1: तालिका 3) के अनुसार तेजी से वृद्धि हुई। यह राजस्व पुनरुद्धार वित्तीय वर्ष 2022 में सभी प्रमुख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों (उत्पाद शुल्क को छोड़कर) के संग्रह में परिखर्तन करने के कारण हुआ था। राजस्व में पिछले वर्ष की तेजी की गति वर्तमान वर्ष में भी जारी है। सकल कर राजस्व में अप्रैल से नवंबर 2022 तक 15.5 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई और राज्यों को आबंटन के बाद केंद्र को शुद्ध कर राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 7.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका 1, 2)।

तालिकाः III.2: अप्रैल से नवंबर 2022 तक केंद्र सरकार के कर में वृद्धि

	लाख करोड़ रु. में			ब.अ. के प्रतिशत के रूप में		वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)	
	ब.अ. वित्तीय वर्ष 2023	अप्रैल-नवम्बर 2021	अप्रैल-नवम्बर 2022	अप्रैल-नवम्बर 2021	अप्रैल-नवम्बर 2022	अप्रैल-नवम्बर 2021	अप्रैल-नवम्बर 2022
कुल कर राजस्व में से	27.58	15.42	17.81	69.5	64.6	50.3	15.5
प्रत्यक्ष कर	14.20	7.00	8.67	63.1	61.0	66.3	23.9
क. निगम कर	7.20	3.54	4.28	64.6	59.5	90.4	21.1
ख. निगम कर के अलावा आय पर कर	7.00	3.46	4.39	61.7	62.7	47.2	26.7
अप्रत्यक्ष कर	13.30	8.21	8.91	74.5	67.0	38.6	8.5
ग. सीमा शुल्क	2.13	1.26	1.41	92.5	66.4	99.5	12.4
घ. केंद्रीय उत्पाद शुल्क	3.35	2.42	1.91	72.2	57.1	23.2	-20.9
ङ. सेवा कर	0.02	0.01	0.00	50.2	20.4	-52.6	-18.7
च. जीएसटी	7.80	4.53	5.57	71.9	71.5	36.5	23.1

Source: O/o CGA

3.9 आर्थिक विकास द्वारा प्रदर्शित लचीलापन वर्षों से देखी गई निरंतर राजस्व वृद्धि को कम करता है। तथ. ापि, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की तुलना में राजस्व में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है, जो कर के आधार का विस्तार करने और कर अनुपालन के बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की प्रभावशीलता का प्रमाण है। जीएसटी की शुरूआत और आर्थिक लेन-देन के डिजिटलीकरण जैसे संरचनात्मक सुधारों ने अर्थव्यवस्था को अधिक औपचारिक रूप प्रदान किया है और इसलिए करों में भी वृद्धि हुई है। अन्य कर प्रशासन/नीतिगत उपाय, जैसे कि फेसलेस असेसमेंट और अपील, रिटर्न फाइलिंग का सरलीकरण, करदाताओं को सिस्टम से परिचित होने में सहायता, जीएसटी सिस्टम के तहत ई-वे बिल बनाना, और सरकारी विभागों तथा अन्य के बीच सूचना साझा करना आदि ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कर के अनुपालन को बढ़ावा दिया है। विवरण अनुलग्नक 2 और 3 में देखा जा सकता है।

सकल कर राजस्व में वृद्धि को बढ़ावा देने वाले प्रत्यक्ष कर

3.10 प्रत्यक्ष कर, जो मोटे तौर पर सकल कर राजस्व (चित्र 3) का आधा हिस्सा हैं, ने अप्रैल से नवंबर 2022 तक 26 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की है, जो कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आयकर वृद्धि द्वारा हुई है। वित्तीय वर्ष 2023 के पहले आठ महीनों के दौरान प्रमुख प्रत्यक्ष करों में देखी गई वृद्धि दर उनके दीर्घावधि औसत (चित्र 4) की तुलना में बहुत अधिक थी।

सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क का फ्लेक्सी-फिस्कल पॉलिसी टूल के रूप में कार्य करना

आकृतिः III.3: केंद्र सरकार के कर विवरण के घटक

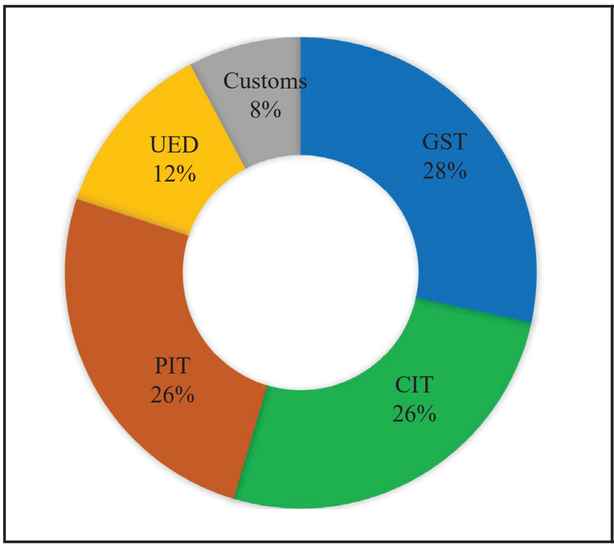

आकृतिः III.4: अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान केंद्र के प्रत्यक्ष करों में वृद्धि उनके दीर्घावधि औसत से अधिक है

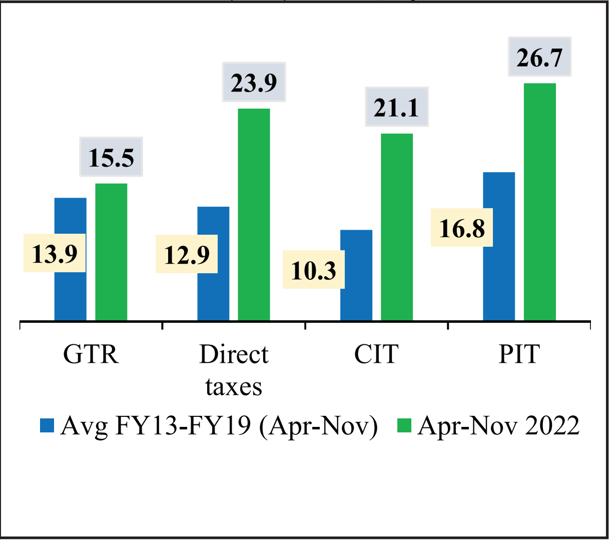

जीएसटी - वस्तु एवं सेवा कर, यू.ई.डी.- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सी.आई.टी. - कॉरपोरेट टैक्स, पी.आई.टी- आयकर

स्रोतः केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 2023

सकल कर राजस्व प्रत्यक्ष करए निगम कर निगम कर के अलावा आय पर कर

स्रोतः सीजीए कार्यालय

3.11 जबकि प्रत्यक्ष करों ने राजस्व में हुई तेजी की सुरक्षा की है, अप्रत्यक्ष करों जैसे कि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क ने वैश्विक महामारी में राजकोषीय कार्रवाई के दौरान फ्लेक्सीवल पॉलिसी टूल के रूप में काम किया है। जब महामारी वर्ष वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वैश्विक तेल की कम कीमतों ने पेट्रोलियम पर कर बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया, तो सरकार ने राजस्व पूल को बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया। इसके बाद, जब अन्य करों में सुधार हुआ, और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दबाव बना, तो सरकार ने उपभोक्ताओं पर बढ़ती वैश्विक तेल कीमतों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए नवंबर 2021 और मई 2022 में उत्पाद शुल्क घटा दिया। वित्तीय वर्ष 2023 के उत्पाद शुल्क संग्रह पर बजट अनुमान में 15 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। अपेक्षा के अनुरूप, अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान उत्पाद शुल्क संग्रह में वर्ष दर वर्ष आधार पर 20.9 प्रतिशत की गिरावट आई है।

3.12 वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान आवश्यक आयातित उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए, खाद्य तेलों, दालों, सूत, स्टील आदि पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क को कम किया गया था। तथापि, चालू वर्ष के दौरान उच्च आयात के कारण वर्ष-दर-वर्ष अप्रैल-नवंबर 2022 (तालिका 2) की अवधि में सीमा शुल्क संग्रह में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो वित्तीय वर्ष 2013 से वित्तीय वर्ष 2019 की इसी अवधि के दौरान हुई औसत वृद्धि से अधिक है।

वस्तु एवं सेवा कर आधारित रिटर्न को स्थिर करना

3.13 केंद्र और राज्य सरकारों के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत के रूप में विकसित और स्थिर हो गया है (बॉक्स1 देखें)। उनका कुल सकल जीएसटी संग्रह, अप्रैल से दिसंबर 2022 तक 13.40 लाख करोड़ था। इस प्रकार, 24.8 प्रतिशत (चित्र 5) वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई। 1.5 लाख करोड़ रु. (चित्र 6) के औसत मासिक संग्रह के साथ चालू वित्त वर्ष के दौरान सभी महीनों में जीएसटी संग्रह में लगातार वृद्धि हुई। वैश्विक महामारी के बाद तेजी से हुई आर्थिक रिकवरी हाल ही में किए गए कई प्रणालीगत

परिखर्तनों जीएसटी चोरी करने वालों और फर्जी बिलों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के साथ और जीएसटी परिषद द्वारा असंगत कर संरचना को सही करने के लिए किए गए विभिन्न तर्क संगत उपायों के संयुक्त प्रभाव के कारण जीएसटी संग्रह में सुधार हुआ है। लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप जीएसटी का दायरा दोगुना हो गया है, जिसमें जीएसटी करदाताओं की संख्या वर्ष 2017 में 70 लाख से बढ़कर वर्ष 2022 में 1.4 करोड़ से अधिक हो गई है। सीधे तौर पर सरकारी राजस्व में इजाफा करने के अलावा, जीएसटी से आय बेहतर हुई है, जिसका आयकर संग्रह और आर्थिक गतिविधि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा हैं।

आकृति- III.5: अप्रैल से दिसंबर तक संचयी सकल जीएसटी संग्रह में वर्ष-दर-वर्ष उच्च वृद्धि

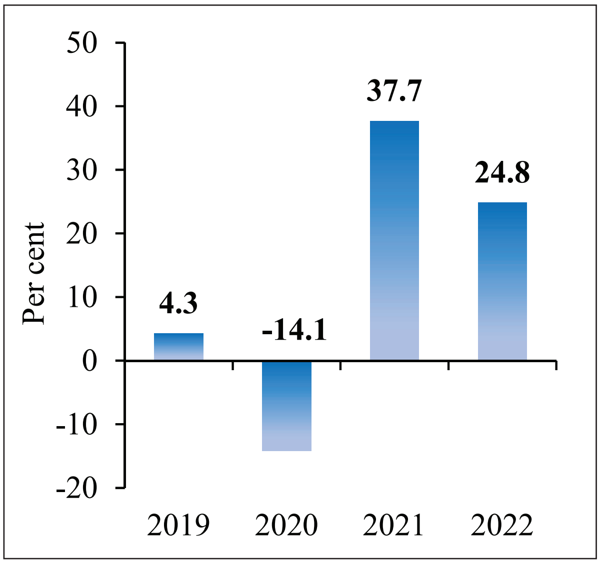

स्रोतः सीजीए कार्यालय

आकृति III.6: पिछले कई वर्षों से मासिक सकल जीएसटी संग्रह में निरंतर वृद्धि

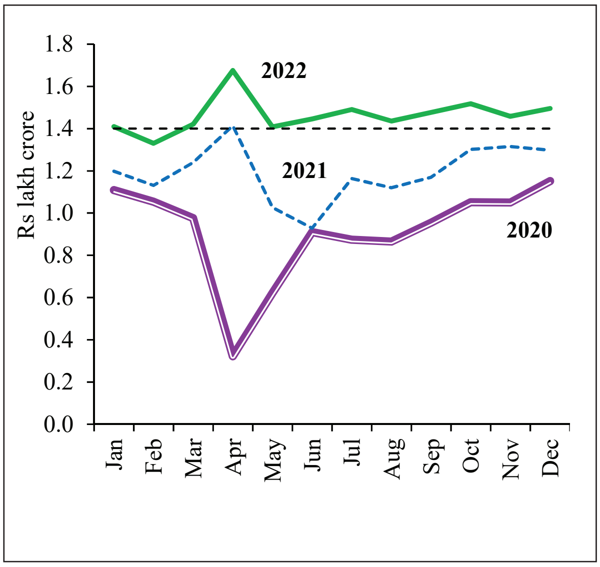

स्रोतः राजस्व विभाग

बॉक्स 1: अप्रत्यक्ष कर संग्रह की परिपक्व प्रणाली

क्या जीएसटी लागू होने से भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की वृद्धि में सुधार हुआ है या यह बिगड़ गई है? यह बॉक्स इस प्रश्न पर प्रकाश डालने के लिए एक विश्लेषणात्मक प्रयास करता है।

जीएसटी में समाहित कुल राज्य और केंद्रीय करों ने जीएसटी से पूर्व की अवधि (वित्तीय वर्ष 2013 से वित्तीय वर्ष 2017) में सीएजीआर 11.53 प्रतिशत का दर्शाई गई। इस अवधि के दौरान सामान्य जीडीपी 11.54 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ी (तालिका 1क की मद 1 से 7 देखें)। चूंकि समाहित करों की वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की तुलना में मामूली रूप से कम थी, अतः वृद्धि एक से नीचे थी और व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एक के रूप में मानी जा सकती है।

जीएसटी के बाद की अवधि में कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, सबसे महत्वपूर्ण रूप से कोविड वैश्विक महामारी का बाह्य झटका। जीएसटी के बाद के वर्षों (वित्तीय वर्ष 2019 से वित्तीय वर्ष 2023) में सामान्य जीडीपी में 9.6 प्रतिशत की धीमी सीएजीआर से वृद्धि हुई। तथापि, जीएसटी संग्रह में 10.9 प्रतिशत के सीएजीआर से वृद्धि हुई है (तालिका के मद 8 से 10 देखें)। इस प्रकार, कुल जीएसटी संग्रह में लगभग 1.1 की वृद्धि देखी गई है। यह तब भी हुआ है जब प्रभावी जीएसटी दर शुरुआत से गिर गई है (आरबीआई के अनुसार वर्ष 2017 में 14.4 प्रतिशत से घटकर 2019 में 11.6 प्रतिशत)।

[2]PMEAC Report- ‘GST-Connecting the remaining dots’, June 2022

बेहतर कर संग्रह की क्षमता जीएसटी के पक्ष में मुख्य तर्कों में से एक था। अब तक के साक्ष्यों से पता चलता है कि वास्तव में जीएसटी में पूर्व-जीएसटी प्रणाली की तुलना में अधिक वृद्धि दिख रही है। अर्थव्यवस्था में भविष्य में संसाधन जुटाने के लिए यह शुभ संकेत है।

तालिका 1क: जीएसटी में समाहित सभी करों के प्रदर्शन की तुलना (पूर्व बनाम जीएसटी के बाद की अवधि)

तालिका 1.क जीएसटी से पहले की अवधि

	वित्तीय वर्ष 2013	वित्तीय वर्ष 2014	वित्तीय वर्ष 2015	वित्तीय वर्ष 2016	वित्तीय वर्ष 2017	सीएजीआर (वित्तीय वर्ष 2013 से वित्तीय वर्ष 2017)
				लाख करोड़ रु.		
जीएसटी में सम्मिलित राज्य कर						
1. राज्य का जीएसटी पोर्टल पर सम्मिलित कुल कर संग्रह	2.86	3.09	3.32	3.97	3.92	
2. जीएसटी में सम्मिलित संबंधित कुल राज्य कर @	3.22	3.48	3.73	4.41	4.41	
3. जीएसटी में सम्मिलित संबंधित कुल राज्य कर						
राज्य का जीएसटी पोर्टल पर सम्मिलित कुल कर संग्रह	0.33	0.35	0.34	0.37	0.60	
4. सेवा कर	1.33	1.55	1.68	2.11	2.54	
5. जीएसटी में सम्मिलित कुल केंद्रीय कर	1.66	1.90	2.02	2.48	3.14	
6. जीएसटी में सम्मिलित कुल कर (केंद्र + राज्य)	4.88	5.37	5.75	6.90	7.55	11.53%
7. नाममात्र जीडीपी	99.44	112.34	124.68	137.72	153.92	11.54%
जीएसटी में सम्मिलित कुल करो की वृद्धि						**0.9988**

तालिका 1.ख जीएसटी के बाद की अवधि

	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2022	वित्तीय वर्ष 2023*	सीएजीआर
				लाख करोड़ रु.		
कुल जीएसटी संग्रह (घरेलू आपूर्ति)	8.77	9.44	8.66	10.98	12.94	10.2%
कुल जीएसटी संग्रह (आयात पर जीएसटी सहित)	11.77	12.22	11.37	14.90	17.80	10.9%
भारत की नाममात्र जीडीपी	189.00	200.75	198.01	236.65	273.09	9.6%
जीएसटी संग्रह की वृद्धि (घरेलू आपूर्ति)						**1.0603**
जीएसटी संग्रह की वृद्धि (आयात पर जीएसटी सहित)						**1.1299**

नोट: (क) जीएसटी में सामूहिक राज्य करों को जीएसटी पोर्टल से लिया गया है। चूंकि पोर्टल में प्रस्तुत किए गए आकड़ों में गुजरात, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश के लिए सामूहिक राज्य कर शामिल नहीं हैं, सभी समावेशी संग्रह आंकड़ों (पंक्ति ख) पर पहुंचने के लिए आकड़ों को बढ़ाया गया है।

(ख) ' मई से दिसंबर 2022 तक के औसत संग्रहण के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023 के संग्रहण में विस्तार किया गया है।

स्रोत: जीएसटी पोर्टल, केंद्रीय बजट, सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, पत्र सूचना कार्यालय विज्ञप्ति

केंद्र गैर-कर राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने के ट्रैक पर

14. केंद्र के गैर-कर राजस्व में मुख्य रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्तियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त लाभांश और लाभ तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए होने वाली बाहरी अनुदान और प्राप्तियां शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 के बजट में चालू वर्ष के दौरान गैर-कर राजस्व प्राप्तियों का संग्रहण कम होने की परिकल्पना की गई है (वित्तीय वर्ष 2022 के पीए की तुलना में लगभग 22.5 प्रतिशत कम) (तालिका 3)। नवंबर 2022 तक बजट राशि का 73.5 प्रतिशत एकत्र किया जा चुका है।

तालिका III.3: केन्द्र सरकार के गैर-कर राजस्व की प्रवृति

	2018 वित्तीय वर्ष	2019 वित्तीय वर्ष	2020 वित्तीय वर्ष	2021 वित्तीय वर्ष	2022 प्रतिवर्ष	वित्तीय वर्ष 2023 बजट अनुमान	अप्रैल-नवम्बर 2022
							(लाख करोड़ रु. में)
ब्याज प्राप्तियां	0.14	0.12	0.12	0.17	0.22	0.18	0.17
लाभांश और मुनाफा	0.91	1.13	1.86	0.97	1.61	1.14	0.68
विदेशी अनुदान	0.04	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01
अन्य	0.84	1.07	1.27	0.90	1.64	1.34	1.12
गैर-कर राजस्व	1.93	2.36	3.27	2.08	3.48	2.70	1.98

Source: Office of CGA

विनिवेश के प्रति प्रतिबद्ध परन्तु विदेशी कारकों पर निर्भर

3.15 केंद्र सरकार के कर और गैर-कर राजस्व के अलावा, गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, जिसमें ऋण और अग्रिम की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं, केंद्र सरकार की गैर-ऋण प्राप्तियों के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में विकसित हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2015 से वित्तीय वर्ष 2023 (18 जनवरी 2023 तक) के दौरान, विभिन्न तरीकों/लिखतों का उपयोग करके 154 लेनदेन के माध्यम से विनिवेश से प्राप्त आय के रूप में लगभग रु4.07 लाख करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। इसमें अल्पसंख्यक हिस्सेदारी की बिक्री से प्राप्त रु3.02 लाख करोड़ और रणनीतिक विनिवेश लेनदेन (10 सीपीएसई - एचपीसीएल, आरईसी, डीसीआईएल, एचएससीसी, एनपीसीसी, नीपको, टीएचडीसी, कामराजार पोर्ट, एयर इंडिया और एनआईएनएल) से प्राप्त रु 69,412 करोड़ शामिल हैं।

3.16. पिछले तीन वर्षों के दौरान वैश्विक महामारी से उत्पन्न अनिश्चितता, भू-राजनीतिक संघर्ष और संबंधित जोखिमों ने सरकार की विनिवेश लेनदेन संबंधी योजनाओं और संभावनाओं के सामने चुनौतियां पेश की हैं। फिर भी, सरकार ने नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति और आस्ति मुद्रीकरण रणनीति को लागू करके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण और रणनीतिक विनिवेश के प्रति पुनः अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की है। वित्तीय वर्ष 2023 में 65,000 करोड़ रुपये की बजट राशि में से, 18 जनवरी 2023 तक 48 प्रतिशत संग्रह किया गया है।

केंद्र सरकार के व्यय का प्रदर्शन

पुनः प्राथमिकता की व्यावहारिक व्यय नीति

3.17 पिछले कुछ वर्षों में संकट के दौरान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए काउंटर साइकल राजकोषीय नीति संबंधी उपायों के महत्व पर बल दिया गया है। वैश्विक महामारी ने वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान अतिरिक्त व्यय संबंधी आवश्यकताओं को अनिवार्य कर दिया। वित्तीय वर्ष 2021 में केंद्र सरकार का कुल व्यय बढ़कर जीडीपी

का 17.7 प्रतिशत हो गया, जो पिछले 5-वर्ष की औसत जीडीपी के 12.8 प्रतिशत से अधिक है (अनुलग्नक 1: तालिका 2)। सरकार ने अंशांकित तरीके से अपने व्यय को बढ़ाने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। कमजोर वर्गों के लिए बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर, सरकारी व्यय में उत्पादक घरेलू पूंजीगत व्यय पर बल दिया गया। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2022 में कुल केंद्र सरकार का व्यय कम करके जीडीपी (पीए) का 16 प्रतिशत कर दिया गया था, और इसका एक बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय (चित्र 7) के लिए एकत्र किया गया था। केंद्र द्वारा पूंजीगत व्यय में जीडीपी के 1.7 प्रतिशत (वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2020) के दीर्घकालिक औसत से वित्तीय वर्ष 2022 पीए में जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक की लगातार वृद्धि की गई है। वित्तीय वर्ष 2023 में इसे जीडीपी के 2.9 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। (चित्र 8)। यह वर्षों के दौरान सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार पर प्रकाश डालता है।

आकृति III.7: केंद्र सरकार का जीडीपी अनुपात में कैपेक्स पूर्व के दीर्घावधि औसत से अधिक है

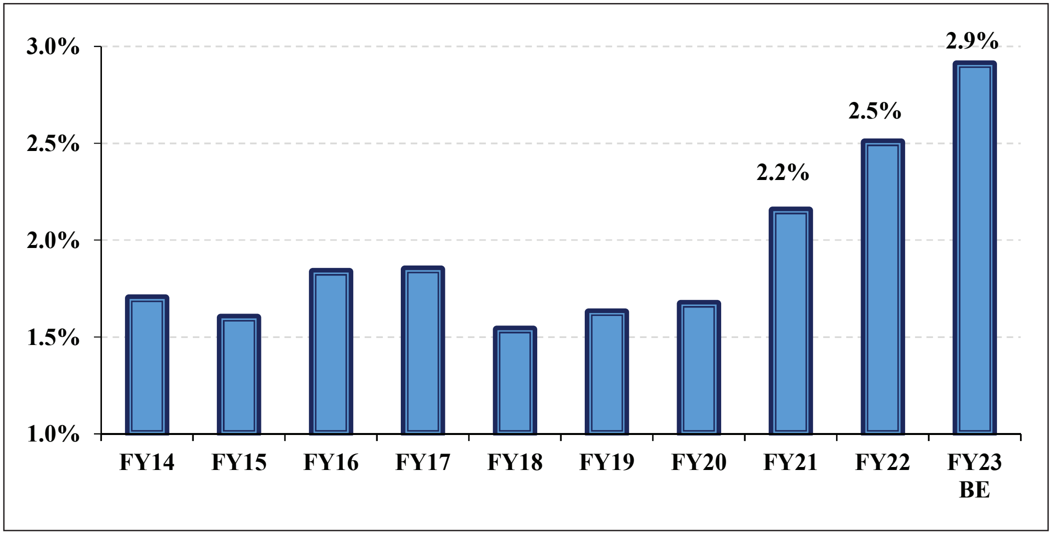

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज, सीजीए कार्यालय

आकृति III.8: केंद्र सरकार के कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का बढ़ता हुआ अंश

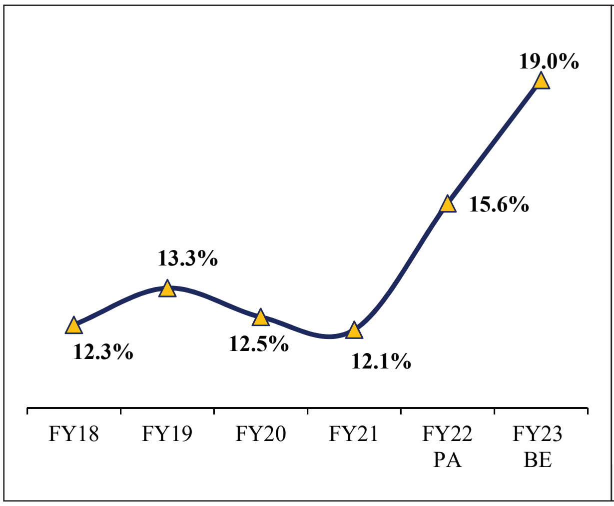

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज, सीजीए कार्यालय

आकृति III.9: अप्रैल से नवम्बर की अवधि में केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में बड़ी वृद्धि

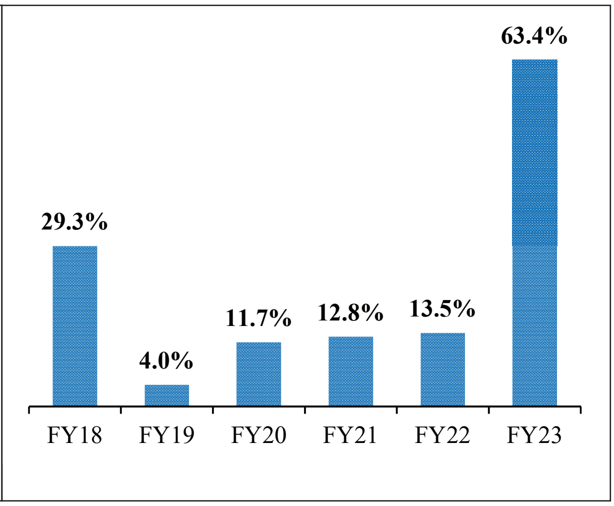

स्रोत: राजस्व विभाग

केपेक्स आधारित वृद्धि उत्साह लौटाने और कर्ज के स्तर नियंत्रित करने के लिए

3.18. निरपेक्ष रूप से, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए अभूतपूर्व 7.5 लाख करोड़ रु. के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा था, जिसमें से अप्रैल से नवंबर 2022 तक 59.6 प्रतिशत से अधिक खर्च किया जा चुका है। इस अवधि के दौरान, पूंजीगत व्यय में वर्ष-दर-वर्ष 60 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्तीय वर्ष 2016 से वित्तीय वर्ष 2020 की इसी अवधि में दर्ज की गई 13.5 प्रतिशत की दीर्घकालिक औसत वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक है। (चित्र 9)

3.19. सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय, विशेष रूप से सड़क एवं राजमार्ग, रेलवे और आवास तथा शहरी मामलों जैसे अवसंरचनात्मक-गहन क्षेत्रों पर बल देने से विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा हैं (तालिका 4)। जबकि ओर, पूंजीगत व्यय जोखिम से बचने के समय में कुल मांग को मजबूत करता है और निजी खर्च में वृद्धि करता है; यह लंबी अवधि की आपूर्ति-पक्ष संबंधी उत्पादक क्षमता को भी बढ़ाता है। हाल के महीनों में निजी क्षेत्र के निवेश में वापसी के शुरुआती संकेतों के साथ, पूंजीगत व्यय ने अपनी भूमिका निभाई है (विवरण अध्याय 1 में)। सभी दिशाओं से कैपेक्स बढ़ाने पर जोर देने के लिए, केंद्र ने लंबी अवधि के ब्याज मुक्त ऋण और कैपेक्स से जुड़े अतिरिक्त उधार प्रावधानों के रूप में राज्यों के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहनों की घोषणा की।

तालिका III. 4: केंद्र का अवसंरचना से जुड़े क्षेत्रों पर आधारित पूंजीगत व्यय

	बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2023	अप्रैल-नवम्बर 2022	अप्रैल-नवम्बर 2021	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि
	लाख करोड़ रु.			(प्रतिशत)
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	1.88	1.49*	0.74	102.10
रेलवे	1.37	1.15	0.65	76.65
रक्षा सेवाएं (पूंजीगत परिव्यय)	1.52	0.73	0.73	0.88
राज्यों को हस्तांतरित	1.12	0.43	0.08	438.54
दूरसंचार	0.54	0.25	0.03	692.43
आवास और शहरी कार्य	0.27	0.11	0.17	-32.47
आण्विक ऊर्जा	0.14	0.09	0.06	47.50
रक्षा (सिविल)	0.08	0.05	0.04	22.13
पुलिस	0.11	0.05	0.03	53.22
अंतरिक्ष	0.07	0.02	0.04	-48.74
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	0.06	0.01	0.02	-16.33

नोट: ' जिनमें से 1.44 लाख करोड़ रु. पूंजीगत वण्ड से रिजर्व निधियों में अंतर-लेवा-हस्तांतरण के कारण है।

स्रोत: सीजीए कार्यालय

भू-राजनीतिक विकास से राजस्व व्यय संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि

3.20 केंद्र के राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण घटकों में ब्याज भुगतान, प्रमुख सब्सिडी, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, रक्षा राजस्व व्यय और राज्यों को स्थानांतरण शामिल हैं (तालिका 5)। केंद्र के राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध है और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त राजकोषीय हेडरूम बनाने में सीमित लचीलेपन की अनुमति देता है। तथापि, कुल मांग को प्रोत्साहित करने और फनर्वितरण संबंधी अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए व्यय को फिर से प्राथमिकता देना और सब्सिडी को यफक्तिसंगत बनाना आवश्यक साधन (टूल) हैं।

तालिका III. 5: केंद्र सरकार द्वारा किए गए राजस्व व्यय की प्रमुख मदें

मदें	वित्तीय वर्ष 2018	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2022 प्रतिवर्ष*	वित्तीय वर्ष 2023 बजट अनुमान
						(लाख करोड़ रु. में)
राजस्व व्यय जिसमें से	18.79	20.07	23.51	30.84	32.01	31.95
क. वेतन (वेतन एवं भत्ते)	1.94	2.11	2.28	3.34	3.67	4.10
ख. पेंशन	1.46	1.6	1.84	2.08	1.99	2.07
ग. ब्याज भुगतान	5.29	5.83	6.12	6.80	8.05	9.41
घ. प्रमुख सब्सिडी	1.91	1.97	2.28	7.08	4.46	3.18
ङ. रक्षा सेवाएं	1.86	1.96	2.08	2.06	2.29	2.33

नोट: वित्तीय वर्ष 2022 के लिए वेतन संशोधित अनुमान हैं
स्रोत: बजट दस्तावेज, सीजीए कार्यालय

3.21 वैश्विक महामारी से संबंधित सहायता को समाप्त करने के साथ, केंद्र सरकार का राजस्व व्यय वैश्विक महामारी वित्तीय वर्ष 2021 में जीडीपी के 15.6 प्रतिशत से घटाकर वित्तीय वर्ष 2022 पीए में जीडीपी का 13.5 प्रतिशत कर दिया गया (अनुलग्नक 1: तालिका 2)। सब्सिडी व्यय में कमी के कारण यह संकुचन किया गया था क्योंकि अर्थव्यवस्था वैश्विक महामारी से उबर गई थी। सब्सिडी व्यय को वित्तीय वर्ष 2021 में जीडीपी के 3.6 प्रतिशत से घटाकर वित्तीय वर्ष 2022 पीए में जीडीपी का 1.9 प्रतिशत कर दिया गया। इसको आगे वित्तीय वर्ष 2023 में जीडीपी के 1.2 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था।

3.22 भू-राजनीतिक संघर्ष के अचानक प्रकोप के परिणामस्वरूप खाद्य, उर्वरक और ईंधन के लिए उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ीं, लोगों को सहायता प्रदान करने और बृहत आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उच्च खाद्य और उर्वरक सब्सिडी की आवश्यकता थी। अप्रैल से नवंबर 2022 तक सब्सिडी पर बजटीय व्यय का लगभग 94.7 प्रतिशत उपयोग किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में, केंद्र सरकार ने खाद्य सब्सिडी और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेओवाई) तथा वर्ष के दौरान आवश्यक उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.09 लाख करोड़ रु. के अंतर्गत अतिरिक्त आवंटन के लिए अतिरिक्त 80,000 करोड़ रुपये की मांग की है। परिणामस्वरूप, अप्रैल से नवंबर 2022 तक राजस्व व्यय में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज की गई वृद्धि से अधिक है (तालिका 1)।

3.23 वैश्विक महामारी से पूर्व के वर्षों के दौरान राजस्व व्यय के एक अन्य प्रमुख घटक, ब्याज भुगतान, ने गैर-ऋण प्राप्तियों और राजस्व व्यय के एक स्थिर अनुपात बनाए रखा था (चित्र 10)। वैश्विक महामारी के दौरान संसाधन संबंधी उच्चतर आवश्यकताओं और कम राजस्व संग्रह के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार द्वारा अधिक उधारी ली गई। वैश्विक महामारी फैलने के बाद प्राप्तियों के अनुपात में ब्याज के भुगतान बढ़ गए। तथापि, मध्यम अवधि में, जैसे-जैसे हम राजकोषीय ग्लाइड पथ पर आगे बढ़ेंगे, राजस्व में वृद्धि, तीव्र आस्ति मुद्रीकरण, दक्षता लाभ और निजीकरण से सार्वजनिक ऋण का भुगतान करने में मदद मिलेगी, इस प्रकार ब्याज भुगतान में कमी आएगी और अन्य प्राथमिकताओं के लिए अधिक धन जारी होगा।

रेखाचित्र III.10: संसाधन जुटाने के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उच्च-ब्याज भुगतान को कम किया जाना

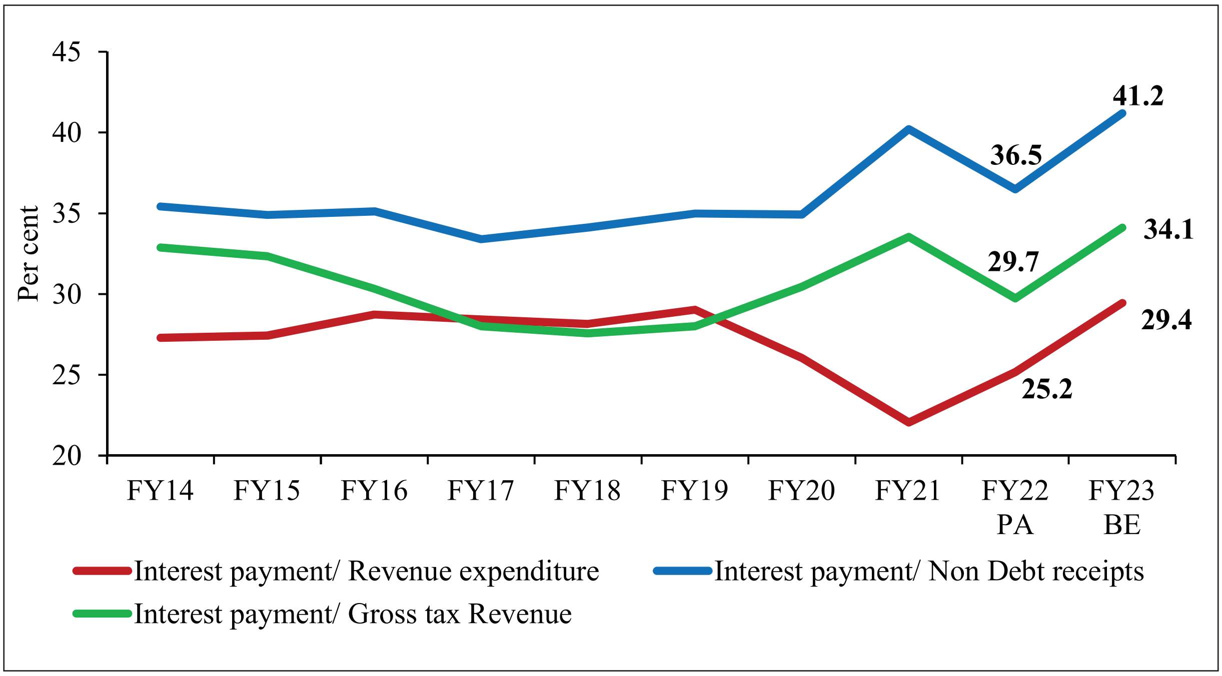

स्रोत: सीजीए कार्यालय, बजट दस्तावेज

3.24. केंद्र सरकार की वित्तीय व्यवस्था के इस अवलोकन से यह स्पष्ट है कि केंद्र की चालू वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त व्यय आवश्यकताओं को अनुमानित से अधिक राजस्व संग्रह द्वारा पूरा किए जाने की आशा है। इस प्रकार, यह आशा है कि वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान राजकोषीय घाटे के बजट अनुमान तक पहुंचना केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं होगा। लचीले आर्थिक विकास, निरंतर राजस्व वृद्धि और मध्यम अवधि में सावधानीपूर्वक व्यय प्रबंधन के साथ, केंद्र सरकार मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण द्वारा उल्लिवित राजकोषीय पथ के साथ ट्रैक पर होगी। इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए बजटीय सुधार राजकोषीय नीति संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेंगे (बॉक्स 2)।

बॉक्स 2: पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय बजट में किए गए प्रमुख सुधार

एक पारदर्शी और संतुलित बजटीय प्रक्रिया बेहतर वित्तीय प्रबंधन होता है। इस खंड में पिछले कुछ वर्षों के दौरान केंद्रीय बजट में शुरू किए गए कुछ प्रमुख प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा की गई है, जिनके परिणामस्वरूप सार्वजनिक व्यय अधिक सक्षम हुआ है।

1. बजट में बेहतर राजकोषीय पारदर्शिता और वास्तविक राजस्व अनुमान

केंद्र सरकार ने सीमा से अधिक के व्यय को सीमा नीचे लाकर अपने वित्तीय विवरणियों और खातों की पारदर्शिता में सुधार करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। केंद्र सरकार की अतिरिक्त-बजटीय उधारी को वित्तीय वर्ष 2020 में रु1.48 लाख करोड़ और वित्तीय वर्ष 2021 में रूपये 1.21 लाख करोड़ से घटाकर वित्तीय वर्ष 2022 (स.अ.) में रु750 करोड़ कर दिया गया। बजट में वित्तीय वर्ष 2023 के लिए कोई अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का अनुमान नहीं लगाया गया था।

[3]Section 3- Budget preparation - Guidelines for Public Expenditure Management (IMF, 1999)- https://www.imf.org/external/pubs/ft/expend/guide3.htm

स्वच्छ राजकोषीय लेवांकन के अलावा, बजट 2022 ने अपने राजस्व अनुमानों को यथार्थवादी मान्यताओं पर आधारित किया, इस प्रकार अनिश्चित वैश्विक वातावरण में सरकार को एक बफर प्राप्त हुआ। ये उपाय ठोस वित्तीय प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को विश्वसनीय रूप से प्रदर्शित करते हैं और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त बफर प्रदान करते हैं।

2. योजना-गैर योजना वर्गीकरण को समाप्त करना[4]

वित्तीय वर्ष 2018 के बजट में सरकारी व्यय के योजनागत और गैर-योजनागत वर्गीकरण को बंद कर दिया गया है। इस सुधार ने सरकारी व्यय के राजस्व और पूंजी वर्गीकरण पर अधिक बल दिया। वर्षों से, एक व्यापक समझ यह रही है कि योजनागत व्यय अच्छे थे और गैर-योजनागत व्यय खराब थे, जिसके परिणामस्वरूप बजटीय में आवंटन में कमी आई। इस सुधार ने प्रभावी नियोजन और बजट में संसाधनों के आवंटन को सक्षम किया।

3. रेल बजट का मुख्य बजट में विलय[5]

वित्तीय वर्ष 2018 से रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया था। इस सुधार ने सरकार की वित्तीय स्थिति की समग्र तस्वीर प्रस्तुत की। इस पहल में राजमार्गों, रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्गों के बीच मल्टीमॉडल परिवहन योजना को सुगम बनाने की परिकल्पना की गई थी, जिसे गतिशक्ति के माध्यम से बाद के वर्षों में मजबूत किया गया है।

इस सुधार ने रेलवे और केंद्र सरकार दोनों के लिए संसाधनों की दक्षता बढ़ाने में मदद की है। जबकि इस विलय ने रेलवे को सरकारी राजस्व के लाभांश का भुगतान करने से छूट दी है, तथापि यह संसाधनों के बेहतर आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय को मध्य-वर्ष की समीक्षा में अधिक अवसर प्रदान करता है। हाल के वर्षों में इसने वित्त मंत्रालय को सभी क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय पर एक सुसंगत बल देने को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया है।

4. बजट की तारीख को बदलकर 1 फरवरी तक शिफ्ट करना

बजट की तारीख को वित्तीय वर्ष 2018 के बजट से 1 फरवरी कर दिया गया था। बजट को एक महीने पहले प्रस्तुत करने से बजट चक्र के जल्द पूरा होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसने मंत्रालयों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से योजनाओं की बेहतर आयोजना और निष्पादन सुनिश्चित करने में भी सक्षम बनाया है।

राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था का अवलोकन

राज्य की वित्तीय व्यवस्था का प्रदर्शन

3.25 वित्तीय वर्ष 2021 में वैश्विक महामारी से बुरी तरह से प्रभावित होने के बाद राज्य सरकारों ने वित्तीय वर्ष 2022 में अपनी वित्तीय व्यवस्था में सुधार किया। राज्यों का संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी), जो वैश्विक महामारी से प्रभावित वर्ष में जीडीपी के 4.1 प्रतिशत तक बढ़ गया था, वित्तीय वर्ष 2022 में घटकर 2.8 प्रतिशत हो गया था। भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं को देखते हुए, राज्यों के लिए समेकित जीएफडी-जीडीपी अनुपात वित्तीय वर्ष 2023 में जीएसडीपी के 3.4 प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया गया है (चित्र III- 11)। तथापि, सीएजी के कार्यालय द्वारा जारी राज्यों के मासिक राजकोषीय लेखा आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल-नवंबर 2022 से, प्रमुख 27 राज्यों की संयुक्त उधारी वर्ष के लिए उनके कुल बजटीय उधार के 33.5 प्रतिशत तक ही पहुंच पाई है (चित्र III-12)।

[4]https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=136996
[5]https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=153672

चित्र III-11: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों के घाटे का समेकन

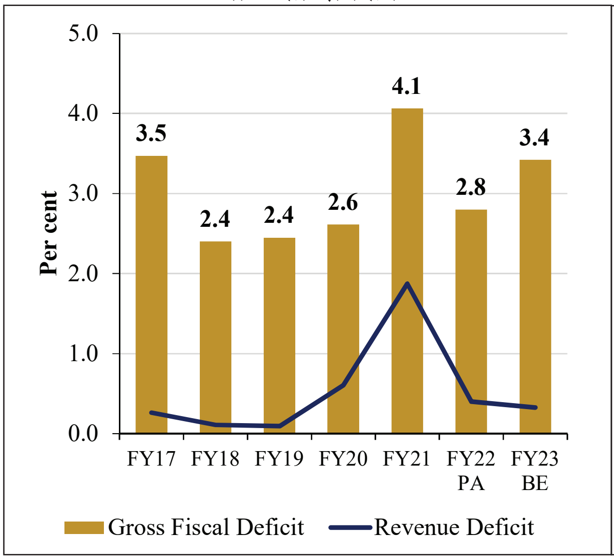

चित्र III-12: अप्रैल-नवंबर के दौरान राज्यों का कम राजकोषीय घाटा

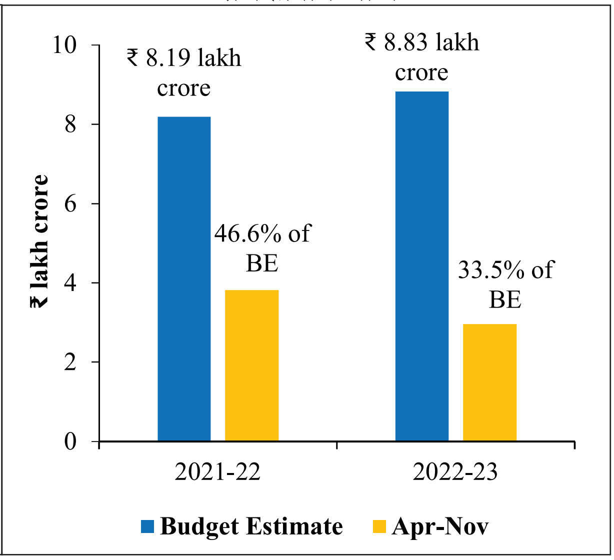

स्रोत: राज्यों के बजट जनवरी, 2023, आरबीआई का अध्ययन, सीएजी कार्यालय
नोट: चित्र 12 में 27 राज्यों के आंकड़े शामिल हैं

3.26 यह ध्यान रखना उचित है कि राज्यों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उधार लेने की सीमा का उपयोग नहीं किया था। राज्य सरकारों की संसाधन संबंधी बाधाओं को देखते हुए, केंद्र ने राज्यों के लिए निवल उधारी सीमा (एनबीसी) को वित्तीय वर्ष 2021 में जीएसडीपी के 5 प्रतिशत, वित्त वर्ष 22 में जीएसडीपी के 4 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2023 में जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया।

3.27 राज्य सरकारों के वित्तीय वर्ष 23 बजट अनुमानों के अनुसार, राज्यों के संयुक्त स्वयं के कर राजस्व और स्वयं के गैर-कर राजस्व को वित्त वर्ष 22 सं.अ. के मुकाबले क्रमशः 17.5 प्रतिशत और 25.6 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान था। यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 22 सं.अ. में देखे गए वृद्धि की गति की निरंतरता है। व्यय पक्ष पर, वित्तीय वर्ष 22 ब.अ. में राजस्व और पूंजीगत व्यय क्रमशः वित्तीय वर्ष 22 सं.अ. के मुकाबले 10.4 प्रतिशत और 16 प्रतिशत बढ़ने की परिकल्पना की गई थी। राज्य के वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पूंजीगत परिव्यय, पूंजीगत व्यय का एक हिस्सा है, ने संशोधित अनुमानों की तुलना में अनंतिम वास्तविक में उच्च वृद्धि दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 22 पीए में राज्यों का पूंजीगत परिव्यय 31.7 प्रतिशत बढ़ा। यह वृद्धि मजबूत राजस्व उछाल और राज्यों को भुगतान की अग्रिम निर्गम, जीएसटी मुआवजा भुगतान और ब्याज मुक्त ऋण के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता के कारण है। राज्य के वित्त की सहायता करने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर आगामी भागों में चर्चा की गई है।

सहकारी राजकोषीय संघवाद एक भलीभांति से लक्षित राजकोषीय नीति को संचालित करता है

केंद्र से राज्यों में हस्तांतरण

3.28 राज्यों को निधियों के हस्तांतरण में राज्यों को हस्तांतरित केंद्रीय करों, वित्तीय आयोग के अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस), और अन्य हस्तांतरणों में राज्यों का हिस्सा शामिल है। वित्तीय वर्ष 2019 और वित्तीय वर्ष 2023 बजट अनुमानों के बीच राज्यों को कुल हस्तांतरण में वृद्धि हुई है (तालिका प्प् 6 देखें)।

तालिका III 6: केंद्र से राज्यों को किए गए हस्तांतरण का विवरण (राज्यों के लिए अंतरण के अलावा)

	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2022	संशोधित अनुमान वित्तीय वर्ष 2023 बजट अनुमान
					लाख करोड़ रु. में
केंद्र प्रायोजित योजनाएं	3.0	3.1	3.8	4.2	4.4
वित्त आयोग के अनुदान	0.9	1.2	1.8	2.1	1.9
अन्य अनुदान/ऋण/हस्तांतरण	0.9	2.0	1.9	2.3	3.0

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज

3.29 वित्त आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकायों को अनुदान, स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान और आपदा प्रबंधन अनुदान के संबंध में वित्तीय वर्ष 2023 में 1.92 लाख करोड़ रु. की राशि के आवंटन की सिफारिश की थी। चालू वर्ष के दौरान जारी अनुदानों का विवरण नीचे तालिका 7 में देखा जा सकता है।

तालिका III 7: 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकारों को अनुदान का आवंटन (करोड़ रु)

क्र.सं.	घटक	वित्तीय वर्ष 2023 के लिए आवंटन	जारी की गई राशि (22 नवम्बर, 2022 की स्थिति के अनुसार)
1	अंतरण के बाद राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए अनुदान	86,201	57,467
2	आपदा प्रबंधन संबंधी अनुदान (केंद्रीय अंश)	23,294	10,976
3	स्थानीय निकायों से संबंधित अनुदान	69,421	28,609
4.	स्वास्थ्य क्षेत्र को अनुदान	13,192	275
	कुल योग	**1,92,108**	**1,61,230**

स्रोत: व्यय विभाग

संकट के दौरान राज्य के राजस्व में सहायता करना

3.30 राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय सरकारों द्वारा एक अच्छी तरह से लक्षित राजकोषीय नीति के महत्व को स्वीकार करते हुए, केंद्र सरकार ने राज्य की वित्तीय व्यवस्था में सहायता करने और राज्यों को सुधारवादी एजेंडे पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कदम उठाए हैं। राज्यों के जीएसटी मुआवजे में हुई कमी को पूरा करने के लिए, सरकार ने कोष से नियमित जीएसटी मुआवजा जारी करने के अलावा वित्तीय वर्ष 2021 और वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान 2.69 लाख करोड़ रुपये उधार लिए और इस धनराशि को एक-एक करके राज्यों को जारी कर दिया। इसके अतिरिक्त, शीघ्र निधियां पहुंचाने के लिए राज्यों को पहले उपकर भुगतान और कर अंतरण संबंधी किश्ते प्रदान कर दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, भारत सरकार ने 30 जून 2022 तक राज्यों को देय कुल जीएसटी मुआवजे के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपये जारी किए। भले ही नवंबर 2022 तक कुल उपकर संग्रह राज्यों को यह पूरा भुगतान करने के लिए प्रर्याप्त नहीं था, केंद्र ने शेष राशि अपने संसाधनों से जारी की। बॉक्स 3 में राज्यों को संसाधनों प्रदान करने पर जीएसटी के प्रभाव की चर्चा की गई है।

बॉक्स 3: जीएसटी और राज्यों को संसाधन प्रदान करना

पिछले पांच वर्षों में जीएसटी से संबंधित अनुभवों के आधार पर दर युक्तिकरण, रिटर्न ाइलिंग को सरल बनाने, उत्पादों पर मुआवजा उपकर, राज्यों को मुआवजा भुगतान आदि के बारे में कई नीतिगत बहस हुई हैं। एक प्रासंगिक प्रश्न जिसका सावधानीपूर्वक अध्ययन नहीं किया गया, वह है राज्यों के लिए संसाधनों के मुहैया कराने जीएसटी का

प्रभाव। जीएसटी से पहले और बाद की व्यवस्थाओं में राज्यों को मिलने वाले कुल राजकोषीय संसाधनों की तुलना करते समय, अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की तुलना में करों के सापेक्ष प्रदर्शन को मापना आवश्यक है। जीएसटी पूर्व की व्यवस्था में, जब अर्थव्यवस्था में नाममात्र 11.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई तो जीएसटी में समाहित केंद्र और राज्य करों से राज्यों को अर्जित होने वाले कुल राजकोषीय संसाधनों (अंतरण सहित) में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें 0.97 की वृद्धि निहित है (तालिका 3क देखें)।

तालिका 3क- जीएसटी में समाहित करों से राज्यों को प्राप्त कुल राजकोषीय संसाधन (अंतरण सहित)

	वित्तीय वर्ष 2013	वित्तीय वर्ष 2014	वित्तीय वर्ष 2015	वित्तीय वर्ष 2016	वित्तीय वर्ष 2017	सीएजीआर (वित्तीय वर्ष 2013 से वित्तीय वर्ष 2017)
				₹ लाख करोड़ रु.		
जीएसटी में समाहित राज्यकर						
जीएसटी में सम्मिलित राज्य कर	3.22	3.48	3.73	4.41	4.41	
जीएसटी में सम्मिलित केंद्रीय कर	1.66	1.90	2.02	2.48	3.14	
अंतरण कारक	0.32	0.32	0.32	0.42	0.42	
जीएसटी में सम्मिलित करों से राज्यों को के लिए कुल राजकोषीय संसाधन	3.75	4.08	4.38	5.46	5.73	11.1%
नाममात्र जीडीपी	99.44	112.34	124.68	137.72	153.92	11.5%
राज्यों को देय जीएसटी में सम्मिलित करों से जीएसटी से पहले राजस्व की वृद्धि						0.97

जीएसटी के बाद की अवधि में, जीएसटी से राज्यों को प्राप्त होने वाले कुल राजकोषीय संसाधनों (केंद्र के जीएसटी से अंतरण सहित) में जीएसटी से पहले की अवधि (तालिका 3ख) की तुलना में अधिक वृद्धि हुई। प्रभावी भारित औसत जीएसटी दर प्रारंभ के 14.4 प्रतिशत से घटकर 2019 में 11.6 प्रतिशत (आरबीआई) रह गया और इसे देखते हुए यह प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

तालिका 3ख- जीएसटी प्रणाली से राज्यों को प्राप्त कुल वित्तीय संसाधन (अंतरण सहित)

	वितीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2022	वित्तीय वर्ष 23	सीएजीआर (वित्तीय वर्ष 2019 की अपेक्षा वित्तीय वर्ष 2023)
				₹ लाख करोड़ रु.		
सीजीएसटी संग्रह	2.02	2.27	2.10	2.69	3.14	
एसजीएसटी संग्रह	2.79	3.09	2.73	3.44	3.98	
आईजीएसटी संग्रह	5.99	5.87	5.66	7.62	9.40	
वर्ष में भुगतान किया गया जीएसटी मुआवजा	0.85	1.66	1.68	0.69	0.35	
एक के बाद एक ऋण			1.10	1.59		

	वितीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2022	वित्तीय वर्ष 23*	सीएजीआर (वित्तीय वर्ष 2019 की अपेक्षा वित्तीय वर्ष 2023)
जीएसटी प्रणाली से राज्यों के लिए कुल केन्द्रीय संसाधन						
(1) एसजीएसटी + राज्यों का आईजीएसटी + केंद्र के जीएसटी से अंतरण	7.89	8.21	7.61	9.96	11.95	10.9%
(2) एसजीएसटी + राज्यों का आईजीएसटी + केंद्र के जीएसटी से अंतरण + मुआवजा	8.74	9.87	9.29	10.65	12.30	8.9%
(3) एसजीएसटी + राज्यों का आईजीएसटी + केंद्र के जीएसटी से अंतरण + मुआवजा + ऋण	8.74	9.87	10.39	12.24	12.30	**8.9%**
भारत की नाममात्र जीडीपी	189.00	200.75	198.01	236.65	273.09	9.6%
राज्यों को देय जीएसटी राजस्व में जीएसटी के बाद हुई वृद्धि (मुआवजा/ऋण को छोड़कर)						1.13

नोट: (क) संबंधित वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अंतरण कारक वित्तीय वर्ष 2013 से वित्तीय वर्ष 2015 तक 0.32 वित्तीय वर्ष 2016 से वित्तीय वर्ष 2020 तक 0.42; और वित्तीय वर्ष 2021 से आगे 0.41 माना जाता है।
(ख) राज्यों के लिए आईजीएसटी को कुल आईजीएसटी संग्रह का 50: माना जाता है। केंद्र के जीएसटी में राज्य का अंश सीजीएसटी और केंद्र के आईजीएसटी हिस्से के साथ अंतरण कारक को गुणा करके प्राप्त किया जाता है।
(ग) मई से दिसंबर 2022 तक के औसत संग्रह के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023 के संग्रह का बहिर्वेशन किया गया है।
(घ) उपयोग किए गए जीएसटी संग्रह घरेलू आपूर्ति और आयात सहित सकल संग्रह हैं। तथापि, घरेलू आपूर्ति के माध्यम से केवल जीएसटी संग्रह के साथ, जीएसटी के बाद की वृद्धि अभी भी 1 (=1.05) से अधिक है।

जीएसटी से राजस्व के नियमित प्रवाह के अलावा, जीएसटी के बाद की अवधि में राज्यों को मुआवजा भी प्रदान किया गया था। चूंकि जीएसटी एक नई कर व्यवस्था थी, पांच साल के लिए प्रति वर्ष 14 प्रतिशत की स्थिर राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करके नई बनाम फरानी कर व्यवस्था में किसी भी अंतर से राज्यों को बचाने के लिए मुआवजे की योजना तैयार की गई थी। मुआवजे की व्यवस्था राज्यों को जीएसटी के अंतर-राज्य वितरण में अंतर को दूर करने में मदद करने के लिए भी थी। यहां यह ध्यान देना उचित है कि आर्थिक विकास में गिरावट के परिणामस्वरूप कर राजस्व में गिरावट की स्थिति में मुआवजा प्रणाली को राज्य के राजस्व के बफर के रूप में परिकल्पित नहीं किया गया था।

तथापि, वैश्विक महामारी की घटना ने जीएसटी मुआवजे की प्रासंगिकता को राज्यों के राजस्व के बफर के रूप में विशिष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान, आर्थिक दबाव के कारण केंद्र और राज्यों के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सीजीएसटी और मुआवजा उपकर संग्रह में गिरावट के मद्देनजर राज्यों द्वारा मुआवजे की आवश्यकता में काफी वृद्धि हुई है। एक संकट के बीच सीमित राजकोषीय संसाधन होने के बावजूद, केंद्र ने निधियां उधार ली और नियमित जीएसटी मुआवजे जारी करने के अलावा उन्हें एक-एक करके ऋण के आधार पर राज्यों को दे दिया। इन ऋणों को जीएसटी मुआवजा उपकर कोष में भविष्य में होने वाली आय से चुकाया जाएगा और इसलिए यह राज्यों पर बोझ नहीं है।

तालिका 3ग: मुआवजा योजना ने वित्तीय वर्ष 2019 से वित्तीय वर्ष 2023 तक सीजीएसटी राजस्व में सहायता की।

	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2022	वित्तीय वर्ष 2023*
					लाख करोड़ रु., निर्दिष्ट न होने तक
(1)एसजीएसटी+ आईजीएसटी में राज्य का अंश	5.78	6.03	5.56	7.25	8.69
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		4.2%	-7.8%	30.5%	19.8%
(2) एसजीएसटी + आईजीएसटी में राज्य का अंश + मुआवजा	6.63	7.68	7.24	7.94	9.04
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		15.9%	-5.7%	9.7%	13.5%
(3) एसजीएसटी + आईजीएसटी में राज्य का अंश + मुआवजा + ऋण	6.63	7.68	8.34	9.53	9.04
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		15.9%	8.6%	14.3%	-5.2%

नोटः (क) ' मई से दिसंबर 2022 तक के औसत संग्रह के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023 के संग्रह में बहिर्वेशन किया गया है; (ख) वित्तीय वर्ष 2023 में सभी समावेशी एसजीएसटी, मुआवजे और ऋणों (उपर्युक्त तालिका में मद 3) में वर्ष दर वर्ष वृद्धि नकारात्मक है क्योंकि मुआवजा भुगतान केवल जून 2022 तक लागू थे। इस प्रकार, कुल एसजीएसटी (तालिका में मद 1) में वृद्धि की तुलना राज्यों के एसजीएसटी राजस्व के प्रदर्शन को मापने का एक बेहतर उपाय है।
(ग) उपरोक्त विश्लेषण में घरेलू आपूर्ति और आयात दोनों से होने वाले एसजीएसटी और आईजीएसटी संग्रह शामिल हैं। तथापि, यदि हम घरेलू आपूर्ति पर संग्रह की बात करें, तो तालिका के मद 1 में वृद्धि वित्तीय वर्ष 2022 में 26.5 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2023 में 17.3 प्रतिशत है।

उपरोक्त विश्लेषण में हम देखते हैं कि जीएसटी की व्यवस्था और इसके कार्यान्वयन तंत्र ने इस प्रकार न केवल राज्यों के राजस्व को एक नई कर प्रणाली की शुरुआती परेशानियों से सुरक्षित रखा है बल्कि पिछले पांच वर्षों के दौरान अभूतपूर्व बाहरी आघातों के बीच राज्यों की वित्तीय व्यवस्था की रक्षा भी की है। जीएसटी के अभाव में, भारतीय राज्यों के पास मुआवजे का कोई सहारा नहीं होता, न ही वे वैश्विक महामारी के दौरान नए और/अथवा उच्च करों के माध्यम से अपने राजस्व को बढ़ाने पर विचार कर सकते थे।

स्रोतः जीएसटी पोर्टल, आरबीआई, केंद्रीय बजट, सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, पत्र सूचना कार्यालय की विज्ञप्तियां

राज्यों के लिए उधार लेने की बढ़ी हुई सीमा और सुधारों के लिए प्रोत्साहन

3.31 वैश्विक महामारी फैलने के बाद से, केंद्र ने राज्य सरकारों की निवल उधारी सीमा को राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) की सीमा से ऊपर रखा है। यह वित्तीय वर्ष 2021 में जीएसडीपी का 5 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2022 में जीएसडीपी का 4 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2023 में जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। इस अतिरिक्त उधारी का एक हिस्सा उन सुधारों से जुड़ा था जो राज्यों को उन्हें शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2021 में, अतिरिक्त उधार सीमा का एक हिस्सा 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' प्रणाली को लागू करने, व्यापार करने में आसानी से संबंधित सुधार, शहरी स्थानीय निकाय/संस्थाओं संबंधी सुधारों और बिजली क्षेत्र के सुधारों को लागू करने की शर्तों पर आधारित था। परिणामस्वरूप, 17 राज्यों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू किया, 20 राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में निर्धारित सुधारों को पूरा किया, 11 राज्यों ने स्थानीय निकाय संबंधी सुधार किए और 17 राज्यों ने पूर्ण/आंशिक रूप से विद्युत क्षेत्र में सुधार किए। इसी तरह, अतिरिक्त उधारी का एक हिस्सा वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान राज्यों द्वारा किए जाने वाले वृद्धिशील पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किया गया था। कैपेक्स लक्ष्य को पूरा करने पर सोलह राज्यों ने अतिरिक्त उधारी प्राप्त की।

3.32 राज्यों के लिए निर्धारित शुद्ध उधार सीमा के अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग ने बिजली क्षेत्र में राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत के प्रदर्शन-आधारित अतिरिक्त उधार लेने का अवसर प्रदान करने की सिफारिश की थी। वित्तीय वर्ष 2022 से 2024-25 तक प्रत्येक वर्ष चार वर्षों के लिए इस विशेष संवितरण की सिफारिश की गई है। वित्तीय वर्ष 2022 के लिए, निर्धारित सुधार मानदंडों को पूरा करने के लिए 12 राज्यों को रु39,175 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी गई थी।

राज्यों के पूंजीगत व्यय के संबंध में केंद्रीय सहायता

3.33 केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' के तहत 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2021 और वित्तीय वर्ष 2022 में राज्यों को क्रमशः 11,830 करोड़ रु. और 14,186 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई। राज्यों को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसईएस) के निजीकरण/विनिवेश और संपत्तियों के मुद्रीकरण/पुनर्चक्रण हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 में आवंटन का एक भाग निर्धारित किया गया था। वित्तीय वर्ष 23 के दौरान, स्टेट कैपेक्स योजनाओं को और गति प्रदान करने के लिए योजना के तहत आवंटन को बढ़ाकर 1.05 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस राशि में एक बिना शर्त घटक और विशिष्ट सुधारों/पहलों से जुड़े छोटे घटक शामिल हैं (तालिका 8)। विशेष रूप से, यदि राज्य सरकारों को अतिरिक्त उधार सीमा के रूप में इस 1 लाख करोड़ रुपये की अनुमति दी जाती, तो वे केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले उधार पर देय ब्याज दर से अधिक ब्याज दर वहन करते। इसके अतिरिक्त, वे इसका उपयोग राजस्व व्यय के लिए कर सकते हैं। वर्तमान व्यवस्था में यह ब्याज मुक्त ऋण केवल पूंजीगत व्यय करने के लिए है।

तालिका 8: वित्तीय वर्ष 2023 में पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों के लिए विशेष सहायता योजना का ब्यौरा

(करोड़ रु.)

घटक	आधार	आवंटित	अनुमोदित	जारी किया गया
1	वित्तीय वर्ष 2023 में कर अंतरण के अनुपात में आवंटन	80000	68,592	31,571
II	पीएम गतिशक्ति से संबंधित व्यय	5,000	1,458	1,458
III	पीएमजीएसवाइ	4,000	1,616	1,616
IV	डिजिटाइजेशन के लिए प्रोत्साहन	2,000		
V	ऑप्टिकल फाइबर केबल		2,215	2,011
VI	शहरी सुधार	6,000		
VII	विनिवेश और मुद्रीकरण	5,000		

स्रोत: व्यय विभाग

बॉक्स 4: राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों में सुधार के लिए की गई पहले।

वैश्विक महामारी ने व्यय की जरूरतों को बढ़ाकर और राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर राज्य की वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित किया है। यद्यपि केंद्र सरकार ने उपरोक्त पहलों के माध्यम से राज्य सरकारों की सहायता की है, तथापि राज्य सरकारों ने भी अपने संसाधन पूल को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं।

नगरपालिका की वित्तीय व्यवस्था पर अपनी वर्तमान रिपोर्ट में, आरबीआई ने बताया कि भारत का संपत्ति कर संग्रह ओईसीडी देशों की तुलना में बहुत कम था। राज्यों में करों में व्यापक असमानता है, इस प्रकार भारत में संपत्ति कराध ान प्रथाओं में बड़े पैमाने पर सुधार की गुंजाइश पैदा होती है। तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान अपने राज्यों में संपत्ति करों को संशोधित किया है।6 7

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल और असम जैसे कुछ राज्यों तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान अपनी बिजली दरों को संशोधित करने पर खिचार किया है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश ने एक नई शराब नीति की घोषणा की है, जिसके तहत विभिन्न श्रेणियों शराब/शराब के कारख. ानों में लाइसेंस शुल्क, नवीनीकरण शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क और पंजीकरण शुल्क में वृद्धि की गई है।

इसके अतिरिक्त, कई राज्यों ने वित्तीय वर्ष 2021 और वित्तीय वर्ष 22 में केंद्र सरकार से अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए एसपीएसईएस के निजीकरण और संपत्तियों के मुद्रीकरण की दिशा में भी प्रयास किए हैं। इन सुधारों से अनुत्पादक संपत्तियों में फंसे धन को निकालने करने और इसे उत्पादक उपयोग के लिए जारी करने में मदद मिलेगी। राज्यों द्वारा अपनाए गए कुछ अन्य राजस्व सृजन उपायों में बकाया भुगतान के लिए असम की परिसमापन योजना, पुराने वैट बकाया के निपटान के लिए हरियाणा की एकमुश्त योजना, और पुराने वाहनों को हतोत्साहित करने के लिए असम और केरल का हरित कर शामिल हैं।

स्रोत: अवबार की रिपोर्ट, आरबीआई

सरकार का ऋण प्रोफाइल

3.34 वर्ष 2020 में अभूतपूर्व राजकोषीय विस्तार को देखते हुए, दुनिया भर में बढ़ती सरकारी देनदारियां एक महत्वपूर्ण चिंता के रूप में उभरी हैं। आईएमएफ8 ने वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 91 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया है, जो वैश्विक महामारी से पहले के स्तर से लगभग 7.5 प्रतिशत अधिक है। हालांकि दुनिया भर के देशों ने वैश्विक महामारी के दौरान प्रदान की गई राजकोषीय सहायता को बंद करना शुरू कर दिया था, तथापि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच वैश्विक वित्तीय स्थितियों को चुनौती देते हुए बजट नियंत्रणों[9] को कड़ा कर दिया गया। बढ़ते ऊर्जा बिलों से घरों और छोटे व्यवसायों को राहत प्रदान करने के लिए कुछ यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं अपने बजट में विस्तार कर रही हैं (चित्र 14)। बढ़ती ब्याज दरों और धीमी वृद्धि की आशंका के साथ मिलकर, ये सभी कारक, प्रमुख ऋणों की निरंतरता को दुनिया भर में चिंता का विषय बनाते हैं।

चित्र III.13: कुछ देशों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक शेष राशि में वृद्धि

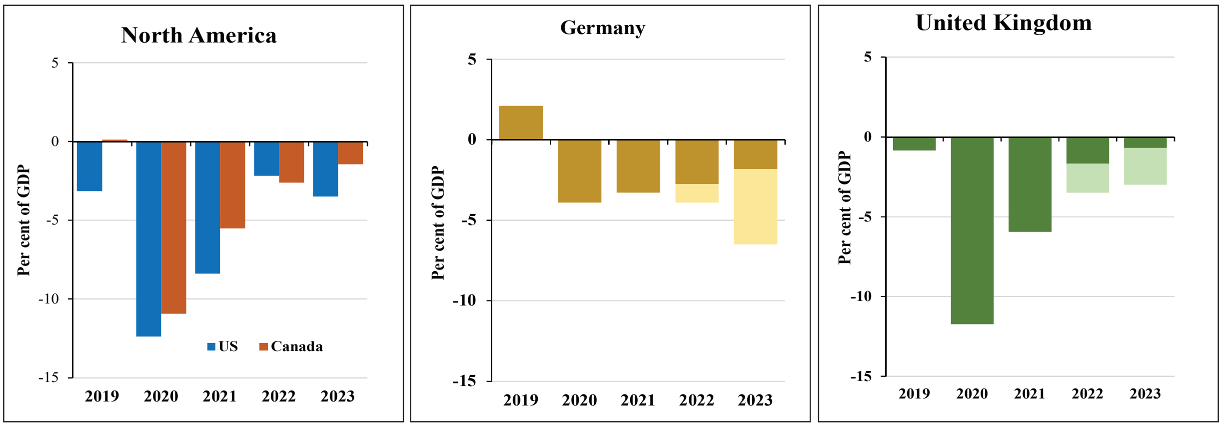

स्रोत: आईएमएफ, रिजर्व बैंक आर्फ ऑस्ट्रेलिया

नोट: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक शेष राशि आईएमएफ से ली गई है; हल्के रंग के बार हाल के महीनों में देशों द्वारा घोषित अतिरिक्त राजकोषीय खर्च को दर्शाते हैं (अप्रत्याशित लाभ करों से उत्पन्न राजस्व को छोड़कर)।

[6]https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/RMF101120223A34C4F7023A4A9E99CB7F7FEF6881D0.PDF

[7]https://www.panchayat.gov.in/documents/448457/0/Assess+the+Availability+of+Resources+for+Creating+the+Assets+and+Initiatives+taken+for+Generating+Various+OSR+%281%29.pdf/b4a01029-d4f5-ab38-becb-b650b269f338?t=1669965866134

[8] आईएमएफ राजकोषीय मोनिटर (अक्तूबर 2022)

[9] वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (अक्तूबर 2022)

3.35 इस वैश्विक पृष्ठभूमि में भारत के सरकारी ऋण प्रोफाइल का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। भारत के संदर्भ में, केंद्र सरकार की कुल देनदारियां, जो पिछले एक दशक में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अपेक्षाकृत स्थिर थीं, जिनमें वैश्विक महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2021 में तेज वृद्धि देखी गई। ऋण में यह वृद्धि वैश्विक महामारी के दौरान कम राजस्व और जीडीपी में तेज गिरावट के कारण बढ़ी हुई अतिरिक्त व्यय की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक सरकारी उधारी के परिणामस्वरूप हुई। वित्तीय वर्ष 2021 में केंद्र सरकार की कुल देनदारियां जीडीपी के 59.2 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2022 (पी) में 56.7 प्रतिशत हो गई (चित्र 15)। केंद्र सरकार की कुल देनदारियों के प्रमुख घटकों का संक्षिप्त विवरण तालिका 9 में दिया गया है।

चित्र III.14: वैश्विक महामारी के कारण आई तेजी के बाद केंद्र सरकार के ऋण-जीडीपी अनुपात में सुधार

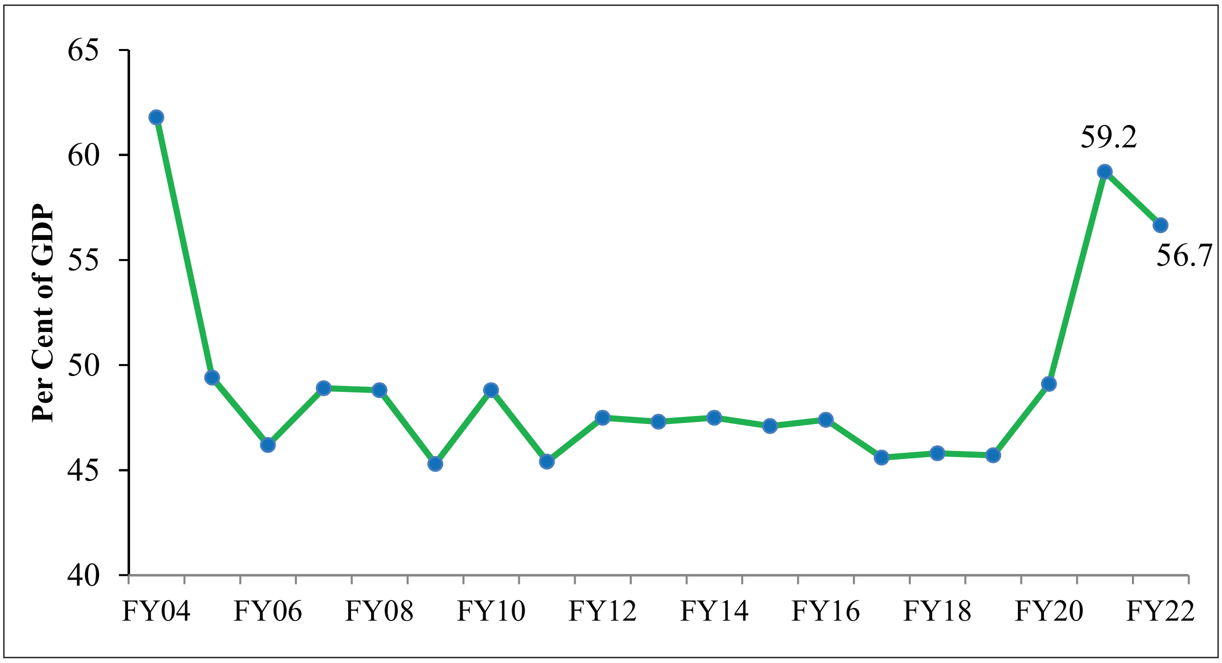

स्रोत: सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र के विभिन्न अंक
नोट: वित्तीय वर्ष 2022 के आंकड़े अनंतिम हैं

तालिका 9: केंद्र सरकार की ऋण स्थिति (लाख करोड़ रु. में)

घटक	वित्तीय वर्ष 2016	वित्तीय वर्ष 2017	वित्तीय वर्ष 2018	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2022 प्रतिवर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
क. सार्वजनिक ऋण (क1+क2)	57.11	61.50	68.45	75.49	85.65	105.23	121.21
क1. आंतरिक ऋण (क+ख)	53.05	57.42	64.01	70.75	80.20	99.08	114.62
क. बिक्री योग्य प्रतिभूतिया	47.28	50.49	55.10	59.69	65.60	78.59	88.17
ख. गैर-बिक्री योग्य प्रतिभूतियां	5.77	6.93	8.91	11.06	14.60	20.49	26.45
क2. बाह्य ऋण	4.07	4.08	4.45	4.74	5.44	6.15	6.59

ख. सार्वजनिक लेखा . अन्य देनदारियां	8.16	8.57	9.15	9.96	13.70	12.74	11.88
ग. अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआरएस)		0.09	0.24	0.99	1.12	1.39	1.39
घ. कुल देनदारियां (क+ख+ग)	65.27	70.16	77.85	86.35	99.91	116.98	134.08

स्रोत: केंद्रीय बजट और वित्त लेखे (विभिन्न मुद्दे); अनंतिम लेखा, सीजीए।
नोट: कुल देनदारियां शुद्ध समायोजित देनदारियां हैं (वित्तीय वर्ष 2020 से राज्यों और अन्य सार्वजनिक एजेंसियों की विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ निवेश, भारत सरकार के नकदी शेष और पाकिस्तान का विभाजन से पहले के ऋण को छोड़कर)

3.36 भारत का सार्वजनिक ऋण प्रोफाइल अपेक्षाकृत स्थिर है और कम मुद्रा तथा ब्याज दर जोखिम इसकी विशेषता हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉ वाईवी रेड्डी ने जिनेवा (अप्रैल 2018) में दक्षिण केंद्र के अपने भाषण के दौरान, कहा, 'चूंकि भारत का अधिकांश सार्वजनिक ऋण निवासियों के पास है और घरेलू मुद्रा में अंकित है। इसलिए, मैं राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋणों पर कम सैद्धांतिक रहूंगा और संदर्भ पर अधिक जोर दूंगा।' मार्च 2021 के अंत में केंद्र सरकार की कुल शुद्ध देनदारियां में, 94.7 प्रतिशत देनदारियां घरेलू मुद्रा में अंकित थी, जबकि सार्वभौमिक बाहरी ऋण 5.3 प्रतिशत था, जो कम मुद्रा जोखिम को दर्शाता है (चित्र 15)। इसके अतिरिक्त, सार्वभौमिक विदेशी ऋण पूरी तरह से प्राप्त हुए आधिकारिक स्रोतों से है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में अस्थिरता से बचाता है।

चित्र III.15: सार्वजनिक ऋण में विदेशी देयता का अनुपात वित्त वर्ष-2022

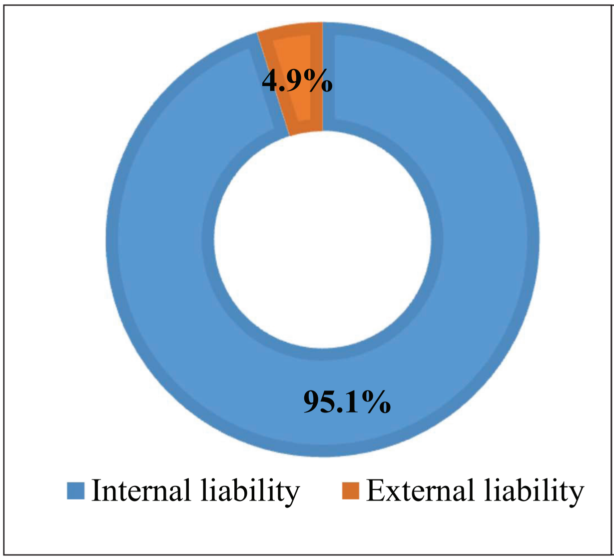

स्रोत: लोक ऋण प्रबंधन प्रेकोष्ठ, आर्थिक कार्य विभाग

चित्र III.16: बकाया दिनांकित केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों परिपक्वता अवधि का विस्तार

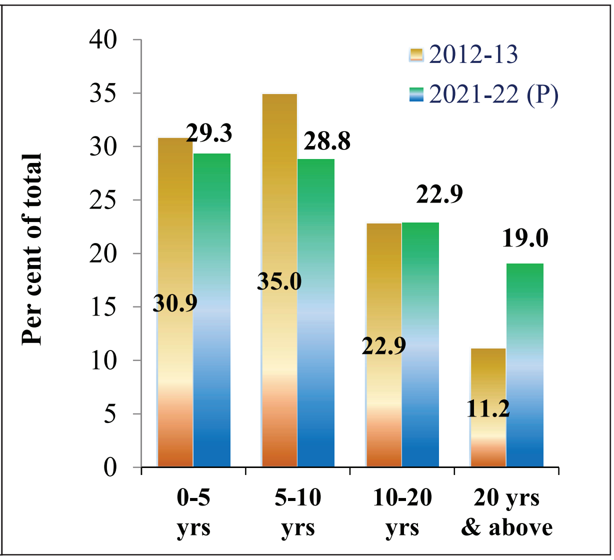

स्रोत: सरकारी ऋण स्थिति पत्र, विभिन्न अंक
नोट: वित्त वर्ष 2022 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

3.37. मार्च 2021 के अंत में भारत में सार्वजनिक ऋण मुख्य रूप से निश्चित ब्याज दरों पर आधारित है, जिसमें अस्थायी आंतरिक ऋण जीडीपी का केवल 1.7 प्रतिशत है। इसलिए ऋण पोर्टफोलियो ब्याज दर की अस्थिरता से अछूता है, जो ब्याज के भुगतान को स्थिरता भी प्रदान करता है। सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक की भारित औसत परिपक्वता मार्च 2010 के अंत 9.7 वर्ष थी जो मार्च 2022 के अंत में बढ़कर 11.71 वर्ष हो गई है, इस प्रकार मध्यम अवधि में रोलओवर जोखिम कम हो गया है (चित्र 17)। पिछले कुछ वर्षों में, पाँच वर्षो से कम समय में परिपक्व होने वाली दिनांकित प्रतिभूतियों के अनुपात में गिरावट आई है, जबकि दीर्घावधि प्रतिभूतियों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है।

सामान्य सरकारी वित्त का समेकन

3.38 सामान्य सरकारी वित्त समग्र रूप से सरकारी क्षेत्र की राजकोषीय स्थिति का अवलोकन प्रदान करता है। चित्र III.17 पिछले कुछ वर्षों में सामान्य सरकारी ऋण और घाटे के रुझान को दर्शाता है। महामारी के कारण केंद्र और राज्यों सरकारों द्वारा किए गए अतिरिक्त उधार के कारण वित्त वर्ष 2021 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सामान्य सरकार की देनदारियों में तेजी से वृद्धि हुई। हालांकि, वित्त वर्ष 22 (सं.अ.) में अनुपात अपने चरम बिन्दु से नीचे आ गया है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सामान्य सरकार के घाटे भी वित्त वर्ष 21 में अपने चरम बिन्दु के बाद समेकित हो गए हैं। मध्यम अवधि में सामान्य सरकार से राजकोषीय समेकन के मार्ग का अनुसरण करने की अपेक्षा की जाती है।

चित्र III.17: जीडीपी के अनुपात में सामान्य सरकार की देनदारियां वित्त वर्ष 21 में प्राप्त अपने चरम बिन्दु से नीचे आ गई हैं

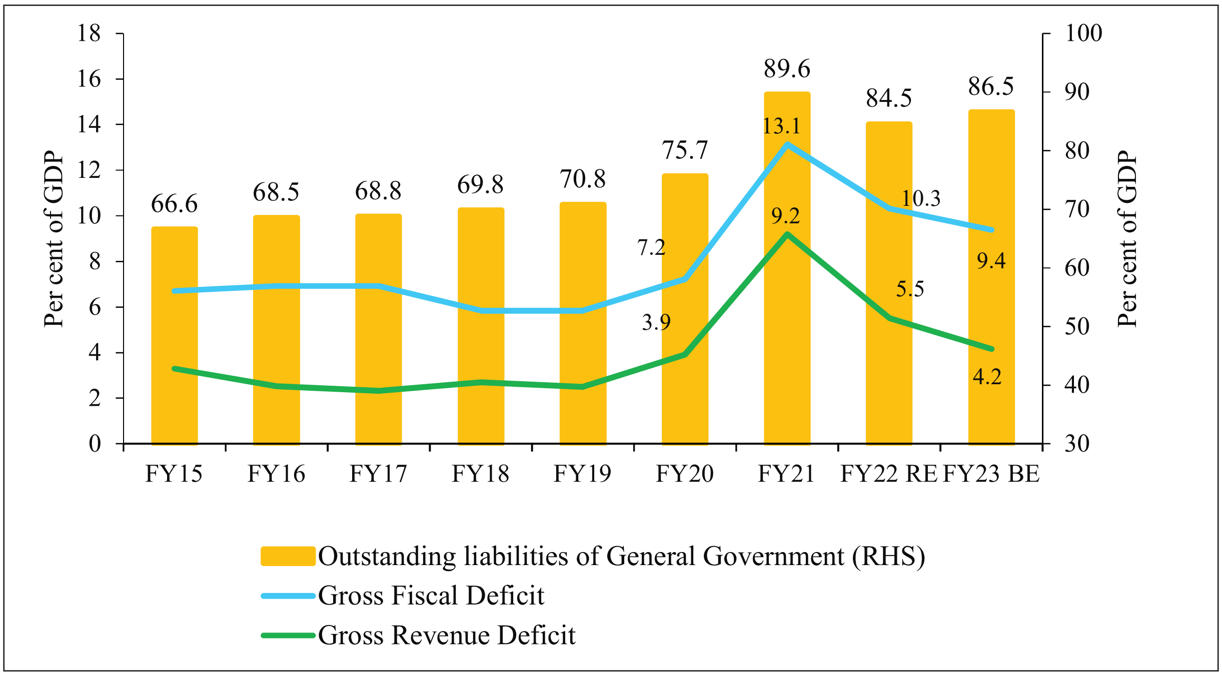

स्रोत: आरबीआई

एक सकारात्मक विकास-ब्याज दर का अंतर सरकारी ऋण को स्थायी बनाए रखता है

3.39 हाल के वर्षों में कैपेक्स पर ध्यान देने से निजी उपभोग व्यय और निजी निवेश पर गुणक प्रभावों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा मिलने की संभावना है। उच्च सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से मध्यम अवधि में बढ़े हुए राजस्व संग्रह करने में की सुविधा होगी, और इस तरह एक स्थायी राजकोषीय मार्ग सक्षम होगा। भारत सरकार ने कर्ज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कैपेक्स-आधारित विकास रणनीति अपनाई। जीडीपी के अनुपात के रूप में सामान्य सरकारी ऋण मार्च 2020 के अंत में 75.7 प्रतिशत था जो बढ़कर वैश्विक महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2021 के अंत में 89.6 प्रतिशत हो गया। मार्च 2022 के अंत तक इसका घटकर जीडीपी के 84.5 प्रतिशत तक होने का अनुमान है। कैपेक्स-आधारित विकास पर जोर देने से भारत विकास-ब्याज दर के अंतर को सकारात्मक बनाए रखने में सक्षम होगा। जैसा कि नीचे चित्र III- 18 में दिखाया गया है, यह अंतर भारत के लिए ऐतिहासिक रूप से सकारात्मक रहा है। एक सकारात्मक विकास-ब्याज दर का अंतर ऋण स्तर को स्थायी बनाए रखता है। बॉक्स 5 दर्शाता है कि कुछ वर्षों के लिए निरंतर आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में राजकोषीय समेकन में सहायता करता है।

आकृति 18: भारत के लिए विकास-ब्याज दर का अंतर

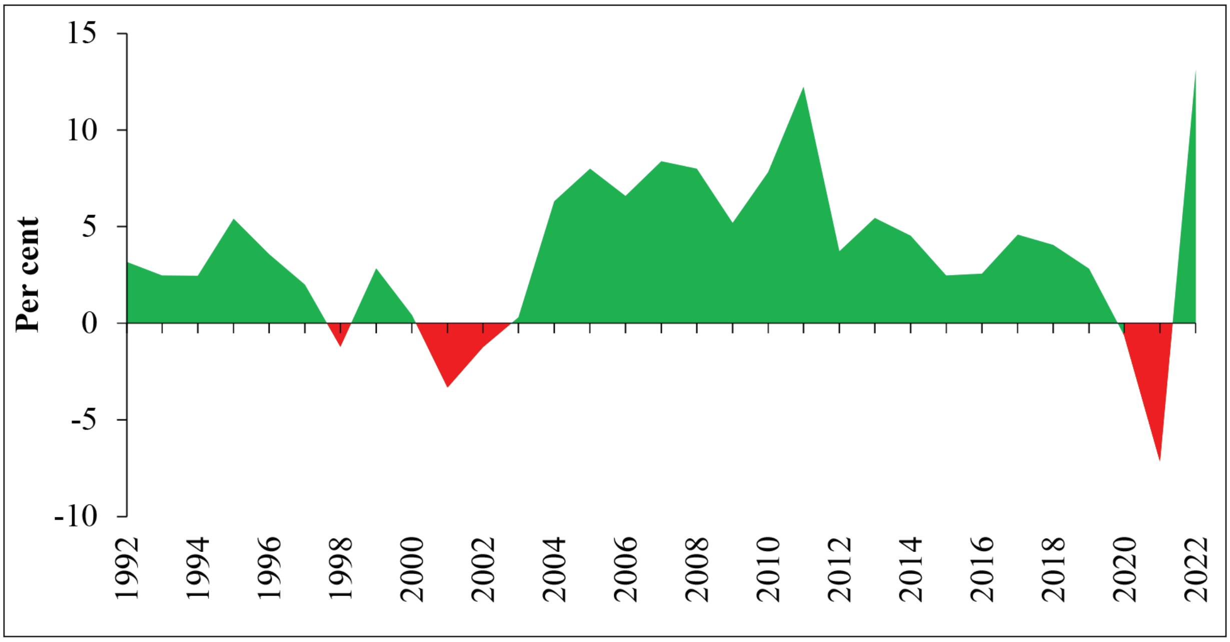

Source: RBI, IMF

3.40 कई देशों में वर्ष 2005 से 2021 तक जीडीपी के अनुपात में ऋण में परिवर्तन की तुलना अधिकांश देशों में पर्याप्त वृद्धि को दर्शाती है। भारत के लिए, यह वृद्धि सामान्य है, जो वर्ष 2005 में जीडीपी के 81 प्रतिशत से वर्ष 2021 में जीडीपी के लगभग 84 प्रतिशत तक रही है (चित्र 19)। यह पिछले 15 वर्षों के दौरान लचीले आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि में संभव हुआ है, जिससे सकारात्मक विकास-ब्याज दर में अंतर हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप, जीडीपी व ऋण अनुपात सतत समान बना रहा है।

आकृति 19: कई देशों में वर्ष 2005 और वर्ष 2021 के जीडीपी अनुपात की सामान्य सरकारी ऋण के साथ तुलना

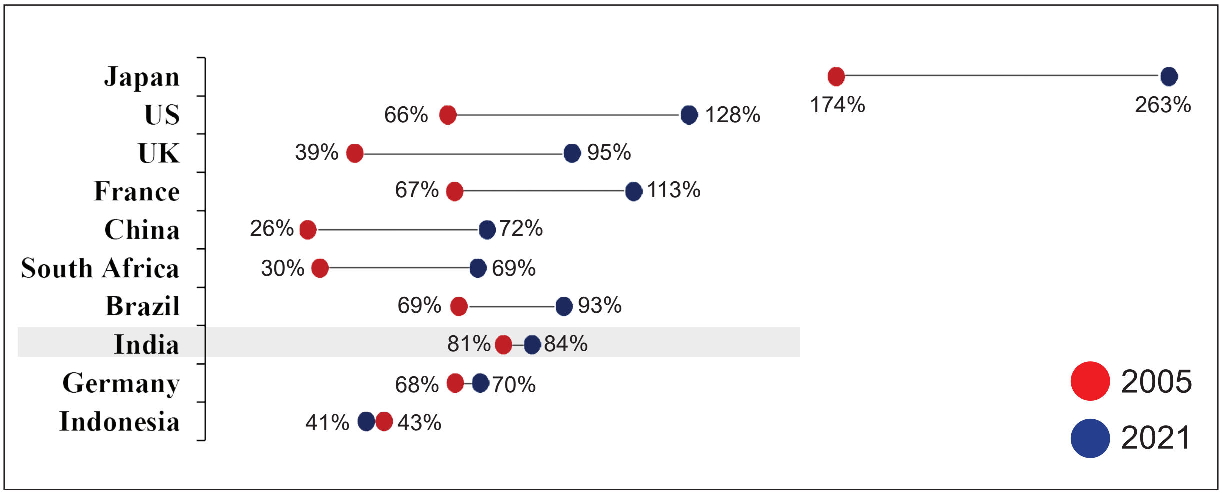

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अक्टूबर 2022।

बॉक्स 5: राजकोषीय समेकन के मार्ग के रूप में सतत विकास का मार्ग

वैश्विक महामारी के बाद जीडीपी अनुपात के रूप में उच्च राजकोषीय घाटा और दुनिया भर के देशों के लिए चिंता का विषय है। बढ़े हुए राजकोषीय घाटे और ऋण- जीडीपी अनुपात का समाधान कुछ वर्षों तक लगातार उच्च विकास में निहित है। एक साधारण प्रतितथ्यात्मक प्रयोग से पता चलता है कि भारत के लिए 10 प्रतिशत की निरंतर वृद्धि के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार का घाटा और ऋण अनुपात बहुत कम हो जाता और यह वैश्विक महामारी के बाद के वर्षों में व्यय के स्तर को समान रखने के बावजूद संभव था।

परिदृश्य 1 के तहत, राजस्व और व्यय को वास्तविक के समान रखते हुए, नाममात्र उच्च जीडीपी वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन राजकोषीय घाटे और ऋण अनुपात के आधार पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020 से वित्तीय वर्ष 2022 तक प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि दर मानकर एक प्रतितथ्यात्मक सामान्य जीडीपी जीडीपी का अनुमान लगाया गया है। प्रतितथ्यात्मक जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का वास्तविक राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2020 में 4.5 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2021 में 8 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2022 में 6.3 प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया गया हैं, जो वास्तविक अनुपात से कम है (तालिका 5क की पंक्ति (क) और (ङ) देखें। इसी प्रकार, अनुमानित जीडीपी एवं केंद्र सरकार के ऋण का अनुपात भी वास्तविक ऋण-जीडीपी अनुपात से कम है (तालिका 5क की पंक्ति (ख) और (च) देखें)।

तालिका 5क: निरंतर वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाले कम घाटे और ऋण अनुपात को दर्शाने के लिए प्रतितथ्यात्मक प्रयोग

	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2022	पंक्ति
वास्तविक जीडीपी (लाख करोड़ रु.)	189.0	200.7	198.0	236.6	
वास्तविक जीडीपी में वृद्धि (:)		6.2	-1.4	19.5	
जीडीपी में कल्पित वृद्धि(:)		10.0	10.0	10.0	
अनुमानित जीडीपी (लाख करोड़ रु.)		207.9	228.7	251.6	
परिदृश्य 1					
वास्तविक राजकोषीय घाटा/अनुमानित जीडीपी (:)		**4.5**	**8.0**	**6.3**	**(A)**
केंद्र सरकार का वास्तविक ऋण/अनुमानित जीडीपी (:)		**50.9**	**54.8**	**55.5**	**(B)**
परिदृश्य 2					
कल्पित राजस्व वृद्धि		0.8	1.6	1.6	
अनुमानित राजस्व संग्रह (लाख करोड़ रु.)		18.1	21.0	24.3	
अनुमानित राजकोषीय घाटा (लाख करोड़ रु.)		8.8	14.1	13.7	
अनुमानित राजकोषीय घाटा/अनुमानित जीडीपी		**4.2**	**6.2**	**5.4**	**(C)**
परिदृश्य 3					
कल्पित राजस्व वृद्धि		0.8	0.9	1.6	
अनुमानित राजस्व संग्रह (लाख करोड़ रु.)		18.1	19.6	22.7	
अनुमानित राजकोषीय घाटा (लाख करोड़ रु.)		8.8	15.5	15.2	
अनुमानित राजकोषीय घाटा/अनुमानित जीडीपी		**4.2**	**6.8**	**6.1**	**(D)**

ज्ञापन मदें					
वास्तविक व्यय (लाख करोड़ रु.)	23.2	26.9	35.1	37.9	
अनुमानित राजस्व संग्रह (लाख करोड़ रु.)	16.7	17.5	16.9	22.1	
अनुमानित राजकोषीय घाटा (लाख करोड़ रु.)	6.5	9.3	18.2	15.9	
वास्तविक राजकोषीय घाटा/वास्तविक जीडीपी (:)		**4.7**	**9.2**	**6.7**	**(E)**
केंद्र सरकार का वास्तविक कर्ज/वास्तविक जीडीपी (:)		**52.7**	**63.3**	**59.0**	**(F)**

स्रोत: अवबार की रिपोर्ट, आरबीआई

तथापि, सकल घरेलू उत्पाद की उच्च विकास दर भी उच्च राजस्व के माध्यम से राजकोषीय घाटे को प्रभावित करती है। विश्लेषण के परिदृश्य 2 में राजस्व चौनल के माध्यम से राजकोषीय घाटे व जीडीपी अनुपात पर उच्च जीडीपी वृद्धि के प्रभाव को शामिल किया गया है। विश्लेषण में व्यय के स्तर को वास्तविक के रूप में बनाए रखा गया था। वित्तीय वर्ष 2020 और वित्तीय वर्ष 2022 में वास्तविक राजस्व वृद्धि और वित्तीय वर्ष 2021 की बजटीय राजस्व वृद्धि से राजस्व पर उच्च जीडीपी वृद्धि के प्रभाव की मात्रा निर्धारित होने का अनुमान लगाया गया था। बजटीय राजस्व वृद्धि वित्तीय वर्ष 2011 के लिए मानी गई थी क्योंकि सामान्य जीडीपी संकुचन के वर्ष में वास्तविक वृद्धि अनुपात का निर्वचन नहीं किया जा सकता था। संबंधित वर्षों के लिए अनुमानित राजस्व और वास्तविक व्यय का उपयोग करके राजकोषीय घाटे की गणना की गई थी। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2020 में 4.2, वित्तीय वर्ष 2021 में 6.2 और वित्तीय वर्ष 2022 में 5.4 था, जो वास्तव में हुए घाटे से बहुत कम है। (तालिका 5क की पंक्तियाँ (ग) और (ङ) देखें)

इसके अतिरिक्त, हम परिदृश्य 3 में देखते हैं कि बजटीय वृद्धि के बजाय वित्तीय वर्ष 2021 में पिछले 5-वर्ष की औसत राजस्व वृद्धि को देखते हुए और वित्तीय वर्ष 2020 और वित्तीय वर्ष 2022 में वास्तविक राजस्व वृद्धि को बनाए रखते हुए, जीडीपी व राजकोषीय घाटे का अनुपात अभी भी वास्तव में हुए घाटे से कम है (देखें तालिका 5क की पंक्तियां (घ) और (च))।

इस प्रतितथ्यात्मक अभ्यास के संदेश सरल हैं: मध्यम वृद्धि भी, यदि बनी रहती है, तो मध्यम अवधि में राजकोषीय समेकन में सहायता करेगी और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था स्थायी बनी रहेगी। दूसरा, भारत का सार्वजनिक ऋण और घाटे का अनुपात हाल के वर्षों में न केवल वैश्विक महामारी के कारण अधिक खर्च और कम कर राजस्व के कारण बल्कि वैश्विक महामारी के बाद वित्तीय प्रणाली पर दबाव के परिणामस्वरूप घटते रुझान के कारण भी तेजी से बढ़ा है। दोनों के समाप्त होने के साथ, सामान्य वृद्धि अपने प्रवाह पथ पर वापस लौटेगी और इसलिए, राजकोषीय मानदंडों में भी सुधार होगा। निरंतर सतर्कता और राजकोषीय विवेक के मार्ग पर चलते रहने की आवश्यकता है, परन्तु एक अनुचित अलार्म अनावश्यक है।

निष्कर्ष

3.41 भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राजकोषीय स्थिरता की दिशा में समग्र नीति अपनाई है। संकट का उपयोग सुधार लाने के अवसर के रूप में करते हुए, सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अनेक नीतिगत उपाय किए। इनमें बजट में पारदर्शिता लाने और बजट में विवेकपूर्ण धारणाओं का उपयोग करने से लेकर प्रौद्योगिकी को लागू करने, जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने, कर दरों को कम करने, कर अनुपालन को सरल बनाने और पूर्वव्यापी कराधान में अनिश्चितता को समाप्त करने के माध्यम से कर पारिस्थितिकी तंत्र को बदलना शामिल हैं। इन सभी उपायों से अर्थव्यवस्था का अधिक औपचारिकीकरण हुआ है, अनुपालन में वृद्धि हुई है और जनता द्वारा आय की बेहतर जानकारी दी गई है और राजकोषीय प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को विश्वसनीयता प्राप्त हुई है।

42. भारत के ऋण और घाटे के अनुपात में वृद्धि न केवल वैश्विक महामारी की वजह से आर्थिक गतिविधियों के बंद होने पर आवश्यक उच्च खर्च के कारण हुई है, बल्कि डिनोमिनेटर (सामान्य जीडीपी) में गिरावट या धीमी वृद्धि के कारण भी हुई है। वित्तीय वर्ष 2020 में, वित्तीय प्रणाली में चल रहे दबाव के कारण भारत की जीडीपी वृद्धि धीमी हो गई। जबकि बैंकिंग क्षेत्र मरम्मत के दौर से गुजर रहा था और पुर्नूंजीकरण कर रहा था, गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के संकट ने बैंकिंग प्रणाली के लिए अनिश्चितताओं को नवीनीकृत कर दिया। इसने ऋण वृद्धि को मौन रखा, जिससे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि धीमी हो गई। महामारी ने वित्त वर्ष 2011 में स्थिति को और खराब कर दिया, जिसके कारण नाममात्र जीडीपी अनुबंधित हो गया, जो भारत में एक दुर्लभ घटना थी। विस्तृत चर्चा अध्याय 2 में देखी जा सकती है।

3.43. निरंतर वैश्विक अनिश्चितताओं और जोखिमों के बीच भारत की आर्थिक सुधार की प्रगति के साथ, राजकोषीय ग्लाइड पथ राजकोषीय नीति के लिए पथ को प्रकाशित करता है। यह अनिश्चित परिस्थितियों में नीतिगत कार्रवाई के लिए अधिक महत्वपूर्ण राजकोषीय अवसर सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त, वास्तव में, राजकोषीय अनुशासन कम ब्याज दरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन में बदल जाता है। जैसे-जैसे सरकारें अपनी वित्तीय स्थितियों को स्थायी बनाती हैं और उस रास्ते पर चलती हैं, उनकी ब्याज दरों में निहित जोखिम प्रीमियम कम हो जाता है, इस प्रकार समाज के सभी वर्गों के लिए उनके शैक्षिक ऋण, आवास ऋण, कार ऋण और व्यवसाय ऋण पर पूंजी की लागत कम हो जाती है और उनके हाथों में अधिक धन पहुंचता है। ईएमडीई के लिए, घटते जोखिम-प्रीमियम के माध्यम से राजकोषीय घाटे का प्रोत्साहन प्रभाव, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक होने की संभावना है। यह वास्तविकता है, क्योंकि वित्तीय बाजार उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समान व्यवहार नहीं करते हैं। राजकोषीय अपव्यय का अत्यधिक प्रभाव ईएमडीई पर पड़ता है। इसलिए, इसका कारण यह है कि उनको राजकोषीय विवेक का अधिक लाभ प्राप्त होता है। जैसा कि पहले कहा गया है, यह बढ़ती ब्याज दरों के युग में विशेष रूप से प्रासंगिक है।

3.44 केन्द्र सरकार को सुधारों और उच्च पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देना जारी रखना चाहिए ताकि एक मजबूत सामान्य सरकार सुनिश्चित किया जा सके। कैपेक्स-आधारित विकास रणनीति से मध्यम अवधि में स्थायी ऋण स्तर सुनिश्चित होगा।

[10]IMF Working paper (WP/22/137)- Financial Sector and Economic Growth in India by Margaux MacDonald ; TengTeng Xu (July 2022) – (https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/07/08/Financial-Sector-and-Economic-Growth-in-India-520580)

ANNEXE

अनुबंध 1: केंद्र सरकार की वित्तीय व्यवस्था में दीर्घावधि प्रवृत्ति से संबंधित आंकड़े

तालिका 1: केंद्र सरकार के राजकोषीय मानदंड

	वित्तीय वर्ष 2018	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वर्ष 2022 प्रतिवर्ष	वित्तीय वर्ष 2023 बजट अनुमान
						लाख करोड़ रु. में
राजस्व प्राप्तियां	14.35	15.53	16.84	16.34	21.68	22.04
सकल कर राजस्व	19.19	20.80	20.10	20.27	27.08	27.58
कुल कर राजस्व	12.42	13.17	13.57	14.26	18.20	19.35
गैर-कर राजस्व	1.93	2.36	3.27	2.08	3.48	2.70
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां*	1.16	1.13	0.69	0.58	0.39	0.79
गैर-ऋण प्राप्तियां	15.51	16.66	17.53	16.92	22.08	22.84
निवल व्यय	21.42	23.15	26.86	35.10	37.94	39.45
राजस्व व्यय	18.79	20.07	23.51	30.84	32.01	31.95
पूंजीगत व्यय	2.63	3.08	3.36	4.26	5.93	7.50
राजकोषीय घाटा	5.91	6.49	9.34	18.18	15.87	16.61
राजस्व घाटा	4.44	4.54	6.67	14.50	10.33	9.90
आरंभिक घाटा	0.62	0.67	3.22	11.38	7.81	7.21
ज्ञापन मद						
बाजार मूल्य पर जीडीपी	170.90	188.87	200.75	198.01	236.65	258.00

तालिका 2: केंद्र सरकार के राजकोषीय मानदंड (जीडीपी का प्रतिशत)

	वित्तीय वर्ष 2018	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वर्ष 2022 प्रतिवर्ष	वित्तीय वर्ष 2023 बजट अनुमान
राजस्व प्राप्तियां	8.4	8.2	8.4	8.3	9.2	8.5
सकल कर राजस्व	11.2	11.0	10.0	10.2	11.4	10.7
निवल कर राजस्व	7.3	7.0	6.8	7.2	7.7	7.5
गैर-कर राजस्व	1.1	1.2	1.6	1.0	1.5	1.0
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां*	0.7	0.6	0.3	0.3	0.2	0.3
गैर-ऋण प्राप्तियां	9.1	8.8	8.7	8.5	9.3	8.9
कुल व्यय	12.5	12.3	13.4	17.7	16.0	15.3
राजस्व व्यय	11.0	10.6	11.7	15.6	13.5	12.4
पूंजीगत व्यय	1.5	1.6	1.7	2.2	2.5	2.9
राजकोषीय घाटा	3.5	3.4	4.7	9.2	6.7	6.4

राजस्व घाटा	2.6	2.4	3.3	7.3	4.4	3.8
आरंभिक घाटा	0.4	0.4	1.6	5.7	3.3	2.8

तालिका 3: केन्द्र सरकार के राजकोषिय संकेतकों की विकास दर (प्रतिशत में)

	वित्तीय वर्ष 2018	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वर्ष 2022 प्रतिवर्ष	वित्तीय वर्ष 2023 बजट अनुमान (1)	वित्तीय वर्ष 2023 बजट अनुमान (2)
राजस्व प्राप्तियां	4.4	8.2	8.4	-3.0	32.7	6.0	1.7
सकल कर राजस्व	11.8	8.4	-3.4	0.8	33.6	9.6	1.8
कुल कर राजस्व	12.8	6.0	3.0	5.1	27.6	9.6	6.3
गैर-कर राजस्व	-29.4	22.3	38.8	-36.5	67.6	-14.1	-22.5
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां*	77.0	-2.5	-39.2	-16.0	-32.0	-20.7	102.2
गैर-ऋण प्राप्तियां	7.7	7.4	5.2	-3.5	30.5	4.8	3.4
निवल व्यय	8.4	8.1	16.0	30.7	8.1	4.6	4.0
राजस्व व्यय	11.1	6.8	17.1	31.2	3.8	0.9	-0.2
पूंजीगत व्यय	-7.5	16.9	9.1	27.0	39.1	24.5	26.6
राजकोषीय घाटा	10.4	9.9	43.8	94.8	-12.7	4.4	4.7
राजस्व घाटा	40.2	2.5	46.7	117.5	-28.7	-9.0	-4.1
आरंभिक घाटा	13.1	7.5	381.6	254.0	-31.4	-7.3	-7.8

Source: Budget documents, O/o CGA

नोट: (1) वित्तीय वर्ष 2022 संशोधित अनुमान की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 बजट अनुमान में वृद्धि हुई (2) वित्तीय वर्ष 2022 प्रतिवर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 बजट अनुमान में वृद्धि हुई

<u>अनुबंध 2: वित्त वर्ष 23 के दौरान सीबीडीटी द्वारा किए गए उपाय</u>

हाल के वर्षों में सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों ने विश्वास-आधारित कर प्रणाली के विकास को सुनिश्चित किया है। एक कुशल और प्रभावी कर प्रशासन की दिशा में प्रगति की गई है, जो ईमानदार करदाताओं का सम्मान करता है और सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीति को आगे बढ़ाते हुए बेहतर करदाता सुविधा प्रदान करता है।

करदाताओं के लिए अनुपालन में आसानी

- 1961 के आयकर अधिनियम में अपडेटेड रिटर्न की एक नई योजना शुरू की गई है, जो करदाता को अतिरिक्त कर का भुगतान करके प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से दो साल के भीतर स्वेच्छा से अपनी रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करती है और मुकदमेबाजी को कम करती है।
- पूर्व-भरे आयकर रिटर्न (आईटीआर) में सूचना का दायरा और अधिक विस्तारित किया गया है, जिसमें गृह संपत्ति आय, प्रतिभूतियों से पूंजीगत लाभ, बैंक ब्याज, और कर अनुपालन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए लाभांश जैसी जानकारी शामिल है।
- आयकर अधिनियम, 1961 के तहत व्यवसाय पुनर्गठन को प्रभावित करने के लिए एक नया प्रावधान किया

गया है, जिसके लिए उत्तराधिकारी इकाई को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्गठन के आदेश के छह महीने के भीतर एक संशोधित रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

- मूल्यांकन अधिकारी और निर्धारिती के बीच मानव इंटरफेस को समाप्त करके, कार्यात्मक विशेषज्ञता के माध्यम से संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करके और कुशल कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके आयकर अधिनियम के तहत मूल्यांकन, अपील और जुर्माना लगाने की प्रक्रियाओं को फेसलेस बना दिया गया है।

मुकदमेबाजी में कमी

- मुकदमेबाजी को कम करने और छोटे करदाताओं के लिए विवाद समाधान को प्रोत्साहन देने के लिए एक विवाद समाधान समिति का गठन किया गया है। 50 लाख रुपये तक की कर योग्य आय और 10 लाख रुपये तक की विवादित आय वाले करदाता समिति से संपर्क करने के पात्र होंगे। दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समिति की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित की जाएगी।
- मुकदमेबाजी प्रबंधन की नीति को आगे बढ़ाते हुए और बार-बार होने वाली अपीलों से बचने के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत एक नया प्रावधान किया गया है, जिसमें यदि एक निर्धारिती के मामले में कानून का प्रश्न लंबित कानून के प्रश्न के समान है अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उसके मामले में या किसी अन्य मामले में अपील, अपीलीय न्यायाधिकरण या निर्धारिती के मामले में अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय में आगे की अपील दाखिल करना तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि प्रासंगिक न्यायालय द्वारा कुछ शर्तों के अधीन कानून के इस तरह के प्रश्न का फैसला नहीं किया जाता है।

कर अपवंचन को रोकने के लिए किए गए उपाय और कर आधार के विस्तार को सुगम बनाना

- वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) और ई-सत्यापन योजना के माध्यम से जानकारी साझा करने का एक औपचारिक तंत्र हाल ही में सक्षम किया गया है। ये उपाय कर आधार को व्यापार और गहरा करने के उद्देश्य को यह सुनिश्चित करके आगे बढ़ाते हैं कि अधिकारियों के पास एक निर्धारिती की सभी प्रासंगिक वित्तीय जानकारी होती है, इस प्रकार एक करदाता को उसकी आय की सही फाइलिंग के लिए ऐसी जानकारी तक पहुंच की अनुमति मिलती है।
- वित्त अधिनियम 2022 ने आभासी डिजिटल आस्ति (वीडीए) के कराधान के लिए विशिष्ट प्रावधान भी पेश किए हैं, जहां वीडीए के अन्तरण पर 30: की दर से कर लगाया जाना है, व्यय (अधिग्रहण की लागत के अलावा) के संबंध में कोई कटौती की अनुमति न दी जाए। इसके अलावा, आभासी डिजिटल आस्तियों के अन्तरण से होने वाले नुकसान को किसी अन्य आय से समायोजित नहीं किया जा सकता है और इसे बाद के वर्षों में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, वीडीए का अन्तरण लेनदेन मूल्य (चाहे नकद/वस्तु दोनों में) के 1 प्रतिशत टीडीएस के अधीन है। वीडीए के उपहार पर प्राप्तकर्ता के हाथों कर लगाया जाएगा।
- व्यापार या पेशे के संबंध में लाभ या अनुलाभ पर स्रोत पर कर की कटौती भी कर आधार को व्यापक और गहरा करने के लिए वित्त अधिनियम 2022 में शुरू की गई है। किसी निवासी को कोई लाभ या अनुलाभ प्रदान करने वाला व्यक्ति इस तरह के लाभ या अनुलाभ के मूल्य या कुल मूल्य के 10: का टीडीएस (चाहे नकद/वस्तु दोनों में) काटेगा।
- वित्त अधिनियम 2022 में प्रावधान किया गया है कि कर अपवंचकों के बीच निश्चितता लाने और प्रतिरोध बढ़ाने के लिए खोज और सर्वेक्षण कार्यों के दौरान पता लगाई गई अघोषित आय के विरुद्ध किसी भी नुकसान के समायोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- वित्त अधिनियम 2022 के द्वारा बोनस स्ट्रिपिंग पर लागू प्रावधानों को प्रतिभूतियों पर भी लागू किया गया है। यह भी व्यवस्था की गई है कि बोनस स्ट्रिपिंग और लाभांश (डिविडेंड) स्ट्रिपिंग संबंधी प्रावधान इन्फ्रास्ट्रक्चर

इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट की इकाइयों या वैकल्पिक निवेश फंडों की इकाइयों पर भी लागू होंगे।

कर प्रोत्साहन

- वित्त अधिनियम 2022 ने वित्त वर्ष 2019-2020 और उसके बाद के वर्षों के दौरान किसी नियोक्ता या किसी व्यक्ति से कोविड-19 के इलाज के लिए चिकित्सा उपचार के लिए प्राप्त राशि पर आयकर राहत प्रदान की है। वित्त वर्ष 2019-2020 और उसके बाद के वर्षों के दौरान कोविड-19 के कारण मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों द्वारा नियोक्ता/अन्य व्यक्ति से प्राप्त अनुग्रह राशि के भुगतान पर भी आयकर राहत प्रदान की गई है।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए भी कर राहत का विस्तार किया गया है। बीमा योजना से वार्षिकी और एकमुश्त राशि का भुगतान माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान अलग-अलग विकलांगों को दिया जाता है, अर्थात माता-पिता /अभिभावक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होने पर और जहां योजना में ऐसा योगदान दिया गया हो बंद कर दिया है।
- राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता लाने के लिए, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस टियर-1 खाते में नियोक्ता अंशदान पर कर कटौती की सीमा मौजूदा 10: से बढ़ाकर 14: कर दी गई है। इससे सामाजिक सुरक्षा लाभों को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
- स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए, 1961 का आयकर अधिनियम दस वर्षों में से तीन लगातार वर्षों के लिए योग्य स्टार्ट-अप्स के लाभ और लाभ के 100: की कटौती की अनुमति देता है। हालांकि, कोविड-19 के कारण ऐसे पात्र व्यवसायों को स्थापित करने में देरी हुई है। इन स्टार्ट-अप्स को समर्थन देने के लिए, वित्त अधिनियम 2022 के माध्यम से पात्र स्टार्ट-अप के निगमन की अवधि को 31.03.2023 तक बढ़ा दिया गया है।
- सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच समान अवसर प्रदान करने के लिए, सहकारी समितियों द्वारा भुगतान की जाने वाली वैकल्पिक न्यूनतम कर दर को 18.5: से घटाकर 15: कर दिया गया है। इसके अलावा, `1 करोड़ से अधिक और `10 करोड़ तक की कुल आय वाली सहकारी समितियों पर अधिभार 12: से घटाकर 7: कर दिया गया है।
- विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी माहौल स्थापित करने के लिए रियायती कर व्यवस्था के लिए, आयकर अधि नियम, 1961 की धारा 115बीएबी के तहत 15: रियायती कर दर का लाभ उठाने के लिए एक नव स्थापित विनिर्माण इकाई के लिए किसी वस्तु या वस्तु के निर्माण या उत्पादन की शुरुआत की तारीख को 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है।
- पिछले कुछ वर्षों में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में स्थित इकाइयों को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कई कर रियायतें प्रदान की गई हैं, ताकि इसे वित्तीय सेवा क्षेत्र का वैश्विक केंद्र बनाया जा सके। आईएफएससी से संचालन को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, वित्त अधिनियम, 2022 के तहत निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निम्नलिखित को कर से छूट दी गई है:

  i. अपतटीय डेरिवेटिव लिखतों से अनिवासी की आय

  ii. अपतटीय बैंकिंग इकाई द्वारा जारी किए गए ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव से आय

  iii. एक जहाज के पट्टे के कारण रॉयल्टी और ब्याज से आय

  iv. आईएफएससी में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय

अनुबंध 3: वित्त वर्ष 23 के दौरान सीबीआईसी द्वारा किए गए उपाय

सीमा शुल्क के संबंध में सुधार के उपाय:

- मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत घरेलू मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की एक सचेत नीति द्वारा सीमा शुल्क शुल्क दर संरचना को निर्देशित किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे माल पर कम शुल्क लगाने और भारत में निर्मित होने वाले सामानों को उचित टैरिफ सहायता प्रदान करने की परिकल्पना करती है। सीमा शुल्क संरचना को पेट्रोलियम अन्वेषण, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अंशाकित (कैलिब्रेट) किया गया है। इस नीति के अनुसार, बीसीडी की एमएफएन दरों में हाल के वर्षों में ऐसी वस्तुओं पर वृद्धि की गई है जो भारत में निर्मित हो रही हैं या जो घरेलू उद्योग निर्माण करना चाहता है। तदनुसार, पिछले 6 वर्षों के दौरान, लगभग 4000 टैरिफ लाइनों (कुल टैरिफ लाइनों का लगभग 1/3) ने बीसीडी के ऊपर अंशांकन देखा है। इस तरह की वस्तुओं में धातु, धातु उत्पाद, ऑटो के फर्जे, जूते, कपड़े, परिधान, निर्दिष्ट रसायन, खिलौने, कुछ मशीनरी, चिकित्सा उपकरण, कई एमएसएमई आइटम जैसे घंटियाँ, घडियाल, चीनी मिट्टी के सामान, टेबल वेयर, बर्तन, हार्डवेयर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, एसी, पंखे, हीटर, हेयर ड्रायर, शेवर, टोस्टर, ओवन आदि सहित घरेलू उपकरण आदि शामिल हैं। साथ ही, इनपुट और कच्चे माल की ड्यूटीज को युक्तिसंगत बनाया गया है।

- महत्वपूर्ण उत्पादों जैसे मोबाइल फोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सौर पैनल आदि के संबंध में चरणबद्ध विनिर्माण योजना (पीएमपी) तरीके जो घरेलू मूल्यवर्धन को धीरे-धीरे गहरा करने को प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन के संबंध में, प्रारंभ में फर्जो (पार्टस) को शून्य बीसीडी के तहत रखा गया था जबकि मोबाइल पर शुल्क लगाया गया था। धीरे-धीरे, फर्जो (पार्टस) पर चरणबद्ध तरीके से शुल्क बढ़ाया गया क्योंकि उनका उत्पादन भारत में शुरू हुआ।

- भारत विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते के तहत सभी प्रतिबद्धताओं का पूरी तरह पालन करता है। फरवरी 2022 की निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन पूरा किया गया है और विश्व व्यापार संगठन द्वारा विधिवत अधिसूचित और स्वीकार किया गया है। प्राप्त किए गए उत्साहजनक परिणामों को यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन में स्टैंडिंग में महत्वपूर्ण सुधार से देखा जा सकता है, जिसमें भारत ने ट्रेड फैसिलिटेशन स्कोर में 2019 में 78.49: से 2021 में 90.32: तक निरंतर सुधार देखा है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया (63.12:) क्षेत्र की तुलना में भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है।

- एक्जिम कार्गो की भौतिक जांच प्रक्रिया में एकरूपता बढ़ाने और प्रक्रिया में शामिल समय और लागत को कम करने के उद्देश्य से, सीबीआईसी ने सर्कुलर संख्या 16/2022-सीमा शुल्क दिनांक 29 अगस्त, 2022 के माध्यम से देश भर के सभी सीमा शुल्क स्थानों पर जोखिम प्रबंधन आधारित एकसमान कार्गो जांच आदेश पेश किया है।

- करदाताओं की सुविधा के लिए उपायों को लागू करने की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, सीबीआईसी ने आयातक, निर्यातक या सीमा शुल्क, शुल्क आदि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति को सक्षम करने के लिए सीमा शुल्क (इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर), विनियम, 2022 दिनांक 30.03.2022 को अधि सूचित किया है। लेन-देन वार भुगतान करने के बजाय सरकार के पास अग्रिम जमा करें जैसा कि पहले किया जा रहा था। इस तरह की जमा राशि का ईसीएल से आवश्यक राशि डेबिट करके सीमा शुल्क से संबंधित शुल्कों और अन्य राशियों के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सीबीआईसी ने मंजूरी में देरी से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए एक अज्ञात वृद्धि तंत्र शुरू किया है। उपरोक्त तंत्र में, सीबीआईसी के आईसीईजीएटूई पंजीकृत उपयोगकर्ता फेसलेस मूल्यांकन के तहत विलंबित मंजूरी के लिए अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं और इसे संबंधित मूल्यांकनकर्ता के साथ-साथ संबंधित एफएजी पोर्ट (फेसलेस असेसमेंट ग्रुप) के उच्च अधिकारियों को गुमनाम रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। अनामित वृद्धि सुविधा भी उपयोगकर्ताओं को अंतिम समाधान तक उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम बनाती है।

- आंतरिक प्रक्रियाओं का अनुकूलन करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के उद्देश्य से, सीबीआईसी ने दिनांक 14.10.2021 को इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम (ईसीटीएस) के कार्यान्वयन के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है, जो आईसीडी में बंदरगाह से गोदाम तक माल की आवाजाही पर नजर रखने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। तुगलकाबाद कंटेनरों के सुरक्षित प्रलेखन और जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है।

- भारतीय सीमा शुल्क ने 9 सितंबर, 2022 की अधिसूचना 74/2022 के माध्यम से मौजूदा सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 को अधिक्रमण करते हुए आईजीसीआरएस नियम, 2022 को अधिसूचित किया है। ये नियम 10 सितंबर 2022 से प्रभावी हो गए हैं। ''ईज ऑफ। डूइंग बिजनेस'' के बड़े लक्ष्यों के अनुसार व्यापार जगत से लंबे समय से चली आ रही मांगों जैसे जॉब वर्क को शामिल करने, पूंजी की निकासी को समायोजित करके शुल्क की रियायती दर पर माल के आयात के लिए प्रक्रियाओं को सरल और स्वचालित बनाने के लिए इन नियमों के जरिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मूल्यह्रासित मूल्य पर माल, पूरी प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बनाने और अधिकारियों के साथ भौतिक इंटरफेस की किसी भी आवश्यकता को समाप्त करने जैसे महत्वपूर्ण बदलाव इन नियमों के जरिए किए गए हैं।

सीमा शुल्क कानून और प्रक्रिया में परिवर्तनः

- व्यापार सुविधा उपाय के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर विनियम, 2021 के तहत जारी ई-स्क्रिप की वैधता को उनके निर्माण की तारीख से एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा, ई-स्क्रिप्स (आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल योजनाओं के तहत जारी) के अंतरिती धारक से वसूली प्रावधानों और इसके क्रेडिट खाते के निलंबन को भी हटा दिया गया है।

- देश भर में डाकघरों के विशाल नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को ई-कॉमर्स या अन्य नियमित चौनलों का उपयोग करके वैश्विक बाजारों में निर्यात करने में सक्षम बनाने के लिए, डाक विभाग (डॉप) के सहयोग से सीबीआईसी डाक निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2022 को अधिसूचित किया है। नई प्रणाली के तहत, एक निर्यातक को निर्यात के डाक बिल (पीबीई) को दर्ज करने और निर्यात पार्सल पेश करने के लिए एक विदेशी डाकघर (एफपीओ) जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, वह अपने घर/कार्यालय से ऑनलाइन पीबीई फाइल करने में सक्षम है और निर्यात पार्सल पास के बुकिंग डाकघर में डाक अधिकारियों को सौंप देता है। डाक अधिकारी बुकिंग डाकघर से एफपीओ तक निर्यात पार्सल के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करेंगे, जहां सीमा शुल्क निकासी होगी।

- परिपत्र संख्या 8/2022-सीमा शुल्क दिनांक 17.5.2022 को बंद कंटेनरों में बांग्लादेश से भारत को निर्यात को सक्षम करने के लिए जारी किया गया है, जिसमें आंतरिक आईसीडी में निकासी शामिल है। प्रक्रिया को डिजिटाइज करने के लिए भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली में एक ट्रांसशिपमेंट मॉड्यूल भी विकसित किया गया है। यह सीमा व्यापार बिंदुओं को कम करेगा और बांग्लादेश के निर्यात को सुविधाजनक बनाएगा।

- परिपत्र सं. 17/2022-सीमा शुल्क दिनांक 9.9.2022 के माध्यम से, सीबीआईसी ने रेल/सड़क मार्ग और नदी मार्ग के संयोजन का उपयोग करके किसी भी अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) से बांग्लादेश में कंटेनरीकृत कार्गो के निर्यात को संभव किया है। उदाहरण के लिए, आईसीडी में सीमा शुल्क निकासी के बाद कंटेनरीकृत कार्गो को रेल या सड़क मार्ग से कोलकाता/हल्दिया बंदरगाह तक पहुँचाया जाएगा, जहाँ से इसे नदी मार्ग का उपयोग करके बांग्लादेश को निर्यात करने के लिए एक बार्ज पर लोड किया जाएगा। सीमा

शुल्क निकासी आईसीडी में होगी और कोलकाता/हल्दिया में केवल निवारक जांच की जाएगी। इस सुविधा से भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों पर निर्यात कार्गो की भीड़ को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

- व्यापार और पारगमन को बढ़ाने के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता का लाभ उठाने की दृष्टि से, सीबीआईसी ने नदी और रेल मार्गों के संयोजन का उपयोग करके भारत के माध्यम से बांग्लादेश के कंटेनरीकृत निर्यात माल की आवाजाही की अनुमति दी है। इस सुविधा की अनुमति परिपत्र सं. 19/2022-सीमा शुल्क दिनांक 14.9.2022 के माध्यम से दी गई है, जिसमें नदी मार्ग का उपयोग करते हुए कोलकाता या हल्दिया के समुद्री बंदरगाह तक भारत में बांग्लादेश से एक बार्ज/जहाज पर कंटेनरीकृत कार्गो का प्रवेश शामिल है। कोलकाता या हल्दिया के समुद्री बंदरगाह से, समुद्री मार्ग से तीसरे देशों को अंतिम निर्यात के लिए माल रेल द्वारा न्हावा शेवा या मुंद्रा के समुद्री बंदरगाह तक पहुंचाया जाएगा। परिपत्र में विस्तृत प्रक्रिया और दस्तावेज दिए गए हैं और ईसीटीएस (इलेक्ट्रॉनिक्स कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम) का उपयोग करके ट्रैक और ट्रेस सुविधा प्रदान की गई है। इस व्यवस्था से वैकल्पिक और अधिक कुशल व्यापार मार्ग प्रदान करके व्यापारियों के लिए समय और लागत बचाने की उम्मीद है।

- सर्कुलर संख्या 09/2022-सीमा शुल्क दिनांक 30.6.2022 के माध्यम से, सीबीआईसी ने अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनलों (आईसीटी) के माध्यम से आभूषणों के ई-कॉमर्स निर्यात के लिए एक सरल नियामक ढांचा तैयार किया है। ई-कॉमर्स व्यवसाय की आवश्यकता को समायोजित करने के लिए, इसमें आभूषणों की वापसी के लिए पुनः आयात प्रक्रिया शामिल है। इस उद्देश्य के लिए, कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2010 को अधिसूचना संख्या 57/2022-सीमा शुल्क (एन.टी) दिनांक 30.6. 2022 द्वारा संशोधित किया गया है। सरलीकृत ढांचा कीमती धातुओं से बने आभूषणों के ई-कॉमर्स निर्यात पर लागू होता है (चाहे कीमती या अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़ी या जड़ित हो या नहीं)। इस सुधार का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मेक-इन-इंडिया ब्रांड का समर्थन करना और तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक ई-मार्केट स्थान का लाभ उठाते हुए भारतीय आभूषण निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

उत्पाद शुल्क में परिवर्तन:

- देश में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य कच्चे तेल की कीमतों से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है। भारतीय बास्केट ऊपर की ओर बढ़ रही है और मई, 2022 में 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। डॉलर विनिमय दर भी ऊपर की ओर थी और पेट्रोल और डीजल की कीमतों को प्रभावित करते हुए ₹77 प्रति यूएसडी के आसपास मंडरा रही थी। पेट्रोल और डीजल का खुदरा बिक्री मूल्य मार्च 2022 में क्रमशः ₹95.41 प्रति लीटर और ₹86.67 प्रति लीटर से बढ़कर 21 मई, 2022 को क्रमशः ₹105.41 प्रति लीटर और ₹96.67 प्रति लीटर हो गया है। इससे पेट्रोल व डीजल पर व्यापार शुल्क में कमी करना आवश्यक हो गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया और पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क दरों को पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर करने का निर्णय लिया गया। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (आरआईसी) को कम करके प्रस्तावित कटौती को प्रभावी किया गया है।

जीएसटी (दरों) में परिवर्तन:

- 2022 में, वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए:

- जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में प्रिंटिंग, राइटिंग या ड्राइंग स्याही जैसी वस्तुओं पर जीएसटी दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया, बिजली से चलने वाले पंप मुख्य रूप से पानी के प्रहस्तन के लिए डिजाइन किए गए जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप, पवन चक्की, ड्राइंग और मार्किंग आउट इंस्ट्रूमेंट, सोलर इन मदों में उल्टे शुल्क संरचना को ठीक करने के लिए वॉटर हीटर और सिस्टम आदि। इसी तरह, कुछ सेवाओं पर जीएसटी दरें जैसे कि फोरमैन द्वारा चिट फंड को आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं, खाल, खाल और चमड़े के प्रसंस्करण के संबंध में जॉब वर्क, चमड़े के सामान और जूते आदि के निर्माण के संबंध में जॉब वर्क आदि को भी उल्टी शुल्क संरचना को सही करने के लिए कैलिब्रेट किया गया था।

- अब तक, ब्रांडेड नहीं होने पर निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों, अनाज आदि पर जीएसटी से छूट दी गई थी, या ब्रांड पर अधिकार छोड़ दिया गया था। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में प्री-पैक्ड, प्री-लेबल दही, लस्सी और छाछ सहित लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के संदर्भ में प्री-पैकेज्ड और प्री-लेबल वाले रिटेल पैक को इससे बाहर करने के लिए छूट के दायरे को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।

- जीएसटी छूट को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से, 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक में चेक, लूजफॉर्फ में या फस्तक के रूप में, मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक और ऐसे ही सभी प्रकार के समान चार्ट या एटलस, वॉल मैप, स्थलाकृतिक योजनाओं तथा ग्लोब जैसी वस्तफओं पर जीएसटी छूट वापस लेने की सिफारिश की गई है। इसी तरह, पेट्रोलियम/कोल बेड मीथेन, सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों को आपूर्ति किए गए वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरणों, ई-कचरे जैसी वस्तुओं पर जीएसटी की रियायती दर के रूप में छूट को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।

जीएसटी कानून और प्रक्रिया में बदलाव:

- 2022-23 में जीएसटी के तहत व्यापार सुविधा और व्यापार करने में आसानी के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए:

व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किए गए उपाय:

- अधिसूचना सं. 14/2022-केंद्रीय कर दिनांक 5.7.2022 के द्वारा, यूपीआई और आईएमपीएस को करदाताओं की सुविधा के लिए और सीजीएसटी नियमावली के नियम 87(3) में संशोधन करके डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए जीएसटी के भुगतान के लिए एक अतिरिक्त मोड के रूप में प्रदान किया गया है। इससे उन्हें जीएसटी भुगतान करने में लचीलापन और मामला मिलेगा।

- सीजीएसटी/आईजीएसटी कैश लेजर बैलेंस को 'अलग-अलग व्यक्तियों' (समान पैन वाली संस्थाएं लेकिन अलग-अलग राज्यों में पंजीकृत) के बीच स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है। करदाताओं द्वारा जीएसटी के तहत किए गए रिफंड आवेदनों को वापस लेने की सुविधा प्रदान की गई है।

- करदाताओं द्वारा जीएसटी के तहत किए गए रिफंड आवेदनों को वापस लेने की सुविधा प्रदान की गई है।

- जीएसटी में, बिजली के निर्यात पर संचित आईटीसी की वापसी के लिए एक तंत्र निर्धारित किया गया है।

- वस्तुओं के निर्यात के मामले में आईजीएसटी रिफंड की मंजूरी की प्रक्रिया, जहां निर्यातकों को जोखिम भरा के रूप में पहचाना गया है, ऐसे दावों के सत्यापन और प्रसंस्करण में तेजी लाने के लिए सुव्यवस्थित किया गया है।

ईज आर्फ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए किए गए उपाय:

- 01.10.2022 से ई–चालान अनिवार्य रूप से जारी करने की सीमा को घटाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया है।
- छोटे करदाताओं को ई–कॉमर्स ऑपरेटरों (ईसीओ) के माध्यम से वस्तुओं की आपूर्ति करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, और राज्य के भीतर ऑफलाइन और ऑनलाइन सामानों की आपूर्ति में समानता प्रदान करने के लिए, जीएसटी के तहत अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता से छूट के लिए सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया गया है। ईसीओ के कंपोजीशन के माध्यम से राज्य के अंदर माल की आपूर्ति के लिए करदाताओं को भी कुछ शर्तों के अधीन ईसीओ के माध्यम से राज्य के अंदर आपूर्ति करने की अनुमति होगी। यह छोटे करदाताओं के लिए अनिवार्य पंजीकरण के बिना अपना सामान बेचने के लिए विशाल ई–कॉमर्स बाजार खोलेगा जिससे छोटे व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। इन परिवर्तनों को नियत समय में अधिसूचित किया जाएगा, क्योंकि जीएसटी परिषद की सिफारिशों के अनुसार जीएसटी प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, और पोर्टल पर और ईसीओ द्वारा भी तकनीकी परिवर्तन की आवश्यकता होगी।

04

अध्याय

मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता: एक अच्छा वर्ष

वर्ष 2022 ने लगभग चार दशकों के बाद, विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, उच्च मुद्रास्फीति की वापसी को चिन्हित किया। मुद्रास्फीति ने उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को भी नहीं छोड़ा। इन गतिविधियों ने पूरे देश में मौद्रिक सख्ती के एक अभूतपूर्व, समकालिक और तेज चक्र को जन्म दिया। प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत दरों में तीव्र वृद्धि लागू की है, 1970 के दशक के बाद से फेडरल रिजर्व की दर वृद्धि सबसे तेज है। जबकि फेडरल रिजर्व ने पॉलिसी दरों में 425 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि की है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) और बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) ने क्रमश: 300 बीपीएस और 250 बीपीएस दर वृद्धि लागू की है। आरबीआई ने अप्रैल 2022 में अपने मौद्रिक सख्त चक्र की शुरूआत की और तब से 225 बीपीएस की पॉलिसी रेपो दर वृद्धि लागू की है। परिणामस्वरूप घरेलू वित्तीय स्थितियां सख्त होने लगीं, जो मौद्रिक समुच्चय की कम वृद्धि में परिलक्षित हुई।

वित्त वर्ष 23 में आरबीआई के पॉलिसी रुख में बदलाव से महामारी के वर्षों के दौरान अधिशेष नकदी की स्थिति में सुधार हुआ। मौद्रिक नीति संचरण अच्छी तरह से चल रहा है क्योंकि नीतिगत दरों में वृद्धि के बाद उधार और जमा दरों में वृद्धि हुई है। सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार में, उच्च मुद्रास्फीति और पॉलिसी दर में वृद्धि की चिंताओं के कारण जून 2022 तक बॉन्ड प्रतिफल ऊपर की ओर था। ये प्रतिफल नवंबर और दिसंबर 2022 में कम हुए, जिसे कच्चे तेल की कम कीमतों, दरों में वृद्धि की धीमी गति, और वैधिक सॉवरेन बॉन्ड प्रकिल में सामान्य नरमी से सहायता मिली।

जबकि वैधिक सख्ती चक्र ने वैधिक दृष्टिकोण को कम करने में योगदान दिया है, ऋण के लिए घरेलू भूख बढ़ रही है। अप्रैल 2022 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा गैर-खाद्य ऋण उठान दोहरे अंकों में बढ़ रहा है, जिसमें वृद्धि व्यापक-आधारित है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) द्वारा वितरित ऋण भी बढ़ रहा है। वित्तीय संस्थानों की ऋण देने की क्षमता बढ़ाने में तुलन पत्र क्लीन-अप अभ्यास महत्वपूर्ण रहा है। एससीबी का सकल गैर-निश्पादित आस्ति (जी एन पी ए) अनुपात 5.0 के सात वर्ष के निचले स्तर तक गिर गया है, जबकि पूंजी-से-जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 16.0 पर स्थिर है और 11.5 की नियामक आवश्यकता से काफी ऊपर है। एनबीएफसी की स्थिति में भी सुधार जारी है। आईबीसी के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वसूली दर अन्य चैनलों की तुलना में वित्त वर्ष 22 में सबसे अधिक थी।

2022 में राजनीतिक और आर्थिक विकास - यूरोप में एक संघर्ष छिड़ना, उच्च मुद्रास्फीति और ब्याज दरों में वृद्धि- का मतलब था कि दुनिया भर के पूंजी बाजारों में वृद्धि की अस्थिरता की विशेषता थी। तथापि, घरेलू पूंजी बाजारों ने कुछ उत्साहजनक रुझान प्रदर्शित किए प्राथमिक इक्विटी बाजारों में सभी खंडों से भागीदारी देखी गई, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के योगदान में वृद्धि हुई, जबकि प्राथमिक निजी ऋण बाजारों में प्लेसमेंट और संसाधन जुटाने में वृद्धि देखी गई। जबकि

निफ्टी 50 और एसएंडपी बीएसई संसेक्स के द्वितीयक पूंजी बाजार सूचकांक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह में अस्थिरता के प्रति प्रतिरक्षित नहीं थे, उन्होंने अप्रैल और दिसंबर 2022 के बीच अपने साथियों की तुलना में बेहतर निष्पादन किया। इसके अलावा, दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही में निवल एफपीआई प्रवाह सकारात्मक हो गया। इस अवधि के दौरान भारत अस्थिरता सूचकांक (VIX) द्वारा मापी गई अस्थिरता में सूचकांकों ने घटती प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। दोनों विकास भारत के सुदृढ़ वृहद् आर्थिक सिद्धांत और अपेक्षाकृत उछाल वाली मांग के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं।

बैंकिंग क्षेत्र और पूंजी बाजार की बढ़ती पहुंच बीमा और पेंशन क्षेत्रों में परिलक्षित होती है। भारत में बीमा की पैठ लगातार बढ़ रही है, जीवन बीमा की पैठ उभरते बाजारों और वैश्विक औसत से ऊपर है। महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप और एक अनुकूल विनियामक वातावरण ने बीमा बाजार के विकास का समर्थन किया है, जिसमें बढ़ती भागीदारी, उत्पाद नवाचार और जीवंत वितरण चौनल देख गए हैं। आने वाले दशक में भारत सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक के रूप में उभरने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), हाल ही में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत के बाद से पेंशन क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति हुई है। इस क्षेत्र में ग्राहकों की संख्या और प्रबंधन के तहत आस्ति (एयूएम) में भारी वृद्धि देखी गई है। सीसीएस (पेंशन) नियमों में छूट, डिजिलॉकर के साथ इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (ई-पीपीओ) का एकीकरण, और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा में छूट जैसे सरकारी उपायों से इस क्षेत्र के विस्तार में मदद मिली है।

जैसा कि वाधिक केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति के प्रति अपनी लड़ाई में अपने आक्रामक रुख और टेलीग्राफ 'उच्च-से-लंबी' पॉलिसी दरों की पुष्टि की है, दुनिया भर में मौद्रिक स्थिति सख्त रहने की संभावना है। घरेलू स्तर पर, तथापि, विकास के लिए आरबीआई का समर्थन वित्तीय बाजारों में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करेगा। ऋण उठान में वृद्धि के बने रहने की उम्मीद है, और निजी कैपेक्स में तेजी के साथ संयुक्त रूप से एक अच्छे निवेश चक्र की शुरुआत होगी। नियामकों द्वारा वित्तीय प्रणाली में जोखिमों की निरंतर निगरानी और उन्हें नियंत्रित करने के उनके प्रयासों से भी क्रेडिट अपचक्र को मदद मिलेगी। एक बार अनिश्चितता का कोहरा हटने के बाद सुदृढ वृहद् आर्थिक सिद्धांत भारत में वैश्विक पूंजी प्रवाह की वापसी को रेखांकित करेंगे। अमृत काल के उद्देश्यों को साकार करने में वित्तीय व्यवस्था अहम भूमिका निभाएगी।

मौद्रिक विकास

4.1 वित्तीय वर्ष 23 में वधिक आर्थिक परिदृश्य पर मुद्रास्फीति के दबाव बना हुए थे। महामारी से वित्त वर्ष 22 में आर्थिक सुधार के साथ मिलकर मूल्य दबावों का निर्माण लंबे समय से क्षणिक के रूप में देख गया था। आपूर्ति श्रखंला के सामान्य होने पर इसमें कमी आने की उम्मीद थी। फरवरी 2022 में यूरोप में प्रस्फुटित हुए संघर्ष के कारण उक्त अस्थायीता पर बहस समाप्त हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप, कमोडिटी की कीमतें बढ़ गई और प्रचलित मुद्रास्फीति के दबावों में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई। इस विकास ने वर्तमान तेज और समकालिक मौद्रिक सख्त चक्र को चालू कर दिया है। संदर्भ स्थापित करते हुए, यह अध्याय वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत के मौद्रिक विकास और वित्तीय प्रणाली के निष्पादन की समीक्षा करेगा। इसमें मौद्रिक नीति कार्रवाइयों और प्रणाली की नकदी पर उनके प्रभाव की समीक्षा करना और बैंकिंग प्रणाली, क्षेत्रीय ऋण विकास और विभिन्न दिवाला ढांचे के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना शमिल है। इसके अलावा, यह पूंजी बाजार, बीमा और पेंशन क्षेत्र के विकास को देखता है।

4.2 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मार्च 2020 और मई 2020 के बीच 115 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती को लागू करने के बाद मई 2020 औरफरवरी 2022 के बीच पॉलिसी रेपो दर पर यथास्थिति बनाए रखी। खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी 2022 से आरबीआई के सहनशीलता बैंड की ऊपरी सीमा को पार कर गई है। मूल्य स्थिरता के लिए एक गंभीर जोखिम को भांपते हुए, आरबीआई ने मौद्रिक सख्त चक्र शुरू किया। अप्रैल 2022 की अपनी बैठक में समिति ने स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) की शुरुआत की, जिसने सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संपार्श्विक की आवश्यकता के बिना आरबीआई के साथ बैंकों द्वारा अतिरिक्त निधि जमा करने की अनुमति दी, जिससे संपार्श्विक-मुक्त तरीके से प्रभावी नकदी प्रबंधन की अनुमति मिलती है। यहां, यह उल्लेखनीय है कि जबकि एसडीएफ विंडो ओवरनाइट डिपॉजिट के लिए उपलब्ध है, रिजर्व बैंक उचित मूल्य निर्धारण के साथ, यदि आवश्यक हो, तो विंडो के तहत लंबी अवधि की अधिशेष नकदी को अवशोषित करने के लिए लचीलेपन को बरकरार रखता है। यहां, यह उल्लेखनीय है कि जबकि एसडीएफ विंडो ओवरनाइट डिपॉजिट के लिए उपलब्ध है, रिजर्व बैंक उचित मूल्य निर्धारण के साथ, यदि आवश्यक हो, तो विंडो के तहत लंबी अवधि की अधिशेष नकदी को अवशोषित करने के लिए लचीलेपन को बरकरार रखता है। एसडीएफ, 3.75 प्रतिशत की दर से पेश किया गया, रिवर्स रेपो दर को नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) कॉरिडोर की नई मंजिल के रूप में बदल दिया। एमपीसी ने इस बैठक में रुख के बदलाव को 'समायोजन' से 'समायोजन' तथा समायोजित की वापसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विकास का समर्थन करते हुए बदलाव का संकेत दिया, जो मौद्रिक सख्त चक्र की शुरुआत का संकेत देता है।

चित्र 1:पॉलिसी दरें

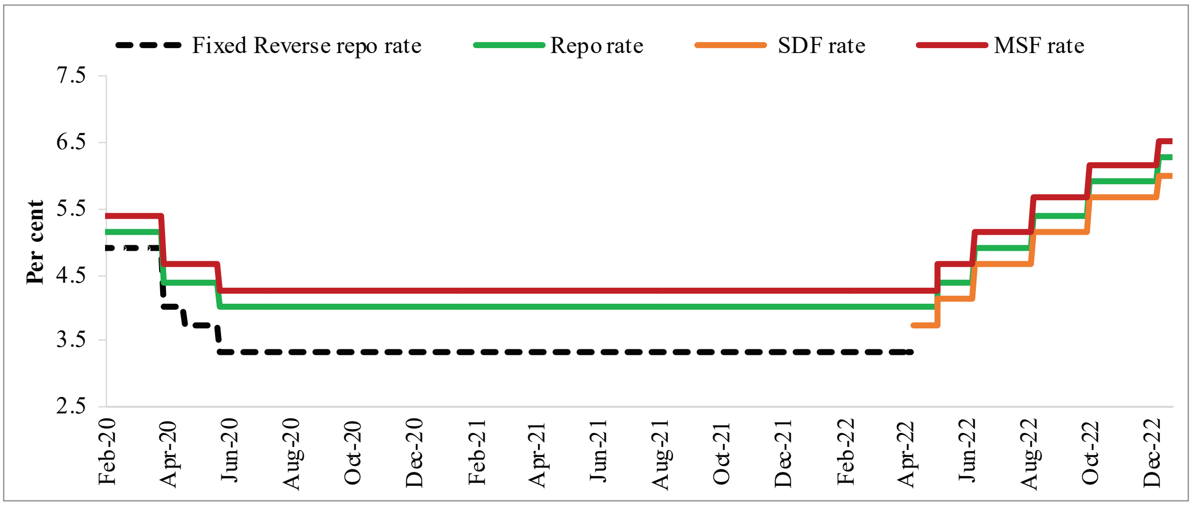

स्रोत: आरबीआईएल

4.3 प्रतिकूल वधिक विकास, जैसे कमोडिटी की कीमतों में सामान्य रूप से सख्त होने और लंबे समय तक आपूर्ति श्रखंला व्यवधानों की बढ़ती संभावना से उत्पन्न होने वाले बड़े जोखिम को देखते हुए, एमपीसी ने मई 2022 में एक ऑफ-साइकिल बैठक बुलाई। सदस्यों ने सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो दर, एसडीएफ और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) में 40 बीपीएस की वृद्धि और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 50 बीपीएस की वृद्धि के लिए मतदान किया। मई 2022 और दिसंबर 2022 के बीच और पाँच से अधिक बैठकें एमपीसी ने पॉलिसी रेपो दर, एसडीएफ, एमएसएफ और बैंक दर में से प्रत्येक में 225 बीपीएस की संचयी वृद्धि लागू की। कठोरता (टाइटनिंग) के चक्र के शुरुआती चरणों में, समिति ने नोट किया कि पण्य मूल्य प्रेरित मुद्रास्फीतिक दबाव, बढ़ी हुई अस्थिरता और उत्पादन में मंदी के शुरुआती संकेत वैश्विक दृष्टिकोण की विशेषता हैं। दिनांक 5-7 दिसंबर, 2022 की अपनी नवीनतम बैठक में, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर में 35 बीपीएस की बढ़ोतरी की और यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजन की वापसी पर अपना ध्यान पुनः आकृष्ट किया कि विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

4.4 पिछले वर्ष के 13 प्रतिशत की तुलना में 30 दिसंबर 2022 को आरक्षित निधि (एमओ) में वर्ष-दर-वर्ष (वाईओवाई) 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित आरक्षित निधि में एक वर्ष पहले 7.8 प्रतिशत की तुलना में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। घटक पक्ष पर परिसंचरण में मुद्रा (करेंसी इन सर्कुलेशन (सीआईसी) में वृद्धि मोटे तौर पर कोविड-19 के बाद देखे गए स्तरों पर स्थिर रही, रूस-यूक्रेन संघर्ष के प्रकोप के तत्काल बाद में मामूली वृद्धि को छोड़कर, जिसे एहतियाती होल्डिंग्स में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब तक, वित्तीय वर्ष 23 के दौरान एम0 में विस्तार मुख्य रूप से सीआरआर में वृद्धि के साथ, आरबीआई के साथ बैंकरों की जमाराशियों द्वारा संचालित था।

तालिका 1: मौद्रिक योग में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिश में)

वस्तु	वित्त वर्ष 17^	वित्त वर्ष 18	वित्त वर्ष 19	वित्त वर्ष 20	वित्त वर्ष 21	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 23
संचित धन (एम0)	**-12.9**	**27.3**	**14.5**	**9.4**	**18.8**	**13.0**	**10.3**
1. क. प्रचलन में मुद्रा (सीआईसी)	-19.7	37.0	16.8	14.5	16.6	9.8	8.2
1. ख. भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकरों की जमा राशि	8.4	3.9	6.4	-9.6	28.5	25.4	17.6
2. नैरो मनी (एम 1)	**-3.9**	**21.8**	**13.6**	**11.2**	**16.2**	**10.7**	**7.6**
3. ब्रॉड मनी (एम 3)	**6.9**	**9.2**	**10.5**	**8.9**	**12.2**	**8.8**	**8.7**
3. क. जनता के पास मुद्रा	-20.8	39.2	16.6	14.5	17.1	10.3	8.4
3. ख. कुल जमा	6.9	5.8	9.6	8.0	11.3	8.4	9.2
मांग जमा	18.4	6.2	9.6	6.8	14.8	10.9	6.2
सावधि जमा	10.2	5.8	9.6	8.1	10.9	8.1	9.1

स्रोत: आरबीआई।

नोट: 31 मार्च, 2017 1 अप्रैल, 2016 से अधिक, एम0, सीआईसी और आरबीआई के पास बैंकर्स डिपॉजिट को छोड़कर।

नोट: 30 दिसंबर, 2023 के अनुसार वित्त वर्ष 23 के ऑकड़े।

मौद्रिक घटनाक्रम सख्त वित्तीय स्थितियों को दर्शाते हैं

चित्र 2क:व्यापक मुद्रा की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि में गिरावट

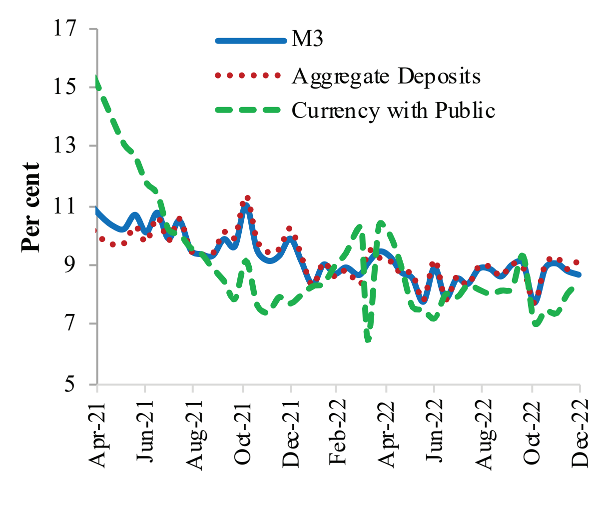

चित्र 2ख:अभिसरण मुद्रा गुणक (एमएम) उपाय

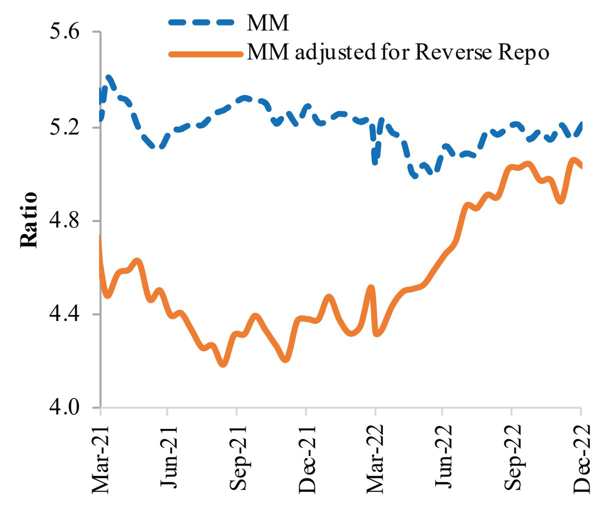

स्रोत: आरबीआईएल

4.5 दिनांक 30 दिसंबर 2022 तक, ब्रॉड मनी स्टॉक (एम3) में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। घटक पक्ष से, कुल जमा सबसे बड़ा घटक रहा है और वर्ष के दौरान अब तक एम3 के विस्तार में सबसे अधिक योगदान दिया है। स्रोतों के बीच, वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बैंक ऋण ने व्यापक धन का विस्तार किया, और सरकार को निवल बैंक ऋण ने इस विस्तार को पूरक बनाया। एम3 में वाणिज्यिक क्षेत्र में बैंक ऋण की हिस्सेदारी में 30 दिसंबर 2022 को 64.3 प्रतिशत की वृद्धि महत्वपूर्ण है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 61.1 प्रतिशशत थी, जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण वितरण में वृद्धि को दर्शाती है।

4.6 धन गुणक – एम3 और एम0 का अनुपात – पिछले वर्ष की इसी अवधि में 5.2 की तुलना में अप्रैल–दिसंबर 2022 की अवधि में मोटे तौर पर 5.1 के औसत पर स्थिर रहा है। तथापि, रिवर्स रेपो के लिए समायोजित एम0, जो विश्लेषणात्मक रूप से आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशि के समान है, अप्रैल 2022 तक बहुत अधिक था। इसलिए, वित्त वर्ष 23 की शुरुआत में समायोजित धन गुणक 4.3 पर कम था। रिवर्स रेपो के लिए समायोजित एम0 अब एम0 के बहुत करीब है; इसलिए, 30 दिसंबर 2022 को मनी मल्टीप्लायर और एडजस्टेड मनी मल्टीप्लायर क्रमशः 5.21 और 5.03 थे।

नकदी की स्थिति

4.7 रिजर्व बैंक के पारंपरिक और अपरंपरागत मौद्रिक उपायों के जवाब में कोविड -19 के बाद प्रचलित अधिशेष नकदी की स्थिति बदली हुई मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप वित्त वर्ष 2023 के दौरान नरम हो गई, जो समायोजन पर केंद्रित थी। पॉलिसी रेपो दर से ऊपर 25 बीपीएस पर एमएसएफ दर बनाए रखने के साथ, एलएएफ कॉरिडोर पॉलिसी रेपो दर के आसपास सन्तुलित हो गई – इस प्रकार कॉरिडोर की चौड़ाई 50 बीपीएस पर पहुंच गई, जो कि महामारी से पहले थी। सीआरआर में 50 बीपीएस की बढ़ोतरी के आरबीआई के कदम के परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली से ₹ 87,000 करोड़ की प्राथमिक नकदी की निकासी हुई।

चलनिधि स्थितियों में सुधार

चित्र 3क:व्यापक धन की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि में गिरावट

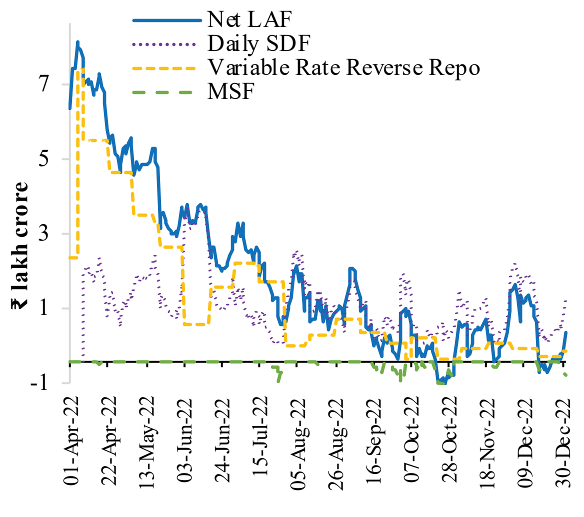

चित्र 3ख:ओवरनाइट कॉल मनी दरें अब एलएएफ कॉरिडोर के भीतर सुव्यवस्थित चलन में हैं

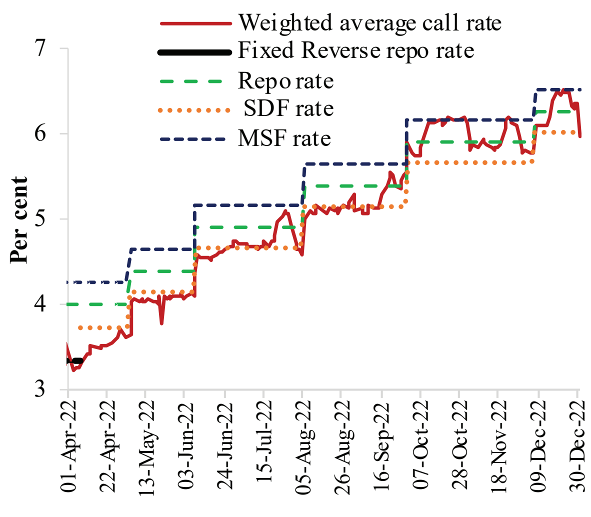

स्रोतः आरबीआई

4.8 वित्त वर्ष 23 (21 दिसंबर 2022 तक) के दौरान दैनिक निवल नकदी अवशोषण औसतन ₹2.5 लाख करोड़ था, जबकि वित्त वर्ष 22 में ₹6.7 लाख करोड़ था। रिजर्व बैंक दो तरफा संचालन करके चलनिधि प्रबंधन में तेज और दक्ष बना रहा। इसने 26 जुलाई और 22 सितंबर 2022 को क्रमश: 3 दिनों में प्रत्येक ₹50,000 करोड़ की दो परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामियों और रातोंरात परिपक्वता के माध्यम से अस्थायी नकदी की तंगी को दूर करने के लिए नकदी डाली। इसने 26 जुलाई और 22 सितंबर 2022 को क्रमश: 3 दिनों में प्रत्येक ₹50,000 करोड़ की दो परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामियों और ओवरनाइट परिपक्वता के माध्यम से क्षणिक नकदी की तंगी को दूर करने के लिए नकदी डाली। अधिशेष नकदी की क्रमिक निकासी ने भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) – मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य – औसत आधार पर पॉलिसी रेपो दर के करीब कर दिया। डब्ल्यूएसीआर ने एच2 (21 दिसंबर 2022 तक) के दौरान औसतन पॉलिसी रेपो दर से 6 बीपीएस ऊपर कारोबार किया, जबकि एच1 के दौरान यह 28 बीपीएस नीचे था। विभिन्न मुद्रा बाजार दरों पर ब्याज दरें – 91-दिवसीय ट्रेजरी बिल (टी-बिल), 3-महीने के जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पत्र – रेपो दर में वृद्धि के अनुरूप धीरे-धीरे मजबूत हुए।

मौद्रिक नीति संचरण

4.9 वित्त वर्ष 23 के दौरान बैंकों की उधार और जमा दरों में पॉलिसी रेपो दर में बदलाव के अनुरूप वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 23 (दिसंबर 2022 तक) के दौरान, बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दर और निधि-आधारित उधार दर (एम सीएलआर) की 1-वर्ष की औसत सीमांत लागत में क्रमश: 225 बीपीएस और 115 बीपीएस की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 23 (नवंबर 2022 तक) में नए और बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यू एएलआर) क्रमश: 135 बीपीएस और 71 बीपीएस बढ़ी। जमा पक्ष पर, वित्त वर्ष 23 (अक्टूबर 2022 तक) में बकाया जमा पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में 59 बीपीएस की वृद्धि हुई।

चित्र4: घरेलू ऋण देने और जमा दरों में वृद्धि

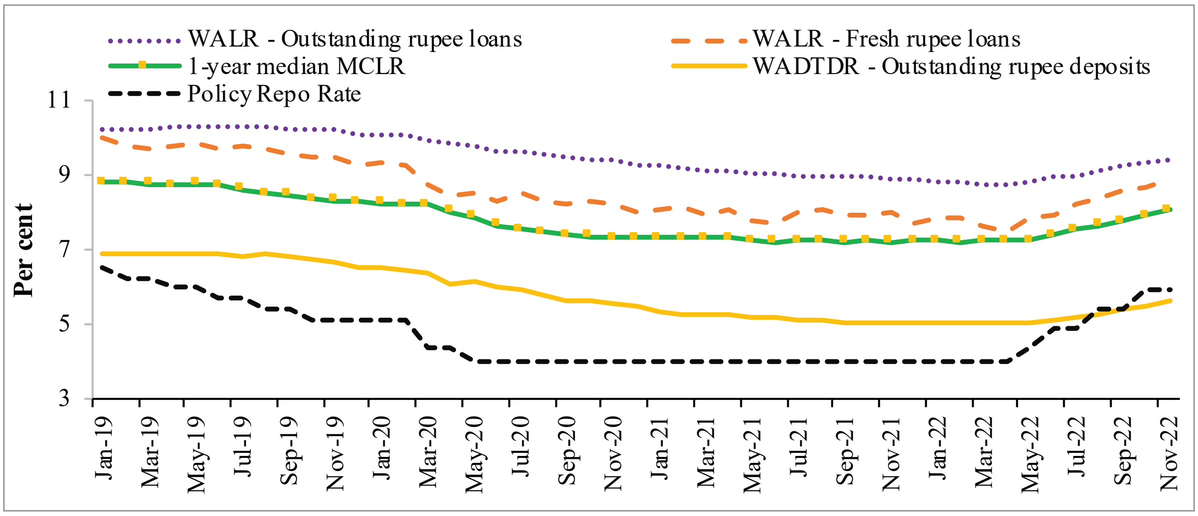

स्रोत: आरबीआई

4.10 वित्त वर्ष 23 (नवंबर 2022 तक) के दौरान बैंक समूहों में संचरण का विश्लेषण इंगित करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में नए ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर में वृद्धि अधिक थी, जबकि बकाया जमा पर डब्ल्यूएडीटीडीआर और बकाया ऋण पर डब्ल्यूएएलआर निजी बैंकों के लिए अधिक था।

तालिका 2: सभी बैंक समूहों में ऋण और जमा दरों में अंतरण

बीपीएस में बदलाव	फरवरी 2019 - मार्च 2022			अप्रैल से नवंबर 2022		
	डब्ल्यूएएलआर - बकाया रुपया ऋण	डब्ल्यूएएलआर - नए रुपए ऋण	डब्ल्यूएडीटीडीआर - बकाया जमा	डब्ल्यूएएलआर - बकाया रुपया ऋण	डब्ल्यूएएलआर - नए रुपए ऋण	डब्ल्यूएडीटीडीआर - बकाया जमा
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	-153	-252	-169	59	149	51
निजी बैंक	-141	-188	-211	82	101	59
एससीबी#	-150	-232	-188	71	135	59

^: मार्च 31, 2017, अप्रैल 1, 2016 के ऊपर, एम0, सीआईसी और बैंकर जमा आरबीआई के पास को छोड़कर
*: वित्तीय वर्ष 23 के आंकड़े दिसंबर 30, 2022 तक के है

स्रोत: आरबीआई
नोट : डब्ल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर; डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर।
एमसीएलआर: निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत;

एससीबी में सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंक शमिल हैं।
पीएसबी:सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पीविबी: निजी क्षेत्र के बैंक

जी-सेक बाजार में विकास

4.11 वर्ष 2020 और 2021 तक कमजोर रहने के बाद 2022 में 10 वर्ष के सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल बढ़ा। भारित औसत प्रतिफल वृद्धि कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, प्रमुख केंद्रीय बैंकों के आक्रामक रुख, वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल में मजबूती और रुपये पर दबाव से उपजी घरेलू बॉन्ड बाजार की अस्थिरता को दर्शाती है। जून 2022 में 7.5 प्रतिफल के चरम पर पहुंचने के बाद दिसंबर 2022 में 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर मासिक औसत प्रतिफल 7.3 प्रतिशत रहा। नवंबर और दिसंबर 2022 में प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में वृद्धि की गति में गिरावट और मुद्रास्फीति में कमी के कारण प्रतिफल में कमी आई। प्रतिफल में नरमी के साथ, 2022 की दूसरी छमाही में अस्थिरता में कमी आई है।

चित्र 5: जुलाई से जी-सेक प्रतिफल में कमी आ रही है, तेल की कीमतों में गिरावट और वैधिक बांड प्रतिफल द्वारा समर्थित

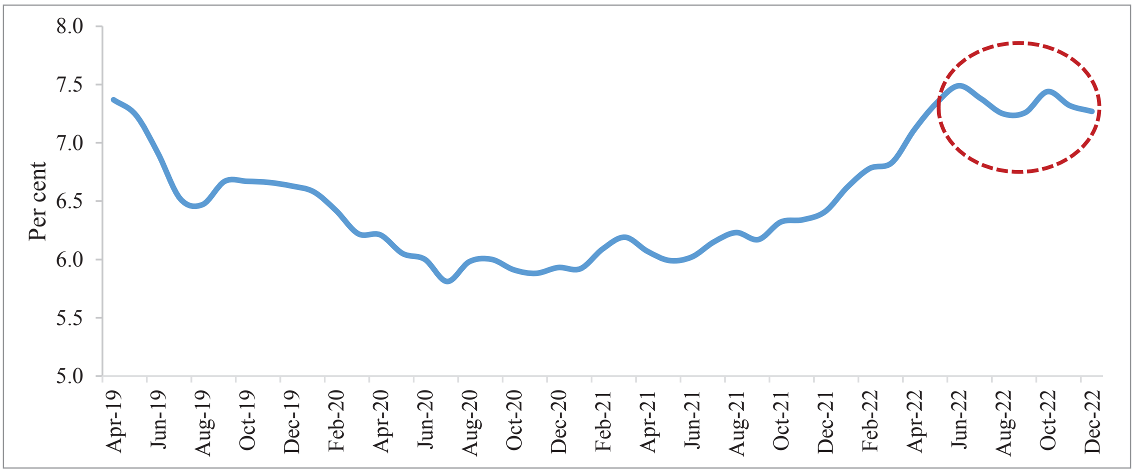

स्रोत: एफबीआईएल

4.12 वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान जी-सेक (टी-बिल और एसडीएल सहित) में ट्रेडिंग वॉल्यूम दो साल के उच्च स्तर ₹ 27.7 लाख करोड़ पर पहुंच गया, जिसमें 6.3 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम सरकारी सुरक्षा बाजार में बाजार के खिलाड़ियों/व्यापारियों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है।

4.13 विदेशी बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, प्राथमिक डीलरों और म्यूचुअल फंड के बाद कुल एकमुश्त व्यापारिक गतिविधि में ''खरीद'' सौदों में 25.0 प्रतिशत और ''बिक्री'' सौदों में 24.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ निजी क्षेत्र के बैंक समीक्षाधीन तिमाही के दौरान द्वितीयक बाजार में प्रमुख व्यापारिक खंड के रूप में उभरे। निवल आधार पर, विदेशी बैंक और प्राथमिक डीलर निवल विक्रेता थे। इसके विपरीत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, म्युचुअल फंड, निजी क्षेत्र के बैंक और 'अन्य' द्वितीयक बाजार में निवल खरीदार थे।

तालिका 3: जी-सेक में कुल एकमुश्त व्यापार गतिविधि का श्रेणी-वार हिस्सा (प्रतिशत)*

श्रेणी	जुलाई - सितंबर 2021		अप्रैल-जून 2022		जुलाई-सितंबर 2022	
	क्रय	विक्रय	क्रय	विक्रय	क्रय	विक्रय
निजी क्षेत्र के बैंक	25.6	28.4	24.3	23.8	25	24.9
विदेशी बैंक	18.6	19.3	20.5	22.7	21.7	22.1
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	16.6	15.6	17.3	16.4	15.7	14
प्राथमिक डीलर	12.3	17.7	13.9	20.3	13.9	19.5
म्यूचुअल फंड्स	14.8	10.1	12.7	8.5	11.2	8.9
अन्य	5.1	3.6	4.1	3.3	5.3	5
सहकारी बैंक	2.9	2.9	3.1	2.8	3.5	3.3
बीमा कंपनियां	3.2	2.1	3.4	2.2	3.1	2.4
वित्तीय संस्थान	1	0.4	0.6	0	0.5	0
कुल	100	100	100	100	100	100

स्रोत: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

नोट: *: टी-बिल और एसडीएल शामिल हैं।

बैंकिंग क्षेत्र

लचीली और सुव्यवस्थित पूंजीकृत बैंकिंग प्रणाली

4.14 पिछले दशक के मध्य से आरबीआई और सरकार ने बैंकिंग प्रणाली के तुलन पत्र को साफ और सुदृढ करने के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूत करने, मान्यता, संकल्प, पुनर्पूंजीकरण और सुधार के 4आर के दृष्किोण को लागू करने जैसे अंशांकित नीतिगत उपायों के संदर्भ में समर्पित प्रयास किए हैं। वर्षों से चल रहे इन निरंतर प्रयासों का परिणाम वर्षों में आस्ति की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में जोखिम अवशोषण क्षमता और एक स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली तुलन पत्र में वृद्धि के रूप में सामने आया है।

बैंकिंग प्रणाली: संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार और तुलन-पत्र को मजबूत करना

चित्र 6क: एससीबी के जीएनपीए अनुपात में गिरावट

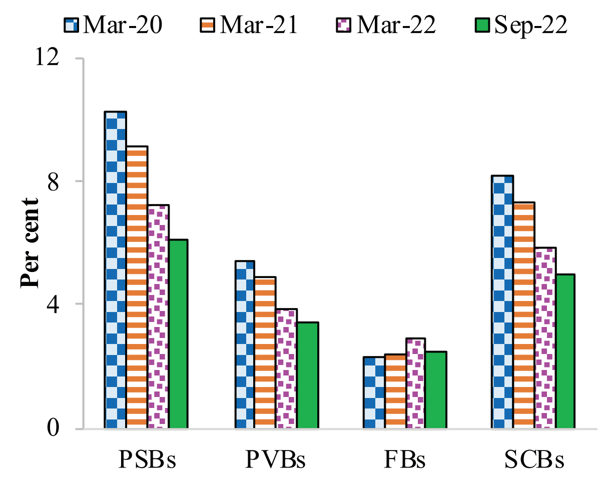

चित्र 6ख: प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात

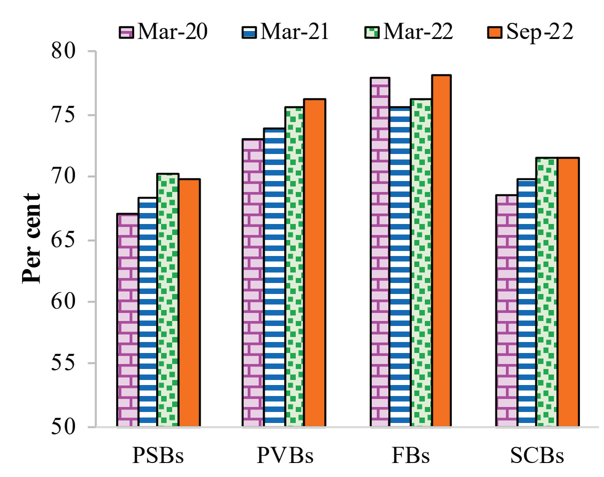

स्रोत: आरबीआई

नोट: एससीबी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए है, पीएसबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए है, पीवीबी निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए है, एफबी विदेशी बैंकों के लिए है।

4.15 परिणामस्वरूप, सभी प्रमुख क्षेत्रों में एससीबी की आस्ति की गुणवत्ता में वर्षो से लगातार सुधार हो रहा है। जीएनपीए अनुपात मार्च 2020 में 8.2 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2022 में सात वर्ष के निचले स्तर 5.0 प्रतिशत पर आ गया है, जबकि गैर निष्पादित आस्ति (एनएनपीए) कुल आस्तियों के 1.3 फीसदी के दस वर्ष के निचले स्तर पर आ गया है। रिकवरी, अपग्रेड और बट्टे खातों के माध्यम से बकाया जीएनपीए में कम चूक और छूट के कारण यह कमी आई है। हाल के वर्षों में संचित उच्च प्रावधानों के साथ मिलकर, कम जीएनपीए ने एनएनपीए में गिरावट में योगदान दिया। औद्योगिक क्षेत्र में जीएनपीए अनुपात में व्यापक आधार पर सुधार हुआ, तथापि यह रत्न और आभूषण और निर्माण उप-क्षेत्रों के लिए अधिक बना रहा। आगे बढ़ते हुए, आरबीआई के तनाव परीक्षण ढांचे के आधारभूत परिदृश्य के अनुसार, जीएनपीए अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है और मार्च 2023 में इसके 4.9 प्रतिशत तक गिरने का अनुमान है।

चित्र 7: जीएनपीए अनुपात में व्यापक आधार पर सुधार

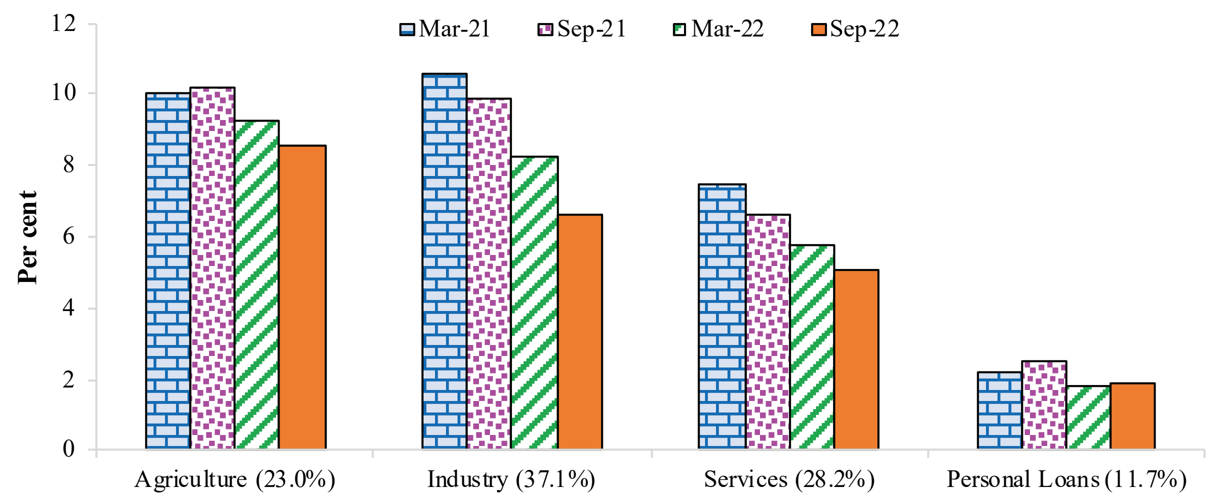

स्रोत: आरबीआई

नोट: लेजेंड के साथ कोष्ठक में संख्या, सितंबर 2022 तक एससीबी के कुल जीएनपीए में संबंधित क्षेत्र के जीएनपीए के हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है।

4.16 इसके अलावा, घटते जीएनपीए के साथ, प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2021 से लगातार बढ़ रहा है और सितंबर 2022 में 71.6 प्रतिशत तक पहुंच गया है। एससीबी का सीआरएआर आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के बाद की अवधि में क्रमिक रूप से बढ़ रहा है। एच 1: वित्त वर्ष 23 के दौरान उधार गतिविधि में तेजी के साथ जोखिम-भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए) में वृद्धि के कारण सितंबर 2022 में सीआरएआर में नरमी आई। तथापि, यह 11.5 प्रतिशत की पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) आवश्यकताओं सहित न्यूनतम पूंजी आवयकता से काफी ऊपर है।

चित्र 8: पूंजी पर्याप्तता अनुपात आवश्यकता मानदंडों से काफी ऊपर है

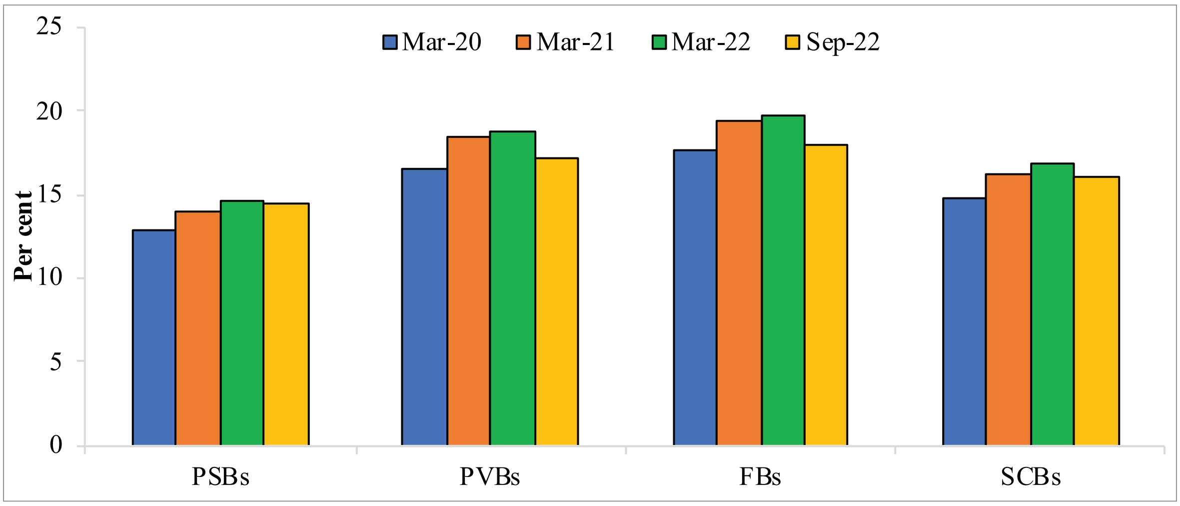

स्रोत: आरबीआई

4.17 वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही के दौरान एससीबी की लाभप्रदता, जिसे रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) और रिटर्न ऑन एसेट्स (आरओए) के संदर्भ में मापा गया, वित्तीय वर्ष 15 में पिछली बार देखे गए स्तरों में सुधार हुआ। प्रणाली स्तर पर, निवल ब्याज आय (एनआईआई) में मजबूत वृद्धि और प्रावधानों में महत्वपूर्ण कमी के कारण सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही में कर के बाद लाभ (पीएटी) में 40.7 प्रतिशत की दो अंकों की वृद्धि देखी गई। क्रेडिट जोखिम के लिए आरबीआई द्वारा किए गए मैक्रो-स्ट्रेस टेस्ट से पता चलता है कि एससीबी सुव्यवस्थित पूंजीकृत हैं और सभी बैंक प्रतिकूल तनाव परिदृश्यों में भी न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का पालन करने में सक्षम होंगे।

निष्पादन संकेतकों में लगातार सुधार

चित्र 9क: आरओई- वार्षिक

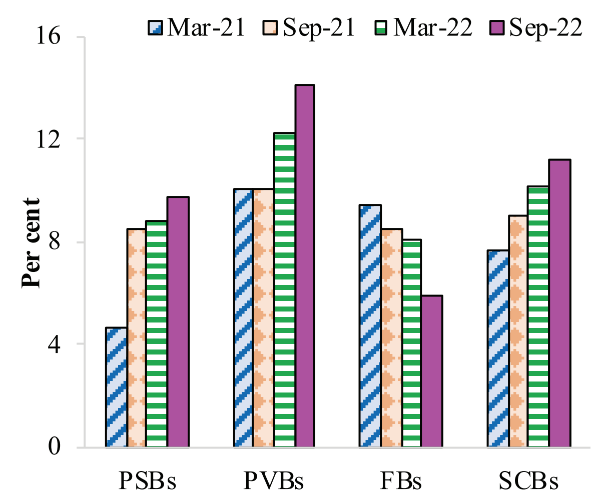

चित्र 9ख आरओए- वार्षिक

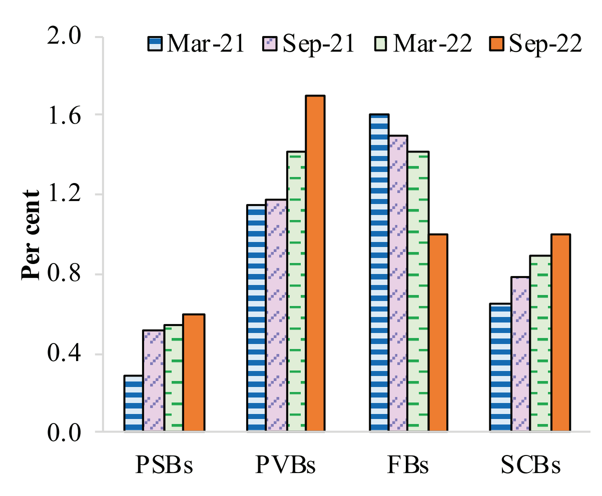

स्रोत: आरबीआई

सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली और ऋणमुक्त कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा सहायता प्राप्त ऋण वृद्धि

4.18 वित्त वर्ष 22 में आर्थिक गतिविधियों में सुधार, बैंकों और कॉरपोरेट्स की बढ़ी हुई वित्तीय सुदृढ़ता के साथ, जून 2021 से गैर-खाद्य बैंक ऋण के विस्तार को बल मिला है। गैर-खाद्य बैंक ऋण में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दिसंबर 2022 में बढ़कर 15.3 प्रतिशत हो गई, जो दिसंबर 2011 के बाद सबसे अधिक है। यह न केवल वर्तमान आर्थिक गतिविधियों के विकास में तेजी दिखाता है बल्कि भविष्य में आर्थिक गतिविधियों में निरंतर गति की प्रत्याश भी दर्शाता है।

चित्र 10: अप्रैल 2022 से गैर-खाद्य बैंक ऋण उच्चतम वृद्धि

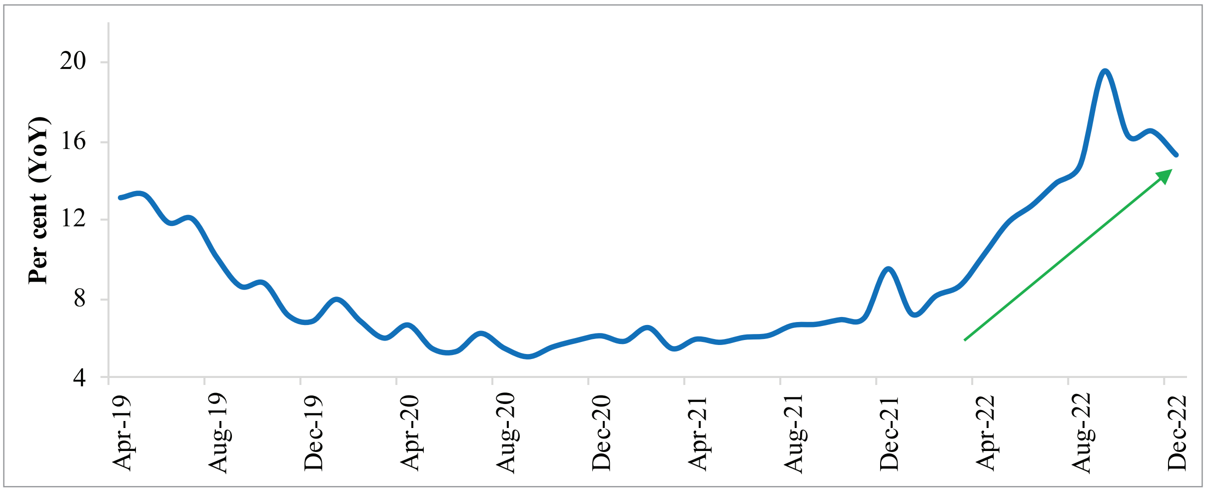

स्रोत: आरबीआई

चित्र 11: क्षेत्रीय गैर-खाद्य बैंक ऋण में व्यापक आधारित वृद्धि

स्रोत: आरबीआई
नोट: नवंबर 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 23 के ऑकड़े।

4.19 ऋण वृद्धि सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से आधारित रही है, जिसमें मुख्य रूप से गष्टह ऋण की बढ़ती मांग के कारण खुदरा ऋण में वृद्धि हुई है। आवास की मांग में वृद्धि अधिक निवेश को प्रेरित करती है, जो बदले में विकास और निवेश का एक अच्छा चक्र स्थापित करती है। सरकार के रियायती संस्थागत ऋण और उच्च कृषि ऋण लक्ष्य द्वारा समर्थित कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण में तेजी आई। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के प्रभावी कार्यान्वयन से अर्जित लाभों और सरकार की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन

योजना द्वारा प्रदान किए गए सहायता और क्षमता उपयोग में सुधार द्वारा प्रदान किए गए समर्थन द्वारा एमएसएमई को ऋण में तेजी से औद्योगिक ऋण वृद्धि में उछाल आया है । सेवाओं में ऋण वृद्धि एनबीएफसी, वाणिज्यिक अचल संपत्ति और व्यापार क्षेत्रों में ऋण में सुधार से प्रेरित थी।

4.20 विदेशी निर्गमों में कमी और निजी इक्विटी (पीई)/उद्यम पूंजी (वीसी) द्वारा कम निवेश के साथ, कॉर्पोरेट क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों को घरेलू संसाधनों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। वित्त वर्ष 23 के दौरान घरेलू इक्विटी बाजारों के प्राथमिक खंड से जुटाई गई धनराशि में गिरावट आई, नियमित परिचालन और क्षमता विस्तार के लिए बैंक ऋण पर निर्भरता बढ़ रही है। साथ ही, वार्षिक (122.0 प्रतिशत, वाई ओवाई) और अर्ध-वार्षिक आधार (172.5 प्रतिशत; सितंबर 2022 मार्च 2022 की तुलना में) दोनों पर वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात तेजी से बढ़ा। पिछले कुछ वर्षों में जमाराशियों के संचयन ने बैंकों को बढ़ती हुई ऋण मांग को वित्तपोशित करने में सक्षम बनाया है। यहां, कम एनपीए अनुपात और अधिक मजबूत कॉर्पोरेट क्षेत्र के बुनियादी सिद्धांतों के साथ अच्छी तरह से पूंजीकृत बैंकिंग प्रणाली बढ़ती ब्याज दरों के साथ नहीं, उत्पादक निवेश के अवसरों में बैंक ऋण के प्रवाह को बढ़ाना जारी रखेगी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का सुधार जारी है

4.21 भारतीय वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसी क्षेत्र का बढ़ता महत्व सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के साथ-साथ एससीबी द्वारा दिए गए ऋण के संबंध में एनबीएफसी के क्रेडिट में लगातार वृद्धि से परिलक्षित होता है। विभिन्न नीतिगत पहलों द्वारा समर्थित, एनबीएफसी महामारी के झटकों को सहन कर सकती हैं। उन्होंने वित्त वर्ष 22 के दौरान तुलन पत्र समेकन, संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार, संवर्धित पूंजी बफर और लाभप्रदता द्वारा चिह्नित वित्तीय सुदृढ़ता का निर्माण किया।

चित्र 12: एनबीएफसी को और उनके द्वारा संवितरित ऋण में वृद्धि

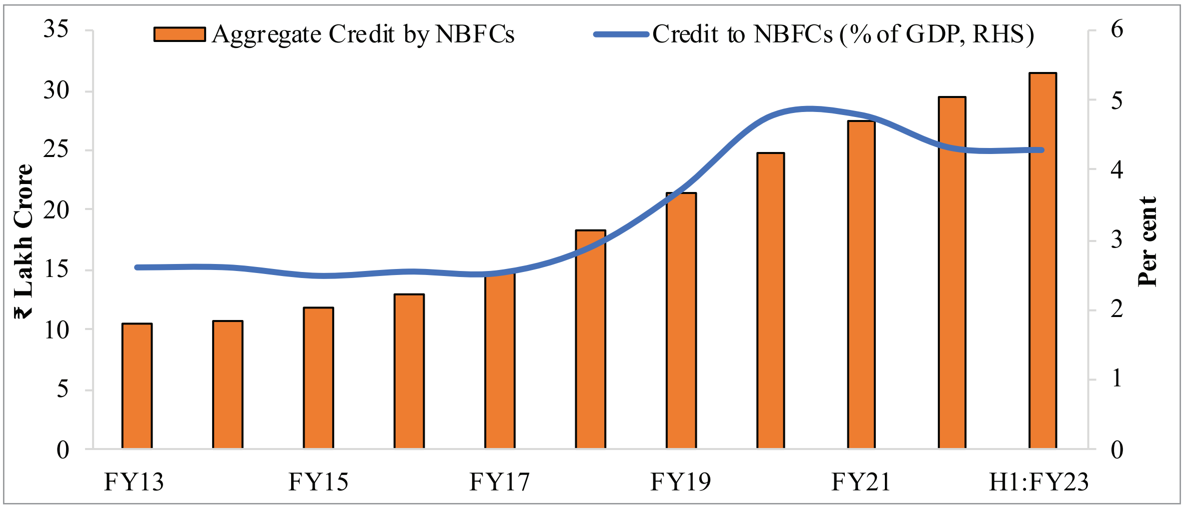

स्रोत: आरबीआई

नोट: वित्त वर्ष 23 (एच1) के लिए एनबीएफसी को क्रेडिट (जीडीपी का प्रतिशत) वित्त वर्ष 23 के लिए एनएसओ के पहले एई और सितंबर 2022 तक एनबीएफसी द्वारा क्रेडिट के आधार पर अनुमानित है।

4.22 आस्ति की गुणवत्ता में निरंतर सुधार एनबीएफसी के गिरते जीएनपीए अनुपात में महामारी की दूसरी लहर (जून 2021) के दौरान दर्ज किए गए 7.2 प्रतिशत के शिखर से सितंबर 2022 में 5.9 प्रतिशत तक देखा गया है, जो पूर्व महामारी स्तर के करीब पहुंच गया है। यद्यपि यह नरमी सभी क्षेत्रों में देखी गई, सेवा क्षेत्र का जीएनपीए अनुपात दो अंकों में बना हुआ है।

चित्र 13: जीएनपीए अनुपात में गिरावट: सभी क्षेत्रों में एनबीएफसी की आस्ति की गुणवत्ता में सुधार

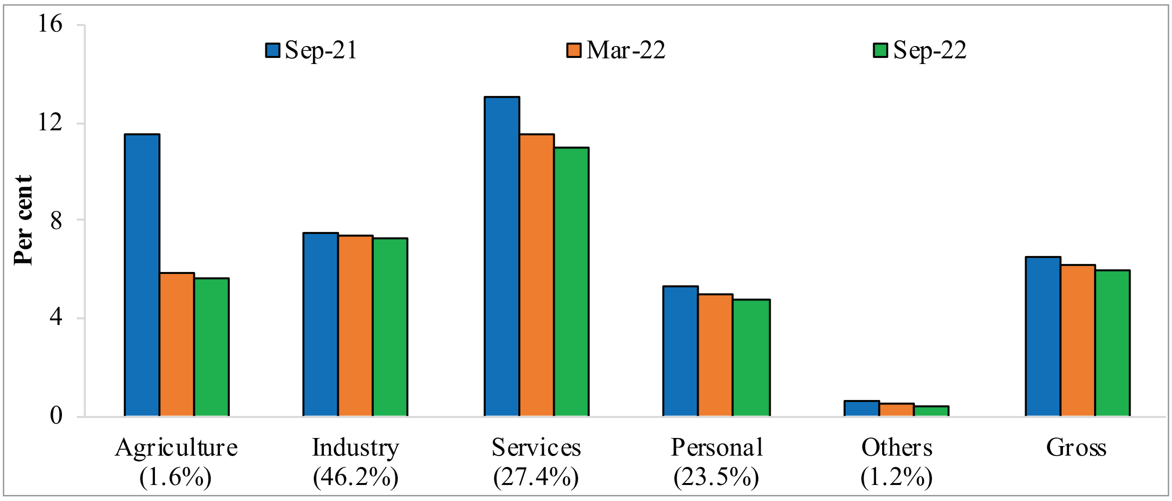

स्रोत: आरबीआई
नोट: ब्रैकेट में संख्या सितंबर -22 में जीएनपीए में क्षेत्रीय शेयरों का प्रतिनिधित्व करती है।

चित्र 14: एनबीएफसी का प्रदर्शन: मजबूत पूंजी स्थिति के साथ आरओए की भरपाई करना

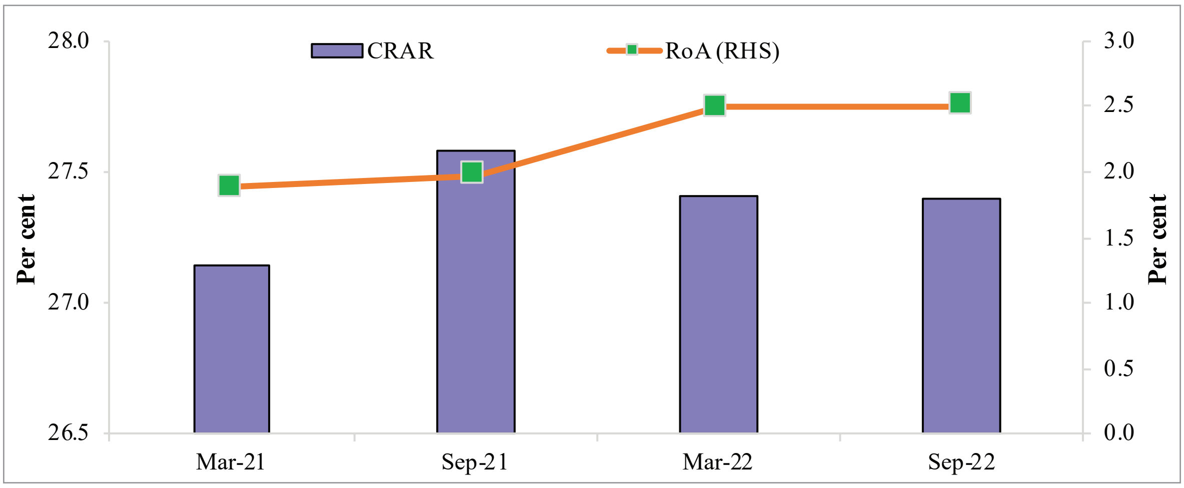

स्रोत: आरबीआई

4.23 जीएनपीए में गिरावट के साथ, एनबीएफसी की पूंजी की स्थिति भी सितंबर 2022 के अंत में 27.4 प्रतिशत के सीआरएआर के साथ मजबूत बनी हुई है, जो मार्च 2022 में 27.6 प्रतिशत से थोड़ा कम है। तथापि, यह नियामक आवश्यकता से काफी ऊपर है। 20 बीपीएस की गिरावट मुख्य रूप से आरडब्ल्यूए में वृद्धि के कारण थी क्योंकि ऋण में तेजी आई थी। लगातार आधे वर्षों में आरओए में सुधार हुआ है। 152 एनबीएफसी के नमूने के लिए एनबीएफसी क्षेत्र के ऋण जोखिम झटकों के लचीलेपन का आकलन करने के लिए आरबीआई के तनाव परीक्षण से पता चलता है कि एनबीएफसी की संख्या जो 15 प्रतिशत की न्यूनतम विनियामक पूंजी आवश्यकता को पूरा करने में विफल होगी, बेसलाइन परिदृश्य के तहत 8 प्रतिशत थी। यह क्रमश: मध्यम और गंभीर तनाव परिदृश्यों के तहत 10 प्रतिशत और 13 प्रतिशत तक बढ़ जाता है।

4.24 सितंबर 2022 तक कुल बकाया राशि ₹ 31.5 लाख करोड़ के साथ, एनबीएफसी द्वारा दिया जाने वाला ऋण गति पकड़ रहा है। एनबीएफसी ने अपनी तुलन पत्र से औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ी मात्रा में ऋण देना जारी रखा, इसके बाद खुदरा, सेवाओं और कृषि का स्थान आता है। सेवा क्षेत्र के लिए ऋण (बकाया ऋण में हिस्सेदारी 14.7 प्रतिशत) और व्यक्तिगत ऋण (29.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी) ने मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की।

चित्र 15: उद्योग में मामूली सुधार के साथ सभी क्षेत्रों में एनबीएफसी द्वारा ऋण संवितरण में मजबूत वृद्धि

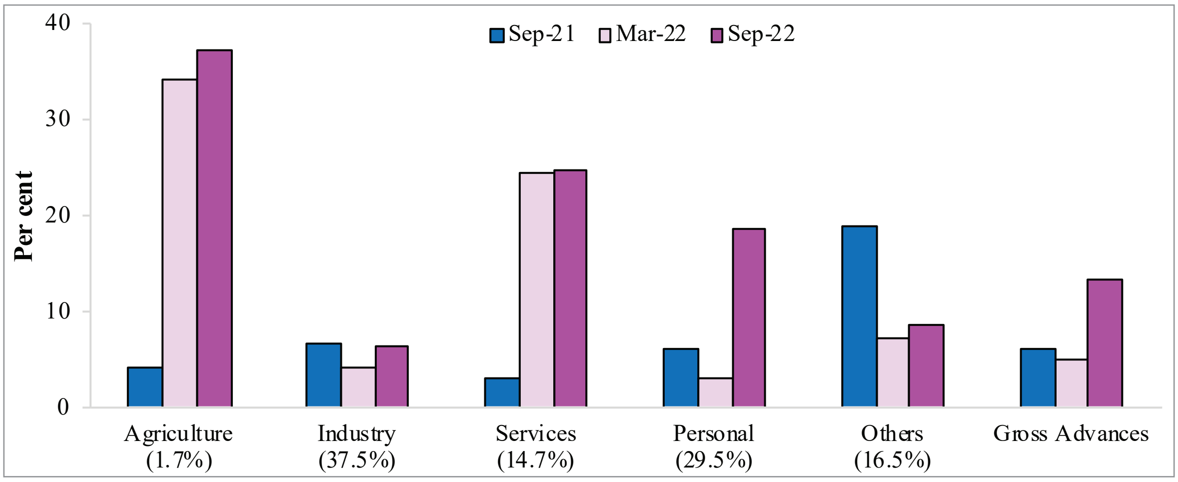

स्रोत: आरबीआई
नोट: ब्रैकेट में संख्याएं सितंबर-22 में बकाया ऋणों में क्षेत्रीय शेयरों से मेल खाती हैं

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत की गई प्रगति

व्यापार की सुगमता: 'निकास की प्रक्रिया को सुगम बनाना'

4.25 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) ने संकटग्रस्त फर्मों के बाहर निकलने की सुविधा प्रदान की है, जिससे दुर्लभ आर्थिक संसाधनों को अधिक उत्पादक उपयोग के लिए आवंटित किया गया है। दिसंबर 2016 में आईबीसी की स्थापना के बाद से, सितंबर 2022 के अंत तक 5,893 कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएँ (सीआइआरपी) शुरू हो चुकी थीं, जिनमें से 67 प्रतिशत को बंद कर दिया गया है। इनमें से, लगभग 21 प्रतिशत अपील या समीक्षा या निपटारे पर बंद कर दिए गए थे, 19 प्रतिशत वापस ले लिए गए थे, 46 प्रतिशत परिसमापन के आदेश समाप्त हो गए थे, और 14 प्रतिशत संकल्प योजनाओं के अनुमोदन में समाप्त हो गए थे। कोड एक कॉर्पोरेट देनदार (सीडी) को स्वेच्छा से खुद को परिसमापन करने के लिए प्रदान करता है, जो कोड के तहत निर्धारित कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन है। सितंबर 2022 के अंत तक 1,351 कॉर्पोरेट व्यक्तियों ने कोड के तहत स्वैच्छिक नकदीकरण की शुरुआत की।

चित्र 16: स्थापना से सीआईआरपी की स्थिति (सितंबर 2022 तक)

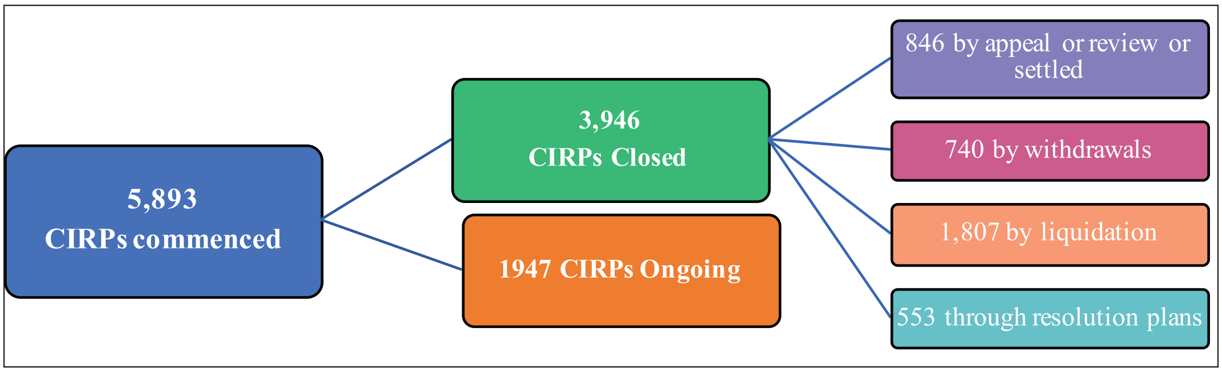

स्रोत: आईबीबीआई (Insolvency and Bankruptcy Board of India)

4.26 क्षेत्रीय विश्लेषण से पता चलता है कि चल रहे सीआईआरपी का 52 प्रतिशत उद्योग से संबंधित है, इसके बाद सितंबर 2022 तक सेवा क्षेत्र में 37 प्रतिशत है। इसके अलावा, उद्योग के भीतर, शुरू किए गए सीआईआरपी का 74 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र से था। इनमें से कपड़ा, मूलभूत धातु और खाद्य क्षेत्र चालू सीआईआरपी के 48 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं। जबकि सेवा क्षेत्र में, चल रहे सीआईआरपी का 60 प्रतिशत रियल एस्टेट, किराये और व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित है।

चित्र 17: क्षेत्रवार सीआईआरपी की स्थिति (सितंबर 2022 तक)

स्रोत: आईबीबीआई

चित्र 18: विनिर्माण क्षेत्र में चल रहे सीआईआरपी का क्षेत्रीय विभाजन

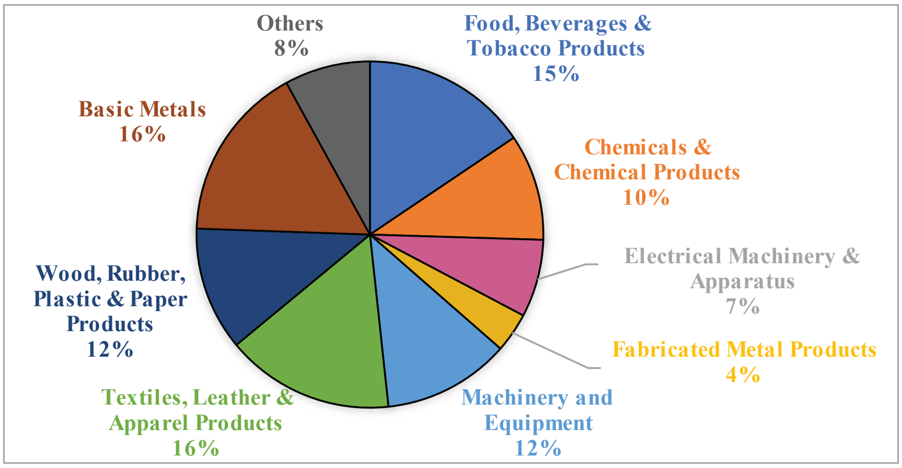

स्रोत: आईबीबीआई

चित्र 19: सेवा क्षेत्र में चल रहे सीआईआरपी का क्षेत्रीय विभाजन

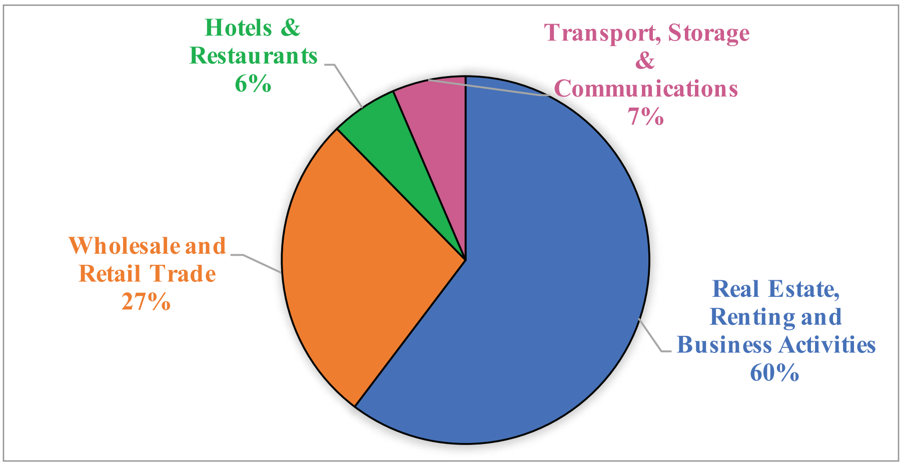

स्रोत: आईबीबीआई

व्यवहारिक परिवर्तन: व्यापार संबंधों को रिकोड करना

4.27 कोड के दूरगामी स्पिल-ओवर प्रभावों में से एक देनदारों के बीच इसके द्वारा व्यवहारिक परिवर्तन किया गया है। सीआईआरपी के शुरू होने पर सीडी पर नियंत्रण खोने के डर ने हजारों देनदारों को दिवाला कार्यवाही शुरू होने से पहले ही अपना बकाया चुकाने के लिए मजबूर कर दिया है। 30 सितंबर, 2022 तक, 7.3 लाख करोड़ के अंतर्निहित डिफॉल्ट वाले सीडी के सीआईआरपी शुरू करने के लिए 23,417 आवेदनों को सीआईआरपी में शामिल करने से पहले निपटा दिया गया था।

संकटग्रस्त आस्तियों का 69 प्रतिशत बचा लिया गया, वसूली मान परिसमापन मूल्य का लगभग 178 प्रतिशत

4.28 30 सितंबर, 2022 तक 553 सीआईआरपी का समाधान हो चुका है। शुरुआत में संकटग्रस्तफर्मों के बहुत कम मूल्य के बावजूद, संहिता द्वारा 69 प्रतिशत संकटग्रस्त आस्तियों को बचाया गया। कुल मिलाकर, सीआईआरपी के आरंभकर्ताओं के लिए मूल्य प्राप्ति के संदर्भ में (जिसमें वित्तीय लेनदार, परिचालन लेनदार और कॉर्पोरेट देनदार शामिल हैं), समाधान योजनाओं से 2.4 लाख करोड़ प्राप्त हुए, जो परिसमापन मूल्य का 177.6 प्रतिशत और बचाए गए 553 सीडी के उचित मूल्य का 84 प्रतिशत है। इसके अलावा, परिसमापन मूल्य की तुलना में संकल्प योजनाओं के तहत वित्तीय लेनदारों द्वारा वसूली 201 प्रतिशत थी, जबकि उनके द्वारा वसूली उनके दावों का 33 प्रतिशत थी।

परिसमापन प्रक्रिया के तहत वसूल किए गए मूल्य का 92 प्रतिशत

4.29 1807 सीडी सितंबर 2022 तक परिसमापन के आदेशों के साथ समाप्त हो गई। इन सीडी आस्तियों का मूल्य जमीन पर कुल दावा राशि के 8 प्रतिशत से कम था। हालांकि, परिसमापन में समाप्त होने वाले सीआईआरपी के 76 प्रतिशत से अधिक (1774 में से 1349 जिसके लिए डेटा उपलब्ध हैं) पहले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के पास थे और/या निष्क्रिय हैं। अधिकांश कॉर्पोरेट देनदारों का आर्थिक मूल्य जो परिसमापन में समाप्त हो गया था, सीआईआरपी में भर्ती होने से पहले ही लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया था। 429 सीडी का पूरी तरह से परिसमापन कर दिया गया है। संहिता ने इन कंपनियों के परिसमापन के माध्यम से 92 प्रतिशत मूल्य की वसूली की सुविधा प्रदान की है।

तालिका 4: 30 सितंबर के अनुसार संकटग्रस्त आस्तियों का बचाव (राशि करोड़ रुपये में)

संकटग्रस्त आस्तियों का बचाव	संकल्प द्वारा बचाई गई कंपनियां	कंपनियों को परिसमापन का आदेश दिया	कुल
कंपनियों की संख्या	553	1807	2360
सकल दावे	7,90,626	8,28,180	16,18,806
परिसमापन मूल्य	1,37,119	60,143	1,97,261
कुल दावों के % के रूप में उपलब्ध आस्तियां	17.3	7.3	12.19
संकल्प मूल्य	2,43,452	लागू नहीं	2,43,452
परिसमापन मूल्य के % के रूप में संकल्प मूल्य	177.6	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल दावों के : के रूप में संकल्प मूल्य	30.8	लागू नहीं	लागू नहीं
औसत समय लिया गया	561 दिन	437 days	लागू नहीं
समाधान मूल्य का लागत :	0.6	लागू नहीं	लागू नहीं

स्रोत: आईबीबीआई

एनपीए: आईबीसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए उच्चतम राशि वसूल करता है।

4.30 आरबीआई आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में लोक अदालत, सरफेसी अधिनियम और डीआरटी जैसे अन्य चौनलों की तुलना में आईबीसी के तहत एससीबी द्वारा वसूल की गई कुल राशि सबसे अधिक रही है।

4.31 आईबीसी जैसे सार्वजनिक नीलामी-आधारित समाधान मॉडल में हेयरकट की सीमा उस छूट का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी मांग दबावग्रस्त इकाई को लाभकारी कारबार वाले संस्थान के रूप में प्राप्त करने के लिए बाजार मांग करता है। चूंकि इन आस्तियों में महत्वपूर्ण मूल्य विनाश पहले ही हो सकता है, स्वीकृत दावों के साथ प्राप्त मूल्य की तुलना समाधान प्रक्रिया की प्रभावशीलता का एक उचित संकेतक नहीं हो सकती है। इसके अलावा, रिकवरी की दर कई कारकों पर निर्भर है, जिसमें समग्र वृहद् आर्थिक वातावरण, इकाई और उसके क्षेत्र की कथित विकास संभावनाएं और इकाई के आंतरिक मूल्य में क्षरण की सीमा शामिल है। एक व्यापक आधार वाली रिकवरी के रूप में, इन कारकों के वित्तीय समाधान[3] के लिए अनुकूल होने की संभावना है।

तालिका 5: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विभिन्न माध्यमों से वसूल की गई राशि (राशि करोड़ में)

रिकवरी चौनल	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि*				
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22(P)
लोक अदालतें	1,811	2,750	4,211	1,119	2,777
डीआरटी	7,235	10,552	9,986	8,113	12,114
सरफेसी एक्ट	26,380	38,905	34,283	27,686	27,349
आईबीसी	4,926	66,440	1,04,117	27,311	47,421
कुल	**40,352**	**1,18,647**	**1,52,597**	**64,229**	**89,661**

स्रोत: ऑफ-साइट रिटर्न, आरबीआई और आईबीबीआई
नोट: पी: अनंतिम, डीआरटी ऋण वसूली न्यायाधिकरण के लिए है
नोट *: दिए गए वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि को संदर्भित करता है, जो कि दिए गए वर्ष के दौरान और साथ ही पिछले वर्षों के दौरान संदर्भित मामलों के संदर्भ में हो सकता है।

पूंजी बाजार में विकास

वैश्विक मैक्रोइकॉनॉमिक अनिश्चितता, अभूतपूर्व मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति को सख्त करना, अस्थिर बाजार, आदि के परिणामस्वरूप निवेशकों की भावना को ठेस पहुंची है, जिससे वित्त वर्ष 23 में वैश्विक पूंजी बाजारों के निष्पादन में गिरावट आई है। तथापि वैश्विक व्यापक आर्थिक और वित्तीय बाजार के विकास ने भारतीय पूंजी बाजारों पर कुछ प्रभाव डाला, कुल मिलाकर भारत के पूंजी बाजार का वर्ष अच्छा रहा।

प्राथमिक बाजार

इक्विटी: सार्वजनिक पेशकश के साथ बड़ी संख्या में एसएमई सामने आ रहे हैं

4.32 अप्रैल से नवंबर 2022 तक, वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल के बावजूद प्राथमिक बाजार का उछाल देखा गया है। वित्त वर्ष 22 की तुलना में, एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने वालीफर्मों की संख्या में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई, तथापि जुटाई गई राशि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग आधी हो गई।

4.33 यद्यपि अभी तक आईपीओ के माध्यम सेफंड जुटाने के मामले में यह वर्ष कमजोर रहा है, सार्वजनिक पेशकश के साथ आने वाले एसएमई की संख्या काफी उत्साहजनक रही है। वित्त वर्ष 22 (नवंबर 2021 तक) की तुलना में, इस वर्ष न केवल आईपीओ के साथ आने वाले एसएमई की संख्या लगभग दोगुनी हुई, बल्कि उनके द्वारा जुटाई गई कुल धनराशि पिछले वर्ष की समान अवधि में उनके द्वारा जुटाई गई राशि से लगभग तीन गुना अधिक थी।

4.34 इसके अलावा, इस वर्ष भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ भी देखा गया। मई 2022 में, केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपनी हिस्सेदारी को कम कर दिया और इसे स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कर दिया, जिससे एलआईसी का आईपीओ भारत में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ और 2022 का विश्व स्तर पर छठा सबसे बड़ा आईपीओ बन गया। नवंबर, 2022 तक प्राथमिक इक्विटी बाजार में जुटाए गए संसाधनों के एक तिहाई से अधिक के लिए एलआईसी की सूचीबद्ध हुई।

ऋण: सार्वजनिक ऋण जारी करने में कम सक्रियता निजी ऋण प्लेसमेंट द्वारा क्षतिपूर्ति से अधिक है

4.35 अप्रैल-नवंबर 2022 में, प्राथमिक बाजार में ऋण प्रतिभूतियों को जारी करके जुटाए गए संसाधनों की मात्रा में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि में निर्गमों की कुल संख्या में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल से नवंबर 2022 तक, ऋण के सार्वजनिक निर्गम में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 15 प्रतिशत की मामूली कमी देखी गई, और इसी अवधि में ऋण के सार्वजनिक निर्गम द्वारा जुटाई गई राशि भी एक तिहाई से भी कम हो गई। हालांकि, सार्वजनिक ऋण जारी करने में कम सक्रियता निजी ऋण प्लेसमेंट द्वारा क्षतिपूर्ति से अधिक थी। निजी ऋण प्लेसमेंट की संख्या 851 से 945 तक 11 प्रतिशत बढ़ गई, जबकि अप्रैल-नवंबर 2022 में संसाधन जुटाए गए वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तालिका 6: प्राथमिक बाजार से संसाधन जुटाना

विवरण	अप्रैल - नवम्बर 2021		अप्रैल - नवम्बर 2022	
	जारी करने की संख्या	राशि (करोड़)	जारी करने की संख्या	राशि (करोड़)
क. इक्विटी	**350**	**1,81,532**	**448**	**1,14,361**
आईपीओ	76	89,166	104	48,095
एफपीओ	0	0	1	4,300
निर्गम	18	22,659	37	3,436
क्यूआईपी	23	26,704	8	4,115
अधिमान्य आवंटन	233	43,004	298	54,414
ख. ऋण	**871**	**3,71,590**	**967**	**3,91,997**
जनता	20	9,132	22	6,624
निजी कार्य नियुक्ति	851	3,62,458	945	3,85,373
कुल (क+ख)	**1,221**	**5,53,122**	**1,415**	**5,06,358**

स्रोत: सेबी

द्वितीयक बाजार

शेयर बाजार का निष्पादन: भारतीय शेयर बाजार में लचीला निष्पादन देखा जा रहा है

4.36 अप्रैल-दिसंबर 2022 में भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट आई। इसके विपरीत, भारतीय शेयर बाजार ने एक लचीला प्रदर्शन देखा, उसी अवधि के दौरान निफ्टी 50 ने 3.7 प्रतिशत की वापसी दर्ज की। निफ्टी 50-अमेरिकी डॉलर समायोजित प्रतिफल भी -4.7 प्रतिशत रहा, जो अमेरिकी डॉलर के प्रति भारतीय रुपये के मूल्यह्रास को समायोजित करता है। यूएस के संबंध में एसएंडपी 500 औसत सूचकांक में 15.3 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक कंपोजिट ख प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों के प्रति भारी भार (49 प्रतिशत) में 26.4 प्रतिशत की तेजी से गिरावट आई। दिसंबर 2022 के अंत में, सेंसेक्स दिनांक 31 मार्च, 2022 को अपने समापन स्तर से क्रमश: 3.9 प्रतिशत अधिक बंद हुए। प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भी, भारत ने अप्रैल-दिसंबर 2022 में अपने साथियों को पीछे छोड़ दिया।

तालिका 7: वित्त वर्ष 2023 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान भारत ने अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन किया

सूची	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	30 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार	वित्त वर्ष 22 में प्रतिशत परिवर्तन (अप्रैल-नवंबर)	वित्त वर्ष 23 में प्रतिशत परिवर्तन (अप्रैल-दिसंबर)
भारत				
निफ्टी 50	17,464.7	18,105.3	18.1	3.7
एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स	58,568.5	60,840.7	17.7	3.9
उभरते बाजार				
शंघाई कम्पोजिट, चीन	3,252.2	3,089.3	5.8	-5.0
ब्राजील इबोवेस्पा	1,19,999.0	1,09,735.0	-10.1	-8.6
कोस्पी, कोरिया	2,757.6	2,236.4	-2.7	-18.9
विकसित बाजार				
नैस्डैक	14,220.5	10,466.5	18.1	-26.4
डॉव जोन्स, यूएसए	34,678.3	33,147.3	10.2	-4.4
एस एण्ड पी 500, यूएसए	4,530.4	3,839.5	20.0	-15.3
सीएसी, फ्रांस	6,659.9	6,473.8	17.9	-2.8
डैक्स, जर्मनी	14,414.8	13,923.6	5.8	-3.4
एफटीएसई 100, यूके	7,515.7	7,451.7	10.0	-0.9
हैंग सेंग, हांग कांग	21,997.8	19,781.0	-17.5	-10.1
निक्केई, जापान	27,821.4	26,094.5	-1.3	-6.2

स्रोत: रिफिनिटिव, एनएसई, बीएसई

चित्र 20: भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों में तेजी से सुधार देखा गया

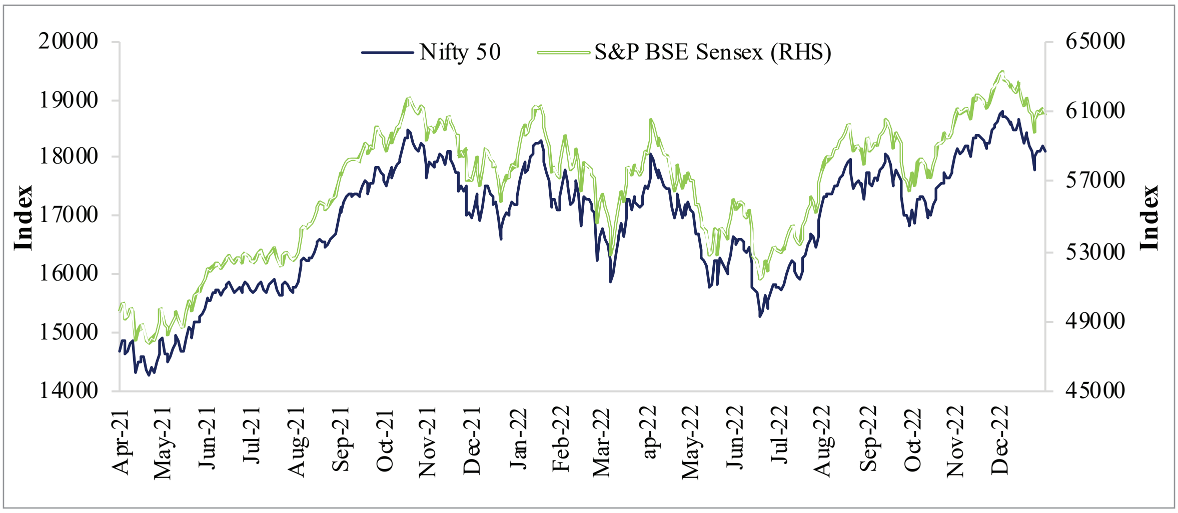

स्रोत: सेबी

चित्र 21: इंडिया वीआईएक्स में गिरावट का रुख देखा गया

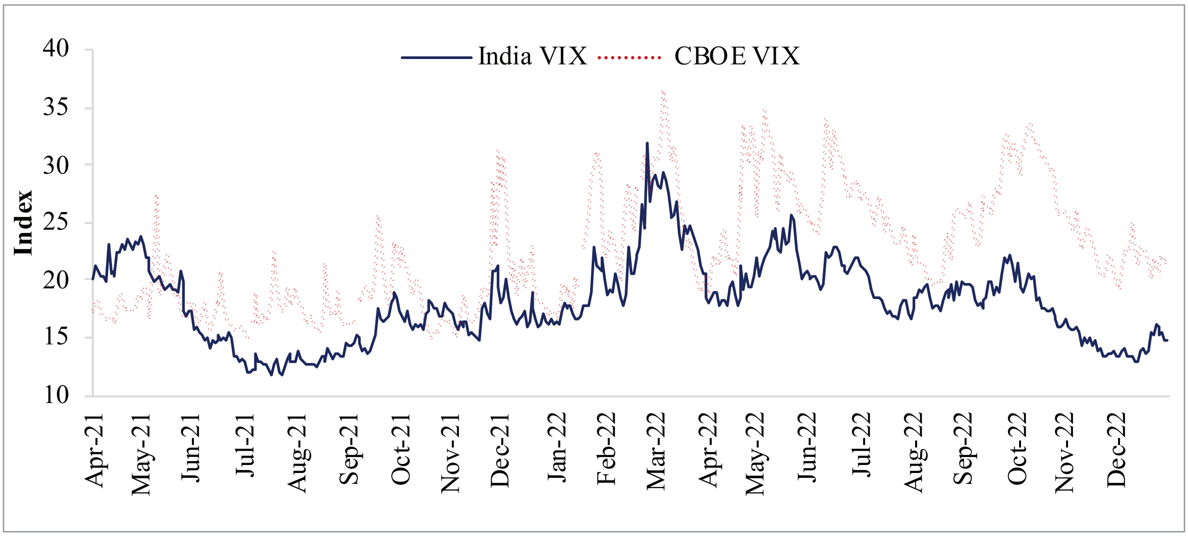

स्रोत: सेबी, ब्लूमबर्ग

नोट: VIX का मतलब अस्थिरता सूचकांक है। सीबीओई का मतलब शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज है

4.37 रूस-यूक्रेन संकट के बाद भू-राजनीतिक अनिश्चितता और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान के कारण शेयर बाजार में अस्थिरता बढ़ गई। भारत VIX, जो शेयर बाजार में अल्पकालिक अस्थिरता को मापता है, 24 फरवरी 2022 को रूस-यूक्रेन संघर्ष के प्रकोप के साथ 32.0 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी इक्विटी बाजार (सीबीओई वीआईएक्स द्वारा मापा गया) में समान प्रवृत्ति देखी गई। संघर्ष के प्रकोप के बाद, भू-राजनीतिक संकट ने बाजार के रूझान को कमजोर कर दिया, जो कुछ हफ्ते में बेंचमार्क सूचकांकों के नीचे की ओर बढ़ने में परिलक्षित हुआ। भारतीय शेयर बाजार ने भी नुकसान दर्ज किया लेकिन जल्दी ही मार्च 2022 में एक सकारात्मक नोट पर समाप्त हुआ। अप्रैल-नवंबर 2022 में, भारत VIX में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई क्योंकि वर्ष बढ़ने के साथ संघर्ष का प्रभाव कम होने लगा।

चित्र 22: वित्तीय वर्ष 23 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान भारतीय सूचकांकों में वार्षिक अस्थिरता अपेक्षाकृत कम रही

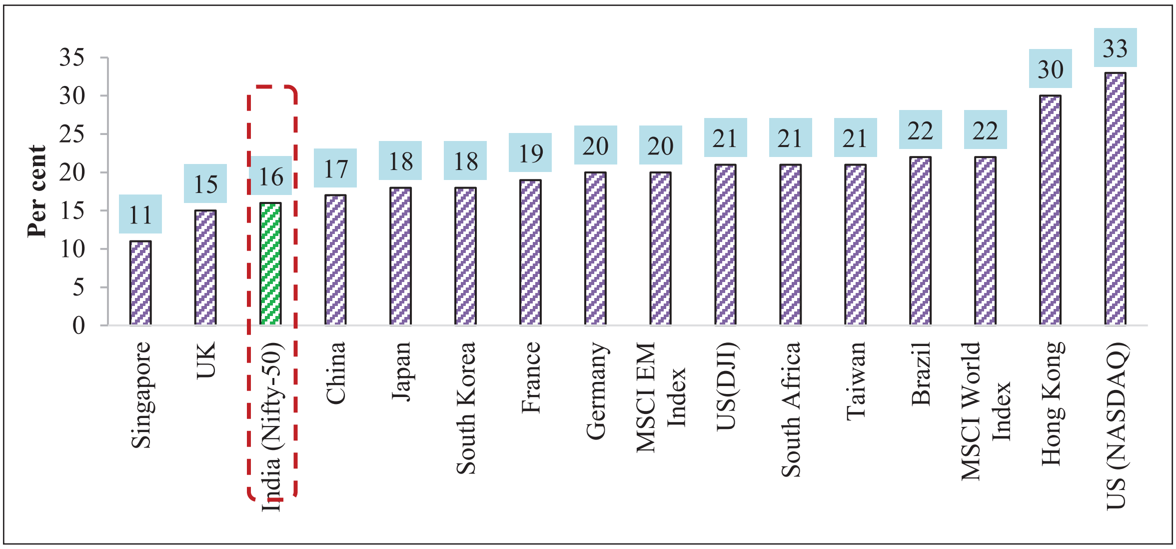

स्रोत: सेबी

मूल्यांकन (पी/ई अनुपात): वैश्विक बाजारों की तुलना में निफ्टी 50

4.38 निफ्टी 50, दिसंबर 2022 के अंत में ट्रेलिंग आधार पर 21.8 गुना मूल्य-से-कमाई (पी/ई अनुपात) अनुपात के साथ, वैश्विक बाजारों की तुलना में महंगा है, हालांकि अभी भी अपने पिछले पांच साल के औसत की तुलना में कम है।

चित्र 23: निफ्टी 50 वैश्विक बाजारों की तुलना में महंगा है, हालांकि अपने 5 साल (2017-2021) के औसत की तुलना में अभी भी कम है

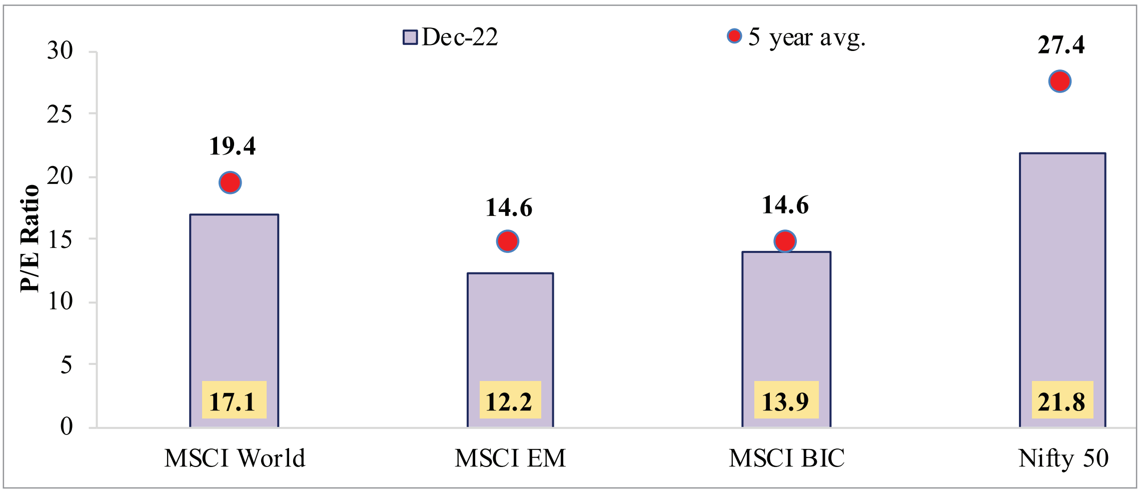

स्रोत: सेबी

टिप्पणियाँ: एम एससीआई वर्ल्ड इंडेक्स 23 विकसित बाजारों (डीएम) देशों में बड़े और मिड-कैप प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। एम एससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स 24 इमर्जिंग मार्केट्स (ईएम) देशों में बड़े और मिड कैप प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। एम एससीआई बीआईसी इंडेक्स एकपफी लोट-एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेन वेटेड इंडेक्स है जिसे तीन इमर्जिंग मार्केट कंट्री इंडेक्स: ब्राजील, भारत और चीन में इक्विटी मार्केट के प्रदर्शन को मापने के लिए डिजाइन किया गया है।

पूंजी बाजार में खुदरा भागीदारी

4.40 वित्तीय वर्ष 22 के दौरान इसी अवधि की तुलना में वित्त वर्ष 23 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान नकद खंड में व्यक्ति गत निवेशकों की हिस्सेदारी में मामूली गिरावट आई है। हालांकि, वर्ष दर वर्ष आधार पर नवंबर 2022

के अंत तक डीमैट खातों की संख्या में तेजी से 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, डीमैट खातों की वृद्धिशील वृद्धि चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रचलित वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बीच संभवत: द्वितीयक बाजार में बढ़ी हुई अस्थिरता और प्राथमिक बाजार के कमजोर निष्पादन के कारण वित्तीय वर्ष 22 की तुलना में वित्त वर्ष 23 के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति रही है।

तालिका 8: इक्विटी कैश सेगमेंट टर्नओवर में व्यक्तिगत निवेशकों की हिस्सेदारी में गिरावट आई

वर्ष	व्यक्तिगत निवेशकों का शेयर (प्रतिशत)
वित्त वर्ष	41.1
वित्त वर्ष 22 (अप्रैल से नवंबर)	42.2
वित्त वर्ष 23 (अप्रैल से नवंबर)	37.5

स्रोत: एनएसई, बीएसई

नोट: व्यक्तिगत निवेशकों में व्यक्तिगत घरेलू निवेशक, एनआरआई, एकमात्र स्वामित्वफर्म और एचयूएफ शामिल हैं, अन्य: पार्टनरशिपफफर्म/एलएलपी, ट्रस्ट/सोसायटी, डिपॉजिटरी रसीदें, सांविधिक निकाय, ओसीबी, एफएन, आदि।

तालिका 9: वित्त वर्ष 2022 में डीमैट खातों में तेज वृद्धि देखी गई

वर्ष	डीमैट खातों की कुल संख्या (लाख में)	अवधि के दौरान जोड़े गए खाते (लाख में)
वित्त वर्ष 22*	890.3	344.8
वित्त वर्ष 22@	766.1	220.7
वित्त वर्ष 23#	1,061.7	171.5

नोट: *2022 मार्च के अंत में, @ नवंबर 2021 के अंत में, # नवंबर 2022 के अंत में

टर्नओवर सांख्यिकी: इक्विटी व्युत्पन्न वॉल्यूम में भारी उछाल देखा गया

4.41 पिछले साल की समान अवधि की तुलना में अप्रैल और नवंबर 2022 के बीच नकदी खंड का कारोबार घट गया, जबकि इक्विटी व्युत्पन्नी मात्रा (वॉल्यूम) में काफी उछाल दर्ज किया गया, जो इक्विटी नकदी खंड से इक्विटी व्युत्पन्नी सेगमेंट में व्यक्तियों और मालिकाना व्यापारियों के बढ़ते हितों को दर्शाता है। दुनिया भर में व्याप्त भारी अनिश्चितता से प्रेरित, मुद्रा और कमोडिटी व्युत्पन्नी मात्रा (वॉल्यूम) में भी इसी अवधि के दौरान वृद्धि दर्ज की गई।

तालिका 10: इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी डेरिवेटिव्स में टर्नओवर सांख्यिकी में वृद्धि हुई

Year	वित्तीय वर्ष- 22 (1)	वित्तीय वर्ष- 22# (₹ लाख करोड़) (2)	वित्तीय वर्ष- 23# (₹ लाख करोड़) (3)	प्रतिशत परिवर्तन (4)
नकद खंड	179.0	124.3	98.2	-21
इक्विटी व्युत्पन्नी	17,613.1	9,860.8	20,979.6	113
करेंसी व्युत्पन्नी	277.2	152.7	280.4	87
कमोडिटी व्युत्पन्नी	100.3	65.2	92.6	42
ब्याज दर व्युत्पन्नी	0.7	0.4	0.3	-17

स्रोत: सेबी

#अवधि-अप्रैल से नवंबर

कमोडिटी व्युत्पन्न बाजार: फेड द्वारा मौद्रिक सख्ती के कारण तेज सुधार देखा गया

4.42 रूस-यूक्रेन संघर्ष ने वस्तुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, आधार धातुओं और खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न किया। परिणामस्वरूप, कच्चे तेल और निकेल और एल्युमीनियम जैसी कुछ बेस मेटल्स की कीमतों में अचानक उछाल देखा गया। हालांकि, बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए फेडरल रिजर्व द्वारा मार्च 2022 में ब्याज दरों में वृद्धि शुरू करने के कारण कमोडिटी की कीमतों में तेज सुधार देखा गया है। 31 मार्च 2022 की तुलना में नवंबर 2022 के अंत तक एमसीएक्सआई कॉमडेक्स बेस मेटल इंडेक्स की कीमत में 19.1फीसदी की गिरावट आई, इसके बाद बुलियन इंडेक्स (-3.5 फीसदी) और एनर्जी इंडेक्स (-1फीसदी) का नंबर आता है। एमसीएक्स पर एल्युमीनियम, कॉपर, जिंक और निकेल की कीमतों में भी नवंबर 2022 में 20 मार्च की तुलना में गिरावट दर्ज की गई।

म्युचुअल फंड में कम निवल प्रवाह देखा गया

4.43 अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान, म्यूचुअलफंड में पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम शुद्ध प्रवाह देखा गया। तथापि, इसी अवधि के दौरान, विकास/इक्विटी-उन्मुख योजनाओं और समाधान-उन्मुख योजनाओं वाली कुछ योजनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक अंतर्वाह देखा गया।

4.44 दूसरी ओर, आय/ऋण-उन्मुख योजनाओं और हाइब्रिड योजनाओं में पिछले वर्ष की समान अवधि में प्रवाह की तुलना में बहिर्वाह दर्ज किया गया। कॉरपोरेट्स द्वारा ब्याज दर चक्र, नकदी आवश्यकताओं और अग्रिम कर प्रतिबद्धताओं में वृद्धि से मुख्य रूप से नकद निधियों और हाइब्रिड योजनाओं से बहिर्वाह प्रभावित हुआ। इसके बावजूद, बाजार के निष्पादन की बदौलत म्यूचुअलफंड उद्योग की संपत्ति प्रबंधन (एयूएम) में नवंबर 2022 के अंत में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तालिका 11: म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम में वृद्धि

वर्ष	फोलियो संख्या (करोड़)	सकल संसाधन जुटाना (लाख करोड़)	मोचन (लाख करोड़)	शुद्ध संसाधन जुटाना (लाख करोड़)	एयूएम (लाख करोड़)
वित्तीय वर्ष 22	13.0	93.2	90.7	2.5	37.6
वित्तीय वर्ष 22#	11.7	58.6	56.1	2.5	37.3
वित्तीय वर्ष 23#	14.0	69.1	68.4	0.7	40.4

स्रोत: सेबी।
#संबंधित वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक

तालिका 12: इक्विटी-उन्मुख योजनाओं में शुद्ध प्रवाह देखा गया

वर्ष	आय/ऋण उन्मुख (लाख करोड़)	विकास/इक्विटी उन्मुख (लाख करोड़)	हाइब्रिड (करोड़)	समाधान उन्मुख (करोड़)	अन्य (लाख करोड़)	संपूर्ण (लाख करोड़)
वित्तीय वर्ष 22	2.0	-0.4	-2,936	1,577	0.6	2.1
वित्तीय वर्ष 22#	0.2	0.7	88,854	650	0.8	2.5
वित्तीय वर्ष 23#	-1.1	0.9	-13,649	1,091	1.0	0.7

स्रोत: सेबी।
नोट: अन्य योजनाओं में इंडेक्स निधि, गोल्ड ईटीएफ, अन्य ईटीएफ और विदेशों में निवेश करने वाले एफओएफ शामिल हैं।
#संबंधित वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश

सुदृढ वृहद् आर्थिक आधार भारत एक आकर्षक गंतव्य बने सुनिश्चित करता है

4.45 वैश्विक आर्थिक कारकों, जैसे कि मुद्रास्फीति के दबाव, केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक दबाव, और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की आशंकाओं ने एफपीआई पर भारतीय बाजारों में बिक्री के लिए दबाव डाला है। इसके अलावा, निवेशक भारतीय शेयरों के मुनाफा लिए बैठे थे, जिन्हें अन्यत्र ऑफसेट नुकसान के लिए साधित किया जा सकता था। बहरहाल, भारतीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ वृहद् आर्थिक आधार और समय-समय पर बाजार जोखिम की प्रवृत्ति में सुधार के कारण, संरक्षण प्राप्त संपत्ति (धारित के कुल बाजार मूल्य को दर्शाती एफपीआई की अभिरक्षण संबंधी धारित) में वैश्विक कारकों द्वारा संचालित बहिर्वाह के बावजूद वृद्धि देखी गई। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 के अंत में एफपीआई के पास संरक्षित कुल संपत्ति में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिक 13: एफपीआई के तहत संरक्षित संपत्तियां में वद्धि

वर्ष	इक्विटी (लाख करोड़)	ऋण (लाख करोड़)	ऋण वीआरआर (लाख करोड़)	हाइब्रिड (लाख करोड़)	संपूर्ण (लाख करोड़)
नवंबर 2022 को समाप्त	49.9	2.4	1.4	0.3	54.0
नवंबर 2021 को समाप्त	48.0	2.7	1.3	0.3	52.2

स्रोत: सेबी।

4.46 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा कुल शुद्ध निवेश में दिसंबर, 2021 के अंत में रू. 5,578 करोड़ के प्रवाह से दिसंबर, 2022 के अंत में रू. 16,153 करोड़ का प्रवाह दर्ज किया, इक्विटी खंड और ऋण खंड दोनों में शुद्ध एफपीआई बहिर्वाह देखा गया।

तालिका 14: एफपीआई में दर्ज बहिर्वाह के अनुसार शुद्ध निवेश

मासिक एफपीआई शुद्ध निवेश (वित्त वर्ष 23)					
माह	₹ करोड़				
	इक्विटी	ऋण	ऋण-वीआरआर	हाइब्रिड	कुल
अप्रैल	-17,144	-4,439	-1,175	69	-22,688
मई	-39,993	-5,506	9,043	-62	-36,518
जून	-50,203	-1,414	87	108	-51,422
जुलाई	4,989	-2,056	-785	-176	1,971
अगस्त	51,204	3,845	2,997	-1,525	56,521
सितंबर	-7,624	4,012	-1,455	1,112	-3,955
अक्टूबर	-8	-3,532	762	-301	-3,080
नवंबर	36,239	-1,637	-540	-214	33,847
दिसम्बर	11,119	-1,673	-272	-4	9,171
कुल – FY23	**-11,421**	**-12,400**	**8,662**	**-993**	**-16,153**

स्रोत: सेबी

* ऊपर प्रस्तुत डेटा धारितों द्वारा सेबी/जमाकर्ताओं को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संकलित किया गया है और एफपीआई द्वारा पिछले ट्रेडिंग दिवस पर और उस तक किए गए ट्रेडों का गठन करता है।

दिसम्बर 2022 तक।

4.47 भारत और चीन जैसे ईएमडीई से बड़े पूंजी प्रवाह, जो वस्तुओं के आयातक हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्राजील जैसे वस्तु निर्यात उन्मुख बाजारों में प्रवाह से मेल खाते थे।

तालिका 15: चयनित बाजारों में कुल पोर्टफोलियो प्रवाह का रुझान (बिलियन अमेरिकी डॉलर)

	2019	2020	2021	2022 (नवंबर तक)
दक्षिण कोरिया	46.7	42.2	83.2	43.6
चीन	196.1	408.3	230.3	-183.3
ब्राजिल	-19.4	-6.4	14.6	3.1
जापान	88.9	-87.7	141.7	-39.0
भारत	17.7	9.5	2.2	-18.9
दक्षिण अफ्रीका	-10.2	-9.7	-23.6	-20.7
थाईलैंड	-2.0	-9.3	4.9	11.1
ताइवान	9.4	-15.3	-15.6	-41.5
तुर्की	-2.7	-9.4	0.4	-3.1

स्रोत: ब्लूमबर्ग, 12 दिसंबर, 2022 तक के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित

4.48 हाल के वर्षों के दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईई) के निवेशों की बराबर करने वाली प्रकृति ने एफपीआई बहिर्वाह के प्रति बराबर करने वाले बल के रूप में काम किया है, भारतीय इक्विटी ने बाजार को बड़े पैमाने पर सुधार के लिए अपेक्षाकृत कम संवेदनशील बना दिया है। वित्त वर्ष 23 (नवंबर 2022 तक) के दौरान इक्विटी में म्यूचुअलफंड द्वारा शुद्ध डीआईआई प्रवाह और शुद्ध निवेश देखा गया है।

चित्र 24: हाल के वर्षों के दौरान एफपीआई बहिर्गमन के लिए डीआईआई निवेश ने बराबर करने वाले बल के रूप में कार्य किया

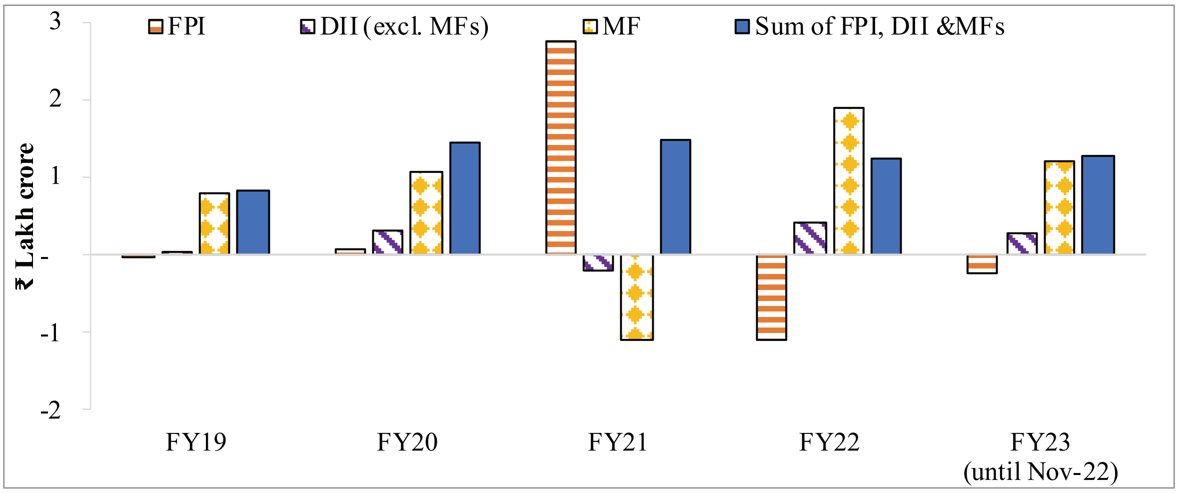

स्रोत: सेबी

अन्य विकास

क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र को विनियमित करने के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण की आवश्यकता

4.49 क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के हालिया पतन और क्रिप्टो बाजार में आगामी बिकवाली ने क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र की कमजोरियों पर प्रकाश डाला है। क्रिप्टो आस्तियां स्व-संदर्भित उपकरण हैं और वित्तीय संपत्ति होने की कसौटी

पर सख्ती से खारा नहीं उतरते हैं क्योंकि इसमें कोई आंतरिक नकदी प्रवाह नहीं है। अमेरिकी नियामकों ने बिटकॉइन, ईथर और विभिन्न अन्य क्रिप्टो आस्तियों को प्रतिभूतियों4 के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया है। फेडरल रिजर्व, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (एफडीआईसी) और मुद्रा नियंत्रक कार्यालय (ओसीसी) द्वारा 3 जनवरी 2023 को एक असाधारण संयुत्त वत्तव्य5 में बैंकिंग प्रणाली के लिए क्रिप्टो-एसेट जोखिमों के बारे में उनकी चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है। क्रिप्टो पारिस्थितिकी की भौगोलिक रूप से व्यापक प्रकृति इन अस्थिर उपकरणों के नियमन के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, क्रिप्टो के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया आ रही है, और बॉक्स 1 दुनिया भर में क्रिप्टो के लिए विनियामक दृश्टिकोण की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है।[1]

बॉक्स 1: क्रॉस कंट्री विश्लेषण: क्रिप्टोकरंसी का विनियमन

क्रिप्टो आस्ति क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों का उपयोग करके लागू की गई डिजिटल आस्ति के नए रूप हैं। क्रिप्टो आस्ति मार्केट बहुत अस्थिर रहा है, जिसका कुल मूल्यांकन बदलते हुए नवंबर 2021 में लगभग 3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बदले जनवरी 2023 में 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से कम हो गया है। क्रिप्टो एसेट पारिस्थितिकी की अस्थिरता ने उनके नाजुक समर्थन और शासन की समस्याओं के साथ-साथ बढ़ती जटिलता और गैर-पारदर्शिता को सबसे आगे ला दिया है। संबंधित वित्तीय स्थिरता जोखिम बढ़ने के साथ, क्रिप्टो आस्ति विनियमन के मुद्दे ने हाल ही में कई देशों के नीतिगत कार्यसूची को आगे बढ़ाया है। ओईसीडी और जी 20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच क्रिप्टो आस्ति को विनियमित करने के लिए विश्व स्तर पर समन्वित दृष्टिकोण पर चर्चा कर रहे हैं।

क्रिप्टो बाजार पूंजीकरण (बिलियन अमरीकी डॉलर)

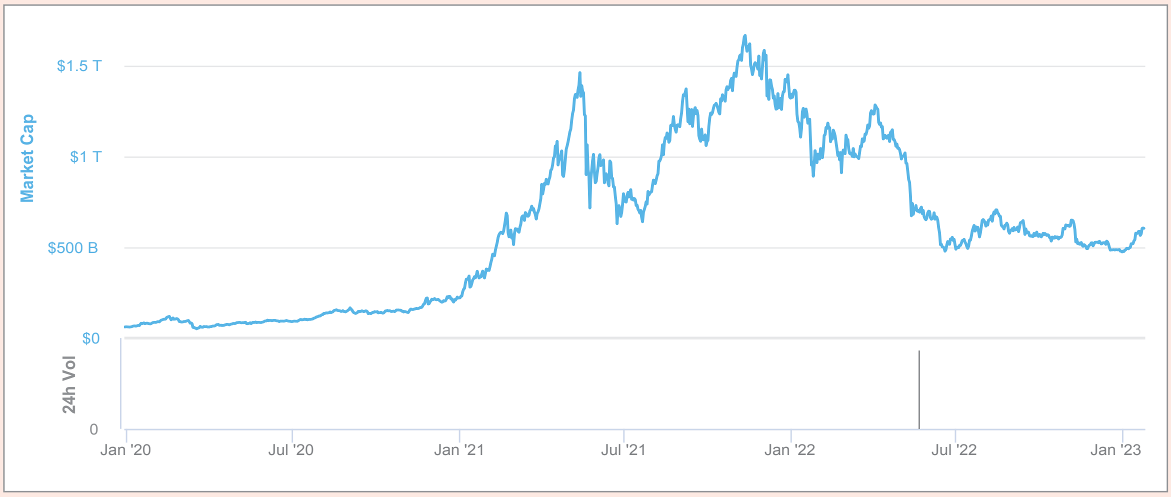

स्रोतः : कोएनएमांआरकेटकेप

क्रिप्टोकरेंसी की निगरानी और विनियमन मुश्किल हो गया है, और दुनिया भर के नियामकों को तेजी से बढ़ते अज्ञात क्षेत्र में नए और उभरते मुद्दों पर नजर रखना चुनौतीपूर्ण लगता है। जबकि क्रिप्टो आस्तियाँ स्पष्ट रूप से पारंपरिक वित्तीय सेवाओं को विकेंद्रीकृत करने के लिए डिजाइन की गई थी, इसने नई अनियमित मध्यस्थ संस्थाओं का निर्माण किया है। विकेंद्रीकरण का वादा भी व्यवहार में अभी तक साकार नहीं हुआ है। नए केंद्रीकृत मध्यस्थ, जैसे कि क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज, वॉलेट प्रदाता और क्रिप्टो समूह, के उपयोगकर्ताओं को केंद्रीकृत संस्थाओं पर भरोसा करना अपेक्षित है। इन संस्थाओं का बढ़ता महत्व नियामकों को उन्हें प्रणालीगत वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)6 के रूप में मानने के लिए मजबूर कर सकता है। फिर भी, तथ्य यह है कि वे अभी तक बड़े पैमाने पर अनियमित हैं, विश्व स्तर पर चिंता का कारण है।

1 बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अनुसार,फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर (एफएमआई) को भाग लेने वाले संस्थाओं के बीच एक बहुपक्षीय प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है जिसमें सिस्टम के ऑपरेटर शामिल हैं, जिसका उपयोग समाशोधान, निपटान, या भुगतान, प्रतिभूति, डेरिवेटिव, या अन्य वित्तीय लेनदेन रिकॉर्ड करने के उद्देश्यों के लिए किया है आरबीआई के अनुसार एफएमआई शब्द आम तौर पर व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज (सीएमडी), सिक्योरिटीज सिस्टम्स (एसएसएस), सेंट्रल काउंटर पार्टियों (सीसीपी) और ट्रेड रिपॉजिटरीज (टीआर) को संदर्भित करता हैं। जो वित्तीय लेनदेन की समाशोधान, निपटान और रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करता है।

दिलचस्प बात यह है, कि क्रिप्टो आस्तियां मुख्य रूप से कुछ ''व्हेल'' के हाथों में केंद्रित हैं। अनुमान बताते हैं कि सभी सर्कुलेटिंग बिटकॉइन का लगभग 85 प्रतिशत का 4.5 प्रतिशत संस्थाओं (बेन मरियम एट अल, 2020) के पास है। क्रिप्टो आस्तियां बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंतर्निहित प्रोटोकॉल अन्य सार्वजनिक नीति उद्देश्यों उदाहरण के लिए, ''खनन'' क्रिप्टो संपत्ति की विशाल ऊर्जा तीव्रता के साथ भी विरोधाभास कर सकते हैं।

गैर-समर्थित क्रिप्टो आस्तियों पर न्यूनतम वैश्विक मानक लागू होते हैं, जो वर्तमान में सभी जोखिमों और अति संवेदनशीलता को कम नहीं करते हैं। यहां तक कि मानक-निर्धारण निकाय (एसएसबी) मानकों को समायोजित और विकसित करने के प्रयास कर रहे हैं, ये मुख्य रूप से विशिष्ट मुद्दों (वित्तीय अखंडता), क्षेत्रों (भुगतान, प्रतिभूति और बैंकिंग), उत्पादों (वैश्विक स्थिर सिक्के), या घरेलू प्राधिकारियों द्वारा प्रणालीगत के रूप में नामित संस्थाओं पर केंद्रित हैं। इस प्रकार, जब गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा क्रिप्टो आस्तियों को जारी, स्थानांतरित, विनिमय, या संग्रहीत किए जाते हैं तब प्रत्येक चरण में विनियामक अंतराल होता है। क्रिप्टो का पार-क्षेत्र और सीमा-पार प्रकृति असंगठित राष्ट्रीय दृष्टिकोणों की प्रभावशीलता को सीमित करता है। विभिन्न गतिविधियों, उत्पादों और हितधारकों का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली श्टाब्दावली विश्व स्तर पर सुसंगत नहीं है। 'क्रिप्टो आस्तियां' शब्द स्वयं ही डिजिटल उत्पादों के एक व्यापक विस्तार को संदर्भित करता है, जिसे उनके वास्तविक या भावी उपयोग के आधार पर कई घरेलू नियामकों के ध्यान की आवश्यकता हो सकती है। क्रिप्टों उपयोगकर्ताओं की एक श्रखंला है, जैसे कि माइनर, वैलिडेटर्स और प्रोटोकॉल डेवलपर्स, जो पारंपरिक वित्तीय विनियमन (नरैन और मोरेटी, 2022) द्वारा आसानी से कवर नहीं किए जा सकते हैं। गैर-समर्थित क्रिप्टो आस्तियों को विनियमित करने का प्रयास करने वाले देखों और न्यायालयों के कुछ मामलों के अध्ययन पर नीचे चर्चा की गई है:

* यूरोपीय संघ: यूरोपीय संघ की डिजिटल वित्त रणनीति में क्रिप्टो आस्तियों (एमआईसीए) में बाजारों को विनियमित करना शमिल है। यहां तक कि अन्य क्रिप्टो आस्तियों और एक्सचेंजों तथा वॉलेट प्रदाताओं जैसे महत्वपूर्ण कार्यो को वितरित करने वाली प्रमुख संस्थाओं के लिए स्थिर मुद्रा पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, एमआईसीए ऑनशोरिंग, अधिसूचना और लाइसेंस देने की व्यवस्था का प्रस्ताव करता है।

* जापान: जापान वित्तीय सेवा एजेंसी ने अप्रैल 2017 में क्रिप्टो आस्तियां सेवा प्रदाताओं के विनियमन की शुरुआत की, जिसमें ग्राहकों की आस्तियों का पृथक्करण, संचालन जोखिम और साइबर सुरक्षा प्रबंधन, अपने ग्राहक को जानें, आंतरिक ऑडिट और न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं अनिवार्य हैं। यह भुगतान सेवा अधि नियम में संशोधन करके लागू किया गया था। मई 2019 और जून 2020 में कानून में और संशोधन किए गए ताकि क्रिप्टो विनियमन को अन्य संस्थाओं तक बढ़ाया जा सके, जैसे कि वॉलेट सेवा प्रदाता, क्रिप्टो आस्तियां एक्सचेंजों द्वारा खुदरा ग्राहकों को प्रदान किए गए लाभ को सीमित करना, और क्रमशः सुरक्षा टोकन और स्थिर मुद्रा के लिए नियम पेश करना।

जून 2022 में भुगतान सेवा अधिनियम आदि में आंशिक संशोधन के लिए कानून अधिनियमित किया गया था। ताकि एक स्थिर और कुशल निधि निपटान प्रणाली स्थापित किया जा सके और स्थिर सिक्कों के विनियमन के लिए प्रदान किया जा सके।

*स्विट्जरलैंड: स्विसफाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी (एफआईएनएमए) ने फरवरी 2018 में प्रारंभिक सिक्के की पेशकश के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। टोकन की तीन श्रेणियां पेश की गईं: भुगतान टोकन, उपयोगिता टोकन, और आस्तियां टोकन (एक स्पष्टीकरण के साथ कि पूर्व वित्तपोषण पर व्यापार योग्य टोकन और पूर्व बिक्री चरण को प्रतिभूतियों के रूप में माना जा सकता है)। इसके बाद, जून 2018 में वित्तीय सेवा अधि नियम ने सभी प्रतिभूतियों (आस्तियां टोकन सहित) में विवरणिका की आवश्यकताओं को सुसंगत बनाया। फरवरी 2021 में वितरित खाता प्रौद्योगिकी (डीएलटी) ने विभिन्न नागरिक और वित्तीय बाजार कानूनों में संशोधन किया

ताकि ब्लॉकचेन पर खाता-आधारित प्रतिभूतियों की शुरूआत को सक्षम किया जा सके और क्रिप्टो धारितों के दिवालिया होने की स्थिति में क्रिप्टो आस्तियों के पृथक्करण के लिए नियम प्रदान करें।

* यूनाइटेड किंगडम: जून 2019 में 'ाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी द्वारा 'क्रिप्टो आस्तियों पर अंतिम मार्गदर्शन' घोषित किया गया कि सुरक्षा टोकन ('निर्दिष्ट निवेश' के समान अधिकारों और दायित्वों के साथ क्रिप्टो आस्तियों) विनियामक दायरे में आते हैं, उपयोगिता और ''एक्सचेंज टोकन'' (अर्थात अनबैक्ड क्रिप्टो आस्तियां) विवेकपूर्ण और आचरण व्यवस्था के बाहर थे। क्रिप्टो आस्तियां बाजार पर महत्वपूर्ण उपभोक्ता अनुसंधान के बाद, अप्रैल 2022 में यूके ट्रेजरी ने क्रिप्टो आस्तियां विनियमन के लिए अपना रोडमैप तैयार किया है, जिसमें स्थिर मुद्रा पर ध्यान केंद्रित किया गया और ब्लॉकचौन-आधारित एफएमआई के लिए सैंडबॉक्स व्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया। क्रिप्टो आस्तियों के प्रचार-प्रसार को विनियमित करने के संबंध में, 2018 में यूके क्रिप्टो एसेट्स टास्कफोर्स[8] ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया जिसमें पाया गया कि भ्रामक विज्ञापन (लाभों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना और शायद ही कभी खुदरा निवेशकों को अस्थिरता और जोखिमों की चेतावनी देना) और उपयुत्त जानकारी की कमी क्रिप्टो- आस्तियां बाजारों में महत्वपूर्ण उपभोत्ता संरक्षण के मुद्दे थे। जनवरी 2022 में, यूके ट्रेजरी ने क्रिप्टो आस्तियों को अपने वित्तीय प्रचार व्यवस्था के भीतर लाने का प्रस्ताव दिया, क्रिप्टो आस्तियों के प्रचार को स्टॉक, शेयर और बीमा उत्पादों जैसे अन्य वित्तीय प्रचारों के समान उच्च मानकों के अध्यधीन किया है। इसी तरह, जनवरी 2022 सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने में सिंगापुर में क्रिप्टो आस्तियों के विपणन को प्रतिबंधित करने के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए, क्रिप्टो आस्तियों के प्रचार को कॉर्पोरेट वेबसाइट की एक इकाई, आधि कारिक सोशल मीडिया खातों और मोबाइल एप्लिकेशन तक सीमित कर दिया।

* अल्बानिया: मई 2020 में अल्बानिया में निवेश उद्देश्यों के लिए 'डीएलटी-आधारित वित्तीय बाजार' (जिसे ''फिनटोकन एक्ट'' भी कहा जाता है) पर अल्बानिया का कानून क्रिप्टो आस्तियों को वैध करता है। विनियमन में डिजिटल टोकन और आभासी मुद्रा जारी करना और वितरण, व्यापार और संरक्षण में लगी संस्थाओं की लाइसेंसिंग, निगरानी और पर्यवेक्षण ष्शामिल है। अल्बानियाई वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण (एएफएसए) और नेशनल एजेंसीफॉर इंफॉर्मेशन सोसाइटी (एनएआईएस) को अनबैक्ड क्रिप्टो एसेट्स (और बैंक ऑफ अल्बानियाफॉर स्टैब्लॉक्स) के लिए सक्षम प्राधिकारियों के रूप में सौंपा गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि क्रिप्टो आस्तियां सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस देना तीसरे पक्ष के एजेंटों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जब एनएआईएस द्वारा तकनीकी अनुपालन से निपटने के दौरान 'अभिनव सेवा प्रदाता' के रूप में एएफएसए द्वारा विनियामक और वित्तीय अनुपालन पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'डिजिटल टोकन एजेंट' के रूप में लाइसेंस दिया जाता है।

* नाइजीरिया:फरवरी 2018 में सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया (सीबीएन) ने घोषित किया कि क्रिप्टो आस्तियां नाइजीरिया में कानूनी निविदा नहीं हैं। इसके अलावा,फरवरी 2021 में, सीबीएन ने विनियमित वित्तीय संस्थानों को लिखा है कि क्रिप्टो आस्तियों में व्यवहार करना और क्रिप्टो आस्तियां सेवा प्रदाताओं के लिए भुगतान की सुविधा प्रतिबंधित थी। अभी हाल ही में, मई 2022 में प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने 'डिजिटल आस्तियों की पेशकश करने वाले प्लेटफॉर्म" और 'डिजिटल आस्तियों की पेशकश करने वाले धारक' पर मांग को लागू करने और एसईसी के दायरे में 'डिजिटल आस्तियां पेशकश' को रेखांकित करते हुए और "डिजिटल आस्तियों के परिणाम, पेशकश प्लैटफॉर्म और धारक पर नए नियम" प्रकाशित किया है।

एफएटीएफ द्वारा निर्धारित क्रिप्टो आस्तियों के प्रदाताओं के लिए एएमएल/सीएफटी दायित्वों के माध्यम से कुछ प्रगति के बावजूद उनका कार्यान्वयन अभी भी प्रगति पर है (एफएटीएफ 2021)[9], 'यात्रा नियम' जैसे समीक्षात्मक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विलंब के साथ, आभासी आस्तियां (वीए) और आभासी आस्तियां सेवा प्रदाताओं (वीएएसपी) क्षेत्र को आपराधिक और आतंकवादी दुरुपयोग[10] के लिए असुरक्षित छोड़ देता है। मार्च

2022 तक, जबकि 98 में से 29 उत्तर देने वाले न्यायालयों ने यात्रा नियम कानून पारित होने की सूचना दी, केवल 11 न्यायालयों ने प्रवर्तन और पर्यवेक्षी उपाय शुरू किए हैं। इसलिए, वैश्विक मानकों को व्यापक और सुसंगत होने की आवश्यकता है; विनियामक प्रतिक्रियाएं मानक वर्गीकरण पर आधारित होनी चाहिए, स्पर्श संचार प्रभावों को दूर करने के लिए विश्वसनीय डेटा, और भविष्य में बाजार के विकास और भविष्य के अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर समायोजित करने के लिए पर्याप्त लचीला होना चाहिए।

आईएफएससी - जीआईएफटी सिटी

4.50: पिछले कुछ वर्षों में, सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों ने पूंजी बाजार के खिलाड़ियों के लिए नए रास्ते और अवसर खोले हैं। जीआईएफटी सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) की स्थापना और संचालन सबसे महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के एक मजबूत आधार के विकास को गति देकर भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने की सुविधा प्रदान करना है। नीचे दिया गया बॉक्स 2 प्रमुख भूमिका पर चर्चा करता है जो आईएफएससी भारत के विकास को और बढ़ावा देने के लिए पूंजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए एक पसंदीदा क्षेत्राधिकार के रूप में भारत के उद्भव को सुविधाजनक बनाने और विदेशी निवेशकों से आसान पहुंच और अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने में निभा सकता है।

बॉक्स 2: जीआईएफटी आईएफएससी - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए एक मुख्य अधिकार क्षेत्र के रूप में उभरना

विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों (आईएफसी) ने मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं के पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुखता ग्रहण की है क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन के विकास में वृहद पैमाने योगदान दिया है। इन केंद्रों ने वित्तीय वैश्वीकरण की गति को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आम बोलचाल में, एक आईएफसी वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों, स्टॉक मार्केट्स और संबंधित संस्थाओं, बीमाफर्मो,फंड मैनेजरों, फिनटेक फर्मों आदि के उच्च संकेंद्रण के साथ एक अधिकार क्षेत्र है, जो गैर-निवासियों और निवासियों को, ऐसे माहौल में जो वित्तीय नवाचार और सीमा पार लेनदेन की सुविधायुत्त विशेष वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं।

इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, जीआईएफटी सिटी में भारत के पहले आईएफएससी की स्थापना और संचालन एक पथ-प्रवर्तक वित्तीय सुधार रहा है, जो पूंजी खाता परिवर्तनीयता के प्रति भारत के तेजी से उदार दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। जीआईएफटी-आईएफएससी विश्व स्तरीय वाणिज्यिक, सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के साथ भारत के पहले पूरी तरह से संचालित स्मार्ट सिटी है। आईएफएससी के विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 2019 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से आईएफएससी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के लिए अपनी तरह का पहला, एकीकृत और चुस्त वित्तीय क्षेत्र नियामक स्थापित करने के लिए एक प्रमुख नीतिगत निर्णय लिया। दिनांक 1 अक्तूबर 2020 से, जहां तक भारत में आईएफएससी के विकास और विनियमन का संबंध है, आईएफएससीए ने चार घरेलू क्षेत्र के नियामकों, अर्थात् आरबीआई, सेबी,आईआरडीएआई और पीएफआरडीएआई की शक्ति ग्रहण की।

पिछले दो वर्षों में, जीआईएफटी-आईएफएससी ने बैंकिंग, पूंजी बाजार, बीमा,फंड प्रबंधन, विमान पट्टे पर देने आदि सहित वित्तीय सेवाओं के पूरे विस्तार में अतिबष्टहत वृद्धि और संकर्षण के साथ एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरेखित नियामक व्यवस्था, प्रतिस्पर्धी कर संरचना और संचालन की लाभकारी लागत के साथ जीआईएफटी-आईएफएससी अब अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए एक पसंदीदा क्षेत्राधिकार के रूप में उभर रहा है। आईएफएससी के बढ़ते महत्व को स्वीकार करते हुए, वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक, लंदन रिपोर्ट (मार्च 2022) ने जीआईएफटी सिटी में आईएफएससी को विश्व स्तर पर 15 केंद्रों में शीर्ष पर रखा है, जिसके अगले 2 से 3 वर्षों में और अधिक महत्वपूर्ण होने की संभावना है।

जीआईएफटी-आईएफएससी में बैंक, पूंजी बाजार, बीमा, फिनटेक, एयरक्राफ्ट लीजिंग, शर्रफा बाजार आदि सहित वित्तीय सेवाओं के पूर्ण विस्तार में 390+ से अधिक संस्थाएं पंजीकृत हैं। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वित्तीय संस्थानों की स्वस्थ और बढ़ती भागीदारी के साथ वित्तीय सेवा बाजार तेजी से बढ़ रहा है।

हाल के विकास/उपलब्धियाँ/नवाचार/अन्य देशों के साथ सहयोग

वैश्विक महत्ता का एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनने की अपनी दृष्टि के अनुसरण में आईएफएससीए कई विश्व स्तर पर प्रमुख वित्तीय प्राधिकरणों और मानक-निर्धारण निकायों के साथ लगातार विचार-विमर्श में लगा हुआ है। अभी तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईएफएससीए द्वारा विदेशी नियामकों के साथ सहयोग को गहरा करने और जीआईएफटी-आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए सूचनाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान में सहायता के लिए 2 बहुपक्षीय समझौता ज्ञापनों (एमएमओयू) और 7 द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों (बीएमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। नीचे दी गई तालिका केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित समझौता ज्ञापनों की नवीनतम स्थिति प्रदान करती है-

बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमएमओयू)

- प्रतिभूति आयोगों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ)
- बीमा पर्यवेक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईएआईएस)

द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (बीएमओयू)

- दुबई वित्तीय सेवा प्राधिकरण (डीएफएसए)
- कतर वित्तीय सेवा प्राधिकरण (क्यूएफसीए)
- अबू धाबी ग्लोबल मार्केट (एडीजीएम) वित्तीय सेवा नियामक प्राधिकरण (एफएसआरए)
- फ्रांस के ऑटोराइट डेस मार्च फाइनेंसर्स (एएमएफ)
- कमीशन डी सर्विलांस डू सेक्टर फाइनेंसर (सीएसएसएफ) लक्समबर्ग
- फिनान्सिन्सपेक्टिओन (एफआई) स्वीडन।
- सिंगापुर का मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस)

उपरोक्त के अलावा, आईएफएससीए ने आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं के लिए विश्व स्तरीय नियामक वातावरण के विकास के लिए तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण के लिए समझौते भी किए हैं। वैश्विक समुदाय के साथ आईएफएससीए के बढ़ते जुड़ाव को दर्शाने वाली कुछ परियोजनाएँ/समझौते पर नीचे प्रकाश डाला गया है:

सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ फिनटेक ब्रिज

भारत और सिंगापुर दोनों फिनटेक क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। फिनटेक विकास के अगले चरण को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार जीआईएफटी-आईएफएससी को सभी फिनटेक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने एक संयुक्त नियामक सैंडबॉक्स सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक में नियामक सहयोग और साझेदारी की सुविधा के लिए फिनटेक सहयोग समझौते (सीए) पर हस्ताक्षर किए हैं जो प्रौद्योगिकी नवाचारों के प्रयोग का समर्थन करने के लिए अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में मौजूदा नियामक सैंडबॉक्स का लाभ उठाएगा। यह समझौता फिनटेकफर्मों को एक क्षेत्राधिकार से दूसरे क्षेत्राधिकार में एक नियामक रेफरल प्रणाली के माध्यम से बाजार पहुंच प्राप्त करने में सक्षम करेगा।

एनएसई आईएफएससी -एसजीएक्स कनेक्ट

एनएसई–आईएफएससी – एसजीएक्स कनेक्ट, जिसका 29 जुलाई, 2022 को प्रधान मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया, पूंजी बाजार के क्षेत्र में भारत और सिंगापुर के बीच सीमा पार सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कनेक्ट को, जून, 2023 तक पूरी तरह से चालू करने की संभावना है, एसजीएक्स, सिंगापुर से एनएसई–आईएफएससी, जीआईएफटी सिटी के लिए निफ्टी उत्पादों में ऑनशोरिंग डेरिवेटिव ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कनेक्ट से जीआईएफटी आईएफएससी में डेरिवेटिव उपकरणों में मात्रा को मजबूत करने और नकदी को गहरा करने, अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों को लाने और जीआईएफटी–आईएफएससी में अन्य वित्तीय पारिस्थितिक तंत्रों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की संभावना है। इसे संबंधित एक्सचेंजों के लाभों का उपयोग करने के लिए, निवेशकों तक आसानी से पहुंच के लिए एसजीएक्स और सभी को लाभ प्रदान करने के लिए सहजीवी तरीके से व्युत्पन्न अनुबंधों के व्यापार तथा समाशोधन के लिए एनएसई आईएफएससी को डिजाइन किया गया है ।

विश्व स्तर पर फिनटेक के बीच सदृश्यता और मन की बात

जीआईएफटी–आईएफएससी में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और वैश्विक फिनटेक समुदाय के बीच दृश्यता बनाने के लिए, आईएफएससीए ने भारत सरकार के समर्थन से, 2021 से शुरू होने वाली वार्षिक विशेषता के रूप में एक प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी और वैश्विक विचार नेतृत्व कार्यक्रम, 'इन्फिनिटीफोरम' की स्थापना की है। यह चर्चा करने और कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी में दुनिया के अग्रणी दिमाग को एकजुट करता है कि कैसे फिनटेक उद्योग समावेशी विकास के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठा सकता है। 3 और 4 दिसंबर 2021 को आयोजितफोरम के पहले संस्करण का उद्घाटन प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था, जिसमें इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम भागीदार देशों के रूप में भाग ले रहे थे। इस आयोजन में कुल 94,300 पंजीकरण हुए, जिसने एक बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय पदचिह्न को पीछे छोड़ दिया।

इंडिया आईएनएक्स और लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच सहयोग समझौता

01 जून, 2022 को आईएफएससी–आधारित एक्सचेंज इंडिया आईएनएक्स ने लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोनों एक्सचेंज एलयूएक्सएसई पर सूचीबद्ध ऐसी प्रतिभूतियों के प्रवेश की सुविधा देकर अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के प्रति सूचीबद्ध भारतीय प्रतिभूतियों की दृश्यता बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नवंबर 2020 में यह समझौता दोनों संस्थानों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पर आधारित है, जो भारत में हरित वित्त को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। इंडिया आईएनएक्स और एलयूएक्सएसई के बीच इस दोहरी सूचीबद्ध सहयोग समझौते के साथ स्थापित ग्रीन कॉरिडोर अवसर भारती और उसके क्षेत्र से अधिक जारीकर्ताओं को आकर्षित करने और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से हरित पूंजी तक पहुंच प्रदान करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

वित्तीय वर्ष 2024 और उसके बाद के लिए आईएफएससीए विजन

वित्त वर्ष 2023 आईएफएससी के लिए एक ऐतिहासिक घटना वर्ष है। यह भारत को प्रथम आईएफएससी दशक को चिह्नित करता है। 2022 से आगे की दृष्टि योजना जीआईएफटी–आईएफएससी को नए युग की वैश्विक वित्तीय सेवाओं और गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में एक गुणी आत्मनिर्भर प्रक्षेपवक्र तक बढ़ाने के इर्द–गिर्द घूमती है। वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने की यह महत्वाकांक्षी खोज सीखने में समृद्ध रही है जिसे केंद्र को वित्तीय नवाचार और गतिशीलता की उच्च क्षेत्र में ले जाने के लिए अत्याधुनिक वैधानिक और नियामक ढांचे को डिजाइन करने

के लिए व्यवस्थित रूप से पूंजीकृत किया जा रहा है। जीआईएफटी-आईएफएससी अपनी स्थापना वर्षों के भीतर भारत में वैश्विक पूंजी के प्रवाह के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार बन गया है। शर्राफा व्यापार, एयरक्राफ्ट और शिप लीजिंग, ग्लोबल-इन हाउस सेंटर्स, फिनटेक, सस्टेनेबलफाइनेंसिंग और पार देश बिल डिस्काउंटिंग औरफैक्टरी निर्माण जैसी प्रायोगिक और अभिनव वित्तीय सेवाओं को शुरू करने में महत्वपूर्ण लाभ हुआ है।

परिशकृत वित्तीय उत्पाद जैसे शर्राफा डिपॉजिटरी रसीदें, अप्रयोजित डिपॉजिटरी रसीदें, और वित्तीय और परिचालन पट्टे पेश किए गए हैं, और भी कई कतार में हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी, एकीकृत आवासीय परियोजनाओं, सेंट्रल पार्क, रिवरफ्रंट और मनोरंजक केंद्रों सहित आवश्यक परियोजनाओं के साथ जीवन की संपूर्ण गुणवत्ता के लिए अत्याधुनिक अवसंरचनाएं तैयार की गई है।

घरेलू विनियमों से मुत्त आईएफएससी में छूट देकर विदेशी विश्वविद्यालयों को संचालन स्थापित करने की अनुमति देकर एक संपन्न ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने की नींव रखी गई है। इसके साथ ही, जीआईएफटी सिटी में भारत के प्रमुख फिनटेक संस्थान और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए बाहरी सहायता जुटाई जाती है। केंद्र, ₹ 800 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ, फिनटेक में भारत के बढ़ते कद और नेतृत्व को मजबूत करेगा और विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करेगा।

गौरतलब है कि जीआईएफटी-आईएफएससी के लिए सरकार का दृष्टिकोण पारंपरिक वित्त और उद्यम से कहीं आगे बढ़कर वैचारिक नेतृत्व करता है। इसे सरलता और नवीनता के केंद्र, आत्म निर्भर भारत के अवतार के रूप में देश गया है। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, दृष्टिकोण के बारे में कल्पना में एक लंबी छलांग लगाता है और जीआईएफटी सिटी को एक हलचल भरे वित्तीय केंद्र में बदलने का प्रयास करता है, एक व्यवसायिक शहर जो एक विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय चरित्र रखता है और वित्त से जुड़ी जटिल समस्या बयानों का अग्रणी समाधान है।

बीमा बाजार में विकास

वैश्विक स्तर पर बीमा बाजारों ने महामारी के प्रभाव पर काबू पाने में उल्लेखनीय लचीलेपन और लचीला निष्पादन किया है

4.51 बीमा, वित्तीय क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है, जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मृत्यु दर, संपत्ति और हताहत जोखिमों से सुरक्षा और सुरक्षा जाल प्रदान करने के अलावा, बीमा क्षेत्र बचत को प्रोत्साहित करता है और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालिक धन प्रदान करता है। इसके निरंतर आर्थिक परिवर्तन का समर्थन करने के लिए बीमा क्षेत्र का विकास आवश्यक है।

4.52 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बीमा क्षेत्र की क्षमता और प्रदर्शन का आकलन आम तौर पर दो मापदंडों के आधार पर किया जाता है, जैसे, बीमा प्रवेश, जो एक वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिए कुल बीमा प्रीमियम के अनुपात और 'बीमा घनत्व' को संदर्भित करता है, जो जनसंख्या के लिए बीमा प्रीमियम के अनुपात को संदर्भित करता है, अर्थात; प्रति व्यक्ति बीमा प्रीमियम और अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है, क्योंकि वे किसी देश में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर को दर्शाते हैं। 2021 में, कुल वैश्विक बीमा प्रीमियम में वास्तविक रूप से 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो विकसित बाजारों में वाणिज्यिक लाइनों में सख्त दर से प्रेरित थी। हालांकि, चीन में, सबसे बड़ा उभरता हुआ बाजार, गैर-जीवन

12 https://m.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=3619

प्रीमियम वॉल्यूम 0.7 प्रतिशत तक सिकुड़ गया क्योंकि मोटर बीमा के डी-टैरिफिकेशन[11] ने भयंकर प्रतिस्पर्धा और दर में कटौती को बढ़ावा दिया।

चित्र 25क: 2021 में जीवन-बीमा प्रीमियम की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन

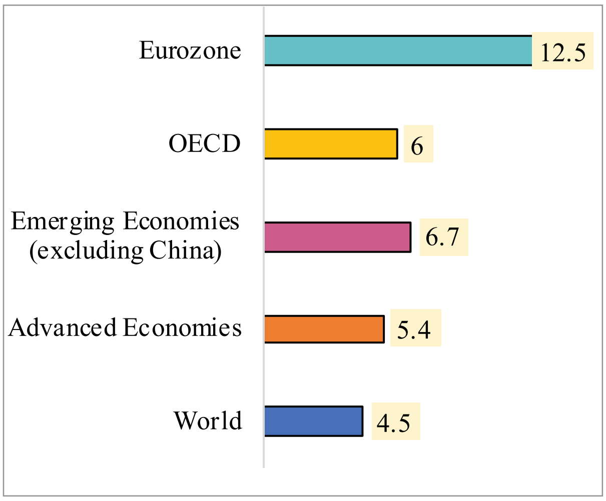

चित्र 25ख: 2021 में गैर-जीवन बीमा प्रीमियम की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन

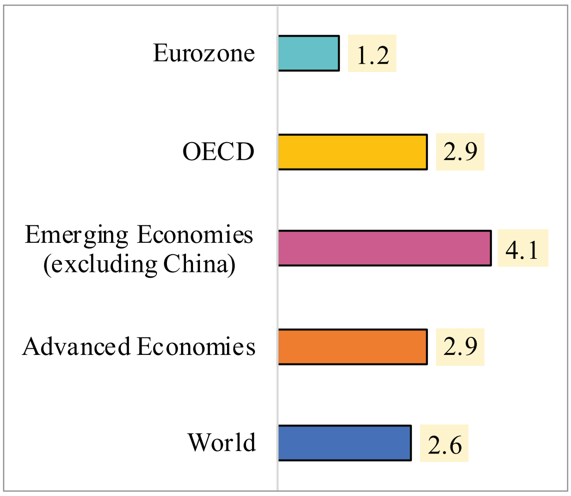

स्रोत: स्विस रे, सिग्मा विभिन्न मुद्दे

4.53 जीवन बीमा खंड में, वैश्विक प्रीमियम वृद्धि ने 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए जोरदार वापसी की। 2021 में यूएस + 2.8 ट्रिलियन के कुल प्रीमियम (गैर-जीवन और जीवन) के साथ अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बीमा बाजार बना रहा, इसके बाद चीन और जापान का स्थान रहा। विशेष रूप से यूरोप में यूक्रेन में संघर्ष आर्थिक विकास पर भार के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि उभरते हुए बाजारों में बीमा उद्योग की वृद्धि इस साल विकसित बाजारों से आगे निकल जाएगी, जिसमें उभरता हुआ एशिया प्रमुख होगा।

भारत आने वाले दशक में सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है

4.54: 2020 में सहस्राब्दी के मोड़ के आसपास भारत में बीमा प्रवेश 2.7 प्रतिशत से लगातार बढ़कर 4.2 प्रतिशत हो गई और 2021 में समान रही। 2021 में भारत में जीवन बीमा की प्रवेश 3.2 प्रतिशत थी, जो उभरते बाजारों से लगभग दोगुनी और वैश्विक औसत से थोड़ी अधिक थी। तथापि केवल एक छोटे से सुरक्षा घटक के साथ भारत में बेचे जाने वाले अधिकांश जीवन बीमा उत्पाद बचत से जुड़े होते हैं। इसलिए, प्राथमिक अर्जक की समय से पहले मष्ट्यु होने की स्थिति में परिवारों को एक महत्वपूर्ण वित्तीय अंतर का सामना करना पड़ता है। भारत में बीमा घनत्व 2001 में 11.1 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021 में 91 अमेरिकी डॉलर हो गया है (जीवन बीमा के लिए घनत्व 69 अमेरिकी डॉलर था और गैर-जीवन बीमा 2021 में 22 अमेरिकी डॉलर था)।

4.55 वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, गैर-जीवन बीमाकर्ताओं (भारत के भीतर और बाहर) के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम में 10.8 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई, जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य और मोटरफंड द्वारा संचालित है। वित्त वर्ष 2022, में गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का निवल दावा ₹ 1.4 लाख करोड़ था, जो मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति आय, उत्पाद नवाचारों और अनुकूलन, मजबूत वितरण चौनलों के विकास और बढ़ती वित्तीय साक्षरता से प्रेरित था। वित्त वर्ष 2022 में जीवन बीमा प्रीमियम में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें नए व्यवसायों

का योगदान जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त कुल प्रीमियम का 45.5 प्रतिशत था। जीवन बीमा उद्योग ने वित्त वर्ष 2022 में 5.02 लाख करोड़ रुपये का लाभ दिया, जिसमें से 8.3 प्रतिशत लाभ मृत्यु दावों पर थे।

चित्र 26क: बीमा प्रवेश में लगातार वृद्धि

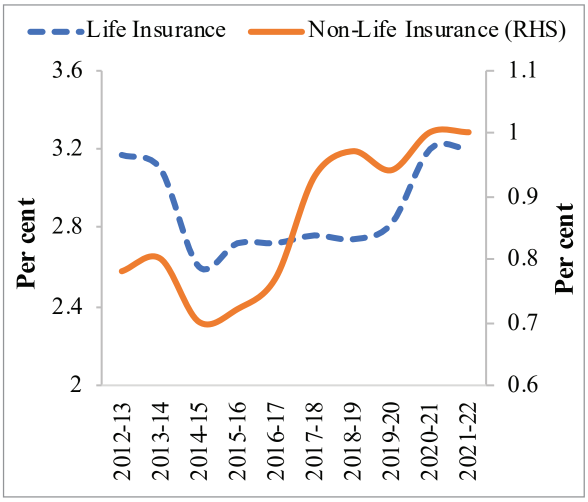

चित्र 26ख: बीमा घनत्व में दो अंकों की वृद्धि

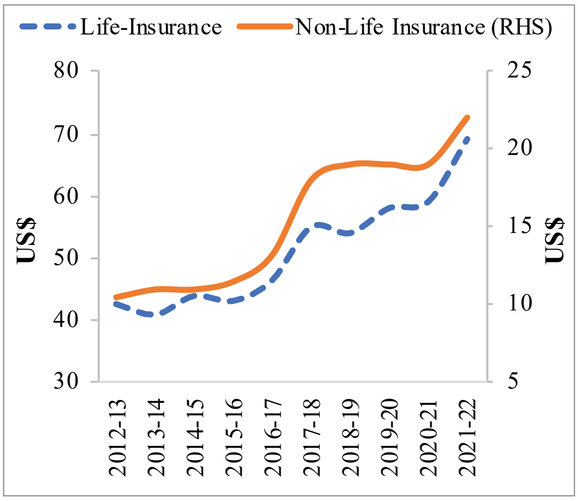

स्रोत: स्विस रे, सिग्मा विभिन्न मुद्दे

4.56 सार्वजनिक लिस्टिंग सार्वजनिक प्रकटीकरण, कॉर्पोरेट प्रशासन और मूल्यांकन में सुधार करती है। इस समझ के अनुरूप, भारत का सबसे बड़ा जीवन बीमाकर्ता, भारतीय जीवन बीमा निगम, मई 2022 में सार्वजनिक हुआ, जिसने देश के अब तक के सबसे बड़े आईपीओ में 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। निजि बीमा प्रदाता भी ऐसे अवसरों का लाभ उठा रहें है। देश में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कंपनी स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस को दिसंबर 2021 में सूचीबद्ध किया गया था, जिससे यह आईपीओ में निजी क्षेत्र की पांचवीं बीमा कंपनी बन गई। सार्वजनिक लिस्टिंग सार्वजनिक प्रकटीकरण, कॉर्पोरेट प्रशासन और मूल्यांकन[12] में सुधार करती है। बीमा क्षेत्र अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है और पहले से ही विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) गतिविधि देख रहा है क्योंकि बीमाकर्ताओं के पास अंतरिक्ष में सह-अस्तित्व के लिए जबरदस्त अवसर और मात्रा है। अतिरिक्त एफडीआई प्रवाह, आईपीओ, सरलीकृत नियम और विनियम और बेहतर कॉर्पोरेट मूल्यांकन से क्षेत्र में एम एंड ए गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। तेजी से परिपक्व हो रहे बीमा बाजार ने सरकार को बीमा कारोबार में अपनी हिस्सेदारी का निजीकरण करने का आकर्षक अवसर प्रदान किया है। तदनुसार, सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2021 केंद्र सरकार को एक निर्दिष्ट बीमाकर्ता में इक्विटी पूंजी के 51 प्रतिशत से कम हिस्सेदारी को कम करने की अनुमति देता है।

4.57 जनसंख्या के निम्न आयफंड को बीमा प्रवेश की सुविधा देने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015 जारी किया, जो ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए वहनीय बीमा उत्पादों के वितरण के लिए एक मंच प्रदान करता है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के लिए बीमाकर्ताओं की बाध्यताएं) विनियम, 2015 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में बीमाकर्ताओं के लिए दायित्वों को निर्धारित करता है और इसने भारत में सूक्ष्म-बीमा उत्पादों को विकसित करने और बढ़ावा देने में योगदान दिया है। वित्त वर्ष 2021 में, 10.7 लाख नई माइक्रो-बीमा पॉलिसी व्यक्तियों को ₹ 355.3 करोड़ (जीवन-बीमा खंड में) के नए व्यावसायिक प्रीमियम के साथ जारी की गई, और 53,046 नई माइक्रो-बीमा पॉलिसियाँ सामान्य बीमा खंड (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता को छोड़कर) में जारी की गई।

4.58 सरकारी योजनाओं और वित्तीय समावेशन की पहलों ने बीमा अपनाने और सभी क्षेत्रों में पैठ बनाने में मदद की है। फसल बीमा के लिए सरकार की प्रमुख पहल, प्रधानमंत्रीफसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) नेफसल बीमा के लिए प्रीमियम आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) (एबी पीएम-जेएवाई) का लक्ष्य माध्यमिक और तखतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹ 5 लाख का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। बीमा नियामक आईआरडीएआई ने बीमा पैठ बढ़ाने की दिखा में कई पहल की हैं, जैसे कि बीमाकर्ताओं को वीडियो-आधारित नो योर कस्टमर (केवाईसी) आयोजित करने की अनुमति देना, मानकीकृत बीमा उत्पादों को लॉन्च करना और बीमाकर्ताओं को कम जोखिम वाले व्यवहार के लिए पुरस्कार की पेशकश करने की अनुमति देना। महत्वपूर्ण सरकारी पहलें, मजबूत जनसांख्यिकीय कारक, एक अनुकूल नियामक वातावरण, एम एंड ए में वृद्धि, उत्पाद नवाचार और जीवंत वितरण चैनल बीमा बाजार के विकास का समर्थन कर रहे हैं।

विभिन्न सरकारी बीमा योजनाओं की सूची और अब तक हुई प्रगति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 16: सरकारी बीमा योजनाएं और प्रगति

योजना का नाम	संक्षिप्त विवरण	उपलब्धि
आयुष्मान भारत योजना	यह योजना चुनिंदा अभावों और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर पहचान किए गए गरीब और कमजोर परिवारों को प्रतिवर्ष प्रति लाभार्थी परिवार को ₹ 5 लाख का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है।	थापना के बाद से, 19.7 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए हैं, और 20 जनवरी, 2023 तक 13,115 निजी अस्पतालों सहित 28,667 सूचीबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से ₹ 4.3 करोड़ से अधिक असपताल में ₹ 0.49 लाख करोड़ मूल्य से अधिक को प्रवेश के लिए अधिकृत किया गया है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	इस योजना के तहत, लाभार्थियों को आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए ₹ 2 लाख और आंशिक विकलांगता के लिए ₹ 1 लाख का जोखिम कवरेज दिया जाता है।	इसकी स्थापना के बाद से, 31.3 करोड़ लाभार्थियों को योजना के तहत नामांकित किया गया है, और 30 नवंबर 2022 तक 1.07 लाख दावों का वितरण किया गया है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	योजना के तहत, बीमाधारक की मृत्यु के मामले में धारक के बचत बैंक खाते में ₹ 2 लाख का जोखिम कवरेज जमा किया जाता है।	इसकी स्थापना के बाद से, 14.4 करोड़ लाभार्थियों को योजना के तहत नामांकित किया गया है, और 30 नवंबर 2022 तक 6.3 लाख दावों का वितरण किया गया है।

प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना	इस योजना के तहत, एलआईसी को सरकारी गारंटी के आधार पर सदस्यता राशि से जुड़ी सुनिश्चित पेंशन/वापसी के प्रावधान के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान की जाती है।	30 सितंबर 2022 तक इन ग्राहकों द्वारा जमा की गई ₹ 84,659.4 करोड़ की सब्सक्रिप्शन राशि के साथ कुल 8.6 लाख सब्सक्राइबर इस योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं।
प्रधानमंत्रीफसल बीमा योजना	इस योजना के तहत, संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचितफसलों/क्षेत्रों के लिए पूर्व-बुवाई से लेकर कटाई के बाद के गैर-रोकथाम प्राकृतिक जोखिमों के कारण किसानों कोफसल क्षति के लिए जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है।	वर्ष 2016 और वर्ष 2022 के दौरान, योजना के तहत 2763.9 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, और किसानों को लगभग 1.28 लाख करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है।

स्रोत: डीएफएस, पीआईबी, पीएमएफबीवाई

4.59 मुद्रास्फीति के दबाव, आर्थिक अनिश्चितता और मौद्रिक तंगी से चल रही महामारी के कारण पिछले साल की मजबूत रिकवरी के बाद वैश्विक जीवन प्रीमियम 2022 में थोड़ा कम होने की संभावना है। वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और प्रयोज्य आय में गिरावट के कारण बचत प्रीमियम में गिरावट की उम्मीद है। कोविड-19 के कारण बढ़ी हुई जोखिम जागरूकता जीवन सुरक्षा (और स्वास्थ्य) बीमा उत्पादों की मांग का समर्थन करना जारी रख सकती है।

4.60 स्विस रे इंस्टीट्यूट वर्ल्ड इंश्योरेंस: 'मुद्रास्फीति जोखिम सामने और केंद्र रिपोर्ट'[13] के अनुसार, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक है। कुल प्रीमियम मात्राओं में, यह वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर 10वां सबसे बड़ा था, जिसकी अनुमानित बाजार हिस्सेदारी 1.9 प्रतिशत थी और जो सभी उभरते बाजारों में दूसरा सबसे बड़ा था। जर्मनी, कनाडा, इटली और दक्षिण कोरिया से आगे, भारत के 2032 तक दुनिया के शीर्ष छह बीमा बाजारों में से एक के रूप में उभरने की उम्मीद है। इसके अलावा, गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में वृद्धि स्वास्थ्य कवरेज की मांग से प्रेरित होने की संभावना है, क्योंकि लोग कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में अधिक जागरूक हैं और सरकार द्वारा प्रायोजित जन स्वास्थ्य कार्यक्रम (आयुष्मान भारत) से मजबूत समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। अनिवार्य मोटर थर्ड-पार्टी बीमा कई गुना बढ़ जाएगा क्योंकि जैसे-जैसे भारत का मध्यम वर्ग बदला है और अधिक कारें खरीदता है।

4.61 भारत के बीमा बाजार का डिजिटलीकरण टेलीमैटिक्स और ग्राहक जोखिम मूल्यांकन से परे है। हाल के वर्षों में कई डिजिटल प्लेटफॉर्म उभरे हैं, जो बीमा खरीद सहित विभिन्न सेवाओं की पेशकश करते हैं। बीमा कंपनियों के लिए एफडीआई सीमा में वृद्धि के साथ-साथ इन उपायों से दीर्घकालिक पूंजी, वैश्विक प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रवाह में वृद्धि की संभावना है, जो भारत के बीमा क्षेत्र के विकास का समर्थन करेगा।

पेंशन क्षेत्र

कोविड-19 के दौरान भारत के पेंशन क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया

4.62 पेंशन प्रणाली का ढांचा विश्व स्तर पर विकसित हुआ है। उन्नत देशों में, पेंशन क्षेत्र पर्याप्त है, आंशिक रूप से औपचारिक वेतनभोगी रोजगार के एक बड़े हिस्से से उपजा है। जबकि राज्य कुछ मूल पेंशन प्रदान करता है, यह केवल कभी-कभी वित्त पोषित होता है और इस प्रकार पेंशन भुगतान के लिए वर्तमान सरकारी राजस्व

16 https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshtml?ID=2170

पर निर्भर उपयोगानुसार भुगतान करें वाली योजना है। वर्ष 2021 में, ओईसीडी देशों में पेंशन आस्तियां14 38.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो सकल घरेलु उत्पाद का 66.9 प्रतिशत थी। कुछ ओईसीडी देशों में, पेंशन आस्तियां सकल घरेलू उत्पाद के 100 प्रतिशत से अधिक थीं। यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बाद संयुत्त राज्य अमेरिका ने पेंशनफंड में सबसे बड़ी हिस्सेदारी दर्ज की। कोविड-19 के दौरान, देशों ने स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने, श्रम बाजारों पर संकट के प्रभाव को सीमित करने, आय का समर्थन करने और व्यापक आर्थिक नीतियों को समायोजित करने के लिए अभूतपूर्व और तेजी से स्वास्थ्य और पेंशन संबंधी सुधार15 किए।

4.63 दुनिया भर के देशों ने हाशिए पर पड़े, गरीब और कमजोर वर्गों पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए पेंशन क्षेत्र में सुधारों की एक श्रखंला शुरू की, जैसे नौकरी प्रतिधारण योजना (जेआरएस) के माध्यम से मजदूरी और पेंशन पात्रता में सब्सिडी देना, बेरोजगारी लाभों तक पहुंच को व्यापक बनाना, या श्रमिकों के नए समूहों को बेरोजगारी बीमा प्रदान करना। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वरोजगार के लिए बेरोजगारी लाभों के कवरेज का विस्तार किया और फिनलैंड ने स्वरोजगार के लिए पहले से मौजूद योजना के कवरेज को व्यापक बनाया। चिली ने श्रमिकों के लिए बेरोजगारी बीमा के कवरेज का स्थायी रूप से विस्तार किया। न्यूजीलैंड ने उन कर्मचारियों के लिए तीन महीने तक के लिए अस्थायी लाभ का भुगतान किया, जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी और स्व-नियोजित उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी गतिविधि बंद कर दी।

4.64 भारत सरकार ने कोविड के कारण अपने कमाने वाले सदस्यों को खोने वाले परिवारों को पेंशन प्रदान करने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की। इसने बीमा मुआवजे को बढ़ाने और उदार बनाने की दिशा में भी पहल की। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) पेंशन योजना का लाभ उन लोगों को भी दिया गया जिन्होंने कोविड-19 के कारण कमाने वाले सदस्यों को खो दिया है। ऐसे व्यक्तियों के आश्रित परिवार के सदस्य मौजूदा मानदंडों के अनुसार श्रमिक द्वारा प्राप्त औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत के बराबर पेंशन के हकदार थे। कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (ईडीएलआई) योजना के तहत बीमा लाभों को भी बढ़ाया और उदार बनाया गया।

4.65 अप्रैल-जून 2020 के दौरान तीन महीने के लिए लगभग तीन करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और आबादी के विकलांग वर्गों (60 वर्ष से अधिक आयु) को ₹ 1,000 की अनुग्रह राशि दी गई। सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 64, 1972, अभूतपूर्व महामारी के बीच पेंशन लाभों की तत्काल अनंतिम मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए ढील दी गई थी। केंद्र सरकार के सिविल पेंशन भोगियों के 'जीवनयापन की सुगमता' को बढ़ाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (ई-पीपीओ) को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया गया, जिससे डिजी लॉकर में एक स्थायी पीपीओ रिकॉर्ड बनाया गया। डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पेंशन भोगियों को डोरस्टेप सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा में छूट दी गई है।

4.66 भारत सरकार ने 4.7 करोड़ के कुल लाभार्थी कवरेज के साथ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत विभिन्न पेंशन योजनाओं जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडी पीएस) को लागू कर रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए उपयोगानुसार भुगतान करें (पे-एज-यू-गो) परिभाषित लाभ योजना के साथ प्राथमिक पेंशन प्रणाली के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को जनवरी 2004 में पेश किया गया था। सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस सरकार के सह-योगदान के साथ परिभाषित अंशदान योजना है। पेंशन कॉर्पस का मूल्य मार्क-टू-मार्केट है, और तदनुसार, वापसी की दर बाजार निर्धारित होती है। एनपीएस को वर्ष 2009 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (स्वैच्छिक आधार पर) सहित 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के सभी नागरिकों के लिए विस्तारित किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज के सभी वर्गों के लिए बचत का अवसर उपलब्ध है। पीएफआरडीए ने पीएसयू सहित कॉर्पोरेट संस्थाओं के कर्मचारियों को एनपीए, प्रदान करने के लिए वर्ष 2011 में 'एनपीएस-कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल' लॉन्च किया।

4.67 सरकार ने सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के व्यापक उद्देश्य के एक हिस्से के रूप में जून 2015 में एपीवाई की शुरुआत की। यह योजना 18–40 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, जिसमें वंचितों, असंगठित और निम्न–आय वाले व्यक्तियों पर जोर दिया जाता है। एनपीएस और हाल ही में, एपीवाई की शुरुआत के बाद से, भारत के पेंशन क्षेत्र का विस्तार हुआ है। एनपीएस और एपीवाई के तहत ग्राहकों की कुल संख्या ने नवंबर 2022 में 25.1 प्रतिशत की साल–दर–साल वृद्धि दर्ज की, इसी अवधि के दौरान एयूएम में 22.7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। समग्र योगदान में नवंबर 2022 में 27.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें अधिकतम वृद्धि कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा अपनाए गए ऑल–सिटिजन मॉडल द्वारा दर्ज की गई।

तालिका 17: भारत के पेंशन क्षेत्र का प्रदर्शन

	ग्राहक संख्या		साल दर साल	योगदान (करोड़)		साल दर साल	एयूएम (करोड़)		साल दर साल
सीजी+एसजी	Nov-21	Nov-22	प्रतिशत	Nov-21	Nov-22	प्रतिशत	Nov-21	Nov-22	प्रतिशत
कॉर्पोरेट+सभी नागरिक	77	83	8	3,93,690	4,89,855	24	5,55,932	6,67,255	20
एनपीएस लाइट	32	42	31	8,41,80	1,19,817	42	1,07,554	1,46,705	36
एपीवाई	325	429	32	16,877	22,437	33	19,352	24,829	28

स्रोत: पीएफआरडीए
सीजी का मतलब केंद्र सरकार और एसजी का मतलब राज्य सरकार है

4.68 वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2021 की पांच वर्ष की अवधि के लिए एनपीएस ग्राहकों (सभी नागरिक मॉडल) की सामाजिक–आर्थिक विशेषताओं पर पीएफआरडीए16 द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 24 प्रतिशत महिला ग्राहक थीं, शेष 76 प्रतिशत पुरुष ग्राहक थे। यह एपी वाई के मामले में बेहतर लिंग संतुलन के विपरीत है। एपी वाई के तहत महिला ग्राहक योजना के शुरुआती वर्षों में लगभग 38 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 202117 तक लगभग 44 प्रतिशत हो गई हैं। विभिन्न राज्यों में, महाराष्ट्र से नामांकन सबसे अधिक था, जो 17 प्रतिशत था। एपीवाई योजना में ग्राहकों की आयु प्रोफाइल कम उम्र में बढ़ते नामांकन का सुझाव देती है। अगस्त 2022 तक, 44.8 प्रतिशत ग्राहक 18 से 25 वर्ष के बीच थे, जबकि मार्च 2016 में यह 29.3 प्रतिशत था। इसके अलावा, अधिक लोग अब प्रति माह ₹ 1000 की पेंशन राशि का विकल्प चुन रहे हैं। मार्च 2022 तक, लगभग 76 प्रतिशत ग्राहकों ने [1000 प्रति माह पेंशन राशि का विकल्प चुना है, जबकि मार्च 201618 में यह संख्या 38 प्रतिशत थी। हालांकि, ₹ 5000 प्रति माह पेंशन का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों की संख्या मार्च 2016 में 47 प्रतिशत से घटकर मार्च 2022 तक 15 प्रतिशत हो गई है। कुल जनसंख्या के भाग के रूप में एनपीएस और एपीवाई के तहत पेंशन में जनसंख्या का कवरेज वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2022 तक के छह वर्षों के दौरान 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 3.7 प्रतिशत हो गया है। सकल घरेलु उत्पाद के अनुपात के रूप में आस्तियां 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गई है, यह दर्शाता है कि पेंशन क्षेत्र अर्थव्यवस्था और जनसंख्या की नाममात्र वृद्धि की तुलना में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है।

4.69 पीएफआरडीए ने ग्राहकों के लिए एनपीएस और एपीवाई की पहुँच को आसान बनाने के लिए निपटारे को संसाधित करने की समय–सीमा को घटाकर टी+2 करना जैसे कई उपाय किए हैं। सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों ने इलेक्ट्रॉनिक–पेंशन सेवानिवृत्ति खाता संख्या (ई–पीआरएएन), इलेक्ट्रॉनिक खाता विवरण और आधार और

डिजिलॉकर-आधारित खाता खोलने जैसी ग्राहक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिलॉकर के साथ अपनी प्रणालियों को एकीकृत किया है। सरकारी क्षेत्र के ग्राहक सीआरए लॉगइन में सीधे अनुरोध सबमिट करके अपने निवेश विकल्पों को ऑनलाइन बदल सकते हैं। एनपीएस ग्राहकों के लाभ के लिए यूपीआई हैंडल के माध्यम से योगदान स्वीकार किया जा सकता है, जिससे उन्हें सीआरए द्वारा प्रदान किए गए वर्चुअल अकाउंट नंबर के माध्यम से अपने पीआरएएन में धन भेजने की अनुमति मिलती है।

4.70 भारत के पेंशन क्षेत्र में विकास की जबरदस्त विषय-क्षेत्र है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में और वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि अर्थव्यवस्था एक उच्च-मध्यम-आय वाले देश में परिवर्तित हो रही है। भारत की जनसांख्यिकीय संरचना, युवा लोगों के अधिक महत्वपूर्ण अनुपात के साथ, संचय के एक चरण का समर्थन करती है। हालांकि, न केवल उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं बल्कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में भी वित्तीय साक्षरता एक महत्वपूर्ण चुनौती है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) के तत्वावधान में पीएफआरडीए, ने वित्तीय शिक्षा को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, ताकि उपभोक्ता सही निर्णय ले सकें और शामिल किए गए जोखिमों और विभिन्न व्यापार-नापसंदों के प्रति सचेत रहते हुए औपचारिक वित्तीय क्षेत्र का लाभ उठा सकें। इनमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पेंशन शिक्षा, व्यापार निकायों के माध्यम से आउटरीच कार्यक्रम, बैंक जैसे मध्यस्थ और टाउन हॉल कार्यक्रम शामिल हैं।

4.71 भारत का पेंशन क्षेत्र वेतनभोगी कर्मचारियों और आम व्यक्ति के लिए वृद्धावस्था आय-सुरक्षा का एक लचीला तरीका प्रदान करता है। हाल के पांच वर्षों में, वित्त वर्ष 2018 से वित्त वर्ष 2022 तक, ग्राहकों की संख्या तीन गुना से अधिक हो गई है, जिसमें एपीवाई, और एयूएम चार गुना से अधिक, एनपीएस में हुआ है। एनपीएस में भविष्य में विस्तार वेतनभोगी और स्वरोजगार दोनों, निजी क्षेत्र से निकलने की संभावना है। पेंशन योजना में शमिल होने के लिए, युवा वयस्कों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ नियामक और सरकार की ओर से प्रोत्साहन के साथ-साथ ग्राहकों और बिचौलियों दोनों के लिए बढ़ी हुई पेंशन साक्षरता की दिशा में कदम, पेंशनयुक्त समाज की दिशा में आंदोलन को गति प्रदान करेंगे।

दृष्टिकोण

4.72 घरेलू वित्तीय प्रणाली का लचीलापन बैंकों की स्वस्थ बैलेंस शीट, एनबीएफसी के मजबूत पूंजीगत स्तर और घरेलू म्यूचुअलफंड के एयूएम में मजबूत वृद्धि में परिलक्षित होता है। आस्ति की गुणवत्ता में सुधार, लाभप्रदता में वापसी और लचीला पूंजी और नकदी बफर्स से बैंक ऋण की प्रचंड मांग और निवेश चक्र में पुनरुद्धार के शुरुआती संकेत लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा, आईबीसी तंत्रफर्मों के लिए समयबद्ध प्रस्तावों के साथ आसान निकास की सुविधा देकर भारत में व्यापार करने में आसानी का समर्थन करना जारी रखता है। ये ताकतें चाहे बाहरी स्पिलओवर से, वैश्विक वित्तीय स्थितियों को सख्त करके और वित्तीय बाजारों में उच्च अस्थिरता से वित्तीय प्रणाली की मदद कर रही हैं

4.73 भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक है और 2032 तक शीर्ष छह बीमा बाजारों में से एक के रूप में उभरने की उम्मीद है। बीमा कंपनियों के लिए एफडीआई सीमा में वृद्धि के साथ भारत के बीमा बाजार का डिजिटलीकरण होने की संभावना है। दीर्घावधि पूंजी, एक वैश्विक प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के बढ़ते प्रवाह की सुविधा प्रदान करना, जो भारत के बीमा क्षेत्र के विकास का समर्थन करेगा। साथ ही, जब हम एक उच्च मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, भारत के पेंशन क्षेत्र में विकास की जबरदस्त गुंजाइश है। ग्राहकों और बिचौलियों की पेंशन साक्षरता बढ़ाने की दिशा में सरकार की पहल, और युवा वयस्कों को पेंशन योजना में शमिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नियामक और सरकार की ओर से समाज के अधिक व्यापक वर्ग के लिए पेंशन उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कीमतें और मुद्रास्फीतिः नाज़ुक परिस्थितियों पर कामयाबी

05

अध्याय

वर्ष 2022 में भारत में तीन चरण में उपभोक्ता मुद्रास्फीति हुई। इसके चरम तक पहुँचने का चरण अप्रैल 2022 तक था जब यह 7.8 प्रतिशत तक पहुँच गई थी, इसके बाद स्थिरता का चरण अगस्त 2022 तक था जब यह 7.0 प्रतिशत बनी रही फिर दिसंबर, 2022 तक इसमें कमी आई और यह लगभग 5.7 प्रतिशत तक पहुंच गई। इसमें वृद्धि का कारण रूस-यूक्रेन युद्ध के नतीजों और देश के कुछ भागों में अत्यधिक गर्मी के कारण फसल की कटाई में कमी थी। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किए गए त्वरित और पर्याप्त उपायों ने मुद्रास्फीति में वृद्धि पर लगाम लगाई है और इसे सेंट्रल बैंक की सहनशीलता सीमा के भीतर लाया है। इसके विपरीत, प्रमुख पश्चिमी देश जिन्हें महामारी के दौरान प्रोत्साहन प्रदान किया गया, वे मुद्रास्फीति के उच्च स्तर से जूझ रहे हैं।

मई, 2022 में अपेक्षाकृत उच्च थोक मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) मुद्रास्फीति और निम्न उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के बीच अंतर मुख्य रूप से दो सूचकांकों के सापेक्ष भार में अंतर और खुदरा कीमतों पर आयातित इनपुट लागत के विलंबन प्रभाव के कारण बढ़ा। हालांकि तब से मुद्रास्फीति के दो परिमाणों के बीच का अंतर कम हो गया है, जो अभिसरण की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति का महत्वपूर्ण उपाय - मुख्य मुद्रास्फीति - स्थिर बनी हुई है। भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के बीच खुदरा मुद्रास्फीति दरों में बड़ा अंतर रहा है।

नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) द्वारा प्रकाशित हाउसिंग प्राइस इंडेक्स (एचपीआई) के अनुसार, समाप्त तिमाही (क्यूई) सितंबर, 2021 की तुलना में सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही (क्यूई) में समग्र एचपीआई मूल्यांकन और एचपीआई बाजार मूल्य में समग्र वृद्धि आवास वित्त क्षेत्र में बहाली का संकेत देती है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने मई और दिसंबर, 2022 के बीच नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 225 आधार अंक बढ़ाकर 4.0 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत कर दिया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी, गेहूँ उत्पादों के निर्यात पर रोक, चावल पर निर्यात शुल्क लगाने, दालों पर आयात शुल्क में कमी और उपकर, खाद्य तेलों और तिलहन पर टैरिफ का युक्तिकरण और स्टॉक सीमा नियत करना, प्याज और दालों के लिए बफर स्टॉक बनाए रखना और विनिर्माण उत्पादों में प्रयुक्त कच्चे माल पर आयात शुल्क का युक्तिकरण जैसे राजकोषीय उपाय किए हैं।

आरबीआई ने आपूर्ति की कमी के कारण निकट अवधि में अनाज और मसालों की घरेलू कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाया है। उच्च फीड लागत को दर्शाते हुए दूध की कीमतों में भी वृद्धि की संभावना है। सामान्य तौर पर, दुनिया भर में जलवायु तेजी से अनिश्चित हो गई है, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि का जोखिम और बढ़ गया है। बहुत कुछ औद्योगिक इनपुट कीमतों पर निर्भर करता है: इनमें कमी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उपभोक्ता कीमतों में उनका लाभ पहुँचने में विलंब के कारण प्रमुख मुद्रास्फीति स्थिर रह सकती है।

सामान्य तौर पर, वर्ष 2022 को, तीन से चार दशकों के बाद आधुनिक विश्व में उच्च मुद्रास्फीति की वापसी के रूप में चिह्नित किया गया था। भारत में, सरकार और केंद्रीय बैंक ने कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाए। अप्रैल, 2022 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर 7.8 प्रतिशत पर पहुंच गई। भारत में मुद्रास्फीति का लक्ष्य सीमा से पार बढ़ना विश्व की तुलना में सबसे कम था। हमें विश्वास है कि यदि वर्ष 2023 में भारत में मुद्रास्फीति का दबाव फिर से उभरता है तो प्राधिकरण सतर्क रहेंगे और वर्ष 2022 की तरह ही सक्रिय रहेंगे।

परिचय

5.1 बढ़ती कीमतें हमेशा नीति निर्माताओं के लिए चिंता का कारण होती हैं क्योंकि वे आम आदमी को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के संकट अधिक महसूस किए जाते हैं, जहां विकसित देशों की तुलना में उपभोग विविधता में आवश्यकताओं का हिस्सा अधिक होता है। हाल के वर्षों में, भारत की मुद्रास्फीति की दर अच्छी रही है, जो 2017 से 2019 तक आरबीआई के लक्ष्य दर 4 प्रतिशत से काफी नीचे है।

5.2 वर्ष 2020 में, आपूर्ति–पक्ष की बाधाओं ने मुद्रास्फीति को आरबीआई की 6 प्रतिशत की ऊपरी छूट सीमा से परे पहुँचा दिया। महामारी ने आवश्यक वस्तुओं, भोजन, दवा और औद्योगिक सामानों के मामले में आपूर्ति–श्रृंखला की बाधाओं के माध्यम से मांग की तुलना में आपूर्ति को अधिक प्रभावित किया। परिणामतः, इसने देश में लागत–प्रेरित मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया।

5.3 जैसे–जैसे महामारी कम हुई, रूस–यूक्रेन में संघर्ष छिड़ गया, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ी, जो ज्यादातर कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण थी। कीमतें एक दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गई और घरेलू बजट को नुकसान पहुंचाया, जिसने केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति को सख्त करने के लिए प्रेरित किया। एक स्वस्थ विश्व अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति की अभूतपूर्व दरों का सामना करना पड़ा था। मुद्रास्फीति जनित मंदी का प्रभाव वैश्विक स्तर पर था। इसकी प्रतिक्रिया में, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के सम्मुख ब्याज दरें बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में वृद्धि करने से, अमेरिकी डॉलर में उछाल आया, जिसके कारण डॉलर–आधारित ईंधन आयात और भी महंगा हो गया।

5.4 विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा मुद्रास्फीति की दर को वर्ष 2021 में 3.1 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2022 में 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जो वर्ष 1982 के बाद सबसे अधिक है। सितंबर, 2022 में यूरो क्षेत्र में यह दर 10.0 प्रतिशत तक पहुंच गई (डबल्यूईओ, अक्टूबर 2022[1])। दिसंबर, 2022 में 6.5 प्रतिशत तक कम होने से पहले जून 2022 में अमेरिकी मुद्रास्फीति अपने 40 वर्षों के उच्च स्तर 9.1 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि यूके में दिसंबर, 2022 में 9.2 प्रतिशत की वार्षिक मूल्य वृद्धि देखी गई। जर्मनी में दिसंबर, 2022 में 8.6 प्रतिशत की मुद्रास्फीति देखी गई। उभरते बाजारों में, ब्राजील ने कीमतों के रुझान में कमी देखी, जबकि तुर्की की मुद्रास्फीति दिसंबर, 2022 में थोड़ी सी घटकर 64.3 प्रतिशत होने से पहले अगस्त से नवंबर, 2022 तक 80 प्रतिशत से ऊपर थी। युद्ध ने महामारी के बाद वस्तुओं और सेवाओं की मांग में मजबूत सुधार के प्रभावों को बढ़ा दिया था। उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में मुद्रास्फीति की दर वर्ष 2021 में 5.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022 में 9.9 प्रतिशत हो गई है (डब्ल्यूईओ, अक्टूबर 2022)।

1 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ), आईएमएफ, अक्टूबर 2022

चित्र V.1: कैलेंडर वर्ष 2022 में रिकॉर्ड उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

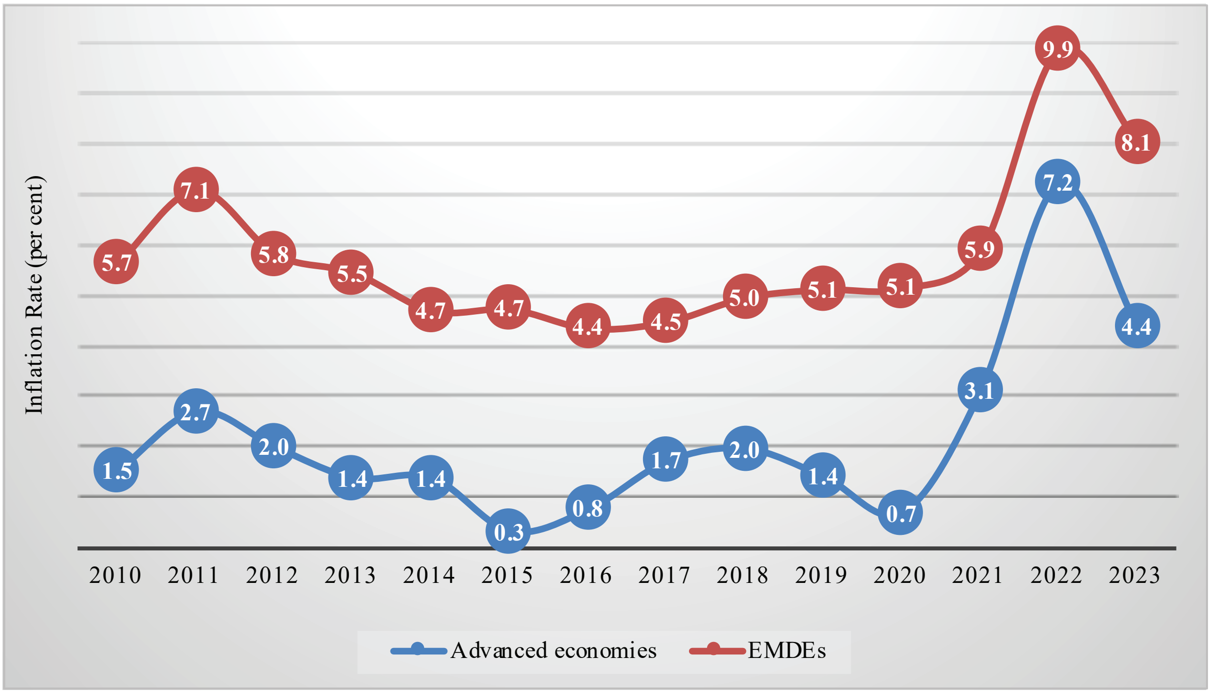

स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अक्टूबर 2022, आईएमएफ

नोट: *आंकड़े वार्षिक औसत हैं; वर्ष 2022 और 2023 के आंकड़े पूर्वानुमानित हैं।

आईएमएफ वर्गीकरण के अनुसार विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 40 अर्थव्यवस्थाएं और ईएमडीई में 156 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।

चित्र V.2: विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उच्च उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

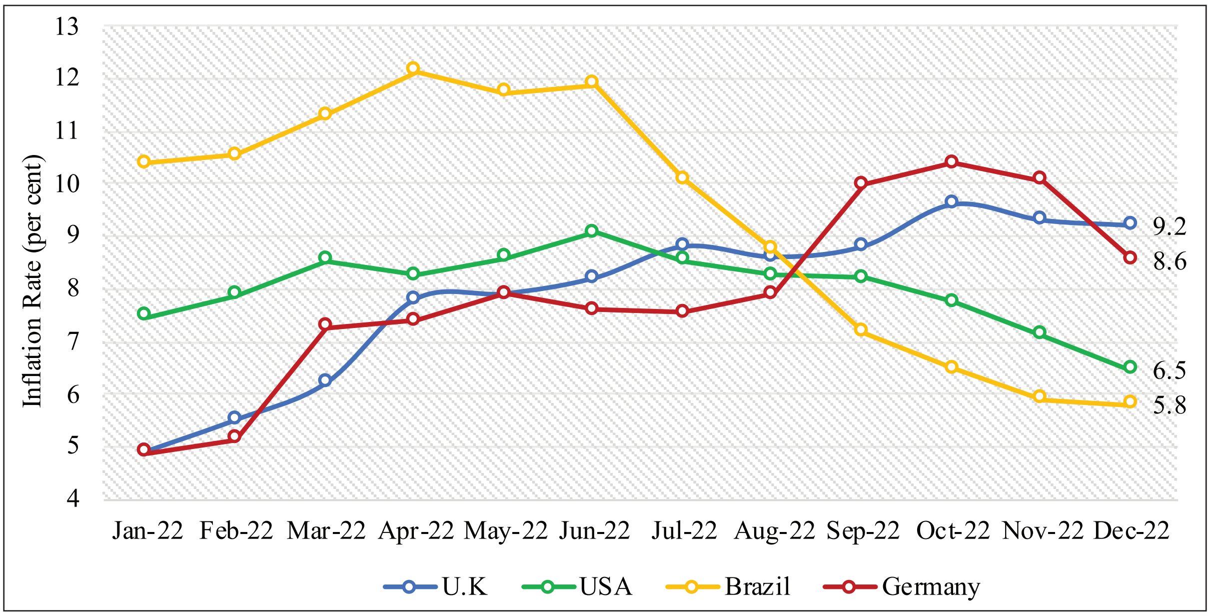

स्रोत: ओईसीडी

5.5 भारत में सराहनीय मुद्रास्फीति प्रबंधन के लिए नींव पहले ही रख दी गई थी क्योंकि महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए अपनाए गए राजकोषीय और मौद्रिक उपाय विवेकपूर्ण और अच्छी तरह से कैलिब्रेट किए गए थे। भारत ने अतिउत्साहित न होने का फैसला किया और इसीलिए रूस-यूक्रेन संघर्ष के

कारण मूल्य दबावों को नियंत्रित किया जा सकता था। गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और उसके बाद देश के कुछ हिस्सों में हुई असमान वर्षा ने कृषि क्षेत्र पर प्रभाव डाला, जिससे आपूर्ति कम हो गई और कुछ प्रमुख उत्पादों की कीमतें बढ़ गई। अच्छे मानसून के साथ-साथ पर्याप्त खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले त्वरित सरकारी उपायों के कारण दिसंबर, 2022 में 5.7 प्रतिशत तक कम होने से पहले भारत की मुद्रास्फीति की दर अप्रैल, 2022 में 7.8 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। वैश्विक आर्थिक मंदी और ब्याज दर में वृद्धि होने से वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है, जिससे थोक मूल्य मुद्रास्फीति में भारी गिरावट हुई है। इस प्रकार, भारतीय निर्माताओं पर इनपुट मूल्य दबाव कम हो गया है।

5.6 यहाँ तक कि थोक स्तर पर मुद्रास्फीति कम होने के बावजूद, खुदरा कीमतों पर पहले की उच्च इनपुट लागतों का प्रभाव पड़ा है। कोर मुद्रास्फीति लगभग 6 प्रतिशत पर बनी हुई है और इस वर्ष की शुरुआत में आए आपूर्ति संकटों के दूसरे दौर के प्रभावों को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, मांग में सुधार के साथ, सेवा मुद्रास्फीति में तेजी आई है। इस पृष्ठभूमि की तुलना में, हम वित्तीय वर्ष 22 और वित्तीय वर्ष 23 में खुदरा और थोक मूल्य मुद्रास्फीति के रुझानों और प्रेरकों, उपभोक्ता मुद्रास्फीति में राज्य-वार और ग्रामीण-शहरी अंतर, ईंधन मूल्य मुद्रास्फीति, सीपीआई और डबल्यूपीआई अभिसरण, आवासन की कीमतें, दवा मूल्य निर्धारण पर चर्चा करेंगे तथा अध्याय में आगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए वित्तीय और मौद्रिक नीति के उपायो के बारे में चर्चा करेंगे।

घरेलू खुदरा मुद्रास्फीति

प्रमुख मुद्रास्फीति अपनी चरम सीमा से घट गई

5.7 वित्त वर्ष 22 में वित्त वर्ष 21 की तुलना में सीपीआई-संयुक्त (सीपीआई-सी) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति कम देखी गई। फिर भी, महामारी से पहले के वर्षों के दौरान देखी गई कमी की तुलना में मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर रही। वित्त वर्ष 22 के दौरान, कुछ उप-समूहों जैसे 'तेल और वसा', 'ईंधन और बिजली' और 'परिवहन और संचार' में उच्च मुद्रास्फीति देखी गई थी। इसका मुख्य कारण महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान था। इसके बाद के वर्ष (वित्त वर्ष 23) की शुरुआत में रूस-यूक्रेन संकट आया, जिसके कारण अप्रैल, 2022 में प्रमुख मुद्रास्फीति की दर उच्च रही।

5.8 वित्त वर्ष 23 में, खुदरा मुद्रास्फीति मुख्य रूप से उच्च खाद्य मुद्रास्फीति द्वारा संचालित थी, जबकि कोर मुद्रास्फीति मध्यम स्तर पर रही। अप्रैल और दिसंबर, 2022 के बीच खाद्य मुद्रास्फीति 4.2 से 8.6 प्रतिशत के बीच रही, जबकि कोर मुद्रास्फीति दर अप्रैल, 2022 को छोड़कर लगभग 6 प्रतिशत पर रही।

सारणी V.1: सीपीआई-सी के आधार पर औसतन वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति (प्रतिशत) (आधार: 2012=100)

समूह/उप-समूह	भार	वित्त वर्ष 20	वित्त वर्ष 21	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 23*
खाद्य और पेय पदार्थ	**45.9**	**6.0**	**7.3**	**4.2**	**7.0**
अनाज और उत्पाद	9.7	2.8	3.8	0.5	9.3
मांस और मछली	3.6	9.3	15.4	7.9	4.7
अंडा	0.4	4.5	12.9	7.6	-1.0
दूध और उत्पाद	6.6	2.9	5.4	2.8	6.8
तेल और वसा	3.6	2.9	16.0	27.4	5.4
फल	2.9	0.7	2.6	6.2	4.4
सब्जियाँ	6.0	21.3	5.8	-7.2	7.6
दलहन और उत्पाद	2.4	9.9	16.4	6.0	1.8

	भार	वित्त वर्ष 20	वित्त वर्ष 21	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 23*
चीनी और कन्फेक्शनरी	1.4	0.8	2.5	2.3	2.7
मसालें	2.5	4.4	10.9	5.3	14.9
पान, तम्बाकू और नशीला पदार्थ	**2.4**	**4.2**	**9.9**	**4.5**	**2.0**
कपड़े और जूते	**6.5**	**1.6**	**3.4**	**7.2**	**9.7**
आवासन	**10.1**	**4.5**	**3.3**	**3.7**	**4.1**
ईंधन और बिजली	**6.8**	**1.3**	**2.7**	**11.3**	**10.5**
विविध	**28.3**	**4.4**	**6.6**	**6.7**	**6.3**
घरेलू सामान और सेवाएं	3.8	3.1	3.0	5.8	7.5
स्वास्थ्य	5.9	6.2	5.1	7.5	5.8
परिवहन और संचार	8.6	2.4	9.9	10.1	6.4
मनोरंजन और आमोद	1.7	4.9	5.1	6.5	6.4
शिक्षा	4.5	5.5	2.8	2.9	5.2
प्रमुख मुद्रास्फीति	***100.0***	***4.8***	***6.2***	***5.5***	***6.8***
मूल स्फीति	***47.3***	***4.0***	***5.5***	***6.0***	***6.1***
खाद्य मुद्रास्फीति	***39.1***	***6.7***	***7.7***	***3.8***	***7.0***

स्रोत: एमओएसपीआई,
टिप्पणी *अप्रैल-दिसंबर, दिसंबर, 2022 के लिए सीपीआई आंकड़े अनंतिम हैं

चित्र V.3: खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट

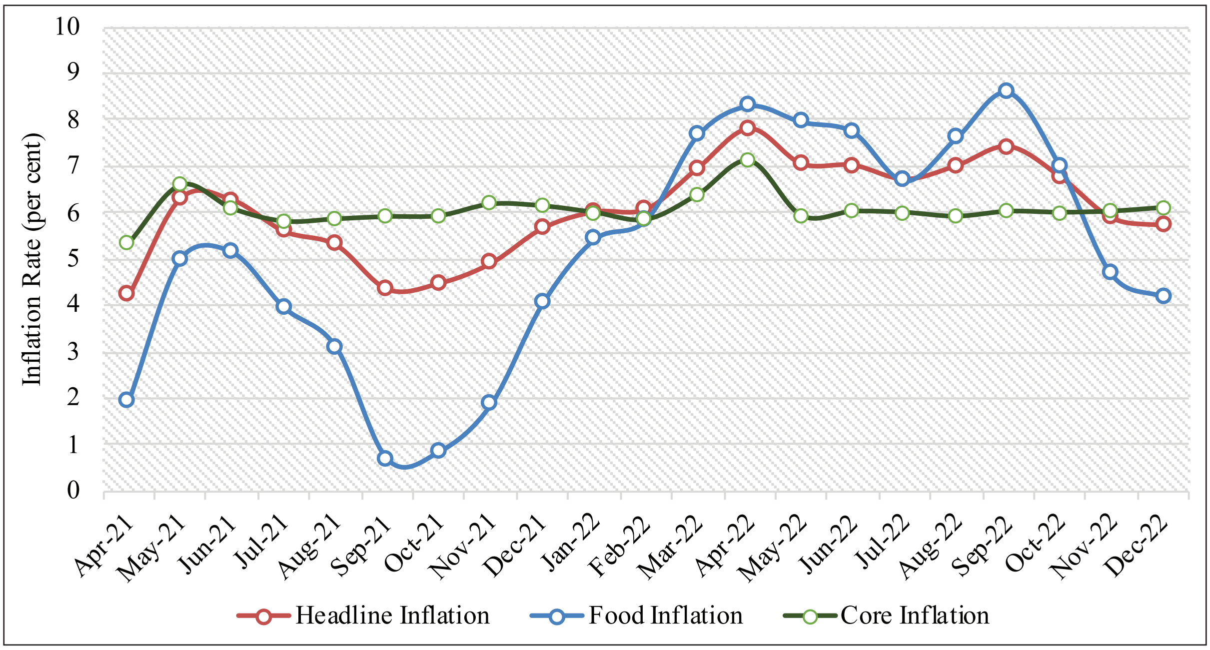

स्रोत: एमओएसपीआई

खाद्य-सामग्री द्वारा प्रेरित खुदरा मुद्रास्फीति

5.9 मुद्रास्फीति मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्र, आवास, कपड़ा और भेषज क्षेत्रों से उत्पन्न होती है, इसके अतिरिक्त आयातित मुद्रास्फीति चैनल का प्रतिनिधित्व करने वाले वैश्विक स्पिलओवर ऊर्जा, खनन, रसायन, व्यापार, बुनियादी और मशीनरी[2], खुदरा क्षेत्र में मुख्य रूप से थोक मूल्य मुद्रास्फीति के माध्यम से पहुँचता है, में कीमतों के दबाव से प्रेरित होते हैं। वित्त वर्ष 23 के दौरान, 'खाद्य और पेय पदार्थ', 'कपड़े और जूते', और 'ईंधन और बिजली' प्रमुख मुद्रास्फीति में मुख्य योगदानकर्ता थे– प्रथम दो प्रेरकों ने इस वित्तीय वर्ष में पिछले एक प्रेरक की तुलना में अधिक योगदान दिया।

5.10 'विविध' समूह के अंतर्गत, उप-समूहों 'घरेलू सामान और सेवाओं' और 'व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव' में उच्च मुद्रास्फीति देखी गई, जो कि कोविड-19 के बाद की अवधि में उपभोक्ता मांग के पुर्नरुद्धार के कारण हुई है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 22 की तुलना में वर्तमान वित्त वर्ष में 'स्वास्थ्य' उप-समूह में खुदरा मुद्रास्फीति में कमी आई है। तथापि, शिक्षा उपसमूह में मुद्रास्फीति महामारी के बाद व्यक्तिगत वर्गों के लिए फिर से खुलने वाले स्कूलों के कारण बढ़ी।

चित्र V.4: 'खाद्य और पेय पदार्थ' समूह द्वारा प्रेरित खुदरा मुद्रास्फीति

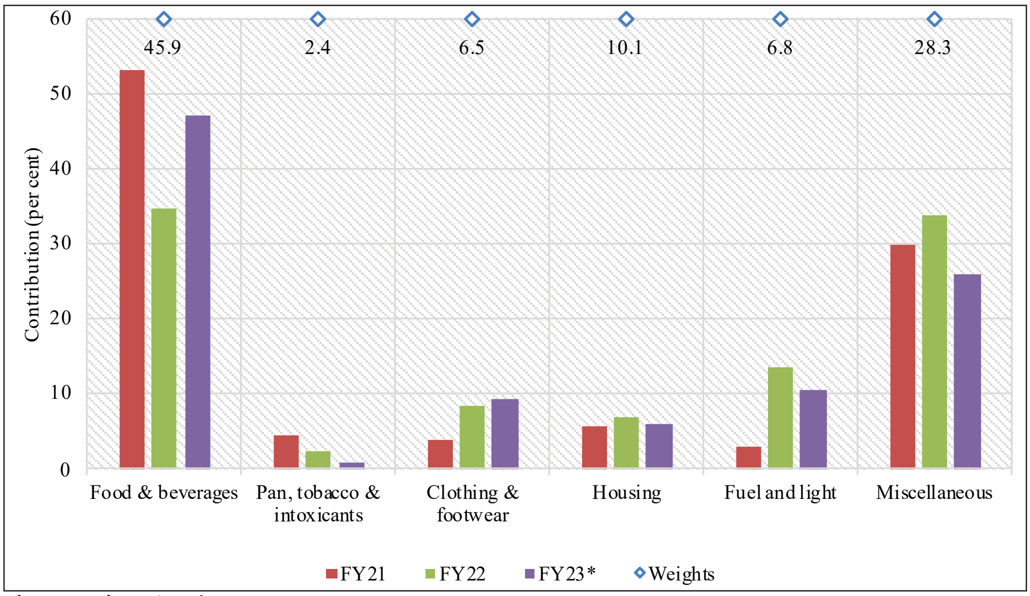

स्रोत: एमओएसपीआई

टिप्पणी: *अप्रैल-दिसम्बर

वित्त वर्ष 23 में सब्जी और अनाजों के कारण हुई खाद्य मुद्रास्फीति

5.11 वित्त वर्ष 22 में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति 3.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 7.0 प्रतिशत हो गई। हालांकि, खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि का आधार व्यापक है, तथापि इसमें सब्जियां, अनाज, दूध और मसालों आदि द्वारा प्रमुख योगदान दिया जाता है। आरबीआई ने आपूर्ति की कमी के कारण निकट भविष्य में अनाज और मसालों की घरेलू कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाया है। उच्च फीड लागत को दर्शाते हुए दूध की कीमतों में भी वृद्धि की संभावना है। सितंबर, 2022 से अनाज में दो अंकों की मुद्रास्फीति देखी गई। सरकार ने एचएस कोड 1101 के तहत गेहूँ और चावल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए गेहूँ उत्पादों के निर्यात पर रोक लगा दी है और चावल पर निर्यात शुल्क लगा दिया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कमजोर वर्गों को बढ़ती हुई कीमतों से बचाने के लिए 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों हेतु निशुल्क अनाज वितरण करने के लिए 1 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नामक नई समेकित खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है।

2 मौद्रिक नीति रिपोर्ट, आरबीआई, सितंबर 2022

चित्र V.5: प्रमुख समूहों/उप-समूहों में खुदरा मुद्रास्फीति

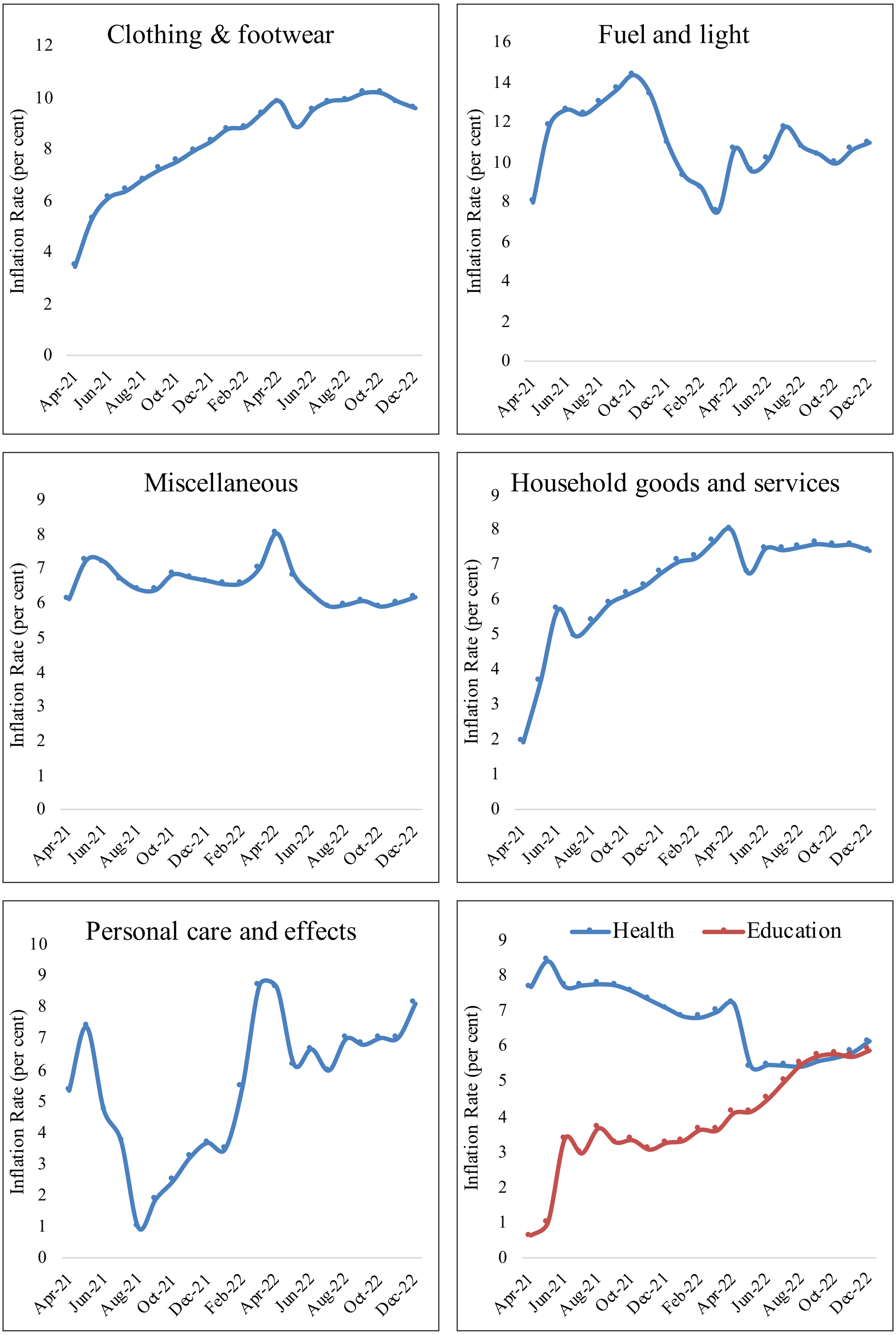

स्रोत: एमओएसपीआई

चित्र V.6: वित्त वर्ष 23 में खाद्य मुद्रास्फीति के प्रेरक – सब्जियां, अनाज, दूध और मसालें

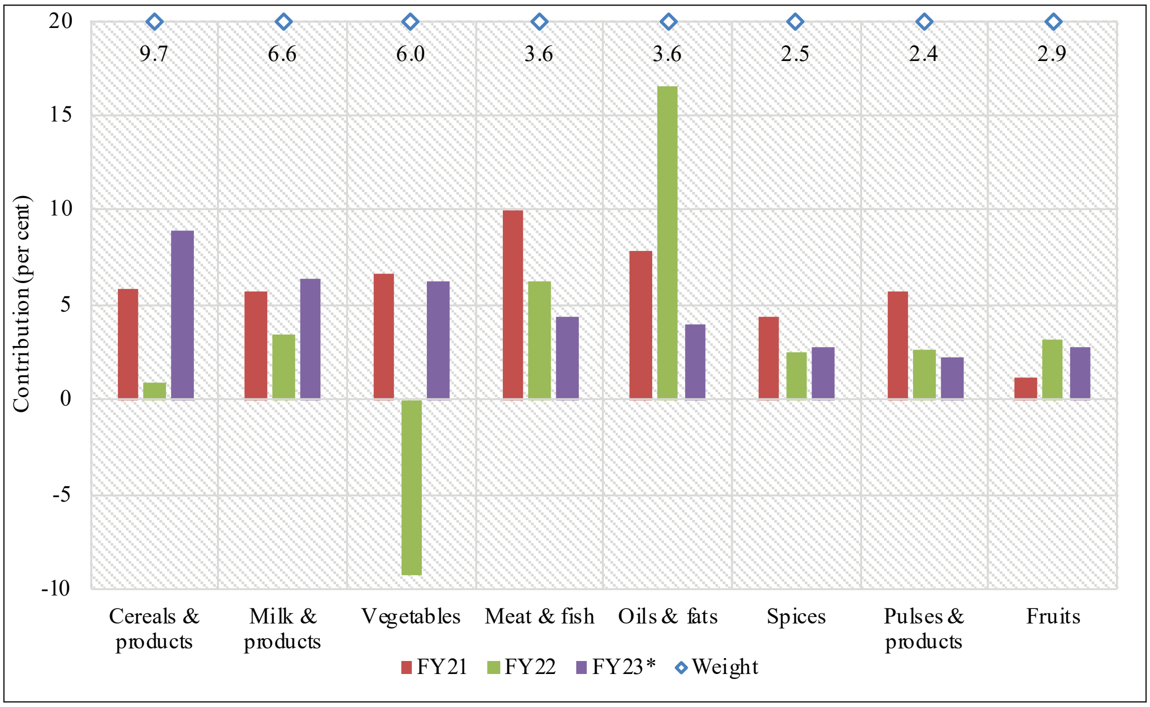

स्रोत: एमओएसपीआई
टिप्पणी: *अप्रैल-दिसम्बर

5.12 अप्रैल से सितंबर, 2022 तक सब्जियों में उच्च मुद्रास्फीति मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में बेमौसम भारी बारिश के कारण फसल की क्षति और आपूर्ति बाधित होने के कारण टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हुई।

चित्र V.7: वित्त वर्ष 23 में टमाटर की कीमत और 'सब्जियों' की मुद्रास्फीति में उछाल

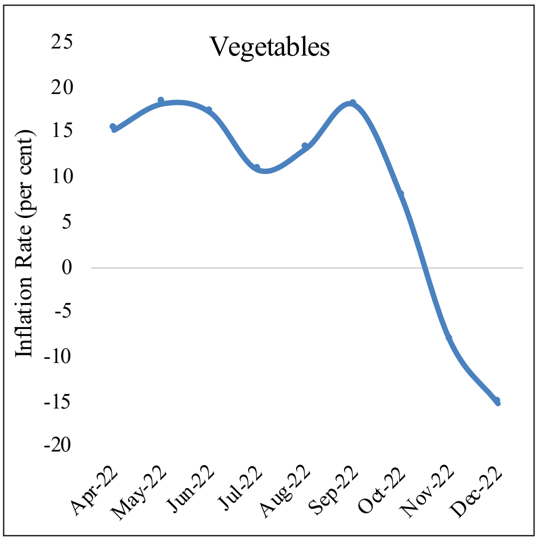

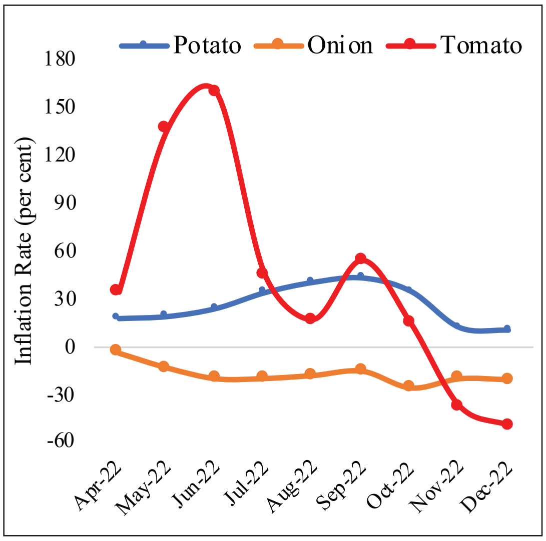

स्रोत: एमओएसपीआई

5.13 उच्च उत्पादन और बफर स्टॉक बनाए रखने और दालों पर आयात शुल्क और उपकर में कमी के संदर्भ में सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण दालों की मुद्रास्फीति अप्रभावित रही।

5.14 वैश्विक उत्पादन में कमी और विभिन्न देशों द्वारा निर्यात कर वसूलने में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 22 में खाद्य तेलों की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ीं। भारत अपने खाद्य तेलों की 60 प्रतिशत मांग को आयात के माध्यम से पूरा करता है, जिससे यह कीमतों में अंतरराष्ट्रीय उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है। उदाहरण के लिए, सूरजमुखी का तेल, जो हमारे कुल खाद्य तेल आयात का 15 प्रतिशत है, मुख्य रूप से यूक्रेन और रूस से खरीदा जाता है। इस प्रकार, वित वर्ष 22 ने अंतरराष्ट्रीय मूल्य दबावों के कारण खाद्य तेल की मुद्रास्फीति देखी। तथापि, टैरिफ के युक्तिकरण और खाद्य तेलों तथा तिलहन पर स्टॉक सीमा लागू करने के कारण वित्त वर्ष 2023 में मुद्रास्फीति कम रही।

चित्र V.8: खाद्य तेलों में आयातित मुद्रास्फीति

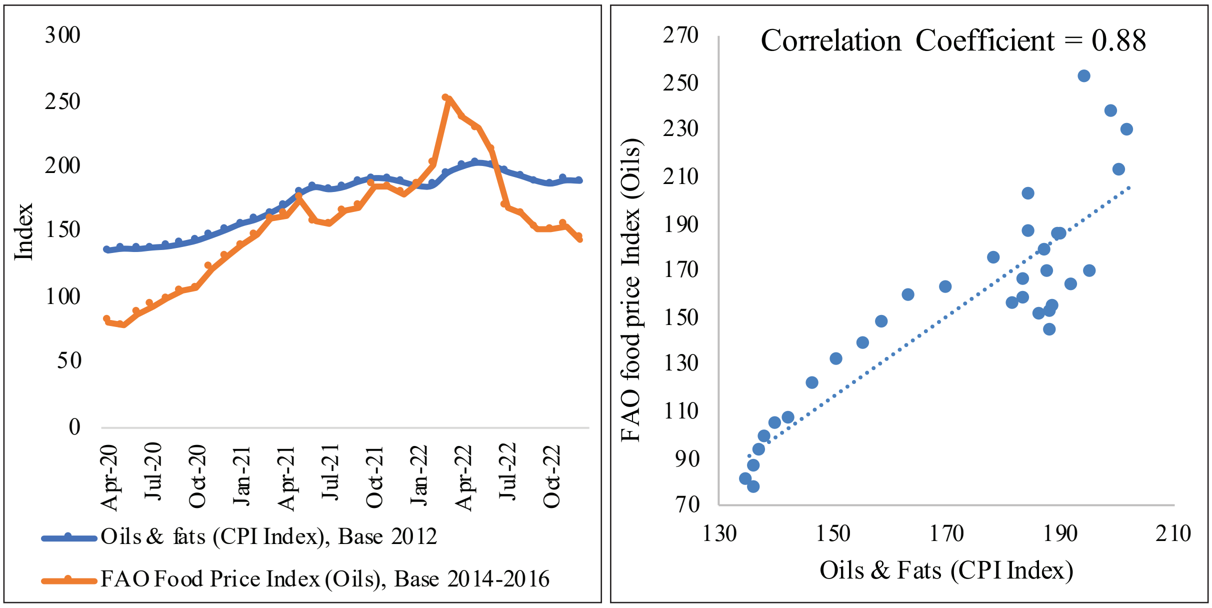

स्रोत: एफएओ और एमओएसपीआई

चित्र V.9: खाद्य तेलों का आयात

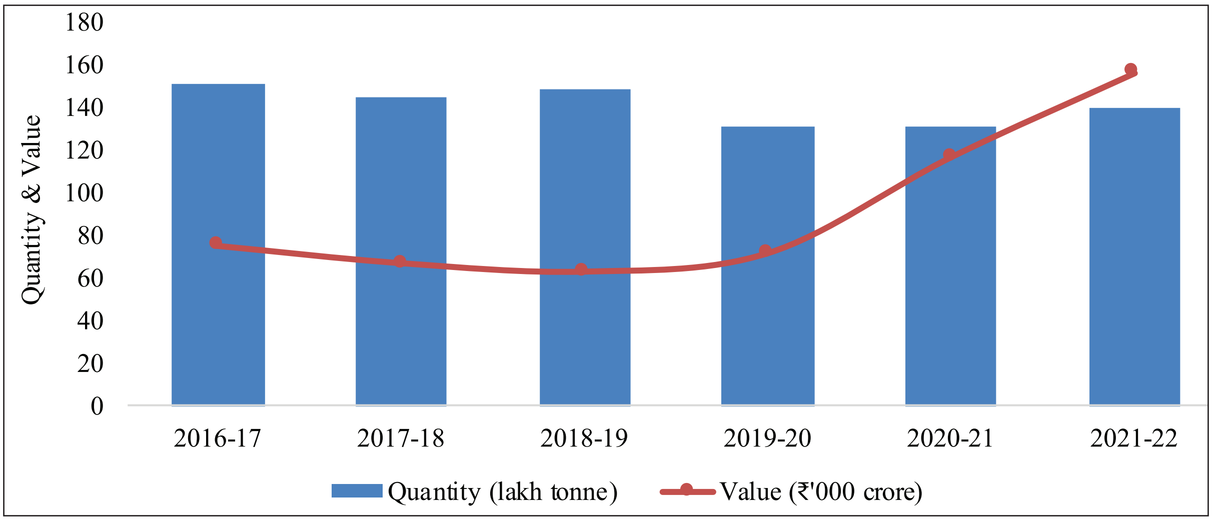

स्रोत: सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
नोट: तेल वर्ष (नवंबर-अक्टूबर) के अनुरूप डाटा

चित्र V.10: खाद्य तेलों की संयत खुदरा कीमत

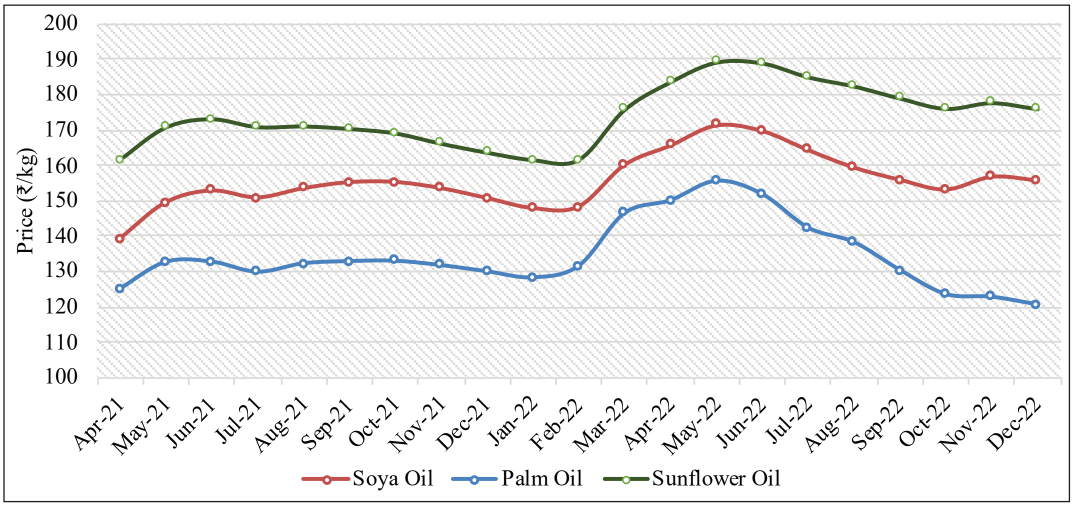

स्रोत: डीओसीए

बॉक्स V.1: आवश्यक खाद्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय

सरकार अंतर-मंत्रालयी समिति और सचिवों की समिति के द्वारा नियमित समीक्षा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखती है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए निम्नलिखित राजकोषीय उपाय किए गए हैं:

अनाज

- घरेलू कीमतों में उछाल को रोकने के लिए 13 मई, 2022 को गेहूँ के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- 12 जुलाई, 2022 से गेहूँ के आटे के निर्यात की अनुमति दी गई थी लेकिन अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा अनुशंसित प्रतिबंधों के अधीन थे।
- 14 अगस्त, 2022 से मैदा और सूजी के निर्यात को अंतर-मंत्रालयी समिति की मंजूरी के बाद ही अनुमति दी गई थी।
- दिनांक 27 अगस्त 2022 की अधिसूचना ने गेहूँ या मेसलिन आटा (आटा), मैदा, समोलिना (रवा/सिरगी), साबुत आटा और परिणामी आटा (एचएस कोड 1101) के निर्यात पर रोक लगा दी है। नीति में इस संशोधन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और देश में गेहूँ के आटे की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाना है।
- 9 सितंबर 2022 से प्रभावी केंद्र सरकार चावल, ब्राउन राइस और सेमी-मिल्ड के साथ-साथ परबोल्ड राइस को छोड़कर पूरी तरह मिल्ड राइस पर 20 फीसदी का निर्यात शुल्क लगाया।

दलहन

- 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में मूल्य स्थिरीकरण के लिए दालों का बफर स्टॉक बनाए रखा गया है। बफर स्टॉक से दालों के कैलिब्रेटेड रिलीज से बाजार कीमतों में संतुलन आयेगा।
- 26 जुलाई, 2021 से मसूर पर आयात शुल्क शून्य प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, 12 फरवरी, 2022 से मसूर पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) को शून्य प्रतिशत पर लाया गया था। एआईडीसी की शून्य दर को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया है।
- 30 मार्च, 2022 को मुक्त श्रेणी के तहत तुअर और उड़द का आयात 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया था।

- 1 सितंबर, 2022 को केंद्र सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 1.5 मिलियन टन चना रियायती दर पर उपलब्ध कराने का फैसला किया। राज्य अपने संबंधित निर्गम मूल्य पर 8 रुपये प्रति किलोग्राम की छूट पर चना खरीद सकेंगे।

खाद्य तेल

- केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए 24 मई, 2022 को कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल, प्रत्येक के 20 लाख मीट्रिक टन के वार्षिक आयात पर सीमा शुल्क और एआईडीसी को छूट दी।
- 21 दिसंबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक रिफाइंड पाम ऑयल पर बेसिक ड्यूटी 17.5 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी और 13 फरवरी, 2022 से 30 सितंबर 2022 तक क्रूड पाम ऑयल पर बेसिक ड्यूटी 7.5 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर, 2022 तक रिफाइंड पाम ऑयल के मुफ्त आयात की अनुमति दी है।
- केंद्र सरकार ने नवंबर, 2021 में क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लॉवर ऑयल पर बेसिक ड्यूटी 2.5 फीसदी से घटाकर शून्य कर दी थी। इन तेलों पर कृषि उपकर को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मूल आयात शुल्क को मौजूदा 32.5 प्रतिशत से घटाकर 17.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- सोया मील की घरेलू कीमतों को कम करने के लिए, केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून 2022 तक 'सोया मील' को आवश्यक वस्तु घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एक आदेश अधिसूचित किया है। सोया मील पर 23 दिसंबर, 2021 से 30 जून 2022 तक के लिए स्टॉक सीमा लगाई गई है।
- सभी खाद्य तेलों और तिलहनों पर लगाई गई स्टॉक सीमा को दिनांक 3 फरवरी 2022 के आदेश द्वारा लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को हटाने, विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर स्टॉक सीमा और आवाजाही पर प्रतिबंध आदेश, 2016 में संशोधन करके 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था। इस उपाय से बाजार में जमाखोरी, कालाबाजारी आदि जैसी किसी भी अनुचित प्रथा पर अंकुश लगा और इससे खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिली।
- जुलाई, 2022 में, केंद्र सरकार ने प्रमुख खाद्य तेल संघों को तत्काल प्रभाव से खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्य में ₹15 प्रति लीटर की कमी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। केंद्र द्वारा खाद्य तेल कंपनियों को वैश्विक खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को देने के निर्देश के बाद मदर डेयरी ने चावल की भूसी और सोयाबीन तेल की कीमतों में ₹14 प्रति लीटर तक की कमी की है।

ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति में अंतर कम हुआ है

5.15 महामारी के वर्षों के दौरान देखी गई प्रवृत्ति से विपरीत, वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण मुद्रास्फीति अपने शहरी समकक्ष से ऊपर रही। सीपीआई-सी आधारित खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल, 2022 में 8.3 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुँचने के बाद वैश्विक खाद्य कीमतों में सुधार और कृषि इनपुट लागत में कमी के कारण गिरावट आई है। तथापि, शहरी मुद्रास्फीति के लिए राहत अधिक स्पष्ट थी, जो दिसंबर, 2022 में घटकर 2.8 प्रतिशत हो गई। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण ईंधन मुद्रास्फीति अपने शहरी समकक्ष की तुलना में कम रही, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के विपरीत जलाऊ लकड़ी और गोबर के उपले जैसे पारंपरिक ईंधन की कीमतों पर दबाव कम रहा।

5.16 जबकि वर्तमान वित्त वर्ष में ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के बीच अंतर कम हो रहा था, लेकिन वित्त वर्ष 22 में दोनों के बीच व्यापक अंतर देखा गया था। खाद्य मुद्रास्फीति में अंतर के कारण मार्च, 2022 में ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति के बीच का अंतर अपने सबसे बड़े स्तर पर पहुंच गया। भीतरी इलाकों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में इस समय के दौरान सब्जियों और तेलों की खाद्य कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई।

चित्र V.11: शहरी और ग्रामीण मुद्रास्फीति

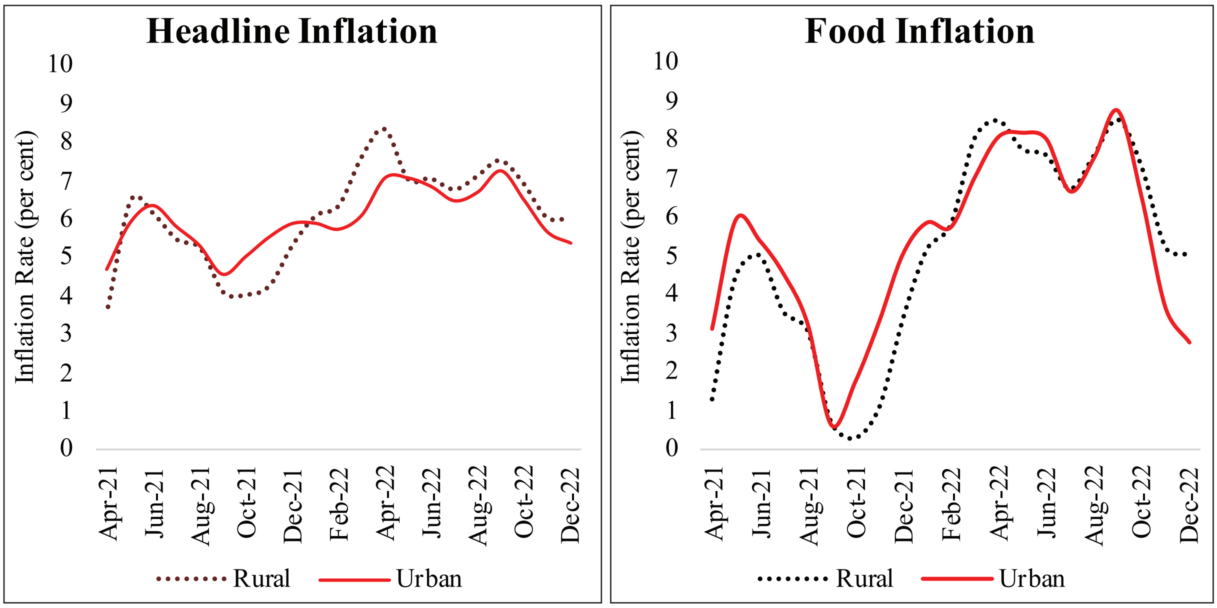

स्रोत : एमओएसपीआई

अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी मुद्रास्फीति से ग्रामीण मुद्रास्फीति अधिक है

5.17 वित्त वर्ष 22 की तुलना में वित्त वर्ष 23 में अधिकांश राज्यों के सीपीआई-सी मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 23 में तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से मुद्रास्फीति की उच्च दर देखी गई। मुद्रास्फीति वृद्धि में ईंधन और कपड़े का प्रमुख योगदान था।

चित्र V.12: वित्त वर्ष 23* में अधिकांश राज्यों में उच्च खुदरा मुद्रास्फीति

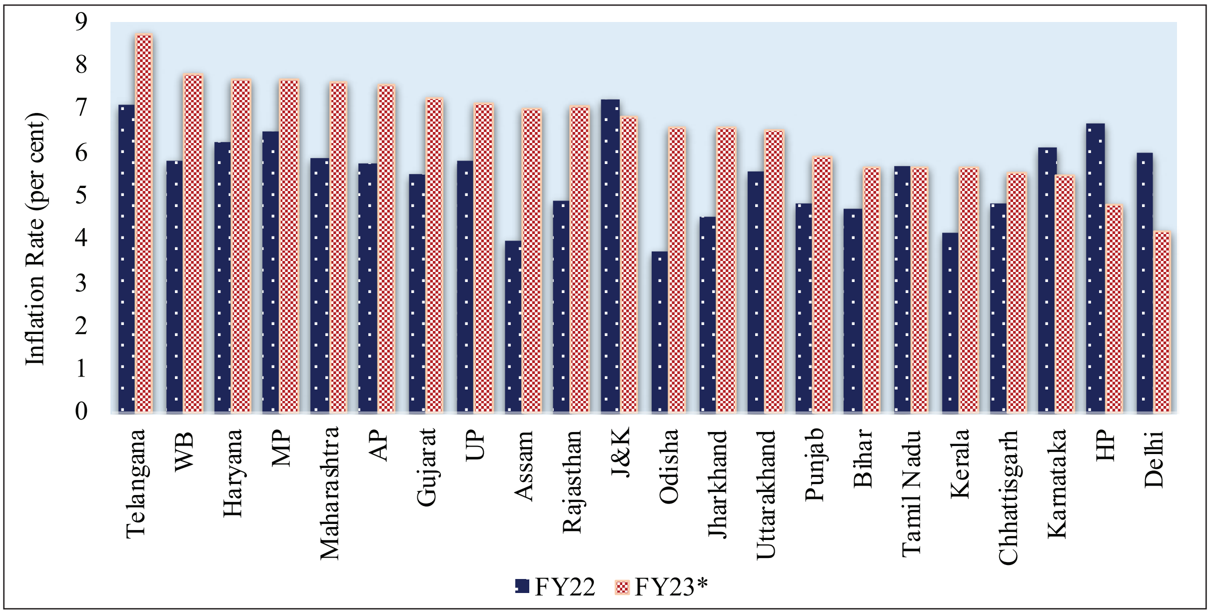

स्रोत: एमओएसपीआई

टिप्पणी: (i) *अप्रैल-दिसम्बर

(ii) कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल और मई, 2020 के महीनों के लिए सूचकांकों की अनुपलब्धता के कारण वित्त वर्ष 22 की मुद्रास्फीति जून, 2021 से मार्च, 2022 के औसत पर आधारित है।

(iii) 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 22 प्रमुख राज्यों को दर्शाया गया है

5.18 अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वर्तमान वर्ष में शहरी मुद्रास्फीति की तुलना में ग्रामीण मुद्रास्फीति अधिक देखी गई है, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हुई है। असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में शहरी मुद्रास्फीति की तुलना में ग्रामीण मुद्रास्फीति अधिक रही। हरियाणा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में यह इसलिए अधिक थी क्योंकि वहाँ 'खाद्य और पेय पदार्थ' और 'कपड़े और जूते' से संबंधित मुद्रास्फीति अधिक है। मध्य प्रदेश, मणिपुर और असम के ग्रामीण क्षेत्रों में, यह 'ईंधन और प्रकाश' खंडों के कारण हुआ था। बिहार, मेघालय और त्रिपुरा के शहरी क्षेत्रों में उच्च मुद्रास्फीति के लिए भोजन, कपड़े और ईंधन का प्रमुख योगदान था।

चित्र V.13: वित्त वर्ष 23* में अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उच्चतर ग्रामीण मुद्रास्फीति

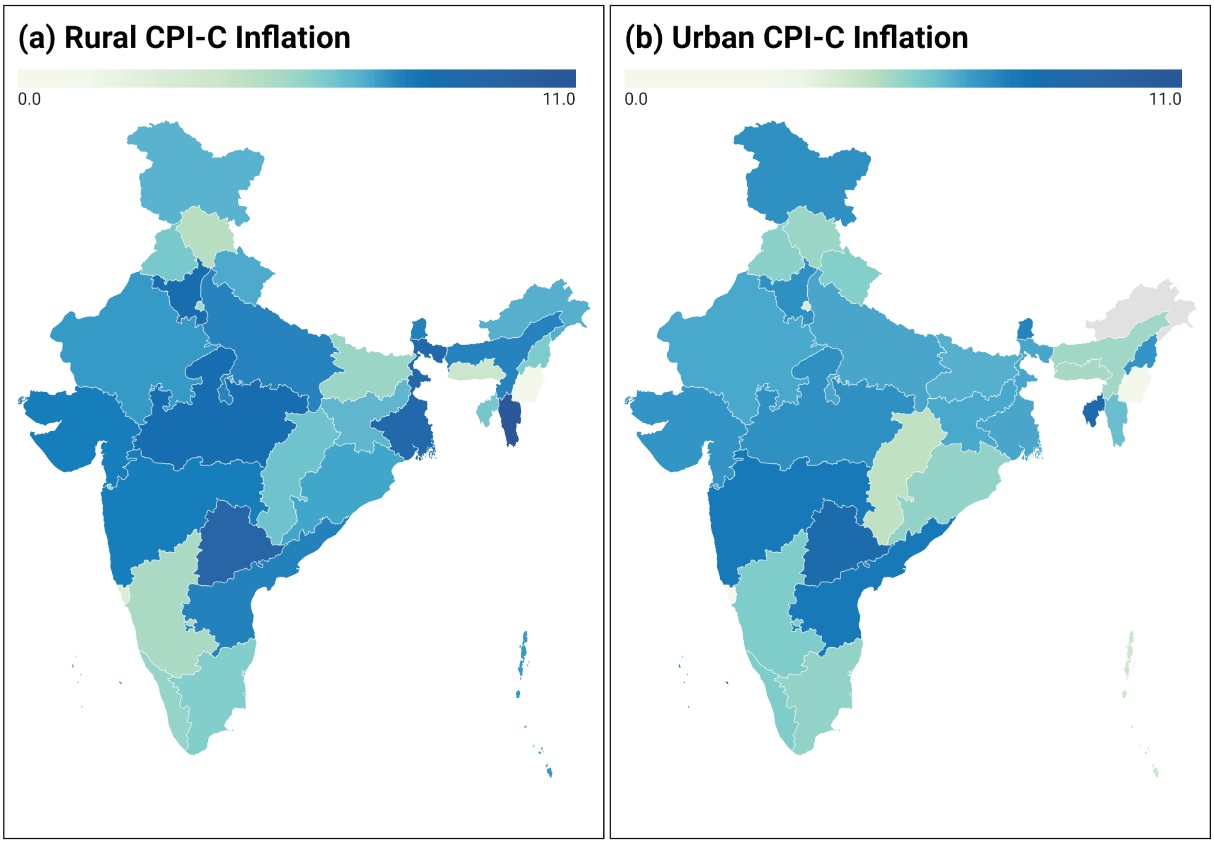

स्रोत: एमओएसपीआई

टिप्पणी: (i) *अप्रैल- दिसम्बर

(ii) शहरी अरुणाचल प्रदेश के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

घरेलू थोक मूल्य मुद्रास्फीति

वैश्विक आपूर्ति व्यवधान के कारण हुई थोक मूल्य मुद्रास्फीति

5.19 कोविड-19 की अवधि के दौरान डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति कम रही, और महामारी के बाद की अवधि में आर्थिक कार्यकलापों के फिर से शुरू होने पर इसमें पुन: तेजी आने लगी। रूस-यूक्रेन संघर्ष ने इस बोझ को और बढ़ा दिया क्योंकि इससे आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही के साथ-साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बिगड़ गईं। इसके परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2022 में थोक मुद्रास्फीति की दर लगभग 13.0 प्रतिशत तक बढ़ गई। पेट्रोलियम उत्पादों, बुनियादी धातुओं, रसायनों और रासायनिक उत्पादों और खाद्य तेलों जैसी वस्तुओं की कीमतें, अंतरराष्ट्रीय मूल्य निर्धारण के अधिकतम जोखिम सहित घरेलू थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में वृद्धि के रूप में परिवर्तित हुए हैं।

सारणी V.2: डब्ल्यूपीआई (प्रतिशत) के आधार पर औसतन वार्षिक थोक मुद्रास्फीति (आधार: 2011-12=100

समूह/उप-समूह	भार	वित्त वर्ष 20	वित्त वर्ष 21	वित्त वर्ष 22	वित्त वर्ष 23*
प्राथमिक सामग्री	**22.6**	**6.8**	**1.7**	**10.3**	**12.3**
खाद्य सामग्री	**15.3**	**8.4**	**3.1**	**4.1**	**8.3**
अनाज	2.8	7.5	-2.6	1.6	10.7
दाल	0.6	15.9	11.6	6.9	0.0
सब्जियाँ	1.9	31.2	3.4	0.4	13.2
फल	1.6	3.2	1.4	11.3	10.4
गैर-खाद्य सामग्री	**4.1**	**4.5**	**1.4**	**21.1**	**12.0**
खनिज पदार्थ	0.8	13.2	6.7	19.6	6.2
कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	**2.4**	**-7.7**	**-17.5**	**56.7**	**57.7**
ईंधन और विद्युत	**13.2**	**-1.8**	**-8.0**	**32.6**	**33.8**
एलपीजी	0.6	-8.3	-2.7	43.3	16.9
पेट्रोल	1.6	-3.2	-11.8	62.9	41.9
हाई स्पीड डीजल	3.1	-3.5	-14.4	59.9	60.8
विनिर्मित उत्पाद	**64.2**	**0.3**	**2.7**	**11.1**	**7.1**
खाद्य उत्पाद	**9.1**	**4.1**	**5.6**	**11.7**	**6.0**
खाद्य तेल	2.6	1.4	20.3	30.5	1.4
खाद्य मुद्रास्फीति (खाद्य सामग्री + खाद्य उत्पाद)	***24.4***	***6.9***	***3.9***	***6.8***	***7.5***
मूल मुद्रास्फीति (निर्मित उत्पाद-खाद्य उत्पाद)	***55.1***	***-0.4***	***2.2***	***11.0***	***9.2***
मुख्य मुद्रास्फीति	***100***	***1.7***	***1.3***	***13.0***	***11.5***

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी
टिप्पणी: *अप्रैल-दिसंबर 2022, नवंबर और दिसंबर, 2022 के आकड़े अनंतिम है।

5.20 वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही के दौरान डब्ल्यूपीआई में दो अंकों की मुद्रास्फीति के लिए खाद्य मुद्रास्फीति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो वित्त वर्ष 22 में 6.8 प्रतिशत की तुलना में 7.5 प्रतिशत पर रही। अनियमित जलवायु परिस्थिति के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में अनाज और सब्जियों का प्रमुख योगदान था। वित्त वर्ष 23 में 'विनिर्माण उत्पाद' उपसमूह में मुद्रास्फीति में पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण इनपुट पर शुल्कों के युक्तिकरण और वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में कमी के कारण काफी गिरावट देखी गई। वित्त वर्ष 22 की तुलना में, वित्त वर्ष 23 में मूल मुद्रास्फीति कम रही।

5.21 समग्र रूप से, थोक मूल्य मुद्रास्फीति की मासिक प्रवृत्ति अपने चरम 16.6 प्रतिशत से नीचे की ओर गिरी है, सितंबर, 2022 में 10.6 प्रतिशत और दिसंबर, 2022 में 5.0 प्रतिशत हो गई है। डबल्यूपीआई के सभी तीन उपसमूहों के मुद्रास्फीति में गिरावट देखी गई थी।

5.22 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, डबल्यूपीआई मुद्रास्फीति का एक भाग आयातित मुद्रास्फीति है। खाद्य तेलों पर उच्च आयात निर्भरता का अर्थ है कि इन उत्पादों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों का अस्थायी प्रभाव घरेलू कीमतों में भी परिलक्षित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन[3] में दर्शाया गया है कि वैश्विक

3 मौद्रिक नीति रिपोर्ट, आरबीआई, सितम्बर 2022

मुद्रास्फीति के झटके के कारण सभी देशों और क्षेत्रों में कीमतों में एक प्रतिशत की वृद्धि भारत में मुद्रास्फीति को लगभग 63 आधार अंकों तक बढ़ा सकती है, जिसमें 100 आधार अंकों के प्रत्यक्ष प्रभाव के अतिरिक्त घरेलू अप्रत्यक्ष प्रभाव (46 आधार अंक) और वैश्विक प्रभाव (17 आधार अंक) शामिल हैं। डबल्यूपीआई (विनिर्माण घटक) पर विश्व बाजारों में कीमतों का प्रभाव विशेष रूप से तेल और बुनियादी धातुओं की कीमतों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वर्तमान वित्त वर्ष में खाद्य तेल, रबर, कपास, कच्चा तेल और धातुओं की वैश्विक कीमतों में कमी आई है। वित्त वर्ष 23 के प्रथम छमाही में पूंजी के बर्हिप्रवाह ने भारत की विनिमय दर पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था, यह आयातित इनपुट की उच्च कीमतों का एक और कारण था, जो ज्यादातर डॉलर आधारित होता है।

चित्र V.14: मूल और खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट

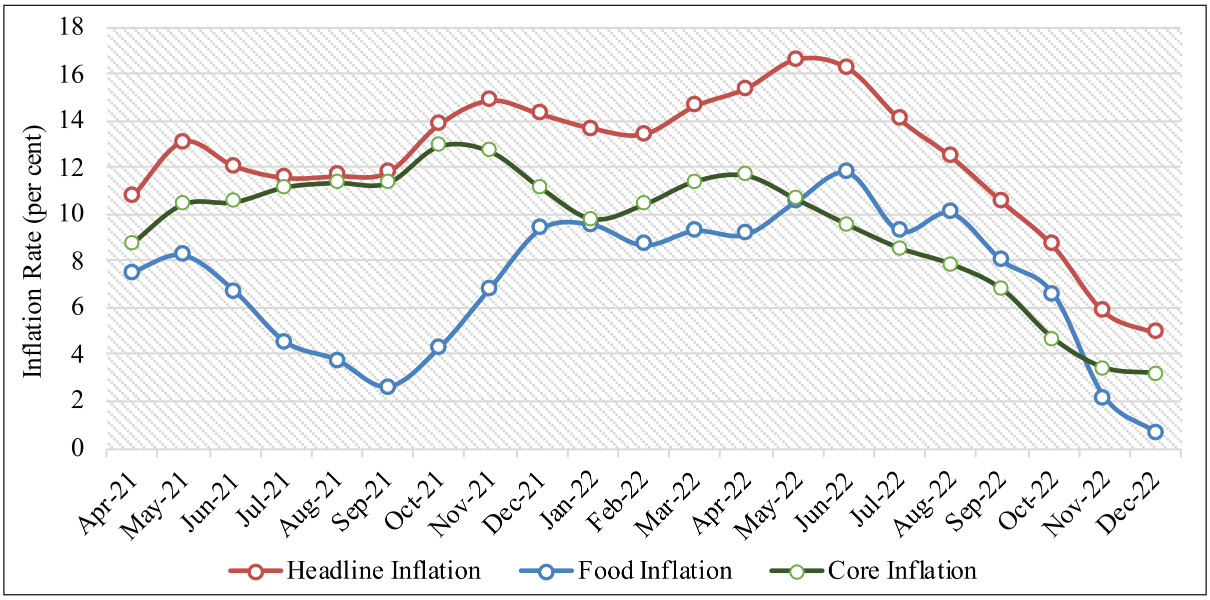

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी

चित्र V.15: वित्त वर्ष 23* में थोक मुद्रास्फीति के प्रेरक – ''प्राथमिक सामग्री'' और ''ईंधन और विद्युत''

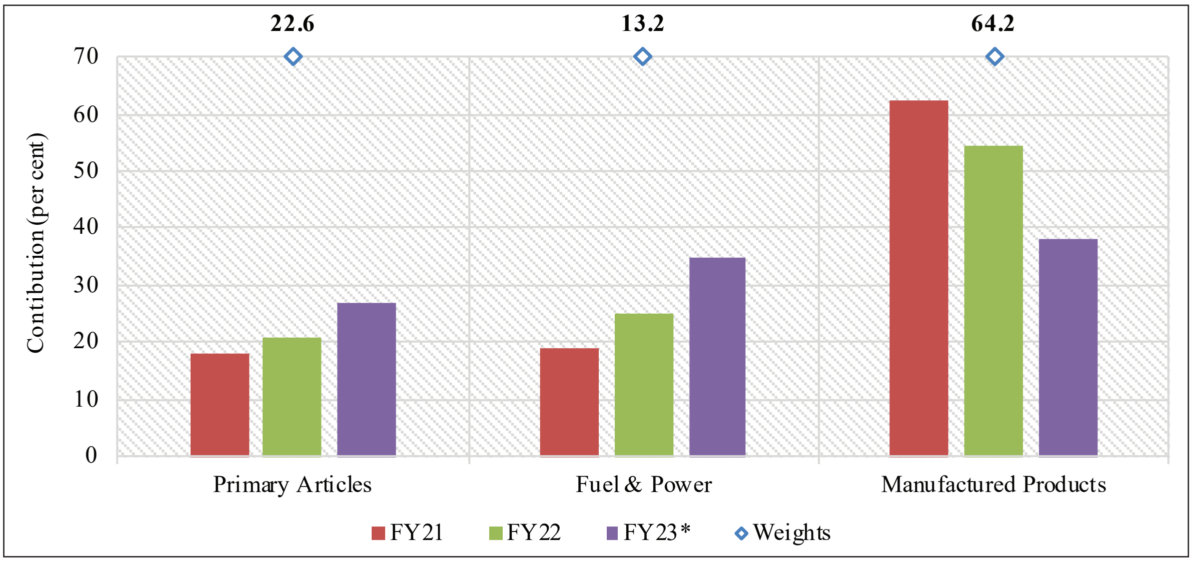

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी

टिप्पणी: *अप्रैल-दिसंबर

चित्र V.16: वैश्विक वस्तु कीमतों में कमी

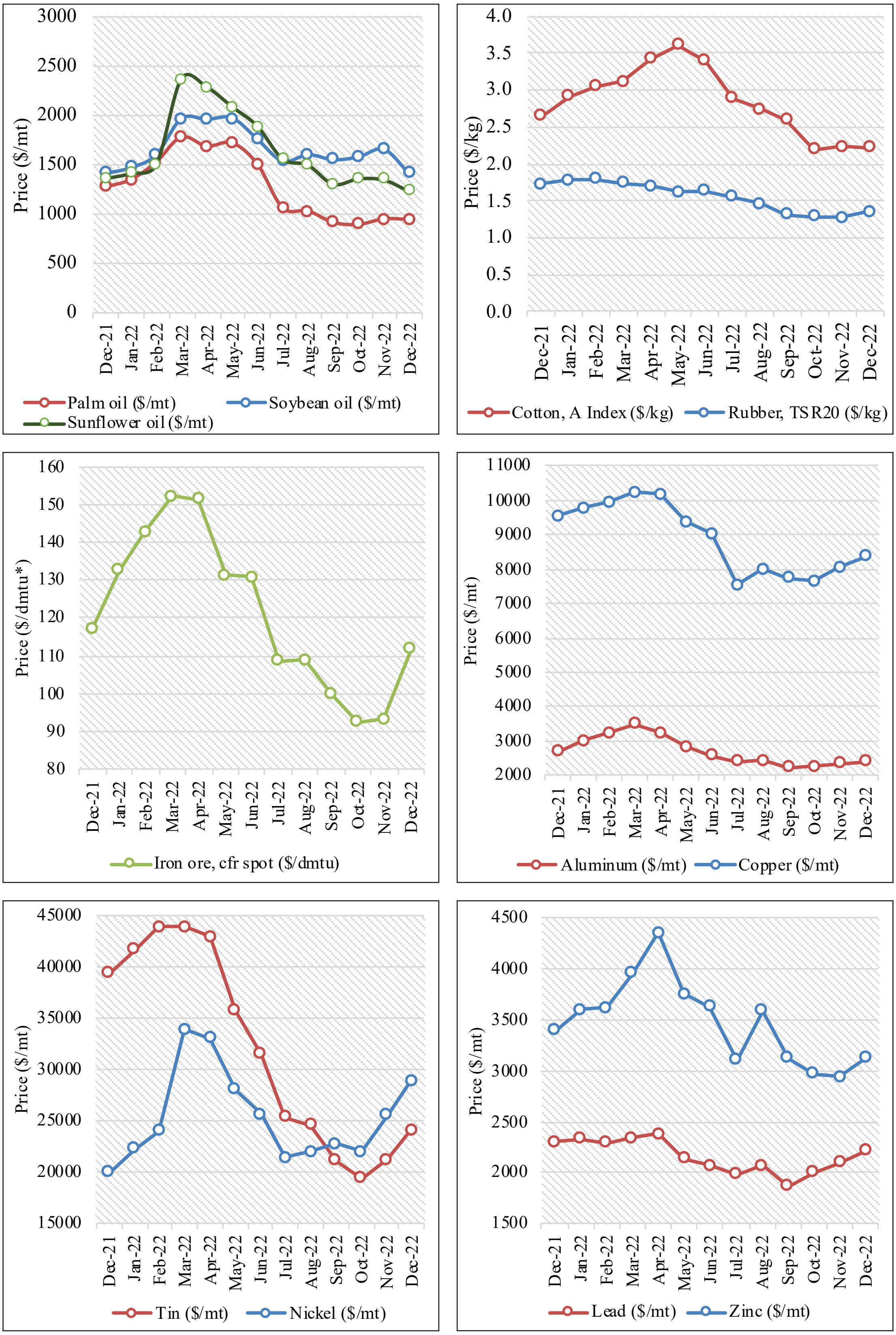

स्रोत: पिंक शीट, विश्व बैंक

टिप्पणी: *डीएमटीयू: शुष्क मीट्रिक टन इकाई

बॉक्स V.2: इनपुट कीमतों में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय

- **ईंधन की कीमतें:** केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क को समायोजित करके हस्तक्षेप किया है। पेट्रोल पर ₹5 और डीजल पर ₹10 की कटौती का पहला चरण दिनांक 4 नवंबर, 2021 से और दूसरा चरण दिनांक 22 मई, 2022 से प्रभावी किया गया था (पेट्रोल पर ₹8 प्रति लीटर और डीजल पर ₹6 प्रति लीटर)।
- **प्लास्टिक उत्पाद:** घरेलू विनिर्माण की लागत को कम करने के लिए प्लास्टिक उद्योग में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आयात पर आयात शुल्क घटा दिया गया है। दिनांक 21 मई, 2022 को नाफ्था, प्रोपलीन ऑक्साइड और पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड पर शुल्क क्रमशः 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- **इस्पात:** दिनांक 21 मई 2022 को, प्रमुख इनपुट – फेरोनिकेल, कोकिंग कोल, पीसीआई कोल – पर आयात शुल्क 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कोक और सेमी-कोक पर शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। लौह अयस्क और कंसन्ट्रेट के निर्यात पर कर 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि लौह छर्रों पर कर को बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर दिया गया है।
- **कपास:** सरकार ने दिनांक 14 अप्रैल, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क माफ कर दिया था, ताकि वस्त्र उद्योग को लाभ हो सके और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर उपलब्ध हो सके। इससे पहले, कपास के आयात पर 5 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और 5 प्रतिशत एआईडीसी लगाया गया था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कपास के आयात के लिए सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर से छूट को अधिसूचित किया था।
- हीरे और रत्न: बजट 2022-2023 में, कटे और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया था और साधारण रूप से काटे गए हीरे पर शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया था।
- **रसायनिक उत्पाद:** बजट 2022-23 में पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए कुछ महत्वपूर्ण रसायनों जैसे मेथनॉल, एसिटिक एसिड और भारी फीडस्टॉक्स पर सीमा शुल्क घटाया गया था।

ईंधन मूल्य मुद्रास्फीति: वैश्विक कच्चे तेल की घटती कीमत

5.23 वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 23 में, डबल्यूपीआई 'ईंधन और विद्युत' में मुद्रास्फीति ज्यादातर उच्च अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों से प्रेरित थी। कोविड-19 में प्रतिबंधों के कारण वैश्विक मांग में कमी के प्रत्युत्तर में, वित्त वर्ष 21 के दौरान कच्चे तेल की भारतीय बास्केट की कीमत 20-65 अमेरिकी डॉलर/बीबीएल की सीमा में रही। तत्पश्चात् पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) और अन्य तेल उत्पादक देशों द्वारा कच्चे तेल की आपूर्ति में अभूतपूर्व कटौती के कारण कीमतें बढ़ने लगीं। वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 23 में रुझान बढ़ोत्तरी की ओर जारी रहा, क्योंकि दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में कोविड -19 प्रतिबंधों में छूट सहित मांग में बढ़ोतरी हुई थी। इसके अतिरिक्त, जून 2022 में पूर्वी यूरोप और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच आपूर्ति में व्यवधान के कारण, कच्चे तेल की भारतीय बास्केट 116 अमरीकी डॉलर/बीबीएल पर पहुंच गई। इसके बाद, दिसंबर, 2022 में कीमत गिरकर 78 अमरीकी डॉलर/बीबीएल हो गई। इसके अतिरिक्त, नवंबर, 2021 और मई, 2022 में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद राज्य सरकारों द्वारा मूल्य वर्धित कर (वैट) में कमी के कारण भारत में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में कमी आई।

चित्र V.17: कच्चे तेल की कीमतों में कमी

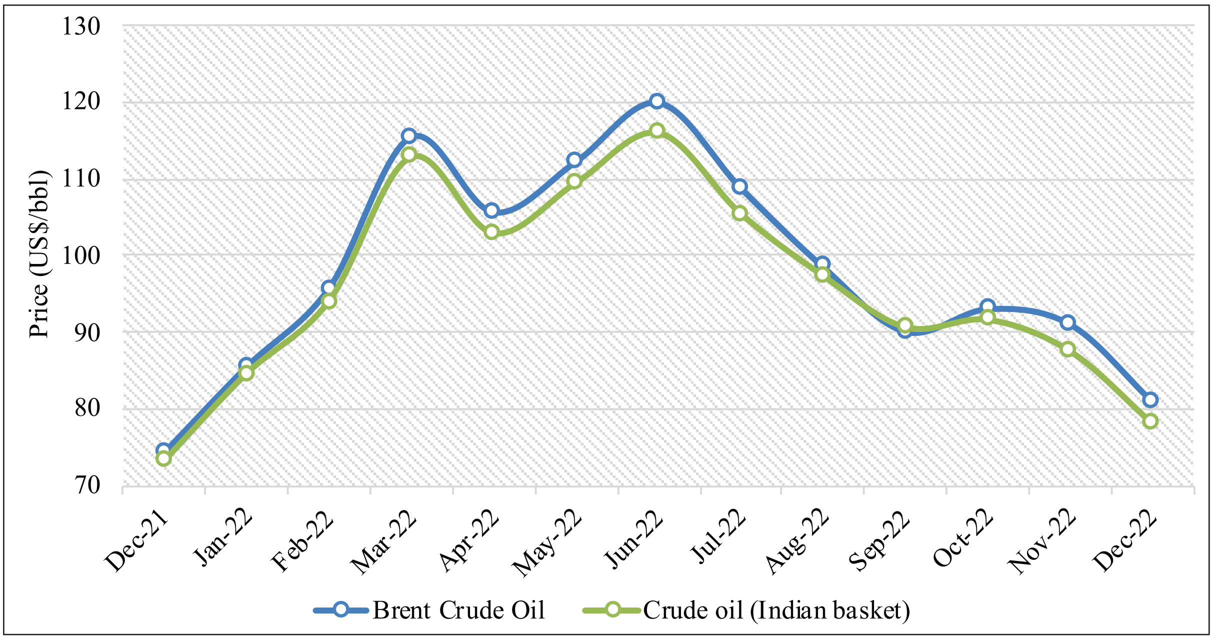

स्रोत: पिंक शीट, विश्व बैंक और पीपीएसी, एमओपीएनजी

डब्ल्यूपीआई और सीपीआई मुद्रास्फीति का अभिसरण

5.24 महामारी के प्रकोप के बाद से भारत में मुद्रास्फीति की गतिशीलता विभिन्न घरेलू और वैश्विक कारकों से प्रभावित हुई है। जबकि अंतरराष्ट्रीय कीमतों का थोक मूल्यों पर प्रभाव अपेक्षाकृत जल्दी होता है, यह खुदरा कीमतों को एक अंतराल के साथ प्रभावित करता है। यह डब्ल्यूपीआई और सीपीआई मुद्रास्फीति दरों के बीच अंतर उत्पन्न करता है। यह दो सूचकांकों में अलग-अलग सूचकांक को सौंपी गई संरचना और भार में अंतर के कारण भी है।

5.25 डबल्यूपीआई और सीपीआई-सी पर आधारित मुख्य मुद्रास्फीति मार्च, 2021 में विभाजित होने लगी, क्योंकि डबल्यूपीआई मुद्रास्फीति प्रतिकूल आधारित प्रभावों के कारण दोहरे अंकों में पहुंच गई, जबकि सीपीआई-सी मुद्रास्फीति स्थिर रही। नवंबर, 2021 में 10 प्रतिशत के अपने चरम स्तर पर पहुंचने से पहले सीपीआई-सी और डबल्यूपीआई मुद्रास्फीति का अंतर बढ़ता रहा। इसके बाद, अप्रैल 2022 तक अंतर कम होना शुरू हो गया। हालांकि, अभिसरण का मार्ग अल्पकालिक था क्योंकि रूस-यूक्रेन संघर्ष के परिणामस्वरूप फरवरी 2022 में एक और मुद्रास्फीति दबाव शुरू होने लगा था। सूचकांक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती मांग का नुकसान 2 महीने के छोटे अंतराल सहित डबल्यूपीआई में परिलक्षित हुआ। इसके परिणामस्वरूप, मई, 2022 में मुद्रास्फीति के दो संकेतक फिर से अलग होने लगे। तेल सहित वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में कमी आने और अनुकूल मॉनसून, टीकाकरण की अगुवाई वाली आर्थिक बहाली आदि जैसे मजबूत सहायक घरेलू कारकों के प्रभावों के बाद ही ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह कमी उसको संकुचित करने लगी और 21 महीने के पश्चात नवंबर, 2022 में समाप्त हो गई। इसने खुदरा क्षेत्र की उच्च निविष्टि लागतों के निकटतम निकासी के पूरा होने का भी संकेत दिया।

5.26 डबल्यूपीआई और सीपीआई सूचकांकों के बीच अभिसरण मुख्य रूप से दो कारकों से प्रेरित था। सबसे पहले, कच्चा ईंधन, लोहा, एल्युमीनियम और कपास जैसी वस्तुओं की मुद्रास्फीति में कमी के कारण थोक मूल्य सूचकांक कम हुआ। सीपीआई की तुलना में ये वस्तुएं डबल्यूपीआई में अधिक भार रखती हैं। इसके अतिरिक्त, ये

वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं और थोक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों द्वारा इनका गहनता से उपयोग किया जाता है। इन पण्यों की कीमतों में कमी आने से मुद्रास्फीति के दोनों माप नजदीक आने लगे। दूसरा, सीपीआइ मुद्रास्फीति सेवाओं की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ी। सेवाएँ सीपीआई-सी के मुख्य घटक का हिस्सा हैं, परंतु यह डबल्यूपीआई बास्केट में शामिल नहीं हैं।

चित्र V.18: प्रमुख डबल्यूपीआई की मुद्रास्फीति सहित मुख्य सीपीआई- मुद्रास्फीति अभिसरण

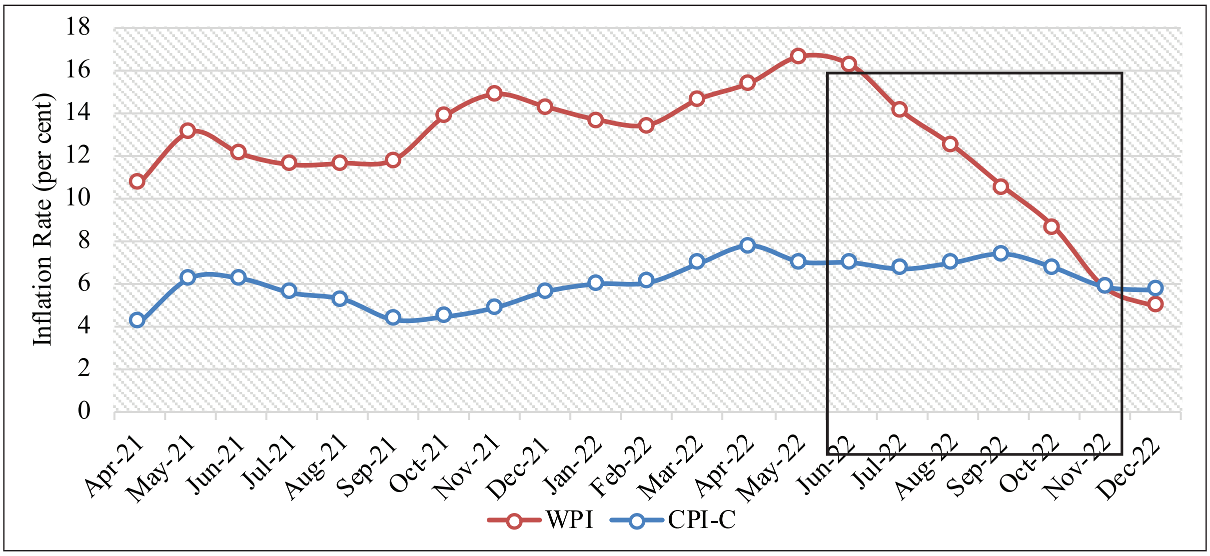

स्रोत: एमओएसपीआई और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी

चित्र V.19: मूल मुद्रास्फीति में अभिसरण सीपीआई-सी बनाम डबल्यूपीआई

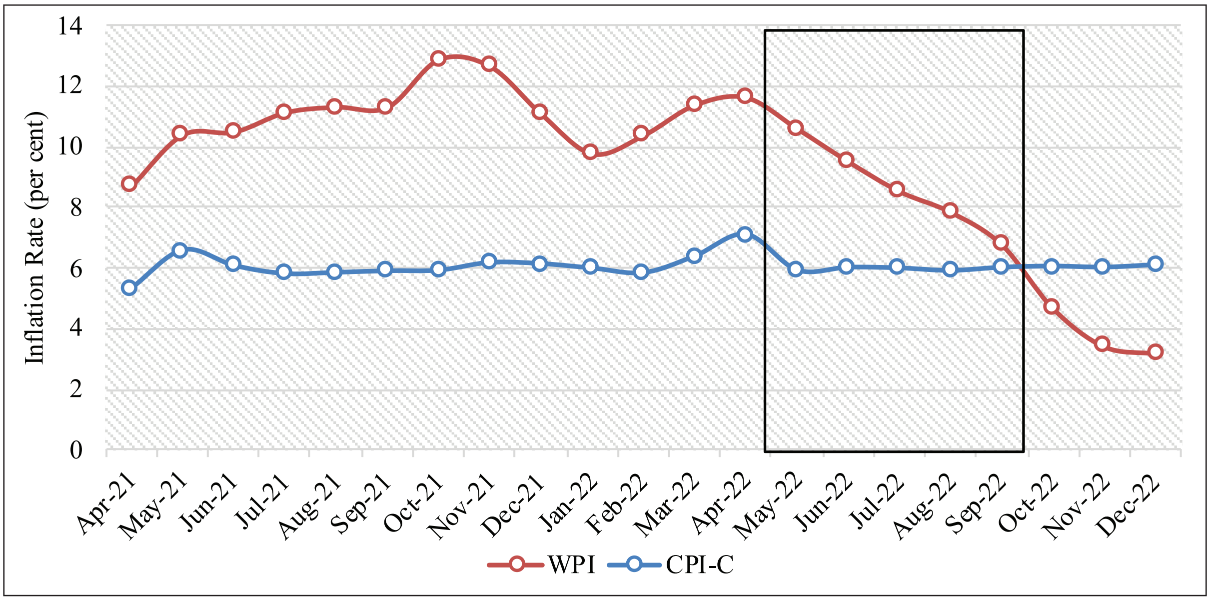

स्रोत: एमओएसपीआई और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी

चित्र V.20: खाद्य मुद्रास्फीति में अभिसरण सीपीआई-सी बनाम डब्ल्यूपीआई

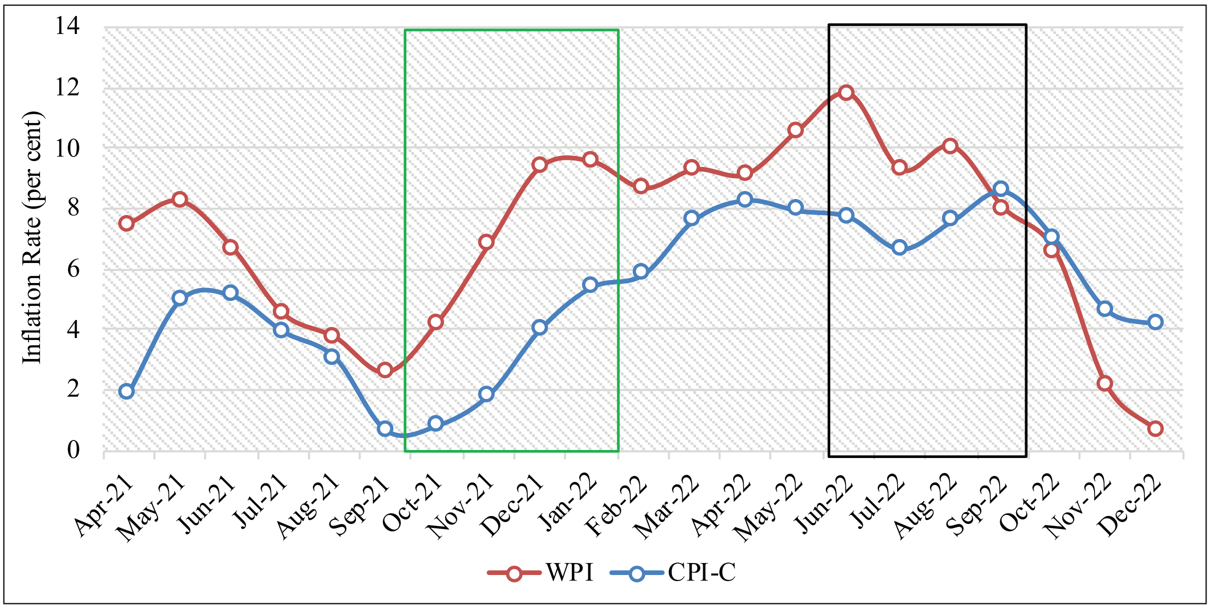

स्रोत: एमओएसपीआई और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी

चित्र V.21: सीपीआई (ईंधन और विद्युत) और डब्ल्यूपीआई (ईंधन और बिजली) के बीच मुद्रास्फीति दरों का अभिसरण

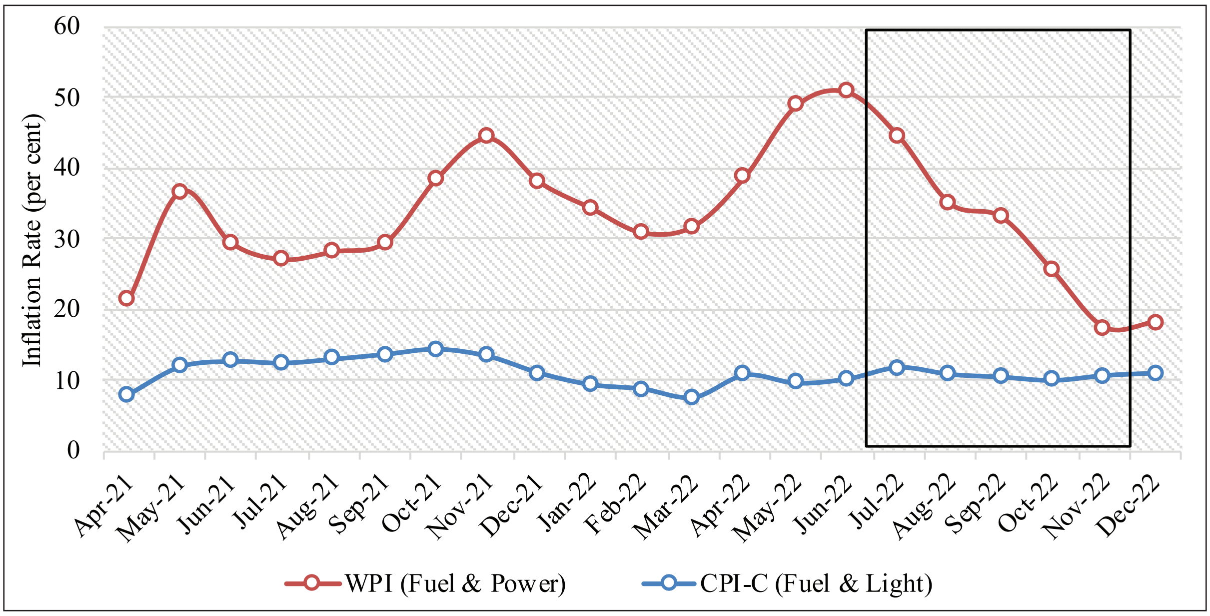

स्रोत: एमओएसपीआई और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी

चित्र V.22: खुदरा और थोक ऊर्जा मुद्रास्फीति दरों में अभिसरण

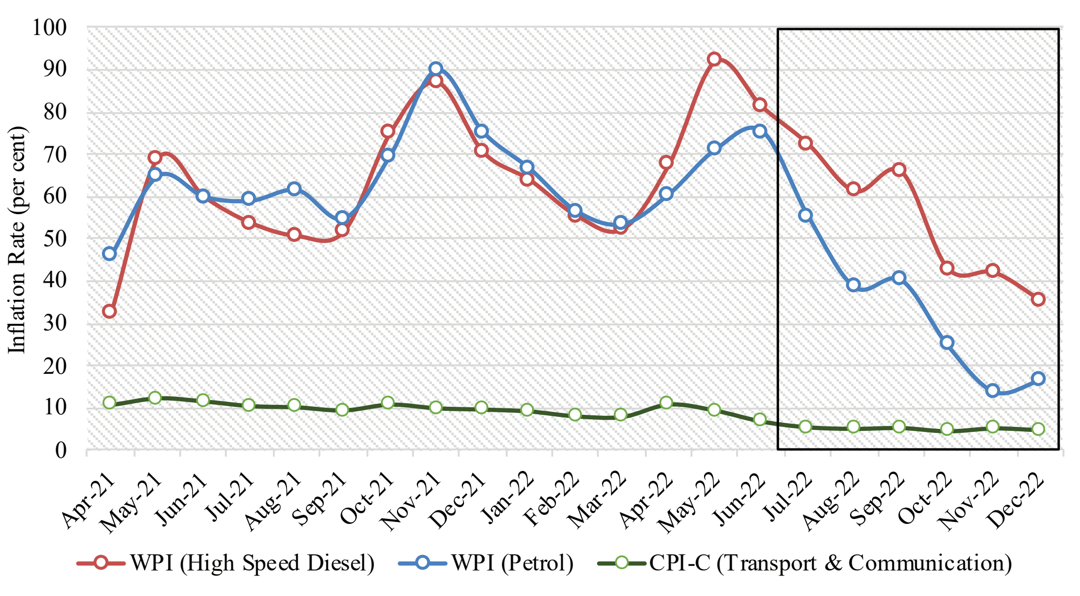

स्रोत: एमओएसपीआई और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी

मुद्रास्फीतिक संभावनाओं में गिरावट

5.27 मुद्रास्फीति को रेखांकित करने में मुद्रास्फीतिक संभावनाएं निर्णायक हैं। आरबीआई ने अपने भावी मार्गदर्शन और उत्तरदायी मौद्रिक नीति से मुद्रास्फीति संभावनाओं की एंकरिंग करके देश की मुद्रास्फीति के प्रक्षेप-पथ के मार्गदर्शन में मदद की है। व्यवसायों द्वारा आगामी वर्ष की मुद्रास्फीतिक संभावनाओं ने वर्तमान वित्त वर्ष में घटती प्रवृत्ति दर्शायी है। जैसा कि व्यवसाय मूल्य निर्धारित करता हैं, मुद्रास्फीति पर उनकी धारणा यह समझने में महत्वपूर्ण है कि क्या लागत को पारित किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप निकट भविष्य में कीमतें अधिक होंगी। इसी तरह, परिवारों द्वारा मुद्रास्फीतिक संभावनाओं - जो अर्थव्यवस्था के मूल्य स्वीकारकर्ता हैं- निकट भविष्य में उनके उपभोग विकल्पों का निर्धारण करते हैं। कारोबारों की तरह घरेलू महंगाई की संभावना में भी कमी आई है।

चित्र V.23: व्यापार और घरेलू मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं कम हो रही हैं

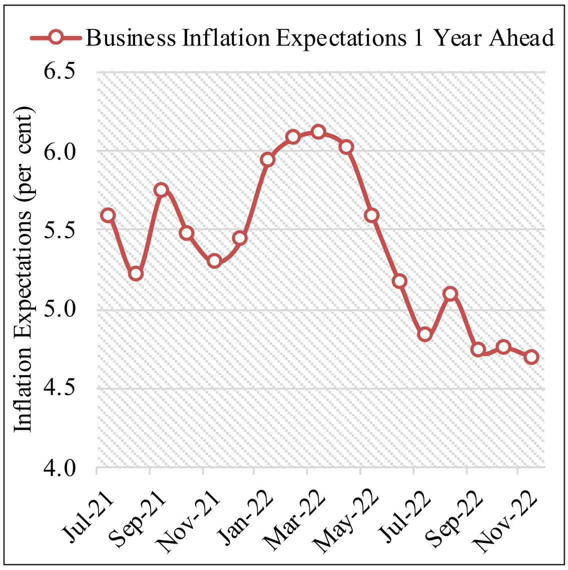

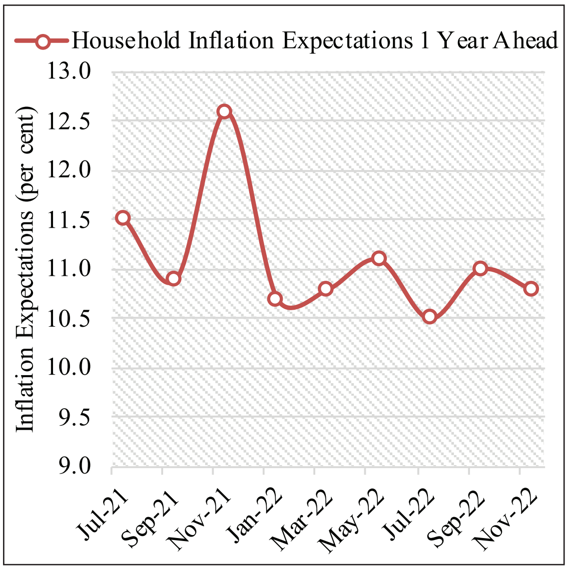

स्रोत: आईआईएम-ए और आरबीआई

मूल्य स्थिरता के लिए मौद्रिक नीतिगत उपाय

5.28 भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मई और दिसंबर, 2022 के बीच नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 2.25 प्रतिशत (225 आधार अंक) बढ़ाकर 4.0 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत कर दिया।

सारणी V.3: मौद्रिक नीति संबंधी विवरण- सख्त मौद्रिक नीति

एमपीसी विवरण की तारीख	एलएएफ के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर में परिवर्तन
8 अप्रैल, 2022	4 प्रतिशत पर यथावत
4 मई, 2022	4.0 प्रतिशत से बढ़कर 4.4 प्रतिशत (40 आधार अंक)
8 जून, 2022	4.4 प्रतिशत से बढ़कर 4.9 प्रतिशत (50 आधार अंक)
5 अगस्त, 2022	4.9 प्रतिशत से बढ़कर 5.4 प्रतिशत (50 आधार अंक)
30 सितंबर, 2022	5.4 प्रतिशत से बढ़कर 5.9 प्रतिशत (50 आधार अंक)
7 दिसंबर 2022	5.9 प्रतिशत से बढ़कर 6.25 प्रतिशत (35 आधार अंक)

स्रोत: आरबीआई।

बॉक्स V.3: वर्तमान मुद्रास्फीति 1970 के दशक से किस प्रकार भिन्न है?

वर्तमान वर्ष में अभूतपूर्व वैश्विक मुद्रास्फीति वर्ष 1970 के दशक के अनुभव को दोहराती है, विशेष रूप से वर्ष 1973 और वर्ष 1979 में तेल संकट के बाद। दोनों संकटों ने दुनिया भर में वस्तु की कीमतों में वृद्धि और अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर उनके विस्तारित प्रभाव में योगदान दिया। तथापि, संकट का वातावरण और तीव्रता विभिन्न संदर्भों में भिन्न है।

प्रथमत: हाल ही में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी 1970 के दशक के संकट की तुलना में आनुपातिक रूप से कम है, जिसने तेल की कीमतों को ऐतिहासिक ऊँचाई पर पहुंचा दिया था।

द्वितीयत: 1970 के दशक के संकट के विपरीत, जो तेल की कीमतों तक ही सीमित था, हाल के संकट में वस्तुओं की विस्तृत श्रेणी में व्यापक वृद्धि देखी गई है। वर्तमान वर्ष में गैर-तेल ऊर्जा, कुछ कृषि वस्तुओं, उर्वरकों और धातुओं की कीमतें अपने पूर्व-महामारी के स्तर से काफी ऊपर बढ़ गई हैं।

तृतीयत: वस्तु आपूर्ति व्यवधानों ने 1970 के दशक की तुलना में हाल की कीमत वृद्धि में छोटी भूमिका निभाई है। पिछले एक साल में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि सहित तेल के अतिरिक्त कई वस्तुओं के उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई है। चूंकि वर्ष 1970 के दशक की तुलना में वैश्विक वस्तु आपूर्ति श्रृंखला अब अधिक कुशल हो गई है और इसलिए, मुद्रास्फीति के दबाव को काफी आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। तथापि, आने वाले वर्ष में आपूर्ति व्यवधान तेज हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध के कारण गेहूँ, मक्का और उर्वरकों के वैश्विक उत्पादन को कम करेगा, जबकि रूसी तेल और गैस पर अधिकमत मूल्य इन उत्पादों की आपूर्ति को कम कर सकती है।

चतुर्थत: वैश्विक मुद्रास्फीति, जो वर्ष 2021 की शुरुआत के बाद से काफी बढ़ गई है, कई वर्षों के निम्न मुद्रास्फीति के बाद हुआ है। इसके विपरीत, 1973 का संकट कई वर्षों की पृष्ठभूमि से लगातार बढ़ती विश्व मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की उम्मीदों में न मिलते मुद्दों के संकेतों के कारण हुआ था।

अंततः 1973 के संकट ने ब्रेटन वुड्स द्वारा प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली के पतन का बारीकी से पालन किया गया था क्योंकि लक्ष्यों और यहाँ तक कि मौद्रिक नीति के उपकरणों को कई देशों में कमजोर तरीके से परिभाषित किया गया था। यकीनन, केंद्रीय बैंकों के पास अधिक स्पष्ट और अधिक मजबूत संस्थागत रूपरेखा हैं जो आज मूल्य स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसने वर्ष 2022 के दौरान मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि के बावजूद जनता की मुद्रास्फीति की संभावना को अनियंत्रित होने से रोका है।

वस्तु बाजार के रूख के अलावा, ऊर्जा की ऊंची कीमतें अतीत की तुलना में आज कम मायने रखती हैं। वैश्विक केंद्रीय बैंकों के बीच बेहतर समन्वय और अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरणों के अनुप्रयोग सहित, मुद्रास्फीति को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया गया है ताकि इसका नकारात्मक उतार-चढ़ाव सीमित और अस्थाई हो। सकल घरेलू उत्पाद की ऊर्जा तीव्रता - वस्तुओं और सेवाओं की निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा - 1970 के दशक के अंत से लगभग 40 प्रतिशत तक गिर गई है। साधन के लिए इनपुट बास्केट और गंतव्यों के विविधीकरण सहित, वस्तु पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कुछ हद तक नियंत्रित किया गया है। इसलिए, हम आशा कर सकते हैं कि 1970 के दशक की तुलना में हाल की वस्तु मूल्य वृद्धि कम विघटनकारी होगी।

स्रोत: बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स और वोक्स ईयू, 2022 द्वारा वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट, जून 2022

आवासन मूल्य: महामारी के बाद उभरता हुआ आवासन क्षेत्र

5.29 आवास की कीमतें आस्ति बाजारों में उतार-चढ़ाव के माध्यम से अर्थव्यवस्था की स्थिति पर उपयोगी जानकारी प्रदान करती हैं, जो आर्थिक असंतुलन उत्पन्न करती हैं। मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता और विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवास की कीमतों की निगरानी आवश्यक है। इन कीमतों में उतार-चढ़ाव घरेलू निधि और उपभोक्ता विश्वास पर इसके प्रभाव के माध्यम से उपभोग व्यय को प्रभावित करते हैं।

5.30 राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) वित्त वर्ष 18 को आधार वर्ष मानकर दो आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई), क्रमशः 'एचपीआई मूल्यांकन मूल्य' और 'एचपीआई बाजार मूल्य' त्रैमासिक प्रकाशित करता है। एचपीआई मूल्यांकन मूल्य प्राथमिक ऋण देने वाली संस्थाओं से एकत्रित आवासीय इकाइयों के मूल्यांकन मूल्यों पर आधारित है जबकि इसके विपरीत, एचपीआई बाजार मूल्य विकासक से न बेची गई सूची संग्रह के बाजार मूल्य पर आधारित है। भार के रूप में शहरों की जनसंख्या का उपयोग करके पूरे भारत के 50 शहरों के लिए समग्र सूचकांक की गणना की जाती है।

5.31 एचपीआई बाजार मूल्य में वार्षिक भिन्नता भुवनेश्वर में 37.7 प्रतिशत की वृद्धि से लेकर सितंबर, 21 को समाप्त तिमाही की तुलना में सितंबर 22 को समाप्त तिमाही (क्यूई) में इंदौर में 6.5 प्रतिशत के संकुचन तक थी। 50 शहरों में से 43 ने सूचकांक में वृद्धि दर्ज की, जबकि 7 शहरों में वार्षिक गिरावट देखी गई। देश के सभी आठ प्रमुख महानगरों, अर्थात अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में वार्षिक आधार पर सूचकांक में वृद्धि दर्ज की गई।

5.32 एचपीआई मूल्यांकन मूल्य में वार्षिक परिवर्तन अलग-अलग शहरों में व्यापक रूप से भिन्न है। जिसमें गांधीनगर में 20.2 प्रतिशत की वृद्धि से लेकर सितंबर, 22 को समाप्त तिमाही में सितंबर, 21 को समाप्त तिमाही की तुलना में भिवाड़ी में 2.3 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। 50 शहरों में से, 46 शहरों ने सूचकांक में वृद्धि दर्ज की, जबकि 4 शहरों में वार्षिक आधार पर गिरावट देखी गई। देश के सभी आठ प्रमुख महानगरों के सूचकांक में वार्षिक वृद्धि देखी गई।

चित्र V.24: मेट्रो शहरों के लिए एचपीआई – 'अहमदाबाद' और 'हैदराबाद' में उछाल

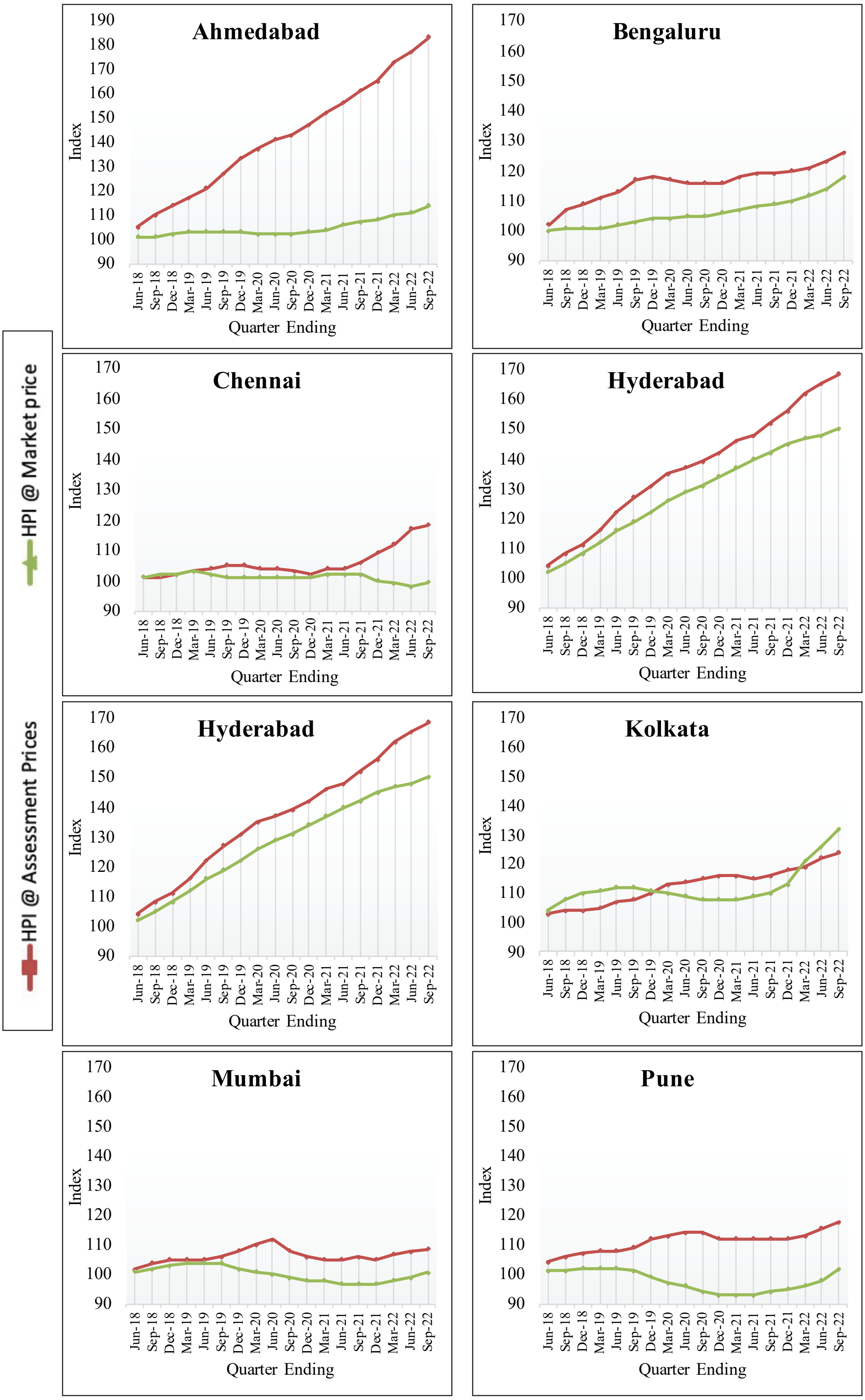

स्रोत: रेजीडेक्स, एनएचबी

चित्र V.25: अखिल भारतीय समग्र एचपीआई - आवास बाजार में सुधार

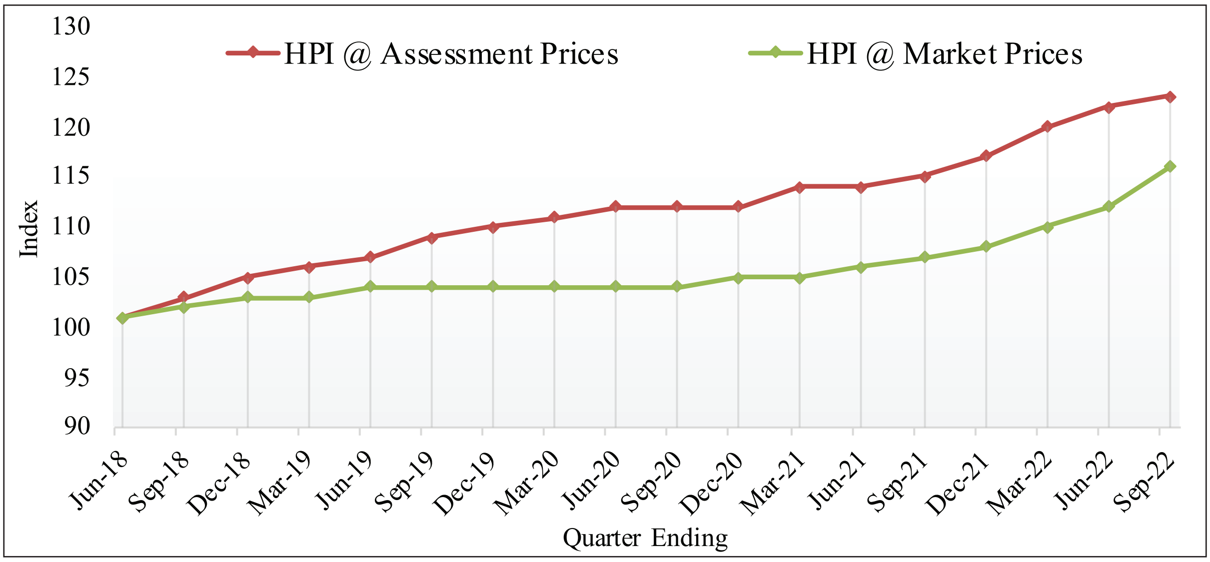

स्रोत: रेजीडेक्स, एनएचबी

5.33 कोविड-19 संकट ने आवासीय रियल एस्टेट बाजार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। अप्रैल-जून, 2020 में महामारी के प्रारंभिक चरण के दौरान स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और घर पर रहने के आदेशों के कारण घरों की तलाश करने वाले खरीदारों की संख्या कम हो गई थी। इसके बाद, भारत के रियल एस्टेट उद्योग ने सितंबर, 2020 से गति पकड़ी और मार्च, 2021 में समाप्त होने वाली तिमाही में चरम स्तर तक पहुंच गया। महामारी की दूसरी लहर ने रियल एस्टेट क्षेत्र को फिर से प्रभावित किया जब बढ़ती अनिश्चितता और प्रतिबंधित आवाजाही के कारण घर खरीदारों ने खरीदारी में देरी की। तथापि, होम लोन की कम ब्याज दरों के साथ सरकार द्वारा समय पर किए गए नीतिगत हस्तक्षेप से वित्त वर्ष 23 के वहनीय खंड की मांग और आकर्षित खरीदारों की संख्या में अधिक तीर्व गति से वृद्धि हुई। समग्र एचपीआई मूल्यांकन और एचपीआई बाजार कीमतों में समग्र वृद्धि, आवास वित्त क्षेत्र में पुनरुद्धार का संकेत देती है। एचपीआई में स्थिर से मध्यम वृद्धि भी संपत्ति के बरकरार मूल्य के संदर्भ में घर के मालिकों और गृह ऋण फाइनेंसरों को विश्वास प्रदान करती है।

बॉक्स V.4: आवासन वित्त क्षेत्र (एचएफसी) को एनएचबी समर्थन

आवासन क्षेत्र के लिए गत 3 वर्ष चुनौती पूर्ण थे। पिछले तीन वर्षों में आवासन वित्तीय क्षेत्र को हो रही नकदी संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए एनएचबी ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहचान किए गए, व्यैक्तिक आवास ऋण पोर्टफोलियो सृजित करने के लिए, जो प्राथमिकता क्षेत्र के तहत आता है, एचएफसी को समर्थन देने के लिए वर्ष 2019 में नकदी समायोजन सुविधा योजना शुरू की गई थी।
- कोविड-19 महामारी के दौरान आरबीआई द्वारा विशेष नकदी सुविधा के तहत प्रदान की गई ₹10000 करोड़ की राशि को वितरित करने के लिए विशेष पुनर्वित्तीय सुविधा (एसआरएफ) शुरू की गई थी और आरबीआई द्वारा अतिरिक्त विशेष नकदी सुविधा के तहत ₹5000 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी।
- वर्ष 2020-21 के दौरान आरबीआई द्वारा एसएलएफ-2 के तहत प्रदान की गई ₹10000 करोड़ की पूंजी के साथ एसआरएफ 2021 शुरू किया गया था। अपनी शुरूआत से एनएचबी ने ₹3.3 लाख करोड़ का पुनर्वित्तीय वितरण किया है, जिसमें से ₹0.84 लाख करोड़ विगत 03 वित्तीय वर्षों के दौरान वितरित किए थे।

- इसके अतिरिक्त आजादी का अमृत महोत्सव (एकएएम) के भाग के रूप में एनएचबी ने महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्रों, अजा/अजजा, महत्वकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्रों, तीसरे लिंग/दिव्यांगजन, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र एवं ग्रीन हाउसिंग सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए पुनर्वित्त के तहत 25/30 आधार बिंदु की छूट प्रदान की गई है।
- सीओपी26 में वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन तक पहुँचने की देश की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए एनएचबी ने ग्रीन हाउसिंग के तहत ऋणों हेतु 100 बीपीएस की छूट दी है।
- एकएएम के भाग के रूप में और भौगोलिक रूप से सुदूर स्थित क्षेत्रों, जो कि देश की प्राथमिकता हैं, में ऋण को बढ़ावा देने के लिए एनएचबी ने पहचाने गए महत्वकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्रों, तीसरे लिंग/दिव्यांगजन, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में सितम्बर, 2023 तक ऋणों हेतु 100 बीपीएस छूट पुनर्वित्त देने का निर्णय लिया है।

भेषज मूल्य निर्धारण को नियंत्रित रखना

5.34 दवाओं की कीमतों के विनियमन के सिद्धांत नेशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग पॉलिसी, 2012 पर आधारित हैं, जिसे भेषज विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है। नीति के प्रमुख सिद्धांत दवाओं की अनिवार्यता, सूत्रीकरण कीमतों पर नियंत्रण और बाजार आधारित मूल्य निर्धारण हैं। 31 दिसंबर, 2022 तक, विभिन्न चिकित्सीय श्रेणियों में 358 दवाओं के 890 सूत्रीकरणों के लिए राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम), 2015 द्वारा अधिकतम मूल्य निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनएलईएम, 2022 लागू किया और एनएलईएम, 2022 को शामिल करते हुए भेषज विभाग द्वारा दिनांक 11.11.2022 को संशोधित औषधी की अनुसूची 1 (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) अधिसूचित किया गया था। दिनांक 31 दिसम्बर 2022 तक एनएलईएम, 2022 के तहत 119 सूत्रीकरणों के अधिकतम मूल्य निर्धारित किए गए है। इसके अतिरिक्त, डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत 2,196 सूत्रीकरण के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित किए गए हैं।

5.35 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) सभी को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सभी को और विशेषतः गरीबों और वंचितों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जनऔषधि केंद्र के रूप में जाने जाने वाले प्रतिबद्ध दुकान खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) स्थायी और नियमित कमाई के अवसरों सहित स्वरोजगार भी प्रदान करते हैं। पीएमबीजेपी के अंतर्गत दिनांक 31 दिसंबर, 2022 तक देश भर में 9000 से अधिक पीएमबीजेके खोले जा चुके हैं। वर्तमान में, पीएमबीजेपी की उत्पाद बास्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध 1759 दवाएं और 280 शल्य चिकित्सा उपकरण शामिल हैं।

निष्कर्ष

5.36 यह कोई इच्छाकल्पित चिन्तन नहीं है कि वर्ष 2023 अपने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कम व्यापक आर्थिक अस्थिरता दिखाएगा। सीपीआई-सी और डबल्यूपीआई दोनों 6 प्रतिशत से नीचे गिर गए हैं (जो कि पूर्व के लिए आरबीआई की सहनशीलता की सीमा है) और वर्तमान वित्त वर्ष की पहली छमाही में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले उछाल के अवरोही ढलान पर हैं। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें, इस वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति के प्रमुख संवाहक, सामान्य स्तर पर लौट आए हैं और परिणामतः अन्य प्रमुख वस्तुओं की कीमतें भी सामान्य स्तर पर वापस आ गयी हैं। आरबीआई ने सामान्य मानसून की धारणा पर-वित्त वर्ष 24 की प्रथम तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति को 5.0 प्रतिशत और-वित्त वर्ष 24 की द्वितीय तिमाही के लिए 5.4 प्रतिशत अनुमान लगाया है।

5.37 भारत का मुद्रास्फीति प्रबंधन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है और इसकी तुलना उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से की जा सकती है जो अभी भी स्थिर मुद्रास्फीति दरों से जूझ रहे हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्याशित मंदी के कारण, वैश्विक वस्तु कीमतों से आने वाले मुद्रास्फीति जोखिम वित्त वर्ष 23 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में कम होने की संभावना है। तथापि, मुद्रास्फीति पर बेहतर आधारभूत दृष्टिकोण के लिए समग्र जोखिमों के संदर्भ में, भारत की ऊपर की ओर जाने वाली दरें अनुमानित नीचे की ओर जाने वाले जोखिमों पर भारी हो सकता है। उदाहरणार्थ चीन में कोविड-19 के फिर से उभरने से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, जैसा कि महामारी के दौरान हुआ था। दूसरी ओर, अगर चीन में कोविड-19 की स्थिति सामान्य होती है, तो वस्तु की माँग में उछाल आ सकता है - इस प्रकार वस्तु की कीमतों में हालिया गिरावट के स्थान पर उछाल देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना हाल के महीनों में बढ़ी है, और इससे तेल की अमेरिकी मांग में वृद्धि हो सकती है। इसी तरह, तेल से जुड़ी भू-राजनीति हमारी आयातित मुद्रास्फीति को विशेष रूप से प्रभावित कर सकती है।

5.38 आरबीआई ने आपूर्ति की कमी के कारण निकट भविष्य में अनाज और मसालों की घरेलू कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाया है। उच्च फीड लागत को दर्शाते हुए दूध की कीमतों में भी वृद्धि की उम्मीद है। सामान्य तौर पर, दुनिया भर में जलवायु तेजी से अनिश्चित हो गई है, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि का जोखिम और बढ़ गया है। बहुत कुछ औद्योगिक इनपुट कीमतों पर निर्भर करता है: वे कम हो सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर उपभोक्ता कीमतों में उनके विलंबित निकासी मूल मुद्रास्फीति की स्थिरता में अंशदान कर सकते हैं।

5.39 फिर भी, कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 24 में मुद्रास्फीति की चुनौती इस वर्ष की तुलना में काफी आसान होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि मौद्रिक और वित्तीय प्राधिकरण इस वर्ष की तरह ही सक्रिय और सतर्क रहेंगे।

******

06

अध्याय

सामाजिक अवसंरचना और रोजगारः व्यापक व्यवस्था

वैश्विक महामारी से होने वाले व्यापक, अप्रत्याशित व्यवधान के बाद वर्ष 2022 में जब मानवजाति ने पुनः करवट ली और धीरे-धीरे सामान्य होने के लिए हरकत में आई। हालाँकि, इस संकट के पश्चात की चुनौतियों, महामारी की उत्तरवर्ती प्रत्याशित अनुवर्ती हलचलों और चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष ने विश्व के साथ-साथ भारत के विकास पथ को भी प्रभावित किया है। नागरिकों के सामाजिक कल्याण जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा आदि जैसे प्रमुख पहलुओं पर जोर था और सरकार ने सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अपना सहयोग जारी रखा। वित्त वर्ष 23 के अंतिम पड़ाव पर सामाजिक विकास के विभिन्न संकेतकों की पुनः बहाली होती दिखाई दे रही है। मानव विकास के दीर्घकालिक लक्ष्यों और ''सबका साथ, सबका विकास'' पर ध्यान केंद्रित करना प्रमुख हो गया है। वित्त वर्ष 23 (बीई) में केंद्र और राज्य सरकारों का सामाजिक क्षेत्र व्यय परिव्यय लगातार बढ़कर 21.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो कि कुल सामान्य सरकारी व्यय का 26.6 प्रतिशत हिस्सा है।

2030 तक गरीबी को कम करने के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए ऑन-ट्रैक प्रोग्रेस के निरूपण में यूएन मल्टी डाइमेनशनल पावर्टी इंडेक्स (संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक) के अनुसार 2005-06 और 2019-21 के बीच 41 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आबादी के विभिन्न वर्गों जैसे बुजुर्गों, असंगठित श्रमिकों के लिए अनुकूलित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के समूह को समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए सम्मान की रक्षा को सुनिश्चित करने में प्राथमिकता दी गई है। 'आकांक्षी जिलों' पर विशेष ध्यान देने के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और बुनियादी सरंचना में लगातार सुधार हुआ है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से कल्याण योजना का लाभ पहुँचाने में 'जन धन खाता, आधार और मोबाइल जेएएम 'की त्रिमूर्ति ने सरकार-नागरिक संपर्क के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, केंद्रीय सरकार की 318 योजनाओं और राज्य सरकार की 720 से अधिक डीबीटी योजनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लक्षित वितरण को सक्षम बना दिया है, 'वन नेशन वन राशन कार्ड' और असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस 'ईश्रम पोर्टल' के माध्यम से राज्यों में राशन कार्ड की निर्बाध सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) आ गयी है श्रम बाजार के आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों को सम्मिलित करने वाले आंकड़ों में रोजगार संकेतकों में व्यापक सुधार देखा गया है।

आपूर्ति-पक्ष और मांग-पक्ष के रोजगार डेटा में यह देखा गया है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में श्रम बाजार पूर्व-कोविड स्तरों से काफी बेहतर हो गए हैं। त्रैमासिक शहरी रोजगार डेटा पूर्व-महामारी के स्तर से बेहतर प्रगति दर्शाता है क्योंकि जुलाई-सितंबर 2019 में बेरोजगारी दर 8.3 प्रतिशत से घटकर जुलाई-सितंबर 2022 में 7.2 प्रतिशत हो गई। रोजगार की बढ़ती औपचारिकता को दर्शाते हुए, कोविड-19 की स्थिति से तेजी से उबरने के बाद, ईपीएफओ पेरोल में निवल वृद्धि लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है, जिसमें अधिकांश हिस्सेदारी युवाओं की रही है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण वर्ष 2019-20 के अनुसार, संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार ने समय के साथ लगातार वृद्धि की है, साथ ही प्रति फैक्ट्री रोजगार

भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। छोटे कारखानों की तुलना में 100 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले कारखानों के रोजगार तेजी से बढ़ रहा है, जो विनिर्माण इकाइयों के विस्तार का सुझाव देता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस/MGNREGS) के काम की मासिक मांग में वर्ष-दर-वर्ष (वाईओवाई) गिरावट, मजबूत कृषि विकास और कोविड से तेजी से उबरने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति में लौट रही है।

ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) में वर्ष 2018-19 में 19.7 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2020-21 में 27.7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि एक सकारात्मक विकास है। विशेष रूप से, भारत की महिला एलएफपीआर को कम करके आंका गया है, कामकाजी महिलाओं की वास्तविकता को अधिक सटीक रूप से आंकने के लिए सर्वेक्षण डिजाइन और सामग्री में सुधार की आवश्यकता है। स्वयं-सहायता समूह, जिन्होंने कोविड के दौरान अपने लचीलेपन और लोच का प्रदर्शन किया है, जो काम करने के लिए महिलाओं की बढ़ती इच्छा का दोहन करने के लिए एक प्रभावी माध्यम हो सकते हैं। 1.2 करोड़ एसएचजी में 88 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं, जो 14.2 करोड़ परिवारों को सेवा देती हैं।

मानव पूंजी निर्माण के मोर्चे पर शिक्षा और स्वास्थ्य के जुड़वां स्तंभों को मूल रूप से सशक्त किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के प्रगतिशील ढांचे में, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार और शिक्षकों की बढ़ती उपलब्धता से लाभांश मिलने की उम्मीद है जो आने वाले दशकों में देश की वृद्धि और विकास की संभावनाओं को समृद्ध करेगा। सरकार ने स्वास्थ्य अवसंरचना को भी मजबूत किया है और वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद को तैयार किया है। नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए, कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा वित्तीय वर्ष 14 में 28.6 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 19 में 40.6 प्रतिशत हो गया है, इसके साथ-साथ वित्त वर्ष 2014 में कुल स्वास्थ्य व्यय के 64.2 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2019 में 48.2 प्रतिशत के प्रतिशत के रूप में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय में सहवर्ती गिरावट आयी है। पिछले आठ वर्षों में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मियों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बढ़ाने से उप-केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) की संख्या में काफी सुधार हुआ है। नतीजतन, स्वास्थ्य संबंधी संकेतक जैसे कि संस्थागत जन्म, टीकाकरण और स्वास्थ्य बीमा के कवरेज में वृद्धि देखी गई है, जैसा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़ों से पता चला है। लगभग 22 करोड़ से अधिक लाभार्थियों वाले पथ-प्रदर्शक आयुष्मान भारत कार्यक्रम की प्रगति को डिजिटल हेल्थ आईडी एबीएचए और ई-संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन के माध्यम से और अधिक तकनीक-सक्षम बनाया जा रहा है।

अमृत काल में, ग्रामीण भारत में रहने वाली दो-तिहाई भारतीय आबादी का जीवन कुछ साल पहले की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बेहतर है, जो बुनियादी सुविधाओं और कुशल कार्यक्रम कार्यान्वयन पर दिए गए नीतिगत फोकस से प्राप्त हुआ है। ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता से संबंधित परिणाम-उन्मुख आंकड़े बिजली तक पहुंच, बेहतर पेयजल स्रोतों की उपस्थिति, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत कवरेज, महिला सशक्तिकरण आदि में ठोस प्रगति की पुष्टि करते हैं। स्वामित्व के माध्यम से डिजिटल भूमि रिकॉर्ड पर जोर एक संरचनात्मक सुधार है।

ग्रामीण भूमि प्रबंधन और व्यक्तिगत आर्थिक सशक्तिकरण भारत के आगे बढ़ने के साथ ही उसने महामारी के कारण सामाजिक क्षेत्र के सुधार संबंधी लाभ को बड़े पैमाने पर पुन: प्राप्त कर लिया है। जो त्वरित नीति निर्धारण और कुशल कार्यान्वयन द्वारा संचालित है, और जो प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ा हुआ है। आगामी आर्थिक विकास के लिए 'न्यूनतम सरकार; अधिकतम शासन', अधिक न्यायसंगत सिद्ध होंगे।

परिचय

6.1 भारत का सामाजिक-आर्थिक परिवेश और अद्वितीय लोकाचार उसकी असंख्य संस्कृतियों, भाषाओं और भुगोल वाली विविध और विशाल आबादी में बसते हैं, जो देश की वास्तविक संपदा हैं। कई शहरों और गांवों में रहने वाले युवा और आकांक्षी नागरिकों द्वारा पोषित अपार संभावनाओं का एहसास करने और परिस्थितियों की विविधता और विभिन्न वर्गों की विशेष आवश्यकताओं के अनुकूलन के लिए महत्वाकांक्षी दृष्टि और सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन की आवश्यकता है। प्रारंभ में 21 वीं सदी के भारतीय की मंथन ऊर्जा को चौनलाइज करने के लिए प्रत्येक घर में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, आवास, कनेक्टिविटी आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं पहली आवश्यकता है। आधारभूत सेवाएं और संरचनाएं जो जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने में समाज की सहायता करती हैं, यानी सामाजिक आधारभूत संरचना, अप्रत्यक्ष रूप से आय और रोजगार के अवसरों, उत्पादकता वृद्धि और तकनीकी उन्नति में वृद्धि की नींव रखकर आर्थिक विकास में योगदान करती है। उक्त अनुसार, गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर और काम करने की स्थितियां इस क्षमता के दीर्घकालिक सतत विकास के रुप में तराशने के लिए आवश्यक उपकरण हैं। अगले 25 वर्षो के अपने अमृत काल में, भारत को जनसांख्यिकी से होने वाले लाभ मिलने की संभावना है।

6.2 अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के होने से जीवन की गुणवत्ता की अवधारणा में आय के पारंपरिक मेट्रिक्स (जो भोजन और आश्रय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की उपलब्धता निर्धारित करती है) और शिक्षा के स्तर की तुलना में कई और तत्वों को समाहित किया है। अब इसमें स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, रोजगार की संभावनाएं, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, कनेक्टिविटी आदि तक की पहुंच शामिल है। ये सभी मिलकर जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। अनुसंधान अध्ययनों ने निष्कर्ष निकला है कि जीवन की गुणवत्ता बुनियादी जरूरतों की पूर्ति और अनुकूल वातावरण में रहने में सक्षम होने पर निर्भर करती है।[1] इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार देश के सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास को उच्च प्राथमिकता देती है।

6.3 समकालीन परिदृश्य में यह और अधिक प्रासंगिक है क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) 2030 को अपनाया है, जो व्यापक, दूरगामी और जन- केंद्रित सार्वभौमिक और परिवर्तनकारी लक्ष्य और ध्येय है। इन सत्रह लक्ष्यों में से कई लक्ष्य व्यक्तियों की सामाजिक रहन-सहन से संबंधित हैं, जिनका समाधान निम्नानुसार है:

"हम अब और 2030 के बीच हर जगह गरीबी और भुखमरी को खत्म करने, देशों के अंदर और उनके बीच असमानताओं का मुकाबला करने; शांतिपूर्ण, न्यायसंगत और समावेशी समाज बनाने; मानव अधिकारों की रक्षा और लैंगिक समानता और महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने; और ग्रह और उसके प्राकृतिक संसाधनों की स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संकल्प लेते हैं। हम राष्ट्रीय विकास और क्षमताओं के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए सतत, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, साझा समृद्धि और सभी के लिए कामकाज की बेहतर स्थितियां बनाने का भी संकल्प लेते हैं।''[2]

6.4 देश पिछले दशकों में आय बढ़ाने और जीवन स्तर में सुधार करने में अच्छी प्रगति कर रहा है। जैसा कि अध्याय में विस्तार से बताया गया है, कई सामाजिक संकेतकों में सुधार जारी है। वर्ष 2020 और 2021 महामारी के चरम वर्ष थे, जिनमें देश के सामाजिक और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की ताकत, का परीक्षण हुआ, शिक्षा में बाधा आई, नौकरी के अवसरों आदि नुकसान हुआ, आदि। इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर महामारी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए कई उपाय किए गए जो 2022 में जारी रहे। वित्त वर्ष 23 इस क्षेत्र के लिए कायाकल्प का वर्ष रहा है, जिसमें महामारी के तूफान को पछाड़ दिया और मजबूत होकर उभरा। इस क्षेत्र के विभिन्न आयाम खोए हुए आधार को पुन: प्राप्त कर रहे हैं और ''*सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास*'' के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए पुन: सक्रिय किया जा रहा है।

---

[1]उदाहरण के लिए: मार्था नुसबौम और अमर्त्य सेन, संस्करण। (1993)। जीवन की गुणवत्ता, ऑक्सफोर्ड: क्लेरेंडन प्रेस। और बारकासिया, बारबरा (4 सितंबर 2013)। ''जीवन की गुणवत्ता: हर कोई इसे चाहता है, लेकिन यह क्या है?''। फोर्ब्स/एजुकेशन।

[2]हमारी दुनिया को बदलना: सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा, 25 सितंबर 2015 को महासभा द्वारा अपनाया गया संकल्प।

6.5 भारत बेहतर सुविधाओं से लैस स्कूलों, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, बढ़ते औपचारिक रोजगार, सशक्त महिला समूहों और स्वच्छता, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं तक दूरगामी पहुंच के साथ अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। यह अध्याय इन मोर्चों पर उपलब्धियों के उभरते प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसमें सामाजिक बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर प्रगति और देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की समीक्षा की गई है। इसमें सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें सामाजिक क्षेत्र पर सरकार के व्यय के रुझान; मानव विकास के मोर्चे पर प्रगति; सभी नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताएं सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय रोजगार और शिक्षा के रुझान और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन और शासन की गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। यह विभिन्न एसडीजी और उसके परिणामों को प्राप्त करने की दिशा में विभिन्न सरकारी पहलों पर आधारित है।

क्षेत्र के बढ़ते महत्व को गति देने के लिए सामाजिक क्षेत्र व्यय

6.6 सामाजिक सेवाओं पर होने वाले सरकार के खर्च में वृद्धि दर्शायी गई है।[3] वित्त वर्ष 2016 से देश के नागरिकों के सामाजिक हित के कई पहलुओं पर ध्यान देते हुए वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 20 तक सरकार के कुल खर्च में सामाजिक सेवाओं पर खर्च का हिस्सा करीब 25 फीसदी रहा है। वित्त वर्ष 23 (बीई) में यह बढ़कर 26.6 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाओं के व्यय में वित्त वर्ष 2011 की बनिस्पत वित्त वर्ष 2012 में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वित्त वर्ष 21 बनिस्पत वित्त वर्ष 2012 में 31.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, महामारी के वर्षों में, विशेष रूप से स्वास्थ्य[4] और शिक्षा[5] क्षेत्रों के परिव्यय में वृद्धि की आवश्यकता थी। जबकि वित्त वर्ष 19 में केंद्र और राज्य सरकारों का सामाजिक क्षेत्र का व्यय परिव्यय 12.8 लाख करोड़ रुपये था, यह धीरे-धीरे बढ़कर वित्त वर्ष 23 (बीई) में 21.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

चित्र VI.1: सामान्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्र व्यय में रुझान (केंद्र और राज्य संयुक्त रुप में)

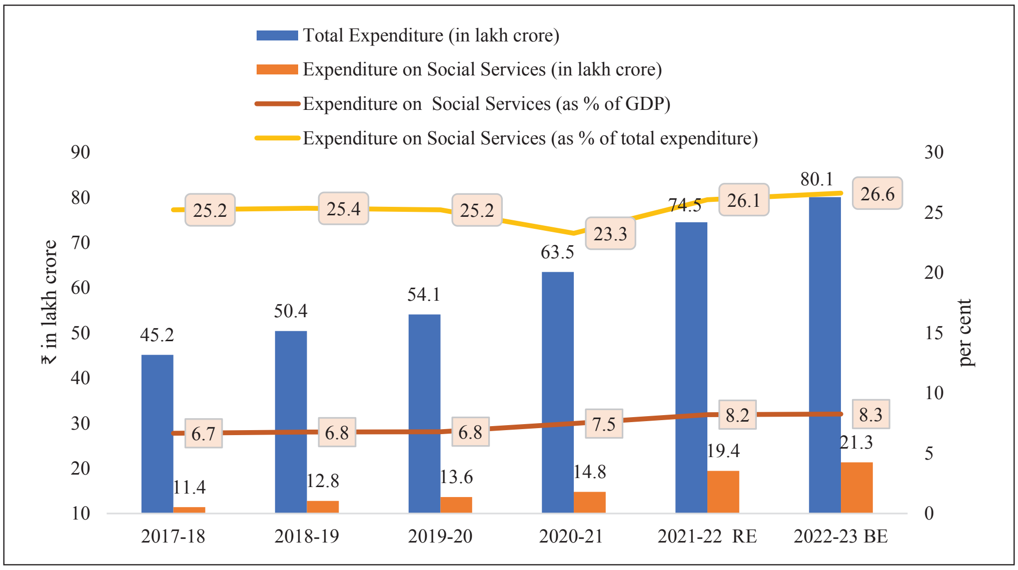

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, संघ और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

टिप्पणी: 1. बजट अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आरई)।

2. मौजूदा बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात 2011-12 के आधार पर आधारित हैं।

3. बीई, वित्त वर्ष 22 के लिए अनुमानित जीडीपी ₹222,87,379 करोड़ है।

[3]सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति शामिल हैं; चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण; जल आपूर्ति और स्वच्छता; आवास; शहरी विकास; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण, श्रम और श्रमिक कल्याण; सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, पोषण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत आदि।

[4]'स्वास्थ्य' पर व्यय में 'चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य', 'परिवार कल्याण' और 'जल आपूर्ति और स्वच्छता' पर व्यय शामिल है।

[5]'शिक्षा' पर व्यय 'शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति' पर व्यय से संबंधित है।

6.7 सामाजिक सेवाओं के कुल व्यय में स्वास्थ्य पर खर्च का हिस्सा 21 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 23 (बीई) में 26 प्रतिशत हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 अपने लक्ष्य के रूप में सभी विकासात्मक नीतियों में एक निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल उन्मुखीरण के माध्यम से "सभी उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति, और परिणाम के रूप में किसी को भी वित्तीय कठिनाई दिए बिना अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच" के रूप में परिकल्पना करती है। पहुंच को बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार करने और स्वास्थ्य सेवा वितरण की लागत को कम करके प्राप्त किया जाएगा। तद्नुसार, नीति में 2025 तक सरकार के स्वास्थ्य व्यय को मौजूदा 1.2 प्रतिशत से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत करने की सिफ़ारिश की है। साथ ही, पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि संघ और राज्यों का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय एक साथ मिलाकर प्रगतिशील तरीके से 2025 तक जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए (एफएफसी रिपोर्ट, पैरा 9.41, पपप)। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकारों का बजटीय व्यय वित्त वर्ष 2023 (बीई) में जीडीपी के 2.1 प्रतिशत और वित्त वर्ष 22 (आरई) में 2.2 प्रतिशत तक पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 21 में यह 1.6 प्रतिशत था।

तालिका VI.1: सामान्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवा व्यय का रुझान (केंद्र और राज्य संयुक्त रुप में)

(₹ करोड़ में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 आरई	2022-23 ब.अ
कुल व्यय	3760611	4265969	4515946	5040747	5410887	6353359	7453320	8008684
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	915500	1040620	1139524	1278124	1364906	1479389	1944013	2132059
जिसमें :								
शिक्षा	391881	434974	483481	526481	579575	575834	681396	757138
स्वास्थ्य	175272	213119	243388	265813	272648	317687	516427	548855
अन्य	348348	392527	412655	485829	512683	585868	746191	826065
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में								
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	6.6	6.8	6.7	6.8	6.8	7.5	8.2	8.3
जिसमें :								
शिक्षा	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9
स्वास्थ्य	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	2.2	2.1
अन्य	2.5	2.6	2.4	2.6	2.6	3.0	3.2	3.2
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में								
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	24.3	24.4	25.2	25.4	25.2	23.3	26.1	26.6
जिसमें :								
शिक्षा	10.4	10.2	10.7	10.4	10.7	9.1	9.1	9.5
स्वास्थ्य	4.7	5.0	5.4	5.3	5.0	5.0	6.9	6.9
अन्य	9.3	9.2	9.1	9.6	9.5	9.2	10.0	10.3
सामाजिक सेवाओं के प्रतिशत के रूप में								
शिक्षा	42.8	41.8	42.4	41.2	42.5	38.9	35.1	35.5
स्वास्थ्य	19.1	20.5	21.4	20.8	20.0	21.5	26.6	25.7
अन्य	38.0	37.7	36.2	38.0	37.6	39.6	38.4	38.7

2021-22 तक की मौजूदा बाजार कीमतों की जीडीपी का अनुपात 2011-12 पर आधारित हैं। 2022-23 के लिए जीडीपी केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार है।

स्रोत: संघ और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

मानव विकास मानदंडों में सुधार करना

6.8 ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के लिए 'मानव विकास' एक प्रमुख प्रवर्तक है। 2020 और 2021 में कोविड-19 महामारी के चरम के बाद उत्पन्न चुनौतियों और 2022 में आगामी रूस-यूक्रेन संघर्ष ने भारत और दुनिया के विकास पथ को प्रभावित किया है। इन विकासों के मद्देनजर, मानव विकास में वैश्विक गिरावट आई थी। इन विकासों के मद्देनजर, मानव विकास में वैश्विक गिरावट आई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की रिपोर्ट के अनुसार, 90 प्रतिशत देशों ने 2020 या 2021 में अपने मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)[6] मूल्य में कमी दर्ज की है जो यह दर्शाता है कि दुनिया भर में मानव विकास विगत 32 वर्षों में पहली बार ठप हुआ है। वर्ष 2021/2022 एचडीआई की रिपोर्ट[7] में भारत 191 देशों और क्षेत्रों में 132 वें स्थान पर है। वर्ष 2021 में भारत का एचडीआई मान 0.633 देश को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखता है, जो 2019 में इसके मान 0.645 से कम है। हालांकि, भारत का एचडीआई मान दक्षिण एशिया[8] के औसत मानव विकास से अधिक है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य और शिक्षा सुनिश्चित करने सहित सामाजिक बुनियादी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता देने के कारण 1990 के बाद से यह लगातार वृद्धि कर रहा है और विश्व औसत की ओर बढ़ रहा है।

6.9. लैंगिक असमानता के पैरामीटर पर, भारत का लैंगिक असमानता सूचकांक (GII)[9] मान 2021 में 0.490 है और भारत 122 वें स्थान पर है। यह स्कोर दक्षिण एशियाई क्षेत्र (मान : 0.508) से बेहतर है और विश्व औसत 0.465 के करीब है। यह अधिक समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा और लिंग-उत्तरदायी विकास नीतियों की दिशा में सरकार की पहल और निवेश को दर्शाता है। बहुआयामी गरीबी से निपटने में देश की प्रगति बॉक्स VI-1 में दर्शाई गई है।

तालिका VI.2: वैश्विक एचडीआई 2021 में भारत की स्थिति एवं रुझान

	एचडीआई 2021		एचडीआई रैंक 2020	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष	स्कूली शिक्षा के अनुमानित वर्ष	प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय
	रैंक	मान					
स्विट्जरलैंड	1	0.962	3	84.0	16.5	13.9	66,933
नॉर्वे	2	0.961	1	83.2	18.2	13.0	64,660
यूनाइटेड किंगडम	18	0.929	17	80.7	17.3	13.4	45,225
जापान	19	0.925	19	84.8	15.2	13.4	42,274
संयुक्त राज्य अमेरिका	21	0.921	21	77.2	16.3	13.7	64,765
चीन	79	0.768	82	78.2	14.2	7.6	17,504
ब्राजिल	87	0.754	86	72.8	15.6	8.1	14,370
दक्षिण अफ्रीका	109	0.713	102	62.3	13.6	11.4	12,948
इंडोनेशिया	114	0.705	116	67.6	13.7	8.6	11,466
भारत	**132**	**0.633**	**130**	**67.2**	**11.9**	**6.7**	**6,590**
दक्षिण एशियाई क्षेत्र		0.632		67.9	11.6	6.7	6,481
विश्व औसत		0.732		71.4	12.8	8.6	16,752

स्रोत: 2021/2022 मानव विकास रिपोर्ट, यूएनडीपी

[6] यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट तीन बुनियादी मापदंडों के संदर्भ में एचडीआई का अनुमान लगाती है: एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए; शिक्षित और जानकार होना और जीवन के सभ्य आर्थिक स्तर का लाभ लेना। इसकी गणना 4 संकेतकों का उपयोग करके की जाती है – जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति जीएनआई।
[7] 8 सितंबर 2022 को जारी किया गया और वर्ष 2021 के लिए रैंकिंग प्रदान करता है।
[8] दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, इस्लामिक गणराज्य ईरान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका शामिल हैं।
[9] सूचकांक महिलाओं और पुरुषों के बीच उपलब्धि में असमानता को तीन आयामों में मापता है, अर्थात प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार। यह इन आयामों में महिला और पुरुष की उपलब्धियों के बीच असमानता के कारण संभावित मानव विकास में कमी को दर्शाता है। जीआईआई का मान 0 होता है जहां महिला और पुरुष के साथ समान व्यवहार होता है। इसका मान 1 होता है, जहां लैंगिक भेदभाव होता है।

बॉक्सः VI-1: यूएनडीपी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022

आम तौर पर, गरीबी को मुख्य रूप से एक अच्छी तरह जीवन यापन के लिए मौद्रिक साधनों की कमी के रूप में मापा जाता है। हालाँकि, परिभाषा के अनुसार 'गरीबी' के व्यापक निहितार्थ हैं और एक ही समय में कई नुकसान होते हैं – जैसे कि खराब स्वास्थ्य या कुपोषण, स्वच्छता की कमी, स्वच्छ पेयजल या बिजली, शिक्षा की खराब गुणवत्ता आदि। अकेले एक कारक पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे आय के रूप में, गरीबी की वास्तविकता को पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए अधिक व्यापक तस्वीर बनाने के लिए बहुआयामी गरीबी उपायों का उपयोग किया जाता है। यह बताता है कि कौन गरीब है और कैसे गरीब है और उनके द्वारा अनुभव किए गए विभिन्न अभावों की सीमा। ऐसा ही एक उपाय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) है जो 100 से अधिक विकासशील देशों में तीव्र बहुआयामी गरीबी को मापता है। कार्यप्रणाली में तीन समान भारित आयामों: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में 10 संकेतकों में प्रत्येक व्यक्ति के अतिव्यापी अभावों को मापना शामिल है। स्वास्थ्य और शिक्षा आयाम प्रत्येक दो संकेतकों पर आधारित हैं, जबकि जीवन स्तर छह संकेतकों पर आधारित है। किसी देश के लिए MPI के निर्माण के लिए आवश्यक सभी संकेतक एक ही घरेलू सर्वेक्षण से लिए गए हैं। प्रत्येक संकेतक को उसके आयाम के भीतर समान रूप से भारित किया जाता है, इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक प्रत्येक को 1/6 भारित किया जाता है, और जीवन स्तर संकेतकों को 1/18 भारित किया जाता है। एमपीआई 0 से 1 तक होता है, और उच्च मूल्य उच्च बहुआयामी गरीबी का संकेत देते हैं। डच्ब् अंतर्राष्ट्रीय ेन्+ 1.90–दिन की गरीबी रेखा को यह पहचान कर पूरा करता है कि कौन बहुआयामी रूप से गरीब है और बहुआयामी गरीबी की संरचना को दर्शाता है।

भारत के लिए एमपीआई

एमपीआई पर यूएनडीपी की 2022 की रिपोर्ट अक्टूबर 2022 में जारी की गई थी और इसमें 111 विकासशील देशों को शामिल किया गया था। जहां तक भारत का संबंध है, 2019–21 के सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। इन अनुमानों के आधार पर, भारत में 16.4 प्रतिशत आबादी (2020 में 228.9 मिलियन लोग) बहुआयामी रूप से गरीब हैं, जबकि अतिरिक्त 18.7 प्रतिशत को बहुआयामी गरीबी (2020 में 260.9 मिलियन लोग) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत में वंचितता की तीव्रता, जो कि बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों के बीच औसत अभाव स्कोर है, 42 प्रतिशत है। MPI मान, आबादी का वह हिस्सा है जो बहुआयामी रूप गरीब हैं जिसे बंचीतों की तीव्रता 0.69 से समायोजित हैं।

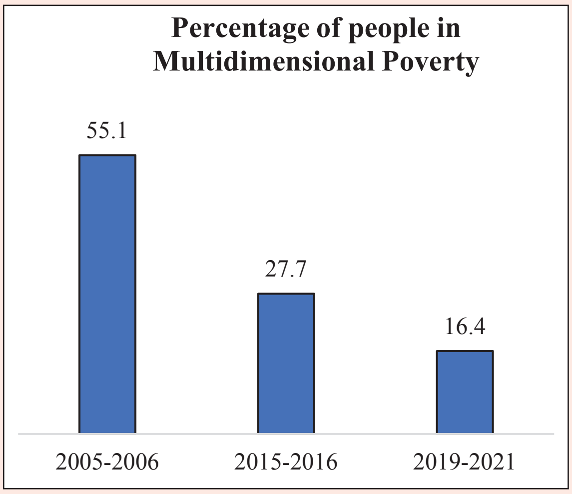

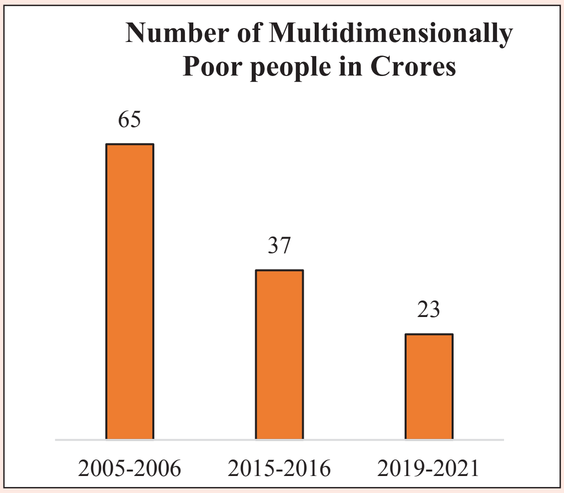

Source: UNDP Report on Multidimensional Poverty, 2022

रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी की तुलना मौद्रिक गरीबी के साथ की गई है, जिसे 2011 के पीपीपी यूएस + 1.90 प्रति दिन से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत से मापा जाता है। यह दर्शाता है कि मौद्रिक गरीबी पूरी तस्वीर पेश नहीं करती है। बहुआयामी गरीबी की संख्या या घटना मौद्रिक गरीबी की घटना की तुलना में 6.1 प्रतिशत अंक कम है। इसका तात्पर्य यह है कि मौद्रिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की गैर-आय संसाधनों तक पहुंच हो सकती है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष बताते हैं कि भारत में 2005-06 और 2019-21 के बीच 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, यह दर्शाता है कि एसडीजी लक्ष्य 1.2 में रहने वाले सभी उम्र के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अनुपात को कम से कम आधा करने का है। राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार 2030 तक गरीबी को उसके सभी आयामों में प्राप्त करना संभव है।

सबसे गरीब राज्यों और समूहों (बच्चों, निचली जातियों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों) ने गरीबी को पूर्ण रूप से सबसे तेजी से कम किया, हालांकि डेटा कोविड-19 महामारी के बाद के बदलावों को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

बहुआयामी रूप से गरीबों के बीच, वंचन श्रेणियों में वंचन प्रसार में गिरावट आई है।

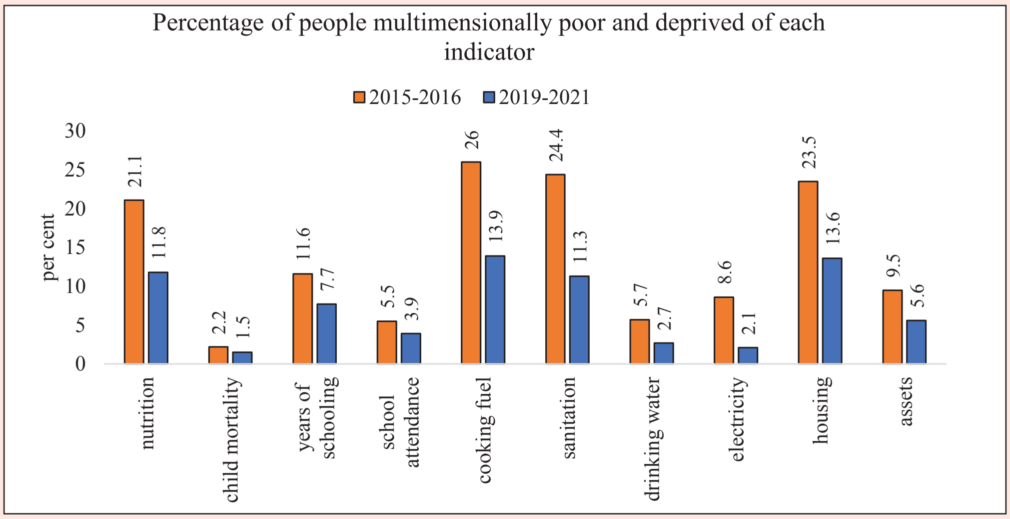

जमीनी स्तर पर चीजें कैसे बदल रही हैं, इसका एक उदाहरण देते हुए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के अध्यक्ष डॉ. सुदीप्तो मुंडले ने एक समाचार पत्र के लेख 'पेरीफेरी पर गांव और पिछड़ेपन का बदलता चेहरा', लाइव मिंट, में 24 नवंबर 2022 को सूचित किया है कि उन्होने झारखंड के चार पिछड़े गांवों की यात्रा की और सड़क, घर, डिजिटल कनेक्टिविटी, पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), शिक्षा सुविधाओं आदि जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति के बारे में अध्ययन किया। राज्य और सामान्य बाजार के हस्तक्षेप से इन गांवों में सामान्य बाजार विकास, अत्यधिक अभाव और भूख को समाप्त कर दिया गया है।[10]

आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम का परिवर्तन

6.10 भारत सरकार ने 2022 तक एक नए भारत के विजन के साथ जनवरी 2018 में 'आकांक्षी जिलों का परिवर्तन' (एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम (एडीपी)) पहल शुरू की, जिसमें अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सभी की बढ़ती अर्थव्यवस्था में। जिलों को पहले अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ जिलों के साथ पकड़ने के लिए प्रोत्साहित और प्रोत्साहित किया जाता

[10]https://www.livemint.com/opinion/online-views/villages-at-the-periphery-and-the-change-face-of-backwardness-11669313591060.html

है, और बाद में प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना से प्रतिस्पर्धा करके और दूसरों से सीखकर देश में सर्वश्रेष्ठ बनने की आकांक्षा रखते हैं।

6.11 नीति आयोग द्वारा 28 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 117 आकांक्षी जिलों (एडी) की पहचान स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, और बुनियादी ढांचे से लेकर समग्र संकेतकों के आधार पर की गई है, जिनका एचडीआई पर असर पड़ता है। कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा अभिसरण (केंद्रीय और राज्य योजनाओं का), सहयोग (केंद्रीय, राज्य स्तर के नोडल अधिकारियों और जिला कलेक्टरों का), और मासिक जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से सभी एक जन आंदोलन द्व ारा संचालित है।

6.12 मुख्य संचालको के रूप में राज्यों के साथ, यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले की ताकत पर ध्यान केंद्रित करता है, तत्काल सुधार के लिए कम लटके ऱलों की पहचान करता है और हर महीने जिलों की रैंकिंग करके प्रगति को मापता है। रैंकिंग ऊपर वर्णित पांच व्यापक सामाजिक-आर्थिक विषयों के तहत 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) में हुई वृद्धिशील प्रगति पर आधारित है।

6.13 नीति आयोग ने जिला योजनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक खाका विकसित किया है। चूंकि विभिन्न जिलों में अलग-अलग अवसर और चुनौतियां हैं, इसलिए उन्हें सलाह दी गई है कि वे टेम्पलेट को अनुकूलित करें। केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों की मदद से संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त जानकारी से संकलित प्रत्येक संकेतक में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों को शामिल करते हुए एक प्राइमर भी विकसित किया गया है और इसे जिला प्रशासन के साथ साझा किया गया है।

6.14 कार्यक्रम की उपलब्धियां

(क) कार्यक्रम के तहत मॉनिटर किए गए स्वास्थ्य और पोषण विषय के तहत कई संकेतकों में कई एडी ने औसत राज्य मूल्यों को पार कर लिया है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य के 10 संकेतकों में, 73 एडी ने राज्य के औसत को पार कर लिया है।

(ख) कार्यक्रम पांच फोकस क्षेत्रों में प्रगति पर नजर रखता है। सभी जिलों ने विभिन्न संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार किया है, उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य और पोषण के तहत, 46 जिलों में 45 प्रतिशत तक सुधार हुआ है, और 23 जिलों में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण संकेतकों में 69 प्रतिशत तक सुधार हुआ है। मातृ और शिशु मृत्यु दर पर प्रभाव जैसे कि प्रसवपूर्व देखभाल जांच की आवृत्ति और कवरेज; गर्भवती महिलाओं द्वारा पूरक पोषण सेवन की नियमितता, और समय पर एनीमिया का पता लगाने और उपचार की दर।

शिक्षा के तहत, 46 जिलों में 34 प्रतिशत तक सुधार हुआ है, और 29 जिलों में महत्वपूर्ण संकेतकों में 49 प्रतिशत तक सुधार हुआ है, जो छात्रों द्वारा प्राप्त सीखने के परिणामों को प्रभावित करते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का अनुपालन करने वाले प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत (आरटीई) निर्दिष्ट छात्र-शिक्षक अनुपात; कार्यात्मक पेयजल सुविधा वाले स्कूलों का प्रतिशत और कार्यात्मक लड़कियों के शौचालयों वाले स्कूलों का प्रतिशत।

(ग) वित्तीय समावेशन के परिणाम की निगरानी करते समय, यह देखा गया कि एडी ने गैर-आकांक्षी जिलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका मतलब है कि अधिक लोगों की बैंक खातों तक पहुंच है, अधिक लोगों को सरकारी बीमा योजनाओं के तहत कवर किया गया है और अधिक लोग एडी में मुद्रा (एमयूडीआरए) ऋण सुरक्षित कर सकते हैं।

(घ) कई एडी ने बिजली कनेक्शन वाले परिवारों के प्रतिशत जैसे बुनियादी बुनियादी ढांचे के संकेतकों में संतृप्ति

की सूचना दी है; प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बारहमासी सड़कों तक पहुंच वाली बस्तियों का प्रतिशत; पीएमजीएसवाई के तहत जिले में कुल स्वीकृत किलोमीटर के प्रतिशत के रूप में पूर्ण किए गए बारहमासी सड़क कार्य के किलोमीटर की संचयी संख्या; और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों वाले परिवारों का प्रतिशत, आदि।

सुशासन का नमूना

6.15 एडीपी सुशासन के लिए एक टेम्पलेट के रूप में उभरा है, विशेष रूप से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में। वर्तमान में, एडीपी डिजाइन की तर्ज पर दो कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई है, एक है 'मिशन उत्कर्ष' और दूसरा है 'एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम' (एबीपी)। 22 जनवरी 2022 को 'मिशन उत्कर्ष' की शुरुआत की गई, जिसके तहत 15 केंद्रीय मंत्रालयों ने जनता से संपर्क कर अपने कम प्रदर्शन करने वाले 10-15 जिलों की पहचान की है. एडीपी टेम्पलेट के बाद, मंत्रालयों ने इन जिलों को एक वर्ष में राज्य के एक औसत जिले के बराबर और दूसरे में अखिल भारतीय औसत के करीब लाने के लिए कार्रवाई शुरू की है।

6.16 केंद्र सरकार और राज्य पिछड़े ब्लॉकों की पहचान करने के लिए एडीपी टेम्पलेट का उपयोग करने के लिए एक साथ आए हैं और देश में सबसे कम विकसित ब्लॉकों में सुधार के लिए समान डेटा निगरानी और प्रतिस्पर्धा आधारित कार्यक्रम का उपयोग करते हैं। इस पहल को और अधिक मजबूत बनाने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 500 सबसे पिछड़े ब्लाकों को तेजी से विकास के लिए चुना गया है।

प्रगामी श्रम सुधार उपाय

6.17 2019 और 2020 में, 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समामेलित, युक्तिसंगत और सरल बनाया गया था, अर्थात, मजदूरी संहिता, 2019 (अगस्त 2019), औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 (सितंबर 2020)। नए कानून बदलते श्रम बाजार के रुझानों के अनुरूप हैं और साथ ही, कानून के ढांचे के भीतर स्वरोजगार और प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता और कल्याणकारी जरूरतों को समायोजित करते हैं। श्रम संहिताओं को वर्तमान आर्थिक परिदृश्य और तकनीकी प्रगति के साथ-साथ परिभाषाओं और प्राधिकरणों की बहुलता में कमी के साथ जोड़ा गया है। संहिताएं अनुपालन तंत्र को भी आसान बनाती हैं, जिसका उद्देश्य व्यवसाय करने/उद्यमों की स्थापना में आसानी को बढ़ावा देना और प्रत्येक कार्यकर्ता की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वेब आधारित निरीक्षण जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू किया गया है। श्रम संहिताओं में छोटे-मोटे अपराधों को भी गैर-अपराधीकरण प्रदान किया गया है।

6.18 संहिताओं के तहत बनाए गए नियमों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उपयक्तु स्तर पर सौंपा गया है। सार्वजनिक परामर्श के लिए उनके आधिकारिक राजपत्रों में नियमों के पूर्व-प्रकाशन की आवश्यकता है। 13 दिसंबर 2022 तक, 31 राज्यों ने वेतन संहिता के तहत, 28 राज्यों ने औद्योगिक संबंध संहिता के तहत, 28 राज्यों ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत, और 26 राज्यों ने व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों के कोड के तहत मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है।

तालिका VI.3: चार श्रम संहिताओं के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा नियमों की स्थिति

कोड का नाम	उन राज्यों के नाम जिन्होंने मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है
वेतन संहिता, 2019	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी **(31)**
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी **(28)**
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पांदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश **(28)**
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी **(26)**

स्रोत: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; 13 दिसंबर 2022 तक की स्थिति

ईश्रम पोर्टल

6.19 सरकार संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कामगारों के हितों की रक्षा और सुरक्षा, उनके कल्याण को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके देश की श्रम शक्ति के जीवन और सम्मान में सुधार लाने के लिए काम कर रही है। तदनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) ने असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ईश्रम पोर्टल विकसित किया है, जो आधार से सत्यापित है। यह श्रमिकों के नाम, व्यवसाय, पता, व्यवसाय प्रकार, शैक्षिक योग्यता और कौशल प्रकार आदि जैसे विवरणों को उनकी रोजगार क्षमता के इष्टतम अहसास के लिए कैप्चर करता है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार करता है। यह असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है, जिसमें प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों आदि शामिल हैं। वर्तमान में, ई-असीम (एसएचआरएएम) पोर्टल को सेवाओं की निर्बाध सुविधा के लिए एनसीएस पोर्टल और एएसई ईएम पोर्टल से जोड़ा गया है।

6.20 31 दिसंबर 2022 तक, कुल 28.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। महिला पंजीकरण कुल का 52.8 प्रतिशत था और कुल पंजीकरण का 61.7 प्रतिशत 18-40 वर्ष की आयु वर्ग का था। राज्य-वार, उत्तर प्रदेश (29.1 प्रतिशत), बिहार (10.0 प्रतिशत), और पश्चिम बंगाल (9.0 प्रतिशत) कुल पंजीकरण का लगभग आधा हिस्सा हैं। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों ने कुल पंजीकरण में 52.4

प्रतिशत का योगदान दिया, इसके बाद घरेलू और घरेलू श्रमिकों (9.8 प्रतिशत) और निर्माण श्रमिकों (9.1 प्रतिशत) का स्थान रहा।

चित्र VI.2: ई-श्रम पोर्टल के तहत संचयी पंजीकरण

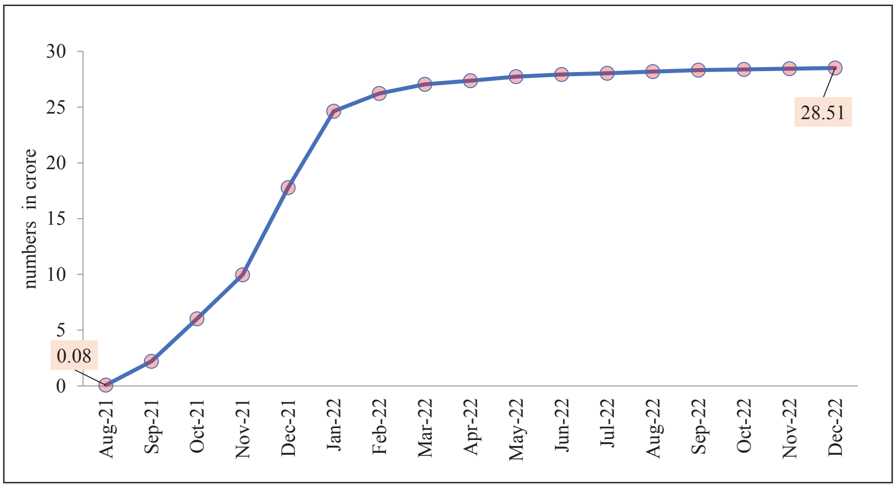

स्रोत: ई-श्रम डैशबोर्ड, एमओएलई

आधार: विशिष्ट पहचान की कई उपलब्धियां

6.21 आधार, एक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या भारत के निवासियों को एक डिजिटल पहचान प्रदान करती है और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करती है। यह सरकार और व्यक्ति को जोड़ता है, कई उद्देश्यों के लिए कई आईडी के असंबद्ध वेब की जगह लेता है, और राज्य और नागरिक के बीच सामाजिक अनुबंध को सुरक्षित करता है। यह 2010 में की गई पहल के कारण है कि आज देश लगातार एक डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण और मजबूती कर रहा है, जो अंततः वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देगा कि कैसे पैसा और सामान अपने प्रतिस्पर्धियों पर देश भर में घूमते हैं।

6.22 पॉल रोमर, नोबेल पुरस्कार विजेता और विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री, ने भारत के 135 करोड़ नागरिकों, जो जनसंख्या का 94 प्रतिशत और 100 प्रतिशत वयस्क (>18 वर्ष) हैं, के बारे में वर्णन किया है, 'सबसे परिष्कृत' दुनिया में आईडी कार्यक्रम।[11] आधार, आधार धारक की तस्वीर, उसके उंगलियों के निशान और आईरिस स्कैन विवरण के बीच एक निर्णायक संबंध प्रदान करता है।

आधार की उपलब्धियां

6.23 आधार राज्य द्वारा सामाजिक वितरण के लिए एक आवश्यक उपकरण है। 318 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और 720 से अधिक राज्य डीबीटी योजनाएं आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत अधिसूचित हैं, और ये सभी योजनाएं वित्तीय सेवाओं, सब्सिडी और लाभों के लक्षित वितरण के लिए आधार का उपयोग करती हैं। आधार भारत के डिजिटल एकीकरण की नींव है, जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों द्वारा दिखाया गया है (नवंबर 2022 तक):

- आधार सृजित- 135.2 करोड़
- आधार अद्यतन- 71.1 करोड़

[11]'आधार' दुनिया में सबसे परिष्कृत आईडी कार्यक्रम: विश्व बैंक''। दाईजी वर्ल्ड, ब्लूमबर्ग के साथ एक साक्षात्कार से उद्धृत।

- प्रमाणीकरण संपन्न – 8621.2 करोड़
- eKYC हो गया – 1350.2 करोड़
- 75.3 करोड़ निवासियों ने राशन का लाभ उठाने के लिए अपने आधार को राशन कार्ड से जोड़ा है
- एलपीजी सब्सिडी के लिए 27.9 करोड़ निवासियों ने आधार को रसोई गैस कनेक्शन से जोड़ा
- 75.4 करोड़ बैंक खाते आधार से जुड़े हैं और 1549.8 करोड़ लेनदेन आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से किए गए हैं

6.24 नागरिकों के दैनिक जीवन में आधार के प्रमुख उपयोग हैं:

- ***आधार - डीबीटी में उपयोग:*** जब बैंक खाते से जोड़ा जाता है, तो आधार एक व्यक्ति का 'वित्तीय पता' बन जाता है, जो देश के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है। आधार भुगतान ब्रिज (ए पीबी) के माध्यम से किसी व्यक्ति के बैंक खाते में किसी भी भुगतान को स्थानांतरित करने के लिए संख्या पर्याप्त है, इस प्रकार अन्य विवरण देने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, अर्थात। बैंक खाता, आईएफएससी कोड, और सरकार / संस्थानों को बैंक शाखा का विवरण।
- ***आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस):*** एईपीएस एक व्यक्ति को बुनियादी बैंकिंग लेनदेन करने में मदद करता है, जैसे। केवल अपने आधार का उपयोग करके निकासी, नकद जमा, अपने बैंक खाते से धन का हस्तांतरण आदि। इससे डोर-स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में काफी मदद मिली है और कोविड-19 महामारी के कारण लोगों की कठिनाइयों को कम करने में मदद मिली है।
- ***जेएएम (जन-धन, आधार और मोबाइल)*** त्रिमूर्ति, डीबीटी की शक्ति के साथ मिलकर, लोगों को सशक्त बनाकर पारदर्शी और जवाबदेह शासन के मार्ग में क्रांति लाते हुए, समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में ले आई है। नवंबर 2022 तक, पहल, मनरेगा आदि सहित कई बड़ी केंद्रीय योजनाओं ने 1,010 करोड़ से अधिक सफल लेनदेन के माध्यम से ₹7,66,055.9 करोड़ से अधिक का भुगतान किया है।[12]
- ***वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना:*** आधार ने ओएनओआरसी योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जबकि पीडीएस डेटाबेस की आधार सीडिंग के परिणामस्वरूप फर्जी और नकली लाभार्थियों को समाप्त करने के कारण महत्वपूर्ण बचत हुई है। आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से अनाज वितरण से पीडीएस के लॉजिस्टिक नेटवर्क में सार्थक पारदर्शिता और बैक-ऑफिस सुधार आया है। 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' (पीएमजीकेवाई) के तहत खाद्यान्न के मुफ्त वितरण ने कोविड महामारी के प्रभाव को बहुत कम कर दिया है, खासकर समाज के सबसे कमजोर और सबसे कमजोर वर्गों के लिए।
- ***पीएम किसान सम्मान निधि:*** आधार ईकेवाईसी के माध्यम से पंजीकरण से लेकर एपीबी के माध्यम से डीबीटी तक, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए आधार प्लेटफॉर्म आधार बनाता है।
- ***को-विन:*** को-विन प्लेटफॉर्म के बिना कोविड महामारी का सफल प्रबंधन संभव नहीं था। आधार ने को-विन प्लेटफॉर्म को विकसित करने और 2 बिलियन से अधिक वैक्सीन खुराक के पारदर्शी प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- ***चेहरा प्रमाणीकरण:*** प्रमाणीकरण के एक अतिरिक्त साधन के रूप में चेहरे का उपयोग बढ़ रहा है। इससे, विशेष रूप से बुजुर्गों को, पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने स्मार्टफोन के माध्यम से 'जीवन प्रमाण' प्राप्त करने में मदद मिली है।

---
[12]स्रोत: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

आधार पारिस्थितिकी तंत्र

6.25 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को प्रत्येक निवासी व्यक्ति को आधार संख्या जारी करने और प्रमाणीकरण करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करने का अधिकार है। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने की भी जिम्मेदारी है कि केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में संग्रहीत जानकारी सुरक्षित है और अनधिकृत पहुंच या दुरुपयोग से सुरक्षित है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र में अब निम्नलिखित शामिल हैं (30 नवंबर 2022 तक):

- 66,103 आधार काउंटर और 34,834 चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट डिवाइस काम कर रहे हैं
- 180 सक्रिय रजिस्ट्रार
- 507 सक्रिय नामांकन एजेंसियां
- यूआईडीएआई द्वारा संचालित 88 आधार सेवा केंद्र 72 शहरों में काम कर रहे हैं
- 15,002 ग्रामीण स्तर के उद्यमी जो बैंकिंग प्रतिनिधियों के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें आधार अद्यतन सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है
- इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत लगभग 53,750 पोस्टमैन/ग्रामीण डाक सेवकों को मोबाइल नंबर अपडेट सुविधा प्रदान करने की मंजूरी दी गई है
- 178 आधार उपयोगकर्ता एजेंसियां
- 169 ई-केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसियां

रोजगार प्रवृतियों में सुधार करना

6.26 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा संचालित पीएलएफएस जैसे घरेलू सर्वेक्षणों के माध्यम से श्रम की आपूर्ति पक्ष से रोजगार के रुझान का अध्ययन किया जा सकता है, और उद्यम या स्थापना सर्वेक्षण जैसे वार्षिक सर्वेक्षण के माध्यम से श्रम की मांग पक्ष एमओएसपीआई द्वारा उद्योग (ASI)] श्रम ब्यूरो द्वारा त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण, आदि। ये श्रम बाजार और उसके रुझानों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।

6.27 श्रम बाजार के आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों को कवर करने वाले आंकड़ों में रोजगार संकेतकों में व्यापक सुधार देखा जा सकता है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में श्रम बाजार पूर्व-कोविड स्तरों से आगे निकल गए हैं, बेरोजगारी दर 2018-19 में 5.8 प्रतिशत से गिरकर 2020-21 में 4.2 प्रतिशत हो गई है, और ग्रामीण एफएलएफपीआर में 19.7 प्रतिशत से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2018-19 से 2020-21 में 27.7 प्रतिशत। हाल ही के शहरी रोजगार डेटा पूर्व-महामारी के स्तर से आगे की प्रगति दिखाते हैं क्योंकि जुलाई-सितंबर 2019 में बेरोजगारी दर 8.3 प्रतिशत से घटकर जुलाई-सितंबर 2022 में 7.2 प्रतिशत हो गई।

ईपीएफओ पेरोल में शुद्ध जोड़ लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जिसमें अधिकांश हिस्सा युवाओं का है। क्यूईएस के अनुसार वर्ष 2021-22 में नौ प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार में 10 लाख की वृद्धि हुई है। एएसआई 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार, संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रहा है। एमएसएमई, रेहड़ी-पटरी वालों और विनिर्माण इकाइयों पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए किए गए कई उपायों को रोजगार के स्तर में लगातार वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और विभिन्न लक्षित योजनाओं और उपायों के माध्यम से नौकरी के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, जैसा कि अध्याय में बाद में विस्तार से बताया गया है। विभिन्न डेटा स्रोतों से उपलब्ध आपूर्ति और मांग पक्ष पर रोजगार के रुझान नीचे प्रस्तुत किए गए हैं।

रोजगार का आपूर्ति पक्ष

वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण

6.28 सामान्य स्थिति के अनुसार[13], श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर)[14], पीएलएफएस 2020-21 (जुलाई-जून) में श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)[15] और बेरोजगारी दर (यूआर)[16] में पीएलएफएस 2019-20 और 2018-19 की तुलना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सुधार हुआ है।

तालिका VI.4: सामान्य स्थिति में रोजगार के रुझान

(प्रमुख स्थिति + सहायक स्थिति) सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए

(प्रतिशत)

		ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण + शहरी		
		2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
पुरुष	एलएफपीआर	55.1	56.3	57.1	56.7	57.8	58.4	55.6	56.8	57.5
	डब्ल्यूपीआर	52.1	53.8	54.9	52.7	54.1	54.9	52.3	53.9	54.9
	यूआर	5.6	4.5	3.9	7.1	6.4	6.1	6.0	5.1	4.5
महिला	एलएफपीआर	19.7	24.7	27.7	16.1	18.5	18.6	18.6	22.8	25.1
	डब्ल्यूपीआर	19.0	24.0	27.1	14.5	16.8	17	17.6	21.8	24.2
	यूआर	3.5	2.6	2.1	9.9	8.9	8.6	5.2	4.2	3.5
व्यक्ति	एलएफपीआर	37.7	40.8	42.7	36.9	38.6	38.9	37.5	40.1	41.6
	डब्ल्यूपीआर	35.8	39.2	41.3	34.1	35.9	36.3	35.3	38.2	39.8
	यूआर	5.0	4.0	3.3	7.7	7.0	6.7	5.8	4.8	4.2

स्रोत: वार्षिक पीएलएफएस 2017-18 से 2020-21, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

6.29 जबकि सामान्य स्थिति में एक वर्ष की लंबी संदर्भ अवधि होती है, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस)[18] एक सख्त बेंचमार्क है। यह एक सप्ताह की संदर्भ अवधि के साथ महामारी जैसी घटनाओं के दौरान रोजगार की अवधि में हुए नुकसान को दर्ज कर सकता है। सीडब्ल्यूएस के अनुसार, श्रम बाजार संकेतक 2019-20 (जुलाई-जून) से 2020-21 तक तेजी से ठीक हुए, और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए, रोजगार संकेतकों में सुधार हुआ। क्षेत्रवार, जबकि ग्रामीण श्रम बाजार संकेतक पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सुधार कर रहे हैं, शहरी श्रम बाजार 2020-21 (जुलाई-जून) में पूर्व-कोविड स्तर से थोड़ा पीछे है। हालांकि, हाल की तिमाहियों के लिए उपलब्ध शहरी क्षेत्रों के लिए तिमाही पीएलएफएस रिपोर्ट से संकेत लेते हुए, पूर्व-कोविड स्तरों से परे शहरी श्रम बाजारों की रिकवरी देखी जा सकती है। त्रैमासिक शहरी बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर 2019 में पूर्व-महामारी के स्तर 8.3 प्रतिशत से घटकर जुलाई-सितंबर 2022 में 7.2 प्रतिशत हो गई, साथ ही इसी अवधि के दौरान एलएफपीआर 47.3 प्रतिशत से बढ़कर 47.9 प्रतिशत हो गया। जैसा कि पैराग्राफ 6.33 और 6.34 में चर्चा की गई है।

---

[13]किसी व्यक्ति को सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार नियोजित के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, उसे सर्वेक्षण की तारीख से पहले के 365 दिनों के दौरान कम से कम 30 दिनों के लिए आर्थिक गतिविधि होनी चाहिए।

[14]पीएलएफएस के अनुसार, एलएफपीआर काम करने की उम्र वाली आबादी का प्रतिशत है जो काम में लगी हुई है या 'काम' की तलाश के लिए ठोस प्रयास कर रही है या 'काम' के लिए उपलब्ध है, अगर यह उपलब्ध है। 'कार्य' में स्व-रोजगार (निर्वाह कृषि और आत्म-उपभोग के लिए जलाऊ लकड़ी, मुर्गी पालन, आदि का संग्रह), नियमित मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार, और आकस्मिक श्रम शामिल हैं।

[15]WPR को कुल जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

[16]यूआर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

[17]यह जून, 2022 में जारी किया गया नवीनतम उपलब्ध वार्षिक सर्वेक्षण है।

[18]किसी व्यक्ति को वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के अनुसार नियोजित रूप में वर्गीकृत करने के लिए, उसे सर्वेक्षण की तारीख से पहले सात दिनों के दौरान कम से कम 1 घंटे के लिए आर्थिक गतिविधि होनी चाहिए ।

तालिका VI.5: वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में रोजगार के रुझान

		ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण + शहरी		
		2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
पुरुष	एलएफपीआर	75.5	76.7	76.7	73.7	73.8	73.8	74.9	75.8	75.8
	डब्ल्यूपीआर	69.0	70.1	71.2	67.2	66.0	66.8	68.4	68.8	69.9
	यूआर	8.6	8.7	7.1	8.8	10.5	9.4	8.7	9.3	7.8
महिला	एलएफपीआर	22.5	28.3	30.0	19.7	22.1	21.7	21.6	26.3	27.5
	डब्ल्यूपीआर	20.9	26.7	28.6	17.4	19.4	19.0	19.8	24.4	25.7
	यूआर	7.3	5.5	4.8	12.1	12.4	12.2	8.7	7.3	6.6
व्यक्ति	एलएफपीआर	49.1	52.5	53.4	47.1	48.2	48.0	48.5	51.2	51.8
	डब्ल्यूपीआर	45.0	48.4	50.0	42.7	43.0	43.1	44.3	46.7	47.9
	यूआर	8.3	7.8	6.5	9.5	11.0	10.1	8.7	8.8	7.5

स्रोत: वार्षिक पीएलएफएस 2017-18 से 2020-21, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

टिप्पणी: 2020-21 जुलाई 2020-जून 2021 की अवधि को संदर्भित करता है और इसी तरह 2019-20 और 2018-19 के लिए

6.30 रोजगार में व्यापक स्थिति के अनुसार, 2019-20 की तुलना में 2020-21 में स्वरोजगार करने वालों की हिस्सेदारी बढ़ी और नियमित वेतन/वेतनभोगी श्रमिकों की हिस्सेदारी में गिरावट आई, जो कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों की प्रवृत्ति से प्रेरित है। ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा संचालित आकस्मिक श्रम की हिस्सेदारी में थोड़ी गिरावट आई है।

चित्र VI.3: व्यापक रोजगार स्थिति में रुझान (व्यक्ति, ग्रामीण+शहरी)

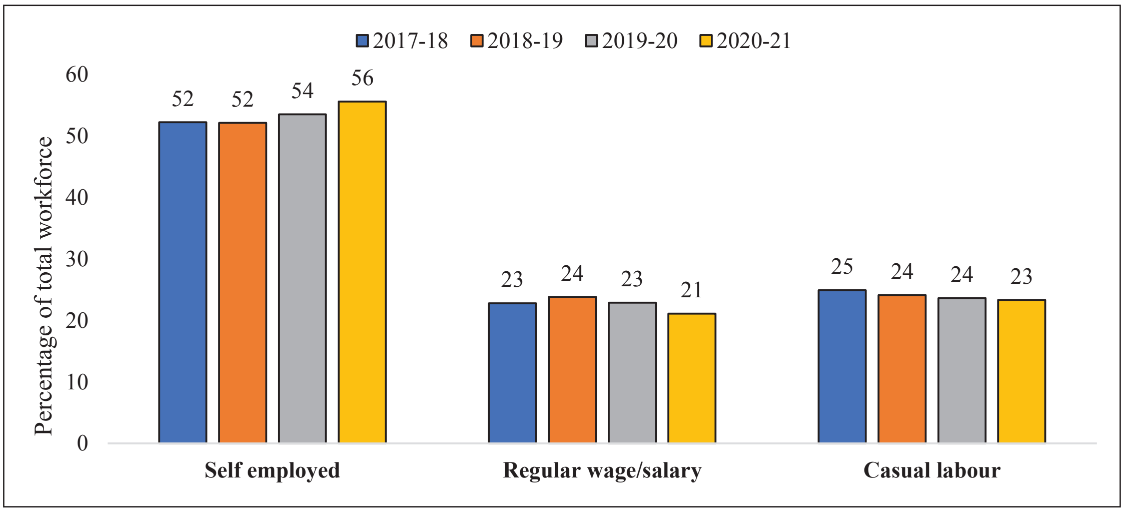

स्रोत: वार्षिक पीएलएफएस, एमओएसपीआई

6.31 कार्य उद्योग के आधार पर, कृषि में लगे श्रमिकों की हिस्सेदारी 2019-20 में 45.6 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 46.5 प्रतिशत हो गई, विनिर्माण की हिस्सेदारी 11.2 प्रतिशत से घटकर 10.9 प्रतिशत हो गई, इसी अवधि में निर्माण का हिस्सा 11.6 प्रतिशत से बढ़कर 12.1 प्रतिशत हो गया, और व्यापार, होटल और रेस्तरां का

हिस्सा 13.2 प्रतिशत से घटकर 12.2 प्रतिशत हो गया। यह विनिर्माण और सेवा रोजगार पर कोविड के प्रभाव का कारण हो सकता है (2020-21 डेटा में जुलाई 2020 से जून 2021 की अवधि शामिल है), जबकि इस अवधि के दौरान कृषि विकास मजबूत रहा। एफएलएफपीआर में वृद्धि (सामान्य स्थिति के लिए 2017-18 से 2020-21 में 9.5 प्रतिशत अंक (पीपी) की वृद्धि और सीडब्ल्यूएस के लिए 8.3 पीपी) रोजगार के लैंगिक पहलू का एक सकारात्मक विकास है, जो बढ़ते ग्रामीण विकास के कारण हो सकता है। महिलाओं के समय को देकर ग्रामीण सुविधाओं में वृद्धि, और वर्षों में उच्च कृषि विकास हो सकते हैं। बॉक्स VI-2 एफएलपीएफआर के माप पहलुओं पर परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

चित्र VI.4: महिला श्रम बल भागीदारी दर में बदलाव

(2017-18की तुलना में 2020-21; सामान्य स्थिति, सभी आयु)

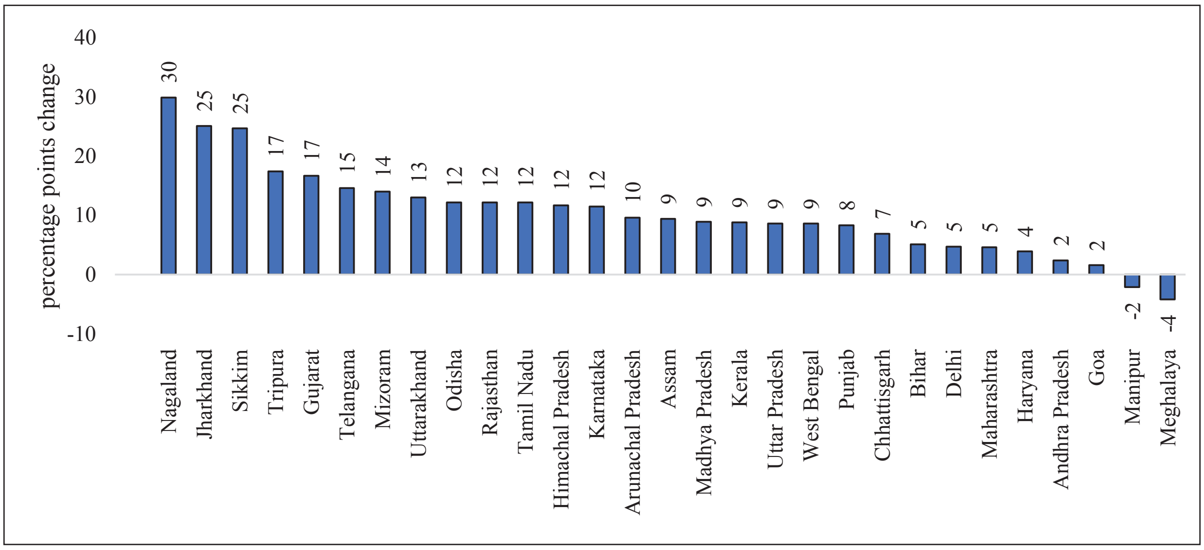

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

बॉक्स: VI-2: महिला श्रम बल भागीदारी दर में माप के मुद्दे

भारतीय महिलाओं के कम एलएफपीआर की आम कहानी घरेलू और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी कामकाजी महिलाओं की वास्तविकता को याद करती है। सर्वेक्षण डिजाइन और सामग्री के माध्यम से रोजगार का माप अंतिम एलएफपीआर अनुमानों में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है, और यह पुरुष एलएफपीआर की तुलना में महिला एलएफपीआर को मापने के लिए अधिक मायने रखता है। यहां, तीन मुख्य माप मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है: अत्यधिक व्यापक श्रेणियां, श्रम बल की स्थिति को वर्गीकृत करने के लिए एक ही प्रश्न पर निर्भरता, और उत्पादक कार्य को श्रम बल की भागीदारी तक सीमित करने का संकीर्ण दृष्टिकोण।

अत्यधिक व्यापक श्रेणियों का उपयोग घरेलू कर्तव्यों के साथ उत्पादक कार्य (जलाऊ लकड़ी, मुर्गी पालन, आदि का संग्रह) को जोड़ना: अत्यधिक व्यापक श्रेणियों का उपयोग जो घरेलू कार्यों के साथ उत्पादक कार्य (जलाऊ लकड़ी, मुर्गी पालन, आदि का संग्रह) को एक साथ जोड़ सकता है श्रम बल में महिलाओं के एक महत्वपूर्ण अनुपात को श्रम-बल से बाहर की श्रेणी में स्थानांतरित करना। उदाहरण के लिए, जब तक प्रतिवादी द्वारा प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन को मुख्य गतिविधि के रूप में पहचाना नहीं जाता है, तब तक पीएलएफएस प्रश्नावली उन महिलाओं को वर्गीकृत करेगी जो घरेलू गतिविधियों और प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन/संग्रह दोनों को श्गतिविधि कोड 93,[19] में वर्गीकृत करती हैं और इस प्रकार आउट-ऑफ-द-श्रम बल।

[19]एनएसएसओ सर्वेक्षण प्रश्नावली में, प्रत्येक घर के सदस्य को उनकी प्राथमिक गतिविधि के अनुसार गतिविधि स्थिति कोड सौंपे जाते हैं। गतिविधि कोड 93 ''घरेलू कर्तव्यों में लगे हुए और घरेलू उपयोग के लिए सामान (सब्जी, जलाऊ लकड़ी, पशु चारा, आदि), सिलाई, आदि के मुफ्त संग्रह में लगे हुए'' को संदर्भित करता है।

गतिविधि कोड 93 में महिलाओं के अनुपात को आधिकारिक LFPR में जोड़ने से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए वित्त वर्ष 21 के लिए 46.2 प्रतिशत की 'संवर्धित महिला LFPR * प्राप्त होती है, जो पारंपरिक परिभाषा (सामान्य के लिए PLFS डेटा) द्वारा अनुमानित 32.5 प्रतिशत से बहुत अधिक है। दर्जा)। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के एक शोध पत्र[20], में इसी तरह का प्रयास किया गया है, जो 2012 के लिए भारत में 56.4 प्रतिशत महिला एलएफपीआर पर पहुंचा है, जबकि 2012 के लिए यह 31.2 प्रतिशत के बहुत कम आधिकारिक अनुमान के मुकाबले है।

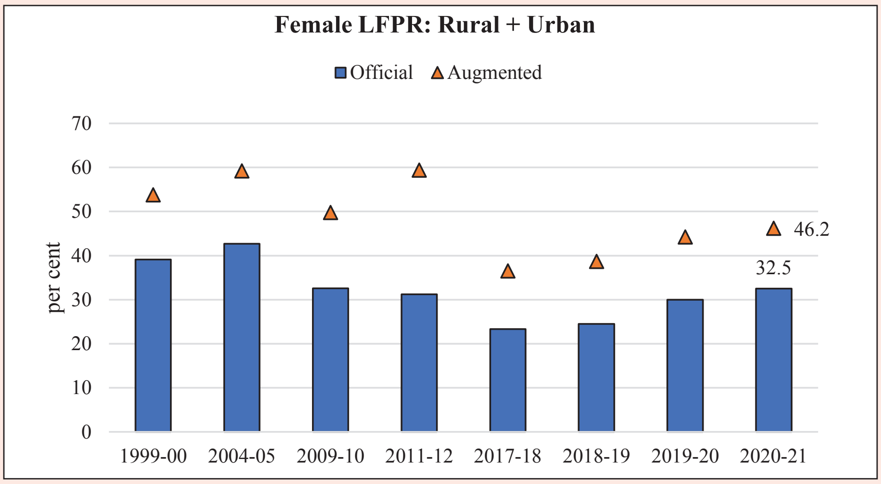

स्रोत: 1999-00 से 2011-12 के लिए एनएसएस रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण (एनएसएस-ईयूएस), 2017-18 से 2011-12 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)।

नोट: 1. सामान्य गतिविधि (पीएस+एसएस) स्थिति (15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए) प्रतिशत में 2. एनएसएस-ईयूएस और पीएलएफएस की तुलना अलग-अलग सैंपलिंग वेट, फ्रीक्वेंसी और डेटा कलेक्शन तकनीकों को देखते हुए नहीं की जा सकती है।

पीएलएफएस प्रश्नावली में कोई पुनर्प्राप्ति प्रश्न नहीं: सर्वेक्षण डिजाइन मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की श्रम शक्ति की स्थिति को मापने के लिए एक प्रश्न पर निर्भर करता है, जो बड़ी ग्रामीण आबादी और साक्षरता के स्तर पर विचार करते हुए स्व-रिपोर्टिंग में किसी भी त्रुटि को सुधारने की गुंजाइश को समाप्त कर देता है। आईएलओ की सिफारिशों के विपरीत, पीएलएफएस प्रश्नावली में व्यक्तियों की श्रम शक्ति की स्थिति की दोबारा जांच करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रश्न ('पुनप्राप्ति प्रश्न') नहीं हैं, यह इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि व्यक्ति पहली बार में स्वयं की पहचान कैसे करता है। प्स्ठ कई जांच या ञ्नर्प्राप्ति प्रश्नों का उपयोग करने की स्फ़ारिश करता है जैसे ष्क्या व्यक्ति ने पारिवारिक व्यवसाय में मदद की' और 'क्या व्यक्ति ने पिछले 1 सप्ताह/वर्ष में अपने व्यवसाय में काम किया'' और ''क्या व्यक्ति ने नौकरी में परिवार की मदद की''।

श्रीलंका[21] में विश्व बैंक और आईएलओ के एक अध्ययन में, इस तरह के पद्धतिगत मुद्दों को महिला रोजगार-से-जनसंख्या अनुपात के एक प्रतिशत बिंदु के करीब कम करके आंका गया।

[20]कैप्सोस, एस., बोरमपोला, ई., सिल्बरमैन, ए. (2014), 'क्यों भारत में महिला श्रम भागीदारी दर में इतनी तेजी से गिरावट आ रही है?', आईएलओ शोध पत्र संख्या 10

[21]डिस्कोंजा, ए., गद्दीस, आई., पलासियोस-लोपेज, ए., वॉल्श, के. (2021)। महिलाओं और पुरुषों के काम को मापना: श्रीलंका में एक संयुक्त आईएलओ और विश्व बैंक अध्ययन से मुख्य निष्कर्ष।

[22]2013 में श्रम सांख्यिकीविदों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने 'कार्य' के रूप में वर्गीकृत उत्पादक गतिविधियों के सेट का विस्तार करने के लिए मानदंडों का एक नया सेट अपनाया, जिसमें किसी भी लिंग और आयु के व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करने या दूसरों द्वारा उपयोग के लिए सेवाएं प्रदान करने या स्वयं के उपयोग के लिए की गई कोई भी गतिविधि शामिल है। कार्य की परिभाषा सामान्य उत्पादन सीमा के साथ संरेखित की गई है, जैसा कि राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 में परिभाषित किया गया है, जिसमें स्वयं का उपयोग उत्पादन कार्य और स्वयंसेवी कार्य शामिल हैं।

'रोजगार' के साथ-साथ कार्य का मापन: मापन कार्य के क्षितिज को व्यापक बनाने की आवश्यकता है, जो रोजगार के साथ-साथ उत्पादक गतिविधियों के पूरे ब्रह्मांड का गठन करता है। नवीनतम प्स० मानकों[22] के अनुसार, उत्पादक कार्य को श्रम बल की भागीदारी तक सीमित करना संकीर्ण है और केवल उपाय ही बाजार उत्पाद के रूप में काम करते हैं। इसमें महिलाओं के अवैतनिक घरेलू कार्य का मूल्य शामिल नहीं है, जिसे व्यय-बचत कार्य जैसे जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना, खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना आदि के रूप में देखा जा सकता है, और यह घरेलू जीवन स्तर में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

कहा गया कि, श्रम बाजार में शामिल होने के लिए महिलाओं की स्वतंत्र पसंद को सक्षम करने के लिए लिंग-आधारित नुकसान को दूर करने के लिए और भी महत्वपूर्ण गुंजाइश है। इस प्रकार, ''कार्य'' के एक संपूर्ण मापन के लिए पुन: डिजाइन किए गए सर्वेक्षणों के माध्यम से बेहतर परिमाणीकरण की आवश्यकता हो सकती है।

6.32 यह देखा जा सकता है कि 75 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण महिला श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसका तात्पर्य कृषि से संबंधित क्षेत्रों जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण में महिलाओं के कौशल को बढ़ाने और रोजगार सृजित करने की आवश्यकता से है। यहां, स्व-सहायता समूह (एसएचजी) ग्रामीण महिलाओं की क्षमता को वित्तीय समावेशन, आजीविका विविधीकरण, और कौशल विकास के ठोस विकासात्मक परिणामों में आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जैसा कि बॉक्स VI-3 में चर्चा की गई है।

बॉक्स: VI-3: महिला सशक्तिकरण में स्व-सहायता समूहों की भूमिका

स्व-सहायता समूह (एसएचजी)[23] आंदोलन, समूह एकजुटता और माइक्रोइनेंस के सिद्धांतों पर आधारित है, भारत में किसी न किसी रूप में 50 वर्षों से अस्तित्व में है, 1972 से जिसकी जड़ें स्व-नियोजित महिला संघ (सेवा) के गठन से जुड़ी हैं। स्वयं सहायता समूहों की परिवर्तनकारी क्षमता ने कोविड- 19 की जमीनी प्रतिक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम से उदाहरण के तौर पर, महिला सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण विकास के आधार के रूप में कार्य किया है।

भारत में लगभग 1.2 करोड़ एसएचजी हैं, जिनमें 88 प्रतिशत संपूर्ण महिला एसएचजी हैं। इसमें सफलता की कहानियों में केरल में कुदुम्बश्री, बिहार में जीविका, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महिला मंडल (एमएवीआईएम) और हाल ही में लूम्स ऑफ लद्दाख शामिल हैं।

1992 में शुरू की गई एसएचजी बैंक लिंकेज परियोजना (एसएचजी - बीएलपी) दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोफाइनेंस परियोजना बन गई है। एसएचजी आंदोलन, जो अब अपने 30वें वर्ष में है, छोटे और सीमांत वर्गों को शामिल करने के लिए एक शक्तिशाली मध्यस्थ के रूप में उभरा है। वर्तमान में, बैंक से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। बैंकों से ऋण लेने के लिए इन्हें नियमित बैठकों, नियमित बचतों, नियमित अंतर ऋण, समयानुसार पुनर्भुगतान और लेखों की अद्यतित पुस्तकों के 'पंचसूत्र' का अभ्यास करना होता है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार हितधारकों के सक्रिय सहयोग से एसएचजी - बीएलपी में ₹47,240.5 करोड़ की बचत राशि वाले 119 लाख एसएचजी के माध्यम से 14.2 करोड़ परिवार शामिल है 31 मार्च 2022 तक ₹1,51,051. 30 करोड़ के बकाया संपार्श्विक - मुक्त ऋण वाले 67 लाख समूह शामिल हैं। पिछले दस वर्षों (वित्त वर्ष 13 से वित्त वर्ष 22) के दौरान एसएचजी क्रेडिट लिंक्ड की संख्या 10.8 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ी है, जबकि इसी अवधि के दौरान प्रति एसएचजी क्रेडिट संवितरण 5.7 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ा है। विशेष रूप से, स्वयं सहायता समूहों का बैंक पुनर्भुगतान 96 प्रतिशत से अधिक है, जो उनके ऋण अनुशासन और विश्वसनीयता को रेखांकित करता है।

[23]एसएचजी अधिकतम 20 व्यक्तियों का एक सामाजिक और आर्थिक समरूप समूह है जो बचत और क्रेडित के सामूहिक उद्देश्य के लिए स्वैच्छिक रूप से बनाया गया है साथ ही इसमें संपार्श्विक रूप से ऋणों और क्रेडिट के उपयोग के लिए कोई आग्रह नहीं किया जाता है।

Table: Progress under SHG-Bank Linkage Programme
(2019-20 to 2021-22)
(Number in lakh/Amount in ₹ crore)

Particulars		2019-20		2020-21		2021-22	
		No. of SHGs	Amount	No. of SHGs	Amount	No. of SHGs	Amount
SHG Savings with Banks as of 31st March	Total SHG Nos.	102.4 (2.3)	26152.1 (12.1)	112.2 (9.6)	37477.6 (43.3)	118.9 (5.9)	47240.5 (26.1)
	All women SHGs (W)	88.3 (3.5)	23320.6 (13.9)	97.3 (10.1)	32686.1 (40.2)	104.1 (7.0)	42104.8 (28.8)
	% of W	86.2	89.2	86.7	87.2	87.5	89.1
	DAY-NRLM SHGs	57.9 (3.8)	14312.7 (11.2)	64.8 (11.9)	19353.7 (35.2)	71.8 (10.9)	27576.9 (42.5)
Loans Disbursed to SHGs during the year	Total No. of SHGs extended loans.	31.5 (16.6)	77659.4 (33.2)	28.9 (-8.2)	58070.7 (-25.2)	33.9 (17.7)	99729.2 (71.7)
	All women SHGs (W)	28.8 (21.9)	73297.6 (37.6)	25.9 (-10.2)	54423.1 (-25.8)	31.5 (21.6)	93817.2 (72.4)
	% of W	91.7	94.4	89.7	93.7	92.7	94.1
	DAY-NRLM SHGs	20.5 (24.3)	52183.7 (56.2)	15.8 (-22.7)	29643.0 (-43.2)	22.9 (44.6)	63100.8 (112.9)

(कोष्टक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी दर्शाते हैं)

स्रोत: नाबार्ड

एसएचजी का प्रभाव: सशक्त महिला, सशक्त गाँव

महिलाओं के आर्थिक एसएचजी से महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण पर सकारात्मक, सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, साथ ही विभिन्न तरीकों से प्राप्त सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि पैसे को संभालने, वित्तीय निर्णय लेने, बेहतर सामाजिक नेटवर्क[24], संपत्ति का स्वामित्व[25] और आजीविका विविधीकरण के बारे में जानकारी[26]

डीएवाई – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से चलाया जा रहा है, (विवरण के लिए पैरा 6.104 देखें) के हालिया[27] आकलन के अनुसार, प्रतिभागियों और पदाधिकारियों, दोनों ने महिला सशक्तिकरण, आत्म-सम्मान वृद्धि, व्यक्तित्व विकास, कम हुई सामाजिक बुराइयों से संबंधित क्षेत्रों में कार्यक्रम के उच्च प्रभावों को महसूस किया; और इसके अतिरिक्त, बेहतर शिक्षा, ग्रामीण संस्थानों में उच्च भागीदारी और सरकारी योजनाओं तक बेहतर पहुंच के संदर्भ में मध्यम प्रभाव पड़ा है।

कोविड-19 प्रतिक्रिया: एसएचजी की क्षमता का उदाहरण

स्वयं सहायता समूहों के लिए सरकार का कोविड-19 पैकेज

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए संपाश्विर्क – मुक्त

[24]ब्रॉडी, सी, डी हूप, टी, वोज्तकोवा, एम, वॉर्नॉक, आर, डनबर, एम, मूर्ति, पी और ड्वोर्किन, एसएल (2016)। 'महिला सशक्तिकरण में सुधार के लिए आर्थिक स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम: एक व्यवस्थित समीक्षा', 3आई व्यवस्थित समीक्षा। लंदन: प्रभाव मूल्यांकन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल (3पम)

[25]दत्ता, यू. (2015). 'जीविका के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: बिहार, भारत में एक बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूह परियोजना', विश्व विकास, 68:1-18।

[26]पांडे, वी., गुप्ता, ए., और गुप्ता, एस. (2019)। 'बड़े पैमाने पर आजीविका कार्यक्रम के श्रम और कल्याण प्रभाव: भारत से अर्ध-प्रायोगिक साक्ष्य', पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर नंबर 8883, विश्व बैंक।

[27]आईआरएमए (2017)। ''डीएवाई-एनआरएलएम के डिजाइन, रणनीतियों और प्रभावों का स्वतंत्र आकलन''

ऋण की सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दिया गया। इससे 63 लाख महिला एसएचजी और 6.85 करोड़ परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है।

- एनआरएलएम ने कोविड हॉटस्पॉट क्षेत्रों और कमजोर समूहों के लिए ग्राम संगठनों (वीओ) को ₹1.5 लाख की अतिरिक्त भेद्यता न्यूनीकरण निधि की अनुमति दी है।

कोविड के दौरान एसएचजी की कार्रवाई

महामारी के वर्षों ने एसएचजी महिलाओं को एकजुट करने, उनकी समूह पहचान को उत्कृष्ट बनाने और सामूहिक रूप से संकट प्रबंधन में योगदान देने की दिशा में एक अवसर के रूप में काम किया। वे संकट प्रबंधन में प्रमुख प्लेयर के रूप में उभरे, मास्क (असम में गामुसा मास्क जैसे सांस्कृतिक रूपों के साथ), सैनिटाइटर, और सुरक्षात्मक गियर के उत्पादन में महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने (जैसे झारखंड की पत्रकार दीदी), माल के लिए आवश्यक रुप से वितरित करने माल (जैसे केरल में फ्लोटिंग सुपरमार्केट), सामुदायिक रसोई चलाने (जैसे उत्तर प्रदेश में प्रेरणा कैंटीन), कृषि आजीविका का समर्थन करने (जैसे पशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए पशु सखी, झारखंड में सब्जियों के लिए आजीविका ार्म फ्रेश ऑनलाइन बिक्री और वितरण तंत्र), और डळछत्म्ळै (यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ में) के साथ अभिसरण करने और वित्तीय सेवाओं के वितरण में अग्रणी होकर भाग लिया (जैसे बैंक सखियों ने कोविड - राहत डीबीटी नकद हस्तांतरण का लाभ उठाने के लिए बैंक भीड़ का प्रबंधन किया)। एसएचजी द्वारा मास्क का उत्पादन एक उल्लेखनीय योगदान रहा है, जिससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में समुदायों द्वारा मास्क की पहुंच बनाने और उपयोग करने में सक्षम बनाया तथा कोविड- 19 वायरस के खिलफ़ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान की। 4 जनवरी 2023 तक, डीएवाई - एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा 16.9 करोड़ से अधिक मास्क का उत्पादन किया गया था।

आगे का रास्ता (वे फॉरवार्ड)

अंतिम मील तक उनकी पहुंच, समुदायों के विश्वास और एकजुटता को लाने की क्षमता, स्थानीय गतिशीलता का ज्ञान, और सदस्यों के आर्थिक गतिविधियों के एकत्रीकरण के माध्यम से सरल उत्पादों और सेवाओं का तेजी से विनिर्माण क्षमता के कारण एसएचजी समग्र ग्रामीण विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सुव्यवस्थित है। कोविड समेत अनेक संकटों की अवधि में उनके लोच और लचीलेपन का दर्शाने के लिए लंबे समय तक चलने वाले ग्रामीण परिवर्तन को नियमित करने की आवश्यकता है। इसमें अन्य बातों के अलावा, एसएचजी आंदोलन को तीव्र करने में अंतर - क्षेत्रीय असमानता का पता करना, एसएचजी सदस्यों को सूक्ष्म - उद्यमियों में शामिल करना, उत्पादों और सेवाओं में मूल्य श्रृंखला को ऊपर ले जाने के लिए सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक कौशल विकास, और एसएचजी छत्र के तहत कम से कम विशेषाधि कार प्राप्त करना शामिल हैं।

शहरी क्षेत्रों के लिए तिमाही पीएलएफएस

6.33 शहरी क्षेत्रों के लिए तिमाही स्तर पर एमओएसपीआई द्वारा संचालित पीएलएफएस जुलाई-सितंबर 2022 तक उपलब्ध है। सीडब्ल्यूएस के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही में सभी प्रमुख श्रम बाजार संकेतक क्रमिक रूप से और पिछले वर्ष की तुलना में सुधार को दर्शाते हैं। जुलाई-सितंबर 2022 में श्रम भागीदारी दर एक साल पहले के 46.9 प्रतिशत से बढ़कर 47.9 प्रतिशत हो गई, जबकि इसी अवधि में श्रमिक - जनसंख्या अनुपात 42.3 प्रतिशत से बढ़कर 44.5 प्रतिशत हो गया। बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर 2021 में 9.8 प्रतिशत से घटकर जुलाई-सितंबर 2022 में 7.2 प्रतिशत हो गई। इस प्रवृत्ति से यह पता लगता है कि श्रम बाजार कोविड के प्रभाव से उबर चुके हैं।

चित्र VI.5: त्रैमासिक शहरी रोजगार संकेतक

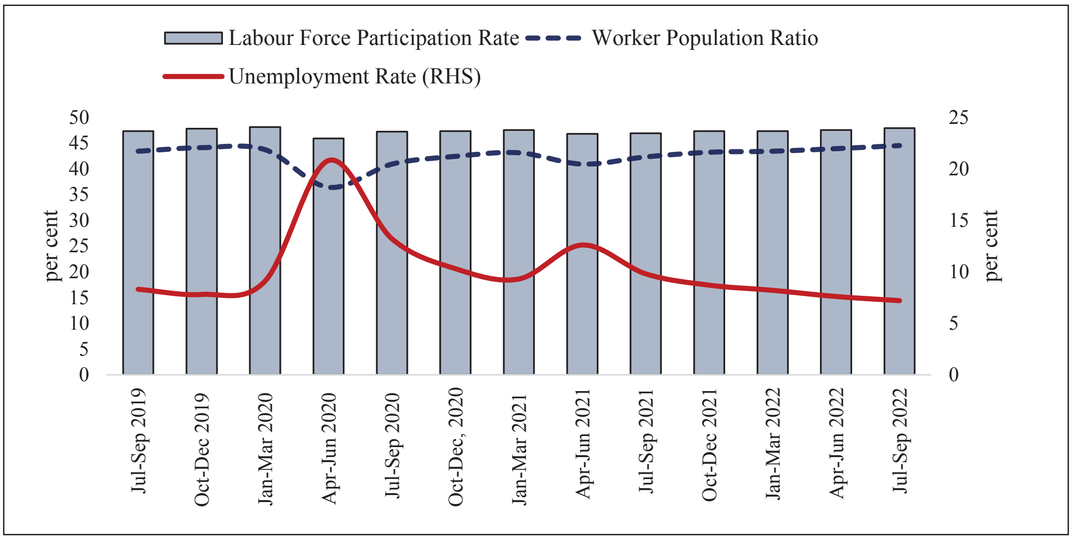

स्रोत: त्रैमासिक पीएलएफएस रिपोर्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

6.34 जुलाई-सितंबर 2022 में रोजगार की व्यापक स्थिति के लिए शहरी कार्यबल की संरचना पिछली चार तिमाहियों में स्थिर रही है, जिसमें स्वरोजगार की हिस्सेदारी 39.7 प्रतिशत, नियमित वेतन / वेतनभोगी 48.7 प्रतिशत और अनियत श्रम 11.6 प्रतिशत है। जुलाई - सितंबर 2022 में कार्य उद्योग में समान स्थिरता दिखाई दे रही है, जुलाई-सितंबर 2022 में द्वितीयक क्षेत्र में लगे श्रमिकों की हिस्सेदारी 33.4 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 60.9 प्रतिशत रही।

रोजगार का मांग पक्ष

त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस)

6.35 श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस)में नौ प्रमुख क्षेत्रों के दस या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं अर्थात विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्तरां, आईटी / बीपीओ और वित्तीय सेवाएं। एमओएसपीआई द्वारा आयोजित 6वीं आर्थिक जनगणना (2013-14) के अनुसार, इन नौ क्षेत्रों के दस या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान कुल रोजगार का लगभग 83 प्रतिशत है।

6.36 अब तक क्यूईएस के चार दौर के नतीजे जारी किए जा चुके हैं, जिसमें वित्त वर्ष 22[28] की चार तिमाहियों को शामिल किया गया है द्य क्यूईएस के चौथे दौर (जनवरी से मार्च 2022) तक नौ चयनित क्षेत्रों का अनुमानित कुल रोजगार 3.2 करोड़ रहा, जो क्यूईएस के पहले दौर (अप्रैल - जून 2021) से अनुमानित रोजगार से लगभग दस लाख अधिक है।

वित्तीय वर्ष 22 की पहली तिमाही से वित्त वर्ष 22 की चौथी तिमाही तक श्रमिकों के अनुमान में वृद्धि आईटी/ बीपीओ (17.6 लाख), स्वास्थ्य (7.8 लाख), और शिक्षा (1.7 लाख) जैसे क्षेत्रों में बढ़ते डिजिटलीकरण और सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के कारण हुई थी।

6.37 नियोजन के संबंधा में सभी क्षेत्रों में नियमित कर्मचारियों की बहुमत रहा जो 21-22 की चौथी तिमाही के कुल कार्यबल का 26.4: है। निर्माण (12.4:) एवं विनिर्माण (19.0:) को छोड़कर अन्य 9 क्षेत्रों के कार्य बल में संविदागत कर्मचारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही।

[28]क्यूईएस के चौथे दौर (जनवरी-मार्च, 2022) पर नवीनतम रिपोर्ट सितंबर 2022 में जारी की गई थी।

इसके अलावा, त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण क्यूईएस के चौथे दौर में नियोजित कुल में से 98.0 प्रतिशत कर्मचारी हैं जबकि 1.9 प्रतिशत स्व-नियोजित हैं। लिंग के आधार पर, कुल अनुमानित नियोजित में से 31.8 प्रतिशत महिलाएं हैं और 68.2 प्रतिशत पुरुष हैं।

चित्र VI.6: तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार श्रमिकों की अनुमानित संख्या (वित्त वर्ष 22 में, लाख में)

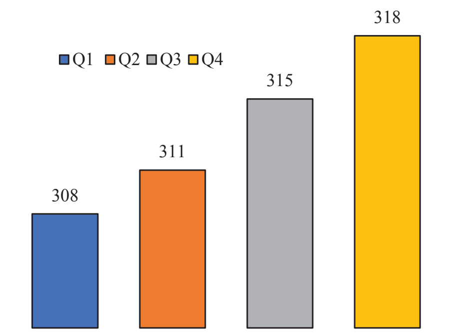

चित्र VI.7: तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार कुल रोजगार का क्षेत्रवार हिस्सा (वित्त वर्ष 22 की चौथी तिमाही में; प्रतिशत में)

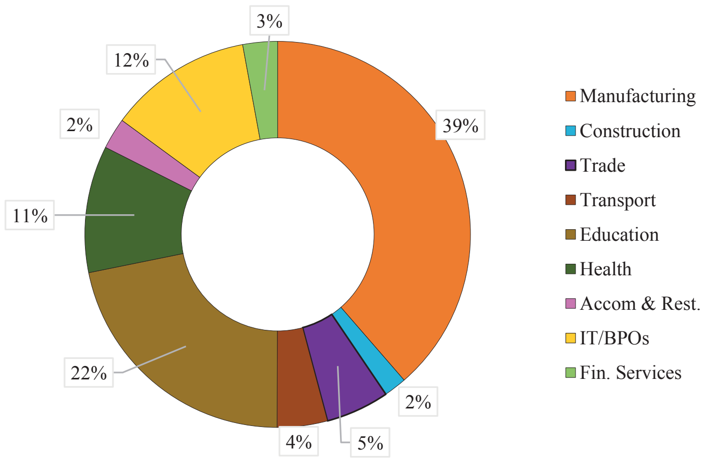

स्रोत: त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण रिपोर्ट, श्रम ब्यूरो

तालिका VI.6: क्यूईएस के अनुसार क्षेत्रवार श्रमिकों की अनुमानित संख्या

सेक्टर्स	अप्रैल-जून, 2021	जुलाई-सितंबर, 2021	अक्टूबर-दिसंबर, 2021	जनवरी-मार्च, 2022
विनिर्माण	125.2	121.4	124.0	122.5
निर्माण	7.4	6.1	6.2	6.1
व्यापार	20.4	16.5	16.8	17.0
यातायात	13.4	14.4	13.2	13.3
शिक्षा	67.3	68.5	69.3	69.0
स्वास्थ्य	26.0	33.5	32.9	33.8
आवास और रेस्तरां	8.9	7.8	8.1	8.2
आईटी / बीपीओ	20.7	33.2	34.6	38.3
वित्तीय सेवाएं	17.4	8.7	8.9	9.1
संपूर्ण	308.2	310.6	314.5	318.0

स्रोत: क्यूईएस रिपोर्ट्स, लेबर ब्यूरो

तालिका VI.7: रोजगार की शर्तों के अनुसार श्रमिकों का क्षेत्रवार वितरण (त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार)। (प्रतिशत, जनवरी-मार्च 2022 के लिए)

सेक्टर्स	स्वनियोजित	नियमित (अनुबंध पर नहीं) कर्मचारी	संविदा कर्मचारी	निश्चित अवधि के कर्मचारी	आकस्मिक कर्मचारी
विनिर्माण	2.5	80.2	12.4	1.0	4.0
निर्माण	1.3	73.4	19.0	0.5	5.7
व्यापार	4.2	90.1	3.5	0.3	2.0
यातायात	0.6	91.9	5.1	0.6	1.8
शिक्षा	1.2	91.1	6.4	0.5	0.8
स्वास्थ्य	0.6	89.0	9.1	0.5	0.9
आवास	6.7	84.5	5.2	0.6	3.0
और रेस्तरां	6.7	84.5	5.2	0.6	3.0
आईटी / बीपीओ	0.1	94.7	4.8	0.0	0.4
वित्तीय	**2.0**	**86.4**	**8.7**	**0.7**	**2.3**
सेवाएं	6.4	87.7	1.9	0.4	3.6
संपूर्ण	2.0	86.4	8.7	0.7	2.3

स्रोत: क्यूईएस रिपोर्ट्स, लेबर ब्यूरो

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) 2019-20[29]

6.38 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित एएसआई, अर्थव्यवस्था के पंजीकृत संगठित विनिर्माण क्षेत्र के औद्योगिक आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2एम (i) और 2एम (ii) के तहत पंजीकृत सभी कारखाने शामिल हैं, यानि वे कारखाने जो बिजली का उपयोग कर दस या अधिक श्रमिकों को रोजगार देते हैं; और वे कारण से जो बिजली का उपयोग किए बिना बीस या अधिक श्रमिकों को नियोजित करते हैं।

6.39 नवीनतम एएसआई वित्त वर्ष 20 के अनुसार, संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार ने समय के साथ लगातार प्रगति की है, साथ ही प्रति फैक्ट्री रोजगार धीरे - धीरे बढ़ रहा है। रोजगार की हिस्सेदारी (कुल नियुक्त व्यक्ति) के संदर्भ में, खाद्य उत्पाद उद्योग (11.1 प्रतिशत) सबसे बड़ा नियोक्ता बना रहा, इसके बाद परिधान (7.6 प्रतिशत), बुनियादी धातुएं (7.3 प्रतिशत), और मोटर वाहन, ट्रेलर और अर्ध- ट्रेलर (6.5 प्रतिशत) द्य राज्य - वार, तमिलनाडु के कारखानों में लगे लोगों की सबसे बड़ी संख्या (26.6 लाख), इसके बाद गुजरात (20.7 लाख), महाराष्ट्र (20.4 लाख), उत्तर प्रदेश (11.3 लाख) और कर्नाटक (10.8 लाख) का स्थान है।

[29]एएसआई 2019-20 के नतीजे 2022 में जारी किए गए थे।

चित्र VI.8: एएसआई के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा कारखानों में लगे कुल व्यक्ति (वित्तीय वर्ष 20 में)

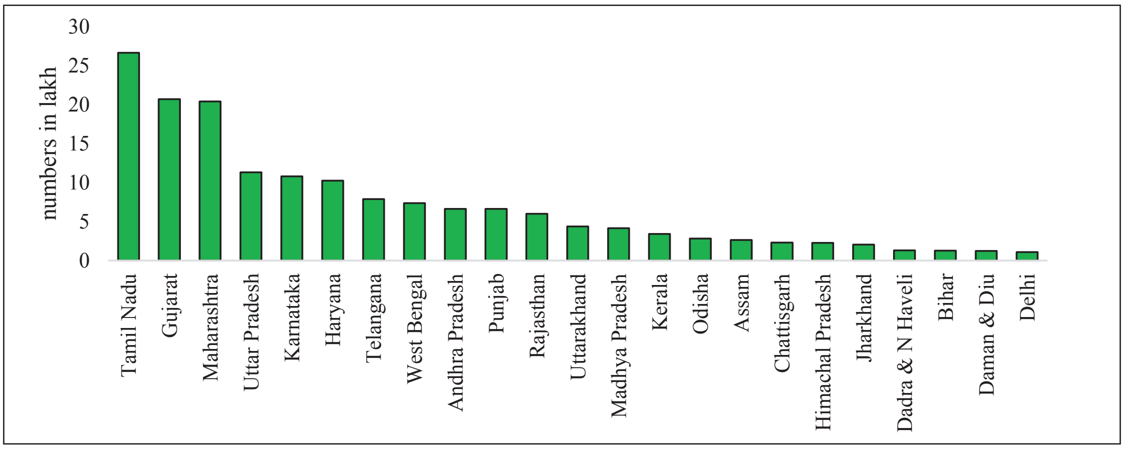

स्रोत: एएसआई, एमओएसपीआई

नोट: जिन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कम से कम एक लाख लोग फैक्ट्री क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन्हें चार्ट में दिखाया गया है।

6.40 रोजगार के आकार के संदर्भ में, आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कम रोजगार आकार वाले कारखानों की बड़ी संख्या और उच्च रोजगार देने वाले कारखानों की संख्या में विषमता है। उदाहरण के लिए, अनुमानित 1,98,628 फैक्ट्रियों में से 1,34,577 फैक्ट्रियों में 50 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं। हालाँकि, लगे हुए व्यक्तियों का वितरण अधिक संतुलित और एक समान है, जिसमें बड़े कारखाने बड़े हिस्से का रोजगार देते हैं। उदाहरण के लिए, कार्यरत कुल व्यक्तियों में से 77.3 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे कारखानों में हैं जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं। समय के साथ, छोटे कारखानों की व्यापक रूप से श्रमिकों की स्थिर संख्या की तुलना में उनकी संख्या वित्त वर्ष 17 से वित्त वर्ष 20 तक की अवधि में जो 12.7 प्रतिशत बढी है। 100 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले बड़े कारखानों की ओर एक स्पष्ट रुझान दिखाई दे रहा है, वित्त वर्ष – 17 और वित्त वर्ष 20 के बीच, बड़े कारखानों में लगे कुल व्यक्तियों की संख्या में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि छोटे कारखानों में यह 4.6 प्रतिशत था। परिणामस्वरूप, कारखानों की कुल संख्या में बड़े कारखानों की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 17 में 18 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 20 में 19.8 प्रतिशत हो गई है और कार्यरत कुल व्यक्तियों में उनकी हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2017 में 75.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 20 में 77.3 प्रतिशत हो गई है। इस प्रकार, श्रमिकों और कुल व्यक्तियों के रुझान के संदर्भ में, छोटे कारखानों की तुलना में बड़े कारखानों (100 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले) में रोजगार बढ़ रहा है, जो विनिर्माण इकाईयों को बढ़ाने का सुझाव देता है।

चित्र VI.9: एएसआई के अनुसार कारखानों में रोजगार के रुझान

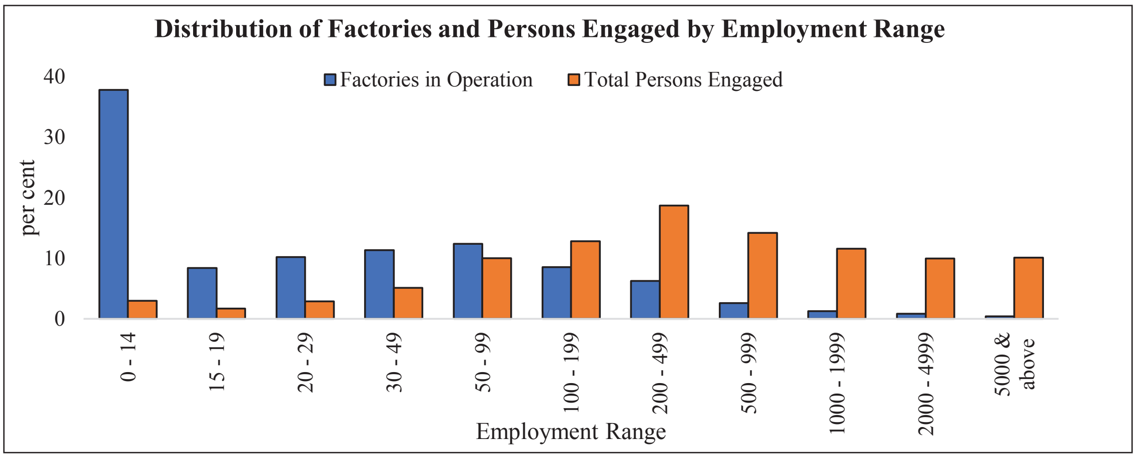

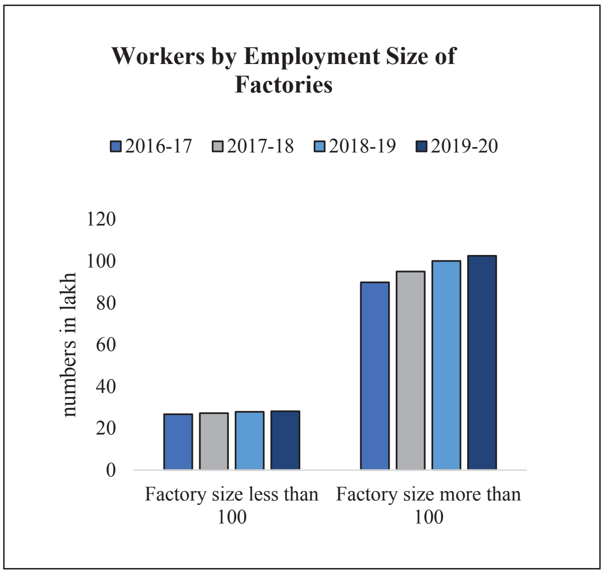

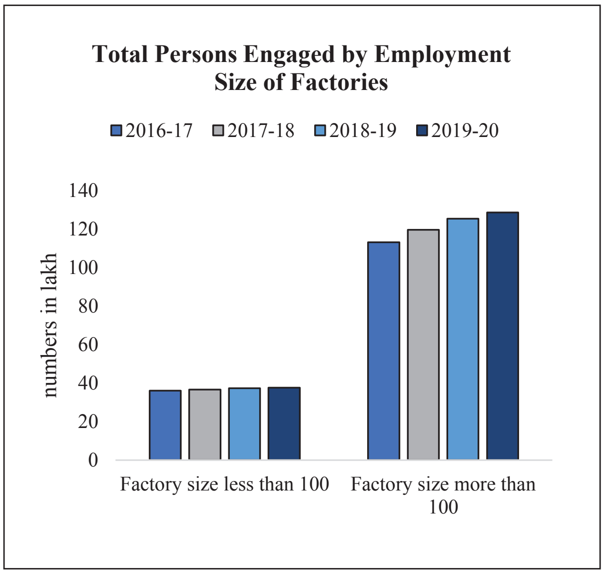

स्रोत: एएसआई, एमओएसपीआई

औपचारिक रोजगार

6.41 रोजगार सृजन के साथ - साथ रोजगार में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। इस मार्ग को अपनाते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के लिए पेरोल डेटा ने आंकी गई संगठित क्षेत्र में नौकरी बाजार की स्थितियां, सभी योजनाओं में श्रम बाजार में सुधार की दिशा में सरकार की पहल के लाभों को दर्शाया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंकड़े पेरोल वृद्धि में साल-दर-साल लगातार वृद्धि का संकेत देते हैं, जो आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने के साथ औपचारिकता में सुधार की ओर इशारा करता है। वित्त वर्ष 22 के दौरान ईपीएफ अंशदान में शुद्ध वृद्धि वित्त वर्ष 21 की तुलना में 58.7 प्रतिशत अधिक थी और पूर्व - महामारी वर्ष 2019 की तुलना में 55.7 प्रतिशत अधिक थी। वित्त वर्ष 23 में, ईपीएफओ के तहत जोड़े गए शुद्ध औसत मासिक ग्राहक अप्रैल - नवंबर 2021 में 8.8 लाख से बढ़ कर अप्रैल - नवंबर 2022 में 13.2 लाख हो गए।

6.42 अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, कोविड-19 रिकवरी चरण में रोजगार सृजन में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने और महामारी के दौरान खोए हुए रोजगार की बहाली के लिए। अक्टूबर 2020 में शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) को औपचारिक क्षेत्र के पेरोल में तेजी से वृद्धि का श्रेय दिया जा सकता है। जनवरी 2023 तक, योजना के तहत कुल पंजीकरण 75.1 लाख है, और 1.5 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 60.2 लाख लाभार्थियों को कुल 8,210 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया है।

6.43 इसी अवधि के लिए ईएसआईसी के तहत औसत मासिक ग्राहक वृद्धि 11.9 लाख से बढ़कर 14.4 लाख हो गई। इसी तरह, एनपीएस के तहत, 'अप्रैल-अक्टूबर की अवधि के लिए औसत मासिक शुद्ध सदस्यता 2021 में 61.9 हजार से बढ़कर 2022 में 63.2 हजार हो गई।[31]

[31]पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से डेटा।

चित्र VI.10: ईपीएफओ में ग्राहकों की शुद्ध वृद्धि (लाख में)

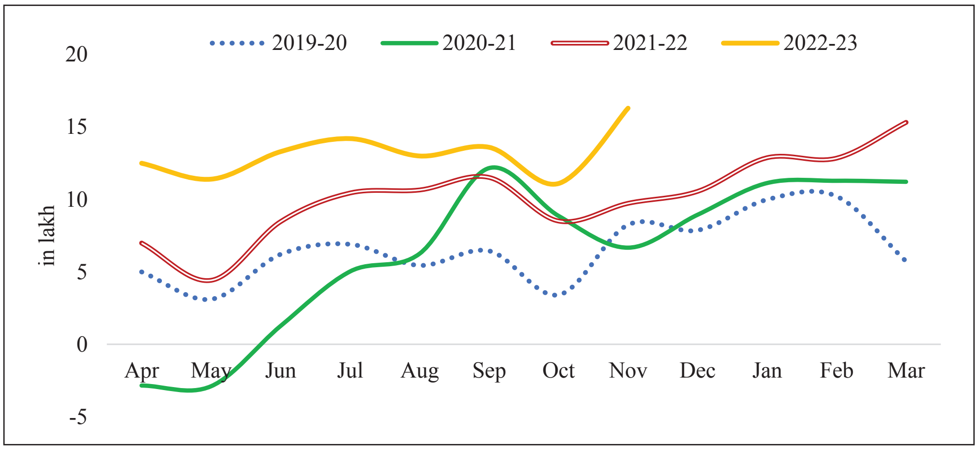

स्रोत: ईपीएफओ

नोट: पेरोल में शुद्ध वृद्धि = नए ग्राहकों की संख्या + बाहर निकलने वाले सदस्यों की संख्या जो फिर से शामिल हो गए - बाहर निकलने वाले सदस्यों की संख्या।

6.44 औद्योगिक संरचना के संदर्भ में, विशेषज्ञ सेवाएं (जनशक्ति एजेंसियों, निजी सुरक्षा एजेंसियों और छोटे ठेकेदारों आदि को मिलाकर) ईपीएफओ पेरोल वृद्धि (वित्त वर्ष 23, अप्रैल - नवंबर में 41.1 प्रतिशत) का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसके बाद व्यापार-वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (6.9 प्रतिशत) है। सभी आयु समूहों में, 18-25 वर्ष के आयु समूह ने अप्रैल - नवंबर 2022 में शुद्ध पेरोल वृद्धि में 48.5 प्रतिशत का योगदान दिया। लगभग 62.7 प्रतिशत शुद्ध पेरोल वृद्धि 29 वर्ष से कम आयु (इसी अवधि में) में हुई।), संगठित क्षेत्र में नई नौकरियां मुख्य रूप से युवाओं को मिली हैं। 18-25 वर्ष आयु वर्ग में, महाराष्ट्र (21.4 प्रतिशत), कर्नाटक (12.1 प्रतिशत), तमिलनाडु (10.9 प्रतिशत), हरियाणा (9.0 प्रतिशत), गुजरात (8.4 प्रतिशत), और दिल्ली (7.6 प्रतिशत) प्रतिशत) ने अप्रैल - नवंबर 2022 में शुद्ध पेरोल में लगभग 70 प्रतिशत का योगदान दिया।

तालिका VI.8: सभी आयु समूहों में मुख्य उद्योगों के लिए ईपीएफओ पेरोल डेटा *(लाख में)*

उद्योग	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अप्रैल-नवंबर)	2022-23 में : हिस्सा
विशेषज्ञ सेवाएं	35.2	37.0	51.7	43.4	41.1
व्यापार - वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	5.2	3.4	8.7	7.3	6.9
अन्य	1.5	2.6	7.3	7.1	6.8
इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग। ठेकेदारों	4.1	4.9	6.2	5.6	5.4
भवन और निर्माण उद्योग	5.1	4.7	6.0	5.5	5.2
चुनाव।, मेक। या जनरल इंजीनियरिंग। उत्पादों	3.8	3.8	4.9	4.9	4.7
निर्माण, मार्केटिंग सर्विसिंग, कंप्यूटर के उपयोग में लगी स्थापना	2.7	2.0	4.4	2.9	2.7
सफाई, स्वीपिंग सेवाओं में लगे प्रतिष्ठान	1.8	2.5	3.3	3.0	2.8
कपड़ा	1.7	1.7	3.1	2.0	1.0
कुल योग (सभी उद्योग)	**78.6**	**77.1**	**122.3**	**105.4**	**100.0**

स्रोत: ईपीएफओ, एमओएलई

मनरेगा के तहत काम की मांग

6.45 मनरेगा के तहत काम मांगने वाले लोगों की संख्या जुलाई से नवंबर 2022 तक महामारी से पहले के स्तर के आसपास देखी गई थी। इसे मजबूत कृषि विकास और कोविड प्रेरित मंदी से तेजी से बहाली के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सामान्यीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर रोजगार के अवसर सामने आए। 24 जनवरी 2023 तक 6.49 करोड़ परिवारों ने मनरेगा के तहत रोजगार की माँग की और 6.48 करोड़ परिवारों को रोजगार की पेशकश की गई जबकि 5.7 करोड़ परिवारों ने रोजगार का लाभ उठाया।

चित्र VI.11: मनरेगा के तहत काम मांगने वाले व्यक्तियों की संख्या

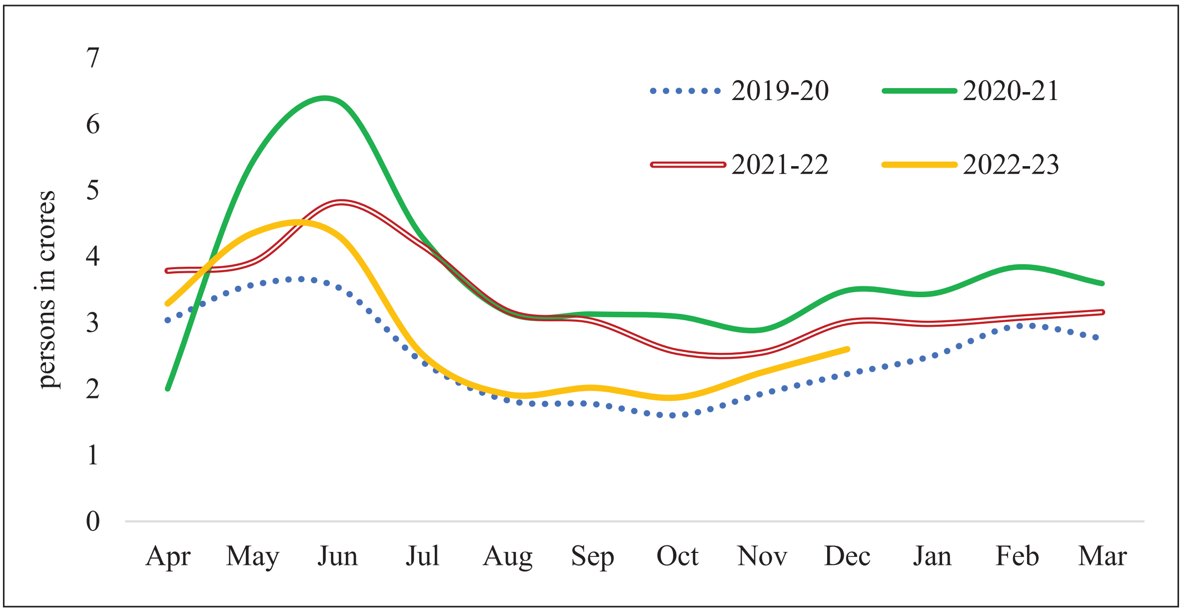

स्रोत: मनरेगा वेब पोर्टल

6.46 मनरेगा के तहत किए गए कार्यों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है, वित्तीय वर्ष 22 में 85 लाख पूर्ण कार्य पूर्ण हुए हैं और वित्त वर्ष 23 में अब तक 70.6 लाख कार्य (9 जनवरी 2023 तक) पूर्ण हो चुके हैं। कार्यों की संरचना के संबंध में, 'व्यक्तिगत भूमि पर किए गए कार्यों' (2009 में अनुमेय कार्य सूची में शामिल और तब से विस्तारित) का हिस्सा वित्त वर्ष 2015 के कुल पूर्ण कार्यों के 16 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 73 प्रतिशत हो गया है। इन कार्यों में घरेलू संपत्ति जैसे पशु घर, खेत तालाब, खोदे गए कुएं, बागवानी बागान, वर्मीकम्पोस्टिंग पिट आदि शामिल हैं, जिसमें लाभार्थी को मानक दरों के अनुसार श्रम और सामग्री लागत दोनों मिलती है। प्रायोगिक रूप से, 2-3 वर्षों की छोटी अवधि में, इन संपत्तियों को कृषि उत्पादकता, उत्पादन-संबंधी व्यय और प्रति परिवार आय पर महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव के साथ-साथ प्रवासन और ऋणग्रस्तता में गिरावट विशेष रूप से गैर-संस्थागत स्रोतों से, के साथ नकारात्मक संबंध देखा गया है।[32] आय विविधीकरण में सहायता करने और ग्रामीण आजीविका में लचीलापन लाने के लिए इसके दीर्घकालिक निहितार्थ हैं।

[32]मनरेगा के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन घटक का तेजी से आकलन और सतत आजीविका पर इसका प्रभाव, आर्थिक विकास संस्थान, मई 2018

चित्र VI.12: मनरेगा के अंतर्गत परियोजनाओं की संख्या

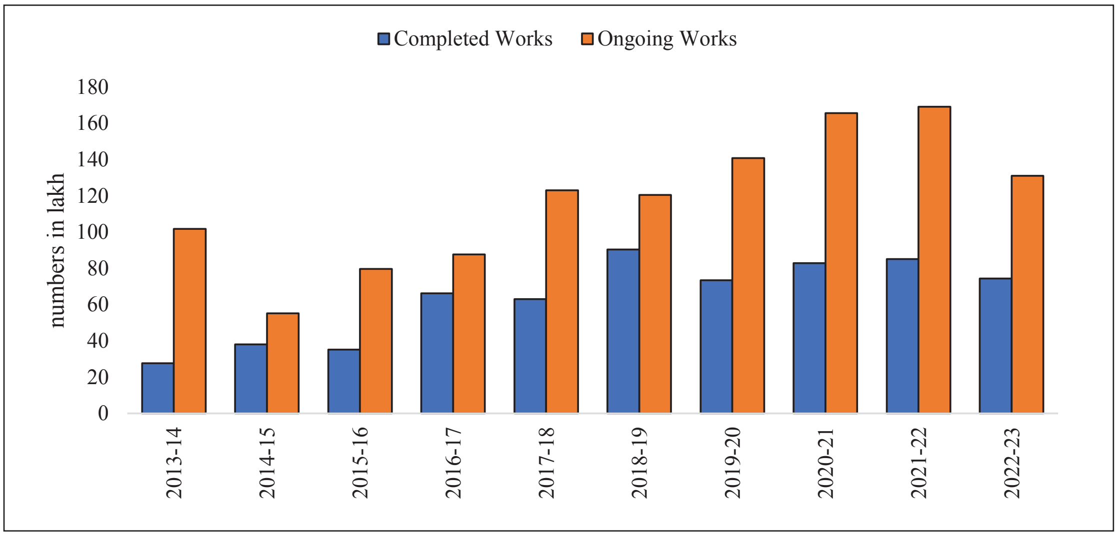

चित्र VI.13: मनरेगा के तहत पूर्ण कार्यों का हिस्सा (गणना के अनुसार)

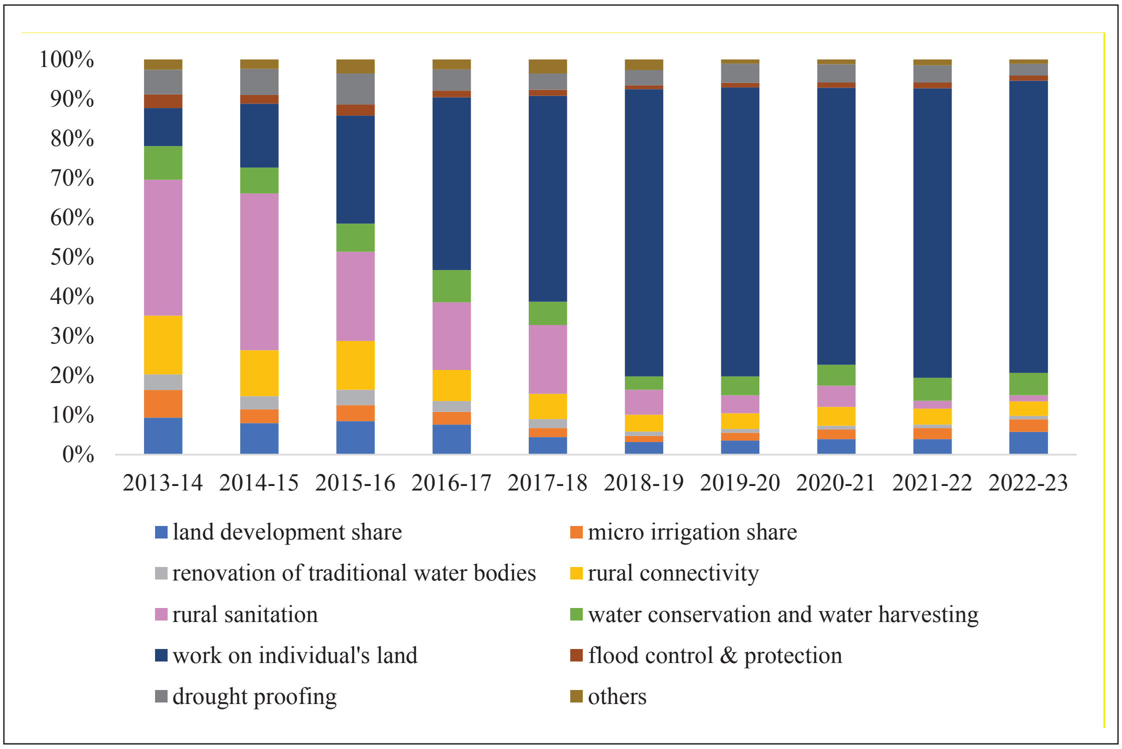

स्रोत: MGNREGS वेब पोर्टल, FY23 के लिए डेटा 10 जनवरी 2023 तक है

6.47 सरकार सभी पात्र और काम करने के इच्छुक लोगों के लिए रोजगार के अवसरों की पहुंच बढ़ाने के लिए कई उपाय कर रही है। नेशनल करियर सर्विस (NCS) प्रोजेक्ट भी ऐसा ही उपाय है, जिसका विवरण बॉक्स VI-4 में दिया गया है।

बॉक्स: VI-4: नेशनल कैरियर सर्विस (एनसीएस) परियोजना

'नेशनल कैरियर सर्विस (एनसीएस)' परियोजना का प्रारंभ जुलाई 2015 को रोजगार और व्यवसाय से संबंधित सेवाओं की श्रेणी के एकमात्र समाधान के रूप में किया गया था। यह उम्मीदवारों व नियोक्ताओं, प्रशिक्षण तथा कैरियर मार्गदर्शन चाहने वाले उम्मीदवार और प्रशिक्षण / कैरियर परामर्श प्रदान करने वाली एजेंसियों के बीच अन्तराल को कम करने की दिशा में काम करता है। एनसीएस पोर्टल में सभी हितधारकों अर्थात मॉडल कैरियर केंद्रों, नोडल अधिकारियों, रोजगार चाहने वालों और नियोक्ताओं को शामिल करके एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 'जॉब फेयर' गतिविधि की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने वाला एक जॉब फेयर मॉड्यूल है। उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए इसकी एक समर्पित हेल्पलाइन (बहुभाषी) भी है।
5 जनवरी 2023 तक, 2.8 करोड़ नौकरी चाहने वालों और 6.8 लाख नियोक्ताओं ने एनसीएस पोर्टल में पंजीकरण कराया है, 2.5 लाख सक्रिय रिक्तियों और कुल 1.2 करोड़ रिक्तियों को जुटाया गया है और राष्ट्रीय कैरियर सेवा के हिस्से के रूप में 9100 से अधिक नौकरी मेले आयोजित किए गए हैं।

एनसीएस ने डिजिसक्षम कार्यक्रम के अंतर्गत निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी की है ताकि "व्यवसाय कौशल" पर एक निः शुल्क, स्व-केंद्रित ऑनलाइन / ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश की जा सके, ताकि नौकरी चाहने वालों को उनकी रोजगार क्षमता में सुधार के जनादेश के साथ सॉफ्ट और डिजिटल कौशल से लैस किया जा सके। इस कार्यक्रम में उन्नत कंप्यूटिंग क्षेत्र भी शामिल हैं और इसे निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। एनसीएस शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और का अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के साथ भी मिलकर काम कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका लाभ संभावित छात्रों / उम्मीदवारों तक पहुंच रहा है। एनसीएस पोर्टल पर कार्यबल के देशव्यापी डेटाबेस के माध्यम से सही उम्मीदवारों का चयन (शॉर्टलिस्ट) करने में सक्षम बनाने के लिए इच्छुक नियोक्ताओं को जोड़ने के लिए ईपीएफओ और ईएसआईसी के साथ ऑनलाइन एकीकरण भी किया गया है। एनसीएस ने डिजिलॉकर के साथ भी एकीकरण किया है ताकि उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज / प्रमाण- पत्र अपलोड करने में सक्षम बनाया जा सके और उन्हें नियोक्ताओं को उपलब्ध करवाकर भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जा सके।

2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार, एनसीएस पोर्टल को e-SHRAM, UDYAM और स्किल इंडिया पोर्टल (ASEEM पोर्टल के प्राथमिक डेटा स्रोत) के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा गया है। इसके परिणामस्वरूप नौकरी खोजने वालों और नियोक्ताओं दोनों के लिए नौकरी की खोज और मिलान की सुविधा के लिए एक रोजगार संतुलन / पारिस्थितिकी तंत्र का विकास हुआ है। अब तक, ई-श्रम से 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने एनसीएस पर पंजीकरण कराया है, जिनमें से 1 लाख से अधिक उम्मीदवारों को नौकरियों के लिए नियोक्ताओं द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया है। स्किल इंडिया पोर्टल के 46 लाख से अधिक कुशल उम्मीदवारों को डेटा एक्सचेंज के माध्यम से एनसीएस पर पंजीकृत किया गया है। ये उम्मीदवार भावी नियोक्ताओं को अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं, इस प्रकार वे नौकरी पाने के अपने अवसर को बढ़ा सकते हैं। UDYAM और एनसीएस (NC) के बीच एकीकरण ने 4,76,650 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के नियोक्ताओं को एनसीएस पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है।
राष्ट्रीय करियर सेवा ने हाल ही में मार्च 2022 में पोर्टल पर 'अंतर्राष्ट्रीय नौकरी' मॉड्यूल जोड़ा है जो विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत नियोक्ताओं को एनसीएस पोर्टल पर अंतरराष्ट्रीय नौकरी के अवसर पोस्ट करने और नौकरी चाहने वालों को एनसीएस पोर्टल के माध्यम से इन अवसरों को खोजने और आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। अब तक, 400 से अधिक भर्ती एजेंटों (आरए) ने एनसीएस पर पंजीकरण किया है और लगभग 1400 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रिक्तियों को पोस्ट किया है।

ग्रामीण मजदूरी में रूझान

6.48 वित्त वर्ष 23 (नवंबर 2022 तक) के दौरान नाममात्र ग्रामीण मजदूरी स्थिर सकारात्मक दर से बढ़ी है। कृषि में, अप्रैल-नवंबर 2022 की अवधि के दौरान, कृषि में नाममात्र मजदूरी दरों की वृद्धि दर पुरुषों के लिए

5.1 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 7.5 प्रतिशत थी। गैर-कृषि गतिविधियों में, समान अवधि के दौरान पुरुषों के लिए नाममात्र मजदूरी दरों की वृद्धि 4.7 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 3.7 प्रतिशत थी। हालांकि, बढ़ी हुई मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि नकारात्मक रही है। आगे बढ़ते हुए, चूंकि अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतों और घरेलू खाद्य कीमतों में कमी के साथ मुद्रास्फीति के नरम होने की उम्मीद है, यह उम्मीद की जाती है कि यह वास्तविक मजदूरी में वृद्धि में तब्दील हो जाएगा।

चित्र VI.14: ग्रामीण मजदूरी में रुझान

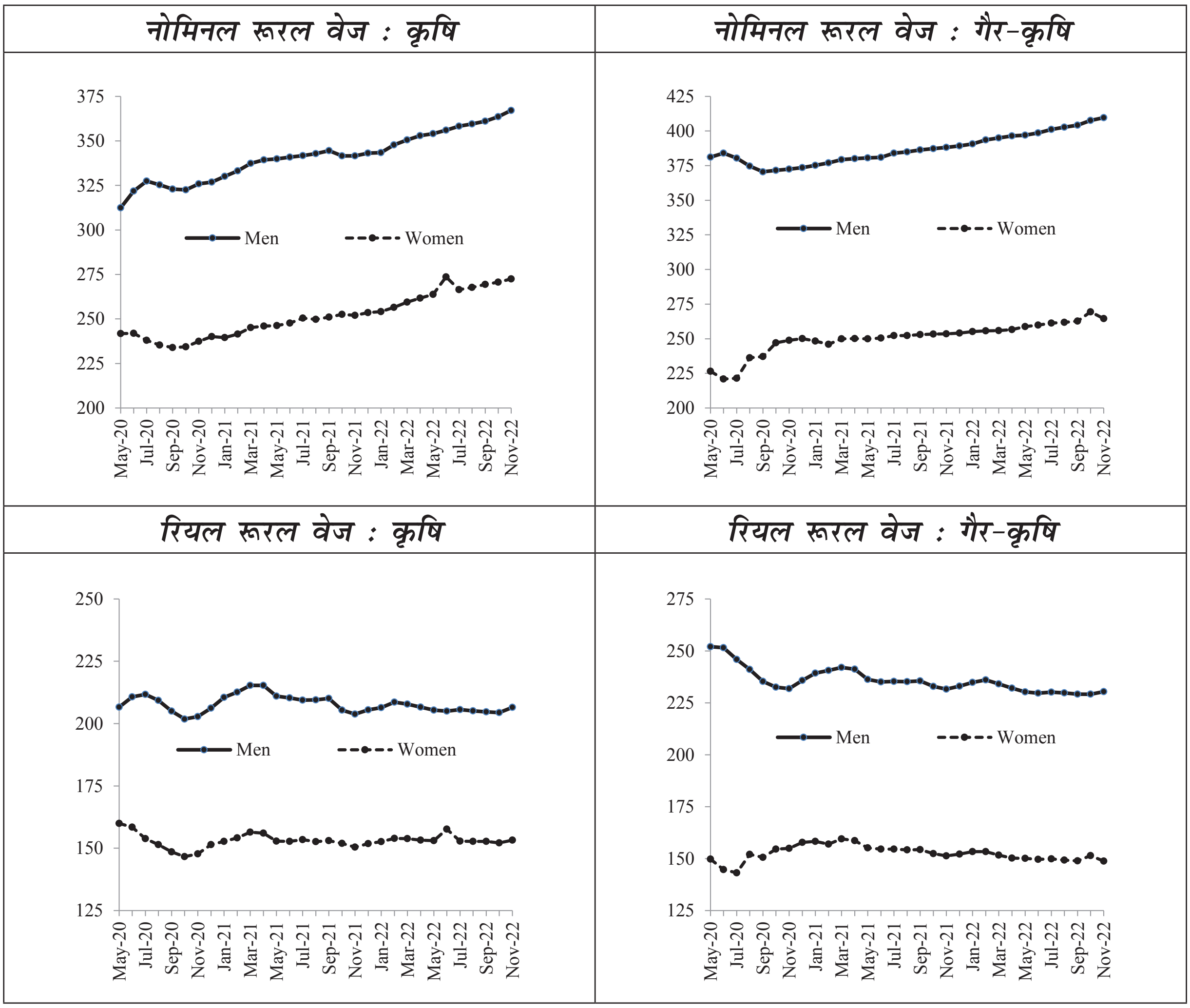

स्रोतः श्रम ब्यूरो द्वारा निर्धारित मासिक ग्रामीण मजदूरी दरें

सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना

6.49 सभी के लिए शिक्षा का महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता चूंकि यह प्रत्येक व्यक्ति और समाज के विकास की नींव है। जैसा कि डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम ने कहा था- "सीखना रचनात्मकता देता है,रचनात्मकता विचार की ओर ले जाती है, विचार ज्ञान की ओर ले जाता है, ज्ञान आपको महान बनाता है !"

6.50 शिक्षा, कामकाजी उम्र की आबादी की रोजगार क्षमता बढ़ाने के अतिरिक्त, गरीबी और सामाजिक हाशिए के चक्र को तोड़ने में भी समान प्रभाव डालती है। 'क्वालिटी एजुकेशन' जिसे संयुक्त राष्ट्र एसडीजी (एसडीजी 4) के अंतर्गत लक्ष्य 4 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, का उद्देश्य 2030 तक 'समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है और सभी के लिए आजीवन सीखते रहने के अवसरों को बढ़ावा देना' है। इस

लक्ष्य का मूल्यांकनात्मक महत्व है क्योंकि इसके परिवर्तनकारी प्रभाव अन्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर हो सकते हैं, जैसे 'नो पावटी', 'नो - हंगर', 'जेंडर - इक्वलिटी' आदि। सतत विकास, वास्तव में, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक बच्चे पर केन्द्रित होता है, जो उसको उसकी पूर्ण क्षमता तक विकसित करने और 'प्रोडक्टिव सिटीजन' बनने में साधन उपलब्ध करवाता है इससे उसके स्वयं की सामाजिक आर्थिक प्रगति होती और वह अपने राष्ट्र की सहायता करता।

6.51 इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) को 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति के रूप में निधारित किया गया था, जिसका लक्ष्य देश की कई बढ़ती विकास संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाना था। यह स्वीकार करते हुए कि शिक्षा भारत जैसे युवा देश के लिए मानव पूंजी निर्माण की जीवन दायिनी है, यह नीति शिक्षा ढांचे के सभी पहलुओं में संशोधन और सुधार के लिए बनायी गई है। इसमें भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणालियों का निर्माण करते हुए एसडीजी 4 सहित 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के साथ सरेखित एक नई प्रणाली का निर्माण, उसका विनियमन और नियंत्रण शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समावेशी, सफलभ और बहुभाषी परिस्थिति में युवाओं द्वारा सर्वागीण विकास और कौशल अधिग्रहण का पोषण करती है।

6.52 एकीकृत दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, भारत सरकार ने प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में 2018 में समग्र शिक्षा की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।

स्कूल नामांकन

6.53 वित्त वर्ष 22 में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)[34] में सुधार और लिंग समानता में सुधार देखा गया। 6 से 10 वर्ष की आयु के लड़के-लड़कियों की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में कक्षा ᐟ से ट के प्राथमिक नामांकन में वित्त वर्ष 22 में सकल नामांकन अनुपात में सुधार हुआ है। इस सुधार ने वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 19 के बीच गिरावट की प्रवृत्ति को उलट दिया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (11-13 वर्ष की आयु में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में छठी से आठवीं कक्षा में नामांकन), जो वित्तवर्ष 17 और वित्तर्ष 19 के बीच स्थिर था, वित्तवर्ष 22 में सुधार हुआ। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर संबंधित आयु समूहों में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात लड़कों की तुलना में बेहतर है।

तालिका VI.9: स्कूल सकल नामांकन अनुपात (प्रतिशत में)

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय			माध्यमिक स्कूल		
	लड़कियां	लड़के	कुल	लड़कियां	लड़के	कुल	लड़कियां	लड़के	कुल
2013-14	107.9	106.5	107.2	88.6	85.0	86.7	73.5	74.2	73.8
2019-20	103.7	101.9	102.7	90.5	88.9	89.7	77.8	78.0	77.9
2020-21	104.5	102.2	103.3	92.7	91.6	92.2	79.5	80.1	79.8
2021-22	104.8	102.1	103.4	94.9	94.5	94.7	79.4	79.7	79.6

स्रोत: शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई+)[35]

टिप्पणी: 1. UDISE+ डेटा एक वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद आता है, इसलिए डेटा 2021-22 तक उपलब्ध है

2. 100 प्रतिशत से अधिक सकल नामांकन अनुपात किसी विशेष स्तर की शिक्षा में अधिक या कम आयु के बच्चों की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है।

---

[34]नियोजित कुल व्यक्तियों में उपरोक्त परिभाषित कर्मचारी और सभी कार्यरत प्रोपराइटर और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं जो बिना किसी वेतन के भी कारखाने के काम में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, और इसमें सहकारी समितियों के अवैतनिक सदस्य भी हैं, जिन्होंने किसी भी प्रत्यक्ष और उत्पादक क्षमता में कारखाने में या उसके लिए काम किया है।

[35]पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से डेटा।

6.54 वित्त वर्ष 22 में कुल मिलाकर 26.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नामांकित हुए और 19.4 लाख अतिरिक्त बच्चों को प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नामांकित किया गया। वित्त वर्ष 22 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) का कुल नामांकन 22.7 लाख है, जबकि वित्त वर्ष 21 में यह 21.9 लाख था, जो 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पूर्व - प्राथमिक स्तर को छोड़कर सभी स्तरों अर्थात प्राथमिक, उच्च-प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में नामांकन में वृद्धि हुई है। पूर्व - प्राथमिक स्तर पर, वित्त वर्ष 21 में नामांकन 1.1 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 22 में 1.0 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान पूर्व - प्राथमिक स्तर पर लगभग 1.0 करोड़, प्राथमिक पर 12.2 करोड़, उच्च प्राथमिक पर 6.7 करोड़, माध्यमिक पर 3.9 करोड़ और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 2.9 करोड़ बच्चों का नामांकन हुआ।

स्कूल ड्राप आउट

6.55 हाल के वर्षों में सभी स्तरों पर स्कूल ड्राप आउट40 की दर में लगातार गिरावट देखी गई है। लड़कियों और लड़कों दोनों में गिरावट देखी गई है। समग्र शिक्षा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, स्कूल के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार, आवासीय छात्रावास भवन, शिक्षकों की उपलब्धता, शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण जैसी योजनाएं स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और बच्चों की स्कूलों में पढाई जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

तालिका VI.10: स्कूल ड्रापआउट रेट

(प्रतिशत में)

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय			माध्यमिक स्कूल		
	लड़कियां	लड़के	कुल	लड़कियां	लड़के	कुल	लड़कियां	लड़के	कुल
2013-14	4.7	4.7	4.7	4.0	2.3	3.1	14.5	14.5	14.5
2019-20	1.2	1.7	1.5	3.0	2.2	2.6	15.1	17.0	16.1
2020-21	0.7	0.8	0.8	2.6	2.0	2.3	13.7	14.3	14.0
2021-22	1.4	1.6	1.5	3.3	2.7	3.0	12.3	13.0	12.6

स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर (अपसरंचना)

6.56 अध्यापन विज्ञान पर ध्यान देने के साथ-साथ स्कूलों, सुविधाओं और डिजिटलीकरण के रूप में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को लगातार बढ़ावा दिया गया है। शिक्षा क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों के लाभांश आने वाले दशकों में देश की वृद्धि और विकास की संभावनाओं को समृद्ध करेंगे। स्कूलों में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं - मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या और छात्र-शिक्षक अनुपात में परिलक्षित शिक्षकों की उपलब्धता दोनों के संदर्भ में वित्त वर्ष 22 में सुधार दिखा। विभिन्न स्तरों के लिए मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या में प्रवृत्ति एक स्थिर प्रगति दिखती है।

तालिका VI.11: भारत में स्कूल छोड़ने वालों की दर (प्रतिशत में)

	2013-14	2019-20	2020-21	2021-22
Total Schools	15.2	15.1	15.1	14.9
Primary & Upper Primary schools	12.9	12.2	12.2	11.9
Secondary & Sr. Secondary Schools	2.3	2.9	2.9	2.9

[36]ड्रॉपआउट दर को किसी प्रदत्त स्कूल वर्ष में किसी प्रदत्त स्तर पर नामांकित समूह के विद्यार्थियों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अगले स्कूल वर्ष में किसी भी ग्रेड में नामांकित नहीं होते हैं।

6.57 स्कूलों में मेडिकल चेक-अप को छोड़कर वित्त वर्ष 22 में पिछले वर्षों की तुलना में स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार जारी रहा, क्योंकि स्कूल कोविड-19 प्रतिबंधों के मद्देनजर भौतिक रूप से बंद रहे। । अधिकांश सरकारी स्कूलों में अब शौचालय (लड़कियों या लड़कों के लिए), पीने का पानी और हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है। समग्र शिक्षा योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत विद्यालयों में पेयजल एवं स्वच्छता की प्राथमिकता विद्यालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और इन परिसंपत्तियों के निर्माण में सहायक रहे हैं। समग्र शिक्षा योजना के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) घटक के तहत, सरकार स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं और आईसीटी प्रयोगशालाओं की स्थापना में सहायता करती है, जिसमें हार्डवेयर, शैक्षिक सॉफ्टवेयर और शिक्षण के लिए ई-सामग्री शामिल है।

तालिका VI.12: स्कूल अवसरंचना में सुधार
(सभी स्कूलों के प्रतिशत के रूप में बुनियादी सुविधाओं वाले स्कूल)

वर्ष	2012-13	2019-20	2020-21	2021-22
लड़कियों का शौचालय	88.1	96.9	97.3	97.5
लड़कों का शौचालय	67.2	95.9	96.2	96.2
हाथ धोने की सुविधा	36.3	90.2	91.9	93.6
पुस्तकालय/ वाचनालय/ रीडिंग कार्नर	69.2	84.1	85.6	87.3
विद्युत	54.6	83.4	86.9	89.3
वर्ष में स्कूल में चिकित्सा जांच	61.1	82.3	50.4'	54.6'
कम्प्यूटर	22.2	38.5	41.3	47.5
इंटरनेट	6.2	22.3	24.5	33.9

'कोविड के कारण विद्यालय प्रत्यक्ष रूप से बंद थे। इसलिए, बहुत कम चिकित्सा जांच की गई।
स्रोत: यूडीआईएसई+

6.58 इसके अतिरिक्त, शिक्षकों की उपलब्धता, जिसे छात्र - शिक्षक अनुपात द्वारा मापा जाता है, संकेतक जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से विलोम संबंध रखता है, में वित्त वर्ष 13 से वित्त वर्ष 22 की अवधि में लगातार सभी स्तरों: प्राथमिक स्तर पर 34.0 से 26.2, उच्च प्राथमिक में 23.0 से 19.6, माध्यमिक में 30.0 से 17.6 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 39.0 से 27.1, तक की कमी हुई जिसके परिणाम स्वरुप शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ। स्कूलों की संख्या, शिक्षकों की उपलब्धता और स्कूलों में सुविधाओं के सुधार से नामांकन में सुधार होने और (ड्रॉपआउट) की दरों को कम किए जाने की आशा है।

वित्त वर्ष 23 के दौरान स्कूली शिक्षा के लिए शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं निम्नलिखित पैरा में प्रस्तुत की गई हैं।

6.59 **प्रधान मंत्री - स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM SRI):** सरकार ने 7 सितंबर, 2022 को पीएम - स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (उभरते भारत के लिए स्कूल) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन का निष्पादन करेंगे और समय के साथ-साथ आस-पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करते हुए अनुकरणीय स्कूलों के रूप में उभरेंगे। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार / राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेश सरकार / स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके वित्त वर्ष 23 से वित्त वर्ष 27 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है।

इन स्कूलों में लैब, स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आर्ट रूम समेत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सज्जित तथा समावेशी होगा और इनका उपयोग विद्यार्थी कर सकेंगे। इन स्कूलों को जल संरक्षण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, ऊर्जा-कुशल बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम में 'आर्गेनिक लाइफस्टाइल' के एकीकरण के साथ ग्रीन स्कूल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। जिससे 20 लाख से अधिक छात्रों को इस योजना से प्रत्यक्ष लाभ मिलने की आशा है।

6.60 **फाउडेशनल स्टेज (मूलभूत स्तर की शिक्षा) के लिये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा):** मूलभूत स्तर की शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को नए 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर के रूप में लॉन्च किया गया है, जो 3 से 8 साल की उम्र के सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा को एकीकृत करता है। जैसा कि एनईपी 2020 में स्पष्ट किया गया है, नींव चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे में पाठ्यक्रम की व्यवस्था के लिए वैचारिक, परिचालन एवं आपस में संवाद संबंधी दृष्टिकोणों, अध्यापन, समय एवं सामग्री की व्यवस्था, और बच्चे के समग्र अनुभव के मूल में 'खेल' का उपयोग किया गया है। यह इस चरण के दौरान वांछित विकासात्मक परिणामों को मूर्तरूप देने और विकसित करने में शिक्षकों के साथ-साथ माता-पिता और समाज की भूमिका को बताता है।

6.61 **बालवाटिका का पायलट प्रोजेक्टः** 49 केन्द्रीय विद्यालयों में 3+, 4+ और 5+ आयु वर्ग के छात्रों के लिए संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर क्षमताओं को विकसित करने और प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता पर ध्यान देने के साथ प्रोजेक्ट बालवाटिका, यानी 'तैयारी कक्षा' अक्टूबर 2022 में शुरू की गई थी।

6.62 **खिलौना आधारित अध्यापन** - विज्ञान स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्वदेशी खिलौनों और उनके अध्यापन - विज्ञान के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए खिलौना आधारित अध्यापन - विज्ञान की एक पुस्तिका तैयार की गई है। यह छात्रों को विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए आयु-उपयुक्त खिलौनों को चुनने या बनाने में शिक्षकों की सहायता करेगी।

6.63 **सीखने की विशिष्ट क्षमताओं के लिए स्क्रीनिंग टूल्स (मोबाइल ऐप, प्रशस्त)।** PRASHAST ऐप स्कूल स्तर पर विकलांगता की स्थिति की जांच करने में मदद करेगा और समग्र शिक्षा के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रमाणीकरण प्रक्रिया शुरू करने तथा अधिकारियों के साथ साझा करने के लिए स्कूल-वार रिपोर्ट तैयार करेगा।

6.64 **नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ):** नई शिक्षा नीति के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, एनसीआरएफ स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को समेकित रूप से एकीकृत करने, स्किलिंग, री - स्किलिंग, अप - स्किलिंग, मान्यता और मूल्यांकन के लिए एक व्यापक ढांचा है जोकि नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NHEQF)] नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) और नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSEQF) को सम्मिलित करता है। यह छात्रों की भावी प्रगति के लिए कई विकल्प खोल देगा और व्यावसायिक विद्या व प्रयोगात्मक विद्या के साथ स्कूल और उच्च शिक्षा को आपस में मिलाने के लिए एक महापरिवर्तनकारी कारक होगा, इस प्रकार कौशल और व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाया जाएगा। 19 अक्टूबर 2022 को सार्वजनिक परामर्श के लिए रूपरेखा जारी की गई है।

6.65 **राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणाम का सुदृढ़ीकरण (स्टार्स):** योजना स्टार्स योजना को छह राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और केरल में 5 वर्षों की अवधि में अर्थात वित्त वर्ष 25 तक आंशिक रूप से विश्व बैंक के ऋण द्वारा वित्तपोषित केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य चयनित राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना है।

6.66 **विद्यांजलि (स्कूल स्वयंसेवी पहल):** समाज, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से देश भर के स्कूलों को सुदृढ़ करने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से, सरकार ने विद्यांजलि (स्कूल स्वयंसेवी प्रबंधन कार्यक्रम) की शुरूआत की है। विद्यांजलि पोर्टल (https%@@ vidyanjali-education-gov-in@en) समुदाय और स्वयंसेवकों/संगठनों को उनकी पसंद के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ बातचीत करने और सीध जुड़ने और उनके ज्ञान और कौशल को साझा करने और / या स्कूलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संपत्ति/सामग्री/उपकरण के रूप में योगदान करने में सक्षम बनाता है। 20 जनवरी 2023 तक, 3,95,177 स्कूलों को जोड़ा गया है और 1,14,674 स्वयंसेवकों ने विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। यह कार्यक्रम पूरे देश में लगभग 11,34,218 छात्रों को सहायता देने में सफल रहा है इसमें कई क्षेत्रों में स्वयंसेवकों का समर्थन लेकर अध्ययन विषय से संबंधित जानकारी, प्रतिभाशाली बच्चों को परामर्श, व्यावसायिक कौशल शिक्षण, छत के पंणें और वाटर प्यूरीफायरों का दिया जाना, वर्चुअल मोड और संगीत वाद्ययंत्रों के माध्यम से शिक्षण देने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपहार देना, स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा संबंधी प्रशिक्षण देना, बेसिक सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर और कक्षा की अन्य जरूरतों आदि के लिए सहायता करना सम्मिलित है।

6.67 **समग्र शिक्षा योजना:** स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की समग्र शिक्षा की एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। समग्र शिक्षा योजना को एनईपी 2020 की सिफ़ारिशों के साथ जोड़ा गया है और वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 26 तक बढ़ाया गया है। योजना के आईसीटी घटक के तहत, देश भर में पाठ्यक्रम-आधारित इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया, डिजिटल किताबें, वर्चुअल लैब आदि विकसित और वितरित करके बच्चों को कंप्यूटर साक्षरता और कंप्यूटर-सक्षम शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। यह स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं और आईसीटी प्रयोगशालाओं की स्थापना का समर्थन करता है, जिसमें हार्डवेयर, शैक्षिक सॉफ्टवेयर और शिक्षण के लिए ई-सामग्री शामिल है। इसमें छठी से बारहवीं कक्षा तक के सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। नवंबर 2022 तक (स्थापना के बाद से), देश भर के 1,20,614 स्कूलों और 82,120 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं में आईसीटी प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है।

उच्च शिक्षा

6.68 15-29 वर्ष आयु वर्ग[37] में भारत की 27 प्रतिशत से अधिक आबादी के साथ, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी में से एक के लिए, भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली परिवर्तन की प्रयोगशाला है। समय के साथ उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाया गया है। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 में 387 से बढ़ाकर 2022 में 648 कर दी गई है और एमबीबीएस सीटों की संख्या 51,348 से बढ़ाकर 96,077 कर दी गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) की संख्या क्रमशः 2014 में 16 और 13 के मुकाबले 2022 में 23 और 20 पर है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIIT) की संख्या 2014 में 9 के मुकाबले 2022 में 25 है। 2014 में, देश में 723 विश्वविद्यालय थे, जिन्हें बढ़ाकर 1,113 कर दिया गया है।

6.69 उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वित्त वर्ष 20 में 3.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 21 में लगभग 4.1 करोड़ हो गया है। वित्त वर्ष 15 के बाद से, नामांकन में लगभग 72 लाख (21 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 20 में 1.9 करोड़ से वित्त वर्ष 21 में महिला नामांकन बढ़कर 2.0 करोड़ हो गया है।

[37]भारत में युवा 2022 रिपार्ट, एमओएसपीआई

चित्र VI.15: उच्च शिक्षा में छात्रों का कुल नामांकन

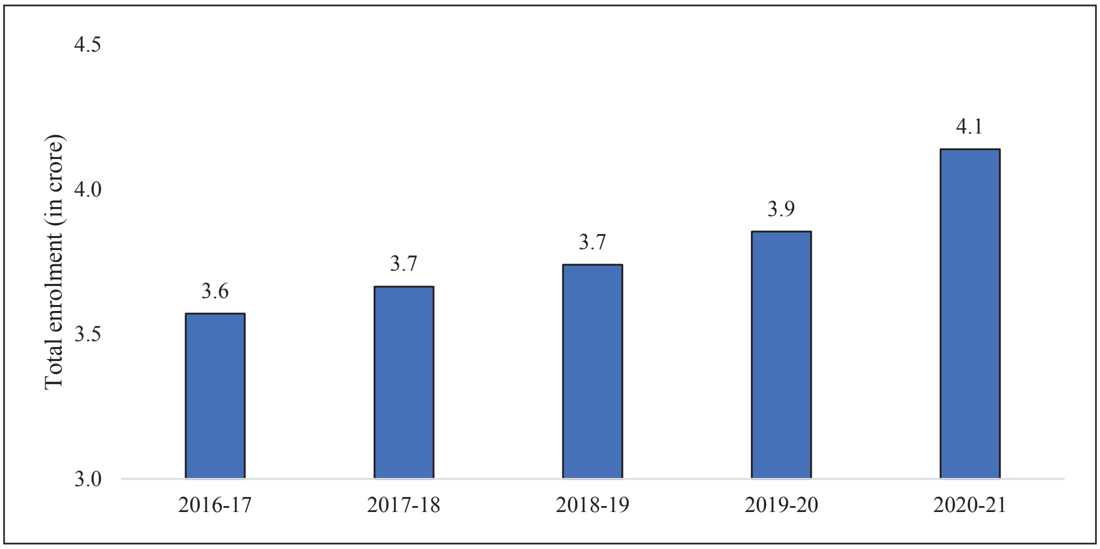

स्रोत: उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट 2020-21, शिक्षा मंत्रालय

तालिका VI.13: उच्च शिक्षा में छात्रों का नामांकन

(करोड़ में)

वर्ष	पुरूष	महिला	ज्वजंस
2016-17	1.9	1.7	3.6
2017-18	1.9	1.7	3.6
2018-19	1.9	1.8	3.7
2019-20	2.0	1.9	3.9
2020-21	2.1	2.0	4.1

Source: AISHE report 2020-21

6.70 इसके अलावा, दूरस्थ शिक्षा में नामांकन 45.7 लाख (20.9 लाख महिलाओं के साथ) है, वित्त वर्ष 20 से लगभग 7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2011 के जनसंख्या अनुमानों (संशोधित) के आधार पर उच्च शिक्षा में जीईआर वित्त वर्ष 21 में 27.3 प्रतिशत दर्ज किया गया था, जो वित्त वर्ष 20 में 25.6 से सुधार है। पुरुषों के लिए जीईआर वित्त वर्ष 20 में 24.8 से बढ़कर वित्त वर्ष 21 में 26.7 हो गया जबकि जीईआर महिलाओं के लिए भी इसी अवधि के दौरान 26.4 से 27.9 तक सुधार दिखाया गया है।

6.71 वित्त वर्ष 21 के अंत तक पंजीकृत विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय संस्थानों की कुल संख्या 1,113, कॉलेजों की संख्या 43,796 और स्टैंडअलोन संस्थानों की संख्या 11,296 है। संकाय/शिक्षकों की कुल संख्या 15,51,070 है, जिनमें से लगभग 57.1 प्रतिशत पुरुष हैं और 42.9 प्रतिशत महिलाएं हैं।

तालिका VI.14: उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की संख्या

(लाख में)

वर्ष	पुरूष	महिला	ज्वजंस
2016-17	8.1	5.5	13.6
2017-18	7.5	5.4	12.9
2018-19	8.2	6.0	14.2
2019-20	8.6	6.4	15.0
2020-21	8.9	6.6	15.5

Source: AISHE report 2020-21

उच्च शिक्षा के लिए पहल

6.72 **उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ (RDC):** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नई शिक्षा नीति - 2020 के प्रावधानों के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में अनुसंधान एवं विकास सेल (आरडीसी) की स्थापना के लिए पहल का प्रारंभ किया है, जिसमें गुणवत्ता अनुसंधान को बढ़ावा देकर ष्आत्मनिर्भर भारतष के लक्ष्य को प्राप्त करने में सार्थक योगदान दिया जा सके। इसके लिए मार्च 2022 में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें शोध उत्पादकता बढ़ाने; स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग, सरकार, समुदाय - आधारित संगठनों और एजेंसियों में सहयोग के प्रोत्साहन तथा संसाधनों व निधि करण के माध्यम से अनुसंधान तक की पहुंच को सुगम बनाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का प्रावधान किया गया था।

6.73 **एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को पढ़ने के लिए दिशानिर्देश:** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अप्रैल 2022 में छात्रों को एनईपी 2020 में परिकल्पित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को पढ़ने की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए, अर्थात अध्ययन के लिए विषयों के रचनात्मक संयोजन को सक्षम बनाने के लिए लचीली पाठ्यचर्या संरचना प्रदान करना, जो कई प्रवेश और निकास बिंदुओं की पेशकश करेगा, इससे वर्तमान में प्रचलित सख्त सीमाओं को हटाकर जीवन भर सीखने की नई संभावनाएं पैदा होगी और केंद्रीय रूप से महत्वपूर्ण और अंत:विषय सोच को शामिल करेगा।

दिशा-निर्देश में यह व्यवस्था है कि एक छात्र प्रत्यक्ष मोड में दो पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों की पढ़ाई कर सकता है या दो शैक्षणिक कार्यक्रमों का अनुसरण कर सकता है, एक पूर्णकालिक प्रत्यक्ष मोड में और दूसरा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) / ऑनलाइन मोड में; या एक साथ दो ओडीएल / ऑनलाइन कार्यक्रम में पढ़ाई कर सकता है। ये शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी द्वारा अधिसूचित विनियमों द्वारा शासित होंगे।।

6.74 **शिक्षा ऋण पर ब्याज अनुदान:** भारत में व्यावसायिक अध्ययन के लिए 2009 में शुरू की गई केंद्रीय ब्याज सब्सिडी योजना (CSIS) के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (EWS) के छात्रों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण पर अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि + एक वर्ष) के दौरान पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिनके माता-पिता की आय 4.5 लाख प्रतिवर्ष रूपए से कम है।

बॉक्सः VI-5: अखिल भारतीय शिक्षा समागम

शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से 7-9 जुलाई 2022 को वाराणसी में तीन दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया, जिसमें सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों के 300 से अधिक कुलपति और निदेशक शिक्षाविद्, नीति निर्माता, उद्योग के प्रतिनिधि भी एक साथ आए, इस विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए कि पिछले दो वर्षों में कई पहलों के सफल कार्यान्वयन के बाद देश भर में एनईपी 2020 के कार्यान्वयन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। शिखर सम्मेलन ने विचारोत्तेजक चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान किया जिसने रोडमैप और कार्यान्वयन रणनीतियों को स्पष्ट करने, ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने, अंत:विषय विचार-विमर्श के माध्यम से नेटवर्क बनाने और शैक्षणिक संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने और समाधानों को स्पष्ट करने में सहायता मिली।

समागम का मुख्य आकर्षण भारत की विस्तारित दृष्टि और उच्च शिक्षा प्रणाली के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक एक नई प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना था।

मिशन मोड में कार्यबल को नियोजनयोग्य कौशल एवं ज्ञान से सुसज्जित करना

6.75 कौशल विकास का उद्देश्य कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को दूर करना, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ढांचे का निर्माण, कौशल उन्नयन और नए कौशल का निर्माण करना है और न केवल मौजूदा नौकरियों बल्कि भावी नौकरियों के लिए भी नवीन सोच रखना है। बढ़ती जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने और युवाओं को पर्याप्त कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय 2014 में बनाया गया था और कौशल भारत मिशन 2015 में प्रारंभ किया गया था। एक केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना करके, कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने और सुव्यवस्थित करने के प्रयासों में तेजी आई क्योंकि सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के साथ-साथ कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति शुरू की है। एनईपी 2020 के तहत भी व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण और व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने को देश की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार के रूप में चिन्हित किया गया है।

6.76 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) वित्त वर्ष 21 से पता चलता है कि युवाओं (उम्र 15 - 29 वर्ष) और कामकाजी आबादी (आयु 15 - 59 वर्ष) के बीच औपचारिक व्यावसायिक / तकनीकी प्रशिक्षण का वित्त वर्ष 21 में, वित्त वर्ष 19 और वित्त वर्ष 20 की तुलना में सुधार हुआ है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पुरुषों और महिलाओं के कौशल में भी सुधार हुआ है।

तालिका VI.15: औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का वितरण

(प्रतिशत)

आयु वर्ग	ग्रामीण			शहरी			अखिल भारत		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
2018-19									
15-29 वर्ष	2.4	1.5	2.0	4.8	4.6	4.7	3.2	2.5	2.8
15-59 वर्ष	1.8	1.1	1.5	4.9	3.9	4.4	2.8	2.0	2.4

2019-20									
15-29 वर्ष	3.1	2.7	2.9	7.0	6.5	6.8	4.3	3.8	4.1
15-59 वर्ष	2.2	1.7	2.0	6.3	5.4	5.8	3.5	2.9	3.2
2020-21									
15-29 वर्ष	3.4	2.6	3.0	7.3	6.5	6.9	4.5	3.7	4.1
15-59 वर्ष	2.5	1.9	2.2	6.2	5.3	5.8	3.6	2.9	3.3

स्रोत: वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट, 2017-18 से 2020-21

6.77 प्रमुख नौ क्षेत्रों में कम से कम 10 श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में क्यूईएस के चौथे दौर की रिपोर्ट (जनवरी-मार्च 2022) के अनुसार, अनुमानित प्रतिष्ठानों में से 15.6 प्रतिशत ने औपचारिक कौशल प्रशिक्षण दिया और 20.5 प्रतिशत ने नौकरी का प्रशिक्षण दिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में औपचारिक कौशल प्रशिक्षण (24.7 प्रतिशत) और ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (31.6 प्रतिशत) देने वाले अनुमानित प्रतिष्ठानों का उच्चतम प्रतिशत था, इसके बाद वित्तीय सेवाओं का स्थान रहा (जिसमें प्रतिष्ठानों ने 20.4 प्रतिशत औपचारिक प्रशिक्षण और 26.4 प्रतिशत ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान किया)।

तालिका VI.16: औपचारिक कौशल विकास प्रशिक्षण और ऑन जॉब प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अनुमानित प्रतिष्ठानों का क्षेत्रवार प्रतिशत

	Q1FY22		Q2FY22		Q3FY22		Q4FY22	
	Formal	Job Training	Formal	Job Training	Formal	Job Training	Formal	Job Training
Manufacturing	17.4	28.3	13.2	25.2	14.1	22.2	12.8	19.4
Construction	15.5	26.0	7.8	22.7	11.2	25.0	8.4	23.9
Trade	11.2	17.4	11.6	23.7	10.5	20.5	9.8	16.7
Transport	13.0	20.6	10.7	17.9	13.6	21.5	16.5	20.0
Education	21.1	22.1	21	24.7	19.9	24.0	19.1	20.6
Health	20.2	24.0	26.6	36.6	24.8	34.9	24.7	31.6
Accommodation & Restaurants	7.1	13.4	11.3	15.6	10.9	19.4	8.5	14.9
IT/BPOs	29.8	**36.1**	24.1	34.1	25.1	31.1	18.2	23.4
Financial Services	22.6	34.8	20.9	21.2	27.2	26.1	20.4	26.4
Total	**17.9**	**24.3**	**16.8**	**24.3**	**17.1**	**23.6**	**15.6**	**20.5**

स्रोत: वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही से चौथी तिमाही तक की रिपोर्ट, श्रम ब्यूरो।

कौशल भारत मिशन

6.78 स्किल इंडियन मिशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए स्किलिंग, री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग पर फोकस करता है। कौशल भारत मिशन के तहत, सरकार, 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों सहित, देश भर में विभिन्न कौशल विकास योजनाओं को लागू कर रही है। इनमें दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) और दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) शामिल हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय

शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) जैसी योजनाओं को लागू कर रहा है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और राज्य सरकारों के अभियानों के माध्यम से कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। अधिक से अधिक क्षेत्रों को कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में फैले सामान्य ढांचे के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि सरकारी कौशल कार्यक्रमों के परिणाम कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में समान हों। इनमें से कुछ योजनाओं की प्रगति को बॉक्स VI-6 में प्रस्तुत किया गया है।

बॉक्स: VI-6: स्किल इंडिया मिशन की प्रगति

कौशल विकास योजना	प्रगति
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) पहली बार 2015 में शुरू की गई थी। वर्तमान में, पीएमकेवीवाई का तीसरा चरण, यानी पीएमकेवीवाई 3.0 (2020-22) पूरे देश में लागू किया जा रहा है। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के दो प्रशिक्षण घटक हैं, अर्थात्, लघु अवधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण की पहचान (आरपीएल)। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) देश के हर जिले में प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) के रूप में ज्ञात मॉडल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा देता है।	✓ वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 23 (31 अक्टूबर 2022 तक) के बीच, पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत लगभग 1.1 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित: 83 प्रतिशत प्रमाणित और लगभग 21.4 लाख नियुक्त किया गया है । वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 23 के दौरान (5 जनवरी 2023 तक) वित्त वर्ष 23 में, पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत, 7.0 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित: 66 प्रतिशत को प्रमाणित और 41,437 को नियुक्त किया गया है। ✓ पीएमकेवीवाई ने कोविड-19 से प्रभावित श्रमिक (प्रवासी मजदूरों) को प्रशिक्षण भी प्रदान किया। इस घटक में 6 राज्यों जैसे असम, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 116 जिले शामिल थे, । 31 अक्टूबर 2022 तक, 1.3 लाख(एसटीटी में 0.88 लाख और आरपीएल में 0.38 लाख) प्रवासी मजदूरों को प्रशिक्षित किया गया है ।
जन शिक्षण संस्थान योजना में गैर-साक्षर, नव-साक्षर, 15-45 वर्ष के आयु वर्ग में शिक्षा के प्रारंभिक स्तर वाले व्यक्तियों और बारहवीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वाले व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए जन शिक्षण संस्थानों (एनजीओ) को एकमुश्त वार्षिक अनुदान जारी किया जाता है। प्राथमिकता समूह में महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य पिछड़ा वर्ग सम्मिलित है।	✓ वित्त-वर्ष 20 से वित्त-वर्ष 23 तक (4.11.2022 तक), 16.0 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 28.4 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से हैं और 69 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और 2.7 प्रतिशत आदिवासी क्षेत्रों से हैं। विशेष रूप से, 81 प्रतिशत प्रशिक्षु महिलाएं हैं।
राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुता कार्यक्रम चलाने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।	✓ 2016 में योजना के शुभारंभ के बाद से, 31 दिसम्बर 2022 तक, उद्योगों द्वारा 21.4 लाख प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया है।
देश भर में 14,938 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टीआई) के माध्यम से 149 ट्रेडों में दीर्घकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना।	✓ 2015 से 30 अक्टूबर 2022 तक 91.7 लाख छात्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम में प्रशिक्षक प्रशिक्षुओं को कौशल और प्रशिक्षण पद्धति दोनों में व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे उन्हें शिक्षण की पद्धति और व्यावहारिक अनुभव (हैंड्स-ऑन स्किल्स) को सिखाने की तकनीकों से परिचित कराया जा सके, जिसके द्वारा वे उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति को तैयार कर सकें	✓ वित्त वर्ष 22 के दौरान, कुल 8847 प्रशिक्षुओं को विभिन्न राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया गया है।
भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाना	भारत को विश्व की एक कौशल राजधानी बनाने और कुशल जनशक्ति की गतिशीलता में सुधार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) इंटरनेशनल की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में संस्थानों का एक नेटवर्क बनाना है। संस्थानों के इस नेटवर्क को स्किल इंडिया इंटरनेशनल (SII) नेटवर्क कहा जाएगा। यह अत्याधुनिक सरकारी और निजी संस्थानों के पैनल के माध्यम से बनाया जाएगा। ✓ MSDE ने कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्र में 11 देशों, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, चीन, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कतर, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ✓ एनएसडीसी ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, मलेशिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरब, यूएई आदि जैसे देशों के साथ 18 बी2बी समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
स्किल एक्वीजीशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड ('संकल्प') 2018 में शुरू किया गया एक विश्व बैंक ऋण सहायता प्राप्त कार्यक्रम है जिससे कौशल पहलों का विकेंद्रीकरण किया जा सके और कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा स्थानीय मांग व युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।	✓ "संकल्प" के राष्ट्रीय घटक और राज्य घटक के तहत कौशल और उद्यमिता विकास और निगरानी के सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में क्रमश: 64 और 700 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ✓ 724 जिला कौशल समितियों (DSCs) का गठन किया गया है, जिन्हें जिला स्तर पर कौशल गतिविधियों की योजना, प्रबंधन और निगरानी के लिए अधिकृत किया गया है।

सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती स्वास्थ्य सेवा

6.79 नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इस उद्देश्य की दिशा में, नागरिकों के बेहतर समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुआयामी पहलें शुरू की गई हैं और आगे बढ़ाई गई हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, सरकार ने सभी प्रासंगिक क्षेत्रों और हितधारकों से जुड़ने के लिए ठोस प्रयास किए हैं जिससे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) प्राप्त करने और सभी नागरिकों को बिना आर्थिक कठिनाई के सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। आज, भारतीय स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क में से एक है।

स्वास्थ्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों में सुधार के रूप में एक प्रभावी स्वास्थ्य दृष्टिकोण के परिणाम दिखाई दे रहे हैं।

बेहतर समग्र स्वास्थ्य के लिए 2014 से 2022 तक प्रमुख पहल

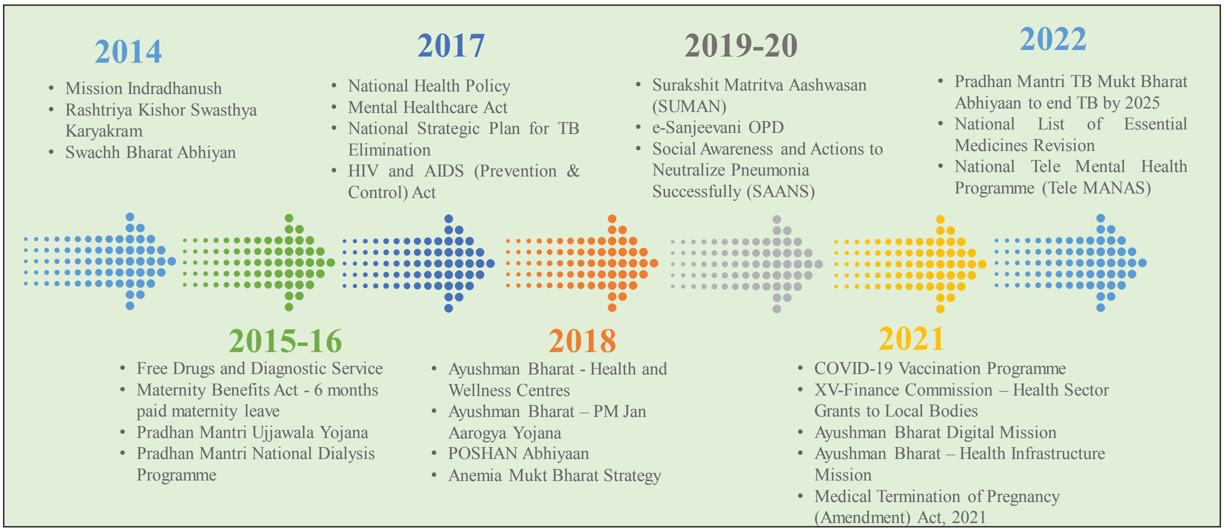

तालिका VI.17: स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों में सुधार

	NFHS-4 (2015-16)	NFHS-5 (2019-21)
स्वास्थ्य बीमा/वित्त पोषण योजना के तहत कवर किए गए किसी भी सामान्य सदस्य वाले परिवार (प्रतिशत)	28.7	↑ 41.0
कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)	2.2	↓ 2.0
परिवार नियोजन पद्धति का वर्तमान उपयोग- कोई भी विधि (प्रतिशत)	53.5	↑ 66.7
जिन माताओं ने प्रसव पूर्व कम से कम 4 बार स्वास्थ्य जाँच करवाई है (प्रतिशत)	51.2	↑ 58.1
चिकित्सा संस्थान में जन्म (प्रतिशत)	78.9	↓ 88.6
नवजात मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	29.5	↓ 24.9
शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	40.7	↓ 35.2
पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	49.7	↑ 41.9
12-23 महीने की उम्र के बच्चों को या तो टीकाकरण कार्ड या मातृ स्मरण (प्रतिशत) की जानकारी के आधार पर पूरी तरह से टीका लगाया गया है	62.0	↑ 76.4
6 महीने से कम उम्र के बच्चे केवल स्तनपान (प्रतिशत)	54.9	↓ 63.7
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनकी विकास वृद्धि दर कम है (उम्र के अनुसार कद) (प्रतिशत)	38.4	↓ 35.5
5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो कमजोर हैं (ऊंचाई के अनुपात में वजन) (प्रतिशत)	21.0	↓ 19.3
5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका वजन कम है (उम्र के अनुसार वजन) (प्रतिशत)	35.8	↑ 32.1
5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन सामान्य से अधिक है (ऊंचाई के अनुपात में वजन) (प्रतिशत)	2.1	↑ 3.4
अधिक वजन वाली या मोटापे से ग्रस्त महिलाएं (बीएमआई झ250 किग्रा/एम^2) (प्रतिशत)	20.6	↑ 24.0
पुरुष जो अधिक वजन वाले या मोटे हैं (बीएमआईझ25.0 किग्रा/एम^2) (प्रतिशत)	18.9	↑ 22.9
15-24 वर्ष की महिलाएं जो अपने मासिक धर्म के दौरान सुरक्षा के स्वच्छ तरीकों का उपयोग करती हैं (प्रतिशत)	57.6	↑ 77.3

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 और 2019-21, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

6.80 प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु, किशोर स्वास्थ्य सहित पोषण (आरएमएनसीएएच + एन) रणनीति के तहत किए गए ठोस प्रयासों के साथ, भारत ने माताओं और बच्चों दोनों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने में पर्याप्त प्रगति की है। नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 2020 तक मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को 100 प्रति लाख जीवित जन्मों से नीचे लाने के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है (राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017-19 में निर्धारित)। 2014-16 में इसे 130 प्रति लाख जीवित जन्म से 2018-20 में 97 प्रति लाख जीवित जन्म पर लाकर। 2030 के एमएमआर को 70 प्रति लाख जीवित जन्म से कम करने के एसडीजी लक्ष्य को आठ राज्यों ने पहले ही हासिल कर लिया है)। इनमें केरल (19), महाराष्ट्र (33), तेलंगाना (43) आंध्र प्रदेश (45), तमिलनाडु (54), झारखंड (56), गुजरात (57) और कर्नाटक (69) शामिल हैं।

6.81 स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने गुणवत्ता आश्वासन; आरएमएनसीएएच+एन; मानव संसाधन, सामुदायिक प्रक्रियाएं; सूचना और ज्ञान; दवाओं और निदान, और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, आदि के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा कवरेज बढ़ाने की दिशा में देशव्यापी प्रयासों के परिणामस्वरूप शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) और नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) में लगातार गिरावट की प्रवृत्ति के बाद और गिरावट आई है।

तालिका VI.18: मृत्यु दर संकेतकों में रुझान

	2014	2016	2018	2020
मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति लाख जीवित जन्म)	167 (2011-13)	130 (2014-16)	113 (2016-18)	97 (2018-20)
शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	39	34	32	28
नवजात मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	26	24	23	20
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	45	39	36	32
प्रारंभिक (0-7 दिन) नवजात मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	20	18	18	15

स्रोत: नमूना पंजीकरण प्रणाली

स्वास्थ्य व्यय अनुमान

6.82 वित्त वर्ष 19 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता (एनएचए)44 (जो नवीनतम उपलब्ध खाता है) यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सुनिश्चित करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालता है। वित्त वर्ष 19 के लिए एनएचए का अनुमान बताता है कि कुल जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय45 की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि वित्त वर्ष 14 में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 19 में 1.3 प्रतिशत हो गयी है। इसके अतिरिक्त, कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) में सरकारी स्वास्थ्य व्यय (जीएचई) की हिस्सेदारी भी समय के साथ बढ़ी है, यह वित्तीय वर्ष 2014 में 28. 6 प्रतिशत थी, जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019 में 40.6 प्रतिशत हो गई।

[38]भारत 2018-19 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता (एनएचए) एनएचए अनुमान एनएचएसआरसी द्वारा तैयार की गई छठी लगातार एनएचए अनुमान रिपोर्ट है, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2014 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय (एनएचएटीएस) के रूप में नामित किया गया है। यह रिपोर्ट 12 सितंबर 2022 को जारी की गई थी।

[39]जीएचई केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा वित्तपोषित और प्रबंधित सभी योजनाओं के तहत खर्च का गठन करता है, जिसमें अर्ध-सरकारी संगठन और दाता शामिल हैं, अगर धन सरकारी संगठनों के माध्यम से दिया जाता है।

[40]कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) में बाहरी निधियों सहित सरकारी और निजी स्रोतों द्वारा किए गए वर्तमान और पूंजीगत व्यय शामिल हैं।

6.83 कुल मिलाकर, वित्त वर्ष–19 में , भारत का कुल स्वास्थ्य व्यय 5,96,440 करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.2 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति 4,470 रुपये) होने का अनुमान है। वर्तमान स्वास्थ्य व्यय (सीएचई)49 5,40,246 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य व्यय का 90.6 प्रतिशत) है और पूंजीगत व्यय 56,194 करोड़ रुपये (कुल स्वास्थ्य व्यय का 9.4 प्रतिशत) है द्यकेंद्र सरकार का हिस्सा 34.3 प्रतिशत और राज्य सरकारों का हिस्सा 65.7 प्रतिशत है।

6.84 सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 की नीतिगत सिफारिशें शामिल हैं, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यय पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो वित्त वर्ष 2014 में 51.1 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 19 में 55.2 प्रतिशत हो गया है। यह न केवल आम लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करता है, बल्कि उन बीमारियों की संभावनाओं को भी कम करता है जिनके लिए द्वितीयक या तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होती है। वित्त वर्ष 14 और 19 के बीच सरकारी क्षेत्र में प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल की हिस्सेदारी 74.4 प्रतिशत से बढ़कर 85.7 प्रतिशत हो गई है। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र में, इसी अवधि के दौरान प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा की हिस्सेदारी 82 प्रतिशत से घटकर 70.2 प्रतिशत हो गई है।

6.85 स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय, जिसमें सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ और सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति शामिल है, वित्त वर्ष 14 में 6 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 19 में 9.6 प्रतिशत हो गई है। यह एक महत्वपूर्ण वृद्धि है जो यह दर्शाती है कि नागरिकों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है, और स्वास्थ्य सुविधाओं तक आम लोगों की पहुँच बढ़ी है। ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जिसके कारण कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत में आउट-ऑफ - पॉकेट व्यय (ओओपीई)50 वित्त वर्ष 14 में 64.2 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 19 में 48.2 प्रतिशत हो गया है।

चित्र VI.16: कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय और जेब से व्यय

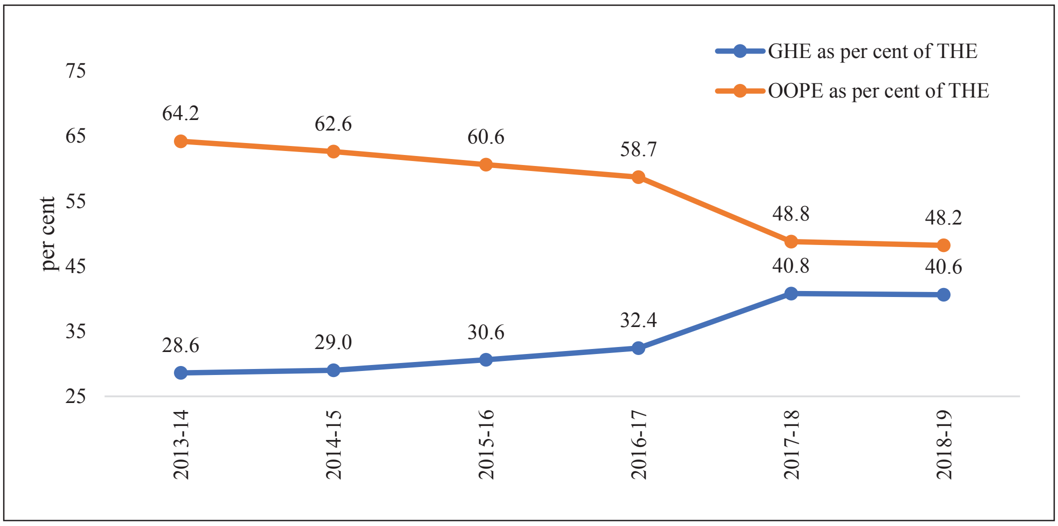

[41]वर्तमान स्वास्थ्य व्यय (सीएचई) में सभी पूंजीगत व्ययों में से स्वास्थ्य संबंधी प्रयोजनों के लिए केवल आवर्तक व्यय शामिल हैं

[42]जेब से किए जाने वाले व्यय स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने के स्थान पर परिवारों द्वारा सीधे किए जाने वाले व्यय होते हैं। ओओपीई आमतौर पर तब होता है जब किसी व्यक्ति के आगमन पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (क्लिनिक/अस्पताल/फार्मेसी/प्रयोगशाला आदि) सरकारी स्वास्थ्य सुविधा या गैर-लाभकारी संगठन द्वारा संचालित सुविधा के माध्यम से 'मुफ्त' स्वास्थ्य सुविधा प्रदान नहीं करता है या यदि वह व्यक्ति सरकारी/निजी स्वास्थ्य बीमा या सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत सुरक्षित नहीं होता है।

चित्र VI.17: कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सुरक्षा व्यय और निजी स्वास्थ्य व्यय

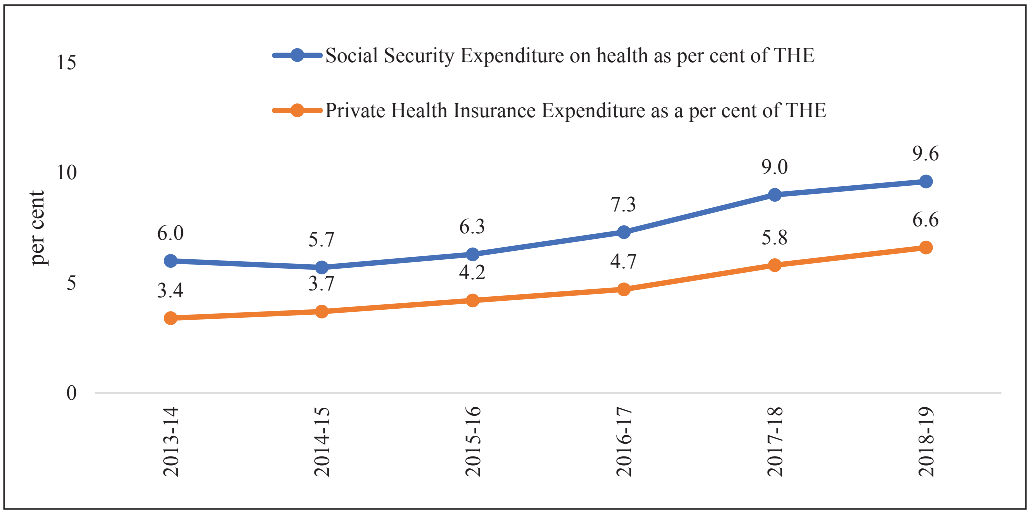

स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

चित्र VI.18: कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में जेब से व्यय - 2018-19 के लिए राज्य-वार

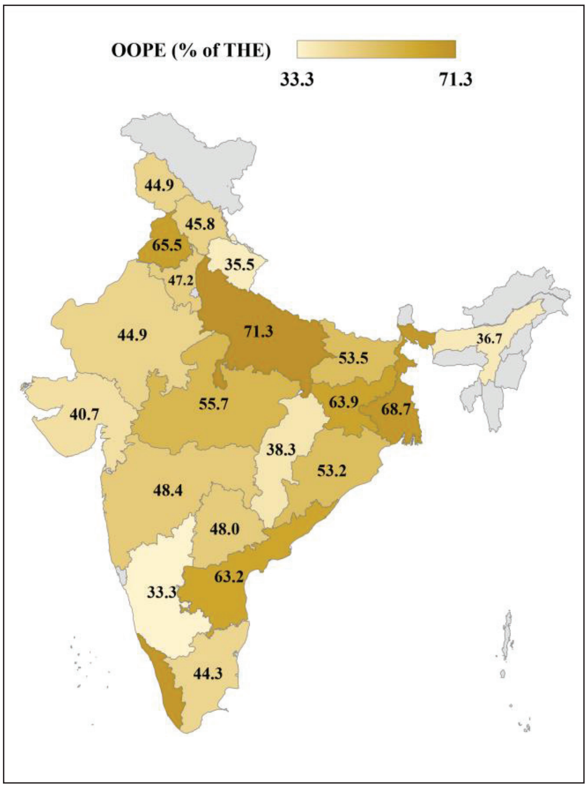

चित्र VI.19: कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय - 2018-19 के लिए राज्यवार

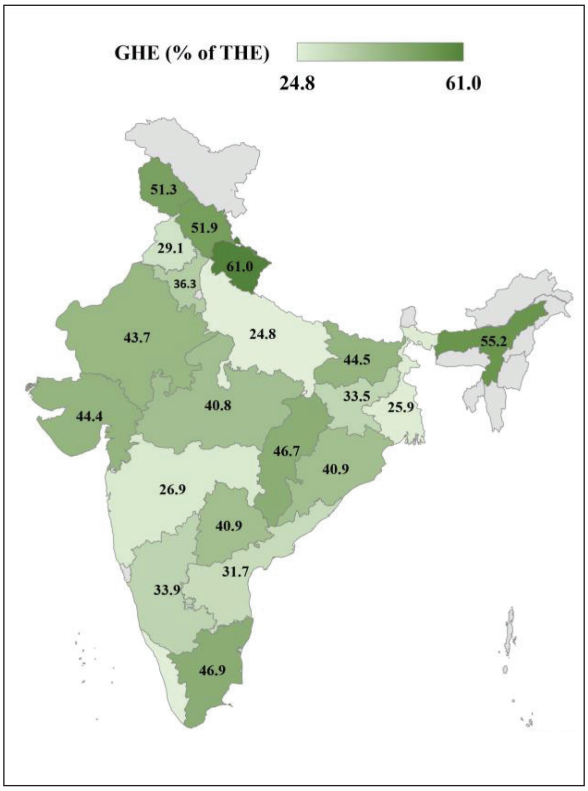

स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2018-19, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नोट: जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर का प्रतिनिधित्व करता है

ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल - बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन को मजबूत करना

6.86 हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश में स्वास्थ सेवा नियमों और कल्याण तंत्र को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। श्सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचनाश को 'सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का तंत्रिका केंद्र' कहा गया है, जिसके द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा से दूरस्व व्यक्ति को भी स्वास्थ लाभ पहुँचाया जा सकता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों (एचआरएच) की पहचान स्वास्थ्य प्रणाली के मुख्य निर्माण ब्लॉक के रूप में की जाती है। इनमें चिकित्सक, नर्स, ग्मीसिस्ट, प्रसाविका, दंत चिकित्सक, संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के साथ-साथ स्वास्थ्य प्रबंधन और सहायक कर्मी शामिल हैं।

6.87 भारत में हाल ही में स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए सुधारों ने सार्वजनिक क्षेत्र प्रणाली में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के साथ-साथ मानव संसाधन संसाधनों को मजबूत करने पर जोर दिया है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में उप-केंद्रों (SCs)] प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ डॉक्टरों, नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मियों की संख्या में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ, इन केंद्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए, चरणबद्ध तरीके से एससी और पीएचसी को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) में परिवर्तित करके मजबूत किया जा रहा है। 31 अक्टूबर 2022 तक, 1.35 लाख एचडब्ल्यूसी पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

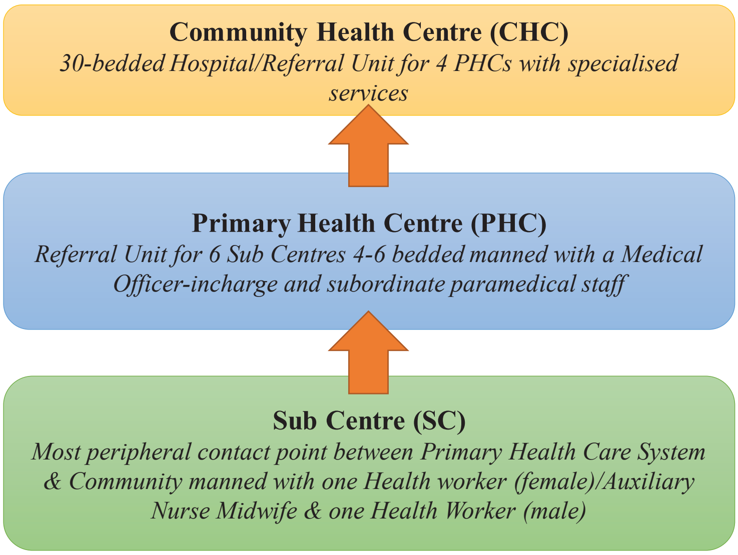

तालिका VI.19: स्वास्थ्य ढांचे में प्रगति (प्रत्येक वर्ष मार्च के अनुसार)

(संख्या हजारों में)

संकेतक	2014	2019	2020	2021	2022
उप-केंद्र (एससी)	152.3	157.4	155.4	156.1	157.9
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)	25.0	24.9	24.9	25.1	24.9
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)	5.4	5.3	5.2	5.5	5.5
पीएचसी में डॉक्टर	27.4	29.8	28.5	31.7	30.6
सीएचसी में कुल विशेषज्ञ	4.1	3.9	5.0	4.4	4.5
एससी और पीएचसी में सहायक नर्स मिडवाइफ	213.4	234.2	212.6	214.8	207.6
पीएचसी और सीएचसी में नर्सिंग स्टाफ	63.9	81.0	71.8	79.0	79.9
पीएचसी और सीएचसी में फार्मासिस्ट	22.7	26.2	25.8	28.5	27.1
पीएचसी और सीएचसी में लैब तकनीशियन	16.7	18.7	19.9	22.7	22.8

स्रोत: ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021-22, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नोट: हरा रंग सुधार का संकेत देता है

स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख सरकारी पहलों के अधीन प्रगति

टीकाकरण

6.88 सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के अधीन, टीकों से निरोध्य 12 बीमारियों: डिफ्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन के तपेदिक का एक गंभीर रूप, रोटावायरस डायरिया, हेपेटाइटिस बी, आदि के लिए मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। सार्वभौमिक टीकाकरण को सुदृढ़ करने के लिए, दिसंबर 2014 में बच्चों के पूर्ण टीकाकरण कवरेज को तेजी से 90 प्रतिशत तक बढ़ाने और उसके बाद इसे बनाए रखने के उद्देश्य से मिशन इन्द्रधनुष (एमआई) शुरू किया गया था। यह अभियान गैर-टीकाकृत और आंशिक रूप से टीकाकृत बच्चों पर केंद्रित है। इसके बाद अक्टूबर 2017 में चिन्हित 190 जिलों/शहरी क्षेत्रों में इंटेन्सिफाइड एमआई की शुरुआत की गई।

6.89 वित्त वर्ष 23 में, कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण से छूट हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को शामिल करने के लिए, 32 राज्यों राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में 416 जिलों (आजादी का अमृत महोत्सव के अधीन लिए गए 75 जिलों सहित) में तीव्र मिशन इन्द्रधनुष (एमआई) चलाया गया। दिसंबर 2022 तक, देश भर के 701 जिलों को शामिल करते हुए एमआई के कुल 11 चरणों को पूरा किया जा चुका है, जिसके तहत कुल 4.5 करोड़ बच्चों और 1.1 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। परिणामस्वरूप, एनएफएचएस-4 की तुलना में एनएफएचएस-5 पूर्ण टीकाकरण कवरेज (एफआईसी) में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि और 30 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के एफआईसी के प्रतिशत में वृद्धि हुई है।

ई-संजीवनी

6.90 ई-संजीवनी एक अभिनव, स्वदेशी, लागत प्रभावी और एकीकृत क्लाउड-आधारित टेलीमेडिसिन सिस्टम एप्लिकेशन है, जो रोगी से डॉक्टर तक टेली-परामर्श को सक्षम बनाता है ताकि देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके और सभी नागरिकों को उनके घरों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकें। वर्तमान में, ई-संजीवनी भारत भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है। 17 जनवरी 2923 तक, ग्रामीण क्षेत्रों में

1,12,553 एचडब्ल्यूसी और तृतीयक स्तर के अस्पताल में 15,465 हब, और राज्य राज्यों में मेडिकल कॉलेज ई-संजीवनी सक्षम किए गए हैं। इस अभिनव समाधान से देश भर में 9.3 करोड़ से अधिक रोगियों की सेवा हुई है और वर्तमान में यह प्रतिदिन लगभग 4 लाख रोगियों की सेवा कर रहा है। ई-संजीवनी- भारत की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा दुनिया की सबसे बड़ी बाह्य रोगी सेवा प्रणाली के रूप में विकसित हुई है।

बॉक्सः VI-7: आयुष्मान भारत के अधीन प्रगति

आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई)

एबी पीएम-जेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च के कारण लक्षित लाभार्थियों के ओओपीई को कम करने का इरादा रखती है। यह योजना 10.7 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ю5 लाख का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। जो कि सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (एसईसीसी 2011) और अन्य राज्य योजनाओं के अभाव और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर पहचान की गई भारतीय आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा है।

4 जनवरी 2023 तक, लगभग 21.9 करोड़ लाभार्थियों को योजना के अधीन सत्यापित किया गया है, जिसमें 3 करोड़ लाभार्थियों को राज्य आईटी सिस्टम का उपयोग करके सत्यापित किया गया है।

इस योजना के अधीन 26,055 से अधिक अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से लगभग 4.3 करोड़ अस्पताल में दाखिले के लिए 50,409 करोड़ रुपये की राशि अधिकृत की गई है।

आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी)

योजना के अधीन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एसएचसी और पीएचसी को अपग्रेड करके 1.5 लाख एबी-एचडब्ल्यूसी स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी, जो समुदाय के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करेगा।

ये एबी-एचडब्ल्यूसी मौजूदा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं और संचारी रोग सेवाओं का विस्तार और मजबूती करके और उच्च रक्तचाप, मधुमेह और 3 सामान्य कैंसर जैसे गैर-संचारी रोगों से संबंधित सेवाओं को शामिल करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। मौखिक, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा। 31 दिसंबर 2022 तक एबी-एचडब्ल्यूसी के माध्यम से सेवा वितरण की स्थिति निम्नानुसार हैः

- ✓ पहले एचडब्ल्यूसी का उद्घाटन 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में किया गया था।
- ✓ 1,54,070 एचडब्लूसी देशभर में परिचालित
- ✓ 135 करोड़ से अधिक संचयी फुटफॉल।
- ✓ गैर संचारी रोगों की 87.0 करोड़ से अधिक संचयी जांच
- ✓ योग सहित 1.6 करोड़ से अधिक वेलनेस सत्र।
- ✓ ई-संजीवनी टेलीकंसल्टेशन प्लेटफॉर्म के अधीन,

15,465 हब (क्षेत्रीय स्तर पर एमबीबीएस/स्पेशियलिटी/सुपर-स्पेशियलिटी डॉक्टरों सहित) पर कार्यात्मक एचडब्ल्यूसी के माध्यम से 9.3 करोड़ से अधिक टेली-परामर्श प्रदान किए गए हैं और 17 जनवरी 2023 तक देश भर में 1,12,987 प्रवक्ता (राज्य स्तर पर एबी- एचडब्ल्यूसीएस)।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)

मिशन का उद्देश्य खुले, इंटरऑपरेबल डिजिटल मानकों के आधार पर एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करना है। यह स्वास्थ्य आईडी जारी करने, स्वास्थ्य सेवा पेशेवर रजिस्ट्री, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री और स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसी सेवाओं के माध्यम से नागरिकों की सहमति से उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच और आदान-प्रदान

को सक्षम करेगा। यह स्वास्थ्य सेवा में डिजिटल तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा अधिक सुलभ और सस्ती होगी। 10 जनवरी 2023 तक प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- ✓ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (जिसे पहले स्वास्थ्य आईडी के रूप में जाना जाता था) बनाया गया: 31,11,96,965
- ✓ स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री सत्यापित सुविधाएं: 1,92,706
- ✓ स्वास्थ्य सेवा पेशेवर रजिस्ट्री सत्यापित स्वास्थ्य पेशेवर: 1,23,442
- ✓ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जुड़े: 7,52,01,236

बॉक्स: VI-8: राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस

बाल स्वास्थ्य क्षेत्र में लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करना

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी), 2015 में 11 राज्यों में शुरू किया गया और 2016 में पूरे देश में विस्तारित किया गया, यह एल्बेंडाजोल गोलियों के साथ 1-19 वर्ष की आयु के बच्चों में आंतों के कीड़े के संक्रमण के इलाज के लिए एक निश्चित दिन का दृष्टिकोण है। यह कार्यक्रम हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को स्कूलों और आंगनबाड़ियों के माध्यम से आयोजित किया जाता है, इसके बाद अनुपस्थिति या बीमारी के कारण छूटे हुए लोगों को कवर करने के लिए मॉप-अप दिन होते हैं। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और आंगनबाड़ियों के अलावा, स्कूल न जाने वाले बच्चों तक पहुँचने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं, और निजी स्कूल भी उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में शामिल हुए हुए हैं।

कोविड-19 के दौरान, जोखिमों को कम करते हुए कृमिनाशक प्रयासों की निरंतरता बनाए रखी गई थी। फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को घर के दौरे के दौरान या "ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस" आधारित मॉडल के माध्यम से उपयुक्त सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था।

कार्यक्रम की आवश्यकता

मृदा-संचारित हेल्मिंथियासिस (एसटीएच), जिसे परजीवी आंत्र कृमि संक्रमण के रूप में भी जाना जाता है, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है जो बच्चों के शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। आंतों के कीड़ों के संक्रमण को विशेष रूप से विटामिन ए और आयरन के पोषण संबंधी नुकसान को बढ़ाने, बढ़ाने और तीव्र करने के लिए जाना जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और कृमि संक्रमण मिलकर बच्चों की वृद्धि और विकास को अवरुद्ध कर देते हैं।

कृमि मुक्ति की प्रभाव प्रणाली

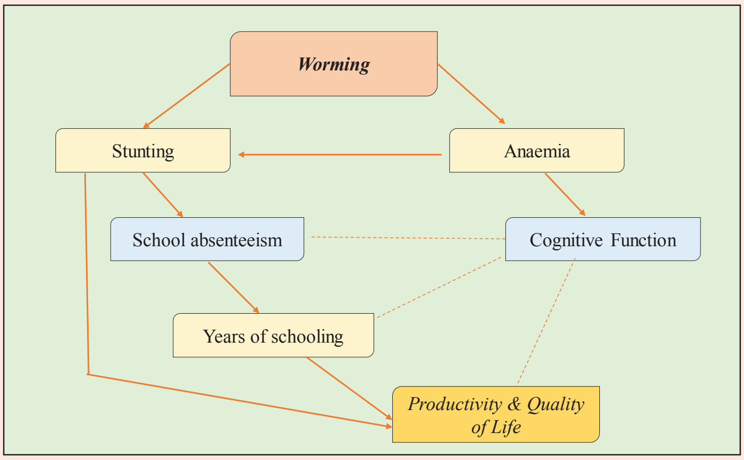

कृमि मुक्तिः एक कम लागत वाला उच्च लाभ वाला हस्तक्षेप

2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. माइकल क्रेमर सहित अन्य प्रमुख शोधों ने स्कूल में अनुपस्थिति, स्वास्थ्य, पोषण और सीखने के परिणामों पर कृमिनाशक दवा के महत्वपूर्ण प्रभाव को दिखाया है। लंबी अवधि के अध्ययनों में, कृमिनाशक उपचार के दस साल बाद, कृमिनाशक दवा से उच्च वेतन वाली नौकरियों की संभावना में काफी वृद्धि हुई है। इस प्रकार नियमित रूप से डीवॉर्मिंग बेहतर पोषण और स्वास्थ्य प्राप्त करने में योगदान देता है। कृमिनाशक पहल स्वच्छता से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को दूर करने में स्वच्छ भारत अभियान का पूरक भी है।

कृमिनाशक के संयुक्त लाभ, हस्तक्षेप की कम लागत की तुलना में, उल्लेखनीय रूप से उच्च लाभ-से-लागत अनुपात की ओर ले जाते हैं। केन्या में 20 साल के लंबे अध्ययन में वापसी की वार्षिक सामाजिक आंतरिक दर लगभग 37 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

इस प्रकार, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, गहरी जड़ों वाले विकास के लिए अच्छी तरह से लगाए गए स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचारों के कार्यक्रम का कम लटका हुआ फल है।

राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम

6.91 भारत का राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम, जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है, 16 जनवरी 2021 को शुरु हुआ, प्रारंभ में जिसका उद्देश्य देश की वयस्क आबादी को कम से कम समय में टीकाकरण करना था। 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को शामिल करने के लिए और 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए एहतियाती खुराक के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया गया था। टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना कोविड प्रबंधन के लिए परीक्षित रणनीति बनी हुई है।

6.92 कोविड-19 टीकों की शुरूआत में कई चुनौतियाँ शामिल थीं जैसे कि नए कोविड टीकों के लिए अनुसंधान और विकास, 2.6 लाख से अधिक वैक्सीनेटरों और 4.8 लाख अन्य टीकाकरण टीम के सदस्यों का प्रशिक्षण, उपलब्ध वैक्सीन का इष्टतम उपयोग, दुर्गम आबादी, और टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ाने के साथ-साथ सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स पर टीकों के भंडारण और विकेन्द्रीकृत वितरण, कोल्ड चेन क्षमता को बढ़ाने और लाभार्थियों को पंजीकृत करने और वैक्सीन सेवा वितरण के लिए आईटी प्लेटफॉर्म विकसित करने जैसी लॉजिस्टिक चुनौतियों पर भी ध्यान दिया गया। कार्यक्रम इन चुनौतियों पर काबू पाने और अल्प समय सीमा में अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम था।

6.93 6 जनवरी 2023 तक, भारत देश भर में 220 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक देने में सक्षम रहा है। पात्र लाभार्थियों में से 97 प्रतिशत को पहले ही कोविड-19 टीके की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है और लगभग 90 प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। 12-14 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण 16 मार्च 2022 को शुरू किया गया था, इसके बाद 10 अप्रैल 2022 से 18-59 वर्ष आयु वर्ग के लिए एहतियाती खुराक दी गई। अब तक 4.2 करोड़ से अधिक किशोरों को इसकी पहली खुराक दी जा चुकी है। कोविड-19 वैक्सीन और 22.4 करोड़ एहतियाती खुराक दी गई है।

चित्र VI.20: कोविड-19 वैक्सीन के साथ वयस्क आबादी का संचयी प्रतिशत

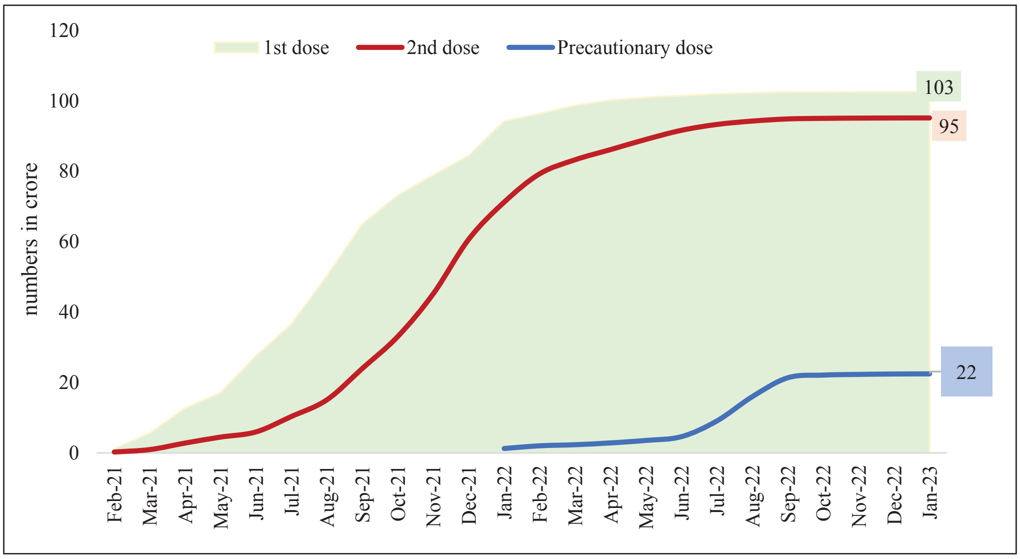

स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

बॉक्स: VI-9: स्वास्थ्य- समर्पित कोविड अवसंरचना पर एक वर्णनात्मक व्याख्या

भारत में प्रथम कोविड-19 का मामला दिनांक 30 जनवरी 2020 को पता चला था, उसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इसे अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। आधिकारिक तौर पर पहले कुछ मामलों का पता चलने से पहले ही भारत ने दिनांक 17 जनवरी 2020 की शुरुआत में सतर्कता से निगरानी लागू कर दी थी। कोविड-19 वायरस ने देश के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती पेश की, जिसे फीड-बैक लूप, वास्तविक परिणामों की वास्तविक समय की निगरानी, लचीली प्रतिक्रियाओं और सुरक्षा-नेट कर्स के आधार पर एक चुस्त दृष्टिकोण के साथ निपटा गया था, जैसा कि पिछले आर्थिक सर्वेक्षणों में इसकी चर्चा की गई थी।61 महामारी घोषित होने के दो साल से अधिक समय के बाद, सरकार ने अर्थव्यवस्था के ़नरुद्धार को संतुलित करने और बढ़ते केस के मामले से निपटने के लिए विभिन्न वित्तीय और सामाजिक उपाय किए हैं। इनमें भौतिक और डिजिटल दोनों तरह से स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण में वृद्धि और बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान को जारी रखना शामिल है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, केंद्र सरकार ने (क) जमीनी स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों में निवेश करके और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एचडब्ल्यूसी को बढ़ाकर; (ख) सभी जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित करना; और (ग) महामारी के प्रबंधन के लिए सभी जिलों और ब्लॉकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं द्वारा प्रयोगशाला नेटवर्क और निगरानी को सुदृढ़ करके स्वास्थ्य अवसंरचना पर व्यय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। राज्य सरकारों ने भी महामारी से लड़ने के लिए कई उपाय किए। इसे बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए को-विन और अंतिम मील तक पहुंचने के लिए टेलीमेडिसिन के लिए ई- संजीवनी के माध्यम से डिजिटल अवसंरचना द्वारा इसे पूरक बनाया गया था। सभी स्तरों पर और समय पर किए गए हस्तक्षेप ने भारत को लगातार झटकों के बावजूद कोविड महामारी से सफलतापूर्वक निपटने में मदद की।

पिछले कुछ महीनों में, कोविड मामलों की संख्या काफी कम हो गई है, जहां सक्रिय मामलों की संख्या 4000 से कम है और दैनिक नए मामले 300 से नीचे दर्ज किए गए हैं (दिनांक 29 दिसंबर 2022 तक)। भारत ने

[47]आर्थिक समीक्षा 2021-22 और 2020-21, अध्याय 1 और 10

शायद एक बड़ी लड़ाई जीत ली है। भारत उन देशों में से एक है जिसने अपने नागरिकों और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए एक तंत्र बनाने के लिए महामारी से सबसे अधिक सीखा है। स्वदेशी टीकों की दो खुराक के सफल शुरुआत के बाद तीसरी खुराक शुरू की गई।

समर्पित कोविड अवसंरचना:

कोविड रोगियों को संक्रमण के जोखिम को कम करने और गैर- कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रावधान करने के लिए देश में समर्पित कोविड-19 स्वास्थ्य सुविधाओं की त्रि-स्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं की इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल हैं (i) हल्के या पूर्व-लक्षण वाले मामलों के लिए आइसोलेशन बेड के साथ एक समर्पित कोविड देखभाल केंद्र; (ii) मध्यम स्तर के मामलों के लिए एक समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र ऑक्सीजन समर्थित आइसोलेशन बेड, और (iii) गंभीर मामलों के लिए आईसीयू बेड के साथ समर्पित कोविड अस्पताल। इसके अलावा, ईएसआईसी, रक्षा, रेलवे, केंद्रीय सशस्त्र ुलिस बल, इस्पात मंत्रालय, आदि के तहत तृतीयक देखभाल अस्पतालों को भी मामले के प्रबंधन के लिए इसका लाभ उठाया गया था। इसके अलावा, कई राज्यों में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने उपचार क्षमताओं को तेजी से बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर फील्ड अस्पतालों का उपयोग किया है।

कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

प्रेशर स्विंग एडजॉर्शन (पीएसए) ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स: पीएसए प्लांट अस्पतालों में स्थापित किए जा रहे हैं, खासकर दूर-दराज के इलाकों में, जिससे अस्पताल अपनी जरूरतों के लिए ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकें और जिससे देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति ग्रिड पर पड़ने वाले बोझ कम हो सके। इस बात पर जोर दिया गया कि देश के प्रत्येक जिले में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में पीएम-केयर्स सहायता से कम से कम 1 पीएसए संयंत्र होना चाहिए। तदनुसार, देश में 4,135 पीएसए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता को 4,852 मीट्रिक टन तक बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने दिनांक 6 जुलाई 2021 को राज्यों के साथ सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए सांकेतिक मानदंडों पर दिशानिर्देश विकसित किये गये और साझा किए हैं।

Source	No. of PSA Plants	Commissioned
PM-CARES	1225	1225
Central Government PSUs	283	283
Foreign Aid	53	50
State/CSR Initiatives	2574	2571
Total	**4135**	**4127**

- *ऑक्सीजन सिलेंडर:* सरकार ने राज्यों में मरीजों की देखभाल के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की है। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केंद्र सरकार के अस्पतालों को 4,02,517 ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति की जा चुकी है; जिसमें वर्ष 2020 में सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी (सीएमएसएस) द्वारा 1.0 लाख; वर्ष 2021 में सीएमएसएस द्वारा 1.3 लाख; वर्ष 2021 में डीआरडीओ द्वारा 1.5 लाख और विदेशी सहायता से 23,000 शामिल हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर का आवंटन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रो के साथ पारदर्शी और भागीदारीपूर्ण तरीके से किया गया है।
- इसके अलावा, एमओएचएफडब्ल्यू ने यूनिसेफ-एडीबी (एशियाई विकास बैंक) की सहायता से राज्यों के बीच अतिरिक्त 14,340 डी-टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर के वितरण को भी मंजूरी दे दी है, जो प्रक्रियाधीन है।

➢ *ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर:* कोविड प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा कुल 1,13,186 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे गए हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग के लिए ओएनजीसी के माध्यम से पीएम-केयर्स के तहत 99,186; और आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज (ईसीआरपी) सहायता के तहत 14,000 खरीदे गये हैं। ये सभी घरेलू स्तर पर खरीदे गए कंसंट्रेटर्स पहले ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे परेषिती बिंदु (कंसाइनी पॉइंट्स) के विवरण के साथ जिलों को तुरंत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जारी करें और ओसी-एमआईएस पोर्टल (ऑक्सीकेयर एमआईएस पोर्टल) पर जिला स्तर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की प्राप्ति से संबंधित डेटा तुरंत दर्ज करें।

डॉक्टर-रोगी अनुपात

वर्ष 2014 से औषधीय शिक्षा प्रणाली में आने वाले हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप डॉक्टरों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के अनुसार, 13,08,009 एलोपैथिक डॉक्टर जून 2022 तक राज्य चिकित्सा परिषदों और एनएमसी के साथ पंजीकृत हैं। पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों की 80 प्रतिशत उपलब्धता और 5.7 लाख आयुष डॉक्टरों को मानते हुए, डब्ल्यूएचओ मानदंडों 1:834 के खिलाफ देश में डॉक्टर-जनसंख्या का अनुपात 1:1000 है।

डॉक्टरों और कर्मचारियों की वृद्धि/नियुक्ति/भर्ती के लिए पहल

चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं को और बेहतर बनाने और चिकित्सा मानकों में सुधार करने के लिए, सरकार ने विभिन्न अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की परिकल्पना की गयी है, जिनमें निम्न शामिल हैं: –

क. जिला/रेफरल अस्पतालों को अपग्रेड कर नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एक सीएसएस, जिसके तहत 157 नए मेडिकल कॉलेज अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से 94 पहले से ही चालू हैं।

ख. एमबीबीएस और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिए एक सीएसएस।

ग. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) योजना के "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन" के तहत 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

घ. नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 22 एम्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 19 में स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं।

ङ. संकाय सदस्य, स्टाफ, बेड की संख्या और अन्य अवसंरचना की आवश्यकता के संदर्भ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए मानदंडों में छूट।

च. फैकल्टी की कमी को पूरा करने के लिए टीचिंग फैकल्टी के रूप में नियुक्ति के लिए डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड क्वालिफिकेशन को मान्यता दी गई है।

छ. चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षकों/डीन/प्राचार्य/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/विस्तार/फनर्रोजगार हेतु आयु सीमा में 70 वर्ष तक की वृद्धि।

संक्षेप में, 'सार्वजनिक स्वास्थ्य' राज्य का विषय होने के कारण, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में डॉक्टरों और कर्मचारियों की नियुक्ति/भर्ती/नियुक्ति सहित सभी प्रशासनिक और कार्मिक मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारों के अधीन हैं। कोविड महामारी जैसे किसी भी तात्कालिक झटके का मुकाबला करने के लिए उपायों का कोई सेट पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उपायों को 'सेटरिस परिबस' की धारणा के साथ डिजाइन किया गया है, जिसका अर्थ है कि अन्य सभी चीजें अपरिवर्तित या स्थिर हैं। किन्तु लेकिन प्रमुख अंतर यह है कि हम एक नए सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं, और इसलिए अंत की ओर, यह सब संकट के बेहतर प्रबंधन और आगे की योजना बनाने के बारे में है। इस प्रकार, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जो मजबूत सूची बनाई है, वह देश के समग्र स्वास्थ्य ढांचे और शासन प्रणाली में सुधार करेगी।

बॉक्सः VI-10: को-विनः बताने के लिए टीकाकरण की एक सफल डिजिटल कहानी

भारत में टीकों और टीकों का इतिहास हमें 1802 में वापस ले जाता है जब चेचक के लिए टीके की पहली खुराक दर्ज की गई थी।62 उस समय टीकों के चिकित्सा इतिहास का पता लगाना एक कठिन कार्य था। हालाँकि, समकालीन परिदृश्य में, हमने डिजिटल यात्रा में काफी प्रगति की है, और अधिकांश चिकित्सा विज्ञान खोजें मात्र एक 'क्लिक' दूर हैं। साथ ही, कोविड के आने से पहले ही भारत ने सामूहिक टीकाकरण की रणनीति बना ली थी क्योंकि कई अन्य बीमारियों के लिए साल भर के कार्यक्रम चल रहे थे। वर्षों से, सरकार ने "अंत्योदय" के मूल दर्शन को आत्मसात करके डिजिटल स्वास्थ्य सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित किया। हालाँकि, टीकाकरण प्रक्रिया में एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि महामारी के दौरान समूह प्रतिरक्षा हासिल करने का यही एकमात्र तरीका था। जबकि कई अर्थव्यवस्थाओं को शून्य से एक मॉडल विकसित करना था, भारत सहज स्थिति में था। सरकार के जेइएम ट्रिनिटी विजन के लिए धन्यवाद, राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करने में को-विन (कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क) के माध्यम से महत्वपूर्ण चुनौती को समयबद्ध तरीके से सामना किया गया।

को-विन को ईविन (इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क) प्लेटफॉर्म के विस्तार के रूप में विकसित किया गया है। भारत में कोविड-19 टीकाकरण की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक व्यापक क्लाउड-आधारित आईटी समाधान, को-विन सिस्टम संपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए उपयोगिताओं के साथ एक एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करता है। खुले मंच के दोहरे इंटरुेस ने इसे नागरिक और प्रशासक-केंद्रित सेवाओं में स्केलेबल बना दिया। टीकाकरण के लिए आपूर्ति श्रृंखला में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, मंच ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर (सरकारी और निजी) पर रीयल-टाइम स्टॉक ट्रैकिंग प्रदान की। इसने आगे चलकर कोविड-19 टीकों की बर्बादी को रोका, जो अन्यथा को-विन से पहले हुआ था।

उपयोगकर्ताओं (प्रशासकों, पर्यवेक्षकों और टीकाकरणकर्ताओं), टीकाकरण केंद्रों और 12 क्षेत्रीय भाषाओं में लाभार्थियों के पंजीकरण से परे जाकर, वेब समाधान ने डिजिटल रूप से सत्यापन योग्य प्रमाणपत्र जारी करने का विस्तार किया। टीकाकरण प्रमाणपत्र को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सहायता के लिए डब्ल्यूएचओ दिशानिर्देशों के अनुरूप डिजाइन किया गया था। एक दस्तावेज (आधार) पर पंजीकरण के बोझ को कम करने के लिए, सरकार ने 10 फोटो पहचान पत्रों [आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र, गेटो के साथ राशन कार्ड, छात्र गेटो आईडी कार्ड] में से किसी का भी उपयोग करके पंजीकरण की अनुमति दी गयी। डिजिटल डिवाइड और डिजिटल एक्सक्लूजन की समस्या से निपटने के लिए, नेशनल कोविड हेल्पलाइन के माध्यम से एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग करके कई लाभार्थियों (छह तक) को ऑनबोर्डिंग की अनुमति दी गई थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उम्र, अक्षमता या पहचान के कारण कोविड के समय में भौतिक सुविधाओं तक सीमित पहुंच वाले लोग छूटे नहीं हैं, इसके लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में ष्कार्यस्थल कोविड टीकाकरण केंद्रष के माध्यम से और "होम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स के पास" के माध्यम से भी विशेष प्रावधान उपलब्ध कराया गया।

को-विन के मजबूत डिजिटल अवसंरचना के कारण 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन खुराक का वर्तमान में दिया जाना संभव हो पाया है। यह डिजिटल अवसंरचना का व्यापक इंटरलॉक था और बेहतर समावेशन के लिए अपनी पहुंच में लगातार सुधार करने की सरकार की उत्साह थी कि भारत जीवन और आजीविका दोनों क्षेत्रों को सुरक्षित रखते हुए एक त्वरित और टिकाऊ आर्थिक सुधार दर्ज कर सका। कुल 104 करोड़ (जनवरी 2021 से सितंबर 2022 के बीच) में से 84.7 करोड़ से अधिक को-विन लाभार्थियों को आधार से जोड़ा गया, वित्त वर्ष 2015 में बोया गया जैम का सीड राष्ट्र के लिए जीवन रक्षक साबित हुआ।

[48]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4078488/

आपातकाल के लिए सामाजिक संरक्षण

6.94 विकास से कम आय वाले लोगों को जाल से बाहर निकाल सकते हैं, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वे अपने जीवनकाल में किसी भी संकट की स्थिति के प्रति संवेदनशील न रहेंगें। इस प्रकार, नागरिकों को बारिश के दिनों में होने वाले जोखिमों से बचाना महत्वपूर्ण है, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, प्राकृतिक आपदाएं, बुढ़ापा, आदि। विशेष रूप से महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों के मद्देनजर, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में अधिक संसाधनों का निवेश किया और वित्तीय वर्ष 23 में इस समझ के साथ ऐसा करना जारी रखा कि मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां विकास प्रक्रिया का समर्थन कर सकती हैं। इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख कार्यक्रम/योजनाएं नीचे सूचीबद्ध हैं।

6.95 **प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई):** पीएमवीवीवाई भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदान की जाती है और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 10 वर्ष की अवधि के लिए सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थित है। जिस कीमत पर वे पेंशन पॉलिसी खरीदते हैं। 31 दिसंबर 2022 तक 11,97,159 पॉलिसी के अधीन सामूहिक रूप से ₹87,081.1 करोड़ की जमा राशि से इस योजना से कुल 8,59,708 अभिदाता लाभान्वित हो रहे हैं।

6.96 **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई):** यह योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए है और किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर ₹436/. के वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का जोखिम बीमा देती है। 11 जनवरी 2023 तक, 14.96 करोड़ लोगों को संचयी रूप से नामांकित किया गया है और पीएमजेजेबीवाई के अधीन 6,39,032 दावों का भुगतान किया गया है।

6.97 **प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई):** यह योजना 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए है, जो आकस्मिक मृत्यु या कुल स्थायी विकलांगता होने पर ₹2 लाख जोखिम बीमा देती है और प्रति वर्ष ₹20 के प्रीमियम पर दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर ₹1 लाख का जोखिम बीमा देती है। 11 जनवरी 2023 तक, 32.1 करोड़ व्यक्तियों को संचयी रूप से नामांकित किया गया है और पीएमएसबीवाई के अधीन 1,10,298 दावों का भुगतान किया गया है।

6.98 **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएमडीवाई):** पीएम-एसवाईएमडीवाई मार्च 2019 में शुरू की गई, पीएम-एसवाईएमडीवाई 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ₹3,000 की मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के श्रमिक जिसकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है और ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं, इस योजना में शामिल हो सकते हैं। 2 नवंबर 2022 तक, 49.1 लाख से अधिक लाभार्थियों को योजना के अधीन नामांकित किया गया है।

6.99 **पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि):** यह 1 जून 2020 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो एक साल की अवधि के साथ ₹10,000 तक के कार्यशील पूंजी ऋण और लाभार्थियों को मुफ्त ऑनबोर्डिंग देकर स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पर। लाभार्थी पहली किश्त के समय पर पुनर्भुगतान के बाद 18 महीने के कार्यकाल में ₹20,000 तक के ऋण की दूसरी किश्त के लिए भी पात्र हैं। यह योजना केवल उन्हीं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के अधीन नियमों और योजनाओं को अधिसूचित किया है। 12 जनवरी 2023 तक, 45,74,866 ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी किश्तों में एक साथ स्वीकृत किया गया है; जिसमें से 39,43,094 ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

6.100 इसके अलावा, आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करने के लिए, **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)** को अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था, जिसमें गतिविधियों सहित आय-सृजन निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों के लिए ₹10 लाख तक का ऋण दिया गया था। कृषि से संबद्ध जैसे पोल्ट्री, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि। पीएमएमवाई के अधीन सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी दोनों आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) के माध्यम से ऋण प्रदान किए जाते हैं; बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई)। योजना की मुख्य विशेषताएं हैं:

- पीएमएम वाई के तत्वावधान में, मुद्रा ने 'शिशु' (50,000 रुपये तक के ऋण), 'किशोर' (50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण) और 'तरुण' (इससे ऊपर के ऋण) नामक तीन उत्पाद बनाए हैं। ₹5 लाख और ₹10 लाख तक) लाभार्थी सूक्ष्म इकाई/उद्यमी की वृद्धि/विकास और वित्त पोषण की जरूरतों के चरण को दर्शाता है और स्नातक/विकास के अगले चरण के लिए एक संदर्भ बिंदु भी प्रदान करता है;
- ऋण की मंजूरी के दौरान संपार्श्विक (संपार्श्विक) पर कोई जोर नहीं है;
- ब्याज की दर ऋण देने वाली संस्था द्वारा तय की जाती है, ब्याज केवल उधारकर्ता द्वारा रात भर रखे गए धन पर लगाया जाता है;
- माइक्रो यूनिट्स के लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) की स्थापना एमएलआई द्वारा पीएमएमवाई के अधीन योग्य माइक्रो यूनिट्स को दिए गए ऋण की गारंटी देने और प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों के अधीन स्वीकृत ओवरड्राफ्ट ऋण राशि के लिए की गई थी।
- वित्तीय वर्ष 21 से आगे, स्वयं सहायता समूहों को ₹10 लाख से ₹20 लाख के बीच स्वीकृत ऋण भी सीजीएफएमयू के अधीन कवरेज के लिए पात्र हैं। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी इस ंड की ट्रस्टी है।

वर्तमान स्थिति

योजना के शुभारंभ के बाद से 21.5 लाख करोड़ रुपये की राशि के 38.4 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 6.8 लाख करोड़ रुपये की राशि के 8.2 करोड़ से अधिक ऋण नए उद्यमियों/खातों को दिए गए हैं, जो योजना के अधीन दिए गए कुल ऋणों का लगभग 21 प्रतिशत है। लगभग 68 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं।

भारत की आकांक्षी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास

6.101 1960 के दशक में भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली आबादी का प्रतिशत लगभग 80 प्रतिशत था और 2007 तक 70 प्रतिशत से अधिक रहा। यह वर्तमान में 2021 के लिए 65 प्रतिशत है। इसके अलावा, 47 प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ऐसे में सरकार का ग्रामीण विकास पर ध्यान देना जरूरी है। अधिक न्यायसंगत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सरकार के जुड़ाव का उद्देश्य ''ग्रामीण भारत के सक्रिय सामाजिक-आर्थिक समावेश, एकीकरण और सशक्तिकरण के माध्यम से जीवन और आजीविका को बदलना'' रहा है।

[49]स्रोत: संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग की विश्व शहरीकरण संभावनाओं के आधार पर विश्व बैंक के कर्मचारियों का अनुमान: 2018 संशोधन।

[50]ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग का विजन दस्तावेज, नवंबर 2019

6.102 ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ग्रामीण आवास, पेयजल, स्वच्छता, स्वच्छ ईंधन, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण कनेक्टिविटी सहित कई उपाय किए गए हैं। माइक्रोफाइनेंस संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और अन्य वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों और छोटे व्यवसायों की वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ले जाना भी ग्रामीण विकास के एजेंडे का एक प्रमुख पहलू रहा है, चाहे वह कृषि गतिविधियों में हो या शासन में। महामारी के कारण आवश्यक जोर देने के साथ-साथ ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य मापदंडों पर भी प्राथमिक ध्यान दिया गया है। इन पहलुओं के सुधारों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

जीवन की गुणवत्ता के पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए बहुआयामी पहल

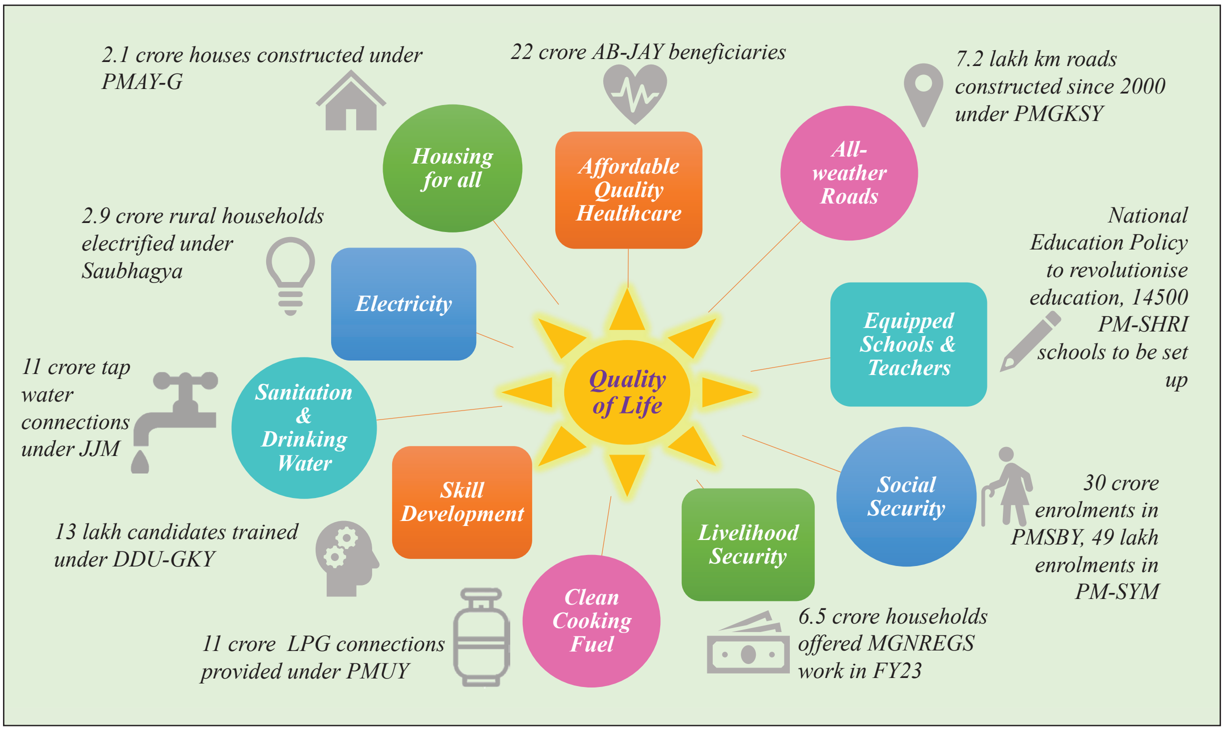

6.103 2019-21 के लिए एनएफएचएस डेटा ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता से संबंधित संकेतकों की एक सरणी में 2015-16 की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार दिखाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बिजली तक पहुंच, बेहतर पेयजल स्रोतों की उपस्थिति, के अधीन कवरेज शामिल है। स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ, आदि। घरेलू निर्णय लेने, बैंक खातों के मालिक होने और मोबाइल फोन के उपयोग में महिला भागीदारी में स्पष्ट प्रगति के साथ महिला सशक्तिकरण को भी गति मिली है। ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित अधिकांश संकेतकों में सुधार हुआ है। ये परिणाम-उन्मुख आँकड़े ग्रामीण जीवन स्तर में ठोस मध्यम-संचालित प्रगति स्थापित करते हैं, जो बुनियादी सुविधाओं और कुशल कार्यक्रम कार्यान्वयन पर नीतिगत फोकस से सहायता प्राप्त करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

तालिका VI.20: ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्ष

	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए	NFHS 4 (2015-16)	NFHS 5 (2019-21)
जनसंख्या	पिछले पांच वर्षों में पैदा हुए बच्चों के लिए जन्म के समय जनसंख्या लिंगानुपात (प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं)	927	↑ 931
	कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)	2.4	↓ 2.1
घरेलू सुविधाएं	बिजली वाले घरों में रहने वाली जनसंख्या (प्रतिशत)	83.2	↑ 95.7
	बेहतर पेयजल स्रोत वाले घरों में रहने वाली जनसंख्या	89.3	↑ 94.6
	खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले परिवार (प्रतिशत)	24.0	↑ 43.2
	बेहतर स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करने वाले घरों में रहने वाली जनसंख्या (प्रतिशत)	36.7	↑ 64.9
स्वास्थ्य	स्वास्थ्य बीमा/वित्त पोषण योजना के तहत शामिल किए गए किसी भी सामान्य सदस्य वाले स्वास्थ्य परिवार (प्रतिशत)	28.9	↑ 42.4
	शिशु मृत्यु दर	46.0	↓ 38.4
	जिन माताओं की पहली तिमाही में प्रसवपूर्व जांच हुई (प्रतिशत)	54.2	↑ 67.9
	जिन माताओं ने गर्भवती होने पर 100 दिनों या उससे अधिक समय तक आयरन फोलिक एसिड का सेवन किया (प्रतिशत)	25.9	↑ 40.2
	संस्थागत जन्म (प्रतिशत)	75.1	↑ 86.7
	केवल टीकाकरण कार्ड की जानकारी के आधार पर 12-23 महीने की आयु के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण (प्रतिशत)	61.3	↑ 84.0
	12-23 महीने की आयु के बच्चे जिन्होंने अपने अधिकांश टीकाकरण सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा (प्रतिशत) में प्राप्त किए	94.2	↑ 97.0
	सर्वेक्षण से पहले 2 सप्ताह में दस्त की बीमारी (प्रतिशत)	9.6	↓ 7.7
	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो नाटे हैं (उम्र के अनुसार ऊंचाई) (प्रतिशत)	41.2	↓ 37.3
	5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो कमजोर हैं (ऊंचाई के अनुसार वजन) (प्रतिशत)	21.5	↓ 19.5
	5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका वजन कम है (उम्र के अनुसार वजन) (प्रतिशत)	38.3	↓ 33.8

[51]आवासीय/अहाते/भूखंड में पाइप द्वारा पानी, पड़ोसी को पाइप, सार्वजनिक नल/स्टैंडपाइप, नलकूप या बोरहोल, संरक्षित कुएं, संरक्षित झरने, वर्षा जल, टैंकर ट्रक, छोटे टैंक के साथ गाड़ी, बोतलबंद पानी, सामुदायिक आरओ प्लांट।

[52]बिजली, एलपीजी/प्राकृतिक गैस, बायोगैस।

[53]पाइप वाले सीवर सिस्टम में फ्लश करें, सेप्टिक टैंक में फ्लश करें, पिट लैट्रिन में फ्लश करें, पता नहीं कहां फ्लश करें, हवादार बेहतर पिट (वीआईपी)/बायोगैस लैट्रिन, स्लैब के साथ पिट लैट्रिन, ट्विन पिट/कंपोस्टिंग टॉयलेट, जो नहीं है किसी अन्य परिवार के साथ साझा किया गया। यह संकेतक शौचालय की सुविधा तक की पहुंच को नहीं दर्शाता है।

	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए	NFHS 4 (2015-16)	NFHS 5 (2019-21)
	6-23 महीने की उम्र के बच्चों को पर्याप्त आहार मिल रहा है	8.8	11.0
	ऐसी महिलाएं जिनका बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) सामान्य से कम है (बीएमआई <18.5 किग्रा/एम'2)	26.7	21.2
	6-59 महीने की आयु के बच्चे जो एनीमिक हैं (प्रतिशत)	59.5	68.3
	15-49 वर्ष की सभी महिलाएं जो एनीमिक हैं (प्रतिशत)	54.3	58.5
	15-49 वर्ष की आयु के पुरुष जो एनीमिक हैं (प्रतिशत)	25.3	27.4
महिला सशक्तिकरण	वर्तमान में विवाहित महिलाएँ जो आमतौर पर तीन घरेलू निर्णयों में भाग लेती हैं (प्रतिशत)	83.0	87.7
	जिन महिलाओं ने पिछले 12 महीनों में काम किया और उन्हें नकद भुगतान किया गया (प्रतिशत)	25.4	25.6
	घर और/या जमीन की मालिक महिलाएं (अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से) (प्रतिशत)	40.1	45.7
	बैंक या बचत खाता रखने वाली महिलाएं जिनका वे स्वयं उपयोग करती हैं (प्रतिशत)	48.5	77.4
	ऐसी महिलाएं जिनके पास मोबाइल फोन है जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं (प्रतिशत)	36.9	46.6
	जिन महिलाओं ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया है (प्रतिशत)	लागू नहीं	24.6
	20-24 साल की महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले (प्रतिशत)	31.5	27.0

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन एफएचएस) 2015-16 और 2019-21, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

ग्रामीणवासी के आय में वृद्धि

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम):

6.104 एनआरएलएम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाना है, जिसके परिणामस्वरूप उनके लिए स्थायी और विविध आजीविका विकल्प उपलब्ध हो। यह गरीबों की आजीविका में सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। मिशन चार मुख्य घटकों (क) ग्रामीण गरीब महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता और स्व-प्रबंधित और वित्तीय रूप से स्थायी सामुदायिक संस्थानों को बढ़ावा देना और मजबूत करना; (ख) वित्तीय समावेशन; (ग) स्थायी आजीविका; और (घ) सामाजिक समावेशन, सामाजिक विकास और अभिसरण के माध्यम से पात्रता तक पहुंच में निवेश करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है।।

6.105 मिशन की आधारशिला इसका श्समुदाय संचालितश दृष्टिकोण है जिसने महिला सशक्तिकरण के लिए सामुदायिक संस्थानों के रूप में एक बड़ा मंच प्रदान किया है। इस कार्यक्रम के मूल में ग्रामीण महिलाएं हैं, जो उनकी क्षमताओं के निर्माण, वित्तीय सहायता प्रदान करने और प्रशिक्षण के माध्यम से उनके सामाजिक-आर्थिक

[54]स्वयं की स्वास्थ्य देखभाल के बारे में निर्णय, घर की प्रमुख खरीदारी करना, और अपने परिवार या रिश्तेदारों से मिलने जाना।

सशक्तिकरण पर व्यापक रूप से केंद्रित है ताकि वे आजीविका गतिविधियों को शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने में सक्षम हो सकें। वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने में सक्षम हो सकें। लगभग 4 लाख एसएचजी सदस्यों को जमीनी स्तर पर मिशन के कार्यान्वयन में सहायता के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) (अर्थात् पशु सखी, कृषि सखी, बैंक सखी, बीमा सखी, पोषण सखी आदि) के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।

112. मिशन की कार्यान्वयन रणनीति के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) के 723 जिलों के 6861 ब्लॉकों में यह कार्य चल रहा है। इसने 81 लाख एसएचजी में गरीब और कमजोर समुदायों की कुल 8.7 करोड़ महिलाओं को संगठित किया है।

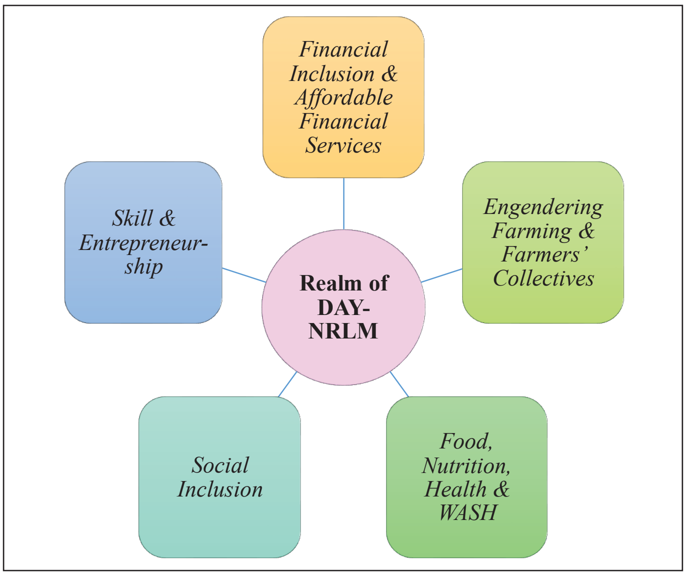

तालिका VI.21: डीएवाई-एनआरएलएम के तहत प्रगति

सूचक	संचयी प्रगति (22 अक्टूबर तक)
कवर किए गए ब्लॉकों की संख्या	6880
पदोन्नत एसएचजी की संख्या (लाख में)	81.1
जुटाए गए परिवारों की संख्या (लाख में)	875
एसएचजी को प्रदान की गई पूंजीकरण सहायता (₹ करोड़ में)	20250.0
एसएचजी द्वारा प्राप्त बैंक ऋण की राशि (₹ लाख करोड़ में)	5.9
एसवीईपी के तहत स्थापित व्यक्तिगत उद्यमों की संख्या	2.2
एजीवाईवाई के तहत तैनात वाहनों की संख्या	2208
शामिल किए गए महिला किसानों की संख्या (लाख में)	196.0
स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटरों की संख्या	26026
किचन गार्डन वाले परिवारों की संख्या (लाख में)	110.3

[55]स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम
[56]आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

6.107 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (मनरेगा) का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करते हैं, की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। यदि काम की मांग के पंजीकरण की तारीख से 15 दिनों के भीतर या अग्रिम आवेदनों के मामले में, जिस तारीख से काम की मांग की गई है, जो भी बाद में हो, रोजगार नहीं दिया जाता है, तो कर्मचारी दैनिक बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार है।

6.108 कुल 5.6 करोड़ परिवारों ने रोजगार प्राप्त किया और योजना के तहत (6 जनवरी 2023 तक) कुल 225.8 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजित किया गया है। मनरेगा की भौतिक प्रगति व्यक्ति-दिनों की पीढ़ी, प्रति परिवार औसत व्यक्ति-दिनों और महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में नीचे दी गई है। बॉक्स VI-11 मनरेगा के तहत उपलब्धियों और शासन के उपायों को सूचीबद्ध करता है

तालिका VI.22: मनरेगा के तहत प्रगति

सूचक	2018-2019	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
किए गए प्रति व्यक्ति कार्य दिवस (करोड़ में)	267.9	265.4	389.1	363.3	225.8
प्रति परिवार औसत प्रति व्यक्ति कार्य दिवस	50.9	48.4	51.5	50.1	47.7
महिला भागीदारी दर (प्रतिशत)	54.6	54.8	53.2	54.7	56.3

*6 जनवरी 2023 तक

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

बॉक्स: VI-11: मनरेगा के तहत उपलब्धियां

आस्तियों की जियो-टैगिंग: योजना के तहत 1 नवंबर 2017 से पहले शुरू हुए सभी पूर्ण कार्यों की जियो-टैगिंग के लिए 1 सितंबर 2016 को जिओ मनरेगा चरण-1 शुरू किया गया था। जियो-मनरेगा चरण-प्प 1 नवंबर 2017 को शुरू किया गया था और इस चरण के तहत संपत्तियों की जियो-टैगिंग तीन चरणों में की जाती है: काम शुरू करने से पहले, काम के दौरान और काम पूरा होने के बाद। 5.2 करोड़ से अधिक संपत्तियों को जियो-टैग किया गया है (6 जनवरी 2023 तक) और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है।

कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर अनिवार्य व्यय: अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, जिला कार्यक्रम समन्वयक को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि लागत के संदर्भ में एक जिले में किए जाने वाले कार्यों का कम से कम 60 प्रतिशत सीधे कृषि और संबद्ध से जुड़ी उत्पादक संपत्तियों के निर्माण के लिए होगा। भूमि, जल और वृक्षों के विकास के माध्यम से गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। वित्त वर्ष 23 (6 जनवरी 2023 तक) में कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर 68.5 प्रतिशत खर्च हुआ है।

ई-भुगतान: मनरेगा के तहत ई-भुगतान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस)/इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली (ई-एफएमएस) का उपयोग करके श्रमिकों के वेतन का भुगतान सीधे उनके बैंक/डाकघर खातों में किया जाता है। अब तक एनईएफएमएस/ई-एफएमएस के माध्यम से किया गया कुल व्यय 99.7 प्रतिशत है.

डीबीटी: योजना के तहत, 99 प्रतिशत वेतन चाहने वालों को उनकी मजदूरी सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त हो रही है। पारदर्शिता की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

आधार-आधारित भुगतानः 14.0 करोड़ आधार को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में जोड़ा गया है जो कुल सक्रिय श्रमिकों (15.3 करोड़) का 92.0 प्रतिशत है। कुल 7.9 करोड़ श्रमिकों को आधार आधारित भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया है।

योजना के तहत सुशासन की कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:

(क) जॉब कार्ड (जेसी) को समय-समय पर सत्यापित और अद्यतन करने की आवश्यकता होती है ताकि फर्जी जेसी, डुप्लीकेट, और प्रवासन और मृत्यु जैसे कारणों को समाप्त किया जा सके। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने जेसी को सत्यापित/अद्यतन करने के लिए यह अभ्यास शुरू कर दिया है।

(ख) सुशासन एक पहल के रूप में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाए जा रहे रजिस्टरों (एक ग्राम पंचायत में औसतन 22 रजिस्टर) की संख्या को घटाकर सात कर दिया गया है।

(ग) दिशानिर्देशों और अनुसूचियों के उल्लंघन के मामलों का नियमित रूप से पालन किया जा रहा है। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार के लिए दौरों के लिए अंतरराज्यीय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित की गई थी। यह एसओपी लेखापरीक्षा मानक नियम, 2011 के अनुसार सभी सामाजिक लेखापरीक्षा अनुपालन सुनिश्चित करेगा इसमें एक स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई की स्थापना, स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षा निदेशक, और ग्राम संसाधन व्यक्ति (वीआरपी) के रूप में प्रशिक्षित होने के लिए पूर्ण मानव संसाधन, एमआईएस में समय पर कैलेंडर अपलोड करना, समय पर नियमित लेखापरीक्षा करना और निर्धारित समय में एमआईएस पर मुद्दों को अपलोड करना शामिल है।

(घ) कौशल की सीढ़ी पर मनरेगा श्रमिकों को ऊपर ले जाने के लिए बेयर फुट तकनीशियन (बीएफटी) जैसी हालिया पहलों के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। अभी तक 20 राज्यों में 8.394 बीएफटी को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(ड.) परियोजना "उन्नति" का उद्देश्य मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को उन्नत करना है, और इस तरह उनकी आजीविका में सुधार करना है ताकि वे अपने वर्तमान आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ सकें। यह परियोजना वित्त वर्ष 2020 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य तीन वर्षों यानी वित्त वर्ष 20, वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 22 में 2 लाख मनरेगा लाभार्थियों के कौशल आधार को बढ़ाना है। अभी तक लगभग 24,373 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्नति स्किलिंग प्रोजेक्ट एक परिवार के एक वयस्क सदस्य (18-45 वर्ष की आयु) को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है, जिसने वित्त वर्ष 19 से वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 100 दिन का काम पूरा कर लिया है। वेतन हानि मुआवजे के एवज में स्टाइपेंड का पूरा खर्च पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 2 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाना है।

(च) एसईसीसी 2011 के अनुसार लगभग 5.5 करोड़ परिवार भूमिहीन परिवारों की श्रेणी में आते हैं जो आजीविका के लिए दस्ती अनियत क्षम पर निर्भर हैं। सरकार इन परिवारों जिनके पास जेसी नहीं है को मनरेगा के तहत रोजगार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे लगभग 5.5 करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है।

(छ) अधिकारियों को अपने निष्कर्षों को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान करने के लिए मई 2021 में क्षेत्रीय अधिकारी निगरानी ऐप लॉन्च किया गया था। यह ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं के लिए समय-मुद्रित और गो-समन्वय टैग की गई तस्वीरों को रिकॉर्ड करने में भी मदद करेगा। इससे निष्कर्षों के विश्लेषण में सुविधा मिलती है जो बदले में कार्यक्रम के बेहतर तरीके से कार्यान्वयन में मदद करता है।

(ज) राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर (एनएमएमएस) ऐप मई 2021 में लॉन्च किया गया था। जो एक जियो-टैग की गई तस्वीर के साथ मनरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय उपस्थिति लेने की अनुमति देता है। यह ऐप पारदर्शिता लाने और योजनाओं की उचित निगरानी की दिशा में एक बड़ा कदम है और कार्यक्रम के नागरिक निरीक्षण को बढ़ाने में मदद करेगा।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

6.109 डीडीयू–जीकेवाई एनआरएलएम के अधीन ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं को मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए बाजार आधारित, प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है। 30 नवंबर 2022 तक इस योजना के अधीन कुल 13,06,851 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें से 7,89,685 को नौकरी मिल चुकी है।

ग्रामीण आवास

6.110 भोजन और वस्त्र के साथ आवास मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। ''2022 तक सभी के लिए आवास'' प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ आश्रय प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस लक्ष्य के साथ, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) को नवंबर 2016 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जीर्ण–शीर्ण घरों में रहने वाले सभी पात्र बेघर परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ लगभग 3 करोड़ पक्के घर उपलब्ध कराना था। अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से, पीएमएवाई–जी शौचालय के निर्माण, पीने के पानी, बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन, और मनरेगा से 90/95 अकुशल श्रम दिवस जैसी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करता है।

6.111 यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता उन लोगों के लिए ही है जो वास्तव में वंचित हैं और चयन वस्तुनिष्ठ और सत्यापन योग्य है, पीएमएवाई–जी एसईसीसी, 2011 की तारीख में आवास अभाव मापदंडों का उपयोग करके लाभार्थियों का चयन करता है जिसे ग्राम सभा द्वारा सत्यापित किया जाना है। योजनान्तर्गत भूमिहीन हितग्राहियों को आवास आवंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। योजना के अधीन कुल 2.7 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है और 6 जनवरी 2023 तक 2.1 करोड़ घरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। वित्त वर्ष 23 में 52.8 लाख घरों को पूरा करने के कुल लक्ष्य के मुकाबले 32.4 लाख घरों को पूरा किया जा चुका है।

पेयजल और स्वच्छता

6.112 यूएन–एसडी जी 6 का उद्देश्य ''सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना है।'' भारत ने शहरी और ग्रामीण परिवारों को पेयजल और सुरक्षित स्वच्छता प्रदान करने में काफी प्रगति की है। पानी और स्वच्छता के एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में ऑपरेशन के अधीन प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के कुछ विवरण नीचे सूचीबद्ध हैं।

जल जीवन मिशन

6.113 सरकार ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 'जीवन सुगमता' को बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। 73वें स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त 2019 को, जल जीवन मिशन (जेजेएम) की घोषणा की गई थी, जिसे राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जाएगा, ताकि स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रम शालाओं (आदिवासी आवासीय विद्यालयों), स्वास्थ्य केंद्रों, जैसे गांवों में हर ग्रामीण घर और सार्वजनिक संस्थानों को नल का जल कनेक्शन प्रदान किया जा सके। ग्राम पंचायत भवन, आदि, 2024 तक 3.60 लाख करोड़ रुपए के कुल परिव्यय होगा, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 2.08 लाख करोड़ रुपए है और शेष 1.52 लाख करोड़ राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा साझा किया जाना है।

6.114 अगस्त 2019 में जेजेएम के रोलआउट के समय, कुल 18.9 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 3.2 करोड़ (17 प्रतिशत) घरों में नल के पानी की आपूर्ति थी। मिशन की शुरुआत के बाद से, 18 जनवरी 2023 तक, 19.4 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 11.0 करोड़ परिवारों को उनके घरों में नल से जलापूर्ति मिल रही है। इसके अलावा, चार राज्य, अर्थात, गोवा, गुजरात, तेलंगाना और हरियाणा, और तीन केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव और पुडुचेरी 'हर घर जल' राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, अर्थात 100 प्रतिशत घरों में नल से जलापूर्ति हो रही है। इसी तरह, 121 जिले, 1,515 ब्लॉक, 82,071 ग्राम पंचायत और 1.5 लाख से अधिक गांव भी क्रमश: 'हर घर जल ब्लॉक', 'हर घर जल पंचायत' और 'हर घर जल गांव' बन गए हैं। इसके अलावा, 8.8 लाख से अधिक स्कूलों और 9.1 लाख आंगनवाड़ी

केंद्रों को पाइप से पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जा रही है। बॉक्स VI-12 मिशन के बारे में अधिक विवरण प्रदान करता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए यह कैसे काम कर रहा है।

बॉक्सः VI-12: जन स्वास्थ्य के साधन के रूप में जल जीवन मिशन

क्रेमर एट अल द्वारा एक हालिया अध्ययन (2022) से यह अनुमान लगाया गया है कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) के माध्यम से सूक्ष्मजीवविज्ञानी संदूषण मुक्त पानी की आपूर्ति से हर साल 5 वर्ष से कम उम्र के 1.36 लाख बच्चों की मौत को रोका जा सकता है। इस प्रकार, जल उपचार से बड़े पैमाने पर शुद्ध लाभ होने की संभावना है और यह स्वच्छ भारत अभियान जैसे कदमों का पूरक है, जिससे स्वच्छता में सुधार के माध्यम से बाल मृत्यु दर को रोका जा सके।

स्वास्थ सेवाओं के महा निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, के अनुसार, प्रत्येक ग्रामीण घर के दरवाजे पर सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल की उपलब्धता के साथ, जल जनित रोग 2019 में 1.8 करोड़ से घटकर 2021 में 59.0 लाख हो गए हैं।

पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

- जेजेएम भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित पर्याप्त मात्रा और अच्छी गुणवत्ता के पीने योग्य पानी के प्रावधान पर जोर देता है। मिशन के अधीन जल गुणवत्ता निगरानी और निगरानी गतिविधियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।
- जल आपूर्ति, स्वच्छता और स्वच्छता (डब्ल्यूएएसएच) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, इस प्रकार सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए, एक राष्ट्रव्यापी जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) को क्षेत्र परीक्षण किटों के साथ-साथ प्रयोगशालाओं में जल गुणवत्ता परीक्षण का उपयोग करके शुरू किया गया है। डेटा अपलोड, विश्लेषण और गुणवत्ता के मुद्दों के मामले में, स्थानीय अधिकारियों को तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए सतर्क किया जाता है।

कार्यात्मक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत

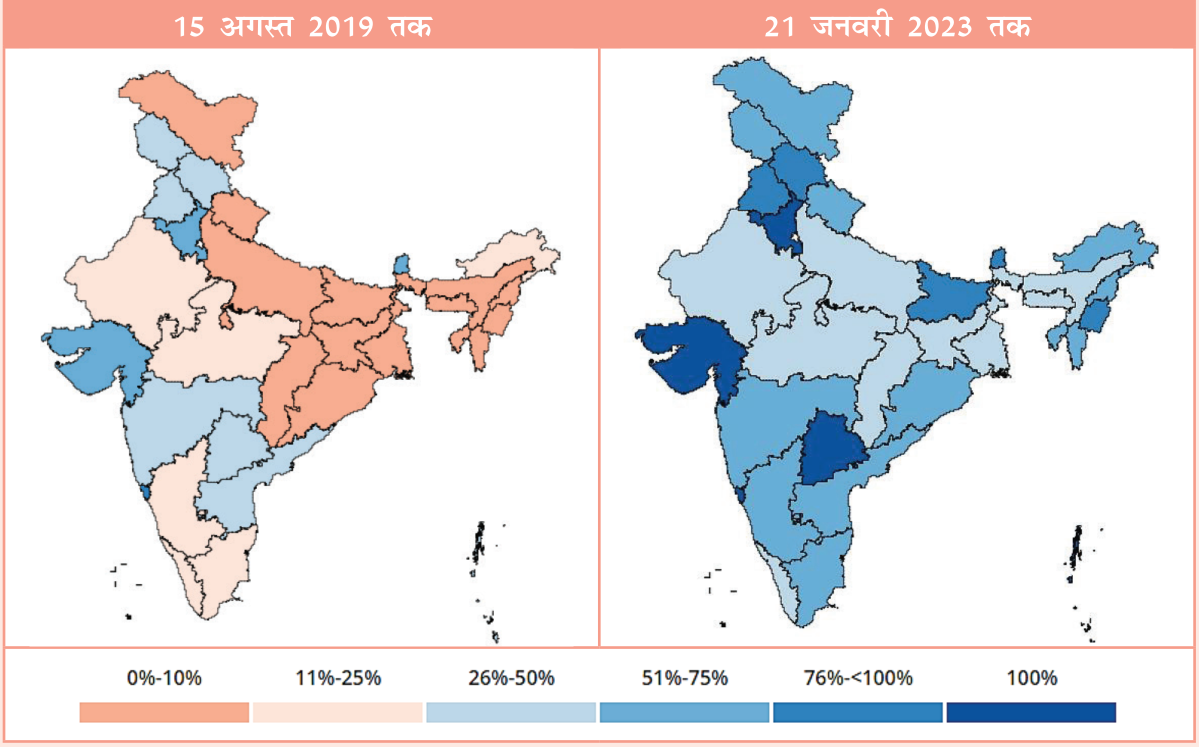

स्रोतः जल जीवन मिशन डैशबोर्ड

- प्रत्येक गांव में कम से कम एक आशा कार्यकर्ता और एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित पांच महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके किसी भी प्रकार के संदूषण के पानी के नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। एकटीके खरीदे जाते हैं और पंचायतों को सौंपे जाते हैं। एकटीके नौ मापदंडों पर पानी का परीक्षण करने में मदद करता है। पीएच, क्षारीयता, क्लोराइड, नाइट्रेट, कुल कठोरता, फ्लोराइड, लोहा, अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन और दिसंबर 2022 तक, एकटीके के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण पर लगभग 2.0 लाख गांवों में 16.2 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है, और 58.0 लाख से अधिक पानी के नमूनों का परीक्षण किया गया है।
- देश में 2,067 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। इनमें से 657 प्रयोगशालाएं एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हैं। पानी के नमूनों की नाममात्र दरों पर जांच कराने के लिए लोगों के लिए जल परीक्षण प्रयोगशालाएं खोल दी गई हैं। कई राज्यों ने दूरदराज के गांवों में पानी के नमूने एकत्र करने और परीक्षण करने में सक्षम बनाने के लिए मोबाइल वैन उपलब्ध कराए हैं। वित्त वर्ष 23 में, दिसंबर 2022 तक, प्रयोगशालाओं में 27.0 लाख से अधिक पानी के नमूनों का परीक्षण किया गया है।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न स्थानीय जल उपयोगिताओं के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, घरों में जल सेवा वितरण की स्थिति का आकलन करने के लिए हर साल एक कार्यात्मक मूल्यांकन अभ्यास किया जाता है। घरेलू नल कनेक्शन-2022 की कार्यक्षमता के आकलन के अनुसार, 87 प्रतिशत नमूना परिवारों को पीने योग्य पानी प्राप्त हुआ।
- 10 अक्टूबर 2022 तक, देश भर में 8.7 लाख स्कूलों (84.6 प्रतिशत) और 8.9 लाख (80.6 प्रतिशत) आंगनवाड़ी केंद्रों को पीने और मध्याह्न भोजन पकाने, हाथ धोने और शौचालयों में उपयोग के लिए पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराया गया है।
- 2 अक्टूबर 2022 को 100 दिवसीय जल गुणवत्ता अभियान ष्स्वच्छ जल से सुरक्षाष की घोषणा की गई थी, जिसमें सूचना, शिक्षा और संचार, प्रशिक्षण गतिविधियों और नागरिक विज्ञान दृष्टिकोण का उपयोग करके ग्रामीणों की क्षमता निर्माण के माध्यम से पानी की गुणवत्ता के महत्व पर जागरूकता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- जेजेएम द्वारा समर्थित विभिन्न आईआईटी में पांच 'सतत पेयजल केंद्र' पेयजल में स्थिरता लाने के लिए नवाचारों और प्रौद्योगिकियों के विकास पर काम कर रहे हैं।

मिशन अमृत सरोवर

6.115 भविष्य के लिए जल संरक्षण के उद्देश्य से 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ किया गया। मिशन का उद्देश्य स्वतंत्रता के 75वें वर्ष इस अमृत वर्ष के दौरान देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। अब तक, 50,000 अमृत सरोवर के प्रारंभिक लक्ष्य को लेकर, कुल 93,291 से अधिक अमृत सरोवर स्थलों की पहचान की गई है और 54,047 से अधिक स्थलों पर काम शुरू हो गया है। इन शुरू किए गए कार्यों में से अब तक कुल 27,071 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण किया जा चुका है। इस पहल से निम्नलिखित कार्य किए गए:

- लगभग 32 करोड़ घनमीटर जल धारण क्षमता को बढाया गया है।
- जल उपभोक्ता समूहों को प्रत्येक अमृत सरोवर के साथ जोड़ा गया है, साथ ही साथ स्थानीय समुदाय की आजीविका के आधार में सुधार किया गया है।
- स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों के परिवारों, पद्म पुरस्कार विजेताओं और स्थानीय क्षेत्रों के अन्य वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी ने बड़े पैमाने पर सामुदायिक भागीदारी में मदद की, सामाजिक सद्भाव और देशभक्ति को बढ़ावा दिया और इस मिशन को एक जन आंदोलन बना दिया।

- इस मिशन में ''श्रम-दान'' के रूप में लोगों की भागीदारी देखी गई है।
- इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 1,04,818 टन कार्बन की कुल कार्बन पृथक्करण क्षमता का निर्माण होगा।

जलदूत ऐप

6.116 एक ग्राम पंचायत के 2-3 चयनित खुले कुओं के माध्यम से वर्ष में दो बार (मानसून पूर्व और मानसून के बाद) पानी के स्तर को मापने के लिए 27 सितंबर 2022 को जलदूत ऐप को लॉन्च किया गया था। जल स्तर को मापने के लिए ग्राम रोजगार सहायक की आवश्यकता होती है और जलदूत मोबाइल ऐप का उपयोग करके केंद्रीय सर्वर पर इसका दस्तावेजीकरण किया जाता है। इससे भूजल की निगरानी, जल बजट और जल संचयन और संरक्षण संबंधी कार्यों की योजना बनाने में मदद मिलेगी। 7 दिसंबर 2022 तक कुल 3,66,354 कुओं की माप की जा चुकी है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

6.117 स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम (जी)) भारत में स्वच्छता सुनिश्चित करने और इसे खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों में ओडीएफ का दर्जा हासिल करने के बाद, एसबीएम (जी) का चरण- II अब वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 25 के दौरान लागू किया जा रहा है, जिसमें गांवों की ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने और सभी गांवों को शामिल करने पर ध्यान दिया जा रहा है। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, अर्थात गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस में बदलने के लिए। इस मिशन के अधीन 10 नवंबर 2022 तक लगभग 1,24,099 गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने अपने सभी गांवों को ओडीए्फ प्लस मॉडल घोषित किया है, इस प्रकार यह पहला स्वच्छ, सुजल प्रदेश बन गया है।

एलपीजी कनेक्शन

6.118 आवश्यक वस्तुओं सहित कमोडिटी की कीमतें पिछले एक साल में अस्थिर बनी रहने के कारण सरकार कमजोर लोगों का समर्थन करना जारी रखे हुए है। इसमें सब्सिडी युक्त खाना पकाने के ईंधन के साथ परिवारों को समर्थन देना शामिल है।

6.119 ***प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, स्वच्छ भारत बेहतर जीवन:*** ''प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना'' (पीएमयूवाई) मई 2016 में ग्रामीण और वंचित परिवारों को रसोई गैस जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन उपलब्ध कराने के लिए एक प्रमुख योजना के रूप में शुरू की गई थी, जो अन्यथा परंपरागत उपयोग कर रहे थे। खाना पकाने के ईंधन जैसे जलाऊ लकड़ी, कोयला, गाय के गोबर के उपले आदि। पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ा है। योजना के अधीन 9.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करके भी एलपीजी कवरेज को 1 मई 2016 के 62 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2021 को 99.8 प्रतिशत करने में मदद मिली है।

6.120 वित्त वर्ष 22 के केंद्रीय बजट के अधीन, पीएमयूवाई योजना अर्थात उज्ज्वला 2.0 के अधीन अतिरिक्त एक करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया गया है। यह योजना लाभार्थियों को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन, पहली रिफिल और हॉट प्लेट मुफ्त और एक सरलीकृत नामांकन प्रक्रिया की पेशकश करेगी। इस चरण में प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा दी गई है। इस उज्जवला 2.0 योजना के अधीन 24 नवंबर 2022 तक 1.6 करोड़ कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।

ग्रामीण कनेक्टिविटी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

6.121 पीएमजीएसवाई का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों की निर्दिष्ट जनसंख्या आकार वाली (मैदानी क्षेत्रों में 500+, उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों में 250+) सभी पात्र असंबद्ध बस्तियों को एकल बारहमासी सड़क संपर्क की व्यवस्था करना है। कार्यक्रम में उन जिलों के लिए एक उन्नयन घटक भी है, जहां निर्दिष्ट जनसंख्या आकार के सभी पात्र आवासों को बारहमासी सड़क संपर्क दिया गया है। हालाँकि, यह उन्नयन कार्यक्रम के घटकों में से एक है।

6.122 कार्यक्रम को तीन चरणों में प्रारंभ किया गया है, जिसमें नवीनतम तीसरे चरण की शुरुआत 10 जुलाई 2019 को मार्गों के माध्यम से 1,25,000 किमी के समेकन और बस्तियों को जोड़ने वाले प्रमुख ग्रामीण लिंक, अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, और अस्पतालों से की गई है। इसकी स्थापना के बाद से, ₹3,63,233 करोड़ से 8,01,838 किमी कुल 1,84,984 सड़कों और 10,383 स्पैन वाले 10,383 फलों (एलएसबी) को पीएमजीएसआई के सभी हस्तक्षेपों/कार्यक्षेत्रों के तहत स्वीकृत किया गया है। 7,23,893 किमी लंबी और 1,73,775 सड़कों और 7,789 एलएसबी को पूरा किया गया है।

6.123 इस योजना ने बुनियादी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने और ग्रामीण जनता की आय बढ़ाने में अत्यधिक मदद की है। पीएमजीएसवाई पर विभिन्न स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए गए, जिनसे यह निष्कर्ष निकला कि इस योजना का कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरीकरण, रोजगार सृजन आदि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

बिजली

सौभाग्य- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

6.124 सरकार ने अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य मार्च 2019 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और देश में शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना है। इस योजना में ऑन-स्पॉट पंजीकरण और कनेक्शन जारी करने के लिए गांवों/क्लस्टर गांवों में शिविरों का आयोजन करना शामिल था। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मुफ्त कनेक्शन दिए गए और अन्य के लिए 10 किस्तों में कनेक्शन जारी होने के बाद 500 रुपए का शुल्क लिया गया। सौभाग्य योजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और 31 मार्च 2022 को बंद कर दिया गया है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

6.125 यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से नवंबर 2014 में शुरू की गई थी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए गांवों/बस्तियों में बुनियादी बिजली के बुनियादी ढांचे के निर्माण, मौजूदा बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और वृद्धि, और मौजूदा फीडरों/वितरण ट्रांसफार्मरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग की परिकल्पना की गई थी। इसके अलावा, राज्यों द्वारा उनकी सूची के अनुसार पहचाने गए बीपीएल परिवारों को अंतिम-मील कनेक्टिविटी और मुफ्त बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए गए थे।

6.126 अक्टूबर 2017 में सौभाग्य अवधि शुरू होने के बाद से कुल 2.9 करोड़ घरों का विद्युतीकरण विभिन्न योजनाओं (सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई, आदि) के तहत किया गया है।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणः गेम चेंजर

6.127 आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 ने दिखाया कि यद्यपि भारत में सरकारों द्वारा अपने गरीबी रोकथाम कार्यक्रमों में मानक टूलकिट के हिस्से के रूप में मूल्य सब्सिडी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, वे अक्सर प्रतिगामी होते हैं, बाजारों को ऐसे तरीकों से विकृत करते हैं जो अंततः आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और जो इसके रिसाव मूल्य के साथ-साथ उत्पाद सब्सिडी की प्रभावशीलता को गंभीरता से कम करते हैं। इन विकृतियोँ और रिसाव का सामाजिक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह सिफारिश की गई थी कि मूल्य सब्सिडी द्वारा गरीबों के लिए जो लाभ देने का प्रयास किया जाता है, उसे एकमुश्त आय हस्तांतरण के माध्यम से सीधे गरीबों को हस्तांतरित किया जा सकता है, जिससे कीमतों में सब्सिडी से होने वाली विकृतियों से बचा जा सके। सब्सिडी को खत्म करना या चरणबद्ध तरीके से कम करना न तो संभव है और न ही वांछनीय जब तक कि गरीबों और कमजोरों को सहारा देने के लिए अन्य प्रकार के समर्थन के साथ और उनकी आर्थिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सक्षम न हो। जेएएम नंबर ट्रिनिटी - जन धन योजना, आधार और मोबाइल नंबर - ने सरकार को डीबीटी के रूप में लक्षित और कम विकृत तरीके से पहचाने गए परिवारों को इस सहायता को देने की अनुमति दी है।

6.128 डीबीटी की स्थापना के बाद से, केंद्रीय योजनाओं के संबंध में ₹26.5 लाख करोड़ से अधिक का संचयी हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से किया गया है। इस प्रक्रिया में, 31 मार्च 2021 तक अकेले केंद्रीय योजनाओं के लिए 9.4 करोड़ डुप्लिकेट, नकली/मौजूद लाभार्थियों को सभी डेटाबेस से हटाने के कारण कुल 2.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है।

6.129 कोविड-19 महामारी की शुरुआत और लॉकडाउन लागू होने और सामाजिक दूरी के मानदंडों को लागू होने से डीबीटी पारिस्थितिकी तंत्र को एक कठिन परीक्षण का सामना करना पड़ा और लाखों नागरिकों के लिए राहत के रूप में उभरा, जिनकी आजीविका प्रभावित हुई थी। जीवन को बनाए रखने में डीबीटी ने प्रमुख भूमिका निभाई, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों को तत्काल राहत देकर लाखों लोगों की मदद की। पीएम-किसान, मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), एनआरएलएम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) जैसी केंद्रीय योजनाओं के तहत नकद हस्तांतरण, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों की छात्रवृत्ति योजनाएं) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सब्सिडी और आत्म निर्भर भारत पैकेज कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान भारत की संपूर्ण प्रतिकूल प्रभावित जनता के लिए एक बड़ी राहत थी।

6.131 डीबीटी के भारत के सफल कार्यान्वयन ने अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से प्रशंसा प्राप्त की है, कम आय वाले स्तर (85 प्रतिशत) पर बड़ी जनता को कुशलतापूर्वक सहायता (सब्सिडी, खाद्यान्न, और नकद लाभ सीधे) प्रदान करने के लिए ग्रामीण परिवारों की और 69 प्रतिशत शहरी परिवारों की)। बॉक्स VI-11 भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जेएएम-ट्रिनिटी-आधारित डीबीटी ढांचे की प्रगति को सूचित करता है।

बॉक्स: VI-13: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना में प्रगति

डीबीटी को 2013 में आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करके तत्कालीन मौजूदा वितरण प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करने के लिए लॉन्च किया गया था ताकि लाभ सीधे लक्षित लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किए जा सकें। पिछले एक दशक की अवधि में, डीबीटी 2013 में 43 जिलों में केवल 24 योजनाओं (पायलट कार्यक्रम के भाग के रूप में) से दिसंबर 2022 तक पूरे भारत में 300 से अधिक केंद्रीय योजनाओं और 2000 से अधिक राज्य योजनाओं तक विस्तारित हो गया है।

तालिका VI.23: समग्र डीबीटी प्रगति रिपोर्ट

	2013-14	2016-17	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (Till 5 Jan 2023)
No of DBT Schemes	28	142	440	426	316	313	310
Total Funds Transferred (in ₹crore)	7,368	74,689	3,29,796	3,81,632	5,52,527	6,30,265	3,80,380
Cash schemes	7,368	74,689	2,14,092	2,39,729	2,96,578	2,68,139	1,71,842
In-kind schemes	-	-	1,15,704	1,41,902	2,55,950	3,62,126	2,08,538
Eligible Beneficiaries [non-unique] (in crore)	10.8	35.7	129.2	144.7	179.9	178.9	159.5

स्रोत: मंत्रालयों/विभागों द्वारा डीबीटी मिशन, कैबिनेट सचिवालय को भेजे गए आंकड़े

अपने संचालन के वर्षों में, डीबीटी पैटर्न से निम्नलिखित लाभ मिले हैं :

- लाभार्थियों की सटीक पहचान और लक्ष्यीकरण;
- ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से व्यापक समावेशन और सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी;
- लाभार्थियों को निधि अंतरण में पारदर्शिता;
- बिचौलियों/एजेंटों के उन्मूलन के माध्यम से लाभ वितरण प्रक्रियाओं में रिसाव को रोकना;
- सरकार की ओर से अधिक जवाबदेही ;
- री-इंजीनियरिंग के माध्यम से सरकारी प्रक्रियाओं में सुधारों को सुगम बनाना;
- योजना वितरण प्रक्रियाओं में दक्षता में वृद्धि; और
- समय पर कार्यान्वयन के माध्यम से योजनाओं की प्रभावशीलता।

समावेशी विकास के लिए ग्रामीण शासन में सुधार करना

6.132 सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने, सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की स्थिरता प्राप्त करने में मदद करने के लिए अच्छा ग्रामीण शासन अनिवार्य है। ग्रामीण प्रशासन में सुधार की दिशा में हाल ही में किए गए कुछ उपायों का विवरण नीचे दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

6.133 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के एक सीएसएस को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अप्रैल 2018 में वित्तीय वर्ष 19 से वित्त वर्ष 22 तक कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य मिशन अंत्योदय के साथ अभिसरण पर मुख्य जोर के साथ एसडीजी प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को मजबूत करना था। 117 आकांक्षी जिलों में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। यह योजना भारत के संविधान के गैर-भाग IX सहित उन सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक फैली हुई है जहाँ पंचायतें नहीं हैं।

6.134 पीआरआई को सशक्त बनाने और पंचायतों के संबंधित स्तर पर अभिसरण योजना तैयार करने के लिए आरजीएसए की योजना का प्रमुख फोकस क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) था। योजना के तहत, न केवल लगभग 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) को प्रशिक्षण के विभिन्न तरीकों के माध्यम से सक्षम बनाया गया है, बल्कि एसएचजी सदस्यों सहित पंचायतों के पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को भी बेहतर एसएचजी-पीआरआई के लिए प्रशिक्षण दिया गया है।

6.135 वित्त वर्ष 23 से वित्त वर्ष 26 की अवधि में कार्यान्वयन के लिए योजना को अप्रैल 2022 में संशोधित और अनुमोदित किया गया है। पुनर्गठित आरजीएसए की योजना का ध्यान केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य लाइन विभागों और अन्य हितधारकों को 'संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज' दृष्टिकोण के साथ ठोस और सहयोगी प्रयासों के माध्यम से जमीनी स्तर पर एसडीजी (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानीय स्वशासन के जीवंत केंद्रों के रूप में पीआरआई की फिर से कल्पना करना है। यह योजना स्थानीय विकास की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनने के लिए ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। एलएसडीजी के नौ विषयगत दृष्टिकोणों को अपनाते हुए एसडीजी से जुड़ी स्थानीय समस्याओं के स्थायी समाधान को साकार करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाली भागीदारी योजनाएं तैयार करें और उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करें।

स्वामित्व योजना

6.136 स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों का सर्वेक्षण और बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण) 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में घर रखने वाले ग्रामीण परिवारों के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना है। इस योजना में विविध पहलुओं को शामिल किया गया है। संपत्तियों के मुद्रीकरण को सुगम बनाना और बैंक ऋणों को सक्षम बनाना; संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना; व्यापक ग्राम-स्तरीय योजना, जो सही अर्थों में ग्राम स्वराज प्राप्त करने और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। योजना का उद्देश्य निम्नलिखित लाभ प्रदान करना है:

- ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना।
- ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभों के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना।
- संपत्ति कर का निर्धारण, जो उन राज्यों में सीधे ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है या अन्यथा, राज्य के खजाने में जोड़ा जाएगा।
- सर्वेक्षण अवसंरचना और जीआईएस मानचित्रों का निर्माण जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा उनके उपयोग के लिए किया जा सकता है।

- जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके एक बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता करना।

6.137 31 दिसंबर 2022 तक, देश भर के 2.15 लाख गांवों का ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है, और हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा, और लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पुडुचेरी, और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित राज्यों में संतृप्त किया गया है। लगभग 65,000 गांवों के लिए एक करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। हरियाणा के बाद उत्तराखंड और पुडुचेरी के सभी बसे हुए गांवों के संपत्ति कार्ड बनाए गए हैं।

निष्कर्ष और भावी परिदृश्य

6.138 इतिहास बताता है कि जब मानव विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा जाता है, तो सर्वांगीण क्रांतिकारी नवाचार के परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी के नेतृत्व में विकास और समृद्धि आती है। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 2015 में किए गए अवलोकन के अनुसार

''सरकार को निम्न पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना चाहिए:

- जहां विकास के लिए अर्थव्यवस्था प्रमुख है; और विकास से सर्वांगीण विकास को बढ़ावा मिले ;

- जहां विकास से रोजगार पैदा हो रहा है; और रोजगार कौशल युक्त होता है;

- जहां कौशल को उत्पादन के साथ जोड़ा जाता है; और गुणवत्ता उत्पादन के लिए बेंचमार्क है;

- जहां गुणवत्ता वैश्विक मानकों को पूरा करती हो; और वैश्विक मानकों को पूरा करने से समृद्धि आती है सबसे महत्वपूर्ण, यह समृद्धि सभी के कल्याण के लिए है''

6.139 आज, भारत संयुक्त राष्ट्र एसडीजी हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। ऐसा करते समय, यह इस तथ्य का ज्ञान होना चाहिए कि समान विकास के लिए, भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश को पर्याप्त और समान वित्तीय संसाधनों द्वारा समर्थित व्यापक-आधारित समावेशी सामाजिक नीतियों के कार्यान्वयन की आवश्यकता है। इस प्रकार, विकास के लिए इस तरह के दृष्टिकोण का चरित्र और रूपरेखा चुनौतियों का एक अनूठा समूह प्रस्तुत करता है जिसे लगातार सुधारों के रूप में संबोधित किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करना कि सामाजिक क्षेत्र की विकास योजनाओं के इच्छित परिणाम अभीष्ट हों, शासन के जमीनी स्तर की भागीदारी अनिवार्य है और इसे सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। लक्षित नागरिकों के लिए सरकारी योजनाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी एक महान प्रवर्तक रही है। इसने पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करते हुए सेवाओं के वितरण में क्रांति ला दी है। सामाजिक मोर्चे पर उच्च एसडीजी प्राप्त करने में सरकार की मदद करने के लिए इसे और अधिक उपयोग करने की आवश्यकता है।

6.140 जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे महामारी के कारण सामाजिक क्षेत्र में सुधार के संबंध में खोई हुई जमीन को बड़े पैमाने पर पुन: प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रौद्योगिकी के साथ त्वरित नीति निर्माण और कुशल कार्यान्वयन द्वारा संचालित है। मिनिमम गवर्नमेंट; अधिकतम शासन, आगामी घटनाक्रम अधिक न्यायसंगत आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगें। प्रत्यक्ष रूप से स्कूलों में डिजिटल और शिक्षण हस्तक्षेपों के माध्यम से सीखने के परिणामों को आगे बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवा में सामुदायिक कार्यकर्ताओं की भूमिका को बढ़ाना, बेहतर उत्पाद डिजाइन और अपस्केलिंग उद्यमों के माध्यम से एसएचजी को आगे बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं जैसे कि देखभाल के काम के लिए किफायती बाजार विकल्प, सुरक्षित परिवहन और आवास, और दीर्घकालिक परामर्श सहायता के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक क्षमता को चौनलाइज करना, देश के भविष्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लैंगिक लाभांश को भुनाने में मदद कर सकता है।

---

https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=114728

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण: भविष्य का सामना करने की तैयारी

07

अध्याय

जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से विकसित देशों के ग्रीनहाउस गैसों के काफी लम्बे समय से चले आ रहे और उच्च प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्सर्जन दोनों के असमान अनुपात में उच्च संचयी उत्सर्जन के कारण हो रहा है। संचयी वैश्विक उत्सर्जन (वर्ष 1850-2019 की अवधि के लिए) में मात्र लगभग 4 प्रतिशत का योगदान देने और विश्व औसत से इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अत्यधिक कम होने के बावजूद, भारत, इस समस्या की वैश्विक प्रकृति होने के कारण विश्व के सबसे प्रभावित राष्ट्रों में से एक है। जहाँ भारत उत्सर्जन की उच्च मात्रा के लिए कम जिम्मेदार है, फिर भी यह लगातार विभिन्न उपायों को अपनाने की दिशा में वैश्विक प्रयासों का पालन कर रहा है और वर्ष 2070 तक निवल-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की प्रतिबद्धता के साथ कम-उत्सर्जन विकास के नीतिगत मार्गों को सुनिश्चित कर रहा है

भारत के महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई संबंधी लक्ष्यों के साथ विकास लक्ष्यों को एकीकृत किया है, चाहे वह संवर्धित सौर ऊर्जा क्षमता (संस्थापित) के रूप में, पीएटी चक्र-VII में अधिसूचित उच्च ऊर्जा बचत लक्ष्य, ग्रीन इंडिया मिशन द्वारा सुगम बनाए गए बेहतर हरित आवरण, अन्य लक्षित सरकार से संबंधित किसी भी कार्रवाई के रूप में हो। पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के लिए समर्पित प्रयासों के लिए, भारत में अब मैंग्रोव की संरक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न विनियामक और प्रचार संबंधी उपायों के अलावा आर्द्रभूमि के लिए 75 रामसर स्थलों की व्यवस्था की है। नमामि गंगे और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) द्वारा से निरंतर नदी संरक्षण और कायाकल्प के प्रयास जारी हैं।

अगस्त 2022 में, देश ने यूएनएफसीसीसी के पार्टियों के सम्मेलन की 26वीं बैठक में व्यक्त किए गए माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण (विजन) के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किए गए योगदान (एनडीसी) को अद्यतन किया गया। अक्षय ऊर्जा के स्रोतों में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में, भारत ने वर्ष 2030 से पहले ही गैर-जीवाश्म ईंधन से 40 प्रतिशत संस्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसने अपने लक्ष्य में 50 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे औसत उत्सर्जन दर में उल्लेखनीय कमी को आएगी। वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन और हरित हाइड्रोजन नीति शुरू की गई है। भारत की दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति (एलटी-एलईडीएस) में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ती है।

पर्याप्त और वहनीय वित्त की उपलब्धता भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाइयों में एक बाधा बनी हुई है। देश ने अब तक अपनी जरूरतों को बड़े पैमाने पर घरेलू स्रोतों से ही पूरा किया है। जलवायु संबंधी कार्रवाइयों के लिए वित्त एक महत्वपूर्ण इनपुट है। इसलिए, देश ने जलवायु संबंधी कार्रवाई के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड सहित निजी पूंजी जुटाने की दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाया है। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन (आईसीएमए) ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स (2021) के अनुपालन में परीवर्ती के लिए ढांचा जारी किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की पहल उल्लेखनीय रही है। देश के विभिन्न अंतर-सरकारी संगठनों के गठन और इनका सुदृढ़ीकरण करते हुए वैश्विक कार्रवाइयों में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

परिचय

7.1 जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से तापमान और मौसम के पैटर्न में होने वाला एक दीर्घकालिक परिवर्तन है, लेकिन 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद यह मुख्य रूप से मानवजनित गतिविधियों के कारण हुआ है। ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन दशकों से शताब्दियों तक वातावरण में बना रहता है, जिसके सूर्य से निकलने वाली गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। सीमा के भीतर, रहते हुए ये हमारी पृथ्वी को और अधिक रहने योग्य बनाते हैं, जो स्वास्थ्यकर मौसम की स्थिति के अनुकूल हैं, और इस तरह संवर्धित उत्सर्जन ने समुद्र के स्तर में वृद्धि, मानसून चक्र में परिवर्तन और भूमि प्रणालियों को प्रभावित करने की क्षमता के साथ तापमान में वृद्धि की है।

7.2 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन मानवता और दुनिया के सामने आने वाली अपरिहार्य वास्तविकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कम करने और बदलती जलवायु परिस्थितियों के साथ अनुकूलित होने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि दुनिया ने पहले ही इसके परिणामों का सामना कर रही है। उदाहरण के लिए, यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 तक, दुनिया भर में लगभग 700 मिलियन लोगों को केवल सूखे की आपदा के कारण विस्थापन का खतरा होगा (यूएन एसडीजी पोर्टल)। इस प्रकार, ग्लोबल वार्मिंग एक वास्तविकता है, और जलवायु परिवर्तन भी ऐसा ही है। इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि वर्तमान में मुख्य रूप से मानव गतिविधि ही इसके लिए जिम्मेदार है, हालांकि सुदूर अतीत में भी जलवायु परिवर्तन हुआ था जब पृथ्वी ग्रह पर बहुत कम आबादी थी।

7.3 उपरोक्त पर सहमति होने के बावजूद, जलवायु परिवर्तन की बात आने पर आगे क्या होगा और इसके बारे में हमें क्या करना है, इसके बारे में अभी भी बहुत भिन्नता हो सकती है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अधिकांश वैश्विक चिंता विशेष रूप से ग्रीनहाउस गैसों और कार्बन से होने वाले उत्सर्जन के बारे में है। जितना अधिक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, उतना ही अधिक वे वातावरण में बने रहते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि यदि कुछ विनाशकारी परिणामों से बचना है, तो ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाना चाहिए, धीमा किया जाना चाहिए और यदि संभव हो तो इसके प्रतिकूल कार्य किया जाना चाहिए। कार्बन सहित जीएचजी के उत्सर्जन को कम करने का ऐसा प्रयास किया जा सकता है। कई राष्ट्रों ने वर्ष 2050 तक अपने निवल गैस उत्सर्जन को शून्य तक कम करने की प्रतिज्ञा की है। कुछ राष्ट्र इसे वर्ष 2060 और 2070 तक हासिल करना चाहते हैं।

चित्र VII.1: विभिन्न देशों (प्रतिज्ञा वर्ष दंडा रेख के ऊपर है) की निवल शून्य प्रतिज्ञा

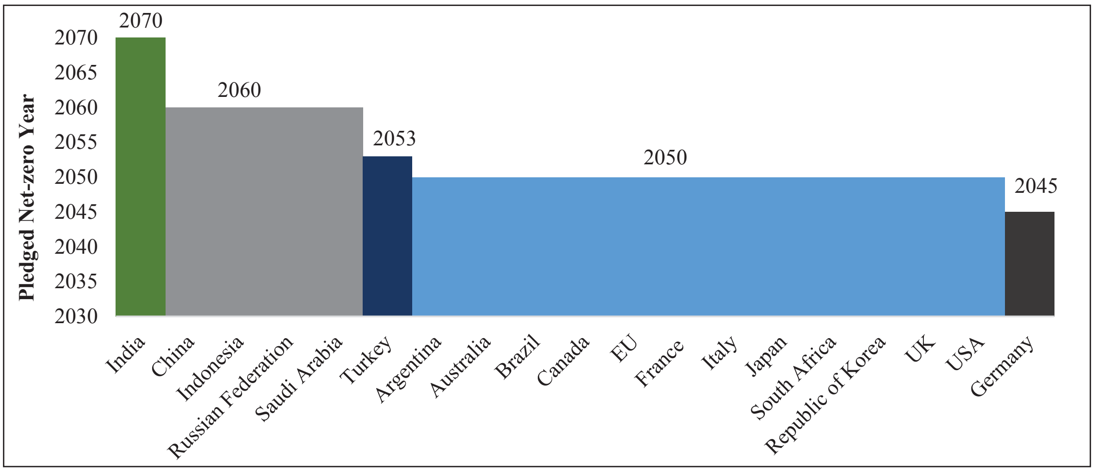

स्रोत: इमिशन गैप रिपोर्ट, 2022 युएनईपी

7.4 हालाँकि, यहीं से विषय दिलचस्प होने लगता है। विज्ञान से इस बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है कि क्या आगामी कार्बन उत्सर्जन में होने वाली कमी आवश्यक रूप से ग्लोबल वार्मिंग को रोकने या इसके प्रतिकूल होने की गारंटी देगी। इसका कारण यह है कि आज के उन्नत राष्ट्रों, मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरोप में औद्योगीकरण के नेतृत्व वाली आर्थिक वृद्धि वाली पिछली ढाई शताब्दियों में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन पहले ही हो चुका है। विकसित देशों की तुलना में जीएचजी गैसों (आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य के रूप में मापा जाता है) के स्टॉक में विकासशील देशों का हिस्सा न्यूनतम रहा है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) द्वारा इसकी परिपुष्टि की गई है, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वे मुख्य रूप से विकसित देशों के संचयी ऐतिहासिक और वर्तमान ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण हैं। संचयन का प्रभाव भी अन्यायपूर्ण होगा, विकासशील देशों को न केवल जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगतना होगा बल्कि इसकी चुनौतियों का जवाब देने की उनकी क्षमता से भी विवश होना पड़ेगा। आईपीसीसी की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट (इआर6) में यह कहा गया है कि उच्च मानव सुभेद्यता वाले वैश्विक हॉटस्पॉट विशेष रूप से पश्चिम, मध्य और पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एशिया, मध्य और दक्षिण अमेरिका, छोटे द्वीप विकासशील राज्यों और आर्कटिक में पाए जाते हैं।

7.5 इसके अलावा, इस रिपोर्ट के अनुसार, एशिया जलवायु परिवर्तन, विशेष रूप से अत्यधिक गर्मी, बाढ़, समुद्र के स्तर में वृद्धि और अनियमित वर्षा के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। विडंबना तो यह है कि इस अनुकूलन का बोझ उन लोगों पर सबसे अधिक पड़ेगा, जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग में सबसे कम योगदान दिया है। उस दुर्भाग्यपूर्ण अनिवार्यता का अर्थ है कि वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के भंडार ने पहले से ही घटनाओं की एक श्रृंखला निर्धारित कर दी है जो भविष्य में होने वाले उत्सर्जन में होने वाल कमी को रोकने या इसके प्रतिकूल प्रभाव को बहुत कम कर सकती है।

7.6 भले ही इस प्रश्न का उत्तर अस्पष्ट या अज्ञात हो, फिर भी कुछ लोग सही तर्क देते हैं कि इस ग्रह को अधिक रहने योग्य और कम खतरनाक बनाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, उसे नहीं करना आपराधिक लापरवाही की श्रेणी में आ सकता है। समस्या यह है कि जो लोग और राष्ट्र इस तरह के तर्क दे रहें हैं उनकी ये प्राथमिकताएं उनके लिए सही हैं, किन्तु यह उन देशों के लिए सही नहीं है जिन्हें समृद्धि की सीढ़ियां चढ़ना अभी बाकी है। यह अर्थशास्त्र का एक स्थायी सिद्धांत है कि संसाधनों का प्रतिस्पर्धात्मक उपयोग होता है और व्यापार में सदैव लेन-देन होता है।

7.7 इसलिए आज के विकासशील राष्ट्र एक दुविधा की स्थिति में हैं। रोजी-रोटी की विकासात्मक प्राथमिकताओं और पहले से ही बदलती जलवायु के साथ अनुकूलित होने के लिए हमें और कितने संसाधनों का उपयोग करना है, और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए हमें और कितना समर्पित होना होगा? आज के विकसित राष्ट्र कोयला, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस सहित जीवाश्म ईंधन के अप्रतिबंधित उपयोग के जरिये समृद्ध हुए हैं। यह तर्क देना सैद्धांतिक रूप से सुरुचिपूर्ण है कि अक्षय ऊर्जा या गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा को अपनाने से निवेश और नौकरियां पैदा होंगी। फिर भी, शायद ही यह कभी व्यवहार में इतनी आसानी से काम करे।

7.8 उदाहरणस्वरुप, चीन ने यह घोषणा की है कि वैकल्पिक ऊर्जा सहित मौजूदा ऊर्जा स्रोतों को उपभोग करने से पूर्व भावी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित किया जाना चाहिए। यह हो सकता है कि देश खुद को कोयला चालित बिजली संयंत्रों को खत्म न कर पाएं, और इसके विकल्प या तो प्रौद्योगिकी, वित्तीय संसाधनों, कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधनों, या सभी इन तीनों के संयोजन की कमी के कारण रुके रह सकते हैं। इन देशों को इस बात की जानकारी है कि तथाकथित 'हरित अर्थव्यवस्था' में जिन नौकरियां के सृजित होने की संभावना है, वे पारंपरिक उद्योगों[1] की तुलना में कौशल और प्रौद्योगिकी-केंद्रित उद्योगों की ओर झुकी हुई हैं। इस संबन्ध में कोई यह भी तर्क दे सकता है कि वास्तव में ऐसा करने की तुलना में लोगों को पुनः प्रशिक्षण और स्थानांतरित करने की बात करना आसान हो सकता है।

---

[1] World Economic Outlook, October 2021, Ch.1 World Economic Outlook, October 2021: Recovery During A Pandemic (imf.org)

7.9 नोबेल पुरस्कार विजेता थॉमस शेलिंग (2005) ने यह तर्क दिया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका राष्ट्रों को पहले तरक्की करने देना था[2]:

''यदि अगले 40 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की तुलना पिछले 40 वर्षों से की जाए, तो जलवायु परिवर्तन की सुभेद्यता कम होनी चाहिए, और अनुकूलन के लिए उपलब्ध संसाधन अधिक होने चाहिए। मैं यह बात जलवायु परिवर्तन के बारे में चिंता को कम करने के लिए नहीं बल्कि यह पूर्वानुमान लगाता हूं कि क्या विकासशील देशों को गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने विकास का बलिदान देना चाहिए जो उनके नुकसान के लिए जलवायु को बदल सकते हैं। स्वयं का निरंतर विकास ही जलवायु परिवर्तन के प्रति उनका सबसे अच्छा बचाव हो सकता है।''

7.10 कॉर्पोरेट वित्त के छात्रों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि आर्थिक विकास होने से संसाधन पैदा होंगे। कंपनियां लाभ और आंतरिक संसाधन उत्पन्न करती हैं और इस प्रकार अपने निवेश के लिए निधि देती हैं। दुनिया भर की कंपनियों के लिए, अपने पूंजी निवेश के लिए वित्त का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत, बाजारों की ओर रुख करने से पूर्व, उनके अपने संसाधन अपनाना है। यह राष्ट्रों के लिए भी काम करेगा।

7.11 इसका एक और कारण है कि यह एक यथार्थवादी प्रस्ताव क्यों है कि विकसित देशों या बहुपक्षीय संगठनों से निधीयन हासिल करना अपेक्षाकृत मुश्किल है। विकसित देशों में सार्वजनिक वित्त को बढ़ाया जाता है और विकासशील देशों में जलवायु संबंधी कार्रवाई के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने का इरादा नहीं है। उनके पास बहुपक्षीय संस्थानों को अतिरिक्त पूंजी देने की ललक भी नहीं है ताकि वे अधिक उधार देने या अधिक संसाधन जुटाने में सक्षम हो सकें। इसके अलावा, लंबी अवधि की परियोजनाओं को शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र की इच्छा और प्रोत्साहन-संरेखण सबसे अच्छे या गैर-अस्तित्व में सबसे खराब हैं।

7.12 अंततः, यह इतना अजीब या गैर-जिम्मेदार नहीं है कि विकासशील देश अपने वैश्विक जलवायु संबंधी दायित्वों के समक्ष अपनी प्रगति और विकास की आकांक्षाओं को रखते हैं, जब कोई यह मानता है कि विकसित देशों ने इस वर्ष बिजली पैदा करने के लिए अधिक कोयला जलाने के लिए जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अपनी जुनूनी चिंताओं को अलग कर दिया है। इस वर्ष रूसी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर अपनी निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से, यूरोप के देशों को अपने घरों को गर्म और रोशन करने के लिए कोयले का प्रयोग करना पड़ा[3]। वर्ष 2022 में यूरोपीय देशों का व्यवहार, प्रमुख रूप से समझा जा सकता है, यह देशों की प्रमुख आवश्यकता के रूप में ऊर्जा सुरक्षा की वापसी को दर्शाता है। इसलिए, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी इससे अलग राय रखने का कोई कारण नहीं होगा।

7.13 वर्ष की शुरुआत में, हार्वर्ड में ओईसीडी और सोशल इकोनॉमिक्स लैब ने इस यह समझने के लिए एक टीम गठित की कि जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए नीतियों को लागू करना क्यों मुश्किल हो गया है और दुनिया के 20 सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जक देशों (वैश्विक CO2 (कार्बन डाइ ऑक्साइड) उत्सर्जन का 72 प्रतिशत दर्शाता है)[4] में 40 000 से अधिक उत्तरदाताओं का सर्वेक्षण किया। इसके निष्कर्ष चौंकाने वाले थे। सामान्य तौर पर, विकसित देशों में नागरिकों ने ड्राइविंग, उड़ान और खान-पान के संबंध में अपनी जीवन शैली और आदतों को परिवर्तित करने में काफी अनिच्छा व्यक्त की, जो कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कम करने में योगदान देगा। सभी यूरोपीय देशों में कार्बन मूल्य निर्धारण को लागू करने की नीतियां आसान नहीं रही हैं। फ्रांस ने इसके लिए कोशिश की और वर्ष 2018 में इससे पीछे हट गया। स्विट्जरलैंड का प्रस्ताव वर्ष 2021 में हुए जनमत संग्रह में हार गया।

---

2 Thomas C. Schelling (1992): 'Some economics of global warming', American Economic Review, March 1992 Some Economics of Global Warming on JSTOR

3 Germany Revives Coal as Energy Security Trumps Climate Goals', Bloomberg, 22 December 2022 (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-22/germany-returns-to-coal-as-energy-security-trumps-climate-goals)

4 'Fighting Climate Change: International Attitudes Toward Climate Policies', NBER Working Paper No. 30265, September 2022 (https://www.nber.org/papers/w30265)

7.14 ये चुनौतियाँ पर्याप्त नहीं हैं, कई विशेषज्ञ दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) और महत्वपूर्ण खनिजों (सीएम) की उपलब्धता को लेकर अगले भू-राजनीतिक युद्ध का मैदान होने की चेतावनी देते हैं जैसे कि पिछले पचास वर्षों में कच्चा तेल रहा है।[5] जैसा कि हम इस बात से अवगत हैं कि अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आरईई और सीएम आवश्यक हैं। समस्या यह है कि वे कुछ ही देशों में उपलब्ध हैं और उससे भी कम देशों में ये संसाधित होते हैं। पर्याप्त आरईई और सीएम के उपलब्ध नहीं होने पर गैर-जीवाश्म ईंधन के लिए विश्व स्तर पर सिंक्रनाइज ऊर्जा संक्रमण को दूर करना मुश्किल हो सकता है। कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए जीवाश्म ईंधन-आधारित आस्तियां मुश्किल में ंफस सकती हैं।

7.15 ब्रूगल संस्थान से जुड़े और फ्रांसीसी सरकार के सलाहकार जीन पिसानी-फेरी ने जलवायु परिवर्तन की महत्वपूर्ण अल्पकालिक मैक्रोइकॉनॉमिक लागत लागतों के बारे में चेतावनी देना शुरू कर दिया है। डैनियल येरगिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 'वत्त और विकास' के अपने लेख में उनका हवाला देते हुए, लिखते हैं[6],

''यूरोप के अग्रणी आर्थिक थिंक टैंक, ब्रगेल के सह-संस्थापक, अर्थशास्त्री जीन पिसानी-फेरी ने पाया है कि निवल कार्बन के उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्यों को आक्रामक रूप से तेजी लाने के लिए आम तौर पर जो अनुमान लगाया जाता है, उससे कहीं अधिक बड़े आर्थिक व्यवधान पैदा हो सकते हैं - जिसे उन्होंने ''प्रतिकूल आपूर्ति शॉक''- जो 1970 के दशक के आघातों की तरह है" कहा। इस तरह का एक संक्रमण, जिसे पिसानी-फेरी ने वर्तमान ऊर्जा संकट शुरू होने से ठीक पहले 2021 में लिखा था, इसके साथ हमारे अनुकूल होने की संभावना नहीं है और नीति निर्माताओं को कठिन विकल्पों के लिए तैयार रहना चाहिए। बाद में उन्होंने वर्ष 2022 में इसमें आगे जोड़ा: "जलवायु कार्रवाई एक प्रमुख मैक्रोइकॉनॉमिक मुद्दा बन गया है, लेकिन जलवायु कार्रवाई का मैक्रोइकॉनॉमिक्स कठोरता और सटीकता के स्तर से काफी दूर है जो अब सार्वजनिक चर्चाओं के लिए एक ठोस आधार प्रदान करने और नीति निर्माताओं को पर्याप्त रूप से मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक है। समझ में आने वाले कारणों के लिए, वकालत को अक्सर विश्लेषण पर वरीयता दी जाती है। लेकिन चर्चा के इस स्तर पर, आत्मसंतुष्ट परिदृश्य प्रतिकूल हो गए हैं। अब नीतिगत विचार पर कार्रवाई करने हेतु वैकल्पिक योजनाओं की संभावित लागतों और लाभों के व्यवस्थित, सहकर्मी-परीक्षित मूल्यांकनों की आवश्यकता है।"

7.16 हालाँकि, हम इसे पसंद करते हैं या नहीं, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा तेजी से प्रासंगिक होगा और यह वैश्विक स्तर पर व्याप्त हो जाएगा और नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित करेगा। भले ही देश कार्बन उत्सर्जन शमन के लिए वित्तीय, प्रौद्योगिकीय और मानव संसाधनों की प्रतीक्षा करते हों, परंतु उन्हें अपने लोगों को इसके प्रति स्थिति-परक बनाने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए कार्रवाई करनी होगी। इसलिए, संसाधनों के अनुमान, जीवन शैली समायोजन आदि सहित कई मोर्चों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

7.17 यहां, लंबी तटरेखा वाले, मानसून पर निर्भर कृषि और बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था वाले भारत देश को अतिसंवदेनशील देशों में से एक माना जाता है, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। संचयी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में इसका योगदान केवल 4 प्रतिशत (2019 तक) है और इसकी प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की मात्रा वैश्विक औसत से बहुत ही कम है।

7.18 तथ्य यह है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक परिघटना है और इसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, जिसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और इसके पेरिस समझौते में की गयी प्रतिबद्धताओं का आधार है। देशों की अलग-अलग जिम्मेदारी (जीएचजी उत्सर्जन में उनकी भूमिका के मद्देनजर) और विकासशील देशों की उच्च विकासात्मक आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए, वे इक्विटी और सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी और संबंधित क्षमताओं

5 'The new-style energy crisis', Daniel Yergin interviewed by Project Syndicate, July 2022 (https://www.project-syndicate.org/onpoint/new-style-energy-crisis-by-daniel-yergin-2022-07)

6 Daniel Yergin (2022): 'Bumps in the Energy Transition', Finance & Development, International Monetary Fund, December 2022 (https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/12/bumps-in-the-energy-transition-yergin)

(सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांतों के आधार पर एक सामूहिक कार्रवाई की मांग करते हैं। इस सामूहिक कार्रवाई से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के रूप में परिणत किया है - जिसके माध्यम से प्रत्येक देश ने तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के सामूहिक लक्ष्य की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता जताई है।

7.19 भारत सतत् विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहा है। यह अपने एनडीसी के माध्यम से अत्यधिक सशक्त जलवायु संबंधी कार्रवाइयों में से एक की अगुआई करता है, जिसमें दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा के बदलाव वाला महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शामिल है। अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद, देश ने अपनी जलवायु महत्वाकांक्षा को कई गुना बढ़ा दिया है और कम जीएचजी उत्सर्जन विकास रणनीति की दिशा में दीर्घकालिक रणनीति शुरू की है।

7.20 संदर्भ निर्धारण के बाद इस अध्याय में भारत के परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे संबंधी अद्यतन चर्चा प्रस्तुत की गई है, जिसमें वनों पर चर्चा और कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कम करने में उनकी भूमिका, अक्षय ऊर्जा में संक्रमण के लिए एक दृष्टिकोण और हाल ही में प्रस्तुत की गयी कम उत्सर्जन विकास रणनीति शामिल है। इस अध्याय में आगे पार्टियों के सम्मेलन (कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी27) के 27वें सत्र के परिणामों, सतत विकास के लिए सक्षम वित्त पोषण पर हुई प्रगति और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को हल करने की दिशा में वैश्विक प्रयासों में भारत की भूमिका पर चर्चा प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा, पर्यावरण नियमों हुए हालिया बदलाव और जैव विविधता और वन्य जीवन जैसे अन्य पर्यावरणीय पहलुओं पर भी चर्चा की गई है।

भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाई पर प्रगति

7.21 भारत की जलवायु संबंधी दृष्टिकोण उसके विकास के दृष्टिकोण से अभिन्न रूप से जुड़ा है जिसमें, गरीबी उन्मूलन के लक्ष्यों को सामने रखा गया है और अपने सभी नागरिकों के लिए बुनियादी कल्याण की गारंटी देता है। पेरिस समझौते के अस्तित्व में आने से पूर्व ही जलवायु कार्रवाई को प्रारंभ करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। वर्ष 2008 में, भारत ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) की शुरुआत की, आठ राष्ट्रीय मिशनों की स्थापना की, जिसमें कई पहलों और सौर, जल, ऊर्जा दक्षता, वन, स्थायी आवास, संधारणीय कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना, क्षमता निर्माण और अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)।

चित्र VII.2: एनएपीसीसी के आठ राष्ट्रीय मिशनों की प्रगति के क्षेत्र में कई उपायों को शामिल किया गया।

राष्ट्रीय सौर मिशन	• 61.62 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता अधिष्ठापित किया गया
उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन	• 6.63 मिलियन टन तेल समतुल्य (एमटीओई) के ऊर्जा बचत लक्ष्य के लिए पीएटी चक्र-VII अधिसूचित किया गया
सतत् पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन	• 721 किमी का मेट्रो रेल नेटवर्क चालू हो गया • 62.79 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और 6.21 लाख सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया
हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन	• 2.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण लक्ष्य के लिए 626.96 करोड़ रुपये
राष्ट्रीय जल मिशन	• ''जल शक्ति अभियान: कैच द रेन 2022''
जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन	• जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए और उन्हें मजबूत किया गया
हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन	• अंतर-विश्वविद्यालय संघ • 8 प्रमुख अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम शुरू किए गए
सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन	• जैविक खेती के तहत 0.15 लाख हेक्टेयर और सूक्ष्म सिंचाई के तहत 10 लाख हेक्टेयर को कवर करने वाले प्रमुख लक्ष्य

7.22 जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (एनएएफसीसी), एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 2015-16 में भारत के उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में अनुकूलन गतिविधियों का समर्थन करने के उदेश्य से शुरू किया गया था जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं। एनएएफसीसी को प्रोजेक्ट मोड में लागू किया गया है, और अब तक 27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 847.48 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यूएनएफसीसीसी अनुकूलन कार्रवाई का समर्थन करने के साथ-साथ, कृषि, जल, वानिकी, पशुधन, और पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करता है। वर्तमान में (नवंबर 2022), 28 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

7.23 अपनी जलवायु कार्रवाई में काफी अधिक महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन करते हुए, भारत सरकार ने दिनांक 26 अगस्त 2022 को अपना अद्यतन एनडीसी प्रस्तुत किया। संवर्धित लक्ष्यों वाला नया एनडीसी नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित यूएनएफसीसीसी पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी 26) में 'पंचामृत' के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्ति की गयी दृष्टिकोण को साकार करता है। इस दृष्टिकोण में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से प्रभावित गरीबों और कमजोर लोगों की रक्षा के लिए संधारणीय जीवन शैली और जलवायु न्याय का उल्लेख है । इस दृष्टिकोण के अनुरूप, समग्र क्षमता में समय के साथ गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता का हिस्सा तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2014-15 में बड़े जलविद्युत सहित, कुल संस्थापित बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 27.3 प्रतिशत की तुलना में (दिनांक 31.09.2022 को) लगभग 40.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। इस अवधि में सौर और पवन ऊर्जा में संस्थापित बिजली क्षमता के हिस्से में वर्ष 2014-15 के 8.9 प्रतिशत से वर्ष 2022-23 (अप्रैल-सितंबर) में 25.1 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।

बॉक्स VII.1: भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अद्यतन योगदान (एनडीसी)

भारत ने अपना पहला एनडीसी अक्टूबर 2015 में यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत किया। इसे अगस्त 2022 में अद्यतन किया गया था। वर्ष 2015 के एनडीसी में आठ लक्ष्य शामिल थे, इनमें से तीन वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य हैं। तीन लक्ष्यों में गैर-जीवाश्म स्रोतों से संचयी विद्युत ऊर्जा की संस्थापित क्षमता 40 प्रतिशत तक पहुँचना, वर्ष 2005 के स्तरों की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन की मात्रा में 33 से 35 प्रतिशत की कमी, और अतिरिक्त वन और वृक्षों के आच्छादन के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन सीओ2 (CO_2) के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना।

पेरिस समझौते के अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पार्टी हर पांच वर्ष में अपने एनडीसी को संप्रेषित या अद्यतन करेगा। इसलिए, पेरिस समझौते के पूर्वोक्त प्रावधान के अनुसार, भारत ने वर्ष 2015 के अपने पहले एनडीसी के लिए निम्नलिखित अद्यतन प्रस्तुत किए हैं।

1. जलवायु परिवर्तन का सामना करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में 'एलआईएफई (लाइफ)'-''पर्यावरण के लिए जीवन शैली'' के लिए एक जन आंदोलन के माध्यम से सहित, परंपराओं और संरक्षण और संयम के मूल्यों पर आधारित जीवन जीने के एक स्वस्थ और स्थायी तरीके को आगे बढ़ाने और इसे प्रचारित करना।
2. अब तक आर्थिक विकास के तदनुरूपी स्तर पर दूसरों द्वारा अपनाए गए पथ की तुलना में जलवायु-अनुकूल और स्वच्छ पथ को अपनाना।
3. वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन की मात्रा को 45 प्रतिशत तक कम करना।
4. ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) सहित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त की मदद से वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता प्राप्त करना।

5. वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आच्छादन के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 (कार्बन डाइ ऑक्साइड) के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना।
6. जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि, जल संसाधन, हिमालयी क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों, और स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन के विकास कार्यक्रमों में निवेश को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन हेतु बेहतर अनुकूलन करना।
7. आवश्यक संसाधन और संसाधन अंतराल को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त शमन और अनुकूलन कार्रवाईयों को लागू करने के लिए विकसित देशों से घरेलू और नई तथा अतिरिक्त धनराशि जुटाना।
8. भारत में अत्याधुनिक जलवायु प्रौद्योगिकी के त्वरित प्रसार के लिए और भविष्य की ऐसी प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त सहयोगी अनुसंधान एवं विकास की क्षमताओं का निर्माण और घरेलू ढांचा और अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला तैयार करना।

स्रोत: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

वन और वृक्ष आवरण की स्थिति

7.24 भारत के एनडीसी के तीन मात्रात्मक लक्ष्यों में से एक वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 बिलियन से 3.0 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक प्राप्त करना है। पिछले डेढ़ दशक में भारत में वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि की धीमी और स्थिर प्रवृत्ति देखी गई है।

7.25 वर्ष 2010 और 2020 के बीच की अवधि में औसत वार्षिक वन क्षेत्र की निवल वृद्धि के संबंध में देश का वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान है। इस वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के सुदृढ़ ढांचे और नीतियों को दिया जाता है जिन्होंने वनों को बढ़ावा दिया और उनकी रक्षा की। हरित भारत मिशन (जीआईएम), प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए), राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी), हरित राजमार्ग नीति - 2015, शहरी हरित क्षेत्र में वृद्धि के लिए नीति, राष्ट्रीय कृषि-वानिकी नीति और सब मिशन ऑन एग्रो-फॉरेस्ट्री (एसएमएएफ), आदि सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है।

भारत के वन और वृक्ष आवरण में कार्बन स्टॉक

7.26 मजबूत वन पारिस्थितिकी तंत्र कार्बन का एक महत्वपूर्ण सिंक है। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) ने वर्ष 2004 में पहली बार और वर्ष 2011 से द्विवार्षिक रूप में भारत के वनों में कार्बन स्टॉक (पर कार्बन की वह मात्रा है जो वायुमंडल से पृथक की जाती है और बायोमास, डेडवुड, मिट्टी और वन के कूड़े में संग्रहीत होती है) का आकलन किया। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (आईएसएफआर) का अनुमान है कि वर्ष 2019[7] में वनों और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग 7,204 मिलियन टन होगा, जो कि वर्ष 2017 में किये गये पिछले आकलन के अनुमानों की तुलना में 79.4 मिलियन टन कार्बन स्टॉक अधिक है। यह वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से निकले कार्बन उत्सर्जन की मात्रा 30.1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) के समतुल्य होने के लिए परिवर्तित होता है।

7 ISFR-2021. https://fsi.nic.in/forest-report-2021-details

चित्र VII.3: आईएसएफआर 2013 से आईएसएफआर 2021 तक कार्बन स्टॉक

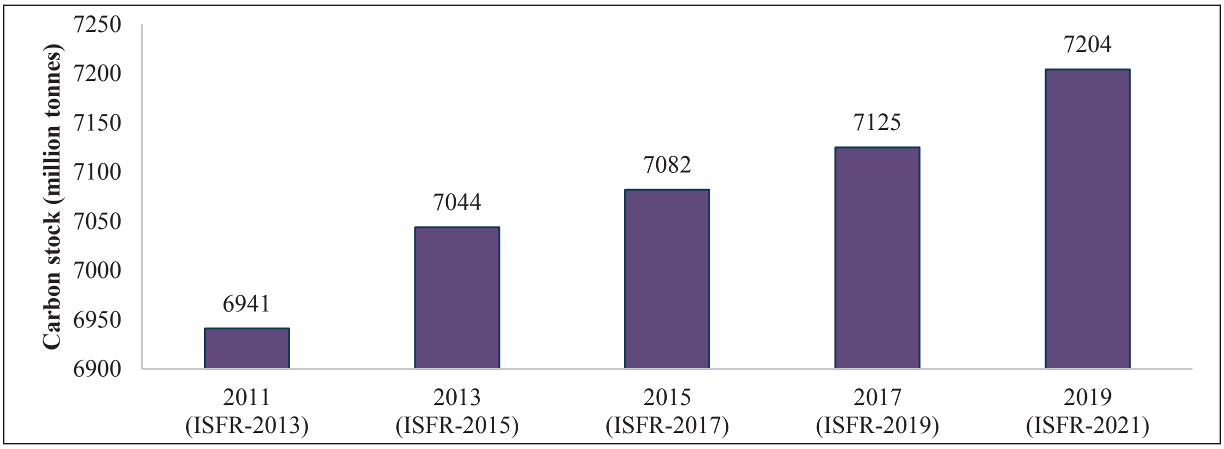

स्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित

7.27 भारतीय राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश के वनों में अधिकतम कार्बन स्टॉक (1023.84 मिलियन टन) है, इसके बाद मध्य प्रदेश (609.25 मिलियन टन) का स्थान है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर वन कार्बन स्टॉक यह निर्दिष्ट करता है कि जम्मू और कश्मीर 173.41 टन प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक का अधिकतम योगदान दे रहा है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश (167 टन), सिक्किम (166.24 टन) और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (162.89 टन) का स्थान है।

पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण: एक महत्वपूर्ण अनुकूलन क्रिया

7.28 पारिस्थितिक तंत्र कार्बन भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं, और सांस्कृतिक, आध्यात्मिक या पर्यटक आकर्षण जैसी अन्य सेवाओं के अलावा पानी की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। आर्द्रभूमि बाढ़, सूखे और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विरुद्ध प्राकृतिक कर हैं। आर्द्रभूमि (वेटलैंड्स) स्पंज के रूप में कार्य कर सकती हैं जो भारी वर्षा के दौरान जलसंचयन कर सकते हैं और शुष्क मौसम में धीरे-धीरे पानी छोड़ सकते हैं। सितंबर 2014 में कश्मीर घाटी और दिसंबर 2015 में चेन्नई शहर में आई बाढ़ इस बात की याद दिलाती है कि आर्द्रभूमि का विनाश किस तरह हमारे जीवन को असुरक्षित बना सकता है। दिनांक 2 फरवरी, 1971 को हस्ताक्षरित रामसर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपने आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक विशेषता को संरक्षित करने के उद्देश्य से सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित सबसे पुराने अंतर-सरकारी समझौतों में से एक है। रामसर स्थलों के रूप में घोषित आर्द्रभूमि (वेटलैंड्स) संरक्षित हैं। भारत में 75 रामसर स्थल हैं जो 13.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित हैं, और इनमें से 49 स्थलों को पिछले 8 वर्षों में जोड़ा गया है।

7.29 मैंग्रोव तटीय आर्द्रभूमि हैं और यह बढ़ते तूफान, बाढ़ और तूफान के विरुद्ध तटीय समुदायों के लिए रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करती है। हाल के एक अध्ययन के अनुसार, वर्षा और समुद्र के स्तर में परिवर्तन8 होने से उपयुक्त आवासों में गिरावट के कारण पूर्वी तट के साथ चिल्का और सुंदरवन और भारत के पश्चिमी तट के साथ द्वारका और पोरबंदर में कुछ मैंग्रोव प्रजातियों के वर्ष 2070 तक कम होने और भूमि की ओर स्थानांतरित होने की संभावना है।[8]

7.30 सरकार ने मैंग्रोव की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विनियामक और प्रचारात्मक दोनों उपाय किए हैं। मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और प्रबंधन पर राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; के तहत तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना (2019) के

8 Pujarini Samal, Jyoti Srivastava, S.R. Singarasubramanian, Pooja Nitin Saraf, Bipin Charles, Ensemble modeling approach to predict the past and future climate suitability for two mangrove species along the coastal wetlands of peninsular India, Ecological Informatics, Volume 72, 2022. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2022.101819.

वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972; भारतीय वन अधिनियम, 1927; जैविक विविधता अधिनियम, 2002; और समय-समय पर संशोधित इन अधिनियमों के तहत बनाये गये नियम के माध्यम से विनियामक उपायों को लागू किया गया है। आईएसएफआर 2021 के अनुसार, वर्ष 2013 की तुलना में 2021 में देश में मैंग्रोव कवर में 364 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है।

चित्र VII.4: भारत में मैंग्रोव आवरण (वर्ग किमी)

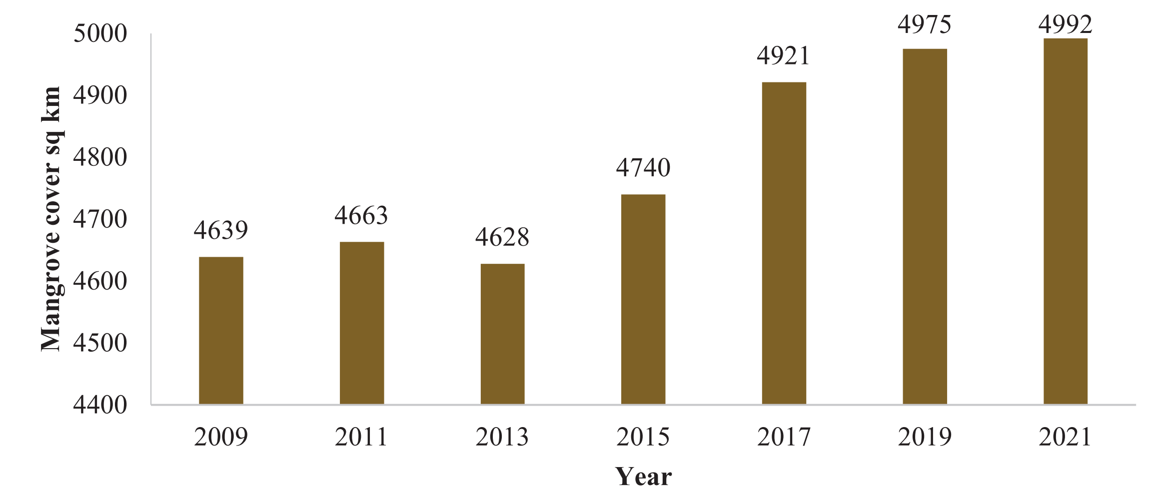

स्रोत: आईएसएफआर 2021

नदी संरक्षण और कायाकल्प

7.31 सरकार 5पी' - लोग, नीति, योजना, कार्यक्रम और परियोजना की मैपिंग और अभिसरण पर काम कर रही है। यह गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के लिए नमामि गंगे की केंद्रीय क्षेत्र योजना और अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से देश में नदियों के चिन्हित प्रदूषित हिस्सों में प्रदूषण को कम करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के प्रयासों का पूरक रहा है।

7.32 इसके अलावा, सरकार ने हाल ही में राज्य के वन विभागों और अन्य लाइन विभागों के परामर्श से भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), देहरादून द्वारा तैयार की गई 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जारी की है। इन डीपीआर के तहत प्रस्तावित कार्यों में नदी के किनारों पर वनीकरण, जिससे हरित आवरण में वृद्धि, मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय, भूजल तालिका का ुनर्भरण, सीवेस्टर कार्बन डाइऑक्साइड, जलग्रहण क्षेत्र उपचार, पारिस्थितिक बहाली, नमी संरक्षण, आजीविका सुधार और आय सृजन आदि शामिल हैं।

अक्षय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण के लिए दृष्टिकोण

7.33 वर्ष 2015 में प्रस्तुत प्रारंभिक एनडीसी में वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से संस्थापित विद्युत क्षमता का 40 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य था, इस लक्ष्य को पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। भारत अब अद्यतन एनडीसी के अनुरूप, वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50 प्रतिशत संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।

चित्र VII.5: गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित क्षमता के बढ़ते हिस्से के साथ संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि

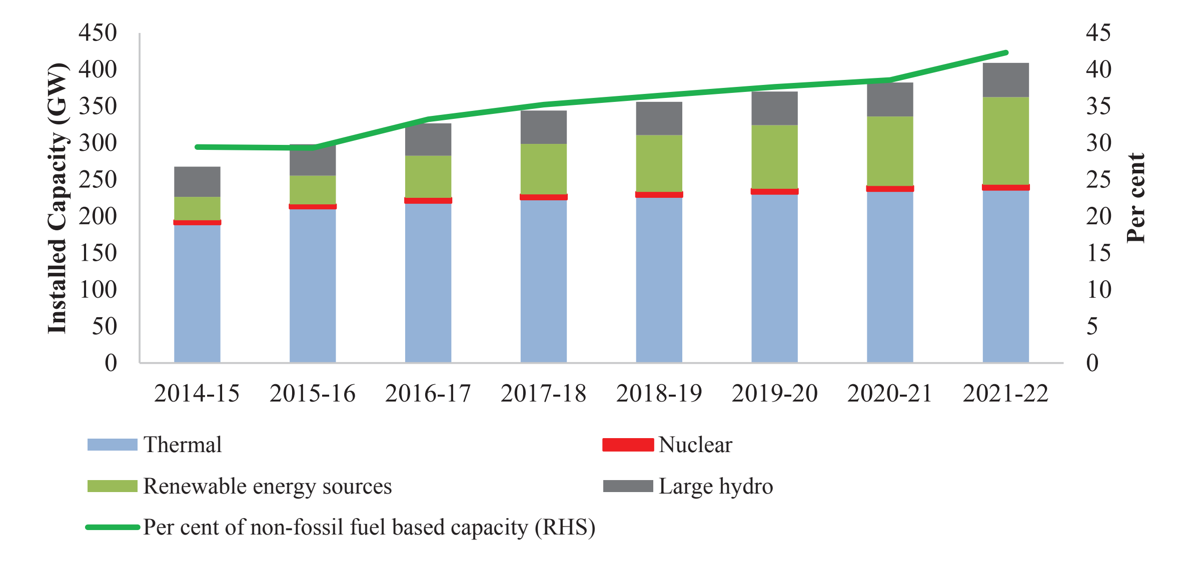

स्रोत: विद्युत मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित।

7.34 भारत धीरे-धीरे नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है। रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014 -2021 की अवधि में, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में कुल निवेश 78.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। विभिन्न कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण वर्ष 2020 में आयी गिरावट को छोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश वर्ष 2016 से प्रति वर्ष 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब या उससे अधिक रहा है।

चित्र VII.6: 2014 से भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश

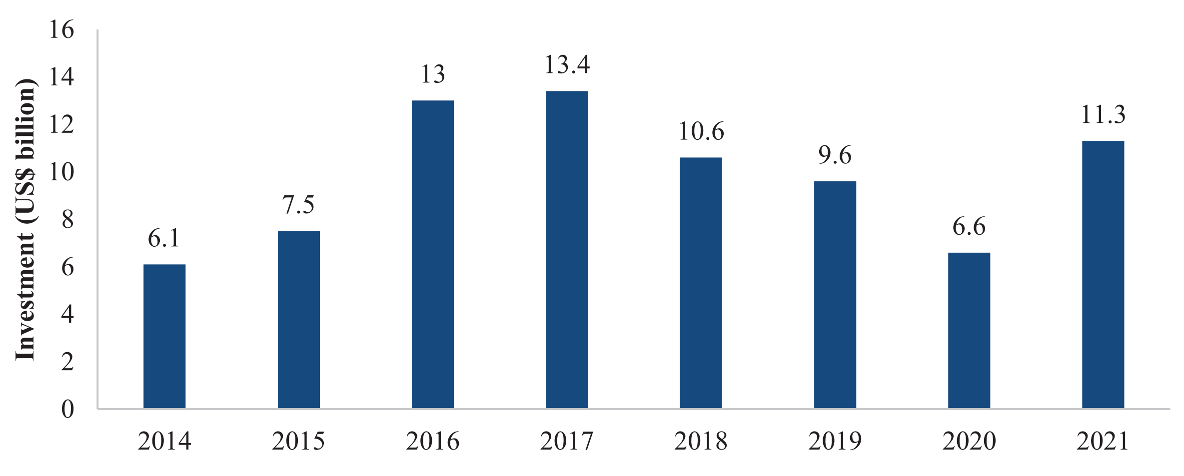

स्रोत: आरईएन 21. नवीकरणीय 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट

7.35 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2029-30 के लिए अत्यधिक बिजली की मांग और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इष्टतम उत्पादन क्षमता मिश्रण का अनुमान लगाया है। बेहतर दक्षता का अनुमान है और विभिन्न तकनीकी/वित्तीय बाधाओं में कुल प्रणाली लागत को कम करता है। वर्ष 2029-30 के अंत तक संभावित संस्थापित क्षमता 800 गीगावाट से अधिक होने की उम्मीद है, जिसमें से गैर-जीवाश्म ईंधन 500 गीगावाट से अधिक होगा।

चित्र VII.7: वर्ष 2029-30 के लिए संस्थापित क्षमता का इष्टतम मिश्रण

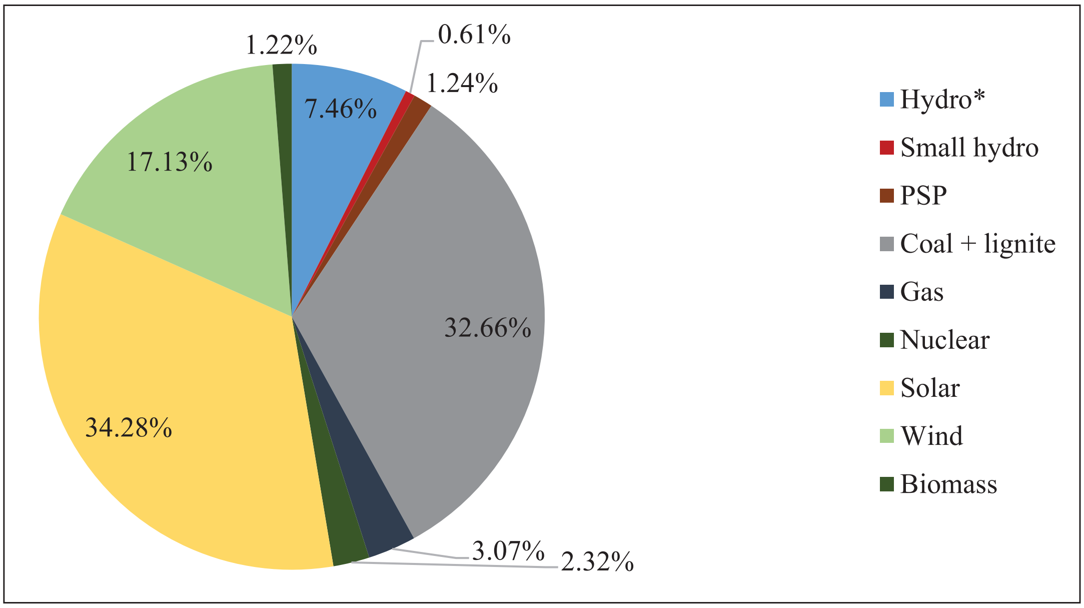

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

7.36 इसके अलावा, सीईए ने यह भी अनुमान लगाया है कि वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2029-30 तक औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29 प्रतिशत की गिरावट आएगी।

चित्र VII.8: गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित संस्थापित क्षमता में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण प्रति किलोवाट घंटे बिजली के अनुसार औसत कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), उत्सर्जन दर की अनुमानित गिरावट।

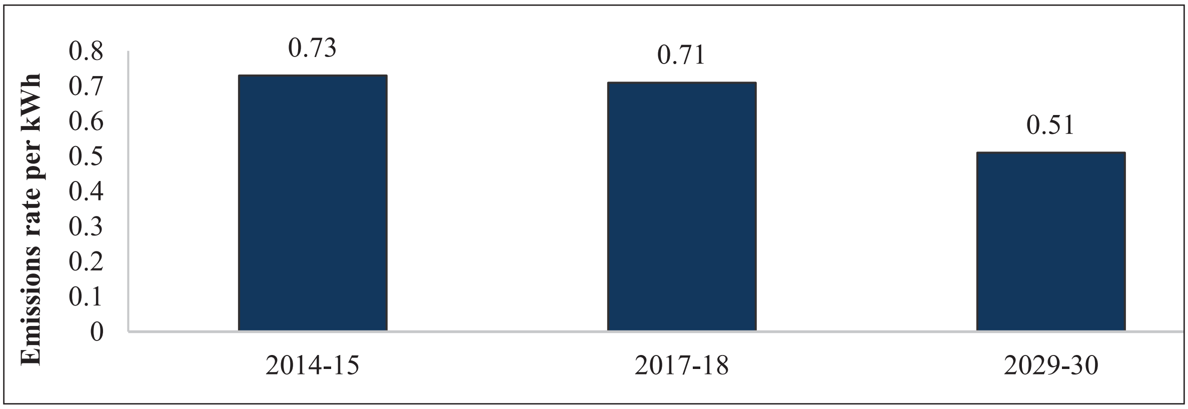

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों पर आधारित

ग्रीन हाइड्रोजन-वैकल्पिक ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत

7.37 हरित हाइड्रोजन पर उभरती वैश्विक गति से, भारत इस डीकार्बोनाइजेशन अवसर को न केवल कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, बल्कि देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के एक प्रबल समर्थक के रूप में भी स्थापित कर सकता है। यह उर्वरक, रिफाइनिंग, मेथनॉल, समुद्री नौवहन, लोहा और इस्पात और लॉग हॉल परिवहन जैसे कठिन-से-कम क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। हरित हाइड्रोजन भारत की दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति (एलटी-एलईडीएस) का भी एक महत्वपूर्ण तत्व है।

7.38 भारत को एक ऊर्जा-स्वतंत्र राष्ट्र महत्वपूर्ण क्षेत्रों को डीकार्बोनाइन करने की दृष्टि से, सरकार ने 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय वाले राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। मिशन 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की मांग निर्माण, उत्पादन, उपयोग और निर्यात की सुविधा देगा और 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जुटाएगा।

चित्र VII.9: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मुख्य विशेषताएं।

वर्ष 2030 तथा संभावित परिणणम	• प्रति वर्ष कम से कम 5 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता। • जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ से अधिक की संचयी कमी और 6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन। • अक्षय ऊर्जा की क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि और वार्षिक जीएचजी के उत्सर्जन में लगभग 50 एमएमटी की कमी।
हस्तक्षेप	• इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को लक्षित वित्तीय प्रोत्साहन। • हाइड्रोजन के बड़े पैमाने पर उत्पादन और/या उपयोग में सहायता करने में सक्षम क्षेत्रों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाना है।
नीतिगत ढांचा	• ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना का समर्थन करने के लिए एक सक्षम नीतिगत ढांचे का विकास। • मजबूत मानक और विनियम ढांचा। • अनुसंधान एवं विकास (आर-डी) के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी ढांचा। • कौशल विकास कार्यक्रम

स्रोत: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

7.39 जून 2022 में प्रकाशित नीति आयोग[9] की एक रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि भारत में, हाल के वर्षों में नवीकरणीय टैरिफ में गिरावट आई है, और भविष्य में इलेक्ट्रोलाइजर की लागत में गिरावट आने की उम्मीद की गयी है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (2020)[10] की एक हालिया रिपोर्ट के से यह सुझाव दिया गया है कि हरित हाइड्रोजन को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर की लागत महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट में इलेक्ट्रोलाइजर प्रौद्योगिकी में नवाचार के महत्व और इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन की तीव्र वृद्धि को मुख्य कारकों के रूप में रेखांकित किया गया है जो इलेक्ट्रोलाइजर और हरित हाइड्रोजन की लागत को कम करेगा।

7.40 नीति की रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत में हरित हाइड्रोजन बाजार का संचयी मूल्य वर्ष 2030 तक 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2050 तक 340 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइजर का बाजार वर्ष 2030 तक लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2050 तक 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। इसके अलावा, हरित हाइड्रोजन को अपनाने से वर्ष 2050 तक संचयी कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) के उत्सर्जन में 3.6 गीगा टन की कमी आएगी। इससे भारी ऊर्जा के आयात में बचत भी होगी, उद्योग इनपुट कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित होगी, और दीर्घकाल में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां मजबूत होंगी।

9 'Harnessing Green Hydrogen – Opportunities for Deep Decarbonisation in India', published in June 2022 by NITI Aayog. https://www.niti.gov.in/sites/default/files/202206/Harnessing_Green_Hydrogen_V21_DIGITAL_29062022.pdf

10 International Renewable Energy Agency (IRENA) (2020) Green hydrogen cost reduction: Scaling up electrolysers to meet the 1.5^{0}C Climate Goal. Green hydrogen cost reduction (irena.org)

चित्र VII.10: हरे और भूरे हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन की स्तरीकृत लागत (एलसीओएच[11])

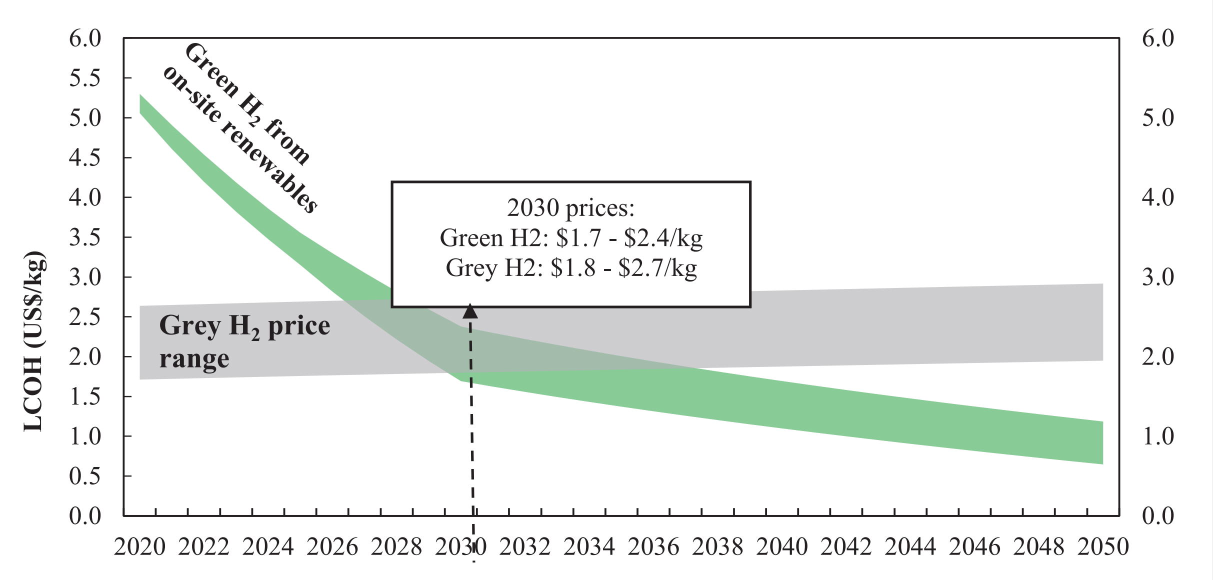

स्रोत: नीति आयोग

7.41 हालांकि, यह सब इस अनुमान पर आधारित है कि उचित लागत वाली अक्षय ऊर्जा के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच जारी रहेगी–जो कुछ देशों तक पहुंच में एकाधिकार वाले कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में इन खनिजों की सघनता के सामने प्रभावी बाधा हो सकती है।

बॉक्स VII.2: महत्वपूर्ण खनिज-हरित परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक

महत्वपूर्ण खनिजों का आवश्यकताओं में भारी वृद्धि के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली में बदलाव निर्धारित है। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित ऊर्जा प्रणाली पारंपरिक हाइड्रोकार्बन संसाधनों द्वारा संचालित प्रणाली से बहुत अलग होने के कारण ऐसा है। कोबाल्ट, तांबा, लिथियम, निकल और दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई) बिजली के वाहनों और बैटरी के उत्पादन और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) संयंत्रों, पवन फार्मों और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को आम तौर पर उनके जीवाश्म ईंधन आधारित प्रतिरूपों की तुलना में अधिक खनिजों की आवश्यकता होती है। एक पारंपरिक कार की तुलना में विशिष्ट इलेक्ट्रिक कार को छह गुना खनिज इनपुट की आवश्यकता होती है, और एक तटवर्ती पवन संयंत्र को गैस से चलने वाले संयंत्र की तुलना में नौ गुना अधिक खनिज संसाधनों की आवश्यकता होती है।[12]

उपयोग किए जाने वाले खनिज संसाधनों के प्रकार प्रौद्योगिकी के अनुसार भिन्न होते हैं। बैटरी की कार्यक्षमता, टिकाऊ और ऊर्जा घनत्व के लिए लिथियम, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज और ग्रेफाइट जैसे धातुएं महत्वपूर्ण हैं। दुर्लभ मृदा तत्व स्थायी चुम्बकों के लिए आवश्यक हैं जो पवन टर्बाइनों और ईवी मोटर्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। बिजली नेटवर्क को बड़ी मात्रा में तांबे और एल्यूमीनियम की आवश्यकता होती है, जिसमें बिजली से संबंधित सभी प्रौद्योगिकियों के लिए तांबा आधारशिला है।

भौगोलिक रूप से, चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया में प्रचुर मात्रा में खजिन उपलब्ध है। खनिज इसके साथ साथ पेरू, चिली, ब्राजील, मैक्सिको, अफ्रीकी देशों कांगो और क्यूबा जैसे दक्षिण अमेरिकी देशों में कुछ खनिजों की उच्च सांद्रता है। यहां तक कि इंडोनेशिया और वियतनाम के एशियाई देश क्रमश: तांबा और दुर्लभ मृदा तत्वों का भंडार है।

11 LCOH refers to the cost of hydrogen production per unit of hydrogen includind capital and operational costs.

12 International Energy Agency Report on 'The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions'. The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions – Analysis - IEA

चित्र VII.11: वर्ष 2019 और 2025 में चयनित खनिजों के उत्पादन का संकेन्द्रण

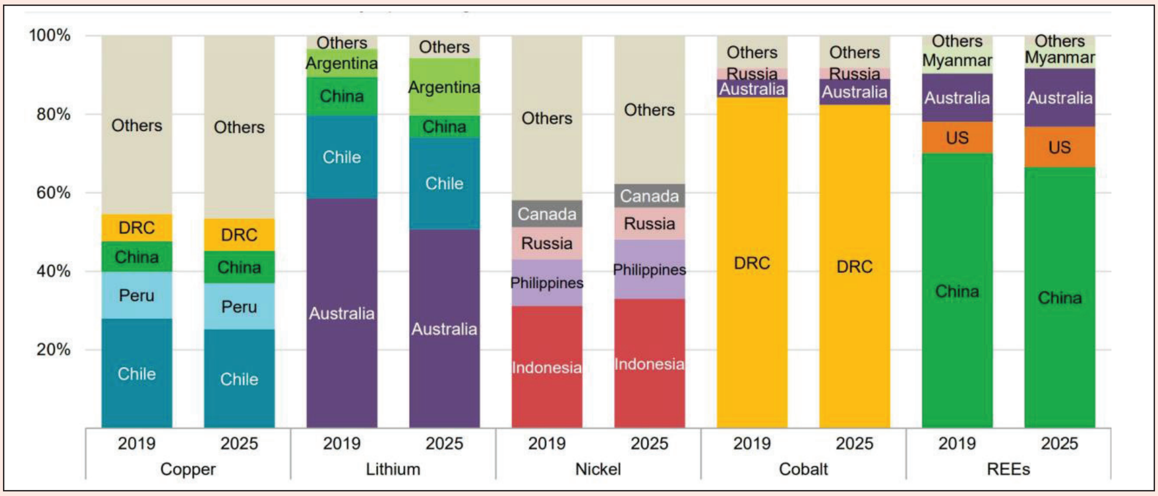

स्रोत: 'स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में महत्वपूर्ण खनिजों की भूमिका' पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट

हालांकि भारत जैसे विकासशील देश के लिए महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर मौजूदा भू-राजनीति चिंता का विषय है, सावधानीपूर्वक तैयार की गई बहु-आयामी खनिज नीति हमारी निर्भरता को कम करेगी और भविष्य की समस्याओं का समाधान करेगी। देश में निकल, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और भारी दुर्लभ मृदा तत्वों के संसाधन हैं, लेकिन उनके भंडार की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए और खोज की आवश्यकता होगी। खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों की तर्ज पर सामरिक खनिज भंडार बनाने की आवश्यकता है। साथ ही, नीतियों को खनिज आपूर्ति श्रृंखला के लिए आंतरिक अनुसंधान और विकास में निवेश करने पर विचार करना चाहिए। इसमें खनिज अन्वेषण और प्रसंस्करण के लिए तकनीकी नवाचार और खनिजों के लिए पुनर्चक्रण, पुनप्रयोग और पुन: प्रयोजन (आर3) प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल है।

राष्ट्र की खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण तथा रणनीतिक खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, खान मंत्रालय ने नाल्को, एचसीएल और एमईसीएल के सहभागी हितों के साथ खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल) नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है। काबिल (केएबीआईएल) को लिथियम, कोबाल्ट आदि जैसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रकृति की विदेशी खनिज संपत्तियों की पहचान और अधिग्रहण करने के लिए अधिदेशित किया गया है। इसके अलावा, खान मंत्रालय, भारत सरकार और उद्योग, विज्ञान, ऊर्जा और संसाधन विभाग (डीआईएसईआर), ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दिनांक 3 जून 2020 को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के खनन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, काबिल (केएबीआईएल) ने 10 मार्च 2022 को डीआईएसईआर के तहत महत्वपूर्ण खनिज सुविधा कार्यालय से मिलकर सहयोगी ढांचे वाले विस्तृत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि अंतिम संयुक्त निवेश निर्णयों के लिए लिथियम और कोबाल्ट खनिज संपत्ति की पहचान की जा सके और दोनों देशों के महत्वपूर्ण और रणनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र की पूर्ति के लिए ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सके।

दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति (एलटी-एलईडीएस)

7.42 भारत ने दिनांक 4 नवंबर, 2022 को सीओपी27 में अपनी दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति (एलटी-एलईडीएस) प्रस्तुत की है। एलटी-एलईडीएस की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग पर ध्यान देना। जीवाश्म ईंधन से होने वाले संक्रमण से न्यायसंगत, सुचारू रूप से, संधारणीय और सर्व-समावेशी तरीके से किया जाएगा।

- राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति के उद्देश्यों को शामिल किया गया है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन का तेजी से विस्तार, देश में इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता में वृद्धि, और वर्ष 2032 तक परमाणु क्षमता में तीन गुना वृद्धि कुछ अन्य मील के पत्थर हैं जिनकी परिकल्पना बिजली क्षेत्र के समग्र विकास के साथ की गई है।
- जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि, विशेष रूप से पेट्रोल में इथेनॉल का सम्मिश्रण। इलेक्ट्रिक वाहन में पैठ बढ़ाने के लिए अभियान, और हरित हाइड्रोजन ईंधन के बढ़ते उपयोग से परिवहन क्षेत्र से कम कार्बन विकास को बढ़ावा मिलने की अपेक्षा की जाती है। भारत वर्ष 2025-26 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अधिकतम करने, इथेनॉल सम्मिश्रण को 20 प्रतिशत तक पहुंचाने और यात्रियों और माल ढुलाई के लिए सार्वजनिक परिवहन में एक सशक्त मोडल लाना चाहता है।
- जलवायु के अनुकूल शहरी विकास को स्मार्ट सिटी संबंधी पहलों, मुख्यधारा के अनुकूलन के लिए शहरों की एकीकृत योजना और ऊर्जा तथा और संसाधन क्षमता में वृद्धि, प्रभावी ग्रीन बिल्डिंग कोड और नवीन ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विकास द्वारा संचालित किया जाएगा।
- आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' के दृष्टिकोण से भारत का औद्योगिक क्षेत्र एक मजबूत विकास पथ पर अग्रसर रहेगा।

7.43 एलटी-एलईडीएस वैश्विक कार्बन बजट के एक समान और उचित हिस्से के लिए भारत के अधिकार के ढांचे में तैयार किया गया है और यह 'जलवायु न्याय' के लिए भारत के आह्वान का व्यावहारिक कार्यान्वयन है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए तीव्र विकास और आर्थिक परिवर्तन से भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में कोई बाधा न हो। एलटी-एलईडीएस, एलआईएफई लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के विजन से प्रेरित है, जिसमे नासमझ और विनाशकारी खपत से सचेत होकर और जानबूझकर उपयोग करने के लिए दुनिया भर में प्रतिमान बदलाव की मांग करता है। यहां, निम्न कार्बन विकास पथ में परिवर्तन के लिए लागत की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त के लिए प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसलिए, अनुदान और रियायती ऋण के रूप में काफी वृद्धि करने की आवश्यकता है।

संधारणीय विकास के लिए वित्त

7.44 भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाईयों में वित्त एक महत्वपूर्ण इनपुट है। देश की जलवायु कार्रवाइयों को बड़े पैमाने पर अब तक घरेलू स्रोतों से वित्तपोषित किया गया है, जिसमें सरकारी बजटीय सहायता, बाजार तंत्र का परस्पर संसर्ग, वित्तीय साधन और नीतिगत हस्तक्षेप शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन के विरूद्ध लड़ाई में भारत ने वैश्विक नेतृत्व का परिचय दिया है और स्वयं को वर्ष 2070 तक निवल-शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। जबकि भारत द्वारा तैयार एलटी-एलईडीएस रिपोर्ट में आवश्यक निवेश के कई अनुमानों का संकेत दिया गया है, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सभी में दसियों ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता की ओर संकेत देते हैं।

7.45 सम्मेलन और पेरिस समझौते का अभिप्राय यह है कि विकसित देश उचित लागत पर वित्तीय संसाधनों के प्रवाह को सक्षम करने के लिए निजी वित्त को उत्प्रेरित बनाने सहित सार्वजनिक और अन्य स्रोतों के माध्यम से संसाधन जुटाएंगे। जबकि ये अभी तक अमल में नहीं आए हैं, भारत ने अपने महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निजी पूंजी को अधिक से अधिक जुटाने की दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाया है।

ग्रीन बॉन्ड्स

7.46 ग्रीन बांड एक वित्तीय लिखत हैं, जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से संधारणीय और जलवायु-उपयुक्त परियोजनाओं में निवेश करने हेतु आय जनरेट करते हैं। परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्थिरता पर बढ़ते ध्यान

से, ग्रीन बांड व्यापक रूप से जलवायु और पर्यावरणीय परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए धन जुटाने के उदेश्य से एक लिखत के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और नियमित बांडों की तुलना में पूंजी की अपेक्षाकृत कम लागत पर नियंत्रण रखते हैं। धन जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड का सहारा लेने वाले प्रमुख देशों में यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए और चीन शामिल हैं। आईएमएफ डेटा पर इंगित करता है कि वर्ष 2021 में दुनिया भर में लगभग 620 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के ग्रीन बांड जारी किए गए थे, जिसमें देशों ने 587.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के ग्रीन बांड जारी किए और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने 32.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के बांड जारी किए। हरी ऋण प्रतिभूतियां को लेकर के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 से सितंबर 2022 की अवधि के दौरान, 15 भारतीय कॉरपोरेट्स ने 4,539 करोड़ रू. मूल्य के ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। इनमें से अधिकांश अक्षय ऊर्जा उत्पादन से संबंधित हैं, जबकि इनमें से एक का उपयोग अपशिष्ट जल के तृतीयक उपचार के लिए किया जाना है।

चित्र VII.12: वर्ष 2021 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करना

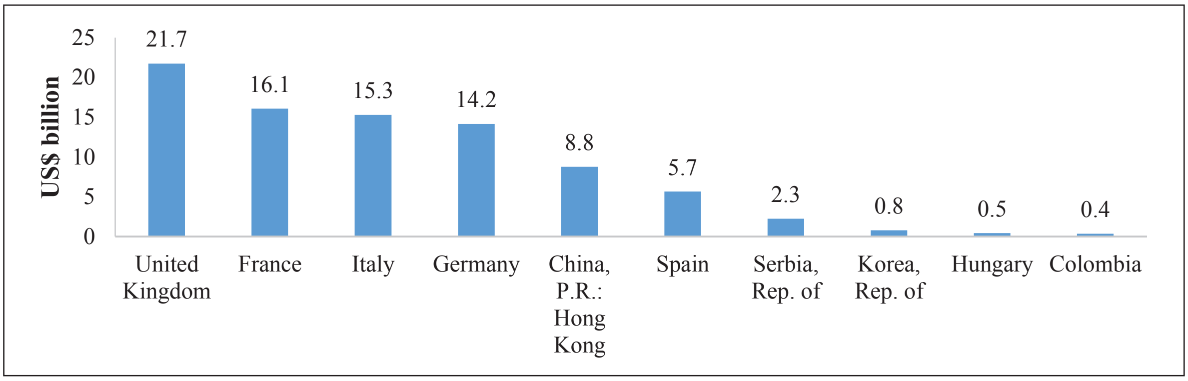

स्रोत: आईएमएफ जलवायु परिवर्तन डैशबोर्ड

7.47 अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को उल्लेखनीय रूप से कम करने की महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय बजट 2022-23 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने से सरकार को अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में परिनियोजन के लिए संभावित निवेशकों से अपेक्षित वित्त प्राप्त करने में मदद मिलेगी। भारत का अंतिम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ढांचा जारी कर दिया गया है। इस फ्रेमवर्क को अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ (आईसीएमए) के ग्रीन बॉन्ड सिद्धांतों (2021) के घटकों और प्रमुख सिफारिशों के अनुपालन के लिए डिजाइन किया गया है।

7.48 सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने के प्रमुख निर्णयों की देखरेख और इसका सत्यापन करने के लिए एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया है। आय के आवंटन के लिए समिति को परियोजनाओं का चयन करने, आवंटन की समयबद्ध समीक्षा करने और जारी किए गए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त आय के प्रभाव के आकलन के साथ-साथ वार्षिक रिपोर्टिंग करने का अधिकार है।

हरित ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए विनियामक ढांचा

7.49 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) जारी करने के लिए सांकेतिक कैलेंडर अधिसूचित किया है। यह निर्गमन प्रत्येक 8,000 करोड़ रुपये में, कुल 16,000 करोड़ रुपये के लिए क्रमश: दिनांक 25 जनवरी 2023 और 9 फरवरी 2023 को दो नीलामी के माध्यम से होगा। सुरक्षा-वार आवंटन में दोनों नीलामियों के लिए 4,000 करोड़ रुपये के 5 साल और 10 साल के एसजीआरबी शामिल होंगे। बिक्री की अधिसूचित राशि का पांच प्रतिशत खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित किया गया है, जैसा कि 'भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूति और ट्रेजरी बिलों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली

सुविधा के लिए योजना' के तहत निर्दिष्ट है। एसजीआरबी को अनिवासियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए 'पूरी तरह से सुलभ मार्ग' के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के रूप में नामित किया जाएगा। समय के साथ, एसजीआरबी पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) बांड के माध्यम से भारत में निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए उनके घरेलू उधार के लिए एक मूल्य निर्धारण संदर्भ प्रदान करेगा। इस प्रकार, एसजीआरबी जारी करने से एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद मिलेगी जो हरित परियोजनाओं और ऐसी परियोजनाओं को चलाने वाली संस्थाओं में पूंजी के अधिक प्रवाह को बढ़ावा देता है।

ग्रीन ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए विनियामक ढांचा

7.50. दिनांक 3 नवंबर, 2021 को, आरबीआई ने अपना 'स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू सपोर्ट ग्रीनिंग इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम' - एनजीएफएस प्रकाशित किया। यहां, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं, प्राथमिकताओं और हमारी वित्तीय प्रणाली की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध है कि जलवायु परिदृश्य अभ्यास का उपयोग, आरबीआई-पर्यवेक्षित संस्थाओं के तुलन-पत्र में कमजोरियों की पहचान करने के लिए, व्यापार मॉडल और जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों का आकलन करने और इसे प्रबंधित करने के लिए कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा, वर्ष 2007 में, आरबीआई ने बैंकों को सतत विकास में सार्थक योगदान देने के लिए एक उचित कार्य योजना बनाने की सलाह दी। समय के साथ, आरबीआई ने हरित उद्योगों और परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण देने को प्रोत्साहित किया है। उदाहरण के लिए, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) के तहत शामिल किया गया है। आरबीआई अपने प्रकाशनों और अन्य संचार के माध्यम से हरित वित्त के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करके हरित और स्थायी वित्त के मुद्दे पर जागरूकता फैला रहा है।

7.51 सेबी ने दिनांक 30 मई, 2017 के परिपत्र द्वारा पूर्ववर्ती सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण) विनियम, 2008, (आईएलडीएस विनियम) के तहत स्थायी वित्त के तरीके के रूप में हरित ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए विनियामक ढांचा शुरू किया।

7.52 आईएलडीएस विनियमों की समीक्षा करते समय, पूर्ववर्ती परिपत्र के प्रावधानों को शामिल किया गया था, और ''हरित ऋण प्रतिभूति'' की परिभाषा को सेबी (निर्गम और गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की सूची) विनियम, 2021 ('एनसीएस विनियम') में विनियम 2(1)(क्यू) के रूप में शामिल किया गया था। दिनांक 10 अगस्त, 2021 के परिचालन परिपत्र द्वारा प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया था।

7.53 हाल ही में, दिनांक 24 नवंबर, 2022 के एक परिपत्र के माध्यम से, सेबी ने एक जारीकर्ता को सेबी (मुनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण) विनियम, 2015 ('आईएलएमडीएस विनियम') के तहत एक ग्रीन ऋण सुरक्षा जारी करने की अनुमति दी है, यदि यह एनसीएस विनियम के विनियम 2(1)(q) के अनुसार ''हरित ऋण सुरक्षा'' ''हरित ऋण सुरक्षा'' परिभाषा के अंतर्गत आता है। ऐसे जारीकर्ता को 'आईएलएमडीएस विनियम और एनसीएस विनियम' दोनों का अनुपालन करना होगा।

7.54 भारत के साथ-साथ दुनिया भर में संधारणीय वित्त में बढ़ती रुचि की पृष्ठभूमि में, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ), सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त अद्यतन ग्रीन बॉन्ड सिद्धांतों के साथ ग्रीन ऋण प्रतिभूतियों के लिए मौजूदा ढांचे को संरेखित करने की दृष्टि से हरित ऋण प्रतिभूतियों के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा की। समीक्षा के आधार पर, दिनांक 20 दिसंबर, 2022 को सेबी बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि:

(क) प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, पर्यावरण-कुशल उत्पादों, आदि के संबंध में संधारणीय वित्त के नए तरीकों को शामिल करके हरित ऋण प्रतिभूति की परिभाषा के क्षेत्र को बढ़ाना;

(ख) ब्लू बॉन्ड (जल प्रबंधन और समुद्री क्षेत्र से संबंधित), येलो बॉन्ड (सौर ऊर्जा से संबंधित) और ट्रांजिशन बॉन्ड की अवधारणा को हरित ऋण प्रतिभूतियों की उपश्रेणियों के रूप में शुरू करना।

संधारणीय विकास के लिए लचीलापन में निवेश

7.55 सेबी सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए संधारमीमता संबंधी की शुरूआत करने वालों में से एक रहा है और वर्ष 2012 से शीर्ष 100 सूचीबद्ध संस्थाओं (बाजार पूंजीकरण द्वारा) के लिए अनिवार्य ईएसजी-संबंधित खुलासे की आवश्यकता है। प्रारंभ में वर्षों से, शीर्ष 500 संस्थाओं और फिर शीर्ष 1000 संस्थाओं शामिल को सुदृढ किया गया। सेबी ने बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट (बीआरएसआर) के तहत नई सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आवश्यकताएं जारी की हैं, जो 'जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश' में निहित सिद्धांतों के अनुरूप मात्रात्मक मेट्रिक्स के साथ अधिक सूक्ष्म हैं। वर्ष 2022-23 से शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं (बाजार पूंजीकरण द्वारा) के लिए बीआरएसआर अनिवार्य कर दिया गया था। प्रारंभिक शोधों से पता चलता है कि शीर्ष भारतीय फर्मों के लिए, ईएसजी प्रदर्शन ने कोविड-19[13] के दौरान स्टॉक रिटर्न की अस्थिरता को कम कर दिया और निवेशकों में विश्वास पैदा करके कम लागत पर पूंजी तक पहुंचने में सक्षम फर्मों को सक्षम किया क्योंकि ईएसजी के खुलासे निवेशकों के लिए दीर्घकालिक साख बनती है और साथ ही इससे सूचना विषमता को कम होती है।[14]

सीओपी-27 में लिए गये प्रमुख निर्णय

7.56 यूएनएफसीसीसी के लिए सीओपी27 का आयोजन दिनांक 6 से 20 नवंबर 2022 तक शर्म अल-शेख, मिस्र में किया गया। सीओपी27 के साथ, क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की बैठक के रूप में कार्य कर रही पार्टियों के सम्मेलन का 17वां सत्र (सीएमपी17), पेरिस समझौते के पक्षकारों की बैठक (सीएमए4) के रूप में सेवारत पार्टियों के सम्मेलन का चौथा सत्र, वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह के लिए सहायक निकाय (एसबीएसटीए) और कार्यान्वयन के लिए सहायक निकाय (एसबीआई) का 57वां सत्र भी आयोजित किया गया।

7.57 भारत ने, एलआईएफई-लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की थीम को मुख्यधारा में लाने पर ध्यान सीओपी27 में भाग लिया देने के लिए केंद्रित किया गया। सीओपी27 में भारतीय पवेलियन ने विभिन्न तरीकों - मॉडल, ऑडियो-विजुअल डिस्प्ले, गतिविधियाँ और 49 साइड इवेंट से एलआईएफई की थीम पर प्रकाश डाला। भारत ने सभी देशों को एलआईएफई मूवमेंट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जो एक जन-समर्थक और ग्रह-समर्थक प्रयास है, जो दुनिया को नासमझ और बेकार की खपत से प्राकृतिक संसाधनों के सचेत और जानबूझकर उपयोग करने के लिए स्थानांतरित करने का प्रयास करता है।

7.58 शर्म अल-शेख कार्यान्वयन योजना शीर्षक वाले सीओपी27 का कवर निर्णय, 'जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के प्रयासों के लिए स्थायी जीवन शैली और खपत और उत्पादन के स्थायी पैटर्न' के लिए संक्रमण के महत्व को लेकर है। अन्य निर्णयों में न्यायोचित संक्रमण और शमन कार्य कार्यक्रम की स्थापना और कृषि तथा खाद्य सुरक्षा पर चार वर्षों में आयोजित होने वाली जलवायु कार्रवाई के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त कार्य समझौता था।

7.59 सीओपी27 के दौरान, विकासशील देशों ने हानि और क्षति के लिए एक अलग कोष स्थापित करने की जोरदार आवाज उठाई। बातचीत के बाद, नुकसान और क्षति को संबोधित करने पर ध्यान देने के साथ, नुकसान और क्षति के जवाब में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के लिए विशेष रूप से कमजोर विकासशील देशों

13 Beloskar, V. D., & Rao, S. V. D. (2022). Did ESG Save the Day? Evidence from India During the Covid-19 Crisis. Asia-Pacific Financial Markets, 1-35.

14 Mulchandani, K., Mulchandani, K., Iyer, G., & Lonare, A. (2022). Do Equity Investors Care about Environment, Social and Governance (ESG) Disclosure Performance? Evidence from India. Global Business Review, 23(6), 1336-1352.

की सहायता के लिए नई धन व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इन तौर-तरीकों पर काम करने के लिए एक संक्रमणकालीन समिति का गठन किया गया है।

7.60 शर्म अल-शेख कार्यान्वयन योजना में शामिल अन्य मूल तत्व हैं - जलवायु कार्रवाई का मार्गदर्शन करने में विज्ञान का महत्व, अनुकूलन वित्त को दोगुना करना, कम उत्सर्जन के साथ वित्त प्रवाह को सुसंगत बनाने पर संवाद, और बड़े पैमाने पर जलवायु वित्त प्रदान करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) के सुधार पर जलवायु-अनुकूल विकास की मांग ; वित्त (नए और अतिरिक्त वित्त सहित) के स्रोतों की विविधता, आदि। सीओपी27 ने अनुकूलन में पर भी प्रगति देखी, सरकारों ने अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य पर आगे बढ़ने के तरीके पर सहमति व्यक्त की, जो सीओपी28 पर समाप्त होगा और वर्ष 2023 में पहले वैश्विक स्टॉकटेक को सूचित करेगा।

7.61 अंत में, सीओपी27 के दौरान, यह भी माना गया कि प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल किया जाना शेष है। सीओपी21 ने निर्णय लिया कि, वर्ष 2025 से पहले, विकासशील देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की न्यूनतम सीमा से जलवायु वित्त पर एक नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (एनसीक्यूजी) निर्धारित किया जाएगा। वर्ष 2024 तक एनसीक्यूजी की स्थापना के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, सीओपी27 ने फैसला किया कि सीओपी28 से पहले चार तकनीकी विशेषज्ञ संवाद (टीईडी) किए जाएंगे।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहल

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)

7.62 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन है जो सौर ऊर्जा का लाभ उठाने और स्वच्छ ऊर्जा अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक बाजार प्रणाली बनाने के लिए काम कर रहा है। आईएसए का मिशन प्रौद्योगिकी की लागत और इसके वित्तपोषण को कम करते हुए वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करना है। दिनांक 6 दिसंबर 2017 को 15 देशों द्वारा आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन से, आईएसए भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन बन गया। आईएसए सौर ऊर्जा के माध्यम से, विशेष रूप से अल्प विकसित देशों (एलडीसी) और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) में लागत प्रभावी और परिवर्तनकारी समाधान मुहैया करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी), विकास वित्तीय संस्थानों (डीएफआई), निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, नागरिक समाज और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझेदारी कर रहा है।

7.63 आईएसए ने अपने सभी 110 सदस्य देशों में अपने कवरेज का विस्तार किया है। यह ऊर्जा पहुंच में सुधार, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के दृष्टिकोण से सौर ऊर्जा को अपनाने में उनकी सहायता करता है। आईएसए द्वारा प्रदान किए दिए प्रोग्रामेटिक समर्थन के माध्यम से, इसके सदस्य देशों में 9.5 जीडब्ल्यू सौर ऊर्जा क्षमता वाली पाइपलाइन की पहचान की वाले है, जिसमें कई विकासशील देशों में बड़े पैमाने सौर पार्क शामिल हैं। अपने सदस्य देशों में 50,000 अमेरिकी डॉलर के अनुदान के साथ आईएसए सौर ऊर्जा प्रदर्शन परियोजनाओं की स्थापना में सहायता कर रहा है। आईएसए की पांचवीं सभा में ऐसी तीन प्रदर्शन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया।

आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन

7.64 दिनांक 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सीडीआरआई का शुभारम्भ किया गया था। इसमें राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और वित्तपोषण तंत्रों, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक और ज्ञान संस्थानों की

वैश्विक साझेदारी है। इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए अवसंरचना प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना है, जिससे संधारणीय को विकास सुनिश्चित किया जा सके।

7.65 दिनांक 29 जून 2022 तक, इकतीस देश, छह अंतर्राष्ट्रीय संगठन और दो निजी क्षेत्र के संगठन सीडीआरआई के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। सीडीआरआई विभिन्न प्रकार के आर्थिक रूप से उन्नत देशों, विकासशील देशों और जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के प्रति सबसे संवेदनशील देशों को आकर्षित करके अपनी सदस्यता का निरंतर विस्तार कर रहा है। समय रहते न केवल भारत में बल्कि अन्य भागीदार देशों में भी आपदा-रोधी अवसंरचनाओं को आगे बढ़ाने के लिए संगठनों/हितधारकों का एक नेटवर्क विकसित किया जाएगा।

उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह (लीडआईटी)

7.66 लीडआईटी उन देशों और कंपनियों को एकत्र करता है जो पेरिस समझौते को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसे सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में स्वीडन और भारत की सरकारों द्वारा शुरू किया गया था और इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा समर्थन दिया गया है। लीडआईटी सदस्य इस धारणा का समर्थन करते हैं कि निवल-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के उद्देश्य से ऊर्जा-गहन उद्योग निम्न-कार्बन मार्गों पर प्रगति कर सकते हैं और उन्हें इसे अवश्य करना चाहिए।

7.67 सीओपी27 के दौरान, लीडआईटी सदस्यों ने एक संयुक्त वक्तव्य अपनाया जिसमें सदस्य सामूहिक रूप से निम्नलिखित बातों पर सहमत हुए:

(i) मूल्य शृंखला भागीदारी और सामग्री चक्रीकरण को बढ़ावा देना;

(ii) ऊर्जा और उद्योग परिवर्तन का समर्थन करने हेतु अवसंरचना की योजना बनाना और कार्यान्वयन पर निवेश और सहयोग करना;

(iii) उभरते और विकासशील देशों में भारी उद्योगों के संक्रमण में निवेश के जोखिम को कम करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंक और बहुपक्षीय जलवायु कोष का अधिदेश देना;

(iv) संक्रमण वित्त की सुविधा और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारी उद्योग क्षेत्रों के लिए रोडमैप तैयार करना जिसमें विनियामक ढांचे, प्रोत्साहन और दीर्घकालिक रणनीतियां शामिल है।

अन्य पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित पहल

जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना

7.68 जैव विविधता का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव और सभी जीवित प्राणियों के भरण-पोषण के लिए आवश्यक संसाधन और सेवाएं प्रदान करता है। यह पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को बढ़ाता है, जहां प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, उन सबकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैविक विविधता के संरक्षण के महत्व और आवश्यकता को लेकर नागरिकों और हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष 22 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

7.69 विश्व में विशाल विविधता वाले देशों में भारत का स्थान आठवां और एशिया में चौथा है। यह जीव-जन्तुओं में भी समृद्ध है, और दर्ज की गई उभयचर प्रजातियों में से लगभग 62 प्रतिशत भारत के लिए स्थानिक हैं, जो मुख्य रूप से पश्चिमी घाटों में पाई जाती हैं। विश्व स्तर पर, भारत फसल पौधों की उत्पत्ति और विविधता के लिए आठवें स्थान पर है, क्योंकि इसमें 300 से अधिक पौधे जंगली उत्पति के है और खेती किए गए पौधों के काफी करीबी रूप से संबंधित है जो प्राकृतिक रूप से बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से, स्वदेशी स्वास्थ्य प्रथाओं में लगभग 9,500 पौधों की प्रजातियों का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। इसके अलावा, स्थानीय और

स्वदेशी लोग भोजन, फाइबर, चारा, कीटनाशकों और कीटनाशकों, गोंद, रेजिन, रंजक, इत्र और लकड़ी के रूप में 3,900 से अधिक पौधों की प्रजातियों का उपयोग करते हैं।

7.70 वर्ष 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में संरक्षण, संधारणीय उपयोग और जैविक विविधता के उपयोग से होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी कानूनी उपकरण, जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) को अपनाया गया। जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) के लिए पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी15) की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 7 से 19 दिसंबर 2022 के बीच मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुई। सीओपी15 के प्रमुख परिणामों में शामिल हैं-

- दुनिया की कम से कम 30 प्रतिशत भूमि, अंतर्देशीय जलक्षेत्र, तटीय क्षेत्रों और महासागरों का प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन। वर्तमान में, दुनिया के 17 प्रतिशत और 10 प्रतिशत स्थलीय और समुद्री क्षेत्र संरक्षण में हैं।
- उच्च जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों के नुकसान को लगभग शून्य तक कम करना।
- वैश्विक खाद्य कचरे को आधा करना और अत्यधिक खपत और अपशिष्ट उत्पादन को पर्याप्त रूप से कम करना।
- कीटनाशकों और अत्यधिक खतरनाक रसायनों द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त पोषक तत्वों और समग्र जोखिम दोनों को आधा कर देना।
- जैव विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग के लिए सकारात्मक प्रोत्साहन को बढ़ाते हुए वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले सब्सिडी को धीरे-धीरे समाप्त करना या उसमें सुधार करना।
- वर्ष 2030 तक कम से कम 200 अरब अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष घरेलू और अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता से संबंधित निधीयन सभी स्रोतों - सार्वजनिक और निजी से जुटाना।
- विकसित से विकासशील देशों, विशेष रूप से अल्प विकसित देशों, छोटे द्वीप विकासशील राज्यों, और संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था वाले देशों में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह को वर्ष 2025 तक कम से कम 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष और वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना।

7.71 सीबीडी की भावना के अनुरूप, भारत ने वर्ष 2002 में जैविक विविधता अधिनियम बनाया। अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्डों और स्थानीय निकाय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों के साथ विकेंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से उद्देश्यों के कार्यान्वयन को अधिदेशित करता है। इनमें से प्रत्येक संस्था अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए विशिष्ट अधिदेश और शक्तियों वाला एक संविधिक और स्वायत्त निकाय है।

7.72 भारत और नेपाल ने अगस्त 2022 में वनों, वन्य जीव, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में समन्वय और सहयोग को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए जैव विविधता संरक्षण के एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें गलियारों और इंटरलिंकिंग क्षेत्रों की बहाली और दोनों देशों के बीच ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना शामिल है। समझौता ज्ञापन (एमओयू) वनों, वन्य जीवन, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण, और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में पार्टियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा, जिसमें गलियारों की बहाली और क्षेत्रों को आपस में जोड़ना और ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना शामिल है।

बॉक्स VII.3: प्रोजेक्ट चीता

प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीतों को लाने की शुरूआत की जा रही है, जो दुनिया की पहली अंतर-महाद्वीपीय वृहत जंगली मांसाहारी स्थानान्तरण परियोजना है। वर्ष 1952 चीता को में भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इस योजना के तहत नामीबिया के आठ जंगली चीतों को दिनांक 17 सितंबर 2022 को कुनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में लाया गया था। आठ चीतों में से पाँच मादा और तीन नर चीते हैं।

भारत में चीतों का ऐतिहासिक पुनः आगमन स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के उपायों की एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है। भारत में खुले जंगल और चरागाह पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने में चीता मददगार हो सकता है। इससे जैव विविधता के संरक्षण में मदद मिलेगी और जल सुरक्षा, कार्बन प्रच्छादन और मिट्टी की नमी संरक्षण जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाएगा, जिससे समाज को लाभ होगा। इसे प्रयास से पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप स्थानीय समुदाय के लिए पारिस्थितिकी विकास और पर्यावरणीय पर्यटन गतिविधियों से आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे।

चीतों के आगमन के बाद उनकी निगरानी हेतु सरकार ने एक कार्य बल का गठन किया है। यह कार्य बल दो वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा। कार्य बल का गठन निम्न कार्यों के लिए किया गया है:-

- चीतों के स्वास्थ्य की स्थिति की समीक्षा, प्रगति और निगरानी, क्वारंटाइन और सॉफ्ट रिलीज बाड़ों का रखरखाव, पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति, वन और पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा परिभाषित प्रोटोकॉल का पालन, और भारत में चीता की शुरूआत के बाद उनके समग्र स्वास्थ्य, व्यवहार और उनके रखरखाव पर सलाह।
- कूनो राष्ट्रीय उद्यान कें आवास के दौरान चीता के शिकार कौशल और अनुकूलन की निगरानी करना।
- चीता को क्वारंटाइन बोमास से सॉफ्ट-रिलीज बाड़ों, घास के मैदान और खुले वन क्षेत्रों में छोड़ने पर निगरानी करना।
- ईको-टूरिज्म के लिए चीता आवास खोलना और इस संबंध में विनियम संबंधी सुझाव देना।
- कूनो नेशनल पार्क और अन्य संरक्षित क्षेत्रों के सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन अवसंरचना के विकास पर सुझाव और सलाह देना।

वन्यजीव - इसका संरक्षण और संरक्षा

7.73 भारत में वन्यजीवों की एक समृद्ध विरासत और संरक्षण का एक लंबा इतिहास और परंपरा रही है। वन्य जीव की चिंता वास्तव में स्वयं मनुष्य की चिंता है। जीवन के सभी रूप - मानव, पशु और पौधे आपस में इतने घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि एक की अशांति दूसरे में असंतुलन पैदा कर देती है। हमारे वन्य जीवन और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों को विशेष कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1972 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 नामक एक व्यापक कानून बनाया गया था।

7.74 बाघ, शेर और हाथी जैसे जानवर महत्वपूर्ण और प्रमुख प्रजातियां हैं जिनके संरक्षण से पूरे पारिस्थितिक तंत्र को लाभ होता है। दिनांक 10 अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार, भारत के 18 राज्यों के लगभग 75,796.8 वर्ग किमी क्षेत्र में कवर करने वाले 53 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें जंगली बाघों की वैश्विक स्तर की आबादी का लगभग 75 प्रतिशत है। भारत ने लक्षित वर्ष 2022 से चार साल पहले 2018 में बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया था। इसके अलावा, देश के 17 टाइगर रिजर्व को सीए/टीएस अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, और दो को अंतर्राष्ट्रीय टी × 2 पुरस्कार मिल चुका है।[15]

15 The TX2 Tiger Conservation Award is given away by Conservation Assured | Tiger Standards (CA|TS), Fauna & Flora International, Global Tiger Forum, IUCN Integrated Tiger Habitat Conservation Programme, Panthera, UNDP Lion's Share, Wildlife Conservation Society, and World Wide Fund For Nature's (WWF's) Tigers Alive Initiative.

7.75 इसी तरह, एशियाई शेरों की आबादी में 674 शेरों (2020) की आबादी में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या की तुलना में 28.87 प्रतिशत (अब तक की उच्चतम वृद्धि दर में से एक) अधिक है। वर्ष 2014 के पिछले अनुमान 7910 की तुलना में भारत में अब (2020) में 12,852 तेंदुए हैं। इसकी आबादी में 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। दुनिया भर में इस समय लगभग 50,000-60,000 एशियाई हाथी हैं। इसकी कुल आबादी का 60 प्रतिशत से अधिक भारत में है। फरवरी 2020 में गांधी नगर, गुजरात में आयोजित सीएमएस13 के पार्टियों के सम्मेलन में प्रवासी प्रजातियों के समागम के परिशिष्ट I में भारतीय हाथी को भी सूचीबद्ध किया गया है।

चित्र VII.13: बाघ संरक्षण के प्रयासों की सफलता की कहानी बढ़ी हुई बाघों की संख्या में परिलक्षित होती है

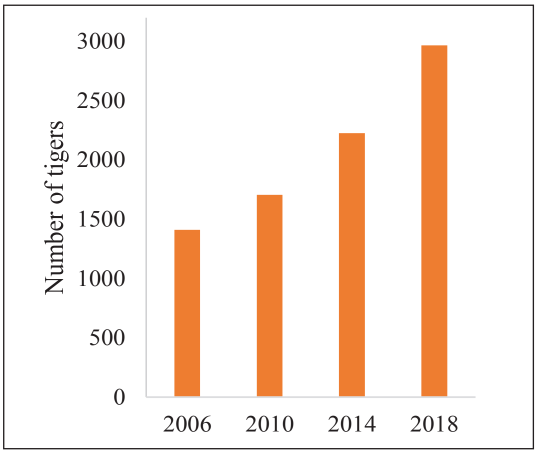

स्रोत: राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्रधिकरण

चित्र VII.14: विगत वर्षों में शेरों की बढ़ती संख्या, विभिन्न संरक्षण प्रयासों द्वारा प्रेरित है

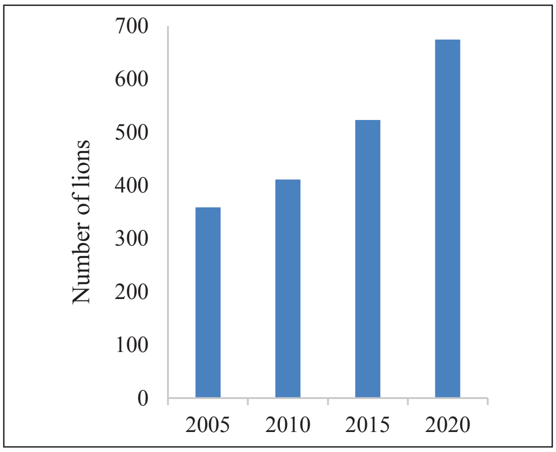

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो विज्ञप्ति

7.76 संरक्षण उपायों को मजबूत करने और वन्यजीव संरक्षण की बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया है। वन्यजीव संरक्षण में और सुधारों को लक्षित करते हुए, सरकार वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 लेकर आई। अधिनियम कानून के तहत संरक्षित प्रजातियों की संख्या बढ़ाने और वन्य जीवों और वनस्पतियों (सीआईटीईएस) की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास किया गया है। वन्य जीव (संरक्षण)[16] अधिनियम, 1972 में छह अनुसूचियां हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य (i) विशेष रूप से संरक्षित जानवरों के लिए अनुसूचियों की संख्या को दो तक कम करना, (ii) वर्मिन प्रजातियों के लिए कार्यक्रम को हटाना, और (iii) सीआईटीईएस (अनुसूचित नमूने) के तहत परिशिष्ट में सूचीबद्ध नमूनों के लिए एक नयी अनुसूची को सम्मिलित करके अनुसूचियों को युक्तिसंगत बनाना है। अंत में, यह अधिनियम सरकार को आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आयात, व्यापार, कब्जे या प्रसार को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और पहचाने गए एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का उन्मूलन

7.77 भारत एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के ढेर से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की रिपोर्ट के अनुसार, प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत का वैश्विक औसत 28 किलोग्राम है, और भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत 11 किलोग्राम है। हालाँकि, देश में प्लास्टिक कचरे के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने के प्रयास के रूप में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक

16 CITES is an international agreement between governments to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten the survival of the species.

अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया। दिनांक 1 जुलाई को 2022, पूरे देश में चिन्हित एकल-उपयोग वाली उन प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिनकी उपयोगिता कम और अधिक कूड़ेदान बनाने की संभावना है। ये उपाय सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे, प्लास्टिक पैकेजिंग के प्लास्टिक पदचिह्न को कम करेंगे, प्लास्टिक पैकेजिंग के नए विकल्पों के विकास को बढ़ावा देंगे और व्यवसायों द्वारा स्थायी प्लास्टिक पैकेजिंग की ओर बढ़ने के लिए और कदम उठाएंगे।

7.78 वर्ष 2022 में निम्नलिखित घरेलू विनियामक कार्रवाइयाँ की गई:

i. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 16 फरवरी 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2022 के माध्यम से प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया गया। दिनांक 16 फरवरी 2022 को अधिसूचित प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पर दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

   क. एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (पीआईबीओ) और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर (पीडब्ल्यूपी) का अनिवार्य पंजीकरण;

   ख. प्लास्टिक पैकेजिंग की चार श्रेणियों का कवरेज अर्थात कठोर, लचीला, बहुस्तरीय प्लास्टिक पैकेजिंग, और खाद योग्य प्लास्टिक पैकेजिंग;

   ग. ईपीआर के लिए स्पष्ट परिभाषित लक्ष्य;

   घ. कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग के पुन: उपयोग के लिए अनिवार्य लक्ष्य, प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर और प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक सामग्री का उपयोग;

   ङ. ईपीआर के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल;

   च. अधिशेष ईपीआर प्रमाणपत्रों की बिक्री और खरीद के लिए प्रावधान;

   छ. ईपीआर दायित्वों को पूरा न करने पर पर्यावरणीय मुआवजे की वसूली; और

   ज. बाध्य संस्थाओं के सत्यापन, लेखापरीक्षा और निगरानी के लिए प्रावधान।

ii. 6 जुलाई, 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 अधिसूचित किया गया था। संशोधन नियमों को प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पर दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाता है। संशोधन बीआईएस मानकों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) प्रमाणन के अनुरूप बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के लिए एक वैधानिक ढांचा है। नियमों में यह अधिदेशित किया गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर प्रदूषण भुगतान सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी।

7.79 स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन के अवसंरचना को भी मजबूत किया जा रहा है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एकल उपयोग प्लास्टिक को खत्म करने और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक विशेष कार्य दल का गठन किया है नियम, 2016. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को खत्म करने और प्लास्टिक कचरे के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समन्वित प्रयास करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यबल का गठन किया गया है।

7.80 दिनांक 2 मार्च 2022 को नैरोबी में आयोजित पांचवीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में पुन: सत्र में ''प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें: एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन की ओर'' एक संकल्प अपनाया गया।

भारत प्लास्टिक प्रदूषण पर वैश्विक कार्रवाई चलाने के संकल्प पर आम सहमति बनाने के लिए सभी सदस्य देशों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। भारत के आग्रह पर, विकासशील देशों को अपने विकास पथ का पालन करने की अनुमति देने के लिए संकल्प पाठ में प्लास्टिक[17] प्रदूषण से निपटते समय राष्ट्रीय परिस्थितियों और क्षमता के सिद्धांत को शामिल किया गया था।

बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन

7.81 सरकार ने दिनांक 24 अगस्त 2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 प्रकाशित किया, ताकि बेकार बैटरियों का पर्यावरणीय रूप से उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। इन नियमों को अधिसूचित करना चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। नए नियम बैटरी (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2001 की जगह लेंगे। इस नियम में सभी प्रकार की बैटरी शामिल हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी।

7.82 विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) की अवधारणा पर आधारित नियम कार्य करते हैं, जहां बैटरी के निर्माता (आयातकों सहित) अपशिष्ट बैटरी के संग्रह और पुनर्चक्रण/नवीनीकरण और कचरे से नई बैटरी में बरामद सामग्री के उपयोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। ईपीआर यह अधिदेशित करता है कि सभी अपशिष्ट बैटरियों को एकत्र किया जाए और उन्हें पुनर्चक्रण/नवीनीकरण के लिए भेजा जाए, लैंडफिल और भस्मीकरण में निपटान पर रोक लगाई जाए। ईपीआर दायित्वों को पूरा करने के लिए, निर्माता बेकार बैटरियों को इकट्ठा करने, रिसाइकल करने या नवीनीकरण करने के लिए खुद को जोड़ सकते हैं या किसी अन्य संस्था को अधिकृत कर सकते हैं।

ई-कचरा प्रबंधन

7.83 सरकार ने दिनांक 2 नवंबर 2022 को ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया। ये नियम ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 की जगह लेंगे और दिनांक 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे। ये नियम ई-कचरा पुनर्चक्रण के लिए एक नया विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था शुरू करेंगे। नए नियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- सीपीसीबी से पंजीकृत प्रत्येक विनिर्माता, निर्माता, नवीनीकरणकर्ता, भंजक और पुनर्चक्रणकर्ता लागू, कोई भी संस्था पंजीकरण के बिना व्यवसाय नहीं करेगी और न ही किसी अपंजीकृत इकाई के साथ किसी प्रकार की डील करेगी।
- अब एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण द्वारा प्राधिकार प्रतिस्थापित किया गया है, और केवल विनिर्माताओं, उत्पादकों, नवीनीकरणकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं को पंजीकरण की आवश्यकता है।
- अनुसूची I का विस्तार किया गया है, और अब 106 इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ईईई) को ईपीआर व्यवस्था के तहत शामिल किया गया है।
- अधिसूचित ईईई के उत्पादकों को पहले बेचे गए ईईई से उत्पादन के आधार पर या ईईई की बिक्री के आधार पर, जैसा भी मामला हो, वार्षिक ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण लक्ष्य दिए गए हैं।
- सौर पीवी मॉड्यूल/पैनल/सेल का प्रबंधन नए नियमों में जोड़े गए है।
- झूठे दावों से बचने के लिए फनर्चक्रित मात्रा की गणना अंतिम उत्पादों के आधार पर की जाएगी।
- ईपीआर प्रमाणपत्र तैयार करना और लेन-देन का प्रावधान शुरू किया गया है।
- पर्यावरण क्षतिपूर्ति और सत्यापन और लेखापरीक्षा के प्रावधान शुरू किए गए हैं।

---

17 It was essential as not all countries are equally placed in terms of development and capabilities.

7.84 इन नियमों के तहत ईईई के विनिर्माण में खतरनाक पदार्थों को कम करने का प्रावधान किया गया है। इसमें यह अधिदेश दिया गया है कि ईईई और उनके संघटकों के प्रत्येक निर्माता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पादों में सीसा, पारा और अन्य खतरनाक पदार्थ अधिकतम निर्धारित मात्रा से अधिक न हों। यह ई-अपशिष्ट के विखंडन और पुनर्चक्रण में शामिल श्रमिकों की पहचान और पंजीकरण, कौशल विकास, निगरानी और सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए भी प्रदान करता है।

निष्कर्ष

7.85 भारत दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनों में से एक का नेतृत्व कर रहा है और जलवायु परिवर्तन का सामना करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ बना हुआ है। अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद, भारत ने अपनी जलवायु आकांक्षा को कई गुना बढ़ा दिया है और बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाकर कम जीएचजी उत्सर्जन विकास रणनीति की दिशा में एक दीर्घकालिक रणनीति शुरू की है।

7.86 हरित हाइड्रोजन जैसे होनहार तकनीकी नवाचारों को लागू करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने के उद्देश्य से ऊर्जा संक्रमण योजना को कई नीतियों द्वारा पूरा किया गया है। देश ने नई तकनीक के विकास और इसे अपनाने में सहायता के लिए विनियामक मानकों को लगातार आशोधित/संशोधित किया है और नीति-स्तरीय हस्तक्षेपों को अपनाया है। ऊर्जा परिवर्तन पर भारत की प्रगति को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि इसने अपने अद्यतन एनडीसी में अपने गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित क्षमता लक्ष्य को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है क्योंकि पहले एनडीसी के 40 प्रतिशत का लक्ष्य काफी पहले ही प्राप्त कर लिया गया था।

7.87 संधारणीयता मानकों के अनुरूप शीर्ष सूचीबद्ध 100 कंपनियों को करके प्रारंभिक कदमों से स्थायी वित्त ढांचा भी विकसित हुआ है। अब अनिवार्य आधार पर आवश्यकता को न केवल 1000 शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों तक बढ़ाया गया है, बल्कि भारत के विशिष्ट संदर्भ को ध्यान में रखते हुए स्थिरता मानकों को भी अधिक मजबूत और आकलन करने योग्य बना दिया गया है जो सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हैं।

7.88 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, संसाधनों का प्रतिस्पर्धात्मक उपयोग हुआ है, और विकास रणनीतियाँ प्रतिस्थापन योग्य नहीं होती हैं। विकास मार्ग में संशोधन की एक संक्रमण लागत है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक लागतें शामिल हैं। भारत की जलवायु आकांक्षाओं के लिए संसाधनों की आवश्यकता है जो देश के विकास लक्ष्यों के लिए आवश्यक संसाधनों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के कारणों के लिए समर्पित हों। सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्यों और आकांक्षाओं को खतरे में न डालते हुए, जलवायु संबंधी दायित्वों का जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे निवेशों की समय पर उपलब्धता के साथ मिलान किया जाना चाहिए।

7.89 यहां तक कि अगर भारत ने अब तक अपने दम पर जलवायु कार्रवाई की है, तो बड़े पैमाने पर जलवायु उपायों की बढ़ी हुई उम्मीदों को वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण सहायता सहित कार्यान्वयन के साधन प्रदान करने के मामले में विकसित देशों द्वारा की गई पहल के बराबर होना चाहिए।

7.90 इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैश्विक जलवायु एजेंडा तभी आगे बढ़ेगा जब उन्नत देश उन नीतिगत और व्यवहारिक परिवर्तनों के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जो देश उनके परोक्ष रूप में काम करते हैं और जिनके ट्रेड-ऑफ अच्छी तरह से पहचाने जाते हैं और उनके लोगों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। इसके बाद उपयुक्त अनुकूलन के साथ विकासशील देशों में परिवारों की ऐसी नीतियों और व्यवहारिक अपेक्षाओं के फ़ल होने की उम्मीद करना यथार्थवादी हो सकता है।

******

08

अध्याय

कृषि और खाद्य प्रबंधनः खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक

पिछले कई वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का प्रदर्शन उत्साहजनक रहा है, जो कि फसल और पशुधन उत्पादकता बढ़ाना है, मूल्य समर्थन के माध्यम से किसानों को प्रतिलाभ (रिटर्न) की निश्चितता सुनिश्चित करना, फसल को बढ़ावा देना, कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से कृषि-उत्पादक संगठनों की स्थापना और बुनियादी सुविधाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए दी गई प्रेरणा के माध्यम से विविधीकरण, बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार करना सरकार द्वारा किए गए उपायों से हुआ है।

इस अध्याय में इन पहलुओं पर चर्चा कि गई है, इसके साथ ही ऋण उपलब्धता बढ़ाने, मशीनीकरण की सुविधा और बागवानी और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अन्य सरकारी हस्तक्षेपों पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

यह अध्याय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन का दर्शाता है, जिन्हें फसल क्षेत्र के सापेक्ष प्रदर्शन और खाद्य टोकरी और किसानों की आय में उनके महत्व के माध्यम से तेजी से उभरते क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाता है।

विधि समर्थित राष्ट्रव्यापी खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) पर चर्चा की गई है। गरीबों के आर्थिक बोझ को दूर करने के लिए सरकार ने 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

परिचय

8.1 अपनी ठोस अग्रिम कड़ियों के साथ, कृषि और संबद्ध गतिविधि क्षेत्र ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके देश के समग्र प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले छह वर्षो के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। 2020-21 में 3.3 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 में इसमें 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हाल के वर्षों में, भारत भी तेजी से कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है। पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में, भारत से कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत बढ़ा है। 2021-22 के दौरान, कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। सरकार द्वारा किसान-उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने, और मशीनीकरण के लिए दिए गए समर्थन और कृषि अवसंरचना कोष के निर्माण के माध्यम से कृषि में उत्पादकता में सुधार के लिए किए गए उपायों के लिए उत्साहजनक कार्यनिष्पादन अवधि को श्रेय दिया जा सकता है। इस प्रकार, देश की वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को साकार करने के लिए, अन्य देशों को कोविड-19 महामारी के दौरान उनको हुए नुकसान के लिए आवश्यक और अनिवार्य सहायता प्रदान की। इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के माध्यम से किसानों की आय में सहायता

देने और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने से किसानों की आय के स्रोतों में विविधता आई है, जिससे मौसम से हुए नुकसान के प्रति उनकी सहनशीलता में सुधार हुआ है।

चित्र VIII.1: कोविड-19 महामारी के बावजूद कृषि और संबद्ध क्षेत्र में लोचदार वृद्धि

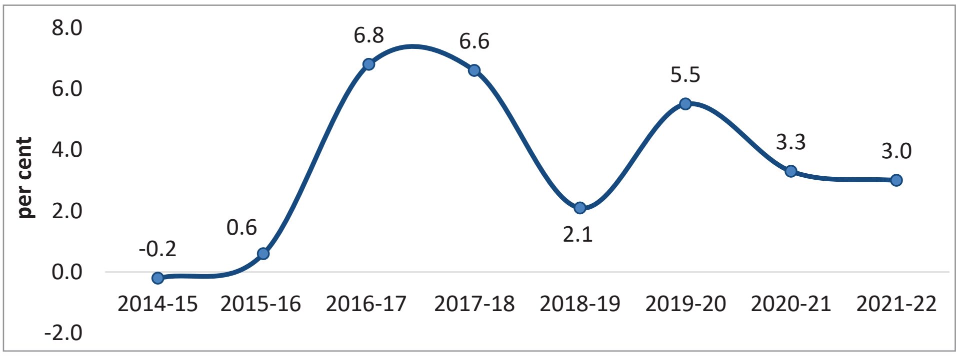

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का वार्षिक और तिमाही अनुमान, 2011-12 श्रृंखला।

8.2 किसानों की आय को दोगुना करने संबंधी सरकार के हस्तक्षेप समिति की सिफारिशों के अनुरूप रहे हैं, जिसने फसल और पशुधन उत्पादकता में सुधार, उच्च मूल्य वाली फसलों का विविधीकरण, बेहतर संसाधन दक्षता, संवर्धित फसल उत्पादकता, किसानों को मिलने वाली वास्तविक कीमतों में सुधार तथा विकास के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इसे कृषि से गैर-कृषि व्यवसायों में स्थानांतरित किया है। कई नीतिगत उपाय, जैसे उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत का डेढ़ गुना मूल्य सुरक्षित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), तिलहन जैसी उच्च मूल्य वर्धित फसलों, पर ध्यान केंद्रित करने के लिए योजनाएँ और मूल्य उपाय मूल्य नीति उपायों के माध्यम से फसल विविधीकरण के लिए, प्रोत्साहन कृषि विपणन में सुधार और संसाधन उपयोग दक्षता बढ़ाने आदि को अपनाया गया है। भारतीय कृषि ने यथोचित रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, इस क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन से प्रतिकूल प्रभाव, खंडित भूमि जोत, उप-इष्टतम कृषि मशीनीकरण, कम उत्पादकता, प्रच्छन्न बेरोजगारी, बढ़ती इनपुट लागत, आदि जैसी कुछेक चुनौतियों से निपटने के लिए पुनर्विचार की आवश्यकता है।

इस अध्याय में इन मुद्दों से निपटने के लिए शुरू और लागू की गई विभिन्न नीतिगत पहलों पर बाद में चर्चा की गई है।

चित्र VIII.2: कृषि में निजी निवेश को बढ़ावा देना

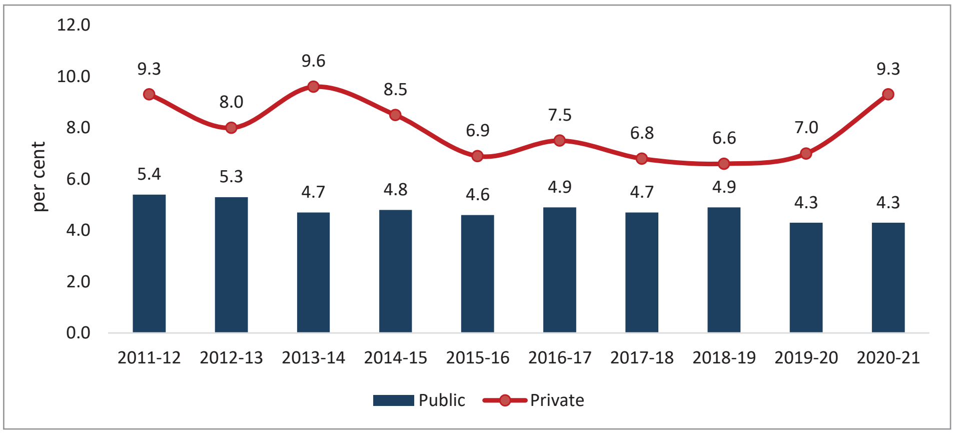

स्रोत: 2021 एक नजर में कृषि सांख्यिकी आंकड़े 2021

चित्र VIII.3: कृषि के लिए भारत की बिजली खपत (वार्षिक)

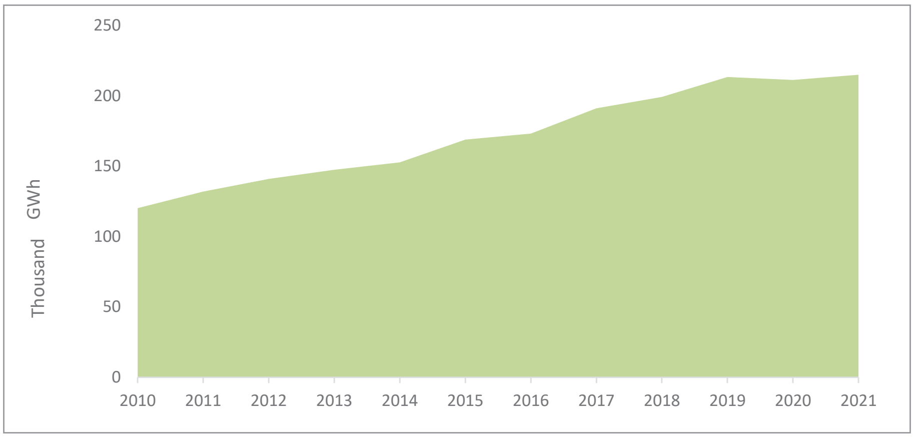

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन

8.3 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार, खाद्यान्न और तिलहन का उत्पादन साल-दर-साल (वाईओवाई) बढ़ रहा है। दालों का उत्पादन भी पिछले पांच वर्षों के औसत 23.8 मिलियन टन से उल्लेखनीय रूप से अधिक रहा है। हालाँकि, जैसा कि पहले संकेत दिया गया था कि बदलती जलवायु कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। वर्ष 2022 में गेहूं की कटाई के मौसम के दौरान शुरुआती गर्मी की लहर देखी गई, जिससे इसके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस वर्ष मानसून में देरी और कम वर्षा के कारण खरीफ मौसम में भी धान की खेती के बुआई क्षेत्र में गिरावट देखी गई। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 (केवल खरीफ) के अनुसार धान का रकबा 2021-22 (खरीफ सीजन) के दौरान 411.2 लाख हेक्टेयर बोए गए क्षेत्र से लगभग 3.8 लाख हेक्टेयर कम था। इसके अलावा, चालू रबी सीजन में रबी धान की बुआई में पिछले साल की तुलना में 6.60 लाख हेक्टेयर का विस्तार किया गया (क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप 12 जनवरी 2023)। खरीफ धान के बुआई क्षेत्र में गिरावट के बावजूद, 2022-23 के दौरान खरीफ चावल का कुल उत्पादन 104.9 मिलियन टन अनुमानित है, जो पिछले पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के औसत खरीफ चावल उत्पादन 100.5 मिलियन टन से अधिक है।

चित्र VIII.4: भारत के खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि (मिलियन टन)

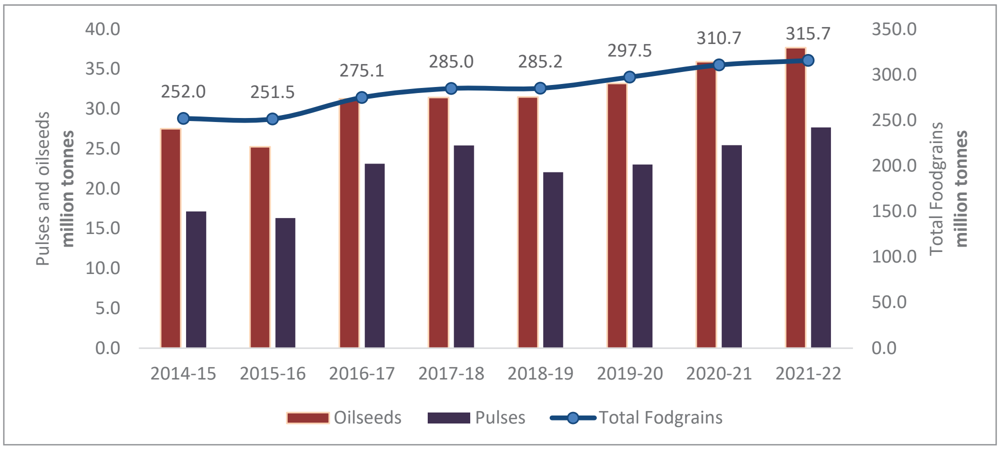

स्रोत: दिनांक 21.09.2022 को जारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का प्रथम अग्रिम अनुमान (2022-23)।

उत्पादन की लागत पर प्रतिलाभ सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

8.4 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई कि भारत के किसानों को उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तदनुसार, कृषि वर्ष 2018-19 के बाद से सरकार खरीफ, रबी का सभी 22 और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत की वापसी सहित वृद्धि करती रही है। पोषण संबंधी आवश्यकताओं और बदलते आहार पैटर्न को देखते हुए और दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार ने दालों और तिलहन के लिए अपेक्षाकृत अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है।

चित्र VIII.5: चयनित खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹/क्विंटल)

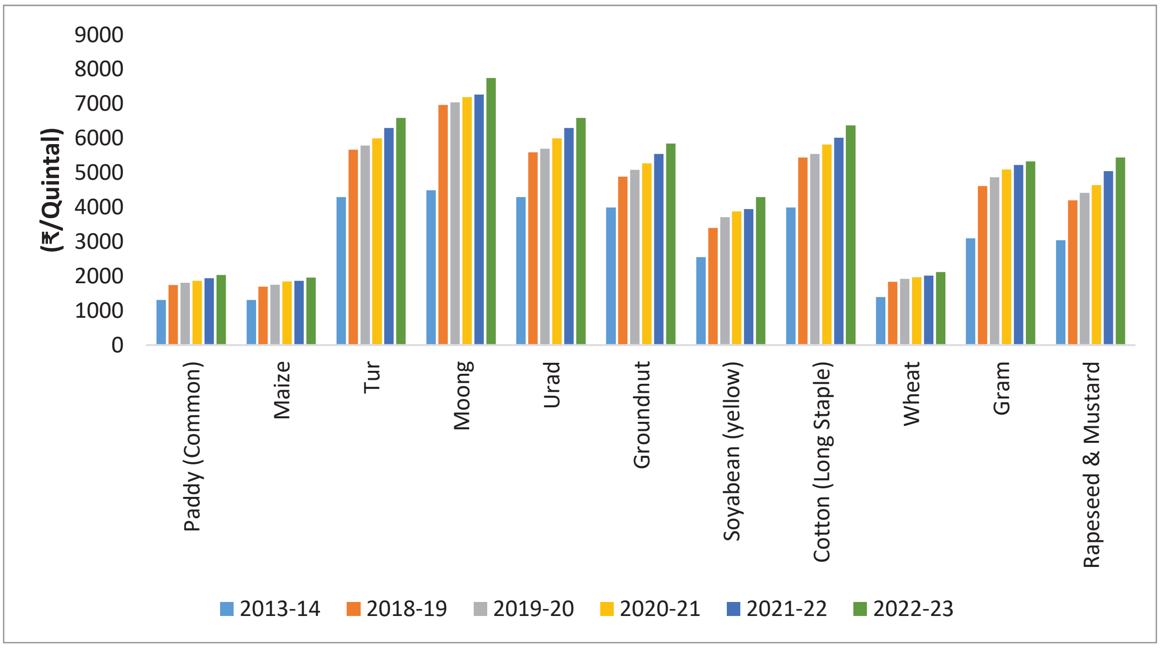

स्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और कृषि लागत और मूल्य आयोग के आंकड़ों के आधार पर।

कृषि संबंधी ऋण तक पहुंच में वृद्धि

8.5 किसानों को बिना किसी परेशानी के सस्ती दर पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। तदनुसार, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की ताकि किसान किसी भी समय ऋण पर कृषि उत्पादों और सेवाओं को खरीद सके। 30 दिसम्बर 2022 तक, बैंकों ने ₹ 4,51,672 करोड़ की केसीसी सीमा वाले 3.89 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए। भारत सरकार द्वारा 2018-19 में मत्स्य पालन और पशुपालन किसानों को केसीसी सुविधा प्रदान करने के साथ, मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र में ऐसे कार्डों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 17 अक्टूबर 2022 तक, मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 1.0 लाख केसीसी और पशुपालन क्षेत्र के लिए 9.5 लाख (4 नवंबर 2022 तक) संस्वीकृत किए गए हैं।

8.6 यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान बैंकों को न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान करे , भारत सरकार ने किसानों को रियायती ब्याज दरों पर अल्पकालिक ऋण देने के लिए ब्याज अनुदान योजना (आईएसएस) शुरू की है, जिसे अब संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत, कृषि और पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री, मछली पालन आदि सहित अन्य संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों को 3

लाख रुपये तक का अल्पकालिक कृषि ऋण 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर उपलब्ध है। ऋणों के शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त 3 प्रतिशत अनुदान (त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन) भी किसानों को दिया जाता है। इसलिए, यदि कोई किसान अपना ऋण समय पर चुकाता है, तो उसे 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ऋण मिलता है।

8.7 प्रारंभ की गई पहलों और मौजूदा नीतियों को सशक्त करने के उपायों से, पिछले कई वर्षों से कृषि ऋण प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है, जो पिछले कई वर्षों से प्रति वर्ष के लक्ष्य से अधिक है। 2021-22 में भी, यह 16.5 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से लगभग 13 प्रतिशत अधिक था। 2022-23 में कृषि के लिए ऋण प्रवाह का लक्ष्य 18.5 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

चित्र VIII.6: कृषि क्षेत्र के संस्थागत ऋण में निरंतर वृद्धि (₹ लाख करोड़)

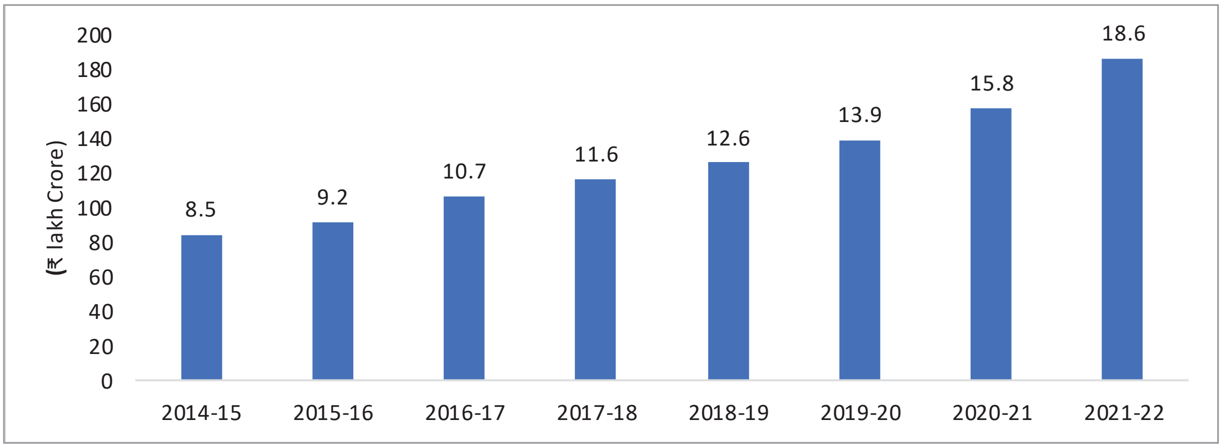

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और कृषि सांख्यिकी के आंकड़ों पर आधारित एक नजर में 2021

फार्म मशीनीकरण- उत्पादकता में सुधार की कुंजी

8.8 फार्म मशीनीकरण अन्य इनपुट्स और प्राकृतिक संसाधनों के समय पर और कुशल उपयोग के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने में मदद करतें हैं, इसके साथ ही यह खेती की लागत और विभिन्न कृषि कार्यों से जुड़े कठिन परिश्रम को कम करता है। कृषि मशीनीकरण के उप मिशन (एसएमएएम) के तहत, राज्य सरकारों को कृषि मशीनरी के प्रशिक्षण और प्रदर्शन में सहायता दी जा रही है और किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित करने के अलावा विभिन्न कृषि मशीनरी और उपकरण को खरीदने में मदद की जा रही है। दिसंबर 2022 तक, 21628 सीएचसी और 467 हाई-टेक हब और 18306 कृषि मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। कृषि जोत के बढ़ते विखंडन (2005-06 में 1.23 हेक्टेयर से घटकर 2010-11 में 1.10 हेक्टेयर और 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर तक घरेलू स्वामित्व के औसत आकार के साथ) ऐसी मशीनों की आवश्यकता है जो छोटे कृषि जोत के लिए व्यवहार्य और कुशल हों।[1]

रसायन मुक्त भारत: जैविक और प्राकृतिक खेती

8.9 जैविक और प्राकृतिक खेती से रासायनिक खाद और कीटनाशक मुक्त खाद्यान्न और अन्य फसलें प्राप्त होती है, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है और पर्यावरण प्रदूषण को कम करती है। भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है, और लगभग 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को 2021-22 तक जैविक खेती के तहत लाया गया था। सिक्किम ने स्वेच्छा से जैविक खेती को अपनाया और जैविक खेती के तहत 58,168 हेक्टेयर की कुल खेती योग्य भूमि को लेने की प्रक्रिया 2010 में जमीनी स्तर पर शुरू हुई। यह पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है, और त्रिपुरा और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों ने समान लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

1 कृषि सांख्यिकी 2021 एक नजर में

8.10 2015 से सरकार क्लस्टर/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन के माध्यम से दो समर्पित योजनाओं, अर्थात परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) को लागू करके जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। परम्परागत कृषि विकास योजना क्लस्टर मोड में (न्यूनतम 20 हेक्टेयर आकार के साथ) कार्यान्वित की जा रही है। किसान को तीन वर्षों के लिए ₹50,000 प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें से ₹31,000 सीधे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान किए गए जैविक आदानों के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं। 16 नवंबर 2022 तक परम्परागत कृषि विकास योजना के अधीन कुल 6.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के 32,384 क्लस्टर और 16.1 लाख किसानों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 1.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के तहत शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशिष्ट फसलों की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन के अधीन, 177 किसान उत्पादक संगठन/एफपीसी बनाए गए हैं, जिसमें 1.5 लाख किसान और 1.7 लाख हेक्टेयर शामिल हैं।

8.11 2019-20 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जब शून्य-बजट प्राकृतिक खेती (जेबीएनएफ) सहित पारिस्थितिक खेती के सभी रूपों को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को अपनाने में किसानों की सहायता करने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना की एक उप-योजना, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) शुरू की गई थी। यह योजना चैंपियन किसानों के माध्यम से क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, हैंडहोल्डिंग और प्राकृतिक खेती के ऑन-फील्ड प्रदर्शन पर केंद्रित है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अधीन, 8 राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु) में 4.09 लाख हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाया गया है।

कृषि में अन्य महत्वपूर्ण पहलें

8.12 पीएम किसान योजना: यह भूमि-धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। प्रति वर्ष ₹6,000 का वित्तीय लाभ डीबीटी के माध्यम से किसान परिवारों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है। पीएम किसान के तहत किसी भी किस्त अवधि के लिए लाभ पाने वालों की संख्या अब पहली किस्त अवधि के 3.2 करोड़ से 10 करोड़ किसानों को पार कर गई है। पीएम किसान ने तीन साल से अधिक समय के दौरान जरूरतमंद किसानों को सफलतापूर्वक ₹ 2 लाख करोड़ से अधिक की सहायता दी है। कई अध्ययनों और निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि पीएम किसान योजना ने किसानों को कृषि गतिविधियों में उत्पादक निवेश की दिशा में मदद की है। गुणक प्रभाव के माध्यम से इसने कृषि क्षेत्र के समग्र सुधार में योगदान दिया है।[2] उदाहरण के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के सहयोग से किए गए एक अनुभवजन्य अध्ययन में, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) ने पाया कि इस योजना ने कृषि आदानों को खरीदने के लिए किसानों की तरलता की कमी को दूर करने में सक्षम बनाया है। इसके अलावा, इसने छोटे और सीमांत किसानों की कृषि आदानों और उनके दैनिक उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आकस्मिक खर्चों के लिए धन की आवश्यकता को पूरा करने में मदद की है।

---

2 वार्ष्णेय, दीपक; जोशी, प्रमोद कुमार; रॉय, देवेश; और कुमार, अंजनी। 2020. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) और उत्तर प्रदेश, भारत में आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) चर्चा पत्र 1907 । वाशिंगटन, डीसी: अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई)

8.13 **कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ):** कृषि अवसंरचना निधि एक वित्तपोषण सुविधा है जो वर्ष 2020-21 से 2032-33 तक की फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण के लिए 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी समर्थन सहित लाभों के साथ चल रही है। इसके तहत, 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और वर्ष 2032-33 तक ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहायता दी जाएगी। कृषि अवसंरचना निधि योजना में राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना के साथ अभिसरण की सुविधा है और यह कृषि क्षेत्र में निवेश की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हो सकती है।

इसकी स्थापना के बाद से अब तक, देश में कृषि बुनियादी ढांचे के लिए ₹ 13,681 करोड़ की राशि संस्वीकृत की गई है, जिसमें 18,133 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें 8,076 गोदाम, 2,788 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयां, 1,860 कस्टम हायरिंग सेंटर, 937 छँटाई और ग्रेडिंग इकाईयां, 696 कोल्ड स्टोर परियोजनाएँ, 163 परख और लगभग 3613 अन्य प्रकार की पोस्ट-फसल प्रबंधन परियोजनाएँ और सामुदायिक कृषि संपत्तियाँ शामिल हैं।

8.14 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई): पीएमएफबीवाई वर्तमान में किसान नामांकन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है, हर साल औसतन 5.5 करोड़ आवेदन और प्राप्त प्रीमियम के मामले में यह तीसरी सबसे बड़ी योजना है। यह योजना किसान पर न्यूनतम वित्तीय बोझ का वादा करती है, जिसमें किसान रबी और खरीफ सीजन के लिए कुल प्रीमियम का केवल 1.5 प्रतिशत और 2 प्रतिशत का भुगतान करते हैं, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें प्रीमियम लागत का अधिकांश हिस्सा वहन करती हैं। इसके कार्यान्वयन के पिछले छह वर्षों के दौरान, किसानों ने ₹25,186 करोड़ के प्रीमियम का भुगतान किया और ₹1.2 लाख करोड़ की राशि के दावे प्राप्त किए (31 अक्टूबर 2022 तक)। किसान के बीच योजना की स्वीकार्यता का पता इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद से गैर-कर्जदार, सीमांत और छोटे किसानों की हिस्सेदारी में 282 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

बॉक्स VIII.1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) 2016 में खरीफ सीजन में फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को व्यापक बीमा कवरेज देने के लिए शुरू की गई थी, जिससे उनकी आय को स्थिर करने में मदद मिली। यह योजना सूचीबद्ध सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। देश में फसल बीमा की प्रचलित नीति व्यवस्था और नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसे समयबद्ध आधार पर संशोधित/नवीनीकृत किया जाता है। इस योजना में सभी खाद्य और; तिलहन फसलें और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें, जिनके पिछले उपज आंकड़े उपलब्ध हैं और जिनके लिए अपेक्षित संख्या में फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) का संचालन सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (जीसीईएस) के तहत किया जा रहा है। खरीफ 2020 से प्रभावी योजना में कई विशेषताएं हैं, जिसमें सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक भागीदारी, 3 साल के लिए राज्यों द्वारा बीमा कंपनियों का चयन, फसल उपज अनुमान की दो-चरणीय प्रक्रिया, फसल काटने के प्रयोगों के लिए उपग्रह डेटा के माध्यम से स्मार्ट नमूना तकनीक का उपयोग करना आदि शामिल हैं।
- योजना को 'क्षेत्र दृष्टिकोण' के आधार पर लागू किया गया है। संबंधित बीमा कंपनी को प्रस्तुत प्रति इकाई क्षेत्र में सीसीई की आवश्यक संख्या के आधार पर उपज डेटा के आधार पर बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकार्य दावों की गणना की जाती है और सीधे बीमित किसान के खाते में भुगतान किया जाता है। हालांकि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन आदि के स्थानीय जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान की गणना व्यक्तिगत-बीमित खेत के आधार पर की जाती है। संयुक्त समिति द्वारा इन दावों का मूल्यांकन किया जाता है जिसमें राज्य सरकार और संबंधित बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) वर्तमान में किसान नामांकन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है, हर साल औसतन 5.5 करोड़ आवेदन और प्राप्त प्रीमियम के मामले में तीसरी सबसे बड़ी योजना है। इसके कार्यान्वयन के पिछले छह वर्षों में, किसानों ने ₹25,186 करोड़ के प्रीमियम का भुगतान किया है और ₹1.26 लाख करोड़ की राशि के दावे प्राप्त किए हैं (31 अक्टूबर 2022 तक)। किसानों में योजना की स्वीकार्यता में वृद्धि का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद से गैर-कर्जदार, सीमांत और छोटे किसानों की हिस्सेदारी में 282 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मौसम की मार से प्रभावित 2017, 2018 और 2019 के कठिन मौसम के दौरान, यह योजना किसानों की आजीविका को सुरक्षित करने में निर्णायक कारक साबित हुई, कई राज्यों में एकत्र किए गए सकल प्रीमियम के मुकाबले दावा भुगतान अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक रहा। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ (2017), ओडिशा (2017), तमिलनाडु (2018), और झारखंड (2019) राज्यों ने सकल प्रीमियम के मुकाबले दावों के अनुपात का 384 प्रतिशत, 222 प्रतिशत, 163 प्रतिशत और 159 प्रतिशत रहा।
- योजना की अंदरुनी शिकायतों को बेहतर ढंग से हल करने के लिए, अंत से अंत तक सभी शिकायतों से निपटने के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल तैयार किया गया है। यह पोर्टल आवश्यक सुविधाओं से लैस है, जैसे कि कई तरीकों से शिकायत/जांच करना, किसान प्रमाणीकरण और संबंधित कंपनी को ऑनलाइन टिकट अग्रेषण, वृद्धि मैट्रिसेस के अनुसार ऑनलाइन वृद्धि, संकल्प विवरण का अद्यतन करना, डेटा विश्लेषण के लिए एमआईएस और डैशबोर्ड। इसमें बीमा कंपनियों के लिए एपीआई-आधारित संयोजकता (कनेक्टिविटी) है और इसे अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है ताकि किसान की संतुष्टि के लिए हर शिकायत का तार्किक निष्कर्ष निकला जा सके। इसके साथ ही संबंधित राज्य एवं केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में शिकायतों के निवारण की निगरानी की जाती है। पोर्टल का बीटा संस्करण 21 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया था।
- 'इसके अतिरिक्त, शिकायतों को हल करने के लिए योजना के संशोधित परिचालन दिशानिर्देशों में स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान, अर्थात जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) बनाया गया है।

8.15 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई): पीएमएफबीवाई वर्तमान में किसान नामांकन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है, हर साल औसतन 5.5 करोड़ आवेदन और प्राप्त प्रीमियम के मामले में यह तीसरी सबसे बड़ी योजना है। यह योजना किसान पर न्यूनतम वित्तीय बोझ का वादा करती है, जिसमें किसान रबी और खरीफ सीजन के लिए कुल प्रीमियम का केवल 1.5 प्रतिशत और 2 प्रतिशत का भुगतान करते हैं, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें प्रीमियम लागत का अधिकांश हिस्सा वहन करती हैं। इसके कार्यान्वयन के पिछले छह वर्षों के दौरान, किसानों ने ₹ 25,186 करोड़ के प्रीमियम का भुगतान किया और ₹ 1.2 लाख करोड़ की राशि के दावे प्राप्त किए (31 अक्टूबर 2022 तक)। किसान के बीच योजना की स्वीकार्यता का पता इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद से गैर-कर्जदार, सीमांत और छोटे किसानों की हिस्सेदारी में 282 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

8.15 बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच): कई विशेषज्ञ समूहों ने बागवानी को एक उच्च पैदावार क्षेत्र और उत्साही आय के स्रोत और किसानों के लिए बेहतर लचीलापन के रूप में पहचाना है। 2014-15 में फल, सब्जियां, जड़ और कंद फसलों, मसालों, फूलों, रोपण फसलों आदि को शामिल करते हुए बागवानी को बढ़ावा देने की योजना 2014-15 में शुरू की गई थी। उन्नत किस्मों और गुणवत्ता वाले बीजों को शामिल करना, रोपण फसलों के लिए प्रोत्साहन, क्लस्टर विकास और फसल कटाई के बाद का प्रबंधन करना व्यवधानों में शामिल है। तीसरे अग्रिम अनुमान (2021-22) के अनुसार, 28.0 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में 342.3 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। सरकार ने 55 बागवानी समूहों की पहचान की है, जिनमें से 12 को

क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के प्रारंभिक चरण के लिए चुना गया है। यह कार्यक्रम बागवानी समूहों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला सहित पूर्व-उत्पादन, उत्पादन और कटाई के बाद की गतिविधियों के एकीकृत और बाजार-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।

8.16 राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना: भारत सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना शुरू की ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली तैयार की जा सके। ई-नाम योजना के अधीन, सरकार संबंधित हार्डवेयर के लिए प्रति एपीएमसी मंडी को मुफ्त सॉफ्टवेयर और ₹ 75 लाख की सहायता प्रदान करती है, जिसमें गुणवत्ता परख उपकरण और सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकेजिंग, खाद इकाई आदि जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। 31 दिसंबर 2022 तक, 1.7 करोड़ से अधिक किसान और 2.3 लाख ई-एनएएम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।

8.17 जलवायु-स्मार्ट खेती पद्धतियां: सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने वाले किसानों के बीच इन पद्धतियों को स्वीकार कर रहा है। सौर के माध्यम से उत्पन्न बिजली को स्थानीय ग्रिड में स्थानांतरित करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया है। मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन का उपयोग कर फसल उपज भविष्यवाणी मॉडल शुरू किए गए हैं। स्मार्ट खेती फसल विविधीकरण को भी सक्षम बनाती है, जिससे किसानों को पानी के लिए मानसून पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। भारत में 1000 से अधिक एग्रीटेक स्टार्ट-अप हैं। ये किसानों को खेती की तकनीक में सुधार करने में सहायता करते हैं।[3]

बॉक्स VIII.2: मोटा अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष: हमारा पारंपरिक स्टेपल और एक स्वस्थ विकल्प

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (आईवाईएम) घोषित किया। मोटा अनाज उच्च पोषण मूल्य वाला स्मार्ट भोजन है, जो जलवायु के अनुकूल है, और संयुक्त राष्ट्र के

3 www.investindia.gov.in/team-india-blogs/digitalization-agriculture-india

कई सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजीएस) के अनुरूप है। आजीविका सृजित करने, किसानों की आय बढ़ाने और पूरी दुनिया में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी विशाल क्षमता के कारण इनका अत्यधिक महत्व है।
भारत बाजरा का 50.9 मिलियन टन (चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार) से अधिक मोटा अनाज का उत्पादन करता है जो एशिया के 80 प्रतिशत और वैश्विक उत्पादन का 20 प्रतिशत है। वैश्विक औसत उपज 1229 किग्रा/हेक्टेयर है, जबकि भारत में उच्च औसत उपज 1239 किग्रा/हेक्टेयर है। भारत में, मोटा अनाज मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, जो ज्यादातर वर्षा आधारित परिस्थितियों में उगाई जाती है, जिसमें अन्य मुख्य स्टेपल की तुलना में कम पानी और कृषि आदानों की आवश्यकता होती है।
मोटे अनाज के पोषण मूल्य को देखते हुए, सरकार ने अप्रैल 2018 में मोटे अनाज को पोषक-अनाज के रूप में अधिसूचित किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएमएस) के तहत बाजरा प्रदान करने के लिए पेश किया गया है। पोषण संबंधी सहायता के लिए मोटा अनाज को शामिल किया। 2018-19 से 14 राज्यों के 212 जिलों में न्यूट्री-अनाज पर सब-मिशन क्रियान्वित किया गया है।
भारत में मोटा अनाज मूल्य वर्धित श्रृंखला में 500 से अधिक स्टार्ट-अप काम कर रहे हैं, जबकि भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के कायाकल्प के लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-आरएएफटीएआर) के तहत 250 स्टार्ट-अप को इनक्यूबेट किया है। संबद्ध क्षेत्र: हाल के वर्षों में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन तेजी से बढ़ रहा है

संबद्ध क्षेत्र - पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन हाल के वर्षों में तेजी पकड़ रहा है।

8.18 भारतीय कृषि के संबद्ध क्षेत्र - पशुधन, वानिकी और लॉगिंग और मछली पकड़ने और जलीय कृषि धीरे-धीरे तेजी से विकास के क्षेत्र बन रहे हैं और ये बेहतर कृषि आय के संभावित स्रोत हैं। पशुधन क्षेत्र 2014-15 से 2020-21 (स्थिर कीमतों पर) के दौरान 7.9 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा, और 2014-15 में कुल कृषि जीवीए (स्थिर कीमतों पर) में इसका योगदान 24.3 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 30.1 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह, 2016-17 से मत्स्य पालन क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत रही है और कुल कृषि जीवीए में इसकी हिस्सेदारी लगभग 6.7 प्रतिशत है। कृषि जीवीए में फसल क्षेत्र की तुलना में संबद्ध क्षेत्रों की उच्च वृद्धि में पहली मद का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। संबद्ध क्षेत्रों के बढ़ते महत्व को स्वीकार करते हुए, किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी समिति (डीएफआई, 2018) डेयरी, पशुधन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और बागवानी को उच्च विकास इंजन के रूप में मानती है और संबद्ध क्षेत्र के लिए सहवर्ती समर्थन प्रणाली वाली एकाग्र नीति की सिफारिश की है।

चित्र VIII.7: यद्यपि कृषि जीवीए में फसल क्षेत्र का अभी भी प्रमुख योगदान है, पशुधन क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है (प्रतिशत में)

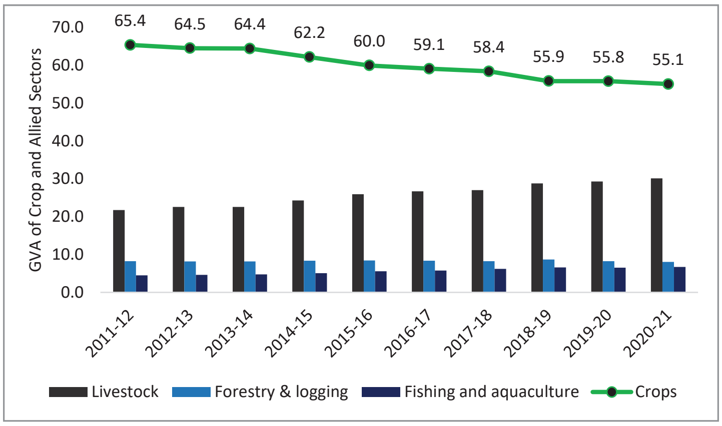

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के डेटा के आधार पर।

8.19 डेयरी क्षेत्र पशुधन क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो सीधे तौर पर आठ करोड़ से अधिक किसानों को रोजगार देता है और सबसे प्रमुख कृषि उत्पाद है। अन्य पशुधन उत्पाद, जैसे अंडे और मांस का महत्व भी बढ़ रहा है। जबकि दुनिया में दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, दुनिया में अंडे के उत्पादन में तीसरे और मांस उत्पादन में आठवें स्थान पर है।

8.20 संबद्ध क्षेत्रों के महत्व को समझते हुए, सरकार ने बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और पशुधन उत्पादकता और रोग नियंत्रण में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए हैं। वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में, 2020 में 15,000 करोड़ रुपये का पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) प्रारंभ किया था। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार उधारकर्ता को 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान और कुल उधारी के 25 प्रतिशत तक की क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। 14 अक्टूबर 2022 तक, ₹ 3,731.4 करोड़ की परियोजना लागत वाली योजना के तहत 116 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) योजना को 2021-22 से 2025-26 के लिए पुनर्गठित किया गया है। यह योजना फीड और चारा विकास सहित मुर्गीपालन, भेड़, बकरी और सुअर पालन में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर केंद्रित है। साथ ही, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच एवं डीसी) योजना को टीकाकरण द्वारा आर्थिक और जूनोटिक महत्व के पशु रोगों को रोकने, नियंत्रित करने और नियंत्रित करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। खुरपका और मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करने के लिए मवेशियों, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी को खुरपका और मुंहपका रोग और 4-8 महीने की उम्र की गोजातीय मादा बछड़ों को ब्रुसेलोसिस के खिलाफ पुर्णत: टीकाकरण करके राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) लागू किया जा रहा है।

8.21 मई 2020 में, आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) पैकेज के एक भाग के रूप में, भारत सरकार ने ₹ 20,050 करोड़ के कुल परिव्यय वाली अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) शुरू की। भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अब तक का सर्वाधिक निवेश है, जिसे सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वित्तीय वर्ष 21 से वित्तीय वर्ष 25 तक पाँच वर्षों में लागू किया जाएगा ताकि मछुआरों, मछली किसान और मछली श्रमिक के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और उत्तरदायी विकास किया जा सके। इससे पहले, मत्स्य पालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने पर ध्यान दिया गया है। ₹ 7,522 करोड़ के निवेश से 2018-19 से 2022-23 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिए एक समर्पित मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) की स्थापना की गई थी। मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष के तहत, 17 अक्टूबर 2022 तक, ₹ 4,923.9 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और मछली पकड़ने और संबद्ध गतिविधियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के माध्यम से 9.4 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है।

सहकार-से-समृद्धि: सहयोग से समृद्धि तक

8.22 विशेष रूप से कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों की, सहकारी समितियाँ, ग्रामीण आबादी को आजीविका के अवसर और समुदाय-आधारित दृष्टिकोण युक्त वित्तीय सुरक्षा जाल मुहैया कराती हैं। सहकारी समितियां ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन की कुंजी है। देश में 8.5 लाख पंजीकृत सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें 29 करोड़ से अधिक सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हाशिए और निम्न-आय समूहों से जुड़े हैं, और 98 प्रतिशत गाँव प्राथमिक कृषि साख समितियों में (पीएसीएस) शामिल किए गए हैं।

8.23 ''सहकार-से-समृद्धि'' के विजन को साकार करने के लिए सहकारी क्षेत्र के विकास को नए सिरे से गति दी गई। वर्तमान में, यह कार्य लगभग 19 प्रतिशत कृषि वित्त सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है।

सहकारी क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने के लिए जुलाई 2021 में एक पूर्ण सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा, सरकार ने प्राथमिक कृषि साख समितियों को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जैसे 63,000 कार्यात्मक प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण और प्राथमिक कृषि साख समितियों को अपनी गतिविधियों का विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए उप-नियम तैयार करना।

8.24 बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (एमएससीएस) को बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 को निरस्त करने के बाद अधिनियमित किया गया था, ताकि स्थापित सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों के लोकतांत्रिक कामकाज और स्वायत्त कामकाज को सुविधाजनक बनाया जा सके। तिथि के अनुसार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत 1528 पंजीकृत सोसाइटियां हैं। बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों में लगभग 66 बहु-राज्य सहकारी बैंक शामिल हैं, जिनमें लगभग ₹ 2.6 लाख करोड़ जमा राशि है। महाराष्ट्र 661 सहकारी सोसाइटियों का नेतृत्व करता है, इसके बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश हैं।

चित्र VIII.8: 20 अक्टूबर 2022 तक बहु-राज्य सहकारी सोसाइटियों वाले शीर्ष दस राज्य

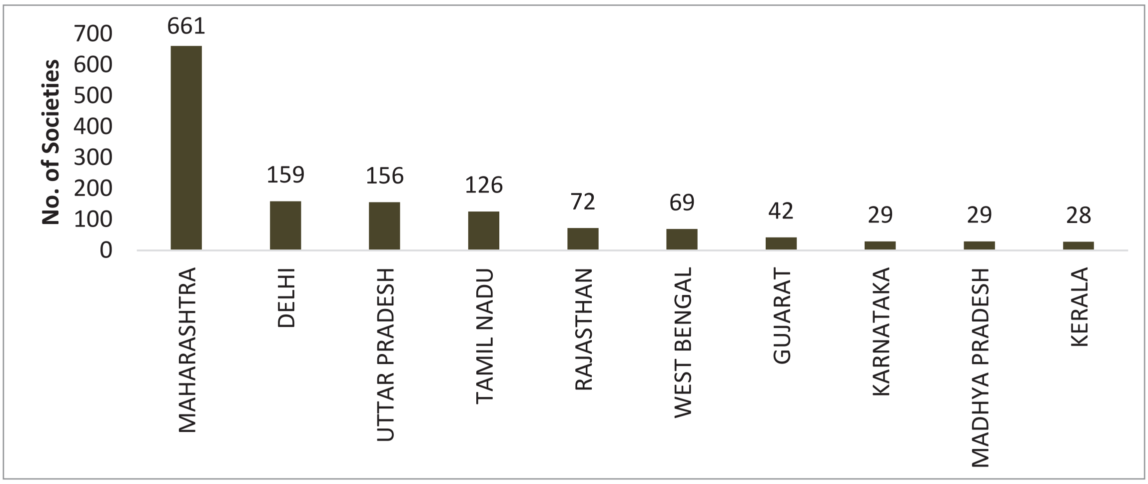

बॉक्स VIII.3: नई राष्ट्रीय सहयोग नीति

देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने, जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को गहरा करने और सहकारिता आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक नई राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जा रही है, जिसमें प्रासंगिक हितधारकों जैसे कि सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ, राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि शामिल हैं। राज्य/जिला/प्राथमिक स्तर की सहकारी सोसाइटियां, सचिव (सहकारिता) और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के निवासी आयुक्त, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी। नीति बनाने का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र की वास्तविक क्षमता की संभावनाएं तलाशना है।

इसके अलावा, सरकार ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश करने का भी फैसला किया है। विधेयक में बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन प्रस्तावित है ताकि इसे संविधान के भाग IXख के अनुरूप लाया जा सके और देश में चुनावी सुधारों, शासन को मजबूत करने और पारदर्शिता से संबंधित प्रावधानों को अपनाकर सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए, बोर्ड की संरचना, बैठकों और सदस्यता में सुधार करना; सहकारी क्षेत्र द्वारा धन जुटाने को सक्षम करना, निगरानी तंत्र को मजबूत करना, 'कारोबार करने में आसानी' को बढ़ावा आदि देकर व्यवस्था की जा सके। संसद के शीतकालीन सत्र में 7 दिसंबर 2022 को बिल लोकसभा में पेश किया गया था।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र-सूर्योदय क्षेत्र

8.25 उद्योग और कृषि के बीच मजबूत संबंधों और अंत:क्रियाओं को बढ़ावा देने के कारण खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का भारत के विकास में अत्यधिक महत्व है। वित्तीय वर्ष 21 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र लगभग 8.3 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) 2019-20 के अनुसार, पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में लगे कुल व्यक्तियों में से 12.2 प्रतिशत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत थे। 2021-22 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात सहित कृषि-खाद्य निर्यात का मूल्य, भारत के कुल निर्यात का लगभग 10.9 प्रतिशत था।

8.26 उपभोक्ता टोकरी में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बढ़ते महत्व के कारण, अब कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों के लिए खेती में विविधीकरण और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना, संसाधनों के उपयोग की दक्षता में सुधार, किसानों की आय में वृद्धि, कृषि खाद्य पदार्थों के निर्यात और रोजगार के अवसरों के सृजन में विस्तार जैसे नए क्षितिज खुले हुए हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का इष्टतम विकास होने से कई विकास संबंधी चिंताओं जैसे कृषि में प्रच्छन्न ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण गरीबी, खाद्य सुरक्षा, खाद्य मुद्रास्फीति, बेहतर पोषण, भोजन की बर्बादी की रोकथाम आदि से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

8.27 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अबाध विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे में व्यापक निवेश और लॉजिस्टिक चुनौतियों का समाधान करने की निरंतर आवश्यकता है। नीति आयोग नए भारत संबंधी रणनीति में पर्याप्त और कुशल कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को आपूर्ति की महत्वपूर्ण रूकावट माना गया है, जिससे कटाई के बाद बड़े पैमाने पर फसल का नुकसान (ज्यादातर खराब होने वाले) होता है, जिसका अनुमान ₹ 92,561 करोड़ प्रतिवर्ष है।[4] कोल्ड स्टोरेज के बुनियादी ढांचे के असमान भौगोलिक वितरण से भी क्षेत्रीय स्तर की असमानताएँ बढ़ती है। दुनिया भर के देशों में खाद्य और कृषि उत्पादों के आयात के कड़े दिशानिर्देशों के होने से पर्याप्त कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण भारत से होने वाले निर्यात को खारिज करने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा, कनेक्टिविटी से संबंधित सांभर तंत्र बाधाएं भी आपूर्ति के लिए चुनौतियां बनती हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, कुल सड़क नेटवर्क का 2 प्रतिशत है और इससे सभी प्रकार के कार्गो का 40 प्रतिशत ले जाया जाता है यह मौजूदा सड़क नेटवर्क पर बोझ और भीड़भाड़ की संभावना, जो भोजन (और विशेष रूप से खराब होने वाले) परिवहन के लिए हानिकारक का उदहारण प्रस्तुत करता है।

8.28 इस क्षेत्र की प्रचुर क्षमता को पहचानते हुए, सरकार देश में खाद्य प्रसंस्करण के विकास के उद्देश्य से विभिन्न हस्तक्षेपों में सबसे आगे रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) की घटक योजनाओं के माध्यम से, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास और विकास के लिए वित्तीय सहायता देता है। पीएमकेएसवाई के तहत, 31 दिसम्बर, 2022 तक 677 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। मंत्रालय ने 2020 में असंगठित क्षेत्र में व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एएनबी अभियान के हिस्से के रूप में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) योजना के प्रधान मंत्री के औपचारिककरण की भी शुरुआत की। देश में 2 लाख सूक्ष्म इकाईयों के उन्नयन/स्थापना के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करके इस क्षेत्र को खंडित करना और औपचारिकता को बढ़ावा देना। 31 दिसम्बर 2022 तक ₹ 1402.6 करोड़ के 15,095 ऋण संस्वीकृत किए गए। यह योजना साझा सेवाओं और विपणन उत्पादों का उपयोग करके इनपुट की खरीद में बड़े पैमाने पर लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के दृष्टिकोण को अपनाती है। अब तक 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ओडीओपी के तहत 137 विशिष्ट उत्पादों वाले 713 जिलों को मंजूरी दी गई है।

4 नीति आयोग, भारत के लिए नई रणनीति @75, दिसंबर 2018, अध्याय 7, पृष्ठ 36

8.29 मार्च 2022 में शुरू किए गए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) को वैश्विक खाद्य चौंपियन हेतु निवेश को प्रोत्साहित करने का विशिष्ट माध्यम है। सहायता के लिए उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्र, जैसे समुद्री उत्पाद, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, और 'रेडी टू ईट/रेडी टू कुक' उत्पाद, को शामिल किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के अधीन चरण-I में पीएलआईएसएफपीआई के तहत सहायता के लिए 149 आवेदनों का चयन किया गया है। 800 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मोटे अनाज आधारित उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भी शुरू की गई थी। इस घटक के अधीन, दूसरे चरण में 33 आवेदन (जैविक और मोटा अनाज उत्पाद दोनों) चुने गए हैं।

8.30 पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों से बागवानी, मत्स्य पालन, पशुधन और प्रसंस्कृत उत्पादों सहित खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, कृषि उड़ान 2.0 संस्करण को छह महीने की पायलट परियोजना के रूप में अक्टूबर 2021 में प्रारंभ किया गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) भारतीय मालवाहकों और पी2सी (पैसेंजर-टू-कार्गो) विमानों के लिए लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग चार्ज (टीएनएलसी) और रूट नेविगेशन सुविधा प्रभार (आरएनएफसी) की पूर्ण छूट देता है। इस योजना में मुख्य रूप से पूर्वोत्तर, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले लगभग 25 हवाई अड्डे और अन्य क्षेत्रों/क्षेत्रों में 28 हवाई अड्डे शामिल हैं। इस प्रकार, यह योजना किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता करती है और मूल्य प्राप्ति में सुधार करती है।

खाद्य सुरक्षा-राष्ट्र के लोगों के लिए सामाजिक और कानूनी प्रतिबद्धता

8.31 खाद्य सुरक्षा न केवल भोजन पैदा करने की क्षमता का सवाल है बल्कि भोजन तक पहुंचने की क्षमता का भी सवाल है। सरकार वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत भारत की लगभग 80 करोड़ आबादी को शामिल करते हुए दुनिया में सबसे व्यापक कानून-आधारित खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चला रही है। भारत में खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम में किसानों से लाभकारी कीमतों पर खाद्यान्न की खरीद, उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों, सस्ती कीमतों पर और खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता के लिए खाद्य बफर स्टॉक का रखरखाव शामिल है। दिसंबर 2022 तक, एनएफएसए ने 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को मोटे अनाज/गेहूं/चावल के लिए ₹ 1/2/3 प्रति किलोग्राम की दर से अत्यधिक सब्सिडी वाला खाद्यान्न दिया। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले परिवारों को क्रमशः 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से और प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से। ऐतिहासिक फैसले द्वारा, सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अधीन लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने का फैसला किया है। गरीबों के वित्तीय बोझ को दूर करने के लिए सरकार इस अवधि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्य सब्सिडी पर 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी। इसके तहत, सरकार अगले एक साल के लिए प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थियों (गरीब से गरीब) को 35 किलोग्राम प्रति परिवार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी।

8.32 इस कार्यक्रम के लिए किसानों से एमएसपी पर खरीद की गई है। खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2021-22 के दौरान, 532.7 एलएमटी के अनुमानित लक्ष्य के मुकाबले 581.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चावल की खरीद की गई। चालू वर्ष खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2022-23 में 10 दिसंबर 2022 तक कुल 355 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद की गई है। इसके अलावा, रबी विपणन सीजन (आरएमएस)

2021-22 के 433.4 लाख मीट्रिक टन की तुलना में रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2022-23 में 187.9 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। खरीद सीजन के दौरान गेहूं का बाजार मूल्य एमएसपी से अधिक होने के कारण खरीद कम हुई। 2022-23 के दौरान, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं आदि के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 968.1 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया।

चित्र VIII.9: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत 2022-23 और 1 जनवरी 2023 (लाख टन) के तहत खाद्यान्न का आवंटन

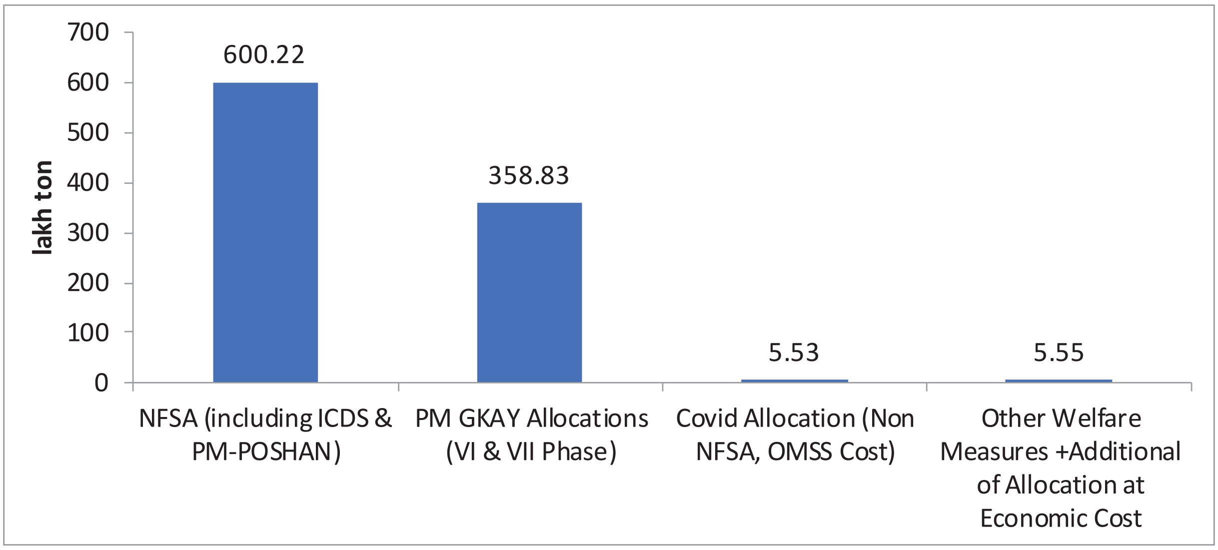

स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग।

8.33 कोविड-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधान के कारण गरीबों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, शुरुआत में सरकार ने अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) शुरू की। फिर भी, गरीबों और जरूरतमंदों को निरंतर सहायता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, योजना को बढ़ाया गया है और इसे विभिन्न चरणों में लागू किया गया है (चरण VII अक्टूबर-दिसंबर, 2022 को शामिल करने वाला नवीनतम चरण है)। योजना के तहत, सभी चरणों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया गया है/किया जा रहा है। 15 नवंबर 2022 तक, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) योजना के तहत, सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 1118 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया है।

8.34 भोजन तक पहुंच की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए, सरकार ने 2019 में एक नागरिक-केंद्रित और प्रौद्योगिकी-संचालित योजना शुरू की, जिसे वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना कहा गया। वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली राशन कार्डों की अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्य सुवाह्यता को सक्षम बनाती है। यह उचित मूल्य की दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरणों पर बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के बाद उसी राशन कार्ड का उपयोग करके प्रवासी लाभार्थियों को उनकी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से उनकी खाद्य सुरक्षा पात्रता तक पहुँचने में मदद करता है। वर्तमान में, सभी 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय/अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी सक्षम है, जिसमें कुल एनएफएसए आबादी को शत प्रतिशत शामिल किया गया है।

8.35 पीएमएमजीकेएवाई के तहत सरकार के मुफ्त भोजन वितरण कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप अन्य वर्षों की तुलना में 2020-21 और 2021-22 के दौरान खाद्य सब्सिडी बिल अधिक था। यह समर्पित सहायता यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गई थी कि किसान और कमजोर परिवार कोविड-19 की महामारी के झटके से सुरक्षित रहें।

चित्र VIII.10: 2014-15 से भारत सरकार द्वारा जारी कुल खाद्य सब्सिडी (हजार करोड़)

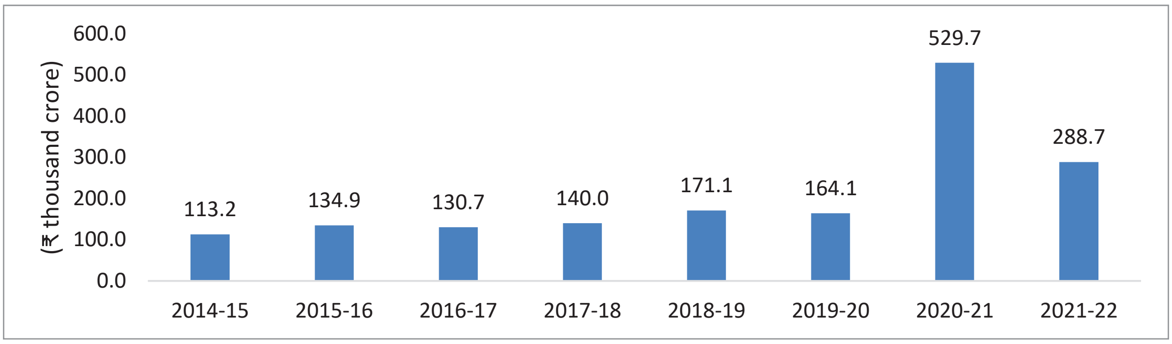

स्रोतः खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

टिप्पणीः (i) उपर्युक्त सब्सिडी आंकड़ों में वित्त वर्ष 2017-18 में 40,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय लघु बचत कोष राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि (एनएसएसए) संबंधी ऋण, वित्त वर्ष 2018-19 में 70,000 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2019-20 में 44,164.02 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(ii) वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय खाद्य निगम को जारी कुल धनराशि में से, 462789 करोड़ रुपए का उपयोग 31.03.2021 तक पूरे राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि (एनएसएसएफ) संबंधी ऋण को चुकाने के लिए किया गया था।

निष्कर्ष

8.36 देश में विकास और रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन महत्वपूर्ण बना हुआ है। ऋण वितरण के लिए एक किफायती, समय पर और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम किसान के माध्यम से सरकार द्वारा हस्तक्षेप, पीएमएफबीवाई के माध्यम से संस्थागत वित्त और बीमा को मजबूत करना और किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देना और उत्पादकता में सुधार करने वाली मशीनों और उपकरणों तक पहुंच महत्वपूर्ण रही है। बागवानी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने और संबद्ध गतिविधियों की ओर बढ़ने से किसानों की आय में विविधता आई है, जिससे वे मौसम के आघातों के प्रति अधिक लचीले हो गए हैं।

8.37 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास पर अधिक ध्यान देने से बर्बादी/हानि को कम किया जा सकता है और भंडारण की अवधि बढ़ाई जा सकती है, जिससे किसानों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित हो सकता है। कृषि बाजार को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन को बढ़ावा देने जैसी पहल शुरू की गई हैं। प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री औपचारिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई), उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) आदि सहित हस्तक्षेपों से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कृषि क्षेत्र के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाने के लिए बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। कोल्ड स्टोरेज और बेहतर लॉजिस्टिक्स जैसे बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ सुविकसित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बर्बादी को कम करने, मूल्यवर्धन में सुधार करने, किसानों को बेहतर प्रतिलाभ सुनिश्चित करने, रोजगार को बढ़ावा देने और निर्यात आय में वृद्धि करने में मदद करता है।

09

अध्याय

उद्योग: स्थायी विकास

उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्य स्थान रखता है यह औसतन वित्त वर्ष 12 और वित्त वर्ष 21 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 31 प्रतिशत था और इसने 12.1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया। वित्त वर्ष 23 में, भारतीय उद्योग को कुछ असाधारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि इस दौरान रूसी-यूक्रेन संघर्ष शुरु हो गया था। इससे कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक उछाल आया। खाद्य तेल, कच्चा तेल, उर्वरक और खाद्यान्न की कीमतें तेजी से बढ़ीं। ये कीमतें कई महीनों तक ऊंचे स्तर पर बनी रहीं। आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के एक और दौर का खतरा सामने आया, लेकिन वे उतने गंभीर नहीं थे जितनी कि आशंका थी। फिर भी, आवश्यक वस्तुओं की कीमत और उपलब्धता दोनों में वित्त वर्ष 22 की वसूली को मजबूत करने तथा इसे और तेज करने के उद्योग की उम्मीद में सेंध लगाने की क्षमता थी। यह कहना उचित है कि भारतीय उद्योग ने कठिन परिस्थितियों में स्वंय को काफी हद तक मुक्त कर लिया। वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) 3.7 प्रतिशत बढ़ा, जो पिछले दशक की पहली छमाही में प्राप्त 2.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि से अधिक है।

वित्त वर्ष 2022 के बाद से मजबूत घरेलू परिस्थितियों ने औद्योगिक विकास को एक मांग प्रोत्साहन प्रदान किया है। वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) वित्त वर्ष 2015 के बाद से सभी छमाहियों, पहली छमाही या दूसरी छमाही में सबसे अधिक था। इसके अलावा, वित्त वर्ष 22 का मजबूत निर्यात प्रदर्शन, वित्त वर्ष 203 की पहली छमाही में कुछ हद तक जारी रहा। वर्ष की इस छमाही में, सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2016 के बाद से सबसे अधिक रहा है। हालांकि, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में लगातार उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरों के कारण निर्यात की वर्ष-दर-वर्ष (वाईओवाई) वृद्धि का प्रदर्शन, पहली तिमाही से दूसरी तिमाही तक घटने के कारण पहली छमाही में कम होना शुरू हो गया। निवेश की मांग में वृद्धि औद्योगिक विकास के लिए एक और शक्तिशाली प्रोत्साहन के रूप में सामने आयी है। यह महामारी से पहले के वर्षों की तुलना में वर्तमान और पिछले वर्ष में केंद्र सरकार के संवर्धित कैपेक्स द्वारा सक्रिय किया गया है। इस उछाल ने निजी निवेश में भी भीड़ बढ़ा दी है, जो पहले से ही दबी हुई मांग, निर्यात प्रोत्साहन और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट को मजबूत करने पर उत्साहित है।

मांग प्रोत्साहन के लिए उद्योग की आपूर्ति प्रतिक्रिया मजबूत रही है, जैसा कि उच्च-आवृत्ति संकेतकों में देखा गया है। पीएमआई विनिर्माण, जुलाई 2021 से 18 महीनों के लिए विस्तार क्षेत्र में रहा है, और इसके उप-सूचकांक इनफट लागत दबावों में कमी, आपूर्तिकर्ता वितरण समय में सुधार, मजबूत निर्यात ऑर्डर और भविष्य के उत्पादन का संकेत देते हैं। जबकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के उपभोक्ता टिकाऊ घटक में वृद्धि 'दबी हुई' मांग के जारी होने के कारण है जबकि पूंजीगत वस्तुओं और बुनियादी ढांचे/निर्माण वस्तुओं में वृद्धि एक अच्छे निवेश चक्र की शुरुआत का संकेत है जिसका नेतृत्व निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने की उम्मीद है। कोयला, उर्वरक, सीमेंट, बिजली, स्टील और रिफाइनरी उत्पादों के आठ प्रमुख उद्योगों की वृद्धि स्थिर रही है, जो औद्योगिक गतिविधियों में व्यापक गति को

दर्शाता है। हालांकि, विनिर्माण परिदृश्य विभिन्न श्रेणियों में असमान वृद्धि दर्शाता है, जिसमें ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों ने प्रभावशाली प्रदर्शन दर्ज किया है जबकि कपड़ा जैसे क्षेत्रों में धीमी वृद्धि दिखाई दे रही है, क्योंकि इन उत्पादों की निर्यात मांग वैश्विक उत्पादन और मांग में कमी के साथ कम हो रही है।

जनवरी 2022 से स्पष्ट वृद्धि के साथ, बैंक ऋण में वृद्धि ने औद्योगिक विकास के साथ गति बनाए रखी है। आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की शुरुआत से सहायता प्राप्त सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के ऋण में भी आंशिक रूप से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जबकि कुल ऋण में वृद्धि, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों द्वारा मांगी गई ऋण में वृद्धि से प्रेरित है, बड़े उद्योगों ने वित्त वर्ष 23 की शुरुआत से अपने ऋण की गति को बढ़ाना शुरू कर दिया है क्योंकि वे अस्थिर ऋण और इक्विटी बाजार से पूंजी जुटाने की अपनी गति को कम करना चाहते हैं। बढ़ती क्षमता उपयोग और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के साथ संयुक्त रूप से ऋण मांग में मजबूत वृद्धि, भविष्य की मांग के संबंध में व्यवसायों के आशावाद को रेखांकित करती है।

बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच, वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में कमी आई है। हालांकि, अंतर्वाह पूर्व-महामारी के स्तर से काफी ऊपर रहा, जो संरचनात्मक सुधारों और व्यापार करने में आसानी में सुधार के उपायों से प्रेरित था, जिससे भारत दुनिया में सबसे आकर्षक एफडीआई गंतव्यों में से एक बन गया।

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के महत्व में वृद्धि जारी है क्योंकि इसके अनुप्रयोग व्यापक हो गए हैं। संचार सेवाओं में निरंतर सुधार द्वारा समर्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्पादकता, कुशल सेवा वितरण और सामाजिक परिखर्तन में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। इस उद्योग के महत्वपूर्ण विकास चालक मोबाइल फोन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। मोबाइल फोन सेगमेंट में, भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है, जिसके हैंडसेट का उत्पादन वित्त वर्ष 15 में 6 करोड़ यूनिट से बढ़कर वित्त वर्ष 21 में 29 करोड़ यूनिट हो गया है।

भारतीय फार्मास्युटिकल्स उद्योग वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। मात्रा के आधार पर फार्मा उत्पादों के उत्पादन में भारत दुनिया भर में तीसरे और मूल्य के आधार पर 14वें स्थान पर है। यह क्षेत्र विश्व स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, जो मात्रा के आधार पर वैश्विक आपूर्ति में 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है, और 60 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ विश्व स्तर पर अग्रणी वैक्सीन निर्माता भी है। वैश्विक व्यापार व्यवधानों और कोविड-19 से संबंधित उपचारों की मांग में गिरावट के बावजूद सकारात्मक वृद्धि को बनाए रखते हुए फार्मा निर्यात का प्रदर्शन मजबूत रहा है। सितंबर 2022 तक फार्मा क्षेत्र में संचयी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है।

महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष ने वैश्विक अर्थ व्यवस्था के लिए आपूर्ति श्रृंखला के झटके के जोखिम को प्रदर्शित किया है। जैसा कि कंपनियां लचीलापन बनाने के लिए अपनी विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला रणनीतियों को अपनाती हैं, भारत के पास इस दशक में वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का एक अनूठा अवसर है। इस संदर्भ में, सरकार की मेक-इन-इंडिया पहल ने घरेलू विनिर्माण क्षमताओं में अंतर को दूर करते हुए निवेश को सुगम बनाया है, नवाचार को बढ़ावा दिया है और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। 14 श्रेणियों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं ने इसे और पूरक बनाया है, क्योंकि अगले पांच वर्षों में इसके 3 लाख करोड़ रुपये के कैपेक्स को आकर्षित करने की उम्मीद है और 3 मिलियन से अधिक रोजगार पैदा करने की क्षमता है। मध्यम अवधि में, योजना घरेलू विनिर्माण क्षमता का निर्माण करके शुद्ध आयात को कम करने में मदद करेगी जो घरेलू और वैश्विक जरूरतों को पूरा करेगी।

परिचय

9.1 उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान रखता है यह औसतन वित्त वर्ष 12 और वित्त वर्ष 21 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 31 प्रतिशत था और इसने 12.1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया। आर्थिक विकास और रोजगार में योगदान देने वाले अन्य क्षेत्रों के साथ अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधों के माध्यम से इस क्षेत्र की प्रासंगिकता की पहचान की जा सकती है। सबसे पहले, यह सुनिश्चित करता है कि घरेलू उत्पादन घरेलू मांग को समायोजित कर सकता है और आयात पर निर्भरता कम कर सकता है। जिससे व्यापार और चालू खाता शेष के सुधार में सहायता मिलती है। दूसरा, औद्योगिक विकास के गुणक प्रभाव होते हैं, जो रोजगार वृद्धि में परिवर्तित होते हैं। कपड़ा और विनिर्माण जैसे कुछ उद्योगों में उच्च रोजगार लोच है। तीसरा, औद्योगिक विकास बैंकिंग, बीमा, रसद आदि जैसे सेवा क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देता है।

Table IX.1: औद्योगिक घटकों का विकास एंव भागीदारी (प्रतिशत में)

	प्रतिशत में वृद्धि		वित्त वर्ष 22 के सापेक्ष वित्त वर्ष 23 में वास्तविक जीवीए वृद्धि	वित्त वर्ष 20 के सापेक्ष वित्त वर्ष 23 में वास्तविक जीवीए वृद्धि	वित्त वर्ष 23 के सकल जीवीए में भागीदारी
	छमाही 1:वित्त वर्ष23	छमाही 2:वित्त वर्ष 23 (अनुमानित)			
उद्योग	3.7	4.5	4.1	11.1	30.0
वनन और उत्वनन	2.2	2.6	2.4	4.4	2.3
उत्पादन	0.1	3.0	1.6	11.0	17.3
बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	10.0	7.9	9.0	13.0	2.3
विनिर्माण	11.5	7.3	9.1	12.8	8.1
कुल जीवीए	**9.0**	**4.7**	**6.7**	**9.8**	**-**

स्रोत: एनएसओ, , सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
नोट: वित्त वर्ष 23 के लिए ऑकड़े, पहला अग्रिम अनुमान प्रदर्शित करते है

2. औद्योगिक उत्पादन देश में औद्योगिक आय बढ़ाने का एक साधन है। औद्योगिक जीवीए की माप के अनुसार, औद्योगिक आय में वृद्धि ने वित्त वर्ष 20 के पूर्व-महामारी वर्ष के बाद से अर्थव्यवस्था में समग्र जीवीए वृद्धि के साथ गतिक्रम को बनाए रखा है। उत्पादन जीवीए, जो औद्योगिक जीवीए में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है, समग्र जीवीए की तुलना में और भी अधिक दर से बढ़ा है। उद्योग क्षेत्र में वित्त वर्ष 22 में 10.3 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 23 में 4.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई। इसके इनपुट लागत-पुश दबावों, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और चीन के लॉकडाउन के कारण आवश्यक इनपुट की उपलब्धता को प्रभावित करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को धीमा करने की संभावना है। आधारभूत प्रभाव के लुप्त होने का असर वित्त वर्ष 23 में विकास पर भी पड़ा होगा। एक सकारात्मक स्थिति पर, दूसरी छमाही: वित्त वर्ष 23 का अनुमान, दोनों वार्षिक और क्रमिक रूप से समग्र औद्योगिक विकास, विशेष रूप से उत्पादन क्षेत्र में सुधार प्रदर्शित करता है। यदि अन्य चीजें पूर्ववत रहें तो, इनपुट कीमतों में कमी और अनुकूल मांग स्थितियों से विकास को समर्थन मिलेगा।

3. इस अध्याय में सर्वेक्षण चालू वित्त वर्ष में भारतीय उद्योग के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा। यह औद्योगिक विकास के लिए मांग उत्तेजक, उद्योग की आपूर्ति प्रतिक्रिया, उद्योग के लिए ऋण रुझान और भारत के औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश की जांच करता है। अध्याय प्रमुख सह-उद्योगों के विकास और उनकी चुनौतियों का भी समाधान करता है। अंततः, यह वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की भारत की आकांक्षाओं और संभावनाओं का मूल्यांकन करता है।

औद्योगिक विकास के लिए मांग प्रोत्साहन

4. वित्त वर्ष 23, एक माह पुराने रूसी–यूक्रेन संघर्ष के साथ शुरू हुआ जिसमें राहत के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। जैसे–जैसे साल आगे बढ रहा है, जैसे–जैसे संघर्ष स्थिर होता दिख रहा है, हालांकि वैश्विक उत्पादों की कीमतें अभी भी अपने पूर्व–महामारी के स्तर तक कम नहीं हुई हैं। इस प्रकार पूरे वर्ष भर देश में उद्योग को आयातित उच्च इनपुट लागतों का सामना करना पड़ा है। मांग प्रभाव के डर से, उद्योग धीरे–धीरे उच्च उत्पादन लागत की ओर आगे बढ़ा रहा है, जिसके कारण स्थिर लेकिन गैर–वर्धित कोर खुदरा मुद्रास्फीति हो गई है। दूसरी ओर गैर–प्रमुख खुदरा मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य और ऊर्जा घटक शामिल हैं, में गिरावट आ रही है क्योंकि स्थानीय मौसम की चरम सीमाएं कम हो गई हैं और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए हस्तक्षेप प्रभावी साबित हुए हैं। समग्र खुदरा मुद्रास्फीति में परिणामी कमी ने इस प्रकार महामारी के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मांग को बनाए रखा है, जिससे वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद औद्योगिक सुधार हुआ है। वैश्विक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अब भी कम हो रही हैं और यह भारत की थोक मुद्रास्फीति की घटती दरों में दिवाई दे रही हैं जिससे मुख्य खुदरा मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद है जिससे देश में औद्योगिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए घरेलू खपत की मांग और अधिक मजबूत हो जाएगी। वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में जीडीपी के हिस्से के रूप में पीएफसीई वित्त वर्ष 15 के बाद सबसे अधिक थी।

5. मजबूत बाहरी मांग ने वित्त वर्ष 22 में भी भारतीय उद्योग की अच्छी तरह से सेवा की, जब वैश्विक वृद्धि में फनः सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए उत्पाद निर्यात अपनी सीमा को पार कर गया था। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अड़चनें कम होने के कारण व्यापार भी संवर्धित हो गया था और बढ़ गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्यात प्रोत्साहन वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में यथावत बना रहा। वर्ष की इस छमाही में, सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2016 के बाद से सबसे अधिक रहा है। हालाँकि, पहली छमाही में ही निर्यात की गति कम हो रही है क्योंकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में लगातार उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरों के कारण निर्यात की साल–दर–साल वृद्धि पहली तिमाही से दूसरी तिमाही तक घट गई है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में निर्यात वृद्धि और धीमी हो सकती है और अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ जाती है तो इसके बाद भी कमजोर रह सकती है। यह भारतीय उद्योग पर निर्भर होगा कि वह अपनी विकास गति को बदले और उस घरेलू बाजार के लिए उत्पादन करे जो वह देश विदेशों से आयात करता है।

6. घरेलू खपत, निर्यात और आयात प्रतिस्थापन के अलावा, निवेश की मांग में वृद्धि, औद्योगिक विकास के लिए एक और शक्तिशाली प्रोत्साहन के रूप में उभरी है। यह महामारी के पूर्व के वर्षों की तुलना में वर्तमान और पिछले वर्ष में केंद्र सरकार के कैपेक्स में उछाल से शुरू हुआ है। इस उछाल में भीड़–भाड़ वाला निजी निवेश भी है, जो पहले से ही दबी हुई खपत की मांग, निर्यात प्रोत्साहन और कॉर्पोरेट तुलन–पत्र (बैलेंस शीट) को मजबूत करने पर उत्साहित है। वित्त वर्ष 23 की पहली तिमाही में मौजूद 74.3 प्रतिशत क्षमता उपयोग पहले ही वित्त वर्ष 22 की चौथी तिमाही में 75.3 प्रतिशत के चरम बिंदु पर पहुंच गया है, जिस पर नई क्षमताओं के निर्माण में निवेश किया जाता है। वित्त वर्ष 23 के अप्रैल–दिसंबर के दौरान उत्पादन क्षेत्र में घोषित नया निवेश, वित्त वर्ष 20 में इसी स्तर का पांच गुना था। पिछले कई वर्षों में सरकार द्वारा की गई नीतिगत कार्रवाइयों के लिए निवेश में वृद्धि भी जिम्मेदार है। वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में एक शुरुआत की गई है, जिसने वित्त वर्ष 2015 के बाद से सभी छमाहियों में सकल घरेलू उत्पाद में सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) का उच्चतम हिस्सा दर्ज किया है।

चित्र IX.1: उत्पादन क्षेत्र में बढ़ता निजी निवेश

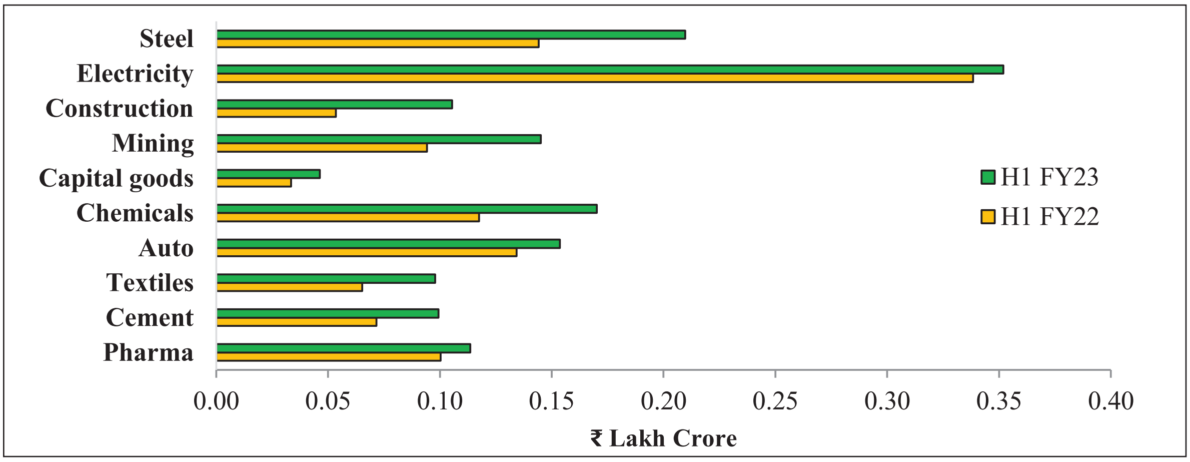

स्रोत: कैपेक्स डेटाबेस, सीएमआईई

बॉक्स IX.1: निजी पूंजी निवेश चक्र का विकास

एक दृष्टिकोण तेजी से उभर रहा है कि निजी क्षेत्र नई सहस्राब्दी के तीसरे दशक में निवेश बढ़ाने के लिए तैयार है। इसकी जड़ें नई सहस्राब्दी के पहले दशक में स्थित हैं जब एक क्रेडिट बूम ने निवेश दरों के बढ़ते स्तरों को वित्तपोषित किया। परिणामस्वरूप, जब तक दूसरा दशक शुरू हुआ, कॉरपोरेट और बैंकों दोनों की बैलेंस शीट दबावग्रस्त हो गई। परिणामस्वरूप, कॉरपोरेट्स ने निवेश से ध्यान हटाकर कर्ज चुकाने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि बैंकों ने उच्च गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को देखते हुए ऋण संवितरण को धीमा कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, निवेश दर कम हो गई तथा अर्थव्यवस्था धीमी होनी शुरू हो गई। दूसरे दशक के मध्य में, समस्याओं की पहचान की गई और शमन उपाय शुरू किए गए। बैंकों के लिए, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) को उनकी दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान करने के लिए स्थापित किया गया था, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के इक्विटी आधार को मजबूत किया गया था। कॉरपोरेट्स के लिए, GST रोलआउट ने उनके व्यवसाय करने में सुलभता में सुधार किया, जबकि निवेश के वित्तपोषण के लिए उनके लाभ/निवेश योग्य भंडार को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर को घटा दिया गया था। महामारी के दौरान, ईसीएलजीएस के कार्यान्वयन ने एमएसएमई को अतिरिक्त सहायता प्रदान की। परिपक्व होती डिजिटल अवसंरचना और आसान और सस्ते डेटा एक्सेस ने निवेश के माहौल को और समृद्ध किया है।

चित्र A: निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र द्वारा उत्तोलन

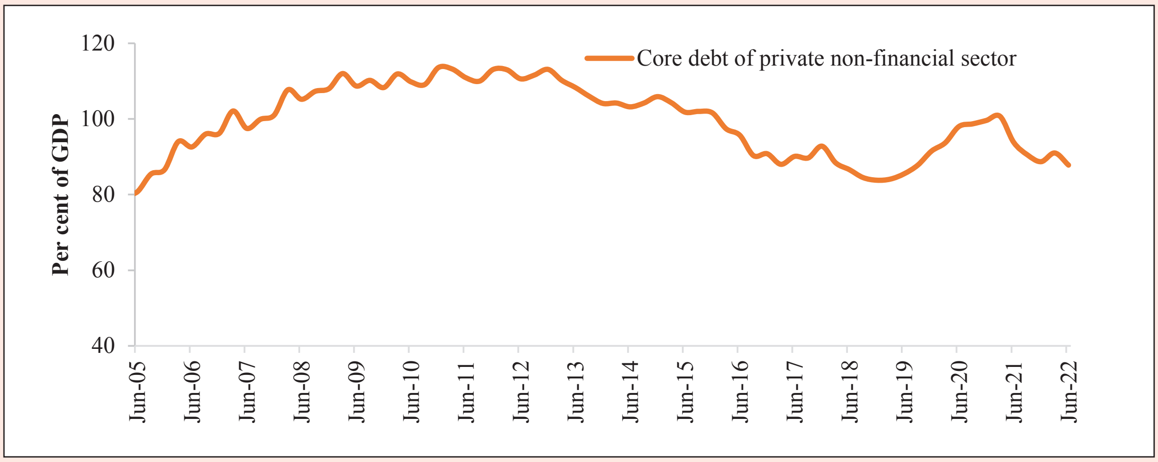

स्रोत: बीआईएस

नोट: गैर-वित्तीय क्षेत्र के लिए ऋण निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र की उधारी गतिविधि को आकर्षित करता है।

ऋण में कमी ने कॉर्पोरेट बैलेंस शीट को मजबूत किया है, जैसा कि निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र के कम होते मूल ऋण से स्पष्ट है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र के लिए ऋण दिसंबर 2010 में 113.0 प्रतिशत के शिखर से दिसंबर 2018 में 83.8 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गया था। इससे पता चलता है कि ऋण में कमी अंत तक पूरा हो गई थी। मई 2019 में चुनावों और सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की घोषणा के साथ, यह निवेश और आर्थिक विकास चक्रों में सुधार के रूप में परिणत हुआ होता लेकिन महामारी के कारण हुए व्यवधान के कारण इसमें दो वर्ष का विलम्ब हुआ। बेहतर कॉर्पोरेट प्रदर्शन और जीडीपी में सुधार के कारण निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र के मुख्य ऋण के रूप में वित्त वर्ष 2022 की शुरुआत से ऋण में कमी फिर से प्रारंभ हुई जो मार्च 2021 की तिमाही में 100.7 प्रतिशत थी वह जून 2022 की तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 87.8 के स्तर तक घट गई।

वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही के दौरान, ब्याज कवरेज अनुपात 5 था, जो इसके पांच वर्ष (वित्त वर्ष 20) के औसत 3 से अधिक था। ऋण-इक्विटी अनुपात भी 0.8 से घटकर 0.4 हो गया। इन सुधारों ने वैश्विक पण्य कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति श्रंखला व्यवधानों से प्रेरित कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं में वृद्धि को और अधिक अवशोषित कर लिया है। दूसरी ओर, वित्त वर्ष 2011 की दूसरी छमाही में लाभ अंतर चरम पर था क्योंकि कम मुद्रास्फीति ने इनपुट लागत को बढ़ने से रोक दिया, जबकि सीमित गतिशीलता ने उपरिव्यय को कम कर दिया। इसके बाद, लाभ अंतर में गिरावट शुरू हो गई क्योंकि बढ़ती वैश्विक पण्य कीमतों के कारण इनपुट लागत में वृद्धि हुई। वैश्विक पण्य कीमतों में गिरावट के साथ, इनपुट लागत में गिरावट आना तय है, और लाभ अंतर के बढ़ने की उम्मीद है। मुनाफे में अपेक्षित वृद्धि और मजबूत बैलेंस शीट ने कॉर्पोरेट क्षेत्र को वित्तीय रूप से मजबूत और शुद्ध बिक्री बढ़ाने के विषय में आशावादी बना दिया है। जुलाई-सितंबर 2022 के दौरान आयोजित आरबीआई का औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण, वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही तक समाहित समयावधि के लिए उत्पादन, ऑर्डर बुक, रोजगार और लाभ अंतर के लिए आशावाद की ओर इशारा करता है।

चित्र B: निवल बिक्री के बढ़ने की उम्मीद है

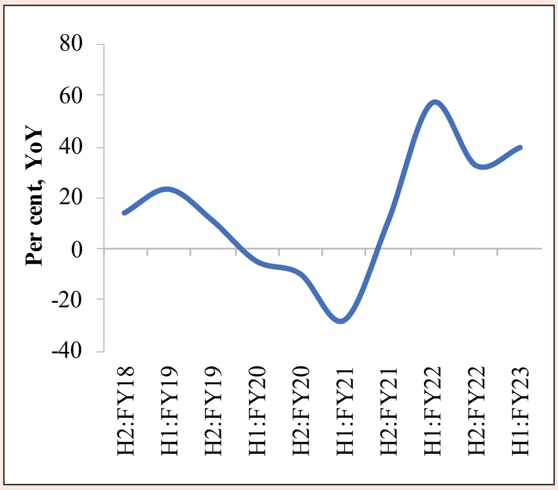

चित्र C: लाभ अंतर में सुधार हो रहा है

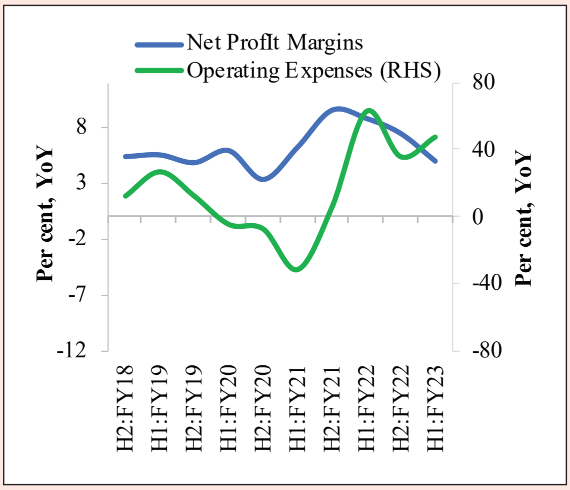

चित्र D: आंशिक रूप से मजबूत नकदी और लाभ

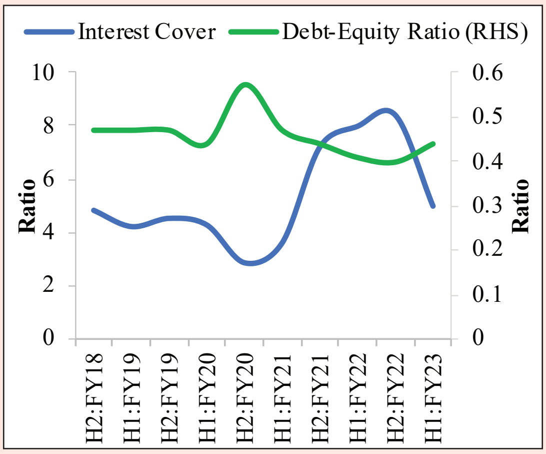

स्रोत: सीएमआईई

चित्र E: क्षमता उपयोग तथा व्यवसाय की आशा

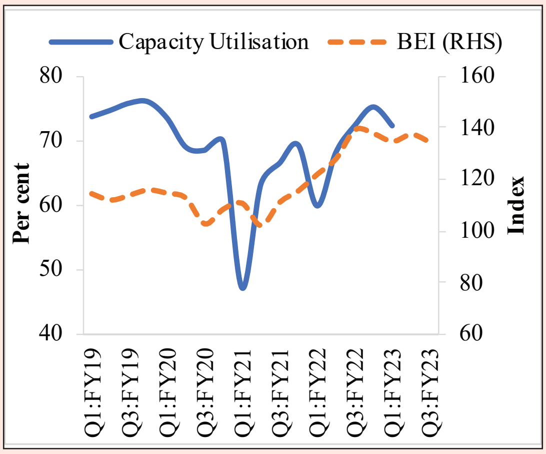

स्रोत: आरबीआई

नोट: बीईआई से तात्पर्य व्यवसाय अपेक्षा सूचकांक है

पहले दशक में क्रेडिट बूम ने गैर-वित्तीय क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र की अग्रिमों को 2004 में सकल घरेलू उत्पाद के 36.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 2014 में 57.3 प्रतिशत (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स) कर दिया। जिसके कारण आरबीआई ने एनपीए का अधिक कड़ा मूल्यांकन लागू किया। परिणामत:, एनपीए वित्त वर्ष 2015 में सकल बैंक अग्रिमों के 4.3 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 18 में 11.2 प्रतिशत हो गया। तथापि, आईबीसी कोड के प्रवर्तन और ऋण संवितरण के लिए अधिक अनुशासित दृष्टिकोण के साथ, एनपीए वित्त वर्ष 21 में 7.3 प्रतिशत और सितंबर 2022 में सात वर्ष के निचले स्तर 5.0 प्रतिशत पर आ गया। पूंजी-से-जोखिम-भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) और प्रावधान कार्यक्षेत्र अनुपात (पीसीआर) में भी सुधार हुआ है और ये सितंबर 2022 में क्रमश: 16.0 प्रतिशत और 71.5 प्रतिशत पर रहे। उचित रूप से पूंजीकृत बैंक, उधार देने के लिए तैयार और इच्छुक हैं और कॉरपोरेट्स वित्तीय रूप से मजबूत और उधार लेने के इच्छुक हैं, ऋण-निवेश चक्र तीसरे दशक में तेजी के लिए तैयार है।

उद्योग की आपूर्ति प्रतिक्रिया

7. मांग प्रोत्साहन के लिए उद्योग की आपूर्ति प्रतिक्रिया मजबूत रही है, जैसा कि उच्च-आवृत्ति संकेतकों में देखा गया है। उदाहरण के लिए, पीएमआई-उत्पादन, जुलाई 2021 से 18 महीनों के लिए विस्तारक क्षेत्र में बना हुआ है। दिसंबर 2022 में, पीएमआई-उत्पादन के उप-सूचकांकों ने, इनपुट लागत दबावों की आसान गति, आपूर्तिकर्ता वितरण समय में सुधार, मजबूत निर्यात आदेश और भविष्य के आउटपुट का संकेत दिया। इनपुट लागत मुद्रास्फीति में नरमी से भी उत्पादन कीमतों की गति में कमी आई है। हालाँकि, नए निर्यात आदेशों में विस्तार की गति में कमी आई, जो कि वैश्विक मांग में कमी को दर्शाता है।

8. उत्पादन आउटपुट की निरंतर वृद्धि समग्र आईआईपी उत्पादक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में ''दबी हुई'' खपत मांग के साथ देखी जा सकती है। पूंजीगत वस्तुओं और बुनियादी ढांचे/विनिर्माण वस्तुओं के उत्पादन में मजबूत वृद्धि अगले वित्तीय वर्ष में निजी क्षेत्र में निवेश चक्र की शुरुआत का संकेत है।

चित्र IX.2: पीएमआई उत्पादन विस्तारक क्षेत्र में बना हुआ है

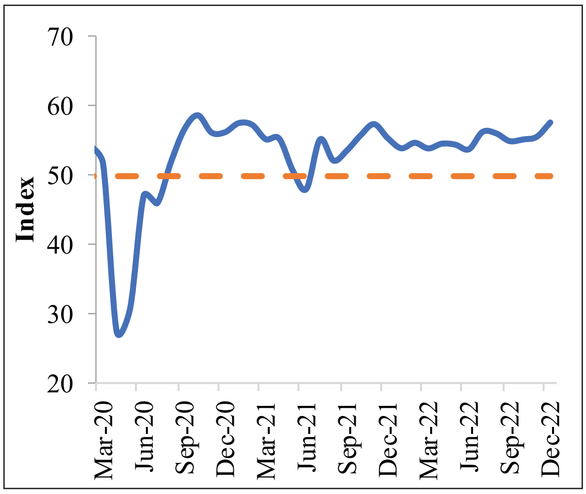

स्रोतः आईएचएस मार्किट

चित्र IX.3: आईआईपी के उप-सूचकांक मजबूत गति से बढ़ रहे हैं (अप्रैल-अक्टूबर)

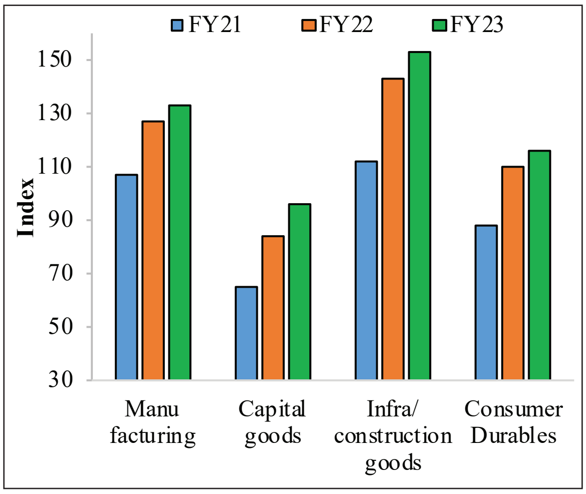

स्रोतः एमओएसपीआई

9. कोयला, उर्वरक, सीमेंट, स्टील, बिजली, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आठ प्रमुख उद्योग, उद्योगों में उत्पादन की मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण हैं। औद्योगिक गतिविधियों में व्यापक गति को दर्शाते हुए, इन उद्योगों में वृद्धि स्थिर रही है। उनकी वृद्धि इस महत्व को रेखांकित करती है कि राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने वाली महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद मूल क्षमताओं की स्वदेशी उपस्थिति से जुड़ रहे हैं।

चित्र IX.4: प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के घटकों में स्थिर वृद्धि

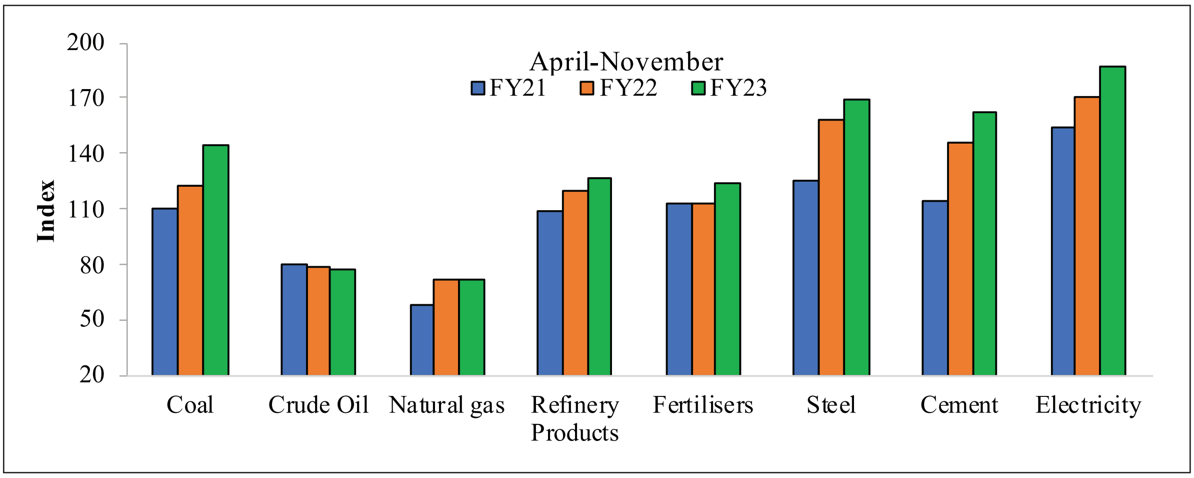

स्रोतः डीपीआईआईटी

10. औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि अधिक होती, लेकिन वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा। मौसमीपन, खनन और उत्खनन और विनिर्माण के संबंध में उत्पादन की वृद्धि को बाधित करने में भागीदार रहा, क्योंकि वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में कुल वर्षा वित्त वर्ष 22 की दूसरी तिमाही की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत अधिक थी। इसके अलावा, उच्च वर्षा के कारण तापमान ठंडा हो गया, बिजली की मांग घट गई और इसलिए उत्पादन वित्त वर्ष 22 की दूसरी तिमाही की तुलना में वित्त वर्ष 23 की दूसरी तिमाही में 5 प्रतिशत से भी कम बढ़ा।

चित्र IX.5: उच्च वर्षा द्वारा सीमित जीवीए निर्माण (विनिर्माण उत्पादन के लिए एक प्रॉक्सी)

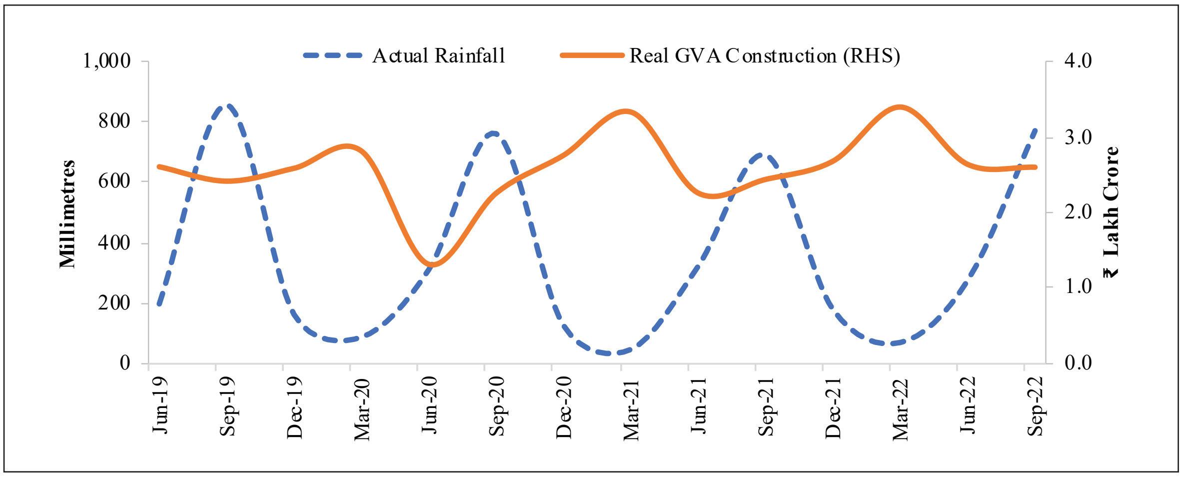

स्रोत: एमओएसपीआई

11. ऐसा प्रतीत होता है कि विनिर्माण उत्पादन, माल सूची में बड़े बिल्ड-अप से बाधित हुआ है। वित्त वर्ष 23 की दूसरी तिमाही में समाप्त होने वाली लगातार पांच तिमाहियों के लिए, भंडार में वार्षिक जीडीपी की 1.3 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई थी। विनिर्माण जीवीए (विनिर्माण उत्पादन के लिए एक प्रॉक्सी) के विकास के साथ-साथ भंडारों में बदलाख का एक विशिष्ट चक्र की तुलना बताती है कि भंडार में वृद्धि, मौजूदा मांग को पूरा करने वाले संचित भंडार के साथ अपनी गति को धीमा करने की अनुमति देती है। जब भंडार कम होने लगता है तो मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए विनिर्माण उत्पादन बढ़ता है और अगले चक्र की शुरुआत से पहले भंडार को भर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भंडार बिल्ड-अप ने दूसरी तिमाही में विनिर्माण उत्पादन की वृद्धि को बाधित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

चित्र IX.6: भंडार में बिल्ड-अप और बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितता के साथ जीवीए विनिर्माण धीमा है

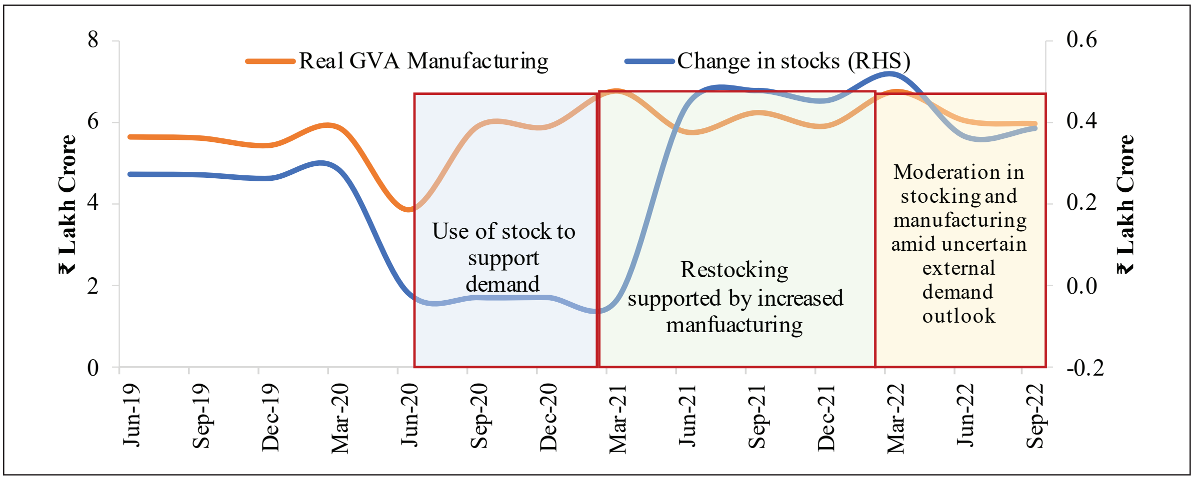

स्रोत: एमओएसपीआई; नोट: भंडारों में परिवर्तन से तात्पर्य जीएफसीएफ में बदलाख से है।

12. विनिर्माण परिदृश्य आगे विभिन्न श्रेणियों में असमान वृद्धि दर्शाता है। उदाहरण के लिए, मजबूत मांग और चिप की कमी को कम करते हुए मोटर वाहन निर्माण खंड के प्रदर्शन में सुधार जारी है। एक आगामी उद्योग, 'कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों' का निर्माण, भी बढ़ रहा है। भारत को सेमीकंडक्टर्स का निर्माण केंद्र बनाने की इच्छुक कई कंपनियों ने इस क्षेत्र में निवेश के दृष्टिकोण को सकारात्मक बना दिया है। कोक

और रिफाइंड पेट्रोलियम का उत्पादन भी बढ़ा है, जिससे वैश्विक बाजार में, जहां कच्चे तेल की कीमतें वित्त वर्ष 22 की तुलना में अधिक थीं वहाँ पर अधिक प्रतिलाभ मिल रहा है। कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों जैसे रसायन और रासायनिक उत्पादों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे निर्यात में वृद्धि के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में विकास की गति को बनाए रखने में योगदान मिला है। साथ ही, कपड़ा, परिधान और चमड़े सहित कुछ उत्पाद श्रेणियों में धीमी वृद्धि दिवाई दे रही है, क्योंकि वैश्विक उत्पादन और मांग में कमी के साथ इन उत्पादों की निर्यात मांग कम हो रही है। प्रतिकूल आधार प्रभाव और महामारी के प्रभाव के कम होने के कारण फार्मास्युटिकल उत्पादन में वृद्धि धीमी हो गई है।

Table IX.2: विनिर्माण क्षेत्रों में वृद्धि (प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

	<0		>0 but <5		>5

	भार	अप्रैल-22	मई-22	जून-22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्टूबर-22	नवंबर-22
खाद्य उत्पाद	5.3	3.8	10.1	5.1	-2.6	0.7	4.0	-3.7	9.9
पेय पदार्थ	1	29.2	130.3	45.7	13.1	6.4	12.3	2.7	8.2
तम्बाकू उत्पाद	0.8	22	21.4	52.7	-9.1	-12.8	-0.7	-14.3	-5.0
कपड़ा	3.3	-0.4	5.9	-3.1	-9.0	-12.5	-13.9	-18.7	-9.0
परिधान	1.3	55.2	69.9	42.6	15.1	-18.3	-21.6	-36.6	-11.7
चमड़ा एवं संबंधित उत्पाद	0.5	5	47.5	1.9	-13.5	-16.0	-17.5	-25.5	-2.0
लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, कार्क	0.2	4.1	54.1	14.4	7.9	-7.9	-3.7	-14.8	-0.5
कागज और कागज के उत्पाद	0.9	-1.9	9.7	8.3	-0.2	-0.1	6.2	-8.2	-2.3
रिकार्डेड मीडिया का मुद्रण और पुनरुत्पादन	0.7	30.1	43	45.1	41.2	27.6	29.1	13.5	22.1
कोक एवं परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद	11.8	10.6	18.1	17.4	7.2	6.6	9.7	-1.0	-9.8
रसायन और रसायन उत्पाद	7.9	4.4	24.3	14.8	7.2	5.7	6.4	-2.5	6.2
फार्मास्यूटिकल्स और औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	5	-5.5	-13.4	-4.6	-4.7	-17.6	-15.1	-21.2	10.0
रबड़ एवं प्लास्टिक उत्पाद	2.4	-1.5	8.7	5.7	-2.2	-4.4	-2.8	-2.1	5.6
अन्य गैर-धातु खनिज उत्पाद	4.1	6.9	22.1	19.6	0.0	1.4	9.7	-3.7	19.8
मूल धातु	12.8	6.9	16.5	7.2	6.7	4.0	5.7	4.4	8.1
निर्मित धातु उत्पाद,	2.7	-0.4	29.2	14.3	-4.1	-14.4	14.6	-11.8	8.2
कम्प्यूटर, इलैक्ट्रानिक और ऑप्टिकल उत्पाद	1.6	6.3	28.7	43.8	2.8	3.3	-0.2	-11.8	3.0
विद्युत उपकरण	3	8.3	59.6	11	-16.1	-28.5	-31.0	-33.0	1.2
मशीनरी और उपकरण एन.ई.सी.	4.8	5.4	38.8	19.9	4.1	2.9	6.4	-7.2	20.8

	भार	अप्रैल-22	मई-22	जून-22	जुलाई-22	अगस्त-22	सितंबर-22	अक्टूबर-22	नवंबर-22
मोटर वाहन, ट्रेलर और अर्ध–ट्रेलर	4.9	6.5	87.3	31.2	17.8	22.7	29.1	12.2	22.2
अन्य परिवहन उपकरण	1.8	-1.5	126.6	36.2	-1.2	7.8	14.8	-8.1	24.0
फर्नीचर	0.1	59.3	73.7	31.8	32.4	44.1	30.3	6.4	15.7
अन्य निर्माण	0.9	-3.2	18.5	26.4	6.9	4.2	4.8	-31.1	13.1

स्रोतः एमओएसपीआई

उद्योग के लिए बैंक ऋण में मजबूत वृद्धि

13. जनवरी 2022 से क्रमिक उछाल के साथ, बैंक ऋण में वृद्धि ने औद्योगिक विकास के साथ गति बनाए रखी है। एक ओर बैंक ऋण का एक बड़ा हिस्सा बड़े उद्योगों को सौंपा जा रहा है तो दूसरी तरफ ईसीएलजीएस की शुरूआत हो जाने से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को भी क्रेडिट में भी सहायता मिली है। राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसीएल), जो ईसीएलजीएस का संचालन करने वाली एजेन्सी है, के अनुसार लगभग 1.2 करोड़ व्यवसाय इस योजना द्वारा समर्थित हैं, जिनमें से 95 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं। परिणामतः, उद्योग के सकल ऋण में एमएसएमई[1] की हिस्सेदारी जनवरी 2020 के 17.7 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर 2022 में 23.7 प्रतिशत हो गई है। हालांकि कुल ऋण में वृद्धि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों द्वारा मांगे गए ऋण में वृद्धि से प्रेरित है तथापि, बड़े उद्योगों ने भी वित्त वर्ष 23 की शुरुआत से ऋण प्राप्त करने की गति को बढ़ाना शुरू कर दिया है। कॉरपोरेट बॉन्ड आय और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) के कम होने और कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में अधिक उतार–चढ़ाव रहने से ऐसा लगता है कि कॉरपोरेट, बॉन्ड मार्केट से फंडिंग के अपने स्रोतों को बैंक कैपिटल में शिफ्ट कर रहे हैं, जहां दरें स्थिर और पूर्वानुमेय बनी हुई हैं। बढ़ते क्षमता उपयोग और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के साथ ऋण मांग में मजबूत वृद्धि भविष्य की मांग के संबंध में व्यवसायों के आशावाद को रेखांकित करती है।

चित्र IX.7: एमएसएमई द्वारा संचालित उद्योग में दो अंकों की ऋण वृद्धि

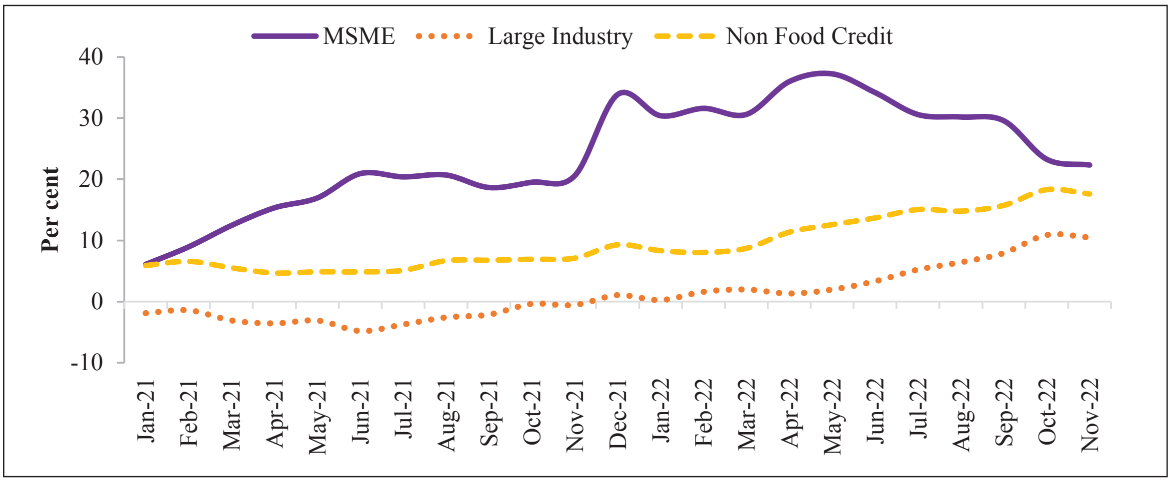

स्रोतः आरबीआई

1 As per the National Credit Guarantee Trustee Company Ltd. (NCGTCL), the agency which operates the ECLGS

Table IX.3: उद्योग उपखंडों में नियोजित ऋण में वृद्धि (प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

-23 0 65

उद्योग	नवंबर-21	अप्रैल-22	नवंबर-22
खनन एवं उत्खनन (कोयले सहित)	13.8	10.9	6.3
खाद्य प्रसंस्करण	6.1	10.7	7.4
पेय और तंबाकू	2.0	4.1	24.4
कपड़ा	8.6	7.1	3.0
चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	-1.7	7.3	5.9
लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद	6.6	8.4	15.9
कागज तथा कागज उत्पाद	8.4	9.3	6.6
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं परमाणु ईंधन	24.6	25.4	65.0
रसायन और रासायनिक उत्पाद	6.4	10.4	19.1
रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	23.3	26.4	18.4
कांच और कांच के बने पदार्थ	-13.2	-3.8	11.0
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	-23.4	-12.2	10.2
मूल धातु और धातु उत्पाद	-15.5	-4.4	15.3
इंजीनियरिंग	5.2	9.7	11.1
वाहन, वाहन के पुर्जे और परिखहन उपकरण	-2.0	6.8	8.3
रत्न और आभूषण	5.0	11.9	-1.2
निर्माण	-8.2	-6.5	2.1
आधारभूत संरचना	6.1	9.7	10.5
अन्य उद्योग	10.9	12.8	25.3

स्रोत: सर्वेक्षण गणना, भारतीय रिजर्व बैंक

14. कपड़ा उद्योग को छोड़कर विनिर्माण क्षेत्र के सभी खण्डों में नवंबर 2022 में ऋण के कुल ऋण में वृद्धि देखी गई। एक ओर ''पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन'', ''रबर, प्लास्टिक और उनके उत्पाद'', और ''इंजीनियरिंग'' जैसे क्षेत्रों में ऋण की मांग लगातार बनी रही है तो दूसरी ओर पिछले वर्ष में सीमेंट और निर्माण क्षेत्रों में ऋण की वृद्धि में हुआ सुधार निर्माण क्षेत्र के बेहतर दृष्टिकोण को दर्शाता है।

विनिर्माण क्षेत्र में लचीला एफडीआई अंतर्वाह

15. विनिर्माण क्षेत्रों में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह वित्त वर्ष 21 के 12.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 21.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। हालाँकि, रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद, वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में विनिर्माण में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा जो वित्त वर्ष 22 की पहली छमाही में प्राप्त 10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम था। ''कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर'',

''निर्माण गतिविधियां'', ''ऑटोमोबाइल उद्योग'', ''परामर्शी सेवाएं'', ''दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स'' और ''इलेक्ट्रॉनिक्स'' में प्रवाह कम रहा है। ''हालांकि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग'', ''चिकित्सा और सर्जिकल उपकरण ा'' ''शिक्षा'', ''सेवाएं'' और ''रेलवे'' में प्रवाह अधिक था।

चित्र IX.8: वैश्विक अनिश्चितता ने एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह को नियंत्रित किया

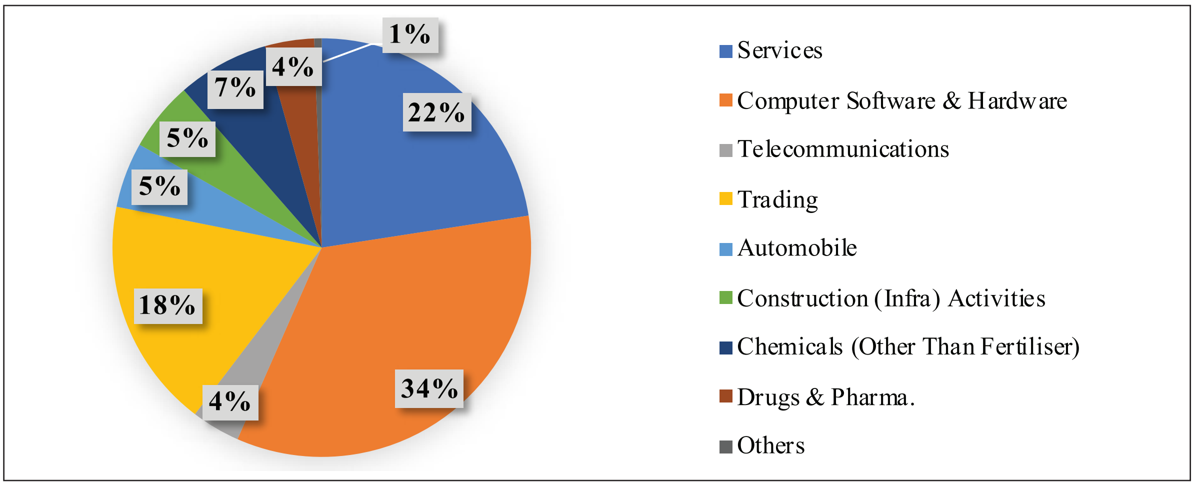

स्रोत: डीपीआईआईटी ऑकड़े

16. वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में एफडीआई में समग्र गिरावट के बावजूद, अंतर्वाह महामारी-पूर्व के स्तर से ऊपर रहा है, जो संरचनात्मक सुधारों और व्यापार करने में आसानी में सुधार के उपायों से प्रेरित है जिसके कारण भारत दुनिया एफडीआई के लिए सबसे आकर्षक गंतव्यों में से एक बन गया है। सरकार ने एक निवेशक-अनुकूल एफडीआई नीति लागू की है जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है। भारत ने, एफडीआई सीमा बढ़ाकर, नियामक बाधाओं को हटाकर, बुनियादी ढांचे के विकास और कारोबारी माहौल में सुधार करके अपने क्षेत्रों को वैश्विक निवेशकों के लिए खोलना जारी रखा हुआ है। इनसे आगे बढ़ते हुए, भारत में आने वाले पांच वर्षों में 475 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एफडीआई प्रवाह को आकर्षित करने की क्षमता है जो पिछले वर्षों[2] में किए गए संरचनात्मक सुधार और नीतिगत समर्थन के कारण बेहतर विकास संभावनाओं से संभव हो सकेगा।

बॉक्स IX.2: निवेश को बढ़ावा देने के लिए एफडीआई नीति में सुधार

- भारत ने एफडीआई सीमा बढ़ाकर और बढ़ते निवेश को आकर्षित करने के लिए नियामक बाधाओं को हटाकर, बुनियादी ढांचे के विकास और कारोबारी माहौल में सुधार के अलावा, वैश्विक निवेशकों के लिए अपने क्षेत्रों को खोलना जारी रखा हुआ है। भारत को अधिक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने के लिए सरकार ने रक्षा, पेंशन, ई-कॉमर्स गतिविधियों आदि जैसे सभी क्षेत्रों में कई क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी एफडीआई सुधारों को लागू किया है।
- प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन संबद्ध प्रसंस्करण अवसंरचना सहित कोयला खनन गतिविधियों के लिए कोयले की बिक्री के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई थी। डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और करंट अफेयर्स को अपलोड/स्ट्रीम करने के लिए सरकारी प्रणाली के अंतर्गत 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। मध्यस्थों या बीमा मध्यस्थों में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है और इनमें बीमा दलाल, फनर्बीमा दलाल, बीमा सलाहकार, कॉर्पोरेट एजेंट, तृतीय पक्ष प्रशासक, सर्वेक्षक और हानि निर्धारक तथा समय समय पर बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अधि सूचित अन्य संस्थाएं शामिल हैं।

- कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण/अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार ने एफडीआई नीति में संशोधन किया, जिसके अनुसार किसी देश की कंपनी जो भारत के साथ एक भू-सीमा साझा करती है या जहां भारत में निवेश का लाभकारी स्वामी स्थित है या ऐसे किसी देश का नागरिक है तो वह केवल सरकारी प्रणाली के अंतर्गत ही निवेश कर सकता है। इसके अलावा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में किसी कंपनी में किसी मौजूदा या भविष्य के एफडीआई के स्वामित्व के हस्तांतरण की स्थिति में, जिसके परिणामस्वरूप लाभकारी स्वामित्व कथित नीति संशोधन के प्रतिबंध/दायरे में आता है, लाभकारी स्वामित्व में इस तरह के बाद के परिवर्तन के लिए भी सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी।
- विदेशी निवेश की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, मई 2017 में पूर्ववर्ती विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को समाप्त कर दिया गया था और एक नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के तहत, एफडीआई अनुमोदन देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिसमें एफडीआई के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण से संबंधित कार्य, संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सौंपे गए हैं, तथा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए डीपीआईआईटी नोडल विभाग है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा हेतु निवेशकों के लिए, भारत सरकार के ऑनलाइन एकल-बिंदु इंटरफेस के रूप में एक नया पोर्टल, ''विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (एफआईएफ पोर्टल)'' लॉन्च किया गया है। पोर्टल उन आवेदनों की एकल खिड़की निकासी की सुविधा प्रदान करता है जो सरकारी अनुमोदन प्रणाली के माध्यम से होते हैं। एफआईएफ पोर्टल को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) के साथ एकीकृत किया गया है।

औद्योगिक समूह एवं उनकी चुनौतियां

महामारी से भली-भांति उबरने पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई)

17. हालांकि समग्र जीवीए में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 18 के 29.3 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 30.5 प्रतिशत हो गया था परन्तु महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 21 में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी घटकर 26.8 प्रतिशत रह गई। वित्त वर्ष 21 में विनिर्माण क्षेत्र के जीवीए में एमएसएमई का योगदान भी मामूली रूप से घटकर 36.0 प्रतिशत रह गया

एमएसएमई का हिस्सा

चित्र IX.9a: निर्यात में एमएसएमई की हिस्सेदारी

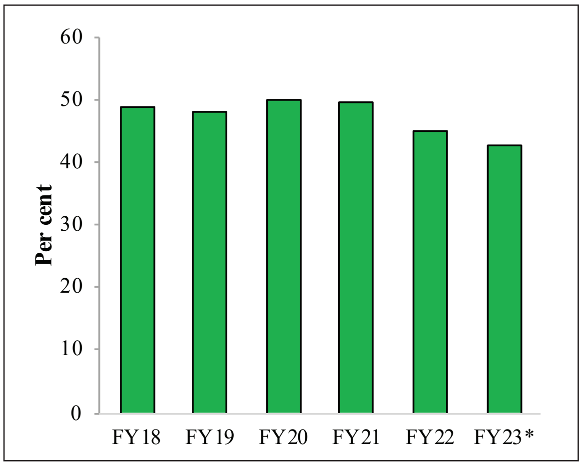

चित्र IX.9b: समग्र जीवीए और निर्माणकारी जीवीए में एमएसएमई की हिस्सेदारी

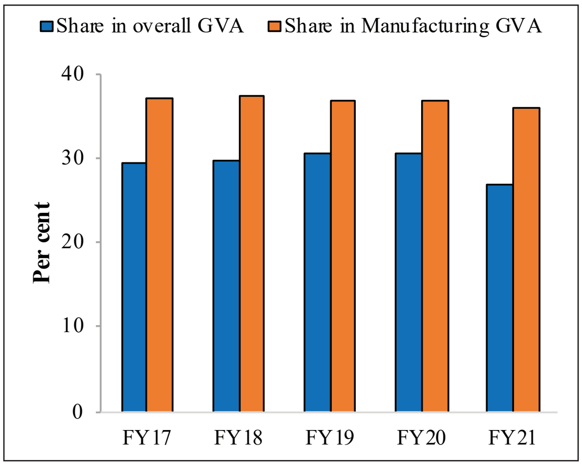

स्रोत: एमओएसपीआई, डीजीसीआई एण्ड एस
Note: *Data for FY23 is until Aug 2022

18. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से, सरकार ने एमएसएमई पर महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। किए गए कुछ उपायों में, एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन; विपदग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये के गौण ऋण का प्रावधान, आत्मनिर्भर भारत फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये इक्विटी इन्फ्यूजन; 200 करोड़ रुपये तक की खरीद के लिए वैश्विक निविदा आवश्यकता की छूट; एमएसएमई पंजीकरण के लिए उद्यम पोर्टल की शुरूआत, एक कागजरहित, मुफ्त पंजीकरण पोर्टल जो स्व-घोषणा पर आधारित है और इसके लिए केवल आधार की आवश्यकता होती है, उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण अगस्त 2022 में एक करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है, जो पिछले 14 वर्षों में पुरानी व्यवस्था के तहत किए गए कुल पंजीकरण को केवल 2.5 वर्षों में पार कर गया। 7 जनवरी 2022 तक, पोर्टल की कुल पंजीकरण संख्या 1.32 करोड़ है, जिसमें से 1.27 करोड़ को सूक्ष्म उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमों में 9.6 करोड़ लोग कार्यरत हैं, जिनमें से 2.3 करोड़ महिलाएं हैं। 1.5 लाख निर्यात इकाइयाँ हैं, जिन्होंने कुल 9.7 लाख करोड़ रुपये के निर्यात में योगदान दिया है।

19. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम के तहत एमएसएमई क्षेत्र की बकाया राशि की निगरानी के लिए स्थापित समाधान पोर्टल की सरकार की पहल, एमएसएमई को उनकी नकदी प्रवाह की कठिनाइयों को हल करने में मदद कर रही है। 7 जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार, पोर्टल को कुल 1.3 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 16.8 प्रतिशत का निपटान किया जा चुका है, जबकि 25.0 प्रतिशत वर्तमान में विचाराधीन हैं और 25.1 प्रतिशत को खारिज कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, सरकार ने सीपीएसई और 200 करोड़ रुपये या उससे अधिक के कारोबार वाली सभी कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे एक से अधिक वित्तदाताओं के माध्यम से एमएसएमई की व्यापार प्राप्तियों की छूट की सुविधा के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म पर स्वंय को लाएं। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जून 2020 में शुरू किए गए एमएसएमई के लिए सिंगल-विंडो शिकायत निवारण पोर्टल चौंपियन्स को, 24 मार्च 2022 तक 44,637 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 44,399 शिकायतों का जवाब दे दिया गया है। 11 क्षेत्रीय भाषाओं में पोर्टल के स्थानीयकरण और चौट बॉट की शुरूआत जैसी पहलों के माध्यम से पोर्टल में सुध ार जारी है।

20. सरकार ने वित्त वर्ष 23 में एमएसएमई के प्रदर्शन के उत्थापन और बढ़ाने (आरएएमपी) की पहल भी की है। विश्व बैंक समर्थित योजना का उद्देश्य केंद्र और राज्य में संस्थानों और शासन व्यवस्था को मजबूत करना, केंद्र-राज्य संबंधों और साझेदारी में सुधार करना और एमएसएमई की बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन और विलंबित भुगतान के मुद्दों को हल करना और एमएसएमई का कायाकल्प करना है। रैंप (आरएएमपी) कार्यक्रम पांच साल की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा। योजना के लिए कुल परिव्यय 6,062.4 करोड़ रुपये है, जिसमें से 3750 करोड़ रुपये विश्व बैंक से ऋण होगा और शेष 2312.4 करोड़ रुपये का वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा होगा।

21. सरकार द्वारा शुरू किए गए उपायों ने एमएसएमई क्षेत्र के लचीलेपन में मदद की है। राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कॉरपोरेशन (एनसीजीटीसी) के ऑकड़ों से पता चलता है कि 30 नवंबर 2022 तक, 1.2 करोड़ एमएसएमई इकाइयों ने आपदकालिक ऋण-व्यवस्था गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का लाभ उठाया और संपार्श्विक-मुक्त संसाधनों को 3.6 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया। सीबिल (सीआईबीआईएल) की एक हालिया[2] रिपोर्ट से पता चला है कि ईसीएलजीएस का लाभ उठाने वाले 83 प्रतिशत उधारकर्ता सूक्ष्म-उद्यम थे और इनमें से आधे से अधिक उधारकर्ताओं का ऋण जोखिम 10 लाख रुपये से कम था। ईसीएलजीएस का लाभ उठाने वाले एमएसएमई उधारकर्ताओं की श्रेणी के लिए बैंकों में एनपीए की दर उस श्रेणी से कम थी जिसने योजना का

2 https://www.transunioncibil.com/resources/tucibil/doc/insights/reports/eclgs-insights-report.pdf

लाभ नहीं उठाया था। महामारी के झटके से एमएसएमई क्षेत्र की रिकवरी एमएसएमई इकाइयों द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी के रुझान से स्पष्ट है। वित्त वर्ष 22 में क्षेत्र द्वारा किया गया भुगतान, वित्त वर्ष 20 में महामारी से पहले के स्तर को पार कर गया है।

चित्र IX.10: वित्त वर्ष 22 में एमएसएमई द्वारा जीएसटी भुगतान, महामारी-पूर्व स्तर को पार कर गया है।

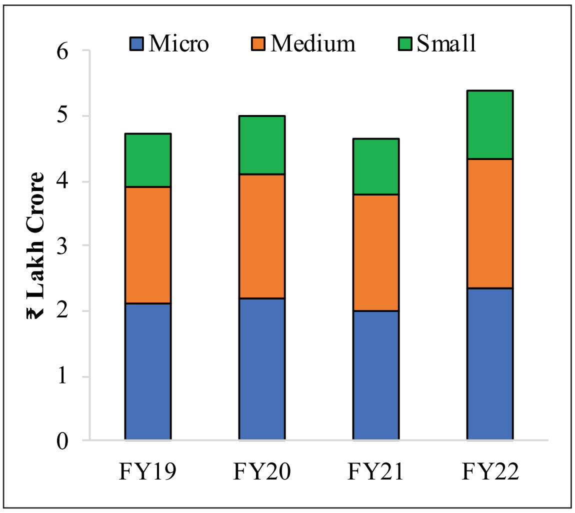

स्रोत: वित्त मंत्रालय

नोट: 1000 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर तक वाली कंपनियो सहित। सूक्ष्म -- <= 25करोड; लघु <= 25 से 100 करोड.; मध्यम 100 से 1000 करोड़।

चित्र IX.11: ईसीएलजीएस सहायता प्राप्त एमएसएमई, उनकी संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार

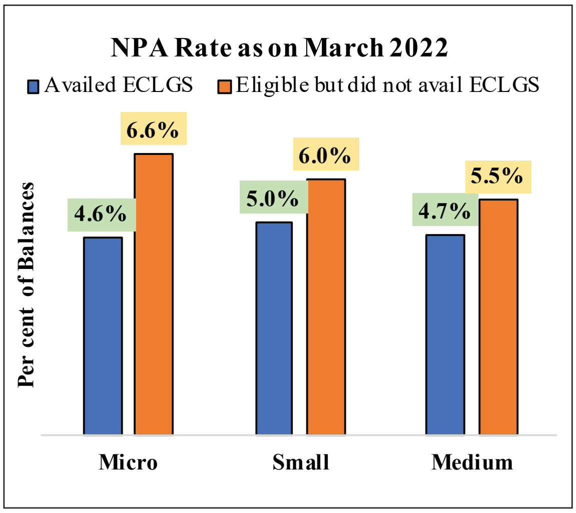

स्रोत: ईसीएलजीएस इनसाइट्स रिपोर्ट4, ट्रांसयूनियन सिबिल, अगस्त 2022

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, विनिर्माण उत्पादन और निर्यात का होने वाला प्रमुख प्रेरक

22. इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का महत्व लगातार बढ़ रहा है क्योंकि इसके अनुप्रयोग व्यापक हो गए हैं, विशेष रूप से किसी देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में। संचार सेवाओं में होते निरंतर सुधार द्वारा समर्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्पादकता, कुशल सेवा वितरण और सामाजिक परिखर्तन में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। वित्त वर्ष 2020 तक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का मूल्य 118 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत का लक्ष्य 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनना है और इस विजन को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 26[3] तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और 120 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के निर्यात तक पहुंचने का लक्ष्य है। पिछले पांच वर्षों में विनिर्माण और निर्यात में सुधार सुनिश्चित करता है कि भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पर अग्रसर है। इलेक्ट्रॉनिक सामान अक्टूबर 2022 में सकारात्मक निर्यात वृद्धि प्रदर्शित करने वाले आवश्यक वस्तुओं के शीर्ष पांच समूहों में शामिल थे, इस खंड में निर्यात में (वर्ष-दर-वर्ष) 37.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

23. इस उद्योग में विकास के प्रमुख प्रेरक मोबाइल फोन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। मोबाइल फोन खंड में, भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है, जिसके हैंडसेट का उत्पादन वित्त वर्ष 2015 के छह करोड़ यूनिट से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 31 करोड़ यूनिट हो गया है। अधिकाधिक घरेलू और वैश्विक उत्पादकों द्वारा भारत में अपने केंद्र स्थापित और विस्तारित करने से इन

3 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1792189

संख्याओं में सुधार होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवाओं में दो प्रमुख वैश्विक और घरेलू उत्पादक, फॉक्सकॉन और डिक्सन, पहले ही पीएलआई योजना[4] को अपना चुके हैं। डिक्सन की तरह, पीएलआई योजना में भागीदारी से कई और घरेलू उत्पादकों को स्थानीयकरण के माध्यम से उत्पादन में बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। इसलिए, इससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और बढ़ेगी और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। उद्योग 4.0 में, बेहतर डिजिटलीकरण और रोबोटिक्स अनुप्रयोगों के कारण औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भी वृद्धि देखी जा रही है। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट सिटीज और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर जोर दिए जाने से, स्मार्ट और स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग सुव्यवस्थित होगी।

चित्र IX.12: इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में मजबूत वृद्धि (अप्रैल-अक्टूबर)

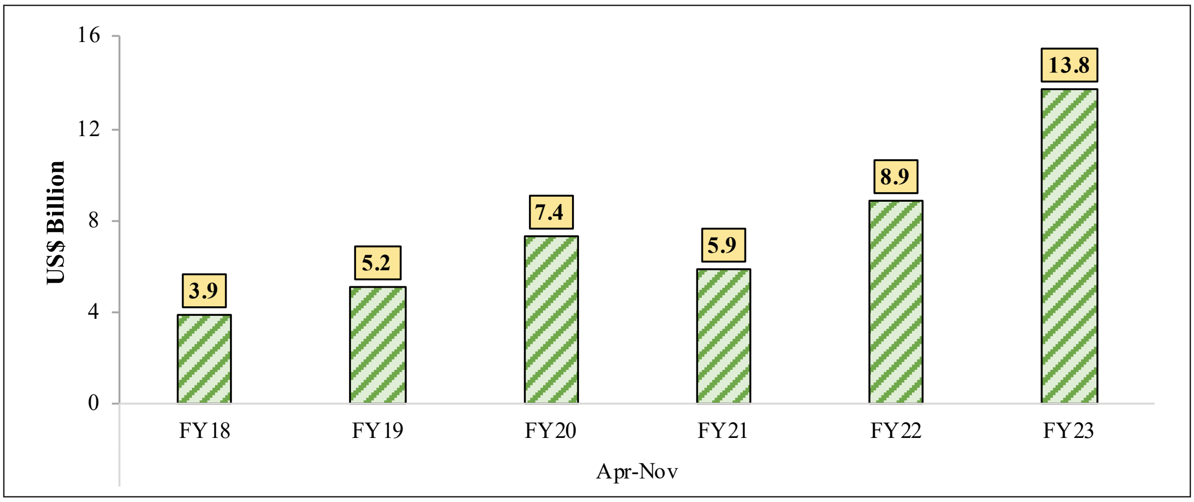

स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस

24. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण आधार को पोषित करने और बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ पहलों और प्रोत्साहनों में, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना, आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सेमीकंडक्टर्स (स्पेक) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना शामिल है। इसके अलावा, भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए कार्यक्रम के तहत, कैबिनेट ने 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ देश में एक स्थायी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र के व्यापक विकास को मंजूरी दी है, जिसका विवरण बॉक्स 3 में दिया गया है। इन योजनाओं और पहलों से भारत की विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलने, आयात पर निर्भरता कम होने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक प्रमुख भागीदार बनने की देश की महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में भी योगदान मिलने की उम्मीद है।

बॉक्स IX.3: अमेरिका और भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन

कोविड-19 महामारी से वैश्विक आर्थिक सुधार ने कई वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखलाओं में कमजोरियों को उजागर किया है। एक उत्पाद जो सुर्खियों में था वह सेमीकंडक्टर (जिसे आमतौर पर 'चिप्स' के रूप से जाना जाता है) था और इसकी कमी का प्रभाव वैश्विक स्तर पर मोटर वाहन उद्योग में विशेष रूप से बढ़ा था। अब जबकि स्थिति पूर्ववत हो चुकी है और इसने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए देशों द्वारा नीतिगत प्रतिक्रिया को प्रेरित किया है।

4 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1885189

सबसे उल्लेखनीय नीतियों में से एक, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सेमीकंडक्टर्स एण्ड साइंस एक्ट, 2022 (चिप्स एण्ड साइंस एक्ट, 2022) को तैयार करने के लिए प्रोत्साहन सहायता देना है। कानून का उद्देश्य अमेरिका की घरेलू सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता में निवेश को प्रेरित करना है। देश दुनिया के अर्धचालकों का लगभग 10 प्रतिशत उत्पादन करता है और चिप्स आयात करने के लिए पूर्वी एशिया पर बहुत अधिक निर्भर करता है। चिप्स एण्ड साइंस एक्ट में अगले दस वर्षों में 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर वर्च करने की बात कही गई है, जिसमें से अधिकांश अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) में किया जाना है।

चित्र A: चिप्स एण्ड साइंस एक्ट, 2022 के अधीन प्रोत्साहन

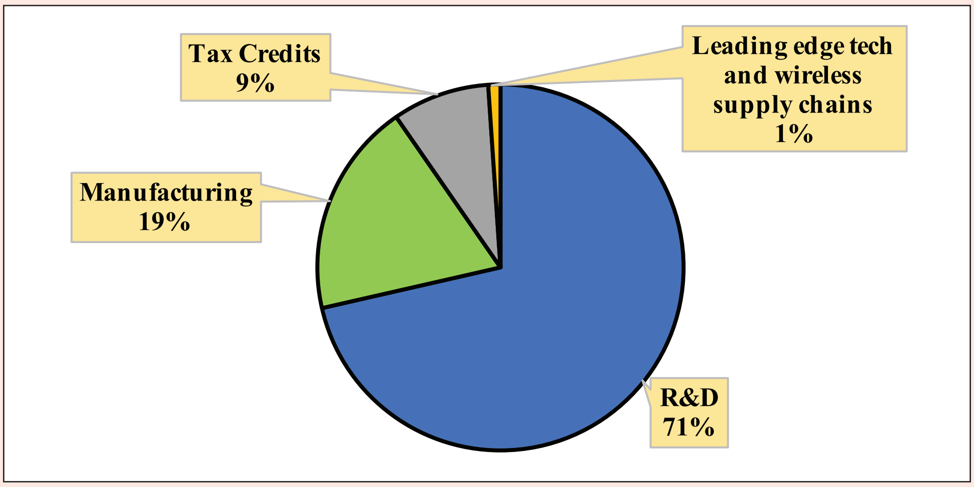

स्रोत: whitehouse.gov.in; मैककिनसे एंड कंपनी

आत्मनिर्भरता की खोज में और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में स्वंय को जोड़ने के उद्देश्य से, भारत ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु निवेश आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहनों की घोषणा की है। इस दिशा में, सितंबर 2022 में भारत सरकार द्वारा 76,000 करोड़ रुपये (लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के परिव्यय के साथ एक व्यापक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी। सरकार, निवेश कंपनियों द्वारा किए जाने वाले पूंजीगत व्यय के 50 प्रतिशत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

Table A: सेमीकंडक्टर योजना के अधीन अनेक प्रोत्साहन

के लिए योजना	वित्तीय समर्थन	रिसर्च एवं अनुसंधान समर्थन
भारत में सेमीकंडक्टर फैब की संस्थापना करने हेतु	कंपनी के कैपेक्स का 50 प्रतिशत	योजना परिव्यय का 2.5 प्रतिशत तक
डिस्प्ले फैब्स के संस्थापन हेतु	कंपनी के कैपेक्स का 50 प्रतिशत	योजना परिव्यय का 2.5 प्रतिशत तक
कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/संसर फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना	कंपनी के कैपेक्स का 50 प्रतिशत	योजना परिव्यय का 2.5 प्रतिशत तक

स्रोत: इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

नोट: एटीएमपी से तात्पर्य असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग है। ओएसएटी से तात्पर्या आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट है

यह जानते हुए कि भले ही भारत के पास दुनिया के सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों का 20 प्रतिशत है, लेकिन बौद्धिक संपदा (आईपी) में एक मामूली हिस्सेदारी है, भारत सरकार ने डिजाइन लिंक्ड-इंसेंटिव (डीएलआई) योजना की भी घोषणा की है। योजना के उद्देश्यों में अर्धचालक डिजाइन की घरेलू कंपनियों का पोषण और उन्हे सुविधा प्रदान करना, देश भर में तैनात अर्धचालक उत्पादों और आईपी के महत्वपूर्ण स्वदेशीकरण को प्राप्त करना और डिजाइन के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है। इस योजना में, डिजाइन पर प्रति आवेदक 15 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन, उपयुक्त व्यय के 50 प्रतिशत की वित्तीय सहायता और प्रति आवेदक 30 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन पांच वर्षों में प्राप्त शुद्ध बिक्री का 4 से 6 प्रतिशत नियोजनबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

यद्यपि ये शुरुआती चरण हैं, वैश्विक और घरेलू उत्पादकों ने भारत में अर्धकुशल उद्योग की संभावनाओं और प्रदान किए गए वित्तीय प्रोत्साहनों के आधार पर रुचि दिखाई है। इजराइल स्थित इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम ने भारत का पहला चिप बनाने वाला संयंत्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक में 22,900 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। वेदांता और टाटा जैसी घरेलू कंपनियों ने भी देश में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने की योजना का संकेत दिया है।

कोयला उद्योग: अस्थिर समय के दौरान ऊर्जा आत्मनिर्भरता बनाए रखने की कुंजी

25. वित्त वर्ष की शुरुआत में, आर्थिक गतिविधियों में पुनरुत्थान और मार्च 2022 के मध्य से मई के मध्य तक हीट वेब के चलने के कारण, भारत के बड़े पैमाने पर थर्मल-आधारित बिजली उत्पादन संयंत्रों के लिए कोयले की उपलब्धता एक चुनौती बन गई, जिससे देश में ऊर्जा की मांग बढ़ गई। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय कोयले की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा क्षेत्र ने वित्त वर्ष 20 में 69 मीट्रिक टन से वित्त वर्ष 21 में 45 मीट्रिक टन और आगे वित्त वर्ष 22 में 27 मीट्रिक टन तक कोयले के आयात में भारी कमी की। चूंकि, घरेलू कोयला उत्पादन, बिजली पैदा करने वाले संयंत्रों की बढ़ती मांग के साथ गति बनाए नहीं रख सका अत: इसकी उपलब्धता सीमित हो गई। परिणामस्वरूप, अप्रैल 2022 में, भले ही कोयले की मांग, अधिक मांग को पूरा करने के लिए बढ़ी और 31 अप्रैल 2022 तक बिजली संयंत्रों के पास कोयले के भंडारण की समयसीमा, एक साल पहले के 12 दिनों से कम होकर, 8 दिन हो गई।

26. भारत सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर कोयले की आपूर्ति की बाधाओं को दूर करने के लिए अप्रैल और मई 2022 के दौरान कई कदम उठाए। सबसे पहले, सभी उत्पादकों को अपनी आवश्यकताओं के 10 प्रतिशत (पहले के 4 प्रतिशत के मुकाबले) तक कोयले का आयात करने के लिए कहा गया था। बिजली संयंत्रों के कोयले का आयात करने में किल रहने पर घरेलू कोयले की हकदारी में कटौती सहित दंड की घोषणा की गई। दूसरा, विद्युत अधिनियम 2003 (अधिनियम) की धारा 11 को लागू किया गया था जिसके अंतर्गत सभी आयातित कोयला आधारित संयंत्रों को निर्देशित किया गया था कि वे पूरी संचालन क्षमता से प्रचालन करें और उनकी बढ़ी हुई प्रचालन लागत की भरपाई की जाएगी। तीसरा, टोलिंग को सक्षम किया गया, जिसने राज्यों को अपने आवंटित कोयले को राज्य के उत्पादकों से बहुत दूर ले जाने के बजाय खानों के पास निजी उत्पादक को स्थानांतरित करने की अनुमति दी। इस कदम से रेलवे रेक की उपलब्धता पर बोझ कम हो गया। चौथा, आरईसी/पीएफसी तथा वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे बिजली उत्पादन संयंत्रों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करें।

चित्र IX.13: पर्याप्त कोयला उत्पादन

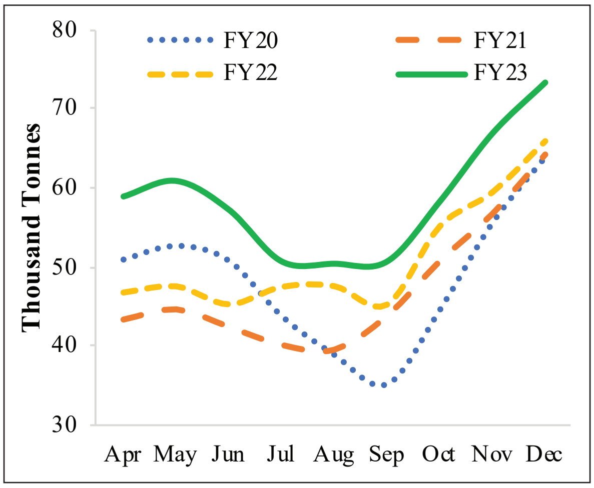

स्रोत: कोयला मंत्रालय

नोट: सीआईएल, एससीसीएल तथा कैप्टिव पावर प्लांट/अन्य द्वारा उत्पादन

चित्र IX.14: बढ़ता हुआ कोयला भंडार

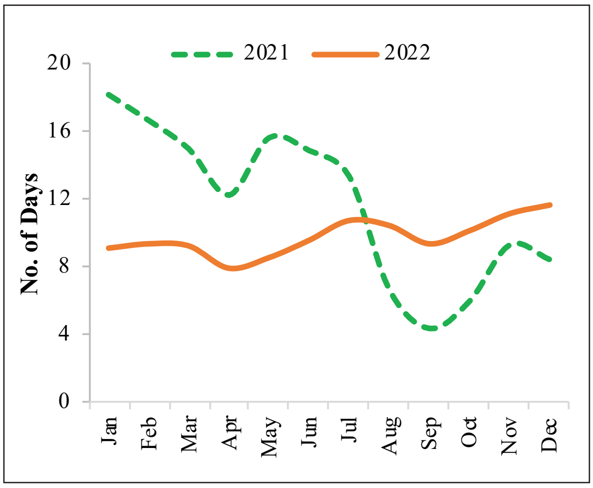

स्रोत: राष्ट्रीय ऊर्जा पोर्टल

27. समय रहते किए गए उपायों ने भारत को ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए बेहतर स्थिति में ला दिया है। वित्त वर्ष 23 के लिए कोयले का उत्पादन बढ़कर 911 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल-अक्टूबर, 2022 में, कोयले का उत्पादन साल-दर-साल आधार पर 18 प्रतिशत बढ़ा और महामारी-पूर्व के वित्त वर्ष 20 की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक था। इसके अलावा, बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार 30 जून 2022 को 10 दिनों और एक साल पहले 8 दिनों की तुलना में बढ़कर 30 दिसंबर 2022 तक 12 दिनों का हो गया है।

28. कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें कोयला उत्पादन में निजी भागीदारी, स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई, वाणिज्यिक उत्पादन के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी, मौजूदा खानों का विस्तार और नई खदानें खोलना, खनन में बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकी उपयोग, लोडिंग के लिए क्रिया-प्रणाली, निकासी के अवसंरचना का विकास आदि शामिल हैं।

29. कोयला उद्योग के वित्त वर्ष 26 तक 1 बिलियन टन और 2030 तक लगभग 1.5 बिलियन टन के उत्पादन स्तर तक पहुंचने के लिए सालाना 6-7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। बढ़े हुए घरेलू कोयले के उत्पादन से घरेलू कोयले की मांग को पूरा करने, प्रतिस्थापन योग्य आयातों को बदलने और निर्यात के बढ़ने की उम्मीद है। प्रणाली क्षमता उपयोग को लगभग 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत से ऊपर करने का लगातार प्रयास किया गया है।

इस्पात उद्योग को चलाने के लिए अवसंरचना क्षेत्र और निर्माण गतिविधि को फिर से सक्रिय करना।

30. इस्पात क्षेत्र निर्माण, अवसंरचना, ऑटोमोबाइल, अभियांत्रिकी और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले कुछ वर्षों में, इस्पात क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। देश अब इस्पात उत्पादन में एक वैश्विक शक्ति है और दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चालू वित्त वर्ष में इस्पात क्षेत्र का अप्रैल-अक्टूबर 2022 के दौरान क्रमशः 68 मीट्रिक टन और 66 मीट्रिक टन तैयार इस्पात के संचयी उत्पादन और खपत के साथ अच्छा प्रदर्शन रहा है, जो पिछले चार वर्षों की इसी अवधि की तुलना में अधिक

है। तैयार इस्पात उत्पादन में वृद्धि को खपत में दो अंकों की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11 प्रतिशत) से समर्थन मिला है, जो सरकार के बढ़े हुए कैपेक्स द्वारा संचालित अवसंरचना के क्षेत्र में तेजी से बढ़ा है।

31. इसके अलावा, विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत 30 कंपनियों के 67 आवेदनों का चयन किया गया है। यह लगभग 26 मिलियन टन की क्षमता में वृद्धि और लगभग 70,000 लोगों की रोजगार सृजन क्षमता के साथ 42,500 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश को आकर्षित करेगा। इसके अलावा, घरेलू स्टील निर्माताओं की स्थिर क्रेडिट प्रोफाइल, घटती-बढ़ती बैलेंस शीट और मजबूत नकद संचय समर्थन उनके कैपेक्स का समर्थन करना जारी रखता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से यूरोप और चीन में मंदी और घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए लगाए गए निर्यात शुल्क के कारण चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में लौह और इस्पात निर्यात में धीमापन आया है। फिर भी, वित्त वर्ष 2020 के महामारी-पूर्व के स्तर की तुलना में लोहे और इस्पात का निर्यात 68 प्रतिशत अधिक है।

चित्र IX.15: इस्पात उत्पादन और खपत में वृद्धि

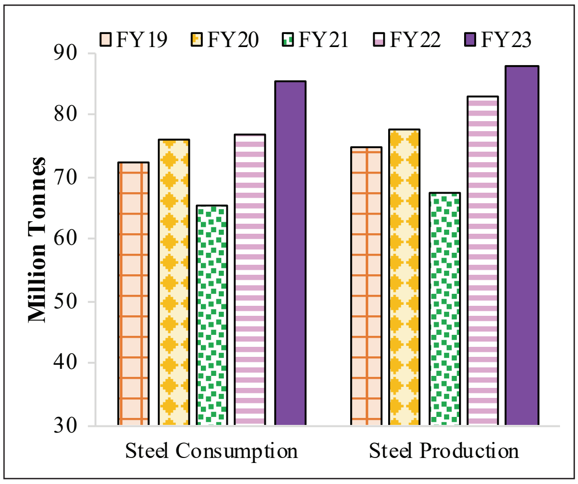

स्रोतः संयुक्त संयंत्र समिति, इस्पात मंत्रालय

चित्र IX.16: वित्त वर्ष 23 के दौरान लौह और इस्पात निर्यात में मामूली सुधार

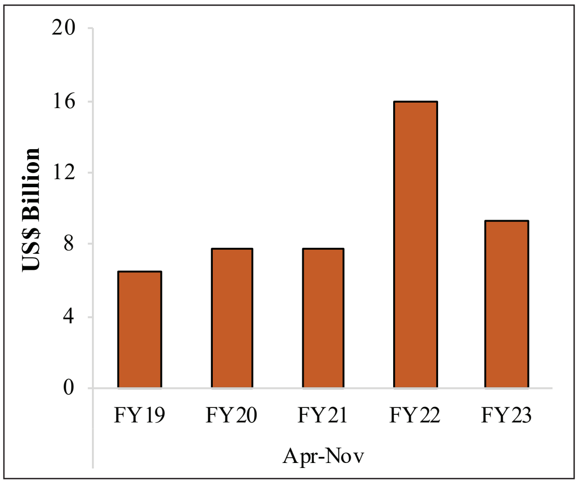

स्रोतः वाणिज्य विभाग

32. भविष्य में, अवसंरचना परियोजनाओं पर सरकार का जोर, निर्माण और रियल एस्टेट गतिविधि में तेजी और ऑटोमोबाइल क्षेत्र से मजबूत मांग इस्पात उत्पादों की मांग के लिए शुभ संकेत देती है। हालांकि, वैश्विक मंदी के साथ निर्यात मांग कमजोर रह सकती है, हालांकि घरेलू उपलब्धता में आसानी के बाद निर्यात शुल्क को हटाने से घरेलू स्टील उत्पादकों की निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो सकती है और बदले में निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है।

कपड़ा उद्योग को मौजूदा चुनौतियों से निपटने में सहायता के लिए सरकारी समर्थन।

33. कपड़ा उद्योग देश के रोजगार सृजन के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है, अनुमान के आधार पर 4.5 करोड़ लोग सीधे इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण आबादी शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष में, उद्योग, वित्त वर्ष 22 की तुलना में निर्यात में धीमी गति की चुनौती का सामना कर रहा है। हालाँकि, पहले छह महीनों में यह स्तर अभी भी महामारी-पूर्व के वित्त वर्ष 20 की इसी समयावधि की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि के दौरान रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यात में साल दर साल आधार पर 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कपड़ा क्षेत्र में एफडीआई का प्रवाह अभी भी पूर्व-महामारी के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है।

चित्र IX.17: कपड़ा निर्यात में कमी आई, जबकि रेडीमेड गारमेंट निर्यात में तेजी आई है।

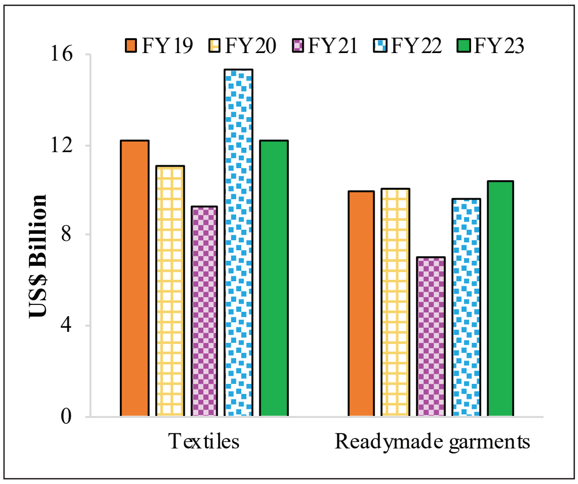

स्रोत: वाणिज्य विभाग

चित्र IX.18: कपड़ा उद्योग में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह अभी तक बहाल नहीं हुआ है

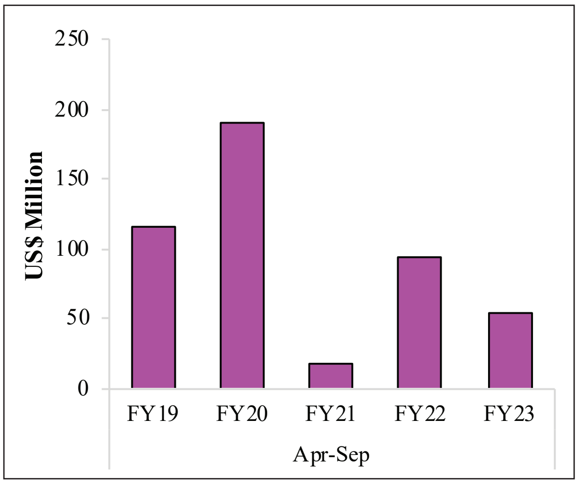

स्रोत: डीपीआईआईटी

34. कपड़ा उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए बड़े पैमाने पर एकीकृत और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधाओं को विकसित करने के लिए, सरकार ने सात पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। पार्क न केवल अवसंरचना लागत को कम और भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेंगे बल्कि रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देंगे, घरेलू निवेश और एफडीआई को आकर्षित करेंगे और भारत को वैश्विक कपड़ा बाजार में मजबूती से स्थापित करेंगे। पार्कों से कुल एक लाख प्रत्यक्ष और दो लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

35. इसके अलावा, उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने और मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) परिधान का उत्पादन बढ़ाने, एमएमएफ कपड़ों तथा तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले पांच वर्षों में 10,683 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ, कपड़ा पीएलआई योजना शुरू की है। यह, कपड़ा क्षेत्र को आकार और पैमाना हासिल करने में सक्षम बनाएगा, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। अब तक स्वीकृत 64 आवेदनों में, प्रस्तावित कुल निवेश प्रतिबद्धता 19,798 करोड़ रुपये है, जिसमें अनुमानित कारोबार और रोजगार सृजन क्रमशः 1.9 लाख करोड़ रुपये और 2.5 लाख करोड़ रुपये है। सरकार वर्तमान में वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाने के लिए पीएलआई 2.0 पर काम कर रही है जो कपड़ा मूल्य श्रृंखला में प्लेयर्स को प्रोत्साहन प्रदान करती है और इस उच्च विकास उद्योग खंड में भारत को पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करती है।

महामारी के बाद औषधि उद्योग में विकास की गति कायम है

36. भारतीय औषध उद्योग, वैश्विक औषध उद्योग में एक मुख्य भूमिका निभाता है। भारत के घरेलू औषध बाजार का 2021 में 41 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 2024 तक 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने और आगे 2030[5] तक 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। औषधीय उत्पादों के उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारत दुनिया भर में तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है। देश, वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, जो मात्रा के हिसाब से वैश्विक आपूर्ति में 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है और 60 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ वैश्विक स्तर पर अग्रणी वैक्सीन निर्माता है।

5 https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1660739

चित्र IX.19: औषधि निर्यात में मजबूत वृद्धि

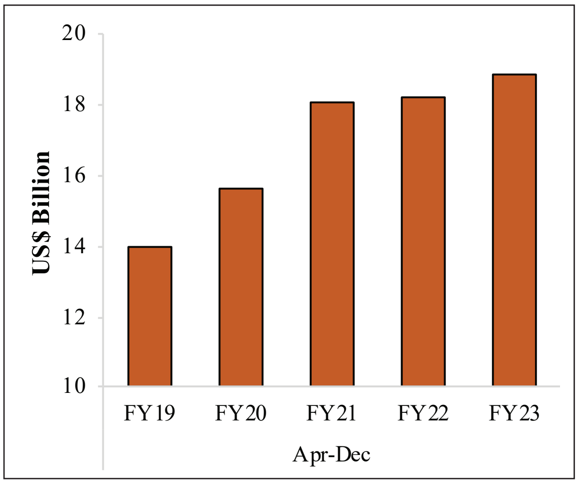

स्रोत: वाणिज्य विभाग

चित्र IX.20: औषध क्षेत्र में उच्च एफडीआई अंतर्वाह

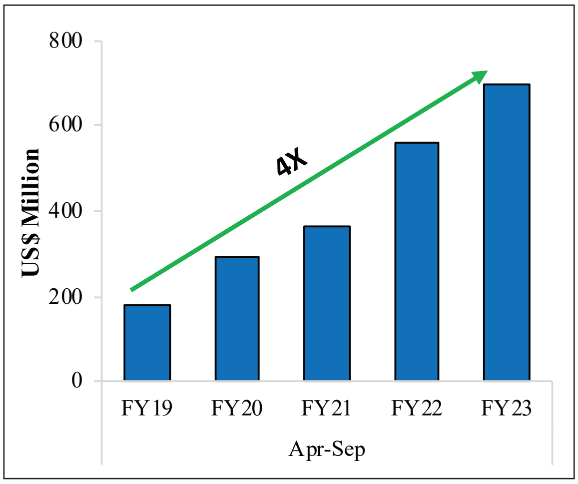

स्रोत: डीपीआईआईटी

37. भारतीय औषधि निर्यात ने वित्त वर्ष 2021 में 24 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हासिल की, जो 150 से अधिक देशों को की गई महत्वपूर्ण दवाओं और अन्य आपूर्ति के लिए कोविड-19-उद्भूत मांग से प्रेरित है। वैश्विक व्यापार व्यवधानों और कोविड-19 से संबंधित उपचारों की मांग में गिरावट के बावजूद वित्त वर्ष 22 में औषधि निर्यात का प्रदर्शन मजबूत रहा है और इसमें निरंतर वृद्धि हुई है। इस विकास गति को आगे बढ़ाते हुए, अप्रैल-अक्टूबर 2022 के दौरान दवा और औषध निर्यात, वित्त वर्ष 20 की इसी पूर्व-महामारी अवधि की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक था। सितंबर 2022 में औषधि क्षेत्र में संचयी एफडीआई 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गई है। इसके अलावा, सितंबर 2022 तक एफडीआई अंतर्वाह पांच वर्षों में चार गुना बढ़कर 699 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो निवेशक-अनुकूल नीतियों और उद्योग के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण द्वारा समर्थित है।

चित्र IX.21: औषधि क्षेत्र में विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए तीन पीएलआई योजनाएं

Critical KSMs/DIs/APIs

- **Tenure**:FY21 to FY30
- **Outlay**: ₹6,940 crore
- **Progress**: Until Dec 2022, 51 applicants approved with committed investment of ₹4,138.4 crore.
- **Employment**: Estimated employment generation from 51 projects is 10,598 persons.
- **Financial incentive**: NA

Medical Devices

- **Tenure**: FY21 to FY28
- **Outlay**: ₹3,420 crore
- **Progress**: Until Dec 2022, 21 applicants approved with committed investment of Rs 1,058.97 crore.
- **Employment**: Estimated employment generation from 21 projects of around 6,411 persons.
- **Financial incentive**: The financial incentive at the rate of 5 per cent on incremental sales of medical devices for 5 years.

Pharmaceuticals

- **Tenure**: FY21 to FY29
- **Outlay**: ₹15,000 crore
- **Progress**: Until June 2022, 55 applicants approved with actual investment of Rs 18,669 crore.
- **Employment**: Estimated employment generation from 55 projects : 20,000 direct and 80,000 indirect jobs.
- **Financial Incentive**: on incremental sales under various categories at varying rate over the years ranging from 10 per cent to 3 per cent.

Source: Department of Pharmaceuticals

38. सरकार ने औषधि क्षेत्र की अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। संबंधित योजना अर्थात औषधि उद्योग का सुदृढीकरण (एसपीआई), 11 मार्च 2022 को कई उद्देश्यों के साथ वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 26 तक पाँच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सर्वप्रथम औषधि समूहों को सामान्य सुविधाएं तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। दूसरा, यह एमएसएमई के पूंजी ऋणों पर ब्याज अनुदान या पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करके, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विनियामक मानकों को पूरा करने के लिए उनकी उत्पादन सुविधाओं का उन्नयन करता है। तीसरा, यह अध्ययन करके, डेटाबेस बनाकर और अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करने के लिए उद्योग जगत के अग्रणियों, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाकर, औषधि और चिकित्सा उपकरण उद्योग के विषय में ज्ञान और जागरूकता को बढ़ावा देता है।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है

39. ऑटोमोबाइल क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है। 2022 में, भारत दोपहिया और तिपहिया वाहनों का सबसे बड़ा निर्माता और यात्री गाडियों का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्माता था। इस क्षेत्र का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि यह क्षेत्र, 2021 के अंत में 37 मिलियन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करते हुए समग्र सकल घरेलू उत्पाद में 7.1 प्रतिशत और विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में 49 प्रतिशत का योगदान देता है।[6]

चित्र IX.22: ऑटोमोबाइल की वृद्धिशील बिक्री

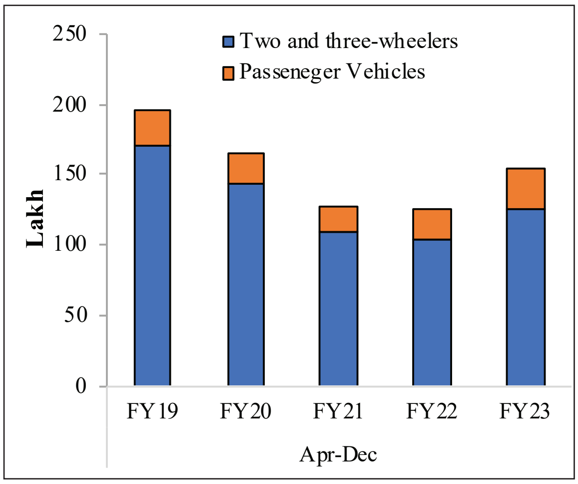

चित्र IX.23: कमजोर वैश्विक मांग के बीच ऑटोमोबाइल निर्यात में मंदी

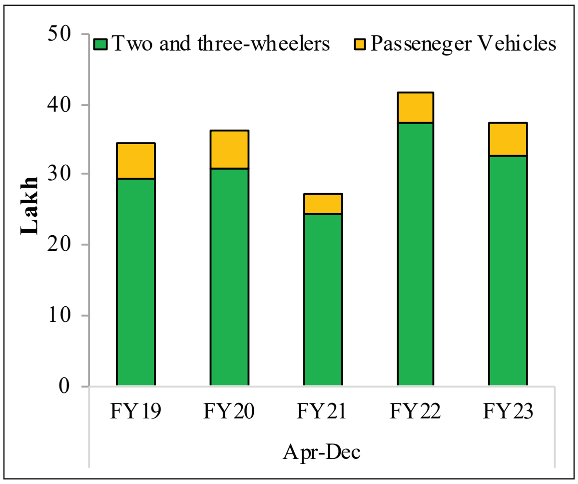

स्रोत: एसआईएएम

40. मोटर वाहन उद्योग के, हरित ऊर्जा की दिशा में परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार के, 2022 और 2030 के बीच 49 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है और 2030 तक दस मिलियन-यूनिट वार्षिक बिक्री तक पहुंचने की उम्मीद है। ईवी उद्योग 2030 तक 50 मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगा। इस विकास की सहायता और पोषण करने के लिए, सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

6 https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/electric-vehicle-ev-sector-india-boost-both-economy-and-environment

चित्र IX.24: ऑटोमोबाइल की वृद्धिशील बिक्री

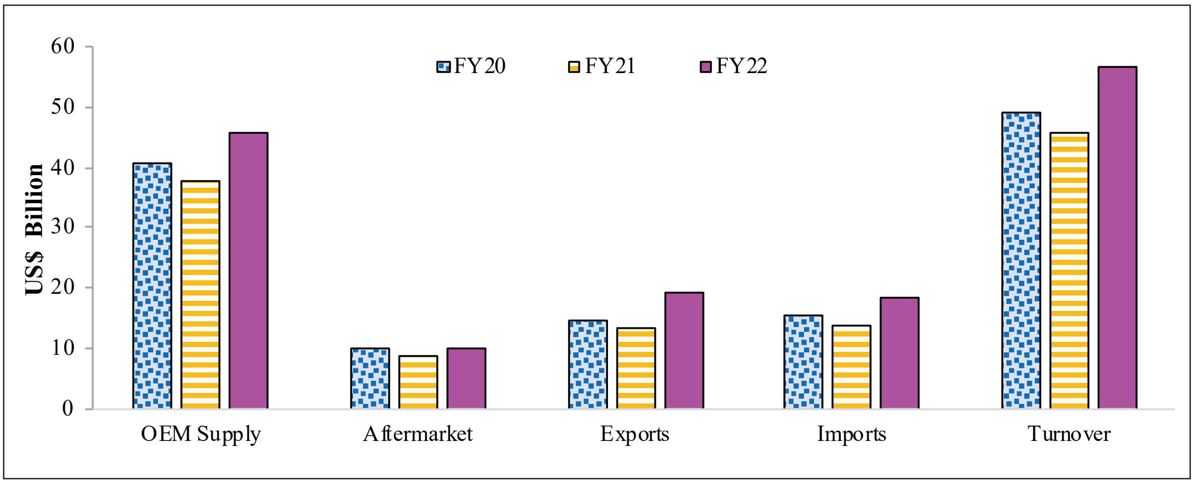

स्रोत: भारी उद्योग मंत्रालय

नोट: ओईएस से तात्पर्य मूल उपकरण विनिर्माण से है

आफ्टरमार्केट से तात्पर्य, मोटर वाहनों के लिए स्पेयर पार्ट्स, सहायक-उपस्कर और पुर्जों के बाजार से है।

चित्र IX.25: खपत बढ़ाने वाली प्रोत्साहन योजनाएँ

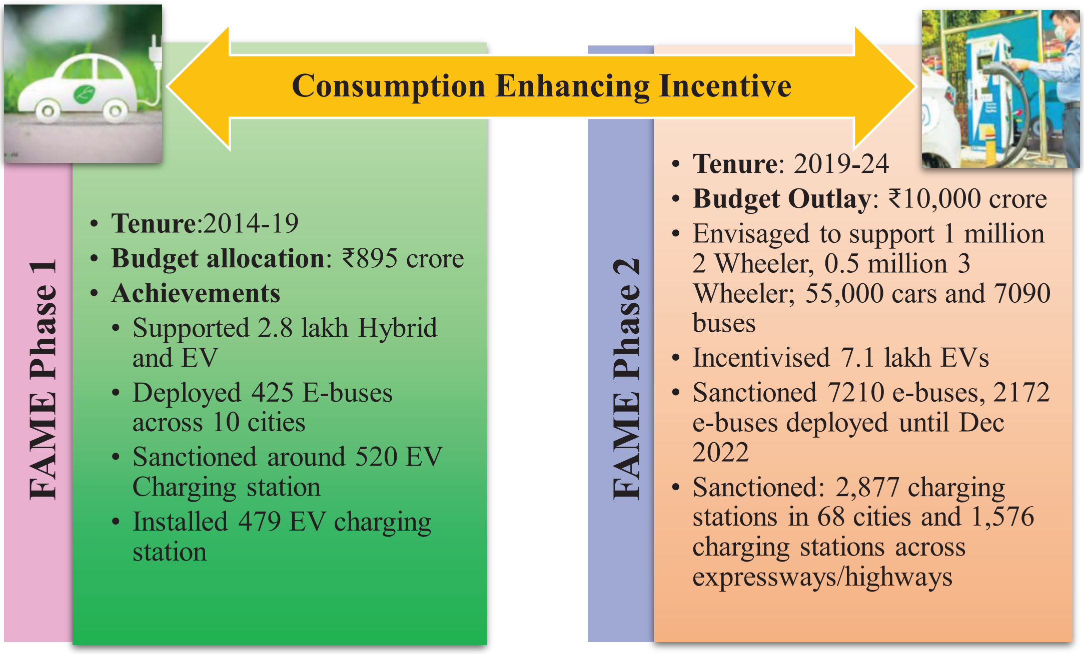

स्रोत: भारी उद्योग मंत्रालय

नोट: एफएएमई का तात्पर्य इलैक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण से है।

चित्र IX.26: उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं

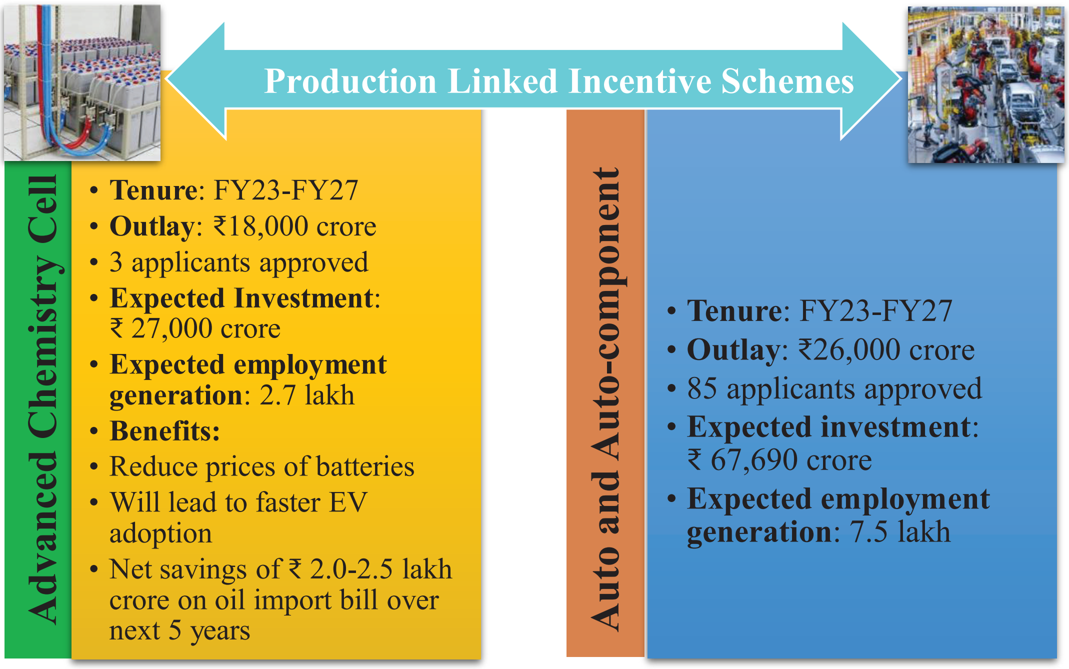

स्रोत: भारी उद्योग मंत्रालय

41. आशावादी दृष्टिकोण के बावजूद, मोटर वाहन उद्योग को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। निकट अवधि में, रुपये में गिरावट और उच्च ऋण लागत के एक उदास वैश्विक परिदृश्य में भागीदार बनने की उम्मीद है। संरचनात्मक मुद्दों के बीच, दीर्घकालिक तृतीय-पक्ष वाहन बीमा प्रीमियम में वृद्धि ने, कुल अग्रिम बीमा लागत विशेष रूप से दोपहिया वाहनों के लिए, में लगभग 10-11 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसलिए, दोपहिया क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है और पिछले दस वर्षों में इसमें सबसे कम बिक्री देखी गई है। इन चुनौतियों का समाधान करने से ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की संभावनाएं

42. यूएस-चीन व्यापार युद्ध, कोविड-19 महामारी और यूक्रेन युद्ध के जटिल संकटों के बाद, आपूर्ति श्रृंखला के झटके का जोखिम, आज की तुलना में कभी भी इतना ज्यादा स्पष्ट नहीं रहा है। इस तेजी से विकसित होने वाले मामले में, जबकि वैश्विक कंपनियां बहाली के लिए अपनी विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला रणनीतियों को अपनाती हैं, भारत के पास इस दशक में वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का एक अनूठा अवसर है। इस अनूठे अवसर को भुनाने के लिए भारत के पास बडे पैमाने पर युवा कार्यबल के साथ तीन प्राथमिक आस्तियां अर्थात महत्वपूर्ण घरेलू मांग की क्षमता, विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का अभियान और एक बड़े अनुपात में विशिष्ट जनसांख्यिकीय बढ़त, मौजूद हैं। भारत में विनिर्माण क्षेत्र धीरे-धीरे अधिक स्वचालित और प्रक्रिया-संचालित विनिर्माण में स्थानांतरित हो रहा है, जिससे दक्षता में वृद्धि और उद्योग उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 2014 में 'मेक-इन-इंडिया' पहल शुरू की गई थी। तब से, इसने निवेश तथा नवाचार को बढ़ावा दिया है और विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण किया है। अवसंरचना विकास में की गई प्रगति पर अध्याय ०० (अद्यतन किया जाना) में चर्चा की गई है।

घरेलू उत्पादन क्षमता में वृद्धि

43. वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के समेकन को और बढ़ाने के लिए, मेक इन इंडिया 2.0 अब 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इनमें से 24 उप-क्षेत्रों को भारतीय उद्योगों की सामर्थ्य और प्रतिस्पर्धी बढ़त, आयात प्रतिस्थापन की आवश्यकता, निर्यात की संभावना और रोजगार में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चुना गया है। समग्र और समन्वित तरीके से उप-क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं।

चित्र IX.27: मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत 24 उप-क्षेत्र

Source: DPIIT

44. मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसरण में और आत्मनिर्भरता हासिल करने की दृष्टि से, सरकार ने पीएलआई योजना शुरू की है। इस योजना से अगले पांच वर्षों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपये कैपेक्स के होने की उम्मीद है। इसमें, भारत में 60 लाख से अधिक के लिए रोजगार पैदा करने और कुल पूंजीगत निर्माण में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाने की क्षमता है, जो वर्तमान में वित्त वर्ष 12 और वित्त वर्ष 20 के बीच लगभग 17-20 प्रतिशत है। इसके अलावा, अगले पांच वर्षो में अधिक निर्यात के कारण निवल आयात में लगभग 35 से 40 ट्रिलियन रुपये तक की कमी आएगी। जिन क्षेत्रों के अंतर्गत पीएलआई योजना की घोषणा ाा की गई है, वर्तमान में वे क्षेत्र कुल आयात का लगभग 40 प्रतिशत हैं। 14 क्षेत्रों में फैली यह योजना, वित्त वर्ष 23 से भारत के वार्षिक विनिर्माण कैपेक्स को 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है। हालांकि, निष्पादन में देरी, वित्तपोषण की बढ़ती लागत, आवश्यक बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता और अनुमोदन में देरी से संभावित चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

45. इन प्रमुख क्षेत्रों में पीएलआई योजना का कार्य, भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, मुख्य योग्यता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना; दक्षता सुनिश्चित करना; विशाल अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करना; निर्यात को बढ़ाना और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बनाना है। इस योजना से देश में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होगा। हर क्षेत्र में निर्मित एंकर इकाइयों को संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में नए आपूर्तिकर्ता स्थापित करने की आवश्यकता होगी। इनमें से अधिकतर सहायक इकाइयां, एमएसएमई क्षेत्र में तैयार की जाएंगी।

46. 31 दिसंबर 2022 तक, 14 योजनाओं के अंतर्गत 717 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। थोक में दवाएं, चिकित्सा उपकरणों, टेलीकॉम, व्हाइट गुड्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में पीएलआई लाभार्थियों में 100 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग शामिल हैं। कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों की हाल की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 47,500 करोड़ रुपये (6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का वास्तविक निवेश किया गया है; योग्य उत्पादों का 3.85 लाख करोड़ (47 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का उत्पादन/बिक्री और लगभग 3 लाख का रोजगार सृजन दर्ज किया गया है और वित्त वर्ष 22 के इसी समयावधि के अनुमानों की तुलना में वास्तविक निवेश में 106 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज की गई है। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, औषधि, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण और व्हाइट गुड्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों ने निवेश, उत्पादन, बिक्री और रोजगार में काफी योगदान दिया है।

47. पीएलआई कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ नवीनतम परिवर्धनों में, जून 2022 में एक डिजाइन-आधारित पीएलआई का शुभारंभ शामिल है, जो दूरसंचार निर्माण में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने और दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना के हिस्से के रूप में 5जी के लिए एक मजबूत कारोबारी माहौल तैयार करने के लिए है। पात्र कंपनियों को इस योजना के अंतर्गत मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। सितंबर 2022 में, मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत में हाई-इफीसिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए कारोबारी माहौल तैयार करने और इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करने के लिए 19,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'हाई-इफीसिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल के राष्ट्रीय कार्यक्रम' पर पीएलआई योजना (ट्रांच II) को मंजूरी प्रदान की है।

बॉक्स IX.4: पोत निर्माण क्षेत्र: आत्मनिर्भरता हासिल करना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना

पोत निर्माण उद्योग ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय रक्षा और भारी इंजीनियरिंग उद्योग के विकास में अपनी भूमिका के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना का लक्ष्य 2047 तक पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। यह क्षेत्र सहायक उद्योगों के साथ अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधों के कारण मेक इन इंडिया पहल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

सहायक उद्योग को बढ़ावा

पोत निर्माण में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग और सेवा क्षेत्रों के योगदान को बढ़ाने की क्षमता है। पोत निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने से सहायक उद्योग भी विकसित होते हैं। अर्थव्यवस्था में अवसंरचना और सेवा क्षेत्रों पर इसकी व्यापक निर्भरता के अलावा, इस क्षेत्र का स्टील, एल्यूमीनियम, विद्युत मशीनरी और उपकरण आदि जैसे अन्य प्रमुख उद्योगों पर अत्यधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निर्माणाधीन जहाज का लगभग 65 प्रतिशत मूल्यवर्धन शिपबोर्ड सामग्री, उपकरण और प्रणालियों के निर्माताओं से आता है।

महत्वपूर्ण निवेश और रोजगार सृजन गुणक प्रभाव

अंतर्राष्ट्रीय पोत निर्माण आंकड़ों के आधार पर, यदि कोई पोत निर्माण क्षेत्र के लिए 0.45 के जीडीपी अनुपात (एमसीजीआर) के परंपरागत सीमांत उपभोग पर विचार करता है, तो निवेश गुणक 1.82 तक काम करेगा। उदाहरण के लिए, नौसैनिक पोत निर्माण परियोजनाओं में लगभग ₹ 1.5 लाख करोड़ का एक निवेश 'गुणक प्रभाव' के कारण पोत निर्माण क्षेत्र में ₹2.73 लाख करोड़ का संचलन अर्जित करेगा।

विनिर्माण गतिविधियों में, पोत निर्माण 6.4[1] पर उच्चतम रोजगार गुणकों में से एक है। पोत निर्माण गतिविधि के स्थान को देखते हुए, यह दूरस्थ, तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर सकता है,

जिससे खेतों से पलायन करने वाले श्रम को शिपयार्ड और उनकी सहायक कंपनियों द्वारा स्थापित विनिर्माण सुविधाओं में आमेलित किया जा सकता है। भारतीय नौसेना द्वारा किए गए स्वदेशीकरण पहलों के परिण ाामस्वरूप एमएसएमई और अन्य उद्योगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हुआ है। उदाहरण के लिए, हाल ही में अधिकृत किए गए आईएनएस विक्रांत में लगभग 500 एमएसएमई, सहायक उद्योग के 12000 कर्मचारी और शिपयार्ड के 2000 कर्मचारी व्यस्त हैं।

इसके अलावा, सात पी17ए जहाजों के निर्माण के लिए नौसेना द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि युद्धपोतों की कुल परियोजना लागत का लगभग तीन-चौथाई भारतीय अर्थव्यवस्था में वापस निवेश किया जाता है। यह निवेश कच्चे माल के स्वदेशी संसाधनों, जहाजों पर स्थापित उपकरणों और प्रणालियों के विकास और अन्य संबंधित जनशक्ति सेवाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था में वापस लाया जाता है।

सहायक उद्योगों को लाभ पहुंचाने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा, एक स्वदेशी पोत परिवहन और पोत निर्माण उद्योग भी माल ढुलाई बिल और विदेशी मुद्रा व्यय को कम कर सकता है, जिससे चालू खाता घाटा कम हो सकता है।

नवाचार को बढ़ावा देना

48. नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार के प्रयासों में उद्भवन (इन्क्यूबेशन), हैन्डहोल्डिंग, वित्तपोषण, उद्योग-शिक्षा क्षेत्र की साझेदारी और सरंक्षण शामिल हैं। सरकार ने बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण करके, कानूनी अनुपालनों को घटाकर और स्टार्ट-अप, महिला उद्यमियों, छोटे उद्योगों और अन्य लोगों के लिए आईपी फाइलिंग की सुविधा देकर अपनी बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था को भी मजबूत किया है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2016-2021 में पेटेंट की घरेलू फाइलिंग में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर भारत के अवस्थांतर का संकेत है।

49. इन उपायों का लाभांश मिलना शुरू हो गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) नवाचार प्रदर्शन के आधार पर देशों को रैंक प्रदान करता है, जिसमें प्रत्येक अर्थव्यवस्था के राजनीतिक वातावरण, शिक्षा, अवसंरचना और ज्ञान निर्माण पर उपाय शामिल करते हुए लगभग 80 संकेतक शामिल हैं। जीआईआई 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, 2007 में जीआईआई की स्थापना के बाद से भारत ने वर्ष 2022 में पहली बार शीर्ष 40 नवाचारी देशों में प्रवेश किया है जो वर्ष 2015 में 81 से अपनी रैंक में सुधार करते हुए 2022 में 40 तक पहुँचा है। इसके अलावा, भारत निम्न मध्य-आय वर्ग वियतनाम (48वें) रैंक को पछाड़कर सबसे नवाचारी राष्ट्र बन गया है जो मध्य और दक्षिणी एशिया क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है।

बॉक्स IX.5: 'फ्लिपिंग एंड रिवर्स फ्लिपिंग: स्टार्ट-अप्स में हाल का घटनाक्रम'

भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में शुमार है।डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स (सेल्फ-रिपोर्टेड) द्वारा प्रभावशाली 9 लाख+ प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की गई हैं।पिछले तीन वर्षों में सृजित नई नौकरियों की औसत संख्या की तुलना में 2022 में उल्लेखनीय 64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारे लगभग 48 प्रतिशत स्टार्टअप टीयर II और III शहरों से हैं, जो हमारे सामान्य जन की जबरदस्त क्षमता का प्रमाण है।

सरकार की विभिन्न लक्षित पहलों ने स्टार्ट-अप्स को बहुत अधिक बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए, स्टार्ट-अप इंडिया पहल के अंतर्गत, पात्र कंपनियों को कर लाभ, आसान अनुपालन और आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार) फास्ट-ट्रैकिंग के मेजबान के रूप में पहुँच के लिए डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता दी जाती

है। विकास और दोहन नवाचार के लिए राष्ट्रीय पहल (एनआईडीएचआई) और अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) की अंब्रेला योजनाओं के एक भाग के रूप में, देश में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है। स्टार्ट-अप्स के लिए निधियों के कोष (एफएफएस) और स्टार्ट-अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस), प्रारंभिक वित्तपोषण और क्रमिक क्रेडिट जरूरतों में सहायता करते हैं। अन्य के साथ-साथ,

प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए अनुसंधान एवं विकास मंच जैसे कि एमईआईटीवाई स्टार्ट-अप हब (एमएसएच) और टेक्नॉलाजी इनक्यूबेशन एण्ड डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्रेन्योर्स (टाइड 2.0) जैसी योजनाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वैश्विक मित्र-समूहों के साथ भारतीय स्टार्ट-अप को जोड़ना, स्टार्ट-अप इंडिया का एक अन्य आवश्यक स्तंभ है और इसे सरकार से सरकार की साझेदारी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भागीदारी और वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा, ई एंड आईटी (एसआईपी-ईआईटी) योजना में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण के लिए समर्थन, भारतीय एमएसएमई और स्टार्ट-अप[9] द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग को प्रोत्साहित करता है।

चित्र A: स्टार्ट-अप्स के द्वारा सृजित नौकरियां

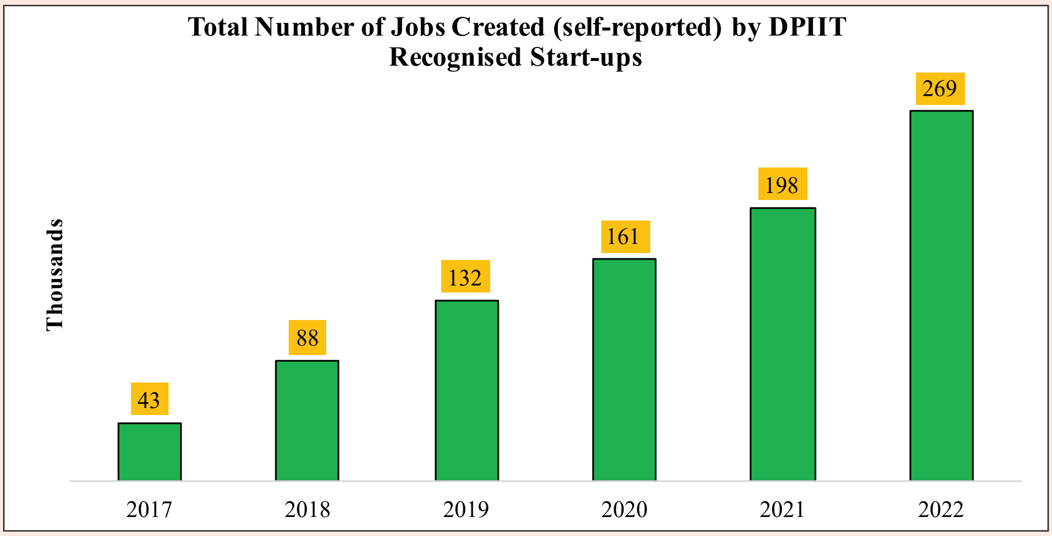

Note: Data as on 17th January 2023

जबकि सरकार के बाहरी समर्थन ने उद्यमशीलता को फलने-फूलने के लिए पहले की तुलना में अपेक्षाकृत आसान बना दिया है वहीं स्टार्ट-अप के सामने अंतर्निहित कई चुनौतियाँ हैं। भले ही यह भ्रामक वित्तपोषण, राजस्व सृजन संघर्ष, सहायक अवसंरचना तक आसान पहुँच की कमी हो या नियामक वातावरण और कर संरचनाओं से बचकर भागना हो। यह भी देवा गया है कि कई भारतीय कंपनियों के मुख्यालय विदेशों में स्थापित हो रहे हैं, विशेष रूप से अनुकूल कानूनी वातावरण और कराधान नीतियों वाले गंतव्यों में। इसके लिए तकनीकी शब्दजाल को 'फ्लिपिंग' के रूप में पहचाना जा सकता है, जो एक भारतीय कंपनी के संपूर्ण स्वामित्व को एक विदेशी संस्था को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है, जिसमें सभी बौद्धिक संपदा (आईपी) और अब तक भारतीय कंपनी के स्वामित्व वाले सभी डेटा का हस्तांतरण होता है। यह प्रभावी रूप से एक भारतीय कंपनी को एक विदेशी कंपनी की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी में परिवर्तित कर देता है, जिसके संस्थापक और निवेशक सभी शेयरों की अदला-बदली करके विदेशी कंपनी के माध्यम से समान स्वामित्व बनाए रखते हैं।

आमतौर पर, ''फ्लिपिंग'' स्टार्ट-अप के शुरुआती चरण में होता है, जो वाणिज्यिक, कराधान और संस्थापकों और निवेशकों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से प्रेरित होता है। कुछ कंपनियां ''फ्लिप'' करने का निर्णय इसलिए लेती

7 Source: PIB https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1884256, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx-?PRID=1884069#:~:text=PLI%20Scheme%20extends%20an%20incentive,2020

हैं क्योंकि उनके उत्पाद का मुख्य बाजार बाहर स्थित होता है। कभी-कभी, इनक्यूबेटरों तक पहुंच जैसी निवेशक प्राथमिकताएं कंपनियों को ''फ्लिप'' करने के लिए प्रेरित करती हैं क्योंकि वे एक विशेष स्थान पर रहने पर जोर देते हैं। कुछ कंपनियां उन देशों में रहना पसंद करती हैं जहां वे बाद में बेहतर मूल्यांकन और टिकट साइज के लिए पूंजीगत बाजार तक पहुंच बनाना चाहती है। बौद्धिक संपदा (आईपी) की बेहतर सुरक्षा और प्रवर्तन तथा बौद्धिक संपदा से लाइसेंसिंग राजस्व का कर उपचार, संस्थापकों की आवासीय स्थिति और कुशल कॉर्पोरेट संरचनाएं, अतीत में ''फ्लिपिंग'' के कारण रहे हैं।

सिंगाफर जैसे लोकप्रिय स्वामित्व वाली (होल्डिंग) कंपनी के क्षेत्राधिकार में, सिंगापुर की कंपनी/सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश पर स्वामित्व (होल्डिंग) स्तर पर कर नहीं लगाया जाता है। निवासियों या अनिवासी शेयरधारकों को लाभांश वितरित करते समय इस पर कोई रोक नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण घटक है चूंकि लाभांश सर्वाधिक

लोकप्रिय प्रत्यावर्तन उपकरणों में से एक है। मौजूदा कानून के तहत यूएई में कोई विदहोल्डिंग कर (टैक्स) नहीं है। इन अधिकार-क्षेत्रों ने कंपनियों को बौद्धिक क्षमता स्टोर करने और धारक कंपनियों को क्षेत्रीय मुख्यालय के रूप में बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपनी नीतियों और कर और प्रोत्साहन संरचनाओं को तैयार किया है। यूरोपीय अधिकार-क्षेत्र जैसे कि नीदरलैण्ड लाभांश तथा पूंजीगत लाभ (कुछ शेयरहोल्डिंग थ्रेशोल्ड, अर्थात 5 प्रतिशत और अन्य परीक्षणों के आधार पर) पर भागीदारी की छूट प्रदान करते हैं। ये छूट वर्तमान में भारत में उपलब्ध नही हैं और भारत में मौजूदा संरचनाओं का कोई भी देशान्तरण पूंजीगत लाभ कर को सक्रिय करता है। हालांकि, हाल ही में, एक व्यावसायिक निजी इक्विटी/उद्यम पूंजीगत पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से पूंजी तक अपेक्षाकृत आसान पहुंच के साथ, राउंड-ट्रिपिंग के संबंध में नियमों में बदलाव और भारत के पूंजीगत बाजारों की बढ़ती परिपक्वता ने न केवल फ्लिपिंग को धीमा कर दिया है, बल्कि कंपनियां ''रिवर्स फ्लिपिंग" के विकल्पों को भी अपना रहीं हैं।

चित्र B: कंपनी की संरचना पर फ्लिपिंग का प्रभाव

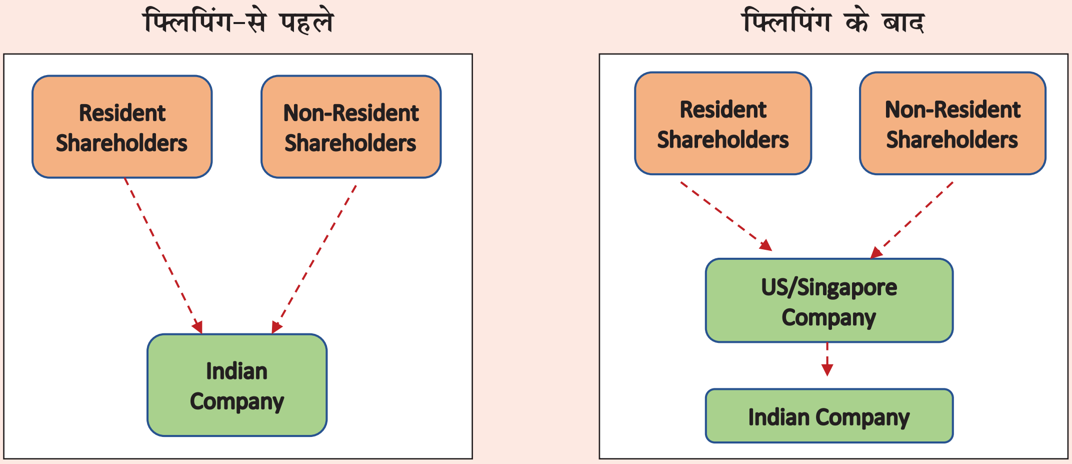

'रिवर्स फ्लिपिंग' में तेजी लाने के लिए कुछ उपाय संभव हैं, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

i. स्टार्ट-अप्स के लिए ''अंतर्मंत्रालयी बोर्ड (आईएमबी) प्रमाणन" प्रदान करने की प्रक्रिया का सरलीकरण

ii. कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) के कराधान का और सरलीकरण

iii. कर की कई परतों और कर मुकदमेबाजी के कारण अनिश्चितता को सरल बनाना

iv. पूंजी अंतर्वाह के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना: अमेरिका और सिंगापुर जैसे कई देशों में आसान कॉर्पोरेट कानून हैं, जिसमें पूंजी के प्रवाह और बहिर्वाह पर कम प्रतिबंध और संकर (हाईब्रिड) प्रतिभूतियों का उपचार है।

v. सर्वोत्तम प्रणालियों और अत्याधुनिक स्टार्ट-अप परामर्श प्लेटफार्मों को विकसित करने के लिए स्थापित निजी संस्थाओं के साथ बेहतर सहयोग और साझेदारी की सुविधा प्रदान करना

vi. सामाजिक नवाचार और प्रभाव निवेश जैसे उभरते क्षेत्रों में स्टार्ट-अप के लिए उद्‌भवन (इन्क्यूबेशन) और वित्तपोषण परिदृश्य की खोज करना।

गतिशील, अनिश्चित भू-राजनीतिक विश्व में अल्प-कालिक लाभ के लिए स्टार्ट-अप उद्यम के रूप में ऊपर उल्लिवित फ्लिपिंग घटना चर्चा का विषय हो सकती है। हालांकि, फ्लिप को सरकार से संबंधित नियामक निकायों और अन्य हितधारकों द्वारा सामूहिक कार्रवाई के साथ फनर्बहाल किया जा सकता है। समाधान-उन्मुव रणनीतियों के साथ, स्टार्ट-अप भारत की उद्यमशीलता की गतिशीलता के संदेशवाहक बने रहेंगे।

ढांचागत सुधारों से व्यापारिक सुगमता में वृद्धि हुई है

50. मेक इन इंडिया पहल यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि देश में व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, भारत में व्यापार करने वाले निवेशकों के लिए अनुकूल है और देश के संवर्धन और विकास में योगदान दे रही है। यह अनेक सुधारों के माध्यम से किया गया है जिससे निवेश अंतर्वाह और आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है। सुधार के उपायों में, कानूनों में संशोधन और अनुपालन के बोझ को कम करने, लागत में कमी लाने और भारत में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए दिशानिर्देशों और विनियमों का उदारीकरण शामिल है। सरलीकरण, युक्तिकरण, गैर-अपराधीकरण और डिजिटलीकरण के माध्यम से नियमों और विनियमों के बोझिल अनुपालन को कम किया गया है, जिससे भारत में व्यापार करना आसान हो गया है। इसके अतिरिक्त, श्रम सुधार से नियुक्त करने और छंटनी करने में लचीलापन आया हैं। स्थानीय विनिर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए गए हैं। विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा देने के उपायों में कॉर्पोरेट करों को कम करना, सार्वजनिक खरीद आदेश और चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम शामिल हैं।

51. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की व्यवसाय सुधार कार्य योजना (पीआरएपी) 2020 (पांचवां संस्करण), राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सुधारों के कार्यान्वयन के आधार पर, 30 जून 2022 को जारी किया गया था। यह दर्शाता है कि बीआरएपी 2020 मूल्यांकन के भाग के रूप में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 7,496 सुधार लागू किए गए थे, जिससे देश भर में व्यापारिक सुगमता में काफी वृद्धि हुई है। व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन बोझ (आरसीबी) को कम करना, शासन उत्कृष्टता के ऊंचे स्तर तक पहुँचने और जीवन सरलता में सुधार करने का एक सतत अभ्यास है। मंत्रालयों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 39,000 से भी अधिक अनुपालनों को कम कर दिया है। इसके विपरीत, डीपीआईआईटी के विनियामक अनुपालन पोर्टल पर अपलोड किए गए विवरण के आधार पर मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, मामूली तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक से संबंधित 3,400 से अधिक प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय एकल विड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) को सितंबर 2021 में अनुमोदन और मंजूरी के लिए निवेशकों को एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करके व्यापारिक सुगमता में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था। पोर्टल तेजी से निवेशक समुदाय के बीच लोकप्रिय हो रहा है और 1 दिसंबर 2022 तक इसके लगभग 3.7 लाख से अधिक अनेक विजिटर हो चुके हैं। एनएसडब्ल्यूएस के माध्यम से 44,000 से अधिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं और 28,000 से अधिक अनुमोदन वर्तमान में प्रक्रियाधीन हैं। पोर्टल, यूजर/उद्योग फीडबैक के आधार पर उत्तरोत्तर अधिक अनुमोदन और लाइसेंस प्रदान करेगा। इस पोर्टल ने निवेशकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की कई मौजूदा निकासी प्रणालियों को एकीकृत किया है।

भारत और उद्योग 4.0

52. चौथी औद्योगिक क्रांति अथवा उद्योग 4.0, जैसा कि आमतौर पर उल्लेख किया जाता है का आगमन शुरू हो गया है। परिवर्तन क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी नई

तकनीकों को विनिर्माण प्रक्रियाओं में एकीकृत करता है, जिससे मूल्य श्रृंखला में प्रभावकारिता आती है। जबकि भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने का काम चल रहा है, बड़े पैमाने पर इसको अपनाया जाना अभी बाकी है। तथापि, एक सक्षम वातावरण तेजी से विकसित हो रहा है। हाल के वर्षों में, भारत ने इंटरनेट की पहुंच में महत्वपूर्ण प्रगति की है जो उद्योग 4.0 की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी और उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने से भारत को इस क्रांति-अति-कुशल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का एक और स्तंभ खड़ा करने में मदद मिलेगी।

53. सरकार आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उद्योग 4.0 के महत्व और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की अपनी महत्वाकांक्षाओं से अवगत है। सरकार द्वारा की गई कुछ पहलों में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत समर्थ (स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब) उद्योग भारत 4.0 शामिल है, जिसका उद्देश्य जागरूकता कार्यक्रमों और प्रदर्शनों के माध्यम से भारतीय विनिर्माण इकाइयों के लिए तकनीकी समाधान को बढ़ावा देना है। एक अन्य पहल 2018 में भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्र की स्थापना करना है, जो उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए नीतिगत ढांचे को विकसित करेगा।

निष्कर्ष और दृष्टिकोण

54. वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, वित्त वर्ष 23 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई जो लगातार मांग की स्थिति से समर्थित थी। जनवरी 2022 से स्पष्ट वृद्धि के साथ, बैंक ऋण में वृद्धि ने औद्योगिक विकास के साथ गति बनाए रखी है। आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की शुरुआत से सहायता प्राप्त सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के ऋण में भी आंशिक रूप से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच, वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में कमी आई है। हालांकि, अंतर्वाह पूर्व-महामारी के स्तर से काफी ऊपर रहा, जो संरचनात्मक सुधारों और व्यापारिक सुगमता में सुधार के उपायों से प्रेरित था, जिससे भारत दुनिया में सबसे आकर्षक एफडीआई गंतव्यों में से एक बन गया।

55. सकारात्मक पक्ष पर, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के कारण इनफट लागत दबाव कम होना, कंपनी के मार्जिन के लिए अच्छा संकेत है। विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग बढ़ रहा है। यह अतिरिक्त क्षमता सृजित करने में नई निवेश गतिविधि के लिए शुभ संकेत है। उद्योग जगत में ऋण वृद्धि भी उल्लेवनीय रूप से बढ़ी है, जो यह सुझाव दे रही है कि कंपनियों द्वारा कैपेक्स निवेश की संभावनाएं उज्जवल हैं। पीएलआई योजनाएं विनिर्माण क्षमता को अनलॉक करने, निर्यात को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने और कुशल और अकुशल श्रम दोनों के लिए रोजगार सृजन के लिए तैयार हैं। हालांकि, नकारात्मक पक्ष देखें तो, निर्यात धीमा हो रहा है और संभावित वैश्विक आर्थिक मंदी के साथ-साथ इसके धीमा होने की संभावना है। वैश्विक स्तर पर नए व्यवधानों को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय आवश्यक वस्तुओं की अस्थिर कीमतें और कच्चे माल की आपूर्ति में व्यवधान, औद्योगिक विकास पर दबाव डाल सकते हैं। चीन में कोविड-19 के फिर से उभरने से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा हो सकता है, जैसा कि महामारी के दौरान हुआ था। दूसरी ओर, यदि चीन कोविड-19 से उभरकर सामान्य स्थिति में लौटता है, तो आवश्यक वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो सकती है - इस प्रकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हाल की गिरावट को रोका जा सकता है। बेशक, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में पुनर्बहाली की क्षमता और अवधि, कई कारकों जैसे कि चीन की आर्थिक सुधार की गति और उत्तरी अमरीका और यूरोप में विकास दृष्टिकोण का एक कार्य होगा। इस तरह के अनुत्तरित प्रश्नों के बावजूद, भारत में औद्योगिक उत्पादन लचीली घरेलू मांग के आधार पर लगातार बढ़ता रहना चाहिए।

10
अध्याय

सेवाएंः शक्ति का स्रोत

वर्ष 2022 में संपर्क-गहन सेवा, जिसने महामारी के अधिकतम दंश को सहन किया है, के उप-क्षेत्र में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत के सेवा क्षेत्र ने द्रुत गति से वापसी देखी की। वित्तीय वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में संपर्क-गहन सेवा उप-क्षेत्र पूरी तरह से महामारी-पूर्व के स्तर पर आ गया चूंकि जिन मांगों में ठहराव था उनमें वृद्धि हुई, गतिशीलता प्रतिबंधों में ढिलाई बढ़ी और लगभग-सभी व्यक्तियों का टीकाकरण हो गया। इसके अतिरिक्त, सशक्त वृद्धि और संपर्क-गहन सेवा क्षेत्र के उच्च-आवृत्ति संकेतकों (एचएफआई) में हुई वृद्धि अगले वित्तीय वर्ष में एक मजबूत विकास के अवसर का संकेत देती है। सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का संकेत देने वाली पीएमआई सेवाओं में हाल के महीनों में इनपुट और कच्चे माल के मूल्य दबाव में आई कमी के फलस्वरूप मजबूत उछाल आया है।

वर्ष 2021 में भारत शीर्ष दस सेवा निर्यातक देशों में शामिल होने के कारण सेवा व्यापार क्षेत्र में एक प्रमुख राष्ट्र रहा है, जिसने विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी को वर्ष 2015 के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2021 में 4 प्रतिशत कर लिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान और मौजूदा भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं में भी भारत का सेवा निर्यात लचीला रहा। देश में नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम अपनी डिजिटल सपोर्ट, क्लाउड सेवाओं और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण संबंधी कारकों की मांगों में वृद्धि होने से ऐसा संभव हुआ है।

विभिन्न उद्योगों के निवेश में उदारीकरण को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने ऑटोमैटिक रूट से सभी सेवाओं और बुनियादी ढांचा प्रदाताओं सहित दूरसंचार सेवाओं में 100 प्रतिशत विदेशी भागीदारी की अनुमति दी है। बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया है। सरकार द्वारा किए गए उपायों, जैसे कि राष्ट्रीय एकल-खिड़की प्रणाली की शुरूआत और ऑटोमैटिक रूट से हुई एफडीआई सीमा में वृद्धि ने निवेश को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

*रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण बाह्य दबाव और महामारी का प्रभाव कम होने से, विभिन्न सेवा उप-क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार आया हैं। होटल उद्योग अधिभोग दर बढ़ रहा है। औसत कक्ष दर (एआरआर) में वृद्धि और प्रति कक्ष राजस्व (*RevPAR*) में वृद्धि होने से यह उद्योग फल-फूल रहा है और अब वित्तीय वर्ष 2020 के महामारी-पूर्व के स्तर के बहुत करीब पहुँच गया है। वित्त वर्ष 2023 में भारत में विदेशी पर्यटकों के आने के साथ-साथ निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बहाली और कोविड-19 नियमों में ढील से पर्यटन क्षेत्र की बहाली के संकेत भी मिल रहे हैं। आवासों की बिक्री होने से और वित्तीय वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही के महामारी-पूर्व स्तर को पार करते*

हुए नए घरों की शुरूआत से रियल एस्टेट क्षेत्र ने चालू वर्ष में लचीले विकास दर दर्शायी है। सूचना प्रौद्योगिकी-बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (आईटी-बीपीएम) और ई-कॉमर्स उद्योग भी कोविड-19 महामारी के दौरान त्वरित प्रौद्योगिकी अपनाते हुए डिजिटल परिवर्तन द्वारा संचालित होते हुए अत्यधिक लचीला बना रहा। सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट का अधिकाधिक उपयोग, स्मार्टफोन अपनाने में वृद्धि और डिजिटल भुगतान को अपनाने में वृद्धि करने पर जोर दे रही है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को लागू करने और इसकी शुरुआत करने से भी डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा मिला है। वित्तीय नवाचार में किए गए ये प्रयास अगली पीढ़ी के लिए एक आधारभूत संरचना तैयार करेंगें।

परिचय

10.1 कोविड-19 महामारी ने विशेष रूप से पर्यटन, वुदरा व्यापार, होटल, मनोरंजन और मनोरंजन जैसे संपर्क-गहन सेवा क्षेत्रों पर प्रभाव डालते हुए अर्थ व्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया है। दूसरी ओर, सूचना, संचार, वित्तीय, पेशेवर और व्यावसायिक सेवाओं जैसी गैर-संपर्क सेवाएं लचीली बनी रहीं। हालाँकि, सेवा क्षेत्र ने वित्त वर्ष 22 में तेजी से वापसी की, यह पिछले वित्त वर्ष में 7.8 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष (YoY) 8.4 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। 'व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं' के उस उप-क्षेत्र की वृद्धि से सुधर हुआ जो महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुआ।

चित्र X.1: सेवा क्षेत्र में व्यापक आधार वाली वृद्धि

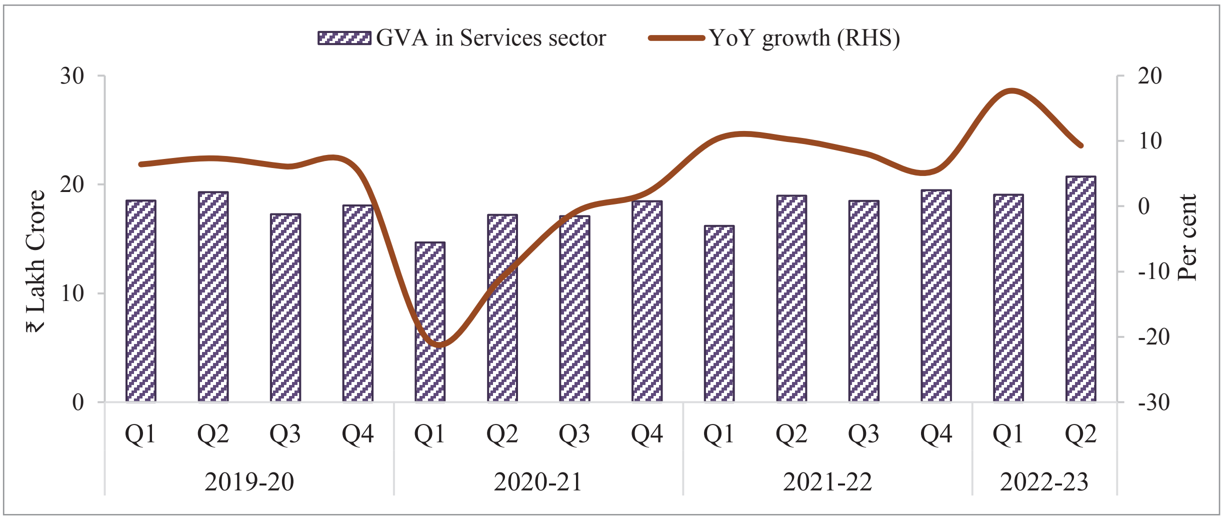

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई

10.2 वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में भी क्रमिक आधार पर रिबाउंड उछाल जारी रही एवं सेवा क्षेत्र में 8.7 प्रतिशत क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई। संपर्क-गहन सेवाओं का उप-क्षेत्र ने महामारी-पूर्व स्थिति में वापस लौट आया है। और इसने 16 प्रतिशत की क्रमिक वृद्धि दर्ज की है, जो कि रुकी हुई मांग की पूर्ति, गतिशीलता प्रतिबंध में आसानी और लगभग-सार्वभौमिक टीकाकरण कवरेज से प्रेरित थी। इससे आगे, एचएफआई के मजबूत निष्पादन के साथ, संपर्क-गहन सेवा क्षेत्र की उछाल वाली स्थिति से यह पता चलता है कि अगले वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र के विकास वाहक होने की संभावना है।

चित्र X.2: वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई।

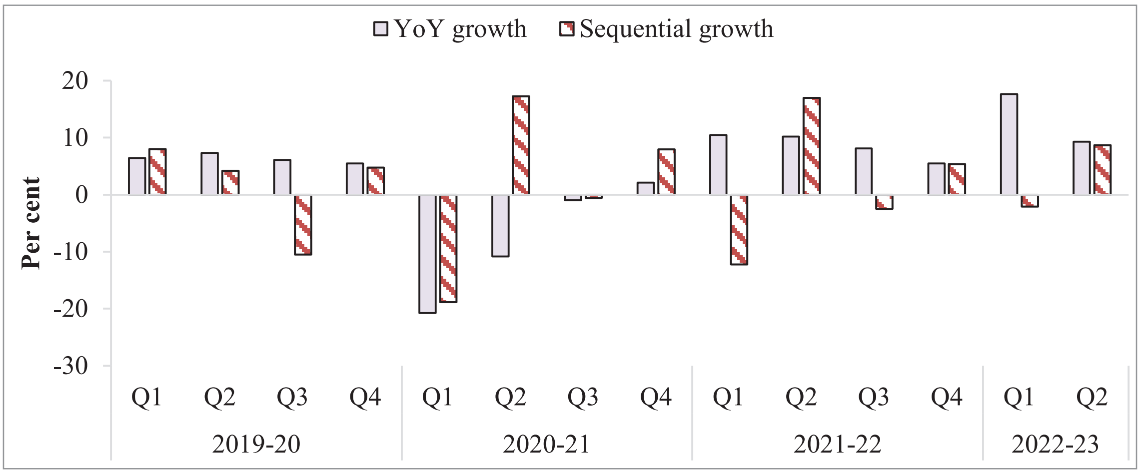

स्रोतः एनएसओ, एमओएसपीआई

10.3 निम्नलिवित खंडों में समग्र रूप से सेवा क्षेत्र की विकास गति को चिह्नित करने के लिए विभिन्न एचएफआई की प्रवृत्ति पर चर्चा की गई हैं, और विभिन्न सेवा उप-क्षेत्रों के प्रदर्शन का वर्णन किया गया हैं।

उच्च-आवृत्ति संकेतकों का रुझान

सेवाएं पीएमआई

10.4 पीएमआई सेवाओं द्वारा मापी गई भारत की सेवा क्षेत्र की गतिविधि, जो कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के कारण 2020 और 2021 के दौरान कई महीनों तक संकुचन क्षेत्र में रही, 2022 की शुरुआत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के घटने के साथ तेजी से बेहतर हो गई। हालांकि, रूस-यूक्रेन संघर्ष के प्रकोप से पीएमआई सेवाओं को फिर से झटका लगा है। मई से सितंबर 2022 तक के संकेतक में सुधार हुआ क्योंकि आर्थिक अनिश्चितता के कारण बिक्री में गिरावट आई और मुद्रास्फीति के दबाव ने कारोबारी बढ़त को रोक दिया। इसके अलावा, कीमतों के दबाव और प्रतिकूल मौसम ने भी घरेलू मांग को प्रभावित किया। हालाँकि, खुदरा मुद्रास्फीति में सुधार के कारण, इनफट और कच्चे माल के मूल्य दबाव की वापसी हुई तथा पीएमआई सेवाओं में तेजी आई और यह दिसंबर 2022 में बढ़कर 58.5 हो गई।

चित्र X.3: पीएमआई सेवाएं भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद विस्तार क्षेत्र में बनी रहीं

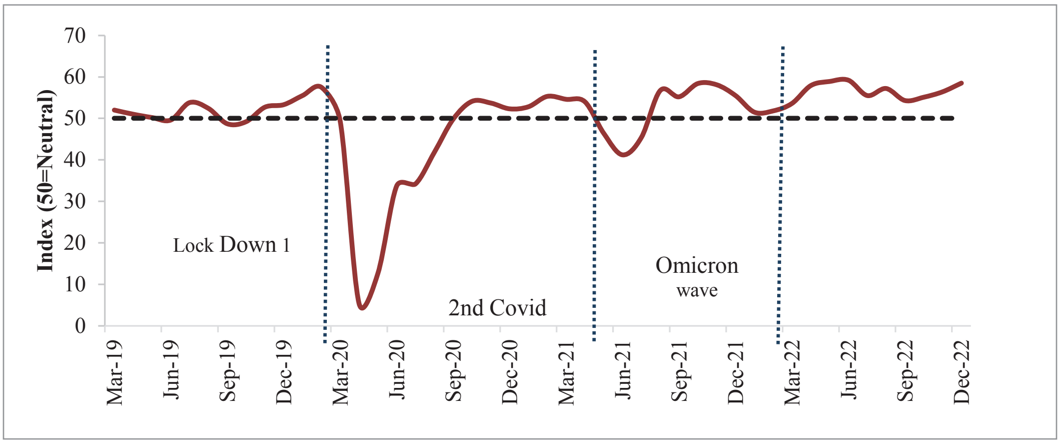

स्रोतः आईएचएस मार्किट

बैंक क्रेडिट

10.5 सेवा क्षेत्रों के बैंक ऋण में अक्टूबर 2021 से वृद्धि हुई, इसका कारण यह था कि टीकाकरण कवरेज में सुधार हुआ और सेवा क्षेत्र में भी रिकवरी हुई थी। नवंबर 2022 में सेवा क्षेत्र के ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 21.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि विगत वर्ष नवंबर 2021 में हुई 3.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 46 महीनों में दूसरी सबसे अधिक वृद्धि है। सेवा क्षेत्र में, थोक और वुदरा व्यापार के ऋण में नवंबर 2022 में क्रमशः 10.2 प्रतिशत और 21.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि आर्थिक क्रियाकलाप की बढ़त को दर्शाता है। एनबीएफसी के ऋण में 32.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई क्योंकि बैंकों से ऋण लेने के लिए एनबीएफसी के रुझान में वृद्धि देखी गई। वैश्विक बाजारों में वृद्धि संबंधी अनिश्चिता की संभावना और परिवहन क्षेत्र के लिए असमान ऋण आवंटन के कारण, नवंबर 2022 में जहाजरानी और विमानन क्षेत्र के ऋण(क्रेडिट) में क्रमशः 7.9 प्रतिशत और 8.7 प्रतिशत की गिरावट आई।

चित्र X.4: अप्रैल 2022 से सेवा क्षेत्र द्वारा ऋण लेने में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई

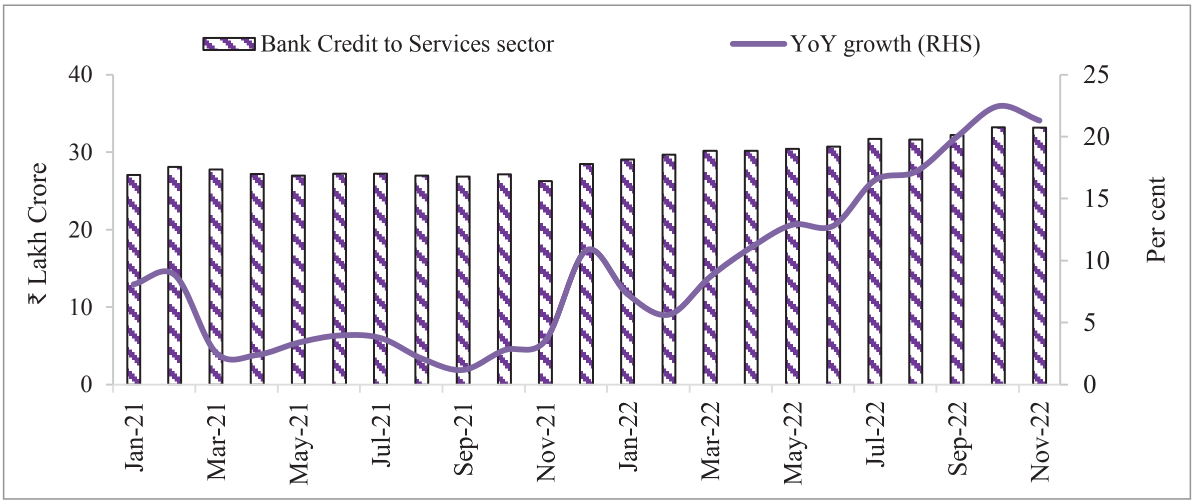

स्रोत: आरबीआई

सेवा व्यापार

10.6 वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में विश्व-सेवा व्यापार की मात्रा में इसके महामारी-पूर्व उंच्च-मात्रा की तुलना में अधिकता देखी गई, और यह आशा की जा रही थी कि यात्रा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सेवा सहित वित्तीय सेवा क्षेत्रों में वर्च के फलस्वरूप तीसरी तिमाही में यह मजबूत स्थिति में रहेगी। हालांकि, डब्ल्यूटीओ की सर्विसेज ट्रेड बैरोमीटर इंडेक्स रीडिंग के अनुसार अक्टूबर 2022 में इसमें 98.3 तक की कमी दर्ज की गई (100 की अपनी बेसलाइन वैल्यू से थोड़ा नीचे), और यह जून 2022 में 105.5 के अपने पिछले रीडिंग से काफी नीचे रही, जो यह दर्शाता है कि वास्तविक वाणिज्यिक सेवाओं में साल दर साल वृद्धि दर वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में कम हो गई। और साथ ही प्रमुव सेवा उद्योग अर्थव्यवस्थाओं में विकास की घटती संभावनाओं के कारण चौथी तिमाही में एवं 2023 की पहली तिमाही में इसकी मात्रा में और कमी हो सकती है। धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय और आईसीटी सेवाएं अब तक सबसे अधिक लचीली रही हैं, जबकि निर्माण सेवाएं और कंटेनर शिपिंग दबाव में आ गए हैं।

10.7 जहां तक भारत का संबंध है, आने वाले महीनों में भारत के कुछ प्रमुव व्यापारिक (कारोबारी) साझेदारों के विकास की गति धीमी होने के कारण कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके विपरीत, ज्योंही विश्व की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के रनवे इन्फ्लेसन में सुधार होगा और वे मजदूरी दर को बधाएंगें और स्थानीय सोर्सिंग को महँगा करेंगें, जिससे कि भारत सहित अन्य कम मेहनताना वाले देशों के लिए नए-नए

अवसर मुहैया होंगे, तो भारत की सेवा निर्यात में सुधार हो सकता है। भारत 2021 में शीर्ष दस सेवा निर्यातक देशों में शामिल होने के कारण सेवा व्यापार में एक महत्वपूर्ण देश है। देश ने विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी वर्ष 2015 के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2021 में 4 प्रतिशत कर लिया है। अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि में 20.4 प्रतिशत की तुलना में सेवा निर्यात में 27.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने के साथ शेयर में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

10.8 सेवाओं के निर्यात के सम्बन्ध में, कोविड-19 महामारी के दौरान एवं वर्तमान भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भी सॉफ्टवेयर निर्यात अपेक्षाकृत लचीला रहा है। इसका कारण यह है कि नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए डिजिटल सपोर्ट, क्लाउड सेवाएं, और बुनियादी सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए इनकी मांगों में वृद्धि हुई है। सेवा निर्यात के दृष्टिकोण से, वर्ष 2021 और 2022 में परिवहन एवं यात्रा सबसे अधिक प्रभावित उप-घटक रहे हैं, जो कोविड-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और पर्यटन पर प्रतिबंध लगने के कारण संकुचित हो गए थे। यदि उन्नत 2021-22 में सार्थक मंदी होती है, तो वित्तीय वर्ष 2024 में पर्यटन और यात्र आय कम हो सकती है।

चित्र X.5: भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच सेवा निर्यात लचीला बना रहा।

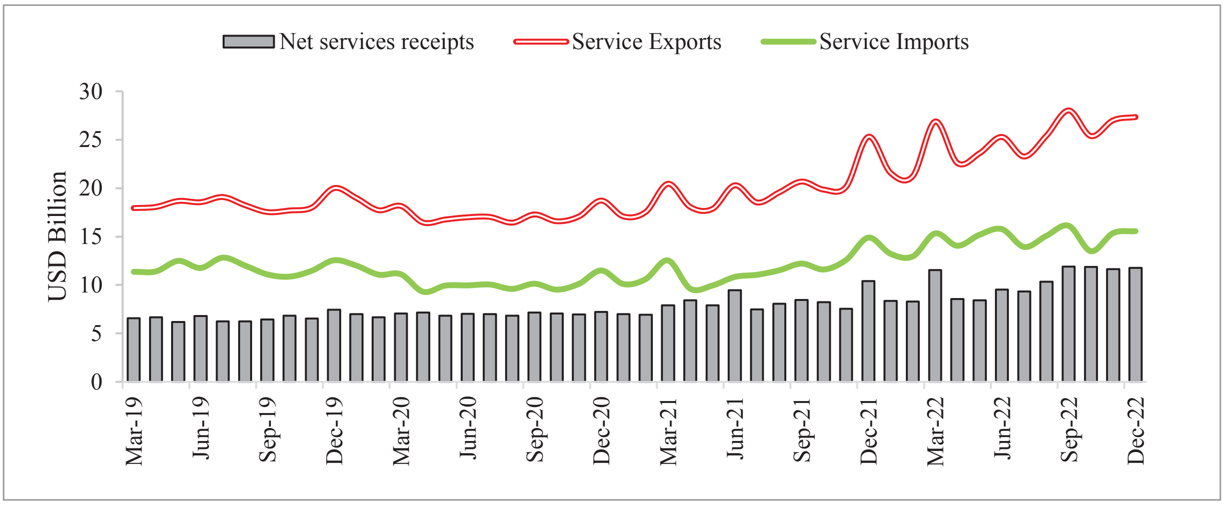

स्रोत: आरबीआई

सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)।

10.9 यूएनसीटीएडी की विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 ने अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र की सूची में भारत को वर्ष 2021 में शीर्ष 20 मेजबान देशों में से सातवें सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया है। वित्त वर्ष 22 में भारत को सेवा क्षेत्र में 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एफडीआई इक्विटी प्रवाह सहित 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उच्चतम एफडीआई अंतरप्रवाह प्राप्त हुई। निवेश के लिए सरकार ने रेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, अनुमादनों के लिए एक समाधान, निवेशकों, उद्यमियों एवं कारोबार द्वारा अपेक्षित समाशेधन, के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। विभिन्न उद्योगों में निवेश के उदारीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आटोमैटिक रुप से सभी सेवा एवं अवसंरचना प्रदाताओं समेत दूर संचार सेवाओं में 100 प्रतिशत भागीदारी की स्वीकृति दी है। निवेश की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय एकल-विड़की प्रणाली का शुभारंभ, निवेशकों, उद्यमियों और व्यवसायों को आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी देने के लिए एक-स्टॉप समाधान। विभिन्न उद्योगों में निवेश उदारीकरण को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने स्वत: मार्ग (आटोमेटिक रुट) के माध्यम से सभी सेवाओं और बुनियादी ढांचा प्रदाताओं सहित दूरसंचार सेवाओं में 100 प्रतिशत विदेशी भागीदारी की अनुमति दी है। बीमा कंपनियों में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दी गई।

बॉक्स X.1: वित्तीय वर्ष 2023 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा बीमा क्षेत्र में पहल[1]

भारतीय बीमा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। भारत अगले दशक में वैश्विक बीमा उद्योग के विकास के मुख्य वाहकों में से एक होगा। भारतीय बीमा बाजार दुनिया में 10 वां सबसे बड़ा है और 2032 तक जर्मनी, कनाडा, इटली और दक्षिण कोरिया से भी आगे निकलकर 6 वां सबसे बड़ा बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। बीमा नियामक, आईआरडीएआई ने सार्वभौमिक बीमा मिशन शुरू किया है, जिससे बीमा लाभ के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। जब भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा, तो प्रत्येक भारतीय के पास उपयुक्त जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा हो रहे और हर उद्यम उपयुक्त बीमा समाधान द्वारा सुरक्षित रहे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, बीमा नियामक ने बीमा उद्योग के विकास को बढ़ावा देने, नियामक ढांचे को युक्तिसंगत बनाने और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार, और सुधारों में तेजी लाने पर जोर देने के के लिए, आईआरडीएआई ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान, प्रौद्योगिकी को मुख्यधारा में रवते हुए और सिद्धांत आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ती पहुंच, नवाचार, प्रतिस्पर्धा, वितरण दक्षता और पसंद की बीमा उपलब्धता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित करवाई प्रारंभ की है:-

i. **बीमा क्षेत्र में आसान प्रवेश:** सिंगल विंडो एनओसी पोर्टल (www.noc.irdai.gov.in) को सुगम बनाया गया है और समय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराकर बीमाकर्ता को बीमा कवरेज में शामिल करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई।

ii. **बीमा उत्पादों का त्वरित लॉन्च:** बीमाकर्ता अब सभी स्वास्थ्य और सामान्य बीमा उत्पादों के साथ-साथ अधिकांश जीवन बीमा उत्पादों को आईआरडीएआई से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना लॉन्च कर सकते हैं, जिससे बाजार में एक नया उत्पाद लॉन्च करने में लगने वाला समय कुछ महीनों से लेकर कुछ दिनों तक के लिए कम हो जाता है।

iii. **बिजनेस करने में आसानी:** आईआरडीएआई ने अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में, अब तक 70 रिटर्न को युक्तिसंगत बनाया गया है और कुछ चिन्हित क्षेत्रों में पूर्व अनुमोदन की आवश्यकताओं को समाप्त करते हुए लगभग 85 परिपत्रों को निरस्त किया गया है।

iv. **उद्योग को अधिक गति प्रदान करना:** यह देखते हुए कि क्षेत्र परिपक्वता के स्तर पर पहुंच गया है, जिसके लिए अधिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं हो सकती है, परिचालन और व्यावसायिक निर्णयों के दृष्टिकोण से विनियमित संस्थाओं के लिए अधिक लचीले बीमा कवरेज पर विचार किया जा रहा है। इस दिशा में आईआरडीएआई द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:-

v. **उद्योग की गतिशील आवश्यकताओं की पहचान करना:** आईआरडीएआई ने क्षेत्र की उभरती जरूरतों के अनुसार विभिन्न सुविधाएँ प्रदान की है, जैसे कि तकनीक-आधारित ऐड-ऑन (सामान्य बीमाकर्ताओं को मोटर बीमा के लिए तकनीक-सक्षम अवधारणाएं पेश करने की अनुमति दी गई है, जैसे कि पे ऐज यू ड्राइव, पे हाउ यू ड्राइव, आदि), स्वास्थ्य बीमा में कैशलेस सुविधा के दायरे का विस्तार, अग्नि बीमा में नवीन उत्पाद, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवनयापन में आसानी।

प्रमुख सेवाएं: उप-क्षेत्रवार प्रदर्शन

पर्यटन और होटल उद्योग

10.10 महामारी के बाद वैश्विक पर्यटन का परिदृश्य धीरे-धीरे सुधर रहा है तथा महामारी-पूर्व की स्थिति में आ रहा है। यात्रा प्रतिबंधों और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कम होने के साथ ही, संपर्क-गहन गतिविधियों के अंतर्गत पर्यटन एक महत्वपूर्ण चालक बन गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (नवंबर 2022) के विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन ने जनवरी-सितंबर 2022 में बेहतर प्रदर्शन किया है। वर्ष 2022 के शुरूआती नौ महीनों में ही अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन महामारी-पूर्व पर्यटकों के आगमन का 63 प्रतिशत हो गया था। इससे इस क्षेत्र की रुकी हुई मांग भी पूरी हुई और विश्वास भी बढ़ा है। रिकवरी की गति और भी मजबूत होती, उन्नत देशों में मंद वैश्विक अनिश्चिता और उच्च मुद्रास्फीति नहीं होती।

[1]Until October 2022
[2]Sigma Report (No 4/2022) by Swiss Re (Page no 15)

10.11 कोविड-19 महामारी ने हाल के वर्षों में आतिथ्य सेवा और पर्यटन उद्योगों के भविष्य को प्रभावित किया। होटल उद्योग वर्ष 2020 को 3-36 प्रतिशत की औसत होटल अधिभोग (ऑक्युपेंसी) दर के साथ बंद हुआ, जो 32 प्रतिशत[3] की गिरावट को दर्शाता है। गिरती मांग और ऑक्युपेंसी के मद्देनजर, होटलों ने व्यापार को आकर्षित करने के लिए टैरिफ को काफी कम कर दिया, इस प्रकार, राजस्व प्रति उपलब्ध कक्ष (आरईवीपीइआर) को 1,500 - 1,800 के निराशाजनक निचले स्तर तक ला दिया, जो लगभग 57-9 प्रतिशत की गिरावट थी। हालांकि, वर्ष 2014 की तीसरी तिमाही में घरेलू अवकाश यात्रा में वृद्धि, देश में व्यापार यात्रा की आंशिक पुन:आरंभ, साथ ही शादी और सामाजिक कार्यक्रमों द्वारा संचालित, होटल अधिभोग (ऑक्युपेंसी) में बेहतर सुधार शुरू हुआ। छोटे से मध्यम आकार के घरेलू एमआईसीई (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनियां) आयोजनों ने भी वापसी की, जिससे होटलों की मांग में तेजी आई। इस क्षेत्र में वर्ष का अंत 42-45 प्रतिशत की औसत अधिभोग के साथ हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10-13 प्रतिशत अधिक था।

10.12 वर्ष 2022 की शुरुआत में एक नए कोविड-19 स्ट्रेन, ओमिक्रॉन के उभरने के कारण राज्यों में यात्रा प्रतिबंधों की फिर से शुरुआत ने भारतीय आतिथ्य क्षेत्र को फिर से उथल-पुथल में डाल दिया। अन्य अवकाश और व्यापार यात्रा योजनाओं को रोक दिया गया था, महत्वपूर्ण और तात्कालिक यात्राओं को छोड़कर लोगों ने सावधानी बरती। कम मांग के परिणामस्वरूप जनवरी-मार्च 2022 के दौरान औसत होटल अधिभोग दर 50 प्रतिशत हो गई। हालांकि, ओमिक्रॉन संस्करण की कम गंभीरता और अस्पताल में भर्ती दर कम होने के कारण, मार्च 2022 में भारत में यात्रा की मांग सामान्य स्थिति में लौटने लगी। यात्रा की मांग का पुनरुद्धार देश में उच्च टीकाकरण दर के साथ-साथ प्रभावी महामारी प्रबंधन भी था जिसने वायरस के प्रसार और कम करने पर बारीकी से नजर रखने के साथ-साथ गतिशीलता प्रतिबंधों को हटाने में गति सुनिश्चित की। दो साल के अंतराल के बाद, भारत ने भी 2021-22 के समाप्त होते ही सभी नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को पूरी क्षमता के साथ फिर से शुरू कर दिया। नतीजतन, देश में सम्पूर्ण विमान परिचालन (कार्गो विमान + यात्री विमान) में अप्रैल और नवंबर 2022 के बीच 52.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो अप्रैल और नवंबर 2019 के बीच दर्ज किए गए परिचालन का 93.9 प्रतिशत तक पहुंच गया। वर्तमान में, होटल उद्योग के अधिभोग दर में सुधार हो रहा है और औसत कक्ष दर (ARR) में वृद्धि एवं RevPAR में वृद्धि हो रही है । नवंबर 2022 में अधिवास दर लगभग 68-70 प्रतिशत थी, जो कि वर्ष 2019-20 के महामारी-पूर्व स्तर के औसत के समान थी।

10.13 पर्यटन उद्योग महामारी से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र था। वित्तीय वर्ष 2021 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में काफी गिरावट आई। पर्यटन मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् के संयुक्त अध्ययन[6] के अनुसार आर्थिक मंदी के कारण इस वित्तीय वर्ष में 'टूरिज्म डायरेक्ट ग्रॉस वैल्यू ऐडेड (टीडीजीवीए) में प्रथम तिमाही में 42.8 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 15.5 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 1.1 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। लॉकडाउन लगने के कारण पर्यटन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष नौकरियां चली गई। वित्तीय वर्ष 2020 की महामारी-पूर्व अवधि की 34.8 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियों की तुलना में प्रथम तिमाही में 14.5 मिलियन, दूसरी तिमाही में 5.2 मिलियन और तीसरी तिमाही में 1.8 मिलियन नौकरियां खत्म हुई।

10.14 हालाँकि, महामारी के कम होने के साथ-साथ, भारत का पर्यटन क्षेत्र भी पुन:उभर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बहाली और कोविड-19 नियमों में ढील के साथ विदेशी पर्यटकों का आगमन माह-दर-माह बढ़ रहा है। फिर भी, अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन की दर महामारी-पूर्व स्तर से नीचे हैं। पर्यटन उद्योग का लाभप्रदता-अनुपात (प्रोफिटेविलिटी रेशियो) जून 2022 तिमाही से मजबूत वापसी की संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा, कॉर्पोरेट यात्रा और लचीली कार्य व्यवस्थाओं की बहाली होने से, एमआईसीई (MICE) पर्यटन और ब्लीजर [1]यात्रा वापसी भारत में फिर से लोकप्रियता हासिल कर रही

[3]https://api.anarock.com/uploads/research/HVS%20ANAROCK%20Indian%20Hospitality%20Overview%202020.pdf
[4]https://api.anarock.com/uploads/research/HVS%20ANAROCK%20India%20Hotel%20Industry%20Overview%202021%20E-book.pdf
[5]https://api.anarock.com/uploads/research/HVS%20ANAROCK_H2O_DEC%2022.pdf
[6]https://tourism.gov.in/sites/default/files/2021-11/Tourism-Corona%20Report_Print%20version.pdf

है। इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी सुविधाओं में हुए अनवरत सुधार से साथ भारत एमआईसीई कार्यक्रमों के लिए पसंदीदा स्थान बना हुआ है।

चित्र X.6: पूर्व-महामारी के स्तर के समय होटल अधिभोग (ऑक्युपेंसी) दर

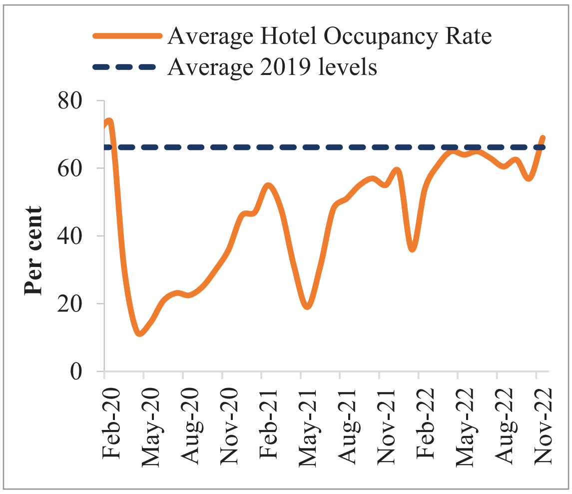

चित्र X.7: पूर्व-महामारी स्तर के पास होटल अधिभोग दर औसत दैनिक दर (एडीआर) और राजस्व प्रति उपलब्ध कक्ष (रेवपीएआर) में सुधार

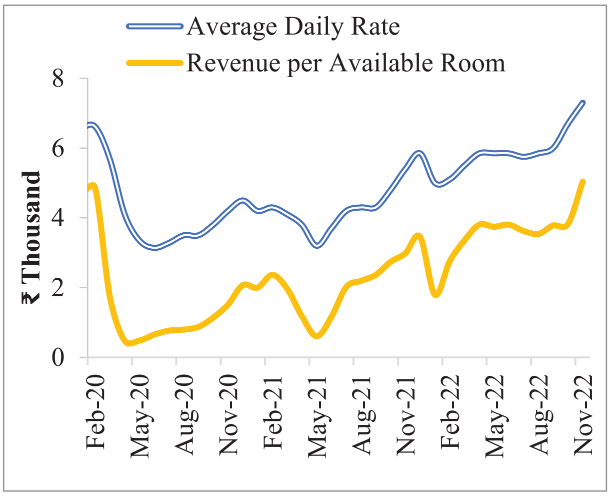

स्रोत: अनारॉक

10.15 मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा जारी मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021 में भारत दुनिया के शीर्ष 46 देशों में 10 वें स्थान पर है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन और आतिथ्य उद्योग पर कोविड-19 महामारी द्वारा डाले गए प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद, भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर तथा भारत की चिकित्सा मूल्य यात्रा (एमवीटी) 2022 तक 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। विश्व स्तरीय अस्पतालों और कुशल चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता, गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवा, अन्य देशों की तुलना में न्यूनतम उपचार लागत, चिकित्सा की वैकल्पिक प्रणालियों में विश्वसनीयता, और योग और ध्यान जैसी स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती वैश्विक मांग जैसे कारक भारत को एक लोकप्रिय चिकित्सा पर्यटन स्थल बना रहे हैं। भारत ने जिस तरह से कोविड की स्थिति को संभाला है, और भविष्य के लिए अपने को तैयार किया है, उससे भारत में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा बढ़ा है। यह मेडिकल वैल्यू टूरिज्म (एमवीटी) को एक बड़ा संबंल देगा, जिसके 2022 तक 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।

चित्र X.8: अभी भी भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन (एफटीए) महामारी पूर्व स्तर से नीचे है

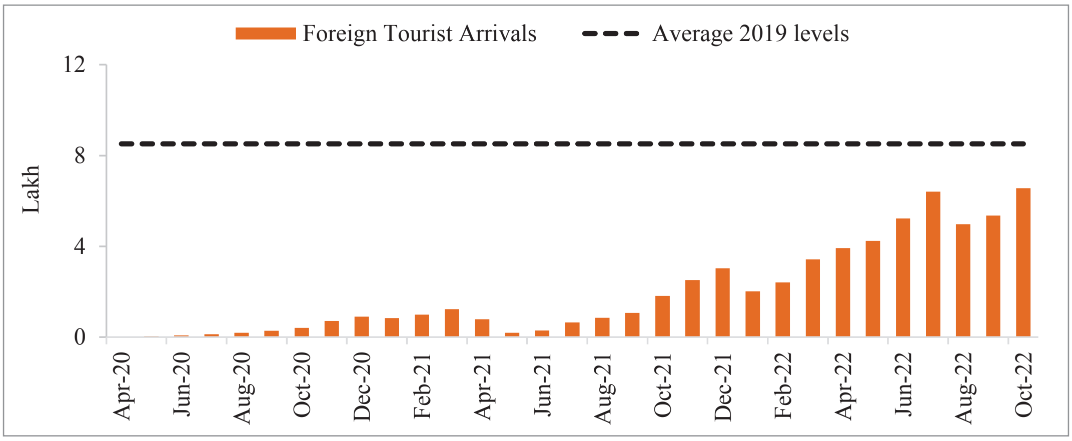

स्रोत: पर्यटन मंत्रालय

[7]Bleisure is a term used to describe travel that combines both business and leisure
[8]https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022-02/AIM-NITI-IPE-whitepaper-on-Blended-Financing.pdf

10.16 भारत एक विशेष पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने के लिए अपने आकर्षण को बढ़ाने का भी प्रयास किया है। चिकित्सकीय उपचार के लिए भारत आने की इच्छा रखने वाले पर्यटकों के लिए आयुष वीजा जैसी हालिया पहल, सतत पर्यटन और जिम्मेदार यात्री अभियान के लिए राष्ट्रीय रणनीति का शुभारंभ, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की शुरुआत, और भारत में रोग मुक्ति (हिल इन इंडिया) जैसे कार्क्रम भारत को बड़े पैमाने पर एक वैश्विक चिकित्सा पर्यटन बाजार का हिस्सा बनाने में सहायक हो सकते हैं। इससे भी अधिक, जी20 की अध्यक्षता भारतीय यात्रा और पर्यटन उद्योग के लिए एक अनूठा अवसर है। इससे भारत को एक "प्रमुव पर्यटन स्थल" के रूप में विकसित होने का अवसर मिलेगा। परिणामस्वरूप, यात्रा और होटल अधिभोग दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है।

बॉक्स X.2: भारत को आकर्षक पर्यटन स्थल बनाना

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिवित शामिल हैं:-

निधि: राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों की मदद से पयर्टन मंत्रालय, मंत्रालय के पोर्टल ''नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री (NIDHI)'' पर देश में आवास इकाइयों को पंजीकृत करने का प्रयास कर रहा है। विभिन्न स्थलों पर पर्यटन के प्रचार और विकास के लिए नीतियां और रणनीति बनाने में व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस मदद करेगा।

साथी: लॉकडाउन के बाद ग्राहकों को आवास और अन्य सेवाएं देते समय वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद के सहयोग से आतिथ्य उद्योग के मूल्यांकन, जागरूकता और प्रशिक्षण प्रणाली (साथी) की शुरुआत की गई थी। योजना का उद्देश्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 नियमों के बारे में उद्योग-धंधों को संवेदनशील बनाना और कार्मिकों और अतिथियों के बीच विश्वास पैदा करना है आतिथ्य इकाई ने कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने का भरपूर प्रयास किया है।

आरसीएस उड़ान 3: किसी भी क्षेत्र में पर्यटन को फलने-फूलने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण घटक है। इस उद्देश्य से, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुगम बनाने/प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस-उड़ान) शुरू की गई थी। पर्यटन आरसीएस हवाई मार्गों की कुल संख्या बढ़कर 59 हो गई है, जिनमें से 51 इस समय कार्य कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 21 और वित्तीय वर्ष 22 के दौरान वायबिलिटी गैप फंडिंग (Viability Gap Funding (VGF) के रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को ₹ 104.19 करोड़ की राशि पहले ही चुकाई जा चुकी है।

एलजीएससीएटीएसएस: नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) के माध्यम से प्रशासित कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (LGSCATSS) के तहत, उन परिवारों को कार्यशील पूंजी/व्यक्तिगत ऋण दिया जाता है जो कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित होने की वजह से अपनी देनदारियों को पूरा करने तथा अपने व्यसाय को फन: प्रारंभ करने में अक्षम थे। यह योजना 10,700 क्षेत्रीय स्तर के टूरिस्ट गाइड्स (पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त), टूरिस्ट गाइड्स (राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त), और लगभग 1,000 यात्रा और पर्यटन हितधारकों (टीटीएस) (पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त) को कवर करने के लिए शुरू की गई थी।

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए सरकार द्वारा पहली बार 5 लाख टूरिस्ट वीजा की घोषणा की गई थी। यह योजना 31 मार्च 2022 तक या 5 लाख मुफ्त वीजा जारी किए जाने तक, जो भी पहले हो, तक लागू थी। यह लाभ प्रति पर्यटक को केवल एक बार उपलब्ध था।

रियल एस्टेट

10.17 कोविड-19 महामारी ने प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र में मंदी को बढ़ा दिया, और रियल एस्टेट क्षेत्र भी इससे से अछुता नहीं रहा। परियोजनाओं में देरी, बड़ी वरीद को टालना, संपत्ति की कीमतों में ठहराव, और डेवलपर्स

के लिए फंडिंग (निधि) की कमी ने इस क्षेत्र में मांग को प्रभावित किया। महामारी से जुड़े लॉकडाउन और सेक्टर इस सेक्टर से जुड़े कर्मचारियों के अपने मूल निवास स्थान की ओर पलायन से स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। वर्क्फ्रॉम-होम मॉडल अपनाए जाने के कारण कॉरपोरेट्स की ऑफिस स्पेस आवश्यकताओं की मांग पर भी प्रभाव पड़ा।

10.18 हालाँकि, महामारी के कारण व्यक्तिगत घर खरीदारों की मानसिकता में बदलाव आया। लोग खुद के लिए अपना घर खरीदने के प्रति जागरूक हुए। प्रतिबंधों में ढील होने से, आवासीय क्षेत्र में रुचि बढ़ी और इससे भी अधिक उस आवास के प्रति लोगो की रूचि बढ़ी जो तैयार स्थिति में उपलब्ध थे। कहीं से भी काम करने के विशेषाधिकार के परिणामस्वरूप हाइब्रिड वर्क मोड ने पहली बार घर खरीदने वालों को पारंपरिक महानगरों से दूर जाने के लिए प्रोत्साहित किया, और इससे टीयर II और III शहरों के आवासीय रियल एस्टेट बाजारों की मांगें बढ़ी। महामारी के दौरान सरकार द्वारा किए गए उपायों के फलस्वरूप बहुत सारे सुधार हुए, जैसे ब्याज दरों में कमी, सर्कल दरों में कमी, और अचल संपत्ति की बिक्री/खरीद संबंधी लेनदेन पर स्टांप शुल्क में कटौती हुई। रियल एस्टेट विनियमन अधिनियम का विस्तार (रेरा) ने भी महामारी के बाद रियल एस्टेट क्षेत्र के उछाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बॉक्स X.3: आवासीय क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

सरकार की विभिन्न नीतियों, जिसमें 'सभी के लिए आवास', आत्मनिर्भर भारत, आदि शामिल हैं, ने आवासीय वित्त क्षेत्र को गति दी। ऋण देने वाली संस्थाओं को 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच भुगतान किलता के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुल 6 (3+3 महीने) माह की अवधि का अधिस्थगन प्रदान करने की अनुमति, गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों (एनबीएफसी), आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs) के लिए ₹ 75,000 करोड़ का इन्फ्यूजन, इत्यादि ने भी रियल एस्टेट क्षेत्र के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

प्रधान मंत्री आवास योजना-क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम अर्बन (PMAY&CLSS (U) के तहत ब्याज सबवेंशन आवासीय स्थान में मांग-पक्ष वाहक रहा है। इसने, ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए सुव्यवस्थित नीतियों के साथ, आवास वित्त के लिए उपभोक्ता-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद की है। इसकी शुरुआत होने के बाद, सरकार ने लगभग 20.87 लाख परिवारों को लाभान्वित करते हुए ₹ 53,548 करोड़ की सब्सिडी जारी की है। इसके अलावा, अफोर्डेबल हाउसिंग फंड (एएचएफ) ने व्यवहार्य विकास (वायबल ग्रोथ) के लिए क्षेत्र में पर्याप्त तरलता सृजित की। अपनी स्थापना के बाद से नेशनल हाउसिंग बैंक ने अफोर्डेबल हाउसिंग फंड के तहत, 3.9 लाख आवासीय इकाइयों के लिए ₹ 34,588 करोड़ का वितरण किया है। आरबीआई की विशेष तरलता सुविधा के तहत, राष्ट्रीय आवास बोर्ड (एनएचबी) ने महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान क्रमश: ₹ 13,917 करोड़ और ₹ 8,112 करोड़ वितरित किए, ताकि क्षेत्र में हमेशा की तरह निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके। उपरोक्त सहित, राष्ट्रीय आवास बैंक ने महामारी की शुरूआत के बाद से विभिन्न पुनर्वित योजनाओं के माध्यम से ₹ 88,400 करोड़ की तरलता सहायता प्रदान की है।

रियायती तरलता ने क्षेत्र को लचीला बनाए रखने के लिए आवश्यक तरलता (इन्फ्लक्स) मिली। समाज के निचले पायदान के व्यक्ति को भी आवास ऋण देने के लिए बैंकों के तरलता आधार और एचएफसी की पहुंच का लाभ देने के उद्देश्य से सह-उधार मॉडल को अपनाया गया है। पूरे भारत में 100 स्मार्ट शहरों के निर्माण की योजना के साथ, रियल एस्टेट क्षेत्र के समग्र अवसर में सुधार लाने और निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी योजना लाई गई। महामारी के बाद की अवधि के दौरान आवासीय अचल संपत्ति क्षेत्र में समग्र सामर्थ्य (एफोर्डेबिलीटी) अधिक थी, जैसा कि जनवरी 2020 में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों से होम लोन पर औसत वार्षिक ब्याज दर में 8.6 प्रतिशत से जनवरी-मार्च 2022 के दौरान 7.3 प्रतिशत हो जाने से ज्ञात होता है। किफायती आवास पर लगातार जोर देने और सरकार और नियामकों द्वारा किए गए उपायों के साथ, इस क्षेत्र ने बिक्री के साथ-साथ नए लॉन्च में लगातार सुधार के साथ और अधिक मजबूत वृद्धि करते हुए वापसी की है।

10.19 रूस और यूक्रेन के बीच भू-राजनीतिक तनाव होने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में पुन: व्यवधान आया है। और रियल एस्टेट क्षेत्र पर इसके होने वाले प्रभाव से चिंताएं बढ़ी हैं। अस्थिर अंतरराष्ट्रीय बाजार और निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि ने विभिन्न डेवलपर्स द्वारा चलाए जा रहे निर्माण कार्यों को रोकने पर विवश किया है। सीमेंट, चूना और प्लास्टर का थोक मूल्य सूचकांक दिसंबर 2021 में 127.1 से बढ़कर दिसंबर 2022 के दौरान 137.6 हो गया, जोकि निर्माण कार्यों के लिए इनफट लागत में वृद्धि का संकेत है। रूस-यूक्रेन संघर्ष ने आपूर्ति श्रृंवला को काफी अधिक प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप स्टील, सीमेंट, परिष्करण सामग्री, आयातित रसायनों और ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई है, और इससे समग्र निर्माण लागत के साथ ही साथ आवास की कीमतों में वृद्धि हुई है।

10.20 आवास ऋण पर बढ़ती ब्याज दरें और संपत्ति की कीमतों में वृद्धि जैसी वर्तमान बाधाओं के बावजूद, इस क्षेत्र में चालू वर्ष में लचीला विकास देवा गया है। आवासों की बिक्री और वित्तीय वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में नए घरों की लॉन्चिंग महामारी-पूर्व वित्तीय वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही के स्तर को भी पार कर गई है। वित्तीय वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही के दौरान पिछले साल के 42 महीनों की तुलना में इन्वेंट्री ओवरहैंग[9] में 33 महीनों तक की महत्वपूर्ण गिरावट का प्रमाण है। निर्माण के विभिन्न चरणों के अधीन 80 प्रतिशत स्टॉक के साथ 2022 के अंत में बिना बिके इन्वेंट्री की संख्या 8.5 लाख थी। इस क्षेत्र की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र महामारी के प्रभाव से लगातार उबर रहा है। इसके अलावा, हाल ही में सरकार द्वारा किए गए उपायों जैसे इस्पात उत्पादों, लौह अयस्क और इस्पात मध्यस्थों पर आयात शुल्क में कमी इत्यादि से निर्माण लागत में कमी आएगी और आवास की बढाती कीमतों को रोकने में मदद मिलेगी।

चित्र X.9: हाउसिंग सेल्स और लॉन्च में निरंतर वृद्धि, पूर्व-महामारी के स्तर को पार करना

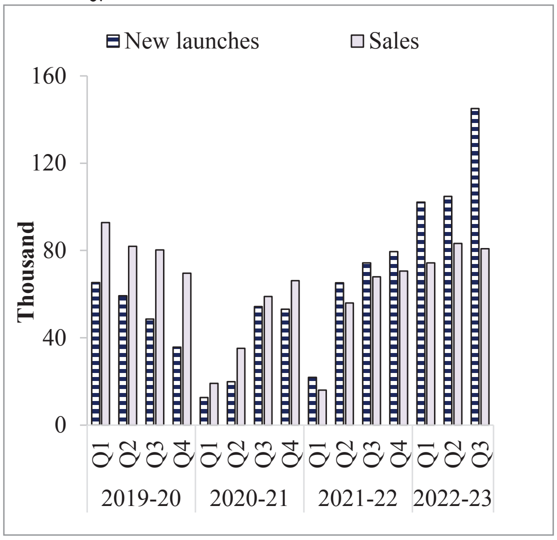

चित्र X.10: इन्वेंटरी ओवरहैंग में गिरावट

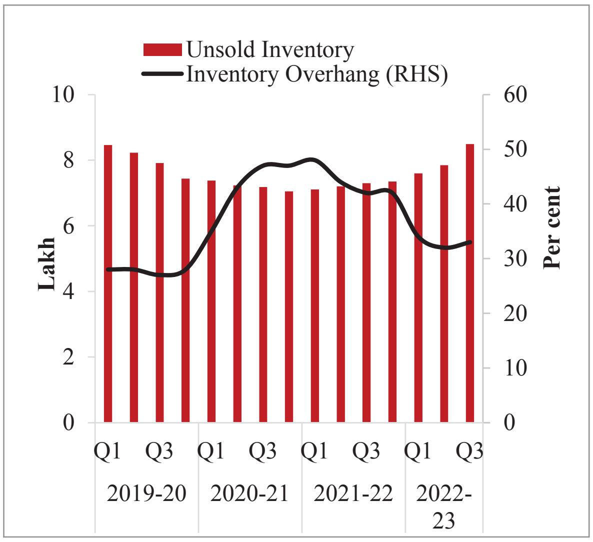

स्रोत: प्रोप टाइगर

10.21 जेएलएल के 2022 ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स[10][11] के अनुसार, भारत के रियल एस्टेट बाजार की पारदर्शिता वैश्विक स्तर पर शीर्ष दस सबसे बेहतर बाजारों में से एक है। इसके समग्र पारदर्शिता (ट्रांसपेरेंसी) स्कोर में वर्ष 2020 में 2.82 से 2022 में 2.73 का सुधार हुआ है, जो संस्थागत निवेश में वृद्धि

[9] Inventory overhang refers to the estimated time period developers are likely to take to sell off the unsold inventory, based on the current sales velocity.

[10] The Global Real Estate Transparency Index is based on a combination of quantitative market data and survey results across 94 countries and 156 city markets. The Index scores markets on a scale of 1 to 5 based on their performance in the following indicators-Performance measurement, Market fundamentals, Governance of Listed Vehicles, Regulatory and Legal, Transaction Process and Sustainability

[11] https://www.us.jll.com/content/dam/jll-com/documents/pdf/research/global/jll-global-real-estate-transparency-index-2022.pdf. A lower value represents a more transparent market, and a higher value represents that the market is opaque

और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) ग्राहकों की बढ़ती संख्या का वाहक है। मॉडल टेनेंसी एक्ट और भूमि रजिस्ट्रियों का डिजिटलीकरण और धरणी तथा महा रेरा प्लेटफार्मों के माध्यम से बाजार डेटा जैसी नियामक पहलों ने बाजार को व्यापक बनाने और क्षेत्र में अधिक औपचारिकता लाने में मदद की है।

चित्र X.11: 2020 और 2022 के बीच वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में शीर्ष पारदर्शिता सुधारक

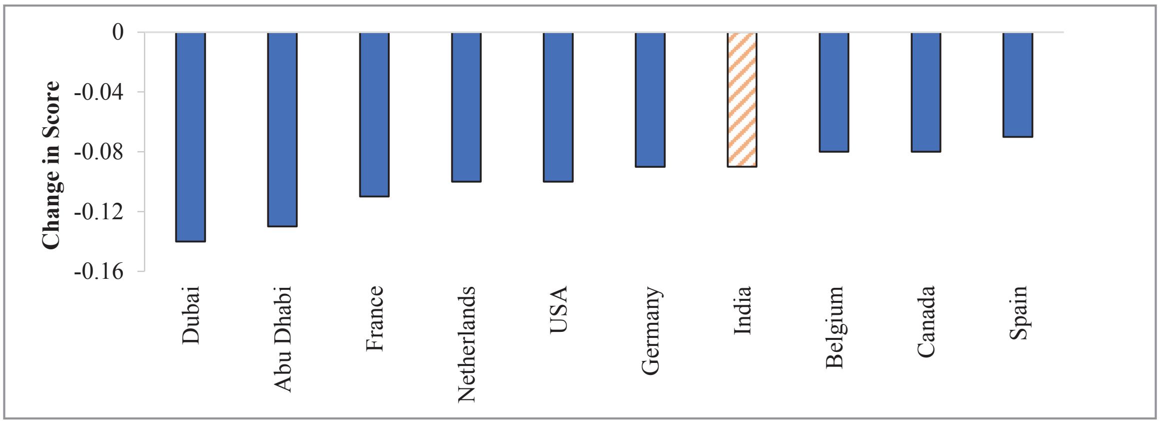

स्रोत: जेएलएल, लासेल 2022

आईटी-बीपीएम उद्योग

10.22 कोविड-19 महामारी ने भारत के अधिकांश अंतिम-उपयोगकर्ता उद्योगों में डिजिटल परिवर्तन की गति को तेज कर दिया है, जिससे कंपनियों के निवेश में वृद्धि, अधिक जटिल प्रौद्योगिकी अभिसरण उपयोग-मामले, और एंटरप्राइज-स्केल डेटा और क्लाउड रणनीति की प्राथमिकता(प्रायोरिटी) में तेजी देखी गई है। मूल्य श्रृंवला में तेजी से डिजिटलीकरण से, अंतिम-उपयोगकर्ता उद्योग दीर्घावधि के लिए एक विकासवादी यात्रा के समग्र एवं बेहतर उद्यम निष्पादन समाधान अपनाने के लिए तैयार हैं।

10.23 एनएएसएससीओएम की रिपोर्ट के अनुसार[12], प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग, त्वरित प्रौद्योगिकी अपनाने और डिजिटल परिवर्तन फलस्वरूप भारत का आईटी-बीपीएम उद्योग महामारी के दौरान भी लचीला बना रहा। यह बात दुनिया के सबसे बड़े आईटी वर्कफोर्स में तीव्र और व्यापक पैमाने पर रिमोट वर्किंग एडॉप्शन से स्पष्ट होती है। महामारी की पहली लहर से मिली सीव से सबक लेते हुए, उद्योग दूसरी लहर के दौरान तत्काल चुनौतियों का समाधान करने के विकल्प से आगे निकलकर भविष्य के लिए तैयार रहने वाले संगठन के रूप में विकसित होने लगें है। ग्राहक-केंद्रित, डोमेन-विशिष्ट समाधान, डिजिटल-फर्स्ट टैलेंट पूल, और भविष्य के लिए तैयार रहने वाले समाधान के तौर पर लेजर-शार्प फोकस प्रमुव स्तंभ रहे हैं, जिन्होंने प्रौद्योगिकी फर्मों को महामारी के दौरान उभरती ग्राहक मांग के लिए सक्रिय रूप से निष्पादन करने में सक्षम बनाया गया है।

10.24 आईटी-बीपिएम राजस्व ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान 15.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 2021 में 2.1 प्रतिशत थी, इसमें सभी उप-क्षेत्र दोहरे अंकों वाली राजस्व वृद्धि भी शामिल थी। आईटी-बीपिएम क्षेत्र में, आईटी सेवाओं का अधिकांश हिस्सा (51 प्रतिशत से अधिक) शामिल है। प्रौद्योगिकी पर व्यवसायों की बढ़ती निर्भरता, लागत कम करने वाले सौदों[13] के रोल-आउट और कोर संचालन के उपयोग के कारण वित्तीय वर्ष 2022 में निर्यात (हार्डवेयर सहित) में 17.2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2021 में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप (यूके को छोड़कर) के साथ सभी प्रमुव

[12] https://nasscom.in/knowledge-center/publications/technology-sector-india-2022-strategic-review

[13] Cost-reducing deals refer to business deals which result in a decline in the company's expenses to maximise profits. It involves identifying and removing expenditures that do not provide added value while also optimizing processes to improve efficiency.

बाजारों में निर्यात में वृद्धि देखी गई और यूके प्रमुख बाजार बना रहा। कई कंपनियां अब नए बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, खासकर मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका जो बाजार विविधीकरण की ओर अग्रसर हैं जिससे आने वाले वर्षों में आईटी-बीपीएम क्षेत्र की लचीलापन में वृद्धि होगी। वित्तीय वर्ष 2022 में उद्योग ने प्रत्यक्ष कर्मचारी पूल में लगभग 10 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर्ज की, जिसमें इसके कर्मचारी आधार में सबसे अधिक निवल-वृद्धि हुई। उद्यम डिजिटल की गति तेज होने और परिवर्तन के कारण घरेलू प्रौद्योगिकी उद्योग में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी अनुमानित है।

चित्र X.12: IT-BPM निर्यात का भौगोलिक वितरण (हार्डवेयर को छोड़कर) FY22 में राजस्व का खंड-वार ब्रेक-अप

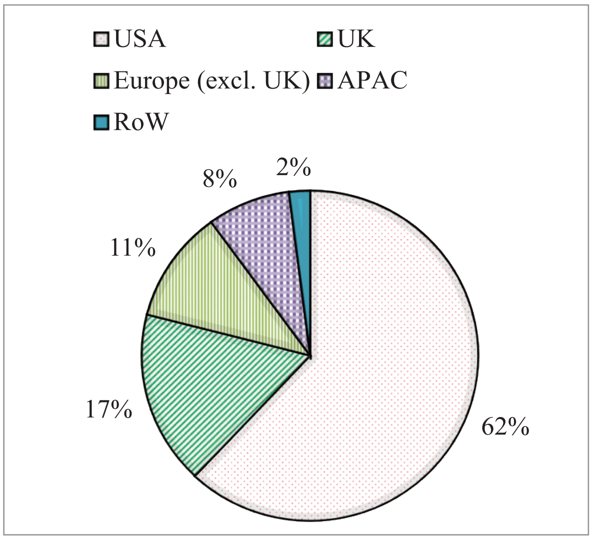

चित्र X.13: वित्त वर्ष 22 में राजस्व का राज्यवार विवरण

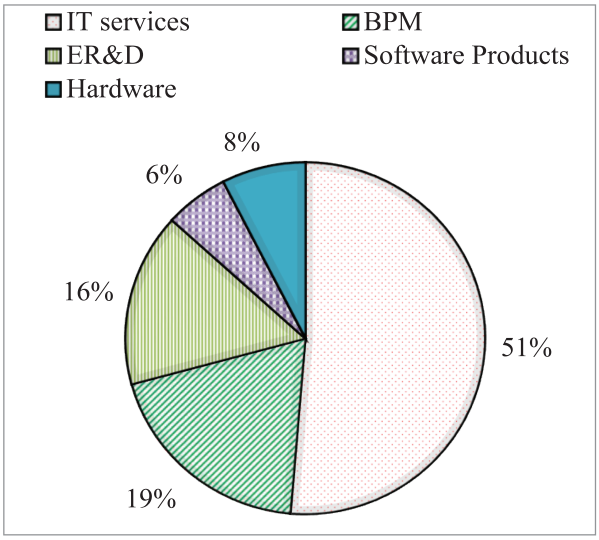

स्रोतः नैसकॉम
एपीएसी का अर्थ एशिया प्रशांत क्षेत्र है

10.25 उद्योग जगत ने मुख्य रूप से डिजिटल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय वर्ष 2022 में 290 से अधिक विलय और अधिग्रहण किए हैं। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म को भारत के डिजिटल लाभ का आधार बनने के साथ ही भारत के बड़े डिजिटल बुनियादी ढांचे ने प्रौद्योगिकी को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि, अगस्त 2022 में एनएएसएससीओएम की तिमाही समीक्षा से संकेत मिलता है कि वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान प्रौद्योगिकी उपयोग में अपेक्षित वैश्विक मंदी के कारण म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिल सकती है।

बॉक्स X.4: आईटी-बीपीएम उद्योग में प्रमुख विकास वाहक

- **डिजिटल तकनीक की बढ़ती पैठ और "मेड इन इंडिया डिजिटल-फर्स्ट सॉल्यूशंस फॉर द वर्ल्ड।"**

  भारत में वित्तीय वर्ष 2020 के लगभग 26.28 प्रतिशत से कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में डिजिटल राजस्व का अनुपात वित्तीय वर्ष से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022 में 30-32 प्रतिशत हो गया है। हाल के वर्षों में, भारत इंजीनियरिंग आर एंड डी (ई आर एंड डी) और नवाचार के लिए एक वैश्विक पावर हाउस के रूप में उभरा है और वैश्विक उद्यमों के लिए भविष्य में विकास और नवाचार की शुरुआत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले छह वर्षों में भारत में कई वैश्विक योग्यता केंद्र (जीसीसी) स्थापित किए गए हैं। भारत में जीसीसी तेजी से कंप्लेक्स आर एंड डी कार्य कर रहे हैं और भविष्य की तकनीकों का लाभ उठा रहे हैं और डिजिटल रूप से नवीन उत्पादों को विकसित कर रहे हैं और साथ ही या तो सबसे बड़े या दूसरे सबसे बड़े ई आर एंड डी हब का निर्माण भारत में कर रहे हैं। पेटेंट फाइलिंग में भी भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-21 के बीच 138,000 से अधिक पेटेंट दाखिल किए गए हैं, जिसमें 85,000 से अधिक पेटेंट उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में दाखिल किए गए हैं।

- **परिचालन उत्कृष्टता के माध्यम से मार्जिन डिफेन्स**

  आपूर्ति संबंधी चुनौतियों के रहते मार्जिन डिफेंस महत्वपूर्ण फोकस बना हुआ है चूंकि तकनीकी प्रतिभा (टेक टैलेंट) की बढ़ती मांग के कारण लागत में मामूली वृद्धि होती है। प्रमुख मार्जिन लीवर में बढ़ी हुई क्षमता का उपयोग, विदेशी राजस्व का एक उच्च हिस्सा, यात्रा और सुविधा लागत का न्यूनतम हिस्सा और परिचालन शक्ति शामिल हैं।

- **भारत एक डिजिटल टैलेंट नेशन है**

  कामकाजी आबादी के उच्च स्तर और बढ़ते स्नातक नामांकन के साथ भारत एक डिजिटल प्रतिभा सम्पन्न राष्ट्र के रूप में उभरा है। डिजिटल प्रतिभा में वृद्धि के साथ प्रौद्योगिकी कंपनियों में रोजगार वृद्धि देखी जा हरी है। गैर-तकनीकी प्रतिभाओं को फिर से कुशल बनाने पर ध्यान दिए जाने के परिणामस्वरूप टियर-2 शहरों से नई-नई प्रतिभाएं निकल रही हैं। इससे भारत को एक महत्वपूर्ण उप-कांट्रेक्टर आधार के रूप में विकसित होने में मदद मिली है, और इस क्षेत्र में अधिकाधिक महिलाएं शामिल हो रही हैं।

- **हाइब्रिड वर्क मॉडल में अग्रणी**

  भारतीय तकनीकी उद्योग हाइब्रिड वर्क मॉडल को अपनाने में अग्रणी है। कर्मचारियों के अनुभव को बढ़ाने और कर्मचारी ऑनबोर्डिंग, संचार, सहयोग, और कर्मचारी कल्याण और सक्षमता जैसे पहलुओं में तकनीकी समाधानों (टेक सोल्यूसंस) को एकीकृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक प्रमुख वाहक रही है। संगठनों में मानव संसाधन संबंधी कार्य परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। संगठन की सेवाओं का विस्तार करते हुए लागत को कम करने के उद्देश्य से मानव संसाधन के कार्यों को आगे बढाया जा रहा है। श्रम मध्यस्थता, अनुकूलित कार्यबल मॉडल, प्रतिभा की तरलता में वृद्धि और लोगों की जगह (कार्य स्थल) की लागत को कम करके लागत में कमी की जा रही है।

ई-कॉमर्स

10.26 महामारी के बाद आईटी-बीपीएम क्षेत्र की तर्ज पर, ई-कॉमर्स क्षेत्र में भी नए सिरे से बढ़त देखने को मिली है। लॉकडाउन और आवागमन संबंधी प्रतिबंधों ने उपभोक्ताओं के कार्य-व्यवहार को बाधित किया है और ऑनलाइन खरीदारी को प्रोत्साहित किया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रोत्साहन, इंटरनेट की बढ़ती उपयोगिता, स्मार्टफोन के प्रयोग में वृद्धि, मोबाइल प्रौद्योगिकी में नवाचार, और डिजिटल भुगतानों को अपनाने में वृद्धि संबंधी समस्त गतिविधियों ने ई-कॉमर्स के अपनाने और विकास को और अधिक तीव्र करने के लिए प्रेरित किया है। वर्ल्डपे के एफआईएस की ग्लोबल पेमेंट्स रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ई-कॉमर्स बाजार में 2025 तक सालाना 18 फीसदी की दर से वृद्धि होने का अनुमान है।

10.27 ई-कॉमर्स के नए सेगमेंट जैसे-ग्रोसरी, फ्रेश-टू-होम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और जनरल मर्चेंडाइज के विस्तार ने पारंपरिक खरीदारों से अलग हटकर ग्राहक आधार के विस्तार में योगदान दिया है। बैन एंड कंपनी की नवीनतम रिपोर्ट 'हाउ इंडिया शॉप्स ऑनलाइन 2022' के अनुसार, उभरती श्रेणियां जैसे-फैशन, ग्रॉसरी, जनरल मर्चेंडाइज इत्यादि से भारत में ई-कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा और ई-कॉमर्स 2027 तक भारतीय बाजार के लगभग दो-तिहाई हिस्से पर कब्जा जमा लेगा।

10.28 राजस्व और मार्जिन में वृद्धि, बेहतर बाजार पहुंच, नए बाजारों तक पहुंच और ग्राहक अधिग्रहण की संभावनाओं को महसूस किया गया है और इसलिए एमएसएमई ने ई-कॉमर्स और ई-प्रोक्योरमेंट जैसे डिजिटल समाधानों को बड़े पैमाने पर अपनाया है। एमएसएमई और ई-कॉमर्स के बीच परस्पर विचार-विमर्श के प्रभाव का विश्लेषण करने वाली संस्था आईआईएफटी की हालिया अध्ययन में पाया गया है कि हाल के वर्षों में डिजिटल समाधान अपनाने वाले एमएसएमई ने ऑफलाइन एमएसएमई की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे उन्हें अधिक लागत वर्च किए बिना एक बड़े बाजार तक पहुंचने में मदद मिली है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने न केवल भौगोलिक बाधाओं को दूर करके और एक बड़ा ग्राहक आधार के साथ छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाया है,

बल्कि उन्हें निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं से सीधे निपटने (व्यवसाय व्यवहार करने) की अनुमति भी दी है, जिससे खरीद की लागत कम हो गई है। आपूर्तिकर्ताओं तक यह बढ़ी हुई पहुंच छोटे व्यवसाय के मालिकों को उनके अपने व्यवसायों को बहुत कम पूंजी निवेश से बढ़ाने में मदद करती है। इस प्रकार उनकी लागत संरचना को बल मिलता है।

10.29 इसके अलावा, ग्रामीण भारत में स्मार्टफोन की पहुंच, अधिकांश लोगों द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने और ग्रामीण ग्राहकों की क्रय शक्ति में हुई वृद्धि के कारण ई-कॉमर्स व्यवसाय में विकास के साथ ही साथ अभूतपूर्व भौगोलिक विस्तार भी हुआ है। इसके अतिरिक्त, महामारी के दौरान वित्तीय सहायता ने ग्रामीण क्षेत्रों में ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने में मदद की। नतीजतन, महामारी के कारण लगे प्रतिबंधों के दौरान ऑनलाइन खरीदारी में वृद्धि हुई थी। एक विशाल अप्रयुक्त बाजार में खपत वृद्धि को मजबूत करने की क्षमता है। नई-नई ई-कॉमर्स कम्पनियाँ जैसे-ट्रेल, मीशो और शॉप 101 टीयर 3 और 4 शहरों में विस्तार कर रही हैं और लोकप्रियता भी हासिल कर रही हैं। ई-कॉमर्स उद्योग ग्रामीण वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के नेटवर्क को मजबूत करते हुए और स्थानीय वितरण केंद्रों को पिक अप ड्रॉप ऑफ पॉइंट के रूप में उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाने के लिए स्थानीय समाधानों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं ताकि रसद(लोजिस्टिक्स) कंपनियां ग्रामीण उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा कर सकें।

चित्र X.14: 2027 तक भारतीय ई-कॉमर्स बाजार के लगभग दो-तिहाई हिस्से पर का करने के लिए फैशन, किराना और सामान्य व्यापार

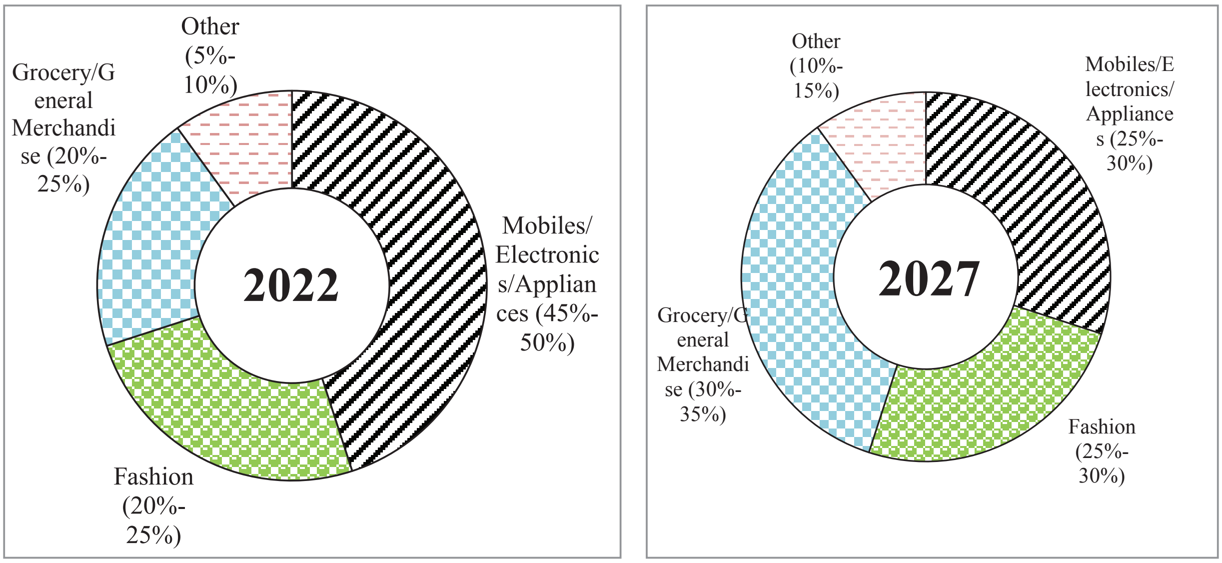

स्रोत: हाउ इंडिया शॉप्स ऑनलाइन 2022, बैन एंड कंपनी

10.30 ऑर्डर की मात्रा और मूल्यांकन के मामले में, भारतीय ई-कॉमर्स स्टार्ट-अप के लिए कोविड-19 के बाद के वर्ष सबसे सफल वर्ष रहे हैं। यूनिकॉमर्स और वजीर एडवाइजर्स[14] द्वारा जारी 'रिटेल और ई-कॉमर्स ट्रेंड्स' के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022 में समग्र ई-कॉमर्स ऑर्डर वॉल्यूम में 69.4 प्रतिशत की वृद्धि देवी गई, जो मुख्य रूप से टियर-II और टियर-III शहरों के उपभोक्ताओं द्वारा विगत दो वर्षों में संचालित की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2022 में कुल बाजार हिस्सेदारी में टियर-II और टियर-III शहरों के खरीदारों की हिस्सेदारी 61.3 प्रतिशत से अधिक थी, जो कि वित्त वर्ष 2021 में 53.8 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2022 में टियर-II और टियर-III शहरों से ऑर्डर की मात्रा क्रमशः 92.2 प्रतिशत और 85.2 प्रतिशत रही जो कि टियर-I शहरों की तुलना में लगभग दोगुनी है। इसके विपरीत, टियर-1 शहरों की ऑर्डर वॉल्यूम वृद्धि दर 47.2 प्रतिशत रही जो कि तुलनात्मक रूप से कम है।

[14] https://retail.economictimes.indiatimes.com/files/cp/1294/cdoc-1661333692-ECOM_july_7_5in%20x%208in_Correction.pdf

10.31 गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने भी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (GMV) में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है और यह Amazon और Flipkart जैसे ई-कॉमर्स दिग्गजों को भी टक्कर दे रहा है। GeM ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 160 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2022 में ₹ 1 लाख करोड़ की वार्षिक खरीद आर्डर प्राप्त किया है। GeM ने स्वयं सहायता समूहों (SHG), आदिवासी समुदायों, कारीगरों, बुनकरों और एमएसएमई के उत्पादों को ऑनबोर्ड करने के लिए कई कदम उठाए हैं। GeM पर कुल कारोबार का 57 प्रतिशत उत्पाद एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से आए हैं और इसमें महिला उद्यमियों ने 6 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया है।

10.32 हाल के वर्षों में, ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारी पहल की गई हैं जिसमें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, यूपीआई, जीईएम आदि शामिल है। ये सभी पहल ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने में प्रमुख रूप से योगदान देने वाले घटक हैं। इस क्षेत्र के छोटे तथा खुदरा विक्रेताओं, विनिर्माताओं और स्वयं सहायता समूहों को अवसर प्रदान करने तथा इस प्लेटफार्म तक उनकी अधिकाधिक आउटरिच को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई हैं। वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट (ODOP) पहल ग्रामीण क्षेत्र के छोटे व्यवसायियों को उनके चिह्नित उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड करने तथा इस प्लेटफोर्म के माध्यम से उनकी बिक्री को सुगम बनाने के लिए कार्य कर रहा है। ई-मार्केटप्लेस www.tribesindia.com पोर्टल ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड) के माध्यम से आदिवासी कारीगरों के उत्पादों को ऑनलाइन बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफोर्म पर ऑनबोर्ड कर रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासियों द्वारा निर्मित उत्पादों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जा सके।

10.33 ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) की शुरूआत से की गई पहल डिजिटल भुगतानों को लोकतांत्रित बनाने, इंटरऑपरेबिलिटी को सक्षम बनाने और लेनदेन लागत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह पहल ओएनडीसी विक्रेताओं को बेहतर बाजार तक उनकी पहुंच को बढाने और देश के दूरस्थ स्थानों को भी ई-कॉमर्स से जोड़ने और डिजिटलीकरण के साथ उन्हें सशक्त बनाने में मदद करता है। ओएनडीसी की प्रयोज्यता और इसके लाभों के बारे में अध्याय-12 'डिजिटल एवं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर: लिफ्टिंग पोटैशियल ग्रोथ' में चर्चा की गई है।

डिजिटल वित्तीय सेवाएं

10.34 उभरती प्रौद्योगिकियों और अभिनव समाधानों द्वारा संभव हुई डिजिटल वित्तीय सेवाएं, वित्तीय समावेशन, लोकतंत्रीकरण और उत्पादों के निजीकरण (मानवीकरण) को तीव्र गति से बढ़ावा दे रही हैं। जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), और अन्य नियामक ढांचे द्वारा डाली गई एक मजबूत नींव के साथ, महामारी ने लेनदेन के लिए डिजिटल प्लेटफोर्म को अपनाने में सहायता की है और बैंकों की डिजिटल वित्तीय सेवा-समाधान, एनबीएफसी, बीमाकर्ता और फिनटेक के लिए भी प्रोत्साहित किया है। महामारी ने फिनटेक कंपनियों को वंचित वर्गों तक पहुंचने और समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी कम लागत वाली वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का अवसर दिया है। विश्व स्तर पर, तकनीकी समाधानों की वजह से महामारी का दुष्परिणाम भी कम हुआ है। भारत में फिनटेक अंगीकरण (एडोप्सन) की दर 87 प्रतिशत रही है, जो कि नवीनतम ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन इंडेक्स[15] के अनुसार 64 प्रतिशत के विश्वक औसत से काफी अधिक है।

10.35 पिछले कुछ वर्षों में, नियोबैंकिंग प्लेटफॉर्म की संख्या और नियो-बैंकिंग सैग्मेंट के वैश्विक निवेश में भी लगातार वृद्धि हुई है। नियोबैंक मुख्यधारा के वित्तीय छत्रछाया में काम करते हैं। पर, ये पारंपरिक संस्थानों जैसे-बैंकों, भुगतान प्रदाताओं आदि से लंबे समय से सम्बद्ध विशिष्ट सेवाओं को भी सशक्त बनाते हैं। नियोबैंक पूरी तरह से ऑनलाइन मोड़ में काम करते हैं और ऑफलाइन मोड़ में कार्यालय स्थान के अलावा और कहीं

[15] https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/banking-and-capital-markets/ey-global-fintech-adoption-index.pdf

इनकी भौतिक उपस्थिति नहीं होती है। इन संस्थानों की समृधि मुख्यरूप से डिजिटल-कुशल युवा आबादी की ऑन-डिमांड और आसानी-से-पहुंच वाले वित्तीय समाधानों की आवश्यकताओं पर निर्भर होती है। नियोबैंक ने उपलब्धता को सुगम बना दिया है और एमएसएमई एवं बैंकिंग सुविधाओं से वंचित ग्राहकों और क्षेत्रों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढाई है। सरकार ने भी अपने विभिन्न प्रयासों के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग समाधानों को बढ़ावा दिया है। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) पूरे देश के कोने-कोने तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए शुरू की गई हैं।

10.36 सीबीडीसी की शुरुआत होने से डिजिटल वित्तीय सेवाओं को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। भारत में सीबीडीसी जारी करना कई मायनों में लाभकारी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नकदी लेन-देन प्रबंधन की परिचालन लागत की कमी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, भुगतान प्रणाली में लचीलापन, दक्षता और नवीनता लाना, देश से बाहर भुगतान में नवाचार को बढ़ावा देना इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ ही जनसमुदाय की आभासी मुद्रा से जुड़े जोखिमों को कम करते हुए इसके सुरक्षित उपयोग के लिए सुविधाएं देना भी इसमे शामिल है। जुलाई 2022 तक 105 देश, सीबीडीसी के बारे में छानबीन कर रहे हैं। इसमें संख्या में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 95 प्रतिशत शामिल है। कई देशों ने पहले ही सीबीडीसी शुरू कर दिया है और कुछ अन्य देशों में यह प्रक्रियाधीन है।

10.37 भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में थोक और खुदरा दोनों सेगमेंट में सीबीडीसी के पायलट्स लाँच किए हैं। डिजिटल रुपी-रिटेल थोक सेगमेंट में पायलट को 1 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था और इसे सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन-देन के निपटान तक ही इसका उपयोग सीमित रवा गया था। डिजिटल रुपये का उपयोग-थोक से अंतर-बैंक बाजार के और अधिक कुशल बनने की उम्मीद है। रिटेल सेगमेंट में पायलट, जिसे डिजिटल रुपी-रिटेल के रूप में भी जाना जाता है, इसे 1 दिसंबर 2022 को सीमित संख्या में भागीदार ग्राहकों और व्यापारियों के एक समूह में शरू किया गया। सीबीडीसी के पूर्ण संचालन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक प्रारंभिक चरम के दौरान प्राप्त इसकी फीडबैक के आधार पर अधिक से अधिक बैंकों, उपयोगकर्ताओं और स्थानों को शामिल करने के लिए धीरे-धीरे पायलट्स के दायरे को बढ़ा रहा है।

10.38 डिजिटल वित्तीय सेवाओं को गति देने में दस्तावेजों के डिजिटलीकरण ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दस्तावेजों के डिजिटलीकरण से सुरक्षा, ऑनलाइन सत्यापन, बेहतर पहुंच में वृद्धि हुई है और धोखाधड़ी में भी कमी आई है। इससे अंतिम ग्राहक के उपयोग और सेवा प्रदाता की कार्य कुशलता में बढ़ोतरी हुई है।

बॉक्स X.5: अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क: भारत की वित्तीय सेवाओं में बदलाव

अकाउंट एग्रीगेटर (एए) एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है जो ग्राहक से संबंधित वित्तीय जानकारी प्राप्त करने या एकत्र करने की सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना एए द्वारा ग्राहक की कोई भी वित्तीय जानकारी पुनर्प्राप्त, साझा या स्थानांतरित नहीं की जाती है। एए किसी व्यक्ति के निर्देश और सहमति के आधार पर एक वित्तीय संस्थान से दूसरे संस्थान में डेटा स्थानांतरित करता है। उपभोक्ताओं के लिए एए के साथ पंजीकरण पूरी तरह से स्वैच्छिक है। संस्थाएं वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) अर्थात बैंकिंग कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बीमा कंपनी, बीमा रिपॉजिटरी, पेंशन फंड आदि और वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयु) जो किसी भी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा पंजीकृत और विनियमित संस्था है, के रूप में एए फ्रेमवर्क पर स्वयं को नामांकित कर सकती हैं। इस दिशा में, आरबीआई ने दिनांक 02 सितंबर, 2016 को मास्टर दिशा-निर्देश अर्थात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अकाउंट एग्रीगेटर (रिजर्व बैंक) निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में, आरबीआई ने एए के रूप में छह कंपनियों को पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया है।

अब तक की उपलब्धियां

- दिनांक 31 दिसंबर 2022 तक, 27 वित्तीय संस्थान एफआईपीएस के रूप में चालू हो गए हैं, जिसमें सभी 12 पीएसबीएस, 10 निजी क्षेत्र के बैंक, 1 लघु वित्त बैंक और 4 जीवन बीमा कंपनियां शामिल हैं।

- 119 वित्तीय संस्थान एफआईपीएस के रूप में चालू हो गए हैं; 93 आरबीआई द्वाराविनियमित, 12 सेबी द्वाराविनियमित, 12 आईआरडीएआई-विनियमित संस्थाएं, और 2 पीएफआरडीए-विनियमित संस्थाएं हैं।
- अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में 23 बैंकों के शामिल होने के साथ, 1.1 बिलियन से अधिक बैंक खाते एए पर डेटा साझा करने के पात्र हैं। 3.3 मिलियन उपयोगकर्ताओं ने अपने खातों को एए ढांचे से जोड़ा है, जिनमें से 3.28 मिलियन उपयोगकर्ताओं ने सफलतापूर्वक एए के माध्यम से डेटा साझा किया।
- आरबीआई ने दिनांक 23 नवंबर 2022 को माल और सेवा कर नेटवर्क को एफआईपी के रूप में अधिसूचित किया है जो डिजिटल इनवॉइस वित्तपोषण को सक्षम करेगा और एमएसएमई क्षेत्र को बहुत आवश्यक क्रेडिट प्रदान करेगा।

बॉक्स X.6: दस्तावेजों का डीमैटीरियलाइजेशन: डिजिटलीकरण की अगली लहर

डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त राष्ट्र बनाने का है। नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NeSL), जोकि एक 'इन्फोर्मेशन यूटिलिटी' है और जिसे आईबीसी 2016 के तत्वावधान में भारत के दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के साथ पंजीकृत किया गया है और इसी के द्वारा विनियमित किया जाता है, ने 2020 में डिजिटल दस्तावेज निष्पादन (DDE) प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया। यह कार्य भारत के इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड की अनुमति से और वित्तीय सेवा विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय के सहयोग से किया गया था।

एनईएसएल-डीडीई प्लेटफॉर्म का मूल सिद्धांत दस्तावेजों/करार निष्पादन के सभी चरणों को डिजिटाइज करना है। इसमें शामिल है:-

- मंच पर प्रस्तुत की जाने वाली सूचना और दस्तावेज निष्पादित किए जाने वाला समझौता
- किसी भी समझौते/दस्तावेज प्रारूप को समायोजित करने के लिए लचीलापन
- सहमति आधारित प्रक्रिया
- स्टाम्प शुल्क का डिजिटल भुगतान एवं डिजिटल ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र लगाना
- निष्पादकों की पहचान का सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग करके डिजिटल निष्पादन करना
- प्लेटफॉर्म के उपयोग से उत्पन्न डिजिटल रूप से निष्पादित दस्तावेज का सुरक्षित भंडारण, संचरण और पुनर्प्राप्ति करना

एनईएसएल-डीडीई प्लेटफॉर्म, निष्पादकों की प्रत्यक्ष उपस्थिति और दस्तावेजों/समझौतों को निष्पादित करने के लिए मैन्युअल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसा करके, मंच (प्लेटफॉर्म) कई तरह से लाभ पहुंचता है जैसे-कम निष्पादन समय और कम लागत, एक सुरक्षित प्रणाली, अधिकृत पहुंच, थोक प्रसंस्करण, धोखाधड़ी की रोकथाम, कानूनी मजबूती और साक्ष्य आधारित सेवा। वित्तीय क्षेत्र में दस्तावेजों/समझौतों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में आधार ई-हस्ताक्षर का उपयोग एक महत्वपूर्ण संबल है। इससे नागरिकों को मामूली लागत पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर बड़े पैमान पर उपलब्ध हुए हैं।

एनईएसएल-डीडीई मंच (प्लेटफॉर्म) को राज्य सरकारों, मंत्रालयों और वित्तीय संस्थानों का समर्थन भी है। डीएफएस, बैंकों को उनके समझौतों के लिए डीडीई को अपनाने पर विचार करने के लिए भी प्रोत्साहित करता रहा है। वर्तमान में, 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एनईएसएल डीडीई प्लेटफॉर्म पर डिजिटल ई-स्टांपिंग के लिए उपलब्ध हैं। 27 बैंक और एनबीएफसी अपने समझौतों को निष्पादित करने के लिए इस मंच का उपयोग कर रहे हैं और अब तक 9 लाख से अधिक लेन-देन किए जा चुके हैं। इसमें छोटे-टिकट वाले उपभोक्ता ऋण लेनदेन से लेकर बड़े-मूल्य वाले कॉर्पोरेट ऋण लेन-देन शामिल हैं।

एनईएसएल-डीडीई प्लेटफॉर्म का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी) भी है, जो प्रत्यक्ष बैंक गारंटी को जारी करने, हस्तांतरण और प्रबंधन से जुड़े सभी मुद्दों और चुनौतियों को समाप्त करता है और समय और लागत की बचत करता है। जैसे-जैसे ई-बीजी को अपनाने में तेजी आएगी, वैसे ही एनईएसएल प्लेटफॉर्म बैंक गारंटी के केंद्रीय भंडार के रूप में भी काम कर सकता है। हाल ही में, व्यय विभाग ने सरकारी खरीद प्रक्रिया में ई-बीजी को अपनाए जाने की अनुमति देने के लिए सामान्य वित्तीय नियम, 2017 में संशोधन किया है।

हालाँकि, एनईएसएल-डीडीई का प्रारंभिक उपयोग वित्तीय दस्तावेज/समझौतों के लिए है, पर यह मंच अन्य दस्तावेजों/समझौतों के डिजिटल निष्पादन को भी सक्षम बनाएगा। एनईएसएल-डीडीई द्वारा प्रस्तुत इस सुरक्षित, कागज रहित और झंझट-मुक्त अनुबंध से देश में आसानी से व्यापार करने में महत्वपूर्ण सुविधा होगी।

आउटलुक

10.39 भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि, जो पिछले 2 वित्तीय वर्षों के दौरान अत्यधिक अस्थिर और नाजुक बनी हुई थी, ने वर्ष 2022-23 में लचीलापन दिखाया है। इसका कारण स्थिर मांग, गतिशीलता प्रतिबंध में ढील, लगभग सभी का टीकाकरण कवरेज और समयानुसार उचित सरकारी हस्तक्षेप है। हाल के महीनों में बड़े पैमाने पर रिकवरी देखी गई है, जिससे लगभग सभी उप-क्षेत्रों में तेजी आई है। विशेष रूप से गहन-संपर्क सेवा क्षेत्र जिसने महामारी का सबसे अधिक सहन किया भुगता है। यह विभिन्न एचएफआई के निष्पादन में तेजी को दर्शाता है, जिससे हाल के महीनों में ठोस उछाल आया है। अतः इससे अगले वित्तीय वर्ष में सेवा क्षेत्र की बेहतर प्रस्तुति का संकेत मिलता है। पर्यटन, होटल, रियल एस्टेट, आईटी-बीपीएम, ई-कॉमर्स आदि जैसे विभिन्न उप-क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं उज्ज्वल दिख रही हैं। हालांकि, अत्यधिक जोखिम, बाहरी कारकों और विकास को प्रभावित करने वाली उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी वाले कारक भी इसे प्रभावित करते हैं।

11

अध्याय

वैदेशिक क्षेत्र: सतर्क और आशावान

भारत का विदेशी क्षेत्र प्रतिकूलताओं और अनिश्चितता से बार-बार प्रभावित हुआ है, जिससे वैश्विक पण्य वस्तुओं (कमोडिटी) की कीमतों में वृद्धि दिखाई दी, हालांकि जो अब घट रही है; अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थितियों को कड़ा किया गया; वित्तीय बाजार में अस्थिरता बढ़ गयी; पूंजी प्रवाह का उत्क्रमण हुआ; मुद्रा मूल्यह्रास हुआ, और वैश्विक विकास व व्यापार को मंदी का सामना करना पड़ा। हालांकि, यह मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल और बफर स्टॉक की मजबूत स्थिति से इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम रहा है।

वित्त वर्ष 23 (दिसंबर 2022 तक) के दौरान भारत के निर्यात ने वित्त वर्ष 22 में निर्यात के रिकॉर्ड स्तर के बाद लचीलेपन का प्रदर्शन किया है। पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, जैविक और अकार्बनिक रसायन, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स प्रमुख निर्यात वस्तुओं में से थे। हालाँकि, वैश्विक व्यापार में मंदी की विशेषता वाली धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय निर्यात में मंदी अपरिहार्य रही। मध्यम से दीर्घावधि दृष्टिकोण में, बाहरी क्षेत्र के लचीलेपन में सुधार लाने में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन उपायों पर विचार किया जा रहा है/उनको कार्यान्वित किया जा रहा है। ये उपाय उस अंतर्निहित तुलनात्मक लाभ का पोषण करेंगे जो भारतीय निर्यात में समाविष्ट रहेंगे। इसके साथ, जहाँ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी (राष्ट्रीय संभार तंत्र नीति) आंतरिक लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करके भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए घरेलू बाधाओं को कम करेगी, वहीं नवीनतम मुक्त व्यापार समझौते, जैसे संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए हैं, रियायती टैरिफ दर देंगे और गैर-टैरिफ बाधाओं पर निर्यात के अवसर देकर विदेशी बाधाओं को समाप्त कर सकेंगे। इस प्रकार, संपूर्ण आर्थिक प्रणाली समय के साथ निर्यात-अनुकूल तरीके से विकसित होगी।

कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के पुनरूद्धार ने आयात में वृद्धि की है। पेट्रोलियम कच्चे और उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोयला और कोक ब्रिकेट आदि मशीनरी इलेक्ट्रिकल एवं गैर इलैक्ट्रिकल तथा स्वर्ण जैसी शीर्ष आयात वस्तुओं में शामिल थे। जहाँ वैश्विक पण्य मूल्य की स्थिति में निरंतर नरमी आयात को आगे बढ़ने में मदद करेगी, वहां गैर-स्वर्ण, गैर-तेल आयात में उल्लेखनीय कमी नहीं हो सकती है। इसके अलावा, भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्थापन को बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं। एक बार जब इन उपायों ने गति पकड़ ली, तो विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम होगी जो संभावित रूप से अर्थव्यवस्था को विदेशी आर्थिक परिवर्तनों के प्रति कम संवेदनशील बना देगी।

भुगतान संतुलन (BoP) को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दबावों का सामना किया। व्यापार की अदृश्य मद (सेवाएं, हस्तांतरण, और आय) पर अधिशेष द्वारा इसे मंद किए जाने के बावजूद, जहाँ तेल की कीमतों में तेज वृद्धि का प्रभाव चालू खाता घाटा (सीएडी) के बढ़ने में दिखाई दे रहा था वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा नीति को कड़ा करने और अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में बहिर्वाह हुआ। नतीजतन, पूंजी खाते का अधिशेष चालू खाते के घाटे से कम था, जिससे भुगतान संतुलन (BoP) के आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई। हालांकि, आगे चलकर, कच्चे तेल की कीमतों में अपेक्षित कमी, शुद्ध सेवाओं के निर्यात का लचीलापन और आवक धन-प्रेषण में वृद्धि के परिणामस्वरूप

वित्त वर्ष 23 के शेष के दौरान चालू खाता घाटा (CAD) कम होगा और इसके वहनीय सीमा के भीतर रहने की आशा है। वैश्विक विपरीत परिस्थितियों को कम करने के लिए भारत के विदेशी क्षेत्र के सुरक्षा उपाय (फोर्टिफाइड शॉक एब्जॉर्बर) विद्यमान हैं चाहे वह दुर्जेय विदेशी मुद्रा भंडार, स्थायी विदेशी ऋण संकेतक अथवा बाजार-निर्धारित विनिमय दर हो। जबकि दिसम्बर 2022 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, (9.3 महीने के आयात के बराबर) और सितंबर 2022 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी ऋण का अनुपात 19.2 प्रतिशत के पूर्ण नियंत्रणीय स्तर पर है।

परिचय

11.1 नई सहस्राब्दी में दो वैश्विक आघातों - पहला आर्थिक आघात और दूसरा, स्वास्थ्य आघात - का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। 2007-08 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, चूंकि मुद्रास्फीति के दबाव शांत थे, लंबे समय तक ब्याज दरें बेहद कम थीं, और निवेशक कम अस्थिरता के आदी हो गए थे। 2007-08 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, चूंकि मुद्रास्फीतिक दबाव मौन थे, लंबे वर्षों तक ब्याज दरें बेहद कम थीं। आसान वित्तीय स्थितियों ने वैश्विक आर्थिक विकास का समर्थन किया, जो 2010 में 4.5 प्रतिशत तक पहुंच गया। अब, कोविड-19 महामारी वैश्विक विकास के लिए एक और आघात है, 2020 में आर्थिक विकास 3.8 प्रतिशत के नकारात्मक स्तर पर आ गया है। अगले दो वर्षों में वैश्विक वस्तु और खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के कारण मुद्रास्फीति की दर कई दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गई। रूस-यूक्रेन संघर्ष से मुद्रास्फीति का स्तर और बढ़ गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक प्राधिकरण, विशेष रूप से अमेरिका के फेडरल रिजर्व, ''मोनेटरी पालिसी नार्मलाईजेशन'' की गति को तेज कर रहे हैं। अमेरिका में 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 2020 के मध्य से 2022 के मध्य तक की अवधि में लगभग छह गुना बढ़ गया है। कई इमर्जिंग मार्किट और फ्रंटियर मार्किट अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी को स्थानांतरित करने के लिए जोखिम वाली परिसंपत्तियों को तेजी से बेचा गया जिससे 2020 की अंतिम तिमाही के बाद से विकासशील देशों में लौटने वाले निवल पूंजीगत प्रवाह को रुकते हुए देखा गया।

11.2 अप्रैल 2022 से जोखिम वाली परिसंपत्तियों की ब्याज दरें और कीमतें बेहद अस्थिर रही हैं, जो आर्थिक और नीतिगत स्थिति के बारे में बढ़ी हुई अनिश्चितता को दर्शाती है, तथा जो कम तरलता से और खराब हो गयी है। इमर्जिंग मार्किट देशों (ईएमई) और उच्च उधार लागत का सामना करने वाले प्रमुख उन्नत देशों की मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर का तेजी से मूल्यवर्धन हुआ है। इस प्रकार, विशेष रूप से अप्रैल 2022 से वैश्विक वित्तीय स्थितियां काफी कठिन हो गई हैं, और जोखिमों का संतुलन काफी नीचे की ओर झुक गया है, जिससे वैश्विक आर्थिक स्थिति कमजोर हो गयी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)[1] के अनुसार वैश्विक विकास 2021 में 6.0 प्रतिशत से 2022 में 3.2 प्रतिशत और 2023 में 2.7 प्रतिशत तक धीमा होने का अनुमान है। यह वैश्विक वित्तीय संकट और महामारी के तीव्र चरण को छोड़कर 2001 के बाद से सबसे कमजोर विकास प्रतिशत रहा है। इसके अतिरिक्त, विदेशी सार्वजनिक ऋण भेद्यता संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इस तरह का ऋण रिकॉर्ड स्तर पर है और इसका अधिकांश हिस्सा निजी लेनदारों पर बकाया है, जिसमें से अधिकांश पर परिवर्तनीय ब्याज दरें लागू हैं जो अचानक[2] बढ़ सकती हैं। इस प्रकार, उभरते बाजारों को उच्च विदेशी उधार लागतों, स्थिर उच्च मुद्रास्फीति, अस्थिर कमोडिटी बाजारों, अनिश्चित वैश्विक आर्थिक विकास स्थिति और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में नीति को कसने से फैलने वाले जोखिमों (स्पिलओवर प्रभाव) का सामना करना पड़ता है।

---

1 वर्ल्ड इकनोमिक आउटलुक रिपोर्ट, आईएमएफ, अक्टूबर 2022।

2 ''दक्षिण एशिया की वर्तमान व्यापक आर्थिक चुनौतियाँ और नीतिगत प्राथमिकताएँ'', श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक -6 जनवरी 2023 - IMF एशिया और प्रशांत विभाग और प्डथ दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण द्वारा सह-आयोजित उच्च-स्तरीय सम्मेलन में मुख्य भाषण और तकनीकी सहायता केंद्र, नई दिल्ली

11.3 इस तेजी से विकसित हो रही वैश्विक पृष्ठभूमि में, यह अध्याय निर्यात, आयात, अंतर्राष्ट्रीय निवेश, विदेशी मुद्रा भंडार, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मुद्रा की आवाजाही, विदेशी ऋण और भुगतान संतुलन की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के विदेशी क्षेत्र में विकास का वर्णन करता है। जहां संकेतक उपलब्ध होते हैं ,वहां कुछ साथी देशों के साथ इनमें से कुछ संकेतकों की तुलना भी भारत के बाहरी क्षेत्र की स्थिति को उचित परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए की जाती है।

वैश्वीकृत संसार के लाभ उठाने में मददगार व्यापार

11.4 वर्तमान वैश्वीकृत और एकीकृत दुनिया में, उत्पादों और वित्तीय बाजारों के बढ़ते वैश्वीकरण का लाभ प्राप्त करने के लिए विकासशील देशों का व्यापार करना आवश्यक हो गया है। यह अच्छी तरह से माना जाता है कि व्यापार अपने आप में एक अंत नहीं है बल्कि संतुलित, न्यायसंगत और संधारणीय विकास का साधन है। पारंपरिक आर्थिक सिद्धांत संभावित लाभ की ओर इशारा करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए खुलेपन से उभर सकते हैं।

11.5 समय के साथ, विश्व के देशों का व्यापार खुलापन बढ़ रहा है जिसका मापन व्यापार की मात्रा द्वारा जीडीपी के अनुपात के रूप में किया जाता है। विश्व बैंक के डेटाबेस के अनुसार, पूरे विश्व के लिए, विश्व सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यापार का हिस्सा[3] 2003 से 50-60 प्रतिशत की सीमा में रहा है और 2020 में 52 प्रतिशत रहा है। भारत के लिए भी, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यापार का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है,यह 2005 से 40 प्रतिशत के ऊपर रहा है (2020 के महामारी वर्ष को छोड़कर)। यह अनुपात 2021 में 46 प्रतिशत और 2022 की पहली छमाही (H1) के लिए 50 प्रतिशत रहा है।

वैश्विक परिदृश्य

11.6 कोविड-19-प्रेरित व्यवधानों के बाद, वित्तीय वर्ष 22 में वैश्विक व्यापार संभावनाओं में सुधार हुआ है। रूस-यूक्रेन संघर्ष से प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, वैश्विक व्यापार ने 2022 की पहली छमाही (H1) में लचीलापन आया है। मजबूत व्यापारिक आयात, विशेष रूप से यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और विकासशील दुनिया के कुछ हिस्सों से उभरते हुए, पहली छमाही (H1) 2022 में पण्य व्यापार के विकास का समर्थन किया। यह आंशिक रूप से महामारी से प्रेरित खर्च के बदलाव तथा संबंधित रुकी हुई मांग को दर्शाता है जिसमें सेवाओं से माल की ओर होता क्रय बदलाव देखा गया है, जो आपूर्ति की बाधाओं के कारण पहले कम हो रहा था। इस प्रवृत्ति में योगदान देने वाले अन्य कारकों में संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में डॉलर की मजबूती, यूरोप में अंतर-क्षेत्रीय व्यापार की सापेक्ष गतिशीलता, और कुछ बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में ऊर्जा की कीमतों[4] में वृद्धि के कारण व्यापार के अनुकूल प्रभाव थे। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक व्यापार की मात्रा 2022 की पहली छमाही में 4.8 प्रतिशत बढ़ी, जो 2021 में 9.7 प्रतिशत थी। मूल्य के संदर्भ में वैश्विक पण्य व्यापार साल दर साल बढ़कर, 2021 में 22.2 प्रतिशत हुआ, इसने पिछले तीन वर्षो में देखी गई मंदी को उलट दिया। 2022 की पहली छमाही के दौरान, ट्रेड-इन वैल्यू के संदर्भ में 2019 की इसी अवधि की तुलना में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई।[5]

11.7 हालांकि, प्रतिकूल कारकों के संगम के कारण 2022 की दूसरी छमाही (H2) में वैश्विक व्यापार स्थिति गंभीर हो गयी है , जिसमें प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की बढ़ती संभावना और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी; कई केंद्रीय बैंकों की सख्त आक्रामक मौद्रिक नीति; अव्यवस्थित वित्तीय स्थिति; आपूर्ति-श्रृंखला

3 सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में मापी गई वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात का योग व्यापार है

4 संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी), ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022,डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टस इन फ्रेकचरड वर्ल्ड:ग्लोबल डिसऑर्डर एंड रीजनल रेस्पोंसेस, अक्टूबर 2022।

5 वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन प्रेस रिलीज,इंटरनेशनल ट्रेड स्टेटिस्टिक्स,5 अक्टूबर2022

में निरंतर व्यवधान और बढ़ा हुआ भाड़ा शुल्क शामिल है। वैश्विक व्यापार के प्रमुख संकेतक जैसे मालसूची और नए निर्यात आदेश इन प्रतिकूल घटनाओं की गवाही देते प्रतीत होते हैं। 28 नवंबर 2022 को जारी डब्ल्यूटीओ गुड्स ट्रेड बैरोमीटर[6] के अनुसार, 2022 के समापन महीनों और 2023 में व्यापार वृद्धि धीमी होने की संभावना है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था मजबूत विपरीत परिस्थितियों से जूझ रही है। 96.2 का वर्तमान मान सूचकांक के आधार मान तथा पिछले मान 100.0 दोनों से नीचे है, जो ट्रेडेड गुड्स(व्यापारिक सामान) की मांग में मंदी को दर्शाती है।

11.8 इस प्रकार, भविष्य के व्यापार अनुमानों के संबंध में, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, विश्व व्यापार के 2022 की दूसरी छमाही में गति खोने और 2023 में कमजोर रहने की उम्मीद है। संगठन का अनुमान है कि वैश्विक व्यापार 2023 में केवल 1 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, जो कि 3.4 प्रतिशत के पिछले अनुमान से तेजी से होने वाली गिरावट है।[7] हालांकि, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति में बदलाव और रूस-यूक्रेन संघर्ष की अप्रत्याशित प्रकृति के कारण पूर्वानुमान के साथ उच्च स्तर की अनिश्चितता जुड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) ने दिसंबर 2022 की अपनी वैश्विक व्यापार रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि वर्तमान व्यापार मंदी के 2023 तक और खराब होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, जबकि वैश्विक व्यापार के लिए स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, नकारात्मक कारक सकारात्मक प्रवृत्तियों से अधिक प्रबल प्रतीत हो रहे हैं।

चित्र XI. 1: वैश्विक पण्य व्यापार में वृद्धिः वास्तविक और पूर्वानुमान

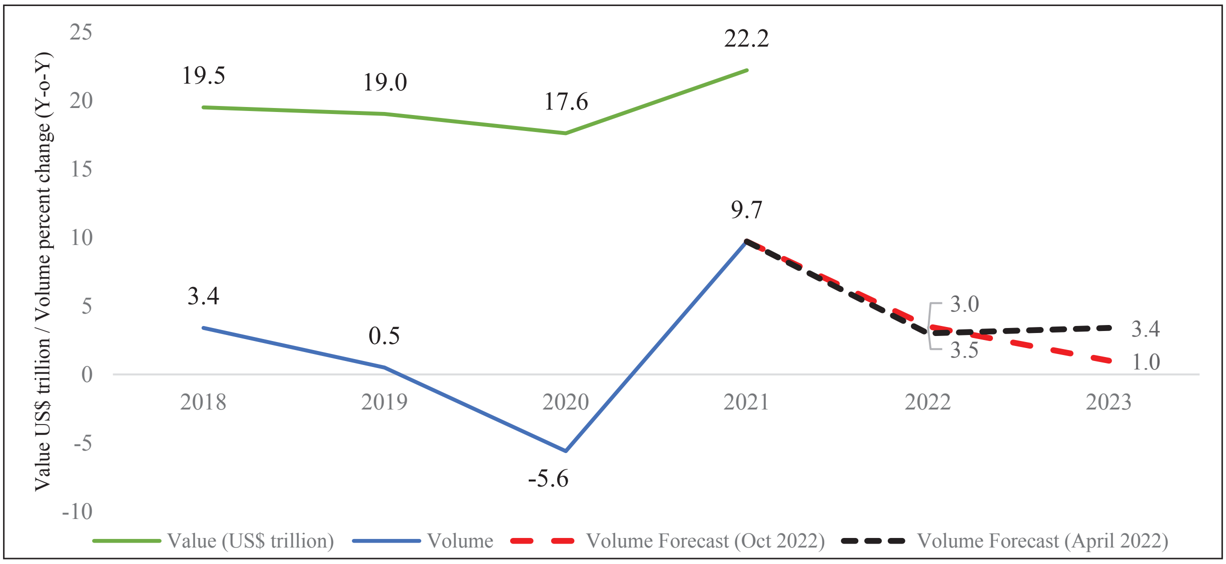

स्रोतः विश्व व्यापार संगठन

भारत का वैविध्य होता और बढ़ता व्यापार

11.9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत के विदेशी क्षेत्र के लचीलेपन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यापार 1980 के दशक में 12-15 प्रतिशत; 1990 के दशक में 16-25 प्रतिशत और 2000 के दशक में 25-50 प्रतिशत की सीमा में था। आगामी पैराग्राफों में भारत के व्यापार निष्पादन का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

6 विश्व व्यापार संगठन ने विश्व व्यापार के रुझानों पर षरियल टाइम(तात्कालिक)ष जानकारी प्रदान करने के लिए संकेतकों का एक सेट विकसित किया है। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर एक प्रमुख संकेतक है जो पण्य व्यापार मात्रा के आंकड़ों से दो से तीन महीने पहले विश्व व्यापार वृद्धि में बदलाव का संकेत देता है। 100 से अधिक मान ऊपर-प्रवृत्ति विस्तार का संकेत देते हैं जबकि 100 से कम मूल्य नीचे-प्रवृत्ति वृद्धि का संकेत देते हैं।

7 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की 5 अक्टूबर, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति।

चित्र XI. 2: भारतीय व्यापार वैश्विक व्यापार स्तरों के साथ गति पकड़ रहा है

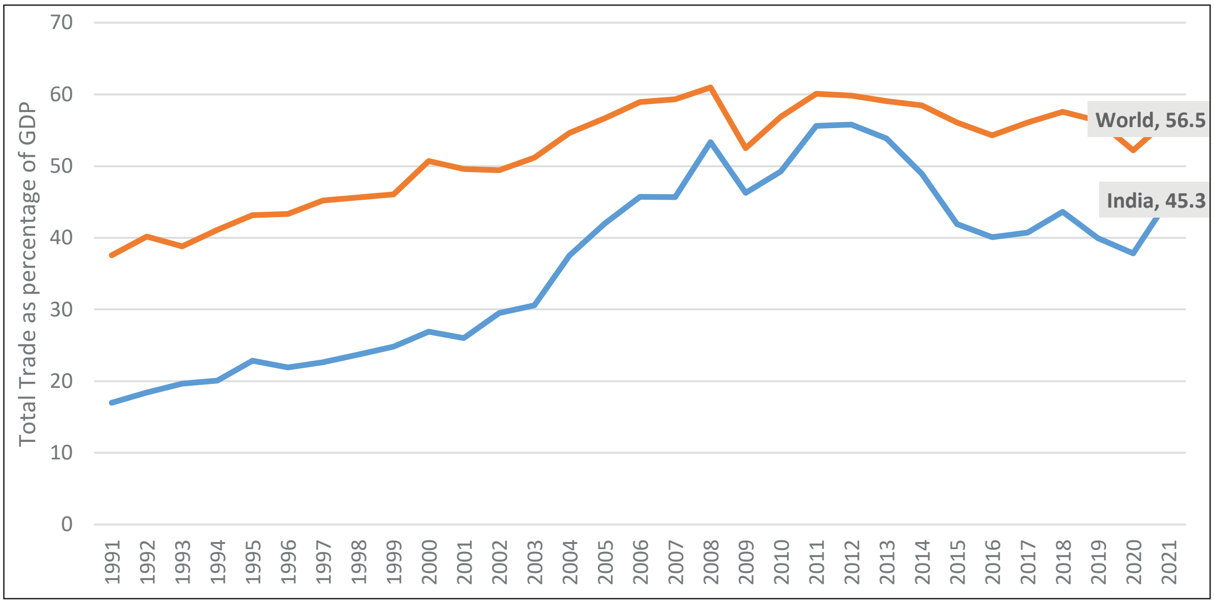

स्रोत: विश्वबैंक डेटाबेस

तालिका XI. 1: भारत के व्यापार के प्रमुख पहलू (कैलेंडर वर्षवार)

	2019	2020	2021
निर्यात निष्पादन (प्रतिशत में)			
विश्व पण्य निर्यात (वर्ल्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स) में हिस्सेदारी	1.7	1.6	1.8
विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में हिस्सेदारी	3.5	4.0	4.0
विश्व पण्य और सेवा निर्यात (वर्ल्ड मर्चेंडाइज प्लस सर्विसेज एक्सपोर्ट्स) में हिस्सेदारी	2.1	2.1	2.2
आयात निष्पादन (प्रतिशत में)			
विश्व पण्य आयात (वर्ल्ड मर्चेंडाइज इंपोर्ट) में हिस्सेदारी	2.5	2.1	2.5
विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के आयात में हिस्सेदारी	3.0	3.2	3.5
विश्व पण्य और सेवा आयात (वर्ल्ड मर्चेंडाइज प्लस सर्विसेज इंपोर्ट) में हिस्सेदारी	2.6	2.3	2.7
विश्व व्यापार में भारत का स्थान			
पण्य निर्यात	18	21	
पण्य आयात	10	14	
सेवा निर्यात	8	7	
सेवा आयात	10	10	

स्रोत: विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) मासिक विदेश व्यापार सांख्यिकी, नवंबर 2022 (अक्टूबर 2022 तक के आंकड़ों पर आधारित)

पण्य व्यापार की प्रवृत्ति

11.10 वित्त वर्ष 22 में भारत ने 422.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सर्वकालिक उच्च वार्षिक व्यापारिक निर्यात हासिल किया है। हालाँकि, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने घोर विपरीत परिस्थितियों का सामना करना शुरू कर दिया है और वैश्विक व्यापार मंदी की लहरों ने भारत के पण्य निर्यात वृद्धि को प्रभावित करना शुरू कर दिया है,और 2022 में इसकी गति में कमी देखी गई है द्य अप्रैल-दिसम्बर 2022 में पण्य निर्यात 332.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-दिसम्बर 2021 की अवधि के दौरान यह 305.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-दिसम्बर 2022 तक गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न/आभूषण निर्यात 233.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-दिसम्बर 2021 में यह 230.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वित्त वर्ष 23 (दिसम्बर 2022 तक) के दौरान पेट्रोलियम, आयल और लुब्रिकेंट(पीओएल) का निर्यात लगभग 21.1 प्रतिशत और गैर-पीओएल निर्यात कुल निर्यात का 78.9 प्रतिशत था। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण, वित्त वर्ष 22 (अप्रैल-दिसम्बर 2022) में पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे अधिक निर्यात किया जाना जारी रहा, इसके बाद रत्न और आभूषण, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, और ड्रग्स /फार्मास्यूटिकल्स का स्थान रहा (सांख्यिकीय परिशिष्ट की सारणी 6.3 क और ख)

चित्र XI.3: भारत का पण्य निर्यात

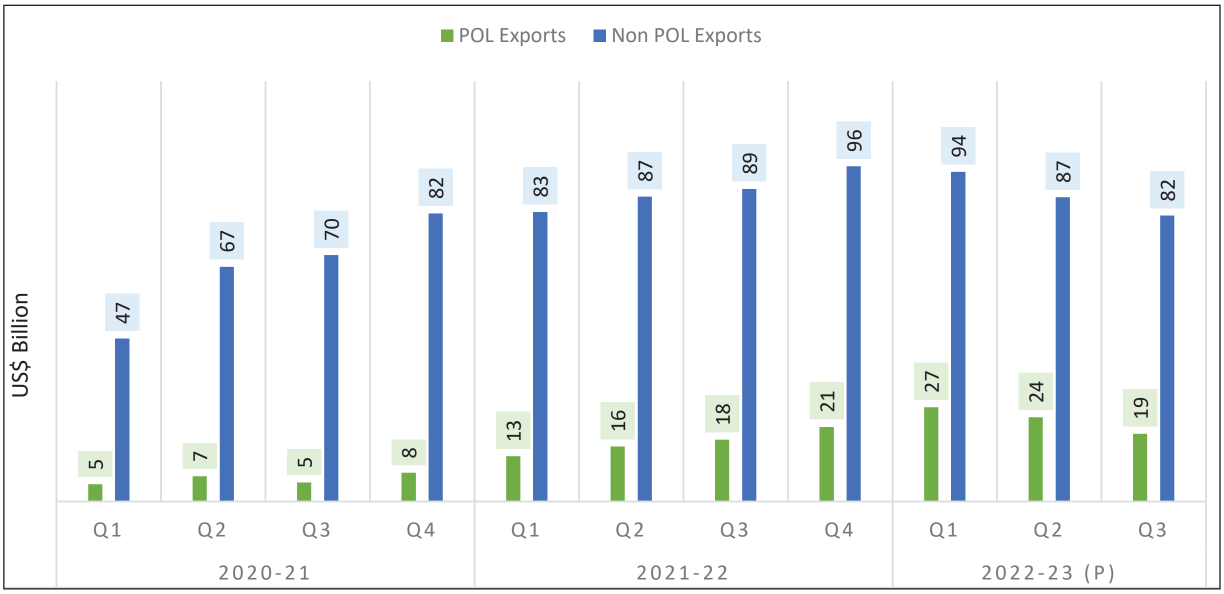

स्रोत: वाणिज्य विभाग
नोट: P: अनंतिम

भारत के व्यापार निष्पादन में बेहतर स्पॉट

11.11 वित्त वर्ष 22 में ड्रग्स और फार्मास्युटिकल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान और जैविक और अकार्बनिक रसायन क्षेत्रों के निर्यात में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही की वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इन क्षेत्रों ने अपनी विकास गति को बनाए रखा है। आपूर्ति श्रृंखला में कोविड के प्रभाव के बावजूद फार्मा निर्यात में वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2015 में भारत का फार्मा निर्यात 15.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 24.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान ड्रग्स और फार्मास्युटिकल का निर्यात 18.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो अप्रैल-दिसंबर 2021 की तुलना में 3.6 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है। निर्यात में उच्च वृद्धि दुनिया भर के देशों द्वारा दवाओं की सूची के स्टॉकिंग और कोविड-19 महामारी से संबंधित टीकों और दवाओं की बढ़ती मांग के कारण थी,

जिसकी पूर्ति करने में भारत सक्षम था। भारत के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में भी लगातार वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात, जो वित्त वर्ष 19 तक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से नीचे रहा, अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान 11.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 51.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इंजीनियरिंग सामान का निर्यात वित्त वर्ष 22 में पहली बार 100 अरब अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। वित्त वर्ष 22 में जैविक और अकार्बनिक रसायनों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान 23.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।

11.12 महामारी के कम होने के साथ, भारत की घरेलू मांग में सुधार देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप आयात में अच्छी वृद्धि हुई। अप्रैल-दिसम्बर 2022 की अवधि के लिए पण्य आयात 551.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-दिसम्बर 2021 की अवधि के दौरान यह 441.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। प्रमुख आयात वस्तुओं में, अप्रैल-दिसम्बर 2022 में पेट्रोलियम कच्चा तेल एवं उत्पाद का आयात 45.6 प्रतिशत बढ़कर 163.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 22 के अपैल-दिसम्बर 2021 तक यह 112.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और यह उच्चतम आयातित वस्तु बना रहा।

11.13 ऊर्जा की मांग कोयले और पैट्रोलियम ऑयल एवं लोहक (पीओएल) सहित हमारे ईंधन आयात को बढ़ा सकती है, जिसका हिस्सा अप्रैल-दिसम्बर 2022 में बढ़ कर कुल आयात में 37.1 प्रतिशत हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 30.4 प्रतिशत था। अन्य प्रमुख आयातों में शामिल हैं-इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोयला, कोक और ब्रिकेट, मशीनरी (इलेक्ट्रिकल और गैर-इलेक्ट्रिकल), और जैविक व अकार्बनिक रसायन (सांख्यिकीय परिशिष्ट की सारणी 6.2 क और ख)।

चित्र XI.4: भारत का पण्य आयात

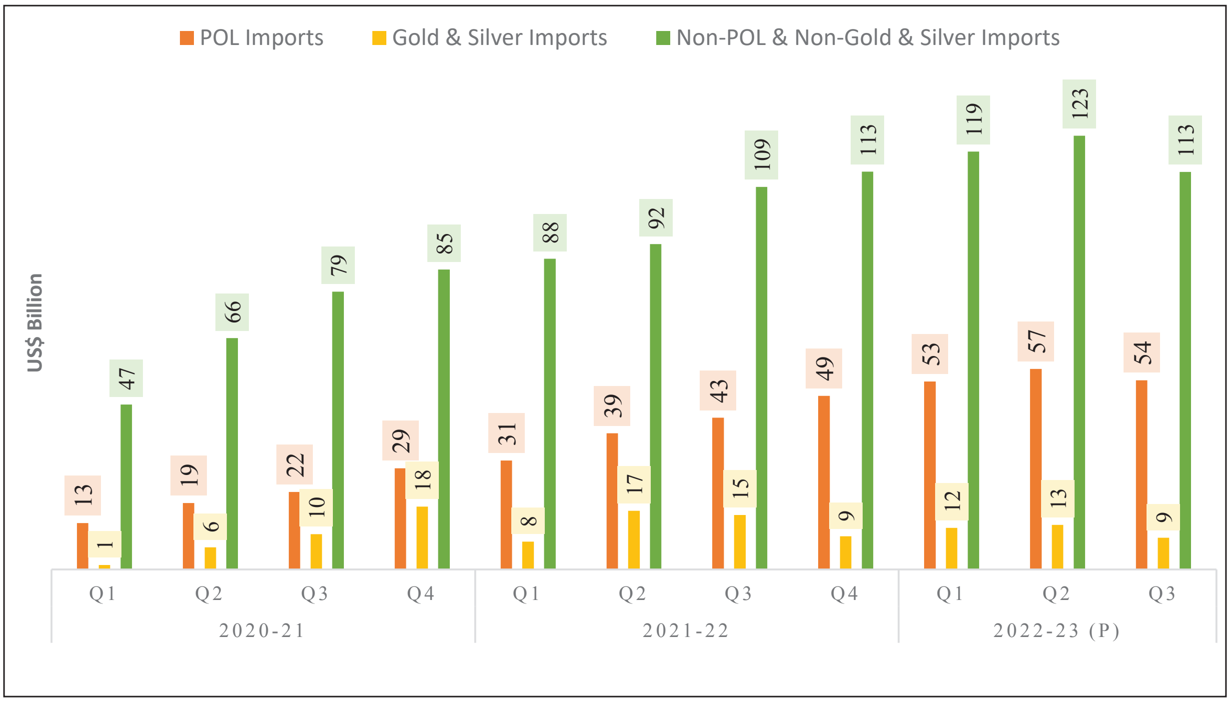

स्रोत: वाणिज्य विभाग

नोट: P: अनंतिम

11.14 अप्रैल-दिसम्बर 2022 के लिए पण्य व्यापार घाटा 218.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान लगाया गया था, जबकि अप्रैल-दिसम्बर 2021 में यह 136.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

चित्र XI.5: पण्य का आयात, निर्यात और व्यापार संतुलन की प्रवृत्ति

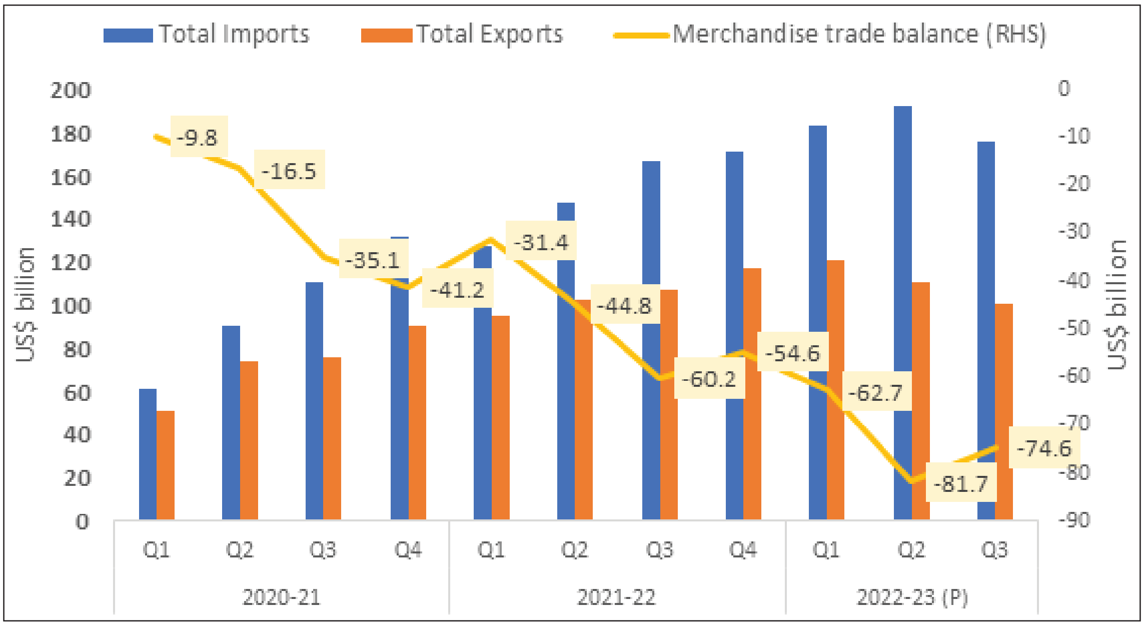

स्रोत: वाणिज्य विभाग P: अनंतिम

11.15 संयुक्त राज्य अमेरिका अप्रैल-नवंबर, 2022 में और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड शीर्ष निर्यात गंतव्य बना रहा। भारत के निर्यात पार्टनर के रुप में नीदरलेंड ने चीन को तीसरे स्थान से हटा दिया। भारत के निर्यात स्थलों में विविधता देखी गयी है। उदाहरण के लिए, कुल निर्यात में दक्षिण अफ्रीका की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 19 में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 23 (अप्रैल से नवंबर) में 2.0 प्रतिशत हो गई है। इसी अवधि में, ब्राजील की हिस्सेदारी 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 2.5 प्रतिशत और सऊदी अरब की हिस्सेदारी 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 2.3 प्रतिशत हो गई है। आयात के संबंध में, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और सऊदी अरब का भारत के कुल आयात में 40 प्रतिशत का संयुक्त हिस्सा है। हालांकि, अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान चीन की हिस्सेदारी एक साल पहले के 15.5 प्रतिशत से घटकर 13.8 प्रतिशत रह गई। इसी तरह, अप्रैल-नवंबर 2022 में यूएसए की हिस्सेदारी एक साल पहले के 7.2 प्रतिशत से घटकर 6.9 प्रतिशत हो गई (सांख्यिकीय परिशिष्ट में तालिका 6.4 देखें)।

सेवाओं का व्यापार

11.16 भारत ने वित्त वर्ष 22 में विश्व सेवा व्यापार में अपना प्रभुत्व बनाए रखा। महामारी से प्रेरित वैश्विक प्रतिबंधों और कमजोर पर्यटन राजस्व के बावजूद, वित्त वर्ष 22 में भारत का सेवा निर्यात 254.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 21 की तुलना में 23.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है और वित्त वर्ष 22 की समान अवधि के मुकाबले अप्रैल-सितंबर 2022 में 32.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाएं मिलकर भारत के कुल सेवा निर्यात का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनाती हैं और वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान मजबूत वृद्धि दर्शाती हैं। जहाँ रिटेल और उपभोक्ता व्यवसाय, संचार और मीडिया, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग, वित्तीय और बीमा सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियोंके के मजबूत राजस्व ने सॉफ्टवेयर निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा दिया,वहां तिमाही के दौरान इंजीनियरिंग, और अनुसंधान/विकास संबंधी सेवाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि ने व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा दिया।

11.17 वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 21 के बीच सेवाओं का आयात 25.1 प्रतिशत बढ़कर 147.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और वित्त वर्ष 22 की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-सितंबर 2022 में 36.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सेवाओं के आयात में वृद्धि मुख्य रूप से परिवहन सेवाओं, यात्रा और अन्य

व्यावसायिक सेवाओं के भुगतान के कारण हुई है। वैश्विक गतिविधि की बहाली के बाद, शिपिंग वेसल की कमी और उच्च परिवहन लागत के परिणामस्वरूप परिवहन भुगतान में वृद्धि हुई। यात्रा प्रतिबंधों में ढील के बाद यात्रा आयात में वृद्धि देखी गई।

तालिका: XI.2: सेवा व्यापार का लचीला प्रदर्शन (मूल्य अमेरिकी डॉलर बिलियन में)

	2020-21		2021-22		अप्रैल-सितंबर 2022 (अनंतिम)	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
सेवाएं	**206.1**	**117.5**	**254.5**	**147.0**	**156.1**	**90.6**
दूसरों के स्वामित्व वाली भौतिक निविष्टियों पर विनिर्माण सेवाएँ	0.3	0.03	0.5	0.1	0.6	0.1
रखरखाव और मरम्मत सेवाएं एनआईई	0.2	0.8	0.2	1.4	0.1	1.0
परिवहन	21.9	19.8	32.7	35.8	19.4	23.1
यात्रा	8.5	11.5	9.1	16.3	10.5	13.8
सन्निर्माण	2.6	2.6	2.6	2.9	1.6	1.6
बीमा और पेंशन सेवाएं	2.4	2.1	3.3	2.1	1.7	1.1
वित्तीय सेवाएं	4.3	4.8	5.5	5.6	3.8	3.1
बौद्धिक संपदा के उपयोग के लिए शुल्क एनआईई	1.3	7.7	0.8	9.0	0.7	4.5
दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	103.1	12.3	125.6	14.5	72.6	8.6
अन्य व्यापार सेवाएँ	49.2	49.5	58.9	51.7	36.9	28.3
व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवाएं	2.3	2.8	3.2	4.5	1.9	2.9
सरकारी सामान और सेवाएं एनआईई	0.6	1.0	0.8	0.9	0.4	0.4
अन्य एनआईई	9.5	2.6	11.3	2.2	6.1	2.2

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, भुगतान संतुलन विवरण

चित्र XI.6: सेवा व्यापार में तेजी का रुझान

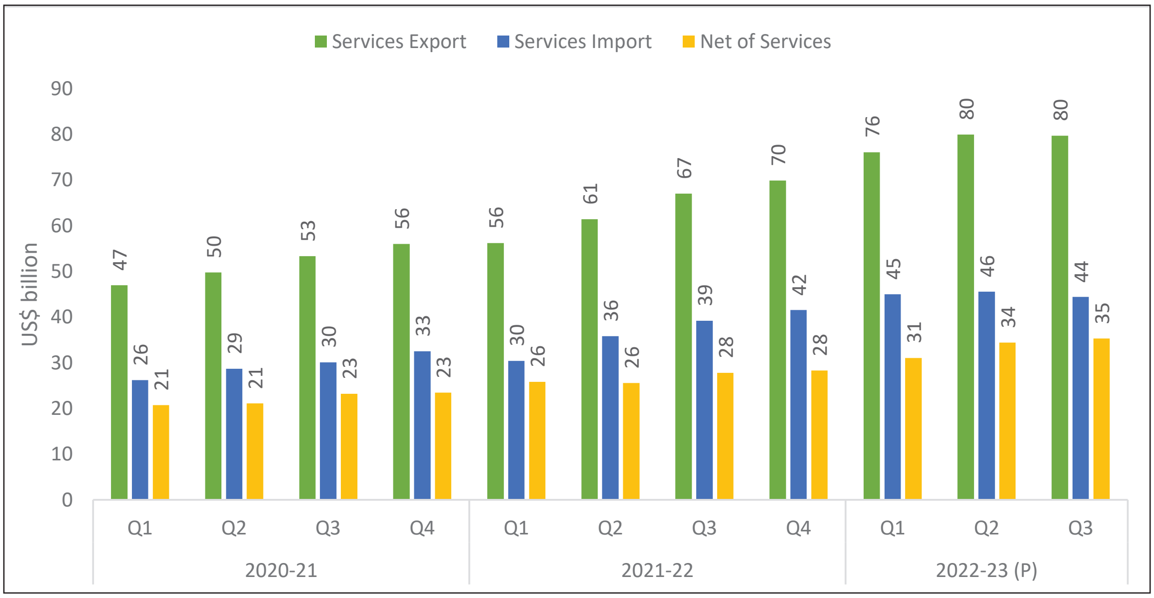

स्रोत: वाणिज्य विभाग; P: अनंतिम

11.18 जहाँ 2022 की दूसरी छमाही में पण्य निर्यात में कुछ मंदी देखी जा रही है, वहीं भारत का सेवा निर्यात मजबूत रहा है। चूंकि भारत कम लागत पर ज्ञान-आधारित सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए वैश्विक आर्थिक मंदी और निकट भविष्य की प्रतिकूल स्थिति में भी उसकी मांग कम नहीं होगी। सेवा क्षेत्र निर्यात में अप्रैल-दिसंबर 2021 के 184.7 बिलियन यूएस डॉलर के मूल्य की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 2022 में 235.8 बिलियन यूएस डॉलर का अनुमानित मूल्य रहा। पिछले वर्ष की इसी अवधि के सेवा क्षेत्र के आयात के अनुमानित मूल्य 105.5 बिलियन डॉर की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2022 में 135.0 बिलियन डॉलर हो गया। सेवा क्षेत्र द्वारा समर्थित, अप्रैल-दिसम्बर 2022 में भारत का समग्र निर्यात (पण्य और सेवाएँ दोनों मिलकर) 568.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.1 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल-दिसम्बर 2022 में कुल आयात 686.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 25.6 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।

विदेश व्यापार नीति

11.19 भारत की विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) परंपरागत रूप से एक बार में पांच साल के लिए तैयार की जाती है। एफटीपी का उद्देश्य निर्यात और आयात के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का ढांचा प्रदान करना और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का समुच्चय प्रदान करना है। 2015-2020 के लिए भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति (FTP) वर्तमान में प्रचलन में है। महामारी की अवधि के दौरान नीतिगत स्थिरता प्रदान करने के लिए, पांच वर्षीय एफटीपी 2015-20 को 2020 से 2022 तक बढ़ा दिया गया था। अस्थिर वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक स्थितियों और मुद्रा में अस्थिरता के कारण नीति को मार्च 2023 तक आगे बढ़ा दिया गया है। इस अवधि के दौरान, सरकार महत्वपूर्ण उपाय कर रही है और लगातार उत्पादों के साथ-साथ संभावित बाजारों तक निर्यात में विविधता लाने के अवसरों की तलाश कर रही है। सरकार सक्रिय रूप से व्यापार समझौतों को सुविधाजनक बनाने और विभिन्न हितधारकों के परामर्श को लेकर योजनाएं शुरू करने पर काम कर रही है। वर्ष 2022 में, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य पण्य(माल) और सेवाओं पर टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं में कमी के द्वारा अधिक बाजार पहुंच प्रदान करना और निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी बनाना है।राज्यों के सम्भाव्य साधन और क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक[8] भी शुरू किया गया है। यह राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में सभी हितधारकों का मार्गदर्शन करेगा।

भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता

11.20 जुलाई 2022 में, भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) ने भारत से निर्यात पर जोर देने के साथ-साथ वैश्विक व्यापार के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रुपये (INR) में इनवॉइस, भुगतान और निर्यात/आयात के निपटान के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की अनुमति देते हुए परिपत्र जारी किया जिससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये (INR) में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि को समर्थन दिया जा सके। इस ढांचे में भारतीय रुपये में निर्यात और आयात का इनवॉइस, व्यापारिक भागीदार देशों की मुद्राओं के बीच बाजार-निर्धारित विनिमय दर और भारत में अधिकृत डीलर बैंकों के साथ खोले गए विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों[9] के माध्यम से निपटान शामिल है।

---

[8] नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साझेदारी में चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने, सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता में वृद्धि; और एक सुविधाजनक नियामक ढांचे को प्रोत्साहित करने के लिए एक निर्यात तत्परता सूचकांक(ईपीआई) तैयार किया है। ईपीआई की संरचना में 4 स्तंभ - नीति; व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र; निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र; निर्यात निष्पादन और 11 उप-स्तंभ - निर्यात प्रोत्साहन नीति; संस्थागत ढांचा; व्यापारिक वातावरण; आधारभूत संरचना; परिवहन कनेक्टिविटी; ऋण सुविधा; निर्यात अवसंरचना; व्यापार समर्थन; अनुसंधान और विकास अवसंरचना; निर्यात विविधीकरण; और विकास-उन्मुखता सम्मिलित हैं।

[9] वोस्ट्रो खाता वह खाता होता है जो घरेलू बैंक, 'घरेलू बैंक की मुद्रा अर्थात रुपये' में किसी अन्य विदेशी बैंक के लिए रखता है। ऐसे खाते घरेलू बैंकों को अपने उन ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं जिनकी वैश्विक बैंकिंग आवश्यकताएं होती हैं।

11.21 निपटान के लिए इस व्यवस्था के अंतर्गत , (क) इस तंत्र के माध्यम से आयात करने वाले भारतीय आयातकों को भारतीय रुपये में भुगतान करना होगा, जो विदेशी आपूर्तिकर्ता/विक्रेता से सेवाओं/माल की आपूर्ति के इनवॉइस के अनुसार भागीदार देश के प्रतिनिधि बैंक के विशेष वोस्ट्रो खाते में जमा किया जाएगा। जबकि (ख) इस तंत्र के माध्यम से माल और सेवाओं का निर्यात करने वाले भारतीय निर्यातकों को भागीदार देश के प्रतिनिधि बैंक के निर्दिष्ट विशेष वोस्ट्रो खाते में शेष राशि से भारतीय रुपये में निर्यात मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

11.22 अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आक्रामक तरीके से पालिसी दरों में बढ़ोतरी और उसका आक्रामक(हॉकिश) रवैया के साथ अमेरिकी डॉलर की बहु-दशकों के उच्च स्तर पर वापसी, और भारतीय रुपये सहित विभिन्न उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (EME) की मुद्राओं का सहवर्ती कमजोर होने की पृष्ठभूमि के सामने भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय निपटान के लिए उपर्युक्त तंत्र बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। यह तंत्र, चालू खाते से संबंधित व्यापार प्रवाह, विशेष रूप से अमेरिकी डॉलर के निपटान में, विदेशी मुद्रा की शुद्ध मांग को काफी हद तक कम कर सकता है। इसके अलावा, सीमा पार व्यापार में भारतीय रुपये के उपयोग से भारतीय व्यवसायों के लिए मुद्रा जोखिम कम होने की उम्मीद है। मुद्रा की अस्थिरता से सुरक्षा न केवल व्यवसाय करने की लागत को कम करती है बल्कि बेहतर व्यावसायिक विकास को भी सक्षम बनाती है, जिससे भारतीय व्यवसायों के वैश्विक स्तर पर बढ़ने की संभावना में सुधार होता है। यह विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता और विदेशी मुद्रा पर निर्भरता को भी कम करता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी आर्थिक आघात (अर्थ व्यवस्था परिवर्तनों) के प्रति कम संवेदनशील हो जाती है।[10] इसके अलावा, यह भारतीय निर्यातकों को विदेशी ग्राहकों से भारतीय रुपये में अग्रिम भुगतान प्राप्त करने में सहायता कर सकता है और जब रुपया निपटान तंत्र समय के साथ गति प्राप्त कर लेगा तब लंबी अवधि में, यह भारतीय रुपये को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भी बढ़ावा देगा। किसी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के उद्‌भव के लिए पूर्वापेक्षाओं में एक शर्त यह है कि उस मुद्रा का व्यापार इनवॉइस में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाए। विदेशी मुद्रा बाजार कारोबार (दैनिक औसत) के संदर्भ में, बीआईएस त्रैवार्षिक सेंट्रल बैंक सर्वे 2022 के अनुसार, अमेरिकी डॉलर डोमिनेंट व्हीकल करेंसी है, जिसमें 88 प्रतिशत वैश्विक विदेशी मुद्रा कारोबार होता है। भारतीय रुपए की हिस्सेदारी 1.6 फीसदी थी। यदि भारतीय रुपये का कारोबार 4 प्रतिशत के वैश्विक विदेशी मुद्रा कारोबार में गैर-अमेरिकी, गैर-यूरो मुद्राओं के हिस्से के बराबर हो जाता है, तो भारतीय रुपये को एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा माना जा सकता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को दर्शाता है।[11]

व्यापार बढ़ाने की पहल

11.23 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य से अधिक,वित्तवर्ष-22 में 422.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारत के निर्यात का सराहनीय प्रदर्शन, सभी क्षेत्रों और सभी हितधारकों के प्रयासों का परिणाम रहा है द्यइस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रणी कारकों में से कुछ लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए थे, जिनमें - देश-वार, उत्पाद-वार और निर्यात संवर्धन परिषद-वार विनिर्दिष्ट लक्ष्यों का निर्धारण; लक्ष्यों का मॉनिटरन और जहां आवश्यकता हो वहां प्रक्रिया में सुधार करना सम्मिलित था। पेट्रोलियम, सूती धागे, कपड़ा, रसायन और इंजीनियरिंग सामान जैसे उत्पादों की मांग में वृद्धि से निर्यात वृद्धि प्रेरित थी। भारत महामारी से संबंधित व्यवध ानों के मद्देनजर कुछ उत्पादों की आपूर्ति में अंतर का लाभ उठाने और वैश्विक मांग को पूरा करने में सक्षम था। अनुकूल वैश्विक पण्य कीमतों से निर्यात को भी सहायता मिली। सरकार की कुछ विशिष्ट योजनाएँ जो निर्यात को सुविधाजनक बना रही हैं व प्रोत्साहित कर रही हैं तथा करती आ रही हैं, वे इस प्रकार हैं।

11.24 कृषि उत्पादों पर बल देना: प्रभावी कृषि निर्यात नीति द्वारा समर्थित भारत का कृषि निर्यात वित्त वर्ष 22 में अब तक का सर्वाधिक निर्यात 37.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और इसने अप्रैल-नवंबर

[10] 20 अक्टूबर 2022 को मुंबई में ग़ॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FEDAI) के वार्षिक दिवस समारोह में श्री टी रबी शंकर, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया मुख्य भाषण।

[11] पात्रा, एम. डी (2022): India/75, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, अगस्त, प्रिंटेड पेज 13-34।

2022 के दौरान US$ 26.8 बिलियन के निर्यात के साथ वित्त वर्ष 23 में अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखा। निर्यात निरीक्षण परिषद (EIC), वृक्षारोपण बोर्ड, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) सहित निर्यात संवर्धन एजेंसियों के सक्रिय समर्थन, निर्यात के लिए आवश्यक प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन जारी करने जैसे निर्यात सुविधा उपायों ने कृषि निर्यात के विकास में सहायता की है। व्यापार मेलों में भागीदारी और भारतीय मिशनों के सहयोग के विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि उत्पादों के लिए नियमित प्रचार-प्रसार किया गया।

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित प्रदेशों से कृषि निर्यात शुरू करने के लिए, एपीडा ने कश्मीर घाटी के स्टार्ट-अप, नए उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठन/किसान समूहों और क्षेत्र के निर्यातकों को आयातकों के साथ जोड़ा है। मध्य पूर्व, यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिका जैसे गंतव्यों के लिए उच्च मूल्य वाले कश्मीर केसर (जीआई) की नियमित शिपमेंट हो रही है।

11.25 **ब्याज समानीकरण योजनाः** यह योजना बैंकों द्वारा निर्यातकों को उनके प्री- और पोस्ट-शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज दरों में लाभ देने के लिए तैयार की गई थी। योजना का विस्तार करते हुए 1 अक्टूबर 2021 से सबवेंशन (सरकारी अनुदान) दरों में भी कमी की गई है। अब से, एमएसएमई विनिर्माण निर्यातकों के लिए 3 प्रतिशत (पहले 5 प्रतिशत) सबवेंशन की घटी हुई संशोधित दरें और 410 (पूर्ववर्ती 416) एचएस लाइनों के साथ निर्यात करने वाले व्यापारी और अन्य निर्माता निर्यातकों पर 2 प्रतिशत (पहले 3 प्रतिशत) की दर लागू होती है।

11.26 **निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजनाः** यह योजना केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर विभिन्न चरणों में उन केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों/करों/लेवी की छूट देती है जो निर्यातित उत्पादों के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया में खर्च किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में इन्हें किसी अन्य शुल्क छूट योजना के तहत धन वापस नहीं की जा रही है।

11.27 **निर्यात ऋण गारंटीः** निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) निर्यात ऋण बीमा सेवाएं देकर भारतीय निर्यातकों और बैंकों की सहायता करता है। ईसीजीसी निर्यातकों को भुगतान जोखिमों के परिणामों से बचाने के लिए निर्यात माल पर बीमा सुरक्षा देता है। यह बैंकों को निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) भी देता है ताकि बैंकों को दिवालियापन के जोखिम और/या निर्यातक उधारकर्ता की दीर्घकालीन चूक के कारण निर्यातकों को दिए गए निर्यात ऋण के कारण होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। इस योजना के तहत ईसीआईबी के अधीन ईसीजीसी ने जुलाई 2022 में नई योजना प्रारंभ की है। छोटे निर्यातकों की सहायता करने के लिए ₹20 करोड़ की निर्यात कार्यशील पूंजी सीमा वाले खातों को प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट ऋण प्रदान करने वाले बैंकों का बीमा कवर जुलाई 2022 में 70 प्रतिशत के औसत कवरेज से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है।

11.28 **कृषि उड़ान योजनाः** कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर अगस्त 2020 में कृषि उड़ान योजना शुरू की गई थी ताकि उनके मूल्य की प्राप्ति में सुधार हो सके। कृषि उड़ान 2.0 को अक्टूबर 2021 में मौजूदा प्रावधानों को बढ़ाते हुए प्रारंभ किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों से खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई परिवहन द्वारा कृषि उपज की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए, लैंडिंग, पार्किंग शुल्क, टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क और भारतीय मालवाहकों और यात्री-से-कार्गो विमान के लिए मुख्य रूप से उत्तर पूर्व, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में लगभग 25 हवाई अड्डों और अन्य क्षेत्रों में 28 हवाई अड्डे के निकट मार्ग नेविगेशन सुविधा शुल्क की पूर्ण छूट देता है। इसके अलावा, योजना के तहत पांच और हवाई अड्डों को शामिल करने पर इनकी संख्या 58 हो गई है।

11.29 **निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना:** सरकार राज्यों से निर्यात के विकास के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता के लिए वित्त वर्ष 18 से निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस) को लागू कर रही है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्यात अवसंरचना की स्थापना या उन्नयन के लिए केंद्र/राज्य सरकार की स्वामित्व वाली एजेंसियों को सहायता अनुदान के रूप में यह योजना वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

11.30 निर्यात केंद्र के रूप में जिला एक जिला एक उत्पाद पहल: निर्यात केंद्र के रूप में जिला -ओडीओपी पहल का उद्देश्य सामान्य जनता के लिए निर्यात प्रोत्साहन, विनिर्माण और रोजगार सृजन को लक्षित करना है जिससे भारत को एक निर्यात महाशक्ति बनाने में राज्यों और जिलों को सार्थक हितधारक व सक्रिय भागीदार बनाया जा सके इस प्रकार आत्मनिर्भर मिशन में योगदान दिया जाए और स्थानीय वस्तुओं के प्रचार से दुनिया में 'मेक इन इंडिया' की संकल्पना को मूर्तरूप दिया जा सके। इस पहल का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना भी है। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम करने, विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिले में निवेश आकर्षित करने में देश के प्रत्येक जिले से उत्पाद/उत्पादों/सेवाओं तथा ब्रांड का चयन और प्रचार करना है। निर्यात केंद्रों के रूप में जिलों पर ध्यान केंद्रित करके निर्यात पर जोर देने से भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ और अधिक निकटता से एकीकृत किया जा सकता है और कृषि, समुद्री उत्पाद, कपड़ा, फार्मास्युटिकल, रसायन और कई इंजीनियरिंग उत्पादों में विविधता और प्रतिस्पर्धा के लाभ से भारत को महत्वपूर्ण निर्यातक बनने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

भारत के वैश्विक व्यापार संबंध

11.31 वैश्वीकरण का यह युग व्यापार समझौतों के प्रसार और प्रतिस्पर्धी व्यापार ब्लॉकों के उद्भव के साथ आया है। ये रुझान हर व्यवसाय, हर उद्योग और हर देश को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए इन परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाना दुनिया भर के नीति निर्माताओं के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। सरकारें बड़े पैमाने पर विविध विदेशी और आंतरिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विचार- जैसे कि शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, बाजार का आकार बढ़ाना और सबसे महत्वपूर्ण, अन्य देशों की प्रतिकूल व्यापार नीतियों के विरुद्ध स्वयं को सुरक्षित करना, से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग का अनुसरण कर रही हैं।

11.32 भारत हमेशा एक खुले, न्यायसंगत, भविष्यवचनीय, गैर-भेदभावपूर्ण और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए खड़ा रहा है। भारत क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं (आरटीए) को व्यापार उदारीकरण के समग्र उद्देश्य की दिशा में 'बिल्डिंग ब्लॉक' और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के पूरक के रूप में मानता है।

यह स्वीकार करते हुए कि क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था (आरटीए) विश्व व्यापार में स्थायी रूप से विशिष्ट स्थान रखेगी, भारत ने पिछले दशक के शुरुआती हिस्से से अपने निर्यात बाजार का विस्तार करने के इरादे से अपने व्यापारिक भागीदारों/ब्लॉकों के साथ काम किया है और कुछ मामलों में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौतों (सीईसीए) की ओर बढ़ने के लिए सैद्धांतिक समझौतों का निष्कर्ष निकालना शुरू किया है जिसमें माल, सेवाओं, निवेश से संबंधित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) और आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना शामिल है।

11.33 एफटीए के लिए आर्थिक तर्क भारत के अपने व्यापारिक भागीदारों के लिए निर्यात का विविधीकरण और विस्तार करना था, जिससे उचित वातावरण प्रदान किया जा सके और हमारे व्यापारिक भागीदारों में तुलनात्मक लाभ रखने वाले प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम लागत पर कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों (सहायक सामग्री/उत्पादों) तक पहुंच सरल की जा सके और मूल्य वर्धित घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके। भारत-दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान), भारत-कोरिया और भारत-जापान से समझौतों के मामले में, यह भी एक भू-राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था जो भारत की ''पूर्व की ओर देखो नीति'' के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है।

11.34 भारत ने अब तक 13 मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और 6 अधिमान्य व्यापार समझौता (पीटीए) किए हैं। सूची में सबसे नया भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) है जिस पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और आधिकारिक तौर पर यह 1 मई 2022 को प्रभावी हुआ था इसके साथ ही भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (INDAUS ECTA) है, जिस पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए और यह 29 दिसंबर 2022 को प्रभावी हुआ था। इसके अतिरिक्त, भारत वर्तमान में अपने कुछ व्यापारिक भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौते की (एफटीए) वार्ताएं कर रहा है, इन एफटीए में - (i) भारत-यूके एफटीए, (ii) भारत-कनाडा सीईपीए/प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौता (ईपीटीए), (iii) भारत-यूरोपीय संघ एफटीए, उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा, भारत ने कुछ मौजूदा एफटीए, अर्थात् भारत-सिंगाफर सीईसीए, भारत-दक्षिण कोरिया सीईपीए, और भारत-आसियान व्यापार समझौते की समीक्षा करने के लिए कार्रवाई शुरू की है और ऑस्ट्रेलिया के साथ सीईसीए के दायरे पर चर्चा शुरू की है, जैसा कि इंड-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए[13] के तहत परिकल्पित है। बॉक्स XI. 1 दुनिया भर में किए जा रहे एफटीए की संख्या में वृद्धि और व्यापारिक भागीदार के लिए उनकी उपयोगिता निर्धारित करने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा करता है।

बॉक्स XI.1: मुक्त व्यापार समझौते

विश्व व्यापार संगठन के नियमों[14] के अनुसार एफटीए, या आरटीए, व्यापार और निवेश में किसी देश के लिए उसकी दक्षताओं का लाभ उठाने के लिए उपलब्ध आर्थिक साधन होते हैं। जून 2016 तक, सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों के पास अब कम से कम एक आरटीए प्रभावी होना चाहिए।

डब्ल्यूटीओ सदस्यों के साथ व्यापार समझौतों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, आरटीए की 355 अधिसूचनाएं प्राप्त हैं (1 दिसंबर 2022 तक- स्रोत: डब्ल्यूटीओ वेबसाइट)। कई डब्ल्यूटीओ सदस्य नए आरटीए बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जो अधिकतर द्विपक्षीय हैं। हालाँकि, हाल ही में दो से अधिक विश्व व्यापार संगठन सदस्यों के बीच बातचीत और नए समझौते हुए हैं, जैसे:

- चिली, कोलंबिया, मेक्सिको और पेरू के बीच प्रशांत गठबंधन (10 फरवरी 2014 को हस्ताक्षरित; 1 मई 2016 से प्रभावी);
- त्रिपक्षीय समझौता, जिसमें 'कॉमन मार्किट फॉर ईस्टर्न एंड साउथर्न अफ्रीका', 'ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी' और 'साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी' के साझा बाजार के साथ पक्षों को जोड़ा गया है (इसे 10 जून 2015 को प्रारंभ किया गया और विभिन्न सदस्यों द्वारा अलग-अलग तारीखों पर यह प्रभावी हुआ);
- व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (8 मार्च 2018 को हस्ताक्षरित; 31 अक्टूबर 2018 से प्रभावी हुआ);
- अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AFCFTA) (21 मार्च 2018 को हस्ताक्षरित और विभिन्न सदस्यों द्वारा अलग-अलग तारीखों से प्रभावी हुआ);
- आसियान सदस्यों और छह अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों के बीच क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी समझौता (आरसीईपी) (15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षरित; 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ)।

विश्व व्यापार संगठन में बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में सीमित प्रगति एफटीए में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारणों में से एक है। विश्व व्यापार संगठन मंच पर बहुपक्षीय वार्ता की तुलना में एफटीए को व्यापारिक देशों द्वारा अनुकूल रूप से देखा जाता है क्योंकि इन पर बातचीत करने में सरलता होती है और ये भू-राजनीतिक विचारों में कारक को लचीलापन प्रदान करते हैं।

आरटीए का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क कम करना और व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापार भागीदारों के बीच सहयोग बढ़ाना, उपभोक्ताओं के लिए सस्ते उत्पाद और उत्पादकों के लिए निर्यात के बेहतर अवसर प्रदान करना है। आरटीए का अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव भी होता है। उदाहरण के लिए, बेली और साथी (2019) ने पाया कि एफटीए प्रत्यक्ष घरेलू मूल्य वर्धित निर्यात के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंधित होते हैं, साथ ही वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में इनका फॉरवर्ड और बैकवर्ड पार्टिसिपेशन रहता है।

---

[12] भारत द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के व्यापार समझौतों को समझने के लिए, कृपया: https://www.tpci.in/research_report/types-of-trade-agreements/ देखें

[13]RTAs, as per WTO rules, are any reciprocal trade agreement between two or more partners, not necessarily belonging to the same region.

टिनबर्गेन (1962) द्वारा विकसित कन्वेंशनल ग्रेविटी मॉडल के अनुसार, दो देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार उनके संबंधित आकार के अनुपात में होता है, जिसे उनके जीडीपी द्वारा मापा जाता है और यह व्यापार भौगोलिक दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो परिवहन लागत का प्रतिनिधि है। समय के साथ, व्यापार को प्रभावित करने में उनकी प्रासंगिकता का परीक्षण करने के लिए विनिमय दर, आय स्तर और शिफ्टिंग डिमांड पैटर्न जैसे अधिक चरों(वेरिएबल्स) , को मानक ग्रेविटी मॉडल में जोड़ा गया है (ओसाबुओहेन और साथी , 2019)।

जबकि एक एफटीए टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करके व्यापार बढ़ाने के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करता है, किसी देश की व्यापार वृद्धि कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे:

(क) एफटीए की विनिर्दिष्ट विशेषताएं जैसे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) टैरिफ[15] की तुलना में दी गई टैरिफ छूट की सीमा, किन उत्पादों पर उन्हें दिया जाता है और छूट किस प्रकार प्रदान की जाती है, अर्थात , क्या छूट को लंबे समय से है या अल्प समय कब से लागू[16] करने पर सहमति दी जाती है।

(ख) 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (आरओओ) के संदर्भ में रियायतों की सीमा और गैर-टैरिफ बाधाओं (एनटीबी) को हटाना/सुधारना। जबकि टैरिफ बाधाओं को एफटीए में कम करने पर सहमति है, एनटीबी, जैसे सैनिटरी और फाइटोसैनेटिक उपाय, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं, आकस्मिक व्यापार-सुरक्षात्मक उपाय आदि, व्यापारियों द्वारा एफटीए को कम उपयोगी बना सकते हैं।

(ग) उत्पादों/सेवाओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक अर्थव्यवस्था की क्षमता जिसके लिए एफटीए ने एक उन्नत निर्यात स्थल प्रदान किया है। यह 'आपूर्ति-प्रतिक्रिया' कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला द्वारा निर्धारित की जाती है जो बड़े पैमाने पर एफटीए की सीमा से बाहर हैं। इनमें उत्पादन पहलुओं पर विभिन्न नीतियां, देश की भौतिक और संस्थागत अवसंरचना, और अर्थव्यवस्था के अल्पकालिक लचीलेपन को निर्धारित करने वाले अन्य तत्व शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, आपूर्ति-प्रतिक्रिया व्यापार निर्माण की संभावना से नियंत्रित होती है जिसमें किसी एफटीए का एक सदस्य, एक उत्पाद का उत्पादन करने में तुलनात्मक लाभ प्राप्त करता है, अब इसे अपने एफटीए भागीदारों को बेचने में सक्षम हो जाता है क्योंकि व्यापार बाधाओं को हटा दिया गया है (विनर) , 1950)।

(घ) एफटीए का प्रभाव आयात करने वाले बाजारों में आय वृद्धि और एक व्यापार समझौते में भागीदार देश के निर्यात की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी निर्भर करेगा ताकि समझौते का लाभ उठाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, सभी व्यापार एफटीए मार्ग के माध्यम से नहीं हो सकते हैं, विशेषकर यदि 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (आरओओ) बोझिल हैं या माल का व्यापार पहले से ही एमएफएन जीरो ड्यूटी हो रहा है। एफटीए का लाभ उठाने के लिए व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं द्वारा इनका अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। और, ऐसा नहीं हो सकता है कि दो या दो से अधिक देशों के बीच एफटीए पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद व्यापार में अचानक से या महत्वपूर्ण वृद्धि होने लगे। व्यापार संतुलन केवल धीरे-धीरे परिवर्तित होगा और क्योंकि यह आंतरिक कारक पर आध ारित रहता है इसलिए यह प्रत्येक भागीदार के पक्ष में भी नहीं हो सकता है, इनमें से कुछ ऊपर सूचीबद्ध किए गए हैं।

संदर्भ

- बायर, एस.एल., वाई.वी. योतोव, और टी. जिलकिन। 2019. ‟ऑन द वाइडली डिफरिंग इफेक्ट्स ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स: लेसन फ्रॉम ट्वेन्टी इयर्स ऑफ ट्रेड इंटीग्रेशन” जर्नल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स 116: 206-226।

[14] एमएफएन खंड एक देश द्वारा दूसरे देश को दी गई विशेष व्यापारिक स्थिति को संदर्भित करता है जो विश्व व्यापार संगठन के अन्य सभी सदस्यों पर लागू होता है।

[15] एफटीए में आम तौर पर फेज-इन अवधि होती है जिसमें मौजूदा व्यापार बाधाओं को समय के साथ समाप्त कर दिया जाता है। यह आम तौर पर इसलिए किया जाता है जिससे आयात करने वाले देश में उत्पादक आयात प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें। यह आमतौर पर एफटीए के अनुसमर्थन के 10 से 15 वर्षों के बाद होता है।

[16] किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' आवश्यक मानदंड होते हैं। उनका महत्व इस तथ्य से निकला है कि कई मामलों में शुल्क और प्रतिबंध आयात के स्रोत पर निर्भर करते हैं।

- ओसाबुहिएन, ई.एस., एफोबी, यू.आर., ओडेबियी, जे.टी., फयोमी, ओ.ओ., और सलामी, ए.ओ. (2019)। ''पश्चिम अफ्रीका में द्विपक्षीय व्यापार प्रदर्शन: एक गुरुत्वाकर्षण मॉडल अनुमान,'' अफ्रीकन डेवलपमेंट रिव्यू, 31(1), 1-14।
- टिनबर्गेन, जे. (1962)। "शेपिंग द वर्ल्ड इकोनामी; सजेशंस फॉर एन इंटरनेशनल इकोनामिक पॉलिसी", न्यूयॉर्क: ट्वेंटिएथ सेंचुरी फंड।
- विनर, जे. (1950)। ''द कस्टम यूनियन'', कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, न्यूयॉर्क।

चुनौतीपूर्ण अवधि में भुगतान संतुलन

चालू खाता शेष

11.35 भारत का बाह्य क्षेत्र भू-राजनीतिक विकास को दर्शाते हुए काफी वैश्विक विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा है, जैसा कि ऊपर के परिचय खंड में बताया गया है। वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में भारत के चालू खाता शेष (CAB) में 36.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 4.4 प्रतिशत) का घाटा दर्ज किया गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) था। FY23 की दूसरी तिमाही में चालू खाता घाटे (CAD) का बढ़ना मुख्य रूप से 83.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च पण्य व्यापार घाटे और निवल निवेश आय में निर्गम के कारण था। अप्रैल-सितंबर 2022 (H1 FY 23) की अवधि के लिए, भारत ने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.3 प्रतिशत का चालू खाता घाटा (CAD) दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में 0.2 प्रतिशत की तुलना में पण्य व्यापार घाटे में वृद्धि के कारण पर था। हालांकि, चयनित देशों के लिए चालू खाता शेष (सीएबी) की स्थिति के साथ तुलना से पता चलता है कि भारत का चालू खाता घाटा (CAD) मामूली और प्रबंधनीय सीमा के भीतर है।

चित्र XI.7: चालू खाता शेष (CAB): परिमाण और संरचना

क) चालू खाता शेष और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष

ख) चालू खाता शेष की संरचना

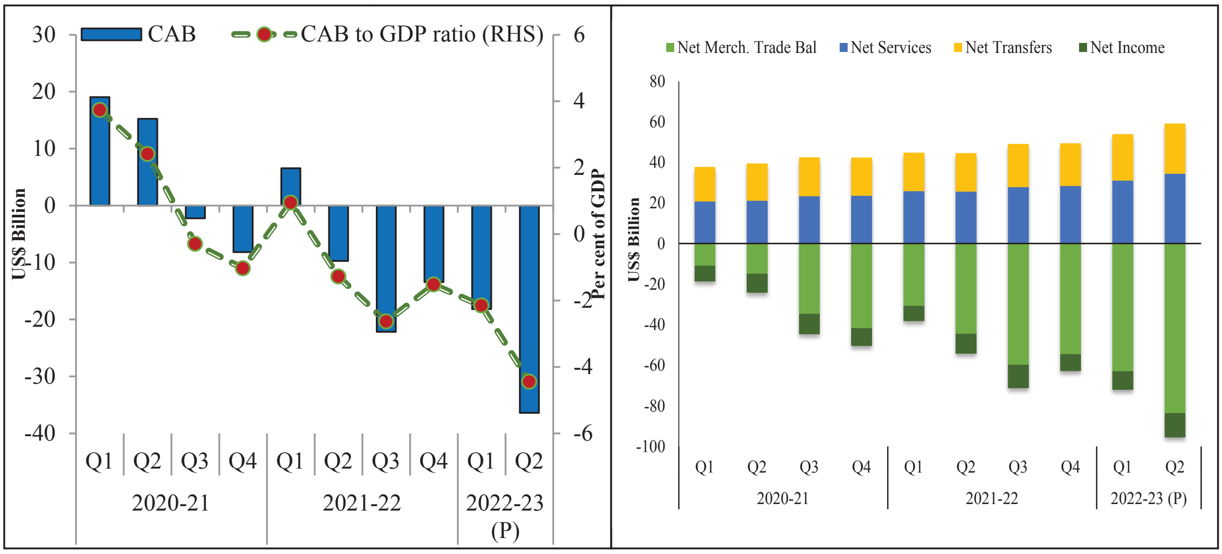

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

P: अनंतिम

चित्र XI.8: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष: भारत बनाम चुनिंदा देश

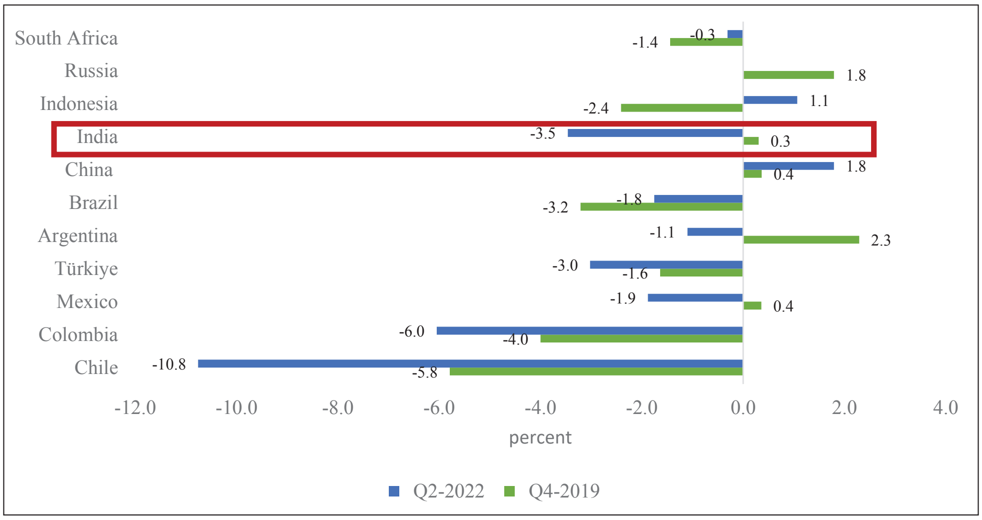

स्रोत: ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) इकोनॉमिक आउटलुक 112 डाटाबेस

व्यापार की अदृश्य मदें

11.36 शुद्ध सेवा प्राप्तियां वित्त वर्ष 22 की पहली छमाही में 51.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में 65.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जिसका मुख्य कारण मजबूत कंप्यूटर और व्यावसायिक सेवा प्राप्तियां हैं। इसी तरह, निवल प्राइवेट ट्रान्सफर रिसिप्ट, जो मुख्य रूप से विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा धन-प्रेषण का प्रतिनिधित्व करती हैं, वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में 48.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि एक साल पहले इसी अवधि के दौरान उनका स्तर 38.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि और भारतीय रुपये के अवमूल्यन ने भारत में धन-प्रेषण प्रवाह को बढ़ावा दिया है। निवल सेवाओं के निर्यात और धन-प्रेषण ने अदृश्य मद व्यापार खाते के अधिशेष में योगदान दिया है, जिसने पण्य व्यापार घाटे को कम किया है।

चित्र XI.9: व्यापार की निवल अदृश्य मदों की संरचना: मजबूत सेवाएं और बड़ी मात्रा में धन-प्रेषण

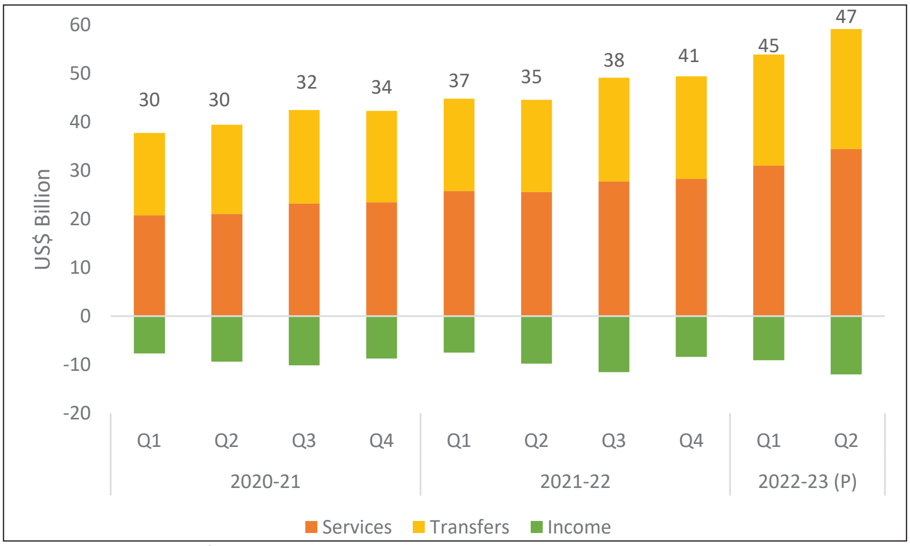

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक P: अनंतिम

11.37 विदेशों में कार्यरत भारतीय द्वारा 'धन-प्रेषण' सेवा निर्यात के बाद विदेशी वित्तपोषण का दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है, जो चालू खाता घाटे (CAD) को कम करने में योगदान देता है और हमेशा भुगतान संतुलन (BoP) का एक स्थिर घटक रहा है। भारत की प्रवासी आबादी सबसे बड़ी है। विश्व बैंक[17] के अनुसार वर्ष 2022 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रत्याशित धन-प्रेषण स्तर के साथ भारत शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश

रहा है। भारतीय प्रवासियों के प्रमुख गंतव्य में क्रमिक संरचनात्मक बदलाव से धन-प्रेषण को लाभ हुआ है, ऐसा बड़े पैमाने पर खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों में कम-कुशल व अनौपचारिक रोजगार के स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और पूर्वी एशिया (सिंगाफर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड)[18] जैसे उच्च आय वाले देशों में उच्च-कुशल रोजगार का बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के कारण हुआ है।

चित्र XI.10: 2022 के दौरान विश्व के शीर्ष धन-प्रेषण प्राप्तकर्ता (अनुमानित)

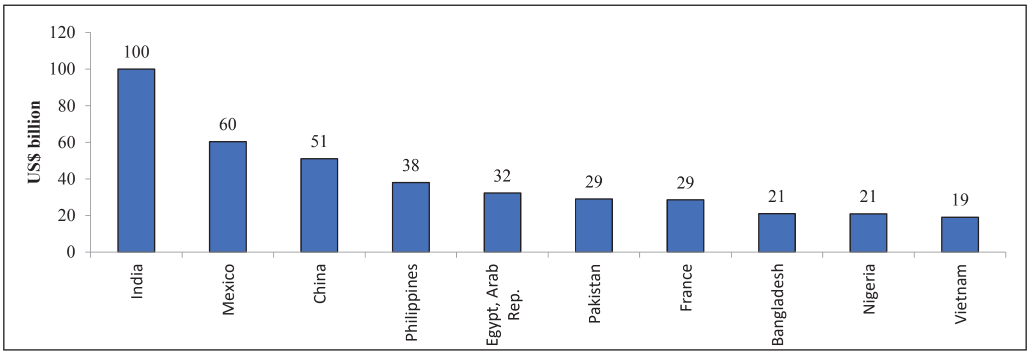

स्रोतः विश्व बैंक

पूंजीगत खाता शेष

11.38 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) से मिलकर विदेशी निवेश, पूंजीगत खाते का सबसे बड़ा घटक है। निवल पूंजीगतगत प्रवाह वित्तवर्ष 22 की पहली माही H1 में अमेरिकी डॉलर 65.0 बिलियन से घटकर वित्तवर्ष 23 की पहली माही H1 में अमेरिकी डॉलर 29.0 बिलियन हो गया[19], ऐसा मुख्य रूप से वित्तवर्ष 23 की पहली माही (Q1FY23) में 14.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के बहिर्गमन के कारण हुआ। वित्तवर्ष 23 की पहली छमायी (H1FY23) में अमेरिकी डॉलर 20.0 बिलियन का निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह वित्तवर्ष 22 की पहली माही (H1FY22) में अमेरिकी डॉलर 20.3 बिलियन के साथ तुलनीय था।

चित्र XI.11: पूंजीगत खाता शेषः परिणाम एवंम संरचना

(क) पूंजीगत लेखा शेषः वैश्विक अनिश्चितता के बीच कम होता सरप्लस | **(ख) पूंजीगत लेखा शेष का संघटन**

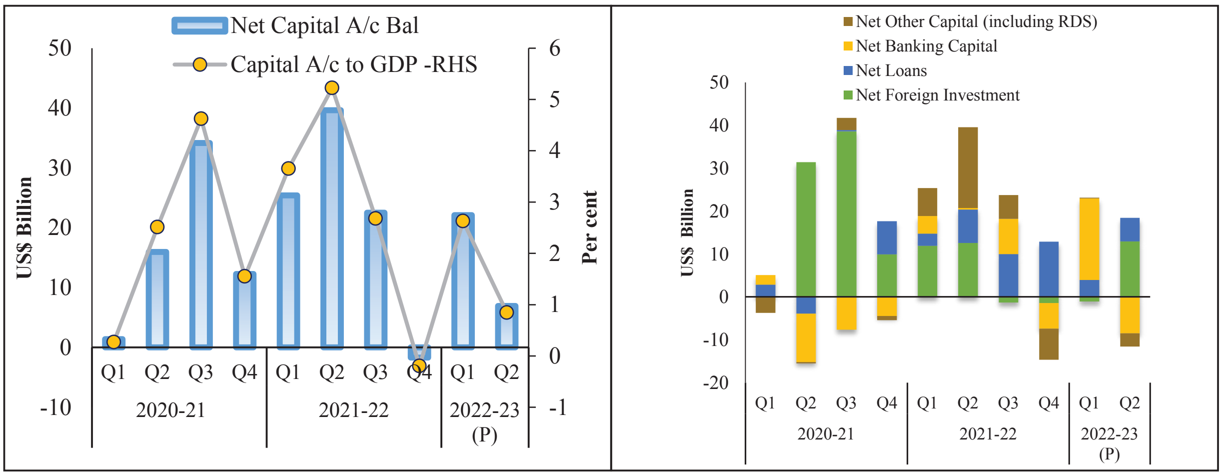

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक P: अनंतिम

11.39 अप्रैल-सितंबर 2022 के दौरान, एक साल पहले के 42.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में सकल एफडीआई प्रवाह 39.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ने विदेशी प्रत्यक्ष

17 वर्ल्ड बैंक, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 37, नवंबर 2022

18 वर्ष 2020-21 के लिए धन-प्रेषण (रेमिटेंस) पर सर्वेक्षण का पांचवां दौर, भारतीय रिजर्व बैंक।

19 इसमें वित्त22 की दूसरी तिमाही (Q2FY22) में US$ 17.9 बिलियन के विशेष आहरण अधिकार (SDR) का अतिरिक्त आवंटन शामिल था।

निवेश इक्विटी प्रवाह का उच्चतम भाग(23.4 प्रतिशत) आकर्षित किया, इसके बाद सेवाओं (15.4 प्रतिशत) और ट्रेडिंग (12.2 प्रतिशत) का स्थान रहा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह के संदर्भ में, सिंगापुर 37.0 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ शीर्ष निवेश करने वाला देश था, इसके बाद मॉरीशस (12.1 प्रतिशत), यूएई (11.0 प्रतिशत) और यूएसए (10.0 प्रतिशत) का स्थान था।

चित्र XI.12: निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

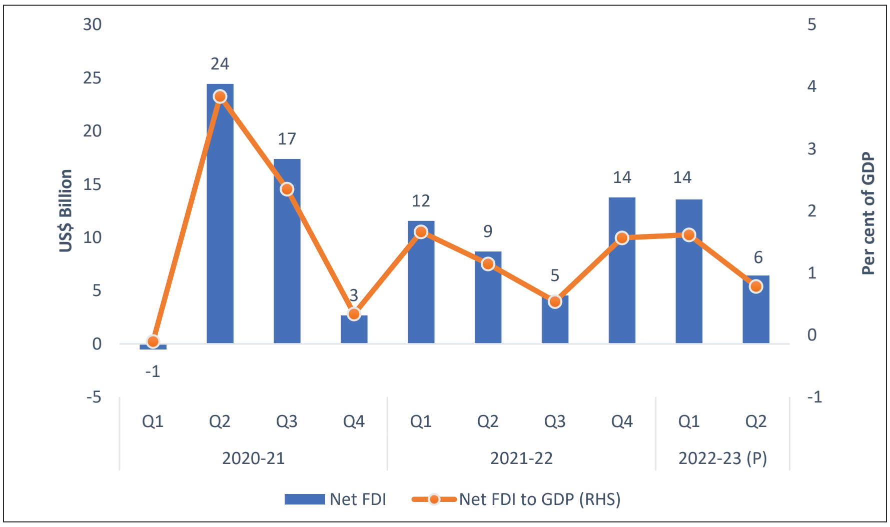

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक P: अनंतिम

11.40 रूस-यूक्रेन संघर्ष और संयुक्त राज्य अमेरिका (फेडरल रिजर्व) द्वारा आक्रामक मौद्रिक नीति को कड़ा करने के नतीजों ने वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता को बढ़ा दिया, जिससे वित्तवर्ष 23 की पहली तिमाही (Q1) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवल आउटफ्लो हुआ। हालाँकि, FPI प्रवाह Q2FY23 में सकारात्मक हो गया, कुल मिलाकर, पोर्टफोलियो निवेश ने अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध बहिर्वाह दर्ज किया, जबकि एक साल पहले 0.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह हुआ था।

चित्र XI.13: निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश

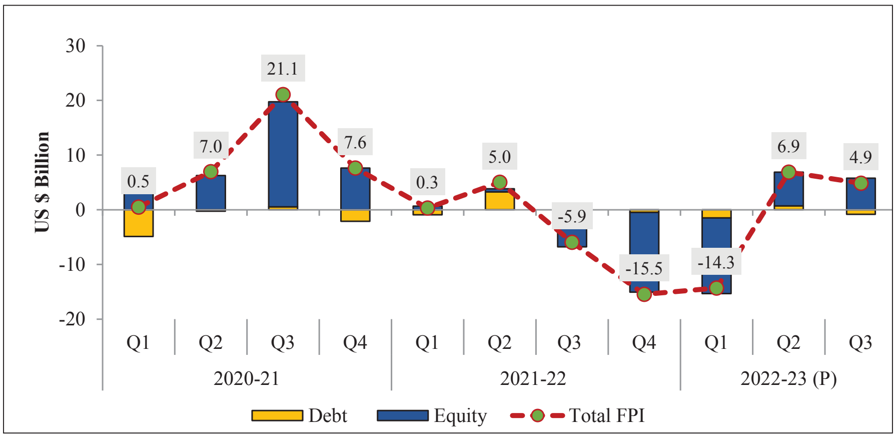

स्रोत: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) P: अनंतिम

11.41 वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही (H1FY23) में पूंजी प्रवाह के अन्य रूपों में, बैंकिंग पूंजीगत प्रवाह ने वित्त वर्ष 2022 की इसी अवधि के दौरान 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्च निवल प्रवाह सूचित हुआ। वैश्विक तरलता की स्थिति कड़ी होने के कारण, वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही (H1FY23) के दौरान अल्पकालिक व्यापार ऋण (ट्रेड-क्रेडिट) की मांग बढ़ी, जिसके परिणामस्वरूप 10.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उच्च निवल अल्पकालिक ऋण प्राप्तियां हुई। इसके अलावा, नए संवितरणों की तुलना में अधिक चुकौती के साथ, भारत में विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) ने वित्त वर्ष

23 की पहली छमाही (H1FY23) में 3.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया, जबकि एक साल पहले 5.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्प्रवाह हुआ था।

भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा भंडार

11.42 कुल मिलाकर, प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक स्थिति ने 2022 में भारत के भुगतान संतुलन (BoP) को दबाव में रखा। जबकि तेल की कीमतों में तेज वृद्धि का प्रभाव चालू खाता घाटा (CAD) के बढ़ने में देखा जा सकता था, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा नीति को कड़ा करने और अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) का बहिर्वाह हुआ। परिणामस्वरूप, चूंकि 'निवल वित्तीय प्रवाह' चालू खाते के घाटे से कम हो गया, इसलिए भुगतान संतुलन (BoP) के आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार में वित्तवर्ष 23 की पहली छमाई (H1FY23) में 25.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आई, जो वित्तवर्ष 22 की पहली छमाई (H1FY22) में अमेरिकी डॉलर 63.1 बिलियन की अभिवृद्धि के विपरीत थी। लेकिन भारी निवेश मूल्यांकन हानियों (48.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर) ने इस अवधि के दौरान नोमिनल दर से 74.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भंडार में निवल कमी की।

11.43 सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 532.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें 8.8 महीने का आयात शामिल था। 9.3 महीने के आयात को सम्मिलित करते हुए दिसंबर 2022 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। आईएमएफ द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2022 के अंत तक, भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था। जैसा कि ग्राफ से देखा जा सकता है, अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में महामारी से पहले के स्तर के बाद से विदेशी मुद्रा भंडार के इम्पोर्ट-कवर में गिरावट आई है; हालाँकि, भारत ने वर्ष 2019 को चौथी तिमाही के 95 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में 96.5 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की। बॉक्स XI.2 में देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार का गठन करने वाले शास्त्र के कुछ पहलुओं पर चर्चा की गयी है।

चित्र XI.14: समग्र भुगतान संतुलन शेष और विदेशी मुद्रा भंडार

(क) भुगतान संतुलन में अधिशेष **(ख) पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और आयात कवर**

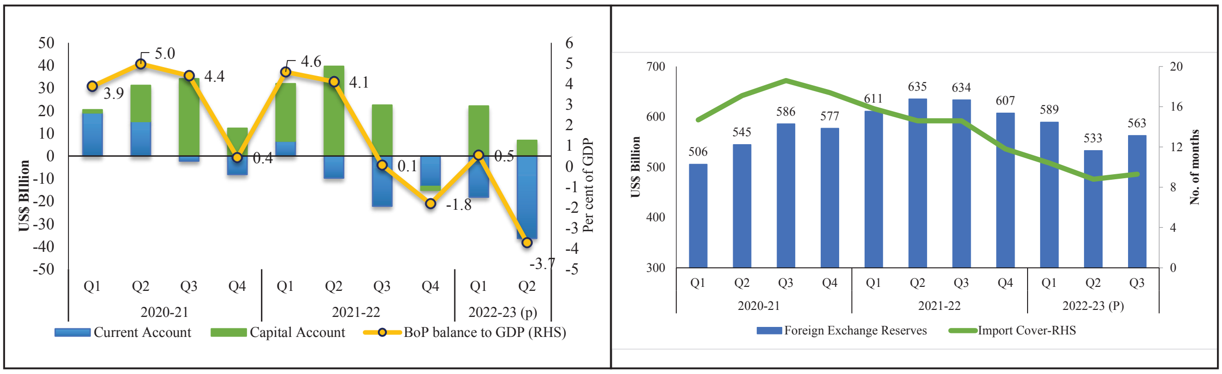

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक P: अनंतिम

चित्र XI.15: भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता (वार्षिक आयात के प्रतिशत के रूप में): एक क्रॉस-कंट्री परिप्रेक्ष्य

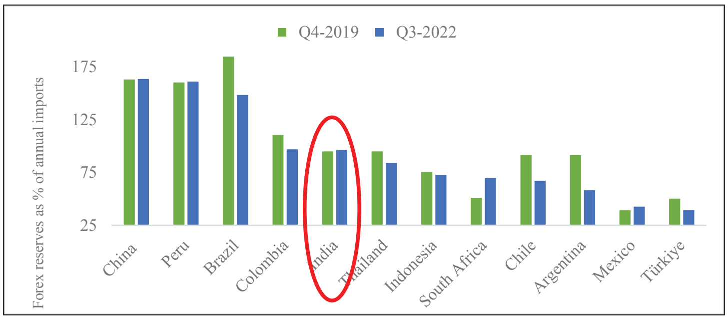

स्रोत: आईएमएफ (विदेशी मुद्रा भंडार) और विश्व व्यापार संगठन (आयात डेटा के लिए)

बॉक्स XI.2 विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता

विदेशी मुद्रा भंडार (FER) के पर्याप्त स्तर का आकलन कैसे करें? क्या कुछ अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क या मूल नियम हैं जो मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं? वे कौन से कारक हैं जिन पर देश को ''पर्याप्तता'' की अपनी सीमा निर्धारित करते समय विचार करना चाहिए? मात्र उपलब्धता की तुलना में इस तरह के भंडार की तरलता को कैसे सुनिश्चित किया जाए? यह बॉक्स प्रासंगिक शास्त्र अध्ययन के अकादमिक दृष्टिकोण संबंधी सवालों के जवाब देने का प्रयास करता है।

विभिन्न उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा भंडार (FER) की आवश्यकता होती है, जैसे कि – आयात के लिए ऋण देना; विदेशी दायित्वों का समय पर निर्वहन करना, विनिमय दर को निश्चित सीमा के भीतर बनाए रखना, या विनिमय दर को किसी निश्चित स्तर पर बनाए रखना यदि देश निश्चित विनिमय दर प्रणाली का पालन करता है; तरलता बनाए रखना और उन स्थितियों में आर्थिक परिवर्तनों को सहने के लिए समय देना, जहां उधार लेने के लिए पहुंच कम होती है या बहुत महंगी होती है। भंडार के संचय के पीछे के कारक का विकास वर्षों में हुआ है: प्रथमत: 2000 के दशक की शुरुआत तक इनका उद्देश्य निवारण करना था, इसके उपरान्त मौद्रिक और विनिमय दर नीतियों में भी इसका लक्ष्य रखा जाने लगा (अर्सलान यवुज, और साथी 2019)। तदनुसार, 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से कई देशों के एफईआर में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है।

तालिका: सोने को छोड़कर कुल विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

	2005	2008	2019	2020	2021	नवंबर-2022	2008 की तुलना में 2021 में परिवर्तन का प्रतिशत
रूसी संघ	175.9	411.8	443.9	457.0	497.6	567.3	20.8
भारत	131.9	247.4	432.4	549.1	594.4	555.3	140.3
ब्राजील	53.3	192.8	353.6	351.5	354.6	331.5	83.9
संयुक्त राज्य अमेरिका	54.1	66.6	118.4	133.9	240.2	237.8	260.7
यूनाइटेड किंगडम	54.0	56.1	158.4	161.2	176.0	204.1	213.7
इंडोनेशिया	33.1	49.6	125.3	131.1	140.3	134.0	182.9
दक्षिण अफ्रीका	18.6	30.6	48.9	47.4	50.3	60.0	64.4
ऑस्ट्रेलिया	41.9	30.7	55.6	39.2	53.8	57.9	75.2
विश्व	**4395.0**	**7418.2**	**12195.3**	**13122.5**	**13944.7**	**11598.6***	**88.0**

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
*Figure as of Sept 2022

यहां विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता पर विचार-विमर्श किया गया है। परंपरागत रूप से, विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता का उपाय तीन प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जैसे विदेशी मुद्राभंडार और आयात का अनुपात रखने, मौद्रिक समुच्चय रखने , और विदेशी ऋण चुकाने के लिए (आईएमएफ, 2000)। भंडार की पर्याप्तता निर्धारण के पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार, मूल सरल नियम तीन महीने का आयात या अल्पकालिक ऋण के लिए संपूर्ण कवर रखना है। पूर्व के संबंध में, दो या छह (आईएमएफ, 2011) के स्थान पर तीन महीने पर्याप्त का कवरेज होना चाहिए या नहीं, इसके लिए बहुत कम अनुभवजन्य साक्ष्य प्राप्त है। परवर्ती कथन गाइडोटी-ग्रीनस्पैन-आईएमएफ नियम पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि देश के भंडार को अल्पकालिक विदेशी ऋण (एक वर्ष या उससे कम परिपक्वता) के बराबर होना चाहिए, जो विदेशी मुद्रा भंडार और अल्पकालिक ऋण के अनुपात का मान 1(एक) रखने का सुझाव देता है। तर्क यह है कि अल्पावधि विदेशी पूंजी की वापसी से निपटने के लिए देशों के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। इसके साथ विदेशी-मुद्रा-भंडार के मुद्रा आधारित संकेतक भी हैं, जो देश से निवासी आधारित

पूंजी का बड़े पैमाने पर पलायन रोकने के उपाय की क्षमता प्रदान करते हैं। उपयोग किए जाने वाले संकेतक 'ब्रॉड मनी' के भंडार का अनुपात या 'बेस मनी' के लिए भंडार का अनुपात हैं, जो निश्चित विनिमय दर व्यवस्थाओं के अंतर्गत विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्तता का आकलन करने में सहायता करते हैं। इन सूचकों में से प्रत्येक, अपने आप में, अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा भंडार (FER) की आवश्यकताओं का आकलन करने में पर्याप्त नहीं हो सकता और अलग-अलग उद्देश्यों के लिए अलग-अलग उपायों का उपयोग किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) (SM/00/65, 3/23/2000) ने जोखिम के स्रोत के रूप में अल्पकालिक ऋण के महत्व को पहचाना पतन्तु निर्भरता के लिए एक ही संकेतक पर अत्यधिक निर्भर रहने के प्रति सावधान किया और विदेशी मुद्रा भंडार के लिए अल्पकालिक मांग के विभिन्न संभावित स्रोतों पर विचार करने की आवश्यकता की ओर संकेत किया। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) (SM/01/311, 10/16/2001) ने भुगतान संतुलन के तनाव-परीक्षण के साथ संकेतक-आधारित विश्लेषणों को पूरा करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया है। इसके अतिरिक्त , विदेशी देनदारियों (ऋण और इक्विटी) के साथ-साथ चालू खाता चर (निर्यात आय) से उत्पन्न होने वाले जोखिम के स्रोतों को पकड़ने के लिए अनुकूलित रिस्क बेस्ड ब्रॉड बेस्ड मेट्रिक्स और संभावित बड़े पैमाने पर पूंजी का पलायन रोकने के कुछ उपाय (ब्रॉड मनी) (आईएमएफ, 2011) तैयार किए गए हैं। इकनोमिक शॉक से निपटने के लिए उपलब्ध कुल संसाधनों के संदर्भ में पर्याप्तता पर विचार किया जाना चाहिए जोकि आरक्षित परिसंपत्तियों की भुगतान क्षमता पर आधारित परिभाषा की तुलना में एक व्यापक अवधारणा है। जबकि विदेशी मुद्रा भंडार वित्तीय-संकट की स्थितियों को रोकने और उनके प्रभाव को कम करने दोनों के लिए आवश्यक होता है, उन्हें धारण करने में लागत लगती है और ये ह्रासमान प्रतिफल देते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार रखने के लिए एक अर्थव्यवस्था द्वारा वहन की जाने वाली लागत में 'अवसर लागत' (घरेलू और विदेशी उधार दरों के बीच अंतर के रूप में) और डेनोमिनेटिड एफईआर के मूल्य में कमी के कारण होने वाला नुकसान शामिल है। रॉड्रिक (2006) ने विदेशी मुद्रा भंडार की सामाजिक लागत की जांच की है और कहा है कि अधिकांश विकासशील देशों की आय की हानि सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत के करीब होती है।

फुकुदा और कोन (2010) विदेशी मुद्रा भंडार संचय के व्यापक आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं और इस बात का प्रमाण पाते हैं कि एफईआर में वृद्धि से विदेशी ऋण बकाया बढ़ जाता है किंतु ऋण परिपक्वता कम हो जाती है। इसके अलावा, लंबे समय में, खपत में गिरावट आती है और निर्यात को बढ़ावा मिलता है जोकि गैर-व्यापार योग्य क्षेत्र से व्यापार योग्य क्षेत्र में उच्च निवेश और विकास के माध्यम से बदलाव को प्रोत्साहित करके होता है। इसके अलावा, 'विदेशी मुद्रा भंडार' विनिमय दर प्रभावों और नैतिक जोखिम व प्रोत्साहन प्रभाव (चिटू, 2016) के कारण मुद्रास्फीतिकारी हो सकते हैं (लिन, और साथी 2009)। इसलिए, विदेशी मुद्रा भंडार रखने के लाभों, लागतों और इसके प्रभावों पर विचार करते हुए देश को अपने विदेशी मुद्रा भंडार और मुद्रा संरचना की इष्टतम मात्रा रखनी चाहिए। रोलओवर संकट के संदर्भ में अचानक आर्थिक ठहराव की बाधा को देखते हुए भंडार का इष्टतम स्तर सरकार को प्रतिनिधि उपभोक्ता के कल्याण को अधिकतम करने का अधिकार देता है। दूसरी ओर, की-करेंसी और व्यापार इनवॉइस की मुद्रा के साथ डोमेस्टिक करेंसी(घरेलू मुद्रा) का सहसंबंध (आईटीओ, 2019); व्यापार प्रवाह (व्यापार इनवॉइस), वित्तीय प्रवाह (मुद्रा में ऋण सेवा भुगतान का हिस्सा),करेंसी पेग्स (आइचेनग्रीन, 2000) विदेशी मुद्रा भंडार की मुद्रा संरचना को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। इसके अलावा, वित्तीय विवरण- वैल्यू एट रिस्क (VaR) दृष्टिकोण का उपयोग भी इष्टतम विदेशी मुद्रा पोर्टफोलियो (हंग और साथी, 2008) को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसा कि ऊपर संक्षेप में समीक्षा की गई है, विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्तता के समृद्ध साहित्य संभावित रूप से नीतिगत विकल्पों के बेहतर चयन और अनुकूल परिणामों के लिए तैयार है।

संदर्भ

- अर्सलन, यावुज एंड कैंटू, कार्लोस (2019), ''द साइज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स'', बीआईएस पेपर नंबर 104
- चिउ, जे-एस, हंग, जे-सी, और हसेउ, एम-एम। (2008), ''अ वीएआर इन्वेस्टिगेशन ऑफ करेंसी कंपोजिशन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स'', इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, 21, 76-92।
- चीटू एल (2016), ं''रिजर्व एकम्यूलेशन, इन्फ्लेशन एंड मोरल हजार्डः एविडेंस फ्रॉम नेचुरल एक्सपेरिमेंट'', वर्किंग पेपर सीरीज, नंबर 1880, यूरोपीयन सेंट्रल बैंक, जनवरी।

- आइचेनग्रीन, बी एंड मैथीसन, डी.जे. (2000), ''द करेंसी कंपोजिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स: रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट्स'', आईएमएफ वर्किंग पेपर्स, WP/00/131।
- फुकुदा, एस. आई. एंड कोन। वाई (2010), ''मैक्रोइकोनॉमिक इपैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक्टिवेशन थ्योरी एंड इंटरनेशनल एविडेंस''; एडीबीआई वर्किंग पेपर सीरीज, नंबर 197, फरवरी।
- आईएमएफ (2000), ''डेट एंड रिजर्व रिलेटेड इंडिकेटर्स ऑफ एक्सटर्नल वूलनेरेबिलिटी", पॉलिसी एंड रिव्यु डिपार्टमेंट'', 23 मार्च।
- आईएमएफ (2011), "अस्सेस्सिंग रिजर्व एडेक्वेसी" मॉनेटरी एंड कैपिटल मार्केट, रिसर्च एंड स्ट्रेटजी, पॉलिसी एंड रिव्यू डिपार्टमेंट
- आईटीओ, एच एंड मैककौली, आर.एन. (2019), ''द करेंसी कंपोजिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स" , मॉनिटरी एंड इकोनामिक डिपार्टमेंट, बीआईएस वर्किंग पेपर्स, नंबर 828, दिसंबर।
- जीन, ओ एंड रेनसीयर, आर (2006), ''द ऑप्टिमल लेवल ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स फॉर इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज: फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन'', IMF वर्किंग पेपर्स, WP/06/229।
- लिन, एम.वाई, एंड वांग, जे.एस. (2009), ''फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड इन्फ्लेशन : एन एम्पिरिकल स्टडी ऑफ फाइव ईस्ट एशियन इकोनामीज": , द एम्पिरिकल इकोनॉमिक्स लेटर, 8(5): मई।
- रोड्रिक, डी. (2006), ''द सोशल कॉस्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स'', इंटरनेशनल इकोनॉमिक जर्नल, 20, 253-266।

वैश्विक विकास के साथ घटती बढ़ती विनिमय दर

11.44 भारतीय रुपये की विनिमय दर बाजार-निर्धारित है, क्योंकि विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई का हस्तक्षेप मुख्य रूप से अत्यधिक अस्थिरता की स्थिति को नियंत्रित करना होता है। वित्तीय वर्ष के आधार पर, अर्थात अप्रैल से दिसंबर 2022 तक, भारतीय रुपये में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8.3 प्रतिशत[20] की गिरावट आई है। इसी अवधि में, यूएस डॉलर इंडेक्स[21] के संदर्भ में अमेरिकी डॉलर में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऐसा कैलेंडर वर्ष के आधार पर भी हुआ है, अर्थात जनवरी से दिसंबर 2022 तक, भारतीय रूपए में 10.8 प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि अमेरिकी डॉलर में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अमेरिकी डॉलर की नोमिनल इफेक्टिव विनिमय दर (27 अर्थव्यवस्था) 2022 में दिसंबर तक 7.8 प्रतिशत बढ़ी। जबकि भारत की एनईईआर (64 अर्थव्यवस्था) में 4.8 प्रतिशत की गिरावट आई है। दूसरे शब्दों में, ऐसा नहीं है कि भारतीय रुपया कमजोर हुआ है, बल्कि अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है। उस टिप्पणी के विरुद्ध कितने ही ट्वीट लिखे जायें, यह एक सच्चाई है। भारतीय रुपये की तुलना में कई अन्य मुद्राओं का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले और भी अधिक मूल्यह्रास हुआ (अध्याय I का चित्र देखें)। इस प्रकार, वर्तमान भू-राजनीतिक संकट की शुरुआत के बाद से वर्ष के दौरान अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के विदेशी मूल्य में बहुत व्यवस्थित गति देखी गई है।

11.45 इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर को छोड़कर चुनिंदा प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये के दाम बढ़े हैं। पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले भारतीय रुपये की औसत विनिमय दर अप्रैल-दिसंबर 2022 में अप्रैल-दिसंबर 2021 की तुलना में 6.7 प्रतिशत बढ़ी। जापानी येन के संबंध में बढ़त की यह दर 14.5 प्रतिशत थी और यूरो के मुकाबले 6.4 प्रतिशत।

20 अप्रैल 2022 की तुलना में दिसंबर 2022 में मासिक औसत विनिमय दर में परिवर्तन।

21 यू.एस. डॉलर इंडेक्स (यूएस+एक्स) विदेशी मुद्राओं के एक सेट के सापेक्ष यू.एस. डॉलर के मूल्य का माप है। ये मुद्राएँ हैं: यूरो, स्विस फ्रैंक, जापानी येन, कैनेडियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड और स्वीडिश क्रोना।

चित्र XI.16: प्रमुख मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये की विनिमय दर

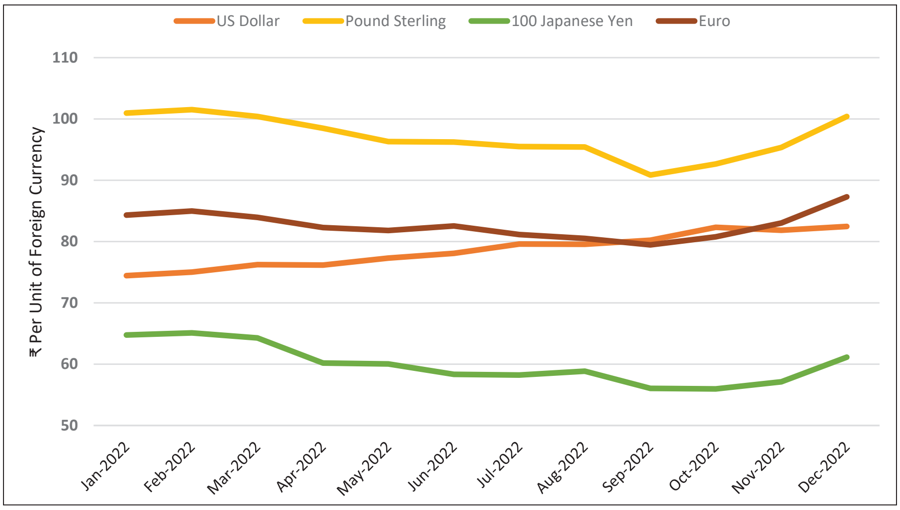

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: जापानी येन की विनिमय दर रुपये प्रति 100 येन में है।

11.46 विनिमय दर के उतार-चढ़ाव की क्रॉस-कंट्री तुलना प्राय: मुद्रास्फीति-समायोजन आधार पर की जाती है या जिसे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (REER) कहा जाता है। वित्तीय वर्ष के आधार पर, अर्थात अप्रैल 2022 और दिसम्बर 2022 के मध्य, भारतीय रुपये में क्रमश: 6-मुद्रा और 40-मुद्रा व्यापार-भारित सूचकांकों के संदर्भ में 3.4 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत की गिरावट हुई। इस प्रकार, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में वैश्विक स्पिलओवर प्रभाव के सामने भी भारतीय रुपये में मामूली मूल्यह्रास देखा गया द्य

11.47 6-मुद्रा नोमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (NEER) (ट्रेड -वेटेड) के संदर्भ में, अप्रैल 2022 की तुलना में दिसम्बर 2022 में रुपये में 0.4 प्रतिशत की गिरावट हुई। इसी तरह, अप्रैल 2022 की तुलना में दिसम्बर 2022 में 40-मुद्रा नोमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (NEER) (ट्रेड -वेटेड) के संदर्भ में रुपये में 0.7 प्रतिशत की गिरावट हुई।[22]

चित्र XI.17: 6-मुद्रा और 40-मुद्रा नोमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (एनईईआर) और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (आरईईआर) (ट्रेड -वेटेड) के सूचकांक में उतार-चढ़ाव (आधार वर्ष 2015-16 = 100)

(क): 6- मुद्राओं के व्यापार पर आधारित

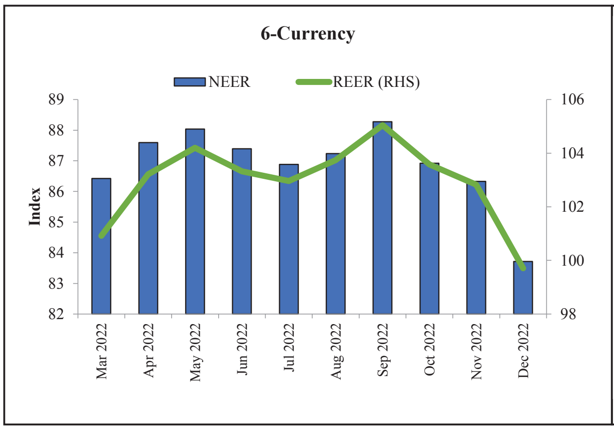

(ख): 40- मुद्राओं में व्यापार पर आधारित

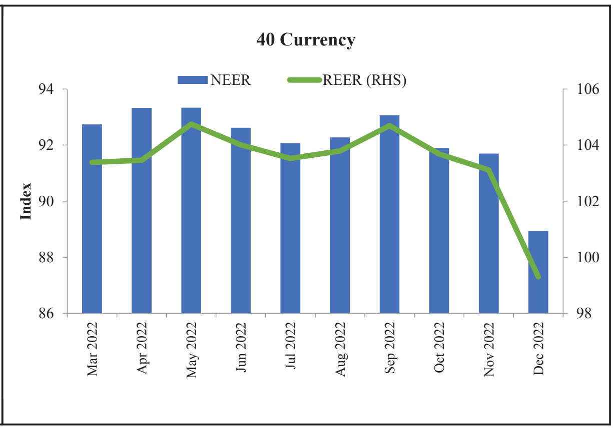

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक P: अनंतिम

22 एनईईआर और आरईईआर सूचकांक विदेशी प्रतिस्पर्धात्मकता के संकेतक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। एनईईआर विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में घरेलू मुद्रा के बाई-लेटरल नोमिनल एक्सचेंज रेट का भारित औसत है। यह भार पिछले तीन वर्षों के दौरान 6 व 40 मुद्राओं द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए देशों/क्षेत्रों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार (निर्यात और आयात) के औसत पर आधारित है। आरईईआर, जिसे घरेलू और विदेशों के बीच सापेक्ष मूल्य अंतर के लिए समायोजित नोमिनल एक्सचेंज रेट के भारित औसत के रूप में परिभाषित किया गया है, पीपीपी परिकल्पना से संबंधित है।

अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति: भारत की ठोस वित्तिय स्थिति का प्रतिबिम्ब

11.48 अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (IIP) एक सांख्यिकीय विवरण है जो, समय के साथ निम्नलिखित की संरचना को दर्शाता है (क) देश के निवासियों की वित्तीय संपत्ति का मूल्य जो अनिवासियों पर धन वापसी का दावा है तथा गोल्ड बुलियन के रूप में आरक्षित संपत्ति है; और (ख) जो देश के निवासियों की अनिवासियों के प्रति देनदारियां हैं। अर्थव्यवस्था की विदेशी वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर अर्थव्यवस्था की निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (IIP) का मान होता है, जो सकारात्मक या नकारात्मक[23] हो सकती है। निवल आईआईपी स्थिति यह निर्धारित करती है कि क्या कोई देश विदेशी संपत्ति और देनदारियों में अंतर को माप कर निवल लेनदार अथवा ऋणी राष्ट्र है या नहीं। यह आंकड़े किसी देश की वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ता के संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। निवल आईआईपी, लेनदेन के भुगतान संतुलन के साथ, घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतरराष्ट्रीय खातों के समूह को दर्शाता है।

11.49 भारत के लिए, सितंबर 2022 के अंत तक, भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय संपत्ति 847.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो मार्च 2022 के अंत के स्तर की तुलना में 73.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 7.9 प्रतिशत कम थी, ऐसा मुख्य रूप से आरक्षित परिसंपत्तियों में कमी के कारण हुआ, यद्मपि व्यापार ऋण और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि दर्ज हुई थी। आरक्षित संपत्ति 532.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो भारत की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संपत्ति का लगभग 62.9 प्रतिशत है, जिसमें इसी अवधि में 12.3 प्रतिशत की गिरावट आई है।

11.50 सितंबर 2022 के अंत तक 1,237.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय देनदारियां मार्च 2022 के अंत के स्तर की तुलना में 41.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (3.2 प्रतिशत) कम थीं। इस गिरावट का मुख्य कारण प्रत्यक्ष निवेश (निवल) बहिर्प्रवाह था, हलांकि अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में मूल्य निर्धारण किया गया तब अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर में भिन्नता ने भी देनदारियों में परिवर्तन को प्रभावित किया। सितंबर 2022 के अंत तक कुल विदेशी देनदारियों में ऋण देनदारियों का हिस्सा 50 प्रतिशत था।

11.51 इस प्रकार, भारत पर अनिवासियों का शुद्ध दावा, जिसका मूल्य सितंबर 2022 के अंत तक 389.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, मार्च 2022 के अंत के स्तर से 31.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गया। सितंबर 2022 के अंत तक भारत की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संपत्ति, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय देनदारियों का 68.5 प्रतिशत था।

चित्र XI.18.: सितंबर 2022 के अंत में भारत के शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(क) निवल आईआईपी और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आईआईपी

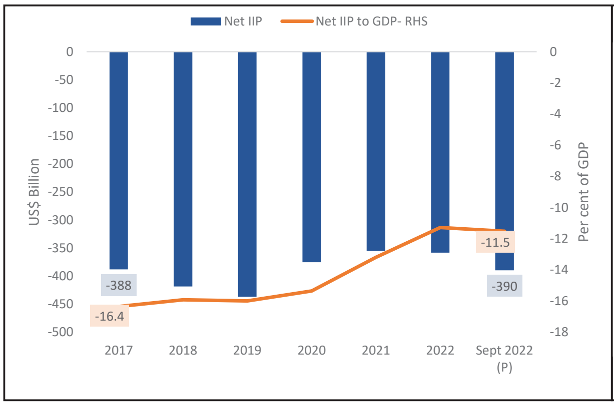

(ख) परिसंपत्ति देयता अनुपात (प्रतिशत में)

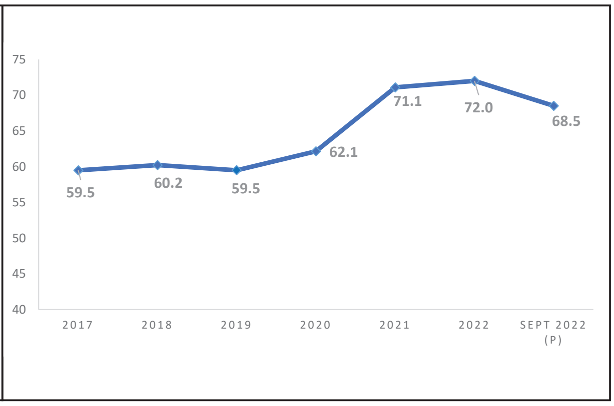

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक; P : अनंतिम

[23] आईएमएफ, भुगतान संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति नियमावली, छठा संस्करण (बीपीएम6),(BPM6),

सुरक्षित एवमं ठोस वैदेशिक ऋण स्थिति

11.52 सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो सितंबर 2021 के अंत तक 602.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 1.3 प्रतिशत (यूएस $ 7.6 बिलियन) बढ़ गया। हालांकि, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में विदेशी ऋण, सितंबर 2022 के अंत तक एक साल पहले के 20.3 प्रतिशत की तुलना में गिरकर 19.2 प्रतिशत हो गया। शास्त्र दस्तावेज के अनुसार भारत के विदेशी ऋण के लिए इष्टतम सीमा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 23-24 प्रतिशत है।[24] इस प्रकार, जहां तक विदेशी ऋण स्तर का संबंध है, भारत की संभावित वृद्धि सकारात्मक हो गई है। भारत के विदेशी ऋण के विवेकपूर्ण प्रबंधन की गवाही देते हुए,यह कई साथी देशों में, पोस्ट-कोविड के सामने आने वाले विदेशी ऋण संकट के विपरीत है।

11.53 सितंबर 2022 के अंत तक दीर्घकालिक ऋण 478.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो एक साल पहले 498.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, इसी अवधि के दौरान दीर्घकालिक ऋण की हिस्सेदारी 82.8 प्रतिशत से घटकर 78.4 प्रतिशत हो गई। दूसरी ओर, सितंबर 2022 के अंत तक 131.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अल्पकालिक ऋण सितंबर 2021 के अंत तक 104.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। तदनुसार, कुल ऋण में अल्पकालिक ऋण का हिस्सा 17.4 प्रतिशत से बढ़कर 21.6 प्रतिशत हो गया। इस संदर्भ में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि लगभग 97 प्रतिशत अल्पकालिक ऋण आयात के वित्तपोषण के लिए व्यापार ऋण के रूप में है और इसलिए अल्पकालिक ऋण में वृद्धि स्थिरता-अनुकूल है। इसके अलावा, जबकि भारत के विदेशी ऋण का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर (सितंबर 2002 के अनुसार 55.5 प्रतिशत) में दर्शाया गया है, भारतीय रुपया-मूल्यवर्गित घटक (30.2 प्रतिशत) विदेशी मुद्रा जोखिम से अलग होकर दूसरी सबसे बड़ा घटक है, जिससे विदेशी ऋण की स्थिरता अनुकूल विशेषताओं में वृद्धि हुई है।

11.54 सितंबर 2022 के अंत तक, सरकारी विदेशी ऋण (एसईडी) की राशि 124.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो एक साल पहले के स्तर से 5.7 प्रतिशत कम है। गैर-सरकारी विदेशी ऋण, सितंबर 2022 के अंत तक 486.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है,इसमें एक साल पहले के स्तर से 3.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। डिपाजिट टेकिंग कारपोरेशन(सेंट्रल बैंक को छोड़कर) और नॉन फाइनेंसियल कारपोरेशन गैर-सरकारी ऋण की बड़ी मात्रा के लिए जिम्मेदार हैं।

11.55 **वित्त मंत्रालय का ''भारत का विदेशी ऋण:-** वित्तीय हैसियत रिपोर्ट 2019-20'', भारत के विदेशी ऋण के परिवर्तन का विवरण प्रदान करता है।[25] वित्त वर्ष 99 से सरकारी विदेशी ऋण (SED) की तुलना में गैर-सरकारी क्षेत्र के विदेशी ऋण में वृद्धि की प्रत्यक्ष प्रवृत्ति देखी गई है। तदनुसार, आम तौर पर, एक सामान्य वर्ष में, यह गैर-सरकारी विदेशी ऋण में सापेक्ष गति होती है जो देश के विदेशी ऋण में बदलाव लाती है। वित्त वर्ष 21 के महामारी वर्ष में, बहुपक्षीय संस्थानों से कोविड -19 ऋण दिए जाने के कारण यह सरकारी विदेशी ऋण (SED) में वृद्धि थी जो विदेशी ऋण के समग्र विकास के बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार थी। जैसे-जैसे महामारी में कमी आई और अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के साथ सामान्य स्थिति बहाल हुई, मार्च 2022 के अंत में गैर-सरकारी विदेशी ऋण में वृद्धि के रूप में भारत के विदेशी ऋण की सामान्य गति समग्र बाह्य ऋण वृद्धि के 8.0 प्रतिशत में से 4.7 प्रतिशत अंक थी। हालाँकि, सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही में फिर से सामान्य गति से विचलन देखा गया। यह सरकारी विदेशी ऋण (महामारी वर्ष के समान) में सापेक्ष वृद्धि थी जिसने विदेशी सहायता के साथ-साथ अन्य सरकारी ऋण में गिरावट पर समग्र विदेशी ऋण गति को प्रभावित किया, जिसमें जी-सेक और एसडीआर में एफपीआई निवेश शामिल है। भारत के विदेशी ऋण में 0.4 प्रतिशत की समग्र गिरावट में से, सरकारी विदेशी ऋण (SED) में 0.5 प्रतिशत की गिरावट थी, जबकि गैर-सरकारी (non-SED) में वृद्धि 0.2 प्रतिशत थी।

---

24 गोपीनाथ, तुलसी और राजेश्वर एस, तंगजाम (2022): ग्रोथ मैक्सिमाइजिंग एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया, आरबीआई, बुलेटिन, मई, p 73-86

25 https://dea.gov.in/external-debt; बॉक्स 2.1 देखें

11.56 भारत के विदेशी ऋण भेद्यता संकेतक हानिकारक नहीं बने रहे। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में विदेशी ऋण, सितंबर 2022 के अंत तक 19.2 प्रतिशत था, जो मार्च 2022 के अंत के 19.9 प्रतिशत से कम था। ऋण चुकौती अनुपात (मूल पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान) मार्च 2022 के अंत तक 5.2 प्रतिशत की तुलना में 5.0 प्रतिशत रहा।

11.57 2021 के साथी देशों के साथ भारत के विभिन्न ऋण भेद्यता संकेतकों की तुलना करने से पता चलता है कि सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) के प्रतिशत के रूप में कुल ऋण के अपेक्षाकृत कम स्तर और कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में अल्पकालिक ऋण के मामले में देश बेहतर स्थिति में है। विदेशी ऋण के मौजूदा स्टॉक का विदेशी मुद्रा भंडार अच्छी तरह से बचाव कर रहा है।

तालिका XI.3 विदेशी ऋण बकाया

(अमेरिकी बिलियन डॉलर जब तक कि अन्यथा सूचित न किया गया हो)

क्षेत्र/ इंस्ट्रूमेंट्स	सितम्बर 2021	जून 2022 PR	सितम्बर 2022 PR	निरपेक्ष विचलन		प्रतिशत विचलन	
				सितंबर 2021 की तुलना में सितंबर 2022	सितंबर 2022 की तुलना में जून 2022	सितंबर 2021 की तुलना में सितंबर 2022	जून 2022 की तुलना में सितंबर 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
i. सामान्य सरकार	132.0	127.7	124.5	-7.5	-3.2	-5.7	-2.5
ii. सेंट्रल बैंक	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	-18.0	-0.5
iii. सेंट्रल बैंक के सिवाय जमा लेने वाले निगम	160.1	155.3	152.2	-8.0	-3.1	-5.0	-2.0
iv. अन्य क्षेत्र	284.7	301.9	305.6	20.9	3.7	7.3	1.2
iv. 1 अन्य वित्तीय निगम	52.0	51.6	50.5	-1.5	-1.1	-2.8	-2.1
iv. 2 गैर-वित्तीय निगम	232.7	250.3	255.1	22.3	4.8	9.6	1.9
iv. 3 परिवारों को सेवा देने वाले घरेलू और गैर-लाभकारी संस्थान (एनपीआईएसआईएस)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-18.5	-6.3
v. प्रत्यक्ष निवेश: इंटरकंपनी लेंडिंग	26.0	27.7	28.1	2.2	0.4	8.4	1.6
सकल बाह्य ऋण (I से V) (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)	602.9 (20.3)	612.7 (19.3)	610.5 (19.2)	7.6	-2.3	1.3	-0.4
मेमो आइटम:							
क. कुल दीर्घकालिक ऋण	498.1	486.7	478.7	-19.4	-8.0	-3.9	-1.6
ख. बी. अल्पकालिक ऋण#	104.8	126.1	131.7	27.0	5.7	25.8	4.5

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय

PR: आंशिक रूप से संशोधित; P: अनंतिम

तालिका XI. 4: भारत के प्रमुख विदेशी ऋण संकेतक: स्थिरता का चित्र

प्रतिशत तब तक की अन्यथा सूचित न हो

मार्च - अंत	विदेशी ऋण(यूएस + बिलियन)	सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी ऋण का अनुपात	ऋण चुकौती अनुपात	कुल ऋण और विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात	रियायती ऋण और कुल ऋण का अनुपात	अल्पावधि ऋण (मूल परिपक्वता) और विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात	अल्पावधि ऋण (मूल परिपक्वता) और कुल ऋण का अनुपात
2017	471.0	19.8	8.3	78.5	9.4	23.8	18.7
2018	529.3	20.1	7.5	80.2	9.1	24.1	19.3
2019	543.1	19.9	6.4	76.0	8.7	26.3	20.0
2020	558.4	20.9	6.5	85.6	8.8	22.4	19.1
2021	573.6	21.2	8.2	100.6	9.0	17.5	17.6
2022PR	619.0	19.9	5.2	98.0	8.3	20.0	19.7
जून अंत **2022 PR**	612.7	19.3	4.9	96.5	8.0	21.4	20.6
सितंबर अंत **2022 P**	610.5	19.2	5.0	87.3	7.7	24.7	21.6

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय PR: आंशिक रूप से संशोधित; P: अनंतिम

चित्र XI.19: ऋण अनुपात: 2021 के लिए क्रॉस-कंट्री तुलना

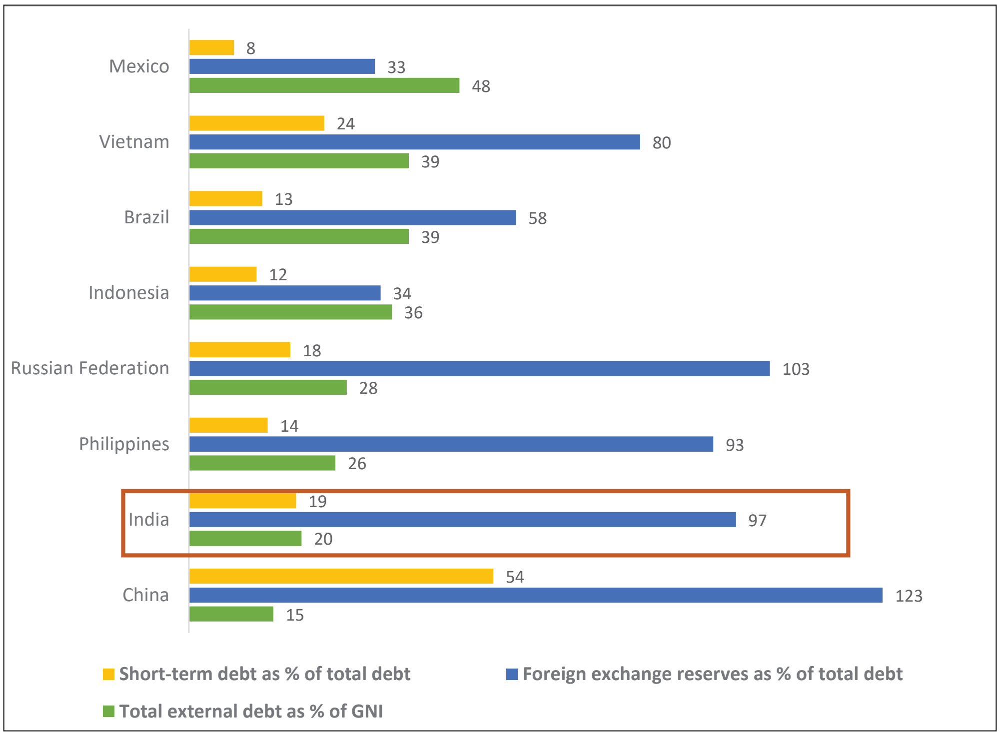

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट, 2022, विश्व बैंक

सतर्क और आशावान वैदेशिक क्षेत्र की स्थिति

11.58 वैश्विक मांग में कमी भारत के व्यापारिक निर्यात पर दबाव डाल रही है। अनुभवजन्य साहित्य दस्तावेज दर्शाते हैं कि वैश्विक विकास भारत के वास्तविक निर्यात पर एक मजबूत सांख्यिकीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, हालांकि पिछले कुछ वर्षों[26] में इसका प्रभाव कम हुआ है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, (पैरा 11.2), आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार 2022 और 2023 में वैश्विक विकास धीमा होने का अनुमान है। वैश्विक वित्तीय संकट और कोविड-19 महामारी के तीव्र चरण को छोड़कर यह 2001 के बाद से सबसे कम विकास की दर है।

11.59 इस प्रकार, आने वाले वर्ष में निर्यात दर सपाट रह सकती है यदि 2023 में वैश्विक विकास गति नहीं पकड़ता है, जैसा कि कई पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है। ऐसे मामलों में, विभिन्न उत्पाद समूह (प्रोडक्ट बास्केट) और गंतव्य विविधीकरण, जिनपर भारत एफटीए के माध्यम से नीति ला रहा है, व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के लिए उपयोगी होगा। ऐसे समय में जब वैश्विक विकास और वैश्विक व्यापार जैसा आधार नहीं बढ़ रहा है, निर्यात वृद्धि मुख्य रूप से बाजार हिस्सेदारी लाभ के माध्यम से होगी। यह निर्यात वृद्धि दक्षता, उत्पादकता, प्रौद्योगिकी और नई खोज पर ध्यान देने से होती है। इस स्थिति में सुधार करना होगा। सरकारें मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से बाजारों को खोलने का प्रयास कर सकती हैं। लेकिन, इसका फायदा उठाना निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों के हाथ में है।

11.60 भारत अपने कुछ निर्यात प्रतिस्पर्धी उत्पादों में दक्षिण एशियाई देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है द्य कपड़ा क्षेत्र में, बांग्लादेश और वियतनाम हाल के वर्षों में विश्व स्तर पर अपने निर्यात का विस्तार करते देखे गए हैं। इसके अलावा, वियतनाम मशीनरी/उपकरण, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, कुछ कृषि उत्पादों आदि में अपने निर्यात का विस्तार करने में सक्षम रहा है। हालांकि, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के लाभ के साथ-साथ कामकाजी आबादी की कम औसत आयु के लाभों को देखते हुए, भारत में लागत प्रभावी तरीके से कई उत्पादों की वैश्विक मांग को पूरा करने की क्षमता है।

11.61 आयात पक्ष पर, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता के बावजूद, इसकी कीमतों में हालिया नरमी भारत के पीओएल आयात के लिए अच्छा संकेत देती है। हालांकि, गैर-तेल, गैर-स्वर्ण आयात क्षेत्र, जो विकास के प्रति संवेदनशील हैं, में बड़ी मंदी नहीं आ सकती है, क्योंकि भारतीय विकास लगातार लचीला बना हुआ है।

11.62 संभावित प्रतिकूल घटनाओं को पहचानते हुए, भारत के विदेशी क्षेत्र के लिए आन्तरिक बफर का संज्ञान लेना महत्वपूर्ण है। भारतीय का सेवाओं का निर्यात, मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर, व्यापार और यात्रा सेवाओं का योगदान, वर्ष के दौरान अब तक मजबूत बना हुआ है और यह लचीलापन के बड़े पैमाने का प्रतीक है। भारत दुनिया में शीर्ष धन-प्रेषण प्राप्तकर्ता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, 2022 के दौरान आवक धन-प्रेषण रिकॉर्ड स्तर पर होने का अनुमान है। तदनुसार, सेवाओं और धन-प्रेषण के तहत एक बड़ा अधिशेष बढ़ते हुए व्यापार घाटे को कम करेगा। वर्षों से चालू खाता घाटे के वित्तपोषण में 'नॉन डेब्ट फ्लो' की बढ़ती हिस्सेदारी को मजबूत करने के लिए, चालू वर्ष के दौरान निवल एफडीआइ प्रवाह मजबूत रहा, जबकि हाल के महीनों में निवल एफपीआई प्रवाह सकारात्मक हो गया। इस प्रकार, चालू खाता घाटा (CAD) प्रबंधनीय सीमा के अंदर होगा और स्पष्ट रूप से आर्थिक रूप से प्रबंधनीय रहेगा। इन सबसे ऊपर, विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर

[26] चिनॉय, एस. जेड और जैन, टी (2018): व्हाट ड्राइव्स इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड व्हाट एक्सप्लेंस द रीसेंट स्लोडाउन? न्यू एविडेंस एंड पालिसी इम्प्लीकेशन; एनसीएईआर, पॉलिसी ोरम; https://www.ncaer.org/wp-content/uploads/2022/09/a4.pdf

2022 के अंत तक 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर रहा, जिसमें 9.3 महीने का आयात शामिल था। भारत के विदेशी ऋण के स्टॉक को विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंधित किया गया है।

11.63 एक क्रॉस–कंट्री परिप्रेक्ष्य से भी, भारत के विदेशी क्षेत्र ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है और इसलिए बदलती प्रतिकूल वैश्विक स्थिति का सामना करने के लिए अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में है। जैसा कि भारतीय रुपये द्वारा अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्था (ईएमई) मुद्राओं से बेहतर प्रदर्शन, आरामदायक आयात कवर और मध्यम चालू खाता घाटा से प्रमाणित होता है। भारत के विदेशी ऋण भेद्यता संकेतक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हानिकारक नहीं हैं। संक्षेप में, जहाँ भारत विदेशी क्षेत्र की चुनौतियों का सामना कर रहा है, वहां यह अपने कई साथियों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर निष्पादन कर रहा है, क्योंकि इसमें कठिन परिस्थिति से सफलतापूर्वक निपटने के लिए साधन अन्तर्निहित हैं।

भौतिक और डिजिटल आधारभूत संरचना: संभावित विकास को प्रोत्साहन

12

अध्याय

पहिये के आविष्कार ने चलने योग्य रास्तों की आवश्यकता को गति प्रदान की, और तब से क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर अवसंरचना की गाथा नहरों से आधुनिक पूंजी संरचनाओं जैसे रेलवे, सड़कों आदि तक फैल गई है। आजादी के बाद से भारत में पिछले 75 वर्षों में, परिवहन, आवास, वाणिज्यिक विकास, दूरसंचार और हाल ही में, स्वच्छता में देश के लिए आवश्यक संपत्ति का निर्माण करते हुए अवसंरचना का विकास लगातार विकास वक्र पर चला गया है। एक क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में, सरकार ने समर्पित बजटीय आवंटन, क्रॉस-सब्सिडीजिंग राजस्व-सृजन अवसंरचना और केंद्रित कार्यक्रम वितरण के माध्यम से देश के दूरस्थ क्षेत्रों में विकास को आगे बढ़ाने के लिए 'सामाजिक उपरि पूंजी' का उपयोग किया है। इससे भौतिक परिवहन और कनेक्टिविटी का विस्तार करने, उपयोग के स्थान पर सेवाएं प्रदान करने और डिजिटल पेनीट्रेशन को गहरा करने में मदद मिली है।

अवसंरचना में कई क्षेत्रों का मेल होने के कारण अर्थव्यवस्था में इसके गुणक प्रभावों को महसूस नहीं किया जा सकता है अगर यह साइलो में काम करता है। इस प्रकार, 2019 में, भारत सरकार ने अवसंरचना के प्रति एक अग्रगामी कार्यक्रम संबंधी दृष्टिकोण अपनाया। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का आरंभ वित्त वर्ष 20-25 के लिए लगभग ₹ 111 लाख करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ हुआ था, ताकि देश में अवसंरचना के विकास का व्यापक दृष्टिकोण अपनाया, समय पर पूरा करने के लिए सरकार में उच्चतम स्तर पर इसकी प्रगति की निगरानी और अवसंरचना के निवेश की योजना बनाने के लिए निवेशकों के लिए पाइपलाइन को देखने हेतु सक्षम बनाया जा सके। अवसंरचना के लिए धन सरकार से लेकर निजी क्षेत्र और बहुपक्षीय, विभिन्न स्रोतों से आता है। हालाँकि, शामिल धन की मात्रा को देखते हुए, संपत्ति के मुद्रीकरण जैसे रचनात्मक वित्तपोषण विकल्प की भी ₹ 5 लाख करोड़ के माध्यम से परिकल्पना की गई थी। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन सृजित करने के अलावा, जोखिम मुक्त ब्राउनफील्ड आस्तियों को चलाने में निजी भागीदारी से सार्वजनिक आस्तियों की प्रचालन दक्षताओं और उनके बेहतर प्रबंधन में भी मदद करेगी।

अवसंरचना के लिए प्रोग्रामेटिक दृष्टिकोण को संरचनात्मक और वित्तीय सुधारों द्वारा पूरक किया जाता है जैसे कि आईएनवीआईटी (InvITs) और आरईआईटी (REITs) के अवसंरचना वित्तपोषण विकल्प, डेडिकेटेड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन (एनएबीएफआईडी) का सृजन, अन्य सेक्टोरल डीएफआई का पुनर्पूंजीकरण, संबंधित मंत्रालयों द्वारा मॉडल रियायत करार के माध्यम से पीपीपी पारितंत्र को बढ़ावा देना और संशोधित व्यवहार्यता अंतराल निधियन स्कीम के माध्यम से सामाजिक अवसंरचना विकास को सुगम बनाना।

केंद्र और राज्यों में व्यापक योजना के साथ और अधिक अभिसरण लाने के लिए, सितंबर 2022 में शुरू की गई राष्ट्रीय रसद नीति के माध्यम से पीएम गतिशक्ति में रसद सुविधा की क्षेत्रीय पूरकता है। इन सबसे केंद्र, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्रों की भागीदारी से हमारे देश द्वारा आरंभ की गई विशाल अवसंरचना यात्रा की कमियों और खामियों को दूर करना प्रत्याशित है।

इस कहानी में कई सफलताएं देखी गई हैं। जबकि पिछले आठ वर्षों में सड़कों, रेलवे और जलमार्गों में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है तथा बंदरगाहों और हवाई अड्डों को यथेष्ठ रूप से उन्नत किया गया है। इससे देश को यूनिमॉडल से मल्टी-मॉडल परिवहन की दिशा में बढ़ने में मदद मिली है, जिससे निजी क्षेत्र को इन आस्तियों में निवेश और पुनर्निवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो पहले से ही आस्ति मुद्रीकरण की नीति द्वारा सुगम बना दिया गया है। अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार, इस कहानी का केवल हिस्सा मात्र है; आधुनिकीकरण एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे अपनाने के लिए ठोस प्रयास किया गया है और बहुत कम अवधि में हासिल किया गया है।

दुनिया भर में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, हमने डिजिटल और संचार विकास पर बहुत अधिक जोर दिया है, लेकिन प्रयोज्यता, अंतर-संचालनीयता और पहुंच के मामले में हम इस सिद्धांत को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। देश एक ऐसे समय, जब एक बुनियादी टेलीफोन कनेक्शन को एक विलासिता के रूप में देखा जाता था, से एक ऐसे चरण तक लंबा सफर तय कर चुका है जहां अब अधिकांश व्यक्तियों के पास मोबाइल कनेक्शन हैं। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि डिजिटल इंडिया पर जोर देने के साथ ही भारत में डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं की कहानी को दुनिया हमेशा एक निश्चित सम्मान और सराहना के साथ देखेगी। बहुत ही कम समय में, देश ने साधारण मोबाइल फोन और आधार संख्या के आधार पर डिजिटल सक्षमता के विभिन्न उपयोगों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास पर एक बहु गुणक प्रभाव देखा है - विभिन्न लाभों के लिए लक्षित लाभार्थी की पहचान, स्वास्थ्य देखरेख तथा शिक्षा सेवाओं का प्रावधान और वित्तीय समावेशन। इसके उपरांत, भारत की स्यू-जेनेरिस भुगतान अवसंरचना (यूपीआई) की सफलता की कहानी हुई, जिसने चयनित अंगीकरण और वैश्विक सराहना के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा की। ई-रुपी, ई-वे बिल, एमएसएमई आदि के लिए टीआरईडीएस जैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना उत्पादों के सामूहिक संवर्धन ने उत्पादकों के लिए अनुपालन के भार को कम करते हुए उपभोक्ताओं के लिए धन का वास्तविक मूल्य सुनिश्चित किया है। और अब, 2025 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विजन के साथ, सरकार अधिक से अधिक ई-गवर्नेंस आधारित सेवाएं प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

ये सभी विकास इस तथ्य के लिए प्रमाण हैं कि भारत, उन कुछ देशों में से एक रहा है जहां प्रौद्योगिकी और डिजिटल कनेक्टिविटी में नवाचार, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है और अब भी जारी है। यूपीआई सफलता एक साझा मंच, जो विविध विकास कार्यों के लिए उपाधार के रूप की सफलता ओएनडीसी के माध्यम से डिजिटल वाणिज्य को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक और अभिनव प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है जो वर्तमान में व्यवसायों और उपभोक्ताओं के बीच बातचीत के तरीके को यथेष्ठ रूप से बदल सकता है। अंतिम-प्रयोक्ताओं को उनके डेटा पर नियंत्रण के साथ सशक्त बनाना एक आवश्यक प्रगतिशील कार्य है जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क द्वारा निर्देशित है।

जैसा कि विकास इंगित करेगा, दुनिया भौतिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करने से डिजिटल अवसंरचना में निवेश करने के लिए निर्बाध रूप से आगे बढ़ी है। आगे बढ़ते हुए, यह लगभग निहित है कि भविष्य की वास्तविक दुनिया के अधिकांश अनुप्रयोग, इन दोनों से मेल खाने वाले हैं, कुछ ऐसा ही स्मार्ट शहरों के तहत प्रयास किया गया है, जो डिजिटल आस्ति और डिजिटल सेवाओं के साथ क्षेत्र-आधारित विकास को अंतर-संबद्ध करता है।

अद्वितीय चुनौतियों, जिसका सामना केवल एक अरब आबादी वाला देश ही कर सकता है, के संदर्भ में भारत की अवसंरचनात्मक यात्रा दृष्टिकोण में वैश्विक रही है, लेकिन नवाचार और कार्यान्वयन में राष्ट्रीय रही है।

परिचय

12.1 जैसे ही भारत ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे किए हैं, राष्ट्र वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में एक प्रमुख शक्ति के रूप में विकसित हो रहा है। भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले वर्षों में स्थिर प्रगति की संभावना उज्ज्वल है। यहां, आर्थिक विकास में अवसंरचना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। आर्थिक विकास में तेजी लाने और इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना[1] में निवेश करना महत्वपूर्ण है। जैसा कि अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं, इसका भारतीय निर्माण फर्मों[2] की उत्पादकता और दक्षता पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यह आगे गरीबी कम करने[3] में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ग्रामीण और कृषि विकास[4] [5]दोनों को बढ़ावा देता है। अनुभवजन्य साक्ष्य भी भारत में समग्र आर्थिक विकास[6] लाने की दिशा में अवसंरचना के सकारात्मक प्रभाव की ओर इशारा करते हैं।

चित्र XII.1: अवसंरचना की मात्रा और गुणवत्ता और देशों में आर्थिक विकास का स्तर दृढ़ता से सहसंबद्ध है

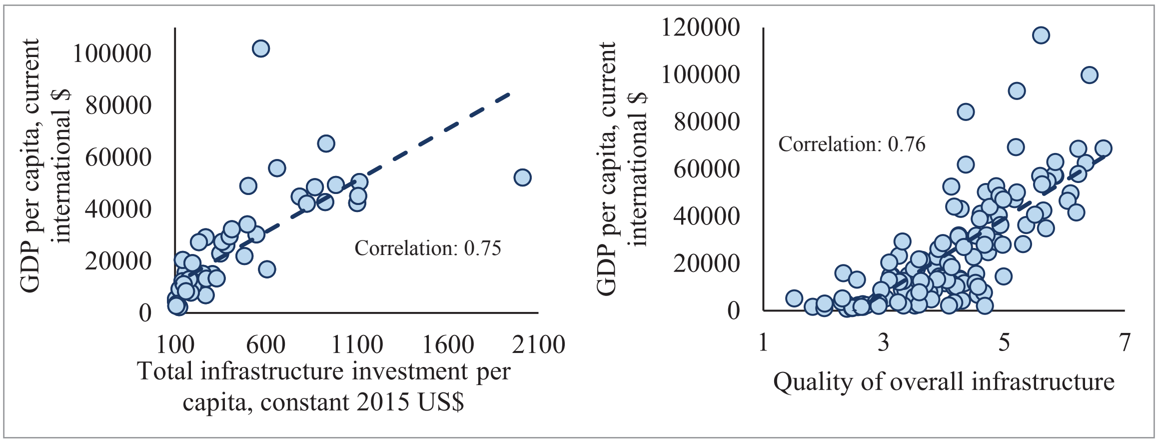

स्रोत: वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स
नोट: बायां ग्राफ 2019 से संबंधित है, और दायां ग्राफ 2018 से संबंधित है।
समग्र अवसंरचना की गुणवत्ता: 1=सबसे खराब और 7=सर्वश्रेष्ठ।

12.2 अवसंरचना और विकास के बीच उपरोक्त सहसंबंध हमें वर्तमान परिदृश्य में लाता है जब महामारी और भू-राजनीतिक संकट के समय में सरकार ने भौतिक, डिजिटल और विनियामक अवसंरचना के क्षेत्रों में सुधारों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। नई और मौजूदा अवसंरचना के निर्माण के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए, सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) जैसी पहल की। इसके अलावा, दक्षता और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से संरचनात्मक सुधारों के भाग के रूप में, गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति भी शुरू की

---

1 एक व्यापक अर्थ में, अवसंरचना शब्द का अर्थ है ''...भौतिक सुविधाएं, संस्थाएं और संगठनात्मक संरचनाएं, या समाज के संचालन के लिए सामाजिक और आर्थिक नींव'' (विश्व निवेश रिपोर्ट 2008: ट्रांसनैशनल कॉर्पोरेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज। (व्यापार और विकास पर राष्ट्र संघ सम्मेलन)। वर्तमान अध्याय केवल भौतिक और डिजिटल अवसंरचना के संदर्भ में उभरते मुद्दों पर केंद्रित है। इस सर्वेक्षण के अलग-अलग अध्याय सामाजिक अवसंरचना और वित्तीय अवसंरचना से संबंधित मुद्दों पर गहन विचार प्रदान करते हैं।

2 मित्रा, ए, वरौदाकिस, ए, और वेगानजोन-वरौदाकिस, एम (2002)। भारतीय राज्यों के विनिर्माण में उत्पादकता और तकनीकी दक्षता: अवसंरचना की भूमिका। आर्थिक विकास और सांस्कृतिक परिवर्तन, 50(2), 395-426. डीओआई:10.1086/321916.

3 दत्त, जी. और रैवेलियन, एम. (1998). ग्रामीण गरीबी को कम करने में कुछ भारतीय राज्यों ने दूसरों की तुलना में बेहतर क्यों किया है? इकोनॉमिका, 65: 17-38। https://doi-org/10.1111/1468-0335.00112

4 बिन्सवांगर, एच; खांडकर, आर. और रोसेनजवेग, एम. (1993)। हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनैंशल इंस्टीट्यूशंस इफैक्ट एग्रीकल्चर आउटपुट एंड इनवेस्टमेंट इन इंडिया, जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम 41, अंक 2, 1993, पेज 337-366, https://doi.org/10.1016/0304-3878(93)90062-R.

5 फैन, एस., हेजल, पी. और थोराट, एस. (2000)। ग्रामीण भारत में सरकारी खर्च, विकास और गरीबी। अमेरिकन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, 82: 1038-1051। https://doi.org/10.1111/0002-9092.00101.

6 साहू, पी. एंड डैश, आर. (2009) इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, जर्नल ऑफ द एशिया पैसिफिक इकोनॉमी, 14:4, 351-365, डीओआई:10.1080/13547860903169340

गई थी। अवसंरचना में निवेश और परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़े सभी पहलुओं पर सुधारों का यह प्रयास न सिर्फ आर्थिक विकास और आर्थिक दक्षता सुनिश्चित करता है बल्कि सरकार के कामकाज के प्रति अर्थव्यवस्था में विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास भी पैदा करता है।

12.3 इस पर कार्य करते हुए, सरकार ने सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन और जलमार्ग जैसी पारंपरिक अवसंरचना के विकास पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखा है। ये राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहु-मॉडल परिवहन प्रणाली जैसे तंत्र भी स्थापित किए गए हैं। बहु-मॉडल कनेक्टिविटी परिवहन के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वस्तुओं और सामानों के आवागमन के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह अंतिम गंतव्य तक मार्ग की सुविधा प्रदान करेगा और लोगों के लिए यात्रा के समय को भी कम करेगा, रसद लागत को कम करेगा और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। ये उपाय सामूहिक रूप से अवसंरचना के कम उपयोग किए गए तरीकों की अप्रयुक्त क्षमता को सामने ला सकते हैं।

12.4 अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए वित्तीयकरण और डिजिटल सेवाओं की पैठ के साथ, केवल भौतिक अवसंरचना में वृद्धि ही विकास का जवाब नहीं हो सकती है। हालांकि भारत की डिजिटल यात्रा महामारी से पहले की है, लेकिन यह कहना तर्कसंगत होगा कि महामारी के परीक्षण के समय ने कई तरीकों से इसकी स्वीकृति, अनुप्रयोग और व्याप्ति को गति दी है। नागरिकों द्वारा प्रौद्योगिकी संचालित परिवर्तनों के प्रति प्रदर्शित की गई अनुकूलनशीलता बहुत उत्साहजनक थी। डिजिटलीकरण और नव-प्रवर्तन के इस संगम ने भारत के लिए बड़े बदलाव का काम किया।

12.5 डिजिटल अवसंरचना के विकास और इसके वैश्विक स्तर पर अपनाने की यात्रा को दर्शाते हुए, यह उल्लेख करना उचित है कि 2009 में, भारत में केवल 17 प्रतिशत वयस्कों के पास बैंक खाते थे, 15 प्रतिशत डिजिटल भुगतान का उपयोग करते थे, 25 में से 1 के पास एक अद्वितीय आईडी दस्तावेज था, और लगभग 37 प्रतिशत के पास मोबाइल फोन थे। आज, इनकी संख्या में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है- संचार घनत्व 93 प्रतिशत तक पहुंच गया है; एक अरब से अधिक लोगों के पास डिजिटल आईडी दस्तावेज हैं, 80 प्रतिशत से अधिक के पास बैंक खाते हैं, और 2022 तक, प्रति माह 600 करोड़ से अधिक डिजिटल भुगतान लेनदेन पूरे किए गए हैं। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) वर्किंग पेपर[7] में अनुमान लगाया गया है कि वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रगति, जिसे भारत ने पारंपरिक विकास प्रक्रियाओं का अनुसरण करने में लगभग आधी सदी लगा दी होती, लेकिन भारत ने यह लगभग दस वर्षों में हासिल कर ली गई थी।

12.6 आज, भारत कई सर्वोत्तम प्रथाओं, विशेष रूप से अपने डिजिटल अवसंरचना नवाचारों के संबंध में, की पेशकश करने में सक्षम है, जिनका विश्व स्तर पर अनुकरण किया जा सकता है। वन-स्टॉप को-विन पोर्टल के माध्यम से सफल टीकाकरण अभियान, डिजिलॉकर, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी), ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (ओसीईएन), गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) सहाय, अनेक सफलता की कहानियां में से कुछ हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल (एनपीसीआईएल) के नेतृत्व में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) एक और ऐसा नवाचार है जिसने भुगतान परिदृश्य को बदल दिया है। यूपीआई आधारित लेन-देन मूल्य और मात्रा, दोनों के लिहाज से बढ़ा है और इसे अंतरराष्ट्रीय रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया है।

12.7 डिजिटल अवसंरचना सहायता का लाभ उठाते हुए, भारत स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के लिए दुनिया के सबसे अनुकूल स्थलों में से एक के रूप में भी उभरा है। स्टार्ट-अप को नए भारत की रीढ़ के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वे युवाओं को नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वैश्विक औसत 64 प्रतिशत की तुलना में जनता के बीच 87 प्रतिशत की उच्चतम फिनटेक अपनाने की दर के

[7] https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap106.pdf,

[8] https://bfsi.economictimes.indiatimes.com/news/fintech/indias-fintech-market-size-at-31-billion-in-2021-third-largest-in-world report/88794336 BLinC per cent20report_Fintech_2022.pdf

साथ, भारत ने डिजिटल भुगतान[8] में यू.एस और चीन के बाद तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जिससे संकेत मिलता है कि भारत का एक अप्रयुक्त बाजार है। अनुकूल पारितंत्र के साथ ये अप्रयुक्त अवसर भारत में फिनटेक के लिए बृहत विकास क्षमता उत्पन्न करते हैं। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, सरकार की नीति पहल के तहत, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (जीआईएफटी) इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) में एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब विकसित किया गया है।

12.8 यह मौजूद अवसरों का केवल एक उदाहरण है। डिजिटलीकरण की व्यापक लहर, स्मार्टफोन की बढ़ती पैठ, और प्रौद्योगिकी के अनुकूलन ने पारंपरिक और नए-फराने दोनों क्षेत्रों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। 5जी सेवाओं की शुरुआत नए आर्थिक अवसरों को खोल सकती है और देश को विकास के लिए पारंपरिक बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकती है, स्टार्ट-अप और व्यावसायिक उद्यमों द्वारा नवाचारों को बढ़ावा दे सकती है और 'डिजिटल इंडिया' की परिकल्पना को आगे बढ़ा सकती है। यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, और हमारी वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

12.9 संक्षेप में, यह अध्याय भौतिक, विनियामक और डिजिटल अवसंरचना की क्षमता को बदलने और आपस में जोड़ने में सरकार के हाल के और पिछले अनुभवों को शामिल करता है। ऐसा करते हुए, अध्याय निम्नलिखित का उत्तर देता है: कोविड-19 के झटके के बाद विभिन्न ढांचागत क्षेत्रों का प्रदर्शन कैसा रहा है? जनता की सेवा में सरकार ने डिजिटल तकनीकों का लाभ कैसे उठाया है? सरकार अवसंरचना परियोजनाओं में समन्वय और दक्षता की भूमिका का निर्धारण कहां तक कर पाई है और अवसंरचना के विकास के प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्या है? ऐसा करने में, हम भारत को शीर्ष तीन वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए सरकार की योजनाओं को शामिल करेंगे और अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक एक विकसित राष्ट्र की स्थिति के करीब आने की स्थिति में होंगे।

भारत में अवसंरचना के विकास के लिए सरकार की परिकल्पना और दृष्टिकोण

12.10 अवसंरचना निवेश में वृद्धि करने से अर्थव्यवस्था के संभावित विकास को महत्वपूर्ण समर्थन मिलता है। सरकार ने हाल के वर्षों में, पूंजीगत व्यय में वृद्धि के माध्यम से अवसंरचना के विकास और निवेश के लिए एक संवर्धित गति प्रदान की है। यह समर्थन संकट के ऐसे समय में दिया गया है जब निजी क्षेत्र द्वारा पूंजीगत व्यय को कम कर दिया गया है। 2022-23 (ब.अ.) में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय (लक्ष्य) पिछले वर्ष (2021-22) के 5.5 लाख करोड़ रुपये से 7.5 लाख करोड़ रुपये करके 35.4 प्रतिशत बढ़ा दिया गया था, जिसमें से लगभग 67 प्रतिशत अप्रैल से दिसंबर 2022 तक खर्च किया जा चुका है।

चित्र XII.2: केंद्र सरकार ने पिछले दो वर्षों में लगातार पूंजीगत व्यय में वृद्धि की है*

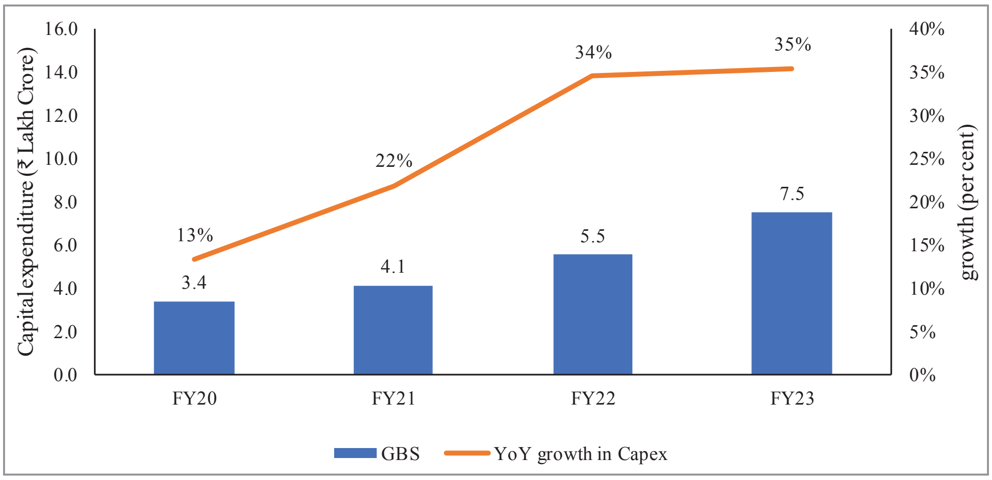

*सभी आंकड़े संबंधित वित्तीय वर्ष के बजटीय अनुमानों के निरूपक हैं
स्रोत: भारत का केंद्रीय बजट

12.11 प्रयासों का परिणाम दिसंबर 2022 तक मंत्रालयों/विभागों के कैपेक्स खर्च में दिखाई दे रहा है, जो वित्त वर्ष 22 में इसी अवधि (यानी, दिसंबर 2021 तक) ₹3.9 लाख करोड़ के मुकाबले ₹5 लाख करोड़ (7.5 लाख करोड़ के बजट कैपेक्स के मुकाबले लगभग 67 प्रतिशत हासिल किया गया है) रहा है। वित्त वर्ष 23 में वास्तविक व्यय भी इसी अवधि के लिए वित्त वर्ष 22 में व्यय की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है।

12.12 सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि ने भविष्य के विकास की नींव रखते हुए आर्थिक विकास की सहायता करने में मदद की है क्योंकि पूंजीगत आस्ति आर्थिक दक्षता और संभावित विकास को बढ़ावा देती है। यह निजी निवेश में भी निवेश जुटा सकता है, जैसा कि आईएमएफ ने भारत[9] के मामले में देखा। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र में क्षमता उपयोग में सुधार हो रहा है।

12.13 हालांकि, एनआईपी और एनएमपी अवसंरचना निवेश को आगे बढ़ाने में बहुत आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेंगे, एनएलपी सेवाओं, डिजिटल अवसंरचना और रसद कार्यबल में कौशल के अंतर को दूर करेगा। पीएम गतिशक्ति को एक बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ, भौतिक अवसंरचना में अंतराल को भरने और विभिन्न एजेंसियों की मौजूदा और प्रस्तावित अवसंरचना विकास पहलों को एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। चूंकि भौतिक अवसंरचना को अपनी लंबी अवधि के दौरान निरंतर समर्थन की आवश्यकता होती है, सरकार ने एक निवेश उच्च निवेश चक्र को गति में लाने के लिए विकास वित्तीय संस्थान के रूप में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) की भी स्थापना की है। भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) के रूप में तेजी से निवेश करने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है।

12.14 अवस्थापना के लिए सरकार का विजन यहीं नहीं रुकता। जैसा कि भारत ने कोप 27 में अपनी दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति पहले ही प्रस्तुत कर दी है, अगली छलांग उन्नत अवसंरचना की ओर होगी, जो अधिक ऊर्जा कुशल है, चक्रीय अर्थव्यवस्था के विचार को शामिल करता है और निम्न कार्बन विकास की ओर बढ़ता है। जलवायु अनुकूल और जलवायु प्रतिरोधी अवसंरचना को स्थापित करने के लिए आवश्यक निवेश की राशि अकेले सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान किए जाने के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। इस तरह की अवसंरचना के वित्तपोषण और निर्माण दोनों के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी की आवश्यकता हो सकती है, यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम आगे बात करेंगे।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)

12.15 अवसंरचना में निजी निवेश मुख्य रूप से पीपीपी के रूप में होता है। पीपीपी अवसंरचना के महत्वपूण र्ा क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की ताकत को आगे बढ़ाने में सरकारों के लिए महत्वपूर्ण साधन हैं। यह अवसंरचनात्मक अंतर को दूर करने और अवसंरचना सेवा सुपुर्दगी की दक्षता में सुधार करने में मदद करता है। पीपीपी की यह सफलता संस्थागत संरचना और वित्तीय सहायता की सुदृढ़ता तथा मानकीकृत दस्तावेजों, जैसे योग्यता के लिए मॉडल अनुरोध (आरएफक्यू), प्रस्ताव के लिए मॉडल अनुरोध (आरएफपी) और मॉडल रियायत समझौते (एमसीए) के उपयोग और उपलब्धता में निहित है।

12.16 भारत में, अवसंरचना के कार्यक्रमों में निजी भागीदारी कई पीपीपी मॉडल का समर्थन करती है, जिसमें बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी), डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर (डीबीएफओटी), रिहैबिलिटेट-ऑपरेट-ट्रांसफर (आरओटी), हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम), और टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) मॉडल जैसे प्रबंधन अनुबंध शामिल हैं। बीओटी मॉडल के तहत दो प्रकार हैं- बीओटी (टोल) और बीओटी (वार्षिकी) जो इस बात पर निर्भर करता है कि यातायात जोखिम कौन वहन करता है। बीओटी (टोल) के मामले में, यातायात जोखिम पीपीपी रियायतग्राही द्वारा वहन किया जाता है, जबकि बीओटी (वार्षिकी) के मामले में, यह सरकार (सार्वजनिक प्राधिकरण) द्वारा वहन किया जाता है।

[9] बहल, गिरीश और रायसी, मेहदी और तुलिन, वलोडिमिर। (2018)। क्राउडिंग-आउट या क्राउडिंग-इन? भारत में सार्वजनिक और निजी निवेश।

12.17 सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी), जो केंद्रीय क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए शीर्ष निकाय है, ने परियोजनाओं का त्वरित मूल्यांकन सुनिश्चित करने, देरी को खत्म करने, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने और मूल्यांकन तंत्र और दिशानिर्देशों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन तंत्र को सुव्यवस्थित किया है। पीपीपीएसी की अध्यक्षता सचिव, आर्थिक कार्य विकास (आ.का.वि.) द्वारा की जाती है, जिसमें व्यय विभाग, विधिक कार्य विभाग, प्रायोजक मंत्रालय/विभाग के सचिव और सीईओ, नीति आयोग सदस्य के रूप में केंद्रीय क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विचार और उनका मूल्यांकन करते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति ने वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2023 तक 2,27,268.1 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली 79 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

12.18 आर्थिक रूप से अव्यवहार्य लेकिन सामाजिक/आर्थिक रूप से वांछनीय पीपीपी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, आर्थिक कार्य विभाग (आ.का.वि.) ने 2006 में व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) स्कीम शुरू की। इस योजना के तहत, आर्थिक क्षेत्र की परियोजनाओं को वीजीएफ अनुदान के रूप में कैपेक्स का 40% तक मिल सकता है। इस स्कीम में सामाजिक क्षेत्रों के लिए वीजीएफ अनुदान के उच्चतर प्रावधान शामिल हैं। वीजीएफ अनुदान के रूप में वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) के बाद पांच वर्षों के लिए सामाजिक क्षेत्रों को कैपेक्स का 80 प्रतिशत और प्रचालन व्यय (ओपेक्स) का 50 प्रतिशत तक मिल सकता है।

12.19 सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं को दो श्रेणियों: उप स्कीम-1 और उप-स्कीम-2 के तहत वीजीएफ मिलता है। उप-स्कीम-1 में अपशिष्ट जल शोधन, जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसे सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित कार्य शामिल हैं। इस श्रेणी के तहत परियोजनाओं में कम से कम 100% प्रचालन लागत वसूली निहित होनी चाहिए। भारत सरकार (जीओआई), कैपेक्स का अधिकतम 30 प्रतिशत प्रदान करेगी और राज्य सरकार, कैपेक्स के 30 प्रतिशत तक अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकती है। उप-स्कीम 2 के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों से प्रदर्शन/प्रायोगिक परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाती है। इस श्रेणी के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं की कम से कम 50 प्रतिशत प्रचालन लागत वसूली होनी चाहिए। वीजीएफ के रूप में वाणिज्यिक प्रचालनों के पांच वर्षों के लिए भारत सरकार परियोजना के कैपेक्स का अधिकतम 40 प्रतिशत और परियोजना के ओपेक्स का अधिकतम 25 प्रतिशत प्रदान करेगी।

12.20 वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक, वीजीएफ स्कीम के तहत, 57870.1 करोड़ रुपये के टीपीसी के साथ 56 परियोजनाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था और 25263.8 करोड़ रुपये की 27 परियोजनाओं को ₹5813.6 करोड़ (भारत सरकार और राज्य, दोनों के हिस्से) के कुल व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण अनुमोदन के साथ अंतिम मंजूरी दी गई थी। अनुमोदित वीजीएफ में भारत सरकार का हिस्सा ₹3102.6 करोड़ है और अनुमादित कुल वीजीएफ में राज्य का हिस्सा ₹2710.9 करोड़ है। वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2023 तक इस स्कीम के तहत डीईए द्वारा संवितरित कुल वीजीएफ राशि 2982.4 करोड़ रुपये है।

12.21 पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना विकास खर्चों के लिए वित्तीय सहायता के लिए एक स्कीम - 'इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम' (आईआईपीडीएफ) - सरकार द्वारा 3 नवंबर, 2022 को अधि सूचित की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य ऑन-बोर्डिंग लेनदेन सलाहकारों द्वारा विश्वसनीय, व्यवहार्य पीपीपी परियोजनाओं की एक शेल्फ बनाने के लिए, केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों में परियोजना-प्रायोजक प्राधिकरणों को आवश्यक निधियन सहायता प्रदान करके गुणवत्तापूर्ण पीपीपी परियोजनाओं को विकसित करना है।

12.22 आईआईपीडीएफ स्कीम का वित्त वर्ष 23 से वित्त वर्ष 25 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए कुल परिव्यय ₹150 करोड़ है। इस स्कीम के तहत, एक प्रस्ताव के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपये की राशि, किसी भी कर निहितार्थ सहित, को वित्तपोषित किया जा सकता है, जिसमें पीपीपी परियोजना के परामर्शियों/लेन-देन सलाहकारों की लागत शामिल हो सकती है। ₹5 करोड़ से अधिक की किसी भी वित्तपोषण की आवश्यकता परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा स्वयं वहन की जाएगी, और आईआईपीडीएफ के तहत वित्तपोषण की वसूली नहीं की जाएगी।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी)

12.23 हमारे जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के विकास की उच्च दर को बनाए रखने के लिए अवसंरचना के निवेश में निरंतर वृद्धि की आवश्यकता है, जो व्यापक सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। इसे देखते हुए, सरकार ने पूरे देश में उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 20-25 के दौरान लगभग 111 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित अवसंरचना के निवेश के साथ एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) शुरु किया। यह परियोजना की तैयारी में सुधार और अवसंरचना में घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की भी परिकल्पना करता है। एनआईपी में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड निवेश को कवर करने वाली ₹100 करोड़ से अधिक की अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं। एनआईपी में वर्तमान में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के तहत 108 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल निवेश के साथ 8,964 परियोजनाएं हैं। क्षेत्रीय संरचना के संबंध में, परियोजनाओं में परिवहन क्षेत्र की आधे से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं।

चित्र XII.3: एनआईपी के तहत परियोजनाओं की स्थिति

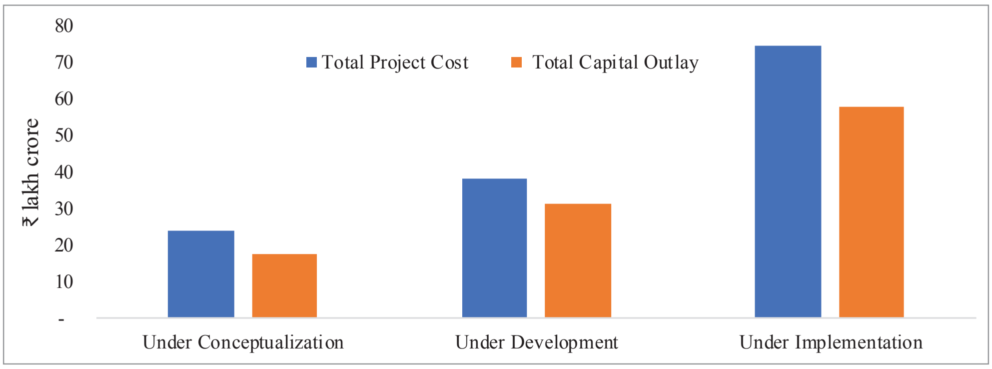

स्रोत: आर्थिक कार्य विभाग।

नोट: डेटा 13 नवंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार

चित्र XII.4: एनआईपी में परिवहन क्षेत्र का दबदबा है

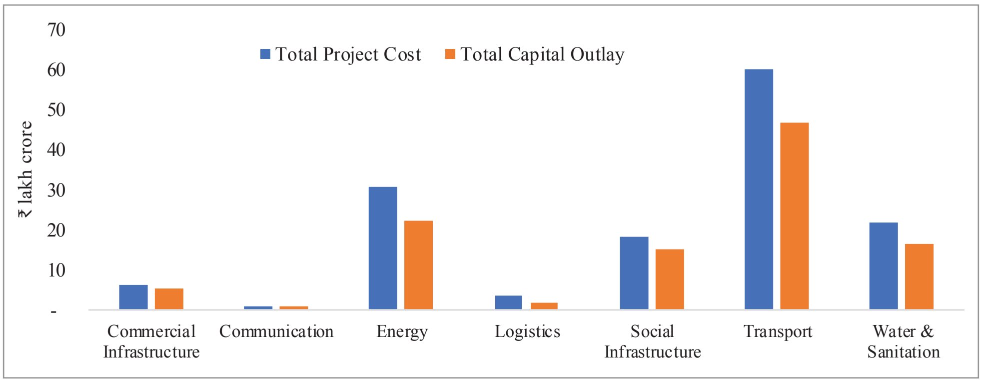

स्रोत: आर्थिक कार्य विभाग।

नोट: डेटा 13 नवंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार

12.24 एनआईपी को इन्वेस्ट इंडिया ग्रिड (आईआईजी) प्लेटफॉर्म पर रखा गया है और यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और मंत्रालयों को एक ही स्थान पर सभी प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को रखने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार आईआईजी सभी आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना उप-क्षेत्रों में परियोजना की प्रगति को पता करने और समीक्षा करने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल के रूप में कार्य करता है। पोर्टल परियोजना-प्रायोजन प्राधिकरणों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने में भी सक्षम बनाता है। परियोजना निगरानी दल (पीएमजी) बड़े पैमाने की परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए

सरकार द्वारा स्थापित एक संस्थागत तंत्र है। पीएमजी ₹ 500 करोड़ और उससे अधिक के अनुमानित निवेश वाली परियोजनाओं के लिए शीघ्र अनुमोदन/मंजूरी में भी शामिल है। अब, एनआईपी और पीएमजी पोर्टल्स को एकीकृत करने का प्रस्ताव दिया गया है। लागू होने पर, एनआईपी सभी अवसंरचना परियोजनाओं (₹100 करोड़ या उससे अधिक की लागत) के लिए पहला प्रवेश बिंदु (डेटाबेस) बन जाएगा। पीएमजी पोर्टल एनआईपी डेटाबेस से आवश्यकताओं (₹500 करोड़ या अधिक की परियोजना लागत) के अनुसार डेटा उठाएगा। इससे मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समय और प्रयास में काफी बचत होगी और बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी में आसानी होगी।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन - मुद्रीकरण के माध्यम से निर्माण

12.25 कोविड-19 महामारी से वित्तीय दबावों के बावजूद अवसंरचना निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता के लिए सभी क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं से पूंजी को अनलॉक करने की आवश्यकता है। इस प्रकार 23 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) की घोषणा की गई। 'मुद्रीकरण के माध्यम से आस्ति सृजन' सिद्धांत के आधार पर, यह नवीन अवसंरचना सृजन के लिए निजी क्षेत्र निवेश करता है।

12.26 यह उम्मीद है कि निजी प्रतिभागी आस्तियों का संचालन और रखरखाव करेंगे। एनएमपी बैलेंस शीट को कम करने और नई आधारभूत आस्तियों में निवेश के लिए राजकोषीय स्थान प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। वित्त वर्ष 20-25 से चार वर्ष की अवधि में एनएमपी के तहत अनुमानित कुल मुद्रीकरण क्षमता केंद्र सरकार की मुख्य आस्तियों के माध्यम से 6.0 लाख करोड़ रुपये है।

12.27 मुद्रीकरण की प्रक्रिया में सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण के स्वामित्व वाली आस्तियों का सीमित अवधि का लाइसेंस/पट्टा किसी निजी क्षेत्र की संस्था को अग्रिम या आवधिक विचार के लिए शामिल है। सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त धन को नई अवसंरचना में पुनर्निवेशित किया जाता है या अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाता है। इस तरह के अनुबंधों में अनुबंध अवधि के अंत में प्राधिकरण को वापस आस्तियों के हस्तांतरण के प्रावधान शामिल हैं। इसमें एक स्थिर राजस्व उत्पादन रूपरेखा (या दीर्घकालिक राजस्व अधिकार) के साथ जोखिम रहित और ब्राउनफील्ड आस्तियों का चयन शामिल है जो स्पष्ट रूप से रिंग-फेंस हो सकते हैं। इसमें 12 से अधिक लाइन मंत्रालयों/विभागों में 20 से अधिक आस्तियों वर्ग शामिल हैं। इसके अलावा, शीर्ष 5 क्षेत्र (अनुमानित मूल्य से) कुल पाइपलाइन मूल्य का लगभग 83 प्रतिशत अधिकृत करते हैं: सड़कें (27 प्रतिशत), इसके बाद रेलवे (25 प्रतिशत), बिजली (15 प्रतिशत), तेल और गैस पाइपलाइन (8 प्रतिशत), और दूरसंचार (6 प्रतिशत)। सड़क और रेलवे मिलकर कुल एनएमपी मूल्य का लगभग 52 प्रतिशत योगदान करते हैं।

12.28 वित्तीय वर्ष 2022 में ₹0.9 लाख करोड़ के मुद्रीकरण लक्ष्य के मुकाबले, इस अवधि के दौरान सड़कों, विद्युत, कोयला और खदान के तहत ₹0.97 लाख करोड़ प्राप्त किए गए हैं। वर्षों की पूर्ण लेनदेन में संचयी निवेश क्षमता ₹ 9.0 लाख करोड़ (प्राप्त मूल्य संचित राशि, प्राप्तियों और/या निजी निवेश के रूप में) अनुमानित है । एनएमपी का दूसरा वर्ष यानी वित्त वर्ष 2023 का लक्ष्य मुख्य-परिसम्पत्ति मुद्रीकरण के तहत 1.6 लाख करोड़ रुपये (समग्र एनएमपी लक्ष्य का 27 प्रतिशत) है। यह एक सांकेतिक मूल्य है, जबकि सार्वजनिक आस्तियों के लिए वास्तविक प्राप्ति समय, लेनदेन संरचना, निवेशक की रुचि आदि के आधार पर भिन्न हो सकती है।

राष्ट्रीय रसद नीति राष्ट्रीय संभार नीति: संभार तंत्र की लागत को कम करना।

12.29 यह देखते हुए कि भारत का लक्ष्य अपने निर्यात को कई गुना बढ़ाना है, यह महत्वपूर्ण है कि इस लक्ष्य को सुगम बनाने वाले रसद पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। वैश्विक बेंचमार्क 8 प्रतिशत के मुकाबले भारत में संभार लागत सकल घरेलू उत्पाद के 14-18 प्रतिशत की सीमा में रही है। व्यापार के लिए रसद में सुधार के लिए दूर किए जाने वाले प्रमुख आयामों में शामिल हैं: सीमा शुल्क सहित सीमा नियंत्रण एजेंसियों द्वारा निकासी प्रक्रिया की दक्षता (यानी, गति, सरलता और औपचारिकताओं की भविष्यवाणी) सुनिश्चित करना; व्यापार और

परिवहन संबंधी अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार (जैसे, बंदरगाह, रेलमार्ग, सड़कें, सूचना प्रौद्योगिकी); प्रतिस्पर्धात्मक कीमत वाले शिपमेंट की व्यवस्था करना आसान बनाना; संभार सेवाओं की क्षमता और गुणवत्ता में वृद्धि (उदाहरण के लिए, परिवहन संचालकों, सीमा शुल्क दलालों); खेप पर नजर रखना और पता करना और निर्धारित या अपेक्षित डिलीवरी समय के भीतर गंतव्यों तक पहुंचने में शिपमेंट की समयबद्धता सुनिश्चित करना। इन पहलुओं को विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स (एलपीआई) के रूप में दर्ज किया है।

12.30 भारत सरकार द्वारा 'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान), भारतमाला, सागरमाला, पर्वतमाला, राष्ट्रीय रेल योजना जैसी 'अवसंरचनात्मक पहलों' तथा 'प्रकिया सुधार', जीएसटी, ई-संचित, व्यापार के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस (स्विफ्ट), भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे (आईसीईजीएटीई), तुरंत सीमा शुल्क, और अन्य के माध्यम से रसद पारिप्रणाली में सुधार के लिए पहले ही कई प्रयास किए जा चुके हैं।

12.31 हालांकि, विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा इन सभी प्रयासों को एकीकृत करने और रसद क्षेत्र के लिए एक व्यापक अंत:विषय, पार-क्षेत्रीय और बहु-क्षेत्राधिकार ढांचा तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई। इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए, प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने, नियामक ढांचे, कौशल विकास और अन्य के बीच रसद को मुख्यधारा में लाने के माध्यम से रसद में दक्षता में सुधार के घटकों को दूर करके एनएलपी को 17 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था।

12.32 एनएलपी का दृष्टिकोण ''तेजी से और समावेशी विकास के लिए देश में एक तकनीकी रूप से सक्षम, एकीकृत, लागत प्रभावी, लचीला, टिकाऊ और भरोसेमंद रसद पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।'' यह नीति भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ाने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का एक प्रयास है। इसका उद्देश्य भंडारण, बहु-मॉडल डिजिटल एकीकरण, रसद सेवाओं में आसानी, मानव संसाधन और कौशल विकास के लिए वैश्विक मानकों को लाना है।

12.33 एनएलपी की परिकल्पना को हासिल करने के लक्ष्य हैं (i) वर्ष 2030 तक भारत में रसद की लागत को वैश्विक बेंचमार्क के बराबर करने के लिए कम करना; (ii) लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार- वर्ष 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होने का प्रयास है, और (iii) एक कुशल रसद पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डेटा-संचालित निर्णय सहायता तंत्र बनाना है।

12.34 नीति को एक व्यापक रसद कार्य योजना (सीएलएपी) के माध्यम से लागू किया जाएगा। सीएलएपी के तहत हस्तक्षेपों को विशिष्ट प्रमुख कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें एकीकृत डिजिटल रसद प्रणाली, भौतिक आस्तियों का मानकीकरण और बेंचमार्किंग सेवा गुणवत्ता मानक, रसद मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण, स्टेट एंगेजमेंट, एक्जिम (निर्यात-आयात) लॉजिस्टिक्स, सेवा सुधार ढांचा, कुशल रसद के लिए क्षेत्रीय योजना और रसद पार्कों के विकास की सुविधा शामिल हैं।

12.35 देश में रसद प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में, विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स इज इंडेक्स (एलइएडीएस) के माध्यम से देश में रसद की स्थिति का उप-राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने की पहल की गई है। निम्नलिखित बॉक्स इस पहल के कुछ विवरण प्रदान करता है।

बॉक्स XII.1: विभिन्न राज्यों में रसद को आसान बनाना

सरकार ने 2018 में एलईएडीएस इंडेक्स के रूप में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में रसद पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण-आधारित मूल्यांकन किया। इसके बाद 2019, 2021 और 2022[10] में सर्वेक्षण किया गया। इनमें से प्रत्येक सर्वेक्षण का उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में रसद बुनियादी ढांचे, नीतिगत ढांचे और नियामक व्यवस्था से संबंधित राज्य स्तर पर कारोबारी माहौल का विश्लेषण करना है।

[10] कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 2020 में सर्वेक्षण नहीं किया जा सका।

यह एक हितधारकों के सर्वेक्षण पर आधारित है और विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई) पद्धति का उपयोग करता है। रसद के प्रमुख क्षेत्रों– अवसंरचना, सेवाओं की समयसीमा, पता लगाने की क्षमता, प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा, परिचालन वातावरण और विनियमन की दक्षता में बैठकों और ऑनलाइन सर्वेक्षणों की एक श्रृंखला के आधार पर हितधारक नियुक्त करने के लिए एक रैंकिंग पद्धति का उपयोग करके राज्य एलपीआई पर पहुंचा है। एलईएडीएस पहल के बाद, 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी रसद नीतियों को तैयार और अधिसूचित किया है।

एलईएडीएस 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट 13 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी, जिसमें पीएम गतिशक्ति एनएमपी और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रसद क्षेत्र में वर्तमान विकास पर विचार किया गया था। सर्वेक्षण ने देश भर में 2100 से अधिक उत्तरदाताओं से 6500 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त की हैं। एलईएडीएस के पिछले संस्करणों के विपरीत, जो सभी राज्यों के लिए रैंकिंग प्रणाली पर आधारित थे, एलईएडीएस 2022 ने एक वर्गीकरण-आधारित ग्रेडिंग को अपनाया है, और राज्यों को अब चार श्रेणियों के तहत तटीय राज्य, भीतरी इलाकों/स्थल से घिरे राज्य, उत्तर-पूर्वी राज्य, और संघ राज्य क्षेत्रों के आकलन के लिए वर्गीकृत किया गया है, कि विशिष्ट क्लस्टर के भीतर शीर्ष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की तुलना में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है।

अतीत से कुछ अलग करते हुए, राज्यों को क्रम में स्थान नहीं दिया गया है। इस बार, उन्हें तीन प्रदर्शन श्रेणियां आवंटित की गई हैं, अचीवर्स: राज्य/केंद्रशासित प्रदेश 90 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले, फास्ट मूवर्स: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 80 से 90 प्रतिशत के बीच प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले, और उम्मीदवार: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 80 प्रतिशत से नीचे प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले, बनाया गया है। परिणाम नीचे दर्शाए गए हैं।

अचीवर्स	फास्ट मुवर्स	उम्मीदवार
उत्तर प्रदेश	केरल	गोवा
तमिलनाडु	सिक्किम	बिहार
उत्तराखंड	मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़
तेलंगाना	त्रिपुरा	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
पंजाब	पुदुचेरी	मिजोरम
ओडिशा	राजस्थान	जम्मू और कश्मीर
कर्नाटक		अरूणाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश		लद्दाख
असम		लक्षद्वीप
दिल्ली		नागालैंड
चंडीगढ़		
हरियाणा		

पीएम गतिशक्ति: एकीकृत परियोजना आयोजना हेतु एक मास्टर प्लान

12.36 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विकास के अनुभव ने बहुविध परिवहन नेटवर्क दृष्टिकोण के महत्व पर प्रकाश डाला है। अवसंरचना परियोजनाओं के मामले में समग्र योजना का परिचय देते हुए, सरकार ने अवसंरचना के विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण तैयार करते हुए पीएम गतिशक्ति की शुरुआत की। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सभी अवसंरचना परियोजनाओं के साथ वास्तविक समय के आधार पर कुशल योजना और कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक डेटाबेस में शामिल एक साझा समावेशी मंच का निर्माण शामिल है। एनआईपी में सात इंजनों (सड़क, रेलवे, हवाईअड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद अवसंरचना) से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। मास्टर प्लान की कसौटी उच्च गुणवत्ता वाले आधुनिक अवसंरचना और आवागमन के विभिन्न तरीकों-लोगों और वस्तुओं दोनों और परियोजनाओं के स्थान के बीच रसद संबंधी तालमेल होगा। इससे उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि और विकास को गति देने में मदद मिलेगी।''

12.37 प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग के साथ मंत्रालयों/विभागों में एकीकृत योजना और समकालिक कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों और वस्तुओं के निर्बाध आवागमन के लिए महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करते हुए बहु-मॉडल कनेक्टिविटी और रसद दक्षता में सुधार करना है, जिसमें व्यवधानों को कम करने और अवसंरचना परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

12.38 एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, एक जीआईएस-आधारित और डेटा-संचालित निर्णय समर्थन मंच जिसे पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान कहा जाता है, पेश किया गया है। 22 मंत्रालयों/विभागों और 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 1950 डेटा स्तरों को राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर गाँव, जिला और तालुका स्तरों तक मैप किया गया था। काम के दोहराव को रोकने और अवसंरचना की योजना के लिए एकल खिड़की प्रणाली बनाने के लिए इसे विभिन्न मंत्रालयों/एजेंसियों के विभिन्न अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, ग्राम पंचायतों, नगर निगम, समाज कल्याण आवास आदि से संबंधित महत्वपूर्ण आस्तियों पर डेटा परतों को मैप किया जा रहा है और भौतिक और सामाजिक अवसंरचना की योजना में पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों के इष्टतम उपयोग के लिए डेटा सत्यापन किया जा रहा है। गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग के मामलों में मॉडल स्कूलों से कनेक्टिविटी और आपदा प्रबंधन योजना आदि शामिल हैं।

भौतिक अवसंरचना क्षेत्रों में विकास

सड़क परिवहन: सरकार द्वारा बढ़ाए गए सड़क संपर्क से बढ़ी हुई बजट सहायता

12.39 राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, जिला सड़कों, ग्रामीण सड़कों और शहरी सड़कों के नेटवर्क के रूप में सड़क अवसंरचना देश की उपभोक्ताओं और व्यवसायों की विविध आबादी के लिए परिवहन और कनेक्टिविटी के प्रमुख साधन के रूप में कार्य करता है। सड़कें देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के माध्यम से परिवहन के अन्य साधनों की पूरक हैं।

12.40 समय के साथ वित्त वर्ष 2022 में 10457 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच)/सड़कों के निर्माण में वृद्धि हुई है, जबकि वित्त वर्ष 2016 में 6061 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ था। वित्त वर्ष 2023 में (अक्टूबर 2022 तक), 4060 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों/सड़कों का निर्माण किया गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में उपलब्धि का लगभग 91 प्रतिशत था। इस क्षेत्र में निवेश के लिए कुल बजटीय समर्थन पिछले चार वर्षों में तेजी से बढ़ रहा है और वित्त वर्ष 2023 (31 अक्टूबर 2022 तक) के दौरान लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये रहा है।

12.41 सार्वजनिक क्षेत्र की आस्तियों के मुद्रीकरण की दृष्टि के अनुरूप, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने वित्त वर्ष 22 में न केवल सड़कों के मुद्रीकरण की सुविधा के लिए बल्कि सड़क क्षेत्र में निवेश

करने के लिए विदेशी और राष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भी अपना आईएनवीआईटी लॉन्च किया। अब तक, एनएचएआई आईएनवीआईटी ने उच्च क्षमता वाले विदेशी और भारतीय संस्थागत निवेशकों से ₹ 10,200 करोड़ से अधिक (दिसंबर 2022 तक) जुटाए हैं।

चित्र XII.5: 2015-16 से राष्ट्रीय राजमार्ग/सड़क निर्माण में वृद्धि हुई है, जो 2020-21 में अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है

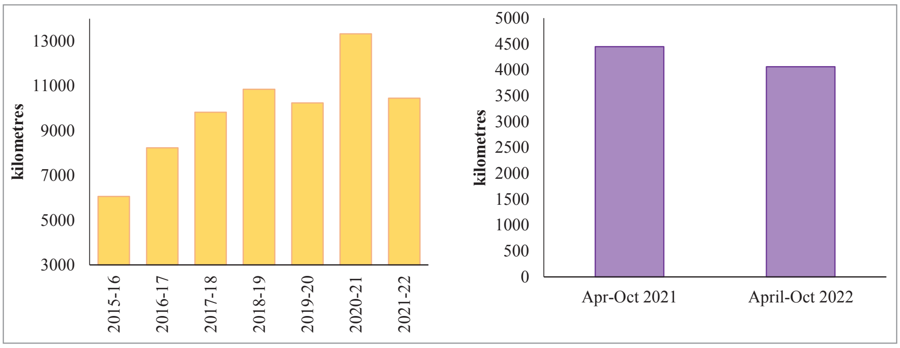

स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

चित्र XII.6: सड़क क्षेत्र में निवेश के लिए कुल बजटीय सहायता में भारी वृद्धि

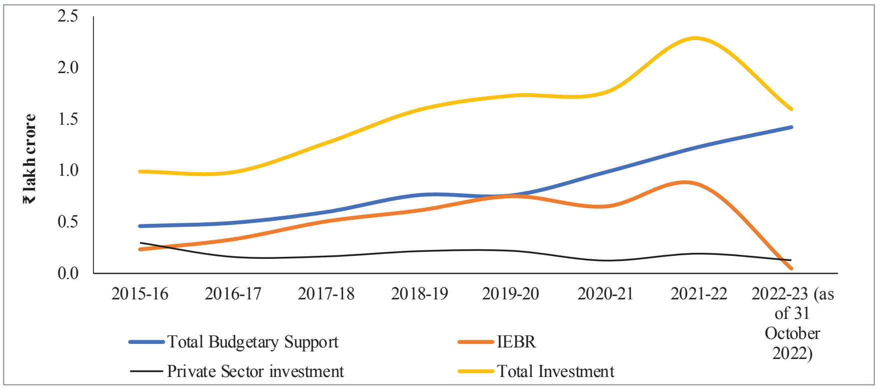

स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

रेलवे: विस्तार और आधुनिकीकरण, एक सतत प्रक्रिया

12.42 एक प्रमुख परिवहन अवसंरचना, जिसे बेहतर तरीके से भारत की जीवन रेखा कहा जा सकता है, और रेलवे राष्ट्रीय एकीकरण और क्षेत्रीय विकास में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए है। 68,031 मार्ग किमी से अधिक के साथ भारतीय रेलवे (आईआर) एकल प्रबंधन के तहत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। पूर्व-कोविड-19 अवधि (2019-20) के दौरान भारतीय रेल में यात्रियों की संख्या 809 करोड़ थी, लेकिन 2020-21 में यह घटकर 125 करोड़ हो गई। इसके बाद से यह 2021-22 में बढ़कर 351.9 करोड़ हो गयी है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, यात्रियों की संख्या में और अधिक वृद्धि देखी गई है, मूल यात्रियों की संख्या पहले से ही 418.4 करोड़ (नवंबर 2022 तक) हो रही है। देश भर में बढ़ी हुई गतिशीलता और तेज और प्रतिस्पर्धी ट्रेनों की मांग आने वाले वर्षों में यात्री यातायात में वृद्धि में सहायता करेगी।

12.43 राजस्व अर्जन के मामले में, कोविड-19 के झटके के बावजूद भारतीय रेल द्वारा माल यातायात को बनाए रखा गया। वित्त वर्ष 20-21 और वित्त वर्ष 21-22 के बीच, माल ढुलाई में तेज वृद्धि हुई, जो घरेलू अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में मजबूत पुनरुद्धार को दर्शाता है। वित्त वर्ष 22-23 (नवंबर 2022 तक) के दौरान, भारतीय रेलवे (आईआर) ने वित्त वर्ष 21-22 (केआरसीएल[11] को छोड़कर) में इसी अवधि के दौरान 901.7 मिलियन टन की तुलना में 976.8 मिलियन टन राजस्व अर्जित करने वाला माल यातायात (केआरसीएल को छोड़कर) किया, जिससे 8.3 प्रतिशत की वृद्धि में हुई है।

चित्र XII.7: कोविड-19 की अवधि के बाद रेलवे यात्री और माल यातायात में मजबूत वृद्धि देखी गई है

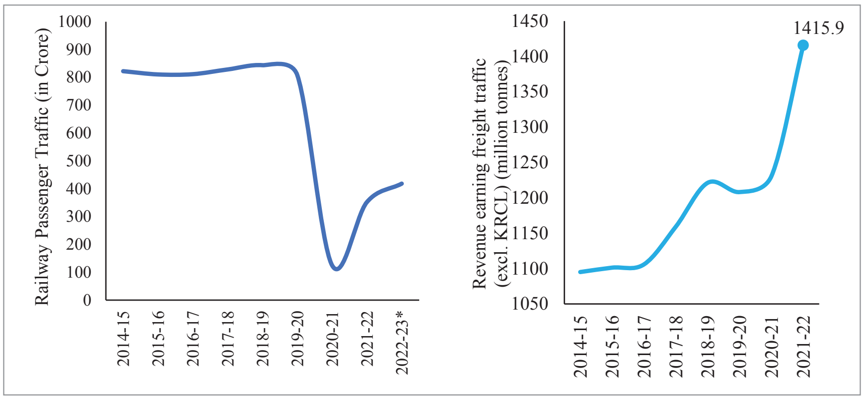

स्रोत: रेल मंत्रालय

नोट: * वित्त वर्ष 23 के लिए डेटा अप्रैल-नवंबर, 2022 तक का है

12.44 रेलवे में अवसंरचना पर पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को 2014 के बाद से जबरदस्त बढ़ावा मिला है। इसमें पिछले चार वर्षों में निरंतर वृद्धि देखी गई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 23 में 2.46 लाख करोड़ के कैपेक्स (ब.अ.) के साथ पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष (12 दिसंबर 2022 तक) के दौरान भारतीय रेल ने पहले ही 2022 पथ किलोमीटर (टीकेएम) पूरा कर लिया है जिसमें 109 टीकेएम नई लाइन, 102 टीकेएम गेज परिवर्तन और 1811 टीकेएम मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएं शामिल हैं। प्रगति की गति को समझने के लिए, यह उल्लेख किया जा सकता है कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यह आंकड़ा मार्च के पहले सप्ताह के दौरान ही पहुंचा था। वित्तीय वर्ष 2014-22 से, पूरे भारतीय रेल में, 20,628 किमी सेक्शन (3,970 किमी नई लाइन, 5,507 किमी गेज परिवर्तन और 11,151 किमी दोहरीकरण) को औसतन 2,579 किमी/वर्ष पर शुरु किया गया है, जो 2009-14 (1,520 किमी/वर्ष) के दौरान औसत शुरुआत से 70 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, पिछले आठ वर्षों (2014-22) के दौरान, पिछले आठ साल की अवधि के दौरान 4,698 आरकेएम के विद्युतीकरण की तुलना में 30,446 मार्ग किलोमीटर (आरकेएम) का विद्युतीकरण किया गया है, जो छह गुना से अधिक है।

तालिका XII.1: रेलवे पर अवसंरचना पूंजीगत व्यय में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है

विवरण	2009-14 के दौरान औसत	2014-19 के दौरान औसत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (ब.अ.)
				(₹ करोड़)		
एनएल, जीसी और दोहरीकरण	10,623	40,389	52,446	43,597	↑ 66,690	↑ 78,576
रोलिंग स्टॉक	16,029	20,878	37,339	32,627	↑ 41,406	↓ 39,853
रेलवे विद्युतीकरण	884	3,258	7,145	6,148	↑ 6,961	↑ 7,700
ट्रैक नवीनीकरण	4,958	7,186	9,391	13,523	↑ 14,082	↓ 13,335
आरओबी/आरयूबी	916	3,178	3,522	4,139	↑ 4,222	↑ 8,750
ब्रिज वर्क्स	351	488	782	772	↑ 1,297	↓ 940
अन्य योजना शीर्ष	12,219	23,801	37,440	54,375	↑ 55,609	↑ 96,646
कुल कैपेक्स	45,980	99,178	1,48,064	1,55,181	↑ 1,90,267	↑ 2,45,800

स्रोत: रेल मंत्रालय

नोट: एनएल: नई लाइनें, जीसी: गेज रूपांतरण

[11] केआरसीएल: कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

12.45 भारतीय रेल द्वारा अवसंरचना वृद्धि की तीव्र गति धन के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि और सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों का परिणाम है। इसमें क्षेत्र स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन शामिल है, जिसने दोहरीकरण परियोजनाओं को चालू करने, विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की प्रगति की करीबी निगरानी, राज्य सरकारों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव मंजूरी और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को शामिल किया है।

बॉक्स XII.2: भारतीय रेलवे की प्रमुख पहलें

✓ मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना (एमएएचएसआर): एमएएचएसआर परियोजना, जिसे 2015 में सरकार द्वारा जापान सरकार के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से स्वीकृत किया गया था, निष्पादन के अधीन है और सर्वेक्षण और डिजाइन के मुद्दों को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

✓ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर परियोजना (डीएफसी): रेलवे में सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में से एक, जिसमें दो समर्पित फ्रेट कॉरिडोर यानी स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ पूर्वी और पश्चिमी डीएफसी, का निर्माण शामिल है, जो कम पारगमन समय और लागत के साथ देश में उच्च परिवहन उत्पादन की पेशकश करेंगे।

✓ गतिशक्ति बहु-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी): उद्योगों की मांग और कार्गो यातायात की संभावना के आधार पर गैर-रेलवे भूमि के साथ-साथ पूरी तरह से/आंशिक रूप से रेलवे भूमि पर जीसीटी का विकास निजी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। 21 जीसीटी शुरु किए गए हैं और 90 से अधिक स्थानों को जीसीटी के विकास के लिए अनंतिम रूप से चिन्हित किया गया है (31 अक्टूबर 2022 तक)। इससे रेल कार्गो को संभालने के लिए अतिरिक्त टर्मिनलों के विकास में उद्योग से निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

✓ सेमी-हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेनसेट को शामिल करना: सेमी-हाई-स्पीड सेल्फ-प्रोपेल्ड वंदे भारत ट्रेनसेट का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई द्वारा स्वदेशी प्रयासों से किया गया था। इन ट्रेनों में अत्याधुनिक विशेषताएं हैं जैसे त्वरित त्वरण, यात्रा के समय में पर्याप्त कमी, 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति, ऑन-बोर्ड इंफोटेनमेंट और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित यात्री सूचना प्रणाली आदि।

✓ इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम: ट्रेन संचालन में सुरक्षा बढ़ाने के लिए बिंदुओं और संकेतों के केंद्रीकृत संचालन की परिकल्पना करता है। ये प्रणाली भारतीय रेलवे के 99 प्रतिशत स्टेशनों (30 सितंबर 2022 तक) को कवर करते हुए 6,322 स्टेशनों पर प्रदान किए गए हैं।

✓ हाइपरलूप तकनीक का विकास: हाइपरलूप एक उभरती हुई परिवहन तकनीक है जो हवाई जहाज और रेलवे की तुलना में तेज और हरित हो सकती है। इस प्रणाली में, वाहन उत्तोलन अवस्था (लीनियर इंडक्शन मोटर्स/इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की सहायता से) और निर्वात वातावरण में चलते हैं। तकनीक अभी भी विकास के चरण में है। भारतीय रेलवे हाइपरलूप प्रौद्योगिकी पर एक प्रदर्शनकारी परियोजना विकसित करने का इरादा रखता है। भारतीय रेल ने ₹8.34 करोड़ की लागत से आईआईटी मद्रास में हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करके हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के विकास के लिए आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग किया है।

✓ किसान रेल ट्रेनों को वित्त वर्ष 2021 में उत्पादन या अधिशेष क्षेत्रों से उपभोग या कमी वाले क्षेत्रों में जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की आवाजाही को सक्षम करने के लिए पेश किया गया था। 31 अक्टूबर 2022 तक, भारतीय रेलवे ने 2,359 किसान रेल सेवाओं का संचालन किया है, जिसमें फलों और सब्जियों सहित लगभग 7.91 लाख टन जल्दी खराब होने वाले सामानों का परिवहन किया गया है।

नागर विमाननः घरेलू मार्ग से पुनर्बहाली

12.46 कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और दुनिया भर में यात्रा प्रतिबंधों को हटाने के साथ, हवाई यात्रा फिर से शुरू हो गई है। जबकि वित्त वर्ष 21 में, हवाई-यातायात (54 प्रतिशत की गिरावट) के साथ-साथ यात्री यातायात (66 प्रतिशत की गिरावट) में काफी गिरावट आई थी, वित्त वर्ष 22 में रिकवरी देखी गई, जिसमें मुख्य भुमिका घरेलू क्षेत्र की थी। चालू वित्त वर्ष में यात्रियों और कार्गो दोनों की आवाजाही पूर्व-कोविड-19 स्तरों के करीब होने के साथ, फिर से वापसी हुई है। दिसम्बर 2022 में यात्रियों की कुल संख्या 150.1 लाख थी, जो पूर्व-कोविड स्तर का 106.4 प्रतिशत था (अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 तक 11 महीनों के लिए औसत) । नवम्बर 2022 के दौरान, कुल एयर कार्गो टन भार 2.5 लाख मीट्रिक टन था, जो कि पूर्व-कोविड स्तरों का 89 प्रतिशत है।

चित्र XII.8: भारतीय विमानन क्षेत्र का प्रदर्शन

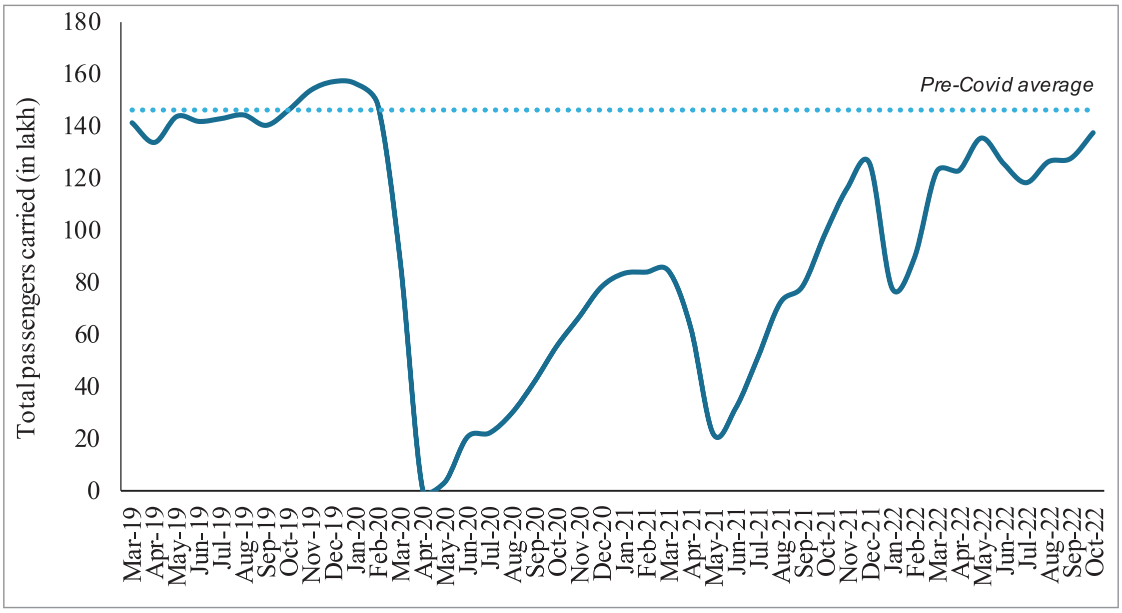

स्रोतः नागरिक उड्डयन मंत्रालय

12.47 भारत में नागर विमानन क्षेत्र में मध्यम वर्ग की बढ़ती मांग, जनसंख्या और पर्यटन में वृद्धि, उच्च प्रयोज्य आय, अनुकूल जनसांख्यिकी, और विमानन अवसंरचना की अधिक पैठ के कारण काफी संभावनाएं हैं। इसे सरकार द्वारा उड़ान, जिसने भारत के भीतरी इलाकों में हवाई अड्डों को खोलकर क्षेत्रीय संपर्क में काफी वृद्धि की है, जैसी स्कीमों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, सरकार ने राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सिविल एन्क्लेव के मौजूदा अप्रयुक्त/असेवित हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों के पुनरुद्धार के लिए ₹4500 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। सरकार ने देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी भी दे दी है। उड़ान योजना की शुरुआत से अब तक एक करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने इसका लाभ उठाया है। यह योजना देश में टियर-2 और 3 शहरों के बीच कनेक्टिविटी पर केंद्रित है और लाभार्थियों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी क्योंकि सेवा से वंचित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

बंदरगाहः शासकीय सुधारों के साथ उच्च क्षमता को संभालना

12.48 सदियों से, समुद्र अवसर का स्रोत रहा है और समुद्र तटों ने भारत के लिए समृद्धि के प्रवेश द्वार के रूप में काम किया है। बंदरगाहों का विकास अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, यह देखते हुए कि अधिकांश

अंतरराष्ट्रीय व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है (मात्रा के हिसाब से लगभग 90 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय व्यापार कार्गो और मूल्य के हिसाब से 79.9 प्रतिशत)। प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता, जो मार्च 2014 के अंत में 871.52 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) थी, मार्च 2022 के अंत तक बढ़कर 1534.9 एमटीपीए हो गई है। संचयी रूप से उन्होंने वित्त वर्ष 2022 के दौरान 720.1 एमटी यातायात को संभाला है।

12.49 लगातार बढ़ती व्यापार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सुविचारित अवसंरचना विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से बंदरगाह क्षमता के विस्तार को सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उनकी दक्षता को और बढ़ाने के लिए, सरकार पोर्ट गवर्नेंस में सुधार, कम क्षमता के उपयोग को दूर करने, तकनीकी कुशल लोडिंग/अनलोडिंग उपकरण के साथ बर्थ का आधुनिकीकरण करने और पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए नए चैनल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बंदरगाहों के अनुपालन को सुव्यवस्थित करने और जहाजों के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) को कम करने के लिए प्रमुख बंदरगाहों पर प्रमुख एक्जिम प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं। पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (पीसीएस 1एक्स) ने लैडिंग का इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बीएल) और लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) तैयार करने की प्रक्रियाओं के अलावा कस्टोडियन द्वारा कार्गो की भौतिक रिलीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान (ई-चालान), इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (ई-भुगतान) और इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑर्डर (ई-डीओ) जैसी प्रक्रियाओं को डिजिटलीकरण किया है। इसके अलावा, रेडियो ीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस (आरएफआईडी) सॉल्यूशन को सभी प्रमुख बंदरगाहों पर लागू किया गया है ताकि पोर्ट गेट्स पर यातायात के निर्बाध आवागमन को सक्षम किया जा सके, जिसमें प्रलेखन जांच में पर्याप्त कमी भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, पीसीएस 1x को राष्ट्रीय रसद पोर्टल-मरीन (एनएलपी-मरीन) में बूटस्ट्रैप करने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है जो सभी समुद्री हितधारकों के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगी।

अंतर्देशीय जल परिवहन: नौगम्य जलमार्गों की संभाव्यता का दोहन

12.50 अंतर्देशीय जल परिवहन में माल और यात्रियों के परिवहन के साधन के रूप में बड़ी अप्रयुक्त क्षमता है। भारत में नदियों, नहरों और अन्य जलमार्गों का विशाल भंडार है। भारत में जलमार्गों की कुल नौगम्य लंबाई लगभग 14,850 किलोमीटर है।

चित्र XII.9: विभिन्न राज्यों में जलमार्गों की नौगम्य लंबाई

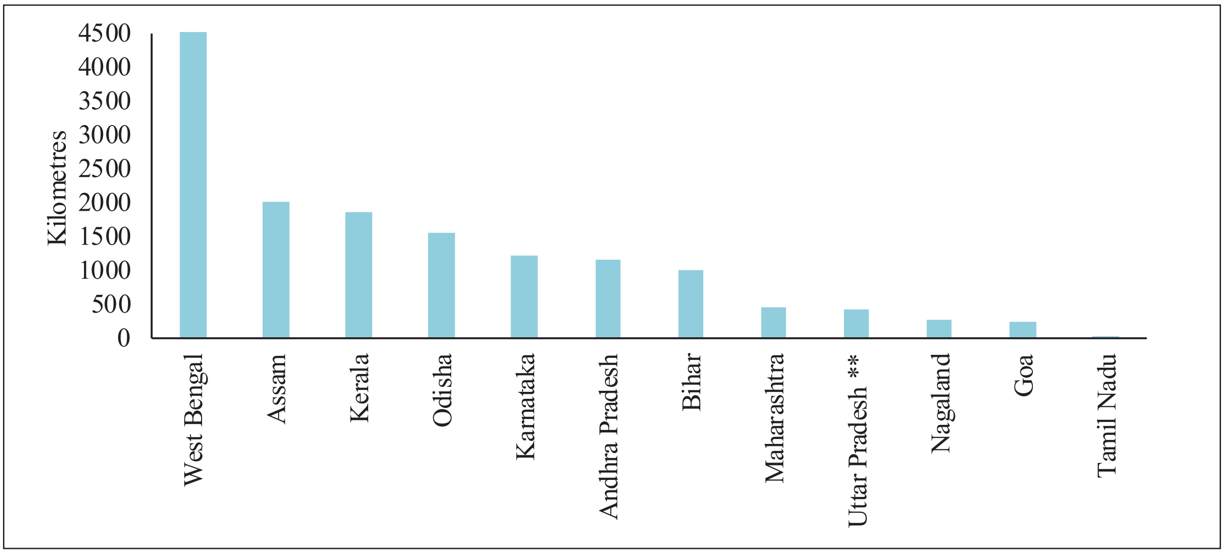

स्रोत: अंतर्देशीय जल परिवहन 2020-21 के आंकड़े, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय

नोट: डेटा 2020-21 से संबंधित है। ** उत्तर प्रदेश के आंकड़े 2016-17 से संबंधित हैं

12.51 राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत, 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) घोषित किया गया है, जिससे देश में एनडब्ल्यू की कुल संख्या 111 हो गई है। तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के परिणाम के आधार पर कार्गो आवाजाही के लिए व्यवहार्य 26 एनडब्ल्यूएस को प्राथमिकता दी गई है, जिनमें से 14 सबसे व्यवहार्य एनडब्ल्यूएस में विकासात्मक गतिविधियाँ शुरू की गई हैं। इसके अलावा, अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा एनडब्ल्यूएस पर जाने वाले जहाजों पर लगाए गए जलमार्ग उपयोग शुल्क को जुलाई 2020 में शुरू में तीन वर्ष की अवधि के लिए माफ कर दिया गया था। वित्त वर्ष 22 के दौरान राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो आवाजाही ने 108.8 मिलियन टन का सर्वकालिक उच्च स्तर हासिल किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।

12.52 अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021, जिसने 100 साल से अधिक पुराने अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 (1917 का अधिनियम सं.1) को प्रतिस्थापित किया, अगस्त 2021 में संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के लिए एक नए युग की शुरूआत करेगा और विधायी ढांचे को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए बहु-मॉडल परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता का उपयोग करने की परिकल्पना को पूरा करेगा। नियमों और विनियमों का एक समान अनुप्रयोग अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करके अंतर्देशीय जहाजों द्वारा निर्बाध, त्वरित और लागत प्रभावी व्यापार और परिवहन सुनिश्चित करेगा। नीचे दिए गए बॉक्स में दिए गए विवरण के अनुसार इस अधिनियम की विभिन्न ध राएं 2022 में लागू हो गई हैं।

बॉक्स XII.3: अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021

1917 के अंतर्देशीय वेसल्स अधिनियम, जिसमें कई संशोधन हुए थे, में विभिन्न राज्यों में यांत्रिक रूप से चलने वाले जहाजों और गैर-समान मानकों और विनियमों के प्रतिबंधात्मक आवागमन के प्रावधान थे। अंतर्देशीय जलमार्ग अधि नियम 2021, जिसने पूर्ववर्ती अधिनियम की जगह ली, का उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों और देश के भीतर नेविगेशन से संबंधित कानून को लागू करने में एकरूपता लाना है। अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- ✓ राज्य सरकारें अधिनियम में निर्धारित अधिकतम महत्वपूर्ण लहर ऊंचाई मानदंड के आधार पर अधिसूचना द्वारा किसी भी अंतर्देशीय जल क्षेत्र को "क्षेत्र" के रूप में घोषित कर सकती हैं। किसी भी यंत्रचालित जहाज को एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जो उस क्षेत्र को इंगित करेगा जिसमें जहाज को संचालित किया जाना है।
- ✓ अंतर्देशीय जहाजों का एक केंद्रीय डेटाबेस का अनुरक्षण सरकार द्वारा किया जाएगा।
- ✓ योग्यता, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान, परीक्षा और योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के मानक केंद्र सरकार द्वारा निध र्रित किए जाएंगे।
- ✓ पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए मानक।
- ✓ राज्य सरकार द्वारा एक विकास कोष का गठन, जिसका उपयोग आपातकालीन तैयारी, प्रदूषण की रोकथाम, अज्ञात मलबे या बाधा को हटाने, अंतर्देशीय जल नेविगेशन के विकास कार्यों को बढ़ावा देने आदि के लिए किया जाएगा।

कुल मिलाकर, नया अधिनियम राज्यों के भीतर और राज्यों के बीच जहाजों की निर्बाध और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने वाले नियमों की एकरूपता को बढ़ावा देगा। यह अंतर्देशीय जल परिवहन को देश भर में बड़े पैमाने पर कार्गो के साथ-साथ यात्रियों के आवागमन के लिए एक संभावित साधन के रूप में बढ़ावा देने की संभावना है क्योंकि इसकी सापेक्ष लागत प्रभावशीलता है।

बिजली: अक्षय श्रोतों से प्रेरित संख्यापित क्षमता बढ़त

12.53 1 मेगावाट (एमडब्ल्यू) और उससे अधिक की मांग वाले उपयोगिताओं और कैप्टिव बिजली संयंत्रों उद्योग की कुल स्थापित बिजली क्षमता 31 मार्च, 2022 को 482.2 जीडब्ल्यू थी, जबकि 31 मार्च, 2021 को 460.7 जीडब्ल्यू की तुलना में 4.7 प्रतिशत अधिक थी। उपयोगिताओं में स्थापित क्षमता 31 मार्च, 2022 को 399.50 जीडब्ल्यू थी, जबकि एक साल पहले यह 382.1 जीडब्ल्यू थी (4.5 प्रतिशत अधिक)। उपयोगिताओं में कुल स्थापित क्षमता का सबसे बड़ा हिस्सा (59.10 प्रतिशत) ऊर्जा के थर्मल स्रोत हैं, इसके बाद अक्षय ऊर्जा संसाधनों का 27.51 प्रतिशत और हाइड्रो का 11.70 प्रतिशत हिस्सा है।

तालिका XII.2: अखिल भारतीय स्थापित क्षमता मोड-वार (जीडब्ल्यू)

	हाइड्रो	थर्मल	न्यूक्लीयर	नवीकरणीय	कुल
2020-21	46.3	307.4	6.8	100.1	460.7
2021-22@	46.9	312.2	6.8	116.4	482.2
वृद्धि (प्रतिशत में)	1.1	1.6	0	16.2	4.7

स्रोत: ऊर्जा मंत्रालय
नोट: @ अनुमानित

12.54 वित्त वर्ष 21 के दौरान 15.9 लाख जीडब्ल्यूएच की तुलना में वित्त वर्ष 22 के दौरान कैप्टिव संयंत्रों से उत्पन्न कुल बिजली, 17.2 लाख जीडब्ल्यूएच थी, जिसमें से 14.8 लाख जीडब्ल्यूएच उपयोगिताओं द्वारा और 2.3 लाख जीडब्ल्यूएच कैप्टिव द्वारा उत्पन्न की गई थी। वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 21 के बीच, बिजली उत्पादन में अधिकतम वृद्धि उपयोगिताओं और कैप्टिव संयंत्रों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में दर्ज की गई थी। भारत के ऊर्जा क्षेत्र में पारंपरिक स्रोतों से गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों में धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ है। भारत गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं पर अडिग है। भारत ने 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50 प्रतिशत संचयी विद्युत ऊर्जा की संस्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखा है। भारत तेजी से बढ़ रही समग्र संस्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी के साथ अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की ओर अग्रसर है। यह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी पहलों का परिणाम है।

तालिका XII.3: अखिल भारतीय सकल विद्युत उत्पादन मोड-वार

	हाइड्रो	थर्मल	न्यूक्लीयर	नवीकरणीय	कुल
2020-21	1.5	12.5	0.4	1.5	15.9
2021-22@	1.5	13.4	0.4	1.7	17.2
वृद्धि (प्रतिशत में)	0.9	7.3	9.5	16.2	7.6

स्रोत : विद्युत मंत्रालय
नोट: @ अनुमानित

12.55 भारत सरकार ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा पहुंच प्राप्त करने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से एक सक्रिय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम चला रही है। कृषि क्षेत्र के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) का उद्देश्य ऊर्जा

और जल सुरक्षा प्रदान करना, कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करना और सौर ऊर्जा का उत्पादन करके किसानों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करना है। इसके अलावा, सरकार ने सभी वैधानिक मंजूरी के साथ-साथ भूमि, ऊर्जा निकासी सुविधाओं, सड़क संपर्क, पानी की सुविधा आदि जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाए प्रदान करने के लिए सोलर पार्क योजना शुरू की है। 30 सितंबर 2022 तक, सरकार ने 16 राज्यों में 59 सौर पार्कों के विकास के लिए 40 जीडब्ल्यू की संपूर्ण लक्ष्य क्षमता को मंजूरी दे दी है।

12.56 भारतीय रेलवे, जो देश में बिजली का एक प्रमुख उपयोगकर्ता है, ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के अपने इरादे की घोषणा की है। इस संबंध में, भारतीय रेलवे ने नवीकरणीय स्रोतों के अधिक उपयोग की ओर अपनी ऊर्जा मांग को फिर से उन्मुख किया है। नवंबर 2022 तक, लगभग 143 मेगा वाट के सौर संयंत्र (छतों और जमीन दोनों पर) और लगभग 103 मेगावाट पवन विद्युत उत्पादन करने वाले संयंत्र चालू किए जा चुके हैं।

12.57 नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए अन्य महत्वपूर्ण प्रोत्साहनों में गैर-सौर नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के भीतर जलविद्युत खरीद दायित्व (एचपीओ) शामिल हैं। सरकार के सहयोग से, निजी क्षेत्र ने समग्र उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और एक अल्प अवधि में इकाई लागत को कम करने में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

डिजिटल अवसंरचना में विकास

12.58 हालांकि पारंपरिक अवसंरचना की भूमिका की पहचान अच्छी तरह से की गई है, हाल के वर्षों में, देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए डिजिटल अवसंरचना की भूमिका काफी बढ़ी है। यह विशेष रूप से कोविड-19 की अवधि के दौरान ऐसा सच था जब वास्तविक बातचीत में कमी के कारण सेवा वितरण और दूरस्थ कार्य के लिए पहले से उपलब्ध डिजिटल अवसंरचना का उपयोग आवश्यक हो गया था। आने वाले वर्षों में, डिजिटल अवसंरचना की उपलब्धता और प्रसार आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसे स्वीकार करते हुए, सरकार का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है, प्रत्येक नागरिक के लिए एक प्रमुख उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना की कल्पना करता है। मुख्य क्षेत्रों में नागरिकों को सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए मुख्य उपयोगिता के रूप में हाई-स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता, यूनिक डिजिटल पहचान, डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में नागरिक भागीदारी को सक्षम करना, सार्वजनिक क्लाउड (नागरिक अपने दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों आदि को डिजिटल रूप से स्टोर कर सकते हैं और उन्हें भौतिक रूप से जमा किए बिना सार्वजनिक एजेंसियों या अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं) पर साझा करने योग्य निजी स्थान और एक सुरक्षित साइबर स्पेस शामिल हैं। डिजिटल अवसंरचना क्षेत्र में कुछ विकास गतिविधियाँ नीचे विस्तृत रूप में दी गई हैं।

दूरसंचार: किफायती सेवओं का प्रावधान

12.59 तकनीकी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार द्वारा किए गए लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप, दूरसंचार सेवाओं ने देश के दूरस्थ कोनों में उपस्थिति दर्ज कराई है। देश उन दिनों से काफी आगे आ चुका है जब एक टेलीफोन कनेक्शन को एक विलासिता के रूप में देखा जाता था और वर्तमान में अधिकांश लोगों के पास मोबाइल कनेक्शन मौजूद है। यह टेलीकॉम कंपनियों, जिन्होंने अपने नेटवर्क बैंडविड्थ को बढ़ाया, सरकार के समर्थकारी वातावरण और स्मार्टफोन के लिए उपभोक्ता की पहुंच के संचयी प्रयास के कारण हुआ था। आज, भारत में कुल टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 117 करोड़ (नवंबर 2022 तक) है। जबकि कुल ग्राहकों में से 97 प्रतिशत से अधिक वायरलेस तरीके से जुड़े हुए हैं (नवंबर 2022 के अंत में 114.3 करोड़) और जून 2022

की स्थिति के अनुसार 83.7 करोड़ ग्राहकों के पास इंटरनेट कनेक्शन हैं। भारत में कुल टेली-घनत्व राज्यों में व्यापक अंतर सहित 84.8 प्रतिशत है। यह बिहार में 55.44 प्रतिशत से लेकर दिल्ली में 270.62 प्रतिशत तक है। आठ लाइसेंस सेवा क्षेत्रों, नामत: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक में टेली-घनत्व 100 प्रतिशत से अधिक था।

चित्र XII.10: लाइसेंस सेवा क्षेत्र-वार समग्र टेली घनत्व

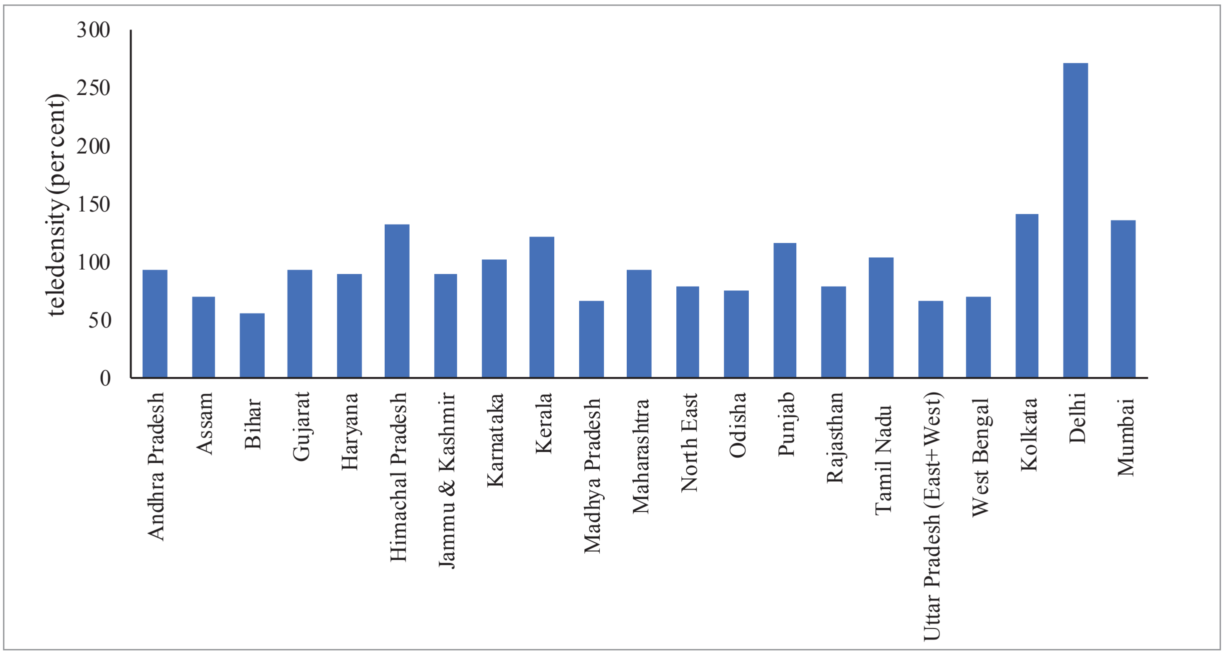

स्रोत: दूरसंचार विभाग

12.60 टेली-घनत्व में अंतरराज्यीय असमानता के अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में टेली-घनत्व शहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम स्तर पर बना हुआ है। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ उत्साहजनक है क्योंकि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (अधिकांश राज्यों के लिए) में इंटरनेट ग्राहकों में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन अधिक है। इसने कोविड-19 के शुरुआती चरण के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक मजबूती प्रदान की, क्योंकि बहुत से लोग आजीविका के लिए ग्रामीण भारत वापस चले गए। वर्षों से बनाए गए डिजिटल अवसंरचना ने न केवल सूचना के निरंतर प्रसारण को सुनिश्चित किया बल्कि व्यवसायों के डिजिटल होने पर आर्थिक वृद्धि भी हुई।

बॉक्स XII.4: ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को कम करना

संकट को अवसर में परिवर्तित करते हुए, भारत अपने लचीले उपायों के माध्यम से कई क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से महामारी के प्रभाव को रोकने में सक्षम रहा है, दूरसंचार उनमें से एक है। कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान, दूरसंचार क्षेत्र ने 'वर्क फ्रॉम होम', 'स्टडी फ्रॉम होम' आदि जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों और सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना जारी रखा। यह किफायती स्मार्टफोन में महत्वपूर्ण वृद्धि द्वारा संभव हो पाया, जो एक संचार उपकरण से अधिक बन गया। यह डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस, ई-कॉमर्स, ई-स्वास्थ्य और ई-शिक्षा जैसी विभिन्न नई सेवाओं और अनुप्रयोगों के साथ डिजिटल इंडिया पहल के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में उभरा है। बैकबोन के रूप में कार्य करते हुए, इन सेवाओं ने देश के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है।

2014 से पहले, डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को शहरी परिवारों का विशेषाधिकार माना जाता था। यह 2014 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 44.01 और 145.46 होने के कारण टेली घनत्व (प्रति 100 निवासियों पर ग्राहकों की संख्या) से देखे गए डिजिटल असमानता द्वारा प्रमाणित किया गया था। हालाँकि, प्रत्येक नागरिक के लिए एक प्रमुख उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना को विकसित करने की दृष्टि से, डिजिटल इंडिया को एक अम्ब्रेला कार्यक्रम के रूप में 2015 में शुरू किया गया था। डिजिटल उपकरणों के माध्यम से सेवा सुपुर्दगी तब से एक लंबी यात्रा तय कर चुका है। हमने पिछले 3 वर्षों (2019-21) में ग्रामीण क्षेत्रों में उनके शहरी समकक्षों (क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 92.81 मिलियन की तुलना में 95.76 मिलियन) अधिक इंटरनेट ग्राहक जोड़े हैं। यह फ्लैगशिप भारतनेट प्रोजेक्ट स्कीम, टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम, समग्रता के माध्यम से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पहलों व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी) और वामपंथ नक्सलवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए पहल आदि जैसी महत्वाकांक्षी सरकारी स्कीमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में समर्पित डिजिटल अभियानों का परिणाम है।

चित्र: इंटरनेट सब्सक्राइबरों में शहरी विकास (प्रतिशत) की तुलना में एलएसए वार ग्रामीण विकास (प्रतिशत) में अंतर

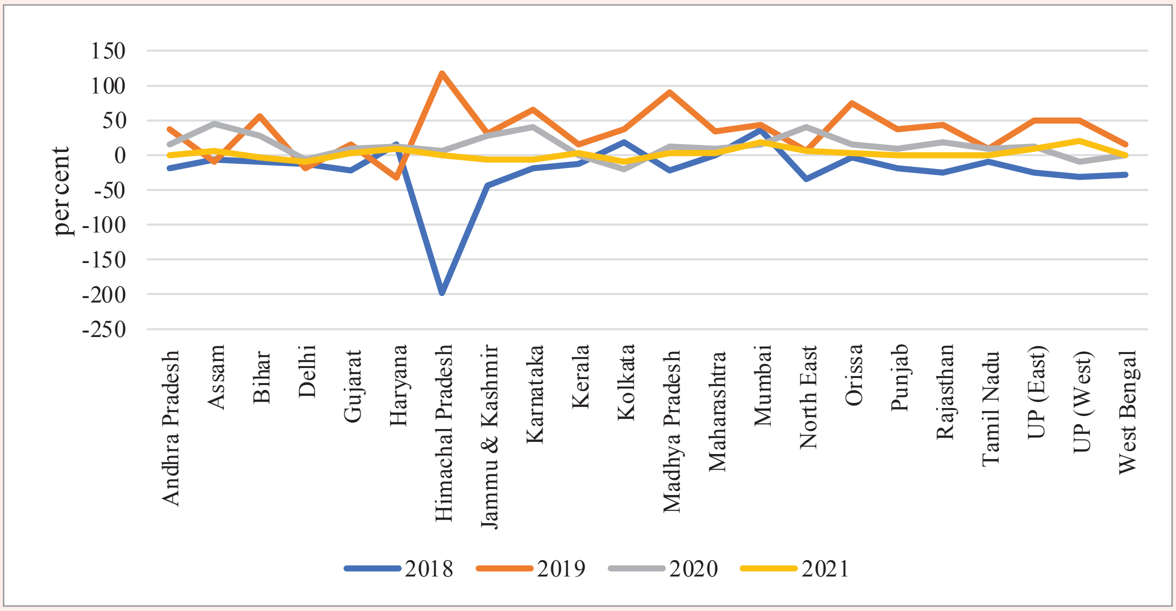

ग्रामीण और शहरी इंटरनेट पैठ के बीच की खाई को पाटने पर इस ठोस ध्यान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट ग्राहकों की वृद्धि दर (प्रतिशत) में अंतर की साजिश राज्यों और वर्षों में कुछ हद तक अस्थिर है। 2018 में एक नकारात्मक अंतर[12] से 2019 में सकारात्मक क्षेत्र (अधिकांश राज्यों के लिए) में 50 प्रतिशत से ऊपर का परिवर्तन डिजिटल सेवाओं में मांग पक्ष की वृद्धि को दर्शाता है, जो बजट स्मार्टफोन की उपलब्धता और किफायती डेटा उपयोग द्वारा समर्थित था। उस समय से अंतर तब तक सकारात्मक रहा है।

ग्रामीण भारत में यह महत्वपूर्ण वृद्धि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रमुख आघात अवशोषक थी जब व्यवसाय और उपभोक्ता मांग दोनों प्रभावित हुए थे। जब अधिकांश कार्यबल आजीविका की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों में वापस चले गए, तो कृषि (वित्त वर्ष 20-21 में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि) के साथ-साथ दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना

12 ग्रामीण अभिदानों में प्रतिशत परिवर्तन - शहरी अभिदानों में प्रतिशत परिवर्तन।

मनरेगा ने घरेलू अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से बनाए गए डिजिटल अवसंरचना ने लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में पारदर्शी और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया और इस प्रकार वायरस के संपर्क में आने को सीमित कर दिया। निजी शिक्षा तक सीमित पहुंच और सामर्थ्य के साथ, सरकारी स्कूलों में डिजिटल समर्थन प्रणाली ने सीखने के अंतर को दूर करने के लिए उस समय के बहुत जरूरी नामांकन को अवशोषित कर लिया। चूंकि स्कूली शिक्षा महामारी के बाद भी काफी समय तक ऑनलाइन रही, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सब्सक्रिप्शन में वृद्धिशील बदलाव ने सीखने के नुकसान को काफी हद तक कम करने में मदद की। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक टीकाकरण के सफल रोलआउट की सुविधा भी प्रदान की।

2015 और 2021 के बीच शहरी क्षेत्रों में 158 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण इंटरनेट सदस्यता में 200 प्रतिशत की वृद्धि, सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी डिजिटल कनेक्टिविटी को समान स्तर पर लाने के लिए बढ़ाए गए प्रोत्साहन को दर्शाती है। संभावनाओं को अधिक बढ़ाने के लिए, असंबद्ध क्षेत्रों और आबादी को शामिल करने के लिए, सरकार द्वारा समर्पित दीर्घकालिक प्रयास किए गए हैं। दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) जैसी सरकारी योजनाएं घरेलू मोबाइल विनिर्माण के साथ-साथ नेटवर्क स्थापना को बढ़ावा देंगी। भारत नेट प्रोजेक्ट जैसे उपायों के निरंतर प्रसार से पूरे भारत में पहुंच, सामर्थ्य, कनेक्टिविटी और समावेशिता में सुधार जारी रहेगा। बदले में यह हमारे माननीय प्रधान मंत्री के हर भारतीय को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगा, जैसे हम भारत के 'टेक एड' की ओर अग्रसर हैं।

12.61 हमारे जमीनी स्तर पर डिजिटल लिंकेज बनाने और शहरी केंद्रों की तरह उपभोक्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए, देश भर के वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में 24,680 वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करेगी, और केवल 2जी/3जी कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को 4जी में उन्नयन किया जाएगा।

12.62 पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ, सरकार एक व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी) लागू कर रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए सीटीडीपी के तहत, वंचित गांवों के साथ असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश (केवल राष्ट्रीय राजमार्ग) के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2004 टावर स्थापित करके टू जी मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है। 25 अक्टूबर 2021 तक 1,358 टावर लगाए जा चुके हैं और वे कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों (कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ) में शामिल नहीं किए गए गांवों को फोर जी मोबाइल कवरेज प्रदान करने की अन्य परियोजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा, देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में उच्च-गुणवत्ता और उच्च गति की इंटरनेट पहुंच उपलब्ध कराने के लिए, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) ने बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी लिमिटेड (बीएससीसीएल), बांग्लादेश से अगरतला के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 10 जीबीपीएस अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ को किराये पर लेने के लिए 18 अगस्त, 2021 को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। पहला 10 जीबीपीएस लिंक 26 नवंबर, 2021 को और दूसरा 10 जीबीपीएस लिंक 21 अप्रैल, 2022 को शुरू किया गया था।

12.63 जब दूरसंचार समुद्र तटों, जंगलों और यहां तक कि रेगिस्तानों में भी फैल रहा है तो द्वीपों को पीछे क्यों छोड़ा जाए? द्वीपों के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना की सरकार की पहल के माध्यम से हमारे द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए एक व्यापक पहल की गई है। पोर्ट ब्लेयर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सात अन्य द्वीपों को चेन्नई से 2313 किमी पानी के भीतर ओएफसी के माध्यम से जोड़ने के लिए चेन्नई से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (सीएएनआई) परियोजना के लिए पनडुब्बी ओएफसी कनेक्टिविटी शुरू की

गई थी। 2.7 जीबीपीएस से 75.7 जीबीपीएस तक, लगभग 30 गुना बैंडविड्थ उपयोग का अत्यधिक प्रसार हुआ है। इस परियोजना के कारण 100 एमबीपीएस की एफटीटीएच स्पीड हुई है, और अब 15 गुना अधिक डेटा मात्रा उपलब्ध है। कोच्चि से लक्षद्वीप द्वीप समूह (केएलआई) परियोजना के लिए पनडुब्बी ओएफसी कनेक्टिविटी को कोच्चि को कवरत्ती और लक्षद्वीप के दस अन्य द्वीपों के साथ 1869 किलोमीटर पानी के भीतर ओएफसी परियोजना के माध्यम से जोड़ने के लिए शुरू किया गया था, और इस परियोजना के मई 2023 तक पूरा होने की संभावना है। यह परियोजना वर्तमान में चल रही है और यह द्वीपों में डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करेगी और कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन की उम्मीद है।

12.64 भारत में दूरसंचार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि 5 जी सेवाओं की शुरुआत थी। उच्च डेटा स्थानांतरण गति और कम विलंबता के माध्यम से 5जी उपभोक्ताओं को सीधे प्रभावित कर सकता है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा विकसित 5 जी उपयोग मामले और शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रमिक सुरक्षा, स्मार्ट कृषि आदि में स्टार्ट-अप अब पूरे देश में लगाए जा रहे हैं। दूरसंचार सुधारों और स्पष्ट नीति निर्देश के कारण 2022 की स्पेक्ट्रम नीलामी ने अब तक की सबसे अधिक बोलियां प्राप्त की।

12.65 एक प्रमुख सुधार उपाय के रूप में, भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2022, 5 जी शुरु करने को सक्षम बनाने के लिए टेलीग्राफ अवसंरचना की तेज और आसान स्थापना की सुविधा प्रदान करेगा। सरकार ने नवाचार, विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आवृत्ति बैंडों को लाइसेंस मुक्त करने सहित वायरलेस लाइसेंसिंग पर प्रक्रियात्मक सुधार किए हैं। नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान 2022 (एनएफएपी) एक व्यापक नियामक ढांचा प्रदान करता है, जो यह पहचानता है कि सेलुलर मोबाइल सेवाओं, वाई-फाई, ध्वनि और टेलीविजन प्रसारण, विमान और जहाजों के लिए रेडियो नेविगेशन और अन्य वायरलेस संचार के लिए कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड उपलब्ध हैं। एनएफएपी स्पेक्ट्रम के उपयोगकर्ताओं को प्रासंगिक आवृत्ति और उसमें प्रदान किए गए मापदंडों के अनुसार अपने नेटवर्क की योजना बनाने के लिए मार्गदर्शन देगा। यह देखते हुए कि स्पेक्ट्रम एक दुर्लभ संसाधन है, एनएफएपी प्रभावी तरीके से उभरती प्रौद्योगिकियों की मांगों के साथ स्पेक्ट्रम उपयोग को संरेखित करने में उपयोगी है।

12.66 विकास को बढ़ावा देने और उपग्रह आधारित सेवाओं के तेजी से उभरते क्षेत्र में नागरिकों के लिए सस्ती सेवाओं के प्रावधान में तेजी लाने के लिए, उपग्रह आधारित संचार सेवाओं के विभिन्न चरणों में शुल्कों की बहुलता को सीमित करके व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए सुधार किए गए हैं। मौजूदा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए, उपग्रह संबंधी मंजूरी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए हैं।

12.67 देश भर, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, में ब्रॉडबैंड सेवाओं की सार्वभौमिक और समान पहुंच, राष्ट्रीय डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए सरकार के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे साकार करने के लिए, 14 मई, 2022 को गतिशक्ति संचार पोर्टल शुरु किया गया था। यह पोर्टल देश भर में राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) आवेदनों और अनुमतियों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा। पोर्टल को मुख्य रूप से राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के दृष्टि क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, जो मांग पर शासन और सेवाएं और विशेष रूप से, हमारे देश के नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण एवं प्रत्येक नागरिक को मुख्य उपयोगिता के रूप में ब्रॉडबैंड अवसंरचना प्रदान कर रहे हैं।

12.68 अब, टेलीकॉम के बारे में विस्तार से चर्चा करने के बाद, अगली डिजिटल कहानी जो हमारे कानों में गूँजती है, वह रेडियो है जो देश के सभी नागरिकों तक पहुँचने का सबसे अच्छा माध्यम रहा है।

बॉक्स XII.5: रेडियो - वे तरंगें जो जोड़ा था...!!

आज के तेजी से बढ़ते सोशल मीडिया युग में, यह स्मरणीय है कि मास मीडिया के घटकों में से एक, अर्थात् रेडियो न केवल महामारी और उसके बाद के समय में पहुंच के लिए बांध के रूप में कायम रहा, बल्कि इस तेजी से विकसित होने वाले डिजिटल युग में भी बहुतों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई। रेडियो भारत में जनसंचार का सबसे सस्ता और लोकप्रिय माध्यम बना हुआ है और एक ऐसा साधन रहा है जिसने हमारे देश के लोगों के सशक्तिकरण और सामाजिक विकास में लगातार मदद की है। पहुंच, व्यापक कवरेज, कार्यक्रमों की विविधता, गतिशीलता और स्थानीय भाषा इसकी लोकप्रियता के कारण बने रहे हैं। उदाहरण के लिए, लोकप्रिय 'मन की बात' कार्यक्रम, जहां प्रधानमंत्री दिन-प्रतिदिन शासन के मुद्दों पर नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करते हैं, 25 दिसंबर 2022 को 96वीं कड़ी को पूरा करने के साथ मील का पत्थर साबित हुआ, और इस वर्ष भी कार्यक्रम होने वाले हैं।

प्रतिष्ठित पंक्ति ''यह ऑल इंडिया रेडियो है। ...द्वारा पढ़ी गई खबर'' हमारे कानों में गूंजती है क्योंकि हम याद करते हैं कि कैसे प्रसार भारती, भारत का स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारक, न केवल देश के इतिहास और ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है, बल्कि यह सभी देश भर के नागरिकों, के लिए कहानी कहने वाला भी रहा है। इसके आदर्श वाक्य 'बहुजन हिताय: बहुजन सुखाय' हैं, जिसका अर्थ है 'बहुतों की खुशी के लिए, बहुतों के कल्याण के लिए'। यह देश भर के 479 स्टेशनों से 23 भाषाओं, 179 बोलियों में प्रसारित होता है, जो क्षेत्र के लगभग 92 प्रतिशत और देश की कुल आबादी के 99.2 प्रतिशत तक पहुंचता है। प्रसार भारती ने 23 नवंबर 2022 को अपनी रजत जयंती मनाई, और यह उल्लेखनीय है कि इसने प्रौद्योगिकी को कैसे अपनाया है, यह इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि ऑल इंडिया रेडियो की 240 से अधिक रेडियो सेवाएं प्रसार भारती के आधिकारिक ऐप, न्यूजऑनएयर ऐप पर लाइव-स्ट्रीम की जाती हैं। इन स्ट्रीम्स के न केवल भारत में, बल्कि विश्व स्तर पर, दुनिया भर के 85 से अधिक देशों में बड़ी संख्या में श्रोता हैं।

सार्वजनिक प्रसारक के साथ, निजी वाणिज्यिक रेडियो स्टेशन (एफएम रेडियो) और सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस), प्रत्येक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए मंच के रूप में कार्य करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में एफएम रेडियो फला-फूला है, जैसा कि एक निजी एफएम रेडियो स्टेशनों में तिमाही वृद्धि में देखी गयी है, उनकी संख्या दिसंबर 2015 को समाप्त तिमाही में 243 से बढ़कर जून 2022[13] को समाप्त तिमाही में 388 हो गई है।

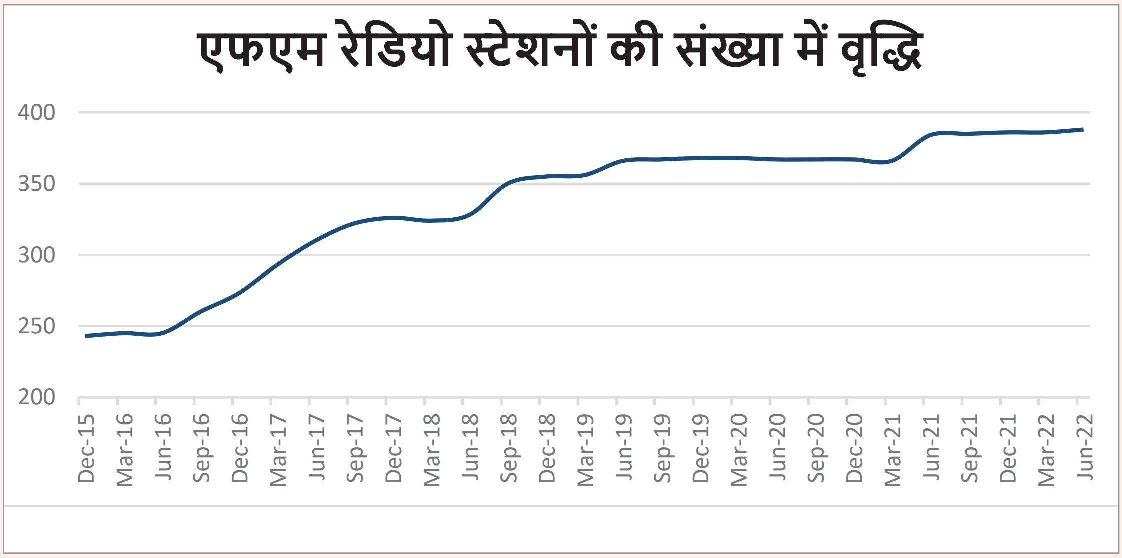

एफएम रेडियो स्टेशनों की बढ़ती संख्या दर्शाती है कि कैसे जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो ने सार्वजनिक सेवा के अपने जनादेश को संतोषजनक ढंग से पूरा किया और महामारी के समय में लोगों के साथ मजबूती से खड़ा रहा। जहां एफएम ने दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों तक अपनी पहुंच बढ़ाई, वहीं सीआरएस ने स्थानीय और अच्छी तरह से परिभाषित समुदायों को लक्षित किया। महामारी पर जागरूकता फैलाने का चुनौतीपूर्ण कार्य और वह भी असंख्य बोलियों के साथ स्थानीय भाषा में संभव हुआ, क्योंकि सीआरएस सामुदायिक भागीदारी के रूप में शामिल था। ऐसे समय में जब देश के दूर-दराज कोने तक केंद्रीकृत मीडिया की पहुंच को आसान करना एक विशाल कार्य था। ये रेडियो तरंगें बड़े सार्वजनिक कारण के लिए बिना किसी रुकावट के यात्रा करती थीं। वे न केवल सूचना के प्रचार प्रसार के लिए एक माध्यम बनी बल्कि सशक्तिकरण के लिए एक चैनल के रूप में भी कार्यशील रहे क्योंकि आसानी शिक्षा ने भी रेडियो का सहारा लिया।

इसके साथ, हम रेडियो को अच्छे और कठिन समय में पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण होते हुए देखते हैं। जैसा कि हम नए सामान्य हालात में काम करते हैं और जैसे-जैसे चीजें समय के साथ व्यवस्थित होती हैं, मैनुअल ट्यूनिंग के ये छोटे बक्से फिर से कुछ निचले अलमारी में अपना स्थान पा सकते हैं। हालांकि, उनकी पहचान बरकरार रहेगी। यह एक बार फिर अपने लिए प्रतिष्ठित पंक्ति "यह ऑल इंडिया रेडियो है। ...द्वारा पढ़ी गई खबर"।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विकास की कहानी

12.69 वित्तीय साक्षरता, नवाचार, उद्यमशीलता, रोजगार सृजन और लाभार्थियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के उद्भव ने अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने और इसे उस स्थिति में लाने में जहां यह आज खड़ा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2009 से, जब आधार पहली बार लोकार्पण किया गया था, डीपीआई की यात्रा उल्लेखनीय रूप से यादगार रही है। अब चौदह वर्ष हो गए हैं, और तब से डिजिटल यात्रा बहुत आगे बढ़ गई है। डीपीआई वृद्धि के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने वाले तीन विकास चालक अनुकूल जनसांख्यिकी, मध्यवर्ग का व्यापक विस्तार और डिजिटल व्यवहार पैटर्न थे। इन विकास चालकों का लाभ उठाकर, भारत ने एक प्रतिस्पर्धी डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है जो प्रत्येक व्यक्ति और व्यवसाय को कागज रहित और नगदी रहित लेनदेन करने के लिए सशक्त बनाता है।

12.70 आधार के साथ कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान की पुष्टि करने के लिए प्रमाणीकरण ढांचा स्थापित करने के साथ, अगला तार्किक कदम प्रमुख सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना था। हालांकि, मौजूदा योजनाओं के बारे में ज्ञान की कमी को लाभार्थियों की योजना के लाभों तक पहुंचने में असमर्थता के पीछे प्राथमिक कारण के रूप में देखा गया था। 'माई स्कीम' योजनाओं के लिए एक ई-मार्केटप्लेस है जहां उपयोगकर्ता अपनी पात्रता के आधार पर उपयुक्त स्कीमों का उपयोग कर सकते हैं। यह सरकारी विभागों की कई वेबसाइटों को खोजने और उनकी पात्रता की जांच करने के लिए कई योजना दिशानिर्देशों का अध्ययन करने की आवश्यकता को दूर करके उपयोगकर्ताओं के समय और प्रयास को कम करने में मदद करता है। यह योजना किसी भी सरकारी योजना को शुरू करने के लिए एकल राष्ट्रीय मंच के रूप में भी कार्य करती है। दिनांक 16 जनवरी 2023 तक 14 विविध श्रेणियों में केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार की योजनाओं को पोर्टल पर रखा गया है।

[13] ट्राई (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) द्वारा तिमाही प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट से प्राप्त डाटा

चित्र XII.11: डलैबीमउम पोर्टल तीन आसान चरणों में योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है

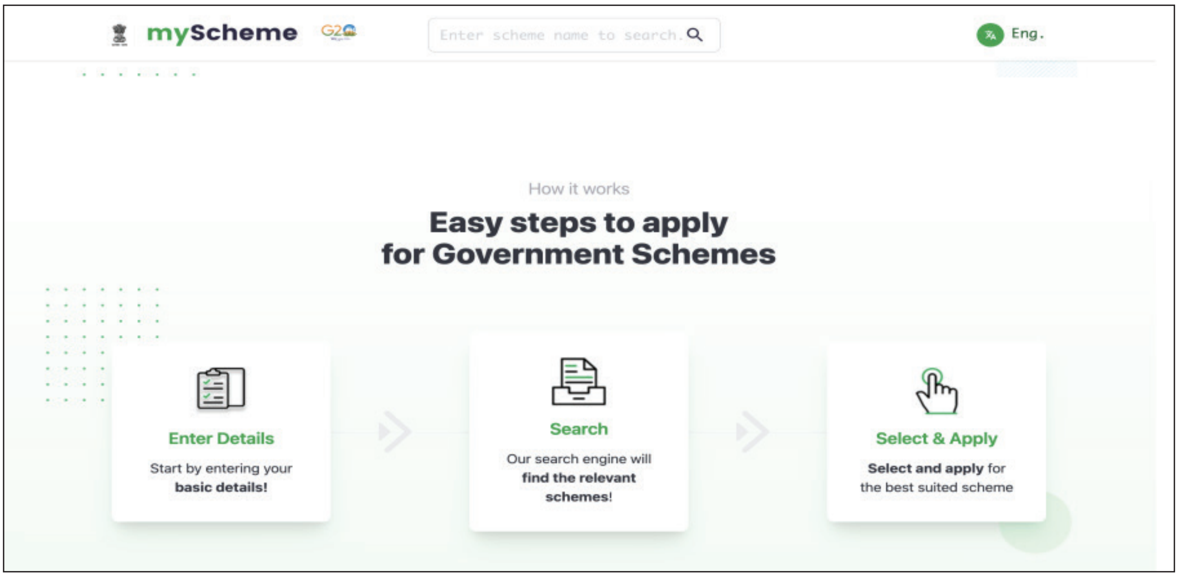

स्रोत: https://www.myscheme.gov.in/, 3 जनवरी 2023 को एक्सेस किया गया।

12.71 आम जनता के लिए खोज लागत को कम करने के लिए, सरकार ने नए युग का शासन (उमंग) के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया, जो नागरिकों को कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कर्मचारी, पेंशनभोगी, छात्र कल्याण, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्र और राज्य सरकारों को दी गई ई-सरकारी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। राशन कार्ड, रेलवे और केन्द्र और राज्य सरकारों से कई और सेवाएं 30 सितंबर, 2022 तक, केंद्र सरकार के 310 विभागों और 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभागों के तहत उमंग की लगभग 21,869 सेवाएं (1,672 केंद्र और राज्य सरकार की सेवाएं और 20197 बिल भुगतान सेवाएं) हैं। उमंग पर 4.9 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता पंजीकृत हैं और सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। सितंबर 2022 तक 489 डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) योजनाओं को उमंग पर सीधा प्रसार किया गया। कोविड-19 के कठिन समय के दौरान, उमंग ने कोविड-19 से संबंधित दावों के लिए ईपीएफओ की सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सितंबर, 2022 तक ईपीएफओ में उमंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 4.9 लाख अग्रिम दावे किए गए हैं।

12.72 हालांकि ऊपर उल्लिखित पहल सरकार को नागरिकों के दरवाजे तक लाने पर केंद्रित है, एक अनूठी पहल जो विशेष उल्लेख के योग्य है, वह है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी)। ओएनडीसी का लक्ष्य वर्तमान प्लेटफॉर्म केंद्रित डिजिटल कॉमर्स मॉडल से आगे जाना है, जहां खरीदार और विक्रेता लेनदेन के लिए एक ही प्लेटफॉर्म या एप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं। ओएनडीसी एक नेटवर्क आधारित खुला प्रोटोकॉल है जो सभी खरीदारों और विक्रेताओं को नेटवर्क से जोड़ेगा और इस प्रकार बिजनेस-टू-कंज्यूमर (बी2सी) और बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) परिदृश्य में बेहतर पारदर्शिता लाएगा। ओएनडीसी ढांचे में, उपभोक्ता संभावित रूप से किसी भी संगत एप्लिकेशन या प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किसी भी विक्रेता, उत्पाद या सेवा की खोज कर सकता है। यह उपभोक्ताओं के लिए पसंद की स्वतंत्रता में वृद्धि करेगा और उन्हें निकटतम उपलब्ध आपूर्ति के साथ मांग का मिलान करने में सक्षम करेगा, जिससे वे अपने पसंदीदा स्थानीय व्यवसायों को चुन सकेंगे। बेंगलुरू शहर में ओएनडीसी का बीटा परीक्षण प्लेटफॉर्म-केंद्रित विकल्प के रूप में ई-कॉमर्स के नेटवर्क दृष्टिकोण के संचालन में एक प्रमुख पहला कदम है। ओपन नेटवर्क सिस्टम ई-कॉमर्स परिदृश्य को सभी उपभोक्ताओं और विक्रेताओं के लिए अधिक समावेशी, सुलभ और अनुभव-संचालित बना देगा, विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए जो व्यापार निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता का प्रयोग करेंगे।

12.73 सरकार मानव पूंजी की उत्पादकता में सुधार की आवश्यकता को भी समझती है। ई-शासन अनुप्रयोगों के खुले सहयोगी सॉफ्टवेयर विकास को बढ़ावा देने के लिए, ओपेन फोर्ज नामक एक मंच विकसित किया गया है। ओपेन फोर्ज के माध्यम से ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग और ई-शासन से संबंधित स्रोत कोड के साझाकरण और पुन: उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। 16 जनवरी 2023 तक प्लेटफॉर्म पर 2205 परियोजनाओं[14] के साथ 10,328 उपयोगकर्ता हैं।

12.74 एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जिस पर सरकार ने जोर दिया है, वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर खुले संसाधनों की उपलब्धता। राष्ट्रीय एआई पोर्टल को देश में एआई पारिस्थितिकी तंत्र तंत्र को एक साथ मिला करके और केंद्र और राज्य सरकारों, उद्योग, शिक्षा, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाजों में हो रहे नवीनतम विकास को उजागर करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। 16 जनवरी 2023 तक, एआई से संबंधित 1724 लेख, 829 समाचार, 276 वीडियो, 127 शोध रिपोर्ट और 120 सरकारी पहल प्रकाशित की गई हैं।

12.75 भारत जैसे देश में, अपनी बेजोड़ भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के साथ, एआई में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए एक उपकरण के रूप में काफी संभावनाएं हैं। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकियों और समाधानों को सार्वजनिक हित में विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन 'भाषिनी' जुलाई 2022 में शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया भाषिनी पोर्टल[15] एक सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिस पर 260 ओपन-सोर्स एपीआई-आधारित एआई मॉडल विभिन्न उद्देश्यों के लिए 11 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भाषण से पाठ रूपांतरण, मशीन अनुवाद और पाठ से भाषण रूपांतरण के लिए उपलब्ध हैं। भाषिनी में लाखों भारतीयों को उनकी अपनी भाषाओं में इंटरनेट और अन्य डिजिटल संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने की काफी क्षमता है।

12.76 डिजिटल परिदृश्य उपभोक्ताओं और व्यवसायों के दरवाजे पर आ रही व्यापक तकनीकों के साथ तेजी से बदल रहा है। वेब प्रौद्योगिकियों में तीसरी पीढ़ी, 'वेब 3.0' एक ऐसा उदाहरण है जहां इंटरनेट का पूरा अनुभव बदल रहा है कि इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, वेबसाइटों का प्रबंधन कैसे किया जाता है और इंटरनेट सेवाएं कैसे प्रदान की जाती हैं। इंटरनेट के उपयोग के क्षितिज व्यापक हो गए हैं, और इसलिए बेहतर मानकों के लिए उनकी तैनाती भी हुई है। ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (ओसीईएन) मानकों का एक ऐसा सेट है जिसे भविष्य में ऋण देने और ऋण लेने के तरीके में एक प्रमुख बदलाव के रूप में सराहा जा रहा है। यह ऋण देने के कार्यों को लोकतांत्रित करने की दिशा में एक और अच्छी पहल है और इस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि छोटे ऋणकर्ता सर्वोत्तम शर्तों जिसके तहत ऋण उपलब्ध है का लाभ उठाने में सक्षम हों।

12.77 आज, हमारे पास डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर एक शक्तिशाली कथ्य है जो वैश्विक प्रतिध्वनि पा रही है। स्वास्थ्य सेवा, कृषि, फिनटेक, शिक्षा और कौशल जैसे क्षेत्रों में कोविड-19 के दौरान बढ़ते डिजिटल स्वीकृति से संकेत मिलता है कि भारत में सेवाओं की डिजिटल सुपुर्दगी में आर्थिक क्षेत्रों में व्यापक क्षमता है। आमतौर पर यह सुझाव दिया जाता है कि विकासशील देशों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करना चाहिए। हालाँकि, भारत ने अपने डीपीआई को कैसे बनाया और उसका उपयोग किया है, यह विश्व स्तर पर कई देशों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। कम लागत वाली पहुंच (आधार), यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसी नागरिक केंद्रित सेवाओं की सफलता, बड़े पैमाने पर अंगीकरण और पहुंच (डिजिलॉकर, माय गोव) और को-विन के माध्यम से वैक्सीन यात्रा भारत में सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना यात्रा महत्वपूर्ण और सफल उपलब्धियां हैं।

---

14 https://openforge.gov.in/ के अनुसार, अंतिम बार 4 जनवरी 2023 को एक्सेस किया गया।

15 ttps://bhashini.gov.in

बॉक्स XII.6: एकीकृत भुगतान इंटरफेस – रीयल-टाइम भुगतान में बड़ा परिवर्तक!

'मुझे अच्छा लगता है जिस तरह से आपने यूपीआई की लोकप्रियता बढ़ाया है। मैं डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए अपने साथी देशवासियों की सराहना करता हूं! देशवासियों ने तकनीकी और नवाचार के प्रति उल्लेखनीय अनुकूलता दिखाई है'

श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधान मंत्री

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (किसी भी भाग लेने वाले बैंक के) में कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान को एक स्थान पर विलय कर देती है। यह ''समान समान'' संग्रह अनुरोध को भी पूरा करता है, जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार निर्धारित और भुगतान किया जा सकता है।

2016 में सार्वभौमिक संचालन, एकल भुगतान पते और कम लागत वाली मोबाइल-प्रथम भुगतान प्रणाली के माध्यम से भुगतान परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए शुरू किया गया, यूपीआई ने देश में अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान को अपनाने में सक्षम बनाने की दिशा में एक सकारात्मक विघटन के रूप में कार्य किया। यूपीआई विभिन्न बैंक खातों तक पहुँचने के लिए एक एकल मोबाइल एप्लिकेशन है। इसे एंड्रोइड और आईओएस जैसे सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म पर पाया जा सकता है। चूंकि एप्लिकेशन उपयोगकर्ता के अनुकूल और तीव्र है, इसलिए उपभोक्ताओं और व्यापारियों ने डिजिटल तकनीक के प्रति काफी जुड़ाव प्रदर्शित किया है, जिससे इस डिजिटल भुगतान अवसंरचना में तेजी से वृद्धि हुई है। यूपीआई की यात्रा आकर्षक रही है। वास्तविक समय भुगतान प्रणाली का हिस्सा बनने वाले बैंकों की संख्या दिसंबर 2017 में 35 थी, जो दिसंबर 2022 में बढ़कर 380 से अधिक हो गई है। हालांकि पहले से मौजूद भुगतान मोड जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) और रीयल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) समय के साथ बढ़ा है, यूपीआई ने भुगतान के पसंदीदा तरीकों में से एक बनने के लिए तुलनात्मक रूप से बड़ी छलांग दिखाई है। इस लिहाज से यूपीआई की प्रगति उल्लेखनीय रही है।

वित्त वर्ष 19 में, यूपीआई का देश के कुल 3,100 करोड़ डिजिटल लेनदेन में 17 प्रतिशत हिस्सा था। अगले वित्तीय वर्ष में यूपीआई की हिस्सेदारी में 27 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई क्योंकि इसने 4,600 करोड़ डिजिटल लेनदेन में से 1250 करोड़ लेनदेन को संसाधित किया। वित्त वर्ष 22 में, यूपीआई का कुल 88,40 करोड़ वित्तीय डिजिटल लेनदेन में 52 प्रतिशत हिस्सा था।

औसतन, वित्त वर्ष 19-22 (कैलेंडर वर्ष) के बीच, यूपीआई-आधारित लेनदेन में मूल्य और मात्रा दोनों के संदर्भ में क्रमशः 121 प्रतिशत और 115 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हाल ही में दिसंबर 2022 में, यूपीआई ने ₹12.8 लाख करोड़ के 782 करोड़ लेनदेन के साथ अपने उच्चतम स्तर को छू लिया।

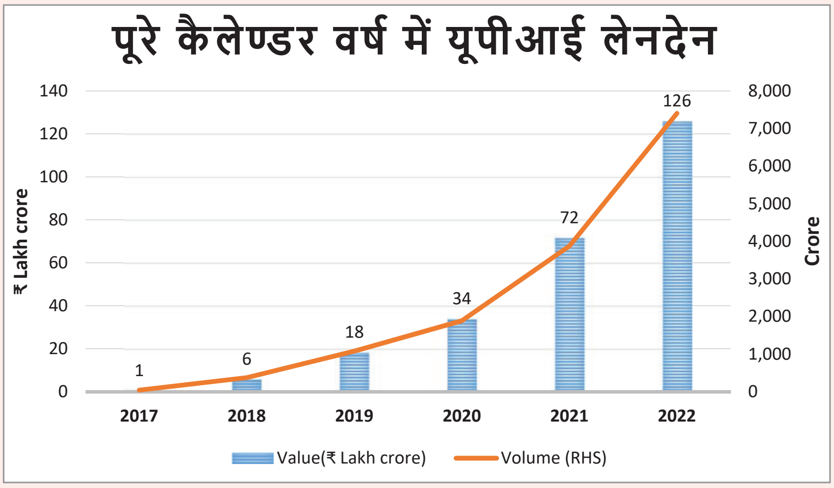

स्रोत: एनपीसीआई

यूपीआई व्यापारियों को एकीकृत करने के लिए कई तरीकों की भी अनुमति देता है- क्यूआर आधारित भुगतान सबसे लोकप्रिय है। केवल 5 वर्षों में, 23 करोड़ से अधिक यूपीआई क्यूआर व्यापारी भुगतान स्वीकार करने के लिए बाजार में उपलब्ध किए गए हैं, केवल 25 लाख डिवाइस जो इससे पहले व्यापारी भुगतान स्वीकार कर रहे थे।

यूपीआई के लाभ कोविड-19 महामारी के दौरान स्पष्ट हुए जब यूपीआई ने विशेष रूप से छोटे और सूक्ष्म व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा के रूप में कार्य किया। इसके अलावा, यूपीआई ने वित्त वर्ष 23 (दिसम्बर 22 तक) में 21.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल मूल्य के साथ 2,922 करोड़ संपर्क रहित व्यापारियों के लेनदेन को संसाधित किया है।

यूपीआई की सफलता केवल भारत तक ही सीमित नहीं है; एनपीसीआई, अपनी अंतरराष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल (एनआईपीएल) के माध्यम से रूपे/ यूपीआई संचालित ऐप्स, सीमा पार प्रेषण और सिंगाफर, यूएई, फ्रांस, नीदरलैंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यूपीआई-जैसी सेवाओं के लिए स्वीकृति पर जोर दे रहा है।

सीमा पार प्रेषण पर चर्चा की दिशा में पहल से प्रवासी श्रमिकों द्वारा वर्तमान में धन हस्तांतरण के लिए शामिल लागत और प्रक्रियाओं को कम करने में मदद मिलेगी। धन के सुचारू हस्तांतरण से प्रेषण के कुल मूल्य में वृद्धि होगी, आर्थिक विकास पर उनका प्रभाव बढ़ेगा। एनपीसीआई एक अनुकरणीय मजबूत भुगतान प्रणाली विकसित करने में भी सफल रहा है जो लागत प्रभावी, सुरक्षित, सुविधाजनक और तात्कालिक है। कई देशों ने देश में एनपीसीआई द्वारा अनुकरणीय नवाचारों से प्रेरित 'वास्तविक समय भुगतान प्रणाली' या 'घरेलू कार्ड योजना' स्थापित करने की दिशा में एक झुकाव प्रदर्शित किया है।

टेक कंपनियां डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तंत्र का विस्तार करने के लिए यूपीआई की शक्ति का तेजी से लाभ उठा रही हैं, जिससे वित्तीय समावेशन की गति में उल्लेखनीय तेजी आई है। यूपीआई ने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने वाले अभिनव समाधान विकसित करने के लिए स्टार्ट-अप और ई-कॉमर्स भागीदारों के लिए कई अवसर खोले हैं। ओपन सिस्टम ने यूपीआई सेवाएं प्रदान करने के लिए गूगल, व्हाट्सएप, वॉलमार्ट, ट्रू कॉलर, अमेजॅन, उबेर इत्यादि जैसे वैश्विक भागीदारों को सक्षम किया है।

यह कल्पना की गई है कि यूपीआई की यात्रा एक अधिक समृद्ध और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर भारत में वित्तीय समावेशन और डिजिटल अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद करेगी जो आने वाले समय में आबादी के बड़े हिस्से को समायोजित कर सके।

12.78 जीएसटी की शुरुआत, सभी प्रक्रियाओं के शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण, कर प्रशासन के डिजिटलीकरण और आयकर के लिए फेसलेस ई-आकलन योजना के साथ, प्रशासन और अर्थव्यवस्था के औपचारिककरण में सुधार हुआ है। ई-वे बिल और इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह की निर्बाध संग्रहण ने सरकार के लिए बेहतर कर संग्रह को और बढ़ाया है। इसने न केवल कर चोरी को रोकने में मदद की है बल्कि निगरानी अनुपालन के माध्यम से छोटे व्यवसायों के लिए विश्वास उत्पन्न किया है।

12.79 सरकार ने वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल से संबंधित आवश्यक सेवाओं का डिजिटल रूप से लाभ उठाने के लिए व्यक्तियों को उनके डेटा पर नियंत्रण के साथ सशक्त बनाने की दिशा में भी पहल की है। अकाउंट एग्रीगेटर (एए) एक वैश्विक तकनीकी-कानूनी ढांचा है जो व्यक्तियों को उनकी सहमति से उनकी पसंद के किसी भी विनियमित तृतीय-पक्ष वित्तीय संस्थान के साथ अपने वित्तीय डेटा को जल्दी और सुरक्षित रूप से साझा करने में सक्षम बनाता है। एए ढांचा वर्तमान में 110 करोड़ से अधिक बैंक खातों में कार्यरत है।

12.80 यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए, वित्त वर्ष 15 को भारतीय स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा सकता है। जनसांख्यिकी, तकनीकी विकास, उद्यमशीलता की भावना और बाजार के

आकार जैसे मौजूदा निहित लाभों के अलावा, हमारी सरकार के नेतृत्व में किए गए सुधारों ने भारत में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र तंत्र के परिदृश्य को बदल दिया है। वर्ष 2021 ने 'स्टैंड-अप इंडिया' योजना (जनवरी 2016 में शुरू) के पांच साल पूरे होने को चिह्नित किया, और 84,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के साथ पूरी कहानी बयां करती है। स्टार्ट-अप उपभोक्ता उत्पादों और सेवाओं के पारंपरिक क्षेत्र से कहीं अधिक मूल्यवर्धित सेवाओं जैसे उपग्रहों से आगे बढ़ गए हैं।

12.81 भारत उभरते हुए ड्रोन उद्योग को मजबूत करने के लिए भी तैयार है। मिशन 'ड्रोन शक्ति' के तहत ड्रोन स्टार्ट-अप और ड्रोन-एज-ए-सर्विस (डीआरएएएस) को बढ़ावा दिया जा रहा है। लगभग 90 प्रतिशत हवाई क्षेत्र को अब 400 फीट तक के ड्रोन उड़ाने के लिए हरित क्षेत्र के रूप में खोल दिया गया है। ड्रोन और ड्रोन आयात नीति के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना अधिसूचित की गई है। साथ ही, कृषि-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निजी इक्विटी निवेश पिछले चार वर्षों में प्रति वर्ष 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ लगभग ₹6600 करोड़ की सीमा तक पहुंच गया है।

12.82 जैसे-जैसे नई सेवाओं को लाने के लिए हमारा डिजिटल स्पेस व्यापक हुआ है, उचित नियमों की आवश्यकता भी सर्वोपरि हो गई है। इसलिए, तकनीकी-स्मार्ट विनियम डिजिटल समाजों का भविष्य हैं। इस संबंध में, दुनिया भर की सरकारों ने मजबूत डेटा गवर्नेंस के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए कानून को अपनाया है या पेश कर रही हैं। उनके नीतिगत लक्ष्यों को मानक, खुले और अंत: प्रचालनीय नयाचार की मदद से पूरक और उन्नत किया जा सकता है जो एक उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध डिजिटल सेवाओं की पसंद को बढ़ाता है और उपयोगकर्ता की गोपनीयता को बढ़ाता है, जैसे कि डेटा अधिकारिता और सुरक्षा वास्तुकला होता है।

निष्कर्ष/आउटलुक

12.83 आज, हम नई सामान्य स्थिति में काम कर रहे हैं, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी महामारी से हुए नुकसान से उबर रही है, और भू-राजनीतिक संघर्ष जारी है। बढ़े हुए कैपेक्स और मजबूत व्यष्टि आर्थिक आधार के माध्यम से अवसंरचना के निर्माण के लिए अपने समर्पित समर्थन के कारण भारत प्रभावी रूप से इस स्थिति से बाहर निकल सकता है। इसने आर्थिक विकास को सहारा दिया जबकि निजी क्षेत्र, अपनी तुलनपत्र संबंधी समस्याओं और वैश्विक झटकों से उपजे अनिश्चित मांग दृष्टिकोण के कारण निवेश करने में सतर्क था।

12.84 निवेश में लक्षित वृद्धि सभी अवसंरचना क्षेत्रों में देखी गई है। निवेश ड्राइव को बनाए रखने में मदद करने के लिए, एनआईपी ने निवेश योग्य परियोजनाओं का एक दूरदर्शी रोडमैप प्रदान किया। इसके अलावा, पीएम गतिशक्ति ने विकास के सात इंजनों (सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना) को एकीकृत करके अवसंरचना के विकास में तेजी लाने में मदद की है। जहां हाल के वर्षों में सड़क और रेलवे जैसे पारंपरिक अवसंरचना के क्षेत्रों को नए सिरे से बढ़ावा मिला है, वहीं अंतर्देशीय जल परिवहन और नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों, जिनमें महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता है, को भी पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। समानांतर रूप से, विभिन्न हितधारकों और मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इससे अनुपालन मुद्दों को हल करने और निवेश की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

12.85 इसके अलावा, ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में किए जा रहे सुधार अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को तेजी से पटरी पर लाने में मदद करेंगे। लगभग 140 करोड़ की आबादी के साथ, भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सहित सभी क्षेत्रों से ऊर्जा की भारी मांग है। विनिर्माण क्षेत्र की सफलता के लिए भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु बिजली की वहनीय और विश्वसनीय उपलब्धता महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, स्वच्छ ऊर्जा के

बढ़ते महत्व के साथ, बिजली क्षेत्र में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों की ओर नए सिरे से जोर दिया गया है। सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में उत्तरोत्तर काम किया है। यह एक क्रमिक लेकिन अंशांकित ऊर्जा परिवर्तन सुनिश्चित करेगा, देश की स्थिरता के लक्ष्यों को पूरा करेगा और अपनी राष्ट्रीय विकासात्मक आवश्यकताओं को प्रधानता देगा।

12.86 नई प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ, हम नई नियामक चुनौतियों को देख रहे हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार न तो रचनात्मक हैं और न ही विनाशकारी। उपयोग के मामले प्रौद्योगिकी और नवाचार के सकारात्मक पहलुओं को प्रस्तुत करते हैं। सरकार उन कानूनों और रूपरेखाओं से संबंधित सहित डिजिटल परिदृश्य के विकास के साथ तालमेल रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जबकि डिजिटल यात्रा की शुरुआत घर-घर सेवा वितरण के माध्यम के रूप में आधार के साथ हुई, यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के अवसंरचना को मजबूत किया। कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में को-विन, ई-रुपी, ट्रेड्स, अकाउंट एग्रीगेटर्स, ओएनडीसी, आदि जैसी अन्य पहलों के साथ, भारत ने बताने के लिए एक अनूठी और ठोस डिजिटल कथ्य विकसित की है। यात्रा जारी है और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थान में बहुत अधिक अप्रयुक्त क्षमता है।

12.87 संक्षेप में, भौतिक और डिजिटल अवसंरचना के बीच तालमेल भारत की भविष्य की विकास गाथा की परिभाषित विशेषताओं में से एक होगा।